माबोजी और मेजर टी० सी० जैनी

को

समर्पित

श्रध्याय १

. भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थः

अर्थशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए दो मागों में बाँटा गया है जिनमें से एक माग 'सैंदान्तिक अर्थशास्त्र' (Theory of economics) श्रीर दूसरा माग 'क्यवहारिक अर्थशास्त्र' (Applied economics) कहा जाता है । सेदान्तिक अर्थशास्त्र में इम कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं जो आवश्यकताओं (wants) की पूर्ति के सम्बन्ध में मनुष्य के व्यवहार की विवेचना करते हैं जब कि उद्देश दिये हों और उनकी पूर्ति के साधन अपर्याप्त हों तथा उनके विभिन्न प्रयोग हों । अर्थशास्त्र में इन आधारभूत सिद्धान्तों को इम उत्पादन, उपभोग विनिम्य और वितरण के अन्तर्गत अध्ययन करते हैं । सीमांत उपयोगिता के हास का नियम, उत्पादन के नियम, जगान का सिद्धान्त और रोजगार तथा व्यवसाय चक्र के सिद्धान्त अर्थशास्त्र के इन आधारभूत सिद्धान्तों के ही उदाहरण हैं । इम सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र का अध्ययन या तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं या विश्लेषणात्मक दृष्टि से । यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाय तो इसका रूप 'अर्थशास्त्र की विचारधारा का इतिहास' जैसा हो जाता है और दूसरी स्थित में विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र (Analytical Economics) जैसा हो जाता है जिसे संज्ञेप में केवल अर्थशास्त्र भी कहते हैं ।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र से जिल्कुल मिन है। इसमें उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्नों के बीच पैदा हो जाती हैं, जैसे कृषि और उद्योग की समस्यायें, उत्पादन, आयात और निर्यात, वैंक और मुद्रा व्यवस्था, आर्थिक नियोजन, आदि। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की माँति, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन हम ऐतिहासिक हिटकोश से भी कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र 'आर्थिक इतिहास', (Economic History) का रूप धारण कर लेता है। यदि विश्लेषण की हिट से अध्ययन किया जाय तो यह 'वर्तमान आर्थिक समस्याओं के अध्ययन' का रूप ले लेता है।

सैद्धान्तिक ग्रर्थशास्त्र की उत्पत्ति वास्तव में मनुष्य के न्यवहार के कुछ ग्राचारमूत सिद्धान्तों ग्रौर जनता की ग्राधिक स्थिति के ग्राचार पर होती है। उदा-इरण के लिये, प्राचीन ग्रर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर हंगलैंड की १८ वीं शताब्दी की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पढ़ा। इसके बाद जनता की श्राधिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए श्रीर उन परिवर्तनों के फलस्वरूप श्राधिक सिद्धान्तों में भी संशोधन परिवर्द्धन होते गये। जैसे ही नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनकी व्याख्या करने के लिये या तो पहले के श्राधिक सिद्धान्तों का विस्तार किया गया या नये सिद्धान्तों का जन्म हुश्रा। इस वर्तमान की श्राधिक समस्याश्रों का श्रम्ययन करने के लिये या श्राधिक इतिहास लिखने के लिए श्रम्थशास्त्र के सिद्धान्तों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तिक श्रीर व्यवहारिक श्रम्थशास्त्र में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है।

भारतीय अर्थशास्त्र—मारतीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक अझ है। इसके अन्तर्गत वर्तमान समय की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे, चकवन्दी, मृमिन्तरण, मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली, इत्यादि और साथ ही उनकी उत्पत्ति कारणों का भी विवेचन किया जाता है। इस अर्थ में भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन विश्लेषणात्मक हो जाता है। इसमें यह प्रयत्न किया जाता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों का सही-सही चित्र प्रस्तुत किया जाय, विभिन्न घटनाओं के कारणों को समसाया जाय और यह भी वर्ताया जाय किया जाय, विभिन्न घटनाओं के उत्पन्न होने की सम्भावना थी, वह क्यों नहीं हुई। वर्तमान समय की समस्याओं का अध्ययन करने में हमें भावी घटनाओं का कुछ आमास हो जाता है। वर्तमान समय की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने और इसकी मावी प्रवृत्तियों का पता लगाने में हम सैद्धांतिक अर्थशास्त्र की सहायता केते हैं। यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भिन्न-भिन्न हैं तो हम जिन परिणामों पर पहुँचते हैं वह भी अवश्य भिन्न होंगे। इसिजिये भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन वहुत कुछ हमारे सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के आन पर निर्भर करता है।

जैसा कि इस पहले कह सुके हैं भारत में विभिन्न आर्थिक समस्याओं के पेतिहासिक विकास का अध्ययन 'भारत का आर्थिक हितहास' कहा जाता है आर्थिक हितहास में घटनायें कमानुसार लिखी जाती हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के अनेक पाठ्य पुस्तकों में "भारत का आर्थिक हितहास" और "भारतीय अर्थशास्त्र' को साय-साय दिया गया है और पाठक को इन दोनों अंगों का साय-साय अध्यय करना पड़ता है। इससे पाठक के लिये आवश्यक और सम्बन्धित समस्याओं इं समसना और वर्तमान समस्याओं पर स्थान केन्द्रित करना कठिन हो जाता है यह बात निस्सन्देह सही है कि भारत के आर्थिक हितहास के अध्ययन के आधा पर ही वर्तमान आर्थक समस्याओं का सही अध्ययन किया जा सकता है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि यह हम भारत के आर्थिक हितहास और मारती

श्रथंशास्त्र को एक में मिला दें तो वर्तमान श्राधिक समस्याएँ, जिन पर पाठक को ध्यान देना श्रावश्यक है, भारत के श्राधिक इतिहास के विस्तृत विवेचन में लुस हो जाती हैं। इसिलये इस पुस्तक में यह प्रयत्न किया गया है कि भारतीय श्रथंशास्त्र की समस्याएँ श्राधिक इतिहास के विस्तृत वर्णन में खो न जायें। जहाँ श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा है वहाँ तुलनात्मक श्रध्ययन के लिये श्राधिक इतिहास का कुछ विस्तृत वर्णन किया गया है। परन्तु विशेष जोर भारत की वर्तमान श्राधिक समस्याश्रों के विवरणात्मक श्रीर विश्लेषणात्मक श्रध्ययन पर दिया गया है।

अन्य परिभाषायें — पूर्व लिखित परिभाषा के श्रतुसार मारतीय श्रर्थशास्त्र भारत की वर्तमान श्राधिक समस्याओं का ग्रध्ययन है। परन्तु भारतीय श्रर्थशास्त्र ,की इसके श्रतिरिक्त तीन श्रीर परिभाषायें दी गयी हैं:—

- (१) भारत की आर्थिक विचारधारा के विकास के अध्ययन की मारतीय अर्थशास्त्र कहा गया है। प्राचीन भारत में मैद्धान्तिक अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया था। भारतीय आर्थिक विचारधारा पश्चिमी आर्थिक विचारधारा के साथ-साथ विकास नहीं कर सकी है। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के चेत्र में भारत ने अवश्य कुछ योगदान किया है। यदि इस पर विचार न किया जाय वो भारतीय आर्थिक विचारधारा पूर्णत्या प्राचीन भारत की देन है। यदि यह मान भी लिया जाय कि भारतीय आर्थिक विचारधारा आधुनिक सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र के साथ विकास कर सकी है तब भी इम उसे भारतीय अर्थशास्त्र का नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक अंग है जब कि आर्थिक विचारधारा का इतिहास, चाहे वह भारतीय हो या यूरो-पीय, 'सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र' के अन्तर्गत आता है।
- (२) यह कहा गया है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति एक विरोध प्रकार की है, उसकी गठन और उसमें निहित विचारधारा अन्य देशों से मिल है इसिलये भारतीय परिस्थितियों के अनुकृत हमें बिल्कुत ही नये प्रकार के आर्थिक सिद्धान्तों का स्वान करना चाहिए और उसे भारतीय अर्थशास्त्र' कहना वाहिए। न्यायाधीश रानाडे ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्थिति परिचमी देशों से नितान्त भिन्न है, प्रतियोगिता (Competition) से कहीं अधिक प्रभावशाली यहाँ के रीति-रिवाल और राज्य के नियम हैं, साथ ही किसी समझौते की अपेदा। समाज में सम्मान अधिक प्रभाव रखता है। यहाँ न पूँ जी गतिशील है और न अम और न इनमें इतना उत्साह (enterprising) और खिंद ही है कि गतिशील बनें। मलदूरी और लाम भी निश्चत है; जनसंख्या

श्रेपने नियम के श्रनुसार बढ़ती जाती है परन्तुं वीमारियों श्रीर श्रकाल से उसमें कंमी भी होती रहती है, उत्पादनं की मात्रा प्रायः स्थिर है, यदि एक वर्ष फर्सल अच्छी हो गयी तो वह अगले वर्ष के अनिश्चित मीसम से होने वाली हानि की पूर्ति का सावन बन जाती है। इसके आधार पर न्यायाधीश रानाडे इस परिणाम पर पहुँचे कि ग्राधुनिक ग्रर्थशास्त्र के सिद्धान्तों में जिन वातों को निश्चित ग्राधार मान लिया गया है वह भारत में लागू ही नहीं होती वलिक वह वास्तव में गलत दिशा की ब्रोर ले बाती हैं। इससे कुछ लोग इस परिगाम पर पहुँचे कि मारत क़ी ग्रार्थिक स्थिति को समझने के लिये नये श्रार्थिक सिद्धान्ती की श्रावश्यकता है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। कोई मी ग्रार्थिक सिदान्त, चाहे वह पश्चिमी देशों में विकसित हुआ हो या पूर्वी देशों में, व्यापक रूप से सारे विश्व पर लागू होता है। आर्थिक सिद्धान्त मनुष्य के स्वमाय पर आधारित होता है और मनुष्य का स्त्रभाव सर्वत्र समान होता है। यदि आर्थिक सिद्धान्त का उचित निरूपण किया गया है तो वह सर्वत्र लागू होगा। परन्तु यह मानना पदेगा कि ऋार्थिक सिदान्त स्थिर सिदान्त नहीं होता श्रीर न वह अपरिवर्तनशील ही होता है। यदि श्रार्थिक स्थिति में परिवर्तन हुश्रा तो श्रार्थिक सिद्धान्त में भी परिवर्तन होगा। इंगलैंड में प्राचीन सेदान्तिक ग्रर्थशास्त्र का जो विकास हुआ वह इंगलैंड की उस समय की त्रार्थिक स्थितियों पर त्राघारित था। वह यह भाव्य नीति (Laissez faire) श्रीर स्वतंत्र न्यापार (Free trade) के सिद्दान्तों पर श्राघारित या। परन्तु बाद में जब विशेष रूप से यूरोपीय देशों में यह पता चला कि स्वतंत्र च्यापार श्रार्थिक परिस्थिति के प्रतिकृत है तो फोड़िक तिस्ट तथा अन्य अर्थ-शास्त्रियों की त्रालोचना के खाधार पर स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त में खावश्यक चंग्रोवन किया गया श्रीर कम विकसित देशों के संरद्द्या के लिये तटकरों (Tariffs) तथा अन्य उपायों का महत्व स्वीकार किया गया । सोवियत संघ की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ समानवाद श्रीर श्रार्थिक नियोजन के सिद्धान्तों में भी परि-वर्तन होता गया। इधर ऋछ वर्षों से पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक दृष्टि से विछाड़े हुए चेत्रों की आर्थिक समस्याओं के कार्य आर्थिक सिद्धान्तों में परिवर्तन-परिवर्द्धन हो रहा है। मारत में श्राष्यात्मिक विचारधारा से प्रमाविव 'श्रावश्यकता' का एक विल्कुल नया सिद्धान्त विकसित हो रहा है निसे 'श्रावश्य-कता रहित होने का सिद्धान्त' (Theory of wantlessness) कहा जाता है। यह पश्चिम के ग्रावश्यकता के सिदान्तों से नितान्त भिन्न है। यह संभव है कि विभिन्न देशों की बदलती परिस्थितियों से प्रमावित होकर, जिनमें भारत मी सन्मिलित है, मिविष्य में अर्थशास्त्र के सिदान्तों में और भी संशोधन हो। परन्द्र

जातिबाद, संयुक्त-परिवार की प्रधा, श्रम श्रीर पृंजी में गतिरीलता का श्रमाव, इत्यादि इस बात को खिद नहीं करते कि इस देश के लिये नये प्रकार के श्राधिक सिद्धान्तों की श्रावर्यकता है। माँग श्रोर पूर्त का सिद्धान्त जितना भारत में लागू होता है उतना ही श्रन्य देशों में भी लागू होता है। इसलिये हमारी भारत की भिन्न परिस्थितियों के कारण नये प्रकार के श्राधिक सिद्धान्तों का विकास करने की माँग उचित नहीं है, साथ ही इन विशेष सिद्धान्तों श्रीर नियमों को जो केवल भारत में लागू होंगे 'भारतीय श्रर्थशास्त्र' का नाम देना न्यायसंगत नहीं है।

(३) यह भी कहा गया है कि यदि उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण के आर्थिक सिदान्तों का विवेचन भारतीय उदाहरणों के साथ किया गया हो तो उसे भारतीय अर्थशास्त्र कहा जाना चाहिये। किसी भी सिदान्त को स्पष्ट रूप से समानों के लिये निश्चय ही कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है परन्तु इससे ही वह भारतीय अर्थशास्त्र' नहीं हो जाता। यदि कोई पाट्य पुस्तक अंग्रेज विद्यापियों के लिये लिखी जाय तो यह स्वाभाविक ही है कि उसमें अंग्रेजी या इंगलैंड के उदाहरण दिये जायेंगे। इसी प्रकार यदि कोई पाठ्य पुस्तक भारतीय विद्यापियों के लिये लिखी जाय तो उसमें भारत के उदाहरण दिये जायेंगे। परन्तु इतने से ही वह 'अंग्रेजी अर्थशास्त्र', या 'भारतीय अर्थशास्त्र' नहीं यन जाते। इन परिस्थितियों में वह केवल सैदान्तिक अर्थशास्त्र रहता है चाहे उसमें किसी भी देश के उदाहरण दिये गये हों।

इससे स्पष्ट है कि मारतीय अर्थशास्त्र भारत की वर्तमान श्राधिक समस्याओं का ठीक वैसा हो अध्ययन है जैसा अन्य देशों में किया जाता है। वर्तमान श्राधिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अन्य देशों की भाँति ही भारत में भी हम देश की समस्याओं पर उन आर्थिक सिद्धान्तों को लागू करते हैं जो सर्वत्र सत्य सिद्ध हो चुके हैं या उन्हें सभी स्वीकार करते हैं। इसलिये अर्थशास्त्र के आर्थिक सिद्धान्तों को भारत की आर्थिक स्थिति पर लागू कर हम जिन परिखामों पर पहुँचते हैं तथा जिन प्रवृत्तियों का पता लगाते हैं उनको भारतीय अर्थशास्त्र कहते हैं तो यह नितान्त न्थायसंगत है।

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता

(१) यदि इम अपनी आर्थिक परिस्पितियां को सही सही समझना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इस भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करें। इसके अध्य-यन से इस यह जान सकते हैं कि इस प्रगति कर रहे हैं या नहीं, यदि कर रहे हैं तो किस सीमा तक और यदि प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण क्या हैं। (२) भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से इम अपने देश की अन्य देशों के खाय वुलना कर सकते हैं और इस प्रकार की तुलना से यह जान सकते हैं कि इस किस प्रकार तथा किस दिशा में सिक्य होकर अपनी किसयों को दूर कर सकते हैं और आर्थिक उन्नति के अभीष्ट स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। (३) मारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करके ही इस मिविष्य के लिये अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं। पञ्च-वर्षीय योजना तैयार करने में और योजनाओं को प्रमुखता देने में योजना आयोग को भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन पर ही अपने निर्ण्यों को आधारित करना पद्मा। भारत के आर्थिक विकास में जो अपूटियाँ रह गयी है तथा आयोग ने आर्थिक प्रगति की वांछित गित से उन्हें दूर कर देने के सुमाव भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर ही दिये हैं।

अध्याय २

श्राकृतिक साधन

भौगोलिक स्थिति

किसी देश के निवासियों को श्रापिक स्थिति तथा उनके व्यवसायों पर उस देश की भीगोलिक स्थिति, भूमि की उपजाक शक्ति, वर्षा, जलवायु श्रीर उसकी बनस्पति तथा उसके वन्य एवम् पालत् प्रशुश्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस-लिये भारत की भीगोलिक स्थिति का श्रध्ययन करना श्रावश्यक है।

भीतिक विशेषताएँ—भारतीय संय का च्रेक्कल १२६६६४० वर्ग मील है। उत्तर से दिन्निण तक इस देश की लम्बाई २००० मील श्रीर पूर्व से पिक्षम तक १७०० मील है। इसकी भीतिक सीमा ८२०० मील श्रीर सामुद्रिक सीमा ३५०० मील है। कर्क रेखा इसको बीचों-बीच से दो भागों में बाँटती है। उत्तरी भाग श्रीतोष्ण कटिवन्थ में श्रीर दिन्निणी उप्ण कटिवंथ में स्थित है। जम्मू श्रोर काशमीर तथा श्रक्टकर १६५३ में निर्मित श्रांध्र राज्य सिंहत भारत संघ में राज्यों के प्रक्तिक के पूर्व २६ राज्य थे। १ नवन्यर १६५६ में राज्यों का पुनर्संगठन होने के पक्षात् श्रव भारत संघ में १४ राज्य यथा श्रांध्र प्रदेश, श्रासम, विदार, केरल, मध्य प्रदेश, मदास, वम्बई, मैसर, उद्दीस, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बङ्गाल, जम्मू श्रीर काशमीर, तथा केन्द्रीय प्रशासन के दिन्नी, हिमांचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, श्रंडमन-निकोबार द्वीप समूह श्रीर लेकिटव, मिनिकाय, श्रामिन्दिवी द्वीप समूह नामक ६ प्रदेश हैं।

भारत उत्तर में हिमालय, उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में पर्वत-श्रीण्यों, दिल्ण में बंगाल की खाड़ी श्रीर हिन्द महाशागर श्रीर पश्चिम में श्ररव शागर द्वारा बिरा हुश्रा है। भारत को चार विभिन्न भीगोलिक भागों में बाँटा जा सक्ता है (१) हिमालय, (२) गङ्गा का मैदान, (३) दिल्ल्णी पठार, (४) तटवर्ती प्रदेश। हिमालय की श्रेणियाँ १५०० मील की लम्बाई में श्रीर १५० मील से लगा कर २५० मील तक की चौड़ाई में फैली हुई हैं। हिमालय उत्तर की बर्फीली वायु से तथा उत्तरीय विदेशियों के श्राक्रमण से भारत की खदा से रक्षा करता श्राया है/ इसके कारण उत्तरीय सीमा के मार्गों से व्यापार में भी बाधा पहुँची है। मान-स्त को रोक कर भारत के उत्तरीय भाग की प्रचुर वर्षा का साधन हिमालय ही रहा है। भारत को श्रनेकों नदियों का उद्गम हसी भाग से हुश्रा है। यहाँ बहु- मूल्य वन पाये जाते हैं जिनका पूर्ण प्रयोग होना श्रमी वाकी है। इसका श्रिध-कांश माग काश्मीर श्रीर जम्मू की घाटियों तथा पूर्वीय चाय के चेत्रों को छोड़ कर खेती के श्रायोग्य है।

गङ्गा का मैदान पूर्व से पश्चिम की श्रोर लगभग १५०० मील लम्बा श्रीर उत्तर से दिश्च की श्रोर १५० से लगाकर २५० मील तक चौड़ा है। यहाँ श्रोनेकों निद्यों श्रपनी सहायक निद्यों के साथ वहती हैं। यहाँ की भूमि वहुत उपजाऊ है श्रीर इसीलिए यहाँ की जनसंख्या का घनत्व भी सबसे श्रिषिक है। देश के बहुत वड़े-बड़े नगर इसी माग में स्थित है।

पठारी भाग जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, दो भागों में बाँटा जा सकता है। (अ) मध्य भारतीय पठार श्रीर (व) दिज्ञणी पठार।

पठारी भाग गङ्गा के मैदान के विपरीत श्रनेकों पर्वत श्रेणियों से भरा हुश्रा है। इनकी ऊँचाई १५०० से ४४०० फीट तक है। इस भाग के दोनों श्रोर पूर्वीय श्रीर पश्चिमीय घाट की पर्वत श्रेणियों हैं। पठार स्वयं पथरीला श्रोर ऊँचानीचा है। इसका विस्तार पूरे दिल्लिण की पहादियों तक है जो कहीं-कहीं पर ४००० फीट ऊँची हैं जैसे नील घाटी श्रोर कार्डमाम की पहादियों। इस पठार से होकर नर्मदा श्रोर ताप्ती निर्दयों बहतीं हैं जो श्रारय सागर में गिरती हैं श्रोर महानदी, कृष्णा तथा कावेरी जो यंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वनो की इस प्रदेश में कमी है पर खिनल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। समुद्री तट कटे हुए नहीं हैं। इस्लिये स्वाभाविक वन्दरगाह केवल विजगापट्टम, कोचीन श्रोर कालीकट हैं। पूर्वी श्रोर पश्चिमी तटों की भूमि उपजाक है। वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है तथा चावल चाय श्रोर कहरा पैदा होता है।

जलवायु और वर्षा—भारत की जलवायु मानस्ती तथा उष्ण प्रदेशीय है। यहाँ की तीन प्रमुख ऋतुर्वे निम्न हैं: (१) मार्च के आरम्म से जून के अन्त तक गर्मी की ऋतु, (२) जून के अंत से खितम्बर के अंत तक वर्षा ऋतु और (३) अक्टूबर से फरवरी के अंत तक शीत ऋतु । अप्रैल और मई के महीनों में स्थं की किरग्रें खीधी लम्बवत पहती हैं और ये महीने देश के सब से अधिक गर्म होते हैं। उत्तरी-पूर्वी मारत में मई के महीने का श्रीसत तापक्रम १००° फैरनहाइट होता है और गंगा के डेल्टा में लगमग ५५० फे०। किन्हीं स्थानों पर तापक्रम ११७° ११८° फे० मी ही जाता है। जून के मध्य में मानस्ती हवार्येचलने लगती हैं और विजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। श्रीधकांश वर्षा दिल्ली-पश्चिमी मानस्त के कारण होती है। उत्तरी-पूर्वीय मानस्त ट्रावनकोर कोचीन तथा मद्रास के कुछ मार्गों में वर्षा का कारण होती है। श्रीतकाल में

जनवरी के महीने में उत्तर से दिल्ला के भागों में तापकम बदलता रहता है। दिन गरम ग्रीर रातें ठंडी होती हैं।

वर्षा के दृष्टिकी से देश को चार मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है।
(१) श्रत्यधिक वर्षा वाला भाग जहाँ ८०" के लगभग वर्षा होती है जैसे श्रासाम, वंगाल, उत्तरी विहार, शायद्वीप का पश्चिमी तट श्रीर कुछ पूर्वीय तट के भाग; (२) साधारण वर्षा वाले माग जहाँ ४०" से लगाकर ८०" तक वर्षा होती है जैसे उद्दीस, दिल्ली विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश श्रीर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ; (३) बहुत कम वर्षा वाले भाग जहाँ २०" से ४०" तक वर्षा होती है जैसे मद्रास, मैसर, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान श्रीर पूर्वीय पंजाब श्रीर (४) स्ले रेगिस्तानी भाग जहाँ २०" से भी कम वर्षा होती है जैसे राजपृताना का रेगिस्तान, पश्चिमी काश्मीर श्रीर पंजाब के भाग। भारतवर्ष में वर्षा की मुख्य विशेषता उसकी श्रानिश्चतता है। यह ठीक ही कहा गया है कि भारतीय कृषि 'वर्षा का जुश्रा' है। यदि वर्षा समय से पर्याप्त हो गई तब तो फसल श्रच्छी होगी, किसान प्रस्व होंगे श्रीर श्रम पर्याप्त होगा। पर यदि वर्षा देर से हुई श्रीर श्रनियमित रूप से हुई, कहीं श्रत्यधिक श्रीर कहीं श्रतिन्यून, तो स्वा पढ़ेगा बाढ़ श्रायेगी श्रीर लोगों की कठिनाह्यों की सीमा न रहेगी।

भूमि—भारत की भूमि को निम्न भागों में बाटा गया है (i) कॉप मिटी (ii) काला मिटी (iii) लाला मिटी जिसमें लाल चिकनी और पीली मिटी मिली होती है (iv) लेटेराइट मिटी (v) रेतीली मिटी (vi) लवणयुक्त और जारिल मिटी और (vii) जीएं मिटी। इनमें से प्रथम चार तो मुख्य हैं और दूसरी चार गीए जो कि कहीं कहीं पाई जाती हैं। "प्रथम तीन प्रकार की मिटियों में पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है पर उनमें कास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और चूना पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है पर उनमें कास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और चूना पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है पर उनमें काम्पाप्त है। केंद्रेराइट मिट्टी में धूमस की मात्रा पर्याप्त है पर अन्य रसा-यनिक गुए कम हैं। कॉप मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ और वहीं आसानी से काम में लाई जाने योग्य है। यह मिट्टी सम्पूर्ण सिध, गंगा के मैदान में तथा पूर्वी और पश्चिमी तट प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी जिसमें नमी को रोक रखने की शक्ति अपार होती है और जो बहुत चिपचिषी होती है दिख्णी पठार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और लाल मिट्टी इसी माग के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मध्यभारत, आसाम, पूर्वी-पश्चिमी धाट के किनारे पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मध्यभारत, आसाम, पूर्वी-पश्चिमी धाट के किनारे पाई जाती है।

जल और विद्युत के साधन — चूँकि भारत में अनेक निद्याँ और मरने हैं इस्रिक्षेय यहाँ पानी और विद्युत के साधनों की कमी नहीं है परन्तु खेद हैं कि इन साधनों का अभी तक उचित रीति से उपयोग नहीं किया जा सका है।

प्रति वर्ष भारत की नदियों से लगभग एक श्ररव ३५ करोड़ ६० लाख एक इ फुट पानी वह जाता है परन्तु इसमें से केवल ७ करोड़ ६० लाख एकड़ फुट या कुल का केवल ५ ६ प्रतिशत सिंचाई के काम में लाया जाता है। श्रनुमान लगाया गया है कि ४५ करोड़ एकड़ फ़ुट पानी सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। संमव है प्रथम पंचवर्षीय योजना की बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित कर देने से श्राधिक पानी का उपयोग किया जा सके श्रीर तब बिजली का भी श्राधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई की कुछ छोटी योजनायें भी है जिनसे तालाबों, कुन्नों न्रौर नहरों का पानी भी सिचाई के काम में लाया जा सकेगा। वर्तमाग समय में ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है, जिसमें से २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, १ करोड़ 40 लाख से कुछ कम एकड़ भूमि कुत्रों द्वारा धींची जाती है, ६० लाख एकड़ से कुछ कम मूर्मि कुन्नों द्वारा चींची जाती है स्त्रीर लगमग ७० लाख एकद स्रन्य साधनों के द्वारा । कृषि की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिये उपलब्ध जल की मात्रा बढ़ाना है। मूमि की उत्पादन शक्ति, खाराज, दालें, तथा कृषि के श्रन्य माल की कुल मात्रा, निनका उत्पादन किसान कर सकता है, बहुत कुछ सिंचाई की सुविधा पर निर्भर करता है। जब तक किसान के पास अपनी खेती में सिंचाई करने के पर्याप्त साधन नहीं है तब तक चाहे वह कितना ही कुशल श्रीर साहसी न्यों न हों, श्रपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकता है।

भारत में शक्ति के मुख्य साधन तेल, कोयला और पानी हैं। भारत में पेट्रोलियम की कभी अवश्य है पर कोयले की खाने बहुत हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खानों में कुल कोयला लगमग २० अरब टन होगा। इसका एक चौथाई कोयला बहुत अच्छा कोयला है और उसका प्रयोग धातुओं के संबंध में सीमित रहना चाहिये। निम्नकोटि के कोयले का प्रयोग शक्ति उत्पादन के लिये किया जा सकता है। परन्तु भारतीय उद्योगों और कृषि के लिये विद्युत शक्ति का समुजित प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। १६२५ तक विद्युत्तनन और विकास की गित बड़ी धीमी रही है। इस वर्ष तक केवल १६२३४१ किलोबाट विद्युत शक्ति पैदा की गई थी। १६३५ में यह शक्ति पचगुनी बढ़ गई और ६००४०२ किलोबेट हो गई। प्रथम पंचवर्धीय योजना के आरम्म में २३ लाख किलोबाट विद्युत शक्ति के उत्पादन का प्रवन्ध थए। नई योजनाओं के फलस्वरूप यह बढ़ कर ३४ लाख किलोबाट हो गयी। इससे यह सिंद होता है कि देश को अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करने वाली योजनायें सफल रही हैं। दितीय पंचवर्धीय योजना के अन्तर्गत ३५ लाख किलोबाट शक्ति वे सहाने का विचार किया है। जब सब दीर्घकालीन

योजनायें तीन या चार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त तक पूर्ण हो जायँगी तब विद्युत शक्ति लगमंग ७० लाख किलोवाट बढ़ जायगी। हमारे देश में समस्या केवल अधिक विद्युत शक्ति के उत्पादन की ही नहीं है वरन् यह भी है कि विद्युत शक्ति पर्याप्त मात्रा में इतने सस्ते मूल्य पर लोगों को पास हो सके कि किसान, फेंक्ट्री वाले और अन्य साधारण कारीगर उसका आसानी से प्रयोग कर सकें।

वनस्पति और जानवर

विशाल चेत्रफल, विभिन्न भौंगोलिक स्थितियों, विभिन्न जलवायु इत्यादि के कारण भारत में वे सब प्रकार के बन, फलों के बाग, श्रीर खेती की उपज जो भायः उच्ण, शीत श्रीर समशीतोच्ण जलवायु वाले भ्-चेत्रों में पाये जाते हैं प्राप्त हैं। देश में पालत् तथा वन्य पशु भी श्रनेक प्रकार के मिलते हैं।

वन—मारत में बनों का चेत्रफल लगभग १४ करोड़ ७७ लाख एकड़ है, जिसमें से ४ करोड़ ३५ लाख एकड़ जंगल दिल्या माग में, ३ करोड़ ६७ लाख एकड़ मध्यम भाग में, ३ करोड़ ६४ लाख एकड़ पूर्वी माग में और ७ करोड़ ६८ लाख ७० हजार एकड़ उत्तरी-पश्चिमी मागों में स्थित हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय और अनेक राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व बहुत बड़ी संख्या में वृद्ध काटे गए, जिसके परिश्वामस्वरूप देश के वन-प्रदेश का चेत्रफल बहुत कम हो गया है। वनों से देश को बहुत अधिक लाम होते हैं। उनसे हैं घन और इमारती लकड़ी तो प्राप्त होती ही है, इसके अतिरिक्त (१) वे औद्योगिक उपयोग के लिए बाँस, सवाई व अन्य वासे, लाख, गोंद इत्यादि भी प्रदान करते हैं, (२) वे भूमि-चरण (Soil erosion) रोकते हैं, भूमि की उर्वरता को सुरिक्त रखते हैं, और (३) पशुओं के लिए चरागाह भी प्रदान करते हैं।

वन राष्ट्रीय श्राय के श्रत्यन्त महत्वपूर्ण शाधन है। उनसे उद्योगों के लिए अनेक कच्चे माल प्राप्त होते हैं। भारत के बनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याएँ यह हैं कि: (१) वनों के चेत्रफल में वृद्धि की जाय, (२) देश में जितने प्रकार के वृद्ध पाए जाते हैं उनका संरच्या किया जाय श्रीर (३) यथासंभव नई जाति के वृद्ध भी उगाने प्रारम्भ हों। भारत सम्बार ने वन नीति से सम्बन्धित मई १९५२ के प्रस्ताव में भारतीय वनों की सुरच्चा श्रीर उनके विकास की श्रावश्यकता पर ध्यान दिया। उस प्रस्ताव में यह लक्ष्य रखा गया कि देश की कुछ भूमि का एक-तिहाई भाग वनों के रूप में रहे। हिमालय-प्रदेश, दक्षिण श्रीर श्रन्य पर्वतीय चेत्रों पर वनों के श्रन्तर्गत कुल भूमि का ८०% रहेगा, जब कि समतल चेत्रों में कुल भूमि २०% पर जंगल उगाए जायेंगे। प्रथम पंचवर्णीय योजना में वनों की विकास-

सम्बन्बी नीति के श्रन्तर्गत यह व्यवस्था रखी,गई थी कि (श्र) मुरु के समय में जो भाग विल्कुल उजद गए थे, उनका नयकरण (renovation) हो, (य) नहीं श्रिषक मात्रा में भूमि-च्ररण हुआ था, वहीं जंगल लगःण नायें, (स) यनी में श्रावागमन के साधनी का विकास किया जाय, (३) ईपन के श्रामाव की द्र करने के लिए गाँवों में श्रिधिक बाग लगाए, जायें, श्रीर (य) कई प्रकार की ऐसी लकड़ी, जो अब तक इमारती लकड़ी के रूप में काम में नहीं आ रही थी, उसे ठीक दंग से विकाने श्रीर मसाला लगाकर मजबूत बनाने के बाद श्रिषकाधिक प्रयोग में लाया जाय। राज्य सरकारों की यन-सम्बन्धी नीति न तो मई १९५२ फे वन-नीति से सम्बन्धित प्रस्ताय के बिल्कुल खनुक्त है ख़ार न यनी का पेन्द्रीय समिति (Central Board of Forests) के श्रानुरूप है। इस यन फेन्ट्रीय समिति की बैठक जून १९५३ को देहरावृन में हुई भी जिसने कई प्रस्ताय पास किए खीर जिनका उद्देश्य यह या कि राज्य सरकार भारत-सरकार की बन-नीति की कियात्मक रूप दें। १९५० में भारत-सरकार ने 'वन-महोत्सव छान्टोलन' प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत से जंगलों का श्रभाव ट्र किया जाय ! कित श्रमाग्यवश इस कार्य-क्रम के श्रंतर्गत लगाए गए श्रधिकारा पृत्र पानी न मिलने श्रीर लापरवाही के कारण सूख गए । श्रधिक वृत्त लगवाना श्रीर जब तक वे काफी बढ़े न हो जायँ इनकी देखमाल करते रहना तो आवश्यक है ही, किंतु उसके साय-साय यह भी श्रास्यक है कि ईंघन श्रथवा श्रग्य किसी उपयोग के लिए खड़े वृत्त न करवाए जायं।

मछली-उद्योग—"भारत के लम्बे समुद्र-तट पर अरंख्य मुद्दाने, नमकीन पानी वाली कीलें और स्थिर जलाशय हैं, जिनसे काफी मछिलयों प्राप्त दोती हैं। नमकीन पानी वाला चेत्र लगभग १० करोड़ ६० लाख एकड़ है, जिसमें चिल्का कील भी शामिल है। यह चिल्का कील २,५६,००० एकड़ के विस्तार में फैली हुई है और इससे प्रतिवर्ष ३,००० टन मछली प्राप्त होती हैं। मछली-उद्योग में भारत की राष्ट्रीय-आय में प्रतिवर्ष १० करोड़ हपये आते हैं। यह मछली-उद्योग सुख्यतः दो प्रकार का है: (१) देश के अंदर का मछली उद्योग (inland fisheries), (२) समुद्री मछली-उद्योग (marine fisheries)। मछली पकड़ने के आँकड़े भारत में विश्वस्त रूप से प्राप्त नहीं हैं। भारत में प्रतिवर्ष समुद्री मछलियों का उत्पादन लगभग १०० लाख मन है और वाजे पानी की मछिलयों का उत्पादन क्ष्मम से कुछ कम होता है। आयात द्वारा प्राप्त मछलियों का क्ष्मादन में प्रतिवर्ष १७० लाख मन की कुल पूर्ति होती है, जिसमें से ७०% मुद्दाने और समुद्र की मछिलयों और शेष ३०% ताजे पानी की मछिलयों होती हैं।

इसको अर्थ यह है कि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति को ३४ पींड मछली मिलती है, जो निश्चित रूप से अपर्याप्त है। उत्तरप्रदेश श्रीर पंजाब की अपेबाइत ट्रावनकोर को चीन, पिश्चमी बंगाल और विमाई में प्रति व्यक्ति मछली को उपयोग अधिक हैं। यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रारम्म में मछलियों की कुल उत्पत्ति लगभग १० लाख मीट्रिक टन थी जिसका २०% घरेलू उपयोग के लिये थी श्रोर बाकी समुद्री मछली अथवा वेचने के लिये देश के अंदर से प्राप्त मछलियों थीं। प्रथम योजना के फलस्वरूप ऐसा अनुमान किया जाता है कि मछलियों की उत्पत्ति १०% बढ़ जायंगी। १६५५—५६ में मछलियों की उत्पत्ति १०% बढ़ जायंगी। १६५५—५६ में मछलियों की उत्पत्ति १०% बढ़ जायंगी। इस्प्रि—५६ में मछलियों की उत्पत्ति १० जाख लाख मिट्रिक टन से कुछ आधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मछलियों का उत्पादन लगभग ३३% बढ़ जायंगा अर्थात् १४ लाख मीट्रिक टन हो जायंगा। वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति मछलियों का वार्षिक उपमोग ४ पौएड से कम ही है। जनता का भोजन संबुखित करने के लिये यह आवश्यक है कि मछलियों का उपभोग बढ़ाया जाय।

समुद्री मर्झालयों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मर्झली पकड़ने में बैज्ञानिक यंत्रों के प्रयाग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक एक सीमित ज्ञेत्र में ही मर्झलयों का शिकार किया जाता है। जहाँ तक देश के अंदर मद्भली पकड़ने का सम्बन्ध है, इस बात की आवश्यकता है कि मर्झलयों का पोषण करने और उनके शिकार करने का कार्य वैज्ञानिक रीति से किया। "भारत के वर्तमान जलाशयों में प्रमुख रूप से तालाब और मीलें आती हैं। कार्प (Carp) मर्झलियाँ बहुधा भारतीय समुद्रों में पोषत होती हैं। चूँकि यह बँधे हुये पानी में अंडे नहीं देतीं, इसीलिये उन्हें प्रतिवर्ष पोषित करने की आवश्कता होती है। यदि बँधे हुए पानी में कार्प मञ्जली के क्षत्रिम अग्रहोत्पादन (artificial spawning) को विकित्त कार्ती हैं या उन्हें मिक्य में खाने के लिए धूप में सुखा लिया जाता है या नमक में जमा लेते हैं। शेष ऐसी मर्झलियाँ जो खाने के योग्य नहीं रह जाती हैं उनकी खाद बना लेते हैं। मर्झली-उद्योग के द्वारा हमें मर्झलियाँ तो प्राप्त होती हैं, इसके अतिरिक्त सार्टीन (Sardines), शार्क लियर तेल (shark liver oil) जैशी अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं।

कृषि उत्पादन—मारतवर्ष में उष्ण कटिवन्य, अर्थ उप्ण कटिवन्य और समग्रीतोष्ण कटिवन्य में उत्पन्न होने वालो विविध प्रकार की फरलें उगाई जाती हैं। इन फरलों में खाद्यान और व्यवसायिक दोनों ही प्रकार की फरलें सम्मिलित हैं, किन्तु प्रमुख रूप से खाद्यान ही अधिक उगाए जाते हैं। उक्त कथन इसी वात से स्पष्ट हो जाता है कि खेती की जाने वालीकुल भूमि के द्रभ% भाग पर खायाज का ही उत्पादन किया जाता है।

हमारे यहाँ रवी श्रीर खरीक दो मुख्य फर्सले होती हैं। खरीक फर्सलों के श्रन्तर्गत मुख्यतः चावल, ज्यार, बाजरा, मक्का, कपास, गया श्रीर मूँगफर्ली मोहें जाती है श्रीर रवी फर्सलों में गेहूँ, जी, चना, मटर, श्रलसी श्रीर सरसों श्रादि की खेती की जाती है। "चायल की खेती गंगा की घाटी, पंजाब के पहाड़ी जिलों, उत्तर-प्रदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल, श्रासाम, पश्चिमी घाट श्रीर उदीसा व मद्रास के समुद्रतटीय भागों में होती है। पंजाब, पेप्स, उत्तर-प्रदेश व मध्य प्रदेश के श्रीपक्षांश भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। गवा गंगा के मैदान, मद्रास, मैस्र, उर्पाया, हैदराबाद श्रीर पंजाब में उगाया जाता है। मृंगकली, श्रलसी, श्रंही, तिल्लों, तिलहन श्रादि मद्रास के उत्तरी भागों में श्रीर कपास दिज्ञ पत्तेटों के उत्तरी-दिज्ञियों भागों व पंजाब में उगाई जाती है। चाय की खेती विशेष कर दार्जिनंग, श्रासाम श्रीर नीलगिरि की पहाड़ियों पर होती है। जूट प्रमुख रूप से बंगाल में पेदा होता है। कहना, चाय, रवड़, काली मिर्च श्रीर हलायची के पेद श्रश्नामजाई श्रीर कार्टमन (cardamom) की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। मालावार तट पर उगे नारियल के बने-पने वृज्ञों से गरी के गोले श्रोर रिस्तर्या बनाने के लिए जटाएँ प्राप्त होतां हैं। इन्हीं खेतों से देश मर के लिए काज़ की मौंग पूरी की जाती है।"

१६५१ की गणना के अनुसार इस देश का मीगोलिक चेत्रफल लगमग पर करोड़ २५ लाख एकड़ है, किंतु इसमें से केवल ६२ करोड़ ३५ लाख एकड़ भूमि ही गाँव के पुराने लेखों (record) में दर्ज मिलती है। इस चेत्रफल में से लगमग २६ करोड़ प्र. लाख एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। यदि इम इस चेत्रफल में उन चेत्रों के भी अनुमानित आँकड़े बोड़ लें जहाँ से कोई स्चना प्राप्त नहीं होती तो खेती की जाने वाली कुल भूमि लगमग ३४ करोड़ एकड़ हो

१. जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ हैं वहाँ सरीफ फसल जून में, नहीं तो फिर बरसात शुरू हो जाने पर जुलाई में थोई जाती है श्रीर जादे में काटी जाती है। रबी फसल बरसात समाप्त हो जाने पर अक्तूबर-नवम्बर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। गन्ना जनवरी-फरवरी में वोया जाता है और अगले जादे में शक्कर के कारखाने में पिराई होने के समय तक वैयार हो जाता। यह पिराई नवम्बर-दिसम्बर से प्रारंभ होता है। यद्यपि गन्ना रबी फसल समाप्त हो जाने पर वोया जाता है, फिर मी इसे खरीफ की फसलों के अन्तर्गत इसिलए शामिल किया जाता है कि इसका क्टाई खरीफ की फसलों के साथ ही होती है।

जायगी। १९५६-५७ में कुल श्रज की उपज ५७३ लाख टन हुई थी, जिसमें से चावल की उपज रद्धश्लाख टन, गेहूँ ६१ लाख टन, ज्वार श्रीर वाजार १०३ लाख टन श्रीर श्रन्य श्रज ६८ लाख टन थी। इसके श्राविरिक्त ११४ लाख टन दालें, चना श्रादि की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार १६५६-५७ में कुल श्रन्न की उपज ६८७ लाख टन हुई थी। इतना श्रज्य भारत की जनता को खिलाने के लिये पर्याप्त नहीं था श्रीर इसलिये विदेश के श्रन्न पर निर्भर रहना पड़ा। पर उचित व्यवस्था से खाद्यान्न के सम्बंध में देश के श्रात्म निर्मर हो सकने की सम्मावना है। श्रन्न के श्रविरिक्त खेती से श्रुनेक प्रकार के कब्चे माल की भी उपज होती है। १६५६-५७ में गन्ने की उपज ६५ लाख टन, जूट की ४२,५ लाख गाँठ, कई ४७,५ लाख गाँठ श्रीर तिलहन ६० लाख टन हुई थी। देश में जितना इन कब्चे मालों का उत्पादन होता है वह हमारी श्रावश्यकता के दृष्टिकोण से कम है। इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये काफी समय तक हमें श्रायात पर

पशु पालन-भारत में पशुत्रों की बहुत श्रिधकवा है। इनकी संख्या सैसार के पशुद्रों की संख्या (रूस के पशुद्रों को छोड़कर) का है है। १९५१ की पशु-गण्ना के श्रनुसार भारत में कुल २६ करोड़ २२ लाख ५० हजार पशु हैं जिनमें से १५ करोड़ ५० लाख गाय-बैल, ४ करोड़ ३२% लाख मैंंग-भैंसे, ३ करोड़ ६० लाख मेहें, ४ करोड़ ७० लाख वकरे-वकरियाँ, ४५ लाख से कुछ कम ग्रुत्र, १५ लाख वोहे, १२ लाख ५० हजार गमे, ६,२६,००० ऊँट श्रीर ६०,००० खन्नर हैं। इसके अतिरिक्त ६ करोड़ ७१ लाख ३० इनार मुर्गे-मुर्गियाँ अौर ६२ लाख ६० हजार बतर्खें हैं। किन्तु भारत के पशुश्रों की नस्त बहुत खराब है। यहाँ एक गाय श्रीसत से प्रतिवर्ष ४१३ पींड दूध देती है, जब कि दूसरे देशों की गाएँ प्रतिवर्ष २००० से ७००० पींड तक दूघ देती हैं। भारत में कुछ श्रच्छी नस्ल के भी पशु हैं, जैसे गुजरात की काँकरेज श्रीर सौराष्ट्र की गिरि गाएँ दूघ देने और अच्छे बछड़े उत्पन्न करने के लिए संसार की सर्वोत्तम नस्लों में गिनी जाती हैं। किन्तु बेकार व निकम्मे पशुश्रों की संख्या अपेचाकृत बहुत श्रिषिक है जो किसानों के लिए तनिक भी सहायक विद, नहीं होते हैं श्रीर उनके लिए भार-स्वरूप बनकर रहते हैं। भारत में विविध प्रकार के जंगली जीव श्रीर पन्नी भी पाय जाते हैं, किन्तु अभाग्यवश "हमारे यहाँ के शेर, गेंडा, चीता आदि प्रमुख जंगली जीवों की नरल समाप्त हो रही है। भारतीय जीवों को सरस्य देने, उनकी नरल को सुरिच्चत रखने श्रीर उन्हें प्राकृतिक व मानवीय वातावरण में सन्तुलित रखने के लिए भारत-सरकार ने अप्रैल, १९५२ में जंगली जीवों के लिए एक

कन्द्रीय बार्ट की स्थापना की"। पश्चियों व संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सिमात (National Committee for Bird Protection) मी बनाई गई है। यह आशा की जाती है कि इन संस्थाओं से मारतीय पश्चियों और जंगली जीवों का संरक्षण और विकास होगा।

खनिज-पदार्थ

किसी देश के श्रीशोगिक विकास के लिए उसकी खनिज सम्पत्ति का विशेष महत्व होता है। खनिज सम्पत्ति को निम्निलिखित वर्गों में गाँटा गया है:—(१) श्रायात खनिज (non-metallic minerals), (२) धात खनिज (metallic minerals) श्रीर (३) हेंघन (fuels)। श्रायात खनिज के श्रन्तर्गत श्रीममृत्तिका, सीलीमेनाहर, मेगनेसाहर, वालू, चूना श्रीर नमक श्रादि श्राते हैं। धात खनिज के श्रन्तर्गत सोना, चाँदी, जस्ता, राँगा, टिन, ताँगा, श्रादि श्राते हैं श्रीर ईंघनों के श्रन्तर्गत कोयला तथा पेट्रोलियम श्राते हैं।

मारत में कोयले, कच्चे लोहे, मेंगनीज, बौक्साइट छीर छवरक जैसे खानज पदायों की बहुतायत है; रिफ क्टरीज (refractories), एवे सिंच (abrasives), चूना छौर जिप्सम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं छौर अवरक, टिटानियम छीर कच्चा योरियम भी काफी वड़ी मात्रा में पाया जाता है। परन्तु दुर्भाख से तौंवा, दिन, सीसा, जस्ता, गिलट, कोवाल्ट, गंधक छौर पेट्रोल जैसे महत्वपूर्ण खिनजों की बहुत कमी है छोर इनके अभाव को पूरा करने के लिए हमें अधिकतर ख़ायात पर निर्मर करना पड़ता है।

"लानों की दृष्टि से सबसे श्रिधिक महत्वशाली माग छोटा नागपुर का पठार है, जिसे गोंडवाना भी कहते हैं, जिसमें दिख्या बिहार; दिख्या पश्चिमी वंगाल उत्तरी उड़ीसा श्राते हैं। कोयला, लोहा, श्रवरक श्रीर ताँवा श्रादि श्रिधिकांश हसी माग से मात होते हैं। कोयला विशेषकर करिया, रानीगंव के चेत्रों से निकाला जाता है पर बश्चश्रंगार (Ligmit) के रूप में दिख्या पूर्वी हैदराबाद, दिख्या मध्य प्रदेश श्रीर दिख्या पूर्वी मद्रास के समुद्री तट पर भी पाया जाता है। लोहा मैस्र में श्रीर अवरक उत्तरी मद्रास श्रीर राजस्थान में पाया जाता है। इस्मेनाहट श्रीर मोनेजाहट (Ilmenite and Monazite) जो युद्ध-कालीन महत्ता रखने वाली घातुर्ये हैं, ट्रावनकोर के तटीय प्रदेश की वालू में पायी जाती हैं। मेगनेसाहट मद्रास की खिड़िया मिट्टी वाली पहााइयों पर श्रीर सोना मैस्र के कोलार चेत्र में पाया जाता है। बीक्साइट स्टीटाइटजिप्सम इमारतों के बनाने में काम श्राने वाले पत्थर नमक, श्रिशिमृत्तिका, कोसन्हम फलर्स श्र्यां श्रादि भी पर्याप्त

मात्रा में यहाँ पाये जाते हैं। संसार भर की अवरक की उत्पत्ति का ६०% भारत में उत्पन्न होता है। मैंगनीज, इल्मेनाइट, मोनेजाइट, लोहा श्रादि संसर में समसे अधिक मारत में ही मिलते हैं। भारत की बातुओं की. पूर्णलप से काम में नहीं लाया गया है। देश में पेट्रोलियम की कमी है केवल आसाम में ही इसके कुयें हैं। इन इश्रों से प्राप्त अत्यक्ति बहुत ही नगयम है। इसी प्रकार श्रन्य धावुश्रों की जैसे रॉमा, मन्धक, चींदी, जस्ता, दिन, पारा श्रादि की उत्पत्ति देश की श्रावस्थकता से बहुत कम है।

श्रध्याय ३ जन संख्या

किसी देश के श्रार्थिक विकास का वहाँ की जनसंख्या से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की संख्या, उनका स्वास्थ्य, श्रवस्था स्त्रीश्रीर पुरुष की संख्या क श्रनुपात, जन्म श्रीर मृत्यु दर श्रीर देश में प्राप्त खिनज पदार्थों के सम्बन्ध में उनके उद्योग श्रादि सब उनकी स्थिति श्राधिक निश्चित करते हैं। यह एक नड़े विचानकी वात है कि मारतवर्ष जो कि संसार का सबसे श्रिष्ठिक घना वसा देश है सब गरीब भी है। इसलिये यहाँ की समस्या जन संख्या के वृद्धि की दर में कमी श्री प्राकृतिक साधनों के उपयोग में वृद्धि करने की है।

भारत की जनसंख्या १८६१ में २३ ५६ करोड़ थी; १६२१ में बढ़व २४ ८२ करोड़ हुई जो १६३१ में २७ ५५ करोड़, १६४१ में ३१ २८ करोड़ थ्रें १६५१ में ३५ ५६ करोड़ हो गई। १६२१ तक तो जनसंख्या की वृद्धि में थ्रका श्रीर बीमारियों द्वारा कमी होती रही श्रीर श्रन्न की उपज बढ़ती हुई जनसंख्या जिये पूरी पड़ती रही। परन्तु १६२१ के पश्चात जनसंख्या में श्रन्न की उपज विवास परिणाम यह हुश्रा कि दे को श्रन्न की कमी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। १६५१ की जनगण रिपोर्ट, १६२१ को महान विमाजक (The Great Divide) के नाम से व्य करती है, क्योंकि (१) इसके पहिले जनसंख्या न्यूनाधिक घटती हुई सी धी पर इस वर्ग के बाद से निरन्तर बढ़ती रही है, श्रीर (२) इस वर्ष के पहिले तक भें का प्रयोग भी जनसंख्या की वृद्धि के श्रनुक्ल ही बढ़ता रहा पर इसके बाद से श्रन्त कमी होती गई।

चृद्धि की दर-१६५१ तक के पिछले १० वर्षों में मारत की जनसंख् लगभग ४ १४ करोड़ के बढ़ गई है जो १२३% की वृद्धि कही जा सकती है अर्थ जिसे १५% प्रांतवर्ष की वृद्धि कह सकते हैं। यह वृद्धि विभिन्न मागों में विभिन्न गं से हुई है। पंजाब, अराउमान और नीकोवार टापुओं में ०५ प्रतिशत और इ प्रतिशत कमशः कमी हुई है। अन्य राज्यों में से दिल्ली (६२ १%), दुर्ग (३० ५५ त्रिपुरा (२१.६%), भैसूर (२१ २%), त्रिवंकुर कोचीन (२१ १%) और वर्ष

हस संख्या में जम्मू काश्मीर श्रीर श्रासाम के श्रादिवासियों की सं सम्मिलित नहीं है।

२. ८%) में सबसे अधिक वृद्धि हुई; हिमांचल प्रदेश (३'७%), पेप्सू (२'६%), विन्ध्य प्रदेश (६%), उड़ीसा (६'२%), भोपाल (७'२%), मध्य प्रदेश (७'६%) और विहार (६'६%) में वृद्धि की गति अपेन्नाकृत कम रही।

जन्म और मृत्यु दर — जन संख्या में वृद्धि श्रीर कमी जन्म श्रीर मृत्यु दर के श्रन्तर पर निमर होती है। इधर पिछले वर्षों में भारत की जन्म दर श्रीर मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है। जन्म दर जो कि १९३१ में ३५ प्रति हजार थी धट कर १६४१ में ३२ १ पति हजार, श्रीर १६५० में २४ प्रति हजार हो गई। मृत्यु दर जो कि १९३१ में २५ प्रति हजार हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन्म दर में मृत्यु दर की श्रपेका श्रीवक्त कमी हुई। चूँ कि जन्म श्रीर मृत्यु के श्राँकड़े विश्वस्त नहीं हैं इसलिए १९५१ की जनगणना रिपोर्ट ने यह श्रनुमान लगाय है कि १६४१ ५० के बीच के दस वर्षों में जन्म दर का श्रीसत ४० प्रति हजार श्रीर मृत्यु दर का श्रोसत करीब २७ प्रति हजार रहा है। इसलिये १३ प्रति हजार प्रति-वर्ष जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यह बड़े हुर्भाग्य की वात है कि हमारे देश में विश्वस्त श्राँकड़े श्रपाप्य हैं पर इम यह तो कह सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि की दर बढ़ती गई है।

जन्म दर में कमी विवाह की अवस्था बढ़ाने, आत्म संयम और गर्भ निरोध के कृतिम उपायों के अनुसार सम्मव हो सकती है। परन्तु जलरी तारुएय अवस्था को प्राप्त करने तथा आर्थिक अथवा अन्य कारणों से विवाह की अवस्था बढ़ाना उम्मव नहीं है। देर में विवाह करने की प्रथा पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रही है इतने रि भी उन लोगों में अभी भी विवाह की अवस्था कम ही है। आत्म-संयम बहुत हो कठिन है। उसके लिये पाय: हममें आत्मवल की कमी है जिसके कारण उसकी फिलता में सन्देह है। गर्भ निरोधक कृतिम उपकरणों का प्रयोग निम्न कारणों व विशेष प्रचलित नहीं हो सका है: (१) उनके विरुद्ध धार्मिक भावना, (२) उनका गिषक मूल्य, (३) जनता में उनके प्रयोग करने के ढंगों के प्रति अनिमञ्जता, ४) इस सम्बन्ध में परामर्श और शिक्षा देने वाले अस्पतालों की कमी। यदि किम उपायों का प्रयोग प्रचलित करना है तो हन कठिनाहयों को दूर करने के उपाय करना अत्यन्त आवश्यक होगा।

डा० स्टोन का सुरिक्ति काल प्रणाली ("Safe Period method") का योग भी सस्ता और सफाई की दृष्टि से उपयुक्त होते हुये भी अधिक लोकप्रिय हीं हो पाया है क्योंकि अधिकांश जनता इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग करना नहीं जानती।

यह दुर्माग्य की वात है कि जन साधारण (बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को सम्मिलित करते हुये) परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा उसके उपायों से अन्मिन्न हैं। वे सब बात भाग्य के भरोते छोड़ देते हैं। इसके कारण परिवार नियोजन का कार्य अपने देश में एक किटन समस्या के रूप में उपस्थित है। "प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्य के प्रति जनता में सिक्ष्य सहानुभृति की भावना जगाना ओर वर्तमान ज्ञान के आधार पर तत्सग्वन्धी परामर्श और स्वा के साधनों के विकास की ओर रहा है। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में भैषांक जैवकीय और संख्याओं को ११५ परिवार नियोजक श्रीपधालयों और १६ सांस्थकीय तथा जैवकीय समस्याओं के प्रति खोज करने वाली योजनाओं को अनुटानों द्वारा सहायता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में वृद्ध करने का विचार किया गया है"।

"यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रांत ५०,००० व्यक्तियों के लिए प्रत्येक नगर श्रीर कस्त्रों में एक श्रीषधालय खोला जाय। छोटे कस्त्रों श्रीर गाँवों में घीरे-घीरे प्रारम्भिक स्वास्थ्य संस्थाश्रों के सहयोग में श्रीषधालय खोले जायँ। इन श्रीषधालयों का कार्य जनता में इस समस्या के प्रति जागरकता उत्पन्न करना होगा श्रीर उन्हें इस सम्बन्ध में परामर्श श्रीर सेवा प्रदान करनी होगी। वंगलीर में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण विरुक्त लय (clinic) का खोला जाना विचाराधीन है। वस्त्रई में कृत्रिम उपायों का परीक्षालय स्थापित हो रहा है। प्रत्येक मैपलिक विद्याधियों श्रीर उपचारिकाश्रों को परिवार नियोजन की शिक्षा देना श्रावश्यक है प्रत्येक श्रीपधालय में परिवार नियोजन सेवा विमाग स्थापित होना चाहिये। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि मैपलिक जैवकीय तथा श्रीक हों से सम्बन्धित श्राव्येण संस्था स्थापित की जाय। ५ करोड़ रु० का प्रवन्ध परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिये निश्चत कर दिया गया है। यह श्राधा की जाती है कि हितीय पंचवर्णीय योजना के श्रान्त तक लगमग ३०० विरुज्ञालय नगरों में श्रीर २००० विरुज्ञालय गाँवों में स्थापित कर दिये जायँगे"।

मृत्युसंख्या की दर प्रात्येक वा दर शार्रायेक कारणों श्रीर वाता-वरण पर निर्भर करती है। शारीरिक दशा पींब्टिक तत्वों, त्वच्छता, चिकित्सा की मुनिधा इत्यादि पर निर्भर करती है। वातावरण की दशा बाढ़, श्रकाल, युद्ध इत्यादि पर निर्भर करती है। मृत्युसंख्या की दर प्रत्येक वर्ष भिन-भिन्न रही है परन्तु प्राप्त श्रांकड़ों के श्रनुसार मृत्युसंख्या की दर घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि चिकित्सा की सुनिधा बढ़ी है श्रीर सफाई की श्रोर श्रिषक ध्यान दिया जाने लगा है। यह आशा की जाती है कि मिन्छ्य में चिकित्सा की सुनिवा
में वृद्धिहोने के साथ-साथ मृत्युसंख्या की दर मी घटती जायगी। वहु मुखी योजनाओं
के पूरा हो जाने के बाद अकाल और बाद का जोर कम हो जायगा। भारत में
बच्चों की मृत्युसंख्या अधिक होने से मृत्युसंख्या की दर अधिक है। यह अनुमान
लगाया गया है कि कुल जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से १५ प्रतिशत एक
वर्ष की आयु होने से पहले ही मर जाते हैं। सरकारी तौर पर की गई गयाना के
अनुसार यह पता चना है कि हन बच्चों में से ५० प्रतिशत पैदा होने में एक
महीने के अन्दर मर जाते हैं और ६० प्रतिशत पहले सताह में ही मर जाते हैं।

मारत में प्रतिवर्ष अनेक बीमारियों जैसे हैजा, चेवक, प्लेग, ज्वर और हिसेन्ट्री इत्यादि से लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। हैजा, चेवक और प्लेग महा-मारियों हैं। सभी बीमारियों से कुल जितने लोगों की मृत्यु होती है उसका प्रश्मातिशत इन महामारियों के शिकार होते हैं। इससे प्रकट है कि महामारियों के कारण बहुत अधिक मृत्यु नहीं होती है। विभिन्न बीमारियों से होने वाली मृत्युओं के प्रज्य प्रतिशत का कारण अनेक प्रकार के ज्वर होते हैं। अस्पतालों की सुविधा बढ़ा कर, स्वास्थ्य-सुधार की योजना लागू कर, लोगों की बीमारियों के आक्रमण से बचने की शक्ति बढ़ाकर साथ ही लोगों को आत्मविश्वासी और माग्य पर कम निर्भर बनाकर मृत्युसंख्या की ऊँची दर के कारणों को दूर किया जा सकता है।

स्त्री-पुरुपों का अनुपात—मारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है परन्तु मद्राध, उड़ीसा, जिवांकुर कीचीन और कच्छ में यह स्थिति विपरीत है। इन राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। १६५१ की जन-गणना के अनुसार कच्छ में सबसे अधिक स्त्रियों हैं। यहाँ प्रति इनार पुरुषों के पीछे १०७६ स्त्रियों हैं। हुए स्थित के अनेक सामाजिक, धार्मिक और पुरुषों के पीछे द्वे कि स्त्रियों हैं। इस स्थित के अनेक सामाजिक, धार्मिक और (Biolgical). कारण हैं। प्राय: सभी वर्ग की जनता और विशेषकर हिन्दू समुदाय लड़की की अपेन्ना लड़के को अधिक चाहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि लड़कियों की उचित देख-रेख नहीं की जाती है और उनकी प्राय: सन्तु हो जाती है। धार्मिक मावना के अतिरिक्त इसका एक कारण यह है कि समाज में शिन्ना का प्रसार कम है और लोग समाज में स्त्री के महत्व को ठीक-ठीक नहीं समक्त पाते हैं। इससे प्राय: लड़कियों की विशेष देख-माल नहीं की जाती है। प्रसव के समय अनेक स्त्रियों की मृत्यु हो जाने से मी स्त्रियों की संख्या कम है।

श्रवस्था—भारत में वच्चे श्रीर नवयुवकों की जनसंख्या में प्रधानता है। १९५१ में १४ वर्ष तक के लोग ३८, ३५ से ५४ वर्ष तक के लोग ३३%, ३५ से ५४ वर्ष तक के लोग २०'४% श्रीर ५५ वर्ष के ऊपर के लोग केवल ८'२% थे। श्रन्य देशों में, जैसे फ्रान्स, इक्क्षीयड, जर्मनी, उत्तरी श्रमरीका श्रादि में, स्थिति इसके विपरीत है। इन देशों में ५५ वर्ष श्रीर इसके ऊपर की श्रवस्था वाले व्यक्ति कुल जनसंख्या के क्रमशः २१'४%, २१'१%, १९'१% श्रीर १६'६% हैं।

धनत्व और वितर्ग-मारत में औरत जनसंख्या का धनत्व ३१२ प्रति वर्ग मील है। घनत्व की मात्रा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदलती हुई है। एक श्रोर दिल्ली में २०१७, ट्रावन्कोर कोचीन में २०१५ प्रति वर्ग मील है तो दूसरी श्रोर श्रगडमान निकोवार में २०, श्रीर कच्छ में ३४ पात वर्ग मील है। इस बदलते हुये धनत्य का कारण प्राकृतिक बनावट, भूमि तथा वर्षा है। इन कारणों पर ही भूमि के उचित प्रयोग की मात्रा निर्मर है। इसांलये घनत्व की समस्या का अध्ययन प्राकृतिक भागों के आघार पर अधिक युक्तिसंगत होगा। इस दृष्टिकोण सिन्यगंगा के मैदान के निचले भाग में घनत्व ८३२ श्रीर कपर के भाग में घनत्व ६८१, मालावार कोकन में ६३८, दिक्णी मद्रास में ५५४, उत्तरी मद्रास श्रीर उड़ीसा के समुद्री तट पर ४६१ है। ये भाग बहुत अधिक धनत्व वाले कहे जा सकते हैं। दक्षिणी भाग में, टक्सी भाग में, गुजरात काठियावाड़ में, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व साधारण कोटि का है, प्रतिवर्ग मील में क्रमशः ३३२, २४७, २४६ श्रीर २२६ व्यक्ति निवास करते हैं। दक्षिणी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में. उत्तरी केन्द्रीय पहाड़ियों में, पूर्वी पठार में, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों में, हिमालय, पश्चिमी हिमाखय त्रीर रेगिस्तानी भागों में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः १६२. १६४, १६३, ११८ ६८ और ६१ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। जनसंख्या के इस श्रसमान नितरण के कारण प्रत्येक स्थान पर प्राप्त प्राकृतिक सुविधाश्चों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाया है।

भृमि के प्रयोग सम्बन्धी आँकड़ों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि (अ) योरुप नहीं संसार मर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है भारत की तुलना में अधिक आगे नहीं है। श्रीसत भारतीय अपनी भृमि का ४३% खेती के काम लाता है जब कि श्रीसत योरुपीय केवल ६० प्रांतशत ही काम में लाता है। (ब) संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के व्याक्तियों के पास योरुप निवासियों और भारतीयों की अपेचा अधिक भृमि है। भारत में भूमि पर जनसंख्या के भार का कुछ अनुमान इस बात से लगता है कि बोये हुये खेतों में जनसंख्या के प्रांत व्यक्ति का औरत ०.८२ एकड़ है।

यदि कटिबन्धों के दृष्टिकोगा से जनसंख्या के वितरण पर विचार किया नाय तो इम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ' ६ - ३२ करोड़ श्रयवा कुल ननसंख्या का १८% है। पूर्वी भारत की (जिसमें विहार, उदीसा, पिन्छमी बंगाल, श्रासाम, मनोपुर, त्रिपुरा और सिकिम श्राते हैं) जन-संख्या ६ करोड़ या कुल जनसंख्या का २५% है। दिल्ला भारत (जिससे मद्रास, मैसर, ट्रावनकोर कोचीन श्रीर कुर्ग श्राते हैं) की जनसंख्या ७५६ करोड़ या कुल जनसंख्या की २१% है। पञ्छिमी मारत की जनसंख्या जिसमें बम्बई, सीराष्ट्र श्लीर कच्छ त्राते हैं ४.०७ करोड़ या ११% है। मध्यभारत की जनसंख्या जिसके श्रम्त-र्गत मध्यभारतः हैदराबाद, भोपाल श्रीर विन्ध्य प्रदेश श्राते हैं ५ २३ करोड़ या १५% है। उत्तरी पश्चिमी मारत की जनसंख्या जिसके अन्तर्गत राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, नम्मू और काश्मीर (आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं), अनमेर दिल्ली, विलासपुर, और हिमालय प्रदेश त्राते हैं, ३५ करोड़ या १०% है। यदि भूमागों के दृष्टिकी स विचार किया जाय तो इम कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान की जनसंख्या ३६ । १%, पायद्वीप पहाड़ियों और दिल्ला पठार की जनसंख्या ३० ४%, पूर्वी घाट श्रीर समुद्री तट की जनसंख्या १४°५%, पश्चिमी घाट श्रौर समुद्री तट की जनसंख्या ११'२%, हिमालय के 'भूभाग की जनसंख्या ४'=% है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि देश के उपजाऊ मैदानों में श्रिधकांश जनसंख्या बसी हुई है।

मध्यप्रदेश का च्रेत्रफल सबसे श्रिषक है, अर्थात् १३०२७२ वर्ग मील, तथा इसके पश्चात् राजस्थान है जिसका च्रेत्रफल १३०२०७ वर्ग मील है, जबकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे श्रिषक श्र्यात् ६ ३ करोड़ है श्रीर इसके पश्चात् मद्रास, बिहार, श्रीर बम्बई हैं जिनकी जनसंख्या कमशः ५,७, ४ तथा ३ ५६ करोड़ है। विध्य प्रदेश तथा दिल्ली के श्रितिरक्त जिनकी जनसंख्या कमसः ३५,७ लाख तथा १७.४ लाख है—किसी भी।स श्रीर द राज्य की जनसंख्या १० लाख से श्रिषक नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश श्रयहमन श्रीर निकोवार द्वीप है जिसकी जनसंख्या केवल ३०६७१ है। मारत की श्रिषकतर जनता गांवों में निवास करती है। ३५ ७ करोड़ की कुल जनसंख्या में से केवल ६ २ करोड़ श्रयवा १७.३% नगरों श्रीर कस्कों में (जिनकी संख्या ३०१८ है) रहती है श्रीर श्रेष २६ ५ करोड़ या ८२ ७% जनसंख्या गाँवों में रहती है जिनकी संख्या ५५८८ है। देश के श्रीद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप गाँवों की जनसंख्या निरन्तर नगरों की श्रोर बढ़ती जा रही है। १६२१ में ८८,७% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी श्रीर ११.२% नगरों में १६४१ में ८६ १% गाँवों में श्रीर १३ ६% नगरों में निवास करती थी श्रीर ११.२% नगरों में १६४१ में ८५ अपरा वताया जा

चुका है, ⊏२'७% गाँवों में और १७'३% नगरों में रहने लगी। दिल्ली श्रीर श्रज-मेर के छोटे राज्यों को छोड़कर जहाँ कि शहर की श्रावादी क्रमशः ⊏३% श्रीर ४३% है, बड़े राज्यों में वमवई श्रीर सीराष्ट्र के राज्य सबसे श्राधुनिक हैं जहाँ ३४% श्रीर ३१% जनसंख्या नगरों में रहती है।

भारत के ७३ शहरों की आवादी एक लाख के जगर है। आसाम और पेप्स में ऐसा कोइ नगर नहीं है। 'स' राज्यों के सात भागों केवल नई दिल्ली अजमेर और भूपाल ऐसे नगर हैं। देश के सबसे बड़े नगरों में अम्बई की जनसंख्या रूट-३५ लाख, है, कलकत्ता की २५ ४६ लाख, मद्रास की १४ १६ लाख, हैदराबाद की १० ८६ लाख, दिल्ली की ६ १९५ लाख, अहमदाबाद की ७ ८८ लाख, और बंगलीर की ७.७६ लाख है।

धर्म स्रोर विवाह— भारत में श्रनेक धर्मों के मानने वाले रहते हैं पर हिन्दुश्रों की संख्या प्रधान है। १९५१ में ३५.७ करोड़ की श्रावादी में से ३०.३ करोड़ हिन्दू थे, ३.५ करोड़ मुसलमान,८२ लाख ईसाई, ६२ लाख सिक्ख, १६ लाख जैन, २ लाख बीद १ लाख जोराष्ट्रियन (पारसी), १७ लाख श्रधिवासियों के धर्मावलम्बी तथा १ लाख श्रन्य धर्मों के पालन करने थाले थे।

मारत में प्रति १०, ००० व्यक्तियों (शरण्यियों को छोड़ कर) में ५१३३ पुरुष तथा ४८६७ छी हैं। इनमें २५२१ पुरुष व १८८६ छियाँ अविवाहित हैं। अर्थात् छियो और पुरुषों को मिलाकर कुल जनसंख्या ४४°१% अविवाहित हैं। बाल विवाह रोक कानून के होते हुए भी देश में अत्यिषक बाल-विवाह होते हैं। १९५१ की जन गणना के अनुसार लगभग २८३३००० पुरुष' ६११८००० विवाहित छियाँ, ६६००० विधुर और १३४००० विध्वाय ५ और १४ वपं की अवस्था के बीच की थीं। इसी रिपोर्ट के अनुसार लगभग ६२०००००० विवाह बाल विवाह निरोधक नियम के पृतिकृल हुये थे।

व्यवसाय—देश भर के ४००% व्यक्ति कृषि पर श्रीर ३०% श्रन्य व्यवसायों पर निर्मर रहते हैं। सीराष्ट्र, कच्छ, श्रजमेर दिल्ली श्रन्डमान, नीकोबार में खेती करने वालों की संख्या की तुलना में श्रन्थप्रकार के व्यवसाययों की संख्या श्रिक है। पिश्चमी वंगाल श्रीर वम्बई प्रदेशों में जो सबसे श्रिक श्रीग्रोगिक प्रदेश हैं वहाँ मो खेती करने वालों की संख्या व्यवसायियों से बढ़ी हुई है। हिमाञ्चल प्रदेश श्रीर सिकिम में कृषि करने वालों की संख्या कुल श्रावादी की ६०% है। प्रत्येक १०० भारतवासियों में ४७ तो ऐसे किसान हैं जिनके पास अपने खेत हैं, ६ श्रासामी हैं, १३ बिना भूमि के श्रीक हैं, १ जमीन्दार है श्रयवा लगान पर श्राश्रित है श्रीर १० उद्योगों में लगे हुए हैं श्रथवा कृषि के श्रतिरिक्त श्रन्य कार्य करते हैं,

६ व्यापार करते हैं, २ यातायात में लगे हैं और १२ विभिन्न प्रकार की नौकरियों में लगे हैं। १६५१ की जनगणना के अनुसार ३५% व्यक्तियों में ते २४% करोड़ किसान और १०% करोड़ खेती के अतिरिक्त अन्य कार्य करने वाले लोग थे। २४% करोड़ किसानों में से १६% करोड़ अपने निजी खेतों पर खेती करने वाले थे। ३९६ करोड़ ऐसे किसान थे जो दूसरों के खेत करने वाले थे, ४८४ करोड़ कृषि कार्य करने वाले मजदूर थे और ० ५३ करोड़ खेती करने वाले बी, ४८४ करोड़ कृषि कार्य करने वाले मजदूर थे और ० ५३ करोड़ खेती करने वाले जमीदार या लगान पर आश्रित व्यक्ति थे। १०% करोड़ अन्य कार्यों में लगे वे, २०१३ करोड़ व्यापार में लगे थे, ० ५६ करोड़ यातायात में लगे थे और ४७३ करोड़ विभिन्न नौकरियों में लगे थे।

श्रध्याय ४

सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ

सामाजिक श्रीर धार्मिक व्यवस्था श्रीं का जनता के श्राधिक जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। यह भीविक सुख-समृद्धि श्रीर सम्पत्ति के संग्रह के प्रांत जनता के दृष्टिकोण को, साथ ही इन उद्देश्यों की पुर्ति के लिए जनता के प्रयक्षों की निर्धारित करती हैं। यह व्यवस्थाएँ श्रीद्योगिक श्रीर वाणिव्य संगठनों को प्रभावित करती हैं साघ ही व्यापार श्रीर उद्योग का किस प्रकार संगठन किया जाना चाहिये इस पर भी इन व्यवस्थाओं का प्रमान पड़ता है। भारत में जाति प्रणाली श्रीर चंयुक्त परि-वार की प्रयाशों का भी देश के आर्थिक संगठन पर काफी प्रभाव पड़ा है; पर्दा-प्रया. श्रहिसा पर विश्वास श्रीर धर्म के प्रति सामान्य जनता के दृष्टिकोण ने उनकी श्रायिक-गतिविधि को निर्धारित एवम् संचालित किया है १०पर्दा-प्रया के कारण उच-जाति की महिलाएँ देश के भ्रार्थिक-कार्य में भाग नहीं लेती हैं श्रीर इस 🗩 प्रकार जनता को निधन रखने में यह प्रया सहायक सिद्ध होती है ता अहिंसा के 🖰 दृष्टिकी जूरीर इस घार्मिक मावना से कि बन्दर ज्रीर नील-गाय (जो बास्तव में गाय नहीं है) पवित्र हैं इनको नप्ट नहीं किया जा सकता। इससे फसल तथा अन्य मुल्यवान सम्पत्ति की मारी इति होती है(अ) वार्मिक संस्थार्थ्यों को जैसे मन्दिरी, मठी श्रीर श्रावाहीं को जनता जो दान देती है उससे इन संस्थाश्री ने बहुत श्राधिक मात्रा में सम्पत्ति का संग्रह कर लिया है निसका परिणाम यह होता कि (१) इन संस्थाओं की चलाने वाल पुजारी पाएँड तया अन्य लोग आलंसी हो जाते हैं श्रीर वेकार पड़े रहते हैं श्रीर इस पकार देश उनके श्रम का लाम उठाने से वंचित रह जाता है; (२) इस प्रकार जो धन इकटा होता है वह विजोरियों में बन्द रखा जाता है श्रीर देश के श्राधिक विकास के कार्य में इसका उपयोग नहीं होता है। विश्व के श्रन्य उन्नत देशों में जनता द्वारा की गई बचत काफी पहिले देश के श्रीद्योगिक तथा कृपि विकास के लिए उपलब्ध हो गई श्रीर पूंजी-निर्माण की प्रति-किया को प्रोतसाहन मिला। परन्तु मारत में धार्मिक संगठनों के प्रमुख श्रीर शास्त्रों के इस आदेश से कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कमाई का कुछ श्रंश इन संस्पाश्रों को दान देना चाहिए श्रोर साथ ही मन्दिरों श्रीर मठों के प्रति जनता की गहरी थदा होने से देश में पूंजी-निर्माण का कार्य बहुत शिथिल पड़ गया।-देश के उत्तराधिकार कानूनों से भूमि तथा श्रन्य प्रकार की सम्पत्ति का श्रन् नित रूप में छोटे-छोटे हिस्सों में विमाजन होता गया है। यदि भारत में सामाजिक श्रीर धार्मिक व्यवस्थाएँ मिल्र मकार होतों तो देश की आर्थिक प्रगति भी मिल्र प्रकार की होती।

जातिप्रया-जाति प्रया हमारे देश की प्राचीनतम प्रयाद्यों में से है। एक परिभाषा के अनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक ऐसा संग्रह है जिसका एक नाम है, जो उसके श्रन्तर्गंत श्रानेवाले लोगों के व्यवसाय सम्बन्धित होता है और इस नाम से ही उसके अन्तर्गत श्रानेवाले लोगों का व्यवसाय से मालूम हो जाता है। इसके साथ ही यह दावा किया जाता है कि किसी पीराणिक मानव या देवता से इसका वंश चला है: इसके अन्तर्गत आनेवाले लोगों का एक पेशा है. श्रीर राय प्रकट करने के श्रधिकारी न्यक्ति इसे एक ही समुदाय समकते हैं जिसमें समानता है। हमें यह मालूम नहीं है कि जाति प्रणाली का विकास कैसे हुआ। जाति प्रया संभवत: श्रम-विभाजन श्रीर विशेषशता के सिद्धांत पर श्राधारित रही होगी। प्राचीनकाल में हिन्दु समाज चार भागों में विभक्त था, अर्थात ब्राह्मण जो श्राध्यामिक नेता, विद्वान ख्रीर पुजारी होते ये, ज्ञिय जो योदा श्रीर प्रशासक थे, वैश्य जो ज्यापारी और सौदागर थे, और शुद्ध जो निम्नकोटि के कार्य करते थे, श्रन्य लोगों की सेवा करते थे-इन श्रन्य लोगों में श्रधिकार प्रथम तीनों वर्ग के लोग ही होते थे। इस चार जातियों की प्रणाली में हमें कार्य का त्रिमाजन स्वष्ट मालूम होता है। साथ ही यह प्रयत्न भी प्रकट होता है कि विभिन्न लोग विभिन्न कायों में दच्चता प्राप्त करें । श्रारंभ में जाति प्रणाली वंशगत या पुरावैनी नहीं थी श्रीर एक जाति का न्यक्ति श्रयने प्रयक्तों के बल पर श्रपनी जाति से उच्च जाति में प्रवेश पा सकता था। परन्तु बाद में जाति प्रया अत्यन्त कट्टर रूप धारण कर गई श्रीर निश्चित रूप वंशगत हो गई। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक उपजातियाँ श्रीर इन उपजातियां के भी श्रानेक निम्न-रूपों को जन्म दिया गया जिससे यह सारी व्यवस्था श्रत्यन्त जटिल हो गई।

स्रारम्म में जाति-प्रणाली से कुछ लाम थे: (१) इस व्यवस्था से किसी कार्य में श्रीर ज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त की जा सकती थी जिससे जो कुछ कार्य किया जाता था उसके गुण में बहुत सुधार होता जाता था। प्रायः वेटा वही व्यवसाय स्राप्त था जो उसका बाप करता था श्रीर इस व्यवसाय के लिए बाप उसे उचित शिक्षा दे देता था। इस प्रकार एक विशेष प्रकार का कार्य-श्रीर तत्सम्बन्धी शान एक परिवार में वंशगत रूप से चला श्राता था श्रीर वेटा बाप से उस व्यवसाय की योग्यता प्राप्त कर कार्य श्रागे बद्दाता था। पण्डितों की सुप्रसिक्त विद्वत्ता, भारतीय यीद्वार्शी की श्रपूर्व सफलताएँ श्रीर उचकोटि की मारतीय दस्त-कारी सभी श्राशिक रूप से इस विशेष योग्यता के ही फल थे जो स्वयं इसी जाति-प्रणाली का परिणाम था; (२) जाति-प्रणाली से उन कष्टमय तथा परेशानियों के दिनों में जब कि भारत पर विजातियों ने इमले किये थे हिन्दू-जाति की शुद्धता की

वनाये रखने में बहुत सहायता मिली। जाति-प्रणाली की कट्टरता के फलस्वरूप ही विजेताओं और विजितों के बीच श्रावश्यकता से अधिक रक्त-सम्बन्ध नहीं हो पाया इसमें काफी रुकावट पड़ी; और (३) जाति-प्रणाली ने श्रारम्भ से ही हिन्दुश्रों को श्रन्य लोगों के विश्वासों श्रीर धर्मों के प्रति सहिष्णु वने रहने का पाठ सिखाया है। इसी कारण विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग भारत में शांति और भाई चारे के साथ रहते श्राये हैं इसमें तिनक भी श्रसत्य नहीं है कि श्रारम्भ में भारत में जाति प्रणाली ने प्रायः उसी उद्देश्य की पूर्ति की जिसकी यूरोंप में गिल्ड-प्रणाली (Guild System) ने की जिसके श्रन्तर्गत गिल्ड के सदस्यों को टैक्निकल शिचा दी जाती थी श्रार उनके श्रन्य हितों की देखमाल की जातो थी।

परन्तु श्राव्यनिक काल में जाति प्रगाली श्रश्यन्त जांटल श्रीर श्रपरिवर्तन-शील हो गई है: उसमें एक प्रकार की कटरता आ गई है और फलस्वरूप इससे देश की आर्थिक प्रगति में सहायता मिलने की अपेका हानि ही अधिक हुई है। जाति प्रणाली के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि: (१) यह त्रावश्यक नहीं है कि वैश्य का पुत्र अच्छा व्यापारी हो श्रीर ब्राह्मण का पुत्र अच्छा पुजारी हो। यह विल्कुल समय है कि ब्राह्मण या वैश्य के पुत्र में ऐसी योग्यता है कि वह ग्रत्यन्त कुशल मोची वन सके। परन्तु जाति प्रया उच जाति के लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती है जो कार्य छोटी जावियो को सौंपे गये हैं। इसी प्रकार यदि कोई शुद्र बहुत शिक्षित श्रीर विद्वान भले हो परन्तु वह किसी मन्दिर का पुजारी नहीं वन सकता। यह जाति प्रथा ही उसके मार्ग में सबसे वड़ी वाघा वन जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा किसी व्यक्तिको ऐसे उत्तम कार्य करने से रोकती है जिसकी उसमें पर्याप्त ज्ञमता श्रीर योग्यता हो । (२) श्रस्प्र्यता श्रीर इससे उद्भुत श्रन्य कठिनाइयों के कारण जाति-प्रया जनता के चरल-स्वाभाविक प्रवाह में बाधक वन जाती है। किसी देश के श्राधिक विकास के लिए पूंजी श्रीर श्रम की निर्नाध गति-शीलता श्रत्यन्त श्रावश्यक होती है। जाति प्रथा ने इसको रोक रखा है श्रीर इस चीमा तक हमारे देश में ऋौद्योगिक तथा कृषि क्रांतियों का अमाव रहा है। (३) कष्टर जाति प्रथा के कारण हम अम-सम्मान (dignity of labour) को भूल गये हैं श्रीर इससे श्रन्य लोगों के विश्वासों, घर्मों श्रीर दृष्टिकोणों के प्रति इमारी सिंहभगुता की मावना भी कम हो गई है। इसीलिए इससे गतिरोध उत्पन हो गया है, इमारा समाज श्रस्थिर हो गया है श्रोर इममें स्वयं श्रागे बढ़कर पथ पदर्शन करने तथा साहस की मावना लुप्त हों गई है।

सीमाग्य से गत कुछ वपों से जाति-प्रथा ट्रंट रही है। मारत में रेलों के निर्माण, इसके प्रसार, यात्रा की सुविधायों में वृद्धि, रेल, वस या इवाई नहाज की यात्रा में विभिन्न जाति के लोगों से होने वाले श्रनिवार्य जन-अम्पर्क के फलस्वरूप जाति-प्रणाली की कट्टरता कम हो गई। श्रंग्रेजी शिचा प्रणाली श्रीर श्रंग्रेजी कानून के श्रन्तर्गत सभी जातियों के साथ समानता का व्यवहार किया गया और सभी जातियों के लोगों को कोई भी व्यवसाय अपनाने की छूट दे दी गई। पेशा श्रपनाने में जाति-प्रया की बाधा नहीं रही। शुद्र जाति के व्यक्ति श्रध्यापक, मजिस्ट्रेट श्रीर उच्च सैन्याधिकारी बने श्रीर उच्च जाति के लोग जिन्हें श्रपना कार्य िख करना होता था इन श्रिषकारियों के सम्पर्क में श्राये श्रीर जाति प्रथा की कहरता का पालन नहीं कर सके। जाति-प्रथा के कारण ही अनेक हिन्दुओं ने श्चन्य घमों को स्वींकार कर लिया। इसकी स्वयं हिन्दू-संमुदाय में प्रतिक्रिया हुई श्रीर अर्थ-समाज जैसे सुघारवादी आन्दोलन हुए जिन्होंने जाति-प्रथा को तोड़ने में बहुत बड़ा कार्य किया है। मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके विरुद्ध संघर्ष करती रही हैं श्रीर भारतीय संविधान में श्रस्पृश्यता को भारी श्रपराध माना गया है श्रीर अब परिगण्ति जाति के विद्यार्थियों को विशेष छ।त्रवृत्ति देने की नीति अपना रही हैं। इन सब प्रयत्नों से जाति-प्रथा की कट्टरता कम हो गई है छीर भारत के आधुनिक नौजवान इसकी अधिक परवाह नहीं करते हैं। कुछ लोग या वह लोग जो अभी अपने गाँवों या कस्त्रों की सीमा से अपने की मुक्त नहीं कर सके हैं श्रीर जिनका दृष्टिकोण अभी भी संकुचित बना हुआ है, अब भी इस जाति-प्रया की कटरता की भावना से ग्रस्त हैं परन्तु इनकी संख्या धीरे-घीरे घटती जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि जाति-प्रथा समाप्त होती जा रही है परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अपन भी लाति-प्रथा का जोर है और भारतीय आर्थिक मणाली को उससे बरावर चति हो रही है।

संयुक्त परिवार की प्रथा (Joint Family System)— धंयुक्त परिवार प्रथा भारत की प्राचीनतम प्रथाओं में से एक है। देश में सामान्यतः श्रायिक इकाई एक व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। बहुत से व्यक्तियों ने संयुक्त परिवार से श्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है और वह श्रलग रहने लगे है परन्तु फिर भी परिवार संगठन में संयुक्त-परिवार प्रथा की पूर्ण प्रधानता है। संयुक्त परिवार में सामान्यतया पिता परिवार का प्रधान होता है श्रीर परिवार के श्रन्य पुरुष तथा स्त्रियाँ उसके श्राधीन होते हैं। वह साथ रहते हैं साथ खाते-पीते हैं श्रीर पूजा-पाठ करते हैं, साथ ही समाज में सबके समान सम्बन्ध होते हैं। यह ठीक कहा गया है कि छोटे पैमाने में संयुक्त-परिवार साम्यवाद का उदाहरण है। यद संयुक्त परिवार का उचित संगठन किया जाय

त्तो वहाँ यह सिद्धान्त लागृ होता है कि "प्रत्येक सदस्य सब के लिए स्त्रीर सारा परिवार प्रत्येक के लिए" (each for all and all for each) श्रयांत प्रत्येक व्यक्ति पूरे समृद्द के लिए उत्तरदायी है श्रीर पूरा समृद्द प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त-परिवार प्रथा के कुछ ग्रार्थिक लाम हैं--(१) इससे रहन-सहन का ज्यय घट जाता है क्योंकि खाना साथ पकाया जाता है, नीकर चाकर समान होते हैं ग्रीर ग्रन्य सभी सुविधार्थों का संयुक्त रूप से उपमीग किया जाता है। बड़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सभी सुविधाएँ इसमें निहित हैं। यदि लोग श्रलग-श्रलग रहते हैं तो रहन-सहन का कुल व्यय परिवार के व्यय से बहुत अधिक होगा; (२) इससे सम्पत्ति और भृमि का छोटे-छोटे भागों में विभा-जन नहीं होता, भूमि पर मिलकर खेती की जाती है जिससे श्रार्थिक चेत्र में श्रनेक लाम होते हैं श्रीर श्रन्य रूपों में भी काफी लाम होता है। एंयुक्त परिवार की पूँजी विखरी हुई नहीं होती विलक एक साय जमा रहती है और उसको अन्य उत्पादन कार्यों में या ज्यागामी उत्पादन कार्य का प्रसार करने में प्रयक्त किया जा सकता है। परन्तु यदि संयुक्त परिवार ट्टर जाय और लोग अलग-अलग रहने लगे तो यह संमव है कि उनके पास पर्याप्त पूँजी न हो; और (३) संयुक्त परिवार प्रया वीमारी, मृत्यु या श्रन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाश्चों के श्रवसर पर एक प्रकार से वीमा का कार्य करती है। विघवाश्रों, श्रनायों श्रीर वृद्धों का संयुक्त परिवार में श्रन्य सदस्यों की तरह ही पालन-पोपण होता है। गत कुछ वर्षों से पश्मि। देशों में वृद व्यक्तियों को, जो कार्य नहीं कर सकते श्रीर निर्धन हैं, उनकी सन्तानों ने उन्हें विना किसी सहारे के छोड़ देने की प्रकृति हो गई है। संयुक्त पिरवार प्रथा के अन्तर्गत ऐसा संमव नहीं है।

परन्तु चंद्रक परिवार-प्रणाली की अनेक हानियाँ मी हैं: (१) चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को मोजन, कपड़े, रहने आदि की पूरी सुविधा उपलब्ध है इसलिए उन लोगों में जो चिरत्र की हिंहर से अब्छे नहीं कहे जा सकते हैं और जिनमें दूर हिंछ का अभाव होता है श्रालस्य पैदा हो जाता है। इन प्रथा से उनके आलिसी स्वभाव को वल प्राप्त होता है। साम्यवाद के अन्तर्गत चूंकि सुगतान कार्य के आधार पर नहीं विक्त आवश्यकता के आधार पर किया जायगा अतएव तब यह कठिनाई उत्पत्र हो जायगी कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी स्वभता के अनुकूल उत्तम कार्य कैसे कराया जाय। इसी प्रकार संयुक्त-परिवार-प्रणाली में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की उसके द्वारा किये गये कार्य की गणाना किये विना ही पूर्ति हो जाती है इससे कुछ लोगों में निठल्ले वैठे रहने और आलिसी वन जाने की प्रकृति पैदा हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि रुपये का मूल्य वही व्यक्ति अव्हीं प्रकार सम

मता है जो दपया कमाता है। इसिलए संयुक्त परिवार में श्रालसी श्रीर निठल्ले लोगों के फिजूल-वर्च बनने की पूरी संभावना रहती है; (२) संयुक्त परिवार प्रयाली के श्रन्तर्गत लोगों की गतिशीलता का हास हो जाता है श्रीर परियाम स्वरूप उनमें श्रागे बहुकर कोई कार्य करने की प्रवृत्ति का भी हास हो जाता है। लोगों को घर में बैठे रहने की श्रादत पह जाती है श्रीर फलस्वरूप साहसपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति से हाथ धा बैठते हैं, उनमें वह स्फूर्ति, सिक्रयता श्रीर साहस नहीं रहता जो देश की श्रार्थिक उलित के लिये श्रावश्यक होता है; श्रीर (३) संयुक्त परिवार में छोटे-छोटे मगड़े पैदा होते रहते हैं, ईंप्या-द्वेष बढ़ता है श्रीर इसके फलस्वरूप मुकदमें बाजी भी हो जाती है जो कि श्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती है।

इधर कुछ वर्षों से संयुक्त परिवार प्रथा विशृंखलित हो रही है। यद्यपि श्रभी भी यह परिवार-संगठन का प्रधान रूप है किर भी संयुक्त परिवार त्याग कर श्रलग रहने वाली की संख्या बढ़ रही है। (१) शिज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात युवक शहरी जीवन का श्रम्यस्त हो जाता है श्रौर किसी कारखाने में नौकरी कर लेता है या है शहर में व्यापार कार्य में लग जाता है श्रीर उसे संयुक्त परिवार से प्टयक होकर रहना प€ता है; (२) जीवन-संवर्ष में वृद्धि होने से श्रीर जीवन-निर्वाह के साधनों को जुटाने की कठिनाइयों से ब्यक्ति संयुक्त परिवार के बन्धन से मुक्त होना चाहता है। अपनी पत्नी अपैर बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त रुपया कमा लेना संयुक्त-परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त रुपया कमा लेने ्से कहीं अधिक अरल होता है; (३) जहाँ तक धनवान व्यक्तियों का प्रश्न है श्राय कर कानून श्रीर हाल ही में सम्पत्ति कर (estate duty) कानून बन जाने से संयुक्त-परिवार प्रया टूटने लगी है। यदि संयुक्त-परिवार के कमाने वाले सदस्यों की भ्राय आयकर के लिये निर्घारित न्यूनतम आय से कम है तो वह संयुक्त-परिवार से अलग होकर आयकर के वोक से बच सकते हैं परन्तु यदि साथ रहें तो सभी को आय जोड़ कर इतनी हो सकती है कि आयकर से मुक्ति न मिल सके। उदाहरण के लिये यदि एक परिवार में चार पुरुष हैं झीर वह कुल ९ हजार रुपया प्रति वर्ष कमाते हैं तो उनको श्राय-कर देना पड़ेगा क्योंकि कानून के अनुसार हिन्दू-संयुक्त परिवार की ८४०० रुपया वार्षिक आय से अधिक आय पर आय-कर देना पड़ता है। परन्तु यदि चारों व्यक्ति संयुक्त-परिवार से सम्बन्ध विच्छेदकर लें और अलग-अलग रहने लगें तो प्रत्येक चार हजार रुपया वार्षिक कमा सकता है श्रीर उसे श्राय-कर भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि कानून के श्रनु-सार व्यक्तिगत ब्राय ४२०० रूपया वार्षिक होने पर ही आय-कर लगेगा। इसी प्रकार सम्पत्ति-कर कानून के अन्तर्गत व्यक्ति गत रूप से एक लाख की सम्पक्ति पर आय-कर की छूटमात है परन्तु संयुक्त-परिवार में प्रत्येक पुरुष सदस्य को केवल ५० हजार रुपये की सम्पत्ति पर ही सम्पत्ति-कर से छूट मात है, इसते अधिक की सम्पत्ति होने पर कर चुकाना पड़ेगा परन्तु यदि वह संयुक्त-परिवार से अज्ञग हो जायें तो एक लाख रुपये को सम्पत्ति पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त किसी की मृत्यु हो जाने पर यह संभव है कि संयुक्त-परिवार को सम्पत्ति कर चुकाना पड़े जब कि प्रयक रहने पर ऐसा होना इतना अधिक सम्भव नहीं है। कर-सम्बन्धी यह कानून धनवान वर्ग की संयुक्त-परिवार प्रया को तोड़ रहे हैं।

पंचायत (Panchayat)—प्राचीन भारत में पंचायत श्रत्यन्त महत्वपूर्ण् संस्था थी जिसे प्रशासन, न्याय श्रीर राजस्य सभी श्राधकार प्राप्त ये। परन्तु जैसे जैसे समय बीतता गया श्राधिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने से तथा प्रशासन श्रीर न्याय के केन्द्रीकरण से पंचायतों का महत्व घट गया श्रीर क्रमशः वह नगर्य हो गयीं। देश के कुछ भागों में पंचायतें स्थापित रहीं परन्तु केवल एक सामाजिक संस्था के रूप में जहाँ लोग श्रापस में मिल सकते, गप्प कर सकते श्रीर हुक्का पी सकते थे श्रीर कभी-कभी छोटे-मोटे क्रगड़े भी तय कर लिये जाते थे। परन्तु पचायत ने प्रशासन श्रीर न्याय के सेत्र में श्रपना प्रमावशाली रूप खी दिया।

परन्तु इघर कुछ वर्षों से महात्मा गांधी श्रांर राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस क्यवस्था के प्रति विशेष रिच दिखायां जाने के कारण पंचायत-प्रणाली को पुनः जीवन प्रदान किया गया है श्रीर पंचायतों को कानूनी मान्यता श्रीर कुछ प्रशासन तथा न्याय श्रिषकार प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों ने श्रावश्यक कानून भी बनाये हैं। परन्तु श्रव तक पंचायतें सन्तायजनक कार्य नहीं कर पायी है क्योंकि जिन लोगों को पंचायतों का कार्य सींपा गया है वह निरन्तर हैं श्रीर प्रशासन तथा श्रदालत की कार्य-प्रणाली की उनको श्रावश्यक जानकारी नहीं है, साथ ही उनके पास धन का भी श्रमान है।

पंचायतों का कार्यचेत्र बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है श्रीर उन्हें श्राधिक नियोजन का प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयत्न हो रहा है। संविधान के ४० वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य श्राम पञ्चायतों की त्यापना करने श्रीर उन्हें त्वशासन की इकाई बनाने के लिए श्रावश्यक श्रधिकार दिलाने के सम्यन्य में कार्रवाई करेगा। राज्य सरकारों द्वारा पञ्चायतों को कुछ श्रधिकार प्रदान किये गये हैं परन्तु यह उतने नहीं है जितने की संविधान में ज्यवस्था की गई है।

जून १९५४ में शिमला में स्वायच-शासन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें यह सिकारिश की गई कि पंचायतों को श्रिषक प्रभावशाली बनाने के लिए श्रिषक ज्यापक आर्थिक, प्रशासकीय श्रीर न्याय श्रीषकार दिये जाने चाहियें।

यह सुमाव दिया गया कि दितीय पञ्चवर्षीय योजना में 'नीचे से जपर की श्रोर' योजना बनायी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए श्रीर ग्राम को ही नियोजन की इकाई बनाना चाहिए। श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जुलाई १६५४ में अपने अजमेर अधिवेशन में इस वात पर विचार किया और अनुमान है कि उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । योजना में यह व्यवस्था की गई है कि पञ्चायतों को स्वशासन की प्रभावशाली श्राघारभूत इकाई श्रीर नीचे से योजना 'बनाये जाने के लिए श्राधारंभन एजेन्सी बनाया जायगा। एक गाँव सभा का निर्माण सारा गाँव करेगा श्रीर निर्वाचन के आधार पर ग्राम पंचायत बनायेगा जो गाँव सभा की कार्यकारिसी होगी। पंचायत को जो कार्य सींपे जायँगे उनमें लगान वसूली, भूमि सम्बन्धी कागजात रखने (इन्दराज), समान उप-योगिता की सरकारी जमीन का प्रबन्ध, कारत के लिए लगान पर जमीन देना, बहुधन्धी श्राम सहकारी समितियो का विकास करना और श्रपने श्रधिकार चेत्र के श्रन्दर सार्व-जनिक उपयोग के कार्यों के लिए सब से अनिवार्यतः कार्य करना आदि काय समिलित हैं। ग्राम के विकास की नीति पंचायत निर्धारित करेगी, ग्रीर भूमिन्न-रण, बनों के विकास, इंधन के सुरित्तत सृष्ट जमा करने, बाँध ख्रीर जलाशय बनाने, वयस्क शिज्ञा, अच्छे बीजों की पूर्ति, और काश्त के नये और सुधरे हुए उपायों को लागू करने की समस्याश्रों पर भी पंचायत विचार करेगी श्रीर इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेगो।

दितीय पंचवर्षीय योजना नीचे से ऊपर की श्रोर धनाई गई है। राज्य सरकारों ने एक-एक गाँव के श्रथवा गाँवों के समूहों के लिये जैसे तहसील, तालुका, विकास-पीली की इकाइयों के श्राधार पर योजना बनवाई है। इस कार्य में पंचायतों ने बहुत महत्वशाली सहयोग दिया है पर यह कहना कठिन है कि स्थानीय योजनाश्रों के बनाने में वे यथार्थ में कार्यशील रही हैं श्रीर ये स्थानीय योजनार्थे इस योग्य रही हैं कि उनको राज्य द्वारा बनाई योजना में सम्मिलित कर लिया जाता। जो कुछ भी हो पंचायत के सदस्यों को यह ज्ञान हो गया है कि दितीय योजना की सफलता के लिये उनके सहयोग की श्रावश्यकता है। इससे स्थानीय लोगों का उत्साइ श्रवश्य बढ़ा है श्रीर वे योजना के प्रति जागरूक हो गये हैं।

सरकार की नीति यह है कि "प्रत्येक गाँव में श्रीर विशेषकर उन चेत्रों में जो राष्ट्रीय विश्तार सेवाश्रों श्रीर सामुदायिक विकास योजनाश्रों के लिए चुने गये हैं एक कानून के श्राधार पर पंचायत की स्थापना की जाय। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पंचायतों की संख्या ८३०८७ से बंह कर ११७५६३ हो गई। दितीय योजना के कार्यक्रम के श्रनुसार १६६०-६१ तक ग्राम पंचायतों की संख्या

वद कर २४४५६४ हो जायगी"। यह सोचना युक्तिसंगत है कि भविष्य में पंचायतों को अधिकाधिक महत्ता दी जायगी और वे योजना को कार्य रूप में परिश्वित करने का एक प्रभावशाली साधन हो जायँगी। परन्तु श्रभी तक तो आम पंचायतों का कार्य बहुत ही असंतोषजनक रहा है। इसके अनेक कारना हैं जैसे (१) "ग्राम पंचायतों के प्रभावशाली न हो सकनं का सबसे वड़ा कारण उनके पास साधन का अभाव रहा है। बहुत सी पंचायतों की प्रांत व्यक्ति वार्षिक न्नाय २ म्ना॰ या ३ म्ना॰ रही हैं"। टेक्जेशन इन्यवायरी कमीधन (१६५३-५४) ने ग्रपनी रिपोर्ट में इस बात की ग्रोर ध्यान खार्कापत किया था कि प्रादेशिक सरकारें "पंचायतों को कुछ करो के लगाने का अधिकार दे कर उन्हें अपने आप श्रपनी सहायता करने के लिये छोड़ देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रायः पंचायतें ब्रारम्भ होते ही करों के ब्रारम्भ करने के कारण जनता को कोपभाजन वन जाती हैं श्रीर यदि करों का श्रारम्भ न करें तो निष्क्रिय हो कर जनता की हॉप्ट में नीचे गिर जाती हैं"। इस्रांलये पंचायती के कार्य की सफल वनाने के लिये चनसे अधिक आवश्यक बात यह है कि उन्हे पयांत विच प्रदान किया जाय। (२) दुसरी कठिनाई यह है कि पंचायतों के ऊपर उनके साधनों श्रीर शक्ति की अपेद्या अत्यधिक कार्य भाग डाल दिया गया है। प्रादेशिक सरकारें जिन्होंने पंचायतो को अनेक उत्तरदायित्व सौंप न्वसे हैं पंचायतों से श्रावश्यकता से श्रधिक श्राशा करती हैं। डिस्ट्वर बोर्ड श्रीर पंचायती के दित मी आपस में टकराते हैं क्योंकि दोनों के कार्य सेत्र एक दूसरे की शीमा का श्रांतक्रमण करते हैं। इस सम्बन्ध में टेक्जेशन इनक्वायरी कमीशन ने यह सिफारिश की है कि श्राधिक चेत्र श्रीर उत्पादन तम्बन्धी कार्य जो सहकारी समितियों द्वारा अधिक श्रन्छी तरह किये जा सकते हैं। उन्हें नियमित रूप से पंचायतों के अन्तर्गत आये हुए कायों से अलग कर देना चाहिये। इम इसे भी श्रावश्यक समक्ते हैं कि पंचायतों के लिये नियमावली में दिये गये श्रसंख्य कायों के स्थान पर थोड़े से चुने हुये कार्य ही दिये जार्वे ताकि उनका जिला बोर्ड तथा श्रन्य स्यानीय ग्राम बोर्ड के कार्यों से सामंजस्य सम्भव हो सके। (३) पंचायतों के मेम्बरों को उन कार्यों की कोई शिक्षा नहीं मिली है जो उनको दिये गये हैं। उनके विचार प्राचीन हैं, उधर उनके मन में स्थानीय कारणों से उत्पन्न द्वेप मावना भरी है, इस लिये जो समस्यायें उनके सामने अज्ञान अशिचा और जाति द्वेप के कारण उपस्थित हैं उनको दूर करने के लिये उनके विचार में वे ही पुराने ढंग आते हैं जिससे वे अपना कर्चंव्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाते।

श्रध्याय ४

कृषि उत्पादन और नीति

मारत कृषि प्रधान देश है। भारत का कुल चेत्रफल श्रन्तिम गण्ना के श्रनुसार लगभग ८१ करोड़ २० लाख ५० इजार एकड़ है, परन्तु श्राधे से बहुत कम भूमि कृषि के काम श्रा रही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने के पहिले ही योजना आयोग ने कुछ प्रदेशों में पिछले ४० वर्षों में विभिन्न फरलों के उगाने में लगी हुई मूमि की जाँच की। इससे यह पता लगा कि (१) खेती की जाने वाली भूमि का चेत्र-फल उत्तर-प्रदेश को छोड़कर कहीं भी विशेष मात्रा में नहीं बढ़ा। एक से श्रिधिक फसलों उगाने वाले चेत्र में २०% की वृद्धि हुई, परन्तु यह वृद्धि बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में नगरंग थी, (२) सिंचाई का चेत्रफल १०% बढ़ा जो कि मुख्यतः नहरों के विस्तार का परिगाम था, (३) परती छोड़ी हुई भूमि का चेत्रफल १६२०-४० तक के ही स्तर पर रहा । उसके बाद कुछ वृद्धि कई का उत्पादन करने वांले चेत्रों में हुई क्योंकि यकायक कई उत्पादन चेत्र में कमी श्रा गई श्रीर खेत परती छोड़ दिये गये। किस प्रकार की फर्नलें उगाने की प्रवृति प्राय: लोगों की रही, इसका योजना ग्रायोग ने ग्रध्ययन किया ग्रौर इस परिशाम पर पहुँचे कि (१) पिछले १० वधों में यद्यपि दुइरो फमल उत्पन्न करने के कारण फसलों के अन्तर्गत कुल चेत्र में वृद्धि हुई पर कोई भी नया भूमि का भाग खेती के कार्य में नहीं लाया गया, (२) मूल्यों में परिवर्तन के कारण फछलों की किस्म में परिवर्तन श्रा गया यद्यपि श्रिधिकाश ये फललें छोटे-छोटे खेतों में उत्पन्न की जाती थीं, (३) जाचान तथा व्यवसायिक फसलों के वीच श्रदला-बदला किसी विशेष ढंग पर नहीं हुई वस्त् मीसम फसलों के हेर-फेर, मूल्य परिवर्तन श्रीर किसान की श्रार्थिक शंकि पर निर्भर रही।

स्वाद्यान श्रीर कच्चे माल में कमी—यह श्राध्वर्य की बात है कि कृषि-प्रधान देश होते हुए भी भारत में खाद्याल की कमी है श्रीर उद्योगों के लिए कच्चे माल का श्रभाव है। इन श्रमावां के मुख्यतः तीन कारण हैं: (१) १६३६ में वर्मा को भारत से श्रलग कर देने के कारण देश के श्रन्दर ही प्राप्त हो जाने वाली खाद्याल की माला में १३ लाख टन की कमी हो गई; (२) १६४७ में देश-विभाजन हो जाने के कारण उस माला में ७५ लाख टन की श्रीर कमी हो गई; (३) देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष १ रै प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, परन्तु खाद्यान की मात्रा में इसी दर से वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान का ग्राभाव हो गया। सन् १६४६-५० में देश की ४६० लाख टन ग्रान की उत्पत्ति ग्रीर सरकारी गोदाम तथा विदेशों से मँगाये श्रान को मिलाकर प्रति वयस्क १३.७१ ग्रींस ग्रान प्रतिदिन पड़ता था। यदि जनसंख्या ग्राधिक होती तो प्रति व्यक्ति ग्रान का माग ग्रार भी कम होता। पौष्टिक पदार्थ सलाहकार समिति के विचारानुसार प्रति स्वरूप व्यक्ति (वयस्क) १४ ग्रींस ग्रान प्रतिदिन ग्रावश्यक है। इसिलए प्रयम पञ्चवर्षीय योजना ने ७६ लाख टन श्रान की उपज बढ़ाने का निश्चय किया था।

पौधिक पदार्थ सलाहकार समिति के सुकाव के अनुसार उन्तुलित भोजन के लिये प्रत्येक व्यक्ति को ३ श्रोंस दाल प्रतिदिन खानी चाहिये। १६५०-५१ में ६३ लाख टन ढाल पैदा हुई, जिसमें से सरकारी त्याक, बीज इत्यादि के लिये २० प्रतिशत निकाल देने के पश्चात् प्रति वयस्क को प्रतिदिन २'१ श्रीस दाल मिली। इस प्रकार प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई जनसंख्या के अतिरिक्त आवश्यकता ५ लाख टन की श्रीर ३ श्रीस प्रति व्यक्ति के हिसाब से ४० लाख टन की श्रीमानित की गई थी।

१६५०-५१ में ५१ लाख टन तिलहन की उपज हुई जिसमें से लगभग १६ लाख ६० इजार टन तेल प्राप्त हुआ। साबुन, रंग तथा वार्निश बनाने के काम में प्रयुक्त तेल को श्रलन करने के पश्चात् रोप १६ लाख टन तेल घरेलू कार्यों के लिए बचा। इसके अनुसार मित वयस्क की प्रतिदिन ०५ औं स तेल मिला, जो श्रावश्यकता से बहुत कम था श्रीर इसलिए उसकी मात्रा बढ़ानी श्रावश्यक सममी गई। नहीं तक क्यास का प्रश्न है, १९५०-५१ में २९ लाख ७० इजार गाँठों का उत्पादन हुत्रा (प्रत्येक गांठ का वजन ३६२ पींड) जर कि खपत ४० लाख ७० हजार गाँठों की थी। उत्पादन श्रौर खपत के इस श्रन्तर की प्रतिवर्ष लगभग ६३० हजार गाँठों का त्रायात करके पूरा किया गया। श्रतुमान लगाया गया है कि १९५६ में ५४ लाख गांठों की ब्रावश्यकता होगी। जुट के उत्पादन के विषय में सरकारी तार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १९५१-५२ में ३३ लाख कच्चे जूट की गाँठों का उत्पादन किया गया। ग्रीर मेस्टा (Mesta) की ६ लाख गींठें पेदा की गई, जो जूर से घटिया किस्म की उपज है और जिसका उपयोग जुट न मिलने पर किया जाता है। ऋनुमान है कि १९५६ में ७२ लाख गाँठों की त्रावश्यकता होगी। इस प्रकार मींग श्रीर पूर्ति में ३३ लाख गाँठों का श्रन्तर रह गया।

इस अध्ययन से यह प्रकट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आईम

में खाद्यान श्रीर उद्योगों के लिए कच्चे माल दोनों का ही श्रभाव था। भारत को स्वानलम्बी बनाने श्रीर विदेशी मुद्रा की वचत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि देश के श्रन्दर ही इनका उत्पादन बहाया जायगा। यदि समस्या केवल खाद्यान या ज्यवसायी फमलों की पूर्ति की मात्रा बहाने की होती, तो इसके लिये घीरे-घीरे एक फ़सल की जमीन को दूसरी फसल के उत्पादन के लिये ज्यवहार में लाया जा सकता था। परन्तु समस्या दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की थी, जिससे माँग श्रीर पूर्ति के बीच का भारी श्रन्तर दूर किया जाय।

खादान्न जाँच कमेटी की रिपोर्ट —कमेटी, जिसके श्रध्यज्ञ श्री श्रशोक मेहता थे तथा जिसने नवम्बर १९५७ में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस निष्कर्ष पर पहुँची कि खाद्यान की कुल उत्पत्ति १६५३-५४ के ६८८% लाख टन से घट कर १६५४-प्य में ६७१'र लाख टन तथा १६५६-५७ में ६५२'९ लाख टन हो गयी। इसके अनन्तर प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ और १६५६-५७ में खाद्योत्पादन बढ़कर ६८६ ९८ लाख टन हो गया। खाद्यात्र के मूल्यों एवम् खाद्य समग्री के श्रमाव की वृद्धि निम्न कारणों से हुई। (i) क्रपकों ने अपनी उत्पत्ति का अधिक माग स्वयं रख लिया। अतएव मूल्यों की वृद्धि में जितना विकोत-अतिरिक्त (marketed surplus) की कमी का हाथ या उतना उत्पादन की कमी का नहीं या। १६५५-५६ में मोटे अनाज (millets) की उत्पत्ति में ३० लाख उन की कमी हुई जिसने मूल्य वृद्धि का क्रम प्रारंभ किया और १९५५-५६ में चावल तथा गेहूँ की माँग बढ़ने के कारण खाद्यान के मूल्य बढ़ने लगे। यद्यपि बाद में उत्पादन बढ़ गया किन्तु मूल्यों में फिर मो चूहि होती रही। (ii) दितीय योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय तथा वैंक उदार की वृद्धि ने भी मूल्य-स्तर के बढ़ाने में मदद की, तथा (iii) "खाद्य स्यित के बारे में अत्यिक आशावादिता ने अनेक राज्यों में खाद्योत्पादन की वृद्धि के प्रयत्नों को या तो शिथिल कर दिया या उनमें तीवता नहीं आने दी"।

सारत की जन संख्या की प्रतिवर्ष १३ - २ प्रतिशत वृद्धि के आघार पर कमेटी ने अनुमान लगाया कि खाद्याओं की माँग में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण १०% तथा आय की वृद्धि से ४.७ प्रतिशत वृद्धि होगी। इस प्रकार द्विवीय योजना में खाद्यान्नों की माँग १४३ से १५ प्रतिशत तक बढ़ जायगी अर्थात् १६५५.५६ में ६६० लाख टन से बढ़कर १६६०-६१ में ७६० लाख टन हो जायगी जबिक उत्पत्ति में केवल १०३ लाख टन की वृद्धि की आशा की जाती है जिसके फलस्वरूप १६६०-६१ तक उत्पत्ति बढ़कर ७७५ लाख टन हो जायगी। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कुछ अगामीवर्षों में प्रतिवर्ष २०-३० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना आवश्यक होगा।

कमेटी ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मृल्य-स्थायित्व (price stabilisation) की नीति की सिफारिश की। (i) इस हेतु उन्होंने उचाधिकारों से युक्त 'मूल्य-स्यापित्व परिपट' (Price Stabilisation Board) की नियुक्ति प्रस्तावित की जिसके कार्य मृल्यनीति का निर्घारण तथा उने लागू करने के उपायों का निर्मय करता था। (ii) नीति को कार्यान्यित करने के लिए खाद्यान्त स्थायित्व संगटन (Foodgrains stabilisation Organisation) के निर्माण की भी छिकारिश की गर्ड। यह संगठन खाद्य श्रीर क्वांप मंत्रालय का एक विभाग हो सकता है या एक परिनियत निगम (Statutory corporation) श्रथवा सं मित दायित्व वाली कमनी का रूप भी ले नकता है। यह संगठन खादान बाजार में एक व्यापारी की माँवि काम करेगा श्रीर श्रन्तःस्य-स्कन्य (bufferstock) का काम करेगा श्रयीत् मूल्य गिरने पर खरीदेगा जो ग्रीर बढंने पर बेचेगा । (ili) खाद्य मंत्रालय तथा मूल्य स्यायित्व परिपद की सद्दायता के लिए केन्द्रीय खाद्य परामर्श समिति (Centralfood Advisory Council) के निर्माण की भी सिफारिश की गई। (vi) प्रसंगानुकृत एवम् विश्वासनीय आँकड़े एकत्र करने के लिए मूल्य-जानकारी-संमान (price Intelligence Division) की स्थापना की भी सिफारिश हुई। परामर्श समिति तथा जानकारी संमाग की सहायता से मूल्य-सामयित्व -परिषद का उद्देश्य मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर सतर्कता वरतने तथा समय समय पर न केवल सामान्य मूल्य स्तर के स्थिर बनाये रखने वरन विभिन्न वस्तु श्री के मुल्यों में अनुचित अन्तर-को रोकने के लिये आवश्यक कार्यावाही की विफारिश करना था।

इस बात को ध्यान में रखने हुये कि वर्तमान परिस्पितियों में स्वतंत्र च्यापार अविद्यालिय है तथा पूर्ण-नियंत्रण (Full-fledged Control) आर्थिक एवम् प्रशा- स्कीय किठनाइयों से भरा ई, कमेटी ने एक मध्य-मार्ग की विफारिश की जिसके अंवर्गत नियंत्रण का कंट्रोल खुले बाजार में खाद्याल के कय-विकय तक सीमित रहेगा, योक व्यापार का अंशत: समाजीकरण होगा, अनुजा (License) द्वारा शेष बाजार में कार्यश्रील व्यापारियों पर नियंत्रण होगा, रेहूँ और चावल का पर्यात स्टॉक रखा लायना तथा अन्य प्रक साथ सामग्री के उपमोग और उत्पादन की वृद्धि के लिये प्रचार का संगठन किया जायगा।

उत्पादन प्रवृत्ति — त्यवन्त्रवा प्राप्त होने के उपरांत भारत में न्यायात्र श्रीर श्रन्य कृषि-सम्बन्धी कन्त्रे माल के उत्पादन में कभी श्रा गई है। १६५०-५१ में लाखात्र का उत्पादन ५०० लाख टन हुश्रा, जर्बाक १८४६-५० में इसका उत्पादन ५४० लाख टन हुश्रा था। कृषि-सम्बन्धी कन्त्रे मालों की उत्पादन-प्रवृत्ति योड़ी भिन्न थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद उत्पादन में कमी आ गई, किन्तु तत्पश्चात् उसमें फिर वृद्धि हो गई। १६४८-४६ में तिलहन का उत्पान ४५ लाख टन, कपास का १७ लाख ७० हजार गाँठों और कब्चे जूट का २० लाख ७० हजार गाँठों तक ही घटकर रह गया। गन्ने का उत्पादन भी कम होकर ४८ लाख ७० हजार टन ही रह गया। किन्तु अगले वर्षों में इन कब्चे मालों के उत्पादन में वृद्धि हुई और १६५०-५१ में, जब कि खाद्यान का उत्पादन गिरता जा रहा था, उनकी उपज बद्दनी प्रारम्म हुई।

'अधिक-ग्रज्ञ-उपजाग्रो' श्रान्दोलन के बावजूद खाद्यात्र के उत्पादन में कमी श्राई। बहुत संमव है कि खाद्याज उत्पादन के सरकारी श्राँकड़े बिल्कुल सही न हों। परन्तु इस बात में कोई। सन्देह नहीं कि सही श्राँकड़े चाहे कुछ भी हों, श्रनेक कारणों से खाद्यान्न का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में काफी गिर गया:

- (१) देश के कुछ भागों में स्ला पड़ने और कहीं-कहीं वाढ़ आ जाने से खाद्याच के उत्पादन में आंशिक कमी अयश्य हुई है, परन्तु केवल प्रकृति का कीप ही उत्पादन की गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- (२) यह भी सुकाव दिया गया है कि क्रिष-सामग्री की कँची कीमतें भी कुछ ग्रंश तक क्रिष-उत्पादन घटने का कारण हैं। साधारण रूप से ग्रिकिक कीमत का ग्रंथ है ग्रिकिक उत्पादन, परन्तु जहाँ तक किसान का सम्बन्ध है ग्राय की लोच (Elasticity) ऋणात्मक (negative) है। इसका तात्पर्य यह है कि किसान कुछ ग्राय चाहता है ग्रीर जब कीमतें ग्रिक होती हैं तो यह योड़ा सा उत्पादन करके उसे प्राप्त कर लेता है, किन्तु जब कीमतें कम होती हैं तो उसे ग्रिकिक उत्पादन करना पड़ता है। इसकिये जैसे ही खाद्याक की कीमतें बढ़ों; उसने ग्रपना उत्पादन कम कर दिया। चूँकि कीमतों ग्रीर उत्पादन के पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तारपूर्वक ग्रध्ययन नहीं किया गया है, इसिलए यह कहना संभव नहीं है कि यह विद्यान्त मारत में कहाँ तक लागू होता है।
- (३) खाद्याल के उत्पादन में कमी श्राने का एक कारण यह भी है कि गन्ने, रुई श्रीर जूट की श्रविक श्रावश्यकता होने के कारण खाद्याल के उत्पादन में प्रयुक्त भूमि के कुछ माग में श्रव न्यवधाई कसर्लें बोई जाती हैं।

भारत-सरकार के 'श्रधिक-श्रन्न-उपनाश्रो' श्रान्दोलन से खाद्यान की कभी पूर्ति करने की जो श्राशा की गई थी, उसमें श्रधिक सफलता नहीं हुई क्योंकि (श्र) इस श्रान्दोलन में पहले से ही काश्त की जाने वाली जमीन में उत्त दन बढ़ाने की श्रपेद्या नयी भूमि को खेती के योग्य बनाने पर श्रधिक जोर दिया गया। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी श्रीर इससे निकट मिविष्य में उत्पादन बढ़ाने की

त्राशा नहीं की ना सकती थी। 'ग्रधिक-ग्रन्न-उपनाग्रो' श्रान्दोलन की नीति में परिवर्तन कर ग्रत्न श्रल्पकालीन योजनाश्चों पर जोर दिया गया है, जिसके श्रन्तर्गेत खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए वीज श्रीर खाद दी जाती है श्रीर साथ ही साथ सिचाई की भी व्यवस्था की जाती है। आरंभ में यह आन्दोलन देश के उन भागों में चलाया गया था नहाँ विचाई की सुविधाएँ नहीं यीं श्रीर इसलिए सन्तोपजनक परिणाम नहीं निकले । बाद की नीति बदल दो गई श्रीर योजनाश्रों को उन्हीं स्थलों पर चलाया गया है जहाँ सिंचाई की सुविधा पहले ही से थी या सरलता से आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सकती थी। इसका परिणाम यह निकला कि 'अधिक श्रम उपजात्रो' श्रान्दोलन में सन्तोपजनक प्रगति हुई: (व) यह ग्रत्यन्त खेद का विषय है कि 'म्राधिक-म्राब-उपजाम्रो' म्रान्दोलन का कार्य-मार जिन श्रविकारियों को सौंपा गया है वह सदैव ईमानदारी श्रीर लगन से कार्य नहीं करते हैं। बहुत सी बातों में काम कुछ नहीं किया जाता, केवल कागजी खाना पूरी कर दी जाती है श्रीर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बीज या खाद ब्रादि किसानों को मिलनी चाहिए थी, उसे या तो वेच दिया गया या उसका रुपया स्वयं रख लिया गया। इस म्रान्दोलन में या किसी भी नियोजन के अन्तर्गत योजना को सुचार रूप से कार्यान्त्रित करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो कि सुसंगठित हो श्रीर जिसके कर्मचारी पूर्णरूप से ईमान-दार हों; (स) किसानों ने भी 'श्रिधिक-श्रब-उपजाश्री' श्रान्दोलन को उतना सहयोग नहीं दिया जितना उनसे आशा की जाती थी।

१६५४-५५ श्रीर १६५५-५६ में हुई उत्पादन की थोड़ी सी कमी को छोड़ कर १६५१ के उपरान्त खाद्यान्न के उत्पादन में उन्तेप जनक वृद्धि हुई है। १६५०-५१ में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन ५०० लाख टन था जो १६५३-५४ में ६८५ लाख टन हो गया। सबसे श्रिषक वृद्धि चावल के उत्पादन में हुई श्रीर इसके बाद कमशः गेहूँ, बाजरा, ज्वार श्रीर जी की उपज बढ़ी। खाद्यान्न के उत्पादन में यह वृद्धि इन कारणों से हुई, (१) मौसम की श्रनुकृल परिस्थितियाँ, (२) १६५०-५१ में प्रारंभ किए गए संघठित उत्पादन कार्यक्रम (Integrated Production Programme) की सफलता, (३) चावल उत्पन्न करने की जापानी पद्धित का प्रयोग, सिचाई की श्रिषक मुविधाएँ श्रीर किसानों को श्राधिक सहायता के रूप में रासायनिक खादें (Fertilisers) श्रादि देना।

१६५४-५५ तथा १६५५-५६ में उत्पादन घटकर क्रमशः ६७१.१ लाख टन तथा ६५२६ लाख टन होने के कारण (i) देश के कुछ भागों में स्वा, (ii) टर्वरक तथा श्रच्छे वीजों का श्रमाव तथा (iii) राज्य सरकारों द्वारा प्रयत्नों में दिलाई देना या जो अंशातः उनकी लापरवाही तथा अंशातः दितीय योजना के खाद्यान की उत्पत्ति और कृषि पर अपर्याप्त ध्यान देने के फलस्वरूप हुई। १९५६.५७ में उत्पादन के ६८६.६ लाख टन तक बढ़ जाने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों में उत्पादन के गिरने से मूल्य बढ़ गये जिसके फलस्वरूप सामान्य व्यक्ति को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। खाद्यान का आयात, जो १९५१ के ४७ लाख टन के ऊँचे स्तर से घटकर १९५४ में ८ लाख टन तथा १९५४ में ७ लाख टन हो गया था, पुनः १९५६ में बढ़कर १४३ लाख टन तथा १९५७ में ३७ लाख टन हो गया।

कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति कुछ मिल ही रही है। १६५२-५३ में कई श्रीर जूट का उत्पादन पिछले वर्ष के ही स्तर पर (३२० लाख श्रीर ४६० लाख गाँठ कमशः) रही पर तिलहन श्रीर गन्ने की उपज कमशः ४७ लाख टन श्रीर ५० लाख टन हो गई। श्रगले वर्षों में जूट को छोड़कर इन सभी १६५६-५७ में श्रनुमान किया जाता है कि तिलहन ६० लाख टन, वर्ड ४७.५ लाख गाँठ जूट ४२.५ लाख गाँठ श्रीर गन्ना ६५ लाख टन होगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—प्रथम पंचवर्षीय योजना का ध्येय खाद्यान तथा उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल की उत्पत्ति इस दृष्टि कोण से बढ़ाने का था कि (१) देश आत्म निर्मरता प्राप्त कर ले, (२) भारतीय उद्योगों को माँग पूरी हो सके और (१) प्रति व्यक्ति अन्न का उपयोग बढ़ाया जा सके।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लच्य

वस्तुयॅ	श्राधार माने हुये साल में उत्पत्ति	प्रस्ताबित श्रतिरिक्त उत्पत्ति* ु	प्राप्त कर लेने	श्राधार माने हुये वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
অাথান	५४० लाख टन	७६ लाख टन	६१६ लाख टन	\$ \$
वित्तहन	५१ लाख टन	४ लाख टन	५५ लाख टन	5
गन्ना (एक)	५६ लाख टन	७ लाख टन	६३ लाख टन	१३
(गुड़) रुई	२६ लाख गाँठें	१३ लाख गाँठें	४२ लाख गाँठें	ጸቭ
नूट	३३ लाख गाँठें	२१ लाख गाँठें	प्र लाख गाँउँ	६४

#साद्यानों के लिए आधार वर्ष १२४६-५० है श्रीर श्रन्य के लिये १६५०-५१ है।

खाद्यान में प्रस्तावित ७६ लाख टन की वृद्धि में से ४० लाख टन चावल, २० लाख टन गेहूँ, १० लाख टन चना और अन्य दालें और ५ लाख टन में अन्य अन हैं। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। उपज ६५० लाख टन हुई। (बजाय ६१६ लाख टन के जो कि लक्ष्य था) गेहूँ, चना और दालों के उपज की मात्रा प्रस्तावित लक्ष्य से अधिक बढ़ गई है परन्तु चावल की उपज विछले वर्ष में बढ़ने के परचात् १६५४-५५ में बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण घट गई। यह कमी संसार के सभी चावल उत्पन्न करने वाले देशों में हुई थी। पर १६५५-५६ में किर उत्पत्ति कुछ बढ़ी। व्यवसायिक फसलों में से तिलहन और सई की उत्पत्ति योजना के अनुकूल बढ़ी पर जुट और गन्ने की उपज में कमी हुई।

प्रथम योजना के काल में अन्न की उत्पत्ति में वृद्धि सिंचाई की सुविधाओं के बढ़ने, खाद के प्रयोग में आधिक्य और वेकार भूमि को खेती के काम में लाने के लिये फिर से अधिकृत करने के कारण हुई, परन्तु यह बता सकना कठिन होगा कि किस कारण से कितनी वृद्धि हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—यद्यिप द्वितीय योजना में उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है पर कृषि के प्रति उदामीनता नहीं दिखाई गई है। द्वितीय योजना में इस वात पर ध्यान रक्खा गया है कि प्रथम योजना के कार्य में विकास हो और कृषि उत्पत्ति तथा कच्चे माल की उत्पत्ति में हमारा देश यथासम्मव श्रात्मिर्मर हो जाय। दूसरे, यह अब अच्छी तरह समक्त में श्रा गया है कि खेती का जेत्रफल बढ़ा लेने मात्र से ही उत्पत्ति में श्रावश्यक वृद्धि न हो सकेगी। अन्त में यद्यि खाद्यान की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर दूसरी योजना में उन वस्तुओं की संख्या काफी वड़ी है जिनकी उत्पत्ति बढ़ाने का ध्येय है। ऐसी वस्तुओं में चाय, काली मिर्च, लाख, नारियल, वृष्कफल, सुपाड़ी भी सम्मिलित हैं। इससे भारतीय किसानों की उन्नति में ।स्थरता और विदेशी विनिमय से अधिक श्राय प्राप्त होगी।

यदि वर्तमान दर से ही श्रन्न का उपमोग चलता रहे तो योजना श्रायोग के श्रनुसार वर्दा हुई जनसंख्या को ७०५ लाख टन श्रन्न की श्रावश्यकता होगी परन्तु प्रति व्यक्ति श्रन्न का उपयोग १८३ श्रोंस प्रतिन्नि कर देने का विचार है, इस्रिलेये कुल श्रन्न की श्रावश्यकता ७५० लाख टन होगी। इसी श्राघार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६६०-६१ तक १०० लाख मेंन की उपज बढ़ाने का निश्चय किया गया। श्रन्न की इस वृद्धि में चावल की ३० से ४० लाख टन, गेहूँ की २० से ३० लाख टन, श्रौर श्रन्य श्रनों की २० से ३० लाख टन, श्रौर श्रन्य श्रनों की २० से ३० लाख टन श्रौर दालों की १५ से २० लाख टन वृद्धि सोचों गई है। बाद में ऐसा प्रतीत हुश्रा कि खादान्न के

उत्पादन की यह वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी और इसीलिये लक्ष्य बढ़ाकर ८०४ लाख टन कर दिया गया जो १९५५-५६ की तुलना में २४३% ग्राधिक है।

द्वितीय पंचवपीय योजना के अन्तर्गत कुछ संशोधित ऋषि उत्पादन लच्च

वस्तु	११५५-५६ में उत्पत्ति श्रनुमानित	प्रस्तावित श्रतिरिक्त उत्पत्ति	१६६०-६१ तक बृद्धि करने की मात्रा का ध्येय	प्रतिशत
खाद्यान	६५० लाग्न टन	१०० लाख टन	८०४ लाख टन	२४.६
विलइन	५५ लाख टन	१५ लाख टन	७६ लाख टन	₹७.०
गन्ना (गुङ्)	५८ लाख टन	१३ लाख टन	७८ लाख टन	3.88
वई	४२ लाख गाँठ	१३ लाख गाँठ	६५ लाख गाँठ	पूप्,इ
जूर	४० लाख गाँठ	१० लाख गाँठ	५५ लाख गाँठ	५⊏.१
श्रन्य फसलें	•••	•••	•••	२२.४
सन वस्तुय	100	•••	•••	₹७.८

वंशोधित लक्ष्यों के अन्तर्गत व्यवसायिक फसलों के सम्बन्ध में यह प्रस्ता-वित हैं कि कपास की उत्पत्ति ४२ लाख गाँठों से बढ़ाकर ६५ लाख गाँठ, जूट की उत्पत्ति ४० लाख गाँठों से बढ़ाकर ५६ लाख गाँठ, गन्ना (गुड़) की उत्पत्ति ५६ लाख टन से बढ़ाकर ७८ लाख टन, तथा प्रमुख तिलहनों की उत्पत्ति ५६ लाख दन से बढ़ाकर ७८ लाख टन की जाय । अन्य कृषि फसलों के सम्बन्ध में, आधार वर्ष की तुलना में ६ प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित थी जो अब बढ़ाकर २२३ प्रतिशत कर दी गई है। दितीय योजना की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि (i) प्रथम पंचवर्णीय योजना में कई की खेती के विकास के सम्बन्ध में जो कार्य कम आरम्म किया गया था वह जारी म्कखा जायगा। दूसरी योजना के अन्तर्गत मुख्य वात इस सम्बन्ध में यह होगी कि लग्ने रेशे वाली कई के उत्पादन पर विशेष जोर दिया खायगा। लग्ने रेशे की कई के उत्पादन में काफी उन्नति की गई है। (ii) जूट की उत्पन्नि के सम्बन्ध में जोर इस वात पर दिया रहा है कि जूट की किस्म अच्छी की जाय न कि केवल उत्पत्ति की मात्रा ही। यदि सभी मिलें भरपूर काम करें तो उन्हें लगभग ७२ लाख जूट की गाँठों की आवश्यकता होगी। इसके श्रितिरिक्त १५०,००० गाँठों श्रन्य कामों के लिये चाहिये। (iii) गन्ने अध्वा गुरू का उत्पादन बढ़ा देने पर यह सम्भव हो सकेगा कि प्रति वयस्क प्रतिदिन १ ७२२ श्रींस का उपयोग कर सकेगा। (iv) शृद्ध की गड़बड़ी के कारण तम्बाक् की इधर कई वर्षों से उपज बड़े निम्नकोटि की हुई है जिसके कारण उसकी विक्री में बड़ी वाघा पड़ी। इससे गोदामों में तम्बाक् के स्टाक्त के पड़े रह जाने के कारण उसका मूल्य गिर गया। इसलिये द्वितीत योजना में उच्चतर कोटि की तम्बाक् के उत्पादन पर जोर दिया गया है, न कि उत्पादन के मात्रा की वृद्धि पर।

खाद्यान्न नीति

मूल्य नीति—खाद्यान्न के सम्बन्ध में सरकार की नीति है कि (१) मारत को खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्वावललम्बी बनाया जाय, (२) जब तक श्रभाय की स्थिति रहती है तब तक खाद्यान्न के मूल्यों श्रीर बितरण पर नियंत्रण रखा जाय, जिससे उपभोक्ताश्रों की कठिनाई दूर हो श्रीर जहाँ तक संभव हो देश के सभी मागों में समान श्राधार पर सभी को खाद्यान्न मिल सके, श्रीर (३) किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

पंचत्रधीय योजना में यह ठीक ही कहा गया है कि "मूल्य के बहने-घटने में खाद्यान्त पर प्रमुख रूप से प्रमाव पहता है। यदि मृत्य पर नियंत्रण रखना है तो यह श्रावश्यक है कि खाद्यान्न का माय ऐसं स्तर रखा जाय जो देश की गरीव जनता की पहुँच के बाहर न हो। भारत का वर्तमान स्थिति में यदि खाद्यान्न की पूर्ति में थोड़ी भी कमी आई, तो भान अपेज्ञाकृत अधिक चढ़ जायेंगे। खाद्यान्न का भाव बढ़ जाने से रहन-सहन का खर्च बढ़ जाता है श्रीर उत्पादन व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए ऐसी नीति जिससे सभी श्रोर माव बढ़ जाये श्रीर रुपया लगाने का कार्य कम ही ठप हो जाय, उत्पादक के लिए किसी भी रूप में लामदाक नहीं है। इस कारण खाद्यान्न नीति निर्धारित करते समय इन सभी वार्तो पर विचार करना त्रावश्यक है।" श्राश्चर्य की वात है कि योजना त्रायोग द्वारा इस सही सिद्धान्त का प्रतिपादन किए जाने के बाद मी मारत-सरकार की नीति इसके विल्कुल विपरीत है। खाद्यान्न के भाव ऊँचे रखे गए हैं, जिससे उपमोक्तात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा श्रौर उद्योगों के उत्पादन-व्यय में भी वृद्धि हुई। खाद्यान्न ऊँचे भावों के समर्थन में यह कहा गया है कि (१) यदि खाद्यान्न के भाव गिराए जार्वे तो किसान खाद्यान्न के स्थान पर गन्ना, कपास और जूट वोयेगा, जिनके भाव श्रपेत्ताकृत श्रिषक ऊँचे हैं। किसान स्वभा-

वतः ही इन ऊँची कीमतों की ग्रोर श्राकृष्ट होगा; ग्रीर (२) खाद्यान्न के भाव केवल भारत में ही ऊँचे नहीं हैं, बल्कि यह स्थिति सारे विश्व में है। जब तक विश्व के श्रम्य देशों में खाद्यान्त के भाव नहीं गिरते हैं, तब तक देश में खाद्यान्त का श्रमाव होने के कारण भाव कम नहीं किए जा सकते हैं।

इन वकों में रात्य का श्रंश बहुत श्रधिक नहीं है। प्रथम तर्क के सम्बन्ध में यह ध्यान देने याय वात है कि गन्ते, कपास श्रीर जूट की कीमत श्रिधिक इमलिये है वयोथि सरकार ने इनकी कीमतोर्जेनी दर पर निश्चित कर रखी है। यदि आरंभ से हो व्यवसायी कमलों श्रीर खायान्न के मृत्यों में बुख सम्बन्य निश्चित किया गया होता तो इस प्रकार की गहबड़ी कभी नहीं होती। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कृषिसामग्री के सम्बन्ध में मूल्य और उत्पादन में उल्टा सम्बन्ध होता है। यदि न्यत्रसायो-फसल ग्रीर खादान्न दोनों के मृत्य कम रखे जाते तो दोनों के उत्पादन में बृद्धि होती। परन्त सरकार हारा व्यवसायी-प्रसल का भाव ऊँचा कर दिए जाने से सारी न्धित ही बटल गई छीर काफी चिति पहुँची। इसका अब एक यह उपाय है कि कपास, जूट, गरने इत्यादि के मूल्य कम किए जायें। इससे दो लाभ होंगे: (१) उद्योगो का उत्पादन न्यय कम होगा श्रीर (२) खादान के भाव घट जायेंगे। जहीं तक दूसरे तर्क का सम्बन्ध है, भारत में खादान का भाव इसलिए ऊँचा नहीं है कि विश्व के बाजारों के मान भी ऊँचे है। उसका कारण तो यह है कि भारत का उत्पादन बहुत कम है। कुछ नमय पूर्व भारत में खाद्यान का माव विश्व-वाजार के भाव की श्रमेज्ञाकृत कहाँ श्राधिक था। यदि यह तर्क सही है तो उस समय भारतीय कीमती की इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए था। भारत में ऊँची कीमतों की समस्या फेबल दो उपायों में इस की जा सकती है-या तो उत्पादन बहाया जाय श्रायवा श्रायात में वृद्धि की जाय । क्योंकि श्राधिक व्यय होने के कारण खाद्यात्र का श्राधिक श्रायात कर सकना संभव नहीं है, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि यही है कि देश में उत्पादन की वृद्धि की जाय। यदि खाद्याचा ग्रीर व्यवसायी फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि में प्रति एकड़ का उत्पादन बढ़ाया जाय, तो दोनों फसलों का उत्पादन बढाया जा सकता है। यह श्रावश्यक नहीं है कि एक फसल बोई जाने वाली जमीन पर दूसरी फसल बोई जाय । सिंचाई की व्यवस्था, अच्छे बीज त्रीर त्र्राधिक खाद के द्वारा प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा सकना संभव है।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त सबसे पहले १६५४ के मध्य में सरकार का ध्यान इस श्रीर श्राकर्षित किया गया कि वह ऐसी नीति कार्यान्यित करे जिससे 'किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके'। पिछले वर्षों में खाद्यांचे के मूह्य श्रिषक में श्रीर सरकार उन्हें नियन्त्रित करने में प्रयक्षशील थी। किन्तु जब जुलाई १९५४ में नई फसल तैयार होकर वाजार में ग्राई, तो पंजाब में गेहूँ का भाव १० रुपए प्रति मन से भी कम हो गया। हापुर श्रादि उत्तर-प्रदेश को भी कुछ मंडियों में नेहूँ लगभग १० काया प्रति मन के हिसाव से विकने लगा। मुल्यों में यह गिरावट इसलिए श्राई कि (१) गेहूँ उत्सन्न करने वाले श्रिषकांश चेत्रों में पिछले वर्षों की अपेज्ञाकृत श्रीवक उत्पादन हुआ, (२) अय-शक्ति कम हो जाने के कारण बहुत से लोगों ने गेहूँ का उपयोग करना बन्द कर दिया, विसके फलस्वरूप उसकी माँग में कमी आ गई, (३) यातायात के राधनी की श्रिषक सुविधाएँ प्राप्त न होने के कारण यह संभव न था कि जिन चेत्रों में गेहूँ का उत्पादन होता है वहाँ से वह उन केन्द्रों को शीघतापूर्वक भेजा जा तके जहाँ उसकी खपत होती है। फलतः मंहियों में उसका भाव गिर गया, ग्रीर (४) जिन श्चन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने गेहूं के भाव को गिराने में सहायता दी, उनके पाछे एक मनावैज्ञानिक कारण भी या श्रीर वह यह कि विश्व भर में गेहूँ की पृति वह गई थी और उसके मूल्य में कमी आ गई थी। इस संकट की दूर करने के लिए पंजाय सरकार ने स्वयं १० रुपया प्रति मन के हिसाव से कुछ गेहूँ खरीदा । उत्तर-प्रदेश चरकार भी ऐसा ही करने के लिए तैयार थी, किन्तु कालान्तर में मूल्यों में वृद्धि हो जाने पर सरकार ने गेहूँ लरीदना अनावश्यक समझा। जब कि गेहूँ और चने के मूल्य में अत्यधिक नीचे गिरने की प्रवृत्ति दिलाई पढ़ने लगी तब चुनी हुई वस्तुम्रों के मूल्यों की सहायता देने की नंगित (Selective price support policy) का अनुसरण किया गया श्रीर अप्रैल १६५५ में गेहूँ, जून में चना और अगस्त में चावल इसके अन्तर्गत समिमिलित कर लिये गये। जुलाई १९५५ से खाद्यानों के मूल्य अधिकार के वाहर जाने लगे क्योंकि बाद श्रादि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण खरीफ की फक्ल बिलकुल नष्ट हो गयी थी। खरकार की मूल्य स्थिर रखने की नीति के कारण थोड़े समय के लिये अन्न की पूर्ति में कमी आ गयी श्रीर ननता की घारणा कुछ ऐसी हो गई कि मूल्य वह गया।

यदि खाद्यात्र या उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कन्चे मालों के मूल्यों के एक निश्चत सीमा से श्रांघक कभी हो जाय, तो उनका सरकार द्वारा खरीदना उसी सीमा तक उचित होगा जहाँ तक उससे किसानों का भला होता है, क्योंकि उनके हितों को सुरक्ति रखना उतना हो महत्वपूर्ण है जितना श्रामिकों या उपमोक्ताश्रों के हितों की रज्ञा करना। किन्तु इस नीति से कई हानियाँ हैं: (१) यदि मूल्य दरावर गिरते गए तो सरकार को भारी ज्ञित उठानी पढ़ जायगी, (२) संमव है कि सरकार जमा किए हुए गल्ले को वैच न सके श्रीर उसे पर्याप्त समय तक स्टाक में ही रखना पढ़ेगा, श्रीर (३) यदि सरकार किसी श्राना को एक ही मान पर

वैचने के लिए जोर देती है तो सामान्य मूल्य स्तर में कृतिमता उत्पन्न हो जायगी।
यदि कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मूल्य विर जाता है तो इसके फलस्वरूप अन्य
कीमतों में भी कभी आ जायगी। इस प्रकार कय-शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण
किसानों को तो लाम होगा ही, उसके आतिन्क सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी
लाभान्तित होगी पर्योकि खाशाब की कीमतों के निर जाने से सामान्य मूल्य-स्तर
निश्चित रूप से कम हो जायगा।

नियन्त्रए (Controls)-- गरकार की साधान्न तथा श्रन्य माम्यिया पर नियन्त्रण लगाने की नीति की उपयोगिता पर बहुत विवाद चला था। नियंत्रण लगाने का समर्थन करते हुए कहा गया है कि (१) गरीव जनता की फाठिनाइयों की दूर करने के लिए ब्रीर ध्रभाव मस्त चेत्रों की खाद्यान्न मेजते रहने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रण लगाना ग्रावश्यक है। नियंत्रण न लगाने से खाचान को कीमतें बहुँगी और एक्त निर्धन जनता की अनेक कठिनाइयों का रामना करना परेगा, (२) योधना की रफलता के लिए नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि नियोजन श्रीर विनियन्त्रग् (De-control) साय-साथ नहीं चल एकते हैं। किन्तु इन तकीं में इस दात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि स्वयं नियंत्रण लगाने से ही अभाव की स्थिति पदा हो जाती है। यदि नियंत्रण हटा दिया जाय तो बहुत संमय है कि गल्ले इत्यादि के छिपाकर रखे गए स्टाक खुले बाजार में श्राने लगें श्रीर उनके वितरण में सुधार हो जाय जिसके फलस्वरूप अभाव की स्पिति मा दूर हो जाय । चुँकि खाबाब क वही आक्रिके प्राप्त नहीं है, इसलिए की कमी की मात्रा का ठीक पता चला सकता कठिन है। यह कहा गया है कि निनं श्रिधिकारियां पर खाद्यात्र-नियंत्रण लाग् धरने का उत्तरदायित्व है वह श्रभाव को श्रावश्यकता से श्रधिक श्रांकते हैं जिससे यह काफी समय तक उस पर पर कार्य कर सकें। यदि नियंत्रमा हुश दिया जायमा तो यह कृत्रिम स्थिति स्वयं दूर हो नायगी। जहां तक नियोजन का प्रश्न है, यह सच है कि विदेशी न्यापार छीर निदेशी पूँजी पर कुछ ग्रीमा तक नियंत्रण रखना आवश्यक है, परन्तु यही तर्क वादान्न-नियंत्रण पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योजना की कार्यान्वित करने के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस तर्क का कोई महत्व नहीं है कि योजना की सफलता के लिए नियंत्रण का होना आवश्यक है।

यदि नियंत्रण कुरालता पूर्वक लागू किए जाते श्रीर उनको प्रभावशाली यनाने के लिए कड़े उपायों की श्रयनाया जाता तो स्थिति में सुधार होना संभव या, परन्तु भारत में नियंत्रण जितनी श्रधिक कठिनाइयाँ इल नहीं कर पाते उससे कहीं श्रधिक कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं। उपभोक्ताश्रों, न्यापारियों श्रीर दुकान- दारों सभी को अनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है। यदि नियंत्रण लाग् न हो तो विशेष हानि नहीं होती है, परन्तु विंद लागू करके भी उनका कुरालता पूर्वक सचालन न किया जाय तो सुविधा की अपेज्ञा कष्ट अधिक बढ़ जाता है श्रीर हानि भी होती है। यदि इस प्रकार के नियंत्रण को हटा दिया जाय तो निश्चय ही स्थिति में सुधार होगा। फिर जब तक नियंत्रण लागृ रहेगा, देश की श्चायिक व्यवस्था श्रपने सामान्य स्तर पर नहीं श्चा सकती है। सामगी नियंत्रस र्जामाति (Commodity Controls Committee) ने इस बात की छोर ध्यान दिया श्रीर यह बताया कि 'ध्वाचाल में श्रव भी कमी वनी हुई है। इसलिए जब तक यातायात सम्बन्धी कठिनाइयाँ है और प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुभिन्न पड़ने की संभावना बनी हुई है तब तक खाद्यान की अनुभूति व उपलब्ध से सम्बन्धित ग्रादेश (Foodgrains Licensing and Procurement Order, 1952) व अन्य पूरक आदेशी का पालन किया जाना शनिवार्य है? । जैसा कि बाद की स्थिति से ज्ञात होता है, नियंत्रण ने स्वयं ही खायान का श्रभाव उत्पन्न कर दिया था। यद्यपि सामग्री नियंत्रण समिति व श्रन्य लोगों का विचार या कि वर्तमान परिस्थिति में नियंत्रण हटाना संभव नहीं होगा, किन्तु उसे हटा देने से खाद्याच की स्थिति निश्चित रूप से सुघर गई है।

भारत के उस समय खाय-मन्त्री स्वर्गीय श्री रक्षी श्रह्मद किद्वर्द की यह धारणा थी कि खायात्र का नियंत्रण कर देने से स्थिति सुधर जायगी। उन्होंने मई १६५२ को अपने एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि जिन राज्यों में खायात्र का उत्पादन उनकी त्रावश्यकता से श्रिषक हो रहा है वहाँ से नियंत्रण हट जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दो तीन राज्यों के श्रन्वर्गत देहातों में भी रासनिङ्ग (Rationing) है, वह भी हटा लेना चाहिये। किद्वर्ड साहब की इस धारणा का सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही च्रेत्रों में विरोध किया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में श्री धी० राजगोपालाचारी ने श्रीगणेश किया और २६ जून १६५२ को मद्रास से खाद्यात्र नियंत्रण हटा लिया। यह विनियन्त्रण की दिशा में पहला कदम था। कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयाँ श्रवश्य हुई, किन्तु खाद्यात्र विनियन्त्रण में पर्याप्त सफलता मिली। उत्तर प्रदेश, विहार श्रादि कई राज्यों ने मद्रास का

^{9.} सामग्री नियंत्रण समिति की नियुक्ति २४ श्रवट्ट्यर १६५२ की काउन्सिल श्रॉव स्टेट्स के उपसभापित श्री पुस० बी० कृष्णमूर्ति राव की श्रध्यचता में की गई थी। इस समिति ने खाद्याझ का विनियंत्रण प्रारंभ होने के थोड़ा पहिले ही २० जुलाई १६५३ की श्रपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी।

श्रनुसरण किया श्रीर खितावर १९५२ तक यह विनियन्त्रण ६ राज्यों में लागू हो गया। धीरे-धीरे यह जार पकड़ता गया और १६५३ तक केन्द्र व राज्य सरकारी ने खाद्यान के नितरण श्रीर उसके मूल्य पर से नियन्त्रण इटाने का काम बिल्कुल पूरा कर लिया ज्वार, बाजरा, भक्ता, जा जैसे मोटे अनाजों पर से १ जनवरी १६५४ को नियन्त्रण हटा लिया गया; इसके साथ ही इन मोटे श्रनाजों का एक राज्य से दूखरे राज्य में ले जाने पर जा प्रतिबन्ध या वह सीराष्ट्र, मध्यमारत श्रीर उत्तर-प्रदेश के ११ जिलों को छोड़कर सभी जगहों से हट गया। बाद को यह प्रतिवन्य भी हटा लिया गया। चावल का विनियन्त्रण १० जुलाई १९५४ से लागू किया गया। उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहां रहा है श्रीर श्रव देश के सभी भागों में उसका व्यागर स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा एकता है। अभी तक चावल अनिवार्य रूप से प्राप्त करना पहता था, किन्तु विनियन्त्रण लागू होने से यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त चावल के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण भी वन्द हो गया है।
"जिस क्रमिक विनियन्त्रण (Gradual de-control) को राजा जी

१६५२ में प्रारम्भ किया था, यह चायल का पूर्ण विनियन्त्रण हो जाने के उपरान्त अपनी चरमावस्था पर पहुँच गया"। अतर-प्रदेशीय प्रतिबन्ध जो गेहूँ के एक स्पान से दूसरे स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में लागू किया गया था वह नियंत्रण का ख्रोतिम कर था ख्रीर १८ मार्च १६५५ से वह भो उठा लिया गया। इससे १०

वर्ष तक लागू नियन्त्रण का ख्रंत हो गया। विनियन्त्रण के समर्थकों ने यह खाशा दिला रखी थी कि खादाल-नियन्त्रण के फलस्यरूप अकाल, खाद्यात्र के सम्बन्ध में स्थानीय अमाव ((Local scarcity) ग्रीर ग्रन्य ग्रापत्तियाँ उत्पन्न हो जार्येगी, किन्तु भाग्यवश ऐसा कुछ मी घटित नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि खाद्यान नियन्त्रण देने कारण श्रव के श्रमाव को कृतिम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं श्रीर जिन श्रिध को साद्यास-नियन्त्रण का कार्य-भार सीवा गया था, स्वार्थरत होकर श्रवना हित साध रहे ये। नियन्त्रण हट जाने से (१) खाद्यान का श्रमाय होने की जो मनः हिथति बन गई थी वह दूर हो गई। इसक श्रातिरिक्त मुनाफा खारी श्रीर चोरवानारी का भी भन्त हुआ, (२) देश में खःरान के वितरण की स्थित सुघर गई, (३) खादान का माव कम हो गया जिसक फलर का लागा के रहन-सहन की लागत घटी श्रीर किसानों को भी श्रधिक उत्पादन करने में प्रवृत्त होना पड़ा, जिससे वे उतनी आय का उपार्जन कर सकें जी उन्हें पहले प्राप्त हो रही थी, (४) केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा खाद्याल नियन्त्रम् व राशनिङ्ग पर जो ब्यय होता था उसमें

कमी आ गई। विनियन्त्रण से यदि कोई हानि हुई है तो यही कि खादाज़ नियन्त्रण और राशनिङ्क विभाग के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गये और मुनाफाखोरों व चोरबाजारी करने वालों की आप का एक बहुत बड़ा साधन छिन गया।

खाद्य स्थिति विगद्रते जाने के फलस्वरूप १६५६ में चावल तथा गेहूँ के मएडल (zone) निश्चित करके, उचित मूल्य पर बेचने वाली दृकानों द्वारा विकी करके तथा खाद्यान्न के न्यापार एवम् लाने-ले जाने पर प्रतिवन्य लगा कर चीमित नियंत्रण फिर से लागू किया गया। चरकारी श्रिष्कारियों की एक वर्ग पूर्ण नियंत्रण के पन्न में है तथा योजना श्रायंग के श्रर्थशास्त्रियों ने भी इस विचार का समर्थन किया। किन्तु, जैसा कि हम करर संकेत कर जुके हैं, खाद्याल जाँच कमेटी के नियंत्रण के विरुद्ध सिफारिश की।

ऋध्याय ६

जमींदारी उन्मूलन

श्रार्थिक दृष्टि से जमींदारी उन्मूलन का विशेष महत्व है। श्रांखिल मारतीय कांग्रेस कमेटी की श्रार्थिक नीति का यह सदैव महत्वपूर्ण ग्राधार रहा है। विशेषज्ञों की श्रनेक समितियों ने भी समय-समय पर जमींदारी का उन्मूलन करने की सिफारिश की। १६४७ में भारत को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन को श्रपने श्रार्थिक कार्य-क्रम का महत्वपूर्ण श्रंग बना लिया श्रीर धीरे-धीरे सभी राज्यों में इस नीति को लागू किया है। बहुत से राज्यों ने, जहाँ जमींदारी या इसी के श्रनुरूप कोई श्रन्य प्रथा प्रचलित थी, इन विशेषाधिकारों का उन्मूलन करने के लिए कानून बनाए हैं श्रीर उत्तर प्रदेश तथा विहार ने तो जमींदारी का उन्मूलन कर उन पर श्रपना कठना भी कर लिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन सरकारों ने मुश्रावजा देकर जमींदारी-उन्मूलन करने की नीति श्रपनाई है श्रर्थात् सरकार ने जमींदार को उसकी जमीन के बदले उपयुक्त मुश्रावजा (Compensation) दिया है। ३१ मार्च १६५६ तक जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो गया तथा ४,३६ करोड़ एकड़ श्रयवा राज्य की ६६. प्रतिशन कृषि जीतों पर भूमि सुधार के उपाय लागू किये गये।

उत्सूलन के पत्त में तर्क जमीदारी उत्सूलन करने के समर्थन में अनेक तर्क दिए गए हैं। यह कहा गया है कि नमीदार किसानो का शोषक (Parasite) है और उसने अपने कब्जे की नमीन में कुछ सुधार नहीं किया, भूमि की चक-बन्दी (Consolidation of holding) करने में सदैव रकावट डाली है श्रीर किसान को जा जमीन जीतता बोता है भूम सुधार के लिये अपनी अनुमित नहीं दी है। यदि जमीदार को हटा दिया जाय तो भूमि में सुधार किया जा सकेगा, खादान्त्र के उत्पादन में वृद्धि होगी और भूमि सुधार योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा जिसकी बहुत समय से आवश्यकता अनुमन की जा रही है। यह तर्क बहुत श्रंशों में सही है, फिर भी इस तथ्य को टाला नहीं जा सकता है कि कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिन पर जमीदार का बश नहीं है श्रीर यदि वह वश में रखना भी चाहे तो सफल नहीं हो सकता।

जमीदारी उन्मूलन का समर्थन करते हुए यह भी कहा गया है कि इससे राज्य की भू-राजस्व (Land revenue) श्राय बढ़ेगी । यह तर्क बिल्कुल सही है क्योंकि १६५१-५२ में राज्यों की भ्-राजस्व से आप ४० ६६ करोड़ रुपये थी जो चढ़कर १६५७-५८ में (बजट के अनुसार) ६२ ५४ करोड़ रुपये हो जायगी। इससे राज्य सरकार मुआवजे की किश्त चुकाने के बाद अपनी भूमि मुधार तथा आम-पुनर्निर्माण (Rural reconstruction) योजनाआं को लागू कर सर्केंगी। परिणामस्वरूप देश के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी और किसान की स्पिति में सुधार हो सकेगा।

जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न श्राधिक होने के साथ ही राजनीतिक भी सताया गया है। देश के मतदाताशों में किसानों की संख्या बहुत श्रिष्ठ है। किसान वर्तमान स्थिति से बहुत श्रिसन्तुष्ट हैं श्रीर उनका विचार है कि उनको इस दयनीय स्थिति तक पहुंचाने के लिए केवल जमींदार हो उत्तरदायी हैं। यह सर्वविदित है कि जनतंत्र प्रणाली में बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है चारे उनका हिण्डकोण कुछ भो हो। इस्र लिए किसानों के श्रमन्तीय को कम करके उनका मत श्रमुक्ल करने के लिए जमींदारों उन्मूलन को एक साधन बनाया गया है। पिछले वैर-माच की प्रतिक्रिया के रूप में किसान भविष्य में लागू की जाने वाली किसी मी भूमि सुधार योजना में जमींदारों के साथ सहयोग नहीं करेंगे इस्र लिए भूमि सुधार योजनाएँ तभी सफल हो सकती हैं जब किसानों तथा राज्य संरकार के मध्यस्तों का उन्मूलन कर दिया जाय।

जमींदारी उन्मूलन के बिरुद्ध तर्क—जमींदारी उन्मूलन के विरोध में भी अनेक तर्क दिये गये हैं परन्तु उनमें जान नहीं है। यह कहा गया है कि जमींदार के उन्मूलन से बहुत बड़ी संख्या में लोग वेरोजगार हो जायेंगें, जैसे, जमींदार, उनके जिलेदार, कारिन्दे इत्यादि। इससे केवल जमींदारी की आय पर निर्भर करने वाला वर्ग बहुत कि किसी भी परिवर्तन के साथ कुछ कि उत्तर में यह कहा जा सकता है कि किसी भी परिवर्तन के साथ कुछ कि नाई और अव्यवस्था का होना जलरी है और इस कि किमी अवस्व में महत्व तो इस बात का होता है कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। वास्तव में महत्व तो इस बात का होता है कि परिवर्तन से क्या लाम होगा अथवा उसका क्या परिग्राम होगा। यह सही है कि जमींदारी का उन्मूलन कर देने से जमोंदारा को कि उनाइयों का समना करना पढ़ेगा परन्तु इससे किसानों की दशा में सुधार भी होगा और दीर्घंकालिक दिक्ताण से यह लाभदायक सिद्ध होगा। जमींदारों के कारिन्दे इत्यादि कर्मचारी आरम्भ में बेरोजगार हो जायँगे परन्तु बाद में उन्हें रोजगार मिल सकता है क्योंकि सरकार को लगान वस्त करने के लिए सथा अन्य कारों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमींदारों की कि उनाइयों का प्रशन है व्यारियों की आवश्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमींदारों की कि उनाइयों का प्रशन है व्यारियों की आवश्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमींदारों की कि उनाइयों का प्रशन है

सरकार जमींदारी के बदले उन्हें मुश्रावजा देगी श्रीर उन्हें श्रपने जीवन निर्वाह के लिये खयं श्रन्य साधनों की खोज करनी चाहिए।

यह भी कहा गया है जमींदारी का उन्मूलन हो जाने से किसान को कई पकार से हानि पहुँचेगी। इस समय सामाजिक तथा अन्य कार्यों के लिए जमीदार किसानों को ऋरण देता है, लगान वसूली में वह किसान की परिस्थितियों का ध्यान रखता है और उसे श्रदायगी के लिये समय देता है परन्त सरकार के कर्म-चारी किसान को यह सुविधा नहीं देगें। केवल जमींदारी का उन्मूलन कर देने से ही भूमि सुधार सम्भव नहीं है: यदि सारी घटनाओं को इसी प्रकार घटित होने दिया जायगा तो देश को लाभ होने की अपेना अधिक हानि होगी। इसमें कुछ, सन्देह नहीं कि किसान की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा परन्तु यदि कार्य का सुचार-रूप से संचालन किया गया तो किसान की दशा श्रीर अधिक विगड़ जाने की कोई सम्भावना नहीं। आवश्यकता पड़ने पर किसान को कम सूद पर ऋण देने के लिये विशेष संस्थाएँ स्थापित की जा सकती हैं। यदि जमीदारी का उन्मूलन न किया गया तो जिस भूमि सुधार की बहुत समय से आवश्यकता अनु-मव की जाती रही है वह कभी लागू न हो सकेगा । जमींदारी उन्मूलन से जो श्रव्यवस्था पैदा होगी उसका सामना करना पहेगा श्रीर जितना शीघ यह हो सके उतना ही अच्छा है। इससे सुधार करने के लिये मार्ग खुल जायगा श्रीर कुछ समय तक अस्थायी अञ्यवस्था के पश्चात् भूमि का उत्पादन बढ़ेगा; किसान की दशा सुधरेगी श्रीर देश की श्रार्थिक समृद्धि बढ़ेगी।

उन्मूलन योजना—जमींदारी उन्मूलन कार्य "श्रस्थायी वन्दोबस्त वाले चेत्र में श्रपेद्धाकृत सरल था, जैसे उत्तर प्रदेश श्रीर मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ श्रावर्यक लेखा तथा इस कार्य को करने याले श्राधिकारी उपलब्ध थे। स्थायी घन्दोबस्त वाले चेत्रों में जैसे बिहार, उड़ीसा श्रीर पिछ्छमी बंगाल तथा जागीरदारी चेत्रों जैसे राजस्थान श्रीर सीराष्ट्र में सब लेखा तैयार करना श्रीर नये सिरे से श्राधिकारियों की नियुक्ति श्रावश्यक थी। जो कुछ भी हो मध्यस्थों को हटा देने के कानून श्राधिकारिय प्रदेशों में लागू कर दिये गये हैं"।

जमीं टारी उन्मूलन में साधारणतया निम्न उपायों का प्रयोग किया गया है: (१) वे भूमि के भाग जो परती पड़े थे, जंगल, श्रावादी के चेत्र, श्रादि जो यह परयों के श्रिधकार में थे, प्रवन्ध श्रीर सुधार के लिये सरकार के श्रिधकार में दे दिये गये। (२) खुदकाशत की भूमि तथा निजी काम के चेत्र, जिनकी देख-रेख स्वयं जमींदार ही करते थे उन्हीं के श्रिधकार में रहने दिये गये श्रीर वे काशतकार जिन्होंने ऐसी भूमि पट्टें पर जमींदारों से ले रक्खी थी काशतकार (tenant) की हैसियत से उन्हीं के श्रिषकार में छोड़ दी गई। (३) बहुत से राज्यों में प्रधान श्रासामी जिन्हें मध्यस्थों से सीचे भूमि प्राप्त थी सीचे राज्य की सरकारों से सम्बन्धित कर दिये गये। वम्बई, हैदराबाद श्रौर मैस्तर में इनामों से प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू की गई थी। इन प्रदेशों में मध्यस्थों को श्रासामियों से लेकर कुछ भूमि दी गई। कुछ प्रदेशों में श्रासामियों को स्थायी तथा हर्स्तांतरण का श्रिषकार प्राप्त था, इसलिये श्रव यह श्रावश्यक नहीं था कि उन्हें श्रीर श्रिषक श्रिषकार प्रदान किये लायें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर श्रीर दिक्षी राज्यों में श्रासामियों को भूमिवारी श्रिषकार प्राप्त करने के लिये उसका मृल्य चुकाने का श्रवसर दिया गया। श्रान्त्र, मद्रास, राजस्थान, संराष्ट्र (खाली चेन्न) व मध्य मारत, हैदराबाद (जागीर चेन्न) श्रीर श्रजमेर में या तो श्रासामियों के श्रिषकार बढ़ा दिये गये श्रथवा उनका लगान वटा दिया गया श्रीर उनसे कोई मृल्य नहीं वस्ता गया। ना

"मध्यस्यों को दिये जाने वाले मुश्रावजे श्रीर पुनर्वास में सहायता के रूप में दी जाने वाली रकम का श्रानुमान लगभग ४५० करोड़ रुपया लगाया गया है। इस रक्षम का ७०% केवल उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में दिया जाने वाला मुश्रावजा है।

मुखावजे का खिवकार-विमित्र जमीदारी उत्मूलन कानूनों में मुख्रावजे के विभिन्न श्राधार दिये गये हैं। श्रासाम, विहार, उड़ीसा श्रीर मध्य प्रदेश में मुझा-वजे का त्राघार भूमि से पाप्त होने वाली 'वास्तविक त्राय' (net income) है ! उत्तर प्रदेश में यह श्राधार 'वास्तविक सम्मत्ति' (net assets) श्रीर मद्रास में मूल-भूत वार्षिक ग्राय' (Basic annual sum) है। वास्तविक ग्राय ग्रीर वास्तविक सम्पत्ति के ब्राघार लगभग समान ही है। जमींदारी की कुल ब्राय में से भूराजस्व उपकर (cess), पवन्च का व्यय, रैय्यत के लाभ के लिये किये गये कार्यों में च्यय श्रीर कृषि श्रायकर इत्यादि बटाकर ही वास्तविक श्राय (net income) निकाली नाती है। प्रवन्घ श्रीर रैट्यत (ryot) के लाम के लिये किये गए कार्य में लो रकम व्यय की जाती है वह सभी राज्यों में समान नहीं है। वास्तविक आय निश्चित करने के पश्चात् इसी आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है। मद्रास में 'मूलभूत वार्षिक श्राय' निकालने के लिए रैय्यतवाड़ी से प्राप्त वार्षिक त्राय के एक तिहाई भाग में से पाँच प्रतिशत कर्मचारियों पर व्यय करने श्रीर वस्ली न हो सकने के लिए अलग कर दिया जाता है और ३ व प्रतिशत सिंचाई व्यवस्था को चलाने के लिये काट लिया जाता है। इससे जो श्राय शेष रहती है वही 'मूलभूत वार्षिक आय' कहलाती है। यह ढंग अन्य राज्यों से भिन्न है क्योंकि मुत्रावजा जमींदार से प्राप्त होने वाली वर्तमान वास्तविक श्राय पर श्राधारित न होकर रव्यतवादी प्रधा लागू होने के बाद भू-राजस्व के २५ प्रतिशत पर श्राधारित होगा।

उत्तर प्रदेश में मुश्रावजे की दर वास्तविक सम्मित्त का श्राठ गुना है। इसके साथ ही जो जमींदार १०,००० क्पये से श्रिषक भू-राजस्व नहीं देते उनको जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वास्तविक सम्पत्ति के २० गुने से लेकर एक गुना तक पुनर्वास श्रमुदान दिए जायँगे। यह अनुदान कम श्राय वाले जमींदारों के लिये सबसे श्रीषक गुने होगे श्रीर श्रीषक श्राय वालों के लिये कमशः कम होते जायँगे मध्यस्थों को दिया जाने वाला मुश्रावजा तथा पुनर्वास श्रमुदान का श्रमुमान कमशः ७५ करोड़ स्पया तथा ७० करोड़ स्पया है।

मुत्रावणे के जुकाने में सबसे श्रिषक विचारणीय बात यह है कि मुश्रावणा नकद दिया जाय या वेचे न जा सकने वाले बाएडों के रूप में । जमींदारों के दृष्टि-कोण से यदि मुश्रावजा नकद दिया जाता तो सर्वोत्तम होता क्यों कि इससे वह कोई नया कारोबार खोलते या उद्योगों में रुपया लगाते जिससे उन्हें बरावर श्राय होती रहती। परन्तु मुश्रावणे की रकम को नकद श्रदा करना संभव नहीं है क्यों कि राज्य सरकारें इतना श्रिषक धन नकद देने की ज्यवस्था नहीं कर सकती है। उनके पास इसके मुगतान के लिए रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहाँ जमींदार उन्मूलन कोष का निर्माण किया गया है, किसानों को श्रपने लगान का १० गुना जमा कर भूमिधारी श्रिषकार लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है फिर भी श्रभी तक बहुत कम रुपया इकड़ा हो सका है। मुश्रावजा वेचे न जा सकने वाले बाएडों के रूप में दिया गया। परन्तु इस विधि से जमींदार के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं होता है क्योंकि जमींदारों को उनके मुश्रावजे की रकम श्रीर उस पर व्याज का सुगतान काफी लम्बे समय में किया जायगा श्रीर इस बीच श्रपना वर्तमान खर्च चलाने में तथा कोई नया कारोबार स्थापित करने में जमींदारों को बहुत कठिनाई होगी।

श्चन्य प्रगाली—जमींदारी उन्मूलन कर देने से ही खारी समस्या का इल होना संभव नहीं है। यदि इसके बाद भूमि सुधार लागू नहीं किए तो जमींदारी उन्मूलन का लाम नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य समस्याएँ यह हैं: (१) जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि पर श्चिषकार की व्यवस्था, (२) कृषि के रूप (form of cultivation), श्चीर (३) भू-राजस्व वस्न करने के लिए श्चीर चरागाह, वंबर जैसी जमीन की देख-रेख करने के लिए सरकार की श्चीर से निर्धारित उपयुक्त संस्था।

श्रव तक भूमि सुघार का मुख्य उद्देश्य कृपक को स्वामित्य के श्रधिकार प्रदान करना था। भूमि के इस्तांतरण के सम्बन्ध में भूस्वामी के श्रधिकारों पर कुछ प्रांतवन्य इसलिये रखे गये हैं ताकि लोतें बहुत बढ़ी या बहुत छोटी न हो लाँय श्रीर भूमि गैर-कृपकों के हाथ न चलो लाय। "भूमि मुघार के उपयों के लागू होने के बाद लमींदारी श्रीर लागीरदारी लेशों से श्रधिकांश कृपकों के भूमि सम्बन्धी स्वामित्व के, श्रधिकार प्राप्त कर लिये हैं। इस प्रकार मींवर्धी रैय्यत (occupancy raiyat), नियत लगान वाले रैव्यत श्रादि भू-स्वामी वन गये। गैर मींक्सी रैव्यत श्रार रैव्यत के नीचे वाले किसान, सामान्यतः मूल्य चुकाकर ही भूस्वामी वन सकते हैं। यह सब तथा पूर्ववर्ती मध्यस्य जो श्रयनी सीर श्रीर खुदकारत के मालिक बने हुये है। श्रधिकतर राज्य के काश्तकार कहलाते हैं किन्तु वास्तव में वे श्रयनी भूमि के स्वामी है श्रीर उनके श्रधिकार रैव्यतवारी चेत्रों के भू-स्वामियों की तरह ही हैं।"

श्राधकांश राज्यों में भूस्वामियों को श्रपनी भूमि वेचने का श्राधकार है यद्यपि इस पर कुछ प्रतिवन्ध श्रवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रर, मध्यप्रदेश में भूमि स्वामी श्रीर भूमिषारी, विहार में भूस्वामी श्रीर मीठिंश काश्तकार, पश्चिमी बंगाल में रैट्यत, श्राखाम में भू-स्वामी, विशेष श्रधिकार प्राप्त रैट्यत, में किशी रैट्यत, लगान या सदैव के लिये निश्चित लगान देने वाले काश्तकार, हैटराबाद श्रीर वम्बई में भूमि वाले किसान, पंजाव में भूस्वामी श्रीर मीठिंशी काश्तकार, उड़ींशा में भू-स्वामी श्रीर मीठिंशी काश्तकार, उड़ींशा में भू-स्वामी श्रीर मीठिंशी काश्तकार, पंप्यू में भू-स्वामी, राजस्थान में खातेदार काश्तकार, मध्यमारत में पबके काश्तकार इत्यादि तमी को श्रपनी भूमि वेचने के श्रिषकार प्राप्त हैं। भूमि वेचने पर इस प्रकार के प्रतिवन्ध श्रवश्य हैं जैसे (श्र) किस प्रकार के व्यक्तियों को भूमि वेची जा सकती हैं (व) किस सीमा तक भूमि वेची जा सकती है, खरीदी भूमि के लिये श्रिषकतम सीमा होती है तथा वेचने वाले के पास श्रेष भूमि के लिये निम्नतम सीमा होती है। "

"श्रनेक राज्यों में गैर-कृपकों को भूमि वेचने की मनाही है। वस्तई हैदराबाद, मध्यभारत श्रीर सौराष्ट्र में कानूनन गैर कृपकों को भूमि वेचने की श्राशा नहीं है। वस्त्रई श्रीर पश्चिमी वंगाल में श्रनुमित प्राप्त खरीदारों की प्राथमिकता का क्रम निश्चित है। प्राथमिकता में पहला नम्बर उन काश्तकारों का है जो मूमि पर वास्तव में काबिज हैं। इसके बाद पड़ोसी कृपकों का नम्बर हैं तथा इसी तरह लोगों का क्रम निश्चत है।"

"उत्तरप्रदेश में यद्यपि भूमिधार को अपनी जोतों को वेचने का अधिकार है किन्तु इस पर यह प्रतिवन्घ है कि धार्मिक संस्था के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर खरीदने वाले की जोत ३० एकड़ से श्रिष्ठिक न हो जाय। वम्नई में यह सीमा १२ एकड़ से ४८ एकड़ (जो भूमि की किस्म पर निर्भर है) है। हैदराबाद में यह सीमा परिवारिक जोत की तीन गुनी है। मध्यभारत में यह ५० एकड़, पश्चिमी बंगाल में २५ एकड़ (जिसमें घर से संलग्न खेत नहीं शामिल हैं) दिल्ली में ३० स्टेन्डई एकड़, राजस्थान में ६० श्रिष्ठित एकड़ या ३० सिंचित एकड़, श्रासाम में एक परिवार के लिये १५० वीवा (४६ दे एकड़) तथा सीराष्ट्र में तीन श्रार्थिक जोत है।"

बम्बई, हैदराबाद श्रीर मध्यभारत में ऐसी कोई भूमि नहीं वेची जा सकती जो वेचने वाले की जोत को निर्घारित सीमा से कम कर दे। उदाहरण के लिये बम्बई में कोई भी जोत वेचकर या किसी श्रन्य प्रकार इस तरह विभाजित नहीं की जा सकती कि उसके (एक गुंटा या चार एकड़ सीमा भूमि पर निर्भर है) हुकड़े हो जाँय। हैदराबाद में एक (स्टेन्डर्ड) निश्चित चेत्रफल निर्धारित करने की व्यवस्था किसी भी हालत में भूमि इससे कम चेत्रों में नहीं विभाजित की जा सकती। इसी प्रकार मध्व प्रदेश में पक्का काश्तकार श्रपनी भूमि तभी वेच सकता है जब कि वह श्रपनी कुल भूमि वेचने से तैयार हो श्रथवा बेचने के बाद उसके पास ५ सिचित एकड़ या १५ श्रिसंचित एकड़ सूमि बचरही हो।"

इन सब प्रतिबन्धों के बावजूद भी, श्रिषकांश राज्यों में जमीदारी उन्मूलन के परचात् कृषकों का भू-स्वामित्व हो जायगा तथा प्रत्येक किसान श्रपनी जमीन जोतेगा। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी सीमा तक जमीदारी उन्मूलन के लाभ व्यर्थ हो जाँथेगे। कृषक के पास श्रपनी भूमि में सुधार करने तथा कृषि के सुधारे हुये दंगों का प्रयोग करने के लिये साधन नहीं है।

भूमि से उत्पादन की मात्रा तभी बढ़ाई जा सकती है जब बड़े चित्रों में खेती की जाय थ्रीर श्रावश्यकंता पढ़ने पर मशीनों का उपयोग किया जाय। उत्पादन में वृद्धि होने से किसान की श्राय में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश कान्न में दो तरह की सहकारी-कृषि प्रणालियों की न्यवस्था की गई है-(१) ५० एकड़ या श्रिषक के ऐसे छोटे फार्म जो १० या श्रिषक किसानों ने स्वेच्छा से समसीता करके बनाए हों श्रीर (२) श्राधिक दृष्टि से श्रनुपयुक्त जमीनों को मिलाकर संगठित सहकारी फार्म। यदि दूसरे प्रकार के फार्म के कुल सदस्यों के दो तिहाई यह माँग करते हैं कि इन छोटे फार्मों को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाया जाय तो शेष एक तिहाई को श्रानिवार्य रूप से यह माँग माननी पड़ेगी। परन्तु इससे समस्या नहीं सुलम्म सकती। सहकारी फार्म की प्रणाली लागू करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ेगा।

श्रध्याय ७

भृमि की चकवन्दी

भारत में मृमि को छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त कर देने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत के किसान भूमि के छोटे-छोटे अलग-अलग विखरे हुए दुकड़ों में खेती करते हैं जिससे खादान्न तथा अन्य सामग्री का उत्पादन कम होता है श्रीर किसान की गरीबी बढ़ती जाती है। इसके श्रानेक कारण हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार है, (१) भूमि पर जनसंख्या का द्याय श्रीर मीरुसी इक सम्बन्धी कानून । परिवार के प्रधान के मरने पर जमीन उसके पुत्रों तथा श्रान्य सम्बन्धियों में बाँट दा जाती है। बाँटते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि इन भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों से हिस्सेदारी का जीवन-निवाह नहीं हो सकेगा, इनमें बो कुछ उत्पादन होगा उससे वह अपना भरण-पोपण नहीं कर सकेंगे। (२) किसान के ऋणी होने तथा श्रन्य कारणों से भूमि का विक जाना। भारत के किसान ऋण के बोक्त से दब लाने के कारण ऋपनी जमीन रेहन रख देते हैं श्लीर भ्रम्ण न चुका सकने पर उस जमीन को भ्रम्णदाता वेच देता है या स्वयं ले लेता है; इससे जा जमान पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में थी श्रव श्रीर श्रिथक विभक्त हों जाता है। यदि किसान के संयुक्त परिवार के एक सदस्य का दिस्सा ऋगा न ् चुका सकने अथवा अन्य किसी कारण से वेच दिया जाता है तो रोप भूमि कम हो जाती है स्रौर जब उसका विमाजन किया जाता है तो वह स्रीर छं।टे छोटे दुकड़ों में बँटती जाती है। (३) किसान इस बात से अनिभन्न है कि भूमि का छोटे-छोटे हिस्सों में वंट जाना बुस है। यह अनुभव किया गया है कि किसान भूमि की चकवन्दी के लिये शीघ तैयार नहीं होता। इसके लिये उसे काफी समक्तना पड़ता है श्रीर दबाव डालना पड़ता है। भूमि की चकवन्दी से उत्पादन बहुता है तथा ऋपक की विता भी कम हो जाती है इससे हम छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त होने की गर्म्भार समस्या को ही हल नहीं कर लेते बल्कि ग्राम योजना में, खेल के मैदान, स्कूल, गढ़े श्रादि बनाने में भी सहायता मिलती है।

हानियाँ भूमि का विभाजन श्रीर उसका छोटे-छोटे टुकड़ों में यट जाना एक गम्भीर दोप है। इसते श्रनेक हानियाँ होती है: (१) इससे भूमि में सुधार नहीं किया जा सकता। भूमि छोटे टुकड़ों में वँटी होने के कारण किसान श्रपनी स्त्रेती के लिये न कुश्राँ खोद पाता है, न मशीनों का उपयोग कर पाता है श्रीर न अन्य प्रकार के सुधारों को ही लागू कर पाता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ने पाती और उत्पादन गिरता जाता है। (२) भूमि के छो-छोटे हकड़ों में बैंटे रहने के कारण बहुत सी जमीन एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिये मेढ़ बाँधने में ब्यर्थ नण्ड हो जाती है और भूमि के हकड़े बिखरे होने के कारण किसान अपनी खेती की अच्छी तरह देख-माल भी नहीं कर पाता है। इससे फसल में गहरी हानि होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। और (३) किसान को एक भाग से दूसरे माग में आने-जाने में ही बहुत सा समय नष्ट करना पड़ता है।

यह कहा गया है कि भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में वॅटे रहने से किसान को लाभ है क्योंकि इससे गाँव के अनेक भागों में प्रत्येक किसान की कुछ न कुछ भूमि रहती है। यदि बाह तथा टिल्डी इत्यादिका संकट आ जाय तो उसकी सारी भूमि नध्ट होने से बच जाती है। यदि एक भाग इस संकट से नष्ट भी हो जाय तो अन्य भाग दूर होने के कारण बचाये जा सकते हैं। दूसरा लाम यह बताया जाता है कि भूमि के इस प्रकार के बँटवारे से गाँव की श्रिषकांश जनता के पास भूमि हो जाती है। यदि यह बँटवारा न किया जाय तो बहुत से ग्रामीण बिना भूमि के रह जायेंगे। परन्तु ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से पता चलेगा कि यह दोनों लाभ काल्यनिक हैं। ऐवा बहुत कम संभव है कि प्रकृति के कीप से गाँव का एक ही भाग नष्ट हो और शेष भाग बच जाय। यदि कमी ऐसा हुआ भी तो इससे किसान को बहुत कम लाभ होगा; वर्षों से छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती करने से किसानों को जो हानि होती है वह इस संभावित लाभ की अपेदा कहीं अधिक है। श्रीर जहाँ तक मूमि-विहीन मजदूरों का प्रश्न है यह भूमि के बँटवारे या उसे छोटे छोटे हिस्सों में विमक्त करने से इल नहीं किया जा सकता है। वास्तव में मुख्य समस्या यह है कि किसान को इस योग्य बनाया जाय कि वह रहन-सहन का एक उचित स्तर बनाये रख सके । कुल परिवार के पास संयुक्त रूप से जितनी भूमि है यदि उसका उसके सदस्यों में विभाजन कर दिया नाय श्रीर पत्येक सदस्य को कुछ न कुछ भूमि दे दी जाय तो इससे रहन सहन का उचित स्तर नहीं रखा ना सकता। इन छोटे-छोटे भागों से किसान अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकने में श्रमभर्य होता है। यदि भृमि का इस प्रकार केंटवारा न किया जाता तो शायद वह श्रसमर्थ न होता। भूमि-विहीन मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए सरकार को श्रन्य उपायों से काम लेना पड़ेगा।

यह खेद की बात है कि भूमि के बँटवारे और उसके छोटे-छोटे भागों में विभक्त हो जाने की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। कृषि सम्बन्धी रायल कमीशन (Royal Commission on Agriculture) की रिपोर्ट से वेचल यह सूचना मिलती है कि विभिन्न राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति के पास श्रीसतन कितनी जमीन है। इस सूचना में समस्या की पूर्ण जानकारी नहा होती। किसानों के पास श्रीसत भूमि उत्तर प्रदेश, मद्राम, तियां कुरकोर्च न श्रीर हिमांचल प्रदेश में श्रन्य त्तेत्रों की श्रपेना कम है। उत्तर प्रदेश में भूमि प्राप्त कुल व्यक्तियों में ते ८१ र प्रतिशत के पास ५ एकड़ ते कम भूमि है श्रीर यह कुल काश्त की जाने वाली भूमि का इट'ट प्रतिशत है।

मद्रास में दर र प्रतिशत के पास १० ध्यया या हमसे कम वार्षिक लगान की भूमि है जो काश्त की जाने वाली भूमि का ४१ र प्रतिशत है। प्रविक्त को चीन में ६४.१ प्रतिशत के पास ५ एकड़ ने कम भूमि है जो छुल काश्त की जाने वाली भूमि ४४ प्रतिशत है। श्रम्य राज्यों में भी यह समस्या गर्म्भार है। श्रीर इसते किसानों को श्राय में हानि महनी पड़ी है।

रीति (Methods)—भूमि की चक्रवन्टी करने की टी मुख्य रीतियों है इ (१) स्वयं किलानों में परम्परा स्वेच्छापूर्वक सहयाग की भावना के द्वारा और (२) सरकार द्वारा चक्रवन्दी श्रनिवायं कर देने ने । जहाँ तक स्वेच्छापूर्वक सहयोग करने का प्रश्न है इसमें काफ़ी देर लगती है और चक्रवन्टी का कार्य में मक्रावट पैटा कर देने हैं। इसके साथ ही किलानों का यह सममाना बहुत कठिन है कि चक्रवन्दी से उनका लाभ होगा। किसान न तो श्रपनी भूमि छोड़ने के लिए तैयार होता है और न इस काम में छोड़ा-मोटा ब्यय करने की राजी होता है। परन्यु यदि भूमि की चक्रवन्दी श्रनिवायं कर दी जाय तो किसान इसका विरोध करता है। वह, समम्ता है कि भूमि की चक्रवन्दी से उसके हितों को चोट पहुंचेगी। यदि चक्रवन्टी योजना को लागू करने वाले कर्मचारी कमजोर श्रीर श्रकुशल हुए हुए तो श्रनेक कठिनाइयाँ पैदा हो जाने की संभावना रहती है। परन्यु स्वेच्छान् पूर्वक सहयोग करके भूमि को चक्रवन्दी कराने का परिष्ठाम निराशाजनक ही रहा है इसलिए इस योजना को श्रनिवायं कर देने से हो श्रधिक लाभ हो सकने की संमावना है।

है हिए दिशा में भूमि की चकवन्दी प्रथम प्रयास है। वास्तव में प्रयत्न इस वात का करना है कि भूमि का और बटवारा न हो अन्यथा चकवन्दी से कुछ लाम संमय नहीं। यदि भूमि छोटे दुकड़ों में बँटतो गई तो चकवन्दी का उद्देश्य ही विफल हो जायगा। भूमि को चकवन्दी के प्रश्न का इस बात से गहरा सम्बन्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी एकइ भूमि रख सकता है। "उत्तर प्रदेश में कम से कम सीमा ६ है एकड़ भूमि प्रति व्यक्ति रक्खी गई है, मध्य भारत में यह सीमा सिचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के लिये ५ एकड़ और जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है वहाँ १५ एकड़ निश्चित की गई है। आसाम में पंचायत एकट के अनुसार पचायत को अधिकार है कि यदि उन लोगों में से जिनके लिये यह निर्माण किया जा रहा है हु इस बात पर राजी हो जायँ तों अत्येक किसान के लिये कम से कम भूमि की सीमा १२ बीधा निश्चित कर सकते हैं। वम्बई, पंजाब और पेष्सू में चकवन्दी एकट ने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे जितना भी उपयुक्त समके प्रति किसान भूमि की सीमा निश्चित कर दें। वम्बई की सरकार ने इसिय भूमि की विभिन्न न्यूनतम सीमायें १० गुन्ठे से लगा कर ६ एकड़ तक अपने विभिन्न जिलों में नियत कर दो हैं। इन सब राज्यों में ऐसे बटवारों पर रोक लगा दो गई है जिनके परिखाम स्वरूप वेंट कर न्यूनतम सीमा से कम हो जायगी"। यदि ये प्रतिबन्ध न लगाये जायँ तो चकवन्दी के लाभ मविष्य, में होने वाले बँटवारे के कारण न मिल स्वरेंगे।

कानुन--वम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाव, उत्तर प्रदेश, पेप्स, जम्मू और काश-मीर में चकवन्दी के सम्बन्ध में विशेष कानून पास किये गये हैं। देहली ने पंजाब एक्ट को अपना लिया है और उड़ीसा ने १६५१ के एमीकल्चर एक्ट में कुछ .चकवन्दी सम्बन्धी नियम जोइ दिये हैं। हैदराबाट, सीराष्ट्र, बिलासपुर श्रीर राज-स्थान में इस सम्बन्ध में कानून विचाराधीन है। आरम्भ में कानून अनुमति प्रदान करने वाले (Permissive) ये श्रीर विशेष पदाधिकारियों के द्वारा श्रदला बदली में सहायता तथा छूट श्रादि का प्रबन्ध करते थे। बहाैदा एक्ट इसी ढंग का था। सहकारी समितियाँ किसानों के लिये स्वेब्छा से चकैबन्दी कराने में विशेष सहायक हो सकतों थीं। जो कानून पास किये गये हैं उन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं : (१) वे कानून जो किसानों को यदि उस गाँव में निश्चित प्रतिशत किसान राजी हों तो चकवनदी के लिये वाध्य कर सकते थे अपीर (२) वे कानून जो राज्यों को यह अधिकार प्रदान करते थे कि ने अपनी ओर से चकवन्दी की योजनाओं को लागू करें। मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर के कानून पहिले वर्ग में और पंजाब पेप्सू, देहली श्रीर बम्बई के कानून दूसरे वर्ग में श्राते हैं"। मध्य प्रदेश के कानून के अनुसार यदि किसी महाल, पट्टी अध्यवा गाँव के कम से कम आर्थ निवासी जिनके दिस्से में गाँव की है मूमि ग्राति है मिलकर चकवन्दी की योजना के लागू कराने की प्रार्थना करें ग्रार यदि चकवन्दी योजना पक्की हो चुकी है तो सब भूमि पर श्रिषिकार रखने वालों को चकबन्दी योजना स्वीकार करने के लिये वाध्य किया जा एकता है। जम्मू श्रीर काश्मीर के एक्ट के श्रनुसार यदि है किसान जिनके

श्रिषिकार में किसी गाँव के है खेत हैं श्रीर वे चकवन्दों की योजना स्वीकार करते हैं तो वह योजना पक्षी मान ली जायगी श्रीर लागू कर दी जायगी। इन कानूनों के कारण जो योड़े से व्यक्ति योजना को श्रस्वीकार करते हैं उन्हें भी योजना के श्रन्तर्गत लाकर उनकी सफलता निश्चित कर दी गई है।

चत्तर प्रदेश के कानून—"देश में लागू किये हुये कानूनों की प्रवृत्ति के अनुसार ही उत्तर प्रदेश ने भी इस सम्बन्ध में एक नया कानून पास किया है जिसके अनुसार राज्य अपनी ओर से अनिवार्य रूप से चक्रबन्दी लागू कर सकता है। यह नया कानून १९३९ के कानून के स्थान पर (जो चक्रबन्दी अनिवार्य रूप से लागू करने की तसी अनुमति देता था जब कि किसी गाँव के एक विशेष प्रतिशत लोग चक्रबन्दी के लिये अपनी स्वीकृति देते थे) पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है"। १९५३ के उत्तर प्रदेश भूमि चक्रबन्दी एक्ट में अनिवार्य रूप से उसे लागू करने की अनुमित पास है। यह कानून उ० प० की सरकार द्वारा नियुक्त चक्रबन्दी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है और पंजाब के कानून की ही तरह का है।

इस कानून के श्राधारभूत सिद्धान्त निम्न हैं—(१) प्रत्येक पट्टेदार को जहाँ तक सम्मव हो सके वहीं पर भूमि दी जायगी जिस चेत्र में उसकी श्रिधकांश भूमि है; (२) प्रत्येक गाँव की भूमि का वर्गीकरण निम्न चेत्रों में किया जायगा, (क) चावल पैदा करने वाले चेत्र, (ख) चावल को छोड़ कर श्रन्य एक फसली चेत्र, (ग) दो फसली चेत्र, श्रीर (ध) कछार भूमि के चेत्र; (३) केवल उन्हीं पट्टे-दारों को उस चेत्र में भूमि दी जायगी जहाँ पर पहिले से ही उनकी भूमि है, (४) प्रत्येक पट्टेदार को उतने ही चक दिये जायँगे जितने कि गाँव में चेत्र (श्राबादी के चेत्र को छोड़ कर) बनाये गये हैं जब तक कि किसी गाँव में केवल एक ही चेत्र न हो श्रीर उस चेत्र की भूमि एक प्रकार की न हो; (५) एक परिवार के पट्टेदारों को यथासम्मव एक दूसरे के पड़ोस में ही चक दिये जायँगे; (६) पट्टेदारों के निवास स्थान की स्थिति श्रीर यदि उसने कोई सुधार किया है तो उन्हें चक देने में हन बातों का विशेष ध्यान रक्खा जायगा; (७) यदि कोई चक या फार्म पहिले से ही ६६ एकइ या श्रीषक है तो यथासम्मव वह न तो विभाजित किया जायगा श्रीर न बाँटा ही जायगा"। इन सिद्धान्तों से न्यूनतम गड़नड़ी तथा किसानों को श्रिधकतम लाम होने की सम्मावना है।

इस कानून के अन्तर्गत चकवन्दी के कार्य को करने का एक विशद कम दिया हुआ है। इसको कार्यान्वित करने के पहिले प्रत्येक किसान के प्लार्टी का लेखा उनके चेत्रफ्लों के साथ तथा प्रत्येक का लगान व मालगुजारी आदि के

महित तैयार किया जायगा। एक ऐसी तालिका तैयार की जायगी जिसमें प्रत्येक पट्टेदार के कुल खेतों का चेत्रफल जो उनके पास विभिन्न प्रकार के ग्रासामी श्रिधिकारों के श्रन्तर्गत हैं तथा उसे जितनी मालगुजारी श्रथवा उसका लगान देना पड़ता है, तैयार किया जायगा। जब यह हिसाच पक्के तौर पर तैयार हो जायगा तव किसानों को चक देने की शर्ते तैयार की जायगी जिसमें यह दिखाया जायगा कि कौन कौन से प्लाट प्रत्येक पटटेदार को उसके प्राने खेतों के बदले में दिये जायँगे तथा यदि नये सिरे से दिये हुये प्लाट उसके पुराने प्लाटां की वुलना में कम मूल्य के हैं तो क्या मुख्रावजा दिया जायगा और उसके कुछों, पेड़ों श्रीर इसारतों के बदले में क्या मुश्रावज़ा दिया जायगा इत्यादि । इस प्रस्ताव पर किसानों को उजरदारी करने का अधिकार होगा। परन्तु उजरदारी का जवाक दिये जाने पर प्रस्ताव पक्का हो जायगा और चकवन्शी योजना लागू हो जायगी। इसके पश्चात् चक को दिये जाने का हुक्म जारी हो जायगा जिसमें यह दिखाया जायगा कि योजना के अनुसार कीन-कीन से नये खेत किसके दिस्से में आगए हैं श्रीर उन्हें उन पर श्रिधिकार दे दिया जायगा। इस बात का ध्यान रक्ला जायगा कि किसानों को चक उसी दोत्र में दिया जाय जहाँ पर उनके अधिकाँश खेत हैं। भूमि पर श्राधिकार के सम्बन्ध में निर्णाय ऐसे निर्णायक द्वारा किया जायगा जिसे सरकार उन न्याय-कार्य सम्बन्धी श्रफसरों में से नियक्त करेगी जिन्हें कम से कम ७ वर्ष तक का अनुभव है। किसानों से भी राय ली जायगी और उन्हें आपिता करने का अधिकार होगा परन्तु जब योजना पक्की हो जायगी तब सब को उसे मान लेना पड़ेगा। यह चकबन्दी योजना न्यायालयों के कार्य-तेत्र के बाहर इसिलए मानी गई है कि इस सम्बन्ध में मुकदमेवाजी न हो। एक्ट के अनुसार चकनन्दी का खर्चा ४ ६० प्रति एकड़ नियत कर दिया गया है जो योजना में समिलित विभिन्न व्यक्तियों में बँट जायगा ताकि सरकार को यह खर्च न उठाना पड़े। जिनके खेतों की चकबन्दी की जायगी उन्हें पैमाइश तथा अन्य प्रकार के शारीरिक अम वाले कार्य करने में सहयोग देना होगा और जो यह न कर सर्केंगे वो उन्हें २ २० ८ श्राना प्रति एकड़ के हिसाब से अम के बदले में खर्च के प्रति देना पढ़ेगा । यह कानून मुजफ्फरनगर श्रीर सुल्तानपुर जिलों में लागू कर दिया गया है। थोड़ा श्रनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् पहिले यह २० जिलों में श्रीर लागू किया बायगा। श्राशा की जाती है उत्तर प्रदेश में इस कानून के श्रन्तर्गत चकवन्दी का कार्य बहुत सुगम होगा।

कठिनाइयाँ—चकवन्दी-कार्य बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। कुछः कठिनाइयाँ तो मनोवैज्ञानिक हें और कुछ प्रयोगात्मक। (१) बहुत सी जगहों।

पर भूमि श्राधिकारों का कोई लेखा प्राप्त नहीं है। पंजाब में देश के बँटवारे के पश्चात् सारे लगान सम्बन्धी होखों के खो जाने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

- (२) चकवन्दी का कार्य श्रीद्यौगिक ढंग का है। इसके करने वालों को पैमाइश, बन्दोबस्त, भूमि के वर्गोकरण, भूमि के मूल्यांकन तथा पटट्रेदारी सम्बंधी ज्ञान श्रावश्यक है। ऐसे कार्यकक्तीश्रों की कमी के कारण चकवन्दी के कार्य में बाधा पड़ी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ प्रदेशों में ऐसे श्रफसरों को इस कार्य के लिये विशेष ट्रेनिंग देने का श्रायोजन किया गया है।
- (३) इस कार्य में किसानों की रुद्धिवादिता श्रीर पीढ़ियों से श्रिष्ठकार में स्थित भूमि के प्रति मोइ के कारण भी बाबा पड़ी है। जमोंदारों श्रीर श्रन्य श्रुसामाजिक वर्गों द्वारा बाधा उपस्थित करने से भी काम में रुकावट पहुँची है। शान्तिपूर्वक जनता में इस कार्य के प्रति प्रचार तथा जानकारी की वृद्धि द्वारा तथा जहाँ श्रावश्यक हो वहाँ श्रानिवाय रूप से लागु करने से ही इन बाधाश्रों पर विजय पाई जा सकती है।
- (४) चकबन्दी में रूपया खर्च होता है श्रीर रूपये के प्रबंध के कारण भी इस कार्य में बाधा पहुँचती है। प्रादेशिक सरकारों के समज्ञ श्रनेक प्रकार की विकास योजनायें हैं इसिलये वे सदा इस कार्य के लिये पर्याप्त धन देने के लिये तैय्यार नहीं रह सकती। इस सम्बन्ध में खर्च पूरा करने के लिये तीन उपायों के काम में लाने की श्रनुमित दी गई हैं। (क) दिल्ली, मध्य प्रदेश श्रीर पंजाब में खर्च का एक श्रंश किसानों से चकबन्दी फीस के नाम पर वस्त्ल कर लिया जाता है। इस प्रकार कुछ श्रंश तक किसान द्वारा पूरा कर लिया जाता है; (ख) वम्बई में सारा व्यय सरकार द्वारा सहन किया जाता है जहाँ पर किसानों के साथ रियायत के रूप में बिना फीस लिये काम किया जाता है; श्रीर (ग) उत्तर प्रदेश में जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है पूरा खर्चा किसान से ४ द० प्रति एकइ के हिसाब से वस्त्र कर लिया जाता है।

सफलता की मात्रा—चकबन्दी की क्षणलता विभिन्न प्रदेशों में कम ही रही है। केवल पंजाब, त्रम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेप्सू श्रीर दिल्ली श्रादि ने कुछ क्षणलता इस सम्बन्ध में पास की है। पंजाब में चकबन्दी का काम १६२० से श्रारम्म हुआ। श्रीर उत्तर प्रदेश में १६२४ से। उत्तर प्रदेश में १६५३ के चकबन्दी एक्ट के पास होने पर इस काम की गति बढ़ गई श्रीर आगे चलकर एक्ट में भी उपयुक्त सुधार कर दिया गया। मार्च १६५५ तक पंजाब में ४० लाख एकइ, मध्य प्रदेश में २५ लाख एकइ, पेप्सू में १० लाख एकइ से श्रीषक भूमि

की चंकवन्दी की गई। वम्बई और दिल्ली में १०६० और २१० गाँवों में क्रमशः यह योजना पूर्णतया लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में २१ जिलों में यह योजना लागू हैं। अब भी विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्य को बढ़ाने का अवसर है।

यद्यपि चकवन्दी का कार्यं जरा वीभी गित से हुआ है और बहुत कम उन्नित इस ओर हो पाई है फिर भी इससे लाटों की संख्या कम हो गई है और उनका औसत चेंत्रफल बढ़ गया है। यदि प्लाटों की संख्या में कमी और खेतों के देत्रफल में बृद्धि की दृष्टि से देखा जाय तो इम कह सकते हैं कि सबसे अधिक उन्निति मध्य प्रदेश ने की है जहाँ विलासपुर, रायपुर ओर दुर्ग जिलों में प्लाटों की संख्या ८२% कम हो गई है और उनका औसत चेंत्रफल ४००% बढ़ गया है। इस ओर मद्रास ने सबसे कम उन्नित की है और वहाँ प्लाटों की संख्या में २०% से भी कम कमी हुई है।

खेतों की चकबन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत (economic holding) प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि यदि किसी किसान के खेत गाँव के विभिन्न भागों में छिटके हुये हैं तो चकवन्दी से किसान के श्रिष्ठकार में भूमिका चेत्रफल नहीं बढ़ सकता। इस्रिलेये प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत देने के लिये बहुत बड़े प्रयत्न की श्रावश्यकता है।

श्रध्याय ५

भृमि-क्षरण

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार भूमि संरक्षण से अभिप्राय केवल च्ररण को रोक पाना ही नहीं है परन्तु अपने ज्यापक अर्थ में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत वह सभी वार्ते शामिल हैं जिनका लक्ष्य भूमि की उत्पादन शक्ति को ऊँचे स्तर पर बनाये रखना है, जैसे भूमि की कमियों को दूर करने के उपाय, रासायनिक तथा देशी खाद का उपयोग, फसलों के बोने के कम का उचित संचालन, सिंचाई तथा नाली की ज्यवस्था इत्यादि। इस रूप में भूमि-संरक्षण का प्राय: भूमि के उपयोग के ढंगों में सुधार करने से निकट सम्बन्ध है। भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में भारत की प्रमुख समस्या भूमि-च्ररण को रोकना है। भूमि-च्ररण होते रहने से भूमि का बहुत बड़ा भाग कृषि के योग्य नहीं रहता।

कार्या—भृमि चरण के ग्रानेक कारण हैं परन्तु उनमें से मुख्य निम्न-लिखित हैं:—

- (१) वनों का काटना और वनस्पति का नष्ट हो जाना। जंगल और वनस्पति हवा और पानी के वहाव को रोकते हैं जिससे भूमि का तल इनकी हानि-कारक शक्ति से वच जाता है और उसका चरण नहीं हो पाता। यदि वन काट हाले लाय और वनस्पति नष्ट कर दी जाय तो भूमि पूर्ववत नहीं रहेगी, उसकी उत्पादन शक्ति घट जायगी। प्रायः ईंघन या इमारतो के उपयोग के लिए वनों को काट लिया जाता है। आसाम, बिहार, उझीसा और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में कवायली जनता (Tribal people) एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करती है। वह प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कृषि-चेत्र बदलती रहती है जिसके लिए उसे पेड़ काटते रहना पड़ता है और इससे वनों का विनाश हो जाता है। इघर जमीदारी उन्मूलन होते ही अनेक जमीदारों ने इमारती लकड़ी से दपया पैदा करने के लिए अपने चेत्र के पेड़ काट डाले हैं।
- (२) पशुश्रों श्रौर विशेषकर मेड़ वकरियों का घास-पत्ती इत्यादि चर जाना। इससे भूमि के कण परस्पर गुधे नहीं रह जाते श्रौर उसका ज्ञरण होने लगता है। वनस्पति का इस प्रकार चर लिया जाना भारत के लिए एक गम्भीर समस्या वन गया है। १९५२ में भारतीय कृषि-श्रनुसन्धान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) के तत्वावधान में उसके फसल श्रीर

भूमि विभाग (Crops and Soils Wing) की प्रथम बैठक में उस समय के खाद्याल मंत्री ने कहा कि मेड बकरियों को प्रथम देने का अर्थ है भूमि-ज्राण और महाविनाश । परन्तु गाय-भेंस को प्रथम देकर हम भूमि की सेवा कर सकते हैं श्रीर स्वयं समृद्धिशाली वन सकते हैं । खाद्य मंत्री ने श्रीषक नोर देकर जरूर कहा है परन्तु यह सब है कि मेड वकरियों से भूमि को बहुत क्षति पहुँचती है । उचित यह होगा कि पशुश्रों को चारा दिया जाय और जिना रोक-टोक के हघर-उघर, विशेषकर उन दोत्रों में जो इस कारण पहले ही इतिशस्त हो चुके हैं, चरने न दिया जाय।

(३) जिस भूमि में उत्पादक तत्वों की पहले ही से कमी है उसका शोध चरण हो जाता है। यद भूमि उपजाऊ है और उसकी अच्छी तरह देखभाल की यई तो खराब भूमि की अपेसा इसमें भूमि-स्र्ण कम होगा। काश्त की जाने वाली भूमि का भारत में पीढ़ियों से बिना किसी रोक टोक के बराबर उपयोग होता रहा है और उसकी उत्पादन शक्ति की पूर्ति करने के लिए खाद इत्यादि या तो नहीं बाली गई है या अपर्याप्त रही है। इससे देश के बड़े-बड़े भाग भूमि चरण के संकट से अस्त हो चुके हैं।

मृमि-चरण श्रतेक प्रकार का होता है परन्तु भारत में मुख्य प्रकार निम्न-लिखित हैं:--

- (१) तल चरण (Sheet Erosion)—पानी के तेन बहाम से या तेज हवा के बहने के कारण जब मूमि की ऊपरी उपजाक सतह वह जाती है तब तल- चरण होता है।
- (२) श्रन्तः त्तरण् (Gully Erosion)—पानी के तेज बहाव के कारण् मृमि में गहरे नाले बन जाने से श्रन्तः त्तरण् होता है। प्रायः श्रन्तः त्तरण् होने का कारण् यह होता है कि बहुत समय तक तल-क्तरण् होता रहे श्रीर उसे रोकने का काई उपाय न किया नाय। निद्यों के श्रास-पास की भूमि में श्रन्तः त्तरण् की श्रिषक संभावना गहती है क्योंकि बाद् श्रा जाने से तट की निकटवर्ती भूमि का तल त्तरण् होता रहता है श्रीर धीरे-धीरे गहरे नाले बन जाते हैं।
- (३) वासु क्षरण (Wind Erosion)—वासु चरण देश के मह प्रदेश में जैसे राजस्थान श्रीर पूर्वी पंजाब में होता है। तेज वासु बहने से मह चेत की बालू उहती रहती है श्रीर निकटवर्ती हिस्सों में बैठती रहती है जैसा राजस्थान के मह प्रदेश के निकट होता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति को गहरी हानि पहुँचती है।

भूमि ज्रारा एक गंभीर संकट है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम होती

भारतीय श्रर्थशास्त्र की समस्याएँ

है, भूमि व्यर्थ हो जाती है श्रीर जनता निर्धनता के चंगुल में फंछ जाती है। इससे देश के बड़े-बड़े चेत्र मदस्यल में बदल जाते हैं। उन चेत्रों में जहाँ नदी-धाटी बोलनाएँ लागू की गई हैं, जैसे दामोदर बाटी, वहाँ पर भूमि च्ररण के निर्मित बाँवों को मय उत्पन्त हो जाता है। इस कारण इन बाँघों की देखमाल श्रीर बचाव के लिए श्राधिक व्यय करना पड़ता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इमें श्रपने देश में भूमि-इरण के प्रकार श्रीर प्रधार के सम्बन्ध में सही-इही च्यना प्राप्त नहीं है इस स्वना के प्राप्त हो जाने पर भूमि-च्ररण को रोकने के लिए प्रभावराली उपायों को लागू किया जा सकता है। पिछले छुछ वर्षों में भूम संरक्षण के लिए इन्ह काम किया गया है, वम्बई में छोटे-छोटे बाँध बाँधने श्रीर टेक लगाने (Terracing) से श्रीर उत्तर प्रदेश में नालों कथा छड़ों से पारण्यत भूम पर कृषि करके भूमि संरहण किया जा रहा है। बाँध बाँधने श्रीर टेक हत्यादि का निर्माण करने में श्रीर कटी-पटी भूम को स्मतल दनाने के लिए ट्रैक्टरों तथा श्रम्य वर्डा-बड़ी मर्शानों का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु श्रमी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य करना श्रेप है।

राजस्थान के मक्स्थल का क्रमशः उत्तर की श्रोर विस्तार एक विशेष चिन्ता का विषय हो गया है श्रीर मारत सरकार ने उसकी रोक्स्थाम के लिये निम्न उपाय किये हैं:—

- (१) "दस वर्ष के भीतर ही भीतर ४०० मील लम्बी श्रीर ५ मील भीतर को श्रीर चीड़ी बङ्गल की एक पट्टी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर लगा देना इसमें मेड, बकरी, नाय, हैल, ठँट, ह्याद पश्ची के चरने की श्रीका न होगी।"
- (२) मरुत्यल की सूमि में बालू के कुशों को इरियाली द्वारा स्थिर करने में वैज्ञानिक उपायों की खोज करना।
- (३) ऐसे नखः लखानों की व्यवस्था करना नहीं से पेड़-पीचे फीजी नाकों, रेल के स्टेशनी, पुलिस के यानी, तहसीलों श्रीर खुलों के इर्ट-गिर्ट ले जाकर लगाये जा सकें।
- (४) ऐसी चुनी हुई सहको और रेल की लाइनी पर क्तुघ्यों की आवादी में आवास का प्रवत्य करना को वायु के बहाब को काटती हुई बहती हैं।
- (५) पीची के लगाने वाली एकेंग्सिकों को दीन और पीची के बांटने का प्रवत्य करना।
- (६) उपयुक्त चरागाहों की त्थापना का प्रदत्य करना नो कि समय-समय पर ग्रांर भारी-त्रारी से चरने के लिये खोले नायाँ।

श्रध्याय ११

बहुउद्देशीय योजनाएँ और बाढ नियंत्रण कार्यक्रम

सिंचाई श्रीर शक्ति उत्पादन योजनायें प्रथम श्रीर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाश्रों के मुख्य श्रंग हैं। इनमें विद्युत शक्ति के उत्पादन श्रीर सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होगी जिनका श्रमाच उद्योगों श्रीर कृषि की उन्नित में वाधक रहा है। इन योजनाश्रों से बाद पर नियंत्रण, मलेरिया के फैलने में रकावट, तथा देश को श्रम्य श्रमेकों लाम होंगे। प्रथम श्रीर द्वितीय योजनाश्रों के श्रम्तर्गत तीन प्रकार की सिंचाई योजनाश्रों की व्यवस्था है। (१) बहुउद्देशीय योजनायें, (२) वड़ी तथा साधारण सिंचाई की योजनायें तथा (३) छोटी सिंचाई की योजनायें।

इन योजनाओं की तीन विशेषतायें हैं। (क) इनमें से अनेकों तो पंचव-षीय योजना के आरम्म होने के पूर्व ही से चल रहीं थीं। "द्वितीय महासमर का अन्त होते ही बहुत सी परियोजनायें जिनमें कई बहुउहेशीय योजनायें भी थीं आरम्म कर दी गई थी। इनमें से कुछ तो ऐसी थीं जिनका कार्य तो बिना उनके सम्बन्ध में आवश्यक प्राधीगिक और आर्थिक छान बीन के ही आरम्म कर दिया गया था। १६५१ में जब सिचाई और शक्ति उत्पादन की योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा था, उनके पूर्ण होने में कुल व्यय ७६५ करोड़ रुपये होने का अनु-मान था" इसमें से १५३ करोड़ रुपया तो इन अपूर्ण योजनाओं पर व्यय हो चुका या क्योंकि ऐसा विचारा जाता था कि जितना शीष्ट हो सके उतना शीष्ट ये योजनायें पूर्ण की जाँय जिससे कि जो कुछ धन इन पर व्यय किया जा चुका है वह सार्यक हो और उसका यथा-सम्भव लाम बढ़ी हुई मात्रा में अन्न की उत्पत्ति के रूप में शीष्ट मिल जाय।

(ख) प्रथम योजना के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं को आरम्म किया गया था उन पर पुन: विचार किया गया और सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन की योजना पर व्यय भूभ करोड़ रुपये से बहाकर ६७७ करोड़ रुपया कर दिया गया। जो अन्य महत्वशाली परिवर्तन किये गये वे निम्न हैं। (१) १६५१ में योजना निर्माण के समय सदा से कमी के चेत्र की आवश्यकताओं की और विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इन चेत्रों की जनता के निर्धन होने तथा उनके आर्थिक कार्यों में निरन्तर प्राकृतिक बाधा की उपस्थित के कारण निरन्तर सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती थी। इसिलिये १६५३ अर में इन चेत्रों के स्थायी विकास के

लिये कार्यक्रम निश्चित किए गए श्रीर इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के कुल व्यय में ४० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। इन योजनाश्रों का ध्येय था कि वे जनता के पास धन की वृद्धि करेगी श्रीर वे मिवष्य के विकास कार्यक्रम में उससे सहायता दे सकेंगे। (२) १६५४-५५ में छोटी-छोटी शक्ति उत्पादन की योजनाश्रों इसमें स्मिलित कर लीं गई जिन पर २० करोड़ रू० इस विचार से व्यय करने का निश्चय किया गया कि उनसे छोटे-छोटे कस्बों श्रीर गाँवों में जनता को कार्य पाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, श्रीर (३) बाद पर नियंत्रण रखने का १६५४-५५ में क्रम बनाया गया जिसपर १६३ करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया।

(ग) इन योजनात्रों का कार्य इतना श्रिषक या श्रीर घन तथा श्रन्य श्रावश्वक सावनों का इतना श्रमाय या कि सबको कार्याविन्त करना सम्भव नहीं हो सका। इसलिए सम्पूर्ण कार्यक्रम को श्रंशों में विमासित करना श्रावश्वक हो गया। प्रथम योजना में यह निर्णय किया गया कि सम्बल, कोसी, कृष्णा, कोयना श्रीर रिइन्ड योजनाश्रों को सम्पूर्ण योजना के श्रान्तम काल में श्रारम्म किया लाय।

इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय किया गया है कि कुछ वड़े काम जैने आन्त्र की वमसाघरा योजना, विहार की कनसाई योजना और वम्बई की उमाई नर्मदा, माही, खहरावासला, गिरना और वनस योजनायों, मध्य-प्रदेश की वावा योजना और पिक्झमी वंगाल की कगसावाती योजना सम्पूर्ण योजना काल के अन्तिम भाग में कार्यान्वित की नार्येगी।

योजना के श्रन्य कार्यक्रमों की अपेद्धा विचाई श्रीर शक्ति उत्पादन योज नाश्रों पर वजट में निश्चित व्यय कहीं श्रिषक व्यय किया गया। यह एक संतो-प्रयद वात है, क्योंकि इसमें मारतवर्ष की श्रायिक स्थिति सुघरेगी श्रीर उद्योगों तथा कृषि में तीव गित से विकास समन होगा। प्रथम योजना के तीन वर्ष व्यवित होने के पूर्व ही मारतवर्ष यदि श्रन्न के लिये श्रात्म निर्भर हो सका है तो किसी सीमा तक इसका कारण सिंचाई तथा शिक्त उत्पादन योजनायें हैं। प्रथम योजना के प्रथम चार वर्षों में ६७७ करोड़ की व्यवस्था में से ४४५ करोड़ रूपया व्यय किया वा सुका था। बहुउद्देशीय योजनाश्रों पर १८७ २४ करोड़ रूपया जो कि इल व्यय का ७६% हैं, शिक्त उत्पादन योजनाश्रों पर, ११२ ७५ करोड़ रूपया जो कि इह% है, सिंचाई योजनाश्रों पर (जिनमें कमी के द्वेत्रों का कार्यक्रम सिम्मिलत है) १३३,३७ करोड़ रूपया जो कि ६४% है, व्यय किया, जायगा। १९५४-५५ के श्रन्त तक कृषि के श्रन्तर्गत लाया गया श्रतिरिक्त द्वेत्र ४० लाख एकइ या जव कि लक्ष्य ५७ लाख एकइ या। लम्बे शक्ति उत्पादन के द्वेत्र में

६६२००० किलोवाट शक्ति उत्पादन किया गया, जब कि ध्येय ८८१००० किलोवाट उत्पादित करने का था।

बहुत सी वही योजनाश्चों पर बहुत उसित की जा चुकी है, श्रीर यह श्राशा की जाती है, कि वे दितीय योजना काल में पूर्ण कर दी जायँगी। इन योजनाश्चों में भाकड़ा, दीराकुरह, कोयना, चम्बल श्रीर रिहेन्ड योजनार्ये श्राती हैं। इन सबसे १७ लाख किलोबाट विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकेगी।

बहुउद्देशीय योजनाएँ

कुछ बहुउद्रेशीय योजनाश्रों जैसे भाकड़ा नांगल, हिराकी, दामोदर घाटी श्रीर हीराकुरड श्रादि ने पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में संतोपप्रद उनित कीं श्रीर योजना में निश्चित २८२'०२ करोड़ रुपए में से उन पर १६७'२६ करोड़ रुपया न्यय किया जा चुका है, इसके फलस्करूप ६ लाख एकड़ श्रतिरिक्त भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकी है, श्रीर २०२००० किलोबाट विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकी है।

भाकड़ा नांगल योजना—यह योजना पंजाब, पेम्सू श्रीर राजस्थान को सुनिधार्य पहुँचायेगी। इसके श्रन्तर्गत (१) सतलज नदी के श्रारपार भाकड़ा बाँध बनेगा; (२) नांगल बाँध नदा में बहाब की श्रोर द मील तक बनेगा; (३) नांगल नहर बनेगी, (४) दो नांगल पावर हासउ बनेंगे श्रीर (५) भाकड़ा नहर व्यवस्था बनेगी। यह योजना १९४६ में श्रारम्भ की गई थी, श्रीर श्रव तक नांगल बाँध नहर-नियासक (canal regulator), नांगल जल द्वार तथा पंजाब में माकड़ा नहर की खुदाई पूर्ण हो सुको है। हमारे प्रधान मंत्री ने द लुलाई १९५४ को इस नहर व्यवस्था की उद्धादन किया था। भाकड़ा बाँध को चूने द्वारा ठोस करने के कार्य का उद्धादन १७ नवम्बर १९५५ में किया गया।

दासीदर घाटी योजना—योजना काल के प्रथम चार वर्षों में इस योजना पर ५० १३ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था, और १.१ लाख एकड़ श्रितिरिक्त भूम की सिंचाई श्रीर १.५ लाख किलोबाट विद्युत शक्ति का उत्पादना होने लगा। दामोदरघाटी योजना एक ऐसे महत्वशाली श्रीद्योगिक चेत्र को सुविधार्ये पहुँचाती है, "नहाँ से देश में प्राप्त कुल कोयले की मात्रा का ८०% श्रभ्रक का ७०%, कोमाइट का ७०%, कायरक्कों का ५०%, लोहे का ६८%, ताँवे का १०० प्रतिशत श्रीर कामोनाइट का १००% प्राप्त होता है"। जब यह योजना पूर्ण हो जायगी तब यह देश के श्रीद्योगिक तथा कृपि सम्बन्धी विकास में काकी मात्रा में सहयोग प्रदान करेगी।

हीरा कुएड योजना —यह योजना उद्गीसा राल्य को मुनिधा प्रदान करेगी, श्रीर इस योजना की प्रारम्भिक श्रवस्था में (१) महानदी की घाटी में एक बीध कंकड़ पत्थर श्रीर मिट्टी का, (२) टोनी किनारों पर मिट्टी के जल धरण (dykes) (३) दोनी किनारों पर नहर, (४) बीध पर एक पावर हाउस १८२००० किलीवाट विद्युत उत्पन्न करने के लिये श्रीर (५) ट्रान्स्सिशन लाइन्स बनाई जायेंगी। खेती में नालियों को खुदवा देने से श्रिधकाधिक होतों की सिचाई की मुनिधा हो संकेगी श्रीर इस प्रकार १९५८ तक कुल ४ ५४ लाख एकड़ होत्र सीचा वा सकेगा।

विभिन्न प्रदेशों में योजनाच्यां की प्रगति

राज्यों में खिचाई योजनात्रों की प्रगति बहुउदेशीय योजनात्रों की तुलना में कम हुई। १६५१ से ५५ तक चार वर्षों में वास्तिविक ज्यय १८८० करोड़ रुपया हुन्ना जब कि सम्पूण योजना के पुनरी ज्ञ्रण के पश्चात् २०७१६८ करोड़ रुपये के ज्यय करने की ज्यवस्या की गई थी। द्यांतिरिक चेत्र जिसपर सिंचाई की गई वह केवल ३५ लाख एकड़ था, जब कि योजना में ६४ लाख एकड़ ज्ञांतिरिक भूमि पर सिंचाई करने का ध्येय था। इन योजनात्रों की प्रगति 'क' राज्यों क कुछ भागों में तथा 'ख' राज्यों के द्यांचकांश भागों में धामी ही रही है। इसका कारण संगठन का ज्ञमाब, प्रशासनों द्यांर काम करने वालों का ज्ञमाब ज्ञीर योजना में वार-बार परिवर्तन करना रहा है।

दितीय योजना के खन्तर्गत—दितीय पंचवर्षीय योजना में समिलित नई सिंचाई योजना छों का कुल व्यय लगभग १८० करोड़ रुपये हैं, इसमें से १७२ करोड़ रुपया दितीय योजना काल में व्यय किया जायगा, रोप धन तीसरे तथा अन्य भविष्य में होने वाली पंचवर्षीय योजना छों के काल में व्यय होगा। बड़े और साधारण श्रेणी के सिंचाई साधनों पर दितीय पंचवर्षीय योजना में कुल १८१ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त २५ करोड़ रुपये की श्रोर व्यवस्था की गई है जिससे कि सिन्धु नदी की योजना हों तथा अन्य ऐसी योजना हों से जिनके सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हो पाया है, प्राप्त जल का प्रयोग करने के लिये अन्य नई योजना में पूर्ण करवाई जा सकें। दितीय योजना काल में जो २४० लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी उसमें से लगभग १२० लाख एकड़ भूमि को छोटी सिंचाई की योजना हों से सुविधा प्राप्त होगी श्रीर लगभग ६०० लाख एकड़ भूमि को छोटी सिंचाई की योजना हों से यह सुविधा प्राप्त होगी।

श्रीधकांश श्रीतिरिक्त सिंचाई (लगमग ६० लाख एकड़) जो बड़े श्रीर . साधारण श्रेणी की योजनाश्रों से होगी वह उन कार्यक्रमों की पूर्ति हो जाने के कारण होगी जो कि प्रथम योजना से ही चल रहे हैं। द्वितीय योजना में सम्मिलित नई योजनाश्रों से लगमग ३० लाख एकड़ भूमि सींची जायगी। द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत बड़ी श्रीर साधारण श्रेणी की योजनाश्रों के पूर्ण हो जाने पर उनकी सींचने की शक्ति लगमग १६० लाख एकड़ होगी।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत विद्युत-शक्ति उत्पादन के विकास-कायक्रम के वीन ध्येय हैं: (क) वर्त्तमान पावर हाउसों पर बढ़े हुये सामान्य भार को वहन करना; (ख) पूर्ति के सेत्रों के युक्ति संगत विकास के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और (ग) दितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नवीन आरम्भ किए हुए उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

बाढ़ नियंत्रए का कार्यक्रम

सरकार ने समन्वित श्राघार पर बाह की समस्या के निराकरण का श्रात्यन्त महत्वशाली निर्णय किया है। प्रथम योजना के श्रारम्म में बाह नियंत्रण की कोई भी निश्चित ब्यवस्था नहीं की गई थी। उस समय बाह नियंत्रण योजनाएँ नदी घाटियों के विकास सम्बन्धी बहुउईशीय योजनाश्रों के श्रन्तर्गत रखी गई थी। १६५४ को श्रपूर्व बाहों ने प्राण्य सम्पति तथा यातायात को विशेषकर देश के उत्तर-पूर्वी मांग में, बहुत हानि पहुँचाई। इस कारण बाह की समस्या पर सिंचाई श्रीर विद्युत शक्ति उत्पादन कार्यक्रमों से श्रलग स्वतंत्र रूप से विचार करना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो गया। प्रदेशों हारा तात्कालिक बाह नियंत्रण के लिये उपायों के प्रमावशाली सिद्ध न होने के कारण १६५४ में यह निर्णय किया गया कि एक व्यापक बाह नियंत्रण कार्यक्रम हस समस्या को उचित ढंग से सुलमाने के लिये बनाया जाय। १६५ करोड रूपये की योजना में इसीलिये १६.५ करोड रूप की व्यवस्था श्रीर कर दी गयी। बाह नियंत्रण के काय पर दितीय पंचवर्षीय योजना में श्रिधक ध्यान दिया गया है।

२'३१ करोड़ रुपये का ऋगा प्रदेशों को १६५४-५५ में दिया गया और केन्द्रीय सरकार के १६५५-५६ के बजट में १० करोड़ रुग्ये की व्यवस्था इसके लिये कर दी गई है। जिससे कि ऋगा को सहायता प्रदान की जा सके। मार्च १६५५ तक विभिन्न प्रदेशों में जो सफलता मिली है, उसका विवरसांनिम्नलिखित है।

	१९५४-५५	१६५५-५६	योग
श्रान्त्र	•••	•••	
त्राचाम ज्यासाम	१००	२१०	३१०
विहार विहार	इं प्	શ્યુપ્	१६० .
जम्बर् <u>द</u>	***	•••	•••
मध्य प्रदेश	***	•••	
मद्रास	***		
उद्गेषा	**4		•••
पंजाब	•••		•••
उत्तर प्रदेश	१५	ଓବି	\$3
पश्चिमी वंगाल	રૂપૂ	२६७	३३२
पेप्सू	५०	२००	२५०
जम्मू श्रीर काश्मीर	યુ	१५	50
ग्रन्य प्रदेश	₹0	03	200
सरकार के सी० डबल् और पी०	•••	२००	२००
ची मारत वर्वों मिट्रोला चाकल	३४	१२३	६स७
विभाग इत्यादि		}	}
द ुल	रूप	१३६६	१६५•

भासाम-डिवरूगढ़ श्रीर पलासवाड़ी नगर रहा योजनायें पूर्य हो चुकी है। सैलोना, नवगांग, श्रीर सुवन्सिरी जिलों में वाढ़ से रहा करने की योजना का कार्य श्रारम्म किया गया।

परिचमी वंगाल—श्रिषक महत्वशाली योजनार्ये जिन्हें श्रारम्म किया गया, वे निम्न थीं (१) जलपाईगुरी नगर की रहा, (२) वरनीज मैनागुरी रोमोहाल खेत्र।

विहार-भूरी गण्डक नदी के बाँघ का द०% कार्च समाप्त हो चुका है। मागववी बलान, खिरोही इत्यादि नदियों पर सुरज्ञा कार्य श्रारम्म किया गया था।

उत्तर प्रदेश—"गएडक श्रीर गंगा नदी पर वाढ़ से रहा करने का कार्य जिससे वस्ती, गोरखपुर श्रीर देवरिया जिलों के लगमग ४०० गाँवों की रहा संमव है, पूर्ण किया गया।" पंजाब—निम्न कार्य पूरे किये गये (१) ४३ मील लम्बा ढेरा वाबा नानक से आकर मन्ज तक रावों नदी के किनारे श्राघार वाँघ का बनवाना; (२) देहली प्रदेश में जमुना नदी के किनारे जो पतली दारार पाई गई थी उनको बन्द कर-वाना श्रीर टकोला बाँघ बनवाना; (३) कर्नाल जिले में वाबैल से घानसीली तक जमुना नदी के दाहिने किनारे बाढ़ रोकने के लिये बाँघ बनवाना; श्रीर (४) जमुना नदी से ताजेवाला शीर्ष कम से नीने की श्रीर बाँघ बनवाना; ।

यह तो सर्व विदित है, कि बाद न तो सदा के लिये रोकी जा सकती है, श्रीर न रोक देना उचित हो है। इन वाढों से वारीक भिट्टी वह कर श्राती है. जिससे पानी डूब जाने वाले दोत्रों की उपज बह जाती है। उन वर्षों में जब कि बाद ग्रसमान्य हो जाती है, उनसे वहत हानि पहुँचती है ग्रीर जनता को कष्ट पहुँचता है। बाद का प्राय: श्राना और उसके द्वारा हानि को कम करने के लिये बाढ़ों के घनत्व पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके लिये क्रमवद्ध कार्य-क्रम बनाने की त्रावश्यकता है। जिन उपायों से प्रायः काम किया जाता है, वे निम्न हैं। (१) किनारे पर बाँध बाँधना (२) संग्रह जलाशय, विशेषकर सहायक धाराश्चों पर (३) श्रवरोधन गढा बनवाना जहाँ पर बाढ का पानी एकत्रित करके थोड़े समय के लिये रोका जा सके; (४) नदी की घारा को मोड़ देना निससे कि एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुँच जाय ; (५) नदी का ढाल बढ़ाना उसमें श्रारपार द्वार खुदवा कर, (६) निदयों तक ले जाने वाली घाराश्रों को जिनमें मिट्टी भर गई है, खुदवाना और उसकी मिट्टी निकलवाना, (७) स्थानीय रज्ञा के उपाय जैसे पक्की दीवार और ऊँचे टीले आदि बनवाना ताकि भूमि कटने न पानें, श्रीर (८) वन लगाना श्रीर स्थान-स्थान पर बहाव की तीवता रोकने के लिये बाँध बाँधना ।

सिंचाई श्रीर शक्ति मंत्रालय द्वारा कुछ दिन पूर्व ही बाह रोकने के कार्यकम की रूपरेखा बनाई गई है। इसके तीन भाग है। (क) तात्कालिक—इसके
अन्तर्गत अन्वेषण योजना बनाना श्रीर समय का अनुमान करना होगा। दीवार
बनाना श्रीर बाँच श्रादि भी विशेष स्थानों पर बनवाये जा सकते हैं; (ख)श्रव्यकालीन—इसके अन्तर्गत बाँचों श्रीर नालों श्रादि का सुधार किया जायगा।
इस प्रकार की रह्मा के उपायों का प्रयोग उन होत्रों में विशेष रूप से किया
जायगा जहाँ बाह श्राधक श्राती हैं; (ग) दीर्घ कालीन—इसके अन्तर्गत निद्यों
तथा उनकी सहायक धाराश्रों के जल संचय का कार्य सिनाई श्रीर विद्युत शक्ति
उत्पादन योजनाश्रों के कार्य के साथ किया जायगा।

द्वितीय योजना में ६० करोड़ रुपये की व्यवस्था तत्कालीन श्रीर

श्रल्पकालीन योजनात्रों के लिये की गई है। इसमें ५ करोड़ रुपया परी ज्ञाण तथा तत्सम्बन्धी सूचना सामग्री एक त्रित करने के लिये नियत किया गया है। वनों का लगाना श्रीर भूमि सर्चिण के उपायों को कार्य में लाना, बाढ़ नियंत्रण के महत्वशाली उपाय है, इनको बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम में विशेष स्थान मिलना चाहिए।

केन्द्रीय बाढ़ निरोधक मंडल ने जून १६५५ को श्रपनी पाँचवीं सभा में १६ बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें बाँघ वाँघना, नगरों की रच्चा के उपायों श्रीर गाँबों की स्थिति के स्तर को ऊँचा करगे के उपाय श्रादि समितित है। इनमें से प्रत्येक योजना पर १० लाख रुपये से श्रिषक व्यय होगा, श्रीर ७.५ करोड़ रुपये का श्रनुदान प्रादेशिक सरकारों को बाढ़ रोकने के कार्य-क्रमों को कार्यान्वित करने के लिये दिया गया है। बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक प्रदेश के बाढ़ रोकने के कार्यों को प्रदेशीय वाढ़ निरोधक विमाग के नियंत्रण में कर देना चाहिये। इससे कार्य में समन्वय श्रीर उसकी गति में तीवता होगी।

आलोचना-बाढ नियंत्रण की यह योजना जनता के प्राण, सम्पत्त श्रौर फरल की हानि को रोकने में श्रमी तफ रफल नहीं हो पाई है। इसका कारण **स्टरकारी कार्यक्रम के दोष हैं। मुख्य दोष निम्न हैं। (१)** श्रमी तक जो प्रयत्न सरकार द्वारा किये गये हैं, वह सर्वया अपर्याप्त है। योजनाएँ बनाने तथा प्रशा-सन कार्य करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं हो पाया है। जो व्यय नियत किया गया है, वह बहुत ही कम है। द्वितीय योजना में भी केवल ६० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है, जब कि कम से कम इसका दुराना घन उपयुक्त होता। (२) जल विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के श्रभाव के कारण योजनार्ये दोपपूर्ण हो वन पाती हैं। प्रायः प्रयत्न विफल हो जाते हैं, श्रीर परिणाम प्रयत्न की वुलना में कुछ भी नहीं होता (३) वाढ़ों को रोकने के लिये श्रमी तक तटवें घों पर श्रिधिक निर्भर रहे हैं । बाद द्वारा लाई हुई मिट्टी तटबन्घों के किनारे जमा हो जाती है इससे तटवन्घों को ऊँचा करने की श्रथवा मिट्टी खुदवाने की समस्या सदैव बनी रहती है। श्रीर यदि बाद बहुत तीव्र हुई तो तटबन्धों के वह जाने का भी हर रहता है। श्रधिक श्रच्छा उपाय तो भ्मि के संरच्या का है, इससे बाद की तीवता कम हों जायगी। इससे एक श्रीर भी लाम यह होगा कि बाद पीड़ित स्थानों की उपनाक मूमि के वह जाने की समस्या भी सुलम जायगी।

कठिनाइयाँ—िधचाई श्रीर विद्युत शक्ति उत्पादन योजनाश्रों को कार्या-न्वित करमें में निम्नलिखित श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

- (१) दोपपूर्ण योजना श्रीर श्रकुशल प्रवन्ध के कारण बहुत सा धन श्रीर प्रसाधन निष्फल हो गये। राव समिति में दामोदर घाटी कारपोरेशन के कार्य की परीज्ञा की श्रीर इस परिणाम पर पहुँची कि केवल कोनार योजना के कुप्रवन्ध के कारण १ ६४ करोड़ रुपये की हानि हुई। सिंचाई श्रीर विखुत शक्ति उत्पादन योजनायें जैसे बड़े कार्य में धन का थोड़ा बहुत नष्ट होना तो श्रवश्यम्मावी था क्योंकि कर्मचारीगण श्रनुमवहीन थे, श्रीर ऐसी स्थिति में भूत होना स्वामाविक या परन्तु वास्तिक हानि श्रनुमान से कहीं श्रविक हुई इसलिये भविष्य में इस वात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता का धन न्यर्थ न जाय।
- (२) "स्थिरयंत्रों और प्रसाधनों के क्रय के सम्बन्ध में निश्चित नीति के श्रमान के कारण समय-समय पर विभिन्न प्रकार के यंत्रों का क्रय किया गया। सिंचाई, शिक्त और योजना मंत्रालय द्वारा १९५३ में नियुक्त प्लान्ट और मशीनरी कमेटी ने सिफारिश की है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुख्य-मुख्य यांत्रिक प्रसाधनों को एक ही प्रमाप का होना चाहिए।
- (३) अपेद्यित योग्यता और सनद प्राप्त इंजीनियर और विशेषकों के श्रमाव के कारण भारत की नदी घाटी तथा श्रन्य योजनाओं को बहुत बड़ी किठनाई का सामना करना पड़ता है। यह समस्या दो प्रकार की है; (क) विशेषकों का श्रमाव तथा (ख) जो व्यक्ति दामोदर घाटी तथा श्रन्य योजनाओं का कार्य कर रहे हैं, वे श्रपने भविष्य के बारे में सशंक हैं कि इन योजनाओं का कार्य जब समाप्त हो जायगा तब उनका क्या होगा। एक समय भारत सरकार अखिल भारतीय सिंचाई तथा शक्ति विशेषकों का एक विशेष सेवा वर्ग बना रही थी, श्रथवा इसके स्थान पर ऐसे कर्मचारियों का जो विभिन्न प्रदेशों से श्राये थे एक संचय (deputation pool) बनाने का विचार कर रही थी।
- (४) विचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें सुधार-कर लगाने अथवा विचाई की दर बढ़ाने को बाध्य करती हैं। सुधार कर एवं विचाई की बढ़ी हुई दर के कारण कुछ प्रदेशों के कृषकों को अधिक मार वहन करना पड़ा है। इसलिये यह आवश्यक है, कि इन करों के आरोपित करने के साथ ही साथ इस वात का भी ध्यान स्क्खा जाय कि कृपकों की कर क्षमता कितनी है। यदि राज्य सरकारें सिंचाई की दर, सुधार-कर तथा शक्ति की दर (Power rate) निश्चय करते समय कृषकों को देय-समता को भी ध्यान में रखें तो बड़ा ही अच्छा हो।

श्रध्याय ११

सामुदायिक विकास योजनाएँ

भारतीय कृपकों की निर्घनता और आर्थिक दृष्टि से विछ्ड़े होने का प्रमुख कारण है कि वे नई प्रणालियों और जीवन के नवीन उपायों के प्रति उदासीन हैं। उनके सम्मुख जो जटिल समस्याएँ हैं उन्हें इल करने के लिए वे सुसंगठित रूप में प्रयत्न भी नहीं करते । सामुदायिक विकास योजनाश्चों के कार्य-क्रमों श्चौर राष्ट्रीय विस्तार सेवान्नों (National Extension Service) का उद्देश्य यह है कि उनके द्वारा "जनता के मानिसक दृष्टिकीण में परिवर्तन हो, उनमें जीवन के उच्तर स्तर तक पहुँचन का महत्त्वाकां ही श्रीर साथ ही साथ उस स्तर की प्राप्त करने के लिए हढ़ निर्ण्य श्रीर इच्छाशक्ति उत्पन्न की जाय। ग्रामों में निवास करने वाले ७ करोड़ परिवारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, नवीन ज्ञान व जीवन के नवीन उपायों के प्रति उत्पाह उत्पन्न करना श्रीर श्रेष्टतर जीवन व्यतीत करने के लिए उनके हुद्य में अभिलापा वं हुद्द इच्छा-शक्ति का संचार-यह वास्तव में एक मानवीय समस्या है।" इस उद्देश्य के पूर्ण होने के लिए इस बात की श्रावश्य-कता है कि निकास कार्य-क्रम आमीण जनता के ऊपर बलपूर्वक न लादे जायें. वरन् इस बात का प्रयास किया जाय कि उन लोगों में ही आत्मविश्वास का उदय हो ख्रौर वे नियीजन के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से रुचि के सर्कें। सामुदायिक विकास योजनुम्आं के श्राधारभूत सिद्दान्त निम्न हैं:--

(अ) "विकास कार्य के लिए प्रेरक-शक्ति स्वयं ग्रामवासियों से श्रामी चाहिए। श्रामों में विपुल शक्ति निष्क्रिय रूप में विखरी पड़ी है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। श्रातएव इस बात की श्रावश्यकता है कि वह शक्ति कियात्मक कार्यों के लिए नियोजित की जाय और प्रत्येक परिवार के सदस्य न केवल श्रापने हित के लिए कार्य करें वरन् सामुदायिक कल्याण के लिए भी समय दें।"

(व) "सहकारिता के सिद्धान्त को विविध रूपों में लागू होना चाहिए, विससे प्राम्य-जीवन की अनेक समस्याएँ इल की जा सके।"

सापुरायिक विकास योजनाश्चों के तीन उद्देश्य हैं : (१) कृषि, बागवानी, पशु-यालन, मछली-यालन श्रादि में वैज्ञानिक विधियों को लागू करके श्रीर श्रन्य पूर्क धंघों व कुट्टीर-उद्योगों को-पारंम करके वेरोजगारी दूर की जाय श्रीर उत्पादन

में वृद्धि की जाय (२) जनता के सहयोग से प्रत्येक ग्राम या कई ग्रामों को मिलाकर कम से कम एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था होनी चाहिए जिसमें क्रांप करने वाले लगभग सभी परिवारों के प्रतिनिधि हो, (३) गाँव की सहकों, तालाबों, पाट-शालाग्रों, स्वास्थ्य-फेन्द्रों ग्रादि सार्वजनिक हित के निर्माण-कार्यों के लिए ससंगिदत प्रयास होना चाहिए। इसके ग्रांतिरक्त ग्रामीण जनता में प्रगतिशील हिटकोण उत्यन करने की भी ग्रावश्यकता है।

यह सामुदायिक विकास योजना २ श्रयत्वर १६५२ को प्रारंभ की गई यी, जिसके अन्तर्गत ५५ फेन्द्रों में सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रचालित की गई। इन योजनात्रों का कार्यचेत्र लगभग ३०,००० ग्रामी तक विस्तृत है जिनकी जनसंख्या लगभग १ करोड़ ६८ लाख है। कालान्तर में और भी अधिक सामुदा-यिक विकास योजनाएँ चलाई गई श्रीर २ श्रक्त्वर १९५३ को राष्ट्रीय प्रसार सेवा के श्रन्तर्गत प्रसार-मंडलों (Extension Blocks) का भी समारंभ किया गया। इस प्रकार इस समय दो योजनाएँ साथ-साथ चल रही हैं, जिनमें से प्रथम हैं सामुदायिक विकास योजनाएँ श्रीर द्वितीय हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ। 'इन राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के भी वही उद्देश्य हैं जो सामुदायिक विकास योजनाओं के हैं। कृपि, पश्च-पालन, शिचा, स्वास्य्य श्रादि चेत्रों में दोनों के कार्य-कर्मों में पर्याप्त समानता है। उनमें यदि कोई मेद है तो यही कि सामुदायिक विकास योजनाश्ची का कार्य-क्रम विस्तृत है श्रीर इसके श्रन्तर्गत स्थानीय कार्यो पर पर्याप्त धन-राशि भी ज्यय की जायगी योजना में यह ज्यवस्था की गई है कि जिन विकास-मंहलों की प्रगति पर्याप्त रूप से संतोषजनक होगी श्रीर जहाँ जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा, उन्हें सामुदायिक विकास योजना के श्रन्तर्गत सुसंगठित के लिए चन लिया जायगा ।

संगठन सामुदायिक विकास योजना की न्यवस्था पंचायतों श्रीर इसी उद्देश्य के लिए निर्माण की गई श्रन्य उच्च संस्थाओं द्वारा की जाती है। "जनता श्रीर उसके श्रनेक प्रतिनिधियों से काफी विचार-विमर्श करने के उपरान्त विकास कार्य-क्षम निश्चित किया जाता है। गाँव के स्तर पर नियोजन का कार्य-मार पंचायत पर ही रहता है। वही विकास कार्यक्षम को कार्योन्वित भी करती है। जिन चेश्रों में या तो पंचायतें बिल्कुल है ही नहीं या उनका श्रिषक प्रभाव नहीं है, वहाँ यह प्रयास किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए आमीण विकास सिनित्यों की स्थापना की जाय, जिन्हें श्राम-विकास मंडल, श्राम मंडल समिति, श्राम सेवा संघ श्रादि कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इन्हीं संस्थाओं के द्वारा नियोज्जन के कार्य-क्षम को कार्यान्वित करने के लिए जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त

होता है। विकास-मंद्रल के स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति की त्यापना की जाती है, जिसमें ग्राम समितियों के प्रांतनिधि, विधान-परिषद, विधान-सभा व संसद के सदस्य, महकारी समितियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कृपक प्राहि समिन-लित होते हैं। यह परामर्शदात्री सीमिति ग्राम-संस्थात्रीं द्वारा तैयार की गई योज-नाथों पर विचार करती है। फिर इस परामर्शदात्री समिति द्वारा निर्माण की गई मंडल की विकास योजनाओं को जिला विकास समिति के द्वारा जिले की विकास-योजना के कार्य-क्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस जिला विकास समिति में प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति श्रीर जिले के श्रनेक टेविनकल विमागों के श्रध्यक सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विकास योजना तियार करने श्रीर उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकारी श्रीर गैरसरकारी संगठन साय-साय कार्य करते हैं । इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि "वर्तमान शासन-सम्बन्धी सरकारी दाँचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जा रहा है कि वह जन-कल्याण के दायित्व का भी निवाहकर सकें, जिसका परिणाम यह है कि सामान्य प्रशासनयंत्र से मिल्ल एक पृथक जन-कल्याण विभाग स्थापित करने की आवश्यकवा नहीं है। इसका तालर्थ यह है कि निष्ठ मशासन-यंत्र (administrative machinery) की रचना राजस्व-संग्रह (revenue collection) का निरीक्षण ऋौर नियम व न्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने परि-वर्तित होकर कल्यागुकारी शासन का रूप ग्रहण कर लिया है श्रीर सरकार के विकास-सम्बन्धी सभी विमागों के साधनों का उपयोग ग्राम-विकास की समस्याल्ली को इल करने के लिए किया जा रहा है।"

विकास-सम्बन्धी नीति के सामान्य सिद्धान्त निर्घारित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य विकास सिमित (State Development Committee) की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य-मंत्री श्रांर विकास-कार्य ने सम्बद्ध श्रनेक विभागों के श्रध्यज्ञ सिमिलित होते हैं। देवलँपमेन्ट किमिश्नर इस सिमित का मंत्री होता है श्रीर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वह सरकार के विकास के सम्बन्ध! श्रनेक विमागों के श्रध्यज्ञ श्रीर मिन्त्रयों के दल का प्रधान भी होता है। जिले, तहसील श्रीर मंडल के स्तर पर ऐसा ही समन्वय स्थापित करने के लिए देवलपमेन्ट किमिशनर से समान ही कमशाः कलक्टर श्रीर मंडल-विकास श्रिकारी (Block Development Officer) को भी उसी प्रकार के कार्य सींप गए हैं। विकास-सम्बन्धी शासन की इस शृंखला में ग्राम-सेवक श्रन्तिम कड़ी के समान होता है श्रीर जिले के शासन का एक श्रंग समका जाता है। श्रीर वह-उदेशीय कार्य करमें पढ़ते हैं। शासन के दिन्ने को निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि

श्रिधिकारी अधिक से अधिक कार्यं ज्ञमता से काम करें और जनता से अधिकतर सहयोग उपलब्ध है।

योजना के अन्तर्गत—राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनायें अथम पंचवर्षीय योजना की देन हैं। कार्य की इकाई एक विकास मंडल है, जिसके अन्तर्गत लगभग १०० आम आते हैं, जिनकी जनसंख्या ३०,००० से लगाकर ७०,००० तक होती है, और उनका चेत्रफल १५० से १७० वर्गमील तक हो सकता है, १९५२ में जब से यह कार्यक्रम आरम्म हुआ है; समुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत २०० मंडल और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत २०० मंडल वना लिए गये हैं, और इस प्रकार १९५६ तक विस्तार मंडलों का योग १२०० हो गया है। इसके अन्तर्गत तालिका नं० १ के अनुसार १२३००० आम और प्रकार इन्हर्ग व्यक्ति आ नार्येंगे।

तालिका नं ० १ विकास मंडल का कार्य जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में श्रारम्भ किया गया

	१९५२-५३	१६५३-५४	१६५४-५	५ १९५५	-प्६ जोइ
विकास महल					
सामुदायिक विकास	. १४७	પૂર			300
राष्ट्रीय विस्तार	•••	ર પૂ १	२५३	३८६	600
जोइ	२४७	₹08	રપૂર	३९६	१२००
माम संख्या •					
सामुदायिक विकास	१ २५,२६४	७,६६३	•••	•••	३२,६५७
राष्ट्रीय विस्तार	***	२५,१००	२५,३००	३६६००	80,000
जो <i>इ</i>	२५,२६४	₹२,७६३	२५,३००	₹€,600	१,२२,६५७
जनसंख्या (दस लार	झ में)				
रा मुदायिक विकास	१६,४	8.	·	•••	₹0,४
राष्ट्रीय विस्तार	•••	१६.६	१६,७	२६.१	५६.४
जोइ -	. १६.४	₹0.8	१६,७	२६.१	5.30

विकास दोत्र में १४००० नये स्कूलों को आरम्म करना और ५१५४ पाइ-मरी स्कूलों को वेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाना है, ३५००० वयस्कों के लिये शिज्ञा केन्द्रों का स्थापित करना, जिनके द्वारा ७७,३०० वयस्क साज्ञर किये गये हैं, तथा ४०६६ मील पक्की श्रीर २८००० मील कची सहक का बनवाना श्रीर ८०,००० शीचालयों का गाँवों में निर्माण करवाना स्थानीय विकास के उदाहरण हैं। जिनका सामाजिक प्रमाव बहुत ही महत्वशाली होगा। इस कार्य में
बहुत श्रीषक श्रंश तक सहायता जनता तथा विस्तार योजनाश्रों को कार्यान्वित
कराने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त हुई है, जिन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य
किया है। यदि श्राम उद्योगों तथा सहकारिता के च्रेत्र में सफलता कम प्राप्त हुई
है, इसका कारण यदि सम्पूर्ण देश के दिन्दिकोण से ही देखा जाय तो सहकारिता
तथा नवीन उद्योगों की कार्य व्यवस्था का दोप है, जिसमें सुधार करना चाहिए।

"राष्ट्रीय विकास परिपद् ने सितम्बर १६५५ में यह स्वीकार कर लिया या कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त देश राष्ट्रीय विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आ जायगा आर जा राष्ट्रीय विस्तार मंडल सामुदायिक विकास मंडलों में परिणत कर दिये जार्येंगे, आर उनकी संख्या ४०% से कम न होगी। यदि पर्याप्त विचीय सहायता प्राप्त हा सकेगी तो सम्भवतः यह संख्या ५०% भी हो जाय। द्वितीय योजना में ३८०० नये विकास मंडल राष्ट्रीय विस्तार योजना के क्सर्यक्रम के अन्तर्गत आरम्म किये जाने वाले हैं और यह आशा की जातो है कि इनमें से ११२० सामुदायिक विकास मंडलों में परिणित कर दिये जायेंगे। योजना के इस कार्य के लिए २०० करोड़ स्वयों का भी प्रवन्ध प्रवन्ध किया गया है।"

"सामुदायिक योजना प्रशासन के निश्चित किए हुये कार्यक्रम के श्रनुसार —िद्धतीय पंचवर्षीय योजना में, प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय विस्तार मंडल तथा उनके सामु-दायिक विकास मंडलों में परिगात किये जाने का कार्य किया जाया करेगा।" जैसा कि तालिका नं० २ में दिखाया गया है।

तालिका नं० २ विस्तार मंडलॉ की संख्या

वर्प	राष्ट्रीय विस्तार सेवा	सामुदायिक विकास मंडलों में परिवर्तन
१६५६-५७	400	२५०
१ ९५७- ५ ८	६५०	200
१६५⊏-५६	७४०	₹6,0
१ ६५६-६०	800	₹00
१६६० ६१	१०००	3 Ę 0
	, ३८००	११२०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि श्रपने रहन-सहन के स्तर को सुधारना तथा एक निश्चित कार्यक्रम का श्रनुसरण करना श्रीर उसमें सहयोग देना उनका कर्चन्य है। यह श्राशा की नाती है, कि राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा श्रीर श्रन्य श्रनुपूरक कार्यक्रमों द्वारा श्रागामी कुछ वर्षों में ही कृषि उत्पत्ति में वृद्धि के श्रातिरिक्त निम्न श्रन्य चेत्रों में उन्नति होगी। (१) सहकारिता के कार्य में जिसमें सहकारी कृषि भी सम्मितित है विस्तार होगा, (२) ग्रामोन्नति में स्वान्य उत्तरदायित्व रखनेवानो संस्थाओं के रूप में ग्राम पंचायतों का विकास होगा, (३) भूम की चकन्दी, (४) ग्राम के छोटे उद्योगों का विकास होगा, (५) ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना हागा जिनमें गाँव के पिछड़ी हुई जनता को जैसे छोटे-छोटे कुषक, भूमिहीन कृषक, कृषि कार्य करने वाले मजदूर एवं शिल्पी हत्यादि, (६) स्त्रियों श्रीर नवयुवकों की उन्नति के लिये श्रीर पिछड़ी जातियों के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाये नार्येगे।

"ऐसे बहुमुखी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये जिसके अन्तर्गत उद्योग, सहकारिता, कृपि उत्पादन, भूमि सुघार, तथा सामाजिक सेवार्ये आती हैं.. जो च्रेत्र राष्ट्रीय विस्तार तथा सामूदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिये चुने जायेंगे. उनके शीघ ही उन्नांत करने की बहुत श्रधिक सम्मावना होगी। जब इन कार्य-क्रमों को संयोजित रूप से कार्यान्वित किया जाता है, और स्थानीय संस्थाओं का सहयांग व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है, तो एक कार्य में सफलता दुसरे में सफलता के लिए अवसर प्रदान करती हैं। श्रीर इस प्रकार सम्पूर्ण क्रेत्र में आयिक व्यवस्था इद् हो जाती है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य-क्रम में क्रांव उत्पादन को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। इसके पश्चात प्राम की सबसे अधिक महत्वशाली आवश्यकता कार्य करने के पर्याप्त अवसरों का प्रदान करना है। संतुलित प्राप्य श्राधिक व्यवस्था में यह श्रावश्यक है, कि श्रीद्योगिक कार्यो के अवसरों की कृषि कार्यों को अपेचा हहतर गति से वृद्धि की जाये। हाल के माम तथा छोटे उद्योगों के विकास कार्य-कामों के सम्बन्ध में जो अनुमव हुआ है उससे यह संकेत मिलता है, कि ऐसी विस्तार सेवा की श्रावश्यकता है, जिसका सम्पर्क ग्रामीय शिल्पकारों से हो श्रीर जो उन्हें श्रावश्यक पथपदर्शन कर सके. सहायता दे सके, उनकी सहकरिता के आघार पर व्यवस्था कर सके और अपने माल को गाँव में तथा बाहर बेचने में सहायता दे सके। इसका प्रारम्भ २६ श्रमगामी योजनाश्रों को कार्यान्वित करके किया जा चुका है। यह श्रावश्यक है

कि यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक विस्तार तथा सामुदायिक विकास चेत्र में एक प्रवीण प्रशिक्तित इन ग्राम उद्योगों के कार्यक्रम को चलाने के लिये नियुक्त किया जाय।

वित्त की व्यवस्था—इन विकास कार्य-क्रम के लिए वित्त की व्यवस्था सामुदायिक योजना प्रशासन (Community Project Administration), राज्य सरकारों श्रीर जनता के द्वारा की जाती है। सी० पी० श्रार्थिक रूप से वित्त का प्रवस्थ तो करता ही है, इसके श्रातिरिक्त उस पर विशेष यन्त्रों व तत्सम्बन्धी श्रात्य सामांग्रयों को उपलब्ध करने का भी दायित्व है। इस विकास कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने के लिए श्रातिरिक्त कर्मचारियों को रखने पर जितना व्यय होगा, उसका श्राधा धन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा श्राधिक सहायता के रूप में प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार यह प्रयास मी कर रही है कि योजना की श्रविध समाप्त होने तक सहकारी श्रनदोलन श्रीर श्रन्य एजेन्सियों के द्वारा श्रात्यकालीन, श्रीसतकालीन श्रीर दीर्घकालीन श्रीर श्रम्य एजेन्सियों के द्वारा श्रात्यकालीन, श्रीसतकालीन श्रीर दीर्घकालीन श्रीर होने लगे। सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्रम पर जो धन-राशि व्यय होती है उसकी लगमग १०% मारतीय-श्रमरीकी टेकनिकल सहयोग योजना द्वारा यन्त्रों श्रीर टेकनिकल परामर्श श्रादि के रूप में प्राप्त होती है।

सामुदायिक योजनान्नों न्नीर विकास मंडलों के लिए १६५२-५३ से लेकर १६५५-५६ तक कुल मिला कर ३२.६० करोड़ कपये घन का वजट में स्वीकृत हुन्ना है। इस प्रकार मार्च १६५४ तक प्रथम १८ महीनों में व्यय के लिए १६.३० करोड़ कपये निर्धारित थे, किन्तु इस अविध में वास्तव में जो घन राशि व्यय की गई वह केवल ५.६५ करोड़ कपया थी। इसके अतिरिक्त इस अविध में नकद धन, श्रम, सामग्री त्रादि की ऐच्छिक सहायता के रूप में कुल मिलाकर २.६३ करोड़ रूपया का घन प्राप्त हुन्ना, जो सरकारी व्यय के घन के ज्ञाचे से योड़ा ही कम है। प्रारम्भिक काल की श्रमेक कितनाइयों के कारण योजना की प्रगति घीमी रही, किन्तु जब हम इस तथ्य पर घ्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५४ तक व्यय की कई घनराशि ८१० करोड़ रूपये तक पहुँच गई, तो भविष्य में श्रिषक तीत्र प्रगति होने की संभावना प्रकट होती है।

वीमी प्रगति के कारण सामुदायिक योजनात्रों की प्रगति का मृत्यांकन वरने के लिए कीर्ड फाउन्डेशन के सहयाग से एक कार्य-मृत्यांकन संस्था (Programme Evaluation Organisation) की स्थापना की गई है। सामुदायिक योजनात्रों को कार्यान्वित करने के मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ हैं—

(१) प्रारम्भिक अवस्था में प्रगति के अवस्य होने का कारण यह था कि

जनता उदासीन थी और श्रन्य लोकियय व्यक्तियों ने भी योजना के कार्य-कम में सिक्य रूप से माग नहीं लिया। इस स्थिति में किसी सीमा तक सुघार श्रवश्य हुश्रा है, किन्तु फिर भी ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। प्रगति के धीमी और अनिश्चित होने का यह एक प्रमुख कारण था।

(२) पंचायतों श्रयवा विशेष कर इसी उद्देश्य से स्थापित की गई श्रन्य लोक प्रिय संस्थाओं से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, वह श्रपर्याप्त है। पंचायतें सभी चेत्रों में नहीं हैं श्रीर जहाँ हैं भी, वहाँ उनमें गुटबन्दी के कारण प्राय: संघर्ष चलता रहता है। सहकारी संस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं, किन्तु विकास योज नाओं के सम्बन्ध में उनकी उपयोगिता सीमित ही है। उनके नियमों के श्रनुसार सामान्य रूप से सदस्य भी नहीं बनाए जा सकते, वयोंकि उनका चुनाव किया जाता है। सहकारी संस्थार्थों की रचना ही कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है जिससे उनके कार्य सीमित होते हैं। विकास कार्य-कम की सहायता के लिए अनेक परामर्श्वात्री संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनके मिन्न-मिन्न नाम है और जो कुशल श्रिषकारियों के निर्देशन में सन्वोषजनक कार्य कर रही हैं। किन्तु किर भी यह श्राशंका बनी हुई है कि जब सरकारी श्रिषकारी हटा लिए जायेंगे, तो संमव है कि ये संस्थाएँ कार्य करना बन्द कर दें।

(३) चीमी प्रगति के लिए उचित योजना का अमाव भी अधिक सीमा तक उत्तरदायी है। विकास की प्रगति इसलिए घीमी नहीं रही है कि आवश्यक विच का अभाव था, वरन् उसका कारण यह था कि प्रारम्भिक अवस्था में अधि-कारियों-द्वारा वजट में कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की गई। इसके अति-रिक्त अन्य कारण भी थे। बजट बहुत जल्दी में तथा अस्पष्ट विचारों के साथ तैयार किए जाते थे तथा धनराशि को मंजूरी देने के पूर्व विवरण जानने में समय जगता था।

(४) कार्य-क्रम की इस घीमी प्रगति और अनेक भूलों के लिए प्रशिक्षण-प्राप्ति कर्मचारियों का अभाव बहुत बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। किन्तु अब अधिक संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर यह अभाव शोवता से दूर किया. जा रहा है।

पी॰ ई॰ श्रो॰ की तीसरी सफलतांकन रिपोर्ट (Evaluation Report)-ने कार्य को समुचित रूप से चलाने के सम्बन्ध में श्रानेक प्रयोगात्मक सुमान दिये हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्राय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्य-कम को आशानुकूल सफल वनाने के लिये यह आवश्यक है कि (१) औद्योगिक विभागों को प्रत्येक दिशा में

श्रीर प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में दृढ़ बनाया नाय । श्रनेक स्थानी पर प्रत्येक चेत्र तया जिला सम्बंधी श्रीद्योगिक विभागीय व्यवस्था की समता तथा संख्या में सुघार करना श्रावश्यक हो गया है, (२) इसके श्रातिरिक्त श्रन्वेपण के कार्य की सुविधाओं का विस्तार किया जाय, भूमि के श्रास-पास के गवैपगागारों की विस्तृत किया जाय श्रीर इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि खेती ते एव सूचनायें गवेपसागों तक पहुँच जॉय, (३) विभिन्न विषयों के विशेषशी पर चेत्र विकास कर्मचारी के नियन्त्रण (जो आवश्यकता ते अधिक हो एकता है) तथा ज़िलां के श्रन्य प्राविधिक श्रधिकारियों के दुहरे नियन्त्रण की व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है। (४) निर्माण कार्यों ने बामों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का जिनको कृषि तथा कृषि विस्तार की प्रारम्भिक शिज्ञा मिली है और जिनका रायते श्रधिक त्रावरयक कर्त्तन्य कृषि उत्पादन बढ़ाने का है, श्रधिकांश समय ले लिया हैं, (५) ग्राम पंचायतों को श्रपने वृद्धिमान उत्तरदायित्व को जो कि उनके ऊपर ढाल दिया गया है पूर्ण करने के लिये सदीव पथ प्रदर्शन तथा सिक्य सहायता मिलनी चाहिए; (६) कार्य-क्रम को कार्यान्त्रित करने में श्रावश्यकता ते श्राधिक महत्व मीतिक श्रीर श्रायिक उफलताश्रों पर दिया गया है, जैसे निश्चित किये हुये कार्य के, न्यय श्रीर मवन निर्माण के ध्येयों को पूरा करना इत्यादि; श्रीर जनता को नये ढंग से कार्य करने की शिज्ञा देने तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सुघार श्रीर विकास सम्बन्धी कार्यक्रनों के पूर्ण करने के लिये, जो राष्ट्रीय पादेशिक योजना के श्रन्तर्गत ई, एक प्रमावशाली खाधन बनाने की श्रोर कम ध्यान दिया गया है।

कार्य करने में त्रुटि—णमुदायिक विकास योजनाश्रों ने प्रामीण जनता में श्रात्मविश्वास उत्पन्न करने में बहुत कुछ योग दिया है। उसने प्रामनिवासियों को इस बात का श्रामास दिया है कि प्राम्य-जीवन में निश्चित रूप से कुछ गए-वड़ी है जिसका पारस्परिक सहयोग के श्राधार पर ही सुधार किया ना सकता है। श्रामी इतना श्राधिक समय नहीं हुशा है कि इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके; फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि सामुदायिक विकास योजनाशों ने उत्पादन बढ़ाकर श्रीर वेरोजगारों कम करके प्रामों में रहन सहन का स्तर कँचा किया है। किन्तु जिस रूप में कार्य-त्रम को कार्यान्यित किया जा रहा है उसमें कई दोप हैं: (१) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के श्रम का उपयोग करने की समुचित व्यवस्था नहीं है। कृषि के स्त्रेत्र में उत्पादन-वृद्धि श्रीर कृपकों के लिए कार्य के श्रवसर उत्पन्न करना श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है, किन्तु भूमिहीन मजदूरों को बसाने की व्यवस्था मी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब कमी विकास योजनाशों

के ब्रन्तर्गत ब्रस्थायी रूप से मजदूरी देकर कार्य करने की ब्रावश्यकता पड़ती है तभी इन्हें योड़ा-बहुत कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त वे नि:सहाय, वेरोनगार श्रीर उपेद्मित-से रहते हैं, (२) यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय तो छामुदायिक विकास योजना श्रों के कार्य-क्रम में एक श्रीर दोण प्रकट होगा। वह यह है कि खेतिहर मजदूरों को पूरक कार्य उपलब्ध कराने के लिए ग्राम्य-उद्योगों की स्थापना करने पर विशोष ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में पी० ई० स्रो० की यह धारणा है कि "ग्रामीण उद्योग-धन्धों की ग्रानिश्चित संमावना के पीछे चाहे जो मी कारण हों, किन्तु तथ्य तो यह है कि सामुदायिक विकास योजनास्त्रों के वर्तमान स्वरूप और साधनों से भूमिहीन मजदूरों की वेरोजगारी की समस्या इल करने की श्राशा नहीं की जा सकती"। किन्तु पी० ई० श्रो० का यह दृष्टिकीया गलत है। चिक वासुदायिक विकास योजनायों का उद्देश्य है कि उत्पादन कार्य थ्रौर प्रामीण जनता की अगय में वृद्धि हो अगैर ग्रामवासियों में नई श्राशा का संचार किया जाय, इसलिए गैर खेतिहर वर्ग की वेरोजगारी की समस्या को उपेचा की हिन्द से देखना उचित नहीं है ऐसा करने पर सामुदायिक विकास योजनाओं की उपयो-गिता बहुत कुछ कम हो जायगी, (३) सामुदायिक यिकास योजना के अन्तर्गत भूमि की समस्या को सुलकाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। चकवन्दी का कार्य एक अन्य संगठन द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इसने अभी श्रिधिक सफलता नहीं पाप्त की है । बम्बई, उत्तर-प्रदेश श्रीर सीराष्ट्र को छोड़कर सहकारी कृषि के चेत्र में अधिक प्रगति नहीं हुई है और इन राज्यों में भी यह श्रान्दोलन श्रपनी पार्राम्मक श्रवस्था में ही है। बहुत से कृषकों के पास कृषि के लिये इतनी कम भूमि है कि उस पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभ-पूर्ण नहीं है। जब तक कृषि की इकाई के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि का चेत्रफल नहीं बढ़ाया जाता और निम्नतम लागत से अधिकतम उत्पादन नहीं होगा, तब तक किसान खेती की विकसित प्रणालियों का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सर्केंगे, श्रौर (४) सामुदायिक विकास योजना के कार्य-कम में अब तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे जन-संख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाय श्रीर परिवार-ग्रायोजन (Family Planning) का सुचार प्रबन्ध हो सके। जब तक यह कार्य नहीं हो जाता तब तक मारतीय ग्रामीय जनता की जटिल समस्याश्रों को सन्तोषजनक रूप से इल करने की आशा करना क्यर्थ है। उत्पादन बढ़ाकर और जन-संख्या की वृद्धि को नियंत्रित करके ही आमवासियों के रहन सहन का स्तर ऊँचा किया जा सकता है।

श्रध्याय १२

सहकारी आन्दोलन

भारत में सहकारी श्रान्दोलन का विकास २० वीं शताब्दी में हुशा। सहकारिता का श्रर्थ है किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयत्न
करना। समान उद्देश्य की हिंदि से यह व्यक्तिगत प्रयत्न श्रीर सहायता से निल्कुल
भिन्न है। श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की परिभाषा के श्रनुसार सहकारी समिति ऐसे
व्यक्तियों की संस्था है जिनकी श्रायिक स्थिति श्रव्ही नहीं है श्रीर जो समान
श्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के श्राधार पर स्वेच्छा-पूर्वक संगठित होकर श्रपनी
ऐसी समान श्राधिक श्रावश्यकवात्रों की पूर्ति का भार एक संस्था को सींप देते हैं
जिनको वह श्रपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा पूर्ण्वः सन्तुष्ट कर सकने में श्रसमर्थ
होते हैं। यह लोग श्रापस में मिलकर इस संस्था का प्रबन्ध करते हैं श्रीर समान
मौतिक एवम् नैतिक लाम उठाते हैं। इस प्रकार सहकारी समित समान हितों का
संघ है; यह समान श्रिषकार प्राप्त सदस्यों का त्वेच्छा से निर्मित एक ऐसा श्रायिक
संगठन है जो श्रपने सदस्यों की श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति करता है श्रीर उनके
समान हितों की रज्ञा करता है।

सहकारी समितियाँ दो प्रकार की हैं—(१) रेफिजेन (Raiffelsen type) श्रीर (२) ग्रुल्ज डेलिरज (Schulze Delitsch type)। इन दो प्रकार की सहकारी समितियों में जिन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है वह जर्मनी में सहकारी श्रान्दोलन के प्रयोता थे। प्रथम प्रकार की सहकारी समिति के सिद्धान्तों का उपयोग ग्राम में संगठित की जानेवाली समितियों में किया जाता है श्रीर दूसरे प्रकार की समितियों के सिद्धान्तों का उपयोग नगरों में किया जाता है। रेफिजेन-सिर्मितियों का कार्य चेत्र प्रायः एक ग्राम तक सीमित रहता है श्रीर इनके सदस्यों का उत्तरदायित्व श्रसीमित होता है। इन सिमितियों से केवल सदस्यों को ही श्रम्य दिया जाता है श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्त-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीय कर भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्त-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीय कर भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्त-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीय कर भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्त-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीय कर भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्त-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीय कर भी सीमित है। इस प्रकार की सीमित सदस्यों से प्रवेश श्रुक्त वस्ती है श्रीर विना श्राय वाला व्यक्ति इसका सदस्य नहीं वन सकता है।

वित्त, उत्पादन, वितरण इत्यादि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन समितियों को संगठित किया जा सकता है परन्तु भारत में ऋण देने वाली साल समितियों का ही प्रभुत्व है। वास्तव में भारत में सहकारी आन्दोलन आरंभ करने का निश्चित उद्देश्य प्रामों में भूग्ण की भयानक समस्या को हल करना श्रीर आमीयों को सुविधा जनक रीति से भूग्ण देना था। भारत में जून १९५५ में सब प्रकार की २,१६,२८८८ समितियों की तुलना में जून १६५६ में २,४०,३६५ सहकारी समितियाँ थीं। कृषि साल समितियाँ ही प्रमुख थीं। इनकी संख्या कुल समितियों की ६७३% तथा कृषि समितियों की ८०३% थी। आन्दोलन अब भी साल-प्रधान है।

विकास—भारत में सहकारी आन्दोलन के इतिहास की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण घटना १६०४ का सहकारी साल-समिति अधिनियम है। इस नियम के बनने
से पूर्व भी मद्रास में सहकारिता के सिद्धानों का महत्वपूर्ण विकास हो रहा था।
वहाँ साल-समितियों का कार्य 'निधियाँ' करती थीं। देश में सहकारिता के विभिन्न
पश्चों का अध्ययन करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६०१ में एक समिति नियुक्त
की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब तक सरकार अधिनियम
नहीं बनाती इस दिशा में विशेष प्रगति की संमावना नहीं है। इसी रिपोर्ट के
आधार पर सरकार ने सहकारी साल-समिति अधिनियम पास किया। इसमें केवल
साल-समितियों की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार अन्य देशों की अपेशा मारत
में सर्वप्रथम साल-समितियों का ही विकास हुआ। नियम लागू होने के पश्चात
यह अनुभव किया गया कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। साल-समितियों के पास आम में ऋगा प्रथा समाप्त करने के लिए आवश्यकता से बहुत कम
पूँजी थी।

इंग्र नियम के दोषों को दूर करने के लिए १६१२ में दूसरा सहकारी समिति अभिनियम पास किया गया। इस नियम में कथ-विक्रय करने वाली अन्य प्रकार की सहकारी समितियों का संगठन करने की न्यवस्था की गई। नगर और प्राम सितियों के अंतर को मिटा दिया गया। सीमित उत्तरदायित्व और असीमित उत्तर-दायित्व के आधार समितियों को अधिक वैद्यानिक रूप से वर्गीकृत किया गया। नियम में यह निश्चित कर दिया गया कि जिन समितियों के सदस्य राजस्टर्ड समितियाँ हैं वह सीमित उत्तरदायित्व वाली समितियाँ होंगी और साख-समितियाँ तथा ऐसी अन्य समितियाँ जिनके आध्वकांश सदस्य कृषक हैं असीमित उत्तरदायित्व वाली समितियाँ होंगी। इस नियम से सहकारी आन्दोलन के विकास में सहायता मिली। उत्पादन के विकाय के लिए, पशु-बीमा, दूध की पूर्ति और खाद इत्यादि क्रय के लिए नई प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई।

मैक्लैगन समिति की रिपार्ट के श्राधार पर सहकारी श्रान्दोलन के विकास

में एक और प्रयास किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर १६१६ के सुधार अधिनियम (Reform Act) के द्वारा सहकारी आन्दोलन का कार्य राज्य-सरकारों को सींप दिया गया। राज्य सरकारों ने कुछ वर्षों तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की परन्त १६२५ में वम्बई की सरकार ने अलग से सहकारी सिमिति अधिनियम नियम बनाया। इसके पश्चात अन्य राज्यों में भी आवश्यक कानून बनाये गये।

सहकारिता श्रान्दोलन के विकास का कुछ श्रनुमान इस वात से लग सकता है कि १६५१-५२ में समितियों की संख्या, सदस्या संख्या तथा कुल चालू पूँनी क्रमशः १'द्रभ लाख, १३७'६२ लाख तथा ३०६'३४ करोड़ ६० थी। १६५५-५६ में यह बहु कर क्रमशः २.४० लाख, १७६.२ लाख ग्रीर ४६८.८२ करोड़ ६० हो गई। विभिन्न प्रकार की समितियों के दृष्टिकीण से अन्य समितियों की अपेचा कृषि साख समितियों में वृद्धि श्रिषक हुई है। पिछले वर्षों की ही तरह साख समितियाँ ही अधिक प्रधान रही और कुल चालू प्रेंजी का ७५% साख चेत्र में ही था। यह मानते हुए कि भारतीय परिवार के सदस्यों की श्रीसत संख्या ५ है इम कह सकते हैं कि १६५५-५६ में = द करोड़ व्यक्ति श्रयवा जनसंख्या के २३ प्रति-शत व्यक्ति सहकारी श्रान्दोलन के सम्पर्क में श्राये। १६५१-५२ में ६'६ करोड़ व्यक्ति ग्रयना १६ प्रांतशत जन संख्या सम्पर्क में ग्राई थी। इसी प्रकार (प्राइमरी) प्रायमिक समितियों, जो आन्दोलन का आधार प्रस्तुत करती है, द्वारा १६५१-५२ में दिया हुन्ना ९७'६५ करोड़ ६० था। १६५५-५६ में यह राशि बढकर १४०'७८ करोड़ र० हो गयी। दिये गये ऋण की इस वृद्धि से भी प्रगति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। चिन्ता का विषय तो यह है कि वकाया ऋगों के प्रतिशत के रूप में कालातीत ऋगों में कुछ कमी अवश्य हुई है किन्तु उनका अनुपात अव मी बहुत श्रधिक है।

प्रगति के इस संहित सर्वेद्यण से इम इस निष्कपं पर पहुँचते हैं कि (क) सहकारिता से बनसंख्या का बहुत छोटा ग्रंश लाभ उठा रहा है; (ख) जनसंख्या की वृद्धि के श्रानुक्ल श्रानुपात में सहकारिता का विकास नहीं हुआ है; (ग) यद्यपि गैर साख समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है, किर भी साख समितियों का ही श्राधिक विकास हुआ है। इसलिये सहकारिता आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिये यह श्रावश्यक है कि सहकारी समितियों में साख के श्राविरिक्त अन्य पत्तों पर मी आवश्यक ध्यान देना चाहिये।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ — सहकारी आन्दोलन न तो सारे देश में समान रूप से फैला है और न सभी लगह इसका सङ्कठन समान है। सहकारी आन्दोलन ने खरह 'क' के कुछ राज्यों में विशेष प्रगति की है परन्तु अन्य राज्यों में इसका उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है। खरह 'ख' और 'ग' राज्यों में से कुछ में इस आन्दोलन का विल्कुल विकास नहीं हुआ। सम्पूर्ण देश में कुल जितनी सहकारी समितियों हैं उनका ३८ प्रतिशत और प्रारम्भिक समितियों के लगमग ४६ प्रतिशत सहस्य केवल वम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में हैं जबिक उत्तर प्रदेश, मद्रास, वम्बई, पश्चिमी बङ्गाल, पञ्जाब तथा हैदराबाद में क्रमशः ६१ तथा ६५ प्रतिशत है। परन्तु देश में नहाँ जनसंख्या तथा चेत्रफल में मारी अन्तर है सहकारी समितियों की प्रगति की जाँच करने के लिए समितियों की संख्या उपयुक्त नहीं है। यह जानना आवश्यक है कि इन समितियों से कितने प्रतिशत जनता लाम उठाती है। कुछ खरह 'ख' और 'ग' राज्यों में सहकारी समितियों का कार्य सन्तोप-जनक रहा है। रिजर्थ वैद्ध ने सुमाय दिया है कि सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में समितियों के कार्य-चेत्र पर और खरह 'ख', 'ग' और 'घ' राज्यों में उनकी कार्य कुशलता पर विशेष महत्व दिया जाय। सङ्गठन—सहकारी समितियों का सङ्गठन वास्तव में शुंडाकुति (Pyramid)

सङ्गठन—सहकारी समितियों का सङ्गठन वास्तव में शुंडाकृति (Pyramid) के समान है। इस सङ्गठन का आधार वह प्रारम्मिक सहकारी समितियाँ हैं जिनको सङ्गठित करने के लिए कोई भी दस व्यक्ति सहकारी समितियों के रिजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दे सकते हैं। विभाग के निरीक्षक द्वारा आवश्यक लाँच-पहताल के पश्चात् समिति स्थापित करने की अनुमित दी जाती है। इन समितियों की चालू पूँजी, प्रवेश शुल्क, सरकारी श्राण, केन्द्रीय समितियों तथा राज्य वैद्धों से श्राण लेकर एकत्र की जाती हैं। इन में से कुछ समितियों के पास श्रेयरों की पूँजी भी है। केवल साख समितियों को छोड़कर इन समितियों का उत्तरदायित्व सीमित है और सारी व्यवस्था प्रवन्धक समिति तथा आम-सभा के हाथ में होती है।

इन प्रारम्भिक समितियों के कपर केन्द्रीय समितियाँ छौर राज्यीय सहकारी समितियाँ होती हैं। प्रारम्भिक समितियों के सङ्गठन से केन्द्रीय समितियाँ बनती हैं छोर इन (केन्द्रीय) समितियों के सङ्गठन से राज्यीय समितियाँ जन्म लेती हैं। सम्पूर्ण छान्दोलन इसी प्रकार परस्पर गुँथा हुछा है। यद्यपि केन्द्रीय साख-समितियों को छपनी पूँजी का अधिकांश भाग रिज़र्व बैद्ध से छाल्यकालीन ऋण के रूप में प्राप्त होता है फिर भी इनकी छौर प्रदेशीय समितियों की व्यवस्था तथा वित्त की छावश्यकता की पूर्त इत्यादि कार्य प्रारम्भिक समितियों को ही तरह होते हैं। पहले केन्द्रीय समितियों को रिज़र्व बैद्ध से प्राप्त होने वाले छाल्यकालीन ऋण की छावधि ह महीने थी परन्छ अब इसे बढ़ाकर १५ महीने कर दिया गया है। ऋण के

धन पर ब्याल की दर डेढ़ रुपया प्रतिशत है। यह दर वैक्क के ब्याल की दर से दो प्रतिशत कम है।

सहकारी समितियों के शुंडाकृति की व्यवस्था में शीप पर सहकारी सङ्घ नाम की श्राखिल भारतीय संस्था है। इस संस्था का प्रथम सम्मेलन करवरी १९५२ में बम्बई में हुआ था।

साख-समितियाँ—प्रारम्मिक कृषि साख समितियों की संख्या जो कि सहकारी ऋण व्यवस्था का मूलाधार है, जून १९५५.५६ में ११ लाख भी श्रीर उनका सदस्यों की संख्या ७८ लाख थी।

330.54

तालिका नं० ३

J19B

प्रारम्भिक कृषि साख सिर्मातयों का कार्य (त्रन्न वैक श्रीर भूमिर्वधक वैंकों को छोड़कर)

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५
समितियों की संख्या	१,०७,६२५	१,११,६२५	१,२६,६५४	१,४३,३२०
सदस्यों की संख्या	४७,७६,८१६	प्र१,२६,००२	प्रम,४६,३८०	६५,६५,४१६
वर्षं के अन्तर्गत	(करोड़	इपये में)		
दिये हुए ऋग की				
धन राशि	58.50	२५:६६	२६.६४	३५.८८
वर्ष के मीतर				
ऋण में वसूल की				
धनराशि	₹ ≍ :€७	२१'२१	२६४८	२८'६१
वर्षके द्यन्त में वस्र्	ল			
होने वाला ऋग	३३'६६	३७•६८	४ १ -५६	४८'५३
वर्षके अन्त में				
शेप ऋण	द्र'५२	१०.८७	१२ ०३	१४*७०
निजी कोष	१७*६७	१६.५७	૨ શ્યુપ્	२३ ६६
जमा घन	ጸ.	የ ሄየ	४'६१	ų Y Y
ऋग में लिया हुन्रा ध	ान २३'१५	28'8E	२८'२४	३३'५२
चालू पँजी	84.55	४६-१८	५४. ८६	६२ °६३
matara a	-5-5	_ ~ ~	2 2 2	*.

प्रारम्भिक साख समितियाँ श्रार्थिक हिंग्न्से निर्वल हें श्रीर इस कारण कृषक को उतना लाभ नहीं पहुँचा पातीं जितना कि चाहिये। तालिका नं• रे से इम कह सकते हैं कि ऋगा के धन में निन्तर वृद्धि ही हो रही है। श्रासाम, भोपाल, विहार, जम्मू श्रीर काश्मीर, विन्ध्यपदेश श्रीर मध्यभारत में बहुत श्रधिक धन वस्ल होने के लिये शेष रह गया था।

कृषि साख समितियों की वित्त व्यवस्था दोषपूर्ण है। १६५३-५४ के अन्त कृषि साख समितियों की पूँजी का ढाँचा दोषपूर्ण है। निजी सम्पत्ति तथा जमा धन का कम अनुपात कृषि-साख समितियों की आर्थिक दुर्वलता का कारण है। कृषि साख समितियों का ओसत आकार भी छोटा हो है।

१६५५-५६ में श्रीसत सदस्यों की संख्या प्रति समिति ४६ यी श्रीर श्रिध-कांश समितियाँ व्यवसायिक इकाइयों की टिन्ट से अनार्थिक ही यीं । प्रति समिति श्रीसत जमाधन, शेयर पूँजी, श्रीर चालू पूँजी क्रमशः ४४१ द०, १०५१ द० श्रीर ४६४६ द० श्रीर प्रति सदस्य जमाधन, शेयर पूँजी श्रीर दिया हुश्रा श्रुग क्रमशः ६ द०, २२ द० श्रीर ६४ ६० था। यह श्रीसत श्रांकड़े कम ही हैं।

इसी वित्तीय दुर्वलता के कारण समितियाँ कृपकों को सुविधा पूर्वक कम ब्याज पर ऋ्रा देने के उद्देश्य की पूर्ति में असमर्थ हैं। पर्याप्त ऋ्रा दे सकने में असमर्थ होने के कारण ही वे कृपकों से व्याज की अधिक दर वस्त करती हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश, विनध्य प्रदेश और हिमांचल प्रदेश में होता है, वहाँ व्याज की दर ह से लगाक्र १२-१% तक है। "ऊँची व्याज दर के प्रचलन के कुछ कारणों में सहकारी अन्दोलन या अपर्याप्त विस्तार, ठीक दिशा में पर्याप्त जमा एकत्रित करने में सहकारी समितियों की असफलता तथा कुछ राज्यों में केन्द्रीय बैंक और वैंकिंग युनियन को अन्धिक प्रकृति है।"

१६५५-५६ में १०,००६ गैर-कृषि, साल समितियाँ यी जिनकी सदस्य संख्या २०% जाल श्रौर चालू पूँजी द्रम् है करोड़ र० थी। यह वेतन भोगियों, मिल के कर्मचारियों की समितियाँ तथा शहरी वैंक ये जिनका काम वहीं श्रच्छा या क्योंकि इनकी चालू पूँजी में जमा धन का प्रतिनिधित्व था जो ५३ करोड़ र० था। इन समितियों द्वारा उधार दिये गये छू ए की मात्रा ७२ करोड़ र० थी। कुछ समितियाँ गैर साल ३ काम भी करती थीं तथा उनके द्वारा खरीदे श्रौर वेचे माल की मात्रा का मूल्य कमशः २ ४२ करोड़ र० श्रौर २ ७२ करोड़ र० था। यह समितियाँ मुख्यतः वम्बई श्रौर मद्रास में थी इन समितियों के ५४% सदस्य इन्हीं दो राज्यों में थे तथा उधार दिये धन का ६३% भी इन्हीं राज्यों के श्रन्दर था।

गैर-साख समितियाँ—कृषि सम्बन्धी तथा कृषि से श्रसम्बन्धित गैर साख समितियाँ प्रत्येक स्तर पर प्रारम्भिक केन्द्रीय तथा राज्यीय पाई जाती हैं। १९५५-५६ में ३०,२६८ कृषि गैर साख (प्रारम्भिक) समितियाँ थीं जिनके सदस्यों की संख्या २४ लाख यी इनकी चालू पूँ जी २'८ लाख र० यी तथा इनके द्वारा वेचे गये माल का मूल्य ३ लाख र० या । १६५५-५६ में गैर-कृषीय, गैर-साख प्रार्मिमक समितियाँ जैसे उपमोक्ता मगडार, विद्यार्थी भगडार कैन्टीन ग्रादि संख्या में २७,७४५ यों तथा इनकी सदस्य संख्या ३३% लाख ग्रौर चालू पूँ जी ५'८ लाख र० यी तथा इन्होंने ४९ लाख र० के मूल्य का सामान वेचा । इनके ग्रातिरिक्त ८२ राज्यीय गैर साख समितियाँ यी जिनकी सदस्य संख्या २२,८६४ तथा चालू पूँ जी ६२,०४१ र० यो श्रीर इन्होंने १६ लाख र० के मूल्य का सामान वेचा । २७६४ केन्द्रीय गैर साख समितियाँ यो । इनकी सदस्य संख्या १६ लाख तथा चालू पूँ जी २ लाख र० से कम यी तथा इन्होंने ५६% व० का सामान वेचा ।

समस्याएँ—भारत में श्राधिकतर सहकारी समितियों का संगठन प्रायः एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। मनुष्य की विभिन्न माँगों का परस्तर सम्बन्व होता है श्रीर वह एक दूसरे पर निर्भर भी रहती हैं इसिलये उसकी विभिन्न लिटन श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति श्रानेक समितियों की श्रपेक्ता एक ही सिमित श्रिषक सन्तोपजनक रीति से कर सकती है। विशेषशों का विचार है कि प्रामीण समस्याश्रों को बहुमुखी समितियों के द्वारा कुशलता श्रीर श्रिषक बचत के साथ हल किया जा सकता है। श्रानेक समितियों की उचित व्यवस्था करने के लिए योग्य कर्मचारियों का श्रमाव होने के कारण तथा श्रपनी विभिन्न श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए केवल महाजन से सहायता लेने के श्रादी श्रामीणों की विभिन्न समितियों से सम्बन्ध रखने की श्रानिच्छा के कारण भी बहु उद्देश्यीय समितियों की श्रावश्यकता प्रतीत होती है। इसके साथ ही साख की पूर्ति श्रीर विक्रय तथा गैर साख की श्रन्य कियाश्रों से प्रथक करके एक उद्देश्यीय सहकारी कृषि साख-समिति का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय नियोजन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात् मारत में श्रौर विशेषकर उत्तर प्रदेश, श्रासाम श्रौर विहार में बहु उद्देश्यीय समितियाँ स्यापित करने की श्रोर निश्चित प्रयास किया गया है। १६४७ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास योजना तैयार की यी जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि १२ से १५ प्रामों को मिलाकर एक विकास-चेत्र बनाया जाय श्रौर प्रत्येक ग्राम में एक-एक बहु उद्देश्यीय समिति तथा सम्पूर्ण चेत्र में इन समितियों का एक संघ स्थापित किया जाय। इन संघो का जिला सहकारी विकास संघ होता है। इस दिशा में श्रासाम श्रौर विहार ने कमशः १६४८ व १६४६ में प्रयास किया। यह श्रावश्यक है कि श्रन्य राल्यों में भी बहु उद्देश्यीय समितियाँ श्राधिक संख्या में

स्थापित की जायँ परन्तु इनका उद्देश्य सभी कृषि साख-समितियों को इटाना न होकर उनके अध्रेर कार्यचेत्र की पूर्ति करना होना चाहिए।

णाल एमितियों का अधीमित उत्तरदायित्व होने के कारण एहकारी आन्दो-लन की सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है जैसा कि वंगाल प्रदेशीय अधिकोषण जींच एमिति ने कहा है "कि गाँवों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति इत्तनी अव्छी है कि वे इन समितियों के सदस्य बनकर असीमित उत्तरदायित्व का जोखिम उठाना पसन्द नहीं करते हैं।" असीमित उत्तरदायित्व तभी सफल हो सकता है जब जनता की स्थिति समान हो और वह साज्ञर भी हो। इसिलिए वर्तमान समय में आन्दोलन का और तीमता से प्रसार करने के लिये सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित रखने की योजना लागू करना आवश्यक है।

जो समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं श्लौर जिनको श्रमी स्थापित करना है उनका कार्य मुन्यवस्थित रीति से चलाने श्लौर उनका विकास करने के लिए (ट्रेनिंग प्राप्त) प्रशिक्तित कर्मचारियों की श्लावश्यकता है। कुछ ही राज्यों के पास शिच्या-केन्द्र हैं। पूना सहकारी कालेज में श्लन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी शिक्षा दी जाती है। वर्तमान समय में कर्मचारियों की समुचित शिचां की उपयुक्त सुविधा नहीं है, इसलिए यह श्लावश्यक है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शिच्या-केन्द्र स्थापित किया जाय।

मारत की सहकारी समितियों की सबसे बड़ी कठिनाई वित्त की है। इनकी वित्तीय स्थित बहुत नाजुक है। वित्तीय सहायता देने वाली गैर सरकारी संस्थां श्रों की दृष्टि में इन समितियों का विशेष महत्व नहीं है। इसिलए रिज़र्व वैंक के सुमाय के श्रानुसार यह समितियों तमी मान्यता प्राप्त कर सकती हैं जब यह सुरिह्नत की भ श्रीषक धन रखने की व्यवस्था करें। जब तक इन समितियों का सुरिह्नत कीष श्रेयर पूँजी के बराबर नहीं हो जाता तक तक लामांश का कम से कम एक विहाई भाग प्रतिवर्ध सुरिह्नत कोष में जमा कर देना चाहिए। इसके परचात लामांश का केवल २५ प्रतिशत सुरिह्नत कोष में जमा किया जा सकता है। प्रामों में बचत के साधनों का उपयोग करने के लिये ग्रामीणों में श्रीवकोषण स्वमाय, का विकास करना चाहिए।

सहकारी श्रान्दोलन वास्तव में जनता द्वारा भेरित श्रान्दोलन नहीं है। इसका प्रारम्भ बाहर से हुआ। इसी कारण जनता में इसके प्रति उत्साह का अभाव है। राज्य सरकार को अपना कार्य-चेत्र इन समितियों के पय-प्रदर्शन, निरीक्षण तथा थोड़ा नियंत्रण रखने तक ही सोमित रखना चाहिए। राज्य को साक्षरता का प्रसार करना चाहिये और समाचार पत्रों, रेडियो तथा अन्य साधनों द्वारा सहकारिता के लामों का जनता में प्रचार करना चाहिए। सहकारी तथा निजी संस्थाओं में श्रेष्ठतर समन्वय की त्रावश्यकता है।

इन समस्यात्रों के साथ हो साथ तथा उपभोक्ता समितियों की कुछ विशेष समस्याएँ भी हैं, साख समितियों के सामने श्रत्यिक कलातीत ऋणों की समस्या भी है। १६५५-५६ में प्रारम्भिक कृषि साख समितियों के कलातीत ऋणा को धनराशि १४-६६ करांड रुपया थी जो जून १६५६ के श्रन्त तक देय ऋणों का २५ प्रतिशत थी। यह सिंथत मुख्यतः उन चेत्रों में है जो पिछड़े हुए चेत्र कहे जाते हैं। इसका सामान्य कारण पद्मपात श्रीर श्रष्टाचार है।

कुछ राज्यों में, मुख्यतः दिमांचल प्रदेश श्रीर उत्तर प्रदेश में, सहकारी समितियों की ज्याज की दर ६ से १२ में प्रतिशत तक है। यह दरें बहुत श्रिषक है। इन दरों को भी श्रन्य राज्यों की दरों के समान करने की श्रावश्यकता है।

नियन्त्रण की समाप्ति के उपरान्त गैर-कृषि गैर-साख समितियाँ बहुत किनाइयों का समना कर रही हैं श्रीर व्यक्तिगत व्यापारी की सुलना में कार्य संचालन व्यय श्रिषक होने के कारण कुछ समितियाँ तो बन्द भी हो चुकी हैं। कार्य-संचालन व्यय कम करने के लिए इन समितियों के कार्य चेत्र में वृद्धि करने तथा इनको श्रीर श्रिषक कार्य-कुशल बनाने की श्रावश्यकता है। यदि थोक विक्री के स्टोर स्थापित किए जाय श्रीर उनकी पूँजी तथा सुरक्षित कोय में वृद्धि की जाय तो इनकी स्थित सुधर सकती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—विभिन्न प्रदेशों के सहकारी विभाग के मिन्यों की सभा ने जो कि १६५५ में हुई थी यह सुमान दिया कि "१५ वर्ष के अन्दर गाँवों में ज्यापार की ज्यवस्था सहकारिता के आधार पर इस प्रकार की हो जानी चाहिये कि सास विक्रय तथा विधायन इत्यादि जैसे सब ज्यापार का कम से कम ५० % कार्य सहकारी समितियों के द्वारा होने लगे। इस के लिये प्रारम्भिक कृषि सास समितियों के सदस्यों की संख्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५० लाख से बढ़ाकर १५० लाख कर देनी चाहिये और अल्पकालीन अप्रण की राशि ३० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १५० करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन अप्रण की राशि १० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ५५० करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन अप्रण की राशि ३ करोड़ रुपये से बढ़ाकर २५ करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन अप्रण की राशि ३ करोड़ रुपये से बढ़ाकर २५ करोड़ रुपये कर देनी चाहिये।"

उपर्युक्त सुमान के अनुसार द्वितीय पंचनर्पीय योजना में निस्तृत योजना की रूपरेखा बनाई गई है। मारत सरकार के कृषि तथा अन्य निभाग ने इस सम्बन्ध में कानून बनाकर तैयार कर रक्खें हैं जिनकी सहायता से केन्द्रीय और

श्रध्याय १३

सहकारी विक्रय

उत्पादन स्वतः लक्ष्य नहीं है। वो कुछ वस्तु उत्पादित की जाती है या जो कुछ उत्पादन किया जाता है श्रन्ततः उसे उपमोक्ता के पाष पहुँचना चाहिये। उत्पादक से उपमोक्ता तक वस्तु पहुंचने की साधन वाजार होता है। इसके लिये कई स्थितियाँ पार करनी पढ़ती हैं श्रौर इसमें श्रनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। सभी उत्पादित वस्तु के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के श्रपने विशेष गुण होते हैं, जैंसे कुछ वन्तुएँ काफी स्थूल, भारी तथा शीघ नष्ट होने वाली होती हैं श्रौर छोटे-छोटे उत्पादक विस्तृत चेत्र में उनका उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार कुछ वन्तुएँ हलकी, शीघ न होने वाली श्रौर सस्ती होती हैं। इनका उत्पादन बहुत कम लोग करते हैं। इनवस्तुओं के विकय के लिये विभिन्न काम करने पड़ते हैं। उनको एक स्थान में एकत्र किया जाता है, उनके लिये गोदाम की व्यवस्था की जाती है, इनका कमबन्यन श्रौर प्रमाणीकरण किया जाता है, यातायात की व्यवस्था की जाती है, श्रार्थिक सहायता का प्रवन्य किया जाता है श्रौर विक्रय के लिये वातचीत चलाई जाती है, इत्यादि इस प्रकार विक्रय व्यवस्था के लिये वातचीत चलाई जाती है, इत्यादि इस प्रकार विक्रय व्यवस्था के लिये वातचीत चलाई जाती है, इत्यादि इस प्रकार विक्रय व्यवस्था के लिये विशेषज्ञों श्रोर कुशक्त व्यक्तियों की श्रावश्यकता होती है।

कुराल विकय की आवर्यक वार्ते—विकय व्यवस्था उत्तम तभी कहला सकती है जब उत्पादक को उत्पादित वस्तु का अधिकतम मूल्य मिल सके, वस्तु के रखने हत्यादि में निम्नतम व्यय करना पहें और उपमोक्ता को दिये हुये मूल्य के बदले में उचित प्रकार का सामान मिले।

यदि वस्तुश्रों का क्रम वन्धन श्रीर प्रमाणीकरण किया गया हो तो उत्पादक

' कों सर्वोत्तम मूल्य मिल सकता है। श्रिषिकतम लाम उठाने के लिये यह श्रावश्यक

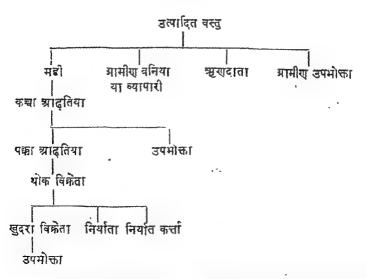
है कि उत्पादक यया समय उचित स्थान पर उसे वेचे। इसके लिये उत्पादक को
विच सम्बन्धी तथा बाजार की परिस्थितियों का शान होना चाहिये।

विकय की दृष्टि से सामान को बरतने (handling) की लागत न्यूनतम करने की दृष्टि से संचार तथा परिवहन के साधन सस्ते और अच्छे होने चाहिये। दलालों की संख्या को न्यूनतम कर दिया जायं क्योंकि दलालों के बढ़ने से लागत तथा परिखामत: मूल्य भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही बस्तु को नष्ट होने से रोकने के लिये यह श्रावश्यक है कि उसके रखने के लिये गोदाम की व्यवस्था की जाय।

वस्तुत्रों का उचित रीति से क्रम बन्धन और प्रमाणिकरण होने तथा सामान में मिलावट श्रीर श्रप्रमाणिक तील जैसे श्रनुचित उपायों के प्रयोग को रोकने से उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ प्रकार की वस्तुर्ये प्राप्त कर सकता है।

विकय की अच्छी व्यवस्था के लिए जिन आवश्यक वातों की ऊपर चर्चा की गई है उनका भारत में पूर्ण अभाव है। कृषकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे निर्धन हैं, अनिभन्न हैं और इधर-उधर विखरे हुये हैं। उन्हें अपने कार्य के लिये ऋण लेना पड़ता है और यह ऋण प्राय: वस्तुओं के रूप में चुकाना पड़ता है। इन वस्तुओं का मूल्य एक प्रकार से पहले ही निर्धारित हो जाता है और उसका लाम ऋणदाता उठाते हैं।

कृपि सामग्री के विकय की किया



देश में संचार और परिवहन के उपयुक्त साधनों का अभाव है। वर्षा ऋतु के समय अधिकांश आमों का एक दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और निर्धन उत्पादकों को वर्षा आरम्म होने से पूर्व ही शीव्रता पूर्वक अपना सामान वेचना पहता है। इससे मूल्यों का स्तर गिर जाता है। यदि सामान रोक लिया जाय तो गोदाम की अच्छी व्यवस्था न होने से अधिकांश सामान के खराब हो जाने का

भय रहता है साथ ही उत्पादकों श्रीर ज्यापारियों में वस्तुश्रों में मिलावट करने का वड़ा जोर है इस कारण उपभोक्ता को शुद्ध, सामान मिलने की कोई गारन्टी नहीं है। मारत में दलालों, जैसे कच्चा श्रादृतिया, पक्का श्रादृतिया, दलाल, थोक विकेता श्रीर खुदरा विकेता इत्यादि की संख्या बहुत श्राधक है। लाभ का बहुत वड़ा श्रंश ये स्वयं ले लेते हैं। विकय (Marketing) ज्यवस्था की विभिन्न स्थितियाँ उपरोक्त चार्ट में दिखाई गई हैं—

सहकारी समितियों की कार्य-च्यवस्था

भारत में सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि विकय व्यवस्था के बहुत से दोषों में सुघार सम्भव हो सका है। सहकारी विकय व्यवस्था सहकारी साख व्यवस्था के प्रकार शुण्डाकृति का है। इसके आघार में प्रारम्भिक कृषि कय-विकय तथा उत्पादन और विकय समितियाँ तथा गैर कृषि कय-विकय और उत्पादन तथा विकय समितियाँ तथा गैर कृषि कय-विकय और उत्पादन तथा विकय समितियाँ हैं। वे अपने सदस्यों के लाभ के लिये कृषीय तथा अन्य वस्तुओं का क्रय विकय करती हैं। बहुउद्देशीय समितियाँ भी अन्य अनेक कार्यों के अतिरक्त कय-विकय का कार्य भी करती हैं।

इन प्रारम्मिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय बिक्री संघ हैं जो क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं श्रीर प्रारम्भिक समितियों को ऋणा तथा श्रम्य प्रकार की सहायता देते हैं। इनके सदस्य दो प्रकार के होते हैं, (क) व्यक्ति तथा (ख) समितियाँ। युद्ध काल में इन केन्द्रीय संस्थाश्रों ने बहुत कार्य किया। परिस्थित बदल जाने श्रीर नियन्त्रण हट जाने से इनका कार्य बहुत कम हो गया है। शीर्ष पर राज्यीय मिक्री संघ हैं जो कय-विक्रय का कार्य करते हैं श्रीर केन्द्रीय संघों तथा समितियों को ऋण तथा श्रन्य प्रकार की सहायता देते हैं। वे सहकारी विक्रय कार्य का समन्वय करते हैं। इनके सदस्य मी (क) व्यक्ति तथा (ख) समितियाँ होती हैं। इस प्रकार के संघ कुछ ही राज्यों में हैं। इनका कार्य-तेत्र सीमित है श्रीर सहकारी विक्रय व्यवस्था की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुक्ल नहीं है।

१६५५-५६ में २७६१ प्रारम्भिक कृषीय क्रय-विक्रय समितियाँ थीं जिनकी सदस्य संख्या ४६ लाख थी। इन्होंने मालिक की हैसियत से ३७,३०८ ६० का सामान तथा श्रमिकर्ता (एजेन्ट) की हैसियत से ३६१० ६० का सामान वेचा। उत्पादन श्रीर विक्रय की समितियों की संख्या ६६८ तथा सदस्य संख्या ४३ लाख थी। इन्होंने मालिक की हैसियत से ३५,६१५ ६० का तथा श्रमिकर्ता (एजेन्ट) की हैसियत से १,१६,३६० ६० का सामान वेचा। गैर कृषीय क्रय-विक्रय समिनियों की संख्या ८०७७ तथा सदस्य संख्या १६°३ लाख थी। इन्होंने मालिक की

हैसियत से १,८३,५७३ र० का तथा अभिकर्ता की हैसियत से १,१०५ र० का सामान वेचा। उत्पादन तथा विकय (गैर कृषीय) समितियों की संख्या ११,५२४ तथा सदस्य संख्या ६°३ लाख थी। इन्होंने २२६, ६२१ र० का सामान मालिक की हैसियत से श्रीर ८७४८ र० का सामान श्रमिकर्ता (एजेन्ट) की हैसियत से वेचा।

शीप संस्थायें—भारत में सहकारी विकय-व्यवस्था का सबसे वहा दोष शीप संस्थायों का अभाव रहा है। १६५५-५६ में १६ राज्यीय विकय संघ थे। इनकी व्यक्ति-सदस्यता की संख्या ४०१४ तथा समिति सदस्यता की संख्या ३५३५ थी। इन्होंने ३३, १७७ क का सामान मालिक की हैसियत से तथा ५१७१४ क का सामान अभिकर्ता की हैसियत से वेचा। इन १६ संघों में से कुर्ग में ४, दिल्ली में ३, उत्तर प्रदेश तथा हैदराबाद प्रत्येक में २, तथा वम्बई, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, जम्मू और काश्मीर, मैस्र, पैस्स, हिमालय प्रदेश और मनीपुर—प्रत्येक में एक संघ था। अधिकतर राज्यों में केन्द्रीय विकय संघ थे। १६५५-५६ में ऐसे संघों की संख्या २३५४ थी। (इनकी व्यक्ति सदस्यता १८ लाख तथा समिति सदस्यता ४५,३६५ थी इन्होंने १ई लाख क का सामान मालिक की हैसियत से तथा ३.३ लाख क का सामान अभिकर्ता की हैसियत से वेचा।) इनमें से २१५३ उत्तर प्रदेश में, ७० विहार में, ४४ राजस्थान में, सौराष्ट्र तथा हिमांचलप्रदेश-प्रत्येक में २६, तथा वम्बई में १६ थे। अंशतः गन्ने के संघों के कारण केन्द्रीय विकय संघों केन्द्रीकरण उत्तर प्रदेश में है। कुछ राज्यों में कोई विकय संघ नहीं था।

विभिन्न राज्यों में शीर्ष संस्थाएँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। "बम्बई की राज्यीय सहकारी समिति फल, सक्जी, नियमित पदार्थ, चीनी, क्वषि की आवश्यकता की बस्तुएँ तथा खाद्य-तैल आदि की क्यापार करती है। वह राज्य में सल्फेट अमोनिया की एक माप वितरक है। समिति ने विकय-ज्ञान-सेवा भी चला रखी है तथा प्रति माइ एक बुलेटिन निकलती है जिसमें इर सप्ताह के अन्त में प्रमुख कृषि पदार्थों के प्रचलित भाव दिये जाते हैं।" मैसूर की प्रान्तीय सहकारी विकय समिति खाद, शहद, चन्दन की लकड़ी का सामान तथा अन्य अनेक सामान खरीदने और वेचने का काम करती है। उद्मीशा की प्रान्तीय सहकारी विकय समिति कुटीर उद्योगों तथा वन की छोटी-मोटी उत्पत्तियों के विकय का कार्य करती है।

इन शीर्ष संस्थाश्रों में सबसे बड़ी श्रौर सुसंगठित उत्तर प्रदेश की विकय संस्था श्रर्थात् सहकारी विकास तथा विकय संघ हैं। उत्तर प्रदेश की इस शीर्ष संस्था ने विशेष उन्नति की है, पर दुर्भाग्य वशा इसका कार्य ऐसी वस्तुश्रो से सम्बन्धित रहा है जिनकी गण्ना कृषि उत्पत्ति में नहीं की जा सकती। इसके कारण कृषकों को आशानुरूप लाम नहीं पहुँच सका है। इन संस्थाओ द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनमें अच्छे बीज, खाद तथा कृषि सम्बन्धी मशीन और श्रीजार का वितरण, शिकोहाबाद में धी परीच्या तथा कमबन्धन के केन्द्र का संचालन, जड़ी बूटियों का विक्रय तथा विकास, विधावगंज की लाख फैन्ट्री को आर्थिक सहायता पहुँचाना, तथा बम्बई में एक कुटीर उद्योगों की उत्पत्ति के प्रदर्शन यह का संचालन आदि है। भविष्य में संघ के कार्यक्रम में इस बात का प्रयत्न है कि (क) सबसे उत्तम प्रकार के बीजों को अपने कोष में संचित करे श्रीग आगामी ३ वर्ष के अन्दर सारे प्रान्त में उनकी भरमार कर दे, (ख) परिदत्त पूँजी की मात्रा बढ़ाकर २५ लाख रुपए कर दे; श्रीर (ग) कृषि-उत्पत्ति के विक्रय पर विशेष ध्यान दे।

शीर्ष संस्थाओं की कार्य प्रणाली की तीन विशेषताएँ हैं (१) इनकी सदस्यता सहकारी समितियों तक ही सीमित नहीं है। राज्यीय संघों में व्यक्ति सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की एक तिहाई है श्रीर केन्द्रीय संघों में व्यक्ति सदस्यों की संख्या समितियों की सदस्य-संख्या की छः गुनी है। व्यक्ति सदस्यों का बाहुल्य कुछ श्रस्थिरता उत्पन्न करता है; (२) परिदत्त हिस्सा पूँजी श्रीर इन संघों का निजी कीप मिलाकर चालू पूँजी का एक बहुत छोटा श्रंश है। इससे भी इनके कार्य में श्रस्थिरता श्राती है; (३) इन संस्थाश्रों का श्रीर विशेषकर केद्रीय संघों का प्रवन्य बहुत श्रिषक है। सहकारी विक्रय को प्रभावपूर्ण मितव्ययो बनाने के लिये इन दोषों का सुधार श्रावश्यक है।

प्रारम्भिक समितियाँ — कृषि उत्पत्ति का क्रय-विक्रय करने के लिए प्रारम्भिक कृषीय ग़ैर-खाल तथा ग़ैर-कृषीय ग़ैर-साल समितियाँ हैं। परन्तु इनका प्रत्येक राज्य में समान रूप से विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक कृषि उत्पत्ति श्रीर विक्रय का सम्बन्ध है विहार, पश्चिमी बंगाल, मद्रास श्रीर श्रांश श्रमगामी ये तथा श्रासाम, उद्गीसा श्रीर राजस्थान पिछुड़े हुये थे। परन्तु ग़ैर-कृषि तथा साल समितियाँ एक भिन्न चित्र श्रोकित करती हैं। श्रासाम, बम्बई, मद्रास श्रीर मध्य-प्रदेश में क्रय-विक्रय समितियों में श्रमगामी थे। जब कि पश्चिमी बंगाल, बम्बई, मद्रास, श्रान्ध श्रीर राजस्थान उत्पत्ति श्रीर विक्रय समितियों में श्रमगामी थे। गैर-कृषि गैर-साल समितियों में उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश श्रीर कुर्ग की स्थिति पिछुड़ी हुई है।

ये समितियाँ या तो उत्पादकों से माल खरीद कर विकय करती हैं, या उत्पादकों मे एजेन्ट्र के रूप में कार्य करती हैं जिससे दलालों की संख्या घट जाती है। कहीं कहीं पर ये सिमितियाँ कारखाने तथा दुकानें चलाती हैं श्रीर इस प्रकार माल का उत्पादन तथा विक्रय करती हैं। वे उन उत्पादकों को श्रूप तथा श्रन्य सिवधायें प्रदान करती हैं जिनसे वे माल खरीदती हैं। उनका कार्य चित्र माल विक्रय करने तक ही सीमित नहीं है वरन् वे उत्पादकों में सिक्रय रूप से सहायता देती हैं। ये सिमितियाँ कभी केवल एक वस्तु का ही क्रय-विक्रय करती हैं श्रीर कभी श्रमेकों का। वहुउद्देशीय सिमितियाँ, जिनका दिन प्रतिदिन श्रिष्टिक प्रचार होता जा रहा है, श्रपने विभिन्न कार्यों के साथ ही साथ कृषि उत्पत्ति तथा अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय का भी कार्य करती हैं। यह कहा जा सकता है कि वहु उद्देशीय सिमितियाँ अपने सहस्यों की लगभग सभी कृषि-सम्बन्धों श्रावश्यकवाश्रों की पूर्ति करती हैं। ये सिमित्याँ कृषि उत्पत्ति की विक्री में श्रीयकाधिक कार्य कर रही हैं श्रीर श्रिष्टकांश राज्यों में वर्तमान हैं।

सबसे अधिक महत्वशाली एको देशीय सहकारी विकी समितियाँ उत्तर प्रदेश और विहार में गन्ने की, वस्वई में रूई और फलों की, मैसूर में इलायची और नारियल की श्रीर कुर्ग में इलायची, शहद श्रीर नारंगियों की हैं। ये समितियाँ निम्न कार्य करती हैं।

- (१) यह समितियाँ श्रपने सदस्यों से कृषि सामग्री श्रीर कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल लेकर उनका क्रमवन्धन श्रीर प्रमाणीकरण करती हैं श्रीर विक्रय के लिए श्रपने सहकारी संघों को दे देती हैं।
- (२) यह मितियाँ उत्पादित माल के बदले अपने सदस्यों को ऋण देती हैं परन्तु घन का अभाव और गोदामों की उचित व्यवस्था न होने के कारण इस कार्य में समितियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- (३) सामान वेचने के लिए यह समितियाँ उत्पादकों के एजेन्टों का भी कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार की गना-समितियाँ केवल यही कार्य करती हैं। गत कुछ वर्षों में श्रनान वस्तुली के लिए कुछ समितियों ने सरकार के एजेन्टों के रूप में कार्य किया।
- (४) उत्पादन भौर विकय समितियों का यह कार्य है कि श्रन्छे प्रकार के माल का उत्पादन करें। श्रन्य समितियाँ श्रपने सदस्यों को श्रन्छे माल का उत्पा-दन करने में सहायता देती हैं।
- (५) मद्रास की कुछ समितियों ने विक्रय के साथ ही ऋगा तथा अन्य सुविघाएँ देने की भी व्यवस्था कर रखी है। कृषि साख समितियाँ इस गर्त पर

सदस्य कृषक को मुख्य प्रकार की फसलें उगाने को ऋगा देती हैं कि फसल तैयार हो जाने पर वही उसका विक्रय करेंगी।

(६) स्कूल तथा पुस्तकालय चला कर तथा श्रस्पताल श्रीर सहकों का निर्माण करके यह समितियाँ समाज सेवा का कार्य भी करतीं हैं।

लाभ (Advantages)—सहकारी विकय समितियों ने कृषि विकय-व्यवस्था के अनेक दोषों को दूर कर दिया है।

- (क) इनसे दलालों की संख्या कम हो गई है। दलालों की लम्बी शृङ्खला में से कबा आदितिया, पक्का आदितिया और थोक व्यापारी प्रायः समाप्त हो गये हैं। यह सिर्मातयाँ उत्यादकों से स्वयं माल कय कर सीधे उपमोक्ताओं को बेच देती हैं। इस रीति से विकय व्यवस्था के व्यय में कमी होती है किन्तु उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी।
- (ख) यह समितियाँ छोटे उत्पादकों को वित्तीय सहायता देती हैं श्रौर विशेष उपरामर्श देती रहती हैं जिससे वह छोटे न्यापारियों के घोखे से बच जाते हैं। उत्पादित माल के विक्रय तथा उसकी देख माल में होने वाली समय श्रीर शक्ति की बरवादी भी बच जाती है। इन समितियों ने कुटीर उद्योगों के माल को छुशालता पूर्वक श्रीर सस्ते मूल्य में वेचने का प्रबन्ध करके उद्योग के लिए बहुत अछ किया है।
- (ग) उपभोक्ताश्चों को भी इन सितियों से बहुत लाम होता है। उन्हें इनसे श्रव्छे प्रकार का माल मिल जाता है क्योंकि सितियों उनका उचित रीति से कम बन्धन तथा परीह्यण करती हैं। इसके साथ ही यह सितियाँ श्रव्छा सामान तैयार करने तथा मिलावट रोकने में वह साधक बन जाती है। इस दिशा में घी श्रीर दूध की सहकारी सितियों ने काफी सफलता प्राप्त की है।

प्रारम्भिक कृषि कय-विकय समितियाँ तथा उत्पादन श्रीर विकय समितियाँ सीमित व्यापार करती हैं, पर गैर कृषि कय विकय समितियाँ, यद्यपि इनका कार्य सेत्र सीमित है, फिर भी श्रिषिक कार्य करती हैं। शीर्ष संस्थाश्रों के तरह इन दोनों प्रकार की समितियों की, परिदन्त हिस्सा पूँजी चालूपूँजी का एक तिहाई ही है श्रीर प्रवन्ध व्यय भी बहुत श्रिषक है। इसके कारण इनका कार्य श्रास्थिर है। यद काल में विशेष परिस्थित के उपस्थित हो जाने पर इन समितियों को गत वर्षों में लाभ भी हुश्रा था, पर परिस्थित बदल जाने से श्रीर कार्य कम हो जाने से प्रारम्भिक कृषि श्रीर गैर कृषि गैर साख समितियों दोनो को हानि उठानी पदी। मिवष्य में इन समितियों के कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना पढ़िगा ताकि ये लामप्रद सिद्द हो सर्के।

भविष्य— यहकारी विक्रय गैर-साख सहकारी समितियों में सबसे महस्वपूर्ण है। ऊपर कहा जा चुका है कि सहकारी साख की तरह इनकी शुंडाकृति है। "यह ढाँचा भ्रूरण समितियों की माँति न सुनिर्मित ही है श्रीर न एक दूसरे से सम्मान्यत ही है। संत्या की प्रत्येक इकाई श्रपने-श्रपने स्थान पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। नीचे की इकाइयों का प्राय: ऊपर की इकाइयों से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रीर इसीलिये ऊपर की इकाइयों नीचे की इकाइयों को कोई विशेष सहायता भी नहीं देतीं। उदाहरण स्वरूप राज्यीय संस्थायें नीचे की इकाइयों की प्रतिनिधि श्रयवा श्राइतियों को तरह कार्य नहीं करती वरन् वे एक स्वतंत्र ज्यापारिक एजेन्सी की तरह कार्य करती हैं"। पर यदि इनकी श्रोर उचित ध्यान दिया गया तो इम कह सकते हैं कि इमारे देश में सहकारी विक्रय समितियों का मिवध्य बहुत उज्जवल है। इमारे देश में सहकारी राष्ट्र (Cooperative Commonwealth) की स्थापना होने से सहकारी क्रय विक्रय समितियों को विशेष महत्व के कार्य करने पड़ेंगे। पर उसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं जिन्हें दूर करना होगा।

- (१) निजी व्यापारी इन सिमितियों का विरोध करते हैं श्रीर इनके सामान के विक्रय में बच्च नहीं दिखलाते। उदाहरणस्वरूप कर्नाटक के व्यापारियों ने सहकारी विक्रय समितियों द्वारा दिये गये कपास को क्रय करने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार के विरोध का प्राय: सभी सिमितियों को सामना करना पड़ता है। इन किनाइयों को तभी दूर किया जा सकता है जब इन्हें सरकार की श्रोर से श्रीर श्रिधक सहायता दी जाय तथा इन सिमितियों का बहुमुखी विकास किया जाय। इन सिमितियों का कार्य-चेत्र श्रीर विस्तृत करना चाहिए जिससे कुटीर उद्योग के उत्पादन का विक्रय कार्य इनके कार्य चेत्र के श्रन्तर्गत श्रा जाय। इसके साथ ही १६५२ के प्रथम भारतीय सहकारी समीतियों के श्रुमाव के श्रुपार राज्य द्वारा व्यापार का कार्य बन्द कर दिया जाय श्रीर इस श्रभाव की पूर्ति करने के लिए सहकारी सिमितियों को यह कार्य सींप दिया जाय। राज्य-व्यापार-जाँच सिमिति ने सिफारिश की है कि ''जब कभी उत्पादक घरेलू व्यापार श्रथवा विदेशी व्यापार के लिए परस्पर मिलकर सहकारी सिमितियों संगठित करें तो सरकार को उन्हें यथासंभव सहायता श्रीर प्रोत्साहन देना चाहिए।''
- (२) मारत में विकय त्यहकारी सिर्मातयों की प्रायः घन के श्रभाव का सामना करना पहता है क्योंकि इनकी हिस्सा पूँजी बहुत कम होती है। उदाहरणार्थ उद्गीस श्रौर हिमाचल प्रदेश की शीर्ष विक्रय सहकारी सिमितियों की हिस्सा पूँजी कमशाः १४,०६० श्रीर १३,४६० हपया है। यह पूँजी बहुत छोटे पैमाने पर विकय

करने के लिए भी कम है। इन समितियों को अपना कार्य मुचार रूप से चलाने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूँजी की आवश्यकता है। यदि यह सितियाँ अपनी हिस्सा पूँजी में वृद्धि कर लें तो दीर्घकालीन पूँजी प्राप्त हो सकती है। मशीनों तथा अन्य प्रकार के सामान क्ष्य करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्यीय श्रीद्योगिक वित्तीय निगमों से दीर्घकालीन पूँजी की सहायता लेनी चाहिए। जिन राक्यों में श्रीद्योगिक वित्तीय निगम नहीं हैं वहाँ इनकी स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत में लाइसेन्स प्राप्त गोदामों (Warehouses) का विकास करने की आवश्यकता है जिससे यह समितियाँ इन गोदामों में जमा किये गये अपने सामान के बदले में मारतीय रिज़र्व बैंक कान्तन की घारा १७ (४) (भ) के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक से अनुया ले सकें। यह खेद की बात है कि बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर और त्रिवांकुर-कोचीन की सरकारों द्वारा आवश्यक कान्तन बना लिये जाने के पश्चात् भी भारत में कहीं ऐसे लाइसेन्स प्राप्त गोदामों की व्यवस्था नहीं की गई है।

- (३) जो विषय समितियाँ इस समय प्रचलित हैं उनमें शिज्ञित, ईमानदार श्रोर श्रनुभवी कर्मचारियों का श्रमाय है, इन समितियों में श्रमशी का बोलवाला है। इससे कार्य में देर श्रीर हानि होती है। इन समितियों में कार्य को सुचार रूप से संचालन करने के लिए श्रनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए जिससे श्रमायश्यक श्रीर श्रकुशल कर्मचारियों को श्रलग करके समिति का न्यय कम किया जा सके। स्वसे छोटी समिति में कम से कम तीन कर्मचारी होते हैं— भैनेजर, सामान तीलनेवाला श्रीर चीकीदार—जब कि निजी ज्यापारी यह तीनों कार्य स्वयं कर लेता है। इससे समितियों की कार्य-ज्ञमता कम तथा लागत श्रिषक हो जाती है।
- (४) विक्रय करने वाली सहकारी समितियों को गोदामों की उचित सुविधा प्राप्त नहीं है। बहुत सी समितियों के अपने गोदाम नहीं हैं और उन्हें बहुत अधिक किराये पर गोटाम लेने पहते हैं। शिक्ष नष्ट हो लाने वाले सामानों को रखने के लिए सिनितयों के पास कोई साधन नहीं हैं। राज्य सरकारों को गोदाम बनाने में हन सिनितयों की सहायता करनी चाहिए और गोदाम निर्माण के कुल ज्यय ५० प्रतिशत स्वयं देना चाहिए। इस कार्य के लिए सहकारी गृह निर्माण सिनितयों से मी भूग का प्रवन्ध करना चाहिए। यदि गोदामों की स्थापना से सिनितयों से मी भूग का प्रवन्ध करना चाहिए। यदि गोदामों की स्थापना से सिनितयों की सामान रखने की किटनाहर्यी बहुत कम हो लायेंगी।
- (५) श्रनेक राज्यों में राज्य के बाहर देश के श्रन्य भागों में वेचने के लिए. शीर्ष संस्थार्थे नहीं है। यदि कही ऐसी संस्थार्ये कार्य करती है तो वह केवल विकय

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कुल सदस्यों में से पूर प्रतिशत वैंक श्रीर सिमितियों हैं श्रीर ४८ प्रतिशत व्यक्ति हैं। इन वैंकों की चालू पूँजी ६२९६७ करोड़ रुपये हैं जिसमें से १६९४ प्रतिशत निजी पूँजी हैं, ६०९१ प्रतिशत जमाधन है, श्रीर २३९५ प्रतिशत अन्य सोतों से लिया गया अप्रण है। १६५१-५२ में यह प्रतिशत कमशाः १६९३, ६३९५, २०९१ थे। स्विंच्च वैंकों की तरह इन बैंकों की निजी पूँजी का अनुपात पिछले वर्षों की अपेन्ना कुछ बढ़ रहा है पर फिर भी निजी पूँजी का अनुपात बहुत कम है। इससे इन वैंकों का कार्य अस्थिर रहता है। मिवष्य में इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनकी हिस्सा पूँजी और सुरिन्नत कोष की पूँजी बढ़ाई जाय जो इन बैंकों की निजी पूँजी होती है। १६५५-५६ में जमाधन का ६७ प्रतिशत विभिन्न व्यक्तियों से और ३० प्रतिशत प्रारम्भिक सिनियों से तथा ३ प्रतिशत सहकारी वैंकों से प्राप्त हुआ। इन्होंने अनुण अधिकतर सहकारी वैंकों से प्राप्त हिन्दीय सहकारी वैंकों को सवोंच्च वैंकों के अतिरिक्त अन्य सोतों से अनुण लोने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

. फेन्द्रीय सहकारी वैंको के कार्य की एक विशेषता यह थी कि व्यक्तियों को दिये जाने वाले अप्रिम में कमी आ गई। १९५५.५६ में वैंकों तथा समितियों को दिये जाने वाला अप्रिम म्ह प्रतिशत तथा व्यक्तियों को दिया जाने वाला अप्रिम १२ प्रतिशत था जबकि इससे पहिले वर्ष के प्रतिशत कमशः दश तथा १९ थे। हरे तथा सन्देहात्मक अप्रुणों का अनुपात अब भी अधिक है हालाँकि इस दिशा

में मी कुछ सुवार हुआ है।

समान विशेषताएँ— सर्वोच श्रीर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है; (१) इन दोनों संस्थाश्रों की हिस्सा पूँजी श्रीर सुरिवृत निधि (श्रर्थात् निजी पूँजी) अपर्याप्त हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति कुछ अञ्छी है, परन्तु उनमें भी हिस्सा पूँजी श्रीर सुरिक्षत कोष का धन पर्याप्त नहीं है इसका एक कारण तो यह है कि इन बैंकों का जिन लोगों से सम्बन्ध रहता है वह निर्धन हैं श्रीर इनको लाभ भी बहुत कम होता है जिससे सुरिवृत कोष में पर्याप्त धन-राशि एकत्रित नहीं हो पाती। यह खेद का विषय है कि द्वितीत महायुद्ध के समय श्रीर महायुद्ध के तुरन्त पश्चात् जब कृषकों की वित्तीय स्थिति सुधरी थी, इन बैंकों की हिस्सा पूँजी बढ़ाने का श्रवसर खो दिया गया। इन बैंकों की हिस्सा पूँजी में तभी वृद्धि की जा सकती है जब कि कृषकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो प्रथम व दितीय पञ्चवर्षीय योजनाश्रों की समाप्ति तक कृषकों की वित्तीय स्थिति सुधर हो प्रथम व दितीय पञ्चवर्षीय योजनाश्रों की समाप्ति तक कृषकों की वित्तीय स्थिति सुधर जायगी श्रीर तब बैंकों की हिस्सा प्ँजी में वृद्धि की जा सकेगी।

(२) दोनो संस्पात्रों में कुछ मिश्रित तथा कुछ श्रमिश्रित वैंक हैं। श्रमिश्रित र्वेक सहकारिता के सिद्धान्त के अधिक अनुकृत होते हैं। परन्तु मिश्रित प्रकार के वैंकों से यह लाम है कि इनको श्रिषिक विच प्राप्त हो सकता है श्रीर साथ ही उन लोगों का ग्रधिक सहयोग मिल सकता है जिनका कृषि से सम्बन्ध नहीं है। इस वात को ध्यान में रखने हुये कि भारतीय क्रुपक श्रमी श्रविकिति श्रवस्या में है यह बहुत बड़ा लाम है। मिश्रित बैंकों से केवल यही हानि नहीं हैं कि इनका व्यवसाय सहकारिता के नियमों के श्रमुसार सामान्य नहीं होता बल्कि साय ही इनका कमी-कभी हानिकारक परिखाम मी होता है। विभिन्न व्यक्तियों को इन बैंकों के शेयरों को कय करने का अधिकार है इसलिये इन बैंकों से ऋए लेने का भी अधिकार है। व्यक्तियों को कृषि की उत्पत्ति के आघार पर ऋग देना सहकारिता के नियमों के श्रनुक्ल नहीं है क्योंकि इससे ये बैंक उन दलालों की भी ग्रहायता करते है जिनको ग्रहकारिता श्रान्दोलन ग्रमाप्त करना चाहती है। साय ही इस प्रकार की सहायता से सहकारी विकय न्यवस्था के विकास में बाघा पहुँचतो है। इसलिए यह उद्देश्य होना चाहिये कि 'मिश्रित' समितियों को कुछ समय तक रहने दिया जाय और नाद में क्रपकों की आर्थिक दियति को सुधारने के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा इन संस्थाओं को विचीय आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर इन्हें श्रमिश्रित समितियों में बदल दिया जाय।

(३) केन्द्रीय सहकारी वैंक श्रीवकतर निश्चित समय के लिये लमा श्रीर वचत को स्वीकार करते हैं परन्तु सर्वोच्च वेंक इनके श्रीतिरक्त चालू खाते में धन स्वीकार करते हैं। सर्वोच्च वेंक श्रीर कुछ सीमा तक केन्द्रीय सहकारी वेंक साधारण व्यापारिक वेंकों का व्यवसाय करते हैं। यह वैंक ड्राफ्ट देते हैं, हुएडी, चेक श्रीर श्रुपपत्रों का क्य-विकय करते हैं श्रीर सामान की सुरक्षित रखते हैं। यह प्रश्न काफी विवाद प्रस्त है कि सहकारी संस्थाश्रों का कार्य-चेंश केवल सहकारी बेंकों के व्यवसाय तक ही सीमित रखा लाय या वे व्यापारिक वैंकों का व्यवसाय भी करें। वर्तमान समय में सहकारी वैंकों का कार्य उनको व्यस्त रखने के लिये पर्याप्त नहीं है इसिलिये इन्हें व्यापारिक वैंकों का मी कार्य करना पढ़ता है। यदि यह

व्यवसाय न किया जाय तो वैंकों की आय बहुत कम हो जामगी।

(४) इन छंत्पान्त्रों को बहुत कम लाम होता है। इन छंत्पान्त्रों का लाभ श्रीर सदस्यों को दिया गया लामाश भारत के श्रन्य वैंकों की श्रपेक्षा कम है।

व्याज दर-मारतीय रिजर्व र्वंक की हाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रनेक राज्यों में छाटी सहकारी सामितियों के व्याज की दर काफी श्रिधिक है। केवल वन्यई श्रीर मद्रास में नहीं सहकारी श्राग्दोलन काफी संगटित है श्रीर

काफ़ी विकसित है ब्याज की दर कुछ कम रखना संभव हो सका है। श्रनेक समितियों ने इस सिद्धान्त पर जोर दिया है कि योग्य कषकों को दिए जानेवाले ऋण पर ब्राल्यकाल तथा मध्यकाल के लिए ६३ प्रतिशत से ब्राधिक ब्याज न लिया जाय श्रीर दोर्घकालिक भ्रमण के लिए न्याज की दर ४ प्रविशत होनी चाहिए। यह सिद्धान्त महास थ्रीर बम्बई में लागू रहा है। इन राज्यों की सरकारें घाटे की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देकर सहकारी वैंकों को कम ब्याज पर ऋगा देने में सहायता कर रही हैं। इसके लिए सरकार वैंक प्रशासन का कुछ भार स्वयं वहन करती है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। सहकारी वैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले व्याज की दर अधिक होने के कुछ कारण निम्न है-(१) चहकारी समितियाँ स्थानीय तौर पर पर्याप्त पूँ जी का संग्रह करने में असफल रही हैं; (२) वम्बई और मद्रास को छोड़कर केन्द्रीय सहकारी वैंक साधाररात: छोटे हैं, इनके प्रश्न्य का व्यय अधिक है श्रीर आर्थिक दृष्टि से यह अनुपयुक्त है। यह अपना कारोबार तभी चला एकते हैं जब ऋण लेने और देने की व्याज की दर में काफी अन्तर हो; श्रीर (३) विभिन्न राज्य जो ऋण तथा त्यार्थिक सहायता से आन्दोलन की सहायता करते रहे हैं अब द्रव्य वाजार से आवश्यक ऋषा एकत्रित करने में और परिशाम स्वरूप उसे कम न्याज पर विभिन्न सहकारी कार्यों में लगाने में विशेष कठिन। ई अनुभव कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के मतानुसार निम्नलिखित प्रयत्नों से ब्याज की दर कम की जा सकती हैं—(श्र) सहकारी ब्रान्दोलन को टढ बनाया जाय, उसकी कार्य कुशलता में सुधार किया जाय श्रीर श्राम्य चेत्रों की बचत को संग्रहीत करने पर जोर दिया जाय: (व) श्रार्थिक दृष्टि से उपयुक्त इकाई का रूप देने के लिए सहकारी बैंकों श्रीर समितियों को एक में मिला दिया जाय श्रीर समितियों के कार्यचेत्र का न्यापक प्रसार किया जाय श्रीर (स) श्रारम्भ में राज्य सरकार वम्बई की तरह श्रार्थिक सहायता दें जिससे सहकारी बैंकों को कम ब्याज लेने से जो घाटा होता है उसकी पूर्ति की जा सके।

रिजर्ब वैंक से ऋष् — रिजर्ब वैंक एक्ट की घारा १७ (२) (व) और १७ (४) (स) के अनुसार यह वैंक सहकारी वैंकों को कृषि उत्पादन और फसल वेचने के लिए विना घरोहर के अल्प-कालिक और मध्य-कालिक ऋण देता है। घारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभृतियों और भूमि बन्धक बैंकों के ऋण्पत्रों की जमानत पर भी ऋण देता है। अन् १९५५ की फर्चरी से रिजीव वैंक ने धारा

१. विस्तार पूर्वक श्रध्यन के लिये 'आम्य वित्त व्यावस्था' का श्रद्याय देखिये

१७ (४) (ग्र) के अन्तर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिये मध्य कालीन अपूरा देना श्रारम्भ कर दिया है। १९५३ के रिजर्व वैंक श्राफ इन्डिया एक्ट के संशोधन के कारण यह सम्भव हो गया है कि १५ मदीने से लगाकर ५ वर्ष तक की श्रविध के लिये ऋगु दिया जा सके। इस नियम का प्रयोग करने के विचार से दी वैंक ने तीन वर्ष की श्रविध के स्थायी ऋग, एक्ट की धारा १७ (४) (श्र) के श्रन्तर्गत देना श्रारम्म कर दिया है, यद्यपि श्रिधिक लम्बी श्रयधि श्रयांत् ५ वर्ष तक के श्रावेदनों पर श्रावश्यकता पढ़ने पर विचार किया जा सकता था। ऐसे ऋणीं पर ब्याज कीर दर वैंक की दर से २% कम निश्चित की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा दी हुई गारन्टी थ्रौर ऋग लेने वाले केन्द्रीय सहकारी वैंक अथवा समिति द्वारा लिये हुये प्रतिज्ञा पत्र ही इन ऋगों की जमानत थे। जिन कायों के लिये मध्य कालीन ऋग दिये जा सकते ये वे वेकार भृमि को पुनः श्रधिकृत करना, बीध बनाना श्रयवा भूमि में किसी श्रन्य प्रकार का सुधार करना, वैल श्रादि जानवर खरीदना, कृपि सम्बन्धी श्रीनार खरीदना तथा जानवरों को बाँधने के बाढे श्रीर खेतों में गोदाम बनाना इत्यादि थे। रिजर्व बैंक द्वारा राज्यीय सहकारी वैंक को दिये गये श्रिप्रिम की राशि १६५१-५२ में ११ रह करोड़ रु० थी। १६५७-५८ में यह बढ़कर ५७'१२ करोड़ रु० हो गई। इस ग्रवधि के ग्रन्त में देय भ्रूगों की राश्चि ७'⊏१ करोड़ ६० से बढ कर ३५.११ करोड़ ६० हो गई। १६५७-५८ में दिये गये ५७ ११ करोड़ रु के कुल ग्रिप्रिम में से ४१ ४१ करोड़ रु घारा १७ (४) (स) के अन्तर्गत, १२.७२ करोड़ रू धारा १७ (४) (भ्र) के अन्तर्गत तथा २'६६ करोड़ ६० धारा १७ (४) (ग्र) के ग्रन्तर्गत दिये गये।

श्रिष्ठिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेच्चण समिति की सिफारिशों के श्रनु-सार १० करोड़ र० की प्रारम्भिक राशि से राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्धंकालीन) कोष का निर्माण ३ फरवरी १६५६ को किया गया ताकि "राज्य सरकारों, (जिससे वे सहकारी समितियों की हिस्सा पूँजी में योग दे सकें) राज्यीय सहकारी बैंकों श्रीर भूमिनन्यक बैंकों को दीर्घ एवम् मध्यकालीन श्रमुण दिये जा सकें।" जून १६५६ में इस कोप में ५ करोड़ र० के वार्षिक श्रनुदान से वृद्धि की गई। मार्च १६५७ के श्रन्त तक २.६८ करोड़ र० का श्रमुण ११ राज्यों को दिया गया ताकि वे सहकारी संस्थाओं की हिस्सा पूँजी में योग दे सकें।

श्रध्याय १६

भूमि वंधक वैंक

भूमि बंधक वैंकों से कुषक को दीर्घकालीन श्रमण प्राप्त होता है। भूमि बंधक वैंकों की आवश्यकता हस लिए है क्योंकि छोटी सहकारी समितियाँ कुषकों को दीर्घकाल के लिए श्रमण नहीं दे सकती क्योंकि वह अपने कार्य संचालन के लिये स्वयं केन्द्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण लिया करती हैं। इसके साथ ही भू-सम्पत्ति के आधार पर दार्घकालिक ऋण देने के लिये विशेषकों की सहायता की आवश्यकता होती है जो भू-सम्पत्ति का मूल्य बता सकें और इस सम्बन्ध में अन्य प्रकार का परामर्श दे सकें। छोटी सहकारी समितियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। इन कारणों से सहकारी समितियों दीर्घकालिक ऋण नहीं दे पाती हैं। पहले जमींदार, साहुकार और महाजन कुषकों को दीर्घकालिन ऋण देते ये परन्तु इस प्रथा के हट जाने से भूमि बन्धक वैंकों की अधिक आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के खाद्यानों तथा व्यापारिक करलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह तभी सम्भव हो संकता है जब कि दीर्घकाल के लिये भूमि के सुधार में काफी धन लगाया जाय। इससे भी भूमि बन्धक वैंकों के सहत्व में वृद्धि हो गई है। यह सभी सम्भव हो संकता है जब

^{9.} कृपक को कृषि में वृद्धि करने और अन्य घरेलू कार्यों के लिये अवपकालिक ऋषा की आवश्यकता होती है और फसल कट जाने के पश्चात् तुरन्त उसको
चुकाया भी जा सकता है। पशु खरीदने, कृषि के औजार इश्यादि का प्रवन्ध करने के
लिये कृपक मध्यकालिक ऋषा लेता है। वह ऋषा एक से तीन वर्ष के लिये और
कभी-कभी ५ वर्ष तक के लिए लिया जाता है। कृपक को दीर्घकालिक ऋषा की भी
आवश्यकता होती है जिससे वह कृषि के लिए मशीनें तथा अन्य मृत्यवान सामान
कथ करता है, भूमि कथ करता है और पुराने ऋषा को चुकाता है। चू कि इस प्रकार
के ऋषा की धन राशि काफी बदी होती है और, जैसा कुछ अन्य देशों में होता है,
इसकी अवधि १७५ वर्ष तक की हो सकती है, इस लिये इस प्रकार के ऋषों को भू
सम्पत्ति के बदले ही प्राप्त किया जा सकता है। (रिज्वै वैंक के कृषि साख विभाग
इसरा प्रकाशत भूमिवन्धक वैंक (Land Mortgage Banks) नामक प्रकाशन से)।

संगठन किया जाय तो इससे जनता की वचत को भृमि सुधार कार्य में पहले की अपेक्षा श्राधिक मात्रा में लगाया जा सकता है। व्यापारिक वैंकों को कपया लोगों को श्रल्पकालिक जमाधन से मिल जाता है परन्तु इसके विपरीत भूमि वन्धक वैंकों को श्रृण पत्र चला कर या वन्धक बाँडों के द्वारा धन मिलता है। ये वांग्रह वैंकों से धन लेने वाले व्यक्तियों द्वारा वन्धक रक्खी हुई सम्पत्ति के श्राधार पर प्राप्त होते हैं। कुछ परिस्थितियों में, जैसे छोटे छोटे कुपकों के लिए विशेष उपयोगी होने के कारण या राष्ट्रीय श्राधिक व्यवस्था में इनका विशेष महत्व होने के कारण, सरकार इन वन्धक बाँगडों के सुगतान की गारनटी देती है।

भूमि बन्यक वैंकों को न्यापारिक वैंकों के श्राघार पर सहकारी संस्थाश्रों के या कार्पोरेशन के श्राघार पर रूप में संगठित किया जा सकता है। भारत में भूमि बन्यक वैंकों को सहकारी श्राघार पर संगठित किया गया है परन्तु चूँकि सुछ न्यक्ति निजी रूप से इस प्रकार के वैंकों के सदस्य हैं इसलिए इनकी प्रकृति श्रयं सहकारी संस्था के समान कही जा सकती है।

मारत में उर्व प्रथम उद्देशी भूमि बन्धक वैंक १६२० में पंजाब के कंग नामक स्थान में स्थापित की गयी परन्तु इसको सकलता नहीं मिली। मद्रास में सर्व प्रथम १६२५ में भूमि बन्धक वैंक स्थापित किये गये श्रीर वहाँ इन्हें श्रिधिक सकलता मिली। यहाँ केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक १६२६ में स्थापित किया गया। इसके पश्चात् कुछ श्रन्य प्रदेशों ने भी मद्रास की तरह भूमि बन्धक वैंक स्थापित किये।

१६२६ में रिजस्ट्रार-सम्मेलन ने भूमि बन्धक बैंकों की समस्या पर विचार किया श्रीर कुछ सुमाव दिये। भारत में इन बैंकों का विकास सम्मेलन के सुमावों के श्रनुसार हुशा। रिजस्ट्रार सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण सुमाव निम्नलिखित हैं—

- (१) इस प्रकार के बैंकों का संगठन सहकारी समिति नियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। इनका कार्य चेत्र न तो इतना कम हो कि आर्थिक हिष्ट से यह अनुपयुक्त सिद्ध हों और न इतना अधिक हो कि प्रवन्ध करना कठिन हो जाय।
- (२) भूमि वन्धक पैंक कृषकों को इन कायों के लिए ऋग दे सकते हैं— (ग्र) भूमि तथा मकान छुड़ाने के लिये, (व) भूमि श्रीर कृषि के साधनों में सुधार करने के लिए, (स) पहले का ऋग चुकाने के लिए श्रीर (द) भूमि कृप करने के लिए। वैंक को श्रपने उपनियमों में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस प्रकार का ऋग कम से कम कितना श्रीर श्रिषक से श्रिषक कितना दिया जा

एकता है। वैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि श्रृण की घन राशि इतनी कम न हो कि उससे लेन-देन का व्यय भी वस्त न हो सके और न इतनी श्रिधिक हो कि प्रारम्भिक समिति उसे सुगमतापूर्वक न दे सके। सम्मेलन ने सुमाव दिया कि श्रृण की घनराशि सम्पत्ति के मूल्य के श्राधे से श्रिधिक नहीं होनी चाहिये।

- (३) वैंक को कृषक की ऋण चुकाने की शक्ति तथा जिस कार्य के लिए ऋण लिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए ऋण चुकाने की अवधि निश्चित करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ऋण से लेने वाले को आर्थिक द्रांबर से लाभ न हो वह ऋण न दिया जाय। सम्मेलन ने सुमाव दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में ऋण चुकाने की अधिकतम सर्वोत्तम अवधि २० वर्ष है।
- (४) प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहाकारी बैंक स्थापित किये जायें। इन बैंको को राज्य के केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, किन्तु प्रान्तीय भूमि बन्धक कार्पोरेशन की स्थापना होने तक अस्थायी रूप में इनके इस कार्य पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।
- (५) सरकार को ऋष्णपत्रों पर न्याज और पूँजी चुकाने की गारन्टी देनी चाहिए। कार्य चालू करने के आरंभ काल में सरकार को भूमि बन्धक वैंकों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इन वैंकों को स्टाम्प कर इत्यादि में कुछ सुविधाएँ दी जानी चाहिये। साथ ही इन वैंकों को रेहन रखी वस्तुओं के छुटाने की अविध समाप्त हो जाने के पश्चात् विना न्यायालय की सहायता लिए उन पर अधिकार कर लेना या उनके विक्रय का अधिकार मिल जाना चाहिये परन्तु ऐसी न्यवस्था होनी चाहिये जिससे दूसरे पद्म के हितों की भी रहा की जा सके।

तालिका १ से यह स्पष्ट है कि यह आन्दोलन समान रूप से देश के विभिन्न भागों में विकित नहीं हुआ है। १६५१-५२ में केवल ६ केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक थे। इसके पश्चात् तीन और स्थापित हुये, एक हैदराबाद में, एक अन्ध में हे इस प्रकार १६५५-५६ के अन्त में केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक ६ राख्यों में स्थापित हो गये (आन्ध्र, वम्बई, मद्रास, उन्हीसा, हैदराबाद, मैस्र, सीराष्ट्र, त्रिवाँकुंर कोचीन और अजमेर) और प्रारम्भिक भूमि बन्धक वैंक ७ 'क' राख्यों में ३ 'ख' राख्यों में और १ 'ग' राख्यों में स्थापित हो गये। चूँकि सीराष्ट्र, उसीहा और बाँवकुर कोचीन में प्रारम्भिक भूमि वन्धक वैंक नहीं हैं, इसिलये इन राख्यों के केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक न्यक्तियों से अपना सीधा समन्ध रखते हैं। आन्ध्र, महास, बम्बई और मैस्र में प्रारम्भिक भूमि बन्धक वैंक

भारतीय श्रर्थशास्त्र की समस्या एँ

तालिका १

मूमि चन्धक वैंकों की सदस्यता १९५५-५६में

राज्य	वैंकों का संख्या	व्यक्तियों की सदस्य संख्या	बैंकों की संख्या
	केन्द्रीय भूमि बन्धव	ह बेंक	
ग्रान्त्र	8	१७४	યુહ
वम्बई	१	१,०१७	११५
मध्य प्रदेश	ਹ	•••	२७
मद्रास	8	३२६	હ્યૂ
उड़ीसा	१	६३६७	₹0
हैदराबाद	१	***	३७
मैस्र	8	२०६	१६३
सौराष्ट्र	१	७३,५१९	• • •
त्रॉवंकुर व	होचीन १	પ્,ે६⊏३	•••
श्रवमेर	१	***	৬
योग	3	६०,२६५	४६१
	प्र	र्रामक भूमि बन्धक वेंक	
ग्रान्ध	યૂહ	६५,८८२	***
श्रासाम	ર	२७५	•••
वम्बई	` १ ८	३२,६४५	***
मध्यप्रदेश	τ ११	२२,४६३	***
मद्राच	७३	ं १,०१,४ ८ ४	***
उत्तर प्रदे	श ६	८७५	•••
पश्चिमी	बङ्गाल ६	२,६६४	***
हैदरा बाद	२०	દ,६५४	***
मध्यभारत	र १	६२	244
मैस्र	⊏३	४५,६२५	***
राजस्यान	₹ 0	२७१	
श्रनमेर	४ ,२	१,५६७	•••
योग	३०२	३,१३,⊏२७	

तानिका नं० २ १९५४-५६ में मूमि बन्धक वैंकों का कारोवार

	केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (लाख रुपयों में)	प्रारम्भिक भूमि बन्धक वैंक (लाख रुपयों में)
शेयर पूँनी	७ ८°७ ३	द्भ:६४
ऋग श्रीर जमा धन		
(क) बैंकों ग्रीर समितियों से	२१ •०२	२३'६६
(ख) व्यक्तियां तथा अन्य स्त्रोंतो से	११७"८६	5 73
सरकार से प्राप्त ऋण	८७ ′ १ २	৵'७४
ऋ्या पत्र	\$ 8€8,\$≃	७'६२
केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक से प्राप्त ऋग	-	६७⊏ *७६
व्यक्तियों को दिया गया ऋण	-	१७३.६४
बेंकों श्रीर समितियों को दिया गया ऋण	२८३"०४	-
वर्ष भर में चुकाया हुआ ऋग	<i>१३७</i> •४५	९.३ °३७
वर्ष के अन्त में कुल ऋण	१३०८७२१	१०५१.१४
सुरित्तत कोष	३६•३२	१७'दर
श्रन्य कोष	१७.६६	६०.०त
चालू प्रुँबी	१८५२'६३	6658.27

सुक्यवस्थित हैं। मध्य प्रदेश में उनकी व्यवस्था साघारण स्तर की है। वहाँ श्रभी कोई केन्द्रीय भूमि वन्यक वैंक नहीं है। इन वैंकों द्वारा क्रवकों की समस्याएँ इल करने के लिये यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय भूमि वन्धक वैंक हो श्रीर श्रनेक छोटे भूमि बन्धक वैंक हो। श्रावश्यकता इस बात की है कि उन राज्यों में केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक स्थापित किये जाँय जहाँ श्रमी तक इनकी स्थापना नहीं हुई है। इसके साथ ही वर्तमान छोटे भूमि वन्धक वैंकों के व्यवसाय में वृद्धि की जाय तथा उन राज्यों में जहाँ यह श्रमी तक नहीं है प्रारम्भिक भूमि बन्धक वैंक स्थापित किये जाँय।

१६५५-५६ में केन्द्रीय श्रीर प्रारम्भिक भूमि बन्वक वैंकों की चालू पूँजी तालिका २ के श्रनुसार कमशः १८-५३ श्रीर ११-३५ करोइ रुपया थी। केन्द्रीय भूमि वन्यक वैंकों ने २८३ करोड़ रुपये तथा प्रारम्भिक भूमि वन्यक वैंकों ने १७४ करोड़ रुपये ऋणु में दिये। इन वैंकों के व्यवसाय की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं।

- (१) इन बेंकों ने जितना ऋण दिया है और जितना व्यवसाय किया है, वह आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है। १६५५-५६ में केन्द्रीय तथा प्रारम्भिक भूमि बन्धक बेंकों द्वारा दिये गये ऋण की मात्रा कमरा: २ ५३ करोड़ र० १ ७४ करोड़ र० थी जब कि इससे पिहले वर्ष में इनके द्वारा ऋण दी हुई राशि कमरा: २ ४३ करोड़ र० तथा १ ४५ करोड़ र० यी। कुपकों को दोर्घकालीन ऋण की आवश्यकता की तुलना में ये धन बहुत कम हैं।
- (२) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के १८.५३ करोड़ र० की चालू पूँजी तथा प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों के ११'३५ करोड़ र० की चालू पूँजी में से मद्रास श्रीर श्रांध्र कमशः १०'१२ करोड़ र० तथा ७.६६ करोड़ र० के लिए उत्तरदायी थे। मद्रास में भूमि बन्धक बैंकों के सफल होने के अनेक कारण हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि छोटे बैंकों के व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के चुनाव, भूमि के मूल्य इत्यादि की परीज्ञा, अगुण लेने वाले की अगुण चुकाने की शक्ति का अनुमान, वस्ला में शीव्रता श्रीर छोटे बैंकों की कार्य कुशलता इत्यादि के विषय में सावधानी से कार्य लिया गया। सरकार ने इन बैंकों के व्यवसाय का भली भाँति निरीज्ञण किया, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों ने बड़ी सतर्कता की नीति श्रपनाई। इसके साथ ही बैंकों के कुशल प्रबन्धकों ने भी श्रपने उत्तरदायत्य को भली भाँति निमाया। इस श्रान्दोलन की सफलता के लिए यही कारण प्रमुख रूप से सहायक रहे। श्रावश्यकता इस बात की है कि श्रादोलन का श्रन्य राज्यों में भी विस्तार किया जाय श्रीर उसे मद्रास की ही तरह सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय।
- (३) राज्य के श्रीर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ही तरह, भूमि बन्धक बैंकों के पास श्रमनी धनराशि बहुत कम है श्रीर टन्हें श्रमण्यत्रों, सरकार से श्रमण् श्रीर जमापूँजी पर ही निर्मर करना पड़ा है। जहाँ तक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों का सम्बन्ध है, १४ '६४ करोड़ रुपया जो कि कुल चालू पूँजी का लगमग ८०% होता है श्रमण्यत्रों द्वारा ही माप्त किया गया था। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों की सहायता करने के विचार से रिजर्ब बैंक ने १६४६ में भूमि बन्धक बैंकों द्वारा निर्मित श्रमण् पत्रों के १०% तक धन (जो सीमा १६५० में २०% कर दी गई थी) इस दशा पर देने की श्रमुमित दी कि उन राज्यों की सरकार जहाँ वे बैंक स्थित हैं, मूलधन श्रीर ज्याज देने का उत्तरदायित्व श्रमने ऊपर खेने को प्रस्तुत हों। १६५३ में इस सहायता योजना का श्रीर श्रधिक विस्तार किया गया श्रीर मारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत जो ५ करोड़ रुपया दीर्धकाल के

लिये कृषि सम्बन्धी ऋगा देने के लिये निश्चित कर दिया था, उसमें से १ करोड़ रुपया भूमि बन्धक वैंकों के ऋगु पत्र क्रय करने के लिये नियत कर दिया गया। यह निश्चित कर दिया गया कि केन्द्रीय सरकार श्रयवा रिजर्व वैंक दो में से कोई भी केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंकों द्वारा निर्मित कुल ऋगापत्रों के ४० प्रति-शत ग्रथवा जितने जनता द्वारा न क्रय किए जाँय दोनों में से जो कम होगा विक्रय करें। कय की दशा यह होगी कि क़ेन्द्रीय भूमि बन्यक बैंक इस सुविधा का लाम के लिये यह बात स्वीकार करें कि वे एक वर्ष के ग्रंदर सरकार श्रीर रिजर्व वैद्ध द्वारा मिल कर दी गई धनराशि का कम से कम आधा उत्पादक कार्यों के लिए श्चिंग रूप में व्यय करें। १९५३ ५४ में वेबल आंध्र के भूमि बन्धक वैंक को १७ लाख रुपये की इस योजना के श्रंतर्गत सहायता दी गई यी। १६५५ के जून के श्रन्त तक इस योजना के श्रन्तर्गत भ्रूणपत्रों के क्रय की बातें श्रांध, मद्रास, मैस्र, श्रीर त्रावंक्कर कोचीन के फेन्द्रीय भूमि बन्चक बैंकों से, जिन्होंने ऋरणपत्र निर्मित किये थे, चलाई गई। मद्रास श्रीर श्रांघ्र सरकारों ने इस योजना की दशाश्रीं को स्वीकार कर लिया था। पर रिजर्व बैंक से इसके क्य में सहयोग माँगने की भृ गपत्रों के जनता द्वारा श्रावश्यकता से श्रधिक क्रय करने के कारण श्रावश्यकता नहीं पड़ी। मैसूर श्रीर त्रावंकुर कोचीन की सरकारों ने रिजर्व वैंक द्वारा उनके ऋग पत्रों के क्रय कर लिये जाने पर जोर नहीं डाला।

१६५५-५६ के अंत में वह योजना समाप्त हो गई जिसके संतर्गत केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक सम्मिलित रूप से केन्द्रीय मूमि बन्धक बैंकों के ऋग्णंपत्रों को खरीदती थीं। किन्तु ऋग्णंपत्रों अप्राधित्व अंश या २०% में से जो भी कम हो रिजर्व बैंक द्वारा उसके योग दान की प्रथा चालू रही। फरवरी १६५६ में राष्ट्रीय ऋषि साख (दीर्घ कालीन) कोष का निर्माण किया गया। इस कोष से लिये गये ऋग्ण से राज्य सरकारों भूमि बन्धक बैंकों की चालू पूंजी में योग दान कर सकती थीं।

प्रारम्भिक भूमि वन्धक वैंकों के सम्बन्ध में उनके ११ ३५ करोड़ रुपये की चालू पूँजी में ह. ७६ करोड़ रुपया श्रायांत कुल का द्र % केन्द्रीय भूमि चन्धक वैंक द्वारा ऋण रूप में प्राप्त हुश्रा था। इन वैंकों के लिये यह तो श्रानिवार्य है कि वे ऋगुण पत्रों द्वारा बाजार से रुपया प्राप्त करें तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंकों से उधार लें, फिर भी उनके व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करने के लिए यह श्रावश्यक है कि उनकी शेयर पूँजी तथा रिश्चत कोष बढ़ाया जाय।

(४) सहकारी वैंकों की भाँति भूमि वन्धकं वैंकों ने भी बहुत श्रधिक व्याज की दर पर श्रुण दिया है। इसका एक कारण यह था कि केन्द्रीय बन्धक वैंकों में व्याज की दर वहुत श्रिष्ठिक थी। दूसरा कारण यह था कि छोटे भूमि वन्थक वैंकों ने स्वयं लाम प्राप्त करने के लिये भी श्रिष्ठिक व्याज लिया। इन वैंकों को कृपकों के लिये लामदायक बनाने के लिए यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि यह वैंक कम व्याज पर श्रृण लें श्रीर श्रुपनी व्याज की दर घटाएँ तथा श्रावश्यकता पड़ने पर इन्हें सरकार भी श्रार्थिक सहायता दे। इसके साथ ही यह प्रयत्न करना चाहिये कि इन वैंकों की कार्यकुशलता वढ़े जिससे छोटे वैंकों ने व्याज में जो श्रातिरिक्त वृद्धि की है वह कम हो जाय। इन वेंकों का प्रवन्ध-सम्बन्धी व्यय कम करना होगा जिससे व्याज की दर में भी कमी की जा सके श्रीर जो कुछ रूपया लगाया गया है उसका उचित लाभ प्राप्त हो।

सुधार-सम्बन्धी सुमाव

भूमि बन्धक बैंकों का मद्रास में २३ वाँ सम्मेलन सम्पन्न हुन्ना जिसमें भूमि वन्धक वैंकों के कार्य में सुधार करने के लिये श्रामेक सुमाव दिये गये। सम्मेलन में यह बताया गया कि बैंकों के पास पर्याप्त धन नहीं है, ऋ ए देने में देर होती है, व्याज की दर बहुत अधिक है श्रीर देश के कुछ मार्गों में, विशेषकर मद्रास में, कृषि की स्थिति बिगड़ने के कारण कृपक आसानी से ऋण नहीं चुका पाता है और वैंकों का ऋण वस्ली का कार्यधीमा पड़ गया है। सम्मेलन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जो भ्रमण लिया जाता है उसका उद्देश्य भूमि में सुधार करने की श्रपेद्या पुराना ऋण चुकाना रह गया है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि वैंक के पास जितना भी धन है उसका उपयोग इस रूप में करना चाहिये निषसे कृपि उत्पादन बढे श्रीर किसानों को वचत करने में सहायता दी जाय ताकि वह श्रपना पुराना भूगा चुका सकें। यद्यपि श्रव तक भूगा इस उद्देश्य से भी दिया जातारहा है कि भूमि ग्रीर कृषि उत्पादन में सुधार हो परन्तु इस बात पर ऋषिक जोर दिया गया है कि ऋगों से पुराने कर्ज को चुकाया जाय। इसका एक कारण यह है कि भूमि बन्धक वैंकों का आरम्भ उस समय हुआ जब आर्थिक मंदी के कारण कृपक ऋण के बोम से लद गया था परन्तु युद्ध के समय कृषि की उपज के मूल्य में वृद्धि हो जाने से किसानों ने श्रपना बहुत कुछ ऋगा चुका दिया श्रीर यह समस्या श्रव किसी भी रूप में उतनी गम्भीर नहीं रह गई है जितनी कि वह पहिले थी। वर्तमान समय में देश की सबसे वड़ी ब्रावश्यकता यह है कि उत्पा दन बढ़ाया जाय, संगठन में सुधार करके उत्पादन न्यय कम किया जाय श्रीर उत्पादन के साधनों में कुशलता प्राप्त की जाय । इसलिये भूमि वन्घक बैंकों से दिये जाने वाले ऋण का अब यही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये। सम्मेलन में यह बताया गया कि वर्तमान ऋण देने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान प्रणाली के श्रनुसार

ऋण लेने वाले को दूसरा श्रीर तीसरा ऋण श्रनुत्पादक कार्यों के लिये दिया जाता है श्रीर ऋण की श्रिष्ठकतम तथा न्यूनतम मात्रा मी निश्चित नहीं की जाती। यह ऋण २० वर्ष के श्रंदर चुकाये जा सकते हैं श्रीर उन पर व्याज की वही दर लागृ होती है जो मूल ऋण के व्याज की दर होती है। इसमें सुधार करने की श्रावश्यकता है—(श्र) दूसरे श्रीर तीसरे ऋण की व्याज की दर श्रिष्ठक होनी चाहिये, (व) ऋण कम समय के लिये दिया जाय जिससे भूमि से प्राप्त श्रिष्ठक श्राय को श्रन्थ कार्यों में लगाने से रोका जाय सके श्रीर उसका उपयोग ऋण चुकाने में किया जा सके, श्रीर (स) ऋण लेने के उद्देश्य पर विशेष रूप से व्यान देना चाहिए।

वर्तमान समय में श्राधिक श्रावेदन पत्र श्राने के कारण, श्रावेदन पत्रों की जाँच करने के लिए शिक्तित कर्मचारियों की कमी होने के कारण, श्रुण के सम्बन्ध में किसान को श्राधिक ज्ञान न होने श्रीर मालिकों द्वारा श्रावश्यक कागजात हत्यादि सावधानी से न रखने के कारण श्रुण देने में बहुत समय लग जाता है। इन कठिनाइयों को हल करने के लिए सम्मेलन में यह सुकाब दिया गया कि केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित करें जैसा कि मद्रास में किया गया है। इस पुस्तिका में सरल शब्दों में उन सारी बातों को लिखा जाय जो श्रुण लेने के लिए श्रावश्यक हैं। पुस्तिका में श्रुण लेने की पूर्ण विधि दी जाय। बैंक में उपयुक्त शिद्या प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये जाँय श्रीर शाम्य चैत्रों में ऐसे एजेन्ट नियुक्त किये जाँय जो श्रुण के सम्बन्ध में जनता को विभिन्न जानकारी दे सकें।

श्रध्याय १७

ग्राम्य वित्त व्यवस्था

कृपक को श्रह्यकालिक, मध्यकालिक श्रीर दीर्घकालिक श्रुण को श्राय-रयकता होती है। बीज, खाट, चारा इत्यादि कय करने के लिये यह श्रह्म-कालिक श्रुण लेता है, पश्रु तथा कृष्य के श्रीजार इत्यादि ज्योदने के लिये वह मध्यकालिक श्रुण लेता है, श्रीर भूमि में स्थायी सुधार करने, बंजर भूमि को उपजाक बनाने श्रीर कुएँ तथा इमारतों का निर्माण करने के लिये उते दोधका-लिक श्रुण की श्रावश्यकता होती है परन्तु इस दिशा में वास्तविक किनार्या यह हैं कि (१) श्रूपक निर्धन श्रीर निरक्तर है। कमी-कभी तो श्रुण लेने के लिये यह श्रावश्यक जमानत भी नहीं दे पाता। साख के च्रिय में उमकी दिश्वि प्रायः नगर्य है; श्रीर (२) श्रूपक साधारणतया जमीदारों श्रीर महाजनों से श्रुण लेता रहा है, यह उसकी परम्परा रही है। परन्तु श्रव (श्र) जमीदारी का उन्मूलन हो जाने से, (व) महाजनी में श्रूनेक कान्ती प्रतिवन्ध लग जाने के, की लाइमेन्स लेना, लेखा रखना, ब्याज की दर पर नियन्त्रण इत्यादि, श्रीर (स्र) महाजनी कार्य की एक प्रतिकृत समाजिक प्रतिक्रिया के कारण कृपक के लिये यह खीन भी प्रायः समात हो गये हैं। महाजन श्रीर जमीदार या तो श्रुण देते ही नहीं श्रीर यदि देते भी है तो बहुत कम।

कृपकों की सहायता के लिये तकावी ऋग् प्रणालों है, परन्तु यह प्रगाली लोकिपय नहीं हो पाई है क्योंकि (श्र) तकावी ऋग्ण लेने में श्रमेक कारवाह्यों करनी पहती है, (व) यह ऋग्ण विशेष कार्य क लिये दिया जाता है, श्रीर (स) ऋग्ण वस्लों में कोई रियायत नहीं दी जाती।

इस दिशा में सहकारी माख समितियों श्रीर भूमि बन्धक बैंकों ने दुछ प्रगति की है, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम है, श्रीर महाजनों तथा जमीडारी के श्राीशिक उन्मूलन से जो श्रभाव हो गया है उनकी पूर्ण कर मकने के लिये यह संस्थाएँ न पर्याप्त हैं श्रीर न सुसँगठित। इसका पिन्साम यह हुआ है कि कुपक बड़ी कठिनाइयों में अस्त दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कृषि उपज के मूल्य में बृद्धि होने ने कुपक की वित्तीय स्थिति में कुछ मुधार हुआ है। इस वृद्धि से कुपक के वित्तीय श्रभाव की श्रांशिक पूर्ति तो हुई है, पर उसे श्रीर श्रिषक वित्त की श्रावश्यकता है। कुपक के लिये यह दुष्चक है। पर्यास वित्त

न होने से वह अपनी भूमि में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता। इससे वह निर्धन रहता है और ऐसी स्थिति में रहकर वित्त प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय कृषक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये इस दुष्चक को समाप्त करना आवश्यक है।

याम्य वैंक व्यवस्था जांच समिति-श्री पुरोपोत्तमदास ठाक़रदास की श्रध्यज्ञता में प्राम्य बैंक व्यवस्था जाँच समिति ने १६५० ग्राम्य साख व्यवस्था के पुर्न छंगठन के लिये विस्तृत सुकाव दिये हैं। प्रामों की खाख व्यवस्था को पुर्न छंग-ठित करने के लिये समिति ने कुछ ग्राधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, (१) समिति का मत है कि ग्रामीए जनता की बचत की संग्रहीत करने का कार्य श्रीर प्रामीण जनता को साख की सुविधा देने का कार्य प्रयक्त नहीं किया जा सकता। ये दोनों कार्य एक ही संस्था द्वारा किए जाने चाहियें। (२) वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आमों में ऋण इत्यादि देने के लिये उपयुक्त सस्याग्रों की न्यवस्था की जाय । (३) देश के विभिन्न भागों में श्रल्यकालिक श्रीर मध्यकालिक ऋण देने की व्यवस्था करने के लिये एक ही प्रकार की संस्था से कार्य नहीं चल सकता है। प्रत्येक क्षेत्र को श्रपनी स्थानीय परिस्थितियों के श्चनुसार उचित प्रकार की संस्था का निर्माण करना होगा श्रीर इस संस्था को सहकारिता के खिदानतों के श्राघार पर संगठित करना होगा। (४) सरकार को भागा तथा भूमि सम्बन्धी कानून बनाते समय इस स्रोर ध्यान देना चाहिये कि इन कार्यों के लिये नई और उपयुक्त संस्थार्ये किसी गति से स्यापित की जा सकती हैं। इस प्रकार के नियमों का साख संस्थाओं पर जो प्रभाव पड़े उसका सरकार को ग्रध्ययन करना चाहिये।

समिति ने यह बताया कि देश में व्यापारिक बैंक व्यवस्था का प्रसार हुआ, परन्तु इसके साथ ही उसने इस तथ्य की छोर भी संकेत किया कि व्यापारिक बैंक और विरोषकर अनुस्चित बैंक बड़े नगरों और करनों में केन्द्रित हैं। छोटे फस्नों और प्राम्य चेत्रों में यह कार्य सहकारी बैंक, डाकखाने के सेविंग बैंक और गिर अनुस्चित बैंक चलाते हैं। समिति ने बताया कि दहह कस्नों में, जिनमें ४२२ स्थानों पर या तो जिले के प्रधान कार्यालय है या तालुका के, बैंक सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

समिति ने सुक्ताव दिया कि यद्यपि व्यापारिक वैंकों को आम्य चेत्रों में अपनी और श्रिषक शाखायें स्थापित करने श्रीर व्यवसाय में उन्नित करने के लिये मोत्साहन देन का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु फिर भी सम्भावना यही है कि वर्तमान परिस्थितियों में न्यापारिक वैंक तालुका या तहसील के प्रधान कार्यालयों, कस्वों, मंडियों और व्यापारिक तथा श्रीद्योगिक महत्त्व के श्रन्य कस्वों के सिवाय

श्रान्यत्र श्रापना प्रसार कम करेंगे। छोटे कस्त्रों में सहकारी वैंकों का विकास करने की श्रावश्यकता है क्योंकि (श्र) उनका प्रामों की सहकारी समितियों से निकट सम्बन्ध रहता है श्रीर (ब) उनके न्यवसाय का न्यय भी श्रापेक्ताकृत कम होता है। छोटे ग्रामों में सहकारी समितियों श्रीर ढाकखाने के सेविंग वैंकों की न्यवस्था होनी चाहिये।

व्यापारिक वैंकों की सहायता करने के लिये समिति ने श्रानेक सुक्ताव दिये हैं, (१) सहकों का निर्माण करके, श्राम-यातायात एवम् संचार के साधनों का विकास करके, इन वैंकों पर दुकान निर्माण नियम लागू न करके श्रीर इन्हें श्रौद्योगिक पंचन्यायालय के निर्णयों से मुक्त करके उन सारी बाधाश्रों को दूर किया जाय जिनसे व्यापारिक वैंकों का विकास श्रवचद है। (२) रिजर्व वेंक तथा उसकी शालाश्रों द्वारा कम व्याल पर या विना व्याज के इनको क्पया दिलाने की व्यवस्था करके श्रप्रत्यत्र प्रोत्साहन दिया जाय। इनको बड़े तथा छोटे कोष यह में श्रपना क्पया सुरिद्धित रखने की सुविधा दी जाय श्रीर मामदागार विकास बीर्ड के द्वारा इनके लिये मंदार बनवाये जाँय (३) सहकारी वैंकों श्रीर सहकारी साख समितियों को विशेष सहायता दी जाय, जैसे इन्हें नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट विकय का श्रिषकार दिया जाय श्रीर हाकखाने के सेविंग वैंकों से प्रति-सप्ताह रूपया निकालने श्रीर श्रिषकतम नित्नेप के सम्बन्ध में सुविधा, कम दर पर रूपया माँगने श्रीर मेजने की सुविधा इत्यादि।

प्रामों में सेविंग वैंक का कार्य करने वाले डाकखानों की संख्या में वृद्धि की जाय और उनके कार्य में सुधार करने का प्रयत्न किया जाय। सिमित के मतानुसार यह मान लेना गलत है कि ग्रामों में काफी मात्रा में नकद बचत है। जिसे वैंकिंग की सुविधाओं का प्रसार करके संग्रह किया जा सकता है।

दीर्घकालीन साख के लिये समिति ने यह सुमाव दिया कि जिस चेत्रों में प्रारम्भिक तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक नहीं हैं वहाँ उन्हें स्थापित किया जाय। समिति ने देश भर के लिये एक केन्द्रीय कृषि साख कारपोरेशन की स्थापना करने श्रीर बैंकों के प्रसार के लिये पोत्साहन देने के लिये नकद श्रार्थिक सहायता देने के श्रनेक प्रस्तावों को सिद्धान्तों के श्रावार पर श्रीर श्रनेक प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण स्वीकार नहीं किया। वर्तमान परिस्थियों में निचेष बीमे को लागू करना श्रीर बड़े पैमाने पर चल बैंकों की न्यवस्था करना उपयुक्त नहीं सममा गया।

सिमिति के प्रस्तावों की आलोचना—जाँच समिति की उक्त योजना की आलोचना करते हुवे यह बताया गया है कि—(१) योजना में आमीण चेत्रों को वित्तीय सहायता देने की अपेद्धा इस बात पर जोर दिया गया है कि शामीणों की बचत को संग्रहीत किया जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित व्यवस्था के श्रन्तर्गत घन एकत्र करने वाली संस्था श्रपने द्वारा संग्रहीत कोष में से स्थानीय उपयोग के लिये कुछ योगदान नहीं देगी श्रीर ऐसी स्थिति में श्रामीण चेत्रों में व्यापारिक एवम् सहकारी बैंकों के कार्य का प्रसार करने में यह आवश्यक नहीं होगा। (२) समिति ने दीर्घकालिक वित्तीय सहायता पर जोर दिया है परन्तु यह सुमाव नहीं दिया है कि यह वित्तीय सहायता किन स्रोतों से श्रीर किस प्रकार प्राप्त की जाय। इसने केवल यह सुम्ताव दिया है कि भूमि बन्धक वैंक स्थापित किये जाँय । इस प्रकार के बैंकों की स्थापना करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं और जहाँ यह स्थापित हो चुके हैं वहाँ भी यह दीर्घकालिक वित्तीय सहायता यदि किसी केन्द्रीय कृषि कार्पोरेशन से भूमि बन्धक बैंकों द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त हो सके तो यह बहुत उपयुक्त होगा। परन्तु कुछ कारगों से समिति ने केन्द्रीय कारपोरेशन स्थापित करने के विचार को श्रस्वीकृत कर दिया। (३) श्रल्पकालिक वित्तीय सहायता के लिये समिति ने सहकारी बैंकों को उपयुक्त साधन माना है, परन्ते समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सुमाव नहीं दिया है कि इन सहकारी संस्थाओं को भविष्य में किस प्रकार अधिक सफल बनाया जा सकता है।

अखिल भारतीय प्रामीण साख सर्वे चाल-श्रविल भारतीय प्रामीण साख सर्वेज्ञण, अथवा गोरवाला कमेटी, ने ग्राम्य अर्घ प्रवन्यन की दशा का विश्लेषण किया और अपनी १६५४ में प्रकाशित रिपोर्ट में विशद अमिस्ताव किये हैं। भारतीय क्रषक संतोषप्रद ढंग से अपनी ऋषा की आवश्यकताओं की पूर्ण नहीं कर पाता। जितना ऋषा शामों में लिया जाता है उसका केवल ३% सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है और ३% से कुछ ही श्रधिक सरकारी संस्थाओं से । अपनी आवश्यकता के ६४% के लिये अब मी आमवासियों को **ग्रामीण महाजन श्रीर** साहुकार के ऊपर निर्मर रहना पड़ता है। इसके कारण क्षपक के लिये अपनी आवश्यकता पर ऋण लेना बहत ही महंगा, अपर्यात और श्रानिश्चित है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कृषि सम्बन्धी ऋणा जैसे प्राप्त है "न तो मात्रा में ही आवश्यकता अनुसार पूर्ण है और न जिस ढंग से मिलता है वही उचित है, श्रीर यदि जनता की श्रावश्यकता की दृष्टि से देखा जाय (ऋण् लेने की इमता की उपेज्ञा न करते हुये) तो जिसे मिलना चाहिये उसे पाप्त भी नहीं होता ।" समिति के मत में सहकारी समितियाँ इस समस्या को सुलक्ताने के लिये अयोग्य हैं, उनके पास धन का अभाव है। उनका यह भी मत है कि सहकारी-ऋग्य-स्रान्दोलन अपने निजी प्रयत्न द्वारा तो कुषकों की ऋगु की

श्रावश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकता। स्मिति ने कहा कि भारत में प्राम्य ऋण समस्त देश की सजीव श्रीर विस्तृत समस्या का एक श्रंश है। बिना उस संदर्भ में उसे ठीक-ठीक समके सुलक्काया नहीं जा सकता। उसकी सर्व विदित कठिनाई का केन्द्र श्राम ही है, पर उसके कार्यों श्रीर निराकरण के उपायों को श्रन्यत्र टूंढ़ना होगा। इस प्रकार यह समस्या केवल ग्राम की ही समस्या नहीं है। प्रत्यत्त रूप से इसका रूप ऋगु लेना है पर वास्तव में यह समस्या श्राधिक व्यवस्था की है, इसलिये विस्तृत श्राधिक कियाश्रों तथा ध्येयों का यह एक श्रंग है।

समिति द्वारा प्राम्य ऋण की श्रमिस्तावित सम्यक योजना तीन मूलायार िव्हान्ती पर श्राधारित है; (१) सरकार को विभिन्न स्तरों पर सहयोग देना चाहिये; (२) ऋण तथा श्रन्य श्राधिक कियाशों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिये; श्रार (३) इस योजना का प्रशासन पूर्ण रूप से प्रशिक्तित तथा कुशल कर्मचारियों द्वारा होना चाहिये जिनके हृदय में श्रामीण जनता की श्रावश्यकताश्रों के प्रति सहानुम् वि हो। सिर्मित ने सरकार के सहकारी ऋण सुविधाश्रों में, भान्डागारों की सुविधाश्रों श्रीर श्रामों में साधारण वैंकों के विस्तार कार्यों में सहयोग के लिये विशद श्रमिन्ताव किये हैं। कमेटी ने हम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की श्रीर रिजर्व बैंक, कृषि तथा खाद्य मंत्रालय राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भारडागर बोडों के तत्वाधान में श्रनेकों कोपों के स्थापना की श्राम पुर्नसंगठन के कार्यों में श्राधिक सहायता देने के लिये सिफारिश की।

श्रालोचना—गोरवाला कमेटी ने भारतीय श्राम्य समस्याश्रों का ठीक-ठीक विश्लेपण किया श्रीर इस निर्णय पर ठीक ही पहुँचों कि श्राम श्रपनी श्रुण समस्या को विना वाह्य सहायता के श्रपने श्राप सुलका नहीं सकते। भूतकाल में मुख्य लोर सहकारी श्रुण सुविधा पर दिया गया था। कमेटी का यह निष्कर्ष उचित ही या कि सहकारी श्रुण श्रान्दोलन श्रपनी वर्तमान समय की स्थित के श्रुनुसार श्रामीण जनता की श्रावश्यकताश्रों को पूर्ण नहीं कर सकता। कमेटी का यह प्रस्ताव भी बहुत ही श्लाधनीय है कि श्रुण समस्या के सुलकाने की योजना को सम्पूर्ण रूप से लेना चाहिये श्रीर साख तथा श्रन्य श्रायिक कियाश्रों को एक साथ कार्यान्वित करना चाहिये तमी योजना सफल हो सकती है। परन्तु कमेटी के सुक्ताव किसे सीमा तक दोषपूर्ण भी हैं। (१) यद्यपि कमेटी ने श्राधकाधिक सरकारी सहयोग की सिक्तारिश की है, पर उन्हें इस बात की श्राशंका न हुई कि इससे जनता सरकारी सहायता पर श्रावश्यकता से श्राधक निर्मर रहने की श्रार्व जनता सरकारी सहायता पर श्रावश्यकता से श्राधक निर्मर रहने की श्रार्व जनता सरकारी सहायता पर श्रावश्यकता से श्राधक निर्मर रहने की श्रार्व जावगी श्रीर उनकी निर्मरता सरकार के हर स्तर पर सहयोग देने से धीरे-धीरे लुत हो लावगी। (२) कमेटी ने इम्पीरियल वैंक श्राफ इंडिया के राष्ट्रीय-

कारण की श्रीर शामों में साधारण वैंकों के विस्तार की सिफ़ारिश की पर उनका हस बात की श्रीर ध्यान नहीं गया कि यह तभी सफ़ल हो सकता है जब श्रामीण जनता की बैंकों के प्रयोग करने की श्रादत पड़ जाय, जिसकी निकट भाविष्य में तो कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती। बिना हस श्रादत के स्टेट वैंक श्राफ़ इंडिया को जो शाखार्य श्रामों में खोली जाँगगी वे वैंकों को हानि ही पहुँचार्येगी श्रीर उसके द्वारा राष्ट्र को हानि होगी श्रीर कार्य कुछ न हो सकेगा; श्रीर (३) कमेटी द्वारा सरकारी सहयोग श्रीर श्राधिक सहायता से श्राम्य श्राण समस्या के सुलक्ता सकते की श्राशा नहीं की जा सकती। यह समस्या इतनी विशाल है श्रीर सरकारी श्राधिक सहायता जो इस कार्य के लिये नियत की गई है हतनी नगरय है कि सम्यक योजना की बड़ी बड़ी बातों के होते हुये भी थोड़ी सी सफ़लता प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। यदि सरकार ने मृतकाल में गाँवों के श्राण स्थोतों के विनाश करने में, जब कि वे उनके स्थान पर दूसरी सुविधा प्रदान करने में श्रीमता न की होती तो स्थित हतनी निराशजनक न होती।

योजना के अन्तर्गत— एवं प्रथम कार्य इस्पीरियल वैंक आफ इंडिया को प्रथम जुलाई १६५५ से राष्ट्रीय करण करके स्टेट वैंक आफ इंडिया को एमपित करके किया गया । ग्राम्य अधिकोषण जाँच कमेटी ने इस्पीरियल वैंक की २७४ नई शाखाओं के खोलने का सुकाव दिया पर इस्पीरियल वैंक १ जुलाई १६५१ से ३० जून १६५६ तक केवल ११४ नई शाखाओं के खोलने के लिये प्रस्तुत हुआ था। जब से स्टेट वैंक आफ इंडिया का जन्म हुआ है, नवीन शाखाओं के खोलने की गति में वृद्धि हुई है। स्टेट वैंक आफ इंडिया के लिए अपने जीवन काल के प्रथम पाँच वर्षों के भीतर अर्थात् ३० जून १६६० तक ४०० नवीन शाखाओं का खोलना नियम के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया है।

श्रीखल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेज्ञण समिति के श्रीभस्तावों के श्रनुसार दित्तीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत श्रल्प कालिक, मध्य कालिक, तथा दीर्घ- कालिक ऋण सुविषाश्रों के सम्बन्ध में निश्चित किये हुये ध्येय प्रथम योजना के ध्येयों की श्रपेज्ञा बहुत ऊँचे नियत किये गये हैं जैसा कि निम्न तालिका से प्रकट होता है।

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना
	के ध्येय	के ध्येय
श्रल्पकालिक ऋण	३० करोड़ रुपया	१५० करोड़ ६०
मध्यकालिक ऋग्	१० करोड़ रुपया	५० करोड़ रु०
दीर्घकालिक ऋग	३ करोड़ रुपया	्रथ् करोड़ र०

इससे यह स्पष्ट है कि ग्राखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेज्ञण ग्रामीण चाख समस्या के प्रति जनता का ध्येय श्राकर्पित करने में सकल हुश्रा है। ग्रामीए साख सर्वेच्च द्वारा प्रस्तावित पुर्नसंगठन की योजना की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने साख तथा शैर साख समितियों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देने की िषफ्रारिश की ताकि कृपक को ऋण, वीज, खाद, कृषि सम्बन्धी श्रीजार तथा श्रावश्यक उपभोग की सामग्री प्राप्त हो सके श्रीर उसे श्रपनी उत्पत्ति को बाज़ार में लेजाकर विकय करने में भी सुविधायें मिल सकें। कार्यों के सीचे हुये विस्तार के श्रनुक्ल प्रामीण साख सर्वेद्यण ने यह भी सिफ़ारिश की कि ग्राम में वर्तमान छोटी छोटी समितियों को मिलाकर बड़ी समितियों में परिखित कर देना चाहिये वाकि वे अनेक ग्रामों के समृद्द की सेवा कर सकें श्रीर ये पहिले पहिले बनाई जाने वाली बड़ी समितियों की रूप रेखा वही हो जो सर्वेक्षण ने प्रस्तावित की है। ऐसी बड़ी समितियों की सामान्य रूप रेखा कुछ इस दंग की होगी कि उसके सदस्य संख्या में लगमग ५०० तक होंगे श्रीर प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व उनके द्वारा जमा की हुई पूँजी के द्राञ्यिक मूल्य के पाँच गुने तक सीमित होगा। सिमिति की न्यूनतम शेयर पूँजी लगभग १५००० ६० के होगी श्रीर वह एक उपयुक्त संख्या में ग्रामों की जो एक समृह के अन्तर्गत रख दिये जाँयेगे सेवा करेगी और जो यथासम्भव प्रतिवर्ष लगभग १५ लाख रुपये का व्यवसाय करके दिखायेगी। ऐसा पत्ताव किया गया है कि १६६०-६१ तक १०,४०० ऐसी बड़ी समितियाँ जिनके मवन्यक प्रशिक्तित होंगे स्थापित हो जानी चाहिये।

सरकार को सहकारिता में सहयोग दे सकने में सुविधा प्रदान करने के विचार से रिजर्व वैंक ने एक राष्ट्रीय-कृषि-साख (दीर्घ कालीन) कोप की स्थापना १० करोड़ रुपये से की है। द्वितीय योजना काल में प्रतिवर्ध ५ करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायगा ताकि १६६०-६१ तक कोप में ३५ करोड़ रुपया हो जाय। इस कोप से राल्यों को इसलिये भूगा दिया जायगा कि वे सहकारी संस्थाओं की शेयर पूँजी क्रय कर सकें। एक दूसरे कोप की भी, जिसका कि नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास कोप होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापना की जायगी। इस कोप से राल्य-सरकारें गैर साख समितियों की शेयर पूँजी खरीदने के लिये भूगा ले सकेंगी। इसो कोप में से मगडारगृह के निर्माण, सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर व्यय, तथा सहकारी विभागों के प्रशासन को हद बनाने पर व्यय करने के लिये द्वाव्यिक सहायता दी जायगी।

भाग्डागार, साख समितियों तथा गैर साख समितियों के बीच एक महत्त्व-पूर्ण संस्थागत कड़ी के रूप में होगे । प्रारम्भिक विकी समितियों श्रीर सुन्यवस्थित

साख समितियों को श्रिधिक संख्या में गोदाम बनवाने होंगे। प्रामीण साख सर्वेज्ञण के सुक्ताव के श्रानुकूल ही यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केन्द्रीय भागडागार-निगम की स्थापना की जाय श्रीर प्रत्येक प्रदेश में भी उसी प्रकार भागडागार-निगम स्थापित किये जाँय। ये निगम राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भागडागार बोर्ड के निर्देशन में कार्य करेंगे। एक प्रदेश के माएडागार निगम की श्रिधकृत पूँची २ करोड़ रुपये तक अनुमानित की गई है पर निगर्भित पूँची विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुकूल होगी। यह प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्रीय मारहागार निगम द्वारा आधी पूँजी और शेष आधी प्रादेशिक सरकार द्वारा कय की जानी चाहिये। यह ब्राशा की जाती है कि १६ भाग्डागार निगम स्यापित किये जायेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५० माग्रहागार विभिन्न केन्द्रों में स्थापित किये जायेंगे, जिनकी माल सुरज्ञित रखने की शक्ति लगभग लाख टन होगी। माएडागारों की स्थापना के लिये उपयुक्त केन्द्रों की खोज की जा रही है। ऐसी आशा की जाती है कि केन्द्रीय भागहागार निगम की कुल पूँजी १० करोड़ रुपये के लगभग होगी जिसमें से केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विकास तथा भागडागार बोर्ड द्वारा ४ करोड़ रुपये तक के शेयर सम्भवत: क्षय कर ले और शेष पूँजी स्टेट बैंक आफ इन्डिया, अनुसूचित बैंकों, तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की जाय। केन्द्रीय भागडागार निगम से यह आशा की जाती है कि वह मुख्य मुख्य केन्द्रों में १०० वहे माएडागार स्पापित करेगा। माएडागार रहीदों को क्य-विकय योग्य (negotiable) माना जायगा, जिसकी जमानत पर श्रिधिकोषण संस्पायें उन व्यक्तियों को भ्राण दे सकेंगी जिन्होंने मायहागारों में कृषि उत्पत्ति जमा की है।"

सहकारी साख, विक्री, विधायन तथा भारहागारों इत्यादि के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मुख्य ध्येय निम्न हैं।

साख

बड़ी समितियों की संख्या	१०४००
श्रल्पकालीन श्रुण की मात्रा का ध्येय	१५० करोड़ ६०
मध्यकालीन ऋग की मात्रा का ध्येय	५० करोइ ६०
दीर्घंकालीन ऋण की मात्रा का ध्येय	२५ करोड़ ६०

विकी

तथा विधायन	
प्रारम्भिक विक्री समितियाँ जिनकी व्यवस्था की जायगी	250a
सहकारी चीनी कारखाने	. ३५

रुई श्रोटने के सहकारी कारखाने श्रन्य प्रकार की विधायन समितियाँ

४८ ११८

भाएडागार तथा गोदाम

केन्द्रीय तथा राज्यीय निगमों के भाग्डागार विक्री समितियों के गोदाम वडी समितियों के गोदाम · ३५० १५००

8000

रिजर्व वेंक का योगदान-वर्तमान नियम के ग्रन्तर्गत रिजर्व वैंक केवल ग्रल्यकालिक वित्तीय सहायता दे सकता है। कृषि को मध्यकालिक ग्रीर दीर्घकालिक विचीय सहायता देने का उसे श्राधकार नहीं है। रिजर्व वैंक विभिन्न फसलों के समय राज्य-सहकारी बैंकों को विना प्रतिभृति लिये ऋरण दे सकता है। यह सहायता घारा १७ (२) (वी) श्रीर १७ (४) (सी) के श्रन्तर्गत दी जा सकती है। साथ ही सरकारी ऋणात्रत्रों श्रीर भूमि बन्धक बैंकों के ऋणपत्र के श्राधार पर प्रतिभूति ऋग घारा १७ (४) (१) के अन्तर्गत दिये जा सकते हैं। घारा १७ (२) (बी) के अन्तर्गत संशोधन के परचात् ऋण वापसी की अवधि ६ महीने से वढा-कर १५ महीने कर दी गई है। इसके अन्तर्गत रिजर्व वैंक हिएडयों और प्रतिज्ञा पत्रों को कय श्रीर विकय कर सकता है। इन हुिएडयों श्रीर प्रतिज्ञा पत्रों पर दो या श्रिषिक श्रावश्यक इस्ताज्ञर होने चाहियें जिनमें से एक हस्ताक्षर श्रनुसूचित वैंक का या राज्य के सहकारी बैंक का होगा। यह हुएडियाँ या प्रतीशा पत्र फसल के समय प्रचलित किए जायँगे जिनकी चुकाने की श्रविध १५ महीने रहेगी। व्यवहार में यह श्रविध १२ महीने ही है परन्तु विशेष स्थिति में १५ महीने कर दी जाती है. श्राशा की जाती है कि इस संशोधन से कृषिकों को श्रधिक सुविधा होगी। सहकारी संस्थाओं को अन्य सुविधायें भारतीय रिजर्व वैंक नियम की संशोधित घारा १७ (२) (ए) के ग्रन्तर्गत दो गई है। ग्रव तक हिएडयों पर एक हस्ताक्तर श्रनुस्चित वैंक के होने पर रिजर्व बैंक से रुपया मिलता था। परन्तु श्रव यह सुविधा सहकारी वैंकों को भी दी गई है।

रिजर्व वैंक आफ इंडिया एक्ट के १६५१ और १६५६ में संशोधन से वैंक के आम्य अनुरा सम्बन्धी कार्यों में और भी अधिक विस्तार आ गया है। संशोधित एक्ट के अनुसार ''मौसमी कृषि न्यापार और फसलों की विक्री'' के अन्तर्गत मिश्रित कृषि कार्य और कृषकों तथा उनकी संस्थाओं द्वारा फसलों का विधायन भी सम्मिलित कर लिया गया है। अल्यकाल अनुरा चुकाने की अवधि १५ महीने कर दी गई है। मध्यकाल तक के अनुरा अधिक से अधिक ५ वर्ष की अवधि के लिये दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी वैंकों के न्यवसाय सम्बन्धी विपत्रों का रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व प्रायणा नियमानुकूल कर दिया गया है श्रीर इस बात की भी श्रानुमति दे दी गई है कि स्वीकृत घरेलू उद्योग तथा छोटे उद्योगों को उत्पादन में तथा उनके माल के विकय में श्रार्थिक सहायता पहुँचा सकता है।

१६४२ से भारतीय रिजर्व बैंक ने फसल की विकी के लिए सहकारी संस्थाओं को बैंक दर से एक प्रतिशत कम ज्याज की दर पर विचीय सहायता दी है। १६४४ में इसके अन्तर्गत फसल बोने, काटने, वेचने इत्यादि का कारोबार भी सम्मिलित कर लिया गया। १६४६ में ज्याज की दर में बैंक दर से एक प्रतिशत से बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत कमी कर दी गई है। बैंक के ज्याज की दर में ३ प्रतिशत से ३ प्रतिशत तक वृद्धि हो जाने पर भी रिजर्व बैंक ने कृषि कार्य के लिए डेढ़ प्रतिशत क्याज की दर पर ही सहायता दी, यह दर अब २ प्रतिशत कम कर दी गई है।

रिजर्व वैंक ने सहकारी वैंकों को कुछ श्रन्य सुविघाएँ प्रदान की हैं। पहले सहकारी वैंकों को सभी ऋष्ण प्रति वर्ष ३० सितम्बर तक चुकाने पहते थे। इससे सहकारी वैंकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रिजर्व वेंक ने श्रम यह निश्चय किया है कि सहकारी वैंकों द्वारा लिए गए ऋषा श्रपनी पूरी श्रविध के बाद भी चुकाये जा सकते हैं परन्तु इसमें यह शर्त लगा दी गई है कि किसी समय इन वेंकों के पास कुल शेष ऋषा उस वर्ष के लिए निर्घारित साख सीमा से श्रिषक न हो। सहकारी वेंकों को एक श्रीर सुविधा दी गई है। श्रम सहकारी वेंक रिजर्व वेंक द्वारा निर्घारित साख सीमा को बढ़ा भी सकते हैं, यह वेंक ऋषा की इस रकम को श्रम श्रपनो सुविधानुसार ले सकते हैं श्रीर उसका सुगतान कर सकते हैं जैसा कि बेंक में जमा रुपये के साथ किया जाता है। पहले यह स्थित थी कि ऋष्ण को निर्घारित श्रविध में चुकाने के पश्चात् पुनः उसी वर्ष बिना रिजर्व वेंक की श्रमुमित के नया श्रमुण नहीं लिया जा सकता था परन्तु श्रम किसी वर्ष की श्रमुमित के नया श्रमुण नहीं लिया जा सकता था परन्तु श्रम किसी वर्ष की श्रमुण की निर्घारित रकम के बराबर उपयोग में इस श्रमुमित की श्रावश्यकता नहीं रही है।

प्राप्य वैंक व्यवस्था जाँच समिति की सिफारिश पर रिजर्व वेंक ने विचीय सहायता देने के सम्बन्ध में सुविधाएँ बदार्यी और १ सितम्बर १६५१ से कमीशन में ५० प्रतिशत कभी कर दी है। जैसा ऊपर बताया गया है रिजर्व वेंक ने राष्ट्रीय कृषि सम्बन्धी साख कोष की स्थापना की है। इस कोष से राज्य सरकारों को दीर्घकालीन श्रुण दिया जायगा जिसकी सहायता से वे सहकारी साख संस्थाओं की शेयर पूँजी कय करने में योगदान दें। १६५६ में रिजर्व वेंक ने राष्ट्रीय कृषि साख

ख्रध्याय १८ कृषि नियोजन

भारत की प्रथम पद्मवर्षीय योजना ने कृषि नियोजन पर विशेष सहत्व दिया या। प्रथम योजना के अन्तर्गत २३५६ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से १५.१% (३५७ करोड़ रु०) कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं, तथा २८.१% (६६१ करोड़ रुपये) सिंचाई तथा विद्युत शक्ति योजनाओं पर व्यय के लिये निश्चित कर दिये गये थे। द्वितीय पद्मपवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि नियोजन का स्थान महत्वपूर्ण है, पर अधिक जोर औद्योगिक विकास पर दिया गया है। इस प्रकार प्रथम योजना में जो असंतुत्तित होने का दोष आ गया पा उसे दूर कर दिया गया है। दितीय योजना में विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में से कृषि तथा समुदायिक विकास योजनाओं को ११ ५% (६१३ करोड़ रुपये) मिले हैं।

प्रथम योजना में कृषि पर विशेष महत्व देने के सम्बन्ध में योजना श्रायोग ने दो तर्क दिये ये—(१) जो योजनाएँ पचितत हैं उनको पूर्य करने की आवश्य-कता है श्रीर (२) जब तक खाद्याज का श्रीर उद्योगों के लिये श्रावश्यक खनिज पदायों का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर लिया जाता श्रौद्योगिक विकास के कार्यक्रम में विशेष प्रगति ला सकना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि उद्योगों का विकास करने के लिये खनिज पदार्थी और खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। यदि यह सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाँय तो भारतीय उद्योग को विकसित करने में निश्चय ही सहायता मिल सकती है। इसके साथही मारत की अधिकाँश जनता कृषि कार्यं करती है। कृषि में सुधार करने से इनकी आय में वृद्धि होगी श्रीर परिगाम स्वरूप रहन सहन में सुधार होगा। परन्तु इतने पर भी योजना आयोग द्वारा कृषि की प्रधानता दिये जाने की कड़ी आलोचना की गई थी। भारत की आर्थिक व्यवस्था श्रमन्तुलित है, क्योंकि उद्योगों का विकास करने की पूर्ण सम्भावना होते हुये भी श्रव तक उद्योग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। इस तथ्य की श्रोर ध्यान न देकर निरन्तर इस बात पर महत्व दिया जा रहा है कि कृषि का विकास करने की विशेष श्रावश्यकता है। पंचवर्षीय योजना के पूर्ण हो जाने पर इस श्रसंतुलित व्यवस्था के दूर होने की सम्मावना नहीं है। वास्तव में

सम्भावना में इस वात की है कि योजना के परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था हद्तर हो नायगी। यदि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण करते समय उद्योगी पर श्रिधक ध्यान दिया गया होता तो इस होप के दूर हो सकने की श्राशा थी श्रीर भारत का श्रीर श्रिधिक सन्तुलित विकास हो सकता था। यदि योजना श्रायोग उद्योगों के विकास पर महत्व देता तो इससे कृषि के विकास की समुचित व्यवस्था करने में उसको किसी बाघा का सामना नहीं करना पड़ता। दृसरे, यह बिल्कुल सहीं है कि भविष्य में ग्रीबोगिक विकास करने के लिए हुंद्र श्राधार का निर्माण किया जाय परन्तु इस बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाय कि भारत की कृषि का पूर्ण विकास हो जाने के पश्चात् उद्योगों का इस स्तर तक विकास कर लिया जायगा कि उसमें उस समय उत्पादित कब्चे माल छौर विजली इत्यादि का पूर्ण उपभोग हो सकेगा। यह बहुत सम्भव है कि उस समय तक अन्य देशों के उद्योग आधिक शक्ति शाली हो जार्येंगे श्रीर भारतीय उद्योग के लिये नवीन समस्याएँ उत्पन्न कर दें। योजना श्रायोग उद्योगों का श्रीर श्रधिक विकास करने श्रीर भारतीय कृषि से उपलब्ध न हो चकने पर लाबाल तथा कच्चे माल का आयात करने की व्यवस्था कर चकता या जैसे जापान श्रीर विटेन ने किया। यदि उद्योग श्रीर कृषि दीनों का साथ साथ विकास किया जाय तो भारत का श्रार्थिक विकास श्रीर श्राधक सन्तु लित हो जायगा श्रीर उद्योग तथा कृषि के विकास का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव हो जायगा। योजना में कृपि पर आवश्यंकता से अधिक महत्व दिये जाने से कृषि तथा उद्योग के विकास में सन्तुलन स्थापित कर उनका सुनियोजित विकास करने में वाघा पहुँचेगी जब कि नियोजन का श्राघार ही सन्तुलित श्रौर कम बद्ध विकास करना है।

प्रथम योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वतीन्मुखी उन्नति का प्रवन्न किया गया था। उसके अन्तर्गत कृषि उत्पत्ति के श्रतिरिक्त पशु-सुधार, सहकारी श्रांदोलन का विकास, गन्यशाला, वन, भूमि संरच्या तथा पंचायतों के विकास श्रीर सुधार की योजनाएँ सम्मिलित थीं। भारत को केवल खादानों श्रीर उद्योगों के लिये कन्ने माल के उत्पादन में ही श्रात्म निर्भर बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, वरन ग्रामीया जनता के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने तथा प्रति न्यक्ति वार्षिक उत्पादन में भी वृद्धि करने का विचार किया गया था। प्रथम योजना में कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाशों पर न्यय किये जाने वाले ३५७ करोड़ रुपये में से १६७ करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी कार्य क्रमों पर, ६० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों पर तथा सामुदायिक योजना चेत्रों पर, २२ करोड़ रुपये पशु पालन पर, १५ करोड़ रुपये दायिक योजना चेत्रों पर, २२ करोड़ रुपया पशु पालन पर, १५ करोड़ रुपये

स्थानीय सुघार कार्यों पर, ११ करोड़ आम पंचायतों पर, १० करोड़ बनों पर, ४ करोड़ सहज़ी पकड़ने के कार्यों पर, ७ करोड़ सहकारिता पर और १ करोड़ रुपये अन्य बातों पर ब्यय करने के लिये नियत किये गये थे।

प्रथम योजना का सिंचाई सम्बन्धी तथा विद्युत शक्ति के विकास का कार्यक्रम बहुत ही विशद था। यह कार्यक्रम उन योजनाश्चों पर श्राधारित था जो योजना के पूर्व से ही प्रचलित थीं। योजना में हन योजनात्रों की श्रागे बढाने का प्रबन्ध किया गया था। परन्तु इनकी संख्या इतनी ऋधिक घी कि सम्पूर्ण योज-नाम्रों को एक साथ नहीं लिया जा सकता था। इसलिये यह निर्णय किया गया कि कीसी, कीयना, कृष्णा, चम्बल और रिइन्ड योजनाओं को योजना काल के श्रंतिम भाग में लिया जायगा। ६६१ करोड़ रुपयों के कुल न्यय में से ३८४ करोड़ सिंचाई के लिये, २६० करोड़ विद्युत योजना के लिये श्रीर १७ करोड़ बाह नियंत्रण तथा अन्य खोज कार्यों के लिये नियत किये गये। प्रथम योजना का लक्ष्य सींची जाने वाली भूमि का चेत्रफल ५१० लाख एकड़ से, जो कि १९५०-५१ में था, बढ़ा कर ६७० लाख एकड़ १६५५-५६ तक करने का और विद्युत शक्ति का उत्पादन २३ लाख किलोबाट से बढ़ाकर ३४ लाख किलोबाट कर देने का था। यदि इस विकास योजना को दीर्घ कालीन हिंदर से देखा जाय तो यह श्राशा की जा सकती यी कि २० वर्षों के अन्तर्गत ही ४०० लाख से लगाकर ४५० लाख एकड़ तक अतिरिक्त भूमि सिचाई के अंतर्गत आ जायगी और वर्तमान विद्युत शक्ति की मात्रा जो उत्पादित की जा रही है उसमें ७० लाख किलोबाट की श्रीर श्रधिक वृद्धि हो जायगी। यह कार्यक्रम का बड़ा ही श्रेष्ठ श्रादर्श है श्रीर यदि पूर्ण हो गया तो भारतीय श्राम्य श्रार्थिक व्यवस्था की रूप रेखा बदल जायगी।

प्रथम योजना में कृषि नियोजन की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं—(१) सम्पूर्ण कार्य केवल राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जायगा और उद्योगों के विपरीत निजी व्यवसाय का इसमें कुछ इाथ नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के कार्य में काफी दीई अविष के पश्चात् लाभ अजित किया जा सकता है और रुपयों के रूप में तुरन्त लाभांश प्राप्त नहीं होता। विगत वर्षों में निजी उद्योग इस प्रकार के कार्यों से पृथक रहा है। इसलिये स्वाभाविक ही योजना आयोग ने इस कार्य का संचालन करने के लिये निजी उद्योगों को उपयुक्त साधन नहीं समका। आयोग को निजी उद्योगों की कार्यस्मता पर विश्वास नहीं हो सका। योजना के अनुसार राज्य सरकार सिंचाई तथा विद्युत योजना कार्यों का प्रवन्ध करेंगी और केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य में उचित सम्बन्ध स्थापित करेगी तथा अन्य सामान्य सहायता देगी; (२) दीधकालीन योजनाओं पर

विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार की योजनाओं से होने वाले लाम का अनुभव १५ से २० वर्ष के पश्चात् किया जा सकेगा जब कि भारत की कृषि का पूर्ण विकास हो चुकेगा। यद्यपि दीर्घकालीन योजनाओं पर महत्व दिया गया है, किर भी अल्पकाल में खाद्याज तथा उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने की भी समुचित व्यवस्था की गई है। जैसा कि 'कृषि उत्पादन और नीति' शीर्षक अध्याय में बताया गया है, यह आशा की जाती है कि खाद्याज के सम्बन्ध में भारत को योजना की अवधि में ही स्वावलम्बी बनाया जा सकेगा और कपास तथा जूट के सम्बन्ध में मारत की विदेशों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा; (३) इस याजना का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि ही नहीं बिलक ग्राम्य-जीवन का वहमुखी विकास भी करना है।

दितीय योजना—प्रथम योजना का श्रमाव दितीय योजना में पूर्ण कर दिया गया श्रीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो कि न्यायपूर्ण श्रीर उचित था। इससे भारत के विकास की श्रसंदुलित श्रवस्था सुघर जायगी श्रीर राष्ट्रीय श्राय में श्रविक तीन गित से वृद्धि होगी श्रीर कार्य करने के श्रविक श्रवसर प्राप्त हो सकेंगे। दितीय योजना के श्रन्तर्गत ४८०० करोड़ रुपयों के विकास कार्य-क्रमों पर नियत व्यय में से १८५% उद्योगों श्रीर खान खोदने पर, २८५% संचार तथा यातायात पर, ११५% (५६८ करोड़ २०) कृषि तथा समुदायिक विकास पर, श्रीर १६% (६१३ करोड़ रुपये) सिंचाई तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन पर व्यय किया जायगा। यद्यपि द्वितीय योजना में उद्योगों श्रीर यातायात को श्रिषक महत्ता दी गई है पर कृषि तथा सिंचाई को छोड़ नहीं दिया गया है। द्वितीय योजना में किय नियोजन की मुख्य विचारणीय वार्ते निम्न हैं—

(श्र) कृषि सुघार सम्बन्धी कार्य-क्रमों से यह श्राशा की जाती है कि वढ़ी हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त खाद्य सामग्री तथा विकसित उद्योग व्यवस्था के लिये कद्या माल दे सकेंगे श्रीर इतनी कृषि उत्पत्ति वच रहेगी कि उसका निर्यात मो किया जा सकेगा। इसलिये यह कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना में प्रथम योजना की श्रपेका कृषि तथा श्रन्य उद्योगों के विकास कार्यक्रम में श्रिष्टिक पारस्य-रिक निर्भरता का श्रायोजन किया गया है। इन ध्येयों को प्राप्त करने के कार्यक्रमों को निर्माण करते समय दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखना श्रावश्यक है ताकि मौतिक साधनों श्रीर मानव अम का सर्वोत्तम प्रयोग, कृषि का सर्वतोन्मुखी संतुलित विकास, श्रीर ग्राम वास्यों की श्राय में तथा रहन-सहन के स्तर में पर्याप्त वृद्धि सम्भव हो सके। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण करने में यह श्रावश्यक है कि ग्राम के सन्मुख एक ऐसा श्रादर्श उपस्थित कर दिया

नाय जिसे प्राप्त करने में वे प्रयक्षशील हो सर्कें। द्वितीय योजना निर्माण के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यह श्रादर्श १० वर्ष के श्रन्तर्गत ही उत्पादन को जिसमें खाद्यान्न, तिलहन, कपास, गन्ना, पशु पालन से प्राप्त वस्तुएँ इत्यादि सम्मिलित होंगी दुगनी कर देगा।

- (ब) कृषि उत्पत्ति को भ्रनेक-रूपता प्रदान करना श्रीर खाद्यान सम्बन्धी फसलों को अब तक ना प्रधानता दो नाती थी उसे बदलना श्रादर्श होगा। दितीय योजना में ऐसी फसलों की वृद्धि भी है जैसे सुपाड़ी, नारियल, लाख, काली मिर्च, वृक्कफल इत्यादि जिनकी श्रोर प्रथम योजना में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था।
- (स) क्षांप के चेत्रफल की वृद्धि करने की सम्मावना तो बहुत सीमित है। जो थोड़ी बहुत वृद्धि कृषि के चेत्रफल में सम्मव होगी उससे मोटे श्रन्न के ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी। जैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होती चलेगी वैसे-वेसे मोटे श्रन्न की माँग गेहूँ श्रौर चावल की माँग में बदल ही जायगी। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पत्ति में वृद्धि का मुख्य स्रोत श्रिषक कुशल, लामदायक तथा धनी खेती ही होगा।

द्वितोय योजना के श्रन्तर्गत कृषि नियोजन की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं—(१) भूमि के प्रयोग का नियोजन; (२) दीर्घकालीन श्रीर श्रल्पकालीन लक्ष्यों का निश्चित करना; (३) उत्पादन लक्ष्यों तथा भूमि प्रयोग योजनाश्रों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देना; श्रीर (४) उपयुक्त मूल्य नीति का निर्धारण करना।

द्वितीय योजना में ५६८ करोड़ रुपयों के ज्यय में से १७० करोड़ रुपये कृषि कार्यक्रमों पर, २०० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं पर, ५६ करोड़ रुपये पशुपालन पर, ४७ करोड़ रुपये वनों और भूमि संरक्षण पर, १५ करोड़ रुपये स्थानीय विकास पर, १२ करोड़ रुपये पंचायतों पर, १२ करोड़ रुपये महाली पक्डने के ज्ययस्थाय पर, ४० करोड़ रुपये सहकारिता पर जिसके अन्तर्गत मायहागार तथा विकय सुविधायें भी सम्मिलित होंगी, और ६ करोड़ रुपये अन्य विविध बातों पर ज्यय किये जायेंगे। इस अकार प्रथम योजना की तलना में कृषि पर कुल ज्यय कम. हो गया है। स्थानीय विकास कार्यों तथा आम पंचायतों पर लगमग समान ही है और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा सामुदायिक योजनाओं, पशुपालन, वन तथा भूमि संरच्या और सहकारिता पर पर्याप्त मान्ना में वृद्धि हो गई है।

कठिनाइयाँ—भारत में कृषि नियोजन को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने में श्रानेक कठिनाइयाँ हैं योजना को सफल बनाने के लिये सर्व प्रथम कृषक का स्वेच्छा से सिक्षय सहयोग श्रावश्यक है, परन्तु भारतीय कृषक श्रिषकतर रुढ़िवादी है श्रीर प्रत्येक बात पर परम्परागत दृष्टिकोण से ही विचार करता है। वह इस बात के लिये प्रस्तुत नहीं कि परम्परा की रूढि छोड़कर कुछ नचीन प्रयोग किये और । श्रतीत में कृपकों की स्थिति में सुधार करने के लिये श्रनेक प्रयव किये गये परन्तु क्रपकों की उदासीनता के कारण उनमें से श्रधिकांश श्रमफल रहे। पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि कृषि के चेत्र में विकास कार्यक्रम की सफल बनाने के लिये थ्रांर निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये यह श्रावश्यक है कि जनता सहयोग दे। बिना जन-सहयोग के समाज फल्या की योजना सफल नहीं हो सकती। कृषि विकास कार्यक्रम उसी सीमा तक सफलता पूर्वक कार्यान्वित हो सकता है जहां तक जनता उत्साह श्रीर स्वेच्छा से उसके लिये कार्य करने को प्रस्तुत हो। क्रपकों का सिकय सहयोग प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि (१) विभिन्न उपायों से क्रुपकों को यह विश्वास दिलाया जाय कि योजना उपयुक्त है और इसके कार्यान्यित होने से उनका लाभ होना निश्चित है; (२) योजना लागू करके श्रीष्ट ही ऐने परिखाम निकाले जाने चाहियेँ जिनसे क्रपकों में विश्वात उत्पन्न हो श्रीर उन्हें प्रेरणा मिले श्रीर जिनको वह स्वयं श्रांखों से देख श्रीर परख सकें। यदि योजना का उद्देश्य दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो क्रपकों में योजना की निश्चित उपयोगिता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काँठन हो जायगा। मूल्य श्रधिक होने से, वेरीजगारी में वृद्धि से श्रीर व्यापक श्राधिक कठिनाइयों के कारण वड़ी योजनाश्रों को सफलता पूर्वक लागू करने में सरकार की समर्थता पर कुलकों में विश्वास घटता जा रहा है: श्रीर (३) जनता में याजना लागू करने के लिये उत्तरदायी पूर्ण श्रधिकारियों की ईमनादारी श्रीर क्तमवा पर विश्वास उत्पन्न किया जाये। यदि जनता प्रशासन के हर स्तर पर अष्टाचार देखे, उसे खब स्थानों पर कार्य में ग्रानावश्यक देरी तथा अक़ुशलता का समना करना पड़े शीर यदि उसे यह मालूम हो कि समाज का शोपण कर समाज की हानि से लाभ उठाने वाले हानिकारक तत्वों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जा रही है तो जनता को उत्ताहित कर उसका एकिय सहयोग माप्त कर सकना श्रत्यन्त कठिन हो जायगा।

कृपि नियोजन की सफलता अन्य योजनाओं की तरह सम्बन्धित आंध-कारियों की कार्यक्षमता और ईमानदारी पर निर्भर करती है। योजना आयोग ने बताया है कि कार्यक्रम की सफलता की गति प्रशासन संगठन, उनकी कार्य-कुलता और उसके द्वारा प्रेरित जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। प्रशासन को आज गत वधों की अपेद्धा अधिक बड़ी और जठिल समस्याओं का समना करना पड़ रहा है। यह समस्याएँ बड़ी और जठिल अवस्य हैं, परन्तु आज इनके महत्व में अतीत की अपेद्धा कहीं अधिक वृद्धि हो गई। योजना के कार्य का सफल अपूर्वक संचालन करने के लिये शिक्ति, कुशल श्रीर ईमानदार श्रिध-कारियों का ग्रमाव है। कार्य बहुत विशद है, परन्तु विभिन्न योजनाश्चों का कार्य सँमालने के लिये शिक्षित कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के अनेक जिला, राजस्व तथा अन्य अधिकारी हैं, जिनमें से कुछ बहुत कुशल और परिधमी हैं, परन्तु खेद है कि इन श्रिषकारी में से श्रानेक प्राचीन प्रधा के अनुकूल चलते हैं और कृपकों से अपने को काफी दूर रखते हैं। इन अधि-कारियों की दृष्टि में रचनात्मक कार्य की अपेक्षा कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने का श्रधिक महत्व है, इससे यह श्रधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के लिये उपमुक्त सिद्ध नहीं हो सकते । 'श्रधिक-श्रम उपनाश्रो' तथा श्रन्य श्रान्दोलनों के सम्बन्ध में अनेक ऐसी घटनायें प्रकाश में थाई है जिनसे पता चलता है कि श्रिधकारियों ने बीज, खाद तथा रुपया कृषकों तक पहुँचाने की श्रिपेक्षा केवल कागुज़ां में खाना पूर्ति की श्रीर रुपयों को स्वयं इड़प लिया। इससे योजना को चफल बनाने में छफलता नहीं मिल सकती श्रीर जनता का उस पर से विश्वास उठ जाता है। पंचवर्षीय यांजना में इस बात पर महत्व दिया गया है कि सर्वप्रथम प्रशासन में निष्ठा, कुशलता, बचत और सार्वजनिक सहयोग पाप्त करने की श्रावश्यकता है। यं।जना में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनेक सुकाव दिये गये है। इनकी पूर्ति में अवस्थ काफी समय लगेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न कायों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को छाँटने ग्रीर उनको उचित ट्रेनिंग देने के साथ ही पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित अधिकारियों की कार्यक्तमता, निष्ठा और ईमानदारी में सुधार करने के लिये अनेक चुमाल दिये गये हैं इनमें से कुछ सुमाल इस प्रकार है-(१) प्रशासन सम्बन्धी, राजनीतिक तथा ब्रान्य पदों पर कार्य करते वाले श्रधिकारियों पर मुख्यचार के शारोपों की जाँच करने के लिये उपयक्त रुयवस्था की जाय । यदि श्रपराघ स्पष्ट हो तो तथ्यों का पता लगाने श्रीर श्रपराध खिद करने के लिये तुरन्त जाँच की जाय। (२) वर्तमान कानून में ऐसे मामली के लिये व्यवस्था की गई है जिनमें सरकारी कर्मचारी श्राय के गैर कानूनी साधनों का उपभोग करता है श्रीर उन साघनों के सम्बन्ध में सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता। परन्तु वर्तमान कानून के श्रनुसार ऐसे मामलों की जाँच करने की व्यवस्था नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि श्रमुक सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार एकाएक धनवान कैसे हो गये। इसलिये कानून के इस अभाव को पूरा करने के लिये श्रध्ययन किया जाय श्रीर अपयुक्त कानून वनाया जाय। (३) ऐसे श्रधिकारी को जिसकी ईमानदारी पर सन्देह किया जाता है बड़े उत्तरदायित्व के पद पर नहीं नियुक्त करना चाहिये।

भारतीय ग्राम्य जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनसे कृषि नियोजन के कार्य में वाघा पहुँचती है। ग्रामों में श्रच्छी सहकों, सिंचाई तथा श्रन्य सुवि-घाओं का अभाव है। कुपकों के इन अभावों की शीघ पूर्त करने की आवश्य-कता है, परन्तु यदि इन कार्यों पर श्रिधिक ध्यान दिया जाय तो वहुमुखी न्यापक कार्यक्रम को लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो जायँगी। यदि दीर्धकालीन योजनात्रों पर श्रिधिक ध्यान दिया गया तो स्थिति में सुधार करने की शीघ फल-दायक योजनाएँ लागू करने की सम्भावना कम हो जायगी। यह सम्भव है कि दीर्घकालीन ग्रीर ग्रहाकालीन दोनों प्रकार की योजनात्रों पर ध्यान दिया जाय परन्तु इससे प्रगति की गति मन्द हो जाती है श्रीर कार्य तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता है। जमींदारी, जागीरदारी तथा इसी प्रकार की ग्रन्य प्रयाश्रों के उन्मूलन से अनेक नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। प्रामों से महाजनों श्रीर साहकारों के घीरे घीरे समाप्त हो जाने से नई कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। इससे एक खाई उत्पन्न हो गई है जिसको अभी तक नई व्यवस्था से पाटा नहीं जा सका है। भारतीय क्रयक एक दुष्चक में फंसा हुआ है। वह निर्धन है क्योंकि अच्छे प्रकार का बीज, श्रन्छे पशु-श्रीर खाद इत्यादि खरीदने के लिये उसके पास द्रन्य नहीं है, श्रीर जब तक वह धनी नहीं बन जाता तब तक वह इन वस्तुश्रों का क्रय कर सकने के साधन नहीं जुटा सकता है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि क्रपकों की ऋण लेने की ज्ञमता नहीं है। वह जमानत न रख सकने के कारण सहकारी वैंकों तथा ऋण नहीं देने वाली अन्य संस्थाओं से ऋण नहीं ले सकता है। श्रौर जब तक कुपकों को श्रार्थिक व्यवस्था अञ्छी नहीं हो जाती वह इन साधनों को नहीं जुटा सकता है। यही कारण है कि शताब्दियों से मारतीय कुषक निर्घनता श्रीर दुखों में फंसा हुश्रा है। कृषि नियोजन को सफल बनाने के लिये कृषकों की इन कठिनाइयों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

श्रध्याय १६

बड़े पैमाने के उद्योग

भारत में अनेक बड़े उद्योग हैं परन्तु श्रौद्योगिक चेत्र में अभी विटेन में १८वीं शताब्दी में हुई श्रौद्योगिक कान्ति के समान श्रौद्योगिक कान्ति यहाँ नहीं हुई है। भारत में प्रति ब्यक्ति श्रौद्योगिक उत्पादन की मात्रा बहुत कम है श्रीर इन उद्योगों में देश की जन संख्या का बहुत कम भाग लगा हुआ है। भारत के कारखानों में प्रदिदिन कार्य करने वाले श्रीमकों की श्रीसत संख्या १९३६ में १६ लाख यी जो बढ़कर श्रव २५ लाख हो गई है। देश की ३८ करोड़ जनसंख्या को देखते हुये यह बहुत कम है। देश में नवीन उद्योगों का विकास करने के लिये काफी बड़ा चेत्र खुला पड़ है श्रीर वर्तमान उद्योगों के उत्पादन में भी श्रिषक वृद्धि की जा सकती है।

दितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएँ यीं— (श्र) कुछ उद्योगों में जैसे स्ती कपड़ा श्रीर चीनी उद्योग में बहुत श्रिषक अमिक कार्य करते थे श्रीर ये उद्योग श्रावश्यकता से श्रिषक उत्पादन करते थे; (ब) इसके साथ ही बड़े रसायनिक, इंजीनियरिंग श्रीर इसी श्रेणी के श्रन्य उद्योग थे ही नहीं। युद्धोत्तर काल में कुछ सीमा तक इन दोषों को दूर कर दिया गया है। यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुश्रों के लिए मारत को श्रायात पर निर्भर करना पड़ता है फिर भी देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुश्रों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इन वस्तुश्रों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है श्रीर ऐसी सम्भावना है कि मिदिष्य में श्रपनी श्रावश्यकता की पूर्ति करने के लिये इनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा। श्राशा की जाती है कि भागतीय श्रीद्योगिक विकास में जो श्रभाव शेष है उनको पंचवर्षीय योजना के श्रीद्योगिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करके पूर्ण कर दिया जायेगा।

सूती कपड़ा उद्योग

भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका युद्ध के पश्चात् विशेष रूप से विकास हुआ है। विश्वयुद्ध के पश्चात् कपड़ों की मिलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। देश का विभाजन हो जाने से मिलों की संख्या १९४७ में ४२३ से गिरकर १९४८ में ४०८ रह गई यी परन्तु नवीन मिलों की स्थापना से और मचीन मिलों में मशीन इत्यादि बढ़ा देने से भारतीय

स्ती मिलों की उत्पादन शक्ति में काफी वृद्धि हो गई है। १६५१ में भारत में ४४५ मिलें यी जिनमें १ करोड़ १२ लाख ४० हजार तकुए (Spindles) श्रीर २,०१,४८४ कर्षे थे पर १६५७ के श्रन्तर्गत में ४६६ मिलें हो गई जिनमें १२६ लाख तकुए श्रीर २०६,१२६ कर्षे हो गये। कई नई मिलें स्थापित की जा रही हैं श्रीर श्राशा की जाती है कि इन मिलों द्वारा उत्पादन श्रारम्भ होने पर भारतीय स्ती मिलों की वास्तविक उत्पादन शक्ति में मुख्यतः कताई मिलों (spinnig mills) में, श्रीर वृद्धि हो जायगी।

कुछ मिलों में केवल सूत काता जाता है श्रीर श्रन्य में सूत की कताई श्रीर बुनाई दानों होती है। युद्ध के पश्चात् काल की योजना समिति ने श्रनुमान लगाया कि ग्रायिक दृष्टि से कताई-बुनाई दोनों कार्य करने वाली श्रनुकुलतम श्राकार की सुती मिल में २५ हजार तकुए श्रीर ६०० करघे होने चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश ग्राधिकांश मिलें जिनमें कताई बुनाई दोनों कार्य होते हैं ग्रीर जिनमें केवल कताई होती है श्रापिक दिण्ट से अनुकूलतम श्राकार की मिलें नहीं कही जा सकतीं। स्ती कपड़ा उद्योग की वांकंड्स पार्टी के अनुमान के अनुसार लगमग १५० मिलों में अनार्थिक हैं। इसके साथ ही अधिकांश मिलों में पुरानी और पिसी पिटी मशीनें हैं। बम्बई मिल-मालिक संघ के अनुमान के अनुसार बम्बई की मिलों में ६०% मशीनें २५ वर्ष से भी श्रधिक पुरानी है । सूर्वा कपड़ा उद्योग के सम्मुख सब से बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान मिलों को श्रायिक हिण्ट से उपयुक्त स्तर पर लाया जाय, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीनें लगाई जायं श्रीर उन्हें त्रावर्यक श्रौद्योगिक प्रसाधनों से सुसिन्जत किया जाय। दूसरी ध्यान देने योग्य वात यह है कि देश के श्रन्य भागों जैसे मद्रास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश श्रीर मध्य भारत में इस उद्योग का विकास हुआ परन्तु फिर भी यह उद्योग वम्बई में ही श्रधिक केन्द्रित है। कुल उद्योग में जितने तकुए श्रीर करघे उपयोग में लाये जाते हैं उनके ६० प्रतिशत केवल वम्बई में हैं। इंग्रेलिए मविष्य में विकास करते समय उद्योगों के स्थान-निर्धारण की समस्या पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। स्थानी करण की स्थिति में सुधार श्रावश्यक है।

ज्लादन की प्रवृत्तियाँ—१६४४ में स्ती कपड़े श्रीर १६४६ में स्त का उत्पादन श्रिषकतम, श्रूयांत कमशः ४८५२० लाख गज श्रीर १६८५० लाख पौरह था। यह उत्पादन १६५० में गिरकर ३६६५० लाख गज श्रीर ११७५० लाख पौरह हो गया। १६४६ ब्रीर १६५० में उत्पादन के गिरने के मुख्य तीन कारण ये—(१) १६४७ में देश का विभाजन हो जाने से कच्चे माल की कमी हो गई श्रीर पाकिस्तान तथा श्रन्य देशों से रुई का श्रायात करने में श्रनेक किनाइयाँ

उत्पन्न हो गई, (२) उद्योगों में श्रमिकों के सगड़े में वृद्धि हुई; श्रीर (३) विद्युत शिक्त पर्याप्त न होने के कारण बम्बई मिलों को दीं जाने वाली विद्युत कम कर दी गई। धीरे धीरे इन कठिनाइयों को दूर करके उत्पादन में वृद्धि होने लगी। स्ती कपड़ा उद्योग में श्रमिक तथा मालिकों के सम्बन्धों में सुधार हुश्रा, उत्पादन शिक्त में वृद्धि की गई श्रीर देश में कपास की उत्पत्ति में वृद्धि से कच्चे माल की पूर्ति में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप १६५१ में सूती कपड़े श्रीर सूत का उत्पादन कमश: ४०७६० लाख गज श्रीर १३०४० लाख पौराह श्रीर स्थान के कय पर से नियंत्रण के इटनाने के कारण, हुई श्रीर कपड़ों के यातायात के लिये मालगाड़ियों के मिलने तथा माँग की वृद्धि से उत्पादन में श्रीर श्रधिक वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप सूती कपड़ों श्रीर सूत का उत्पादन बढ़कर १६५७ में कमश: ५३१५० लाख गज श्रीर १७७६० लाख पौराह हो गया।

मारत की सूती मिलों में पहले मोटे कपढ़े का ही ऋषिकतर उत्पादन किया जाता या परन्तु प्रशुलक मगडल (टिरिफ नोर्ड) की सिफारिशों के अनुसार उत्तम प्रकार के कपढ़े का उत्पादन घटाने के लिए १६२५ से १६४० तक काफी घपया लगाकर अनेक टेकिनिकल युवार किये गये परन्तु उद्योग का पुनर्शक्षटन कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध के लिए सैनिक मांगों तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उद्योग को फिर मोटे तथा माध्यम वर्ग के कपड़े का उत्पादन करना पड़ा। इसमें कुछ और घपया लगाना पड़ा जिससे उद्योग पर काफी भार पड़ा। परन्तु इधर कुछ वर्षों से मोटे और अत्युत्तम प्रकार के कपड़े के स्थान पर मध्यम और उत्तम प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में दृष्टि की गई। यह एक वान्छनीय प्रवृत्ति है और इम यह आशा कर सकते हैं कि भविष्य में देश की मांग पूरी करने तथा निर्यात के लिए इस उद्योग को महीन और मध्यम अंगी के कपड़ों की उत्पाद बढ़ानी पड़ेगी।

कच्चा माल अपनी पूर्ण वास्तिविक उत्पादन शक्ति के बराबर उत्पादन करने के लिये भारतीय सूती का कपड़ा उद्योग को लगभग ५२ ५ लाख गाँठ कपास को श्रावश्यकता होती है। विभाजन होने से देश में कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पा-दन होता या। भारतीय मिलों को श्रावश्यकता पूरी करने के साथ ही विदेशों को भी कपास निर्यात किया जाता था जिससे उद्योग को कच्चे भाल के श्रभाव की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता या। देश विभाजने के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया। देश में कपास का उत्पादन गिर गया। १६४७-४८ में २२ लाख श्रीर १६४८-४६ में १८ लाख गांठों का उत्पादन किया जा सका। इससे उद्योग के सम्मुख कच्चे माल के श्रमाव का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। सामान्य स्थिति में कपास का श्रायात करके इस संकट को दूर किया जा सकता या परन्तु पाकिस्तान ने भारत को श्रावश्यकता के श्रनुसार कपास नहीं दिया। पाकिस्तान के श्रतिरिक्त श्रन्य देशों की कपास का भाव बहुत श्रिष्ठक या श्रीर भारतीय सती कपड़ा उद्योग के श्रनुकूल नहीं या। परन्तु १६५७-५८ में कपास का उत्पादन ५० लाख गांठें से कुछ ही कम या श्रीर इस प्रकार श्रंशतः कच्चे माल की कमी पूरी हो गई। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के श्रंतर्गत कपास के उत्पादन में श्रीर भी वृद्धि होने की सम्मावना है। इससे स्ती कपड़ा उद्योग के कच्चे माल की कठिनाई को बहुत कुछ दूर किया जा सकेगा।

निर्यात—१६४८-४६ के विपरीत १६५०-५१ में स्ती कपड़े और स्त के निर्यात में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। १६४८-४६ में ३४१० लाख गज कपड़ा और ७४ लाख पौरड स्त देश से वाहर मेजा गया। १६५०-५१ में १२६६५ लाख गज कपड़ा और ७४५ लाख पौरड स्त विदेश मेजा गया इस वृद्धि का कारण यह है कि भारतीय माल का मूल्य अपेक्षाकृत कम रहा और साथ ही विदेशी बाजार पर अधिकार जमाने के लिये भारतीय मिल मालिकों ने जीरदार प्रयक्ष किये।

परन्तु बाद में स्थिति फिर बदली श्रीर निर्यात की इसी स्तर पर स्थिर नहीं रखा जा सका। १६५२-५२ में निर्यात की मात्रा घटकर ४२३७ ५ लाख गज कपड़े श्रीर ६२' प्र लाख पौरह सूत तक पहुँच गई। इस कमी के कारण निम्न-लिखित हैं -(१) स्ती कपड़े श्रीर स्त के उत्पाद्न में कमी आजाने से अधिक माल का निर्यात नहीं किया जा सका और सरकार ने कपड़े-के निर्यात पर प्रति-बन्ध लगा दिये। (२) निर्यात कर लगाने से भारतीय सूती माल का मूल्य बढ़ गया। मारतीय एती उद्योग ने वरावर यह मांग की है कि निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिये सरकार निर्यात कर को समाप्त कर दे। (३) भारतीय माल को विदेशों नापान, ब्रिटेन श्रीर श्रन्य देशों की बढ़ती प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। भारतीय सूती मिलें सरकार की अनिश्चित नीति के कारण अपने निर्यात की मात्रा पूर्ण नहीं कर सकी छौर भारतीय माल की प्रकार, पैकिंग इत्यादि निर्यात की शती के अनुकूल नहीं हो सके। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी वाजार में मारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति गिरती चली गई। निर्यात के बढ़ाने के सम्बन्ध में श्रनेकी उपायों का श्रनुसरण किया गया जैसे निर्यात कर की दरों में कमी करना, निर्यात किये जाने वाले कपड़ों के बनाने में काम आने वाली विदेशी रुई पर लगाये गये श्रायात कर में छूट देना, १ मार्च १६५४ से श्रायात-कर की ही वंद कर देना श्रीर निर्यात पर नियंत्रण कम करना इत्यादि । इनके

5.5

परिणाम स्वरूप सूती कपड़ों का निर्यात बढ़ गया है। १९५६ व १९५७ में भारत ने कमशा ६८४० लाख गज तथा ८५४० लाख गज कपड़े का निर्यात किया। किन्तु विश्ववाजार में प्रति स्पर्धा बढ़ने तथा आयात करने वाले देशों में लगे प्रतिक्यों के कारण १९५८ में निर्यात घटकर ६५०० लाख गज रह जाने की संभावना है। मुख्य प्रकार के कपड़े जो भारत से निर्यात किये जाते हैं वे चादरें, कमीज और कोट के कपड़े, वायल तनजेब और छीट आदि हैं।

कर—केन्द्रीय सरकार स्ती कपड़े पर उत्पादन कर श्रीर निर्यात कर लगाती है। सितम्बर १६५६ में उत्पानकर में बहुत वृद्धिकर दी गई। इससे उत्पादन-लागत बढ़ गई। इसके श्रातिरिक्त राज्य सरकार स्ती कपड़े श्रीर स्त पर बिक्री कर खगाती हैं। इससे उत्पादन लागत में श्राधिक चृद्धि हो गई है।

१६५२ में केन्द्रीय सरकार ने इथकर्घा उद्योग अथवा बुनकरों की सहायता के लिये ६ करोड़ रुपये का कोष एकत्र करने के लिये मिल के बने सभी कपड़ों पर ३ पाई प्रति गज की दर से एक उप-कर लगा दिया। यह वास्तव में अपनी मकार का बिल्कुल नवीन उपाय था। इसके अनुसार यह पहले ही स्वीकार कर लिया गया है कि उद्योग को वहत श्रधिक लाम हो रहा है और वह इस नवीन कर का भार वहन कर सकने में समर्थ है। इन सभी प्रकार के करों से सूती मिल उद्योग को अपना उत्पादन व्यय कम करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस-स्थिति में सुधार करने के लिये यह ब्रावश्यक है कि कर कम किये जायँ श्रीर मशीनों की दूट फूट के लिए जिस दर से धनराशि दी जाती है उसके प्रति उदार नीति श्रपनाई जाय जिससे सूती मिल उद्योग पुरानी श्रौर द्वटी मशीनों के स्थान पर नवीन मशीनें लगा सकें ब्रौर कारखानों में ब्राधुनिक टैकनिकल सुविधाएँ प्रदान कर सकें। मशीनों की टूट फूट के लिये जो घनराशि निश्चित की गई है वह अपर्याप्त है। नवीन मशीनों को लगाने के लिये इस बात की ग्रत्यन्त ग्रावश्यकता है कि सरकार कम व्याज पर उद्योग को भ्रूण दे ग्रीर मशीनों की टूट फूट के लिये निश्चित धन के प्रति उदार नीति अपनाये । भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग में युक्तीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्त यह निम्न तीन वातों पर निमंद हैं; (१) आवश्यक धन की प्राप्ति, (२) आवश्यक मशीनों की प्राप्ति श्रीर (३) इस समस्या के प्रति अमिकों का विचार। फिर मी सरकारी कर नीति इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विचारणीय है क्योंकि वही युक्तिकरण के लिये त्रावश्यक धन प्राप्त करने का श्रोत है।

एकत्रित सामग्री का संकट-१९५७ के प्रारम्म से स्तीवस्त्र उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है। लगमग २६ मिलें, जिनमें से १६ उत्तर प्रदेश में हैं, वन्द होगई है तथा ३७ मिले केवल श्रंशतः कार्य कर रही हैं। श्रमेल १६५८ के श्रन्त में मिलों के पास विना विके कपड़े की एकत्रित सामग्री ५०५३०० गिठे तथा मार्च १६५८ के श्रन्त में बिना विके एत की एकत्रित सामग्री १११,८०० गाँठे थीं। श्रनेक मिलों को हानि उठानी पड़ी है तथा, मिलों के श्रनेक मजदूर वेकार हो गये हैं। इस संकट के मुख्य कारण निम्न हैं: (१) खाद्यान्त तथा जीवन की श्रन्य श्रावश्यकताश्रों के मूल्य श्राव्यधिक कँचे होने के कारण लोगों की क्रय शक्त घट गयी जिसके फल स्वरूप विकी कम होगई। साय ही १६५८ में निर्यात में भी कमी श्रागई। (२) कपड़े पर लगे उत्पादकर की कँची दर के फलस्वरूप उत्पादन-लागत वरावर कँची बनी हुई हैं। (३) उद्योग का मजदूरी-विल बहुत श्रावक है। लागत के घटने का कोई सहज उपाय भी नहीं दिखाई देता क्योंकि मशीनें घिसी पिटी तथा पुरानी हैं तथा उत्पादन के सुकीकरण में देर होती रहती है। उद्योग के बरबादी से बचाने के लिये यह श्रावश्यक है कि उत्पादन कर १६५५-५६ के स्वर पर कर दिया जाय तथा उत्पादन का युक्तीकरण किया जाय।

उद्योग के सम्मुल दो कठिनाइयाँ हैं। एक श्रोर उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया गया है तथा दूसरी श्रोर इयकर्षा उत्पादकों के हित में मिल उद्योग पर १ ली दिसम्बर १९५२ से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिनके श्रनुसार धोतियों के उत्पादन के १९५१-५२ के मासिक श्रीसत के ६०% पर मिलों का घोतियों का उत्पादन निश्चित किया गया है तथा साहियों का रंगना निषद्ध घोषित कर दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत—प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत स्ती कपड़ा उद्योग की उत्पादन शक्ति को १६५५-५६ तक ४७७=० लाख गंज कपड़े श्रीर १७२२० लाख पींड स्त तक बढ़ाने का श्रनुमान था श्रीर वास्तविक उत्पादन ४७००० लाख गंज कपड़े श्रीर १६४०० लाख पींड स्त का करने का था। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति को १५ गंज कपड़ा प्राप्त हो सकने का था। प्रथम योजना के श्रन्त तक वास्तविक उत्पादन श्रीर उत्पादन शक्ति दोनों ही लक्ष्य से श्रागे बढ़ गये।

दितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया है कि कुल कपड़े के उत्पादन की मात्रा (मिल और इथक में और शक्ति संचालित कमें से बने कपड़े मिलाकर) को ६८५ करोड़ गज से, जितना कि १९५५-५६ में या, १९६०-६१ तक ८५० करोड़ गज कर दिया जाय और सूत का उत्पादन १६३ करोड़ पींट से १९५ करोड़ पींट कर दिया जाय । इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति कपड़े का उपमोग १८ गज्ञ तक बढ़ा देने का है और लगमग १ अरब गज्ञ कपड़े का निर्यात करना है। द्वितीय योजना में कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में दो मुख्य दोष हैं—(१)
मिविष्य को कपड़े की माँग का कम श्रमुमान करना, क्योंकि बम्बई के मिल
मालिकों की एसोसियेशन के मतानुसार यह माँग ८५० करोड़ गज नहीं वरन्
१००० करोड़ गज होगी; श्रीर (२) मिलों के विस्तार पर इस विश्वास से प्रतिबन्ध
लगाना कि इससे हथकों के प्रयोग को सहायता मिलेगी। हथकर्षा उद्योग को
सहायता मिलों की उत्पत्ति को कार्वे कमेटी के श्रमुसार ५०० करोड़ गज तक
श्रपवा किसी श्रम्य मात्रा तक सीमित कर देने में नहीं मिलेगी।

जूट उद्योग

भारत में जूट की ११२ मिलें हैं जिनमें लगभग ७२,३६५ कर्षे चलते हैं। इनमें से ४५% कर्षे जूट के टाट श्रीर ५५% बोरे हत्यादि बनाने के लिये हैं। श्रातुमान लगाया गया है कि यदि उद्योग में केवल एक शिफ्ट से कार्य चलाया जाय श्रीर प्रति सप्ताह ४८ घंटे उत्पादन किया जाय तो प्रतिवर्ष १२ लाख टन उत्पादन किया जा सकता है। जूट उद्योग श्रिषकतर पश्चिमी बंगाल में केन्द्रित है। भारत की कुल रिजस्टर्ड ११२ जूट मिलों में से १०१ मिलों पश्चिमी बंगाल ही में स्थित है। श्रीष मिलों में से ४ श्रान्ध में, ३ बिहार में ३ उत्तर प्रदेश में श्रीर १ मध्य प्रदेश में हैं।

भारतीय जूट उद्योग श्रम्य सब उद्योगों से श्रिषक सुसंगठित है परन्तु दुर्भाग्यवश इसकी मशीन इत्यादि श्राधुनिक नहीं है श्रीर साथ ही यह मशीनें बनाये हुये माल की वर्तमान माँग के दृष्टिकोण से श्रिषक भी हैं। मारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि करने के लिये यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उसकी पुरानी मशीनों के स्थान पर श्राधुनिक मशीनें लगाई जाँय श्रीर इस प्रकार उत्यादन व्यय घटाया जाय। परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि उद्योग का श्रुकीकरण करने में ४० से ४५ करोड़ रुपये तक की पूँजी लगानी पड़ेगी श्रीर वर्तमान में उद्योग इतनी पूँजी लगा सकने की ज्ञमता नहीं रखता। "श्रामिनवीकरण (modernisation) के लिये राष्ट्रीय श्रीद्योगिक विकास निगम द्वारा श्रुण दिये जा रहे हैं। मार्च १६५८ के श्रन्त तक ६ मिल कम्पनियों के लिये श्र्यण स्वीकृत हो चुके हैं जिनमें से ७ को १.१६ करोड़ रु० दिया भी जा चुका है। वर्तमान स्थित यह है कि ८२ जूट मिल कम्पनियों में से ४४ ने ३० सितम्बर १६५७ तक कराई सम्बन्धी श्राधुनिक मशीनों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णतः तथा कुछ ने श्रेशतः श्रमिनवीकरण कर लिया था। पुराने तकुश्रों में से ४% के स्थान पर नये तकुये लगाये जा चुके तथा लगाये जा रहे हैं।

चत्पाद्न की प्रवृत्ति-जूट उद्योग में उत्पादन १६४५-४६ में उत्तरतर तक पहुँच चुका था जबकि ११ ४ लाख टन माल का उत्पादन किया गया। इसके पश्चात् १६४६ तक उत्पादन दस लाख टन प्रतिवर्ष के क्षगमग रहा। परन्तु १६४६-५० में उत्पादन ८६ लाख टन तक गिर गया । इसके पश्चात् उत्पादन में कुछ सुधार श्रवश्य हुआ। परन्तु फिर भी उत्पादन पूर्व स्तर तक नहीं पहुंच पाया । १९५४-५५ में उत्पादन वढ़ कर १०, ४३,४०० टन हो गया था। उत्पादन में कमी का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी थी क्योंकि देश का विभावन हो जाने के पश्चात् जूट का उत्पादन करने वाले अधिकांश चेत्र पाकिस्तान में चले गये। इस श्रमाव को पूरा करने के लिये देश में ही जूट उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया। तब से देश में जूट के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जूट के माल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जूट उद्योग में प्रति सप्ताह केवल १२ दे घन्टे उत्पादन कार्य हो रहा या श्रीर उद्योग के कुल कर्षे के १२ दे प्रतिशत बन्द पढ़े हुये थे। परन्तु अवदूवर १९५४ से ४८ घन्टे प्रति सप्ताह कार्य आरम्म हो गया और १९५६ के मार्च तक बन्द कर्षों में से ७३ प्रतिशत चालू हो गये थे। १९५६-५७ में उत्पादन १,०२५,२०० टन था तथा आशा की जाती है कि १६५७-५८ में भी लगभग इतना ही होगा।

कुच्चा माल-उद्योग की इस समय सबसे बड़ी कठिनाई कच्चे माल की कमी है। यद एव मिलें शक्ति मर कार्य करें तो मारतीय जूट उद्योग के लिये प्रतिवर्षे पटछन की ७५ लाख गाँठों की आवश्यकता है। परन्तु भारत में १६४७-४८ में १५ लाख गाँठों से कुछ अधिक, १९४८-४६ में २० लाख गाँठ, १९४६-५० में ३० लाख गाँठ श्रीर १९५०-५१ में ३३ लाख गाँठ से कुछ श्रधिक का उत्पादन किया गया । भारत चरकार ने पाकिस्तान चरकार से सममौता कर पटसन के श्रायात की न्यवस्था की, परन्तु श्रायात का यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पाकिस्तान से बहुत थोड़ी सात्रा में जूट का भ्रायांत किया गया। फलस्वरूप भारतीय जूट उद्योग के कच्चे माल की श्रावश्यकता पूर्ण नहीं की जा सकी। इघर हाल के वर्षों में भारत में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ गया है। १९५६-५७ में इसका उत्पादन ४२'५ लाख गाँठे थी। १९५७-५८ में इससे घट-कर ४० लाख गाँठे (४०० पौ० की एक गाँठ) रह जाने की आवश्यकता है। कच्चे ज्रूट के विषय में ब्रात्मिन भरता पाप्त करने के लिये किये जाने वाले गहन प्रयत्नों के संदर्भ में १६५७-५८ में उत्पादन की यह कमी शोचनीय विषय है। द्वितीय योजना के अन्त तक भारत को पाकिस्तान से जूट मंगाना ही पढ़ेगा। किन्तु उन पर हमारी निर्मरता बहुत कुछ कम हो जायगी ख्रीर यह सम्मव हो

सकेगा कि भारत में जूट उद्योग पाकिस्तान से जूट विना पाये भी संतोधपद ढंग में चले।

निर्यात—भारतीय जूट उद्योग श्रिधिकतर श्रापने माल के निर्यात पर निर्भर करता है। १६४-४६ में भारत में ११ लाख टन उत्पादित माल में से ६३०,००० टन माल का विदेशों को निर्यात कर दिया गया। यद्यपि निर्यात की मात्रा पूर्व की श्रपेत्ता घटकर १६५६-५७ में ८५६००० टन हो गई है किर भी यह कुल उत्पादन का बहुत बड़ा भाग है भारतीय जूट के टाट के दो बड़े बाजार यूनाइटेड स्टेटस तथा यू० के० हैं।

मारतीय जूट के टाट के दो बड़े बाजार यूनाइटेड स्टेटस तथा यू० के० हैं।

१६५६-५७ में इन देशों को गये निर्यात में क्रमशः ५% श्रीर ५०% की कमी हुई।
यद्यिष यूनाइटेड स्टेट्स को किये जाने वाले निर्यात की कमी से ऐसा प्रतीत होता

है कि उत्तरी श्रमेरिका में ज्यापारियों ने टाट सामग्री कुछ कम कर दी थी; किन्तु
यह पूर्ण सत्य नहीं है। श्रधिक महत्व की वात तो यह है कि १६५६-५७ में टाट के
अपमोग में (यू० एस० में) १२% को कमी हुई। उपमोग की यह कमी यैंले बनाने
के लिये टाट का प्रयोग कम करने के कारण हुई। सन्तोष का विषय है कि
श्रीद्योगिक तथा श्रन्य उद्देश्यों के लिये जूट का प्रयोग बढ़ता रहा। यू० के० में
कूट के उपमोग में हुई मारी कमी वहाँ पर लागू जूट-नियन्त्रण के कारण हुई।

जूट से बनने वाले येलों से यह लाभ होता है कि यह अपेज्ञाञ्चत सस्ते होते हैं श्रीर हनका श्रनेक बार उपयोग किया जा सकता है जब कि पैकिंग के लिये कागज के येलों तथा श्रन्य हती प्रकार की वस्तुश्रों का केवल एक ही बार अयोग किया जा सकता है। परन्तु जूट के येलों के स्थान पर कागज तथा श्रन्य प्रकार की वस्तुश्रों के प्रयोग से जूट के माल की माँग काफ़ी गिर गई है श्रीर यह जूट उद्योग के लिये चिन्ता का कारण बन चुकी है। फिर भी यदिः उचित प्रयत्न किये जाँय तो श्रन्य वस्तुश्रों की श्रपेज्ञा जूट का माल श्रपने लिये श्रावश्यक स्थान बना सकता है। परन्तु इसके लिए यह श्रावश्यक है कि भारतीय जूट प्रयोग का उत्पादन व्यय घटाया जाय, उत्पादन वहाया जाय श्रीर उत्पादत माल की प्रकार में स्थार किया जाय।

भारत सरकार ने जूट के माल पर बहुत श्रिषक निर्यात कर लगाया जिस से कि माल के भारतीय तथा विदेशी मूल्य का श्रम्तर सरकारी खजाने में जमा हो जाय। यदि यह कर न लगाये गये होते तो उद्योग श्रपने श्राधुनिकीकरण तथा पुरानी घिछी पिटी मशीनों के बदले नई मशीनें लगाने के लिये पर्याप्त सुरक्षित कोष का संग्रह कर सकता था। तिर्यातकर से बहुत हानि उठानी पड़ रही थी। कोरिया युद्ध के कारण हुई मंहगी के काल में जूट के बने कपड़ों पर तो यह कर १५०० ६० प्रति टन श्रीर बोरों पर ३५० ६० प्रति टन तक बढ़ गया था। श्रगस्त १६५५ में पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर घटने पर यह कर हटा लिया गया। हटाते समय टाट पर यह कर १२० ६० प्रति टन श्रीर बोरों पर ६० ६० प्रति टन था। निर्यात कर के हटा देने का परिणाम यह हुआ कि मूल्यों में कमी हो गई श्रीर निर्यात बढ़ गया तथा घरेलू माँग मी बढ़ गई।

जूट जाँच आयोग-जूट जाँच श्रायोग ने जिसके ग्रध्यज्ञ के श्रार• पीo श्रायंगर ये श्रपनी १६५४ में प्रकाशित रिपोर्ट में यह पाया कि ७५% मिलें लगमग १२ मैनेनिंग एजेन्सियों के हाथ में थी, निनमें से चार के अन्तरर्गत ४५% कर्षे थे। मैंनेजिंग एजेन्टों के हाथ में सारे व्यवसाय के केन्द्रित होने और जुट़ उद्योग के भूतकाल में कँची दर पर आय पाष्ठ करने के कारण इन मैनेजिंग एजेन्सियों के शेयर बहुत ही आकर्षक हो गए ये और उनके खरीदारों की संख्या बढ़ गई थी। चँ कि जूट उद्योग के वर्तमान स्थंत्र की उत्पादन शक्ति वर्तमान श्रौर मविष्य की सम्मावित माँग से कहीं अधिक है इसलिये आयोग ने और नई मिलों की स्यापना को पसन्द नहीं किया । उसने मिलों को अपने सयंत्रों को आधुनिक वनाने की विफारिश की। इन्डियन जूट मिल एसोविएशन की यह योजना होते हुए मी, चुँकि इसका परिणाम विनाशकारी प्रतिद्वन्द्विता श्रीर उद्योग की श्रव्यवस्था होगी, श्रायोग ने यह िफारिश की कि काम के घन्टों के सम्बन्य में जो समकीता हुआ है जिसके श्रनुसार सप्ताइ के श्रन्दर कार्य के घन्टे सीमित कर दिये गये हैं श्रीर मशीनों को श्रंशतः चालू करना बन्द कर दिया गया है उसे श्रागे लागू नहीं रखना चाहिये। इस सममीते के अनुसार अकुशल मिलें भी चलती रही हैं श्रीर कुशल मिलों को श्रपना उत्पादन न्यय कम करने में वाचा पहुँची है। इससे पाकिस्तान तथा श्रन्य विदेशी मिलों को लाम पहुँचा है। त्रायोग की यह लिफारिश सर्वया युक्तिसंगत है श्रीर इससे श्राशा की जाती है कि कुशल मिलें श्रिवक श्र-छा कार्य कर चर्नेगी। श्रायोग ने सिफारिश की है कि भारत को कच्चे जूट की पूर्ति के लिये निरमेझ के बजाय सापेश्विक श्रात्मनिर्भरता का लक्ष्य सामने रखना चाहिये। हमें पाकिस्तान से उस प्रकार का जुट आयात करना चाहिये जिसका उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता श्रीर श्रन्य प्रकार के जूट की स्वयं उत्पादित करना चाहिये। जूट की विस्तृत खेती के बजाय गहन खेती तथा किस्म के सुधार पर श्रधिक जोर देना चाहिये।

श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि नियमित वाजारों में नियमों का लागू करना, सहकारी समितियों की व्यवस्था करना, तथा श्रन्य सिफारिशों को कार्या-न्वित करना दीर्धकालीन दृष्टि कोण से उत्पादकों के लिए श्रिविक लाभकारी सिद्ध होगा। मूल्य नियम्त्रण के उपायों के प्रयोग को श्रस्वीकार करते हुए भी निर्यात बढ़ाने के लिए तथा घरेलू माँग बढ़ाने के लिये श्रायोग ने मूल्य स्थिर रखने का प्रयत्न करने की सलाह दी।

योजना के अन्तर्गत—जूट उद्योग के सम्बन्ध में समस्या उत्पादन शक्ति बढ़ाने की नहीं है क्योंकि बाखार की माँग की तुलना में तो भारतीय जूट मिलों के साधन आवश्यकता से कहीं अधिक हैं। वास्तविक समस्या तो कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाने और उद्योग को उत्पादन में अपनी वर्तमान शक्ति के अनुक्ल वृद्धि करने की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसीलिये औद्योगिक प्रसाधनों की वृद्धि के बजाय उत्पादन में वृद्धि करने की सिफारिश की गई थी।

जूट उद्योग की (rated) प्रत्यंकित उत्पादन शक्ति १२ लाख टन थी परन्तु कच्चे माल के अभाव के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है। प्रथम योजना में जूट के उत्पादन को ५१ लाख गाँठों तक ग्रीर जूट के बने माल का सम्पूर्ण प्रत्यक्वित शक्ति भर अर्थात् १२ लाख टन तक बढ़ाने का प्रवन्य किया गया था, जिसमें से १० लाख टन विदेशों को मेज दिया जायगा। परन्तु ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

द्वितीय योजना में भी जूट मिलों की प्रत्यंकित शक्ति बढ़ाने की सिफारिश नहीं की गई है। केवल आसाम में १३ करोड़ रुपयों के व्यय से एक मिल खोलने का प्रस्ताव है। प्रयत्न यह होगा कि जूट के बने माल की १६५५-५६ की १,०४,००० टन की उत्पत्ति को बढ़ाकर १६६०-६१ में १,१००,००० कर दिया जाय। जूट का उत्पादन ४० लाख गाँठों से जो कि १६५५-५६ में था बढ़ा कर १६६०-६१ में ५० लाख गाँठ कर दिया जाय। इस प्रकार भारतीय मिलों को आयात किये हुये जूट पर मविष्य में कुछ काल तक निर्मर रहना ही पड़ेगा।

चीनी उद्योग

निराक्रम्य (Tariff) संरक्षण तथा सरकारी नियोजन के फलस्वरूप भारत में चीनी की मिलों की संख्या १६३१-३२ में ३२ से बढ़कर १६५५-५६ में १६० हो गई। इनमें से १३६ तो १६५४-५५ में उत्पादन कार्य कर रही थीं श्रीर उन्होंने १६ लाख टन से कुछ ही कम चीनी का उत्पादन किया। १६५५-५६ में १३७ मिलों उत्पादन कार्य कर रही थीं श्रीर उन्होंने १७ लाख टन चीनी का उत्पादन किया। १६४८ में सरकार ने चीनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने का निश्चय किया श्रीर नवीन मिलों की स्थापना की स्वीकृत दी। ५५ नई फैक्टरियों, जिनमें ३८ सहकारी इकाइयाँ भी सम्मिलत हैं, की स्थापना तथा वर्तमान ६६ मिलों की उत्पादनशक्ति के विस्तार के लिये श्रनुशा पत्र (लाइसेन्स) दे दिये गये हैं। लाइसेन्स दी हुई उत्पादन इकाइयों में चार ने १६५५-५६ में उत्पादन प्रारम्म किया तथा पाँच ने १६५६-५७ में। १६५७ के अन्त में प्रत्यं कित उत्पादन शक्ति २,०१०,००० टन यी। १६५७-५८ में नी और इकाइयों ने भी उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इसके परिण्यम स्वरूप फैक्ट्री निर्मित चीनी की उत्पत्ति १६५६-५७ के २०३ लाख टन से बहकर १६५७-५८ में २१३ लाख टन होने की सम्भावना है।

चीनी उद्योग के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—(१) चीनी उद्योग विशेषकर उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में केन्द्रित है परन्तु देश के श्रन्य भाग जैसे वम्बई, मद्रास, मैस्र श्रीर हैदरावाद श्रादि भी चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि यहाँ गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन श्रिषक है श्रीर गन्ना पेरने का कार्य भी वहाँ श्रपेज्ञाङ्कत श्रिषक समय तक किया जा सकता है। (२) प्रचलित कारखानों ने कभी भी श्रपनी पूर्ण शक्ति से उत्पादन नहीं किया। इनमें से कुछ तो विल्कुल वन्द रहे जिसके फलस्वरूप उत्पादन सदा वास्तविक उत्पादन शक्ति से कम रहा। (३) चीनी उद्योग में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो श्रमुक्लतम शक्ति से नीचे हैं। एक श्रीसत कारखाने को श्रपनी पूर्ण उत्पादन शक्ति का लाभ उटाने के लिये प्रतिदिन ८०० टन गन्ना पेरना चाहिये परन्तु श्रमुमान लगाया गया है कि लगभग ८० कारखाने इस स्तर से नीचे हैं। इससे भारत में चीनी का उत्पदान व्यय श्रिषक होता है श्रीर श्रार्थिक हिंद से श्रमुपयुक्त कारखानों का लाम भी कम हो जाता है।

उत्पादन की प्रवृत्तियाँ—भारत में चीनी के उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव श्राता रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीनी का उत्पादन गन्ने की पूर्ति की मात्रा, गन्ना पेरने की श्रविध श्रीर गन्ने से प्राप्त चीनी के प्रतिशत पर निर्भर करता है। चीनी का उत्पादन, १९४८-४६ में १० ०६ लाख टन या जो गिरकर १९४६-५० में ६ ०६ लाख टन हो गया क्योंकि (श्र) १९४७-४८ में मिलों के लिये गन्ने का मान २ कण्ये प्रतिमन से घटाकर १९४८-४६ में उत्तर प्रदेश में १ कपया १० श्राना प्रति मन श्रीर विहार में १ कपया १३ श्राना प्रतिमन कर दिया गया। गन्ने का मूल्य घटाने का उद्देश्य चीनी का मान ३५ कपया ७ श्राना प्रतिमन से घटाकर २८ कपना ८ श्राना प्रतिमन करना या। गन्ने के मान में इस कमी से १९४६-५० में कारखानों के लिये गन्ने की पूर्ति में कमी हो गई श्रीर परिणाम स्वरूप उत्पादन भी गिर गया; (व) गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा १९४८-४६ में ६ ६७ से गिरकर १९४६-५० में ६ ९८६ हो गई श्रीर गन्ना पेरने की श्रीसत श्रविध भी १०१ दिन से घटकर ६१ दिन तक श्रागई। इस कारण चीनी के उत्पादन में कमी हुई जनकि कारखानों की संख्या १३४ से बढ़कर १३६ होगई थी।

परन्तु क्रमशः स्थिति बदंली श्रीर उत्पादन बहकर १६५०-५१ में ११'०१ लाख टन श्रीर १६५१-५२ में १४ दर लाख टन हो गया। १६५०-५१ श्रीर १६५१-५२ में चीनी का अधिक उत्पादन होने के तीन मुख्य कारण हैं, (१) मिलों को खुले चाजार में चीनी वैचने की छूट दे दी गई। इसके श्रनुसार कारखानों को १६४=-४६ या १६४६-४० में से जिस वर्ष का उत्पादन कम हो उसके १०७ प्रतिशत से श्रधिक उत्पादित चीनी को खुले बाजार में उस समय के भाव के अनुसार विकय करने की अनुमित दे दी गई। इसके पूर्व कारलानों को श्रपना सम्पूर्ण उत्पादन नियन्त्रित भाव पर वेचना पहता था जिससे उन्हें श्रिधिक लाभ नहीं हो पाता था। इस कारण उत्पादन वृद्धि की श्रोर उनकी प्रवृत्ति नहीं रही। खुत्ते बाजार में श्रतिरिक्त चीनी का विकय करने की छूट देने के फलस्वरूप कारखाने श्रधिक उत्पादन का लाम उठा एकते थे इएलिए स्वामाविक ही उत्पादन में वृद्धि हुई, (२) चीनी के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की गई परन्तु गनने का भाव १९४८-४९ के स्तर पर ही रहा। कारखाने से बाहर चीनी का नियन्त्रित भाव २८ रुपया ८ म्राना स्थिर रखा गया परन्तु पहले यह डी॰ २४ नम्बर की चीनी का मांव था त्रीर त्रव ई० २७ नम्बर की चीनी इस भाव से विक्रय होने लगी। चूँकि ई० २७ नम्बर की चीनी डी० २४ नम्बर की चीनी से घटिया प्रकार की है इसिलिए यह कहना अनुचित न होगा कि कारखानों ने गत वर्षों की अपेद्धा चीनी का श्रधिक मूल्य वसूल किया। उत्तर प्रदेश में १६५७-५१ में गन्ने का मार्च २ श्रा॰ प्रतिमने बढ़ाकर १ वपया १२ श्राना प्रतिमन निश्चित किया गया। कारलाने के बाहर ई० २७ नम्बर की चीनी का भाव बढ़ाकर २६ क्पया १२ आ० प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसका मिल मालिको पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि एक मन चीनी का उत्पादन करने में १० मन गन्ना लगता है श्रीर इस त्राधार पर उत्पादन व्यव १ रुपया ४ ग्राना प्रतिमन बढ़ा श्रीर मूल्य भी इतना ही बढा: (३) गन्ना पेरने की अवधि में भी वृद्धि की गई। १६४६-५० में गन्ना पेरंने की श्रवधि ६१ दिन थी जो १६५०-५१ में बहुकर १०१ श्रीर १६५१-५२ में १३३ दिन हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा १० ०३ से घटकर ६ ५५७ हो गई परन्तु कारखानों को श्रिधिक समय तक चाल रखने के कारण चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई।

चीनी की उत्पत्ति १६५२-५३ में गिरकर १३ १४ लाख टन और १६५३-५४ में १०'०१ लाख टन हो गई। इसके कारण निम्न हैं, (१) उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों की संख्या जो कि १६५१-५२ में १३६ थी १६५२-५३ और १६५३-५४ में घटकर १३४ हो गई और कार्य करने के दिनों की औसत संख्या १३३ से घटकर क्रमशः ११३ छौर ८६ हो गई; (२) १६५२-५३ में कारखानों में पिछला वचा हुआ माल अधिक मात्रा में या और अनेकों मिलें समय से कार्यारम्भ भी न कर सकीं जिसके फलस्वरूप जितना उत्पादन करने की उनमें शक्ति थी उतना भी उत्पादन न हो सका; (३) बहुत सी मिलों में यंत्रादि घिसे पिटे श्रीर प्राचीन ढंग के थे जिनके कारण उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग होना सम्भव नहीं या; श्रीर (४) श्रवैध सम से शराव खींचने के कार्य में लाने के लिए वढ़ी हुई गुड़ की मांग को पूर्ण करने के लिये कुछ गन्ने का प्रयोग गुड़ बनाने में कर लिया गया। १६५२-५३ की फसल के लिए गन्ने का मूल्य घटाकर १ ६० ५ श्राना प्रति मन श्रीर चीनी का नियंत्रित मूल्य २७ ६० प्रतिमन कर दिया गया। गनने का प्रतिमन मुल्य इतना कम हो जाने से कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना ही न मिल सका। १९५३-५४, १९५४-५५ श्रीर १९५५-५६ की फसलों के लिये मारत की सरकार ने गन्ने का मूल्य १ रु० ७ स्रा० प्रतिमन कर दिया। इस समय चीनी के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं हैं, केवल यह प्रतिवन्ध है कि फसल की उत्पत्ति का २५% 'सुरिच्चत माल' सममा जाय जिसमें से सरकार चीनी पिछले नियंत्रित मूल्य पर श्रर्यात् २७ व० प्रतिमन पर वेचती है। कृपकों के दृष्टिकोण से गन्ने का १ व० ७ श्राना प्रति मन मूल्य श्रपर्याप्त है श्रौर इसी कारण फैक्ट्रियों को पर्याप्त मात्रा में कचा माल मिलने में कठिनाई पहती है।

१६५६-५७ में चीनो की उत्पत्ति २०० लाख टन थी। १६५७-५८ में इससे बढ़कर २१३ लाख टन होने की सम्भावना है। इसका कारण वर्तमान फैक्ट्रियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि तथा नई फैक्ट्रियों की स्थापना है।

उत्पादन चमता—चीनी उद्योग की मुख्य समस्या उत्पादन व्यय की अधिकता है। उत्पादन व्यय अधिक होने से उपमोक्ता पर अनावश्यक मार पहता है और अन्य देशों की अपेन्ना मारतीय चीनी का मूल्य अधिक होने के कारण निर्यात की मात्रा मी नहीं वढ़ पाती। मारतीय चीनी का उत्पादन व्यय अधिक होने के अनेक कारण हैं। इसको कम करके चीनी का मूल्य घटाने के लिये काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। चीनी-उद्योग के सम्बन्ध में प्रयम किंटनाई यह है कि कुषकों के हितों की रत्ना के लिये सरकार गन्ने का मूल्य अधिक निश्चित करती है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार उद्योग पर अनेक कर लगाती हैं। गन्ने का अधिक मूल्य, अधिक मजदूरी और अधिक कर का फल यह होता है कि चीनी का उत्पादन व्यय कम होने की अपेन्ना बढ़ता जाता है। चीनी के मूल्य को घटाने के लिये यह आवश्यक होगा कि गन्ने के मूल्य को घटाया जाय। चीनी उद्योग की जींच करने वाले प्रशुक्क मगढ़ल ने मुमाव दिया था कि

१६४६-५० में गनने के मूल्य में ३ श्राना प्रतिमन कमी की जाय, १६५०-५१ में भी इतनी कमी श्रीर की जाय जिससे मान १ क्याय ४ श्राना प्रतिमन तक श्रा जाय। यदि सुक्ताव को लागू किया जाता तो इससे प्रतिमन चीनी में गनने का मूल्य ३ क्या १२ श्राना कम हो जाता। यदि प्रशुल्क मण्डल के सुक्ताव के श्रनु-सार माल तैयार करने की मद में भी २ क्या द्र श्राना की कमी कर दी जाती तो इससे १६५०-५१ में चीनी का भाव २२ क्या ४ श्राना प्रतिमन हो जाता। यह खेद की बात है कि सरकार ने प्रशुल्क मण्डल के सुक्तावों के श्रनुसार कार्य नहीं किया श्रीर गनने का माव घटाने के बजाय बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप चीनी के मूल्य में श्रीर वृद्धि हो गई। १६५२-५३ में गनने का मूल्य उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में घटाकर १ क्या ५ श्राना प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसके पक्षात् मारत सरकार द्वारा फिर से बढ़ाकर १ क्या ७ श्राना प्रतिमन कर दिया गया।

गन्ने की उत्पत्ति—गन्ने के मूल्य की उमस्या उन्तोषजनक दक्क से तमी सुलक्ताई जा उकती है जबिक प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति में वृद्धि की जाय। भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति में वृद्धि की जाय। भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति छंछार भर में उब से कम है और निरन्तर कम होती जा रही है। क्यूबा में प्रति एकड़ उत्पत्ति १७°१२ टन, मारिश्य में १६-६३ टन, श्रास्ट्रेलिया में २१°३४ टन, प्युरटोरीको में २४°१६ टन, जावा में ५६ टन, और हवाई में ६२°०५ टन है जब कि भारत में केवल १४ टन है। गन्ने के प्रत्यादान की प्रतिशत क्यूबा में १२°२५, मारिश्य में १२°०८, श्रास्ट्रेलिया में १४°३३, प्युरटोरीको में १२°२३, जावा में ११°४६ और हवाई में १०°४६ है श्रीर भारत में १०% है। कुषक को तो भूमि से श्रपनी खाधारण श्राय चाहिये श्रीर यदि गन्ने का मूल्य घटा दिया जाय श्रीर यदि गन्ने से प्राप्त प्रति एकड़ श्राय वढ़ जाय तो कुषक के लिये चिन्ता की कोई बात न होगी।

वर्तमान समय में चीनी तैयार करने के लिये कुछ कारलाने सल्फीटेशन प्रोसेस श्रीर कुछ कारलोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। दोनों ही प्रकार के विधायन में गन्थक का उपयोग होता है जिससे चीनी के कारखानों का व्यय बहुता है क्योंकि गन्धक का भारत बहुत श्रिषक मूल्य पर श्रायात करता हैं। कारबोनेशन प्रोसेस में ०'०२%से०'०३५%तक गन्धक लगता है श्रीर सल्फीटेशन प्रोसेस में इसकी मात्रा ०'०५%से ०'०=%तक है। इसलिये इन दोनों में से कारबोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करना श्रावश्यक है क्योंकि इससे उत्पादन व्यय घटेगा। इरिडयन इन्स्टीट्यूट श्राव शुगर टैकनालाजी के संघालक श्री जे० एम० साहा ने बिना गन्धक का प्रयोग किये चीनी बनाने की नई प्रक्रिया खोज निकाली है। इस नई

प्रक्रिया से अधिक मान्ना में चीनी उत्पन्न होती है और चीनी का प्रकार भी अपेनाकृत अञ्छा है। पटना माइन्स कालेन के श्री डी० एन वोष ने एक नई रीति
निकाली है जिससे बिना किसी रसायनिक या ताप की सहायता के विजली के
द्वारा गन्ने का रस साफ किया जा सकता है। इन दोनों प्रणालियों का श्रामी तक
व्यवसायिक पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इनसे
चीनी बनाने के व्यय में कमी अवश्य होगी। चीनी उद्योग में अञ्छी मशीनों के
लगाने से भी उत्पादन व्यय में कमी की जा सकती है।

स्थिति-उत्पादन व्यय श्रिषक होने का एक कारण कारलानों का श्रनु-पयुक्त स्थानों पर स्थित होना भी है। यद्यपि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश श्रीर विद्दार में स्त्रधिकतर कारखाने स्थित हैं परन्तु यदि कारखाने वम्बई या दिख्या भारत में होते तो श्रधिक उपयुक्त होता । बम्बई तथा दिख्या के श्रन्य खेत्रों में गन्ने का पति एकड़ उत्पादन अधिक है और वहाँ गन्ने की पिराई भी अधिक समय तक होती है। यदि उत्तर भारत की अपेद्धा उद्योग दिल्या में ही विकसित होता तो चीनी का उत्पादन व्यय श्रवश्य कम होता। परन्तु श्रव यह है कि चीनी-उद्योग श्रिघि-कतर उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में केन्द्रित हो गया है। १६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियमन) कानून के श्रंवर्गत नियुक्त लाइसेंसिन्ग समिति ने कुछ कारखानों को एक साथ नये स्थानों में ले जाने की िक्फारिश की थी परन्तु यह समस्या का उपयुक्त इल थिद नहीं हुन्ना क्योंकि (१) यदि यह योजना लागू की जाय तो एक कारखाने को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने में १० से १५ लाख रुपया व्यय हो जायगा श्रौर यातायात की व्यवस्था में व्यय होगा। इसके साथ ही कारखाने को इटाने की अविध में उत्पादन बन्द रहेगा; (२) जिन चेत्रों से कारखाने इटाये नायँगे उनकी आर्थिक व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो नायगी श्रीर उनका श्रन्य चेत्रों से सम्बन्ध टूट जायगा। इसिलये उद्योग की स्थिति में सुघार करने का सबसे अन्छा उपाय यही है कि नवीन और उपयुक्त स्थानों में घीरे-घीरे नवीन कारखाने स्यापित किये जायँ और अनुपयुक्त स्थानों में स्थित कारखाने जब पुराने पड़ जायँ श्रीर पुनर्निर्माण की श्रावश्यकता हो तब उनका पुनर्निर्माण न करने दिया जाय।

निर्यात — ग्रतीत में चीनी के लिये भारत विदेशों पर निर्भर था। १६२६-३० में भारत ने लगभग ६३ लाख टन चीनी का आयात किया। परन्तु हाल में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप अब आयात केवल नाम मात्रको होता है। यह बहुत संभव है कि भविष्य में भारत चीनी का आयात करने की अपेका निर्यात करने लगेगा। हवायन अंतर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन के कथनानुसार "बहुत

समय तक भारत को चीनी का नियांत करने की श्रानुमित नहीं दी गई, यहाँ तक कि १६३६-४० में जब देश में चीनी का उत्पादन श्रावश्यकता से कहीं श्रिषक हुशा था, श्रातिरिक्त चीनी का भारत से निर्यात नहीं किया जा सका। कुछ समय से यद्यि भारत चीनी का निर्यात कर सकता है परन्तु निर्यात की मात्रा पर नियंत्रण है। कुछ पढ़ोस के देशों को भारत केवल कुछ इजार टन चीनी प्रतिवर्ष मेज सकता है।"

चीनी का निर्यात बढ़ाने में सबसे बड़ी कठिनाई मारतीय चीनी का अपेबाकृत अधिक मूल्य है। मारत में कारखाने के बाहर चीनी का माव (ex-factory price) २७ क्यया प्रति मन है जब कि अन्य देशों में २१ ते २३ क्यया प्रति मन है। इसिलए जब तक सरकार या तो चीनी के निर्यात के लिये आर्थिक सहायता नहीं देती या विदेशों को कम मूल्य पर निर्यात करने और घाटा पूर्ति के लिये देश में अधिक मूल्य पर वेचने की अनुमति नहीं देती तब तक चीनी का निर्यात बढ़ा सकना असंभव है। परन्तु वर्तमान श्रियति में उक्त दोनों साधन अव्यवहारिक हैं। इन कारखों से चीनी का निर्यात बहुत कम होता है और जब तक चीनी का उत्पादन व्यय नहीं घटाया जाता तब तक भविष्य में मी निर्यात में इहि की कोई आशा नहीं दिखाई देती।

योजना के अन्तर्गत—प्रथम पश्चवर्णीय योजना के श्रारम्भ में चीनी के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि का कोई भी प्रवन्य नहीं किया क्योंकि यह श्राशा की जाती थी कि १५.५ लाख टन की उत्पादन शक्ति का श्रनुमान श्रीर १६.५५.५६ तक १५ लाख टन का वास्तविक उत्पादन उपयुक्त होगा। परन्तु १६.५४.५५ में ही चीनी का उत्पादन १६ लाख टन के लगभग हो गया, श्रयात् योजना के लक्ष्य से १ लाख टन श्रिषक हो गया। इसिल्ट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन कर दिया गया। इसिल्ट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन कर दिया गया। इसिल्ट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन कर दिया गया। इसिल्ट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन कर दिया गया। इसिल्ट स्थम सरकार ने ३७ नई मिलों को श्रीर ४० प्रशानी मिलों के विस्तार के लिये लाइसेन्स प्रदान किये। इससे ५३ लाख टन वहने की श्राशा है।

दितीय पञ्चवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्पादन शिक १७४ लाख टन से जितने का १६५५.५६ में अनुमान किया गया है, १६६०-६१ तक २५ लाख टन कर दी जाय और चीनी का उत्पादन १६५५.५६ के १७ लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ तक २२६ लाख टन कर दिया जाय। उत्पादन की इस वृद्धि में से सहकारी चीनी के कारखाने ३६ लाख टन उत्पादित करेंगे। दितीय योजना में उत्पादन की बढ़ी हुई माजा का लक्ष्य उपयुक्त है। हिएडयन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने श्रपने स्मारकपत्र में जो उसने सरकार को मेजा या यह लिखा था कि वर्तमान चीनी के कारखाने पहिले से लाहसेन्स प्राप्त कारखानों को सम्मिलित करते हुये १६६०-६१ तक २७ लाख टन तक चीनी का उत्पादन करने में समर्थ हैं जबकि योजना का लक्ष्य केवल २२१ लाख टन ही उत्पादन करने का है। यदि मिविष्य की फिटनाइयों जैसे वर्षा का न होना, बाढ़ का श्राना इत्यदि को विचाराधीन रख लिया जाय तब १६६०-६१ तक वर्तमान कारखाने पहिले से लाइसेन्स प्राप्त कारखानों को मिलाकर प्रति वर्ष २५ लाख टन चीनी का उत्पादन कर सर्केंगे जो कि लक्ष्य से २१ लाख टन श्रधिक होगा। इस बात को सोचते हुये सरकार के लिए यह श्रावश्यक है कि नई फैक्ट्रियों को लाइसेन्स देने में सावधानी करें नहीं तो भारतीय चीनी उद्योग में उत्पादन शक्ति का श्राधिक्य हो जायगा श्रीर सम्मवत: उत्पादन भी श्रावश्यकता से श्रधिक होगा।

कोयला उद्योग

मारत में कोयले के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। १६३० का २४० लाख टन का उत्पादन १६५७ में बढ़कर ४३५ लाख टन हो गया। सन् १६५० तक कोयले का उत्पादन लगभग ३०० लाख टन तक बढ़ पाया था पर १६५० में सर्व प्रयम उत्पादन बढ़कर ३२३'३ लाख टन हो गया था। आगामी वर्षों में उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। १६५१ में ३४६'६५ लाख टन, १६५२ में ३६३'३४ लाख टन, १६५५ में ३८६ लाख टन, १६५५ में ३५६ काख टन, १६५५ में ३५६ लाख टन तथा १६५७ में ४३५ लाख टन हुआ था। उत्पादन में यह वृद्धि वर्तमान खानों की अधिक धनी खुदाई करने तथा कोयले की मौँग में वृद्धि होने के कारण नई खानों की खुदाई का कार्य आरंभ करने के कारण हुई है।

उत्पादन श्रमता—यद्यपि भारत में कोयले के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कोयले की खानों के उद्योग की उत्पादन च्रमता बहुत कम है। बहुत सी खानें इतनी छोटो हैं जिन्हें आर्थिक हिंद से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। खानों के यन्त्रीकरण में भी विशेष पगित नहीं की गई है। कोयला उद्योग में जितने श्रमिक कार्य करते हैं उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक है। साथ ही अन्य देशों के विपरीत भारतीय खदान-श्रमिक की कार्य च्रमता कम है और प्रति श्रमिक उत्पादन भी कम होता है। उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या १६४१-५१ के मध्य ५८% बढ़ गई है परन्तु कोयले के उत्पादन में केवल ३२% की ही वृद्धि पाई है इससे श्रमिकों की उत्पादकता में हास प्रगट होता है। यह प्राविधिक (टैक्निकल) पिछड़ापन और कार्यक्तमता में कमी, कोयले के उद्योग की स्पर्ध शक्त और लाम को नीचे स्तर पर रखने के लिये उत्तरदायी है।

च्योलोजिकल, माइनिंग और मैटालर्जिकल छोखाइटी की २८ वों वार्षिक वैठक में यह बताया गया कि भारत में प्रति श्रमिक ग्राठ घंटे की एक शिफ्ट में २.७ टन कोयले का उत्पादन होता है जब कि बिटेन में ६.२६ टन, जर्मनी में ८.६६ टन और श्रमरीका में २१.६८ टन कोयले का उत्पादन होता है। इसका ताल्पर्य यह है कि उत्पादन च्यय कम करने के लिए श्रीर उद्योग की वित्तीय स्थिति हद बनाने के लिए भारतीय कोयला उद्योग का श्रमिनवीकरण करने की श्राव-रयकता है। कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण करने में दो कठिनाहयों का समना करना पहता है—(१) इस प्रक्रिया में बहुत श्रधिक धन की श्रावश्यकता होती है और (२) श्रमिक इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं क्योंकि इस योजना को लागू करने से श्रनेक श्रमिक वेरोजगार हो जायँगे। उद्योग की उत्पादन-ज्ञमता में सुधार करने के लिए इन दोनों कठिनाहयों को दूर करना श्रावश्यक है।

परिरक्ष्म (Conservation) — वर्तमान समय में धातुशोधन के कार्य में आने वाले उत्तम श्रेगी के कोयले की काफी इति हो रही है। इस कोयले का कुल निवना उत्पादन होता है उसका ४० प्रविशत भाग रेलवे के कार्य में श्राता है, २१ प्रतिशत के लगमग लोहे और इस्पात उद्योग में श्रीर १३ प्रतिशत का निर्यात और जहाजों में प्रयोग होता है। इस्पात उद्योग में इस प्रकार के कीयले की बहुत आवश्यकता होती है इस्र हिंचे इस उद्योग के उपयोग के लिये इसका संरच्य करना पड़ेगा। मेटालर्जीकल कोल कमेटी (१६४६) अपनी जांच पड़ताल के पश्चात् इस परियाम पर पहुँची कि प्रत्येक वर्ष पूर्व की कुल खपत में से (उद्योग को बिना कुछ हानि पहुँचाये) आगामी ५ वर्षों में धीरे घीरे १० प्रतिशत की कमी की जा सकती है और इस प्रकार धातुशोधन के कार्य में आने वाले उत्तम श्रेणी के की यले का उत्पादन घटाया जा सकता है। इस समिति ने सुकाव दिया है कि (म्र) किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के कीयले की खार्ने न खोली जायें। यदि पुनः प्रचलित करने में अधिक धन न लगे तो उत्तम श्रेणी के कोयले की अछ खानों को बन्द किया जा सकता है, (ब) कोयले के चट्टे लगाने, मिलाने और घोने को कानूनी रूप से श्रानिवार्य कर देना चाहिए, श्रीर (स) खराब कोयला छोड़कर अच्छा कोयला निकालने की रीति को बन्द कर देना चाहिए। योजना आयोग ने सुमाव दिया है उत्तम श्रेणी के कोयले का संरक्षण किया जाय और कोयले तथा कोयला समिति से सम्बन्धित सभी विषयों पर परस्पर उचित संबन्ध स्थापित करने वाली नीति अपनाई जाय। सरकार ने धातु शोधन के कार्य में आनेवाले कोयले के उत्पादन की श्रिधिकतम मात्रा निर्घारित कर दी है। १६५३ उत्पादन की श्रधिकतम मात्रा १५१ द लाख टन, १६५४-५५ में १४३ द लाख टन, १६५६ में १५४' शाख टन तथा १९५७ में १६० लाख टन कर दी गई।

सरकार की इस नीति की दो श्राधारों पर श्रालोचना की गई है। यह कहा गया है कि (श्र) उत्तम प्रकार के कोयले के उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाना समस्या का उचित इल नहीं है। संरच्च करने का श्रर्थ है रोकी जा सकने वाली च्चित होने की सारी संमावनाएँ समाप्त करना, उत्पादन में श्रिषक उपयुक्त साधनों तथा उपायों का प्रयोग करना श्रीर कोयले के व्यय में बचत करना इत्यादि। इसके साथ ही सरकार की नीति को व्यापक होना भी श्रावश्यक है; (ब) कोयले के चहे लगाने, मिलाने श्रीर धोने में श्रीर संरच्च की नीति को लग्गू करने में श्रितिरक्त व्यय करना पड़ता है जिसका उत्पादन व्यय पर प्रभाव पड़ता है। सरकार न तो उद्योग को श्रावश्यक वित्त की सहायता देती है श्रीर न श्रितिरक्त व्यय का घन वस्त्ल करने के लिये कोयले के मूल्य में वृद्धि करने देती है। उद्योग पर उक्त प्रतिबन्ध लगाना सरकार की न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। इस श्रमाव की पूर्ति किये बिना सरकार की कोयला संरच्या नीति से उद्योग को श्रीर श्रिष्ठक हानि होने की संभावना है।

परिवहन कोयला उद्योग की एक सबसे बड़ी किटनाई परिवहन के साधनों का अभाव है। कोयले को अन्यंत्र मेलने के लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ियाँ या मालगाड़ी के डिब्बे नहीं मिलते हैं। गाड़ियाँ मिलने में बहुत देर होती है जिससे खानों के समीप कोयले के ढेर लग जाते हैं। इससे खानों के कार्य में बहुत किटनाई होती है। बँगाल और विहार के कोयले की खानों के चेत्र में (जो देश के ८०% कोयले के उत्पादन के लिये उत्तर दायी है) प्रतिदिन लादी जाने वाली मालगाड़ियों के डिब्बे की औसत संख्या १९५७ में ३६६७ थी, जब कि १९५६ तया १९५२ में यह संख्या कमशः ३४०५ तथा ३१६३ थी। इससे उन्नति की प्रवृत्ति प्रदिश्त होती है परन्तु खेद है कि कोयले की खानों को उपलब्ध माल गाड़ियों की संख्या न तो आवश्यकता के अनुकृल ही रही है और न रेल विभाग की शिक्त के ही अनुकृल।

कोयले के लिये मालगाहियों के ढिज्बों की पूर्ति में वृद्धि आवश्यक है ताकि उद्योग द्वारा कोयला श्रीवता से और कम मुल्य पर वेचा जा सके। मालगाड़ी के ढिज्बों की पूर्ति में वृद्धि के लिये रेलवे के प्रसाधनों में वृद्धि आवश्यक होगी। इसमें निश्चय ही समय लगेगा। परन्तु कुछ अन्य भी उपाय हैं जिनसे कोयले की खानों के लिये मालगाड़ी के ढिज्बों की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान मालगाड़ी के डिज्बों के आवेदन की प्रणाली बड़ी ही जटिल है जिससे देर भी लगती है और खानों पर अन्यिक कोयला भी एकत्रित हो जाता है। दूसरी समस्या ढोने की दर की है। भारत सरकार ने कोयले के माड़े की दर में ३० प्रतिशत वृद्धि कर दी है। भाड़े की वृद्धि कोयला उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त की गई वर्किंग पार्टी के मुमान के अनुसार की गई है। इस वृद्धि से कोयले के परिवहन ज्यय में वृद्धि हो गई और इस प्रकार कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों का उत्पादन ज्यय भी बढ़ गया। भारतीय उद्योगों का विकास करने के लिए कोयले का परिवहन ज्यय कम करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

कोयले के निर्यात में कमी की समस्या मारत सरकार ने १६५४ में नियुक्त एक कमेटी के सम्मुख रक्खी थी जिसने यह रिपोर्ट दी कि मारत के कोयले के मुख्य बाजार पहोसी देशों में ही हैं। इस लिये बरमा, लंका, पाकिस्तान, दिल्खी पूर्वी एशिया के कुछ देशों को ही भारत को अपना स्वाभाविक वाजार सममना चाहिये। १६५१-५२ में जो यूर्व को अधिक निर्यात हुआ। या वह यूर्व में कोयले के अमाव, दिल्खी अफ्रीका में यातायात की कठिनाईयों, आस्ट्रेलिया में नियंत्रित उत्पादन और कीरिया के युद्ध जनित कारणों से था। १६५३ में ये १६५१-५२ की अपवादी स्थित समाप्त हो गई और जो नवीन वाजार भारत को प्राप्त हो गये ये वे सामान्य स्थिति होने पर फिर समाप्त हो गये। कोयले का निर्यात बढ़ाने के विचार से कमेटी ने निम्न सिफारिशें कीं: (१) कोयले का सरकारी क्य विकय बन्द होना चाहिये, (२) कोयले की विभिन्न प्रकारों पर जो नियंत्रण लगा हुआ है उसे कम करना चाहिये; (३) कोल ग्रेडिंग बोर्ड को वे ही ग्रेड बनाने चाहिये जो कन्ट्रोल आर्डर में दे दिये हैं, और (४) कलकत्ते के बन्दरगाह पर अधिक सुविधाओं के देने के उपाय करने चाहिये।

योजना के श्रन्तर्गत—द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोयला उद्योग को प्रमुख स्थान दिया गया है। धीरे धीरे इसे सरकारी चेत्र में ले श्राया जायगा। कोयले का उत्पादन ३६७.७ लाख टन से जो कि १९५४ में था बढ़ाकर १९६०-६१ में ५९७.७ लाख टन कर दिया जायगा।

१६४८ के श्रीचोगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया था कि प्रत्येक कोयले की नवीन खान सरकारी चेत्र में ही श्रारम्म होगी, ऐसी स्थिति के श्रातिरिक्त जहाँ कि राष्ट्रीय दृष्टिकोश्य से सरकार व्यक्तिगत व्यवसायियों का सहयोग श्रावश्यक सममती है। श्रारम्भ में इस नीति के व्यवहार में कुछ शिथिलता दिखाई गई परन्तु श्रव यह निश्चय कर लिया गया है कि भविष्य में कोयले के उद्योग के नवीन उपक्रमों को सरकारी चेत्र में ही रखने का प्रयत्न किया जायगा श्रीर बढ़ी हुई माँग को पूर्ण करने के लिए श्रतिरिक्त कोयले का उत्पादन द्वितीय योजना काल में श्रिथकतम स्तर तक सरकारी चेत्र में ही किया जायगा।

लोहा श्रीर इस्पात उद्योग

मारतीय लोहे श्रीर इस्पात उद्योग के चेत्र में तीन मुख्य उत्पादक हैं, टाटा श्रायरन एएड स्टील कम्पनी, इिएडयन श्रायरन एएड स्टील कम्पनी (इसमें स्टील कारपोरेशन श्राफ़ बंगाल भी सम्मिलित हैं) श्रीर मैस्र श्रायरन स्टील वक्सं। इन कारखानों में कच्चे लोहे का इस्पात वनाया जाता है श्रीर इस्पात से श्रावश्यक वस्तुर्ये तैयार की जाती हैं। इनके श्रातिरिक्त लगमग ६४ छोटे कारखाने हैं जो व्यर्थ लोहे से श्रीर लोहे के छड़ों से जो उत्पादकों द्वारा प्राप्त होते हैं या श्रायात होते हैं, इस्पात तैयार करते हैं।

मारतीय इस्पात उद्योग एशिया में सबसे वड़ा है श्रीर संसार के सर्वोत्तम इस्पात उद्योगों में से एक है। १६२४ में संरक्षण मिलने के पश्चात् इसने महत्व-पूर्ण प्रगति की है। उद्योग की उत्पादन ज्ञमता में इतनी वृद्धि हुई कि १६४१ में संरक्षण की कुछ श्रावश्यकता नहीं रही। इस्पात का उत्पादन १६४७ में दृष्ट लाख टन या जो बढ़कर १६५२-१६५५ तया १६५७ में क्रमशः ११ लाख टन, १२ लाख टन श्रीर १३ लाख टन हो गया। १६५८ में उत्पादन की मात्रा ४५ लाख टन श्रीर १३ लाख टन हो गया। १६५३ में इस्पात श्रीर उले हुए लोहे का उत्पादन १६५२ की श्रिपेचा कम हो गया। इसका कारण किसी सीमा तक तो अमिनों के कारहे थे श्रीर किसी सीमा तक यन्त्रों के श्रीमनवीकरण के कारण उत्पाद वह श्रव्यवस्था थी जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए कारखानों को बन्द रखना श्रावश्यक हो गया था। इसके श्रान्वर उत्पादन में वृद्धि हुई श्रीर मिवण्य में इसके श्रीर श्रिषक बढ़ने की संमावना है। भारत के इस्पात श्रीर लोहे के उद्योग की मुख्य समस्याएँ (श्र) इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करना, (ब) ढले हुए लोहे के उत्पादन को फाउन्ह्रीयों के लिये बढ़ाना है।

लोहे श्रौर इस्पात टयोग के लिए श्रावश्यक कच्चा माल भारत में ही प्राप्त है। जितना कच्चा माल वर्तमान समय में प्राप्त है उतने से ही उद्योग के लिए इस्पात बढ़ा लेना सम्भव है।

इस्पात का मूल्य—देशी इस्पात का मूल्य श्रायात किये हुये इस्पात से चहुत कम है। मूल्यों में समानता लाना बहुत श्रावश्यक है। यह मूल्य के नियंत्रण द्वारा ही (युद्धकाल से श्राज तक) सम्मव हो सका है। १ श्रवहूबर १६३६ से ३० जून १६४४ तक युद्ध के लिये क्षय किये जाने वाले इस्पात के मूल्य पर नियन्त्रण था। परन्तु इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं था। इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर की नियंत्रण १ जुलाई १६४४ से श्रारम्म हुशा। इस सम्बन्ध में सरकार जिस प्रणाली का श्रनुसरण करती है उसके

अनुसार प्रत्यार स्था मूल्य (retention price) नियत कर दिया जाता है जिस पर मुख्य-मुख्य उत्पादक इस्पात विकय करते हैं, और उपमोक्ताओं के लिये मृल्य की एक अन्य कँची दर नियत होती है जिस पर वे क्रय करते हैं। दोनों मृल्यों के अन्तर से प्राप्त धन समानता स्थापित करने वाले कोष (equalisation method) में जमा कर दिया जाता है जिसमें से इस्पात के आयात में सहायता प्रदान की जाती है और इस्पात उत्पादकों के अभिनवीकरण तथा विकास के कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता दी जाती है। एक जुलाई १६४४ और ३१ मार्च १६४६ के मध्य इस्पात के हो प्रत्यार स्था मृल्य निर्धारित किये गये थे। एक युद्ध के लिये क्रय किये जाने वाले इस्पात के लिये और दूसरा व्यवसायिक प्रयोग के लिये, परन्तु १ अप्रैल १६४६ से केवल एक ही प्रत्यार स्था मृल्य निर्धारित है। परिस्थित के परि-वर्तन के साथ प्रत्यार स्था मृल्य और विकय मृल्य बदलते रहते हैं।

प्रशुक्त मण्डल की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि १६५५-५६ से १६५६-६० तक की अविध के लिये ३६३ ६० प्रति टन के प्रत्यार ज्ञ्या मूल्य की एक ही दर टाटा कम्पनी और इन्डियन आयरन एएड स्टील कम्पनी के लिये नियत की जानी चाहिये। इस पुनर्निश्चित मूल्य के लागू करने के लिये सरकार का प्रस्ताव फरवरी १६५६ में पास हुआ। इसी समय १६५४-५५ के लिये पुनर्परि ज्ञित प्रत्यार ज्ञ्या मूल्य ३४३ ६० प्रति टन का टाटा आयरन एएड स्टील कम्पनी के लिए और ३८६ ६० प्रति टन का हन्डियन आयरन एएड स्टील कम्पनी के लिए नियत किया गया। इस बात को सब ने स्वीकार कर लिया कि १६५४-५५ का समायोजित प्रत्यार ज्ञ्या मूल्य और ३६३ ६० प्रति टन के समान प्रत्यार ज्ञ्या मूल्य का अन्तर प्रत्येक कम्पनी आपने विकास कोष में दे देगी।

भूतकाल में इस्पात का मूल्य बम्बई, कलकत्ता, मद्राम, जमशेदपुर श्रीर बरनपुर में ५०० रुपये प्रति टन या, श्रीर श्रन्य स्थानों पर उपभोक्ताश्रों को उसके साथ परिवहन व्यय मिला कर देना पड़ता था। इसका श्र्य यह था कि (१) उत्तर प्रदेश, पंजाय श्रीर उत्पादन केन्द्रों तथा बन्दरगाहों से दूर स्थित नगरों के उपभोक्ताश्रों को श्रीधक मूल्य देना पड़ता था; श्रीर (२) बन्दरगाहों के निकट उद्योग केन्द्रित होते जा रहे थे क्योंकि उन्हें वहाँ इस्पात सस्ता मिलता था। सरकार की जून १६५६ की नई नीति के श्रनुसार इस्पात का एक ही मूल्य (५२५०० प्रति टन) जिसमें रेल का किराया सम्मिलित होगा रेल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा। इस प्रकार जपर वताये हुए पाँचों स्थानों पर उपभोक्ताश्रों को ने २५ रु० प्रति टन श्रितिरिक्त मूल्य देना पड़ेगा श्रीर उन उपभोक्ताश्रों को जो श्रमृतसर श्रीर कानपुर ऐसे स्थानों में हैं लगभग ३५ रु० प्रतिटन कम देना पड़ेगा। पहले मूल्य

में समानता लाने के लिये सिद्धान्त का प्रयोग केवल इस्पात के सम्बन्ध में ही लागू किया गया था। श्रव यह सिद्धान्त ढाले हुए लोहे के सम्बन्ध में भी लागू किया नायगा। इस नई नीति के कारण इस्पात श्रीर लोहे के मूल्य में भारत के उत्तरी भाग में रहने वाले न्यिक्तयों के लिये कभी हो जायगी श्रीर दुर्लम वस्तुयें प्रत्येक को युक्ति संगत मूल्य पर प्राप्त हो सकेंगी।

इस्पात के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण उपभोक्ताश्रों के लिये लाभकारी विद हुश्रा है क्योंकि तिना इस नियन्त्रण के उन्हें ये क्ख्यें श्रिधिक मूल्य पर प्राप्त होती। परन्तु कम प्रत्यारक्षण मूल्य के नियत किये जाने से उत्पादकों को हानि हुई हैं। यदि उत्पादकों को उँचा मूल्य मिला होता तो वे श्रवश्य उद्योग के विस्तार करने में तथा श्रिमनवीकरण में व्यय किया जाता। श्रव उन्हें इस कार्य के लिये सरकार ते श्रुण लेना पड़ा है श्रीर सरकार ने मूल्य समीकरण कीय (equalisation fund) से यह श्रुण दिया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने टाटा कम्पनी श्रीर स्टोल कारपोरेशन श्राफ वंगाल को तथा श्रन्य इस्पात के उत्पादकों को वह घन श्रुण के रूप में दिया है जो कि त्यायत: उन्हों का था। यदि इस्पात कम्पनियों को ऐसे श्रवसर पर जब कि इस्पात का मूल्य बढ़ा हुश्रा है श्रिधिक मूल्य का लाभ न उठाने दिया जायगा तो श्रार्थिक मन्दी के समय जब मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है वे हानि का सामना किसे करेंगे।

ं भविष्य की माँग —लोहा श्रीर इस्पात मेनर पेनेल ने १६४६ में अनु-मान लगाया कि मारत में २० लाख टन इस्पात की खपत है, जब कि युद्ध के पूर्व केवल दस लाख टन की खपत थी। परन्तु १६४७ में परामर्शदात्री नियोजन परिपद ने श्रनुमान लगाया कि देश में सामान्य स्थिति में १५ लाख टन इस्पात की खपत है। कृषि तथा श्रीशोगिक विकास पर विचार करते हुये योजना श्रायोग ने श्रनुमान लगाया कि १६५२ में कुल ३२ लाख टन की श्रावश्यकता होगी श्रीर १६५७ तक २८ लाख टन की श्रावश्यकता हो जायगी। लोहा श्रीर इस्पात पेनल ने श्रनुमान लगाया है कि भारत को फाउन्ड्रियों के लिये प्रतिवर्ध ३ लाख टन ढले हुये लोहे को श्रावश्यकता होगी। वाणिज्य मन्त्रालय के छोटे श्रीर वहें इंजीनिरिंग उद्योग के जाँच करने वाले पेनेल ने १६५१ में बताया कि मारत को ४ लाख से ४'२ लाख टन तक ढले हुये लोहे की श्रावश्यकता थी। दितीय पंचवर्षीय योजना का श्रनुमान है कि १६६०-६१ में इस्पात की माँग लगमग ४५ लाख टन की श्रीर फाउन्ड्रियों के लिये ढले लोहे की माँग लगमग ७५ लाख टन की होगी। मुख्य उत्पादकगण ढला लोहा श्रपने प्रयोग के लिये तथा फाउन्ड्रियों के लिये ही उत्पादित करते हैं। इसंतिये फाउन्ड्रियों के लिये ढले लोहे की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये प्रमुख उत्पादकों को अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी।

योजना के अन्तर्गत—दितीय पंचवर्षीय योजना ने मारत में इस्पात के उत्पादन के विकास पर विशेष महत्व दिया है। उद्योगीकरण की वर्तमान बढ़ी हुई प्रगति को बनाये रखने के लिये और मारत में यन्त्रों के निर्माण करने वाले उद्योग की स्थापना करने के लिये यह श्रावश्यक होगा कि इस्पात के उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाय। दितीय योजना में १६६०-६१ तक ४३ लाख टन इस्पात के उत्पादन का प्रवन्य किया गया है। इसमें से वर्तमान तीन प्रमुख उत्पादक श्रपने विस्तार के कार्य कम को पूर्ण कर लेने के पश्चात लगमग २३ लाख टन की पूर्ति कर सकेंगे। सरकारी चेत्र में तीन नये स्थापित प्रमुख उत्पादक लगमग २० लाख टन का उत्पादन १६६०-६१ तक कर सकेंगे यद्यपि उनके उत्पादन की चरम सीमा कहीं श्रिषक होगी।

लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन को प्रधानता देने के निर्णय के श्रमुकुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी चेत्र के श्रन्तर्गत तीन इस्पात के कारखानों की स्थापना का निश्चय है जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन होगी, श्रीर इन तीन में से एक को ३-५ लाख टन फाउन्ड्रियों के प्रयोग में आने वाला ढला हुआ लोहा तैयार करने की सुविधायें प्राप्त होंगी । रूरकेला में खोले गये कारखाने में १६५६-६१ में १२८ करोड़ रुपये के विनियोग का अनु-मान हैं। यह श्राशा की जाती है कि ७.२ लाख टन इस्पात की चपटे श्राकार की वस्तुत्रों का उत्पादन करेगा । दूसरा कारखाना, जो कि मध्य-प्रदेश में भिलाई स्थान पर स्थापित किया गया है, उस पर लगभग ११० करोड़ रुपया न्यय किये जाने का अनुमान है। उससे हम आशा करते हैं कि ७७ लाख टन विकय योग्य इस्पात तथा वजनी श्रीर मध्य श्रेगी की वस्तुत्रों का उत्पादन हो चकेगा जिसमें १.४ लाख टन पत्रक का भी रि-रोलिङ्ग उद्योग के लिये उत्पादन सम्मिलित होगा। तीसरा कारखाना दुर्गपूर में, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थिति है, खोला गया है जिसमें लगभग ११५ करोस रुपये के व्यय होने की आशा है। यह कारखाना ऐसे प्रसाधनों से युक्त होगा कि वह हल्की श्रीर मध्य श्रेशी की इत्यात तथा पत्रक की वस्तुत्रों का निर्माण ६.६ लाख टन तक प्रतिवर्ष कर सकेगा।

सरकारी चित्र के समान ही व्यक्तिगत चेत्र में भी इस्पात श्रीर लोहे का स्थान श्रीयोगिक योजना में एक बहुत बड़ी महत्ता रखता है। इस उद्योग पर व्यक्तिगत चेत्र में लगभग ११५ करोइ क्यें के विनियोग का विचार किया गया है। प्रथम योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत चेत्र में लोहे श्रीर इस्पात उद्योगों के

विस्तार सम्बन्धी विनियोग तथा जो कुछ ज्यय द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत किया गया है उस सब का फल १६५८ के मध्य से मिलना प्रारम्म होगा जबिक टाटा श्रायरन एएड स्टील कम्पनी तथा इंग्डियन श्रायरन एएड स्टील कम्पनी की संयुक्त उत्पादन शक्ति वर्तमान १२.५ लाख टन के स्थान पर २३ लाख टन के लगभग हो जायगीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस्पात श्रीर लोहे के उत्पादन के बढ़ाने पर उचित ही ध्यान दिया है। इस्पात श्रीधक मात्रा में श्रीधोगीकरण का श्राधार है श्रीर इस्गत के उत्पादन की वृद्धि श्रीधोगिक उन्नति के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है। लोहे का उत्पादन बढ़ाने में सरकारी चेत्र पर बहुत श्रधिक विश्वास है। २८ मई, १६५५ को वेन्द्रीय सरकार ने लोहे श्रीर इस्पात के लिये एक मंत्रालय की नियुक्ति की जिस पर लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन सम्बन्धी सरकारी कार्यों का तथा सरकारी फाउन्ड्रीयों की देखभाल का भार रक्खा गया। कुछ लोगों के मत में यह श्रधिक श्रन्छा होता यदि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का भार मुख्य रूप से वर्तमान उत्पादकों के ऊपर ही छोड़ दिया गया होता क्योंकि उन्हें इस नात का श्रायश्यक श्रनुभव था श्रीर सम्मवतः वे श्रधिक श्रीधता से श्रीर कम लागत पर उत्पादन की वृद्धि करने में सफल भी हुये होते।

सीमेन्ट उद्योग

सीमेन्ट के उत्पादन में भारत ने उल्लेखनीय प्रगित की है। १६४८ में केवल १५ लाख टन का उत्पादन या जो १६५७ में बद कर ५६ लाख टन हो गया। १६५२ में भारत में केवल २३ फैक्ट्रियाँ थीं, जिनकी उत्पादन शक्ति ३७'६ लाख टन थी। १६५७ में २६ फैक्ट्रियाँ थीं जिनकी स्थापित सामर्थ्य ६६'३ लाख टन थीं। भारतीय सीमेन्ट उद्योग की वास्तिकक उत्पादन शक्ति में नह फैक्ट्रियों की स्थापना तथा पूर्व की फैक्ट्रियों के विस्तार के कारण वृद्धि हुई है। सीमेन्ट उद्योग को श्रनेक कठिनाहयों का सामना करना पड़ा है; (१) मृतकाल में उत्पादन की मात्रा उनकी वास्तिकक उत्पादन शक्ति से बहुत कम थी और १६५० में जब कि वास्तिक उत्पादन शक्ति ३१'२ लाख टन थीउस समय उत्पादन केवल २६'१ लाख टन था। परन्तु इधर हाल में इस दोप का किसी सीमा तक निराकरण कर दिया गया है; (२) बहुत फैक्ट्रियाँ अनुक्लतम उत्पादन शक्ति से बहुत नीचे स्तर पर हैं, नवीन फैक्ट्रियाँ उपयुक्त श्राकार की हैं और शेष्टतम यन्त्रों का प्रयोग कर रही हैं। (३) सीमेन्ट उद्योग को श्रावश्यक संख्या में मालगाड़ी के डिब्वे नहीं प्राप्त होते जिनसे कच्चा माल लाया जा सके श्रीर तैयार सीमेन्ट उपमोग केन्द्रों को शीमता पूर्वक मेजा जा सके, श्रीर (४) सीमेन्ट का नियंत्रत मूल्य सब फैक्ट्रियों के शिमता पूर्वक मेजा जा सके, श्रीर (४) सीमेन्ट का नियंत्रत मूल्य सब फैक्ट्रियों के

दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं रहा है, क्योंकि ग्रन्य फैक्ट्रियों से तन्तनारों जो ग्राधिक व्यवस्थित थीं कुछ फैक्ट्रियों का उत्पादन व्यथ श्राधिक रहा है ।

इघर हाल में स्थित में घोर परिवर्तन हुआ है। सीमेन्ट दुर्लभ ही नहीं वरन् वहुत मंहगा भी हो गया है। इस बात को विचाराधीन करते हुये सरकार ने सीमेन्ट का क्रय विकय अपने हाथों में ले लिया है और उसके लिये एक विकय मूल्य १ जुलाई १६५६ से लागू कर दिया है। सब सीमेन्ट के उत्पादकों को अब अपना सीमेन्ट स्टेट ट्रेडिङ्क कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्राइवेट लि०) के हाथ फीन्ट्री के बाहर उपभोग केन्द्रों तक पहुँचाने में लगे रेलवे के किराये के आधार पर नियत मूल्य पर वेचना होगा। यह कारपोरेशन सीमेन्ट १०२ ६० प्राने प्रति टन के मूल्य पर वेचता है। मई १६५७ में सीमेन्ट पर लगा उत्पादन कर ५ ६० प्रति टन से बढ़ाकर २० ६० प्रति टन कर दिया गया। सीमेन्ट का मूल्य भी इतना ही बढ़ गया।

देश के विभाजन के फलस्वरूप कुछ सीमेन्ट की फैक्टियाँ पाकिस्तान में चली गईं । यही कारण था कि १६४७ में उत्पादन घट कर १५ लाख टन हो गया जब कि १६४५ में २२ लाख टन था। परन्तु देश ने बहुत शीव ही विभाजन के प्रभावों से मुक्ति पा ली श्रीर उत्पादन में वृद्धि श्रारम्भ हो गई जो श्राज तक निरन्तर चल रही है। युद्धोत्तर काल में सीमेन्ट उद्योग की विकास सम्बन्धी उल्लेखनीय विशेषताएँ यह हैं; (१) १६३६ में सीमेन्ट उद्योग प्राय: मध्य प्रदेश श्रीर मध्य भारत में ही केन्द्रित था। परन्तु एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी द्वारा युक्तिकरण की योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप कुछ फैक्टियों को नये स्थानों पर स्थापित किया गया। युद्धोत्तर काल में इस उद्योग का विकास अधिक छन्तुलित ढंग पर हुन्ना न्नीर नवीन स्थानों पर कारलाने स्थापित हुये। इसका परिगाम यह हुआ कि सीमेन्ट के कारखाने सम्पूर्ण देश में फैले हैं। इससे देश के विभिन्न भागों में प्राप्त होने वाले कच्चे माल का भी उचित प्रयोग सम्भव हो गया है। साथ ही यातायात में बहुत सा व्यर्थ व्यय जो उद्योग के किसी एक स्थान पर केन्द्रित होने के कारण करना पड़ता वह भी बच गया। (२) भृत काल में सिमेन्ट उद्योग व्यक्तिगत उपक्रम था, परन्तु श्रव सरकार ने भी इस उपक्रम में भाग लेना श्रारम्म कर दिया। मैसर राज्य की फैनरी के श्रातिरिक्त, जिसकी उत्पादन शक्ति ३६ इजार टन से बढ़ा कर ६० इजार टन कर दी जायगी, उत्तर प्रदेश की राजकीय फैक्ट्री पिपरी में स्थापित की है जिसकी उत्पादन शक्ति २३ लाख की है। (३) भूतकाल में अधिकाँश कारखाने ८००० टन ही के अनार्थिक से भी कम उत्पादन वाले थे। परन्त हाल में जो कारखाने स्थापित किये गये हैं वे श्रायिक

दृष्टि से उपयुक्त हैं श्रीर प्रायः सभी कम मात्रा में उत्पादन करने वाले कारखानों ने श्रपनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि की है।

सीमेन्ट की श्रान्ति साँग उसकी पूर्ति से श्रिषक होगई। देश में उत्पादन की वृद्धि के श्रालावा १६५६ के प्रारंभ में यह निश्चय किया गया कि उस वर्ष विदेशों से ७ लाख टन सीमेन्ट का श्रायात किया जाय। राज्य-न्यापार निगम (State Trading Corporation) ने इस मात्रा के श्रायात के लिये टढ़ न्यवस्था कर रखी थी किन्तु बीच में स्वेज का संकट उपस्थित हो जाने पर १६५६ में केवल १०८,००० टन सीमेन्ट हो श्रा सका। १६५७ में ३२१,००० टन सीमेन्ट श्रीर श्राया। १६५८ में श्रायात श्रीर कम होगा। इसका कारण विदेशी विनियम का संकट तथा देश में उत्पादन का तीव्रता से बढ़ना है।

योजना के अन्तर्गत-प्रथम योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि सिमेंट के कारखानों की संख्या १६४०-५१ में २१ से बढ़ाकर १६५५-५६ में २७ कर दी जाय। साथ ही इनकी ३३ लाख टन की उत्पादन शक्ति तथा २७ लाख टन उत्पादन बढ़ाकर १९५५.५६ में क्रमशः ५३ लाख टन श्रीर ४८ लाख टन , कर दिया जाय। मध्य प्रदेश, मध्यभारत श्रीर ट्रावनकोर कोचीन में छिमेंट के कारखानों को श्रनुगणित शक्ति में वृद्धि का कोई नियोजन नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश, उड़ीसा श्रीर वम्बई में नवीन कारखाने खोले जाने वाले थे। बिहार, राज-स्थान श्रीर मद्राप के कारखानों की शक्ति में वृद्धि करना श्रत्यन्त श्रावश्यक था जो पूर्व के कारखानों में ऋितरिक्त नवीन मशीनों के प्रयोग से ही सम्भव था। इस कार्य के करने में मधान कठिनाई धन के श्रभाव की थी। कारखानों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने श्रौर उन्हें १३ लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन करने योग्य बनाने के लिए बहुत श्रधिक मात्रा में धन की श्रावश्यकता है। उत्तर प्रदेश की िसमेंट फेन्ट्री की स्थापना में, जो कि मिर्जापुर जिले में चुर्क में है, ४३ करोड़ रुपये की लागत लगी थी। टक्की उत्पादन शक्ति २ ५२ लाख टन प्रतिवर्ष की है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रो का कुल व्यय सरकारी कर्मचारियों की श्रनमवहीनता के कारण बहुत श्रिधिक हो गया है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की वह सर्वोत्तम फैक्टियों में से एक है।

प्रथम योजना में अनुगिष्ति उत्पादन शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाये थे, परन्तु काफी हद तक सफलता अवश्य मिली थी। १६५५-५६ में सीमेंट की उत्पादन शक्ति और उत्पादन क्रमशः ४७ लाख टन और ४४ लाख टन यी जबकि प्रथम योजना में क्रमशः ५३ लाख टन और ४८ लाख टन का लक्ष्य था। देश के औद्योगीकरण में उन्नति हो जाने पर सीमेंट

की माँग में वृद्धि होगी। इसिलये द्वितीय योजना ने १६६०-६१ तक उत्पादन शिक्त को १६० लाख टन तक (जिसमें से भ लाख टन सरकारी चेत्र में बढ़ेगा) श्रीर वास्तिवक उत्पादन को १३० लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य बनाया है। श्रव तक भारत सरकार द्वारा ५४ स्कीम जिनमें २५ नई हैं तथा २६ वर्तमान उत्पादन इकाइयों के विस्तार से सम्बन्धित हैं, मंजूर की गई हैं। यद स्कीम प्रगति के विभिन्न स्वरों पर हैं। इनमें से १५ स्कीम (४ नई तथा ११ विस्तार सम्बन्धी) जिनकी कुल उत्पादन शक्ति १८ लाख टन है १६५८ के श्रन्त तक पूरी हो जाँयगी। १६५६ के श्रन्त तक ११ श्रीर स्कीम पूरी हो जाँयगी तथा श्राशा की जाती है कि इस समय तक कुल उत्पादन शक्ति १०४ लाख टन हो जायगा। रोष स्कीम १६६०-६१ तक पूरी होगी।

कागज उद्योग

वर्तमान समय में भारत में कागज की १६ मिलें हैं जिनकी स्थापित उत्पादन शक्ति २५०,००० टन है। कागन उद्योग को १६२५ से १६४७ तक संरक्षण दिया गया था। इस उद्योग ने नि:सन्देह उल्लेखनीय प्रगति की। १६५२ े में भारत में केवल ६ मिलें थीं जिनकी उत्पादन-शक्ति २७ इज़ार टन थी। १९५६ में २१ मिलें थी तथा उनकी उत्पादन शक्ति २११,६०० टन थी। १६५७ में मिलों की संख्या घटकर १६ होगई क्योंकि उत्पादन की दो इकाइयाँ जो बन्द सी ही धीं सूची में से इटा दी गई। किन्तु विस्तार की योजनाश्री के पूरी हो जाने के कारण उद्योग की स्थापित उत्पादन शक्ति बढकर २३ लाख टन हो गई है। कागज उद्योग की तीन श्रेशियाँ हैं (१) कागज़ श्रीर पटा, (२) श्रखबारी कागज़ की सूखी दफ्ती तथा श्रन्य प्रकार की दिप्तयाँ। कागज़ तथा पह के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुली दिफ्तयों तथा श्रान्य प्रकार की दिफ्तयों के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। परन्तु देश में श्राखवारी कागज़ का बहुत श्राभाव है। भविष्य में कागज उद्योग का विकास करते समय श्रखवारी कागज़ के उत्पादन में वृद्धि करने की सस्मया पर विशेष ध्यान देना पहेगा। यद के उत्तर काल में (श्र) यह उद्योग नवीन स्थानों पर मो ग्रारम्भ हो गया है श्रीर श्रधिकाँश प्रदेशों में श्राज कागज़ बनाने वाली मिल हैं. (य) ग्राय श्रानेक प्रकार के कागज़ तथा दिएतयों का उत्पादन होने लगा है यहाँ तक की इस्ले श्रीर ट्रिप्ले दिप्तयों तथा काफ्ट लपेटने के कागज़ के उत्पादन में तो विशेष प्रगति हुई है।

काराज उद्योग की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उत्पादन शक्ति की बहुत श्रिधिक प्रतिशत मात्रा का उत्पादन हुआ है। १६४८, १६४६ श्रीर १६५० में क्रमश: ६७,००० रन, १०३,२०० रन श्रीर १०८,६१२ रन का उत्पादन हुआ था जो कि उत्पादन शक्ति का लगभग ८२%, ६४% श्रीर ८३% होता है। १६५७ में २१०,१२५ टन का उत्पादन हुआ जो कि उत्पादन शक्ति का ८३% था। यह सब होते हुये भी कागज उद्योग को अभिकों के मगड़े तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के न्यायोचित मूल्य पर न मिल सकने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है श्रीर निम्न स्तर के कोयले का जिसके लिये इन्जनों के बायलर श्रमुपयुक्त हैं, प्रयोग करना पड़ता है। बाँस श्रीर घास के मैदानों के न्यायोचित मूल्य पर दीर्घकालीन पट्टों पर न उठाये जाने के कारण हानि उठानी पड़ी है। इसके श्रातिरिक्त जब से रेल विभाग ने श्रपनी श्रिषमान्य पद्धित (Preferential System) को माल के यातायात सुविधा के सम्बन्ध में परिवर्तित कर दिया है कागज़ उद्योग को जो प्रधानता मिलनी थी उसका श्रन्त हो गया है श्रीर श्रन्य विभिन्न पकार की वस्तुश्रों के साथ उसे भी यातायात सुविधा पाने में प्रतीज्ञा करनी पड़ती है। इन कठिनाइयों के कारण ही कागज़ उद्योग की उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा कम हो गई है।

कचा माल-कागज श्रौर पट्टा श्रयवा दफ्ती उद्योग श्रपने कच्चे माल के लिये बाँस ख्रीर सबई घास का उपयोग करता है। इसके ग्रातिरिक्त कुछ कार-लाने चियहे, रही कागज, चोनी की सीठी इत्यादि का उपयोग करते हैं। भारत में ऐसे कच्चे माल का कुछ ग्रभाव नहीं, परन्तु उद्योग के उपयोग के लिये इनकी पूर्ति का संगठन करने की आवश्यकता है। कागज उद्योग में अनेक रसायनी जैसे चूना, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरीन, गंघक श्रादि का भी उपयोग किया जाता है। गंघक को छोड़ कर श्रन्य सब रसायनिक भारत में ही मिल जाते हैं। कुछ सीमा तक कास्टिक सोडा श्रीर सोडा ऐश का विदेशों से श्रायात करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के कागज के कारखाने सवाई की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। परन्तु इसके साथ ही चीड़, देवदार, श्रीर एक प्रकार के सरो के वृज्ञ की कोमल लकड़ी का भी उपयोग किया जा सकता है जिसकी भारत में बहतायत है। यदि मुलायम लकड़ी के वनों का विकास किया जाय, लकड़ी को कारखानों तक पहुँचाने के लिये यातायात की उचित व्यवस्था की जाय और एक कारखाना श्रख्वारी कागज श्रीर केमिकल पल्प बनाने के लिये स्थापित किया जाय तो श्रखवारी कागज उद्योग के लिये ग्रावश्यक कब्चे माल की पूर्ति को बढ़ा सकना सम्भव है। कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित सक्ताव दिये थे; (१) कागज उद्योग के काम श्राने वाले पेड़ों के वनों की सुरज्ञा की जाय श्रीर इनका उपयोग कर सकने के लिये उद्योग को दीर्घकालीन पट्टे के ऋषिकार दिये र्जीय: (२) बाँस ग्रीर सबई घास के आरे देश में एक तर्क संगत ग्राधार पर मूल्य

निर्धारित किये जाँय जिससे उद्योग को कच्चा माल निरंतर प्राप्त हो सके। राज्य सरकारों के हितों की रक्षा करने के लिये कच्चा माल एक निश्चित मूल्य पर उद्योगों को दिया जाय श्रीर इसके साथ ही उनके तैयार माल की विकय मूल्य से सम्बन्धित प्रव्यामि (premium) की कोई मात्रा लामांश में से उनसे वस्त्ली जाय; (३) यातायात की सुविधा के लिये जंगलों में सहके बनाई जाँय; श्रीर (४) कपड़ों की कतरन, पटसन श्रीर जूट तथा रही कागज का निर्यात विलक्कल बन्द कर दिया जाय।

यह खेद की वात है कि वन विकास के संबन्ध में राज्य सरकारों की कोई सुसंबद्ध नीति नहीं है श्रीर कागज की मिलों को जंगल पट्टे पर देने में बहुत श्रधिक सुसंबद्ध नीति नहीं है श्रीर कागज की मिलों को जंगल पट्टे पर देने में बहुत श्रधिक सूल्य वस्त करती हैं। रेल परिवहन के माड़े की दर भी श्रधिक है। मारत सरमूल्य वस्त करती हैं कार पुराने श्रख्यारों की रही के श्रायात पर भारी श्रायात कर वस्त करती है कार प्राने श्रख्यारों की रही के श्रायात पर भारी श्रायात कर वस्त करती है श्रीर श्रपनी रही का स्टाक त्रिना किसी बात का ध्यान किये ठेकेदारों को वेच श्रीर श्रपनी रही का उसे पैकिंग इत्यादि के लिए बाजार में वेच देते हैं। केन्द्रीय तथा देती है, जो उसे पैकिंग इत्यादि के लिए बाजार में वेच देते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की नीति में परिवर्तन करने से उद्योगों को कचा माल पर्याप्त मात्रा में दिया जा सकता है।

योजना के श्रन्तगीत —िविभिन्न कागज की मिलों के प्रधार कार्यक्रम को लागू करने से यह श्राशा की जाती है कि प्रथम योजना काल में उद्योग की उत्पालागू करने से यह श्राशा की जाती है कि प्रथम योजना काल में उद्योग की उत्पालन श्रीर दिन्तयाँ श्रीर ३०,००० टन श्रखनारी दन शांक २११,००० टन कागज श्रीर दिन्तयाँ कागज की हो जायगी श्रीर १६५५-५६ तक २००,०००टन कागज श्रीर दिन्तयाँ श्रीर २७,००० टन श्रखनारी कागज का नास्तिवक रूप से उत्पादन हो जायगा। श्रीर २७,००० टन श्रखनारी कागज का नास्तिवक रूप से अनुमानतः १६५५-५६ स्थ से इत्यादि से ननने वाली दिक्षितयों के उत्पादन संबन्ध में श्रनुमानतः १६५५-५६ तक उद्योग की वार्षिक उत्पादन शक्ति ५८,५०० टन हो जायगी श्रीर वास्तिवक उत्पादन ५२,००० टन होगा।

कागज श्रीर कागज की दिक्तियों के उद्योग के संबन्ध में प्रथम योजना के लहर लगमग पूरे हो गये। अखनारी कागज का उत्पादन करने वाली सर्वेप्रथम लहर लगमग पूरे हो गये। अखनारी कागज का उत्पादन अभी बहुत कम है मिल ने १६५५ में कार्य आरंभ किया। यद्यपि इसका उत्पादन अभी बहुत कम है पर आशा की जाती है कि जब यह मिल शक्ति मर उत्पादन करेगी तब २०,००० पर आशा की जाती है कि जब यह मिल शक्ति मर उत्पादन करेगी तब २०,००० पर आखनारी कागज का उत्पादन संभव हो सकेगा। द्वितीय योजना में यह प्रस्ताय टन अखनारी कागज का उत्पादन संभव हो सकेगा। द्वितीय योजना में यह प्रस्ताय गया है कि १६६०-६१ तक स्थापित उत्पादन शक्ति तथा कागज और ३५५ की दिक्तियों का वास्तविक उत्पादन बढ़ा कर कमशाः ४५५ लाख टन और ३५५ लाख टन कर दिया जाय और अखनारी कागज के स्थापित उत्पादन शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन बढ़ाकर ६०,००० टन तक कर दिया जाय। द्वितीय योजना के वास्तविक उत्पादन बढ़ाकर ६०,००० टन तक कर दिया जाय। द्वितीय योजना के

उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण कर सकने के लिये यह आवश्यक होगा कि (१) कागज उद्योग के कार्य को सरलता से चलाने के लिये देश का आर्थिक वातावरण अनुकूल बनाया जाय, (२) कच्चे माल तथा.तैयार माल के यातायात के लिये मालगाड़ी के डिन्मों की पूर्ति वहाई जाय, और (३) कच्चे माल की पूर्ति वहाई जाय। भारत में चीनी उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में होने के कारण गन्ने की सीठी का कागज बनाने के लिए प्रयोग बड़े लाम के साथ किया जा सकता है। १६५५ के अन्त में जर्मनी के विशेषशों का एक दल भारत में इस विषय का परीच्या करने तथा रिपोर्ट देने के लिये आया था। परिचमी जर्मनी की एक फर्म से सीठी पर आधारित १०० टन प्रतिदिन का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाई की स्थापना पर बातचीत चल रही है।

श्रन्य उद्योगों की माँति कागल उद्योग के उत्पादन के प्रकार तथा उत्पादन व्यय कम करने के लिये उपाय करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। योजना श्रायोग ने यह श्रिमस्ताव किया है कि कागल उद्योग को श्रपने उत्पादन की प्रविधि को श्राधुनिक बनाना चाहिये जिससे वह निम्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सके; (१) ईघन तथा कच्चे माल के प्रयोग में कमी करके कागल की उत्पादन लागत में कमी, श्रीर (२) विभिन्न प्रकार के कागलों, विशेषकर रेपिंग श्रीर काफ्ट कागल, की प्रकार में उन्नति। यदि यह सुधार सम्भव हो सके वो कागल उद्योग में स्थायित्व श्राम्तामा।

श्रध्याय २०

छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योग

मारत की श्रीचोगिक व्यवस्था में छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले श्रीर कुटीर उद्योगों का स्थान चदा से ही महत्वपूर्ण रहा है। शिल्पकारों की एक बहुत बड़ी श्रूब्या खदैव इन उद्योगों पर ही श्रूपनी जीविका के लिये निर्भर रही हैं। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योगों को भारत में वेकारी की कठिन समस्या को हल करने के साधन के रूप में रख कर इनकी श्रोर श्रिषक ध्यान श्राकर्षित किया है। इसके पूर्व कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत हन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर विचार करें यह श्रावश्यक होगा कि इन उद्योगों की कठिनाइयों का परीद्या किया जाय।

उद्योगों को प्राय: तीन वर्गों में विमाजित किया जाता है: (१) वहे पैमाने पर उत्पादन करने वाले अथवा बढ़े उद्योग, (२) छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले त्रायवा छोटे उद्योग, (३) कुटीर उद्योग। इन उद्योगों को विभन्न प्रकार से परिमापित किया गया है। एक मत के अनुसार कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो शिल्पियों द्वारा स्वयं अपने आप ही अयवा-किसी कारखानेदार के निर्देशन में पर पर ही किये जाते हैं। मिंद कार्य छोटे कारलाने में किया जाता है श्रीर उसका निर्देशन उद्योगपति द्वारा किया जाता है तो उसे इक छोटा उद्योग कह सकते हैं चाहे शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग न भी किया जाय। एक अन्य मत के अनुसार घरेलू उद्योग वह है (को श्रंशत: अथवा पूर्णत: परिवार के ही सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है चाहे वे सम्पूर्ण दिन कार्य करें या थोड़ी देर ही नित्य कार्य करें"। श्री चिन्तामणि देशमुख के मतानुसार "घरेल हद्योग" प्रायः इम उन सब उत्पादन के उपक्रमों को कहते हैं जो बहे-बड़े व्यवस्थित कारखानों के श्रातिरिक्त हैं। जो व्यक्ति इन उपक्रमों में लगे हुये हैं मुख्यत: अपने ही प्रयम और कौशल पर निर्मर रहते हैं, सीधे-सादे श्रीजारों का प्रयोग करते हैं और अपने घर पर ही कार्य करते हैं। विशिष्ट ग्रावश्यकताग्रों के कारण इस पकार के ऊछ उद्योग हाल में आरम्म हुये हैं। ये उद्योग प्रधानत: परम्परागत है श्रौर वर्तमान उत्पादन प्रविधि से स्पर्धा करते हुये श्रपनी रज्ञा में प्रयक्षशील है। छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग "घरेलू तथा ग्राम्य उद्योगों से इस श्रथ में मिन्त हैं कि उनको संचालित करने वाले उद्योगपति होते हैं जो पारिश्रमिक पर रक्खें हये श्रमिकों से कार्य लेते हैं।"

उपर्युक्त परिभाषात्रों को विचाराधीन रखते हुये इम यह कह सकते हैं कि | घरेलू उद्योग की निन्न विशेषतार्ये हैं, (१) ऐसे उद्योगों को घर पर ही बिना श्रामकों की सहायता के स्वयं चलाया जाता है, (२) इनमें परम्परागत ढंग का ही श्रनुसरण किया नाता है, श्रीर (३) इनका स्वतंत्र तथा पूर्ण समय का कार्य होना ग्रावश्यक नहीं हैं; ये कृषि तथा किसी ग्रन्य व्यवसाय के सहायक हो सकते हैं। छोटे उद्योग ग्रथवा योड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की मुख्य विशेषता यह है कि ये कार्य करने वालों के घर में नहीं चलाये जा सकते श्रीर कार्यकर्ता के त्रावश्यक स्रोत नियान्त चीमित होते हैं। योड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों के कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या १० से ५० तक सीमित है। इमारे देश में उपर्यक्त दोनों वर्गों में श्रानेवाले श्रनेक उद्योग हैं जैसे कर्घा, कन, रेशम, गुइ, राब, तेल पेरने, ताले बनाने के कार्य इत्यादि । इन उद्योगों में काम में सहायता देने वाले परिवार के सदस्यों श्रीर समय पर इनमें कार्य करने वाले उन व्यक्तियों की संख्या को छोड़कर जो कृषि स्नादि श्रन्य मुख्य व्यवसाय में संलग्न है, लगमग २० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं। इन दोनों प्रकार के उद्योगों का प्रामी श्रीर नगरों दोनों में ही पूर्ण श्रयवा श्रांशिक समय के लिये श्रनुसरण किया जाता है। हैएडी क्रैफ्ट का उद्योग जैसे वेल-बूटे काढ़ने का कार्य, पीतल का कार्य, रेशम बनाने का कार्य इत्यादि पूर्ण समय के कार्य हैं श्रीर इन कार्यों में संलग्न व्यक्तियों ने उत्कृष्ट ज्ञमता भी पाप्त कर ली है।

लाभ—(१) घरेलू उद्योग श्रीर छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों का सबसे बड़ा लाम तो यह है कि वे बहुत बड़ी संख्या में कार्य का श्रवसर प्रदान करते हैं। कितने ब्यक्ति कुटीर श्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों में कार्य करते हैं श्रीर वे कितना कितना उत्पादन करते हैं इस सम्बन्ध में ठीक ठीक श्रांकड़े प्राप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय श्राय समिति ने यह श्रनुमान लगाया था कि १६५०-५१ में छोटे उद्योगों का उत्पादन ६१० करोड़ रुपये का हुश्रा था श्रीर लगमग ११५ लाख व्यक्ति कार्य करते थे जार करते थे श्रीर उनके कुल उत्पादन का मूल्य लगमग ५५० करोड़ रुपया था। इन छोटे उद्योगों में कुटीर उद्योग भी सम्मिलित थे पर वे छोटे छोटे कारखाने जो फेन्ट्री एक्ट के श्रवर्गत श्राते थे। इनमें सम्मिलित नहीं किये गये थे। समिति ने उन्हें फेक्ट्रियों में सम्मिलित किया था। यदि हम इन छोटे छोटे कारखानों को भी घरेलू श्रीर छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों में सम्मिलित कर लें श्रीर हाल में जितने लोग इनमें कार्य कर रहे हैं उनकी बढ़ी हुई संख्या को भी वचाराघीन रख लें तो कुल कार्य करने वालों की संख्या लगमग २०० लाख श्रीर

कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य लगसग १२०० करोड़ रुपये के हो जायेगा। पर यह सब गयाना अनुमान मात्र है इसिलये विश्वस्त नहीं कही जा सकती। इन आँकड़ों से घरेलू और छोटे उद्योगों के विस्तार और माबी सम्मावना का ही कुछ अनुमान ही मिल सकता है।

- (२) कुटीर उद्योग की यह विशेषता है कि इसमें मूल्यवान् मशीनें नहीं लगाई जाती हैं, इसके लिये किसी वड़ी इमारत इस्यादि की आवश्यकता नहीं होती है इसलिये इसको चलाने में अधिक पूँजी नहीं लगानी पड़ती। भारत में पूँजी का अभाव है और इमें कुछ ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जिनमें पूँजी कम लगे और अमिक अधिक।
- (३) इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योग में वैज्ञानिक श्रीर टेकनिकल ज्ञान की विशेष श्रावश्यकता होती है। परन्तु वर्तमान समय में (टेकनिशियन) प्राविधिशों का भारत में श्रमाव है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में यही लाम है कि इनमें श्रिविक प्राविधिक (टेकनिकल) ज्ञान श्रीर प्रविधिशों की श्रावश्यकता नहीं होती है।
- (४) छोटे पैमाने के श्रीर कुटार उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की तरह किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित नहीं है बल्कि सम्पूर्ण देश में विस्तृत हैं। इनमें इभारत, सफाई, स्वास्थ्य इत्यादि की समस्या नहीं होती है, जिनका बड़े पैमाने के उद्योगों को सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही युद्ध के समय इनके विनाश का मय भी कम रहता है। बड़े पैमाने के श्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों का द्वल-नात्मक श्रध्ययन करते समय श्रीर इनके लाभ-हानियों का विवेचन करते समय हमें उक्त समाजिक न्यय का भी विचार करना चाहिये।
- (५) बढ़े पैमाने के उद्योगों की अपेका छोटे पैमाने श्रीर कुटीर उद्योगों में रोजगार में अस्थिरता बहुत कम होती है। हमारे देश के प्रामीण व्यक्तियों का मुख्य उद्यम कृषि करना है श्रीर वे सहायक व्यवसाय के रूप में रस्ती बनाने, गुड़ बनाने, कपड़ा बुनने इत्यादि कार्यों को करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन सहायक उद्योगों में मंदी आ जाय तो अमिक अथवा कारीगर को उतनी अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना किसी श्रीद्योगिक अमिक को मंदी के कारण नौकरी खूट जाने पर करना पड़ता है।

कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों से बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेत्ता कुछ अधिक लाम होते हैं। अब प्रश्न यह उटता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को कौन सा स्थान देना चाहिए। वित्त आयोग (१६४६-५०) के अनुसार इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है;

- (१) उद्योग के प्रकार,
- (२) उद्योग में टेकनिकल व्यवस्था,
- (३) उद्योग के संगठन के लिए श्रावश्यक भ्रम श्रीर पूँजी,
- (४) श्रार्थिक हिंदर से उत्पादन का किस सीमा तक उचित इकाइयों में विकेन्द्री करण िक्या जा सकता है केवल व्यक्तिगत व्यय को ही नहीं वरन् सामाजिक व्यय को मी विचाराघीन रखते हुए।

जहाँ तक उद्योग के प्रकार का प्रश्न है उसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है; (१) ऐसे उद्योग जिनमें बड़ी माना में उत्पादन करने से कुछ निश्चित लाभ है और जिनकों छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट, भारो रसायनिक और खदान उद्योग हत्यादि ! इन उद्योगों को कुटीर में अथवा छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है इस्रालए इस चेन्न में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है; (२) ऐसे उद्योग जिनका छोटे पैमाने पर उत्पादन करके कुछ निश्चित लाभ उठाया जा सकता है, जैसे ताला मोमवन्ती, बटन, चप्पल, खाद्यान इत्यादि उद्योग। इनमें से कुछ में छोटे पैमाने पर उत्पादन करने में उत्पादन व्यय कम होता है। खाद्यान के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जब वस्तुएँ हाथ से तैयार की जाती हैं तो उनमें पौष्टिक तत्य अधिक रहते हैं; (३) ऐसे उद्योग जिन्हें बड़े और छोटे पैमानों पर चलाया जा सकता है। इन उद्योगों के सम्बन्ध में चुनाव का प्रश्न उठता है।

टेकनिकल व्यवस्था के आधार पर उद्योग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) ऐसे उद्योग जिनमें बड़े पैमाने के उद्योगों और कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों में कोई प्रतियोगिता नहीं हैं, जैसे मधु मक्खी पालन, गुड़ बनाना तथा अन्य दस्तकारी के कार्य इत्यादि।(२) ऐसे उद्योग जिनमें छोटी मात्रा के और कुटीर उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के सहायक हैं; इनमें उन वस्पुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी बड़े पैमाने के उद्योगों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ अशों का उत्पादन के उद्योगों के उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ अशों का उत्पादन होटे उद्योगों में किया जाता है, और (३) ऐसे उद्योग जिनमें बड़े पैमाने के अग्रेर छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, जैसे, कर्यों में बुना कपड़ा, खायहसारी चीनी, चमड़े का सामान इत्यादि। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है परन्त दूसरे वर्ग के अन्तर्गत छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में परसर उचित सम्बन्ध स्थापित करके इनकी किसी भी

समस्या को सुगमता पूर्वक सुलकाया जा सकता है। तीसरे वर्ग के उद्योगों के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

कठिनाइयाँ

कच्चे माल, उत्पादन की प्रविधि, वित्त, विक्रय, कर इत्यादि के सम्बन्ध में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़ी किटनाइयों का समना करना पड़ता है। इन उद्योगों को प्रायः उन वस्तुओं की यावश्यकता होती है जिनका बड़े उद्योगों में उत्पादन किया जाता है। कथीं उद्योग पूर्णत्या सूती मिल द्वारा उत्पादित सूत पर निर्भर करता है। दितीय विश्वयुद्ध के समय सूत मिलने में बहुत किटनाई हुई, क्योंकि जितने युत का उत्पादन किया जाता या उसका अधिकार मिलों की ही यावश्यकता पूर्ति में लग जाता या। उस समय अधिकतर मिलों में कराई और द्वाई साय-साथ होती थी। केवल कताई करने वाली मिलों की संख्या बहुत कम है। कथीं उद्योग को अधिक सूत उपलब्ध कराने के लिए सूत की कताई करने वाली कुछ और मिलों की स्थापना की गई हैं और इनमें उत्पादित सूत का कुछ प्रतिश्वत कथीं उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दलालों के कारण कुटीर उद्योग को आवश्यक कच्चे माल का श्रिधक मूल्य चुकाना पड़ता है। इस कठिनाई को सहकारी सिमितियों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

प्रविधि और प्रमाली—इन उद्योगों में लिस ढंग से श्रीर जिन सामनों से उत्पादन किया जाता है वह प्राचीन हो चुके हें श्रीर वर्तमान में उनकी उपयोगिता बहुत घट गई है। खोज कार्य करने श्रीर कारीगरों के शिच्या की उपयुक्त व्यवस्था न होने से उत्पादन के प्रकार में बहुत श्रीत हुई हैं। श्रमिकों को उचित शिच्चा देने श्रीर उत्पादन के प्रकार में सुधार करने के लिए बहुत योही ऐसी संस्थाएँ हैं जो श्रव्ह्या कार्य कर रही हैं, जैसे श्रिखल मारतीय प्राम उद्योग संप, श्रिखल मारतीय कवाई संघ, खादी प्रतिष्ठान श्रीर हाल ही में स्थापित खादी श्रीर ग्राम उद्योग विकास वोर्ड।

अन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने, जिसकी फीर्ड फाउन्डेशन ने नियुक्त किया था, जिसने छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योगों का अध्ययन करने के लिये तथा उनके पुनकत्थान के सुमाव देने के लिये मारत का दौरा किया, १९५४ में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसने यह िफारिश की कि चार शिल्प कला ज्ञान सम्बन्धी संस्थायें स्थापित की जानी चाहिये जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिये कि वे सम्पूर्ण भारत की सेवा कर सर्के। भारत सरकार ने यह

िषकारिश स्वीकार करली है। पर खोज का कार्य करेंगी और श्रपनी खोज के परिणामों को तथा नई उत्पादन विधियों, नये श्रीजारों, श्रीर नई प्रविधियों की स्चना उत्पादकों तक पहुँचायेंगी।

कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देने की श्रावश्यकता है जो कि उचित शिक्षा प्रचार तया प्रत्येक दस्तकारी के लिये स्थानीय परिपद के स्थापित करने से सम्मव हो सकता है।

वित्त व्यवस्था—छोटे उद्योगों श्रीर उद्योगपितयों की वही किताइयों में वित्त को किताई प्रमुख है। मशीन श्रीर श्रावश्यक श्रीजार क्रय करने के लिए उसे दीर्घकालीन पूँजी की श्रावश्यकता होती है। इसके साथ ही कच्चा माल क्रय करने के लिए श्रोर पारिश्रमिक इत्यादि चुकाने के लिए श्राट्यकालीन पूँजी की श्रावश्यकता होती है। छोटे उत्पादकों में श्रिधकतर निर्धन हैं श्रीर श्रूण के लिए श्रावश्यक प्रतिभृति नहीं दे पाते। साथ ही ऐसे उत्पादकों की श्रावश्यकताएँ भी कम होती हैं, इन्हें श्राधक धन की श्रावश्यकता नहीं होती है इस्तिए वड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देने वाले व्यवसायी वैंक इनको श्रूण इत्यादि देने में कुछ लाभ नहों समकते। बहुत कम ऐसी संस्थाएँ हैं जिनसे इन उत्पादकों को वित्त की सहायता मिल सकती है। इन्हें श्राधकतर श्रामीस साहुकारों श्रीर कारखानादारों पर निर्मर करना पड़ता है। कारखानेदार इस शर्त पर श्रमण देते हैं कि उत्पादित माल उनको वेचा जायगा। उत्पादित माल का मूल्य श्रमण देते समय निश्चित कर लिया जाता है। इससे उत्पादक को श्रपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

श्रन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने यह सिफारिश की कि (१) व्यापारिक वैंकों को अपनी शालाओं को अधिक ऋण देने की श्रनुमति देकर इन्हें दिये जाने वाले ऋण की मात्रा बढ़ा देना चाहिये; (२) सहकारी वैंकों को इन उद्योगों की वित्त सहायता करने की ओर और अधिक ध्यान देना चाहिये; (३) प्रत्येक प्रदेश में एक राज्यीय वित्त निगम स्यापित किया जाना चाहिये जिसके कोष को इन छोटे उद्योगों की ही सहायता के लिये सुरक्तित कर देना चाहिये; और (४) वास्तविक सम्पत्ति की प्रतिभृति पर ऋण देने की प्रणाली प्रचलित की जानी चाहिये।

व्यक्तिगत चेत्र की वित्त सहायता के लिये शौफ कमेटी ने भी रिजर्व वैंक को जून १६५४ में दी हुई अपनी रिपोर्ट में उन छोटे उद्योगों के विषय में विचार किया है जिनकी सम्पत्ति १० इज़ार रुपये और ५ लाख रुपये के अन्दर है। कमेटी ने कृपि के सहायक उद्योगों को अपनी परीच्चण परिधि के अन्दर समिलित नहीं

किया। चालू पूँजी के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इन उद्योगों से सरकार द्वारा अय किए गये माल के मूल्य का भुगतान करने में देर नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि न्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा लिखे हुये इकरारनामों की रजिस्ट्री की फीस भी कम कर देनी चाहिये ताकि उनको वैंको से अगा लेने में अधिक स्विधा मिले । दीर्घ कालीन पँजी की आवश्य-कताश्रों के लिये यह सिफारिश की कि पादेशिक सरकारों को इन उद्योगों को 'स्टेट एड ट इएडस्टीन एक्ट' के ज्रान्तर्गत श्रधिकाधिक सहायता देनी चाहिये। इसलिये इन उद्योगों को श्राधिक अगुण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये यह श्रावरयक होगा कि प्रादेशिक बजट में इस पर व्यय करने के लिये श्रधिक धन का अनुदान किया जाय और ऋण देने की प्रणाली को श्रधिक सरल बनाया जाय। कमेटी ने यह सुकाव दिया है कि 'प्रादेशिक वित्त कारपोरेशन' को छोटे उद्योगों को ऋग देना चाहिये। इसके साथ ही उसने यह सिफारिश की कि छोटे उद्योगों की सहायतार्थ एक विशिष्ट विकास निगम की भी स्थापना होनी चाहिये जिसकी प्रारम्भिक शेयर पँजी ५ करोड़ रुपया हो जो कि भारत के रिजर्भ बैंक, व्यवसायिक बैंकों, बीमा कम्पनियों, तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्राप्त होनी चाहिये।

वाजार-दितीय युद के समय श्रीर युद के पश्चात कुछ वर्षों तक बहुत से उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की कोई समस्या नहीं यी क्योंकि माँग पूर्ति से श्रधिक थी परन्तु फिर भी दलालों के कारण श्रीर उत्पादित माल घटिया होने के कारण उत्पादक को अपने परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था। इघर कुछ वर्षों से इन उद्योगों की विकय समस्या गंभीर होती जा रही है। काश्मीर का शाल श्रीर बनारस की सिल्क जैसे मूल्यवान सामानों का उपमोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजात्रों तथा जमीदारों की श्रव पहले जैसी स्थिति नहीं रही। राजाओं की गद्दी श्रीर जमींदारी का उन्मूलन हो चुका है। जनवा की क्रयशक्ति में कमी होने के कारण माँग घट गई है। समस्या यह है कि बाज़ार में उत्पादित माल की माँग बढ़ाई जाय, श्रीर उचित मूल्य वस्ता जाय। माँग में वृद्धि तभी की जा सकती है जब या, तो निर्यात किया जाय या बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के बदले इनका उपभोग किया जाय। कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल का उपभोग कनाडा, श्रमरीका, न्यूजीलैगड, श्रास्ट्रेलिया श्रीर मध्य पूर्वी देशों में बढ़ाया जा सकता है। यह देश पूर्व से ही माल क्रय करते रहे हें ख्रीर दस्तकारी की वस्तुत्रों, कलापूर्ण कपड़ों, लाख तथा खेल के सामान इत्यादि के विषय में पूछताछ करते रहे हैं परन्तु इन देशों को बड़ी मात्रा में एक साथ और नमूने के

त्रमुलप माल की त्रावश्यकता है। उत्पादित माल का बड़ी मात्रा में श्रीर ठीक नमूने के त्रमुलप निर्यात करने के लिए विकय समितियों का विकास करने की त्रावश्यकता है।

राज्य सरकारें छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों पर कर कम लगाने की नीति अपनाती हैं। उदाहरणस्वरूप खराडकारी चीनी पर कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी की अपेना कम उत्पादन कर देना पहता है। इस समत्या का एक दूसरा पन्न भी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सुमाव दिया गया है कि छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों पर कर लगाया जाय। कर्षा उद्योग का विकास करने के लिए हई करोड़ उपया एक करने के लिए चूवी मिलों में तीन पाई प्रति गज के हिसाब से यह कर लगा भी दिया गया है। बड़े पैमाने के उद्योगों पर पूर्व ही से बहुत कर लगे हुए हैं यदि यह नया कर और लगा दिया गया तो इससे उद्योग के विकास में बाघाएं उत्पन्न हो लायेंगी। सभी प्रकार के बड़े, छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास का उद्येश्य इस प्रकार की कर-नीति से पूर्ण नहीं हो सकता है।

छोटे श्रीर कुटीर उद्योगों के सामने विद्युत श्रीर यातायात के श्रमाव की मी समस्या है। इनकी स्थिति सुधारने के लिए सत्ती विद्युत श्रीर सत्ते यातायात की सुविधा देना श्रावश्यक है।

कार्वे कसेटी रिपोर्ट—योजना श्रायोग ने कार्वे कमेटी, श्रयवा श्राम्य उद्योग श्रीर छोटे उद्योग कमेटी, की नियुक्ति ज्न १६५५ में इन उद्योगों की समस्याश्रों का परीद्याय करने श्रीर एक ऐसी योजना प्रस्तुत करने के लिए की जिससे (१) द्वितीय योजना काल में उपमोग की वस्तुश्रों की बढ़ी हुई मांग का श्रिष्किंश इन्हीं उद्योगों से पूर्ण किया जा सके; (२) उनसे उत्तरोत्तर कार्य करने के श्रिषक श्रवसर प्राप्त हो सकें श्रीर (३) उत्पादन श्रीर विनिमय की न्यवस्था सहकारिता के श्राधार पर न्यवस्थित हो सकें।

कमेटी को यह स्पष्ट हो गया था कि ग्राम्य तथा छोटे उद्योगों की उपेत्ता बहुत दिनों से होती श्रा रही है। प्रथम योजना में जो उनके प्रति च्यान दिया गया था वह पर्याप्त न था। प्रथम योजना के परिशामस्वरूप इन उद्योगों के विकास के लिये छ: विशिष्ट बोर्डों की स्थापना है। इन बोर्डों ने १६५१-५२ में १४ ३२ लाख रूपया व्यय किया था जो कि १६५४-५५ में वढ़कर ६ ७३ करोड़ रूपया हो गया श्रीर १६५५-५६ में १५ ४२ करोड़ रूपया; परन्तु यह भी श्रपर्याप्त सिद्ध हुआ। कमिटी ने २६० करोड़ रूपये के विनियोग की सलाह दी श्रर्यात् दितीय योजना काल में प्रति वर्ष ५२ करोड़ रूपया व्यय किया जाय। कार्वे कमेटी ने उन छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले श्रीर कुटीर उद्योगों के विकास की सिफारिश की थी जो नित्यकार्य में श्राने वालो वस्तुश्रों का उत्पादन करते ये जैसे स्ती कपछे, ऊनी कपछे; हाथ के कुटे चावल, वनस्पित तेल, गुड़ श्रोर खरहसारी, चमड़े के ज्ते श्रीर दियासलाई हत्यादि। साथ ही रेशम के कीड़े पालना, रेशम बुनना, हथकर्या उद्योगों की नारियल की जटा का कातना श्रीर खनना, श्रादि उद्योगों की श्रोर कमेटी ने श्रपना ध्यान दिया। कमेटी द्वारा दितीय योजना के श्रन्तर्गत मस्तावित कुल २६० करोड़ रुपए के व्यय से श्राशा की जाती है कि श्रिषक समय के लिये यह उद्योग ५० लाख व्यक्तियों को कार्य करने का श्रवसर प्रदान करेंगे। कपड़े के उद्योगों को कमेटी ने सब से श्रिषक महत्ता दी है। इनमें विकेन्द्रित स्त कातने श्रीर विनने का काम भी सम्मिलत है। इस उद्योग पर लगमग कुल व्यव का ४४% श्रर्थात् ११३ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। श्राशा की जातो है कि यह उद्योग लगमग ३० लाख व्यक्तियों को कार्य प्रदान कर सकेगा।

कमेटी ने तीन मुख्य ध्येय अपने समज्ञ रक्षे थे। (१) द्वितीय योजना काल में यथासम्भव श्रीद्योगिक वेरोज्गारों में दृद्धि न होने देना जो कि प्राय: परम्परागत ग्राम्य उद्योगों में दुश्रा करती है; (२) श्रिष्ठिक से श्रिष्ठिक संख्या में लोगों को योजना काल में ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों द्वारा कार्य करने का श्रवसर प्रदान करना; श्रीर (३) विकेन्द्रित समाज की स्थापना के लिये एक श्राधार प्रदान करना तथा वृद्धि-मान गृति से श्रार्थिक विकास करने की सुविधा देना। कमेटी ने समृद्धि का जो काल्पनिक चित्र श्रपने मन में रक्ष्णा था उसको प्राप्त कर लेने के विचार से निम्म सुक्ताव दिये हैं—

- (१) प्रादेशिक उरकारों को उद्दकारी उपितियों को धन तथा प्रत्याभृति द्वारा उद्दायता देनी चाहिये जिससे वे प्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों की श्रिधिक उद्दायता कर सकें। कमेटी ने रिजर्व वैंक श्रीर स्टेट वैंक श्राफ इिएडया को प्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों की सहायता देने के श्रनेक ढंगों का सुमाव दिया। उसने यह भी सिमा-रिश को कि जब तक इन उद्योगों के लिये एक नई संपूरित संस्थागत श्रृण की व्यवस्था न हो जाय तब तक श्रांखल मारतीय बोडाँ, प्रादेशिक वित्तीय निगमों तथा राजकीय विभागों को श्रावश्यक सहायता देते रहना चाहिये।
- (२) प्रादेशिक सरकारों द्वारा दिये हुये अनुदानों का प्राम्य और छोटे उद्योगों की सहायता करने के स्थान पर कमेटी ने यह अधिक अच्छा समक्ता कि सरकार द्वारा सहकारिता के आधार पर उत्पादित कुछ वस्तुओं का निम्नतम

मूल्य निश्चित कर दिया जाय जिस पर वे वेची जाँय । मूल्य से कम पर वेचने में जो घाटा हो उसे राज्य को पूरा करना चाहिये।

- (३) ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों को विस्तार का अवसर प्रदान करने के विचार से कमेटी ने यह विचित्र सुकाव दिया कि फैक्ट्री उद्योगों के श्रिषिकतम उत्पादन की मात्रा नियत कर देनी चाहिये श्रीर जितनी भी माँग इसके उपरान्त बढ़ें उसे पूर्णतः श्रथवा श्रंशतः ग्राम्य उद्योगों से पूर्ण करना चाहिये।
- (४) समी फैक्ट्री उद्योगों के सम्बन्ध में कमेटी ने एक उपकर श्रारोपित करने की सिफारिश की निसका प्रयोग ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों के विकास श्रीर उत्पत्ति के लिये किया जाय ।
- (५) कमेटी ने सुक्ताव दिया कि केन्द्रीय मन्त्रिमरहल में एक पृथक मंत्री श्राम्य त्रीर छोटे उद्योगों के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये । इस मंत्री को सहयोग देने के लिये मंत्रिमरहल के सदस्यों की एक कमेटी होनी चाहिये जिसका काम भारत सरकार की श्रीद्योगिक नीति में सामंजस्य स्थापित करना होगा।

समालोचना-कार्वे कमेटी की विकारिशों में निम्न गंभीर दोष हैं।

- (श्र) कमेटी ने प्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों का श्राधुनिकीकरण तथा श्रिमिनवी करण तमी करने की िक्फारिश की है जब कि उससे वेकारी न बढ़ें परंतु यह श्रिसम्ब है।
- (ब) मिल उद्योगों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अर्थ यह है कि आम्य और छोटे उद्योग उपयोग की वस्तुओं की बढ़ी हुई माँग को पूर्ण करने में समर्थ होंगे, जो कि जनसंख्या के बढ़ने तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण होगी । जिन व्यक्तियों को आम्य और छोटे उद्योगों का ज्ञान है वे यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि असम्भव है।
- (स) कार्वे कमेटी का अन्तिहित विचार यह है कि आम्य और छोटे उद्योगों की मिल उद्योगों की स्पर्धा से रहा होनी चाहिये और उनको अपने माल को वेचने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में केवल देश के मिल उद्योग का ही विचार नहीं करना है वरन् विदेशी मिलें भी स्पर्धा करेंगी।
- (द) कमेटी की इस िषकारिश के कलस्वरूप कि राज्य सहकारिता के सिदान्त पर उत्पादित वस्तुओं के कय श्रीर विकय मूल्य का श्रन्तर सहन करे श्रीर एक नया मन्त्रालय स्थापित करे, भारत में राज्यों का व्यय बढ़ जायगा । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक राज्यों के इतने बड़े व्यय तथा श्राय स्रोतों को देखते हुये इस सुकाव को व्यवहारिक नहीं माना जा सकता।

्योजना के अन्त्रात-यह बड़े सीमाग्य की बात है कि योजना श्रायोग

श्रौर सरकार ने कार्वे कमेटी की सब सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया विवाद प्रस्त प्रश्न मिल उद्योगों के उत्पादन की श्रिषकतम मात्रा नियत करने का था, उस पर श्रमी निर्णय नहीं किया गया है। यह बड़े दुर्माग्य की बात है कि उपकर कुछ उद्योगों पर तो लगा ही दिया गया है श्रौर श्रन्य पर लगाये जाने को सम्मावना है। परन्तु श्रमी तक तो कार्वे कमेटी की शिफारिशें उस सीमा तक स्वीकार नहीं की गई है कि भारतीय श्रायिक व्यवस्था को श्रसाध्य हानि पहुँच जाय।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में दस उद्योगों के लिये एक .योजना निर्माण की गई थी—ग्राम्य तेल उद्योग, नीम के तेल का साझन बनाना, धान क्टना, खजूर का गुड़ बनाना, गुड़ श्रीर खरडसारी उद्योग, चमड़े का उद्योग, ऊन के कम्बल बनाना, हाथ से श्रच्छे प्रकार का कागज बनाना, शहद की मक्खी पालना श्रीर क्ट्रीर दियासलाई उद्योग । यह योजना इस विश्वास पर निर्माण की गई थी कि इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार १५ करोड़ क्पया श्रीर प्रादेशिक सरकार ११ करोड़ क्पया श्रीर प्रादेशिक सरकार ११ करोड़ क्पया व्यय करेगी । प्रथम योजना काल में जो धनराशि वास्तव में इन उद्योगों पर व्यय की गई है वह ३१.२ करोड़ क्पये है । इसमें से इयकर्षा उद्योग पर ११.१ करोड़ क्पये, श्राम्य उद्योगों पर ४१ करोड़ क्पये श्रीर छोटे उद्योगों पर ५१२ करोड़ क्पये व्यय हुये ।

दो बड़े महस्तपूर्ण कार्य प्रथम योजना काल में किये गये। उनमें से एक तो केन्द्रीय उरकार द्वारा प्राम्य ख्रौर छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी मात्रा में घनराशि का अलग निकाल देना या ख्रौर दूसरा विभिन्न उद्योगों के लिये ख्राखिल भारतीय बोर्डों की स्थापना था। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण, तथा ख्राखिल मारतीय बोर्डों की कार्य परिधि के विस्तृत हो जाने के कारण, ख्रनेकों उद्योगों का उत्पादन तथा उनमें कार्य करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात सरकार द्वारा स्टोर्स परचेज कमेटी की उन सिफारिशों की स्वीकृति हैं जो स्टोर्स की कुछ प्रकार की वस्तुओं का केवल प्राम्य श्रीर उद्योगों से ही खरीदां जाना अनिवार्य करते है, और बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की वुलना में उन वस्तुओं के मूल्य के अन्तर को ग्राम्य उद्योगों को देने के लिये बाध्य करते हैं।

हितीय पंचवर्णीय योजना में प्रथम योजना की अपेजा छोटे उद्योगों पर अधिक धन मुख्यतः इसिलये ब्यय किया जायगा कि उससे मारत में वेकारी की समस्या हल होगी। कार्वे कमेटी की २६० करोड़ रुपया ब्यय किये जाने की िषकारिश के विपरीत द्वितीय योजना ने केवल २०० करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवस्था की है। आशा यह की जाती है कि जब प्रादेशिक योजनाओं का पुनर्परीक्षण होगा तो यह धनराशि अवश्य वह जायगी।

२०० करोड़ रुपयों के विनियोग में से वे न्द्रीय सरकार २५ करोड़ रुपये व्यय करेंगी। योजना में प्राप्त छोरे छोटे उद्योगों के लिये निश्चित किये हुए २०० करोड़ रुपयों के श्रांतिरिक्त ११ करोड़ रुपया छुटीर श्रीर मध्यवर्ती उद्योगों के विकास के लिये श्रीर श्रीद्योगिक श्रूरण के लिये, श्रीर ७ करोड़ रुपया विभिन्न लोगों के पुनवास के कार्यक्रम के श्रुन्तात श्रीद्योगिक तथा व्यवसायिक शिद्या के लिये निश्चित किया गया है। समुद्रायिक विकास चुनों के बजट में ऐसे उद्योगों के लिये प्रत्येक चित्र में १३ लाख रुपये के व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है। पिछड़ी जातियों की सुख सुविधा के लिये बनाये कार्य-कम में भी कुछ चुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित व्यवसायिक श्रीद्रागिक श्रीद्रागिक श्रिक्त का प्रवन्ध किया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों में कुछ प्रगति हुई है। इन पर ५६ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है श्रीर श्राशा की जाती है कि तीगरे वर्ष की समाप्ति तक यह ६१ करोड़ रुपया हो जायगा। इस व्यय का ४० प्रतिशत खादी श्रीर श्रामोद्योगों के लिये, २५% से कुछ श्रिषक छोटे पैमाने के उद्योग तथा श्रीद्योगिक यस्तियों (Industrial estates) के लिये तथा २०% के लगमग हाय के कर्ष तथा शक्तिचालित कर्षों के लिये या। पहली दो योजनाश्रों में की गई व्यवस्था राज्य तथा केन्द्र की श्रमुमानित व्यय-समता पर श्राधारित थी। १६५८-५६ एक श्रन्य कारण मी महत्त्वपूर्ण हो गया। केन्द्र श्रीर राज्यों के पास योजनाश्रों को लागू करने के लिये घनराशि सीमित थी।

६२ श्रीद्योगिक वस्तियों में से, ११ पहले दो वर्षों में पूरी हो गई तथा श्रम्य १६ के १६५८-५८ तक पूरी होने की श्राशा है। १६५७-५८ के श्रम्त तक छोटे उद्योगों का प्राविधिक तथा विकय सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये, ४ प्रादेशिक लघु उद्योग सेना संस्थान (Small Industries Services Institutes), १३ वहे संस्थान, २ उप संस्थान तथा २७ प्रसार-केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे। १६५८-५६ के एक श्रीर प्रादेशिक लघु उद्योग संस्थान तथा ३३ प्रसार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

१६५६-५७ में हयकर्षे का उत्पादन १६००० लाख गज़ था जो १६५५-५६ के उत्पादन से १३०० लाख गज़ ऋधिक था । १६५७-५८ में श्रनुमानित उत्पादन १६५००लाख गज़ था। श्रव तक की प्रगति लक्ष्य से कहीं कम है। १६५७ के श्रन्त तक श्रम्बर सूत से उत्पादित कपड़ा ७० लाख गज़ था। ऐसा प्रतीत होता है कि १५०० लाख गज़ का संशोधित लक्ष्य योजना काल के श्रन्त तक पूरा नहीं होगा। पुरानी ढंग की खादी का उत्पादन ३५० लाख गज़ के श्राचार भूत उत्पादन से ५० लाख गज़ प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। खादी उत्पादन के लिये कई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था। शक्तिचालित करघों की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त लक्ष्य भी श्रव तक नगरय हैं।

श्रध्याय २१

श्रोद्योगिक उत्पादन श्रीर नियोजन

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजकीय तथा निजी उद्योग क्षेत्र में श्रीद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई थी। अंतर केवल इतना था कि राजकीय उद्योग चेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार ने अपने कपर ले लिया या परन्तु निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये थे। यह भ्राशा प्रकट की गई थी कि निजी उद्योग योजना की स्रविध समाप्त होने तक इन लक्ष्यों तक पहुँच जाँयेगे । पुर्नपरीज्ञित योजना को कार्यान्त्रित करने के लिये निर्घारित २३५६ करोड़ इपयों में से १७६ करोड़ इपया श्रर्थात् कुल व्यय का ७.६% उद्योगों श्रीर खान खोदने पर व्यय करना था जिसमें से बड़े श्रीर मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर १४८ करोड़ रुपया, खानी के सुधार पर १ करोड़ रुपया श्रीर छोटे उद्योगों पर ३० करोड़ रुपया व्यय करना था। इखन बनाने के चितरंजन कारलाने श्रीर रेल के लिये इस्पात की कोच बनाने के कारलाने में जो कुछ वनराशि लगाई गई वह रेलवे विकास योजन का एक अंग थी। इस प्रकार श्राघार भूत उद्योगों श्रीर यातायात के लिये निर्घारित ५० करोड़ की धनराशि पृयक करके सम्पूर्ण राजकीय विकास कार्य कम में ५ वर्ष के झन्दर ६४ करोड़ रुपया निर्घारित किया गया। राजकीय श्रीद्योगिक चेत्र में जो रुपया लगाया गया उममें लोहे तथा इस्पात के नये कारखाने, इखन बनाने के चितरखन कारखाने, मैसर में मशीन श्रीज़ार बनाने के कारखाने, सिन्द्री के रसायनिक खाद के कारखानों श्रीर पेनिसिलिन, डी० डी० टी०, यन्त्र, टेलीफीन इत्यादि बनाने के कारलाने की विभिन्न योजनाश्रों को कार्यान्वित किया गया। जितने उद्योगों की सरकार सरलता से व्यवस्था कर सकती थी उन पर श्रिधिकार कर लिया गया श्रीर शेष निनी चेत्र के लिये छोड़ दिये गये। इस मिश्रित श्रर्थ न्यवस्था से यह लाम है कि राजकीय उद्योग चेत्र का उस सीमा तक प्रसार किया जा सकता है जितना व्यवहारिकता दृष्टि से सम्भव है श्रीर निजी उद्योग की श्रपने साधनों, कुशलता एवम् श्रनुमव के द्वारा देश का श्रीयोगिक विकास करने का श्रवसर मिलता है।

योजना श्रायोग ने श्रनुमान लगाया था कि योजना में उत्पादन के निर्घा-रित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये निली उद्योग चेत्र में पाँच वर्ष के श्रन्दर कुल २३३ करोड़ रुपया लगाना पढ़ेगा। यदि इसमें मशीनों को परिवर्तन तथा उद्योग का श्राधुनिकीकरण करने के लिये १५० करोड़ श्रीर चालू पूँजी के लिये ३२४ करोड़ की धनराशि समिजित कर दो जाय तो पाँच वर्ष में निजी उद्योग चित्र में कुल ७०७ करोड़ रुपया लगाया जायगा। भारतीय उद्योगपितयों ने इस योजना की श्रालोचना की। उनका कहना था कि (श्र) उद्योग के श्राधुनिकीकरण के लिये १५० करोड़ रुपया श्रपर्याप्त है चयों श्रि श्रिधिकांश उद्योगों की मशोनें प्राय: व्यर्थ हो गई हैं। योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये श्रावश्यक मशीनों का प्रवन्य करने में इससे कहीं श्रिधिक रुपयों की श्रावश्यकता होगी; (व) सरकार ने केवल श्रावश्यक घन की मात्रा चता दो है, परन्तु उसकी प्राप्ति की व्यवस्था नहीं की है। उद्योगों के पास ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे यह कार्य किये जा सकें; भारतीय पूँजी वाज़ार की ऐसी स्थित नहीं है कि इतना घन प्राप्त किया जा सके श्रीर विदेशी पूँजी भी प्राय: उपलब्ध नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि निजी उद्योगों का योजना में निर्धारित उत्यादन के लक्ष्यों की पूरा कर सकना सम्भव नहीं है।

योजना में उद्योगों को जिल क्रम से प्राथमिकता दी गई थी उससे स्पष्ट है कि श्राधारभूत एवम् प्रमुख उद्योगों के साथ ही ऐसे उद्योगों को श्रिषक महत्व दिया गया जिनका श्रमेद्वाकृत बहुत कम विकास हुश्रा था। यदि राजकीय तथा निजी उद्योग चित्रों को एक साथ मिला कर देखा जाय तो यह शात होगा कि कुल व्यय का २६ मितरात धातु योधन उद्योगों के लिये, २० मितरात पेट्रोल शोधन शालाशों के लिये, १६ मितरात इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये, प्रमितरात स्ती उद्योगों के लिये, ५ मितरात सीमेंट श्रीर लगभग ४ मितरात कागज, पट्ठे तथा अखगरो कागज उद्योग के लिये निर्धारित किया गया था। इसका श्रम्य यह या कि जिन उद्योगों का श्रमी विकास नहीं हो पाया था उन पर श्रिषक व्यय किया जाय। वर्तमान उद्योगों को छोड़ा नही गया था बिल्क उनके लिये कम धनराशि निर्धारित की गई थी। ऐसा उचित मी था। देश के सभी उपलब्ध साधनों का श्रच्छे से श्रच्छा उपयोग करने के उद्देश्य से ही यह व्यवया की गई थी। श्रीयोगिक विकास कार्यक्रम के लिये योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता-क्रम दिया गया है।

⁽१) जुट श्रीर प्लाइबुढ जैसे उत्पादक वस्तु उद्योग श्रीर स्ती कपड़े, चोनी, खाबुन, बनस्पति, रंग श्रीर वार्निश जैसे उपभोग की वस्तुश्रों के उद्योगों की वतमान उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाय।

⁽२) लोहे तथा इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, रसानिक खाद, भारी

रसायनिक, मर्शीनों के श्रौज़ार इत्यादि उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति को बढाया जाय।

- (३) जिस उद्योग को आरंभ करने के लिए कुछ पूँजी लगा दी गई है उसे पूरा किया जाय।
- (४) देश के श्रीद्योगिक ढाँचे को श्रीघक शक्तिशाली बनाने के लिए श्रपने साधनों को ध्यान में रखते हुए नये कारखाने स्थापित किये जायेँ जैसे जिप्सम से गन्यक का उत्पादन किया जाय।

प्रयम योजना में उद्योगों के तीन वर्ग किये गये थे। (१) जूट श्रोटोमींवाइलस्, मशीन व श्रीजार कपड़े की मशीन तथा चूड़ी के उद्योगों के सम्बन्ध में जिनकी उत्पादन शक्ति प्रयाप्ति थी, इस बात पर महत्व दिया गया कि वे श्रपना उत्पादन वढ़ाकर श्रपनी श्रनुमानित शक्ति के स्तर पर ले श्रार्वे जो बदली नहीं जायगी; ढले हुये लोहे, इस्पात, चीनी, सीमेंट, कागज ब्रीर कागज के पहे, दियासलाई तथा कुछ रषायनिक वस्तुन्नों का उत्पादन करने वाले उद्योग जिनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया या कि उनकी ऋनुमानित शक्ति बढ़ाई तो नायगी पर १०० र्पातरात से कम । इनके अन्तर्गत सीमेंट, सलफ्यूरिक ऐसिड, दला हुआ लोहा, वैयार इत्पात, कागज और कागज के पट्टे, दियासलाई, स्टोरेज वैटरी और विजली के पंखे बनाने वाले उद्योग भी सम्मिलित कर लिये गये ये; (३) विजली से चलने वाले पम्पों, डिज़िल इंजनों, मीने की मशीन, बाइसिकिलों इत्यादि उद्योगों का जिनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति माँग के अनुपात में कम है काफ़ी प्रसार करने की योजना बनाई गई यो। इसी श्रेग्सी में श्रन्य उद्योग भी श्राते हैं जैसे काटन जिन्टर्स, केमिकल पल्य, कुछ दवाइयाँ इत्यादि जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता था परन्तु श्रव इनके उत्पादन की व्यवस्या की गई थी। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना में देश के श्रीद्योगिक विकास की कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया गया था।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रीद्योगिक श्रीर खनिज पदार्थों के विकास को प्रथम योजना की श्रपेत्वा श्रिषक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वास्तव में द्वितीय योजना श्रीद्योगिक विकास पर केन्द्रित है। द्वितीय योजना में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से ८६० करोड़ या १८५% उद्योगों पर व्यय किया जायगा जब कि प्रथम योजना के कुल २,३५६ करोड़ रुपयों के व्यय में से उद्योग पर १७६ करोड़ रुपये या ७ ६% व्यय किया जाना या। द्वितीय योजना प्रथम की श्रपेत्वा श्रिषक विस्तृत है श्रीर इसमें व्यय भी बहुत श्रिषक किया जा रहा है। उद्योगों को श्रिषक महत्व देने का कारण देश

के आर्थिक विकास को अधिक संतुलित करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और वेकारी आदि को कम करना है। दितीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में प्राथमिकता निस प्रकार दी गई है।

- (१) लोहे और इस्पात तथा भारी रखायनिक उद्योगों का निर्माण करना' जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद श्रीर इन्जीनियरिंग तथा मशीनों के निर्माण सम्बन्धी उद्योग सम्मिलित है।
- (२) विकास सम्बन्धी वस्तुश्रों तथा उत्पादन में कार्य श्राने वाली वस्तुश्रों, जैसे श्रलमोनियम, सीमेंट, रसायनिक पल्य, रंग, फास्केट युक्त खाद श्रीर श्रात्यनत श्रावश्यक दवाईयाँ श्रादि की उत्पादन शक्ति में विस्तार करना।
- (३) महत्वशाली राष्ट्रीय उद्योग, जो स्थापित हो चुके हैं, जैसे जुट श्रीर स्ती कपड़े बनाने तथा चीनी उद्योग श्रादि, उनके प्रसाधनों की वृद्धि श्रीर उनका श्राभिनवीकरण।
- (४) उन उद्योगों की उत्पादन शक्ति में जिनकी उत्पादन शक्ति श्रीर वास्त-विक उत्पादन में श्रन्तर है वृद्धि करना।
- (५) साधारण उत्पादन के कार्यक्रमों तथा उद्योगों के विकेन्द्रित श्रंश के उत्पादन लक्ष्य के श्रनुसार उपभोग की वस्तुश्रों के उत्पादन में वृद्धि करना।

श्रीशोगिक विकास के कार्य कम के दृष्टिकोग से द्वितीय योजना की. श्रमेकों विशेषतार्ये हैं:—

(१) इसमें राजकीय त्रेत्र को न्यक्तिगत त्रेत्र से श्रिषक महत्ता दी गई है। दितीय योजना की नवीनता इस बात में है कि राजकीय त्रेत्र में श्रीद्योगिक श्रीर खिन उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों को प्रधानता दी गई है। मारत में कुछि, विद्युत शिक, यातायात, तथा सामाजिक सेवाश्रों के विकास के सम्बन्ध में राजकीय उपक्रमों पर निर्मरता श्राधिक योजना की विशेषता है। परन्तु श्रमी तक तो राजकीय त्रेत्र के श्रन्तर्गत किये गये विनियोग में उद्योगों श्रीर खिनज सम्बन्धी योजनाश्रों को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त हुश्रा था। प्रथम योजना में राजकीय त्रेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये केवल ६४ करोड़ रुपयों के विनियोग का प्रबन्ध किया गया था, जबिक व्यक्तिगत त्रेत्र में २३३ करोड़ रुपयों के विनियोग का श्रमुमान किया गया था। दितीय योजना के श्रन्तर्गत राजकीय त्रेत्र में बड़े उद्योगों श्रीर खिनज के विकास के लिये (वैज्ञानिक श्रन्वेषण कार्य पर व्यय सम्मिलत करते हुये) ६६० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जब कि व्यक्तिगत

चेत्र में उद्योगों श्रीर खानों पर न्यय किये जाने के लिये केवल ५७५ करोड़ रुपयों का ही प्रवन्य है। न्यक्तिगत चेत्र को यद्यपि देश के श्रीद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ा भाग लेना है फिर भी यह प्रत्यच्च है कि राजकीय चेत्र की योजनाश्रों पर न्यक्तिगत चेत्र की योजनाश्रों पर न्यक्तिगत चेत्र की योजनाश्रों से श्रपेचाकृत श्रिषक महत्व दिया गया है।

(२) योजना की दूसरी विशेषता यह है कि मुख्य श्रीर श्राघार उद्योगों का विकास उपभोग की वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की श्रपेक्षा श्रिषक किया जायगा। प्रतिष्ठापित उत्पादन शक्ति के श्रायोजित विकास तथा प्रस्तावित उत्पादन सम्बन्धी १६६०-६१ के श्रांकड़े यह प्रकट करते हैं कि लोहे श्रीर इस्तात, इन्जीनियरिंग तथा रसायनिक उद्योगों के श्रधिकतम प्रसार का श्रायोजन किया गया है। भारत में प्रथम बार मशीन निर्माण उद्योग के विकास का श्रायोजन किया गया है। सत तथा जूट विनने की मशीनों के तथा सीमेंट श्रीर चीनी वनाने की मशीनों के श्रीर छोटे छोटे श्रीजारों के उत्पादन के उद्योग तो भारत में पहिले से ही स्थित हैं, पर उनका बहुत श्रिषक विस्तार कर दिया जायगा। कागज तथा छपाई उद्योग के उत्पादन का मूल्य १६६०-६१ तक क्रमशः ४ करोड़ चपये तथा २ करोड़ चपये तक हो जायगा। वर्तमान समय में तो इन वस्तुर्श्रों का उत्पादन नगयय ही है।

वड़े उद्योगों श्रीर खनिज उद्योग पर जो ६६० करोड़ रुपया व्यय किया जाने वाला है वह लगमग पूर्ण रूप से मूल उद्योगों के विकास के लिये हैं, जैसे लोहा-इस्गत, कोयला, खाद, इन्जीनियरिंग तथा बड़े बड़े विजली के प्रसाधन इत्यादि। योजना में तोन इस्पात संयोगों को स्थापना रूरकेला, भिलाई, श्रीर दुर्गपुर में होगी जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन इस्पात पिंगडों की होगी। इसके श्रांतिरिक्त इनमें से एक संयन्त्र ती ३५०,००० टन दला हुआ लोहा विक्री के लिये उत्पादित करेगा। राजकीय चेत्र के श्रन्तर्गत सब योजनाओं से श्राशा की जाती है कि कुल इस्पात की उत्पादित मात्रा लगमग २० लाख टन दितीय योजना के श्रन्त तक हो जायगी।

इन्जीनियरिंग के बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में चित्तरन्जन खोकोमोटिव फैक्ट्री में एक बड़ी इत्यात फाउन्ड्रो को स्थापना भी सम्मिलित है। इस बात का महन्म किया जा रहा है कि बड़े बढ़े बिजली के मसाधनों का निर्माण राजकीय चेत्र में हो। इसिलये चित्तरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री का विस्तार होना परमावश्यक है ताकि वर्तमान समय के १२५ इन्जिनो के वार्षिक उत्यादन के स्थान पर ३०० इन्जनों का प्रतिवर्ष उत्यादन हो जाय। दि इन्टीगरल कोच फैक्ट्री जिसने उत्यादन कार्य १६५६ में आरम्म किया लगमग ३५० कोच प्रतिवर्ष १६५६

तक उत्पादित कर सकेगी । एक नई मीटर गेज कोच फैक्ट्री की स्थापना का भी

(३) दितीय-योजना में आम्य श्रीर छोटे उद्योगों को प्रथम योजना की श्रमेचा श्रिष्क महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है श्रीर यह प्रस्ताव किया गया है कि उन पर प्रथम योजना के ३० करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर श्रब २०० करोड़ रुपया व्यय किया जाय। शाम्य श्रीर छोटे उद्योगों को इतना महत्व देने का मुख्य कारण यह है कि देश की श्रार्थिक व्यवस्था के विकेन्द्रित भाग में कार्य करने के श्रिषक श्रवसर प्रदान कर सकेंगे।

समालोचना—दितीय योजना प्रथम योजना की अपेना अधिक विचार
पूर्ण है। इस योजना में यह उचित ही है कि क्रिक को तुलना में अयोगोगिक विकास
पर अधिक महत्व दिया गया है। इससे देश का संतुलित विकास सम्मव हो उनेगा
और जो देश की आर्थिक व्यवस्था में अभाव रह गए थे वे पूर्ण हो जायेंगे। यह
भी बहुत उपयुक्त है कि बड़े मूल और मशीनों के निर्माण के उद्योगों के प्रति
विशेष ध्यान दिया है। इन्हों के आधार पर भारत का भावी औद्योगिक विकास
सम्मव हो सकेगा। यह सब होते हुए भी दितीय योजना में अनेकों गम्भीर दोष
रह गये हैं।

(१) राजकीय खेत्र का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया है। यदि सरकार के पास घन के स्नात, अधिमिक ज्ञान, उद्योगों के आरम्म करने की स्नमता आदि होती तन तो इसमें कोई हानि की सम्मात्रना न होती, परन्तु सरकार के पास तो ये पर्याप्त मन्ना में नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेकों उद्योग जो राजकीय चेत्र के अन्दर सम्मिलित कर लिये गये हैं उनमें राजकीय चेत्र से जितना साहस प्राप्त हो सकता है उसकी अपेदाा अधिक जोखिम उठाने और साहस की आवश्यकता है। अन्त में यह भी कहा जाता है कि राजकीय चेत्र को आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर देने से व्यक्तिगत चेत्र के लिये सुगमता पूर्वक कार्य करते रहने के लिये जितने साहस की आवश्यकता है उससे बहुत कम का अवसर छोड़ा गया है। इसमें साब्द रूप से यह भय लिखत होता है कि राजकीय चेत्र अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण न कर सकेगा।

(२) यद्यपि व्यक्तिगत चेत्र पर कुछ, वस्तुश्रों की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन करने का उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, परन्तु इसके लिये न तो पर्यात मात्रा में वित्त की उपनिध्य का कोई प्रवन्ध किया गया है श्रीर न ऐसी सुविधार्य ही प्रदान की गई हैं जैसे श्रवच्याया के लिये वृद्धि श्रयवा करों से छूट श्रादि, जो कि व्यक्तिगत चेत्र के सरलता से कार्य करते रहने के लिये श्रावश्यक

हैं। राष्ट्रीय श्रीद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) जिसकी १६५४ में स्थापना की गई थी व्यक्तिगत चेत्र में उद्योगों के विकास में बहुत सहायता पूर्ण कार्य कर रहा है। द्वितीय योजना में भी यह संस्था व्यक्तिगत चेत्र में सहायता का कार्य करती रहेगी। यह सब होते हुये भी यह निश्चत रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत चेत्र को वित्त संकट उठाना पह रहा है, जिससे श्रीद्योगिक विकास में वाघा पढ़ रही हैं।

(३) भारत के श्रौद्योगिक संगठन में महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण यह सर्वथा उपयुक्त है कि श्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों के विकास का प्रयत्न किया जाय, परन्तु यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि बड़े उद्योगों पर उपकर श्रारोपित किया जाय श्रयवा उनके उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, जिससे कि शाम्य श्रीर छोटे उद्योगों की रच्चा हो सके। इससे कार्यारम्भ का साहस नष्ट हो जाता है श्रीर कोई प्रभावशाली सहायता भी श्राम्य श्रयवा छोटे उद्योगों को नहीं मिलती। इन उद्योगों की समस्या को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुश्रों के गुणों की उन्नति करके, तथा उनके मूल्य को घटा कर करना चाहिये न कि बड़े उद्योगों पर प्रतिबन्ध द्वारा।

द्वितीय योजना के श्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम में उपर्युक्त दोषों के होते हुये भी यह श्राशा की जाती है कि इससे श्रौद्योगिक विकास की गति में श्रवश्य बृद्धि होगी, तथा श्रौद्योगिक विकास संगठन के श्रभावों को पूर्ण करके यह योजना संतुलन स्यापित करेगी श्रौर संसार में भारत का श्रौद्योगिक स्तर ऊँचा उठायेगी।

योजना की प्रगति—"१६५७-५८ तक पहली योजना में प्रारम्म की गई अनेक श्रीधोगिक योजनाएँ पूर्ण हो गईं। इन योजनाश्रों में श्रलवये का डी॰ डी॰ टी॰ का कारखाना, दिल्ली के डी॰ डी॰ टी॰ कारखाने का विस्तार, हिन्दु-स्तान एन्टीवायोटिक्स (कारखाने) का विस्तार, मैस्र में सरकारी पोर्श्लीन फैन्ट्री की पोर्श्लीन इन्सुलेटर्स स्कीम, मैस्र श्राहरन एएड स्टील वर्कस का spun-pipe का कारखाना, बिहार की सुगर फासफेट फैन्ट्री तथा NEPA कारखाने में संग्रलन उपस्कर की व्यवस्था श्राद सम्मिलत थे। इन योजनाश्रों के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप डी॰ डी॰ टी॰ निर्माण करने की शक्ति में २१०० टन की, पैन्सिलीन के सम्बन्ध में १६२ लाख मीगा इकाइयों की तथा सुपर फासफेट की उत्पादन शक्ति में २३,००० टन की वृद्धि हो गई। NEPA ने प्रतिवर्ष ३०,००० टन श्रखवारी कागज़ का उत्पादन करने की श्रपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लिया। २५०० टन इन्सुलेटर्स के निर्माण की शक्ति श्रथवा समर्थ की मी स्थापना हुई। दितीय योजना में इन स्कीमों पर ३ करोड़ ६० व्यय करने की व्यवस्था थी।"

श्राशा की जाती है कि १६५८-५६ में निम्न श्रौद्योगिक स्कीम पूरी हो जॉयगी।

नयी श्रयवा श्रतिरिक्त शक्ति या सामर्थ्य
४७,००० टन नाइट्रोजन
७००,००० टन प्रतिवर्ष ढला लोहा
' (pig iron)
२८५,००० दन कोक
(hard coke)
४०० (hathes, millingl ग्रीर
drilling machines)
५३० मील केविल ग्रीर ३०० मील
co-axial cables.
गभग २१ करोड़ रु है तथा १२ करोड़
। योजना काल में पूरी हो जाँयगी।
नई श्रथवा श्रितिरिक्त सामर्थ्य
२२ लाख टन स्टील, तथा ६००,०००
टन दला हुआ लोहा (pig Iron)
७०,००० टन नाइड्रोजन (fixed)
३५ लाख टन लिगनाइट
४५००० किलोगाम स्ट्रेप्टोमाइसीन
•
१५००० टन फैरो-सिलीकन
२००० टन इन्सुलेटर्स
८-१२ जहाज प्रतिवर्ष वनाने की ज्ञमता
के लिये विस्तार,
२३१००० टन सीमेन्ट,

अध्याय २२

सरकार की श्रौद्योगिक नीति

मारत सरकार की श्रीद्योगिक नीति का श्राघार १६५३ के श्रीद्योगिक (विकास श्रीर नियमन) संशोधना कानून द्वारा संशोधित १६५१ का श्रीद्योगिक (विकास श्रीर नियमन) कानून है। सरकार की नीति 'मिश्रित श्रार्थिक व्यवस्था' पर श्राधारित है जिसमें राजकीय उद्योग तथा निजी उद्योग दोनों का स्थान है। इस कानून में भारत सरकार ने जिस श्रीद्योगिक नीति का निरूपण किया है वह मारत सरकार के उस कक्कव्य से बिल्कुल भिन्न है जो उसने संसद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताब के रूप में ६ श्राप्तेल १६४८ को दिया था।

श्रीचीिक नीति का उद्देश्य देश के श्रीदीिक साधनी का यथा सम्भव गति से सन्त्रलित विकास करना होना चाहिये। यदि यह कार्य पूर्णतया निजी उचोगों को ही समर्पित कर दिया जाय तो यह उद्देश्य पूर्णत: प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि पँजी का श्रमाव, उद्योग के लिये श्रावश्यक सामान श्रीर मशीनों का अभाव, श्रीद्योगिक कुशलता का श्रमाव श्रीर उद्योगपति की शीव लाम उठाने की श्रमिलापा इस दिशा में वाधक बन जाते हैं। इस कारण श्रव तक उपमीग की वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर मशीनों इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों की अपेका अविक महत्व दिया जाता रहा है इसीलिए निजी उद्योगों पर नियत्रंश रखा जाना श्रीर साथ ही राज्य के द्वेत्र में उद्योग पर संचालन तथा प्रवन्ध श्रावश्यक प्रतीत होता है। बहुत समय से इस नीति का समर्थन किया जाता रहा है कि राज्य को निजी उद्योगों पर नियंत्रण रखना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि निजी उद्योगों को सहायता दी जाय, उनको विकास के लिये प्रोत्साहित किया नाय, रावकीय उद्योग का चैत्र निश्चित किया जाय, निजी उद्योग को अनुचित कठिनाइयों और उलकतों में न पड़ने दिया जाय श्रीर एक श्रीदोगिक संस्था को दूसरी श्रीद्योगिक संस्था का शोषण न करने दिया जाय। परना भारत सरकार की श्रीद्योगिक नीति इसके विपरीत है। इससे मारत के उपयुक्त श्रीद्योगिक विकास की सम्भावना नहीं है। इस नीति को नकारात्मक नीति कहा जा सकता है। इसमें निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उन वार्तों का उल्लेख किया गया है जिनको करने के लिये राज्य श्रन-मित नहीं देगा। इसमें यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि राज्य निजी उद्योगों को सहायता देने के लिए क्या करेगा। यह नीति यथार्थवादी नहीं है क्यों कि

इसमें भारत में निजी उद्योग की वर्त्तमान स्थिति और उसके संगठन तथा अपकार-प्रकार पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विवरीत निजी-उद्योग चेत्र में कुछ ऐसी वार्ते लागू की गई हैं जिनकी उपयोगिता पर सन्देह प्रगट किया जा संकता है, जो देश के श्रीद्योगिक विकास में सहायक होने की श्रपेन्ना बाधक हो सकते हैं।

६ अमैल १६४८ का श्रोद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव- १६४८ में घोषित श्रौद्योगिक नीति में 'मिश्रित' श्चर्य व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। परन्तु राष्ट्रीयकरण का विषय इसमें विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। वास्तव में 'मिश्रित श्रर्थ व्यवस्था' के सिद्धान्त में ही 'राष्ट्रीयकरण' का विचार निहित है। परन्तु सरकार ने अपनी घोषणा में इसकी चर्चा करके इसे श्रिविक स्पष्ट कर दिया। इस घोषणा में उद्योगों को तीन श्रेणियों में विमाजित किया गया था। (१) प्रथम श्रेणी के उद्योगों में हथियारों श्रीर गोला-बारूद का उत्पादन, श्राण-शक्ति का उत्पादन श्रीर नियंत्रण श्रीर रेलवे परिवहन का प्रवन्य तथा स्वामित्व सम्मिलित किये गये थे। इन उद्योगी पर राज्य को पूर्ण एकाधिकार दिया गया। इस न्यवस्था से विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि ये उद्योग पहले से ही राज्य के अधिकार में और इस बात की बहुत कम सम्मावना है कि भारत में, निजी उद्योग इनमें से किसी एक की भी श्रपनाने के लिये तैयार होगा। वास्तव में दितीय और तृतीय श्रेणी के उद्योगों पर ही इस श्रीद्योगिक नीति का महत्य निर्मर करता है। (२) द्वितीय श्रेगी के उद्योगों में कोयला, लोहा, इस्पात, विमान-निर्माण जलयान-निर्माण, टेलीफोन, तार तथा वेतार के तार के यंत्रों का निर्माण और पेट्रोल इत्यादि खनिज तेल सम्मिलित किये गये हैं। इन उद्योगों के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि इस श्रेगी के नवीन कारखानों को स्थापित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल राज्य पर होगा श्रीर जो वर्तमान समय में चालू कारखाने हैं उनकी दस वर्ध में पुनः जाँच की जायगी श्रीर यदि श्रावश्यक हुत्रा तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा। इस व्यवस्था का निजी उद्योग पर हुरा ममाव पड़ा। इससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया। उद्योग में सुधार करने के लिये जो कुछ रुपया लगाया जायगा उसका लाभ उठा सकने के लिये १० वर्ष का समय बहुत कम है। श्रीर चॅ्कि नथे कारखाने स्थापित करने का पूर्ण भार राज्य ने स्वीकार कर लिया, इससे इस श्रेगी के उद्योगों में निजी उद्योग के मालिकों की रूचि कम हो गई इस द्वेत्र में उनका सम्पूर्ण उत्साह समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप श्रीद्योगिक उत्पादन घट गया, पूँजी निर्माण की प्रक्रिया घीमी पड़ गई श्रीर श्रीद्योगिक चेत्र में कुछ छीमा तक मन्दी श्रा गई। यदि

राज्य नवीन कारखाने स्थापित कर उत्पादन कार्य आरम्म कर देता तो इससे विशेष हानि की संमावना नहीं थी। परन्तु भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास इस कार्य के लिये आवश्यक घन, साहस और कुशल कर्मचारियों का अभाव है। फल स्वरूप देश की औद्योगिक स्थित प्रगति करने की अपेक्षा अवनत होती गई। (३) शेष उद्योगों को तीसरी अंगी में रखा गया। यद्यपि इस अंगी के उद्योगों को निजी उद्योग चेत्र के लिये छोड़ दिया गया परन्तु यह मी कहा गया कि राज्य इस चेत्र में भी कमशः भाग लेगा। परन्तु साधनों के अभाव के कारस राज्य इस चेत्र में सिक्तय नहीं हो सका।

नवीन औद्योगिक नीति—३० श्रप्रैल १९५६ को वोषित नवीन श्रीयोगिक नीति १९४८ के श्रीयोगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा से मिलती जुलती है, श्रीर उद्योगों को राज्य द्वारा उनमें भाग लेने के श्राधार पर ३ वर्गों में विभाजित करती है। प्रथम वर्ग में १७ उद्योगों की गण्ना की गई है जिनमें कोयला, लोहा श्रीर इस्पात, खनिज-तेल, सामान्य श्रीर विद्युत इन्जीनियरिंग के कुछ श्रंश श्रीर परिवहन सम्बन्धी कुछ ऐसे उद्योग श्राते हैं जिनके भावी विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य के ऊरर है। द्वितीय वर्ग में लगमग एक दर्जन उद्योग सम्मिलित किये गये हैं, जैसे मशीन के यन्त्र, श्रलमुनियम, खाद, सहक श्रीर समुद्री परिवहन इत्यादि जिनमें व्यक्तिगत श्रीर राजकीय उपक्रम साप-साय वर्लोगे परन्तु यह कमशः राजकीय श्रिवकार में श्रा जायेंगे, इस लिये इन में नवीन उपक्रमों के स्थापित करने में राज्य श्रियगणी होगा। शेष उद्योग जैसे स्ती कपड़े, सीमेंट, चीनी इत्यादि तीसरे वर्ग में रक्खे गये हैं। इनका भावी विकास सामान्यतः व्यक्तिगत लेत्र से उपलब्ध कार्यारम्भ साहस पर निर्मर करेगा। राज्य को यह भी श्रिवकार होगा कि इस वर्ग के उद्योगों को भी श्रारम्भ कर सके।

उद्योगों के इस त्रिवर्गीय विमाजन में कोई दोष नहीं है। १६४८ के श्रीद्योगिक नीति प्रस्ताव के श्रमुसार संतोष प्रद ढंग से कार्य. हुश्रा है। परन्तु नवीन श्रीद्योगिक नीति के त्रिवर्गीय विमाजन में कुछ दोष श्रा गये हैं।

(१) राज कीय चेत्र के विस्तार में बहुत श्रिषक वृद्धि कर दी गई है श्रीर क्यक्तिगत चेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया गया है। इससे हानि यह होगी कि श्रीधोगिक ज्ञान वाले कर्मचारियों, संगठन करने की ज्ञमता, पूँजी तथा श्रानुभव के अभाव में राज्य उन उद्योगों का प्रबन्ध न पूर्णतः श्रौर न श्रिधकाँश ही कर सकेगा जिन्हें उसने अपने लिये सुरिद्धित कर रक्खा है। व्यक्तिगत उपकम इस कठिनाई को सुधार सकने में असमर्थ होगा क्योंकि नवीन नीति के श्रानुसार उन्हें यह कर सकने का कोई श्रीधकार ही न होगा श्रौर यदि सरकार उन्हें श्रामन्त्रित

भी करेगी तों उनमें इतना आत्म विश्वास न होगा कि वे ऐसा कर सकें। इस नीति के निर्माता इस कठिनाई से अनिभन्न नहीं थे । जो व्यक्ति व्यक्तिगत उप-क्रमों की कार्य प्रणाली और १६४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रभाव से परिचित हैं वे समक्त सकते हैं कि इस प्रयोगात्मक परिस्थित में व्यक्तिगत उपक्रम सम्मुख त्राने का साइस न कर सकेगें। प्रथम दोनों वर्गों में सम्मिलित व्यक्तिगत उद्योगों को चरलता से कार्य करते रहने के लिये श्रावश्यक वातावरण का श्रमाव है। यदि गत पाँच वर्षों के अनुभव का भरोसा करें तो यह आशा करना कि यदि राजकीय उपक्रम वाञ्छित लक्ष्य को पूरा न कर सके तो उनका स्थान व्यक्तिगत उपक्रम ले लेंगे, युक्ति संगत नहीं है। यदि प्रथम वर्गों में गिने गये कुछ उद्योगों को तीसरे वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता, जिसमें कार्यारम्म का मार व्यक्तिगत उपक्रमों पर है, तो निश्चित रूप से यह सम्मव होता कि वे किसी न किसी प्रकार ऋौद्योगिक ज्ञान, पँजी तथा अनुभव के अभाव को पूर्ण कर सकते जैसा कि गत २०० वर्षों से देखने में आया है। यह कोई तर्क नहीं है कि ओद्योगिक ज्ञमता, पूंजी, अनुभव आदि का सर्वथा अभाव है, और इस लिये राजकीय उपक्रम अथवा व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा इस समस्या को सुलक्ताने में कोई अन्तर नहीं पड़ता बहुत वड़ा अन्तर तो यह है कि व्यक्तिगठ उपक्रमों के पास उत्साह औद्योगिक समता श्रीर कार्य करने की शक्ति है श्रीर राजकीय उपक्रमों के पास इनका श्रमाव है। नवीन श्रौद्योगिक नीति के कारण विकास की गति बढ़ने के स्थान पर श्रवरुद हो जायगी।

- (२) १६४८ की श्रोद्योगिक नीति में वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये १० वर्ष की श्रवधि निश्चित की गई थी, श्रोर तीसरे वर्ग के उद्योगों के लिये यह स्पष्ठ रूप से कह दिया गया था राज्य उन्हीं उद्योगों को हस्तगत करेगा जिनकी प्रगति संतोषप्रद नहीं रही है। इससे व्यक्तिगत उपक्रमों को कुछ श्राशा बन्धी। परन्तु श्रव राज्य को श्रात्यधिक श्रधिकार देकर व्यर्थ में व्यक्तिगत उपक्रमों की सुरत्ता की मावना का श्रवहरण कर लिया गया है। यह राज्य के विचार श्रयदा श्रविचार से कार्य करने का प्रशन नहीं है वरन् यह तो व्यक्तिगत उपक्रम में विश्वास श्रीर संदेह की भावना उत्पन्न करती है तो उससे हम संतोषप्रद परिणाम की श्राशा नहीं कर सकते।
- (३) व्यक्तिगत उपक्रम की बहुत ही एंकुचित चेत्र प्रदान किया गया है जिसके कारण वे सरलता से कार्य नहीं कर सकते। मारत की श्रीद्योगिक नीति में जिस प्रकार राजकीय चेत्र का निश्चित स्थान है वैसे ही व्यक्तिगत चेत्र का भी है। व्यक्तिगत चेत्र के विस्तार को कम करने के किसी भी प्रयक्ष का स्वामाविक

परिशाम भारत के श्रीद्योगिक विकास को कम करना है। वर्तमान समय में प्रचलित आय और सम्पत्ति के अन्तर को कम करने, न्यक्तिगत एकाधिकार को रोकने ग्रीर श्रार्थिक शक्ति को थोड़े से व्यक्तियों के हाय में केन्द्रित होने से बचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह तर्क अधंगत है। इस बात को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत में राज्य को जो श्राधिकार श्राज प्राप्त हैं उनके द्वारा उद्योगों के व्यक्तिगत चेत्र में रहने पर भी वह एकाधिकार तया ग्रार्थिक शक्ति का केन्द्रित होना न रोक सके। जहाँ तक ग्राय के श्रन्तर का सम्बन्ध है वह तो त्रार्थिक तथा अन्य उपायों से पहिले ही काम किया जा चुका है। किर यह कैसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उद्योगों को राजकीय सेत्र में रखने से आधिक शक्ति केन्द्रित न होगी। श्रन्य देशों के श्रनुमव के अनुसार इसका परिगाम अधिक हानिकारक होगा। दूसरा कारण जिसके श्राघार पर वड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उपक्रमों का विस्तार व्यक्तिगत चेत्र में संकुचित किया गया है वह कुटीर, ब्राम्य ब्रीर छोटे उद्योगों की वहे उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाकर श्रीर भिन्न करारोप द्वारा श्रयवा प्रत्यन्त श्रनुदानों द्वारा वहायता करना है। मारत में प्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने में कोई दोष नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि इनका भारत की श्रीद्योगिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु बड़े उद्योगों को हानि पहुँचाकर छोटे उद्योगों की मगति करना सर्वया श्रविचारपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय श्राय श्रीर श्रीद्योगिक विकास में नृद्धि वहें उद्योगीं से ही सम्भव है। द्वितीय योजना का-ध्येय प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय बढ़ानां श्रीर वेकारी घटाना है। यदि बड़े उद्योगों का काल्पनिक श्रादशों के लिये उत्सर्ग कर दिया गया तो वह ध्येय कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत चेत्र के विस्तार को संकुचित कर देने का परिणाम यह होगा कि व्यक्तिगत उपक्रम उचित रीति से कार्य न कर सकेंगे।

नवीन श्रीद्योगिक नीति में वे गुण तो नहीं है जो कि १६४८ के श्रीद्योगिक नीति पस्ताव में थे, परन्तु उसके सब दोप उसमें वर्तमान हैं। १६४८ की नीति मस्ताव में थे, परन्तु उसके सब दोप उसमें वर्तमान हैं। १६४८ की नीति नकारात्मक थी श्रीर उसमें व्यक्तिगत उपक्रमों पर लगाये गये प्रतिदन्ध का ही केवल वर्णन था। राज्य से उन्हें क्या सहायता प्राप्त होगी इसके प्रति कोई संकेत नहीं था। यही दोप नवीन श्रीद्योगिक नीति में जनता को महान प्रतीत होने वाले निरर्थक श्रादशों के सम्मिश्रण के रूप में है। व्यक्तिगत उपक्रम की श्रात्यिक कर, श्रायकर के नियमों के श्रात्कृल उनके लिये पर्याप्त भात्रा में श्रावक्षयण वृत्ति का प्रवन्ध, श्रीर सरकार की श्रम श्रीर मूल्य नीति के कारण सदैव बढ़ते हुये उत्पादन व्यय से रक्षा श्रावश्यक है। राज्य को इस हष्टिकोण से

व्यक्तिगत उपक्रमों को निश्चित सहायता प्रदान फरनी चाहिये जिसते वे सफलता-पूर्वक ग्रापना कार्य कर सकें। सहायता का गया रूप होगा ग्रीर वह किस विधि से दी जायगी ग्रादि बानें सरकार की ग्रीयोगिक नीति का एक ग्रावश्यक ग्रंग वन जानी चाहिये जिससे कि वे सम्भव हो सकें।

१६४१ का उद्योग कानून—११५१ का उद्योग (विकास ग्रीर नियमन) कानून प्रथम श्रनुसूची में दिये गये उन ३७ उद्योगों पर लागू होगा जिनमें १ लाल से श्रिधिक पूँजी लगाई गई है। यह न्यवस्था की गई है कि इन सभी श्रीदोगिक संस्थानों को श्रीनिवार्य स्पर् से श्रपनी रिजस्ट्री करानी पड़ेगी। कोई नवीन कारखाना स्थापित करने के लिये श्रथमा पर्तमान कारखानों का प्रयार करने के लिये श्रथमा पर्तमान कारखानों का प्रयार करने के लिये श्रम्मा पड़ेगा।

कानून के श्रनुसार सरकार को यह श्रिधकार दिया गया है कि वह किसी भी श्रतुष्चित उद्योग की जीच करा एकती है श्रीर श्रायश्यक निर्देश जारी कर सकती है। इन निर्देशी का पालन न करने पर फेन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण उद्योग को या उनके किसी भाग को एक निश्चित काल के लिए किसी व्यक्ति, बोर्ट या विकास-परिषद के द्वार में सींप सकती है। परन्त यह श्रवधि ५ वर्ष से श्रधिक नहीं हो सकती। यह व्यवस्थाएँ श्रस्पष्ट श्रीर विस्तृत है। यह खेद का विषय है कि संगद ने जिस दिवीय प्रवर-समिति को यह विषेयक विचारार्थ संवि उसने प्रथम प्रवर-समिति की रिपोर्ट में दी गई उन शतों को रह कर दिया जिनके श्राधार पर राज्य इस्तर्जेन कर सकता था। प्रथम प्रवर समिति ने भिकारिश की थी कि यदि उद्योग के प्रबन्ध में अधिक श्रव्यवस्था फैली हो, वस्तुश्रों के भाव में श्रनुचित उतार-चढाव हो, बस्तुश्रों का श्रमाय हो, श्रमिको में श्रशांति एवम् ग्रसन्तोप हो श्रीर यदि सम्बन्यित उद्योग के कार्य में श्राने वाले कच्चे माल का श्रभाव श्रीर उसकी शीध समाप्ति को शेकना राष्ट्र हित में हो तभी राज्य को श्रपने नियंत्रण श्रीर हस्तत्तेव के श्रधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इन शतों से निजी उद्योग सन्तुष्ट या श्रीर यदि विघेयक इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो श्रीयोगिक विकास को हानि न उठानी पहती परन्त द्वितीय प्रवर-समिति द्वारा इन निश्चित शतों को रिपोर्ट में से निकाल देने के कारण किर वही श्रानिश्चितता फैल गई जो सरकार की भूतपूर्व श्रीयोगिक नीति से फैली थी।

इस कानून में केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद श्रीर विकास-परिपर्दे स्थापित करने की न्ययस्था की गई है। केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् में उग्रोगपितयों, कर्मचारियों श्रीर श्रनुयुचित उग्रोगों द्वारा उत्पादित माल के उपभोक्तार्श्रों के प्रति-निधि होंगे। इनके साथ ही कुछ ऐसे न्यक्ति भी इस परिषद् में सम्मिलित किए जा सकेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार टिचत समकेगी। श्रम्यक्त को छोए कर परिपद् की सटस्य संख्या ३० ने श्रिधिक नहीं होगी। । केन्द्रीय परामर्शेटात्री परिपद् श्रमु-स्चित उद्योगों के विकास श्रीर नियमन के सम्बन्ध में सरकार को मुक्ताय देगी।

किसी भी अनुस्चित उद्योग अथना उद्योगों के सन्ह के लिए विकासपित्पर्टें स्थापित की वा सकती हैं। विकास पित्पर्ट में उद्योग-तियों, कर्मचारियों
और उन उद्योगों द्वारा उत्यादित माल के उपमोक्ताओं के अतिनिधि होंगे। इसमें
ऐसे व्यक्ति भी सदस्य बनाये वा सकेंगे विन्हें सम्बन्धित उद्योग अथया उत्योगों के
बारे में विशेष टेकनिकल जान हो। विकास-पित्प्ट का कार्यचेत्र बहुत ब्यापक
बनाया गया है। सुख्यतः विकास परिपर्ट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करेंगी,
उत्यादन-कार्य में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मुक्ताय देंगी और समय समय
पर उद्योग अथया उद्योगों की प्रगति की समीक्ता करेंगी; इसके साथ ही इति
रोकने के लिए कुरालता के मान निर्धारित करेंगी, अधिकतम उत्यादन करने,
उत्यादन ब्यय करने और उत्यादित वस्तु की प्रकार में मुधार करने के लिए सुक्ताव
देंगी। विकास परिपर्टें उत्यादित वस्तु की प्रकार का एक निश्चित स्तर निश्चित
करेंगी और विकाय की व्यवस्था करेंगी और ऐसे उपाय मुक्तावेगी जिनसे अधिकों की उत्यादन-शक्ति में वृद्धि हो। जैसा पहले कहा जा चुका है सरकार उद्योग की
पूर्ण व्यवस्था अथवा उसका कुछ माग अधिक से अधिक भ वर्ष के लिए इन
विकास परिपरों के हाथ सींव सकती है।

विकास-परिपदों ते यह श्राशा की जाती है कि वह निजी उद्योग के लिए एक परिचारिका का कार्य करेंगी। १९५३ में ऐसी दो विकास परिपदें स्थापित की गई। बाद में श्रन्य विकास परिपदें स्थापित की गई। १९५७ के श्रन्त में १२ विकास परिपदें निग्न उद्योगों के लिये काम कर रही थीं।

- (१) भारी विद्युत् उद्योग,
- (२) इलका विद्युत् उद्योग
- (३) Internal Combustion Engines तथा राक्तिचालित पम्प

१. ८ मई १६५२ को कान्न लागृ होने के साथ ही फेन्ट्रीय परामर्शदार्थी परिषद् स्थापित की गई, वाश्विज्य तथा उद्योग-मन्त्री इसके खरयहाँ हैं। १६५४ में इसका पुर्नसंगटन किया गया और इसके सदस्यों की संस्था २६ कर दी गई जिनमें से १४ उद्योगपितयों के प्रतिनिधि (श्रनुस्चित उद्योग के), ५ कर्मचारी, ५ उपभोक्ता ख्रार ५ श्रन्य व्यक्ति जिनमें प्रारम्भिक उत्पादक सम्मिलित हैं। इससे यह परिषद् पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि परिषद् यन गई है।

- (४) साइकिल
- (५) अम्ल (acid) श्रीर उर्वरक
- (६) ज्ञार (alkali) तथा सम्बन्धित उद्योग
- (७) द्वाइयाँ
- (८) जनी कपड़ा
- (६) कलापूर्ण रेशमी कपड़ा
- (१०) चीनी (शकर)
- (११) श्रलीह घातुर्ये श्रीर मिश्रित घातुर्ये; तथा
- (१२) मशीन-ऋौजार

इन परिपदों का कार्य श्रपने-श्रपने उद्योगों की समस्याश्रों पर विचार करना। इनका ध्येय है उद्योगों को श्रपनी पूर्ण शक्ति भर उत्पादन कर सकने की सुविधाय प्रदान करना, उनको (रेटेड) श्रंकित शक्ति को श्रावश्यक स्तर तक बहाना, श्रीर उत्पादन व्यय को कम करना है।

विकास परिपरों की संस्था इम लोगों ने बिटेन से अनुसरण की है जहाँ पर इनकी स्थापना अनेकों उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में की गई थी। वहाँ ये परिपद असफल सिंद हुये पर इम लोग अन भी इनकों अपनाए हुए हैं। व्यक्तिगत उपक्रमों के सफलता पूर्वक कार्य करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें नित्य प्रति के कार्यों में प्रवन्ध कर्ता से पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त हो। उपक्रमों को कार्यारम्म करने का साइस और उत्साह होना चाहिये। यही एक आधार है जिस पर व्यक्तिगत उपक्रम से इम सफलता की आशा कर सकते हैं। प्रवन्ध करने में स्वतंत्रता की मात्रा में कभी करने के भय, इन परिपदों की कार्यप्रणाली की अनिश्चितता तथा किसी उपक्रम के आवश्यकता पढ़ने पर सरकारी प्रवन्ध में ले लिये जाने की अनिश्चित्तं शर्तें (बैसे विकास परिपद के निर्देशों का किसी उपक्रम हारा उलंबन) ये उपक्रमी वर्ग के मन में संदेह की भावना भर दी है। इसके अतिरिक्त परिषद एक ही प्रकार की संस्थायें तो है नहीं जो अपने अपने उद्योगों में से विकसित हुई हों, इसिलिये वे मनोवािक्त विकास नहीं कर सकती। यह भी सम्भव है कि विकास परिषद का इस्ताचेष सरकारी नियन्त्रणों से प्रस्त उपक्रमों के विनाश का अनितम कारण सिंद हो।

१६५३ का उद्योग (विकास और नियमन) संशोधन कानून—भारत. सरकार को १६५१ के उद्योग (विकास और नियमन) कानून को लागू करने के एक वर्ष पश्चात् ही संशोधन कानून का आधार लेना पड़ा। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि भारत की औद्योगिक नीति कितनी अनिश्चित है। ऐसी स्थिति

किसी प्रकार भी लामकर नहीं कही जा सकती है। संशोधन कान्त का विश्लेपण करने से जात होगा कि उसकी न्यवस्थाएँ पूर्व की अपेना अधिक दोपपूर्ण हैं। संशोधन कान्त के अनुसार किसो भी उद्योग पर सरकार परामर्शदाओं परिपद से पूछे बिना अधिकार कर सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सरकार निर्देश दे और उद्योग को स्पष्टीकरण का अवसर दे। सरकार के इन नवीन अधिकारों को प्राप्त करने से न्यापारों में उद्योगों के सम्बन्ध में और अनिश्चितता फैली है और इससे देश की अधिभिक्त प्रगति अवस्य हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं।

श्रव यह कानून ४२ उद्योगों पर लागू है, जिनमें श्रवली रेशम, नकली रेशम, रंग बनाने की वस्तुयें, सानुन, प्लाईयुट, फेरोमेगेनीज श्रादि ६ नवीन उद्योग भी सम्मिलित हैं। संशोधन द्वारा सरकार को यह श्रविकार प्राप्त है कि वे यदि चाहें तो ५ वर्ष के पश्चात् भी (जो श्रविष एक्ट में दी हुई थी) किसी उपक्रम का प्रवन्य श्रवने हाथों में रख सकती हैं। इसके लिये यह श्रावश्यक होगा कि नियंत्रण की श्रविष बहाने की एक विश्वित पार्लियामेंट के समझ उपस्थित कर दी जाय। सरकारी उपक्रमों को नई वस्तुश्रों के उत्पादन के लिये लाइसेन्छ लेने ते स्टूट दे दी गई है, यद्यि एक्ट में दी हुई प्रथम तालिका में श्रनुत्वित उपक्रमों को लाइसेन्छ लेना श्रिनवार्य है। सरकार को यह श्रविकार है कि यह जिन उद्योगों को श्रपने श्रविकार में ले उनके संगठन की शर्तों श्रीर नियमावली के विपरीत मी यदि चाहे तो कार्य कर सकती है। इस श्रविकार से हिस्सेटारों के सामान्य श्रविकारों को श्राधात पहुँचता है।

इन संशोधनों से उद्योग (विकास श्रीर नियमन) कानून बहुत कड़ा कानून बन गया हैं। श्रय केवल यह श्राशा की जाती है कि कानून को लागू करने वाले श्रिषकारी उन्द्रिलित दृष्टिकीश से कार्यवाही करेंगे श्रीर भारत के श्रीद्योगिक ढाँचे को सदैव के लिए नष्ट हो जाने से बचाएँगे।

राष्ट्रीयकरण की नीति—राष्ट्रीयकरण की नीति श्रयत्यज्ञ रूप से भारत सरकार की श्रीयोगिक नीति का एक श्रंग है। इसका संकेत उद्योग (विकास श्रीर नियमन) कानून की उस व्यवस्था से मिलता है जिसके श्रनुसार सरकार कुछ स्थितियों में निजी उद्योगों पर श्रपना श्रिषकार कर सकती है।

राष्ट्रीयकरण का ग्रर्थ है कि उत्पादन के साधनों पर जनता का ग्रधिकार हो। राज्य या तो श्रपने उद्योग स्थापित कर सकता है या चालू निजी इद्योगों को ग्रपने श्रधिकार में ले सकता है। राष्ट्रीयकरण का देश की सामाजिक, राजनैतिक, त्रार्थिक स्थितियों से निकट सम्बन्ध है। राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाय यह उस देश के श्रार्थिक विकास पर निर्भर करता है।

विद्वान्त रूप में राष्ट्रीयकरण की नीति का कई श्राधारों से समर्थन किया जा सकता है। प्रायः यह कहा जाता है कि निजी उद्योग देश के सभी उपलब्ध साधनों का न तो पूर्ण उपयोग करना चाहता है और न वह ऐसा कर सकने में समर्थ ही है, इसिलए बिना राजकीय उद्योगों में तीवता से प्रगतिशील श्रीद्योगी-करण नहीं किया जा सकता। निजी उद्योगों द्वारा उद्योग के श्राधुनिकीकरण श्रीर युक्तिकरण (Rationalisation) को श्रोर ध्यान न देने की प्रवृत्ति की श्रालोचना करके भी राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया जाता है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण हो जाने से अमिक-मालिक के सम्बन्धों में सुधार होगा श्रीर श्रमिकों के दूने उत्साह से कार्य करने के कारण उत्सादन भी बढ़िगा। राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का यह भी विश्वास है कि उद्योगों पर सरकार का श्रीधकार हो जाने से बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायगी।

परन्तु यह तर्कं सन्तोपजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय करण की किसी भी योजना को लाग करने से पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य के पास पर्याप्त पूँजी हो और उसे प्रशासन तथा सभी कुशल प्राविधिक सेवाएँ प्राप्त हों। राष्ट्रीय करण के पश्चात अमिक श्रीर उद्योग के प्रवन्यकों के सम्बन्धों में श्रीर तनातनी होने की संमावना है क्योंकि वर्तमान में इन दोनों के बीच राज्य संतुलन स्यापित करता है श्रीर जब कमी इनके बीच कगड़े उत्पन्न होते हैं राज्य उनमें इस्त होप करता है। परन्त यदि राज्य ही उद्योग का अधिकारी हो तो इस प्रकार के मनहों में राज्य स्वयं एक पत्त हो जायगा श्रीर इस कारण मध्यस्थता नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय-करण हो जाने से श्रीद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने का सिद्धान्त इस बात पर श्राधारित है कि जनतन्त्र में अमिक यह सममता है कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसी के हाथ में है। इसलिए उसका राज्य से कोई कगड़ा नहीं होगा। परन्तु यह केवल सिदान्त की बात है। यह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं है कि केवल राष्ट्रीयकरण हो जाने से ही अमिकों का स्वभाव बदल जायगा श्रीर वह श्रधिक कुशलता से श्रधिक परिश्रम कर उत्पादन बढ़ा देंगे। उत्पादन तभी बढ सकता है ग्रीर वेरोजगारी को तमी कम किया जा सकता है जब राज्य चाल उद्यांगों को ग्रपने श्रधिकार में करने की श्रपेक्षा नये उद्योगों को श्रारम्म करे।

राष्ट्रीयकरण की अपनी उपयोगिता होनी चाहिए। उसकी अपनी विशेष-ताएँ होनी चाहिए। केवल निजी उद्योगों में दोष होने के कारण ही राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाना उचित नहीं है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अनेक तर्क दिये जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप यह कहा जाता है कि उद्योगों पर राज्य का श्रिषकार हो जाने से प्रवन्य की कुशलता में श्रमाव श्रा जाता है क्योंकि राजकीय श्रिषकारी उतने सतर्क श्रौर उत्साही नहीं होते हैं जितना निजी उद्योगितयों से श्राशा की जाती है। राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों में प्रवन्धकों को सरकार कर्मचारी होने के कारण उद्योग से निजी लाभ उठाने की संमावना ही नहीं होती, इसलिए उन्हें न तो व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा होती है श्रीर न इस श्रोर कोई श्राकर्पण होता है। जिन उगद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उनका विकास करने के लिए श्रावश्यक पूँजी प्राप्त करने में श्रिषक कर लगाने की श्रावश्यकता पड़ सकती है श्रीर यह संभव है कि श्रार्थिक हिए से श्रिवक्षित देश की जनता कर? के इस श्रीतरिक्त भार का वहन करने में श्रमभर्य रहे।

भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार कुछ उद्योगों की अधिकारिणी हैं और उन्हें चलाती हैं जिनमें रेलचे, डाक-तार, प्रतिरक्षा सम्बन्धी कारखाने, टेली-फोन कम्पनियां और कुछ विजली की कम्पनियां समिलित हैं। गत कुछ वर्षों से अधिगिक चेत्र में राज्य का प्रवेश बढ़ता गया है। प्रीफेबीकेटेड हाउसिंग फैक्टरी १६४६ में स्यापित की गई और अगस्त १६५० से इसका उत्पादन कार्य आरम्म हुआ; चितरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री ने १६५० से कार्य आरम्म किया। यह सभी राज-कीय उद्योग हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दुस्तान विमान निर्माण उद्योग, प्रिसीजन इन्स्ट्र्मेंट फैक्टरी, नेशनल न्यूजप्रिन्ट और पेपर मिल्स लिमिटेड मी राजकीय उद्योग हैं। राज्य ने कुछ वर्तमान उद्योगों को भी अपने अधिकार में कर लिया है। १६५३ के विमान निगम कान्न के अन्तर्गत सरकार ने विमान उद्योग पर अधिकार कर लिया है।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती । राष्ट्रीयकरण होने से कम उत्पादन व्यय पर श्रिषक श्रीर श्रच्छा उत्पादन होना चाहिए । परन्तु मारत सरकार की राष्ट्रीकरण की नीति से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुश्रा है। इसके विपरीत इन उद्योगों में जनता के घन की श्रपार इति हुई है श्रीर उत्पादन में श्रनुचित देरी हुई है। इस सम्बन्ध में सिन्द्री खाद कारखाने का उदाहरण दिया जा सकता है। पहले यह श्रनुमान लगाया गया पा कि १० ५३ करोड़ रुपये में कारखाना स्थापित हो जायगा परन्तु श्रन्त में इस पर २३ करोड़ रुपया ज्यय किया गया श्रीर स्थापित होने के सात वर्ष पश्चात् इसमें उत्पादन कार्य श्रारम्म हो सका शीफेब्रीकेटेड हाउसिंग फैक्टरी द्वारा उत्पादित माल देश

के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुआ इसलिए उत्पादन आरम्भ होने के कुछ समय परचात् हो किमय के लिए मकानों का निर्माण बन्द कर दिया गया।

उक्त तथ्यों से जिनकी संख्या कम नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है कि राज्य सन्तोपजनक रीति से उद्योगों को चला सकने में असमर्थ है। इसका कारण यह है कि राज्य को इस सम्मन्य में अनेक संगठन-सम्मन्यी कठिनाइयों का सामना करना पहता है और विभिन्न समस्याओं को कुशलता पूर्वक इल करने के लिए उपयुक्त प्रशासन का अभाव है। योजना आयोग के कहने पर श्री ए० डी० गोरवाला ने राजकीय उद्योगों की कार्य-स्थित की जाँच की और जुलाई १६५१ में इस सम्मन्य में अपनी रिपोर्ट पेश की। श्री गोरवाला ने सुमाय दिया कि राजकीय उद्योगों को चलाने के लिए ६ सदस्यों की एक समित नियुक्त की जाय जो इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करेगी। इसका एक अध्यन्न होगा। यदि सरकार ने श्री गोरवाला की सिकारिशों को लागू किया होता तो उद्योगों का कार्य कुशलता पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता था।

संगठन सम्बन्धी इन सुधारों के श्रतिरिक्त यह श्रावश्यक है कि सरकार इस बात का श्राश्वासन दे कि उसके पास जो कुछ सीमित पूँजी है उससे चालू निजी उद्योगों को श्रापने अधिकार में कर मुखाबजा देने की श्रपेज्ञा नये कारखाने खोले जायँगे। वास्तव में श्रावश्यकता तो इस बात की है कि सरकार श्राधारभूत उद्योगों तथा ऐसे उद्योगों को चालू करे जिनको अनेक कारखों से निजी उद्योगपित श्रारम्भ नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार यह नीति श्रपनाये तो इससे उद्योगपितयों में मिविष्य के प्रति श्राधा जगेगी श्रीर राजकीय तथा निजी उद्योगों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा जिससे हमारे देश की श्राधिक प्रगति श्रविक तीव्रता से हो सकती है।

अध्याय २३

मनेजिंग एजेन्सी प्रणाली

कोई भी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी जिसे कम्पनी के साथ किए गए सममीते के अनुसार कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यों को व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है भैनेजिंग एजेन्ट कहलाता है। वह कम्पनी के संचालकों के नियन्त्रण में तथा निर्देशों के श्रनुसार या समसीते में दी गई श्रन्य न्यवस्था के श्रनुसार कार्य करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मैतेजिंग एजेन्ट ते श्राभिपाय उस व्यक्ति, पर्म या कंपनी से है जिसके हाथ में लगमग सम्पूर्ण कम्पनी का प्रवन्य है। श्रीर जिसको प्रवन्य करने का यह श्रधिकार या तो कंपनी से किये गये समनीते के ब्रानुसार मिला हो या कंपनी के नियमों के ब्रान्तर्गत निहित सममीते की शर्वों के अनुसार मिला हो। साधारगृतया प्रशासन के दृष्टिकोग्। से प्रवन्यक या नैनेबर ही उंचालकों के नियन्त्रण में श्रीर उनकी देख-रेख में कार्य करता है परन्तु मेनेनिंग एजेन्ट की स्पिति इससे कुछ मिन्न है। मेनेनिंग एजेन्ट संचालको के प्रत्यन्न अपना परोन्न नियंत्रण में नहीं रहता है। उंचालक समनीते की शतों की मीमा के अन्दर ही मैनेजिंग एजेन्ट पर नियन्त्रण रख सकते हैं या उत्ते निर्देश दे सकते हैं या यह सम्बन्ध तत्सम्बन्धी कानून के अनुसार निश्चित हो जाता है। इस प्रकार मैनेजिंग एजेन्ट की मुख्य विशेषताएँ यह है कि (१) वह कम्पनी का एजेन्ट दीता है श्रीर कम्पनी के नियन्त्रण में कार्य करता है, (२) वह कम्पनी के प्रायः सभी कार्यों की न्यवस्था करनेवाला एजेन्ट होता है और (३) कम्पनी श्रीर उसके बीच में समक्तीता होने से ही एजेन्सी स्यापित हो बाती है। व्यवहारिक र्हाष्ट से देखा नाय तो स्वप्ट हो जायगा कि मैनेनिंग एजेन्ट ही कम्पनी का वास्तविक स्वामी होता है। कम्पनी के धंचालक मण्डल का उस पर कुछ विशेष नियन्त्रण नहीं होता।

उत्पत्ति और विकास—इमारे देश में दो प्रकार के मैनेलिंग एजेन्ट हैं— भारतीय ग्रीर वीक्पीय। इन दोनों की उत्पत्ति में मेद है। भारत में उद्योगों की स्थापना का श्रेय ग्रंग्रेलों को है श्रीर उन्होंने ही यह प्रणाली खोज निकाली। मैनेलिंग एजेन्सी की प्रणाली की उत्पत्ति वास्तव में भारत में ब्रिटिश उद्योगों की स्थापना का परिणाम है। पुरानी ब्रिटिश मैनेलिंग एलिन्सियों के श्रथक प्रयत्नों ते ही इस प्रणाली का कमश: विकास हुआ। जब ब्रिटेन तथा भारत के मध्य व्यापार करने का उत्तरदायित्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से निजी न्यापारियों श्रीर सोदागरों के हाथ में चला गया था तब पुरानी मैनेजिंग एजेन्सियों ने प्रथम बार यह श्रनुभव किया कि भारत का श्रार्थिक विकास करने के लिये बहुत न्यापक चेत्र खुला पड़ा है। भारत में यूरोपीय मैनेजिंग प्रणाली की उत्पत्ति का कारण यह या कि यहाँ प्रमुख यूरोपीय न्यापारियों की संख्या बहुत कम थी श्रीर उनमें से ऐसे संचालक श्रयवा प्रबन्ध संचालकों को चुन सकना श्रत्यन्त कठिन या जो न्या-पार की निरन्तर देख-रेख करने के लिये श्रिधिक समय तक भारत में रह सकें।

मारतीय मैनेजिंग एजेन्सो प्रणाली उत्पत्ति पूँजी के संगठित बाजार के स्रमाव के कारण हुई। हमारे देश में लोग पूँजी लगाने से संकुचाते हैं, यहाँ उद्योगों की क्षापना में सहायता देने के लिये स्रीद्योगिक वैंक नहीं है। यहाँ उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के लिये स्रीद्योगिक वैंक नहीं है। रपया लगानेवाली स्रीर स्रम्य प्रकार से प्रोत्साइन देने वाली संस्थाय बहुत कम हैं। इस स्रभाव की पूर्ति के लिये मैनेजिंग एजेन्स्र) का जन्म हुआ। मैनेजिंग एजेन्ट व्यवसाय स्रारम्म करते हैं, उसमें रपया लगाते हैं, उसका प्रवन्ध करते हैं श्रीर श्रन्य रपया लगाने वालों में विश्वास उत्पन्न करते हैं। श्रीद्योगीकरण के श्रारम्म काल में जब न कोई उद्योग चालू करने की प्रवृत्ति यो श्रीर न पूँजी ही स्रधिक मात्रा में उपलब्ध की जा सकती थी उस समय मैनेजिंग एजेन्टों ने इन दोनों श्रमावों की पूर्ति की। स्राज भारत में सुसंगठित श्रीर हढ़ स्थिति वाले सती कपड़े, जूट तथा इस्पात हत्यादि उद्योग चले रहे हैं। इनकी वर्तमान स्थिति तक पहुँचने का श्रेय श्रनेक पुरानी मैनेजिंग एजेन्स्रियों को है जिन्होंने बड़े उत्साह श्रीर लगन के साथ इन उद्योगों की देख रेख की। इस समय भारत की श्रधिकांश कम्पनियों का प्रवन्ध उन्हों के द्वारा होता है।

मैनेजिंग एजेन्सी प्रगाली विस्तार का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। एक स्रोत के अनुसार भारत में कम्पनियों की संख्या रू,५०० से अधिक है, श्रीर सब प्रकार के उद्योगों में विनियोग की कुल मात्रा प्रारम्भिक लागत के आधार पर १६०० या १७०० करोड़ रुपया अनुमान की जाती है। यदि वर्तमान मूल्य स्तर के आधार पर परिसंपत्ति का अनुमान लगाया जाय तो निस्सन्देह कहीं अधिक होगी। भारत में कम्पनियों के उत्पादन में सहायक कुल परिसंपत्ति का द्रुण उन कम्पनियों की परिसम्पत्ति है जो मैनेजिंग एजेन्स्यिं से प्रवन्ध में हैं। यह मी अनुमान किया जाता है कि ६० प्रतिशत मैनेजिंग एजेन्स्यिं सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ है। एक अन्य स्रोत के अनुसार ३१ मार्च १९५५ में ३,६०० कम्पनियाँ सीमित दार्य जो लगभग ४६०० कम्पनियाँ की मैनेजिंग एजेन्ट याँ।

इनमें से २५०० मेनेजिंग एजेन्सियाँ स्वत्वाधिकारी श्रीर सामेदारी फर्म थी श्रीर लगभग १२०० व्यक्तिगत श्रीर २०० जनता की कम्पनियाँ थीं। मेनेजिंग एजेन्सी फर्म प्रधानतः पिन्छमी वंगाल, बम्बई, श्रीर मद्रास में केन्द्रित हैं। उपर्युक्त स्रोत के श्रनुसार पिन्छमी वंगाल, बम्बई श्रीर मद्रास प्रदेशों में क्रमशः १५००, ८०० श्रीर ४५० मेनेजिंग एजेन्सियाँ काम कर रही हैं। श्रन्य प्रदेश, जिनमें १०० से श्रधिक मेनेजिंग एजेन्सियाँ हैं, वे उत्तर प्रदेश, देहली, मध्य प्रदेश श्रीर पंजाव हैं। उपर्युक्त सातों प्रदेशों में कुल मिलाकर देश की ८०% से श्रधिक मेनेजिंग एजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं।

संगठन—कोई मी व्यक्ति, सामेदारी फर्म या निजी लिमिटेड कम्पनी मैनेजिंग एजेन्ट हो सकते हैं। इधर कुछ वपों से सामेदरी फर्म को निजी लिमिटेड कम्पनी में परिवितत करने की प्रवृत्ति हो रही है। इस समय मारत की प्रमुख एजेन्सियों विइला वर्द्ध लिमिटेड, टाटा इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, साहू जैन लिमिटेड, डालिमिया जैन लिमिटेड; जयपुरिया वर्द्ध लिमिटेड, इत्यादि हैं। यह समी निजी कम्पनियाँ हैं। मैंनेजिंग एजेन्सी फर्म बनाने के लिये सर्व प्रथम सीमित उत्तरदायित्व वाली कम्पनी स्थापित कर ली जाती है। इस कम्पनी के शेयरों का अधिकाँश उन्हीं व्यक्तियों के हाथ होता है जो कम्पनी चालू करते हैं। अन्य वाहरी व्यक्तियों को सीमित शेयर दिये जाते हैं। साधारणतः अन्य व्यक्तियों को शेयर, की कुल पूँजी के २५ प्रतिशत शेयर दिये जाते हैं। टाटा सन्य एंड कम्पनी, नवरोजी वाडिया एयड सन्स, इत्यादि कम्पनियाँ इसी प्रकार आरम्म की गईं। परन्तु संगठन सारे देश में समान नहीं है।

साधारण रूप से मैनेजिंग एजेन्सियों के कई प्रकार हैं जैसे बम्बई, ब्रह्मदा-वाद श्रीर कलकत्ता की एजेन्सियों विभिन्न प्रकार की हैं। यह एजेन्सियों श्रपने विकसित रूप में, अपने संगठन की रूप रेखा में एक दूसरे से भिन्न हैं। श्रह्मदा-वाद में मैनेजिंग एजेन्ट एक व्यक्ति होता है, वम्बई में सामेदार या निजी कम्पनी श्रीर कलकत्ता में श्रंप्रेजी प्रकार की लिमिटेड सार्वजनिक कम्पनी। समय की प्रगति के साथ इन एजेन्सियों का यह मेद समाप्त होता जा रहा है श्रीर वर्तमान में सभी स्थानों में सभी प्रकार की एजेन्सियों दिखाई देती हैं।

मैनेजिंग एजेन्ट प्राय: घनवान न्यक्ति होते हैं श्रीर उनके बहुत अच्छे न्या-पारिक सम्बद्ध होते हैं। वहें एजेन्ट जिनके आधीन अनेक कम्पनियाँ होती हैं अपना कार्य विभागों में विभक्त कर देते हैं। जब एरबुथनाट एन्ड कम्पनी का न्यवंशाय समाप्त किया गया उस समय उसके सात विभाग थे, जैसे बैकिंग, जनरल एजेन्सी, आयात श्रीर निर्यात, खाल श्रीर चमहा, नील, कपास श्रीर इमारती लकड़ी, जनरल शिपिंग श्रीर भू-सम्पत्ति श्रीर पश्चिमो तट एजेन्सी विमाग। कुछ मैनेजिंग एजेन्सियों जैसे बिड़ला एजेन्सी के अन्तर्गत एक से श्रिविक मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनियाँ होती हैं जो मिन प्रकार के उद्योगों का व्यवसाय देखती हैं। इसलिए प्रत्येक एन्जेसी अपने-श्रपने कार्य में विशेषज्ञ कही जा सकती है।

मैनेजिंग एन्जेसी का कार्य

साधारण रूप से भारत के मैनेजिंग एजेन्ट तीन महत्वपूर्ण कार्य करते हैं—(१) यह नए उद्योगों के लिए पय प्रदर्शक का कार्य करते हैं। साथ ही उनकी स्थापना में विशेष योगदान देते हैं, (२) उद्योगों को स्थाया और चालू पूंजी के रूप में आर्थिक सहायता देते हैं, और (३) उद्योगों की दिन प्रति दिन की व्यवस्था करते हैं।

पथप्रदर्शक और प्रवर्त्तक के रूप में-इङ्गलैयह श्रीर श्रमरीका में ऐसी श्रनेक संस्थाएँ हैं जो नए उद्योगों के स्थापना की प्रेरणा देती हैं। प्रवर्तक के रूप में यह संस्याएँ उद्योगों के सम्बन्ध में खोज कार्य करती रहती हैं श्रीर मविष्य में विकास कर सकने वाले उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। जब कोई नवीन उद्योग या व्यवसाय चालू किया जाता है तो रुपया लगाने वाले की सदा यह चिन्ता लगी रहती है कि कहीं उद्योग अधफल न हो जाय श्रीर उसकी पूँजी हूब न जाय । पाश्चात्य देशों में ऐसी संस्पाएँ हैं जो ठीक समय पर शेयरों की बिक्री करती हैं श्रीर ऐसी संस्थायें हैं जो भविष्य में उपयुक्त श्रवसर पर विक्रय करने के लिए इन शेयरों को क्रय कर लेती हैं। परन्तु भारत में ऐसी संस्थाएँ बहुत कम हैं न्नौर इनके न्नमाव की पूर्ति मैनेजिंग एजेन्ट करते हैं। भारत में जिन व्यक्तियों ने सर्वप्रयम उद्योगों की स्थापना की उनके पास साधनों का अभाव नहीं था और किसी योजना को ज्यवहारिक रूप देने के पूर्व वे विशेषशों द्वारा उनकी सारी संमावनात्रों की परीचा करा लेते थे। यह उन्हीं के साहस श्रीर उत्हास का फल है कि मारत में सूती कपड़े, लोहे और इस्पात, जूट, सिमेंट इत्यादि के उद्योग चल रहे हैं। वित्त श्रायोग (१६४६-५०) का मत है कि स्ती कपड़ा, जूट, लोहा श्रीर इस्पात तथा सिमेंट उद्योगों की स्थापना का श्रेय मैनेजिंग एजेन्सियों को ही है। इन्हीं एजेन्सियों के पथ प्रदर्शन से यह संभव हो सका। इधर कुछ वर्षों में इन एजेन्सियों ने इंजीनियरिंग, केमिकल श्रीर मोटर उद्योगों की स्थापना की है। हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, टैक्सटायल मशीनरी करपोरेशन लिमिटेड इत्यादि इस पकार के उद्योगों के उदाहरण हैं।

गत कुछ वर्षों से भारतीय मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग में रुपया कम लगा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी इस दिशा में पथप्रदर्शन की तथा नए उद्योगों की स्थापना में सहयोग देने की भावना शिथिल पढ़ गई है। इसका कारण सरकार की श्रौद्योगिक नीति है। इस नीति से श्रनेक किटनाइयाँ उत्पन्न हो गई है। सरकारी नियंत्रणों, श्रम सम्बन्धी कानूनों श्रौर समक्तीता वोहाँ तथा पंच न्यायालयों के न्याय से उत्पादन व्यय में तो वृद्धि होती जाती है परन्तु उत्पादित माल के मुल्य में वृद्धि नहीं की जाती।

वित्त व्यवस्था—मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग के लिए केवल त्यायी पूँजी की ही व्यवस्था नहीं करते वरन् इसके साथ ही पुनंसंगठन, श्राप्ठिनकीकरण श्रीर कारखाने का प्रसार करने के लिए दीर्घकालीन पूँजी की श्रीर चालू पूँजी तथा श्रन्य श्रावश्यकदाश्रों की पूर्ति के लिए श्रल्यकालीन वित्त व्यवस्था भी करते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट श्रुण के रूप में शेयर के रूप में, श्रीर श्रुणपत्र क्रय कर उद्योगों की पूँजी की श्रावश्यकता पूरी करते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट श्रपने संगे-संविन्ध्यों तथा मित्रों को कम्पनी के शेयर क्रय करने की प्रेरणा देते हैं, श्रीर इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। यह श्रुण देने की गारन्टी देते हैं श्रीर इस प्रकार जनता का रूपया प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति ने निम्नलिखित व्यौरा निर्माण किया है जिमको देखने से यह प्रकट होता है कि मैनेजिंग एजेन्टों ने इस सम्बन्ध में कितना कार्य किया है।

	वम्बई की ६४	मिलें इ	प्रह्मदावाद	की ४६ मिलें
	रुपया	कुल धन	रुपया	कुल धन
	(लाखों में)	का प्रतिशत	(लाखी में)	का प्रतिश्रत
(१) मैनर्जिंग एजेन्टों द्वारा				4
दिया गया ऋग्	५३२	२१	२६४	२४
·(२) वैकों द्वारा दिया गया				
ऋण	२२६	3	४२	٧
(३) जनता का जमाघन	२७३	११	४२६	× ₹ε
(४) रोयरों की कुल पूँजी	१,२१४	38	३४०	३२
(५) ऋग पत्र का धन	२३८	१०	5	?

इन र्शांकड़ों से स्पष्ट है कि अाधिक सहायक के रूप में मैनेजिंग एजेन्टों का किवना महत्वपूर्ण स्थान हैं। उद्योगों को अपनी आवश्यकता का लगमग एक चौथाई श्रंश सीचे इनसे मिलता है। अहमदावाद और बग्बई में जनता के जमा-

धन से जो कमश: ३६ प्रतिशत श्रौर ११ प्रतिशत सहायता मिली उसका श्रेय भी मैनेजिंग एन्जेटों की प्रसिद्ध को ही है। हमारे देश में बैंक तब तक ऋण नहीं देते हैं जब तक दो जमानती न बर्नें। मैनेज़िंग एजेन्ट ऐसे अवसरों पर दूसरी जमानत स्वयं लेते हैं। जहाँ तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेन्टों का प्रश्न है उनके कार्य में शिथिलता का अनुभव किया जा रहा है। विच आवश्यकता की पूर्वि करने और इंग्रमी गारन्टी देने की श्रोर उनका उत्साह घटता दिखाई दे रहा है। मैंनेजिंग एजेन्टों के आर्थिक सहायक के रूप में चाहे कितनी ही शिथिलता हो रुपया लगाने वाला, टाटा, विङ्ला तथा अन्य प्रसिद्ध मैनेजिंग एजेन्टों के नाम से तुरन्त आकृष्ट होता है। कम्पनी कानून समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैनेजिंग एजेन्ट का निजी उद्योगों के लिए श्रव भी महत्वपूर्ण साधन हैं। मँदी के समय जब किसी श्रन्य साधन से रुपया मिलना संभव नहीं रहता है मैनेजिंग एजेन्ट यथा समय पूँजी की व्यवस्था कर देते हैं। कुछ मैनेजिंग एजेन्टों में आत्म सम्मान की इतनी अधिक भावना है कि उन्होंने श्रपने द्वारा श्रारम्भ किए हुए व्यवसाय की नष्ट होने से रचा करने के लिए अपनी समस्त सम्पत्ति तक दांव पर लगा दी। परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं श्रीर यह देखा गया है कि मैनेजिंग एजेन्टों ने अपनेश्राधीन उद्योगों की विशेष देख-माल न कर प्राय: उन्हें उनके माग्य पर ही छोड़ दिया।

प्रबन्ध—मैनेजिंग एजेन्ट केवल उद्योग का सफल आरम्म ही नहीं चाहते वरन् उद्योग की सम्पूर्ण न्यवस्था को उचित रीति से कार्यान्वित करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उद्योग ठीक प्रकार से चले। इसका उन्हें तब तक विश्वास नहीं हो सकता है जब तक उनका उस पर नियंत्रण नहों। इसका प्रायः यह परिणाम हुआ कि मैनेजिंग एजेन्ट उद्योग पर नियंत्रण रखने के साथ ही उसके अधिकारी भी बन बैठे। परन्तु वह बात सर्वत्र लागू नहीं होती हैं। अनेक कम्मनियों में मैनेजिंग एजेन्टों का नियंत्रण तो पूर्ण है, परन्तु शेयर बहुत कम हैं।

पत्येक प्रमुख मैनेजिंग एजेन्सी के केन्द्रीय कार्यालय में उद्योगों के आघार पर मिल मिल विभाग होते हैं; साथ ही प्रत्येक उद्योग के विभिन्न विभागों के लिए केन्द्रीय कार्यालय में उप-विभाग होते हैं। मैंनेजिंग एजेन्ट अपने आघीन कम्पनियों या कारखानों द्वारा उत्पादित माल को क्रय और विक्रय करते हैं। प्रायः यह अनेक वस्तुओं का आयात करते हैं और निर्यात भी करते हैं। इस प्रकार यह वड़े पैमाने पर क्रय-विक्रय करने का लाम उठाते हैं। यह लामांश सदैव कम्पनियों को नहीं दिया जाता है, एजेन्ट इसे स्वयं ले लेते हैं। इस पर भी कम्पनी को अपने माल का इन मैनेजिङ्ग एजेन्टों के द्वारा क्रय-विक्रय कराने में अचत ही होती है इसके

लिए उन्हें एक भिन्न संस्था स्थापित नहीं करनी पड़ती। इसके साथ ही जब मैनेलिंग एजेन्ट एक उद्योग के एक से अधिक कारखानों पर नियन्त्रण रखता है तब इनमें प्रतियोगिता का जोर कम पड़ जाता है और कृति नहीं हो पाती। एक छोटी कम्पनी प्रथम अेणी के विशेषताओं की सहायता लेने में असमर्थ होती हैं परन्तु यह मैनेलिंग एजेन्ट अनेक कम्पनियों के प्रबन्व कर्चा होने के कारण प्रथम अेणी के अभियन्ताओं और प्रविधिशों को नियुक्त करते हैं जो भिन्न कम्पनियों की देख माल कर सकते हैं। इस में जो कुछ न्यय होता है वह इन कम्पनियों में विमाजित कर दिया जाता है।

प्रसाली की त्रुटियाँ

मैनेलिंग एलन्टों ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, परन्तु इघर कुछ वधों से इस प्रणाली में कुछ दोष प्रकट होने लगे हैं। राष्ट्रीय योजना श्रायोग की श्रीद्योगिक वित्त व्यवस्था सम्बन्धी उपसमिति की राय है कि यह प्रणाली विल्कुल व्यर्थ हो चुकी है। परन्तु यह दोषारोपण श्रन्यायपूर्ण श्रीर श्रसंतुलित है। मारत के श्रीद्योगिक श्रीर श्राधिक विकास में दोषों के होते हुये भी मैनेजिंग एजेन्सियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। जो कुछ भी हो, जब तक इसका स्थानापन न मिल जाय इस इस प्रणाली के विना कार्य चला नहीं सकते।

कम्पनी को लाभ होने पर लाभ का कुछ प्रतिशत मैनेजिंग एजेन्ट को वेतन के रूप में दिया जाता है। परन्तु लाम न होने पर कार्यालय का कार्य चलाने के लिये कुछ घन दिया जाता है। इसके साथ ही एजेन्ट कमीशन के रूप में भी कम्पनी से कुछ श्रीर धन वस्ताता है। १६३६ के भारतीय कम्पनी कानून की धारा ८७ (सी) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि कम्पनी को वर्ष भर में जो वास्तविक लाम होगा उसका निश्चित प्रतिशत एजेन्ट को वेतन के रूप में दिया जायगा श्रीर उचित लाभ न होने पर कुछ न कुछ घन दिया जायगा। १९३६ ते पूर्व मैनेजिंग एजेन्ट माल की विक्री के श्राघार पर श्रपना वेतन लेते ये। यह ढंग कम्पनियों के प्रति न्यायसंगत नहीं था। १९३६ के कानून से स्थिति में काफी सुधार हुआ है परन्तु क्योंकि धारा ८७ (सी) उन कम्पनियों पर लागू नहीं होती है जो १५ जनवरी १६३७ से पूर्व ही रजिस्टर हो चुकी थीं, इसलिये कुछ मैनेजिंग एजेन्ट अपना वेतन श्रव भी उसी पुराने श्राधार पर ले रहे हैं। हुकुमचन्द मिल्स लिमिटेड, एलेम्बिक वर्क्ड कम्पनी लिमिटेड, एलेम्बिक ग्लास इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के मैनेजिंग एजेन्ट विक्री श्रीर लाम दोनों के श्राघार पर वेतन पाते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट के वेतन के रूप में एक से अधिक आधार पर धन वसलने के शेष को रोकने के लिये कम्पनी कानून समिति (१६५२) ने सुकाव दिया

कि मैनेजिंग एजेन्ट को कम्पनी के वार्षिक लाभ का १२३ प्रतिशत से अधिक अश न दिया जाय।

वालिका नं २ लाभ तथा मैनेजिंग एजन्टों का वेतन (करोड़ रूपयों में)

१६४६	१९५१
७,३१	१०,१४
20.55	२५.२६
१ ५,५१	२०.६२
₹0.65	₹3.0\$
६१.४८	83.50
	७,३१ २७.८८ १ ५.५१ १०.७८

१६५५ के करारीय जाँच आयोग को यह शत हुआ था कि मैनेजिंग एजेन्टों को १६४६ और १६५१ में शेयर होल्डरों के लाम का आधा माप्त हुआ या, जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है।

मैनेजिंग एजन्टों की श्रीसत ग्राय लाम के प्रतिशत श्रानुपात में १६४६ में १२% यो ग्रीर १६५१ में बढ़ कर १४% हो गई। यद्यपि १६५१ में ग्रीसत १३'७% (श्रयात १४% के लगमग) या, पर विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में प्रतिशत की मात्रा मी विभिन्न थी। जहाजरानी, जूट के बने माल, विजली, कोयला, स्ती कपड़े, चीनी, सीमेंट, लोहा ग्रीर इस्पात ग्रादि उद्योगों में श्राय का प्रतिशत कमशः २६'४, २०'३, १८'१, १६'७ १६'४, १५'८, ०'३ तथा ७'३ या।

- पर्याप्त लाम न होने पर मैनेजिंग एजेन्टों को कम से कम कुछ धन दिया जाता है। प्रायः सममौते के समय यह घनराशि निश्चित कर दी जाती है। कम्पनी कानून समिति ने सुमान दिया है कि कमी-कभी यह धन अत्यिषक हो जाता है इसलिये ५० हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये।

लाभाँश के कुछ निश्चित प्रतिशत के रूप में श्रीर कुछ परिस्थितियों में दिये जाने वाले न्यूनतम धन के श्रितिरिक्त मैनेजिंग एजेन्टों को कार्यालय का भक्ता भी मिलता है। कार्यालय के भक्ते में कार्यालय का विस्तार श्रीर उसका किराया, टैक्स, बिजलो, पंखे, झकों का दफ्तर, पत्र इत्यादि प्रेपित करने का व्यय, जाँच तथा कपये-पैसे की व्यवस्था करने वाला विमाग, सीनियर एकाउन्टैन्ट श्रीर सेकेट्रिएट के कर्मचारियों की सहायता, डाक-व्यय, कागज, पेन्सिल, श्रीर चपरासी इत्यादि पर किया जाने वाला सभी व्यय सम्मिलित है। श्रर्थात् मैनेजिंग एजेन्ट

कम्पनी की श्रोर से कार्यालय में जो कुछ व्यय करता है कार्यालय के मत्ते के रूप में उसको वस्त कर लेता है। परन्तु साधारणतया मैनेजिंग एजेन्ट व्यय से कहीं श्राधक धन वस्तिते हैं श्रीर उसको श्रपंनी श्रातिरिक्त श्राय के रूप में उपभोग करते हैं। कम्पनी कानून समिति (१९५२) ने सुक्ताव दिया है कि मैनेजिंग एजेन्टों को कार्यालय का मत्ता न दिया जाय वरन् इसके स्थान पर जो कुछ वास्तव में व्यय किया गया हो उत्तनी धनराशि दी जाय। इस सुक्ताव की इस श्राधार पर श्रालोचना की गई है कि इस व्यवस्था से कार्य-भार बढ़ जायगा श्रीर हिसाब-किताव रखने में कठिनाई होगी। परन्तु यह कठिनाई एक दोष को समाप्त करने के लिए सहन की जा सकती है।

मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली में श्रीर भी दोष हैं। मैनेजिंग एजेन्ट गैर कानूनी कार्यों के लिए ऋगा लेते हैं, व्यापार के उद्देश्य से नहीं वरन् मित्रों को देने के लिए ऋग लिया नाता है, अन्य कारलानों में लगाकर रुपया फँस नाता है श्रौर वित्त-स्थिति शिथिल हो जाती है। जिन कारखानों या कम्पनियों की वित्त स्थिति दृढ है उनकी सम्पत्ति को रेहन रख दिया जाता है, कम्पनी को रुपयों की श्रावश्यकता न रहते हुए भी भैनेनिंग एजेन्ट की श्रावश्यकता पूर्ति के लिये या उनकी कोई योजना कार्यान्वित करने के लिए ऋणपत्र प्रचलित किये जाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिये कम्पनी कानून-सिमिति ने कुछ सुकाव दिये हैं:-(१) मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा लिखे गये ऋग की न तो कम्पनी गारन्टी दे त्रोर न स्वयं उन्हें ऋग दे, (२) एजेन्ट के पास कम्पनी का चालू खाता २० इनार से अधिक का नहीं होना चाहिये और (३) कम्पनी के रुपये को अन्यन्न किसी कारखाने इत्यादि में लगाने पर प्रतिवन्य लगाना चाहिये। परन्तु इनमें से कुछ प्रतिवन्य ऐसे हैं जिनके लागू हो जाने से मैने जिंग एजेन्ट की कार्य करने की स्ववंत्रवा कम हो जायगी और कोई नया कार्य करने या किसी कठिनाई को हल करने के लिए मैनेजिंग एजेन्ट पूर्व की सी तीव गति से कार्य नहीं कर पायेगा। उसमें कुछ उदासीनता श्राने लगेगी।

वम्बई के शेयर होल्डर एसोसियेशन ने इस श्लोर संकेत किया है कि श्रनेक वार मैनेजिंग एजेन्सी के अधिकारों को बिना खरीदार की वित्त रिथित और प्रीसिंध का पता लगाये और शेयर होल्डरों तथा अन्य कर्मचारियों के हितों पर बिना विचार किये दूसरों को वेच दिया गया। विगत वर्षों में कम्पनी के स्वामियों और मैनेजिंग एजेन्सी के नियन्त्रण में निकट सम्पर्क रहने के कारण सदैव उद्देश्य की एकता बनी रही और एक दूसरे के हितों का हनन प्राय: न हो सका परन्तु अब मैनेजिंग एजेन्ट और उनके अधीन कम्पनी के पृथक व्यक्तियों का निकट सम्बन्ध

मायः समाप्त हो चुका है। ऐसे भी अवसर आए हैं जब मैनेजिंग एजेन्सी के अधिकार संकट में पड़ गए। इससे स्थिति इतनी विगड़ी कि १६५१ में सरकार को भारतीय कम्पनी कानून की घारा ८० (वी) में संशोधन करने के लिये एक अध्यादेश की घोपणा करनी पड़ी। सरकार ने इस अध्यादेश के द्वारा यह व्यवस्था की कि मैनेजिंग एजेन्ट यदि अपने अधिकार किसी को सींपता है तो यह कार्यवाही तब तक वैध नहीं मानी जायगी जब तक कम्पनी इस परिवर्तन को अपनी साधारण सभा में स्वीकार न कर ले और केन्द्रीय सरकार अपनी स्वीकृति न दे।

इन्डियन कम्पनीज एक्ट, १६५६-१६५६ का भारतीय कम्पनी एक्ट मैनेजिंग एजेन्टों पर कड़े प्रतिबन्ध लागू करता है। यह एक्ट १६३६ के एक्ट की श्रपेता श्रधिक विशद तथा पूर्ण है। एकट में यह दिया हुआ है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजेट में श्राधिसचना द्वारा विशेष व्यवसायों तथा उद्योगों में संलग्न सब कम्पनियों के सम्बन्ध में यह घोपणा कर सकती है कि किसी निश्चित तिथि के तीन वर्ष परचात् से अयवा १५ अगस्त १६६० से जो भी बाद में पड़े, वे मैनेजिंग एजेन्टों के प्रवन्य में नहीं रहेंगे। दूसरे श्रंशा में यह व्यक्त किया गया 'है कि इस एक्ट के लाग होने के पश्चात कोई भी मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनी किसी अन्य मैनेजिंग एजीन्ट के प्रबन्ध में न रहेगी। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में मैनेनिंग एजेन्टों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति सर्वेप्रथम कम्पनी द्वारा सर्वेषाधारण की सभा में ग्रीर तत्वश्चात् केन्द्रिय सरकार द्वारा स्वीकृत होना ग्रावश्यक है। ऐसे अवसरों पर सरकार अपनी स्वीकृति तभी देने को तैयार होगी जब कि उसे यह विश्वास हो जायगा कि (१) मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति से जनता से हित की हानि की सम्भावना नहीं है श्रीर (२) जिस मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति श्रपना पुनर्नियुक्ति की जानेवालो है, वह सर्वया उपयुक्त है तथा मैनेजिंग एजेन्सी संविदा की शर्ते न्यायमुक्त तथा तर्कर्सगत है। इन दो श्रंशों से सरकार को बहुत अधिक श्रिषकार माप्त हैं। इसके श्रितिरिक्त मैनेजिंग एजेन्टों के कार्य करने की श्रविध, नेतन, ग्राधिकार इत्यादि पर भ्रानेको प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। एकट में निम्न वात दो हुई है:---

- (१) कोई मो नवीन मैनेजिंग एजेन्सी का संविदा १५ वर्ष से अधिक के लिये नहीं किया जा सकता श्रीर किसी मैनेजिंग एजेन्ट की पुनर्नियुक्ति २० वर्ष से अधिक के लिये नहीं की जा सकती;
- (२) अगस्त १९६० के पश्चात् कोई मी व्यक्ति एक समय में दस कम्पनियों से अधिक का कर्मचारी नहीं वन सकता। जो मैनेजिंग एजेन्ट वर्तमान समय में हैं उनकी कार्यविधि का १५ अगस्त १९६० को अन्त हो जायगा, यदि उनकी

पुनर्नियुक्ति इस तिथि के पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं कर दी जाती;,

- (३) यदि कोई एजेन्ट दिवालिया है स्रयवा उसे कम से कम ६ माह का कारावास का द्राड मिला है तो उसे स्वतः स्रयना पद त्याग देना होगा। यदि कोई एजेन्ट घोखा देता है स्रयवा विश्वासघात करता है या कर्तव्य से गिर जाता है स्रीर कुप्रवन्य करता है तो उस कम्पनी स्रयने तत्सवन्धी प्रस्ताव द्वारा पद से इटा सकती है।
- (४) मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा कार्यालय के स्थानान्तरित करने के संबन्ध में कंपनी त्रीर सरकार दोनों की स्वीकृति परमावश्यक है। विना उसके यह सम्भव नहीं हो सकता।

वहाँ तक एजेन्टों के वेतन का प्रश्न है एक्ट में यह बताया गया है कि किसी भी मैनेजिंग एजेन्ट को सामान्यतः कम्पनी के वास्तविक लाम के १०% से अधिक वेतन के रूप में नहीं दिया जायगा पर अतिरिक्त आय के लिये कम्पनी को एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा अनुमित प्रदान करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आधार पर स्वीकृति प्राप्त करना कि यह जनता के हित में है आवश्यक होगा।

यह एकट मैनेजिंग एजेन्टों के अधिकारों पर भी प्रतिबन्ध लगाता है।'
मैनेजिंग एजेन्ट अपने अधिकारों का प्रयोग कम्पनी के निर्देशकों की धर्मिति के
निरीक्षण, नियत्रण और निर्देशन में ही कर सकता है जो कि कम्पनी के नियमों
तथा सममीते की शतों के अन्तर्गत होगी। अन्य चेत्रों में भी प्रतिबन्ध लगाये गये
हैं जैसे (१) मैनेजिंग एजेन्स्यों के प्रवन्ध में कम्पनियों द्वारा ऐजेन्टों को अध्रण
देना; (२) एक ही मैनेजिंग एजेन्स्यों के प्रवन्ध में एक से अधिक कम्पनियों का
आपत्र में एक दूसरे को अध्रण देना; (३) एक कम्पनी द्वारा उसी वर्ग की अन्य
कम्पनी के शेयरों को कय करना; (४) मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा उनके प्रवन्ध के
अन्तर्गत कम्पनियों के व्यवसाय से स्पर्धा करने वाले व्यवसायों से कार्य करना।
इन नियमों की उपेद्या करने पर कठोर द्यह की भी व्यवस्था की गई है। अन्त
में निर्देशकों की नियुक्ति सम्बन्धी मैनेजिंग एजेन्टों के अधिकारों में भी अनेक प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं। अत्र एजेन्ट ऐसी व्यवसायिक इकाइयों में नहीं पाँच से
अधिक निर्देशक होते हैं दो से अधिक नहीं और जिनमें केवल पाँच तक निर्देशक
होते है उनमें केवल एक निर्देशक की नियुक्ति कर सकता है।

मैनेजिंग एजेन्स्री का भविष्य

त्रतीत में इस प्रणालों में अनेक दोप रहे हैं और भ्रव्याचार के लिए पर्याप्त चेत्र रहा है। राष्ट्रीय योजना आयोग ने सुकाव दिया है कि सर्वप्रथम इस प्रणाली का उन्मूलन कर देना चाहिए जिससे श्रीबोगिक वित्त न्यवस्था के नाम पर इस प्रणाली के समर्थक अपने असंगत तर्क प्रस्तुत न कर सकें। परन्तु बम्बई के मिल मालिक संघ ने इस श्रोर सही संकेत किया है कि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली की त्रावश्यकता इसलिये श्रनुभव की जाती है कि देश में बैंकों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए व्यवसाय चाल करने के लिए शेयरों की पंजी मिल सकना कठिन है भ्रौर किसी उद्योग को चलाने के लिए भ्रावश्यक विच की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसकी पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को सहायता की आव-श्यकता होती है जो मैनेजिंग एजेन्ट से उपलब्ध की जा सकती है। कम्पनी कानून समिति का यह सुकाव उचित है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति में मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली पर निर्भर करने से लाम ही होगा। वास्तव में सम्पूर्ण प्रणाली ही को भंग करने की माँग करने की श्रापेता इस बात की श्रावस्थंकता है कि उपयुक्त कानून बनाकर प्रणाली के दोशों को दूर किया जा जाय। कम्पनी एक्ट के मैनेजिंग प्रणाली पर सम्पूर्ण प्रमाव की ग्रभी से कल्पना कर लेना कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि इससे कुछ महान दोष प्रणाली में अवश्य मिट जायेंगे पर इससे मैनेजिंग एजेन्टा द्वारा नवीन कम्पनियों के ब्रारम्भ में भी संक्रचन ब्रायेगा क्योंकि (१) मैनेजिंग एजेन्सी संविदा की अविधि घटा दी गई है: (२) मैनेजिंग एजेन्टों के नेतन में कमी कर दी गई है, श्रीर (३) विस्तृत प्रतिबन्धों को लगाने से एक विरोधी मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर दिया गया है। परन्त हा० एन० दास के मतानुसार मविष्य श्रंधकारमय नहीं है। उनका कहना है कि कोषाय्यच 📐 श्रीर मन्त्री के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे वर्तमान मैनेजिंग एजेन्सियों को इस बात का अवसर प्रदान करते हैं कि वे अपने को अधिक उपयोगी कार्यं संचालक के रूप में परिणित कर सकते हैं। यह ठीक है कि कोपाध्यज्ञ श्रीर मन्त्री को वास्तविक लाभ का केवल ७३% ही श्राय के रूप में प्राप्त हो सकेगा: उन्हें कम्पनी द्वारा निर्मित माल के विक्रय करने का अधिकार न होगा: श्रौर न उन्हें मशीनों, स्टोर का सामान, श्रौर कचा माल, स्रादि कय करने अथवा उनका ब्यापार करने का अधिकार ही होगा। परन्तु ये सब प्रति-वन्घ वर्तमान सुविधाओं में साधारण कमी मात्र ही है और इसका कोई ख्रीचो-गिक उपक्रमों पर श्रिष्ट्रितकर प्रभाव न पड़ेगा । मारत के उपक्रमिकों ने भूतकाल से ऐसी सहनशीलता दिखलाई है कि उनके मिन और उनके कठोरतम समा-लोचकों को भी श्राश्चर्य हुया है। इसके कोई कारण नहीं कि ने इस नवीन बाघा का जो उनके सम्मुख खड़ी कर दी गई है सफलतापूर्वक सामना न कर सकें।

श्रध्याय २४

श्रौद्योगिक वित्तीय निगम (कार्पोरेशन)

किसी देश का श्रीद्योगिक विकास श्रधिकतर उद्योग की स्थिर तथा चालू पँजी की त्रावश्यकता पूर्ति के लिए उपलब्ध वित्त पर निर्भर करता है। श्रन्य देशों की तरह भारत में बड़े साहसी, जो प्रसिद्ध हैं या जो मैनेजिंग एजेन्ट हैं, श्रपनी श्रौद्योगिक योजनात्रों को कार्यान्त्रित करने के लिए रुपया संग्रह कर लेवे है। वह श्रपना रुपया लगा सकते हैं. श्रपने मित्रों के रुपयों को श्राकर्षित कर सकते हैं और श्रावश्यकता पड़ने पर वैंकों से शृशा ले सकते हैं और इनके श्राधीन कम्पनियों द्वारा प्रचलित किये गये शेयरों की भी शीव ही विक्री हो जाती है। परन्तु इस द्वेत्र में वास्तविक कठिनाई का सामना उन न्यापारियों को करना पड़ता है जो श्रधिक परिचित नहीं हैं, जिनके पास उचित योजनायें तो हैं परन्तु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्त नहीं है। वास्तव में इन्हीं व्यापारियों को सहायता की सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि परिस्थितियाँ पँजी संग्रहीत करने के श्रमुकूल न हों तो बड़े उद्योगपितयों को भी श्रपना न्यवसाय फैलाने के लिए या कारखानों की मशीनों को बदल कर नयी मशीनें लगाने के लिए सहायता की श्रावश्यकता पहती है। कुछ विदेशों में श्रीद्योगिक वैंक हैं जिनसे श्रावश्यक रुपया मिल जाता है, परन्तु मारत में ऐसे श्रीद्योगिक वैंक नहीं हैं। जर्मनी में, जहाँ मिश्रित वैंकिंग की व्यवस्था थी, व्यापारिक वैंक उद्योगों को स्थिर पुँजी भी देते ये परन्तु यह उपयुक्त सिद्दान्त नहीं है। व्यापारिक वैंकों में जमा घन श्रल्प-कालिक होता है इसिलए इसमें मय की संमावना रहती है। मिश्रित वैंक जर्मनी में सफल नहीं हो सके श्रीर वह भारत के लिए भी उचित नहीं हैं। इन कारणों से यह आवश्यक है कि आवश्यकता अस्त उद्योगी की सहायता के लिए पूँजी देने के लिए विशेष प्रकार की संस्था स्थापित की लाय । केन्द्रीय वैंक व्यवस्था जींच समिति ने सुकान दिया कि भारत में इस कार्य के लिए श्रीद्योगिक वित्तीय कार्पी-रेशन की स्थापना की नाय। एशिया तथा सुदूर पूर्वीय आर्थिक सम्मेलन चेत्र में घरेलू पँजी के संग्रह कार्य की जाँच करने वाली विकेंद्र पार्टी ने भी इसी प्रकार के वित्तीय कार्पोरेशन की स्थापना का सुकाव दिया है श्रीर साथ ही विकास कार्पोन रेशन के लिए सुमाव दिये हैं।

केन्द्रीय निगम (कार्पीरेशन)

शेयरों की पूँजी—संसद द्वारा स्वीकृत कानून के श्रनुसार १ जुलाई १९४८ को श्रीयोगिक वित्तीय कार्पोरेशन की स्थापना की गई। कार्पोरेशन के । सम्बन्ध में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि कार्णोरेशन राज्य का हो या हिस्सेदारों का हो। राज्य कार्पोरेशन के लाम अधिक सुदृढ़ता और किसी प्रकार के भेदमाव का अभाव हैं परन्तु चूँ कि इस प्रकार का कार्पोरेशन स्थापित करने के लिए भारत सरकार के पास आवश्यक साधन नहों हैं इसलिए यह उचित समका गया कि कार्पोरेशन हिस्सेदारों की संस्था बने। राजकीय कार्पोरेशन तब उपगुक्त होता जब बैंकों और उद्योगों इत्यादि का भी राष्ट्रीयकरण हो जाता। परन्तु यह सब निजी उद्योगपितयों के हाथ में हैं इसलिए हिस्सेदारों का कार्पोरेशन ही अधिक उपगुक्त है। कार्पोरेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए यह निश्चय किया गया कि इस कार्पोरेशन के हिस्सेदार केवल सरकार, रिज़र्व वैंक और कुछ विशेष संस्थाएँ वर्ने।

कार्पोरेशन के शेयरों की पूँजी १० करोड़ घपये है जो ५,००० घपये के शेयरों में निभक्त है। श्रारम्भ में ५ करोड़ घपये के पूर्ण भुगतान किये जाने नाले शेयर प्रचलित किये गये जो सब क्रय कर लिए गये। इनमें से भारत सरकार श्रीर रिजर्व वैंक को एक करोड़ घपये के शेयर दिए गए हैं, श्रमुस्चित वैंकों को १९ करोड़ घपये श्रीर वीमा कम्पनी तथा विनियोग दृश्यों को १९ करोड़ श्रीर सहकारी वैंकों को ५० लाख घपयों के शेयर दिये गये। भारत सरकार ने पूँजी को चुकाने की गारन्थी दो है श्रीर हिस्सेदारों को न्यूनतम वार्षिक लाभांश (जिस पर कर नहीं लगेगा) भी दिया नायगा जिसकी दर वर्तमान में २९ प्रतिशत है।

कार्पोरेशन का संचालन १२ संचालकों का मराइल करता है जिसमें तीन संचालकों को केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है, दो संचालकों को रिज़र्व वैंक नियुक्त करता है, ६ संचालकों को अन्य हिस्सेदार निर्वाचित करते हैं जिनमें से दो का निर्वाचन अनुस्चित चैंक करते हैं, दो संचालकों को सहकारी चैंक और दो को बीमा कम्पनी चुनती हैं और प्रवन्ध संचालक केन्द्रीय बैंक नियुक्त करता है।

कार्य-कार्पोरेशन को निम्नलिखित कार्य करने का श्रिधिकार दिया गया है:--

ì

- (१) यदि कोई श्रीशोगिक संस्था ऐसी शतों पर जिन पर दोनों पच्च सहमत हो जनता से ऋणा संग्रहीत करे श्रीर यह ऋणा २५ वर्ष के श्रन्दर ही वापस किया जाने वाला हो तो कार्पोरेशन उसकी गारन्टी दे सकता है।
- (२) त्रीद्योगिक संस्थात्रों द्वारा प्रचित्तत किये गए स्टाक, शेयर, बौएड क्रीर ऋगु-पत्रों को कार्पोरेशन स्वयं क्रय कर उनके विक्रय की व्यवस्था कर सकता है परन्तु यह त्रावश्यक है कि इस प्रकार के स्टाक, शेयर इत्यादि सात वर्ष के श्रन्दर विक बार्ये।

(३) कार्पोरेशन ऋग दे सकता है और किसी उद्योग के ऋगएपत्र कर कर सकता है परन्तु ऋग वापस करने की अवधि २५ वर्ष से अधिक न हो।

कापीरेशन किसी कम्पनी के स्टाक अथवा शेयर नहीं क्रय कर सकता। इस प्रतिवन्ध का उद्देश्य कापीरेशन की अनुचित क्रय से रचा करना है। कुछ अन्य देशों में इस प्रकार के कापीरेशन यह कार्य करते हैं परन्तु मारत सरकार ने प्राचीन रीति के अनुसार कार्य करना पसन्द किया है, इसलिए यह कापीरेशन ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो प्राचीन रीति के प्रतिकृत हो। जनता का घन संग्रह करने के सम्बन्ध में कुछ शर्तें लगा दी गई हैं और अंतिम सीमा १० करोड़ रुपया कर दी गई है।

कार्पोरेशन ऐसी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को श्रीर सहकारी समितियों को मध्यकालिक श्रीर दीर्घकालिक श्रीय देता है जो उत्पादन कार्य करती हैं। इस्पर में एक संशोधन के श्रनुसार कार्पोरेशन से वित्तीय सहायता पा सकने वाले श्रन्य उद्योगों में जलयानों को भी समितित कर दिया है। परन्तु सामेदारी श्रीर निजी लिमिटेड कम्पनियों को इसमें समितित कर दिया है। परन्तु सामेदारी श्रीर निजी लिमिटेड कम्पनियों को इसमें समितित नहीं किया गया है। कानून के श्रनुसार कार्पोरेशन किसी एक कारखाने को श्रपनी परिदत्त पूँजी का १० प्रतिशत या ५० लाख कपयों (जो भी कम हो) की सहायता दे सकता है। १९६५२ में एक संशोधन के श्रनुसार श्रव एक करोड़ की सहायता दो जा सकती है श्रीर सरकार की गारन्टी पर इस धन में श्रीर वृद्धि की जा सकती है। संशोधन करने का कारण यह था कि कुछ उद्योगों के लिए ५० लाख की सहायता श्रपर्यात थी। साथ ही ऐसी स्थित में जब कि विश्व बैंक से श्रमुण लिया गया हो तो कार्पोरेशन को एक करोड़ रुपये से श्रिधक की सहायता देनी पढ़ सकती है।

कार्पोरेशन श्रपने विशेषक कर्मचारियों की सहायता से श्रावेदन पत्रों की जाँच करता है श्रीर श्रूग स्वीकृत करते समय निम्नालिखत वातों पर ध्यान देता है:—(१) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व, (२) व्यवस्थापकों की योग्यता, (३) योजना की व्यवहारिकता श्रीर कुल व्यय, (४) उत्पादन का प्रकार, (५) जमानत, (६) कव्चे माल श्रीर टेकनिकल कर्मचारियों की व्यवस्था, श्रीर (७) उत्पादन की देश को श्रावश्यकता।

साधन—कार्पोरेशन बाजार से बौएड श्रीर ऋग्यपत्र द्वारा रुपया एकितत कर सकता है जिसकी मात्रा कार्पोरेशन द्वारा दीं गई गारन्टी श्रीर बीमा के श्रन्तर्गत देय को सम्मिलित करके उसकी परिदत्त पूँजी श्रीर सुरिच्चत कोप के दस गुने से श्रिष्ठिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार जब कार्पोरेशन की कुल शेयरों की पूँजी १० करोड़ रु० हो जायगी और सुरिक्ति कोष में भी १० करोड़ रुपया संग्रह हो जायगा तो अपने पूर्ण विकसित रूप में कार्पोरेशन बाजार से २०० करोड़ रुपया एकत्रित कर सकता है।

१६५२ के संशोधन के अनुसार कार्पोरेशन १८ मास के लिये रिजर्व वैंक से ३ करोड़ रुपया ऋगा ले सकता है। इसके साथ ही कार्पोरेशन पुनर्निर्माण और विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से रुपया ऋगा से ले सकता है। इतना होते हुये भी कार्पोरेशन के साधन सीमित ही हैं।

स्रोद्योगिक वित्त कार्पोरेशन (संशोधन) श्रिधिनियम १६५७:— उद्योगीकरण की गति बढ़ जाने से कार्पोरेशन उत्तरदायित्व श्रीर श्रिधिक हो गया है। श्रतएव १६५७ में श्रिधिनियम को संशोधित कर निम्न बातों की व्यवस्था की गई।

- (१) कार्पोरेशन प्रिदत्त पूँजी तथा सुरिक्त कोन के पाँच गुने के जनाय दस गुने तक ऋगा ले सकता है।
- (ii) कार्पोरेशन अब केवल जनता से ही नहीं वरन् राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों से भी निचेष (deposits) स्वीकार कर सकती है।
- (iii) यदि आयात करने वाले निर्माताओं के साथ विलम्बित सुगतान की व्यवस्था कर सकें तो कार्पोरेशन इन विलम्बित सुगतानों की गारन्टी दे सकता है।
- (iv) कार्पोरेशन से अब और अधिक प्रकार के अौद्योगिक संस्थान सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु संशोधन की धारा २ (सी) में 'वस्तुओं के विधायन' की ऐसी व्याख्या की गई है कि और अधिक औद्योगिक संस्थान कार्पोरेशन से ऋण की सहायता प्राप्त कर सकें। राज्यीय विद्ताः कार्पोरेशन अधिनियम १६५१ में जो संशोधन १६५५ में किया गया था उसी आधार पर उपर्युक्त धारा में भी संशोधन किया गया है। साथ ही घारा २३ की उपधारा (२) में इस प्रकार संघोधन किया गया है कि वे औद्योगिक संस्थान भी ऋण की सहायता पा सकें जो राष्ट्र के हिष्टिकोण से प्रोत्सिहत करने योग्य हैं। शर्त यह है कि इनको दी जाने वाली सहायता के मूलधन और व्याज अदायगी की गारन्टी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, एक अनुस्चित केंक अथवा राज्यीय सहकारी केंक है।

आलोचना-कार्पोरेशन की आलोचना में अनेक वार्ते कही. गई है। (१) कार्पोरेशन का कार्य रुद्धिवादी ढंग से चलाया गया, इससे विशेष सहायता

न मिल सकी। कार्पीरेशन के अधिकारियों ने बताया है कि इन आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने का कारण यह या कि इनमें उचित योजना नहीं दी गई थी। योजना निर्माण से पूर्व टेकनीशियनों, इज्जीनियरों तथा अन्य अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श नहीं किया गया था। मशीनों तथा कच्चे माल को प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया था और यही अनिश्चित स्थित उत्पादित माल के विक्रय के सम्बन्ध में थी। परन्तु कार्पीरेशन इन वार्तों को अपनी कार्रवाई न्याय संगत सिद्ध करने के लिये तर्क के उपयोग में नहीं ला सकता है। क्योंकि यदि आवंदन पत्र ठीक प्रकार से नहीं दिये गये ये तो यह कार्पीरेशन का कर्तव्य था कि वह आवंदन पत्र ठीक प्रकार से प्रस्तुत कराता। वास्तविक कठिनाई यह है कि कार्पीरेशन को इस सम्बन्ध में कुछ चिन्ता नहीं है और वह अपनी प्राचीन रोति से कार्य करता रहा। यह बात उल्लेखनीय है कि कार्पीरेशन अपनी आलोचना से कुछ सतर्क हुआ और प्रार्थी की भूलों के होते हुये भी अस्वीकृत आवंदन पत्रों की संख्या घटने लगी।

(२) श्रालोचकों का कहना है कि कार्परिशन ने सहायता में बहुत कम धनराशि दो। जून १६५७ तक ६ वर्षों में कार्परिशन ने ५५.१२ करोड़ कार्य का श्रृण मंजूर किया जिसमें से २६.५१ करोड़ का वितरण हुआ। कार्परिशन के श्रिधिकारियों का मत है कि इसका कारण उपयुक्त आवेदन पत्रों का श्रमान है। इसके विपरीत यह कहा गया है कि उपयुक्त आवेदन पत्र न आने का कारण अधिकारियों का असहयोग, उनका नीकरशाहो व्यवहार श्रीर आवेदन पत्रों पर निर्णय देने में अनुचित बिलम्ब है। कार्परिशन ने श्रव तक कम्पनियों को ही श्रृण दिये। इसने कानून के अनुसार न किसी रोयर की गारन्टी ली है श्रीर न अगुपात्र खरीदे ही हैं।

यह कहना अनुचित है कि वर्तमान समय में पूँजी बाजार की स्पिति ऐसी नहीं है कि कार्पोरेशन बीमा का कार्य करे। कार्पोरेशन के अध्यद्ध लाला औ राम ने बीधी सामान्य बैठक में बताया कि औद्योगिक विचीय कार्पोरेशन का उद्देश्य पूँजी बाजार के पूरक के रूप में कार्य करना है, न कि पूँजी बाजार की विल्कुल हटाकर स्वयं उसका स्पान ले लेना। इससे स्पष्ट है कि कार्पोरेशन के उद्देश्य को उचित प्रकार से नहीं सममा गया है और उसके कार्यों के सम्बन्ध में भी दृष्टिकीय उचित नहीं है। यदि मारत में पूँजी बाजार विकिस्त होता तो औद्यंगिक संस्थाएँ आवश्यकता पदने पर पूँजी एक जित कर सकती थीं और तब कार्पोरेशन की कीई आवश्यकता नहीं रह जातो। परन्तु चूँकि पूँजी बाजार विकिस्त नहीं है इसलिए कार्पोरेशन की आवश्यकता पदने।

- (३) कार्परिशन ने जो कुछ ऋगा दिया उस पर बहुत श्रिषक ब्याज लिया है। फरवरी १९५२ तक कार्पोरेशन की व्याज दर ५६ प्रतिशत रही। यदि व्याज श्रीर मूलघन की किशत विधि को चुकाने पर तो ३ प्रतिशत की छूट दी जाती थी। तदन्तर ब्याज की दर ७ प्रतिशत कर दी गई श्रीर छूट केवल ३ प्रतिशत ही रही। श्रीचोगिक कारखानों को दीर्घकालिक ऋगा की श्रावश्यकता होती है, श्रीर कारखाना चालू होने से पहले काफी समय तक उन्हें उस क्पये से श्राय नहीं होती है। इस हिंध्य से ६३ प्रतिशत व्याज की दर वास्तव में बहुत श्रिषक है श्रीर यही कारण है कि श्रीचोगिक संस्थाएँ कार्पोरेशन के पास ऋगा के लिए श्रावेदन पत्र नहीं मेजती हैं। कार्पोरेशन के श्रिषकारियों का कहना है कि श्रीचोगिक संस्थाओं द्वारा श्रुण लेने से पूर्व काफी समय तक कार्पोरेशन को उस धन पर स्वयं ऊँची दर से ब्याज देना पड़ना है इसलिए व्याज की दर कम नहीं की जा सकती है। परन्तु कार्पोरेशन की व्यवस्था को श्रीषक लोकपिय बनाने के लिए व्याज की दर कम करने के लिए श्रवश्य कुछ करना चाहिये।
- (४) यह कहा गया है कि कार्पोरेशन ने अब तक सहायता उन्हीं राज्यों को दी है जो पहले से ही विकसित हैं, श्रीर उन्हीं उद्योगों को दी है जो समृद्धि-शाली हैं। जून १६५७ के अन्त तक ६ वर्षों की अवधि में ५५.१२ करोड़ ६० की धनराशि में से १६ ३१ करेंड़ ६० ख च-उद्यागों को ८ ४४ करोड़ ६० वस्त्र उद्योगों को, ७ ५१ करोड़ ६० आधारभून अद्योगक रसायन उद्योग को, ४ २२ करोड़ ६० कागज उद्याग को, तथा ३.७७ करोड़ ६० सीमेन्ट उद्योग को वियागया।

यह कार्पोरेशन के लिये गर्व की बात है कि जून १६५७ के अन्त तक मंजूर की गई ५५.१२ करोड़ ६० की धनराशि में से ३३.८० करोड़ ६० अर्थात् ६१% उन संस्थाओं को दिया गया जिन्होंने १५ अगस्त १६४७ के बाद उत्पादन प्रारम्म किया। इसके अतिरिक्त जून १६५७ के अन्त होने वाले वर्ध में राज्यानुसार ऋण की मंजूरी में भी बहुत परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिये आँध, केरल, पंजाब, और उत्तर प्रदेश जैसे कम विकसित राज्यों को मंजूर किये गये ऋण् की मात्रा अधिक थी।

एक अन्य सन्तोषजनक बात यह यी कि १६५६-५७ में यद्यपि कार्पोरेशन के पास आने वाले आवेदन पत्रों की संख्या कम यो किन्तु ऋगा विवरित करने की गति अधिक यी। १६५६-५७ में ६.७८ करोड़ रु० का ऋगा दिया गया जब कि १६५५-५६ में २.२० करोड़ रु० का ऋगा दिया गया था। इसके निम्न कारण थे।

- (i) कार्पोरेशन के दफ्तर में प्रशासन सम्बन्धी सुधार पूर्ण हो गये थे।
- (ii) श्रीर श्रविक कान्त-श्रविकारियों की नियुक्ति हुई।
- (iii) पर्याप्त सम्पत्ति के आधार पर (दस्तावेजों क पूर्ण होने तक) अन्तरीय भूमण ग्रंजूर करने की विधि को सरल बना दिया।

जाँच की रिपोर्ट —कार्णोरेशन के कार्यों की प्रतीचा के लिये श्रीद्योगिक विचीय कार्णोरेशन जाँच कमेटी की नियुक्ति दिसम्बर १६५२ में श्रीमती सुचेता कृपलानी की श्रम्यच्चता में हुई। इस कमेटी ने ७ मई १६५३ को श्रपनी रिपोर्ट दी। कमेटी ने कार्पोरेशन को उसके विरुद्ध लगाये हुये पद्म गत के श्रामयोग से मुक्त कर दिया। पर यह टीका कि चेयरमैन तथा श्रम्य निर्देशक जिन श्रावेदकों के प्रांत विशेष कृपालु होते हैं उनके साथ कार्पोरेशन का व्यवहार श्रामक उदार होता है श्रीर उनका कार्य भी शीष्ठ कर दिया जाता है। इस प्रकार कार्पोरेशन की प्रवृत्ति उन उपक्रमों के प्रति, जिनका कार्य सुचार रूप से चल रहा है तथा जिनसे किसी लब्बप्रांतब्द उद्योगपति का सम्बन्ध है, पश्चपात करने की रही है। कमेटी के सुक्ताबों को तीन वर्गों में रवखा जा सकता है। प्रशासन और संगठन सम्बन्धी, कार्य प्रणाली सम्बन्धी तथा नीति सम्बन्धी। कमेटी के मुख्य सुक्ताब निम्न थे :—

प्रशासन सम्बन्धी—(१) कार्पोरेशन का संगठन परिवर्तित करके एक स्यायी वैतानक चेयरमैन नियुक्त किया जाना चा'हये जिसकी सहायता के लिये एक जनरल मैनेजर होना चाहिये। वर्तमान संगठन जिनमें अवैतानक चेयरमैन है तथा पूरे समय के जिए एक वैतानक मैनेजिग डाय्रेक्टर है, उपयुक्त नहीं है; (२) मैनेजिंग डाय्रेक्टर और सहायक फैंनेजिग डाय्रेक्टर के अधिकारों को विचार पूर्या ढंग से निश्चत कर देना चाहिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी के हाथ में अनावश्यक ढग से अधिकार वे निद्रत न हो जाँय; (३) कार्पोरेशन के बोर्ड में उद्योगपतियों का अधिकय नहीं होना चाहिये; सरकार को बोर्ड में अपने मनोनीत सदस्यों का नाम मेजत समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि उनमें एक अर्थशास्त्री, एक संगठन में दुशक व्यक्ति और एक चारटर्ड एकाउन्टेन्ट अवश्य हो; और (४) प्रत्येक शास्त्रा कार्यालय में उस पात्र विशेष के सलाहकारों का एक पैनल अवश्य हो जिनमें से दुस्त्र को प्रत्येक क्षत्रण के लिये दिये हुये आवेदनों पर विचार करने के लिये निर्वाचित किया जा सके तथा कार्पोरेशन बोर्ड यथा अवसर वस्वई, कलकत्ता, मद्रास हत्यादि स्थानों पर अपनी वैटक किया करे।

कार्य र गाली सम्बन्धी -(१) यदि कार्पोरेशन के किसी अध्यक्त का सम्बन्ध किसी ऐसे उपक्रम से है जिसने ऋगा के लिये आवेदन दिया है तो उसे श्रपना सम्बन्ध तुरन्त व्यक्त कर देना चाहिये। ऐसे उपक्रम जिनमें श्रीद्योगिक वित्तीय कार्पोरेशन का कंई डायरेक्टर मैनेजिंग डाइरेक्टर है अथवा डायरेक्टर. सामीदार या शेयर होल्डर उसकी मैनेजिंग एजेन्सी में है तो वह ऋण प्राप्त करने का श्रिधिकारी नहीं समका जायगा। ऐसे उपक्रम जिसमें कापीरेशन का हायरेक्टर एक साधारण डायरेक्टर अथवा शेयर होल्डर है, उसे ऋण पाने के लिये यह श्रावश्यक होगा कि हायरेक्टरों के बोर्ड की बैठक में जिसमें बोट देने के श्रिध-कारी ने सदस्य उपस्थित हो उसे (श्रपने ऋण के आवेदन पर) सर्व सम्मति से स्वीकृत मिले । यदि कार्पीरेशन का कोई डायरेक्टर किसी ऋग सम्बन्धी श्रावेदन से सम्बन्ध रखता है तों उसे बोर्ड की कार्यकारिगी समिति की बैठक में जब कि वह शृशा का श्रावेदन विचाराधान हो उपस्थित न होना चाहिये; (२) कार्पीरेशन को अपनी वार्षिक विवरण पत्रिका को अधिक विशद बनाना चाहिये तया अपनी पंच वर्षीय रिपोर्ट में ऋगा प्राप्त व्यक्तियों का नाम देना चाहिये, तथा उनके कार्य थ्रीर सफलता का वर्णन करना चाहिये श्रीर सम्पूर्ण उद्योग के विकास की प्रकृति स्नादि पर भी प्रकाश डालना चाहिये: (३) कम से कम ५०% तक ऋरण देने की सीमा नियत करनी चाहिये; (४) ऋण की न्याकृति देने तथा रुपया देने में देर कम करनी चाहिये, विशेष कर जा समय स्वामित्व सम्बन्त्री कानूनी कागजों की जाँच में लगता है उसे कम करना चाहिये: श्रीर (५) जब कोई उपकम श्रीची-गिक वित्तीय कार्पोरेशन द्वारा ले लिया जाय तब सामान्यतः उसका प्रबन्ध विभाग ऋषवा मैनेजिंग एजेन्सी को सींपने के बजाय मनोनीत डायरेक्टरों के बोर्ड को सींप देना चाहिये।

नीति सम्बन्धी—(१) कार्पोरेशन को श्रीद्योगिक विकास सम्बन्ध में जो प्रधानता योजना श्रायोग द्वारा दी गई है, श्रीर ४२ उद्योगों के सम्बन्ध में जो विकास का कार्यक्रम बनाया गया है उसी के श्रमुक्ल कार्य करना चाहिए। सामान्यतः उन उद्योगों को जो श्रपने विकास को उच्चतम स्थित पर पहुँच गया है काई श्रुण न देना चाहिये; (२) जिन सिद्धान्तों के श्राधार पर कारपोरेशन को कार्य करना चाहिये उनके सम्बन्ध में सरकार को निर्देश देने चाहिये। सरकार को उन चेत्रां के सम्बन्ध में जिन्हें पिछड़ा हुश्रा समक्ता चाहिये निरिचत निर्देश देना चाहिये तिक कारपोरेशन उन्हें प्रधानता दे सके; (३) कार्योरेशन को यह निर्देश देना चाहिये कि वह ५० लाख रुपये से श्रधिक श्रुण के श्रावेदनों को श्रागामी तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमस्वल में स्वीक्षति के लिये भेजे; (४) विचीय कार्पोरेशन के नित्य-प्रति के कार्य में केन्द्राय संसद के सदस्यों का प्रत्यच्च इस्तच्चेप श्रीद्योगिक यथा सम्मव न होना चाहिये, परन्त विधान समा को

कार्गोरेशन तथा नियमों के श्राधार पर स्थापित ऐसी श्रन्य कार्पोरेशनों के कार्यों को श्रिधिक नियमित रूप से परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करने के लिये एक पिल्लिक कार्पोरेशन कमेंटी के नियुक्ति पर विचार करना चाहिये; श्रीर (५) सरकार को यह सोचना चाहिये कि कार्पोरेशनों को श्रनुत्पादक कार्यों के लिये श्रमुण देने की नीति के सम्बन्ध में क्यों न निर्देश दिये जाँय।

सरकार ने कमेटी के कुछ महत्वशाली श्रामिस्तावों को छोड़ कर लगमग समी को स्वीकार कर लिया है। १६४८ के श्रीद्योगिक विचीय कार्पोरेशन एक्ट की घारा ६ की उपधारा (३) के श्रनुसार प्राप्त श्रीधकार के झन्तर्गत केन्द्रीय सर-कार कार्पोरेशन को निम्न निर्देश दिये हैं:—

- (१) कारपोरेशन बोर्ड को समय पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि केन्द्रीय स्थानों पर, अपने प्रधान केन्द्र दिल्लो के श्रतिरिक्त, सभाएँ करना चाहिये।
- (२) कार्परिशन के डायरेक्टरों को भूगण के लिये प्राप्त श्रावेदकों से श्रपना सम्बन्ध (जिसमें भूगण मांगने वाली कम्पनी का हिस्सेदार होना, श्रयवा उसकी मैनेजिंग एजेन्से के हिस्सेदार होना सम्मिलित होगा) श्रवश्य व्यक्त कर देना चाहिये श्रीर जिस समय उनके श्रुण के श्रावेदन पर विचार होने लगे वे समा में सम्मिलित न हो। एक रजिस्टर जैसा कि इन्डियन कम्पनील एक्ट की घारा ६१ ए (३) में बताया गया है वैसा ही कार्पोरेशन को भी रखना चाहिये।
- (३) कार्पोरेशन का वार्षिक विवरण श्रिषिक विशद होना चाहिये श्रीर श्रिषिक से श्रिषक स्चनायें उसमें दी जानी चाहिये। इस विवरण में उद्योगों के विकास का वर्णन श्रीर विशेष कर उन चेन्नों का वर्णन जिनमें श्रुण दिया गया है होना चाहिये। जिन उपक्रमों को स्पया उद्यार दिया गया है उनका नाम भी इसमें छपना चाहिये।
- (४) ऋण की स्वीकृति देते समय ५०% की न्यूनतम सीमा का ध्येय बनाना चाहिये श्रीर ऋण लेने वाले उपक्रम की श्राय श्रांजित करने की स्मता का विरोष रूप से अनुमान लगा लेना चहिये। डायरेक्टरों श्रीर आवेदकों के एजेन्टों के विच सम्बन्ध का विचार किया जाना चाहिये और जहाँ पर ये विच सम्बन्ध, कार्पोरेशन द्वारा सुरक्षा के कारण समफे जाँय, वहाँ डायरेक्टरों और मैनेजिंग एजेन्टों को ऋण लेने वाले उपक्रमों के अपने निजी शेयरों को बिना कार्पोरेशन के अनुमित के वेच डालने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये।
- (५) जिन विशेष आवेदकों को कार्पोरेशन ५० लाख रुपये से आधिक का ऋण देने का निर्णय करे उसकी रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित सरकार को मेजी जानी चाहिये। उन सब ऋण लेने वाले उपकमों की भी रिपोर्ट सरकार को मेजी

जानी चाहिये जिनमें कापोरेशन का कोई डायरेक्टर श्रुण लेने वाले उपक्रम की मैनेजिंग एजेन्धी में डायरेक्टर, सामीदार या मैनेजिंग डायरेक्टर श्रयवा हिस्सेदार हो। उन कम्पनियों को श्रृण प्रदान करने की रिपोर्ट जिनमें कापोरेशन का डायरेक्टर एक साधारण डायरेक्टर श्रयवा हिस्सेदार है, उस स्थिति में मेजना चाहिये जबकि श्रुण की स्वीकृति ऐसी मीटिंग में दी गई हो जिसमें श्रापे से कम डायरेक्टर उपस्थित रहे हों, श्रथवा श्रृण की स्वीकृति एसी मीटिंग में दी गई हो जिसमें श्रापे से कम डायरेक्टर उपस्थित रहे हों, श्रथवा श्रृण की स्वीकृति सर्व सम्मति से न प्राप्त हुई हो।

सरकार ने कमेटी की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की कि जब श्रीयोगिक वित्त का निरंशन का कोई हायरेक्टर ऋण के उपक्रमों मैंनेजिंग हायरेक्टर या **रामीदार इत्यादि** तो उन्हें ऋण पाने का ऋधिकारी न समका जाय। इससे ़ श्रीद्योगिक उपक्रम श्रनावश्यक कठिनाई में पढ़ जाँयेगे, तथा वब तक कि कार-पोरेशन की समस्त रूपरेखा ग्रीर पँजी का संगठन पूर्ण रूप से न बदल दिया जाय ऐसी शर्त लगाना अव्यवहारिक होगा। सरकार ने अनुत्पादक कार्यों तथा विशेष देत्रों को ऋण प्रदान करने की नीति सम्बन्धी कार्पोरेशनों को दिये जाने वाले निर्देशों के सम्बन्ध में की हुई सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि श्रीद्योगिक वित्तीय कारपीरेशन श्रीद्योगिक वित्त सम्बन्धी एक नवीन प्रयोग है श्रीर अनुभव से धीरे धीरे इसके सिद्धान्त विकसित होंगे तथा उसकी कार्य प्रणाली निश्चित होगी। इसके ऋतिरिक्त क्योंकि दो बढ़े सरकारी कर्मचारी कारपोरेशन के बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं सरकार के लिये पेसे निर्देशों को देने की कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती। १६५२ में कानून द्वारा कार्पेरिशन का अधिकार बढ़ा कर ५० लाख रुपये से भी अधिक ऋगा देने का कर दिया गया था, क्यों कि इतना ऋगु लेने वालों की संख्या भी बहुत कम रही है, इसीलिए सरकार को वर्तमान स्थित परिवर्तित करके कार्पोरेशन के लिये ऐसे ऋगा के प्रदान के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर देने का कोई न्यायोचित कारण समक में नहीं आता। ५० लाख रुपये से श्रधिक के भ्राग की सरकार को सचना देने की बात तो अनिवार्य कर ही दी गई है। इस लिये सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वर्तमान परिस्थित में पार्लियामेंट की पब्लिक कार्पोरेशन कमेटी की इस कार्पोरेशन श्रीर श्रन्य कानून द्वारा बनाये हुए कार्पोरेशनों की कार्यवाहियों की देख रेख करने के लिये नियुक्ति की कोई श्राव-श्यकता नहीं है। जाँच कमेटी की रिपोर्ट, तथा सरकार द्वारा उसकी सिकारिशों के अनुकूल किये गये कार्यों से यह आशा की जाती है कि कार्पेरेशन के कार्य में तथा कार्य करने के ढंग में बहुत कुछ परिवर्तन आ जायगा।

प्रान्तीय श्रथवा राज्य वित्तीय कारपोरेशन

२८ सितम्बर १९५१ में राज्य वित्त कार्पीरेशन कानून पास हुआ । यह कानून काश्मीर श्रीर जम्मू राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होगा श्रीर इसके श्चनसार प्रान्तीय सरकारें कार्णेरेशन स्थापित कर सकती हैं। भारतीय श्रीयंगिक वित्त कार्पोरेशन सीमित दायित्व वाली कम्पनियों को सहायता देता है। मध्यम श्रीर छोटे उद्योगों को भी सहायता देना वांच्छनीय समका गया है क्यों कि ये वन्द्रांय कार्पोरेशन के अन्तर्गत नहीं आते इसलिये प्रान्तीय वित्तीय कारपोरेशनी का ध्येय ऐसे ही उद्योगां को सहायता प्रदान करना होगा। इन राज्य विचीय कार्योरेशनों की स्थापना लगमग उसी रूप में होगी निसमें भारतीय श्रीद्योगिक विचीय कार्पोरेशन की स्थापना हुई है। वहुत योड़े से ही परिवर्तन होंगे। राज्य वित्तीय कारपोरेशन के सम्बन्ध में ऋग २० वर्ष के ही लिये दिया जायगा न कि 24 वर्ष के लिये जैसा कि मारतीय श्रोद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन के सम्बन्ध में हैं। राज्य वित्तीय कार्पोरेशन की शेयर पूँ जी ५० लाख रुपये से लगाकर ५ करोड़ रुपये तक होती है। शेवर पूँजी का तीन चौथाई प्रान्तीय राज्यों, रिजर्व बैंक ग्रनसचित वैंको. सहकारी वैंकों, वीमा कम्पनियों, विनियोग टस्टों तथा श्रन्य वित्त संस्याओं द्वारा श्रीर शार श्रन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जानी चाहिये। इस प्रकार राज्य त्रिचीय कार्पेरिशनों को ज्यक्तिगत विधनशोग करने वालों का भी सहयोग प्राप्त है। इन कार्पोरेशनों के सम्बन्ध में जनता द्वारा जमा की हुई धन-राशि कार्पीरशन की प्राप्त पूँ जी की मात्रा से ऋधिक नहीं हो सकती। राज्य वित्तीय कार्पोरेशन किसी एक उपकम को ऋधिकतम विन्त सहायता १० लाख रुपयों तक की दे सकता है।

राज्य वित्तोय कार्गेरेशन (संशोधन) ऋधिनियम १६४६ --राज्य विचीय कार्पोरेशन ऋधिनियम में संशोधन अविश्वयम द्वारा श्रमेक परिवर्तन किये गये जो १ श्रमदृवर १६५६ से लागू हुये। संशोधन श्रिधिनयम में निमन बार्तो की व्यवस्था है।

- (i) दो या अधिक राज्यों के लिये संयुक्त वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना अथवा अन्य राज्यों तक कारपोरेशन के अर्थ का विस्तार करना।
- (ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा श्रीचोगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण, या मंजूर किये गये श्रिशम या श्रिणित ऋणपत्रों के सम्बन्ध में इनके एजेन्ट के रूप में किसी श्रीचोगिक संस्था से व्यवहार करना।
- (iii) राज्य सरकार, अनुस्चित चैंक अथवा राज्यीय सहकारी चैंक की गारन्टी पर उद्योगों को ग्रार्थिक अनुम्रह प्रदान करना ।

- (iv) कारणेरेशन द्वारा सरकारी प्रतिभृतियों के वल पर श्रल्पकालीन श्रुख लेना।
- (v) रिजर्व वैक द्वारा कारपोरेशनों का निरीक्षण, राज्य पुनर्सगठन श्रिषिन्यम १९५६ जो १ नवम्बर १९५६ से लागू किया गया कि घारा १०२ (३) श्रीर (६) के अन्तर्गत किये गये विलयन के फलस्वरूप राज्य वित्तीय निगमों की संख्या दो से घट गईं। वम्बई श्रीर सीराष्ट्र के कार्पोरेशन मिलाकर बम्बई राज्य वित्तीय कारपोरेशन बना दिया गया। श्रान्त्र श्रीर हैदराबाद राज्य के कार्पोरेशन मिलाकर आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्तीय कारपोरेशन बना दिया गया। दिसम्बर १९५७ में निम्न राज्यों में से प्रत्येक में एक राज्य वित्तीय कार्पोरेशन था। मद्रास पंजाब, वम्बई, केरल, पश्चिमी वंगाल, श्रासाम, उद्दीस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार श्रीर श्रान्य प्रदेश।

१६५७-५८ के श्रन्त में १२ राज्य-वित्तीय कार्पोरेशन की कुल सम्पत्ति १८-१०४ करोड़ के थी जिसमें से ६-१५ करोड़ के श्रुण श्रीर श्रांश्रम थे। श्रतः १२ कारपोरेशन की परिटत्त पूँजी १३-१० करोड़ के थी तथा सुरक्ति कोष कुल ५ लाख के था। १६५६-५७ में मंजूर किये गये तथा दिये गये श्रुण की मात्रा क्रमशः ४-४३ करोड़ के तथा २-८६ करोड़ के थी जबिक १६५५-५६ में यह राशि क्रमशः ४-०५ करोड़ के तथा १-८० करोड़ के थी। कार्पोरेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का विस्तार धीरे-धीरे हुआ है, फिर भी जितनी सहायता कार्पोरेशन पूर्ण विकसित होने पर दे सकेगा उससे श्रमी बहुत कम सहायता देता है।

श्रारम्भ में कार्षोरेशन को बहुत ही कठिनाइयों का समना श्रावेदकों के श्रज्ञान, विशेषज्ञों के श्रमाव तथा श्रिषक करों के कारण करना पहा है। इन सब समस्याश्रों पर राज्य वित्तीय कार्पोरेशन की प्रथम श्रीर द्वितीय सभा में जो श्रमस्त १९५४ में श्रीर नवम्बर १९५५ में बम्बई में हुई थी विचार विनिमय किया गया था। प्रथम सभा का उद्घाटन करते समय रिजर्थ वैंक के गवर्नर श्री बीठ रामा राव ने विभिन्न राज्यों में मध्यवर्ती श्रीर छोटे उद्योगों के विकास के लिये ऐसे कार्पोरेशनो की महत्ता पर बहुत जोर दिया। यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि प्रारम्भिक श्रवस्था में श्रनुसरण की जाने वाली नीति की रूप रेखा पर सब एकमत ही, श्रच्छी परिपाटियों की नीव पहे, श्रीर उपयुक्त व्यवसायिक कार्य विधियों निश्चत हो, ताकि ये कार्पोरेशन श्रपने चेत्र के लिये श्रीधकतम लामकारी सिद्ध हों। हर बात में एकरूपता लाने के बजाय ध्येय में तथा कार्य विधि में समानता लाने श्रीर प्रीक्षोगिक कर्मचारियों तथा कार्य चेत्र श्रादि में समानता

लाने का श्रादर्श होना चाहिये। कार्णेरेशनों को जो गंभीर कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं, उनमें से एक तो प्रौद्योगिक कर्म चारियों के श्रभाव की है जो ऋगः के लिये आवेदन करने वाले उपक्रमिकों की योजनाओं की उपयुक्तता का परीचण कर सकें। कार्पोरेशान ६-७ प्रांतशत का जो व्याज वस्त् कर रहे हैं वह वहुत श्रधिक है। प्रारम्भिक श्रवस्था में इन कार्पोरेशनों का व्यय श्रवश्य बहुत श्रधिक है श्रौर सभा ने उनको राज्य सरकारों की स्टाम्प ब्यूटी से मुक्त करने की तथा केन्द्रीय सरकार के ग्राय कर से मुक्त करने की सिफाएश भी की थी। सबसे बड़ी क्रिनाई इस बात की है कि श्रमण के लिये आवेटन करने वाले उपक्रम अपना हिसाब किताब ठीक से लिखने तथा श्रन्य लेखा श्रीद्योगिक वैंकिंग के मान्य स्तर पर निर्माण करने के प्रति उदासीन लगते हैं। इससे आवेदनों पर कार्यवाही करने में श्रनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। कार्पोरेशनों को व्यक्तिगत सीमित दायित्व वाली कम्पनियों, सामेदारी, संयुक्त परिवार व्यवसाय, तथा एकाकी स्वामित्व वाले उपकर्मों से भी सम्पर्क रखना पड़ता है। ये उपक्रम सामा-न्यतः ऐसे कानून सम्बन्धी कागजों को जिन्से उस उपक्रम से उनका सम्बन्ध निश्चित होता है सुरक्तित रखने के प्रति उदासीन रहते हैं। बहुधा यह देखा गया है कि संयुक्त परिवार के व्यक्ति जिना किसी वँटवारे सम्बन्धी कानूनी लिखा पढ़ी के प्रयक हो जाते हैं श्रीर सामेदारों के मध्य हिसाव किताब सममने का कोई साधन नहीं रहता। ऐसे संयुक्त परिवारों और सामेदारियों के आवेदनों की जाँच करने में समय श्रीर व्यय बहुत लगता है। ऐसा पता लगा है कि छोटे उद्योगों के बोर्ड की स्यापना के कारण, जो ऐसे उद्योगों को सहायता देने में श्रिधिक उदार है, तथा चरकार द्वारा हाथ से घान कुटने तथा धानी द्वारा तेल पेरने के उद्योग को प्रोत्वाहित करने के लिये चावल तथा दाल की मिलों के विस्तार पर लगाये हुये प्रतिबन्धों के कारण, राज्य वित्तीय कार्पोरेशन के कार्य में बाधा पड़ी हैं। ये सब दोष घीरे-घीरे प्रयत्न करने से दूर हो सकते हैं।

श्रीद्योगिक विकास कार्पोरेशन

१६५४-५५ की दो महत्वपूर्ण घटनाश्रों में से एक तो २० श्रक्ट्वर १६५४ को राष्ट्रीय श्रीद्योगिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना श्रीर दूसरी १ मार्च १६५५ को भारतीय श्रीद्योगिक साख श्रीर विनियोग कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना थी। इन दोनों कार्पोरेशनों का ध्येय उद्योगों के लिये पूंजी की पूर्ति में वृद्धि करना है परन्तु इन दोनों संस्थाश्रों की कार्यविधि श्रीर कार्यचेत्र मिन्न-भिन्न है। भारतीय साख श्रीर विनियोग कार्पोरेशन लिमिटेड (श्राई० सी० श्राई० सी०)

दोनों में बड़ी संस्था है श्रीर उसे श्रिधक बढ़ा कार्य भी करना है। इसकी श्रिधकृत पृंजी २५ करोड़ रुपया है, जिसके १०० रुपया मृल्य वाले साधारण रोपर ५ लाख रुपये के हैं तथा १०० रु० के मृल्य २० लाख रोपर श्रवगीकृत है। इसकी निर्गमित पूंजी ५ करोड़ रुपया है जिसमें से २ करोड़ रुपये की पृंजी भारतीय वैंकों, बीमा कम्पनियों श्रीर श्रन्य सहयोगी कार्पोरेशनों द्वारा, १ करोड़ रुपये की पृंजी ब्रिटिश ईस्टर्न एवसचेंज वैंक श्रीर श्रन्य कामनवैल्थ तथा ब्रिटिश वीमा कम्पनियो द्वारा, ५० लाख रुपये की पृंजी यू० एस० ए० के बुख व्यक्तियों श्रीर कार्पोरेशनों द्वारा श्रीर रोप १३ करोड़ रुपये की पृंजी श्रन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई है। यह इस श्रव्यं में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था है इसके स्थापित होने में विभिन्न देशों के व्यक्तियों ने सहयोग दिया है।

श्राई० सी० श्राई० सी० एक न्यक्तिगत संस्था है और हसकी रिलस्ट्री इन्टियन कम्पनील एक्ट के ग्रन्तर्गत जनवरी १६५५ में हुई थी। पर इसे सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त है। १६५५ के मार्च में भारत सरकार ने श्राई० सी० को न्याल से मुक्त ७३ करोड़ रुपये का श्रुण प्रदान किया था जो कि दिये जाने की तिथि के १५ वर्ष के पश्चात् से १५ किश्तों में जुकाया जायगा। पुनर्निमांण तथा विकास सम्बन्धी श्रन्तरांष्ट्रीय वैंक ने इस कार्पोरेशन को १५ वर्ष के लिये १ करोड़ डालर तक के श्रुण की श्रनुमति ही है जिस पर ४५% का न्याल होगा जिसमें १% का परिनियत कमीशन भी सम्मिलत होगा। श्राई० सी० श्राई० सी० मारतीय श्रीद्यांगिक उपक्रमों को चेवल श्रुण ही न देगा वरन् वह उनकी शेयर पूँजी श्रीर श्रुण पत्रों को भी खरीदेगा। वह उनके श्रुण की गारन्टी। भी देगा। वह श्रीद्योगिक उपक्रमों को प्रवन्ध, प्रविधि तथा प्रशासन सम्बन्धी परामर्श भी देगा। साराश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा वह सब श्रीद्योगिक उपक्रमों को प्रवन्ध, प्रविधि तथा प्रशासन सम्बन्धी परामर्श भी देगा। साराश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा वह सब श्रीद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्सा होगा वह सब श्रीद्योगिक उपक्रमों को प्रवन्ध, प्रविधि तथा प्रशासन सम्बन्धी परामर्श भी देगा। साराश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा वह सब श्रीद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्सा उपयुक्त योजनाशों के लिये वित्त का प्रवन्ध करने के लिये उपाय करेगा।

तीसरी वापिक रिपोर्ट के अनुसार कारपोरेशन १६५७ के अन्त तक ४१ कार्यों के लिये ११ ६५ करोड़ ६० का अनुसार कारपोरेशन १६५७ के अन्त तक ४१ १६५६ में २५ कार्यों के लिये केवल ६ ०१ करोड़ ६० देने की सहमति दी गई थी। १६ ६५ करोड़ ६० में से ५ ४४ करोड़ ६० अनुसार के रूप में (जबिक १६५६ के अन्त तक केवल २ ६५ करोड़ ६० दिये गये थे) तथा ५ ३५ करोड़ ६० रोयरों तथा अनुपानकों के खरीदने के लिये दिये गये थे (१६५६ में यह राशि २ ३६ करोड़ ६० थी)। शेयरों की प्रत्यक्ष खरीद अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर रही। १६५७ में यह ६६ लाख ६० तथा १६५६ में ६८ लाख ६० थी। १६५७ में

मंजूर किये ऋगों की राशि में जो तीव युद्ध एुई उसका कारण यह या कि पहली बार विदेशी करेन्सी में पाँच ऋगा दिये गये में जिसकी राशि २'२१ करोड़ २० थी।

कारवेरिशन ते लाभ उठाने वाले उथागी का चेत्र बहुत विस्तृत है ! इनमें कागज, रसायन तथा श्रीविध, इन्जेक्शन का मामान (fue injection equipment), बिगली का सामान, यस्त्र, चीनी, धान, चूना श्रीर सीमेन्ट, तथा श्रीरे का निर्माण सम्मलित है। इस विविधता के श्रीतिरक्त कारवेरिशन की सहायता की एक विशेषता यह भी रही है कि इमके श्रम्तांन नये उपक्रमी के विकास तथा श्रम विकासत चेत्रों की शावश्यकता पर श्रीभक जीर दिया गया है। १६५७ के श्रम्त तथा श्राविक सहायता प्राव्त करने बाले इह संस्थाश्री में से १६ नये उपन्म थे।

राष्ट्रीय श्रीयंशिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (एन० श्राई० छी०) एक सरकारी संस्था है श्रीर इसका ध्येय मुख्यतः उन उद्य में को वित्त सहायता देना है जो पंचवर्षीय योजना के श्रम्तर्गत श्रा जाते हैं। २० श्रवट्टवर १६५४ को इसकी र्राजस्ट्री एक व्यक्तिगत सीमित दायित्य वाली कम्पनी के रूप में हुई थी। इसकी श्रिधिकृत पूँजी १ करोड़ कपया है श्रीर परिदत्त पूँजी १० लाख कपया है जो कि भारत सरकार द्वारा ही प्रदान की गई है। कार्गोरेशन को श्रानी पूँजी पदान का श्रावत सम्बत्त है।

एन० छाई० डी० सी० ने प्रथम योजना के छन्तर्गत छाये हुए उद्योगें को सदायता दी है। द्वितीय योजना काल में इयके कार्य का छीर छिक विस्तार होगा छीर इसके पास लगभग ५५ करां इ कपया व्यय करने के लिये होगा। 'इस धन राशि का एक छारा (जो लगभग २० या २५ करोड़ काया छनुमान किया जाता है) छाशा की जाती है स्ता कपड़े छीर जूड के सामान निर्माण करने वाले उद्योगों के छामनवीकरण में व्यय किया जायगा। शेष ३५ करोड़ के लगभग कपया नये मूल तथा बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना छोर विकास के लिये व्यय किया जायगा। जिन उपक्रमों के सम्बन्ध में खोज का कार्य एन० छाई० ही० सी० ने छपने कपर लिया है ये काउन्ही कीर्ज शाष्त, स्ट्रक्चरल फेब्रोकंशन, रिफ क्ट्रीज, छाजगरी कागज, छीपधियों तथा रंग बनाने की वस्तुयें, काला कार्व इत्यादि हैं। इन उपक्रमों के छातिरक्त यह छाशा की जाती है कि एन० छाई० ही० सी० इस बात का भी प्रयत्न करेगी कि छालमूनियम उद्योग का एक कार-खाना खोला जाय छीर भूमि खोदने, खान खोदने, तथा छायस्य छीर छायस्य रहित (ferrous and non-ferrous) उद्योगों में बेलन तथा बेलन के कारखाने

के प्रधाधनों के निर्माण का कारखाना खोला जाय। ज्यापार तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल में एक कमेटी की इस्र लिये नियुक्ति की गई है कि वह इस बात की सलाह दे कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत नई अलमूनियम प्रदावण्याला की स्थापना के लिये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है ताकि ३०,००० टन के उत्पादन का ध्येय जिसकी इस उद्याग के सम्बन्ध में सिकारिश की गई है पूर्ण की जा सके। प्रवन्ध किया जा रहा है कि बड़ी-बड़ी काउन्ड्यों, फोर्ज तथा स्ट्रक्चरल शास्त के उपकमों के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैय्यार की जाय। यह आशा की जाती है कि इन उद्योगों के सम्बन्ध में डिजाइनों के निर्माण तथा इनके विकास की सुविधाओं के उपाय किये जायगे।

"कारपोरेशन द्वारा अपेक्तित विच केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों और अनुषा के रूप में दिया जाता है। १६५६-५० में १४६ करोड़ ६० की व्यवस्था की गई थी। १६५७-५८ के बजट अनुमान में ४५० करोड़ ६० की व्यवस्था की गई थी। १६५७-५८ के बजट अनुमान में ४५० करोड़ ६० की व्यवस्था की गई है। जूट और सूती वस्त्र उद्योग के आभिनवीकरण के हेतु ऋण देने के लिये कार्पोरेशन सरकारी एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। अब तक कार्पोरेशन ने ६ सूती मिलों तथा दो जूट मिलों को कमशः १९६५ करोड़ ६० तथा ५५ लाख ६० मंजूर किये। कारपोरेशन द्वारा दिये गये ऋण की व्याज दर ४३ प्रतिशत प्रतिवर्ष है तथा वे १५ वार्षिक किश्तों में चुकाये जाते हैं"।

पुनर्वित्त कार्पोरेशन (Refinance Corporation)

मध्यम आकार के उद्योगों की सहायता के लिये ५ जून १६५८ को इन्डियन कम्पनील एक्ट १६५६ के अन्तर्गत पुनर्वित्त कार्पोरेशन (प्राइवेट) लि॰ की रिजरही हुई।

यह कारपोरेशन वम्बई मे होगा। इसके संचालक मरहल में सात सदंस्य होंगे जो इस प्रदार हैं:—रिजर्व वैंक श्रॉफ इन्डिया का गवर्नर (श्रध्यज्ञ), रिजर्व बैंक का एक डिप्टी गवर्नर, स्टेट बैंक श्राफ इन्डिया का श्रध्यज्ञ, जीवन बीमा कारपोरेशन का श्रध्यज्ञ तथा भाग लेने वाली बैंकों के तीन प्रतिनिधि।

कारपोरेशन की श्राधकृत पूँजी १ लाख ६० के २५०० रोयरों में विमाजित २५ करोड़ ६० होगां। प्रारम्भिक निर्गामत पूँजी १२'५ करोड़ ६० होगां जिसमें से ५ करोड़ ६० रिजर्व वैँक, २'५ करोड़ ६० जीवन बीमा कारपोरेशन, २'३ करोड़ स्टेट बैंक श्राफ इन्डिया तथा २'७ करोड़ ६० १४ चुनी हुई श्रनुस्चित बैंकों द्वारा प्रार्थित होगा।

र्चेंकों में निम्न सम्मिलित हैं। सेन्द्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद

वैंक, वैंक श्राफ इिएइया, द इन्टियन वैंक, द मरफेन्टाइल वेंक श्राफ इिएटया, हैदराबाद वेंक, वेंक श्राफ वड़ीदा, नेशनल वेंक श्राफ इिएटया, यूनाइटेड कमिरियल वेंक, ल्याड्स वेंक, चार्टर्ट वेंक, द यूनाइटेड वेंक श्राफ इिएटया श्रीर द डेना वेंक (Dena Bank) ।

मृग् ५० लाख २० में श्रिधिक के नहीं होंगे। श्रीर उनकी श्रवित तीन वर्ष

से कम तथा सात वर्ग से श्रधिक नहीं होगी।

यह मुविधा फेबल उन श्राद्योगिक संस्थाश्रो को प्राप्त होगी जिनकी पिन्दस्त पूँजी तथा मुर्राज्ञत कीप (करार्य तथा सामान्य श्रवज्ञयम् के मुर्राज्ञत कीप को छोड़कर) २६ करोड़ द० से श्रिषक न हो। सम्मु प्रधानतः द्वितीय तथा श्रन्य योजनाश्रों ने सम्मिलत उद्योगी का श्रीद्योगिक उत्यादन बदाने के लिये होंगे। इम उद्देश्य के लिये कार्पोरेशन को श्रपने साधनों के श्रातिरिक्त २६ करोड़ ६० के श्रूण का मी लाम मिलेगा जो मारत सरकार यूनाइटेट स्टेट्स की इसी प्रकार की धनराशि में से देगी। यह श्रमण ४० वर्ष के लिये होगा श्रीर इस पर सम्मवतः सरकार यू० एस० ए० को ४% प्रतिवर्ष का न्याज देगी।

कार्पिरशन स्वयं ऋण नहीं देगी। योजना में भाग लेने याली १५ भारतीय तथा विदेशों वैंके ऋण दिया करेगी। कार्पिरशन को इस उपलब्ध साधन ३८३ करोड़ ६० है (अर्थात् १२३ करोड़ ६० अपवा तथा २६ करोड़ ६० यूनाइटेड स्टेट्स का)। इस धनराशि में से अस्येक भाग तेने वाली बैंक का कोटा निश्चित कर दिया जायगा जिसके अन्तर्गत से कार्योरेशन से पुनर्वित्त की मुविधा आप्त कर सर्केंगे।

श्रध्याय २५ विदेशी पूँजी

किसी भी देश फी विछरी हुई आधिक ज्यवस्था की दो विशेषताएँ हैं-श्रपर्याप्त वचत तथा पूँजो का श्रमाय श्रीर मशीन, टेकनिकल सामान, टेकनिकल कुरालता इत्यादि का भागश्यकता की श्रपेत्ता श्रमाव । मारत इन दोनों दोषों से अस्त है श्रीर स्थिति पर विचय प्राप्त करने के लिए यद श्रावश्यक है कि विदेशी पूँजी का स्प्रायात किया जाय। विदेशी पूँजी की सहायता से हम देश की बचत का आर्थिक सायनों के निकास में उपयोग कर सकते हैं। यदि इस केवल अपने -सीमित साधनों पर ही निर्मर रहें तो यह विकास सम्मव नहीं हो सकता। विदेशी पूँजी से विदेशों से मर्शानें, टेकनिकल सामान खीर टेकनिकल कुरालता इत्यादि का आयात कर सकते हैं। यदि विदेशी पूँजी नहीं हो तो इस कार्य के लिए हम मुगतान चन्तुलन के माधनों का उपयोग कर सकते हैं परन्त यह साधन भी चीमित हैं ग्रीर वर्तमान में भारत का भुगतान चन्तुलन प्रतिकृत है। यदि यह श्रवुक्त भी हो तब भी इससे बहुत कम धन प्राप्त होगा। विना विदेशी पुँजी की चहायता के सन्तोपजनक श्राधिक प्रगति नहीं हो सकती। भारत को ही नहीं श्रिपित संसार के श्रान्य देशों को श्रापन श्रापिक विकास के श्रारम्भकाल में विदेशों पूँजी की सहायता लेनी पड़ी है। एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक सम्मेलन ने स्थिति का श्रध्ययम करके इस बात पर मदत्व दिया है कि पिछड़े हुए देशों की ग्रार्थिक स्पित का विकास करने ग्रीर उन्हें समुद्रशाली बनाने के लिए विदेशी पूँजी का श्रायात श्रत्यन्त श्रावश्यक है।

मारत में योजना श्रायोग ने श्रनुमान लगाया है कि १६५०-५१ में ६११० करोड़ की राष्ट्रीय श्राय में से लोगों ने श्रपनी श्राय के ४'६ प्रतिशत भाग की यचत की, श्रयांत् कुल ४५० करोड़ कार्य प्रति वर्ष बचत हुई श्रीर १६५५-५६ में ७६० करोड़ को बचत की जो कि १०८०० करोड़ की राष्ट्रीय श्राय की ७.३% थी। यह काया ज्यापार, यह निर्माण, सम्पत्ति के कय, जेवरी हत्यादि में लगाया

^{9.} दितीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय वचत श्रीर विनियोग की मात्रा में वृद्धि १६६०-६१ तक १,४४० करोड़ रुपया धर्यात् राष्ट्रीय ध्याय का ६,७२% कर दी जाय जो कि श्राशा की जाती है उस समय तक १६४८० करोड़ रुपये ही जायगी।

गया। इसके साथ ही कुछ नवह रवये भी अनावे गये। इम कुल अनत में ने देश के छीसोगिक विश्वास के लिये बहुत कम रवया लगाया रामा। लोग ज्यपनी छाय में से बहुत कम अनत कर याते हैं प्योगि लाधिकनर जनता इनती। निर्धन है कि कुछ भी बनत नहीं कर पाती। छीर जो ब्यांक कुछ अनत करते भी है उन्हें ये पूंजी के बाजार में नहीं लगाते। इन प्रतिभाविधी में वह लाखहूवक है कि इम भारत में विदेशी पेंजी का लाखन लें।

मिटिश शासन के आचीन—भारत में विदेशी शायनवान में विदेशी पूर्ण लगाई गई। यह पूर्ण रेमने, न्या, पूर्, क्षण्येत की गानी, न्यांगी श्रीर ज्यापार इस्माहि में लगाई गई। मिटिश पूर्ण रन उन्य मी पर लगाई गई क्षिण रेस पर उनया श्रांक्य र हुई रहे जा रिएम उन्हें देशा सामान फिल सन दिसकी विदेशों में श्रायात करने वो श्रायत्यका है या दिसके उन्हें श्रायत करने वो श्रायत्यका है या दिसके उन्हें श्रायत करने वो श्रायत्यका में में ई रिंग नहीं भी श्रायत करने प्रायत्यका में में ई रिंग नहीं भी श्रायत के साम है एवं हिलाम हुआ यह उनकी श्रामन विकास में में में पूर्ण करन में पहना श्रा हो गया। इसके कुछ संदेश नहीं कि भागत ने श्रीयाधिक स्था श्रायत है पर मिटिश पूँचा के श्रायत में श्रीयत मान के प्रायत के मिटिश पूँचा के श्रीयतियों ने देश का कमन्य स्थार स्थार हिया होता ना भागत का इस से से श्रीय श्रीय श्रीयक विकास करने के प्रश्न पर स्थार हिया होता ना भागत का इस से प्रश्न कि में से सक्त विकास हो सकता था।

इसी फारण विदेशा पूँजी का तीज विरोध दृष्टा वसीफि (१) जब अग्नेशी ने श्रास्पिक लाम फमाया ती भारतीय अस्टाय से देशने रहे। अंग्रेजी की स्वकार ने श्रानेक स्थियतें मी दी वसीकि सरकार मारतीयी की अपेसा विदेशियों का दहारत करती थी। इस मेद भाव से भारतायों की भारों स्थित उटानी पद्दी विस्ता स्था-मायिक ही विरोध किया गया।

- (२) विदेशा पूँजी से चलाये गये उद्योगी इत्यादि में श्रीधकतर विदेशिकों को ही नीकरी दी गई जिससे भारतीयों में श्रमन्तीय फैला। श्राने ही देश में मारतीय श्रमहाय ये श्रीर विदेशों वह सभी नुःवधार्ए प्राप्त कर रहे ये जिन पर वास्तव में भारतीयों का हो श्रीधकार था।
- (१) डायटर शान चन्द ने बताया है कि यह सत्य है कि हमारे देश में रेलवे, चाय, कहवा, श्रवरक' तींबा, जूट श्रीर श्रन्य श्रमेक उत्योगों के विकास का श्रेय विदेशों पूँजी को है परन्त विदेशा पूँजी ही के कारण मारत में श्रीबोणिक शक्ति का केन्द्रीकरण हुश्रा जिसके विषय में श्रिकिश श्रामनहीं है। इसके ही कारण

उद्योगों के प्रति मेद भाव की नीति के विकद सुरद्धा के वैधानिक प्रयत्न सम्भव ही सके। भारतीय उद्योग द्वेत्र में टाटा, विहला और हाल में डालिमया और वाल चन्द के आने पर भी विटिश उद्यागपितयों का ही प्रभुत्व है। एन्डक यूल, वर्ड, खवालेख, ओक्टेवियस स्टाल और कुछ अन्य विदेशो कम्पनियाँ मारत की श्रीद्यागिक आधिक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमाये हुए है; इसके साथ ही वित्त के साधन जूट, कपास, कीयला, चाय, यातायात, बिजली, इंजीनियरिंग और अनेक उद्योगों पर नियंत्रण रखते हैं। औद्योगिक शक्ति के इस प्रकार केन्द्रित करने की प्रवृत्ति का भारतीय उद्योगपितयों ने भी अनुकरण किया है जिससे देश को काफी इंति पहुँची है।

(४) १६२६ में प्रशुल्क संरक्षण का विदेशी उद्योग ने पूर्ण लाम उठाया श्रीर मारत में श्रवने कारलानों की शाखाएँ स्थापित की जिनके नाम के श्रामे (भारत) जिमिटेड जोड़ दिया। वास्तव में यह संरक्षण भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए या श्रीर जब विदेशी उद्योग ने इसका लाभ उठाया तो इसके श्रवन्तोप फैलना स्वामाविक ही या।

१६२५ में विदेशी पॅजी सामांत ने इस बात की जाँच की श्रीर सुकाव दिया कि विदेशी पँजी को भारत में प्रोत्साइन दिश जाय। परन्तु जब सरकार विदेशी उद्योग को कोई विशेष रियायत दे तो इस बात का ध्यान रखे कि उससे मुख्यतः भारत को ही लाभ पहुँचे । यदि सुविधा किसी विशेष उद्योग को न देकर सभी को सामान्य रूप से दी गई, हो, जैसे प्रशुल्क संरक्षण की सुविधा, तो किसी मकार का मेद भाव करना व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। परन्तु यदि किसी विशेष कारखाने को द्रव्य की सहायता दी जाय तो इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय व्यापारी के हित को हानि न पहुँचे। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक मार्रातयों को तत्सम्बन्धी शिज्ञा की उचित व्यवस्था न की जाय तब तक किसी विदेशी कम्पनी की कोई सुविधा न दी जाय। सार्वजनिक कम्पनियों के सम्बन्ध में यह सुकाव दिया गया है कि उनकी मारतीय कम्पनी कानून के प्रत्वर्गत रिजस्ट्रा करायी जाय, उनकी पूँजी भारतीय मुद्रा में हो श्रीर उनमें भारतीय संचालकों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित संख्या के बराबर हो। किन्तु खनिजों के विकास के लिये सुविधाएँ देने के लिए निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते। परन्तु भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वी-कार नहीं किया श्रीर विदेशी पूँजी प्रशुल्क संरत्त्त्या की सम्पूर्ण सुविधाश्रों का झीर सरकार द्वारा दी गई अन्य रियायतों का लाभ उठाती रही।

सरकार की नीति-यह सत्य है कि अवीत में विदेशी पूँजी के कारण

मारत में ग्रसन्तोष फैला परन्तु श्रव भारत स्वतन्त्र देश है श्रीर इसका कोई कारण नहीं है कि हम विदेशी पूँजी के प्रति श्रव भी प्राचीन मावना को प्रश्नय दें। विदेशी पूँजी से श्रव किसी प्रकार का राजनीतिक प्रमुख्न नहीं हो सकता श्रीर न जनतंत्रीय शासन कार्य में किसी प्रकार का इस्तच्चिप ही हो सकता है। इसके साथ ही विदेशी पूँजी को भारतीय उद्योग की श्रपेचा किसी प्रकार की श्रिषक सुविधा भी नहीं मिल सकती। भारत की प्रथम पंच वर्षीय योजना में २,३५६ करोड़ रुपया न्यय करने का प्रवन्ध था। इसकी पूर्ति में रुपये का श्रमाव था जिसमें से इन्छ श्रमाव किना विदेशी पूँजी प्राप्त किये पूर्ण नहीं हो सकता था। इसके श्रविरिक्त श्रीचोगिक तथा श्रायिक विकास के लिये भी इमें विदेशी पूँजी की श्रावश्यकता है क्योंकि श्रीचोगिक चेत्र का काफी श्रंश श्रमी निजी उद्योगपतियों के हाथ में है श्रीर इस श्रश के विकास के लिये पूँजी की श्रावश्यकता होगी। यही बात द्वितीय योजना में भी है।

इघर कुछ वर्षों से सरकार श्रीर भारतीय उद्योगपितयों के सम्पूर्ण प्रयत्नों के पश्चात् मी विदेशी पूँजी पर्याप्त मात्रा में नहीं ख्रा रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। (ग्र) मारत में विनियोग के भविष्य के विषय में अनिश्चितता का वातावरण है। विदेशी पूँजीपति को इस बात का विश्वास नहीं है कि भविष्य में इसकी पूँजी सुरिचत रहेगी। पूँजीपित रुपया लगाते समय पूँजी की सुरचा श्रीर उससे लाभ इन दां बातों का विशेष ध्यान रखता है। परन्तु विदेशी पूँ जीपति की मारत के सम्बन्ध में इन दोनों वातों पर सन्देह है; (व) भारतीय पूँ की की ही तरह विदेशी पूँजी पर लाभ कम होता है क्योंकि उत्पादन व्यय श्रधिक है और सरकार ने श्रनेक प्रतिवन्ध लगा रखे हैं। पूँजी पर लाम की दर कम होने के कारण विदेशी पूँ नी स्वामाविक रूप से भारत की ऋोर आकर्षित नहीं होती, (छ) अतीत में भारत में श्रिधिकतर ब्रिटिश पूँ जीपति विनियोग करते थे परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् से जिटेन की विच कठिनाइयों के कारण ब्रिटेन का विदेशी विनियोग सब देशों में, भारत को सम्मिलित करते हुये, घटा है। श्रव बिटिश पूँजी बितयों को इमारे देश में विनियं।ग करने के लिये श्रधिक घन कमाना सम्भव नहीं है। श्रम-रीकी पुँजीवित रुपया लगा सकते हैं, परन्तु श्रमी वह भारत में रुपया लगाने के श्रादो नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत हुआ है कि अमेरिकी सरकार विनियोग से पूर्व यह चाहती है कि भारत सरकार श्रमशिका का श्रनुसरण करे। भारत सरकार की विदेशी नीति किसी मी राष्ट्र गुट के साथ सम्मिलित होने की नहीं हैं। इसलिये भारत की तटस्प नीति से श्रमेरीकी पूँजी के श्राने में बाधा उत्पन्न हो गई है।

श्रप्रैल १६४८ तथा १६५६ में श्रीदांशिक नीति सम्मन्त्री घोषणा में श्रीर

पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन देने की श्रावर्यकता है। संसद में प्रधान मंत्री ने इस विषय पर प्रकाश डाला था कि सरकार विदेशी पूँजी को सभी उचित सुविधा श्रोर प्रोत्साहन देने के लिये प्रस्तुत है। विदेशी पूँजी के महत्व को बताते हुये प्रधान मंत्री ने बताया कि श्रतीत में विदेशी पूँजी को जिस प्रकार उपयोग में लाया गया है उसी के परिणाम स्वरूप श्राज इस बात पर महत्व दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय हित में विदेशी पूँजो के कार्य चेत्र श्रीर उसके उपयोग पर नियंत्त्रण रखा जाय। परन्तु श्राज स्थिति विल्कुल मिल्न है। इसलिए विदेशी पूँजी पर नियंत्त्रण रखने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उसका भारत के श्रविकतम लाभ के लिए उपयोग किया जाय। हमारी राष्ट्रीय बचत इतनी नहीं है कि इम जिस पैमाने पर देश का विकास करना चाहते हैं उसे पूर्ण कर सकें। इसके लिये भारतीय पूँजी के श्रमाव की पूर्ति करने के लिए भारतीय पूँजी के साथ ही विदेशी पूँजी की श्रावश्यकता इसलिये भी है कि विदेशी पूंजी के साथ ही हम मशीनें, टेकनिकल और श्रीद्योगिक शान प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि (अ) सभी भारतीय अयवा विदेशी-उद्योगों को भारत सरकार की श्रीद्योगिक नीति का अनुसरण करना पड़ेगा, (व) सरकार विदेशी उद्यागों पर इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी श्रीर न कोई ऐसी शर्ते ही लगायेगी जो अन्य सामान भारतीय उद्योगों पर लागू नहीं हैं, (स) विदेशी कम्पनियाँ उन्हीं नियमों के श्राधार पर लाभ कमाने के लिए स्वतन्त्र होंगी जो श्रन्य उद्योगों पर लागू हैं, (द) यदि कभी विदेशी उद्योग को सरकार श्रानिवार्य रूप से अपने श्राधकार में लेगी तब उसका उचित मुझावजा दिया जायगा, श्रीर (य) सरकार की हिष्ट में लाभ का धन चुकाने की वर्तमान सुविधाओं को लागू रखने में कुछ कठिनाई नहीं है श्रीर सरकार विदेशी पूंजी पर न कोई नये प्रतिबन्ध लगाना चाहती है श्रीर न लगे प्रतिबन्धों को हटाना चाहती है। परन्तु लाम का सुगतान विदेशी मुद्रा-विनियम की स्थित पर निर्भर करेगा। यदि सरकार किसी विदेशी कारखाने का श्रानिवार्यतः श्राने श्रीधकार में करेगी तो उसके श्राय के सुगतान के लिए उचित सुविधा होगी। यह उचित श्रीर निष्पन्च शर्ते हैं श्रीर विदेशी पूंजी को मारत में किसी प्रकार के मेद माव का मय होने का कोई कारखा नहीं है।

विनियोग की मात्रा—मारत में गत वर्षों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई यो इसके ज्ञान के लिए सही श्राँकड़े प्राप्त नहीं हैं। एक श्रतुमान है कि दो विश्व युद्धों के मध्य भारत में ६० करोड़ पौएड विदेशो पूँजी लगी हुई थी। एक श्रन्य श्रनुमान में बताया गया है कि यह पूँजी ८० करोड़ पौग्रह थी। एसोसिएन टेड चेम्बर श्राव कामर्स ने साहमन कमीशन को बताया था कि कुल १०० करोड़ पौग्रह विदेशी पूँजी भारत में लगी हुई है। यह सम्भव है कि द्वितीय युद्ध से पूर्व ब्रिटिश पूँजी की वापसी इत्यादि के पश्चात् भारत में ३० से ४५ करोड़ पौग्रह के मध्य विदेशी पूँजी लगी रही।

इस सम्बन्ध में आधिक विश्वसनीय सूचना भारतीय रिर्जव बैंक की विदेशी परिसम्पत्ति और ऋग्ण सम्बन्धी रिपोर्ट (१६५७) में दी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि १६५५ के अन्त में भारत की कुल देयता और सम्पत्ति कमशः ७६६ ३ करोड़ द० तथा १२५१.८ करोड़ रुपया थी। "इस प्रकार देयताओं के बाद ४८५५ फरोड़ द० की बचत थी। यह स्थिति पूर्णतः सरकारी चित्र के कारण थी जिसकी देयताओं की तुलना में ६६०.८ करोड़ रु० की बचत थी (सरकारो चित्र की सम्पत्ति ११७०.७ करोड़ रु० और कुल देयता २०६.६ करोड़ रु० थी) गैर सरकारी चित्र में सम्पत्ति की तुलना में देयता ४७५.३ करोड़ रु० अधिक थी (कुल देयता ५५६.४ करोड़ रु० तथा कुल सम्पत्ति ८१० करोड़ रु० था)।"

"पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुये स्थित इस प्रकार थी। यू० के० तथा पाकिस्तान भारत के ऋगी थे (४०८ प करोड़ क० तथा २६६ प करोड़ क० कमशः) जब कि यू० एस० ए० तथा शेष अन्य देशों के प्रति भारत ऋगी था। १६६५ प्रमुख में वर्मा के ४८ करोड़ क० के ऋगा को व अदायगी के कारण भारत वर्मा के प्रति ऋगी हो गया।"

"यद्याप १६५५ के अन्त में भारत एक साहूकार देश या किन्तु १६५७ के अन्त तक देश की स्टर्लिंग सम्पत्ति घटने तथा यू० एस० ए० अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कीष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के प्रति देयता बढ़ने के कारण वह ऋणी देश हो गया।

विदेशी व्यवसाय विनियोग

१६५५ के श्रन्त में व्यापारिक उपक्रमों की कुल देयता ५२२ करोड़ रु॰ थी जिसमें से ४८१ करोड़ रु॰ व्यापारिक विनियोग था। यह विनियोग मुख्यतः शाखाओं में तथा समीकृत मूल्य वाले कागजों में (equity holding) था। विनियोग का श्रिधकांश प्रत्यच्च प्रकार का था। विभिन्न व्यापारिक कियाओं के मध्य व्यापारिक विनियोग के वितरण में कुछ महत्वपूर्ण श्रन्तर हैं। विदेशी शाखाओं ने श्रधकतर पूँजी व्यापार, सार्वजनिक उपयोग के उपक्रम, परिवहन तथा रोपण उद्योगों में लगाई थी। प्रत्यच्च रूप से नियंत्रित च्याइंट स्टाक कम्पनियों ने श्रपने विनियोग को मुख्यतः निर्माण चेत्र में लगाया है।

इससे जात होता है कि विदेशी विनियोग में प्रत्यन्त विनियोग का ग्रंश पुरुपत: विदेशी कम्पनियों में बहुत बड़ा है। व्यक्तिगत चेत्र में विदेशी विनियोग के विश्वलेषण से जो कि ४८० ६ करोड़ रुपया का या (श्रीर जिसकी विशेष विवेचना श्रागे करने जा रहे हैं) यह जात होता है कि निर्माण करने वाले उपक्रमों में सबसे श्राधिक धन (१६३ करोड़ रुपया) लगाया गया था; उसके पश्चात दूसरा स्थान व्यापार का है जिसमें १०३ करोड़ रुपया लगाया गया था। बैंक, परिवहन श्रीर खान खोदने के उद्योगों में भो विदेशी पूँजी लगो हुई है। व्यापारों में जो पूंजी लगी हुई है उसका विश्लेषण निम्न है:—

	करोड़ रुपये में
निर्मांख .	१६३'३
च्यापार	१०२'३
रोपख्	⊏ 9°?
उपयोगितार्ये तथा परिवहन	યુર્જ .
ৰি ত্ত	· \$*3\$
खा र्ने	€'€ .
विविष '	२५.६
•	कुल ४८० ६

"शहूकार देशों में ब्रिटेन की स्थिति प्रमुख वनी रही। १६५५ के अन्त में ब्रिटेन के प्रति देयता ४०० करोड़ से अविक भी तथा कुल विदेश। ज्यापारिक देयताओं की ७७% थी। यू० एस० ए० ने ४५ करोड़ की विदेशी पूँजी प्रदान की जिसका अधिकांश पेट्रोलियम में लगाया गया। शेष देशों ने ७४ करोड़ ६० की धनराशि दी जो हमारी विदेशी वित्तीय देयताथों की लगभग आधी हैं।"

१९४८ स्थीर १९४३ के मध्य—रिजर्व वैंक की प्रथम रिपोर्ट ३० जून १९४८ तक के लिये थी। दूसरी रिपोर्ट में रिजर्व वैंक ने विदेशी विनियोग के दिसम्बर १९५३ तक के आंकड़े दिये हैं। उसके अनुसार विदेशी व्यापारिक विनियोग में ३० जून १९४८ से लगा कर ३१ दिसम्बर १९५३ तक वास्तविक वृद्धि १३२ करोड़ कपये की हुई जिसमें से ११२ करोड़ क्पया (अर्थात् ८५%) प्रत्यस् विनियोग था जिसका वितरसा निम्न है:

(करोड़ रुपयों में)

नियन्त्रित भारतीय ज्याइन्टस्टाक कम्पनियाँ विदेशी कम्पनियों की शाखार्यें

४२ ७०

"ब्रिटेन और अमेरिका के विनियोग में क्रमशः १३७ करोड़ और १३ करोड़ नपयों की वृद्धि हुई श्रीर पाकिस्तान तथा लङ्का का फमशः ७ करोड़ श्रीर २ करोड़ रुपया घट गया । विनियोग में वृद्धि का न्यापारी के दिष्टिकी सु से विश्ले-पण करने पर यह ज्ञात होता है कि निर्माण सम्बन्धी चेत्र में ६४ करोड़ रुपये, , न्यापार में ३० करोड़ रुपये, बागवानी में २० करोड़ रुपये, उपयोशिताछों में १६ करोड़ रुपये श्रीर विविध में ६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। विटेन श्रीर श्रमरीका का नवीन विनियोग श्रविकांश नियन्त्रण युक्त या श्रीर यदि कल विनि-योग की वृद्धि से नियन्त्रण युक्त विनियोग का प्रतिशत लगाया जाय तो ब्रिटेन का प्प श्रीर श्रमेरिका ६१% था। श्रमेरिका का नवीन विनियोग विशेषकर न्या-पारिक चेत्र तक ही सीमित रहा परन्तु बिटेन का विनियोग भिन्न चेत्रों में विभक्त है जैसे निर्माण (५६ करोड़ रुपया) बागवानी (२१ करोड़ रुपया), व्यापार (२० करोड़ रुपया), उपयोगिताय (१६ करोड़ रुपया) श्रीर वित्त (१४ करोड़ रुपया)। ३० जून १६४८ के पश्चात् रजिस्टर की हुई कम्पनियों में लगाई हुई विदेशी पूँची की मात्रा तेल परिष्कर्राण्यों को छोड़कर जिनमें लगी हुई पूँजी शाखाश्रों में बढ़े हुये विनियोग में सम्मिलित की जा चुकी है-लगमग ११ करोड़ रुपये के थी, जिसमें से ७ करोड़ रुपयों का नियन्त्रण विदेशों से होता या। ब्रिटेन से प्रात पूँजी की मात्रा ६ करोड़ रुपये के लगभग और श्रमेरिका से प्राप्त लगभग १ करोड़ रुपये के अनुमान किया गया था।

१६५३ और १६५४ के मध्य—यदि वर्तमान सर्वे ज्ञाण की तुलना १६५३ के सर्वे ज्ञाण से की जाय तो पता चलेगा कि इन दो वर्षों में विदेशी विनियोग में ६१ करोड़ के की वृद्धि हुई है। ३१ दिसम्बर १६५५ को विदेशी विनियोग की मात्रा ४८१ करोड़ के यी। चूँ कि इस बीच में मूल्यांकन सम्बन्धी कुछ परिवर्तन हुये हैं इसियं ६१ करोड़ कपया पूँजी की वास्तविक गतिशीलता नहीं दिखाते। ऐसे परिवर्तन छ्राय-व्यय लेखा के चल छोर अचल दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों में हो सकते हैं।"

" मूल्यांकन सम्बन्धी परिवर्तनों को व्यवस्थित कर लेने पर विदेशी व्या-पारिक विनियोग ३६ करोड़ क० का होगा। इसमें से ४ करोड़ क्पया की वैंक-पूँजी निकाल देने पर गैर-वैंकिंग व्यवसाय में विनियोजित राशि ३५ करोड़ ६० होगी। वास्तव में प्रत्यच्च विनियोग ३६ ३ करोड़ क० का था। इसमें से २४५ करोड़ ६० का विनियोग व्यद्धिंट स्टाक कम्यनियों तथा ११८ करोड़ ६० का विनियोग विदेशी कम्पनियों की शाखाओं में था। 'पोर्ट फीलियो' प्रकार के विनियोग में १११ करोड़ ६० की वास्तविक कमी हुई।

ent the telephone purpose programme and prog	करोड़ रु॰ में
मत्यज्ञ विनियोग	the control of the approximation of the second
(a) 'नियंत्रित' भारतीय ज्याइन्ट स्टाक कम्पनियाँ	+ 58.8
(b) विदेशी कम्पनियों की शाखार्ये	+ 55,0
कुल योग	+ ३६⋅२
पोर्ट फोलियो विनियोग	4.4
देश में आई कुल विदेशी पूँजी (inflow)	+ 84.5

३५:२ करोड़ द० में से २४ करोड़ द० नई कर्मानयों (जो ३० जून १६४८ के बाद स्थापित हुई) में लगा था तथा ११:२ करोड़ द० पुरानी कम्पनियों में लगा था। नई कम्पनियों में से १६:५ करोड़ द० पेट्रोलियम निर्माण के लिये तथा ३:४ करोड़ द० पेट्रोलियम के खलावा ख्रम्य में लगा था।

१६५४-५५ में विनियोजकों में यूनाइटेड किंगडम सबसे आगे रहा; फिर भी इस अविध में इसका विनियोग परले की अपेसा बहुत कम था। सम्यत्ति के पुनर्मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुये १६५४-५५ में युनाइटेड किंगडम के विनियोग में २३-२४ करोड़ के की वृद्धि हुई अर्थात् वृद्धि की दर ११-१२ करोड़ के प्रांत वर्ष थी। इसके विगरीत यू०एए०ए० की विनियोग दर कँची उठी। जुलाई १६५८ में दिसम्बर १६५३ तक अधित विनियोग ३'४ करोड़ के थी। १६५४-५५ में यह ४'६ करोड़ के था। १६५४-५५ में यूनाइटेड स्टेट्स का विनियोग मुख्यतः पेट्रोलियम के अन्तर्गत था। १६५४-५५ में जर्मनी के विनियोग में भी उल्लेक्स एवंद्व हुई यरापि कर्मनी का कुल विनियोग अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।"

व्यक्तिगत विनियोग के श्रांतिरिक्त मास्त में विदेशी पूँजी श्रमेरिकी सरकार ने श्रमुदानों तथा श्रमुख के रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय देहु, ने श्रमुख के रूप में श्रीर फोर्ट फाइन्देशन ते श्रमुदान के रूप में तथा कोलम्बो प्लान श्रादि के श्रम्यांगत

प्रथम योजना में प्राप्त विदेशी पूँजी की मात्रा

	ग्रिधिकृत	ऋग	मार्च १९५६ तक	शेष मात्रा जे।
	प्रदान	श्रथवा	प्रयोग में आने	द्वितीय योजना
		श्रनुदान	की मात्रा का	में काम श्रा
			श्रनुमान	स केगी
ध्यमेरिका				
गेहूँ ऋण	€0.3	ऋग	१००३	-
{ भारत-श्रमेरिकी { सहायता कार्य कम	१०२.प	श्रनुदान	७०.त	३२'०
रे सहायता कार्य कम	₹€•₹	ऋग	6.0	३२°३
श्रन्तर्राष्ट्रीय वैंक	15.0	ऋग	দ্ৰ•্ম	ই ' ধ্
कोलम्बो योजना				•
श्चास्ट्रेलिया	१०.स	ग्रनुदान	५ •३	प्रभ
कनादा	३५•६	ग्रनुदान	१ ६ .म	१६•२
न्यू जी लैगड	१•२	ग्र नुदान	٥٠٦	3.0
ब्रिटेन	o •પૂ	श्रनुदान	०'३	٥٠٦
फोर्ड फाउन्डेशन	५.४	श्चनुदान	२'०	₹'४
नावे [°]	०•३	श्रनुदान	۶٬۰	०'१
कुल	२६७ द		२०३'६	६३ दः

प्राप्त होती रही है। वास्तिविकता तो यह है कि प्रथम योजना में जितनी विदेशी पूँजी की प्राप्ति की हम श्राशा लगा रहे थे उससे बहुत कम प्राप्त हुई। श्रांकड़ों के श्रनुसार विदेशो वित्त की कुल मात्रा जो प्रथम योजना में श्रिधकृत थी वह रहद करोड़ स्पया थी, जिसमें से हम केवल २०४ करोड़ स्पयों का प्रथम योजना काल में प्रथोग कर सर्कोंगे श्रीर इस प्रकार ह४ करोड़ स्पया द्वितीय योजना में लगाये जाने के लिये शेष रह जायगा।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में जिन्न भे ४८०० करोड़ रुपया व्यय किया जाने वाला है। सरकारी चेत्र में ८०० करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी और व्यक्तिगत चेत्र में लगभग १०० करोड़ रुपये की। इस प्रकार १६५६ से १६६१ तक के ५ वर्षों में कुल ६०० करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी की आवश्य-कता होगी। दितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में, ऐसा श्रनुमान किया जाता है, कि
४३८ करोड़ रुपया की बाह्य सहायता प्राप्य होगी। (३८ करोड़ रु० १९५६ ५७ में,
१०० करोड़ रु० १९५७ ५८ में, तथा २०० करोड़ रु० १९५८ में)। यदि यह
मानलिया जाय कि द्वितीय योजना के शेष दो वर्षों में ६०० करोड़ रु० की बाह्य
सहायता उपलब्ध होगो तो संपूर्ण योजना काल में उपलब्ध राशि १०३८ करोड़
रु० होगी जो सरकारी देन के लिये श्रनुमानित ८०० रु० की राशि से २३८ करोड़
रु० द्रीभी जो सरकारी देन के लिये श्रनुमानित ८०० रु० की राशि से २३८ करोड़
रु० द्रीभी हो तरकारी देन के लिये श्रनुमानित ८०० रु० की राशि से २३८ करोड़
रु० द्राधक होगी। किन्तु मृल्यों के लेंचे होने तथा द्वितोय योजना की विदेशी
विनिमय की श्रायश्यकता बढ़ जाने के कारण विदेशी विनिमय की उपलब्धि का
उपर्युक्त द्रादि प्रमुल योजनाश्चों के लिये भी श्रपर्यान्त सिंद होगी।

श्रध्याय २६ उद्योगों का स्थान निर्धारण

किसी उद्योग का स्थान निर्धारण अनेक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा प्राकृतिक कारणों पर निर्भर होता है। यदि उपर्युक्त विभिन्न कारणों से किसी उद्योग की अनेक फैक्ट्रियाँ किसी एक स्थान पर केन्द्रित हो जाती हैं तब वह उद्योग का स्थानीयकरण कहलाता है। इस सम्बन्ध में 'वैवर' का सिद्रान्त कुछ दोषों के होते हुये भी सबसे ऋषिक विचार पूर्ण है। यह सिद्धान्त ऋार्यिक कारणों पर भी विचार करता है जैसे टन-मीलो परिवहन व्यय जिसमें माल की मात्रा तथा उसके ले जाये जाने की दूरी का पूर्ण विचार रक्खा जाता है। किसी फैक्ट्री के स्थापित करने के लिये सब से श्राधिक उपयुक्त स्थान वह है जहाँ पर कच्चे माल तथा निर्मित माल दोनों के ही दृष्टिकोण से टन-मील परिवहन व्यय न्यूनतम हो। वैवर ने कच्चे माल को दो भागों में विभाजित किया है (१) सर्वत्र प्राप्य माल' जैसे ईट, मिट्टी, बालू, पानी इत्यादि जो सर्वत्र प्राप्त है और (२) 'स्थानीय माल' जैसे लीह श्रमस्क, नौक्खाइट, चीनी, रुई, कोयला ग्रादि जो विशेष स्थानों से ही प्राप्त हैं। स्थानीय माल को फिर वैतर ने शुद्ध तथा चीण-भार नामक दो मागों में विभाजित किया है। शुद्ध में ऐसी वस्तुयें जैसे कपड़ा विनने तथा सूत कातने के लिये रूई, सीमेंट बनाने के लिये बालू श्रीर चूना श्रादि जो श्रपने सम्पूर्ण भार से निर्मित माल में मिल जाते हैं, सम्मिलित किये जाते हैं। चीया-भार (weightlosing) माल में वे वस्तुयें हैं जिनका भार छीज जाता है जैसे गन्ना, कीयला श्रादि सम्मिलित किये गये हैं। क्योंकि पहले प्रकार की वस्त्ये सर्वत्र प्राप्त होती हैं इसलिये उनका किसी उद्योग के स्थान निर्धारण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता; परन्तु विशेष स्थान में प्राप्त होने वाली वस्तु का प्रमाव उद्योग के स्थान निर्धारण में वहुत श्रिषिक होता है। इनमें भी वे वस्तुयें जिन्हें ज्ञीण-भार कहा गया है विशेष महत्व की हैं। इन वस्तुश्रों का भार निमित वस्तु के निर्माण में छीज जाता है इसिलये इनका प्रयोग करने वाले उद्योगों की, जहाँ पर ये वस्तुर्ये प्राप्त हैं, वहाँ केन्द्रित होने की प्रवृत्ति होती है । वैबर ने 'माल का इन्डेक्स' निर्माण किया ताकि उसके आधार पर यह शात किया जा सके कि कच्चे माल की प्राप्ति का स्थान श्रयवा निर्मित वस्तु के विक्रय का स्थान दोनो में से कौन किसी उद्योग के केन्द्रित होने में श्रधिक प्रभावशाली कारण होता है। यह 'इन्हेक्स' स्थान विशेष पर

प्राप्त कच्चे माल के भार को निर्मित वस्तु के भार से विभाजित करने से प्राप्त होता है। यदि 'माल का इन्डेक्स' किसी उद्योग के सम्बन्ध में बड़ा है तो इससे यह सममाना चाहिये कि कच्चे-माल की प्राप्ति का स्थान श्रिधिक प्रभावशाली कारण है श्रौर उद्योग की स्थापना के लिये वह स्थान श्रधिक उपयुक्त होगा परन्तु. यदि 'माल का इन्डेक्स' छोटा है तो उससे यह सममाना चाहिये कि कच्चेमाल की प्राप्ति कोई विशेष महत्वशाली बात नहीं है श्रौर उद्योग की स्थापना श्रच्छी प्रकार बाजार के निकट की जा सकती है।

परन्तु जैसा इस सिदान्त में बताया गया है उसके अनुसार जहाँ न्यूनतम परिवहन न्यय हो वहाँ सर्वदा उद्योग स्थापित नहीं किये जाते । इसके कई कारण हैं, जैसे (१) उद्योगपतियों को कब्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोतों श्लीर बाजारों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि वे ठीक-ठीक आवश्यक अनुगणन कर सर्के । होता यह है कि श्रीसत दर्जें का व्यवसायी वर्तमान उद्योगों की स्थिति का श्रवमान लगा लेता है श्रीर जहाँ पर उसकी समक में यह श्राता है कि वह श्राधिकतम लाम उठा सकेगा नहीं श्रपना कारखना लोल देता है। सामान्यतः वे उद्योग जो किसी स्थापन निशेष में केन्द्रित हो गये हैं कुछ ऐसी लामकारी स्थिति वहाँ उत्पन्न कर देते हैं जिनके कारण नवीन कारखाने वही स्थापित होने लगते हैं जिससे वहाँ श्रीर श्रिविक स्थानीयकरण हो जाता है, (२) उद्योगपतियों के समज्ञ स्थान निर्धारण में सदा श्रापिक ही कारण नहीं रहते। वे सामाजिक सुविधार्ये तथा जीवन की अन्य सुविधाओं की प्राप्ति का भी विचार करते हैं जो नगरों में सुगमतापूर्वक प्राप्त हैं। इस कारण से भी वे बहुधा बहु-बड़े नगरों में या उनके आसपास अपने कारलानों के खोलने का निश्चय करते हैं चाहे ऐसा करने में उन्हें ग्राम में कारखाना खोलने की अपेन्ना लाभ कुछ कम ही क्यों न पान्त हो; और (३) युद-काल में इवाई हमला से रक्षा का भी व्यान रखना आवश्यक होता है इसिलिये बहुधा उद्योगों की स्थापना खुले हुये नगरों से दूर तथा नदी के किनारों से दूर देश के श्चान्तरिक भाग में करना पड़ता है चाहे इसमें श्चार्थिक हानि ही क्यों न उटानी पड़े।

प्रवृत्ति—भारत में उद्योगों का स्थान-निर्धारण बुटिपूर्ण है। एक ग्रोर जब कि बम्बई, पश्चिम बंगाल ग्रीर बिहार में श्रपेद्धाकृत श्रिषिक श्रीद्योगीकरण हुआ है तो दूसरी ग्रोर श्रन्य राज्यों में श्रीद्योगीकरण के प्राय: सभी साधन होते हुए भी विशेष विकास नहीं हो पाया है। इसके साथ ही दूर मार्मों की श्रपेद्धा नगर के पढ़ोस में ही उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से मारत के बढ़े नगरों का श्रमुचित प्रसार हो गया है।

वालिका १ भारत के छौंचोगिक श्रमिकों की कुल संख्या का प्रतिशत

प्रदेश	१६२१क्ष	\$ E ₹ E \$8	१९४३३	१६५१
वंगाल ग्रीर वम्बई	६२.४	५६•२	₹0.£	तर,३
वंगाल, वम्बई, मद्रास,				
उत्तर प्रदेश ग्रीर विहार	ಜಕ್ಕೆ	<u> </u>	28.8	בביצ
रोप भारत में	१६ ६	१ ४'१	१५ ६	११ 1६
श्राप भारत म		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 2.4	

क्षुत्रविभाजित भारत के श्रांकड़े

तालिका १ के अनुसार १६५१ में भारत के कुल श्रीसांगिक श्रमिकों के ५४ में प्रांतरात बंगाल श्रीर बबर्ग्ड के दो राज्यों में कार्य करते ये श्रीर क्या श्रीर बबर्ग्ड के दो राज्यों में कार्य करते ये श्रीर क्या करते हैं। यह प्रांत वंगाल, बम्बर्ड, मद्रास, उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार के पाँच राज्यों में कार्य करते ये। इसका श्रम्य है कि श्रीसोगिक विकास की हिन्द ने श्रम्य चेत्र पिछड़े हुए हैं जिनमें कुल श्रीसोगिक श्रमिकों के केवल ११ द प्रतिशत कार्य करते हैं। यह प्यान देने योग्य बात है कि बम्बर्ड श्रीर बंगाल चेत्र में कुल श्रीसोगिक श्रमिकों की संख्या १६२१ में ६२ १ प्रतिशत थी जो घटकर १६५१ में ५४ ३ प्रतिशत हो गई जब कि मद्रास, उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में इनकी संख्या १६२१ में कुल श्रमिकों के २१ प्रतिशत से बद्धकर १६५१ में रह द श्रीर १६५१ में ३४ १ प्रशित हो गई। योप भारत के श्रम्य चेत्रों में कुल श्रीसोगिक श्रमिकों की संख्या १६२१ में १६ प्रतिशत यी जो घटकर १६५३ में १५ ६ प्रतिशत श्रीर १६५१ में ११ ६ प्रतिशत यी जो घटकर १६५३ में १५ ६ प्रतिशत श्रीर १६५१ में ११ ६ प्रतिशत हो गई। इसका यह श्रभ है कि बंगाल श्रीर बम्बर्ड तथा देश के श्रम्य चेत्रों की श्रमेना महास, उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में उद्योग श्रीक केन्द्रित हुने हैं।

वालिका २ भारत के कुछ नगरों की जनसंख्या (लाखों में)

	\$ 6 3 8	\$E X \$	१६५१
कलकत्ता	१३'८६	30.82	३५.४६
यम्बर्ड	११.६१	१६•६५	रदः ३६
कानपुर	२'४४	४ ° ८७	७•०५
मद्राप्त	६•४७	6.00	१४・१६
दिस्रो	, ≨. ८७	प् •२१ ·	દ∙શ્પ્

तालिका २ के थ्राँकड़ों को देखने से पता चलता है कि १६२१ से १६५१ के बीच के ३० वर्षों में मारत के बड़े नगरों कलकत्ता और वम्बई की जन-संख्या में बहुत श्रिषक वृद्धि हुई है। कलकत्ता और वम्बई की जन-संख्या श्रपने दो गुने से भी श्रिषक हो गई है जब कि कानपुर की जन-संख्या तीन गुनी हो गई है। इसका एक कारण तो यह है कि श्रन्य नगरों की भांति गाँव से लोग श्राकर इनमें बसते गये हैं थ्राँर साथ दी इन चेबों में उद्यागों के केन्द्रित हो जाने से भी जनसंख्या में बृद्धि हुई है।

ष्टानियाँ-नगरों श्रीर बड़े कस्त्रों में उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से अनेक हानियाँ होती हैं जिनमें से प्रमुख निम्निलिखत हैं :-(१) इससे जन-संख्या स्यान के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ जाती है और इससे भीड़ एवम् धिन-पिन हो जाती है। इसका जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पढ़ता है, सफाई नहीं रह पाती, रहने के लिए घरों का अभाव हो जाता है और इन चेत्रों में अनेफ सामा-निक बराईयों कि वृद्धि श्रीर उनका प्रसार होने लगता है। यदि उद्योगों को उचित रूप से विभिन्न उपयुक्त स्थानों में स्थापित किया जाता तो इनमें से बहुत सी बुराईथों से बचा जा सकता था; (२) उद्योग केवल बड़े कस्बों और नगरों में ही केन्द्रित नहीं हुए हैं वरन् कुछ मुख्य प्रकार के उद्योग खास-खास राज्यों में केन्द्रित हुए हैं। चीनी उद्योग श्रधिकतर उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में, सती उद्योग बम्बई. मध्य-प्रदेश श्रीर उत्तर प्रदेश में, लोहा श्रीर इस्पात उद्योग बिहार में, जूट बगाल में और कांयले की खदानों की उद्योग बंगाल और बिहार में केन्द्रित हैं। इसका एक कारण तो यह है कि इन चेत्रों में अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल और विजली मिल जावी है और दूसरा कारण उद्योगपितयों की रुचि मी कहा जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति से यह हानि होती है कि यदि इनमें से किसी उद्योग में मंदी हा। जाये तो उसका उस चेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पहला है। यदि चीनी के उद्योग में मंदी ह्या जाय तो इससे उत्तर प्रदेश ह्योर विहार की जनता पर विपाल का पहाड़ हुट जायगा और ध्ती उद्योग में मंदी श्राने से बम्बई, मध्य प्रदेश और उत्तर-प्रदेश की जनता संकट में पह जायगी। यदि उद्योग देश में चारों श्रोर वितरित हुए होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। यह बिल्क्ल संमव है कि एक उद्योग में मंदी श्राते ही दूसरे उद्योग में भी मंदी नहीं श्रा जाती है श्रीर यदि उद्यागों को उचित रीति से सम्पूर्ण देश में फैला रखा हो तो मंदी श्राने से उद्याग को चृति अपेचाकृत कम होगी, (३) इन्हीं कुछ चुने हुए चेत्रों में उद्योग के केन्द्रित हो जाने से अन्य चेत्रों की प्राय: उपेज्ञा की गई है। यह हो सकता है कि श्रन्य त्रेत्र इनके समान उत्तम सिंद न हो फिर भी उनमें उद्योगों की स्थापना

से कुछ श्राधिक लाम होने की संमावना है। इन चित्रों की सामाजिक सुविधाओं श्रीर उद्योग के लिए श्रावश्यक प्राकृतिक सावनों का प्राय: विल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। इन चित्रों की जनता श्रपेक्षाकृत श्रधिक वेरोजगार है श्रीर जीविका की उपयुक्त न्यवस्था न होने से उनके रहन-सहन का स्तर भी निम्न है। यदि इन चित्रों में उद्योगों को चालू किया जाता, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, दित्रण भारत श्रीर पंजाब के कुछ स्थान, तो देश में उपलब्ध साधनों का श्रीर श्रच्छा उपयोग किया जा सकता था; (४) हमारे देश में उद्योगों की जैसी न्यवस्था है वह युद्धकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। युद्ध के समय वमवर्ण से इसकी भारी चिति होने की संभावना है। यदि उद्योग कुछ स्थानों पर केन्द्रित होने की श्रपेक्षा बड़े चेत्र में वितरित होता तो इस प्रकार का भय श्रपेक्षाकृत कम रहता।

आधुनिक प्रवृत्ति—यद्यपि स्यानीकरण की द्राष्ट से भारतीय उद्योग में श्रनेक दोष है परन्तु इधर कुछ वर्षों से स्थिति में सुधार होने की संभावना दिखाई देती है। सूती उद्योग के लिए ग्रारंभ में वस्थई नगर ग्रीर उसका समीपवर्ती चेत्र विशेष महत्त्वपूर्ण समका जाता या परन्तु घीरे-बीरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश श्रीर श्रन्य स्थानों में स्ती उद्योग के नये कारखाने खोले गये हैं। इससे बम्बई का महत्व क्रमशः कम होता गया। यद्यपि बम्बई अब भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है श्रन्य स्थानों ने भी श्रपना महत्त्व बढ़ा लिया है। चीनी ठछोग के सम्बंध में श्रव भी उत्तर प्रदेश श्रीर विहार प्रमुख हैं परन्तु महास, बम्बई श्रीर भृतपूर्व रियासतों में भी इस उद्योग की श्रोर श्राकर्पण बढ़ा है। १६३१-३२ में कुल ३२ चीनी के कारखानों में २६ कारखाने उत्तर प्रदेश और विहार में ये परन्तु १६५२-५१ में कुल १३४ कारखानों में से इन दोनों राज्यों में केवल ६३ कारखाने ये। १६३१-३२ श्रीर १६५२-५३ के वीच मद्रास में चीनी के कारखानों की संख्या २ से बद्ध र १३, वम्बई में १ से बदकर १४ और खरुड 'ख' राज्यों में जहाँ एक भी कारखाना नहीं था १२ हो गई। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश श्रीर विहार श्रव भी महत्वपूर्ण राज्य है परन्तु श्रन्य राज्यों में भी चीनी के कारखाने खुल गये है श्रीर उनका भी महस्व कुछ बढ़ गया है।

जहाँ तक कागन के उद्योग का प्रश्न है इनके कारखानों की स्थापना सर्व-प्रथम बंगाल में हुई जिसका मुख्य कारण कोयले की पूर्ति की मुविधा थी। कारखानों में कागन बनाने के लिए हिमालय के पहाड़ी चेत्रों से प्राय: ६०० मील दूर से सवाई घास लाई जाती थी परन्तु चूँ कि एक टन कागन बनाने में २३ टन घास और ५ टन कोयले की आवश्यकता होती थी इसलिए कोयले को प्रायमिकता दी गई। कोयले के चेत्र के निकट कारखाना स्थापित करना श्रिष्ठ उपयुक्त समक्ता गया। परन्तु धीरे-धीरे बाँस ग्रीर बिजली का प्रयोग होने लगा। इससे कागज के कारखाने ग्रन्य स्थानों को हटाये गये। सिमेंट उद्योग सर्वप्रथम मध्य-प्रदेश ग्रीर राजपूताना में स्थापित किया गया परन्तु धीरे-धीरे सिमेंट उद्योग के कारखाने उन चेत्रों में स्थापित होने लगे जो या तो सिमेंट का उपभोग करनेवाले चेत्र हैं या सिमेंट का उपभोग करनेवाले चेत्रों के निकट पड़ते हैं।

उद्योगों की स्थाना में उपर्युक्त वितरण के अनेक कारण है जैसे (१) स्वदेशी बाजार का महत्व बढ़ना, परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि तथा देश के आन्तरिक भागों में द्रव्य बाजार की सुविधाओं की प्राप्ति; (२) उत्पादन प्रविधि में विकास जैसा कि कागज के उत्पादन के स्थान में हुआ; (३) उत्पादकों का विनाशकारी स्पर्धा नीति का स्विचार त्याग तथा उद्योगों की स्थापना में सुधार की प्रवृत्ति जैसा कि सिमेन्ट के उद्योग में दिखाई पड़ा है; (४) देशी रियासतों का जो कि 'ख' राज्य कहलाते है उद्योगों को अपनी और आकृष्ट करने की नीति का अनुसरण करना जिसके अन्तर्गत सब प्रकार की सुविधाय प्रदान करना जैसे अम सम्बन्धी उदार-कानून बनाना, तथा उनकी पूँजी में भाग लेना आदि; और (५) हाल में लागू की हुई उद्योगों को इन्डस्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जाने की सरकार की नीति इत्यादि।

सरकार की नीति—१६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियम) कानून के अनुसर भारत सरकार का उद्योग के स्थान-निर्धारण पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार है। कारखानों को अपनी रिजस्ट्री करनी पहती है और अपना उत्यादन या उत्यदान शक्ति में वृद्धि करने से पूर्व आवश्यक अनुमति लेनी पहती है। प्रत्येक श्रीद्योगिक हकाई अथवा कारखाने के पास लाइसेन्स होता है। लाइसेन्स देने-वाली समिति लाइसेंस देते समय उद्योग कानून के अंतर्गत कारखानों के आकार-प्रकार और स्थान इत्यादि का निश्चित विवरण देती है। चीनी के कुछ कारखानों को अनुकृत स्थानों पर हटाने के लिए यह समिति पहले ही अनुमित दे चुकी है और स्ती मिलों को कपड़े की बुनाई के लिए वहीं नयी शाखा खोलने की अनुमित देना अस्वीकार भी कर चुकी है।

कुछ उद्योगों का लाइसेन्स इसिलये श्रस्वीकार कर दिया गया है कि जहाँ नया कारखाना खोलने का निश्चय था वहाँ पहले से ही श्रिष्ठिक कारखाने या तो स्थित ये श्रयवा जो स्थान श्रावेदन पत्र में कारखना खोलने का बताया गया या लाइसेन्स देने वाली समिति द्वारा उपयुक्त नहीं समका गया। लाइसेन्स देने में उन श्रावेदनों को प्राथमिकता दी जाती है जो किसी नये उपयुक्त स्थान

पर कारखाना खोलने के लिये होती है। उद्योगों के स्थान-निर्धारण की सहकारी नीति का उद्देश्य बढ़े कस्वों श्रीर नगरों में उद्योगों के श्रिषक जमाव को घटाना है। सरकार का उद्देश्य है कि जिन राज्यों में पहले ही श्रपेचाकृत श्रधिक कारखाने खोले जा चुके हैं वहाँ श्रीर श्रधिक कारखानों को स्थापित न होने दिया जाय। इसके विपरीत नये कारखानों को उन चेत्रों की श्रोर श्राकृष्ट किया जाय जिनका श्रमी विकास नहीं हुआ है। परन्तु भारतीय उद्योगों के उचित स्थानीय-करण की समस्या केवल लाइरेन्स देने की व्यवस्था से ही हल नहीं की जा सकती है। उद्योगपित पिछड़े हुए ब्रीर कम विकसित च्रेत्रों में नए कारखाने खोलना नहीं चाहते हैं इसका एक कारण तो उनकी पूर्व धारणा हो सकती है परन्तु वास्तव में बात यह है कि इन द्वेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए न बिजली की सुविधा मिलती है, न कच्चे माज की श्रीर न उपयुक्त अम की। इन पिछड़े श्रीर विक्रित चेत्रों की श्रोर उद्योगों को त्राकृष्ट करने के लिये यह श्रावश्यक है कि (१) इन त्रेत्रों का विकास किया जाय विससे उद्योगपति इनकी स्रोर स्नाकृष्ट हो सकें श्रौर (२) ब्रारम्भ में उद्योगपितयों को कम से कम कुछ सुविधायें दी जायें, जैसे मूमि रियायती दर पर टी जाय, रेलवे का भाड़ा कम किया जाय, श्रीर जहाँ श्रावश्यक हो नकद द्रव्य से चहायता की जाय। मारत में उद्योगों के स्थान-निर्घारण की उमस्या तमी इल की जा सकती है जब सरकार इन सब बातों को घ्यान में रखकर एक उत्तरोत्तर विकासमान नीति श्रपनाये।

अध्याय २७

युक्तिकरण

युक्तिकरण उद्योग की कार्यज्ञमता में वृद्धि करने श्रीर उत्पादन व्यय की घटाने की लम्बी प्रक्रिया है। किसी उद्योग के युक्तिकरण से श्रमिपाय यह है कि कारखाने में पुरानी मश्चीनों के स्थान पर श्राधुनिक मशीनें लगाई लाएँ, नए देकिनकल सुधार किए जाएँ, श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए श्रम बचाने के उपायों तथा त्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाए श्रीर उद्योग को व्यर्थ की प्रतियोगिता से बचाने के लिए उसके संगठन में सुधार करके तथा उसकी व्यवस्था को वैज्ञानिक श्राधार पर संगठित करके उत्पादन कार्य की गति में वृद्धि की जाय। "युक्तिकरण का श्रय यह है कि कार्य करने की प्राचीन परिपाटी, निश्चित कम तथा श्रनुमिक नियमों श्रीर शोधनों के स्थान पर ऐसे ढंग का प्रयोग होने लगे जो कि वर्षों के वैज्ञानिक श्रध्ययन के परिणाम हैं श्रीर जिनका ध्येय साधनों को साध्यों के साथ श्रीकित करने का है जिससे कि उत्पत्ति के प्रयत्न की प्रत्येक इकाई का श्रधिकतम लामकारी परिणाम हो।"

युक्तिकरण का उद्देश्य उत्पादन-व्यय घटाना, उत्पादित वस्तु की प्रकार में युघार करना और उत्पादक को हानि उठाने से बचाना है। यदि उद्योग का प्रवन्ध उचित रीति से किया जाय तो युक्तिकरण उपमोक्ता तथा श्रमिकों श्रीर उत्पादकों के लिए लामकारी सिद्ध होगा। परन्तु वास्तव में यह देखा गया है कि युक्तिकरण से प्राप्त लाम को उत्पादक स्वयं ले लेते हैं श्रीर वस्तुश्रों की प्रकार में युघार करके तथा मूल्यों में कभी करक उपभोक्ताश्रों श्रीर पारिश्रमिक बढ़ाकर श्रमिकों को लाम नहीं उठाने देते। श्रमिक युक्तिकरण का विरोध करते हैं, इसकी योजना से उनमें श्रमंतीय फैलता है क्योंकि इसका परिणाम वेरोज्ञगारी होता है। श्रमिक यह नहीं चाहते कि स्वचालित मशीनों से तथा श्रम बचाने के श्रन्य प्रवन्नों को श्रयनाकर श्रीर पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीन श्राधुनिक मशीनों का उपयोग कर श्रनेक श्रमिकों को वेरोजगार कर दिया जाए। इसी कारण श्रमिकों ने प्राय: युक्तिकरण का विरोध किया है। श्रमिकों की यह माँग बहुत कुछ न्याय संगत है क्योंकि श्रतीत में युक्तिकरण का वह पूर्ण लाम नहीं उठा सके हैं। परन्तु परि उद्योग के युक्तिकरण से पारिश्रमिक बढ़ता है श्रीर उपमोक्ताश्रों को कम मूल्य

पर वस्तु मिल सकती है तो फिर श्रमिको द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध होने का कोई कारण नहीं रह जाता। बहे पैमाने के उद्योग केवल युक्तिकरण के द्वारा ही उचित कर सकते हैं श्रीर तभी श्रामको तथा उपभोकाश्री की स्थिति मुधर सकती है। वह सत्य है कि युक्तिकरण की योजना लागू करने से छारम्भ में कुछ वेरोज-गारी फैलतो है परनतु उत्पादन व्यय छार वस्तु का मृल्य कम हो जाने में भविष्य में उपभोक्ताश्रों की मौंग में चृदि होगी। इस गांग की पूर्ति के लिए उदांग में श्रीर श्रिषक लोगों को रोज़ी मिलेगो । इससे स्वष्ट है कि युक्तिकरण याजना लागू धीने से फैलने वाली वेरोजगारी श्रल्यकालीन धीती है श्रीर उद्योग के उन्नीत करने क साथ इसे दूर किया जा सकता है। समस्या वास्तव में श्रमिक की श्राय श्रीर रहन-सहन के स्तर की है। यदि युक्तिकरण के साथ पारिथमिक में भी वृद्धि होता है तो इससे श्रमिकों की श्राय में वृद्धि होती है थ्रीर रहन-सहन के स्तर में भी सुधार होता है। इस रूप में इस प्रक्रिया का उद्योग चित्र में स्वागत करना चाहिए। श्रंत में यह एक महत्वपूर्ण एवम् विचारणीय प्रश्न है कि यदि भारतीय उद्योग का युक्तिकरण न किया गया तो निश्व चागार की प्रतियोगिता में यह विदेशों की मुसंगठित उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर संकंगा। यदि श्रिभिक युक्तिकरण का विरोध करते हैं तो इसका एक दी परिगाम दो सकता है कि ग्रानेक कारखाने नष्ट हो जाएँगे, उनको बन्द करना पड़ेगा ग्रीर इससे ग्रानेक श्रमिक वेरोज़गार हो जाएँगे। वास्तव में इमारे सम्मुख दो रिधतियाँ हैं कि या तो इम इस बात का समर्थन करें कि युक्तिकरण की योजना लागू कर अभिकी को सुनियोजित एवम् नियंत्रित श्राधार पर नीकरी से प्रथक किया जाए श्रीर फ्रमशः नवीन कार्यों में स्थान दिया जाए या कड़ी प्रतियोगिता का सामना न कर सकने ं के कारण अनेक कारखाने बन्द करके बड़ी संख्या में अभिकों को वेरोजनार धोने .दिया जाए। इमारे सम्मुख समस्या रोजगार स्त्रीर वेरोजगार की नहीं बल्कि एक प्रक्रिया लागू करने से थोड़े अमिकों की थोड़े समय के लिए वेरोजगारी श्रीर दूसरी प्रिक्षया द्वारा प्राय: सभी श्रमिकों की श्रिधिक समय तक वेरोजगारी की है। इमें इन दो प्रक्रियात्रों में से एक को चुनना है।

भारत में जब तक उत्पादित माल की खपत संभव थी श्रीर पूर्ति के श्रमाय के कारण उपभोक्ताश्रों को विभिन्न वस्तुश्रों के लिये श्रिधिक मूल्य देना पहता था तब तक श्रिक्तिरण की समस्या सम्भवतः इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यदि वस्तुश्रों का मूल्य श्रिधिक रहता तो मिल मालिकों को श्रिक्तिरण की श्रावश्यकता का श्रमुमय नहीं होता। मिल मालिकों ने मित मशीन श्रिधिक व्यक्तियों को कार्य में लगाया श्रीर पुरानी तथा व्यर्थ हुई मशीनों से कार्य लेकर भी लाभ उठाया।

परन्तु जब से बाज़ार में वस्तुश्रों की पूर्ति में वृद्धि हुई है श्रीर उपभोक्ता वस्तुश्रों का श्रिषक मूल्य देने को प्रस्तुत नहीं है तब से युक्तिकरण की श्रावश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। मिल मालिक श्रपन। ग्रावश्यकता से श्रिषक श्रमिकों को भाग दे सकने में श्रसमर्थ हैं श्रीर श्रमिकों के स्थान पर मर्शानों का उपयोग श्रानवार्य हो गया है। यदि उपभोक्ता वस्तुश्रों का श्रिषक मूल्य देने को प्रस्तुत होते वो यह स्थित उत्पन्न नहीं होती परन्तु उपभोक्ता उसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं इसलिए उत्पादित वस्तु का मूल्य कम करने के लिये उत्पादन-व्यय कम करने श्रीर श्रपने लाम के श्रंश में वृद्धि करने की दृष्टि से उत्पादक को युक्तिकरण का सहारा लेना पहता है।

श्रीयोगिक विकास सिमिति की योजना—श्रीयोगिक विकास सिमिति ने १६५१ के श्रारम्भ में युक्तिकरण की समस्या पर विचार किया श्रीर इस बात को स्वीकार किया कि उत्पादन न्यय घटाने श्रीर मारतीय उद्योग की कार्य ज्ञमता में वृद्धि करने के लिए युक्तिकरण श्रावश्यक है। परन्तु सिमिति ने इसके साथ ही इस बात को भी माना कि श्रमिकों के हितों की रह्या करना श्रावश्यक है तथा युक्तिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गित से नहीं लागू किया जाना चाहिये। सिमिति ने निम्नलिखित निग्य किए:—

- (१) युक्तिकरण योजना लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इससे वैरोजगार होने वाले अमिकों की संख्या यथासम्भव कम करने के लिए कार्यवाही की लावे। युक्तिकरण के फलस्वरूप होने वाली छटनी और वेरोजगारी को कम करने के लिए समिति ने यह सुक्ताव दिये हैं कि (आ) कर्मचारी को मृत्यु, पद-निवृति इत्यादि के कारण रिक्त स्थानों का पूर्ति कुछ समय के लिए स्थिगत कर दी जाय, (व) अन्य विभागों में कार्य करने वाले अतिथिक्त कर्मचारियों को बिना वेतन में कमी किये हुये और विना गत नीकरी के कम को तोड़े हुये कार्य दिया जाये, (स) स्वेच्छा से कार्य छोड़ने वाले कर्मचारियों को उचित मुआवज़ा दिया जाये और (द) टेकनिकल सुधारों के कारण वेरोजगार हुये अभिकों को खपाने के लिये जहाँ संभव हो कार्य में वृद्धि की जाय।
- (२) प्रति इकाई उत्पादन की स्टैन्डर्ड मात्रा निश्चित की जानी चाहिये और अभिकों का प्रमाणीकरण होना चाहिये। यदि किसी प्रकार का मतमेद हो तो उसकी जाँच होनी चाहिये और स्टैन्डर्ड दोनों पह्यों के विशेषशों द्वारा निश्चित किया जाना चाहिये।
- (३) सम्बन्धित उद्योग की स्थिति श्रीर कार्य की मात्रा इत्यादि को श्रीर समान उद्योगों के श्रनुभवों को ध्यान में रखते हुये नई प्रकार की मशीनों को

लगाने से उत्पन्न टेकनिकल परिवर्तनों का कुछ समय तक परीच्या किया जाना चाहिये।

- (४) जिन अमिकों की छटनी की जाय उनके पुनर्वास के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। अमिकों को ट्रेनिंग देने और ट्रेनिंग की अविध में जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करने की योजना मालिकों तथा अमिकों द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण की जानी चाहिए।
- (५) वेतन अथवा पारिश्रमिक में वृद्धि करके श्रमिक को मी युक्तिकरण के लाम में से भाग देना चाहिए।

इस योजना में युक्तिकरण के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है परन्तु उसके दुष्परिणामों जैसे वेरोजगारी, श्रमिकों का शोपण श्रीर श्राधिक कार्य लेकर भी वेतन में वृद्धि न करने की समस्या को टालने का प्रयक्त किया गया है । मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। विभिन्न राज्य सरकारें श्रपने श्रपने श्रपने होत्रों में उद्योगों के युक्तिकरण की योजनाश्रों का परीक्षण कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस समस्या पर त्रिदलीय श्रम सम्मेलनों में विचार किया गया है श्रीर स्ती तथा चीनी उद्योग के युक्तिकरण का विशेषशों ने वैज्ञानिक श्राधार पर श्रद्ययन किया है।

श्रपील पंचन्यायालयों के निर्एय-भारत में अम अपील पंचन्यायालय के निर्णुयों में दिये गये सिद्धान्तों के आधार पर ही भारतीय उद्योगों में अमिकों की छटनी की जावी है। इन्हीं छिद्यान्तों के अनुसार यह निश्चय किया जाता है कि किस प्रकार श्रीर कितने श्रमिकों की छटनी की जाय। पंचन्यायालय के निर्ण्यों में कहा गया है कि छटनी करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के व्यवस्थापकों पर है। यदि उद्योग के व्यवस्थापक युक्तिकरण अथवा बचत करने या अन्य पर्याप्त कारणों के श्राधार पर यह खिद्ध कर देते हैं कि छटनी की जानी चाहिए तो इसके पश्चात् इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि किसी सीमा तक छटनी की जायगी; इस विषय में इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या व्यवस्थापको द्वारा भिमको की छटनी न्यायसंगत कार्यवाही है; कहीं वह ऋपने अनुचित उद्देश्यों की पृति के लिए तो छटनी नहीं कर रहे हैं। छटनी करने के परिशाम स्वरूप बचे हुये कार्य करने वालों पर कार्य भार वढाना मिल मालिकों की अमिकों के प्रांत अनीति और अन्याय तथा स्वार्थ का एक उदाहरण है। छठनी करने की श्रनुमति केवल तभी दी जाती है जब यह सिद्ध हो जाता है कि, व्यवस्था-पकों की माँग न्यायसंगत है, उसका उद्देश्य अनुचित स्वार्थ साधन नहीं है श्रौर किसी गुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए छटनी नहीं की वा रही है।

इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गईं है कि छुटनी लागू करने में व्यवस्थापको को दो महत्वपूर्ण सिद्धान्ता को मानना पड़ेगा-(१) नई भर्ती के अमिक की छटनी पहले की जायगी श्रीर (२) यदि उद्योग में नई भर्ती हो श्रीर यदि छटनी में निकाले गये योग्य श्रमिक प्राप्त हो सकें तो नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जायगी। ग्रापील पंचन्यायालय के निर्णयों में यह विद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि कोई कम्पनी केवल लामांश कम हो जाने के कारण अपने अमिकों की छटनी नहीं कर सकती है यदि वाजार में उत्पादित माल की माँग कम हैं या कच्चे माल के ग्रभाव के कारण व्यापार में श्रल्पकालीन गतिरोध श्रा जाय तो ऐसी स्पिति में मालिक को श्रमिकों की छटनी कर उनकी आय छीन लेने की अनुमृति नहीं दी जा सकती है। यदि उद्योग श्रयवा कम्पनी के स्थायी आदेशों में व्यवस्था हो तो मालिक ऐशी स्थिति में मास में कुछ दिन कारखाने में बैठकी करा सकता है। स्थायी आदेशों के अनुसार बैठकी कराने से ३३ वीं धारा का उल्लंपन नहीं होता है। घाटे पर चलने वाले कारखाने की बन्द कर देने की मालिक को पूरा श्रधिकार है परन्तु यदि पंचन्यायालय के सम्मुख मामला प्रस्तुत होने की अविध में ऐसी स्थिति आ जाय तो कारखाना बन्द करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी आवश्यक है।

श्रपील पंचन्यायालय के निर्ण्यों के श्राधार पर विकलित प्रणाली काफ़ी संवोधनक रही है परन्तु श्रमिकों की शिकायत है कि (श्र) मालिक श्रपनी स्थित का दुरुपयोग करते हैं, श्रीर श्रावश्यकता न रहते हुए मी श्रमिकों की छटनी की जाती है श्रीर (व) इससे काफी बड़ी संख्या में श्रमिक वेरोजगार हो गये हैं। इसके विपरीत मालिकों की शिकायत है कि उन पर श्रमेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिससे उत्पादन व्यय को कम नहीं किया ना सका है श्रीर श्रावश्यकता न रहते हुए भी उन्हें श्रीक श्रमिकों को कार्य पर लगाये रखना पड़ता है।

सरकारी नीति—भारत चरकार की नीति युक्तिकरण को प्रोत्साहित करने की है (श्र) यदि किसी उत्पादन इकाई के मालिक श्रीर श्रमिक दोनों परस्पर इस बात को स्वीकार करते हैं श्रयवा (ब) श्रीयोगिक विकास समिति की योजना के श्रनुसार युक्तिकरण श्रावश्यक है श्रीर श्रपील पंचन्यायालय के निर्णयों के श्रनुस्त है। इन निर्णयों में यह भी दिया हुश्रा है कि धमिक को श्रल्पकाल के लिये कार्य से प्रयक्त कर देने के बदले में श्रयवा छठनी कर देने के बदले में इरजाना देना पढ़ेगा। जब तक कोई मिल मालिक श्रावश्यक इरजाना देता है श्रीर दी हुई संपूर्ण बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरण में कोई श्रापित नहीं की जा सकती। मार्च १९५४ में लोक समा के तत्कालीन विक्त मन्त्री श्री चिन्तामिण्

देशमुख ने केन्द्रीय सरकार के बजट पर वाद्विवाद का उत्तर देते हुये कहा था कि:---

"संगीत उद्योगों में २५ लाख से कुछ थोड़े से श्रिषक व्यक्ति लगे हुये हैं जिनके सम्बंध में युक्तिकरण का प्रश्न उठाया जाता है। यह तो सर्वविदित है कि उद्योगों में रोजगार के श्रवसरों की पर्याप्त नृद्धि किये बिना कुशल व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण तथा जन संख्या की मृद्धि के फलस्वरूप श्रमिकों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को कार्य देना सम्भव न हो सकेगा। इसके श्रतिरिक्त प्राम्य श्रार्थिक व्यवस्था के श्रन्तर्गत श्रत्यिक संख्या में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें पूर्ण श्रार्थिक व्यवस्था के श्रन्तर्गत श्रवस्था में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें पूर्ण श्राक्त मर कार्य करने का श्रवसर नहीं प्राप्त है। इस बात से तो सभी सहमत होगे कि प्रीद्योगिक विकास के प्रति श्रद्धिता का परिचय देते हुये कार्य करने के श्रवसर में वृद्धि करना उचित न होगा। मेरा ऐसे विश्वास है कि युक्तिकरण द्वारा श्रस्थायी रूप से स्थानान्तरित व्यक्तियों को जो ज्ञति होती है वह जनता के हित के लिये श्रार्थिक व्यवस्था के प्रसार की नीति द्वारा पूर्ण हो जाती है। यह हस बात का एक श्रीर उदाहरण है जिसमें सामाजिक न्याय की बांछनीयता को श्रार्थिक महत्ता के श्रागे मुकना पड़ता है"।

''छमासदों को यह तो जात होगा ही कि हाल में ऐसे कानून बना दिये गये हैं जिनके अन्वर्गत श्रमिकों को अवकाश प्राप्त करने पर सहायता तथा कार्य करने के काल में यदि ग्रस्थायी रूप से कार्य से प्रयक होना पड़े तो भी उसका हरजाना दिया जायगा। सभा सदों को समरण होगा कि एक उद्यांग विशेष में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सरकार ने लोक सभा की बैठक का समय न होने के कारण श्रम्यादेश द्वारा इन कानूनों को प्रचलित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसे श्रमिकों के हित की रच्चा के लिये जो छटनी के श्रन्तर्गत श्रा गये हैं बहुत श्रधिक महत्व देती हैं। मैंने पहिले भी कहा है कि श्रस्थायी रूप से श्रपने कार्य पर से इटाये हुये श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जो कुछ सम्भव हो, किया जाना चाहिये, पर मेरा मत है कि हमें ऐसी नीति का अनुसर्ख नं करना चाहिये जिससे प्रीद्योगिक विकास अवस्द हो जाय श्रीर कार्य करने के श्रवसरों का विकास भी कक जाय। किसी भी समय इर उद्योग में विभिन्न ज्ञमता वाले अनेक उपक्रम उत्पादन-कार्य करते रहते है। उनमें से कुछ तो हाल में ही श्रारम्भ किये हुये होते हैं या श्रारम्भ होते रहते हैं, कुछ में पसरण श्रीर कुछ में संकुचन की प्रवृति लिखत होती है और कुछ की ऐसी स्थित होती है कि उनका श्रन्त होता रहता है। हसलिये उद्योग के समुचित विकास श्रीर वृद्धि के लिये यह . श्रावश्यक है कि प्रत्येक उपकम द्वारा श्रपनी परिस्थित के श्रनुसार नियुक्त श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में कुछ लोच अवश्य रहे। हमें कुल कार्य करने के अवसरों के योग पर विशेष ध्यान देना चाहिये। वह नीति जो अपने आश्वासनों द्वारा छटनी असंभव करती है नये ढंगों से अन्य उपकमों द्वारा उत्पादन के विकास और वृद्धि को निश्चय ही रोक देगी और संभवतः उसके द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था को जिसमें अभिक अवश्य सम्मिलित हैं उस चृति की तुलना में जिसे बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है कहीं अधिक चृति पहुँचावेगी"।

भारत के वित्त मन्त्री द्वारा स्थिति का यह ऐतिहासिक वर्णन हस बात को स्पष्ट करता है कि हमें एक या दो उपक्रमों में छटनी किये जाने से चिन्तित नहीं होना चाहिये, वरन् हमें सम्पूर्ण स्थिति को विस्तृत हिण्टकोण से देखना चाहिये। यदि हम ऐसा करेंगे तो युक्तिकरण हमारे लिये (१) बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये कायं के अवसर प्रदान करने का, (२) अभिकों की आय तथा उनके रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने का और (३) उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने तथा प्रौद्योगिक विकास निश्चय करने का साधन होगा। परन्तु यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत अभिकों की आवश्यक कठिनाइयों से रच्चा की जाय। इस संबन्ध में कार्य से प्रयक्त किये जाने पर हरजाना देने का कानून द्वारा ही प्रबन्ध कर दिया है और उस अभिक विशेष के लिये अन्य कोई कार्य द्वंड लेने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिये।

सूती मिल उद्योग—१९२६-२७ में प्रशुल्क मगढल ने इस स्रोर ध्यान स्राक्षित किया कि स्ती मिल उद्योग में श्रावश्यकता से श्रिषिक पूँ नी एकत्र हो रही है और उसमें श्रावश्यकता से श्रिषिक अमिक लगे हुए हैं। बोर्ड के कथना-नुसार १९१७ और १६२१ के मध्य उद्योग की कुल पूँ नी २० प्रश्न करोड़ से बढ़-कर ४० ६८ करोड़ हो गई नो उस समय उद्योग की मशान इत्यादि संपत्ति को देखते हुए बहुत श्रिषक यी। बोर्ड इन सन बातों का श्रध्ययन कर इस परिणाम पर पहुँचा कि भारतीय स्ती मिलों में अम का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। भारत में एक अमिक १८० तकुश्रों में कार्य करता है जन कि जापान का अमिक १४० में, इक्क के का अमिक १४० से ६०० में और श्रमरीका का श्रमिक १४२० तकुश्रों में कार्य करता हैं। भारत में प्रत्येक बुनकर के पास श्रीसतन २ कर्षे हैं जन कि इनकी सख्या जापान में २१, ब्रिटेन में ४ से ६ श्रीर श्रमरीका में ६ हैं। इन दोषों के कारण भारतीय सती मिलों में उत्पादन न्यय श्रिषक होता है। प्रशुल्क मंडल की सिफारिशों के श्राधार पर सती मिल उद्योग ने बंनई की कुछ मिलों में लागू करने के लिए श्रक्तिकरण की एक योजना निर्माण की। इस योजना की विशेषता यह थी कि एक न्यक्ति एक के स्थान पर दो कातने की मशीन चलाएगा और

एक बुनकर दो के स्थान पर ३ या ४ कर्घे चलायेगा। परन्तु श्रमिकों ने इस योजना का विरोध किया श्रीर इसे लागू नहीं किया जा सका। १६३२ में जाँच करने के पश्चात् प्रशुल्क मगडल ने पता लगाया कि यदि यह योजना लागू की गई होती तो उत्पादन न्यय में १७ से २० प्रतिशत तक कमी हो जाती। स्ती मिल उद्योग ने उत्पादित वस्तु के प्रमाणीकरण, क्रय श्रीर विकय, न्यवसाय के पुनंसंगठन श्रीर श्राधिक हिन्द से श्रनुपयुक्त मशीनों को श्रलग करने के लिए ७ पुनंसंगठन श्रीर श्राधिक हिन्द से श्रनुपयुक्त मशीनों को श्रलग करने के लिए ७ पुनंसंगठन श्रीर श्राधिक हिन्द से श्रनुपयुक्त करने की योजना निर्माण की। इन मनेजिय एजेन्सियों को एक में एकतित करने की योजना निर्माण की। इन एजेन्सियों के पास ३४ मिलें थीं। इस योजना में यह न्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक मिल को पूर्व निर्धारित मूल्य पर ले लिया जायगा, मूल्य साधारण श्रेयरों में दिया जायगा, न विके हुये माल का स्टाक बाजार माव पर क्रय कर लिया जायगा श्रीर नाम के लिए कुछ धनराशि नहीं दी जायगी। परन्तु वित्त के श्रमाव के कारण योजना कार्योन्वित नहीं की जा सकी।

इन योजनाश्रों के विफल हो जाने पर मी सूती मिल उद्योग ने निरन्तर युक्तिकरण योजना लागू करने का प्रयत्न किया है। बम्बई अम समिति द्वारा प्रचलित की गई प्रश्नायली के उत्तर में बम्बई मिल मालिक संघ ने इस बात पर महत्व दिया कि भारतीय उद्योग ने उत्पादन में सभी श्राधुनिक उपायों को श्रपनाया है। अपनेक स्ती मिलों की पूँजी भी घटाई गई स्रीर १६२७ स्रीर १६४० के बीच सूती मिल उद्योग ने प्रशुल्क मगडल के सुमाव के अनुसार मोटे थ्यौर घटिया प्रकार के कपड़े के स्थान पर अच्छे प्रकार के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की नीति श्रपनाई। परन्तु इस सुघारों के होते हुये भी सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन न्तमता कम है और उनके युक्तिकरण की आवश्यकता है। स्ती मिल उचीग सम्बन्धी विक्रिंग पार्टी ने १६५२ में यह पता लगाया था कि लगभग १५० वर्तमान सूती मिल जो कि कुल मिलों की संख्या की लगमग ३३ ६% थीं, आर्थिक दृष्टि-कोण से श्रनुपयुक्त श्रीर हीन क्षमता वाली मिलें थीं। ब्लोरूम के वाहिन्हण विभाग में तथा रंगाई विभाग में जिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है वे अनुपयुक्त थीं। इस प्रकार कर्घों की संख्या के सम्बन्ध में जो प्रत्येक अमिक की देखरेख में था वर्किंग पार्टी ने पता लगाया था कि दिल्ली की एक मिल में क्रौर मद्राप की दो मिलों में स्वचालित कर्षे ही लगाये गये हैं और एक एक बिनने वाला अभिक ४, ६, द श्रीर १६ कर्षों पर कार्य करता है। श्रहमदाबाद की एक मिल में १८ क्यों पर एक अमिक अप्रैर वम्बई की एक अन्य मिल में ६ कर्षे पर एक अमिक कार्य करता है। फिर भी श्रविकांश मिलें उत्पादन ज्ञमता में हीन हैं श्रीर पुरानी मशीनों का प्रयोग करती हैं।

वर्किक्स पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि उन मिलों का कार्य जो स्वचालित कर्षों का प्रयोग कर रही है संतोषजनक हैं। अन्य मिलों में भी स्वचालित कर्षों के आधुनिक ग्रीर मशीनों के प्रयोग किये जाने तथा उत्पादन का युक्तिकरण करने की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। सितम्बर १६५४ में कानूनगो कमेटी ने यह सिफारिश को पी कि उद्योगों के सभी विमागों जैसे मिलों, शिक्त संचालित कर्षों, हाथ कर्षों आदि का युक्तिकरण १५ वर्षों के अन्तर्गत हो जाना चाहिये। वर्षिग पार्टी ने युक्तिकरण की अविध केवल १० वर्ष ही रक्खी थी।

उत्तर प्रदेश में कानपुर की सूती-मिलों को विशेष कठिनाइयां का सामना इसलिये करना पड़ रहा है कि उन्होंने श्रपनी आवश्यकता से आधिक अमिकों को लगा रक्ला है। इससे यहाँ की मिलों का उत्पादन व्यय देश के श्रन्य मागों की मिलों की श्रपेका बहुत श्रधिक है। यदि इनमें युक्तिकरण न किया गया तो इन मिलों के बन्द हो जाने का मय है। यह बड़े शीमाग्य की बात है कि श्रमिक स्वीर मालिक दोनों ही ने जून १९५४ में नैनीताल में हुई त्रिदलीय समा में इस बात को स्वीकार किया था कि कानपुर की सूती मिलों के उत्पादन का युक्तिकरण किया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक श्रमिक, जैसा कि बन्बेई में .हां रहा है, दो कघीं के स्थान पर चार कघीं पर कार्य करेगा श्रीर कार्य मार की मात्रा में भी सामान्यत: वृद्धिहो जायगी। इससे मिलों का बन्द होना एक जायगा ऋौर श्रमिकों को बरबस वेकार न रहना पहेगा। इस योजना के सम्बन्ध में उत्तर अदेश के तत्कालीन अम मंत्री सम्पूर्णानन्दजी ने कहा था कि, "हाल में सेन्द्रल 'डिस्प्यटस एक्ट में जो सुधार हुआ है उसने मालिकों के लिये श्रतिरिक्त अमिकों की छटनी करना हरजाना देकर अपेज्ञाकृत अधिक चरल कर दिया है। अनेकों मिल मालिक इसमें अपना लाम देखेंगे कि वे छटनी करके हरजाना देकर अपने मिल में स्थायी बचत कर लें। हमारी समस्या उन श्रमिकों की किसी प्रकार रक्षा करने की है जिनके छाँट दिये जाने का मय है। सरकार को युक्तिकर्ण की ऐसी योजना बनाने के निर्णय पर, जिसके अन्तर्गत ५००० श्रीर ६००० के मध्य अनुमानित छाट दिये जाने वाले अमिकों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके. इस पृष्ठमूमि के समज्ञ विचार करना चाहिये"। कानपुर की अनेक मिलें जो अभी तक बड़ी कठिनाई से दो शिफ्ट में कार्य कर पा, रही थी अब तीन शिक्ट में कार्य कर सकेंगी जिससे कार्य करने के अधिक अवसर पाप्त हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त युक्तिकरण की यह योजना, कानपुर के सूती कपड़ा उद्योग के अमिकों की श्रीसत पारिश्रमिक जिसमें मेंहगाई भी सम्मिलित होगी, द्यु रु से बढ़ाकर ११५ रु प्रति मास श्रीर विशेष समता वाले श्रीमकों के लिये १५० इ० प्रति मास कर स्केगी ।

जूट उद्योग—जूट उद्योग भारत का सर्वाधिक सुसंगठित उद्योग है श्रीर श्रारम्भ से ही इस उद्योग ने यह नीति श्रपनाई है कि मशीनों का प्रयोग रोक कर तथा प्रति सप्ताह कम धन्टे कार्य करवा कर उत्पादन की मात्रा को श्रावश्यकता श्रिषक न होने दे ताकि विना विका माल स्टाक में एकत्रित न होने पावे। द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व जूट उद्योग के पास श्रीद्योगिक साधन वाजार की कुल सेगाँग से कहीं श्रिषक थे। यह श्रातुमान लगाया गया था कि वाजार की कुल माँग को जूट उद्योग श्रपनी कुल मशीनों में से केवल एक चीधाई का उपयोग करके पूरा कर सकता है। परन्तु वर्तमान स्थिति विल्कुल मित्र है। यह श्राशा की जाती है कि मिवच्य में जूट के सामान की माँग में वृद्ध होगी श्रीर जूट मिलों में इस समय जितनी मशीनें है उन सब का उपयोग करना पढ़ेगा। परन्तु योजना श्रायोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जूट उद्योग का श्रीर प्रसार करने की कोई व्यवस्था नहीं की है। वार्षिक वास्तविक उत्पादन शक्ति १६५५-५६ में भी १२ लाख टन ही रहेगी। १६५०-५१ में भी उत्पादन शक्ति इतनी ही थी। यदि उद्योग श्रपनी पूरी शक्ति से उत्पादन करे तो सारा उत्पादित माल घरेलू माँग श्रीर निर्यात करने में खप जायगा।

१६४२ की गर्मियों में मारत सरकार ने भारतीय जूट मिल मालिक संघ को सुमाव दिया या कि कोयले तथा परिवहन का संरच्या करने के लिए उद्योग का युक्तिकरण त्रावश्यक है। सरकार के कथनानुसार रेलवे विभाग जूट उद्योग के कुल वास्तविक उत्पादन को पश्चिमी मागों तक ले जाने की व्यवस्था कर सकने में श्रसमर्थ या। जाँच करने पर पता चला कि जूट की वन्तुत्रों की कुल मांग, जिनमें देश के श्रन्दर का उपमोग भी सम्मिलित है, लगभग ५५ हजार टन प्रति मास होगी जब कि कुल ६५ इनार टन माल का उत्पादन किया ना रहा या। इससे स्पष्ट या कि उत्पादन में कमी की जानी चाहिए। मारत सरकार ने मुक्ताव दिया कि उत्पादन कम करने के लिए केवल उन्हीं मिलों में उत्पादन कराया जाय जिनमें विद्युत संचालित मशीनें हैं। मारतीय जूट मिलों ने इस सुक्ताव को स्वीकार नहीं किया ग्रीर युक्तिकरण की एक नवीन योजना लागू कर दी जिसके अनुसार व्यय की बचत करने के लिए कोयले के केन्द्रीय स्टाक स्पापित किए गये श्रीर कीयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को नियन्त्रित किया गया। तदपश्चात् एक 'संग्रह योजना' लागू की गई जो १ जुलाई १६४४ से ३१ मार्च १६४६ तक प्रचलित रही। युक्तिकरण की इस योजना से उद्योग कीयले के ज्यय में बचत करने में सफल हुआ और कुछ मिलों को युद्ध की परिस्थितियों से विवश होकर जो हानि उठानी पड़ी उसका श्रीर श्रिधक समान वितर्ण किया जा सका।

वर्तमान समय में अपनी पुरानी और घिसी हुई मशीनों को परिवर्तन करने के लिए और अन्यदेशों के उद्योगों की माँति उत्पादन के बिल्कुल आधुनिक उपायों का उपयोग करने के लिए जूट उद्योग को युक्तिकरण की योजना लागू करने की अत्यन्त आवश्यकता है। चूँ कि मारत के जूट उद्योग को विदेशी उत्पादकों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए अन्य देशों द्वारा प्रयुक्त प्रावि-धिक कुशलताओं का यहाँ भी उपयोग किया जाना चाहिए। भारत की कुछ मिलों ने आधुनिक मशीनों का उपयोग आरम्म कर दिया है। उत्पादन व्यय कम करने के लिए अन्य उद्योगों को भी ऐसा करने की आवश्यकता है। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में दो सब से बड़ी कठिनाइयाँ यह है कि (१) इनके लिए ४० से ४५ करोड़ कपये की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय से उपलब्ध कर सकना कठिन है और (२) इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने से लगमग ४० इजार अमिक वेरोजगार हो जायँगे।

कोयला उद्योग—कोयला उद्योग में कोयले की छोटी-छोटी श्रीर श्राधिक हिन्द से श्रनुपयुक्त खानों को सम्मिलित कर एक वढ़ी हकाई का रूप देने, विभिन्न उपायों से घातुशोधन के कार्य श्रानेवाले बिद्धा कोयले का संरक्षण करने श्रीर कोयले की खानों में मशीनों का उपयोग करने के लिए युक्तिकरण की योजना लागू करना श्रावश्यक है।

कोयला उद्योग में मशीनों का उपयोग करने से अभिप्राय यह है कि खान में कोयला काटने और उसे नियत स्थान तक ले जाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाय और कोयला निकालकर नियत स्थान तक ले जाने की दोनों कियाएँ साथ-साथ हों। भारत में मशीनों का प्रयोग अभी बहुत कम हुआ है। १६४४ में कोयला निकालने की २१० मशीनें थीं जिनसे २१ लाख टन कोयला निकाला जाता था। १६३६ में इस प्रकार की केवल १८६ और १६३५ में केवल ६५ मशीनें थीं। १६५१ के मध्य तक भारत में ३७४ मशीनों से प्रति मास लगभग ५ लाख ६० हजार टन कोयला (अर्थात ७० लाख टन कोयला प्रतिवर्ध) निकाला गया जो औसत मासिक उत्पादन का लगभग १९६ प्रतिशत था। भारतीय कोयला-खान स्थात ने १६४६ में सिफारिश की कि भारतीय कोयले की खानों में मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मशीनों के उपयोग से ही उत्पादन राित्र बढ़ाया जा सकता है जो कि मिविष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में मशीनों के उपयोग के प्रति योदी प्रतिकृतता होने के कारण शायद सस्ते अम की उपलिब्ध है। जब अम महँगा पड़ने लगेगा, पारिश्रमिक बढ़ने लगेगा तो अवश्य ही इस प्रतिकृतता में परिवर्तन होगा और तब मशीन और अम के बीच

उपयोगिता को दृष्टि से विचार कर उपयुक्त साघन छाँटने के सम्बन्ध में निर्ण्य किया जा सकेगा। कोयला उद्योग के सम्बन्ध में १६५० में वर्किङ्ग पार्टी ने सुमाव दिया कि खानों में मशीनों का उपयोग करने से ही सुनियोजित उपाय से शीव उत्पादन बढ़ाया जा सकता है श्रीर मिविष्य में देश के श्रीद्योगीकरण की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति की जा सकती है। सम्पूर्ण व्यवस्था का सन्तुलित विकास करने के लिए खानों में शीघ़ ही मशीनें नहीं लगानी चाहिएँ। इसके लिए एक अवधि निश्चित की जानी चाहिए । यह उचित नहीं है कि एक साथ सभी खानों में मशीनों की सहायता से उत्पादन आरम्म कर दिया जाय। इसके लिए एक एक खान करके प्रगति करनी होगी । क्रमशः मशीनों का उपयोग बढ़ाने पर भी कोयले की खान के अमिकों में वेरोजगारी फैल सकती है। यिक पार्टी इस परिणाम पर पहुँची कि खानों में मशीनों का उपयोग करने में वेरो नगारी के भय से वाघा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मशीनों के उपयोग से हानियों की श्रपेका लाम कहीं अधिक हैं। इसकी सफलता के लिए विकंक्ष पार्टी ने सुमाव दिया है कि (१) छोटी-छोटी कोयले की खानों को कम से कम १० इजार टन प्रति मास उत्पादन करने वाली इकाई के रूप में संगठित कर दिया जाय और (२) कोयले की खानों में लगाई जानेवाली मशीनों का भारत में ही निर्माण किया जाय।

भारत के अधिकांश उद्योगों में कम से कम तीन चेत्रों में युक्तिकरण की योजना लागू करना अत्यन्त आवश्यक है (१) कारखानों के स्थानीयकरण में सुधार, जैसे चीनी श्रीर कुछ सीमा तक लोहे तथा इस्पात के कारखानों में ! १६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियमन) कानून के श्रन्तर्गत स्थापित लाइ-सेन्सिंग समिति ने पूर्व से ही चीनी के कुछ कारलानों को श्रिधिक अच्छे स्थान पर इटा लेने की अनुमित दे दी है। लोहे और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में आशा -की जाती है कि नये लोहे श्रीर इस्पात के कारखानें नये स्थानों पर स्थापित किए जायँगे; (२) उत्पादन के उपायों में सुघार, जैसे गन्धक का व्यय कम करने के 'लिए चीनी उद्योग में, घातुशोधन के काम आने वाले बढ़िया कीयले की बचाने के लिए लोहे तया इस्पात के उद्योग में श्रीर उत्पादित माल का प्रकार सुधारने त्तया उत्पादन न्यय घटाने के लिये उत्पादन के ढंग में सुधार करने की न्त्रावश्यकता है; (३) कारखानों का ग्रार्थिक दृष्टि से उपयुक्त ढाँचा निश्चित करने के लिए प्रति मशीन पीछे कार्य करने वाले अमिकों की संख्या में कमी करने न्त्री श्रावश्यकता है। भारत के लोहे तथा इस्पात, चीनी, सूती, कपड़ा, जूट तथा श्चन्य उद्योगों में प्रत्येक मशीन पर श्चावश्यकता से श्रिधिक श्रमिक नियुक्त किये -जाते हैं जिसके परिग्रामस्वरूप उत्पादन न्यय श्रिधिक होता है श्रीर उद्योग की

यतियोगिता शांक शिथिल पह जाती है। प्रत्येक उद्योग के श्रिष्कांश कारखाने ऐसे हैं कि उनकी उत्पादन शक्ति श्रनुकृततम स्तर से नीचे हैं। उत्पादन इमता में कमी का यह भी एक कारण है कि चीनी की श्रनेक मिलों में प्रतिदिन ८०० टन (जो गन्ना पेरने की श्रनुकृततम शक्ति है) से कम गन्ना पेरा जाता है। यदि उत्पादन की शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय तो ८०० टन गन्ना पेरा जा सकता है। यदी स्थिति श्रन्य उद्योगों की भी है। कागज के कुछ कारखाने प्रतिवर्ष द हवार टन कागज श्रनुकृततम उत्पादन करने की इमता नहीं रखते हैं, कुछ सिमेंट के कारखानों का वार्षिक उत्पादन १ ५ लाख टन की श्रनुकृततम उत्पादन शक्ति से कम है। श्रनेक सूती मिलों की श्रनुकृततम उत्पादन शक्ति भी जैसा पहले कहा जा चुका है श्रावश्यकता से कम है। मिलों की सङ्गठित हकाई में लगभग २५,००० तकुए श्रीर ६०० कर्षे चलने चाहिएँ। युक्तिकरण की योजना लागू करके श्रवकांश कारखानों को श्रनुकृततम उत्पादन शक्ति के स्तर पर लाया जा सकता है श्रीर उत्पादन व्यय कम किया जा सकता है।

युक्तिकरण की योजना लागू करने में चबसे बड़ी कठिनाई श्रमिकों का विरोध श्रीर बहुत बड़ी मात्रा में वित्त की श्रावश्यकता है। कुछ ऐसे उत्पादन भी युक्तिकरण की योजना लागू करने में बाधा उत्पन्न करते हैं जो इस योजना के लाभ को नहीं समकते श्रीर इसे लागू करने के लिये प्रस्तुत नहीं होते हैं। परन्तु अमिकों का सहयोग माप्त कर चतुर उत्पादकों श्रीर सरकार को भारतीय उद्योग की प्रीद्योगिक कार्यह्ममता में सुधार करने के लिए धीरे-धीरे सुनियोजित श्राधार पर युक्तिकरण की योजना लागू कर देनी चाहिये।

अध्याय २५

वेरोजगारी की समस्या

यह श्राश्चर्यजनक बात है कि श्रार्थिक हिन्द से बहुत कम विकित देश में वस्तुश्रों श्रीर विमिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के श्रमाव के साथ वेरोनगारी हो श्रीर बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शक्ति श्रप्रयुक्त पड़ी हो। भारत श्रार्थिक हिन्द से बहुत कम विकास कर सका है परन्तु यहाँ वेरोनगारी भीपण रूप धारण किए हुए है। इस कारण भारत की राष्ट्रीय श्राय बहुत कम है, रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न है श्रीर जनता दुखो तथा श्रसन्तुष्ट है। मारत में केवल शिबित लोगों श्रीर उद्योगों तथा कृषि चेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को ही वेरोनगारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है वरन नागरिक एवम् ग्रामीण चेत्र की प्रायः सम्पूर्ण जनता इसके चंगुल में फॅसी हुई है। पाश्चात्य देशों में भी वेरोनगारी है परन्तु उसका कारण व्यापार में मन्दी श्रा जाने से कुछ समय के लिए वस्तुश्रों के माँग की कमी है। इसके साथ ही वहाँ कुछ ऐसे कारखाने हैं जो वर्ष में कुछ मास चलने के पश्चात् श्रेप मास बन्द रहते हैं श्रीर इन मासों में वहाँ वेरोनगारी फैल जाती है। प्रायः एक कार्य छोड़ने के पश्चात् तुरन्त दूसरा कार्य नहीं मिल पाता श्रीर इस बीच की श्रविध में मी एक प्रकार की श्रस्थायी वेरोनगारी रहती है तथा श्रन्य प्रकार की श्रत्यान वेरोनगारी रहती

भारत में वेरोजगारी तथा श्रांशिक रोजगारी श्रधिकांश जनता के जीवन का स्थायी श्रंग वन चुके हैं। इसका कारण यह है कि देश की जन-संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है श्रोर देश के श्रार्थिक साधनों का बहुत कम विकास किया गया है। गत कुछ वर्षों से इस समस्था ने गम्मीर स्थिति उत्पन्न कर ली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:—

- (त्र) जन-संख्या की तीव गति से वृद्धि;
- (व) ग्राम्य उद्योगों का नष्ट हो जाना जिनमें ग्रामों के बहुत से व्यक्तियों को श्रांशिक व्यवसाय प्राप्त हो जाता था:
 - (स) न्यवसाय की दृष्टि से कृषि के श्रतिरिक्त अन्य उत्पादन चेत्रों का अपर्याप्त विकास (यद्यपि गत ४० वर्षों में काफी विकास हुआ है फिर मी १६११ के पर्त्वात् कृषि चेत्र में व्यवसायों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ३ प्रतिशत रही है);

(द) देश-विभाजन के परिशाम स्वरूप जन-संख्या का बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित होना।

श्रांकड़ों के श्रभाव में यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि भारत में बेरोजगारों या श्रांशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कुछ श्रिषकारियों का श्रनुमान है कि आमों में जन-संख्या का लगभग ३० प्रतिश्वत बेरोजगार है श्रीर ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत श्रीषक है जो श्रांशिक रूप से रोजगार पाए हुए है। श्रन्य श्रनुमानों के श्रनुसार देश की कुल जन-संख्या आमीण एवं नागरिक दोनों चेत्रों में बेरोजगार श्रीर श्रांशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की संख्या ५ या ६ करोंड़ के बीच में है। यह बेरोजगारी की बहुत बड़ी संख्या है। पश्चिम के कुछ काफी विकसित देशों में समृद्धि के समय कुल जितने व्यक्तियों को व्यवसाय प्राप्त है उनके एक से तीन प्रतिशत से भी कम व्यक्ति वेरोजगार रहे हैं। परन्तु मारत की स्थिति विल्कुल भिन्न है। भारत के समृद्धि काल में व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों के श्रनुपात में बेरोजगारों की संख्या पाश्चात्य देशों के श्रधिकतम मन्दी के काल की तुलना में कहीं श्रधिक है।

"भारतीय समस्या का सम्बन्ध देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की अकृति से हैं। इसलिये इस पर विचार इसी दृष्टिकी या से किया नाना चाहिये। शिक्तित वर्ग की वेकारी की विशेष महत्ता के प्रदर्शन से, जी कि स्वाभाविक भी है, इस वर्ग के विशेष मुखरित होने और राजनैतिक प्रभाव ढालने की ज्ञमता रखने के कारण हम आन्ति में पढ़ सकते हैं। वर्तमान स्थित में सबसे अधिक हानि उठाने वाले भूमि हीन कृषि तथा गैर-कृषि आम्य अभिक, नगर में रहने चाले समयिक अभिक, आम्य तथा नगर के छोटे-छोटे उद्योगों में कार्य करने वाले अभिक, तथा फुटकर कार्य करने वाले दस्तकार हत्यादि हैं। इन सब से वे अभिक जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकी या से हीन हैं सबसे अधिक हानि उठाते हैं। सामाजिक दृष्टिकी या से पद्दिलत जातियाँ, आदिवासी तथा निकृष्ट दस्तकारी का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं"।

पाश्चात्य देशों में वेरोजगारी एक श्रस्थायी समस्या के रूप में होती है श्रीर सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा ठीक समय पर कार्यवाई कर देने से उसके हल हो जाने की श्राशा रहती है परन्तु पाश्चात्य देशों में प्रयुक्त उपायों द्वारा भारत की समस्या का हल नहीं किया जा सकता। भारत में इस समस्या को दीर्घ कालीन दृष्टिकोण से हल करने के लिए यह श्रावश्यक होगा कि कृषि की भूमि का चेत्रफल बढ़ाने के साथ ही जनता को सुनियोजित करने श्रीर उस पर नियन्त्रण रखने, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने तथा श्रीद्योगिक सम्भावनाश्रों को विकसित

करने की श्रावश्यकता है। किसी भी सरकार ते यह श्राशा नहीं की जा स्कर्ती है कि वह प्रतिवर्ष १३ प्रतिशत की दर ते बढ़ने वाली जन संख्या को व्यवसाय दे सकेगी जब कि व्यवसाय के साधनों में भी इशी गांत से वृद्धि नहीं होती। चूँ कि प्रवास के द्वारा जन संख्या की समस्या की सुलकाया नहीं जा एकता है इसलिए सभी को व्यवसाय का न्याय संगत श्रवसर प्रवान करने के लिए यह श्रावश्यक है कि भूमि पर श्रीर श्रीद्योगिक साधनों पर जन संख्या के दवाव को कम करने के लिए जनसंख्या से वृद्धि को रोका जाए। परन्तु इस व्यवस्था को लागू करने में श्राविक समय लगेगा श्रीर वेरोजगारी की समस्या को इतने समय तक विना इल किए छोड़ देना संभव नहीं है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कुछ नये व्यवसाय के श्रवसर प्रदान किये गे। परन्तु योजना के तीसरे वर्ष से निरन्तर वेकारी के बहुते रहने के कारण आयोग को यह त्यच्ट हो गया कि देश के श्रीदोगिक श्रीर श्राधिक विकास हारा इस समस्या के सुलक्ताने के उपाय को सर्व-प्रधानता देनी आवश्यक है। इसी दृष्टिकीण से प्रथम योजना पर न्यय की जाने वाली धन राशि श्रवटूबर १६५३ में १८० करोड़ रुपया बढ़ा दी गई जिससे कि नवीन विरोप योंसनाश्रों के लिए, जी कि व्यवसाय के श्रवसरों की वृद्धि करेंगी श्रीर बढ़ती हुई चेकारी रोकेगी, पर्याप्त विच प्राप्त हो सके। इसके श्रातिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम को १६५३-५४ के गत निर्णय के अनुसार अन्त कर देने के स्थान पर पूर्ण योजना काल तक चालू रखने का भी निर्णय किया गया। मेकारी की समस्या को इल करने के पुनर्परीचित कार्यक्रम के श्रन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया कि (१) राज्य-विच निगम स्थापित किये जाँय, (२) केन्द्र से राज्यों को देश की दरिद्रता कम करने के लिए नई योजनाश्रों के चालू करने के लिए विचीय सहायता दी जाय, (३) सङ्कों के निर्माण के लिए तथा छोटी-छोटो शक्ति उत्पादन की योजनास्त्रों को कार्यान्यित करने के लिये अनुदान दिये जीय स्त्रीर (४) श्रीद्योगिक शिचा की सुविधाओं का विस्तार किया नाय। पर जैसा भय या उसके अनुसार यह समस्या सुलम्माने का श्रांशिक प्रयत्न असफल रहा। जामों श्रीर नगरों दोनों स्यानों पर ऐसे न्यक्तियों की संख्या जो आंशिक न्यवसाय प्राप्त या वेरीजगार है निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह आशा की जाती है कि इस समस्या को वास्तविक रूप से सलकाने का प्रयत्न किया जायगा जिसमें देश के श्रीद्योगिक विकास पर ग्राधिक महत्व दिया जायमा ग्रीर साथ ही साथ जन संख्या की वृद्धि पर कुछ: नियंत्रण भी रक्खा जायगा। यही उपाय द्वितीय योजना का मूलाघार है।

यदि भारत के कारखानों द्वारा निर्मित वस्तु के उत्पादन श्रीर विक्रय में

वृद्धि हो तो श्रीद्योगिक वेरोजगारी को कम किया जा सकता है । यह तमी सम्मव है जब प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम किया जाए। बहुत से उद्योगों में पारिश्रमिक उत्पादन व्यय का एक महत्वपूर्ण श्रंग है। गत १० वर्षों में भारत के श्रमिकों के पारिश्रमिक में पूर्व स्तर से ३३ से ४० गुना श्रिषक वृद्धि हुई है परन्तु इस वृद्धि के साथ ही श्रमिक की कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है। इसका स्वामानिक परिणाम यह हुआ कि कुछ कारखाने बन्द कर देने पड़े जिससे श्रमिकों में बेरोजगारी फेली। यह स्थिति बहुत समय पूर्व ही आ गई होती परन्तु युद्ध के समय बस्तुओं का श्रमाव हो गया था श्रीर वह श्रमाव युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् भी रहा। वस्तुओं का उत्पादन व्यय श्रिषक होते हुए और भावों का स्तर श्रिषक रहते हुए भी श्रपने समान का विकय कर सकने में उद्योग सफल रहे। परन्तु श्रब उपमोक्ता इस स्थिति का श्रागे निर्वाह कर सकने में श्रम्मर्थ हैं। इसिंक वेरोजगारी को कम करने के लिए या तो भारत के श्रमिकों को कम पारिश्रमिक लेने के लिए पस्तत रहना होगा या उन्हें कार्य श्रिषक करना पड़ेगा।

इसके साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाने से, विभिन्न सरकारी नियन्त्रणों श्रीर निजी उद्योग में श्रन्य प्रकार के प्रविक्ष्य लगा देने से भारतीय उद्योगों के उत्यादन न्यय में वृद्धि हो गई है। भारत के श्रीद्योगिक चेन्न में लग-भग निजी उद्योगों का ही बोल बाला है। इस्र लिए श्रीर उद्योगों के ही बोल बाला है। इस्र लिए श्रीर उद्योगों में व्यवसाय की संभावना में वृद्धि करने के लिए निजी उद्योग चेन्न को सभी संभव सुविधाएँ श्रीर उसके मार्ग में सरकारी प्रतिक्ष्यों द्वारा बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि सरकार श्रपनी कर, अम तथा उद्योग सम्बन्धी नीतियों में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उत्यादन तथा निर्यात में वृद्धि के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके तो उद्योग चेन्न में वेरोजगारी बहुत श्रंशों में कम की जा सकती है।

यह सुक्ताव दिया गया है कि भारतीय उद्योग चेत्र में युक्तिकरण की योजनाओं को लागू करने की अनुमति न दी जाय क्योंकि. इससे उद्योग चेत्र, में बेरोजगारी में वृद्धि होती है। यदि यह सुक्ताव मान लिया गया तो श्रोद्योगिक चेत्र में वेरोजगारी घटने की अपेदा और श्रिषक बढ़ेगी। जब बाजार में पूर्ति माँग से कम हैं तो इस बात का विशेष महत्व नहीं है कि मारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई का उत्पादन व्यय कितना है। परन्तु चूँकि श्रव खरीदार श्रपनी व्यय शक्ति के श्रवक्ल क्य करना चाहता है जिसके कारण बाजार की स्थित उसी हाथ में है, उद्योगों की परस्पर प्रतियोगिता शक्ति विशेष महत्व की बात हो हो गई है। यदि किसी कारखाने का उत्पादन व्यय मारत या विदेश में श्रपनी

प्रतिद्वन्दी कारखाने के उत्पादन व्यय से अधिक है तो वह कारखाना अवश्य नष्ट हो जायगा युक्तिकरण उत्पादन व्यय को कम करने का एक उपाय है। यदि युक्तिकरण की योजनाओं को लागू किया जायगा तो इससे कुछ वेरोजगारी अवश्य फैलेगी परन्तु यदि युक्तिकरण योजनाओं को लागू ही न किया गया तो यह सम्भव हो सकता है कि कारखाना सदैव के लिए बन्द कर देना पड़े और पूर्व की अपेदा कहीं अधिक संख्या में व्यक्तियों को वेरोजगारी का सामना करना पढ़े।

कुछ व्यक्तियों का मत है कि भारत सरकार ने जून १६४४ में जो योजना प्रकाशित की थी ग्रीर जो श्रव तक वैकल्पिक रही है उसे श्रानिवार्य कर देना चाहिए। इस योजना के श्रनुसार वेरोजगार व्यक्ति को श्रपने वेरोजगारी मास के पूर्वाई में पारिश्रमिक की साधारण दर का ७५ प्रतिशत मिलेगा श्रीर उत्तरार्ध में ५० प्रतिशत। इस योजना में पहले ही मान लिया गया है कि मारतीय उद्योग इस श्रातिरिक्त परिश्रमिक के घन भार वहन कर सकने में समर्थ हैं, परतु वास्तविक स्थित इसके विपरीत है। भारतीय उद्योग को जितना लाम होता था उसकी मात्रा घट गई है श्रीर यदि उद्योग पर श्रधिक मार पड़ा तो वह बहन कर सकने में श्रसमय सिंद होगा। मारत के श्रनेक कारखाने पहले ही बन्द हो चुके हैं। यदि यह योजना श्रानिवार्य की गई तो कुछ श्रीर कारखाने भी बन्द हो जायँग।

'प्रथम योजना काल के अनुभव से यह आवश्यक हो गया है कि वेकारी की समस्या पर केवल सामूहिक रूप से ही नही वरन् आमी आ और नागरिक चेत्रों के दृष्टिकी ए से भी विचार करना चाहिये! इस समस्या के विस्तार का, जो कि आगामी कुछ वर्षों में होगा, ठीक-ठीक अनुमान करने के लिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न मागों के आमी ए और नागरिक चेत्रों में इसकी वास्तविकता को समस्त लिया जाय। यह भी आवश्यक है कि शिक्तित वर्ग की वेकारी को अन्य लोगों की वेकारी से अलग कर लिया जाय"।

"प्रथम योजना के श्राकड़ों के परीक्षण से यह जात होता है कि श्राघी योजना कार्यान्वित होने पर वेकारी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। प्रथम योजना काल में रिजस्टर किये हुये वेरोजगार लोंगों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही यह मार्च १६५१ में ३१३७ लाख र० तथा दिसम्बर १६५३ में बढ़कर ५१२२ लाख हो गई श्रौर १६५६ के मार्च में ७९०५ लाख हो गई। योजना श्रायोग की सिफा-रिश के श्रतुसार नेशनल सैम्पिल सर्वे ने जो प्रारंभिक परीक्षण नगरवासियों में वेरोजगारों का किया था उसके परिशामों के दृष्टिकोण से यदि इन श्रांकड़ों को

देखा जाय तो इनसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पहता है। इस सर्वें के अनुतार नागरिकों में वेरोजगारीं की (१९५४) संख्या २२ ४ लाख आँकी गई थी। इस सर्वें ने वेकार लोगों की संख्या आर जिनका नाम रिक्टर किया जा चुका था उनकी संख्या के बीच अनुपातिक सम्बन्ध मी स्थापित करने का प्रयत्न किया है। सर्वें का अनुमान था कि लगभग २५% वेरोजगार व्यक्ति एक्सचेन्ज के दफ्तर में अपना रिजस्टर करवाते हैं। इस आधार पर नगरवासियों में वेरोजगारी की संख्या वर्तमान काल में २८ लाख के लगभग आती है। यह अनुमान सामान्यतः देश के विभिन्न भागों के नगरों में किये गये परीक्षणों की रिपोर्टों के समान है। सामियक वेकारी, को जो कि विकासमान आधिक व्यवस्था में अवश्यमभावी है, चूर देते हुये इम यह कह सकते हैं कि नगरवासियों में वेकार लोगों की संख्या २५ लाख के लगभग अनुमान की जाती है। इस संख्या में नगर के अभिकों की संख्या नगर के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के सामान का नगर के स्थान के सामान की नगर के सामान का नगर के सामान के सामान का नगर के सामान की नगर के सामान का नगर के सामान की नगर के सामान का नगर के सामान की सामान की नगर के सामान की नगर के सामान की नगर के सामान का नगर के सामान की नगर की नगर का नगर

श्रागामी ५ वयों में श्रीमकों की गण्ना में वृद्धि श्राने वाले नवागन्तुकों की संख्या १ करोड़ श्रुनुमान की गई है। इस संख्या में से नागरिक श्रीमकों में नवागन्तुकों को श्रुनुमानित ३८ लाख संख्या घटा कर १६५६-६१ के मध्य श्राम्य श्रीमकों की गण्ना में वृद्धि करने वाले नवागन्तुकों की संख्या ६२ लाख के लगभग श्राविगी। निम्न तालिका यह बतलाती है कि द्वितीय योजना काल में यदि वेकारी की समस्या को समात करना है तो कितने व्यवसायों के श्रवसर प्रदान करने पढ़ेंगे:—

(१० लाख में संस्थायें) नगरों के ग्रामों के योग चेत्र मं त्तेत्र में श्रमिकों में नवागन्तकों के लिये ₹"5 ६ • २ 80.0 वर्तमान श्रमिकों में वेरोजगार व्यक्तियों के लिये ₹'५ २'प ५.३ योग €.₿ 0.3 १५.३

यदि इस प्रकार रोजगार के ग्रवसरों को पैदा करना सम्भव भी हो सके तो भी श्रांशिक रोजगार की समस्या को जो वेकारी की समस्या की ही तरह महत्व शाली है सुलकाया नहीं जा सकता। हितीय योजना का ध्यान प्रधानतः वरोजगारी श्रीर श्राशिक वरोजगारी की समस्या पर है। इस्रिलेचे हितीय योजना में एक श्रीर वहीं मात्रा में उत्पादन करने वाले संयुक्त पूँजी वाले उपक्रमों के विकास के प्रति श्रीर दूसरी श्रीर प्राम्य तथा छोटे उद्योगों के विकास के प्रति इस श्राशा से प्रधानता दी गई है कि चे किसी सीमा तक वेकारी की समस्या को सुलमा सकेंगे। सरकारी चेत्र में कुल व्यय लगमग ४८०० करोड़ रुपये का श्रानुमान किया गया है, जिसमें से केवल ३८०० करोड़ रुपये का श्रानुमान किया गया है, जिसमें से केवल विनयोग दिखाते हैं। इसके श्रातिरिक्त व्यक्तिगत चेत्र में विनियोग की मात्रा २४०० करोड़ रुपये श्रानुमान की गई है। राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों हारा पूरित श्रांकड़ों तथा व्यक्तिगत चेत्र के लिए उत्पादन शक्त में वृद्धि सम्बन्धी मान्यताश्रों को विचाराधीन रखते हुए जो ध्येय निश्चित किए गए है उनके श्राधार पर हितीय योजना हारा प्रदत्त रोज़ी के श्रातिरिक्त श्रवसरों का श्रानुमान लगाया जा सकता है। निम्न तालिका में इन परिणामों का निष्कर्ष दिया गया है।

(१० लाख	नी संख्या व
को छोड़ क	7]
***	ે ર'શ∙
***	"оЧ
•••	*२५
• • •	**
•••	• ৬५
***	. A.Y
नाएँ …	' ¥₹
***	•३१
***	· * ₹₹
***	.48
***	***
	प्र'२०
	•
ਵੇਂ ···	₹.00
	9.80
	को छोड़ क

द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा कितने नवीन व्यवसायों को अवसर प्रदान किया जा उकेगा उसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना अभी तक उम्भव नहीं हो सका है। "ग्रायोग द्वारा परीचा करने से यह शत होता है कि प्रथम योजना काल में जो प्रत्यन्त न्यवसाय के श्रवसर सरकारी श्रीर न्यक्तिगत न्रेत्र में प्रदान किये गये उनकी संख्या ४५ लाख के लगभग थी। इस अनुमान में वाखिल्य श्रीर ंव्यापार श्रादि के सेत्र के श्रन्तर्गत श्रातिरिक्त व्यवसाय सम्मिलित नहीं किये गये हैं। विकास सम्बन्धी प्रयत्न को द्विगुणित करके जो द्वितीय योजना में अतिरिक्त च्यवसाय के अवसरों के प्रदान करने का ध्येय बनाया गया है वह कुछ विशेष श्रिधिक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी ंव्यय प्रथम योजना काल के व्यय से कोई विशेष अधिक नहीं हो पायेगा, क्यों कि सरकारो चित्र में योजना का 'व्यय १६५५-५६ में ६०० से ६२० करोड़ रुपयों के लगमग निश्चित किया गया है, जब कि विकास योजनात्रों पर १९५०-५१ में २२४ करोड़ रुपया ही ज्यय किया गया था। प्रथम योजना के श्रान्तिम वर्ष में सरकारी सेत्रं में व्यंय की मात्रा १६५०-५१ के व्यय की मात्रा से लगमग ४०० करोड़ वपये श्रिधिक होने की सम्भावना है। यह भी सम्भव है कि प्रथम योजना के श्रन्तिम वर्ष की तुलना में विकास योजनात्रों पर ज्यय में वृद्धि दितीय योजना के अन्तिम वर्ष में लगमग ६०० करोड़ रुपया हो। इसके अतिरिक्त दितीय योजना में विनियोग के ढंग को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मारी उद्योगों श्रीर यातायात पर, जो कि श्रहणकाल में बहुत कम व्यवसाय के श्रवसर प्रदान कर सकते हैं, बहुत अधिक धन व्यय किया जाने वाला है।" इसका अर्थ यह है कि परम सौमाग्य होते हुये भी ८० लाख से ऋषिक व्यक्तियों के लिये (कृषि की छोड़ कर) दितीय योजना के उपायों द्वारा व्यवसाय प्रदान करना सम्भव न हो सकेगा जब कि बेकारी की समस्या को पूर्ण रूपेण इल करने के लिये १५२ ५ लाख व्यक्तियों के लिये व्यवसाय प्रदान करना श्रावश्यक है।

मई १९५८ में योजना श्रायोग द्वारा जारी की गई पुस्तिका 'द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की सम्भावनायें मूल्यांकन' के अनुसार 'पहले दो वर्षों में कृषि के बाहर रोज़ी के २० लाख अवसर प्रदान किये गये। लगमग १० लाख अम-शक्ति १९५८ पह में रोजी पा सकेगी। यह स्मरण रखना चाहिये कि योजना में ७९ लाख व्यक्तियों के कृषि के बाहर तथा १६ लाख व्यक्तियों के कृषि के अन्दर रोजी पाने की सम्भावना है। विभिन्न योजनाश्रों की लागत में वृद्धि हो जाने के फल-स्वरूप कृषि के बाहर सरकारी च्रेत्र में ४८०० करोड़ ६० के व्यय के अनुमान पर लगमग ७० लाख व्यक्तियों को रोजी मिल सकेगी। यदि यह व्यय ४५०० करोड़ रु हो तो रोजी पाने वालों की संख्या ६५ लाख के लगभग होगी। यह अनुसान बिल्कुल सही नहीं है किन्तु इनसे इतना तो पता चलता ही है कि हमारी भूर्य व्यवस्था में अम-शक्ति की वार्षिक वृद्धि के अनुरूप विनियोग नहीं हो रहा है।"

रोजगार के दफ्तरों का कार्य

मारत में रोजगार के दफ्तरों का एक जाल सा विछा हुन्ना है जो वेरोजगार व्यक्तियों के म्रावेदनों को स्वीकार करते हैं और उन रिक्त स्थानों के लिये उन्हें मेज देते हैं जो सरकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विद्याप्ति किये जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तर वेरोजगारी कम करने में सहायक हैं, क्योंकि वे बेरोजगार व्यक्तियों का सम्बन्ध व्यवसाय प्रदान करने वालों से स्थापित कर देते हैं परन्तु ये रोजगार के दफ्तर ही मनुष्य की अप्रयुक्त शक्ति की समस्या को सुलक्ताने के सफल उपाय तो नहीं हैं। इनका कार्य चेत्र प्रचलित आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत ही सुविधायें प्रदान करना है। ये दफ्तर नवीन व्यवसायों को तो उत्पन्न कर नहीं सकते। वे तो केवल वेरोजगार व्यक्तियों को जो कार्य करने की श्वमता रखते हैं आरे करना चाहते हैं निर्देश मात्र ही दे सकते हैं। वे उन व्यवसायों के लिये को निज्ञापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त हैं। वे उन व्यवसायों के लिये को निज्ञापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त हैं। वे उन व्यवसायों के लिये को निज्ञापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त हैं। वे उन व्यवसायों के लिये को निज्ञापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त हैं उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं हुद्ध सकते।

यह सब होते हुए भी बेरोलगार व्यक्तियों को प्राप्त स्थानों के लिये निर्देश देना भी बेरोलगारी की समस्या के सुलम्माने में एक बढ़ी सहायता है। इसके श्रांतिरक्त यद्यांप रोलगार के दफ्तर में नाम रिजस्टर कराये हुए बेरोलगार व्यक्तियों से हमें बेकारी की समस्या का पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होता, पर उससे निःसंदेह बेरोलगारी की बदलती हुई प्रश्निक ज्ञात होती है। यह बढ़ी चिन्ता का विषय है कि रोलगार के दफ्तरों में रिजस्टर किये हुये व्यक्तियों की संख्या १६५६ में ७,५८,५०३ थी। १६५७ में यह बढ़कर ६,२२,०६६ हो गई। १६५६ में केवल १,८८,८५५ के लगह दी गई। १६५७ में यह संख्या बढ़कर १,६२,८३१ हो गई।

रोजगार के दफ्तरों को श्राधक प्रभाव शाली बनाने के लिये यह श्रावश्यक है कि उनका पुनंसंगठन किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण श्रीर व्यवसाय स्थवस्था समिति ने जिसे प्रायः बी० शिवा राव कमेटी कहते हैं भारत सरकार को श्रप्रेल १६५४ में दी हुई रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें की:—

- (१) रांजगार के दफ्तरों की व्यवस्था को विस्तृत करके उसे राष्ट्रीय सेवा का एक स्पार्थ व अधिक अधिकार प्राप्त विभाग बना देना चाहिये;
 - (२) प्रशासन विकेन्द्रित होना चाहिये। इसका यह अर्घ है कि नीति

चाहे सरकार द्वारा क्यों न निर्धारित की नाएं पर उनका नित्य प्रति का प्रशासन । राज्य सरकार द्वारा होना चाहिये;

- (३) केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजगार के दफ्तरों को जो अनुदान ग्रहायतार्थं दिया जाता है वह चालू रहना चाहिये, पर उसकी मान्ना को चेन्नीय प्रधान कार्यालयों तथा राज्यों के रोजगार के दफ्तरों के कुल ज्यय के ६०% तक ग्रीमित कर देना चाहिये; श्रीर १९५३-५४ के बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई हो अयवा १९५२-५३ में जो बास्तिवक ज्यय किया गया हो, इन दोनों राशियों में से जो राज्य की सरकार के हिंग्टकोण से उसके लिये अधिक लाभकारी हो, उसे अनुदान की श्रिधिकतम मान्ना नियत कर देनी चाहिये;
- (४) रोजगार के दफ्तरों के कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिये स्त्रीर उनके कार्यों में निम्न कार्यों को भी सम्मिलित करना चाहिये: (क) मालिकों स्त्रीर कार्य करने वाले वगों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये; उनको चाहिये कि व्यवसाय चाहने वालों के आवेदनों को स्त्रीकार करें श्रीर तब तक उनसे अपना सम्बन्ध रक्खें जब तक कि उस पर नियुक्ति न हो जाय; (ख) नाम रजिस्टर कराये हुये व्यक्तियों का निरीत्त्रण तथा सहायता करें श्रीर उनकी आवश्यक परीत्ता लें; (ग) रजिस्टर कराये हुए व्यक्तियों की फाइलें निर्माण करें, श्रीर योग्य आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को कार्य देने वाले व्यक्तियों के पास मेर्ज श्रीर उनकी निर्माल को लेखा निर्माण करें ख्रीर उनकी निर्माल को लेखा निर्माण करें ग्रीर उनकी निर्माल को लेखा निर्माण करें श्रीर उनकी निर्माल को लेखा निर्माण करें श्रीर स्त्रीत रक्खें; (भ) व्यवसाय के श्रवसरों का पता लगायें श्रीर व्यक्तियों तक इसकी स्चना पहुँचाने की सुविधायें प्रदान करें ताकि वेरोजगारों को व्यवसाय प्राप्त हो सके श्रीर मालिकों को उपयुक्त कार्य करने वाले इन दफ्तरों को चाहिये कि वे व्यवसाय स्मान्य में अपना मत भी मकाशित करें श्रीर कीन सा कार्य कब तक चलेगा इसके सम्बन्ध में श्रपना मत भी मकाशित करें;
- (५) श्रदत्त श्रमिकों को न तो रिजस्टर करने की श्रावश्यकता है श्रीर न उनके श्रावेदनों की। जो व्यक्ति ऐसे श्रमिकों की सेवार्ये चाहते हैं उनको घोषणा द्वारा या किसी श्रन्य रूप से सूचित कर देना ही पर्याप्त होगा। इसके पश्चात् जो कार्य करना चाहते हैं उन्हें सीधे मालिकों के पास पहुँच जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो प्रतिदिन रोजगार के दक्तर पर इकटा होते हैं तथा घोषणा द्वारा जिन रिक्त स्थानों की सूचना दी जाती है उनके श्राकट़े तैयार करने की श्रावश्यकता नहीं है; श्रीर
 - (६) सरकारी तथा श्रर्धं सरकारी संस्थाश्रों द्वारा नियुक्त किये जाने के

सम्बन्ध में ये दफ्तर जो सिफारिशें करें उनके परिशाम की कुछ दिन तक जाँच करने के पश्चात् व्यक्तिगत चेत्र में भी इन दफ्तरों की सिफारिशों पर नियुक्तः करना श्रनिवार्य कर दें।

सरकार ने बी॰ शिवाराव कमेटी के ग्रामिस्तावों को ग्रांशिक रूप में स्वीकार कर लिया है और रोजगार के दफ्तरों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये निम्न उपायों को द्वितीय योजना में कार्यान्वित करने का निर्णय किया है: (१) रोजगार दिलाने के विभाग को १२५ नये रोजगार के दफ्तरों की स्थापना करके विस्तृत करना तांकि अन्य बहुत से व्यवसाय के केन्द्र इनके श्रंतर्गत आ सर्कें; (२) व्यवसाय की स्वनात्रों के एकत्रित करने तथा लोगों तक पहुँचाने की योजना निर्माण करना; (३) चुने हुये व्यवसाय के दफ्तरों में नवयुक्क रोजगार सेवा संस्था की स्थापना करना तथा वयस्कों के लिये व्यवसाय की सलाह देना तथा 'केरियर भैम्फलेट' श्रादि उपयुक्त तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करनाः (४) रोजगार सम्बन्धी विश्लेपण तथा खोज के कार्य-क्रम बनाना ताकि विभिन्न व्यवधार्यों के नाम तथा परिभाषा मान्य स्तर की बनाई जा सकें; श्रीर (५) रोजगार के दफ्तरों में-व्यवसायिक परीक्षी सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना । इन उपायों से मारत की व्यवसाय - दिलाने वाली सेवात्रों की कार्य कुशलता श्रधिक बढ़ जायगी परन्तु यह तभी सम्मव है अब कि रोजगार के दफ्तर राष्ट्रीय सेवा विभाग के रूप में विकसित हो जाँय श्रीर तभी उनके लिये वेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसाय दूढना श्रीर -दिलाना भी सम्भव हो सकेगा। कमेटी ने प्रशासन को विकेन्द्रित करने की सिंकारिश की है क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकारों को भी इस संस्था के प्रति सहातुभूति उत्पन्न हो जायगी श्रीर वेरोजगार के दफ्तरों का राज्य की सरकार।" तयां राज्य के श्रन्तर्गत व्यक्तिगत मालिकों से सम्बन्ध स्थापित करने में भी यह सहायक भी सिद्ध होगी। विकेन्द्रियकरण से पान्तीयता के बहुने तथा स्रन्तरप्रान्तीयः वनसंख्या के श्रावागमन में वाधा पहने का मय निर्मूल है क्योंकि इन रोजगार के दफ्तरों की नीति तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्घारित होगी। इन संस्थाओं के कार्यों के प्रसार के सम्बन्ध में जो सुकाव दिये गये हैं उनसे मालिकों तथा रोजगार के दफ्तरों के बीच श्रीर बेरोजगार व्यक्तियों श्रीर रोजगार के दफ्तरों के बीच श्रब्छा सम्बन्ध भी स्थापित हो सकेगा । श्रदत्त श्रमिकों के सम्बन्ध में उनकी रिजस्ट्री न करने की सलाह देने में ऐसा लगता है कि कमेटी इस कार्य के विस्तार तया सम्मावित श्रिधिक व्यय से विशेष प्रमावित हो गई थी। पर ऐसा करने से इसमें संदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तरों की वेरोजगारी की समस्या सुलकाने के सम्बन्ध में उपयोगिता अवस्य कम हो जायगी।

छाध्याय २६

श्रौद्योगिक गृह निर्माण

श्रीद्योगिक यह निर्माण की समस्या श्रीमकों को कम किराये पर उपयुक्त. त्रावास प्रदान करने की है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भी बड़े बड़े कस्बां श्रीर नगरों में, विशेष कर श्रीद्योगिक केन्द्रों में, रहने के लिये घरों का श्रमाव था। श्रमिक लोग चौल तथा बस्तियों में बड़े श्रस्वास्थ्य वातावरण में रहते हैं। गत कुछ वर्षों से जन संख्या में वृद्धि होने, पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा कम संख्या में नये घरों के निर्माण के कारण दशा और भी अधिक शोचनीय हो गई है। १९३१, १९४१ ब्रीर १९५१ की जनगणना के अनुसार. जनसंख्या में क्रमश: ११, १४ ३ श्रीर १३ ४ प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु नागरिक चेत्रों में यह वृद्धि कमशः २१, ३२ श्रीर ५४ प्रतिशत हुई। पाकिस्तान से लगमग ताख शरणार्थियों के क्रा जाने से नागरिक चेत्रों में जनसंख्या का दबाव वढ़ा जिसके प्रभाव से रहने की व्यवस्था और जिल्ल हो गई। शरणार्थियों ने गाँव की श्रपेजा बड़े कस्बों और नगरों में ही रहना अधिक पसन्द किया। इससे नगरों श्रीर कस्बों में रहने के लिए घरों की माँग बढ़ी, परन्तु पूर्ति न हो सकने से यह स्रमाव की खाई चौड़ी होती गई। माँग के अनुसार घरों की पूर्ति न हो सकने का कारण यह है कि इमारत बनाने के सामान का अधिक मूल्य होने के कारण श्रीर बाजार में सामान के श्रमाव के फलस्वरूप नई इमारतों को पर्याप्त मात्रा में नहीं बृनाया जा सका। इसके साथ ही मकानों को किराये पर देने श्रीर किराये की दरों पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाने से भी इस दिशा में प्रतिकृत प्रभाव पड़ा श्रीर इसी कारण बढती जनसंख्या के साथ मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

गृह निर्माण की प्रवृत्ति—वर्तमान में मुख्य यह निर्माण एजेन्सियाँ निम्नि लिखित हैं :—(१) सरकारी श्रयवा श्रन्य एजेन्सियाँ, (२) उद्योगपति, (३) सहकारी समितियाँ, (४) श्रपने उपयोग के लिए मकान बनाने वाले व्यक्ति, श्रीर (५) निजी उद्योग । निजी उद्योग के मालिकों की श्रीर श्रपने उनयोग के लिए यहनिर्माण कराने वाले व्यक्तियों की श्रव यहनिर्माण की श्रोर गित मन्द हो गई है। गत कुछ वधों में इस दिशा की श्रोर सरकारी तथा श्रन्य मिली-जुली एजेन्सियों, उद्योगपतियों श्रीर सहकारी समितियों की गित में विशेष रूप से वृद्धि हुई है।

े प्रथम योजना, काल में ७६,६७६ किराये के वरों के निर्माण के कार्यक्रम

को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से १६,१६५ वम्बई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, ५,६२६ हैदराबाद में, ५,१८१ मध्यप्रदेश में, ३,४४४ मध्यभारत में तथा इससे कम संख्या में ग्रन्य राज्यों में बनवाये जाने वाले थे। जितने किराये के घरों का निर्माण प्रयम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पूर्व किया जा चुका या उनकी संख्या ४०,००० के लगभग थी। जितने किराये के बरों के निर्माण की श्रनुमति दी गई है उनमें से ६८,२०० श्रयना ८५% के लगभग राज्य सरकारों द्वारा, १०,१६१ श्रथवा १३% आंमकों के निजी उद्योग द्वारा ऋौर १,३१८ या १.६% उद्योगों में काम करने वालों की सहकारी समितियों द्वारा बनवाये जा रहे हैं। जब यह योजना निर्माण की गई थी उस समय सहकारी समितियों श्रीर मालिकों के सहयोग की श्रधिक श्राशा की थी। योजना के इस पत्त पर विचार किया जा रहा है श्रीर ऐसे उपाय सोचे जा रहे हैं जिनसे कि मालिकों श्रीर कारखानों के अमिकों की सहकारी समितियों का श्रिषिक सहयोग प्राप्त हो। इनके श्रितिरिक पुनवीस, रज्ञा, रेलवे, लोहा श्रीर इस्पात, उत्पादन, च्चना, निर्माण, गृहं निर्माण तथा पूर्ति श्रादि मंत्रालयों द्वारा भी गृह निर्माण के समुचित कार्यक्रम कार्यान्यत किये जा रहे हैं। राज्य धरकारें ग्रौर कुछ त्यानीय ग्रधिकारियों के ग्रपने निजी ग्रह निर्माण के कार्यक्रम भी चालू है। यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पुनर्वास मन्त्रालय ने नगरों में ३,२३,००० किराये के वर वनवाये श्रीर राज्य धरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों ने, निर्माण, यहनिर्माण तथा पूर्ति के मन्त्रालयों,को छोड़ कर लगभग ३००,००० गृहीं का निर्माण करवाया। श्रन्य रहिनर्माण की योजनात्रों को, जिनका कपर वर्णन किया जा चुका है, सम्मिलित करते हुए सरकारी विभागों ने प्रथम थोलना काल में लगमग ७,४२,००० गृहों का निर्माण करवाया । व्यक्तिगत लोगों ने कितने गृहों का निर्माण कराया उसकी संख्या जानना कठिन है। कर जाँच श्रायोग के इस सम्मन्य में परीचा करने से शात हुआ कि नगरों में गृहनिर्माण के सम्बन्ध में कल विनियोग १९५३-५४ में लगमग १२५ करोड़ रुपया था। यदि इसे हम पाँच वर्षों की श्रविघ का श्रीसत मान लें श्रीर एक घर के बनवाने में श्रीसत व्यय १०,००० ६० के लगभग मान लें तो यह जात होगा कि प्रथम योजना काल में लगभग ६००,००० गृहों का निर्माण न्यक्तिगत चेत्र में हुत्रा। इस प्रकार प्रथम योजना काल में लगमग १३ लाख घर नगरों में वनवाये गये।

प्रयम योजना काल में ग्रामों में भी रहने की स्थिति में सुघार के कुछ उपायों का प्रयोग किया गया है। सामुदायिक विकास योजना च्लेतों से ५८,००० ग्राम्य शौचालय, १६०० मील लम्बी नालियाँ ग्लीर २०,००० कुँये बनवाये गये हैं श्रीर लगभग ३४,००० कुँश्रों का जीगोंदार किया गया है श्रीर राष्ट्रीय विकास चेत्रों में ८०,००० प्राम्य शीचालय, २७०० मील लम्बी नालियाँ, २०,००० नये कुँये श्रीर ५१०० पुराने कुँश्रों का जीगोंद्वार किया गया है। राष्ट्रीय विकास तथा चामुदायिक विकास योजनाश्रों के च्लेत्रों में लगभग २६००० घरों का निर्माण हुआ है और लगभग उतने ही पुराने वरों का जीगोंदार किया गया है। श्रनेकी राज्यों में प्रामों में हैंट के भटटे स्थापित किये जा रहे हैं। कहीं-कहीं पर सहकारी समितियों की सहायता इस कार्य में ली जा रही है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में १६५०-५१ में १६ सहकारी हेंट के महें खोले गये थे; १६५४-५५ तक उनकी संख्या बढ़कर ७५२ हो गई और भट्टों के आस-पास के मार्मी में अधिकाधिक नचे दंग के पक्के मकान बनते जा रहे हैं। बहुत से राज्यों में इरिजनों के छावास की रिधात की, विशेष भूमि सेवी की उनके लिये नियत करके तथा सहकारी यहनिर्माण समितियों की स्थापना द्वारा, सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत निर्माण, पूर्ति तथा गृहनिर्माण मन्त्रालय ने ब्रास्य राइनिर्माण श्रागार की स्थापना की है जिसका ध्येय इस होत्र की विभिन्न समस्याश्रों का श्रध्ययन करना श्रीर गृहों के नये-नये श्राकारों, श्रीमन्यासों, निर्माण के दंगों तथा स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग करने के उपायों की खोज करना है।

कठिनाइयाँ—श्रधिक मकानों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने में श्रनेक कठिनाइयाँ हैं:

(१) प्राम श्रीर नगर में भूमि, इस्पात, ईंट, सिमेंट, लकड़ी की चीखट इत्यादि के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई। यह सभी चीजें मकान बनाने के लिए बहुत स्थावश्यक है। इन वस्तुश्रों के मूल्य श्रधक होने पर भी ग्रह-निर्माण संमव या परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसके लिए पर्याप्त घन नहीं मिल पाता है। दूसरी श्रोर यदि श्रधिक व्यय पर मकान बनाया जाय तो उसका किराया भी श्रधिक होना चाहिए परन्तु ग्रह निर्माण का कार्य तीन्न गति से करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रमिकों तथा श्रन्य निर्धन श्रोर मध्यम श्रेणी के लोगों को सस्ते किराये पर मकान दिये जा सकें। इसलिए समस्या यह है कि मकान बनाने के सामान का मूल्य घटाया जाय; महँगे सामान के स्थान पर सस्ते मूल्य का कोई दूसरा उपयुक्त सामान लगाया जाय श्रीर श्रमिकों इत्यादि के लिए सुखदाई परन्तु कम व्यय में मकान बनाने के लिए मकान के श्राकार-प्रकार श्रीर उसके दाँचे इत्यादि के सम्बन्ध में खोज कार्य किया जाय। परन्तु यदि ग्रह निर्माण के व्यय में पर्याप्त कमी भी कर दी जाय तब भी ग्रह निर्माण योजना को कार्यन्वित करने के

लिए रपये की आवश्यकता होगी और जब तक पर्याप्त धन, जो कम से कम १०० करोड़ रपया होगा, प्राप्त नहीं होता तब तक सभी आवश्यकता ग्रस्त लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बाजार में रपये की तंगी है और जनता के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए घर बनाने के इच्छुक लोगों को कम व्याज पर रुपया देने के लिये कुछ उपाय खोज निकालना अत्यन्त आवश्यक है।

(२) मकानों का किराया बढ़ाने पर राज्य सरकारों ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। सरकार तथा अन्य एजेन्सी, उद्योगपित और सहकारी समितियाँ लाम की चिन्ता किये बिना यह निर्माण कार्य में वृद्धि कर सकती है। परन्तु किराये पर नियंत्रण लग जाने से और नगरों तथा कस्वां में मकानों का एलीटमैन्ट करने की व्यवस्था से निनी उद्योगों के मालिक नये मकान बनवाने की ओर से लगसग निराश हो चुके हैं। कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि एक निश्चित तिथि के पश्चात् बने नये मकानों पर यह नियन्त्रण लागू नहीं होते हैं इससे नये मकान बनवाने के कार्य की प्रोस्ताहन मिला है।

१६५२ में एशिया और सुदूर पूर्वी आर्थिक सम्मेलन का गृह निर्माण विपयक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में सुमाव दिये गये थे कि (१) आदर्श योजनाएँ चालू की जाँय जिनमें इस्पात और इमारती लकड़ी के स्थान पर बाँस तथा अन्य लकड़ियों के उपयोग की जाँच की जाय और (२) इसी प्रकार की अन्य योजनाओं द्वारा इंट इत्यादि बनाने के लिए उपयुक्त चिकनी मिट्टी की मीं बाँच की नाय। इस प्रकार की आदर्श योजनाओं के द्वारा इम अभिकों तथा अन्य लोगों के लिये सस्ते और सुखदाई मकानों का निर्माण करने के उपाय खोज सकते हैं।

सरकारी योजनाएँ—श्रौद्योगिक शांति प्रस्ताव में सुमाये गये गृह निर्माण कार्य कम के श्राघार पर भारत सरकार ने १६४६ में एक गृह निर्माण योजना तैयार की। इस योजना में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों इत्यादि के द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में जितना रूपया लगेगा उसका दो तिहाई केन्द्रीय सरकार व्याज मुक्त ऋण्ण के रूप में देगी, परन्तु इसके लिये मालिकों को भी कुछ शर्ते माननी पहुँगी। इस योजना के श्रमुसार मालिक तथा राज्य सरकारों को एक तिहाई व्यय की स्वयं व्यवस्था करनी पहुती है। केन्द्रीय सरकार से उन्हें केवल इतना ही लाम प्राप्त है कि श्रावश्यक पूँजी का है श्रंश व्याजयुक्त श्रुण के रूप में प्राप्त हो जाता है।

परन्तु इस योजना के श्रासफल हो जाने पर मारत सरकार ने यह श्रातुंभन

किया कि यह निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों श्रीर कारखाने इत्यादि के मालिकों को इसके लिये नकद श्रार्थिक सहायता देनी पड़ेगी। इसी. विचार से एक योजना निर्माण की गई छीर उसे प्रायः सभी राज्यों की सरकारों के पास विचारार्थ भेजा गया। इस योजना में यह प्रस्ताव रखा गया था कि गृह निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों तथा निजी उद्योगपितयों को भूमि के मूल्य का श्रधिक से श्रधिक २० प्रतिशत केंद्रीय सरकार सहायता के रूप में देगी। परन्तु इसके लिए यह शतें लगाई गई कि (१) मकान वास्तव में श्रमिकों को किराये पर दिया जायगा, (२) किरायेदार से घर की कुल लागत का, जिसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है, केवल ढाई प्रतिशत ही वस्त किया जायगा परन्तु यह किराया अमिक की आय के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, (३) घर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आकार प्रकार के बनने चाहिएँ और (४) घर का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के निरीक्षकों श्रीर गृह-निर्माण बोर्ड को सभी श्रावश्यक सुविधाय दी जानी चाहिएँ। इस योजना का कार्यचेत्र सीमित था श्रीर राज्य सरकारों ने इस स्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसलिये भारत सरकार ने १९५२ के ख्रांत में एक ख्रधिक ब्यापक योजना तैयार की जिसके ग्रन्तर्गत यह ब्यवस्था की गई कि केन्द्रीय सरकार यहनिर्माण कार्य को मोत्सान देने के लिये राज्य सरकारों श्लीर यहनिर्माख बोर्ड को कुल ज्यय का ५० प्रतिशत तक सहायता के रूप में देगी। इसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित किया जायमा । शेप ५० प्रतिशत के लिये सरकार ४३ प्रतिशत व्याज पर ऋगा देगी जिसे २५ वर्ष के अन्दर चुकाया जा सकता है। सहकारी समितियों के सम्बन्ध में यह ज़्यवस्था की गई कि ग्रह निर्माण के कुल व्यय का २५ प्रतिशत सरकार सहायता के रूप में देगी और साथ ही कुल निर्माण-व्यय का ३७ई प्रतिशत धन ४ दे प्रतिशत वार्षिक व्याल पर अप्तुण देशी जिसे १५ वर्ष के अन्दर चुकाया जा सकता है। उद्योग के मालिकों को सरकार कुल लागत का २५ प्रतिशत श्राधिक सहायता के रूप में श्रीर कुल व्यय का ३७३ प्रतिशत तक ४० प्रतिशत वार्षिक •यान की दर से ऋुरा देगी।यह ऋुरा १५ वर्ष के अन्दर चुकाना होगा।इन सब के सम्बन्ध में ऋगा तथा अनुदान की मात्रा स्टेन्डर्ड लागत के आधार पर अनुगिख्ति मात्रा पर ही सीमित कर दी जायगी। बम्बई और कलकत्ता के सम्बन्ध में १ कमरे वाले कई मंत्रिले मकानों की स्टेन्डर्ड लागत ४५०० व्पया श्रीर श्रन्य स्थानों में २७०० रुपया आँकी गई है। दो कमरे वाले कई मंजिले मकानों की बम्मई श्रीर कलकत्ता में लागत ४५३० रुपया (जो कि श्रव बढ़ाकर ५६३० रुपया

कर दी गई है) श्रीर श्रन्य स्थानों में ३४६० रुपया श्रांकी गई है। एक मंजिले मकानों के लिये स्टेन्डर्ड लागत का श्रनुमान कम धन राशि है।

इस पुर्नपरोक्षित योजना की दो मुख्य विशेषतायें हैं: (१) सहकारी सांमितियों को क्यय की ५०% तक श्राण रूप से सहायता मिल सकेगी जबिक मूल योजना के अन्तर्गत केवल ३७६ ही मिल सकती थी और १५ वर्षों में श्राण के चुकता करने के स्थान पर अब २५ वर्ष का समय भी मिल जायगा; और (२) स्टेन्डर्ड किराया विभिन्न प्रकार के मकानों के लिये वम्बई तथा कलकत्ता में १० वपये से लगाकर ३० वपया तक श्रीर अन्य नगरों और कस्बों में १० वपये से लगाकर १० वपया तक नियत कर दिया गया है। इससे योजना अधिक पूर्ण बन गई है। यह आशा की जाती है कि गृह निर्माण कार्य को इस योजना के अन्तर्गत अधिक प्रोस्साहन भी मिलेगा।

त्राधिक सहायता प्राप्त यह निर्माण योजना के श्रन्तर्गत, जो सितम्बर १६५२ में लागू हुई, १६५७-५८ केन्द्रीय सरकार द्वारा मंज्र की गई धनराशि २५.७६ करोड़ रु० थी जिसमें १३-२८ करोड़ रु० श्रुण के रूप में तथा १२-५१ करोड़ रु० श्राधिक सहायता के रूप में थे। इसके श्रन्तर्गत ६१,२५० घर थे। नवम्बर १६५७ तक पूर्ण हुये मकानों की संख्या ६६,७०० थी तथा शेष निर्माण के विभिन्न चरणों में थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत श्रीद्योगिक तथा श्रन्य गृह निर्माण योजनाश्रों के लिये श्रविक घन सहायता में देने का निश्चय किया गया है। प्रथम -योजना में ३८५ करोड़ उपयों की सहायता का प्रवन्य किया गया था परन्तु द्वितीय योजना में १२० करोड़ उपयों की सहायता का निम्न तालिका के श्रनुसार प्रवन्य किया गया है:—

चहायता प्राप्त श्रीद्योगिक गृह निर्माण	. ૪૧	करोड़-	इपये
निम्न श्राय-वर्ग के जिये गृह निर्माण	. 80	>3	53
ब्राम गृह निर्माण	. १०	17	37
वस्तियों की सफाई श्रीर भंगियों के लिये गृह निर्मा	ण २०	27	31
मध्य वर्ती आय वर्ग के लिये ग्रह निर्माण	. ₹	23	33
रोपगोद्योग के लिये यह निर्माण	. 2	. 37	27
योग	१२०	77	77

द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत व्यय की योजना श्रिधिक विस्तृत है श्रीर श्रनेकों नये व्यय के शीर्प उसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं जो कि प्रथम योजना में नहीं ये श्रीर कार्य का ध्येय निम्न है:—

		गृहों की संख्या
₹.	सहायता प्राप्त श्रीद्योगिक घर	१२८,०००
₹.	निम्न त्र्राय वर्ग के लिये घर	६८,०००
₹.	वस्तियों में रहने वालों के लिये नये घर	
	निनमें भंगी भी सम्मिलित हैं—	880,000
٧,	मध्य वर्ती स्राय वर्ग के लिये घर	५,०००
ų,	रोपण उद्योग के श्रमिकों के लिये घर	११,०००
ξ.	प्रामीण गृह निर्माण योजना	१,३३,०००
	. योग	8,44,000

अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा, राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा तथा कोयले की खानों में कार्य करने वाले अमिकों के लिये यह निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनवाये घरों के अतिरिक्त ७५३,००० यहों का (जिनकी संख्या ८००,००० के लगभग द्वितीय योजना काल में आंकी गई है) निर्माण होगा। इस प्रकार द्वितीय योजना में कुल १६ लाख घरों के निर्माण का अनुमान है जबकि प्रथम योजना काल में केवल १३ लाख घरों का ही निर्माण हुआ था।

दितीय योजना के पहले तीन वर्ष में यह निर्माण के ऊपर किये जाने वाले कुल व्यय का अनुमान ४० करोड़ है। "आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक यह निर्माण योजना के अन्तर्गत १६५६-५६ इन तीन वर्षों में ४२,६०० इकाइयों के निर्माण की व्यवस्था है। निर्मा आय वर्ग के अन्तर्गत २२,००० इकाइयों के निर्माण की तथा मंगियों के यह निर्माण के अन्तर्गत २२००० इकाइयों के निर्माण की व्यवस्था है। आभीण यह निर्माण योजना १६५८-५६ में प्रभावपूर्ण ढंग ते लागू की जा रही है। चूँकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काट-छाँट हो रही है अतएव यहनिर्माण के लिये संशोधित राशा १०० करोड़ ६० होगी जो प्रारम्भिक राशा से २० करोड़ ६० कम है। ४५०० करोड़ ६० के कुल व्यय में यह निर्माण पर किया जाने वाला व्यय ८४ करोड़ ६० है। इसमें ६४ करोड़ ६० राज्यों के लिये है तथा २० करोड़ ६० केन्द्र के लिये है ।"

श्रध्याय ३० श्रम की कार्यच्चमता

यह लोक प्रसिद्ध है कि भारतीय श्रमिक निपुण नहीं है। उसकी प्रति घंटा उत्पादन शक्ति भी बहुत कम है। यदि पाश्चात्य देशों के उसी प्रकार के श्रमिकों की उत्पादन शक्ति से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि भारतीय श्रमिकों का उत्पादन बहुत गिरा हुआ है। जापान, ब्रिटेन और श्रमिका के श्रमिक की अपेत्ता उतने ही समय में भारतीय श्रमिक बहुत कम कार्य कर पाता है।

स्ती मिल उद्योग संबन्धी प्रशुल्क मण्डल (१६२६-२७) ने बताया कि भारतीय श्रमिक अथवा आपरेटर ने १८० तकुश्रों पर कार्य किया जब कि इतने ही समय में जापान के श्रमिक ने २४०, इंगलैंड के श्रमिक ने ५०० से ६०० के वीच श्रीर श्रमरीकी श्रमिक ने ११२० तकुश्रों पर कार्य किया । मारतीय बुनकर श्रीसतन २ कर्ये चलाता है जब कि जापान का बुनकर २६, ब्रिटेन का ४ से ६ तक श्रीर श्रमरीका का ६ कर्षे चला लेता है। इससे भारतीय श्रमिक की सापेक्षिक कार्यज्ञमता का श्राभास मिलता है। यहाँ यह बता देना श्रावश्यक है कि गत कुछ वर्षों से कतिपय स्ती मिलों में कार्यच्यमता में काफी वृद्धि हुई है। स्ती उद्योग सम्बन्धी वर्किङ्ग पार्टी (१९५२) ने जाँच करके पता लगाया कि दिल्ली की एक श्रीर मद्रास की दो मिलों में एक बुनकर ४, ६, ८ श्रीर १६, श्रहमदाबाद की एक मिल में १८ श्रौर वम्बई की एक मिल में ६ कर्षे चला लेता है। कार्यज्ञमता में इस वृद्धि का कारण यह है कि इन मिलों में स्वचालित ऋाधुनिक मशीनें लगी हुई हैं जिससे अभिक श्रिकि काम कर सकता है परन्तु कार्य में इतनी प्रगति होते हुए भी आज तक यह बात सत्य मानो जाती है कि भारतीय श्रमिक ब्रिटेन या जापान के श्रापने ही प्रकार के अभिक से कम निपुण है। कोयला-खदान उद्योग के सम्बन्ध में मारत की जिश्रोलोजीकल, माइनिंग श्रीर मेटालर्जीकल सोसाइटी के २८ वें वार्षिक त्र्रिधिवेशन के श्रम्यच के भाषणा में बताया गया कि भारत में एक श्रमिक का उत्पादन २'७ टन है जब कि ब्रिटेन के मजदूर का ६'२९ टन, जर्मनी के श्रमिक का ८ १६ टन श्रीर श्रमरीका के श्रमिक का २१ ६८ टन है। भारतीय श्रमिक का प्रतिषरटा उत्पादन गत कुछ वर्षों में गिरा है। योजना त्रायोग ने बताया है कि कोयला खदान उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या १६४१ में २, १४, २४४ से बढ़कर १६५१ में ३,४०,००० हो गई है जब कि इसी अविध में कोयले

का उत्पादन २ करोइ ५८ लाख ६० हजार टन से बहुकर ३ करोड़ ४० लाख टन हो गया। इस प्रकार जब अभिकों की संख्या में ५८ प्रतिशत नृद्धि की गई तो उत्पादन केवल ३२ प्रतिशत बढ़ा है परन्तु अभिक का प्रतिष्टा उत्पादन १२७ टन से गिरकर लगभग १०० टन हो गया।

यद्यपि सभी उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं है फिर भी स्ट्रिप्य में प्रकाशित कतिपय उद्योगों की उत्पादकता श्रीर श्रिकिंत त्राय के परिवर्तनों से निम्न बार्ते ज्ञात होती हैं:

- (i) कीयला उद्योग में १६५१-१६५४ के बीच खोदने तथा लादने वालों की उत्पादकता में ० ० ७६ प्रांत माइ वृद्धि हुई जन्निक प्रति सप्ताह नकद आय में ० १६६ की वृद्धि हुई।
- (ii) काग़ज उद्योग में, १६४८-१६५३ के बीच मजदूरों की श्रीसत श्राय में तो बृद्धि हुई किन्तु इनकी उत्पादकता बढ़ने का कोई चिन्ह नहीं था।
- (iii) जूट उद्योग में १६४८-१६५३ के बीच उत्पादकता की वृद्धि २'६ प्रतिवर्ष थी जबकि श्रार्जित श्राय की वृद्धि २'७ थी तथा,
- (iv) स्ती वस्त्र उद्योग में उत्पादकता की वृद्धि की वार्षिक दर १६४८-१६५२ के बीच २°२८ थी जबकि अर्जित आय की वृद्धि १'१४ थी।'

इसके विपरीत अमरीका श्रीर बिटेन के श्रमिक की कार्यक्षमता में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। श्रमरीकी श्रमिक की प्रतिवयटा उत्पादन क्षमता में १६१० तया १६४० के बीच दि प्रतिशत वृद्धि हुई। विगत १५ वर्षों में इसमें श्रीर श्रिषक वृद्धि हुई है। यह बताया गया है कि यदि उत्पादन क्षमता इसी श्रनुपात में बढ़ती गई तो ३० वर्ष में दोगुनी हो जायगी। उत्पादन शक्ति की जांच करनेवाली एक श्रांग्ल-श्रमरीकी परिषद् ने ब्रिटेन के लीहे श्रीर इस्पात के कारखाने के कुछ विभागों की जांच की। परिषद् की रिपोर्ट में बताया गया है कि १६१६ से १६५२ के बीच स्टील फींडिंग में १५ से २० प्रतिशत की श्रीर ड्राप-फींडिंग में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसे ही श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। श्रनेक कारणों से मारतीय श्रमिक की कार्यच्चमता निरन्तर घटती जा रही है। यहाँ यह चता देना श्रनचित न होगा कि कार्यच्चमता में कमी होने के लिये केवल मारतीय श्रमिक ही उत्तरदायी नहीं है। इसका बहुत कुछ कारण खराब मशीनें श्रीर दोष पूर्ण श्रीधोगिक संगठन है। परन्तु इसका परिणाम यह श्रवश्य हुश्रा है कि मारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति घट गई है श्रीर विश्व बाजार में श्रपने माल की निकासी करने में उसे श्रत्यन कठिनाइयों का सामना करना पर रहा है।

कारण-अभिक की कार्यज्ञमता अथवा उसकी निपुणता की परिभाषा करना बहुत फाँटन है और यह अनेक वातों पर निर्भर करती है। अभिक की कार्यज्ञमता की जॉन करने का एक व्यवशासिक दंग अभिक के प्रतिपारता उत्पादन की जाँच करना है। एक श्रमिक की एक शिक्ट के कुल उत्पादन के दिखाव ने भो कार्यक्रमता का पता लगाया जा सकता है। एक शिक्ट में ७३ या 🗅 घरटा कार्य होता है। इसके साथ ही श्रमिक के वार्षिक उत्पटन की भाषा की भी इसका साधन बनाया जा सकता है। अभिक की कार्यज्ञमता केवल अभिक के अम पर ही निर्भर नहीं रहती है। फच्चे गाल के प्रकार, गशीनी के प्रकार खीर उनकी स्पिति श्रीर सम्पूर्णं श्रीदांगिक संगठन का भी उस पर प्रभाव पड़ता है । शक्शकता श्रयवा निपुण न होने के लिये चारा दीय भारतीय भागक पर ही नहीं महा जा सकता । कुछ दीप अचर्य अभिक का भी है परन्तु जिस प्रमाली के अन्तर्गत वह कार्य करता है उसे इस धारोप ने यंचित नहीं किया जा सकता। जय इस मारतीय अभिक की कार्यन्तमता श्रीर ब्रिटेन, श्रमरीका या श्रन्य देशों के अभिकी की कार्यस्मता की तुलना करते हैं तो हमें दोनों देशों के कारखाने में लगी मशीनी श्रीर कार्य की स्थित पर भी विचार करना चाहिए। परना किर भी इन एमी बातो पर विचार करने के बाद भी यह सही है कि भारतीय क्षमिक की कार्यज्ञमता श्रमरीकी तथा बिटिश अभिक की कार्यक्रमता से कम है।

भारतीय श्रमिक के श्रक्तराल होने के श्रमेक कारण बताये गये हैं: (१) श्रमिक की श्रस्वस्थता, (२) क्र्यलता का श्रभाव, (३) उसका प्रमानी स्वभाव, (४) जलवाय, (५) श्रमक का कम देतन, (६) मारतीय उद्योग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल का घटिया प्रकार, (७) ह्टी-फूटी श्रीर पुरानी मशीनें श्रीर बहुत से बारखानों में दोष पूर्ण श्रभिन्यास श्रीर (८) श्रद्धराल श्रीरोशिक संगठन ।

दुर्वल शरीर तथा दुरा स्त्रास्त्य—इसमें कुछ सन्देह नहीं कि भारतीय श्रमिक का स्वास्थ्य विदिश या श्रमरीकी श्रांमक की श्रपेना गिरा हुआ है। प्रश्न भारतीय श्रमिक श्रीर विदिश श्रथवा श्रमरीकी श्रांमकों के स्वास्थ्य की तुलना करना नहीं है। वास्तव में प्रश्न यह है कि भारतीय श्रमिक जो काम करता है वह उस काम के लिये उपयुक्त हैं तो यह कहना उचित नहीं कि विदिश श्रथवा श्रमरीकी श्रमिक की श्रपेन्ता स्वास्थ्य श्रपिक खराव होने के कारण भारतीय श्रमिक की कार्यन्तमता श्रपेन्ताकृत कम है। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर विदिश, श्रमरीकी प्राय: सभी श्रमकों का उत्पादन शिर जाता है, उनकी कार्यन्तमता कम हो जाती है। इसलिये भारतीय श्रमिक की श्रकुशलता का कारण उसकी बीमारी या दुर्चलता नहीं हो सकते हैं।

- (ii) प्रवासी प्रवृत्ति—भारतीय अभिक की प्रवासी प्रवृत्ति से भी उसकी अकुशलता नहीं सिद्ध की जा सकती क्योंकि जनतक अभिक काम करता है तवतक अधियोगिक केन्द्रों में रहता है और इस बीच वह अपनी सम्पूर्ण योग्यता के अनुकूल कार्य कर सकता है। बीच-बीच में गाँव चले जाने से एक निश्चित लाभ यह होता है कि कारखाने के काम से कुछ दिन का अवकाश ले कर कारखाने के नियमित कार्य से अतग हो जाने के कारखा एक नई शिक प्राप्त करता है इससे पुनः कारखाने लीटने पर वह पहले की अपेन्ना अधिक कार्य कर सकता है।
- (iii) कुशलता का प्रभाव—इसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि कुशलता न होने के कारण ही उसकी कार्यज्ञमता कम है, क्योंकि यदि श्रमिक एक विशेष कार्य करता है तो हसका कारण ही यह है कि वह इस कार्य को श्रन्य कार्यों को श्रमेज्ञा श्रन्छी प्रकार कर सकता है। कुशलता का श्रभाव तभी होता है जब कुशल टेकनीशियनों का श्रभाव हो परन्तु जहाँ कुशल टेकनीशियन काम करते हैं वहाँ उनकी कार्यज्ञमता उतनी ही शिक्षा पाये हुए श्रन्य देशों के-टेकनीशियनों से कम नहीं होनी चाहिये। जहाँ तक ऐसे कार्य का सम्बन्ध है जिसको करने में विशेष कुशलता की श्रावश्यकता नहीं होती है वहाँ कुशलता के श्रमाव का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (iv) कम मजद्री-यह कहा जाता है कि पारिश्रमिक कम होने के कारण ही अमिक की कार्यसमता कम है। इसके समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि कम पारिश्रमिक होने से श्रमिक अपना श्रीर अपने परिवारका ठीक से भरग-पोषग नहीं कर पाता है। इससे उसकी कार्यज्ञमता पर बुरा प्रमाव पहता है। परन्तु. यह जानना चाहिए कि इन सब बातों का कारण पारिश्रमिक कम होना नहीं है वरन् मूल्य स्तर की तुलना में पारिश्रमिक का श्रमाव है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक कम हो ख्रौर जिन वस्तुत्रों पर वह अपना पारिश्रमिक व्यय करता है उंनके मूल्य श्रीर मी कम हों तो उसे श्रपने परिवार का मरण-पोषण करने में कुछ केठिनाई नहीं होगी। वह अपनी आवश्यकता पृति के लिए सभी वस्तुएँ क्रय कर सकता है। वास्तव में मुख्य समस्या यह है कि पारिश्रमिक वस्तुत्रों ं के मूल्य की श्रपेचा कम है। इसी कारण श्रमिक श्रपने परिवार को पेट भर भोजन नहीं दे पाता है श्रीर उसकी श्रन्य श्रावश्यकताएँ मी पूर्ण नहीं हो पाती। इससे उसकी कार्यज्ञमंता की ज्ञति होती है। प्रश्न पर्याप्त भोजन न पाने ख्रीर जीवन की सुखी बनाने के प्रसाधनों को न पाने का नहीं है। वास्तव में अभिक वस्तुय्रों के मूल्य की अर्पेक्षा पारिश्रमिक कम होने के कारण परिवार का ठीक तरह से प्रबन्ध भी नहीं कर पाता । इससे उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है जिससे अंत में उसकी कार्यसमता

पर प्रमान पहला है। इस प्रकार एक दुष्चक स्थापित हो नाता है; उसकी कार्यस्मता घट जाती है श्रीर उत्पादन कम हो जाता है। पारिश्रमिक होने से कार्यसमता घट जाती है श्रीर उत्पादन कम हो जाता है। पारिश्रमिक होने से कार्यसमता नहीं बढ़ पाती है श्रीर जब तक कार्यसमता में वृद्धि नहीं होती पारिश्रमिक नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि भारतीय श्रमिक इतने वर्षों के पश्चात् भी श्राज निर्धन ही बना हुश्रा है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक बढ़ नाय श्रीर इसके फलस्वरूप उसकी कार्यसमता में भी वृद्धि हो तो वह भविष्य में श्रीर श्रमिक पारिश्रमिक कमा सकता है। जहाँ तक पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, दितीय महायुद्ध से श्रमकों की स्थित में सुधार हुश्रा है। १९४२ से १९५२ के बीच मारतीय श्रमिकों की मनदूरी में वृद्धि हुई परन्तु दुर्माग्य से पारिश्रमिक बढ़ने के साथ-खाय वस्तुश्रों के मृल्यों में भी वृद्धि हुई श्रीर श्रम्भ वस्तुश्रों की कीमतों में मनदूरी की श्रमेका बहुत श्रमिक वृद्धि हुई। इस १९५२ श्रीर १९५२ के बीच मनदूरों की वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्ध नहीं हुई। जब तक वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं होती श्रार्थात् श्रपने द्राच्यक पारिश्रमिक से वस्तुश्रों श्रीर सेवाश्रों को श्रमिक मात्रा में नहीं खरीद पाता श्रमिकों की कार्यक्रमता में वृद्धि नहीं हो सकती श्रीर यह दुष्चक नहीं टुर सकता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय अभिक की मज़दूरी कम हैं। यद्यपि हाल में द्रान्यिक तथा वास्तिविक मज़दूरी में वृद्धि हुई है किन्तु इसके साथ भारतीय अम की खमता में वैसी वृद्धि नहीं हुई है। अम-मंत्रालय के अम-कार्यालय द्वारा १६५६ में फैक्ट्री की अर्जित आय सम्बन्धी प्रकाशित विवरण से निम्न रोचक निकर्ष निकलते हैं:—

१—भारत में फैक्ट्रों में काम करने वालों की कुल श्रकित श्राप (रेलवे वर्कशाप सम्मिलित नहीं है) १६४७ में १३७'३ करोड़ ६० थी जो १६५५ श्रीर १६५६ में बदकर क्रमश: २४५ करोड़ ६० २६६'५ करोड़ ६० हो गई। स्थायी उद्योगों में लगे तथा २०० ६० प्रति माह से कम पाने वाले व्यक्तियों की वार्षिक श्राय १६४७ में ७३७ ६० थी। १६५५ श्रीर १६५६ में बदकर यह क्रमश: १,१७४ ६० तथा १२१३ ६० हो गई।

र-१६४७ से १६५६ तक दस वर्षों में मारतीय उद्योगों में मनदूरों की वार्षिक श्राय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। चमड़ा उद्योग में ४% तथा सीमेन्ट उद्योग में १६३% हुई है। सम्पूर्ण देश की ध्यान में रखते हुये कहा जा सकता है कि प्रति मनदूर वार्षिक श्राय में ६३% की वृद्धि हुई है।

२—अम कार्यालय द्वारा प्रकाशित र्श्नांकड़े वास्तविक स्राय स्रथवा रहन-सहन के स्तर में कोई सुधार नहीं प्रकट करते। १६४७ से १६५६ के बीच में अभिक वर्ग से सम्बन्धित मूल्यों में २१% की वृद्धि हुई है तथा सामान्य मूल्य स्तर में ३१% की वृद्धि हुई है जब कि श्रीसत द्राव्यिक मजदूरी में ६२% की वृद्धि हुई है है। इससे रहन-सहन के स्तर में होने वाली वृद्धि का श्रानुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि द्राव्यिक एवम् वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है किन्तु मारतीय श्रम की उत्पादकता में उस श्रानुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

(v) जलवायु—श्रमिक की कार्यज्ञमता में कमी होने का एक महत्वपूर्ण कारण भारत की जलवायु है। वर्ण के अधिकांश भाग में न केवल श्रीद्योगिक श्रमिकों को वरन् सभी लोगों को श्रालस्य श्रीर शिथिवता घेरे रहती है। इससे किटन परिश्रम का काम एक प्रकार से श्रसंभव हो जाता है। ब्रिटिश तथा जापानी श्रमिक की श्रपेज्ञाकृत श्राधिक कार्यज्ञमता का एक कारण उन देशों की जलवायु भी है। मारत में भी विभिन्न ज्ञेत्रों के श्रमिकों की कार्यज्ञमता में जलवायु के श्रनुरूप श्रंतर है।

(vi) भारतीय उद्योगों द्वारा घटिया माल का उपयोग-मारतीय श्रीमक की कार्यचमता कम होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी हैं कि भारतीय उद्योग घटिया प्रकर के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कारखानों में पुरानी न्त्रोर घिसी दूटी मशीनें हैं, मिलों के नियोजन में दोव हैं स्त्रोर स्त्रीद्योगिक संगठम खराव है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मिल-मालिको पर है। यदि वह अच्छे मकार का कच्चा माल दें और कारखानों में श्रव्छी मर्शानें लगायें तो भारतीय श्रमिक की कार्यक्रमता बढ़ेगी और अमिक के प्रति घरटा उत्पादन की मात्रा भी पहले की श्रपेचा श्रिविक होगी। कारखानों में पुरानी मशीनों के स्थान पर श्राधुनिक मशीनों को लगा सकना वर्तमान में संभव नहीं हो सका क्योंकि (१) इसके लिए श्रावश्यक वित्त का श्रभाव है, (२) मशीनों इत्यादि श्रीर टेकनिकल सामान का उपलब्ध हो एकना कठिन है, (३) भारतीय मिल-मालिक आधुनिक मशीनों के लाम से श्रवरिचित हैं और (४) कारखानों के युक्तिकरण का श्रमिकों द्वारा विरोध कियां जाता है। मारतीय श्रमिक मशीनों के युक्तिकरण का श्रीर पुरानी विधी मशीनों को बदलने का तीम विरोध करता है। श्रीमकों का कहना है कि इससे बेरोजगारी होती है। भारतीय अभिक की कार्यज्ञमता कम है क्योंकि कारखानी की मशीनें पुरानी श्रीर विसी-पिटी हैं इसलिए जब अमिक इन मशीनों को बदलने का विरोध करता है तब वास्तव में वह अपनी कार्यक्षमता में सुधार को रोकता है। युक्तिकरण के श्रद्याय में नताया गया है कि मशीनों के युक्तिकरण से वेरोजगारी फैलना श्रावश्यक नहीं है, यदि वेरोजगारी फैलती है तो समी लोगों की तरह श्रीमकों को भी प्रगति के लिए यह कच्ट फेलना ही पहेगा। यदि मशीनों में मुधार होने से वेरोनगारो फैलती है और श्रिमकों की कुछ ज्ञित होती है तो दीर्घ काल में श्रिमक की कार्यज्ञमता में वृद्धि होने से श्रीर श्रिमक पारिश्रिमक मिलने से यह हानि लाभ में बदल जाती है।

श्रीमक की कार्यचमता की कमी बहुत कुछ उसकी भानसिक स्थिति पर निर्भर करवी है। कार्यचमता में कमी होने के सभी कारणों में प्रमुख यह है कि मारतीय श्रीमक विलास प्रिय है श्रीर उसमें श्रनुशासन का श्रभाव होता है। जब तक श्रीमक श्रपने उत्तरदायित्व को नहीं सममता श्रीर जब तक मिल-मालिक के श्रीर श्रपने हितों को समान नहीं सममता तब तक वह श्रपनी पूर्ण योग्यता एवम् चमता से कार्य नहीं करता है। उत्पादन शक्ति रखते हुए भी श्रपनी कार्यचमता में कभी बनाये रहता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद श्रमिकों की विचार घारा में पहले की श्रपेना श्रीर खुराई श्रा गई है। श्रमिकों ने कारखानों में काम घीरे करने की नीति श्रपना ली है जिसका श्रर्थ यह है कि कार्य करने के लिए निर्धारित समय में श्रमिक उचित परिश्रम करने के स्थान पर कार्य श्रत्यन्त घीरे-धीरे करके श्रपना समय नच्य करता है। श्रमिक द्वारा 'काम धीरे-घीरे करो' नीति श्रपनान का एक कारण मालिकों को श्रपनी माँगें मानने के लिए मजबूर करना है। परन्तु इस उद्देश्य के पूरे होने के स्थान पर इसके विपरीत उत्पादन कम हो गया है श्रीर इससे उसकी स्थिति श्रीर भी विगइ गई है।

भारतीय श्रमिकों में श्रनुशासन के श्रभाव को गत कुछ वर्षों में (१) उत्पादन के श्राधार पर नहीं बल्कि केवल उपस्थित के श्राधार पर महार्ग मत्ता, वोनस हत्यादि देने से बढ़ावा मिला है। महगाई मत्ते को श्रमिक के रहन-सहन के व्यय में सम्मिलित कर दिया गया है। श्रमिक चाहे श्रपना कार्य पूर्ण करे या न करे उसे महगाई मत्ता मूल्य के देशनाँकों के श्रनुक्ल श्रवश्य मिलता है। इस कारण श्रमिक श्रपने उत्पादन श्रयवा श्रपने कार्य की किंचित् मात्र मी चिन्ता नहीं करता है। यदि महगाई भन्ते को उत्पादन पर श्राधारित कर दिया जाता तो श्रमिक ऐसा नहीं करता। साथ ही निर्धारित मात्रा से श्रमिक उत्पादन करने पर श्रमिक का बोनस श्रीर महगाई भन्ता बढ़ता श्रीर उत्पादन बढ़ता; (२) इन्हस्ट्रियल हिस्प्यूट्स एक्ट के पास होने के पहिले तक श्रीद्योगिक कारसों पर समकौते श्रीर पन्वनिर्णय प्रणाली के श्रन्तर्गत उद्योग श्रयवा कारखाने के मालिक को श्रपने कर्मचारी को निकालने का श्रिकार नहीं था, चाहे कर्मचारी श्रकुराल हो या काम लापरवाही से करता हुआ पाया गया हो। ऐसे मामलों में नौकरी से श्रलग करने का निर्णय समकौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, या श्रीद्योगिक न्यायालय करते करने का निर्णय समकौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, या श्रीद्योगिक न्यायालय करते

अध्याय ३१

ख्रौद्योगिक सम्बंध

श्रीद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, श्रमिकों की श्रार्थिक स्थित को सुघारने श्रौर देश को श्रार्थिक हिष्ट से समृद्धशाली बनाने के लिये श्रीद्योगिक शांति का श्रत्यन्त महत्व है। यदि इइतालें होती हैं, मिलों-कारखानों में तालाबन्दी की जाती है श्रौर श्रीद्योगिक शांति मंग की जाती है तो उत्पादन घटने लगता है, उत्पादन व्यय में वृद्धि होने लगती है श्रौर श्राय कम हो जाने से श्रमिकों को श्रनेक किठिनाह्यों का सामना करना पहला है। बाजार में वस्तुश्रों की पूर्ति नियमित रूप से न होने या उनकी पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा श्रा जाने से उपभोक्ताश्रों को भी किठनाह्यों का सामना करना पहला है। श्रीद्योगिक चेत्र में श्रशांति होने से सम्पूर्ण देश की शांति मंग हो जाती है श्रीर इससे किसी को लाम नहीं होता। पूँजीवादी व्यवस्था में तालाबंदी का होना श्रावश्यक नहीं है। यदि उचित ध्यान रखा जाय श्रीर व्यवस्था ठीक हो तो इन बाधाश्रों को पूरी तरह समात न भी किया जा सके तो कम से कम टाला श्रवश्य जा सकता है।

श्राधुनिक प्रवृत्तियाँ—भारत के श्रीद्योगिक चेत्र में शांति बनाये रखना सदैव संभव नहीं रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में श्रीद्योगिक सगड़ों की संख्या स्त्रीर इन क्ताइों के कारण नष्ट हुए कार्य के दिनों की संख्या काफी कम रही है। आँकड़ों से प्रकट होता है कि १९४३ में जब कि युद्ध अपनी चरम सीमा पर या हड़ताल एवम तालाबन्दियों से केवल २३ लाख कार्य के दिन नष्ट हुए। १६४४ में यह संख्या बढ़कर ३४ लाख दिन और १६४५ में ४१ लाख दिन हो गई। यह संख्या फिर भी अपेज्ञाकृत कम रही; इसकी अत्यंधिक नहीं कहा जा सकता है। युद्ध के समय श्रीयोगिक सम्बन्ध काफी श्रान्छे रहे क्योंकि (१) श्रमिक ने सरकार को लड़ाई में सहयोग देने का वचन दिया और वह यह नहीं चाहते ये कि उत्पादन में किसी प्रकार की बाघा पड़े और युद्ध का सफल संचालन कर सकने में किसी प्रकार की बाघा पहें। (२) उस समय वस्तुत्रों के माव में तथा रहन-सहन के न्यय में वृद्धि की समस्या उत्पंत्र नहीं हुई थी। इसी समस्या से ही बाद में श्रौद्योगिक मगड़े उत्पन्न हुए। १९ श्रगस्त १९३९ को समाप्त होनेवाले सप्ताह को श्राघार मानते हुए १६४१-४२ श्रीर बाद के चार वर्षों में सामान्य मूल्य के देशनीक कमशः १३७ ०, १७१ ०, १३६ ५ २४४ २ और २४४ १ रहे। वस्तुत्रों के मूल्यों में बृद्धि हो गई थी परन्तु इसी समय वेतन में भी त्राशिक वृद्धि हो गई थी। इससे मालिक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध विशेष खराव नहीं हुए; (३) युद्ध के समय भारतीय प्रतिरह्मा नियम की घारा ८१-ए लागू थी जिसके श्रमुसार श्रीद्योगिक कगड़ों का निपटारा करने के लिए सरकार को संकट कालीन श्रिधकार दिये गये थे। सरकार श्रशांति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने को स्वतंत्र थी।

परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही, ज्रीर विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् श्रांबोगिक कगड़ों की संख्या बढ़ी श्रीर उत्पादन में कमी श्रा गई। १६४६ श्रीर १६४७ में कमश: १ करोड़ २७ लाख श्रीर १ करोड़ ६⊏ लाख कार्य के दिन नष्ट हो गये जब कि १६४५ में केवल ४१ लाखकार्य के दिन नष्ट हुए । श्रीद्योगिक मताड़ों में इतनी वृद्धि होने का कारण यह था कि (ग्र) स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् अभिक के दिल में नई आशाएँ नगी थीं। अभिक अपनी आर्थिक स्यिति को मुवारना चाइते ये और इसी के परिणाम स्वरूप इइतालें हुई। सरकार की अम नीति ने भी जिसका उद्देश्य अभिकों का पारिश्रमिक बढ़ाना और कार्य की स्यिति में सुघार करना था, इसमें काफी योगदान दिया, (व) युद्ध काल की अपेक्ष चीजों के भाव में श्रिधिक वृद्धि हुई। १६४५-४६ में योक विकी के भाव का देशनांक २४४'६ या परन्तु १६४६-४७ में बढ़ कर २७५'४ श्रीर १६४७-४८ में ३०७ हो गया। वस्तुश्रों के मृत्यों में तो वृद्धि हुई परन्तु वेतन श्रथवा पारिश्रमिक में इसी श्रनुपात में वृद्धि नहीं हुई। इससे श्रमिक को श्रमेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । परिणामस्वरूप श्रमिकों ने वेतन ग्रयवा पारिश्रमिक बढ़वाने के लिए इड़तालें कीं; (स) मारतीय प्रतिरज्ञा नियम के लागून रहने से शमिकों ने एक छूट का श्रतुमव किया। श्रव श्रमिकों की इच्छा भी युद्ध के समय की तरह कटोर परिश्रम करके उत्पादन बढाने की नहीं रही थी।

स्थिति काफी गंभीर रूप घारण करती गई और १६४० के दिसम्बर में मारत सरकार को श्रीद्यांगिक शांति समफीता कराने के लिए इस्तेज्य करना पड़ा। इससे भारत में श्रीद्योगिक सम्बन्ध सुधारने में काफी सहायता मिली। श्रामक के श्रान्दोलन श्रीर सरकार के इस्ताज्य करने से पारिश्रमिक में वृद्धि हुई; महगाई भत्ता, बोनस श्रीर लाभांश में श्रीमकों के माग में भी वृद्धि हुई। यह कहा गया कि द्रव्य में श्रीमक का पारिश्रमिक बढ़ने से श्रीमक का वास्तविक पारिश्रमिक नहीं बढ़ा श्रीर यदि रुपये को क्रय शक्ति की हिंदि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि श्रीमकों की स्थिति युद्ध से पूर्व के वर्षों की श्रोमं कहीं श्रीधक विगढ़ गई। इस तर्क में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि मूल्य बढ़ जाने से केवल श्रमिक को ही नहीं बल्क सभी वर्गों की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

परन यह नहीं है कि अमिक को कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा या नहीं; वास्तव में विचारणीय बात यह है कि क्या श्रामिकों को समाज के श्रन्य लोगों की अपेचा अधिक कष्ट सहने पढ़े ? यद्यपि अमिकों के कुछ वर्ग ने अधिक वेतन श्रयवा पारिश्रमिक की माँग करते हुए श्रान्दोलन जारी रखा परन्तु जहाँ तक पूरे अमिक वर्ग का प्रश्न है वह एन्तुष्ट रहा और इड़तालों की संख्या भी घट गई। मिल मालिकों ने तालाइन्दी घोषित नहीं की क्योंकि पारिश्रमिक में वृद्धि होने के साथ ही उत्पादित माल के मूल्य में भी वृद्धि हुई श्रीर बाजार विकेता के श्रनुकुल दढ होने के कारण मिल-मालिकों को अधिक हानि नहीं उठानी पड़ी। इसके साथ ही श्रीबोगिक मगड़े सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत मगड़े सलमानेवाली रंस्या क्रमशः अधिक प्रमावशाली बनाई गई और समसीते तथा श्रानिवार्य पंचिनिर्णय के द्वारा श्रानेक होने वाले श्रीहोगिक मगहों को जो श्रवश्य उत्पन्न होते रोक लिया गया। १६५० में कुल नष्ट हुए श्रम-दिनों की संख्या १२८. १ लाख हो गई परन्तु इसका कारण सर्वत्र श्रीद्योगिक सम्बन्धों का विगड़ना नहीं विक सूती मिल उद्योग की लम्बी इइताल थी। कुल नष्ट हुए १२८ १ लाख दिनों में से १३ लांख दिन अकेले सूती उद्योग में ही नष्ट हुए । श्रीद्योगिक सममौते के पश्चात् से मारंत में श्रीद्योगिक शांति श्रधिक मंग नहीं हुई है श्रीर उक्त तालिका के अनुसार नष्ट हुये अम-दिनों की संख्या घटकर १९५१ में ३८ र लाख, १६५२ में ३३ ४ लाख, १६५३ में ३३ ८ लाख और १६५४ में ३७ २ लाख हो गई। १६५६ में ६६ ह लाख अम-दिन नष्ट हुये। श्रीद्योगिक मताङ्गें की संख्या १,२०३ तथा उनसे सम्बन्धित श्रामको की संख्या ७१५,१३० थी। १६५७ में ६४ लाख अमिदन नच्ट हुये तथा श्रीद्योगिक म्हगड़ों की संख्या २,०५६ तथा उनसे सम्बन्धित अमकों की संख्या १,०१८,६२५ थी। नष्ट हुये ६४ लाख अम-दिनों में स्ती वस्र उद्योग में १५ लाख दिन, कोयला तथा अन्य खदान उद्योगों में लगभग १० लाख, रोपण तथा जूट उद्योग में लगभग ५ लाख अस दिन नष्ट हुये।

कानूनी व्यवस्था—एक जनतंत्रवादी देश में जहाँ उद्योग स्वतंत्र है श्रपनो मौंग के श्रनुसार उचित वेतन श्रथवा पारिश्रमिक न मिलने पर श्रमिक को अन्य उपाय असफल रहने के परचात् श्रंत में हड़ताल करने का श्रांघकार है श्रीर यदि मालिक श्रमिकों के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हो तो उसे भी तालावन्दी घोषित करने का पूर्ण श्रांघकार है। यद्यपि जनतंत्री शासन व्यवस्था में यह श्रिषकार निहित हैं किर भी बिना सार्वजनिक हित पर विचार किये इन श्रिषकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। हड़ताल होने से या तालावन्दी घोषित की जाने से उपभोक्ता को भी श्रमेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। श्रमिक तथा मिल

मालिकों द्वारा कमशः इड़वाल श्रीर तालाबन्दी के श्रपने मूलभूव श्रिषकारों के प्रयोग के प्रति जनता श्रीर एरकार उदाधीन नहीं रह सकते। उचित रीति से समक्तीता वार्चा चलाने श्रीर एक दूसरे की कठिनाइयों को समक्ते हुए श्रीद्योगिक क्षगड़े को सुलकाना सदैव संभव है। श्रीद्योगिक क्षगड़े सम्बन्धी कानून का उद्देश्य यह है कि क्षगड़ा होने पर मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच समक्तीता करने के लिए साधन खोजा जाय। इस कानून में विभिन्न परिस्थितियों के श्रमुक्ल भिन्न-भिन्न साधनों की व्यवस्था की गई है श्रीर किसी भी श्रीद्योगिक क्षगड़े में समक्तीते तथा पंचनिर्णय में जितना समय लगना चाहिए उसकी श्रविध भी निश्चित कर दी गयी है। इसमें मामले पर विचार करने की पूर्ण विधि विस्तार से दी गई है। भारत तथा संसार के श्रनेक देशों में यह देखा गया है कि कार्य की श्रस्पष्ट रूपरेखा के कारण श्रम उत्पन्न हो जाता श्रीर इससे श्रीद्योगिक मतमेद हो जाता है। श्रम कानून का यह उद्देश्य है कि इस प्रकार के श्रमों को उत्पन्न हो जाता है। श्रम कानून का यह उद्देश्य है कि इस प्रकार के श्रमों को उत्पन्न हो ने ते रोका जाय श्रीर यदि श्रम उत्पन्न हो गया है तो उसे दूर किया जाय।

१६२६ का भारतीय व्यापारिक विप्रह कानून-इस कानून में सार्व-जनिक उपयोगिता की सेवाओं तथा श्रन्य उद्योगों के लिए पृथक व्यवस्था की गई थी। सार्वजनिक उपयोगिता सेवार्ये जैसे रेलवे डाक तथा तार, विजली श्रीर जल पूर्ति विभाग के कर्मचारियों तथा मंगियों इत्यादि की इड़तालों पर प्रतिक्र लगाया गया था। ये कर्मचारी मालिक को १४ दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात् ही हड़ताल कर सकते ये। अन्य उद्योगों में हड़ताल अयवा तालावन्दी को घोषित किया ना सकता था परन्तु इन मगड़ों को सुलमाने के लिए एक निश्चित साधन नियुक्त किया गया था। श्रीद्योगिक मगड़ों के सम्बन्ध में तदर्थ जाँच समिति श्रीर सममौता परिपद नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई थी। जाँच समिति में एक या एक से श्रधिक निष्पद्य व्यक्ति रखे नायँगे। यह समिति मामले की नाँच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट नियुक्त करने वाली सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। समसीता परिषद् इस बात का प्रयत्न करेगी कि दोनों पत्त साथ बैठकर श्रपने मतमेदों को दूर करके सममौता कर लें। सममौता न हो सकने पर मामले की रिपोर्ट सरकार के पास मेज दी जाती थी। इस कानून में श्रनिवार्य पंचिनिर्णय की न्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अनुसार सरकार ने केवल यही प्रयत्न किया कि दोनों पद्म एक दूसरे के श्रीर अधिक निकट श्रा जाएँ श्रीर मामले तथा उस मगड़े के कारणों को जनता को बतावे जिससे सममौता करने के लिए जनता की राय का भी बल प्राप्त हो। जनहित की सुरज्ञा के लिए कानून की टब्टि में वे हड़तालें श्रौर तालावित्याँ गैर कानूनी थो (क) जिनका उद्देश्य उद्योग के श्रन्दर का प्रसार करने के श्रातिरिक्त कुछ और मी हो या (ल) जिनका उद्देश्य जनता पर अनेक कठिनाइयाँ लादकर सरकार को विशेष कार्यवाही करने को मजबूर करना हो।

यह कानून उपयुक्त खिद्ध नहीं हुआ। श्रीद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि (१) समकौता श्राधिकारी श्राधिका कानिक जींच को श्राधिक महत्व दिया गया श्रीर (२) स्याई श्रीद्योगिक न्यायालय की स्थापना के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई।

बम्बई में १६३४, १६३८ ग्रीर १९४६ में श्रीयोगिक विग्रह कानून बनाकर उक्त कानून के दोपों को कुछ छीमा तक दूर कर दिया गया। इन कानूनों के श्रन्तर्गत मालिको द्वारा अमिक संघों को मान्यता दी जाने की व्यवस्था की गई थी। इन कान्नों में फगड़ों को सलकाने की पूरी विधि श्रोर निश्चित श्रविध दी गई थी। केवल सार्वजनिक जाँच करने की अपेद्धा समकौते और कगड़ा सलकाने पर श्राधिक मुमहत्व दिया गया। इस वात का विशेष ध्यान रखा गया कि कार्य की शतें ग्रस्पच्ट ग्रीर ग्रानिश्चित न हो क्योंकि इससे मागड़े उत्पन्न होते हैं। इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि सममीते की शतें और स्थायी सभायें लिखित श्रीर रजिस्टर्ड हो । अन्य प्रभावशासी छाधनों के साथ ही स्थायी श्रीद्योगिक न्यायालय का विकास हुआ है। पहले के कानूनों में न्याय का मानना अनिवार्य नहीं था परन्तु हङ्ताल अथवा ताले-बन्दी से पूर्व सम्पूर्ण मामले शांतिपूर्ण उपाय से सुलकाने के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक थे। परन्तु बम्बई के १६४६ के कांन्रन में पंचिनिर्ण्य के लिए मामला प्रस्तुत करना ऋनिवार्य कर दिया गया और ऋपील करने के लिए एक अदालत की व्यवस्था की गई। वास्तव में वस्वई ने इन कानुनों का बनाकर सविष्य में अखिल भारतीय पैमाने पर अधिक उपयुक्त कानन बनाने के लिए मार्ग दर्शाया।

भारतीय प्रतिरत्ता नियम के श्रान्तर्गत कार्यवाही—पहले कहा जा चुका है कि युद्ध काल में श्रीद्योगिक कगड़ों को हल करने के लिए सरकार ने सक्कट कालीन श्रीधकार प्राप्त कर लिये थे। मरतीय प्रतिरत्ता नियम की घारा दृश्य (ए) के श्रान्तर्गत, जो जनवरी १९४२ में लागू की गयी थी, यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत की प्रतिरत्ता के लिए, सार्वजनिक सुरत्ता के लिये, शांति श्रीर व्यवस्था जनाये रत्त्वने के लिये युद्ध का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिये समुदाय के जीवन के लिये श्रावश्यक सामान की पूर्वि जारी रत्नने के लिये सामान्य श्रथवा विशेष श्रादेश द्वारा केन्द्रीय सरकार तालावन्द्री तथा हड़वाल पर रोक

लगा सकती है श्रीर श्रीद्योगिक सगड़ों को समसौते या श्रदालती कार्यवाही के लिये मेज सकती है श्रीर श्रदालत के निर्णय को लागू कर सकती है। इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई थी कि इझ्ताल श्रथवा तालवन्टी की पहले से स्वना दी जाय। समसीते की कार्यवाही की श्रविध में इझ्ताल श्रथवा तालेवन्दी पर रोक लगा दी गई थी। क्योंकि सरकार को श्रदालती निर्णय श्रनिवार्य रूप से लागू कर देने का श्रिवकार प्राप्त था इसलिये इम कह सकते हैं कि इस नियम के द्वारा पंचनिर्णय श्रनिवार्य कर दिया गया था।

१६४७ का श्रोद्योगिक विग्रह कानून — फरवरी १६४७ में केन्द्रीय सरकार ने श्रोद्योगिक विग्रह कानून स्वीकृत किया। इस कानून ने वस्वई के श्रानुभव का लाम उठाकर १६२६ के श्रोद्योगिक विग्रह कानून के कुछ दोषों को दूर कर दिया। इस कानून में कार्य समिति, सममौता श्राधकारी, सममौता बोर्ड श्रीर जाँच-श्रदालत नियुक्त करने की व्यवस्था है। इनके श्रातिरिक्त इस कानून में श्रस्थायी श्रीद्यागिक न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें उच न्यायालय के न्यायालय होंगे। इस कानून में परस्पर सममौता करने पर श्रिषक महत्व दिया गया है। पहले कानून में केवल जाँच कार्य को ही महत्व दिया गया था। कार्य समितियों का कार्य परस्पर वातचीत करके मालिक तथा कर्मचारी के बीच का मतमेत दूर करने श्रीर सममौता पदाधिकारियों तथा सममौता बोर्डों का कार्य दोनों पत्तों में सममौता कराना है। परन्तु यदि यह प्रयत्न सफल न हो तो मामले को श्रोद्योगिक न्यायालय में प्रस्तृत करने की व्यवस्था की गई है। सरकार को इन न्यायालयों का न्याय पूर्ण या श्रांशिक रूप में लागू करने का श्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार इस कानून में भी श्रानिवार्य पंचनिर्णय की व्यवस्था है।

१६५१ में श्रीद्योगिक विग्रह (संशोधन) श्रध्यादेश जारी करके इस कार्त की कुछ किमयों को दूर कर दिया गया। इस श्रध्यादेश के द्वारा वे श्रीद्योगिक इकाइयाँ भी श्रदालती कार्यवाही के चेत्र में श्रा गई जिनमें श्रव तक कोई मगहा नहीं हुश्रा था परन्तु मिविष्य में होने की संभावना थी। भिविष्य में एक ही बात पर श्रन्य श्रीद्योगिक इकाइयों में मगइा न होने देने के लिए यह श्रध्यादेश श्रावश्यक समक्ता गया। १६५० के श्रीद्योगिक विग्रह (अम श्रपील न्यायालय) कानून से अम श्रपील न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें विभिन्नों श्रीद्योगिक पंच न्यायालयों, श्रीद्योगिक श्रदालतों, वेतन परिषदों इत्यादि के फैसले पर की गई श्रपीलों की सुनवाई होगी। अम श्रपील न्यायालय के किसी श्रदालत फैसले श्रयवा निश्चय के विरुद्ध की गई श्रपीलों पर विचार करने का श्रपिकार है परन्तु इसकी दो शर्ते हैं: (१) फैसले श्रयवा निश्चय में कोई विशेष कानूनी पेंच

या (२) उसका एंबन्य वेतन, बोनस, छट्नी इत्यादि से हो। विभिन्न राज्यों में द्योगिक न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी फैसले दिये जाने के कारण जिससे देश श्रीद्योगिक संबन्ध श्रधिक जटिल होते जाते थे श्रम श्रपील न्यायालय स्थापित :ने की त्रावश्यकता अनुभव हुई | इसके साथ ही श्रापील करने के लिए कोई वस्था न होने के कारण यह ग्रीबोगिक ग्रदालतें उदार निरंकुश शासक की ह त्राचरण करने लगी थीं। इस प्रकार की निरंकुशता और स्वच्छन्दता जन-गी शासन प्रणाली के अनुकृत नहीं है। मूल कानून की ३३ वीं घारा में यह वस्या की गई थी कि सममीते के लिए किसा भी मागड़े के विचाराधीन होने के ल में कोई मालिक समझौता अधिकारी, बोर्ड अथवा पंचन्यायालय की लिखित तुमति प्राप्त किये विनान किसी कर्मचारी की दरह दे सकता है श्रीर न काल सकता है; साथ ही मामला प्रस्तुत, होने के ठीक पहले की नौकरी की लत में वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस घारा की वस्थाओं को धारा ३३ (ए) जोड़कर श्रीर बढ़ा दिया गया है। घारा ३३ (ए) में ह व्यवस्था की गई है कि यदि मालिक धारा को मंग करता है तो उससे पीड़ित र्भवारी विधियत लिखित रूप में अपनी शिकायत उस पंच अदालत के सामने त कर सकता है जिसमें मामला विचाराधीन है। वह पंचश्रदालत उस शिकायत उसी रूप में विचार करेगी जैसे वह कानून की व्यवस्था के अनुसार पंच दालत में पेश किया गया श्रीद्योगिक मगड़ा हो। इस संशोधन के अनुसार हित कर्मचारी को मामले के विचाराधीन होने के काल में नौकरी की हालत में रिवर्तन, छुरनी, दराह इत्यादि के मामलों को सीचे पंचन्यायालय में विचारार्थ स्तुत कर सकने का अधिकार प्राप्त है। इससे पंचन्यायालय में प्रस्तुत होनेवाले गड़ों की संख्या भी ऋधिक बढ़ने से बच जायगी श्रीर निर्णय भी शीघ हो जायगा।

श्री बी० वी० गिरि का दृष्टिको ग्रा — भारत के श्रम-मंत्री श्री गिरि ने क्टूबर १६५२ में नैनीताल में हुए भारतीय श्रम-सम्मेलन के १२ वें श्री विश्व मं , फरवरी १६५३ में नई दिल्ली में हुए राज्य श्रम-मंत्री सम्मेलन में श्रीर श्रनेक । विजनिक भाषणों में बराबर इस बात पर जोर दिया है कि श्री द्योगिक कगड़ों ने वर्तमान व्यवस्था के श्रमुसार श्रमिवार्य पंचिनर्ण्य के द्वारा नहीं बिल्क परस्पर । मक्तीता करके स्वेच्छिक पंचिनर्ण्य से हल करना चाहिए। इस योजना के श्रम्तरांत सार्वजनिक उपयोग सेवाश्रों के संबन्ध में श्रमिवार्य पंचिनर्ण्य लागू होगा परन्तु श्रम्य संस्थाश्रों या उद्योगों में समक्तीता श्रथवा स्वेच्छिक पंचनेर्ण्य लागू रहेगा। परन्तु संकटकाल में श्रीर केन्द्रीय सरकार से पहले विचार वेमशं कर लेने के बाद राज्य सरकारों को श्री द्योगिक मामला श्रमिवार्य पंच-

निर्णय के लिए सौपने का अधिकार होगा। श्री गिरिका मत था कि श्रम अपील न्यायालय को समाप्त कर दिया जाय क्यों कि मागड़ों को आपस में सुलमा लेने के पश्चात् इस न्यायालय की कोई त्रावश्यकता नहीं रह जाती। श्री गिरि द्वारा सुकाई गई योजना के अन्तर्गत मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच के सभी कगड़ों पर स्वेच्छा से समकीता करना होगा। समकीता वार्चा के संबन्ध में मराडे से संबन्धित कोई भी पत्त सममीता ऋधिकारी की सहायता लेने को स्वतंत्र होगा श्रीर दूसरे पच को यह स्वीकार करना पहेगा। यदि इस प्रकार की सममौता वार्चा असफल हो जाती है और दोनों पन मामले को पंचित्रर्णय के लिए सींपने को प्रस्तुत हों तो पंचों का निर्णय दोनों पह्यों को मानना पड़ेगा। यदि पंच परस्पर सहमत नहीं हों तो माने से संबन्धित पार्टियाँ एक निर्णायक छाँट सकती हैं जिसका फैसला दोनो पत्तों को मान्य होगा। यदि दोनों पार्टियों में निर्णायक छाँउने के प्रश्न पर मतमेद हो तो वह दोनों एक राय से मामला पंच ग्रदालत को सींप सकते हैं। समकीते की इन विभिन्न स्थितियों के लिए ग्रंविध निश्चित होगी। राज्य सरकारें केवल संकट काल में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर गैर सार्वजनिक उपयोग के उद्योगों के मामलों को अनिवार्य पंच-निर्ण्य के लिए धींप सकती हैं। परन्तु यह अधिकार अन्य उद्योगी पर लागू नहीं होगा । गिरि-योजना के अन्तर्गत अमिक समितियाँ, समकीता अधिकारी, समकीता बोर्ड, श्रौद्योगिक न्यायालय श्रौर पंच श्रदालत पूर्ववत रहेंगी परन्त क्षम श्रपील-न्यायालय खत्म हो जायगा।

इससे दो मुख्य प्रश्न उठते हैं: (१) क्या श्रनिवार्य पंचितर्णय हो या स्वैन्छिक पंचितर्णय श्रीर (२) क्या श्रम श्रपील न्यायालय रहना चाहिए या नहीं?

अनिवार्य पंचित्रायं —यह कहा जाता है कि अनिवार्य पंचित्रायं श्रीयोगिक छेत्र में शान्ति बनाए रखने में सहायक नहीं है। स्थायी तौर पर शान्ति तभी रह सकती है जब परस्पर श्रीर स्वैच्छिक समीते किये जायें। यह भी बताया गया है कि श्रनिवार्य पंचित्रायं से श्रीयोगिक समाहों को प्रोत्साहन मिला है श्रीर भारत में इससे श्रीमक संव कमजोर हो गए हैं। "श्रीमक संव की व्यवस्था पर इससे कुठारायात होता है। श्रीमक संव के सदस्यों में एकता निजी स्वार्य का ही परिणाम है। यदि श्रीमकों की समझ में यह श्रा जाय कि एकता के सूत्र में वँघ जाने से ही उनके स्वार्थ की सिद्ध हो सकती है तो उनके संयुक्त होने के लिये श्रन्य किसी प्रेरणा की श्रावश्यकता नहीं रह जाती। श्रीनवार्य पंचित्रायं उनको इस बात के लिये कोई कारण नहीं उपस्थित करता कि उनमें इस प्रकार की एकता हो"। श्रीनवार्य पंचित्रायं, श्रायंक व्यवस्था को एक ऐसी कठोरता

प्रदान करता है जिससे अन्तर्राम्द्रीय बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के लिये बहुत कठिनाई उपस्थित हो जाती है।

परन्तु श्रनिवार्य पंचनिर्णय का समर्थन भी किया गया है। कहा गया है कि श्राधिक हिन्द से कम विकसित देश में श्रीद्योगिक कगड़ों के कारण यदि उत्पादन रक जाता हैं तो इससे राष्ट्र के हितों की हानि होने की संभावना है। उत्पादन में गिरावट रोकने के लिए श्रीर परिशामतः राष्ट्रीय श्राय कम न होने देने के लिए श्रनिवार्य पंचनिर्णय को लागू किया जाना चाहिए। पंचनिर्णय की सफलता के लिए यह श्रावश्यक है कि (१) मालिकों तथा श्रमिकों के कुशल संगठन हों श्रीर (२) समकीते की कार्यवाही में उत्तरदाशित्व समक्तने वाले श्रमुमंवी नेताश्रों को भाग लेने दिया जाय। चूँकि भारत में श्रमिक संगठन श्रव भी बहुत कमजोर हैं, श्रीर समकीते तथा पंचनिर्णय के लिए निष्पन्न व्यक्तियों का श्रमाव है इसलिए यह संभव है कि स्वैच्छिक पंचनिर्णय से सन्तोषजनक परिशाम न निकले।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर इम इस परिणाम पर पहुँचते है कि यद्यपि सार्वजनिक उपयोग के उद्योगों के लिए श्रनिवार्य पंचिनिर्णय श्रावश्यक है श्रीर संकट काल में भी यह लाभदायक साधन सिद हो सकता है परन्तु श्रीचोगिक कगड़ों को सुकक्ताने का यह सन्तोषजनक दंग नहीं है। इससे प्रायः श्रीचोगिक कगड़ों उत्पन्न होते रहते हैं, श्रमिक संगठन कमजोर होते जाते हैं श्रीर देश की श्रार्थिक व्यवस्था कठोर होने लगती है।

परन्तु श्री गिरि का श्रापील न्यायालय को समाप्त कर देने का सुक्ताव पूर्णत्या सत्य नहीं है। देश के विभिन्न भागों में समान श्रम स्थिति उत्पन्न करने में अपील न्यायालय विशेष सहायक रहा है। वेतन, बोनस, कार्य की स्थिति इत्यादि प्रश्नों पर अपील न्यायालय के फैसलों से श्रीशोगिक पंच श्रदालतों को काफी लाभ पहुँचा है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि परस्पर समक्तीता करके या स्वेन्छिक पंचित्रिया द्वारा मामला तय करके ऐसी स्थिति श्रा सकती है कि भविष्य में अपील न्यायालय की श्रावश्यकता न रहे परन्तु जब तक श्रीशोगिक पंच-श्रदालत हैं तब तक देश के विभिन्न भागों में श्रम सम्बन्धी समान स्थिति लाने श्रीर विभिन्न उद्योगों में भी एकरूपता लाने के लिए श्रपील न्यायालयों को समाप्त न किया जाय।

१९४६ का श्रीशोगिक विश्वह कानून—एक बिल श्रीमकों के सम्बन्ध विषयक संसद में १९५० में रक्खा गया, पर उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी, क्योंकि मिल मालिकों श्रीर श्रीमकों के नेताश्रों ने उसका बहुत विरोध किया। १६५५ के सितम्बर में पुनर्परीचित रूप में एक विषेयक १६४७ के श्रौद्योगिक विग्रह कानून का संशोधन करने के लिये लोक समा में प्रस्तुत किया गया श्रीर : १६५६ में श्रौद्योगिक विग्रह (संशोधन तथा विभिन्न शर्तों के साथ) कानून पास किया गया । यह वहें दुर्भाग्य की बात है कि इस कानून में श्री गिरि के विचारों को बहुत ही सीमित मात्रा में सिमालित किया गया है । ऐसा लगता है कि उसने श्रोद्योगिक कानूनों में विस्तार होगा श्रीर समकीता कठिन होगा । इस कानून के मुख्य प्रविधान, जो कि बम्बई के १६४७ के कानून के श्रानुरूप हैं, विम्त हैं :—

- (१) श्रामिकों की परिभाषा विस्तृत कर दो गई है, श्रीर श्रव श्रीयोगिक । कर्मचारी तथा देख रेख करने वाले पदाधिकारी भी जिनका वेतन ५००) मालिक से श्रिवक नहीं है श्रिमकों के श्रन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये हैं। क्योंकि बहुत से इस प्रकार का कार्य करने वालों को गोपनीय श्रीर संगठन सम्बन्धी कार्य दिया गया है श्रीर वे श्रमिकों की अपेका मालिकों के हो विशेष श्रंग हैं, इससे यह भय है कि मालिकों को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
- (२) १६५० के श्रौद्योगिक विग्रह (श्रपील न्यायालय) कानून का प्रत्यानयन कर दिया गया है श्रौर श्रमिकों के श्रपील न्यायालय को समाप्त कर दिया गया है। इस न्यायालय के कारण देश के विभिन्न माग में श्रमिकों की स्थित में समानता, श्रा गई थी श्रौर इसने श्रनेकों ऐसे लाभदायक सामान्य नियम बना दिये ये जिनके विखन्डन से भविष्य में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसते हम केवल एक ही श्रच्छाई की श्राशा कर सकते हैं कि श्रपील न्यायालय के श्रभाव में सम्भवतः मालिकों श्रीर श्रमिकों को स्थिति की वास्तविकता पर विचार करने की प्रेरणा मिले।
- (३) इस कानून के अनुसार तीन प्रकार के मीलिक न्यायालय बनेंगे।
 (अ) अम न्यायालय, (३) औद्योगिक न्यायालय और (स) राष्ट्रीय न्यायालय। अम न्यायालयों को ऐसे औद्योगिक मगड़ों के निर्णय करने का अधिकार है जो मालिकों की ऐसी आशाओं के सम्बन्ध में उत्पन्न हुये हैं जिनका औदित्य तथा नियमानुक्-लता संदिग्ध है और जो स्पायी आशाओं के अन्तर्गत है तथा कर्मचारियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में और इस्ताल अथवा तालाबन्दी के सम्बन्ध में हैं। औद्योगिक न्यायालय ऐसे मगड़ों का निर्णय करेगा जो कि पारिअभिक, कार्य के बन्दे, बींनस, युक्तिकरण और छटनी क सम्बन्ध में हैं। राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे मगड़ों का निर्णय करेगा जो कि सरकार के मत में ऐसे मामले हैं जिनकी राष्ट्रीय हिंदिकीय से महत्ता है, अथवा ऐसे मामले हैं जिनका सम्बन्ध एक से अधिक

राज्यों से है। इन तीन न्यायालयों के निर्णय पर श्रापील करने का कोई अवसर नहीं है इसलिये इनके कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी योग्यता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय न्यायालय अपील न्यायालय का स्थानापन नहीं है।

- (४) यह कानून स्थायी आजाओं के सम्बन्ध में आपित्तजनक परिवर्तन करता है। मालिकों की किन्हीं विशेष मामलों में कार्य करने की स्थिति के सम्बन्ध में बिना उन अमिकों को, जिनसे इसका सम्बन्ध है, २१ दिन पूर्व अपने विचारों की स्वना दिये परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह कानून औद्ये गिक रोजगार (स्थायी आजाओं) कानून का संशोधन करता है और प्रमाण पत्र देने वाले विशेष पदाधिकारी को तथा अन्य अधिकारियों को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वे प्रमाण पत्र देने के पूर्व स्थायी आजाओं की युक्तिसंगतता तथा न्याय पूर्णता पर विचार कर लें। पहिले केवल मालिक को ही स्थायी आजाओं में परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने का अधिकार प्राप्त था। यह कानून अमिकों को भी मालिकों के ही स्थान प्रमाण पत्र देने वाले अधिकार प्रदान करता है।
- (५) मालिकों के साथ एक विशेष रियायत की गई है, जिसे इम रियायत के स्थान पर यदि न्याय का प्रदर्शन कहें वो अधिक उपयुक्त होगा। इसके अन्तर्गत मालिक को किसी कर्मचारी को, जब कि क्षगड़ा।निर्णयार्थ विचाराधीन हो, इस क्षगड़े से असम्बद्ध किसी दुराचार के लिये निकाल देने अथवा सज़ा देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मालिक को आमियुक्त अमिक को एक मास का पारिअमिक देना पड़ेगा और अपनी आज्ञा के लिये अधिकारियों की अनुमित लेनी होगी। इससे कारखानों में अनुसासन ठीक रहने की आशा की जाती है।

इस कानून का सबसे बड़ा दोष यह है कि सरकार को श्रीयोगिक निर्णयों को परिवर्तित कर देने का श्रिषकार दे दिया गया है। बड़ी कठिनाइयों के पश्चात् मालिकों श्रीर श्रिकों के पारस्परिक विरोधी हितों पर समकीता हो पाता है श्रीर यदि ऐसे समकीतों को बदल देने का श्रिषकार सरकार को प्राप्त है तो इससे मामलों के श्रीर श्रिषक उलका जाने का मय है। कानून में ऐसा प्रबन्ध है कि सरकार को परिवर्तन सम्बन्धी श्राशाश्ची को संसद के समझ १५ दिन की श्रविष तक के लिये रक्खा जाय जिसके भीतर प्रस्ताव द्वारा संसद उसे स्वीकार करे श्रथवा श्रस्तीकार कर दे, इससे स्थिति के सुधार की श्राशा नहीं की जा

सकती। वास्तविक बात तो यह है कि यह जानते हुये कि सरकार को अपने इच्छानुक्ल निर्णय बदल देने का अधिकार प्राप्त है सगझा जिन पन्नों के बीच है वे अपनी बात पूरी पूरी ब्दक्त न करेंगे और जल्दी समसीता न करेंगे। कानून की अच्छी बात यह है कि अब सगड़े में पड़े हुये टोनों पन्नों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे किसी समसीते के निर्णय पर इस्तान्तर कर सकते हैं। इस सगड़े को किसी पंच निर्णायक को फैसला करने के लिये सीप सकते हैं। इस प्रवन्ध के अतिरिक्त यह कानून गिरी द्वारा प्रस्तावित संयुक्त रूप से समसीता करने की योजना को कोई स्थान नहीं देता। यदि गिरी के अभिस्ताव इसमें समिलित कर लिये गये होते तो अभिक और मालिक के हितों को बिना कोई हानि पहुँचाये ही पारस्परिक समसीते की सुविधा कुछ अधिक ही सम्भव हुई होती।

श्रीद्योगिक श्रमुशासन संदिता (Code)—१६५७ में भारतीय श्रम कान्फ्रेन्स की स्थायों श्रम-समिति ने 'श्रीद्योगिक श्रमुशासन संदिता' श्रपनाई जिसे कर्मचारियों तथा नियोक्ताश्रों के संघों ने भी स्वीकार किया। इससे भारत में श्रीद्योगिक सम्बन्धों के सुधारने की श्राशा की जाती है। इसके श्रमुसार कर्मचारी तथा नियोक्ता मिवध्य में होने वाले कगड़ों को पारस्परिक पत्र-व्यवहार, समकीता तथा श्रपनी इच्छा से बीच-बचाव करवा के इल करने के लिये वास्य हैं। इसके श्रन्तर्गत श्रमिक तथा नियोक्ता 'घीरे काम करो' की चाल, तालाबन्दी, बिना नोटिस के इड़ताल, धमकी तथा श्रमुशासन दीनता के श्रन्य रूप (जो प्रायः श्रीद्योगिक कगड़ों के कारण होते हैं) को नहीं श्रपनायेंगे।

मार्के की बात तो यह है कि छहिता में इन्हें लागू करने तथा इसके परिणाम श्रांकने की व्यवस्था भी है। १६५८ में केन्द्र में लागू करने तथा श्रांकने के लिये एक छोटी संस्था का निर्माण किया गया। यह संस्था विभिन्न समूहों से श्रंशतः या न लागू होने, निर्णय, श्रधिनियम तथा सममीता श्रादि के दोवपूर्ण ढंग से या देर से लागू होने के सम्बन्ध में विवरण एक करेगी। संघ के श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों से २० फरवरी १९६५८ तक तथा भविष्य में प्रतिमाह की दस तारीख तक प्रश्ताविल के उत्तर के रूप में सूचना देने की प्रार्थना की थी। श्रब्छे श्रीद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने की दिशा में यह एक प्रमावपूर्ण कदम है। श्रधिनियम पास करने तथा संहिता स्वीकार करना ही काफी नहीं है। भविष्य में इसके श्रनुसार कामाहोने; के लिये यह श्रावश्यक है कि उसके लागू करने तथा लागू न होने के कारणों एर कठोर हिन्स रखी जाय।

ترج

ष्ठध्याय ३२ ट्रेड युनियन

भारत में श्रीक श्रान्दोलन बहुत पुराना नहीं है। यद्यपि २० वीं श्राता दों के श्रारम्म में भारत में ट्रेड यूनियन थीं परन्तु उनका कार्यचेत्र बहुत सीमित था श्रीर वह उन कार्यों को नहीं करती थीं जिनकी एक ट्रेड यूनियन सें श्रपेक्त की जाती है। मारत में इनका विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ श्रीर जो कुछ प्रगति हुई भी है वह श्रनेक कारणों से सन्तोपजनक नहीं कहीं जा सकती। श्रिमकों में किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होने की मावना होने के लिए यह श्रावश्यक है कि उन्हें इस प्रकार के संगठन की श्रावश्यकता प्रतीत हो। १८ वीं सदी में ब्रिटेन में श्रीवोधिक कान्ति हुई श्रीर उसके पश्चात् कुछ देशों में उसकी पुनरावृत्ति हुई। परन्तु भारत ने श्रव तक इस प्रकार की श्रीवोधिक कान्ति का श्रवमान नहीं किया है। यदि श्रीवोधिक कान्ति हुई होती तो उससे श्रमिकों के संगठन की श्रावश्यकता उत्पन्न हो जाती श्रीर एक श्रमिक संगठन बन जाता। श्रीवोधिक कान्ति से श्रवेश का समस्याएँ उत्पन्न हो जाती जिनकी पूर्ति के लिए श्रमिकों का संगठत होनो श्रावश्यक हो जाता। भारत के श्रीवोधिक विकास से कुछ समस्याएँ उत्पन्न हुई है परन्तु यह समस्याएँ उतनी तीन नहीं हैं जितनी श्रीवोधिक कान्ति होने पर होतीं।

श्रनेक कारणों से मारत में श्रीमक श्रान्दोलन का विकास नहीं हो पाया है; (१) यह पहले कहा जा चुका है कि भारत की श्रीधकतर श्रीमक जनता निरक्र है श्रीर उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है। श्रीमक भाग्य पर विश्वास करता है श्रीर यह मानता है कि स्वयं प्रयत्न करके वह श्रपनी स्थित नहीं सुधार कर सकता है। इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह श्रपनी स्थित नहीं सुधार कर सकता है। इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह श्रपनी स्थित सुधारनें की श्राव-श्यकवा प्रतीत होती श्रीर उसे यह धात हो जाता कि स्वयं प्रयत्न करके वह श्रपनी स्थित कोवहुत सीमा तक सुधार सकता है। ऐसा श्रनुभव कर वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रपने श्रम्य श्रीमक साथियों को संगठित कर सकता था। यहि भारतीय श्रमिक भी पाश्चात्य देशों के श्रमिकों की तरह भौतिकवादी होता तो वह निरक्तर होते हुए भी संगठित हो सकता था परन्तु भारत में निरक्तरता श्रीर भाग्यवाद के कारण ही श्राज तक श्रमिक का प्रभावशाली संगठन नहीं हो पाया है। श्रमिक त्रान्दोलन सम्बन्बी श्रनेक कार्यवाहियों के होते हुए भी भारतीय श्रमिक की च्यक्तिगत भावना कम नहीं हो पाई है।

- (२) भारत का श्रौद्योगिक श्रमिक केवल कारखानों पर ही निर्भर नहीं है। वीच-बीच में वह गाँव जाता रहता है श्रौर फिर काम करने कारखानों में श्रा जाता है। समान हितों की पूर्ति के लिए संगठित होने में उनके स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति सब से बड़ी वाघक रही है। इघर कुछ वर्षों से स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है श्रौर शुद्ध श्रीद्योगिक श्रमिक के एक वर्ग का उद्मव हो रहा है।
- (३) अभिकों के पारिअभिक में वृद्धि हुई है परन्त इसके साथ ही रहन-सहन के न्यय में भी वृद्धि हुई है। अभिक अवीत की तरह अब भी ट्रेड यूनियन के लिए योड़ा सा चन्दा देने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है। यदि उसे संगठन का लाम मालूम होना तो ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए आवश्यक चन्दा देने से वह पीछे नहीं हटता।
- (४) भारत के उद्योगपित भी श्रोद्योगिक विकास के श्रारम्म काल के श्रन्य देशों के उद्योगपितयों की तरह ट्रेड यूनियनों का विरोध करते हैं श्रीर यह श्रनुभव करते हैं कि ट्रेड यूनियन उनकी प्रतिद्वन्द्वी शक्ति है। यदि उद्योगपित कुछ श्रीर विचारपूर्ण दृष्टिकोण श्रपनाते तो इस श्रान्दोलन की बहुत प्रगति हो गयी होती। इसर कुछ वपों से उद्योगपितयों ने श्रीद्योगिक क्तगड़ों के निपटारे के लिए श्रीर उद्योग में शांति बनाये रखने के लिए ट्रेड यूनियनों का महत्व समक्ता है।
- (५) वर्तमान में भारतीय श्रमिक संघों पर स्वयं श्रमिकों का नहीं विलिक वाहरी लोगों का नियंत्रण है। यदि ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व स्वयं श्रमिकों के हाय में होता तो वह श्रमिकों के हित में ट्रेड यूनियनों का संगठन करने का महत्त्व समस्त सकते श्लौर इससे श्रमिक ग्रान्दोलन तेजी से वह सकता था। परन्छ नेतृत्व स्वयं श्रमिकों के हाथ में नहीं है श्लौर वाहरी लोग ट्रेड यूनियनों का उपयोग ग्रपने राजनीतिक स्वायों की पूर्ति में करते हैं। उनकी हिष्ट में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना गीण विषय होता है। इसीलिए श्रमिक सोचते हैं कि ट्रेड यूनियनों का संगठन करने से विशेष लाम नहीं है। भारतीय ट्रेड यूनियन संगठन में यह दोष होने से ट्रेड यूनियनों का कार्यचेत्र विकसित नहीं हो पाया है श्लौर श्रमिकों में शिचा-प्रधार श्लौर स्वास्थ्य संवन्धी कोई कार्यवाही नहीं की ला सकी है। भारतीय ट्रेड यूनियने श्लिकतर संघर्पशील प्रवृत्ति की हैं। यह एक प्रकार से इन्ताल करने की श्लौर मालिक या सरकार के विरुद्ध श्लान्दोलन करने की एजेन्सी के रूप में कार्य करती हैं। इस नीति के कारण भारतीय ट्रेड यूनियनों का कार्यचेत्र बहुत संकीर्ण हो गया है।

१६५५-५६ में (जिस श्रयंतन वर्ष के श्रांकड़े प्राप्त हैं) मारत में ७८४६ श्रिमक संघ ये जिनके सदस्यों की संख्या २२% लाख थी। निम्न तालिका से यह स्पष्ट होगा कि १६५२-५३ से रिजस्टर्ड श्रम-संघ तथा उनकी सदस्य संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। संघो के इस विकास के होते हुए भी रिजस्टर किये हुये श्रमिक संघों के कुल सदस्यों की संख्या उद्योगों में काय करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या का श्रंग मात्र ही है।

रजिस्टर्ड अम-संघ तथा उनको सदस्य-संख्या

वर्ष	श्रमसंघ का संख्या 		सदस्यों की कुल संख्या	
	रजिस्टर्ङ) सूचना देने वाले		
१९५०-५१	३७६६	२००२	१७,५६,६७१	
१९५१-५२	४६२३	रुप्रप्रह	१६,६६,३११	
१९५२-५३	8838	२७१⊏	₹00,8€,00€	
१९५३-५४	६०२६	ર્ સ્દ્ય	२१,१२,६६५	
१९५४-५५	६६४⊏	३११३	२१,७०,४५०	
१६५५-५६	৬ 586	\$ \$3\$	२२,२५,३१०	

कान्नी व्यवस्था

ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने का उद्देश्य ट्रेड यूनियन की व्याख्या करना, उसके कर्तव्यों श्रीर उत्तरदायित्व को निश्चित करना श्रीर ट्रेड यूनियन सम्बन्धी उचित कार्यवाही के सम्बन्ध में उनकी रक्षा करना है। कानून यह निश्चित करता है कि उद्योगपित ट्रेड यूनियन को मान्यता देंगे श्रीर ट्रेड यूनियन सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने पर किसी श्रदास्त में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा। ऐसा कानून न होने पर उचित कार्यवाही भी श्रन्य श्रयों में श्रवैध घोषित की जा सकती है।

१६२६ का भारतीय ट्रेड यूनियन कानून—१६२६ के भारतीय ट्रेड यूनियन कानून में १६२८, १६४२ श्रीर १६४७ में संशोधन किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन इसी कानून द्वारा संचालित होती हैं। १६२६ के कानून के श्रन्तर्गत ट्रेड यूनियन की यह परिभाषा दी गई है कि कोई भी संगठन चाहे श्रस्थायी हो या स्थायी यदि श्रमिक श्रीर उद्योगपित या मालिक श्रीर कर्मचारियों के बीच श्रयवा कर्मचारियों के बीच पारस्परिक उचित सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बनाया गया

हो, या वाणिज्य-ज्यापार करने पर कुछ प्रतिबन्घ लगाने के लिए बनाया गया हो या दो या दो से श्रिधिक संधों का संगठन हो तो उसको भी ट्रेड यूनियन ही कहा जायगा। इस प्रकार ट्रेंड युनियन की श्रेणी में श्रमिकों श्रीर मालिकों दोनों के संगठन सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी यूनियन के ७ या उससे श्रधिक सदस्य कानून के श्रन्तर्गत नियुक्त रिजिस्ट्रार के पास यूनियन की रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन पत्र मेज सकते हैं। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि यूनियने निर्घारित शर्ते पूरी करती हों। यह भी व्यवस्था की गई है कि रजिस्टर्ड यूनियन के पदाधिकारियों में से आधे वास्तव में उस उद्योग के कर्मचारी हो जिसके श्रमिकों की यह यूनियन हैं। इससे बाहरी व्यक्तियों को ट्रेड यृनियन संगठन में काफी स्थान मिल जाता है। यदि यूनियन के कानून समात उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किये गये सममौते के सम्बन्ध में मगड़ा हो तो यह कानून युनियन के पदाधिकारियों श्रीर सदस्यों की फीजदारी के दावे से सुरचा करता है। इसके साथ ही यदि मालिक अभिकों के मागड़े के बारे में कोई कार्य किया गया है ग्रौर शिकायत केवल यह है कि इस प्रकार के कार्य से श्रन्य श्रमिक द्वारा कांम छोड़ दिये जाने की सम्भावना है या यह व्यापार में श्रयवा किन्हीं लोगों की नियुक्ति में इस्तचेप करना है तो इस कान्न की वजह से यूनियन के पदाधिकारियों त्रीर सदस्यों पर टीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है।

इस कानून द्वाग रिजर्छ ट्रेड युनियन के कीय पर प्रतिवन्य लगाया गया है। इस कीय का केवल उन्हीं कायों में उपयोग किया ना सकता है जिनका कानून में निवरण दिया गया है परन्तु एक प्रयक् कीय का निर्माण करने की अनुमति दे कर युनियन के सदस्यों के नागरिक एवम् राजनीतिक हितों की भी रज्ञा की गई है। प्रत्येक ट्रेड युनियन को प्रतिवर्ष अपना हिसाब छुपे फार्मों में भरकर र्राजस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ ही आय-व्यय का आदिट किया हुआ निवरण भी मेजना पड़ता है। यदि मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन के (१) अधिकतर सदस्य अनियमित इइताल में भाग हों, (२) युनियन को कार्यकारिणी अनियमित इइताल की सलाह दे, उससे सहयोग करे या उसे भड़काए, या (३) युनियन का अधिकारी गलत वक्तव्य प्रकाशित कराए, तो कानून के अनुसार ये कार्यवाहियों अनुचित समसी नौंयगी और इसके लिए दरहस्वरूप युनियन की मान्यता वापस ले लेन की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर यदि उद्योगपित या मालिक (अ) अपने अभिकों के ट्रेड युनियन संगठित करने के अधिकारों में इस्तचेप करे या पारस्परिक सहायता एवम् सुरज्ञा के उद्देश्य से की जाने वाली कार्यवाही में गड़वड़ी पैदा करे, (व) किसी ट्रेड युनियन के सकी जाने वाली कार्यवाही में गड़वड़ी पैदा करे, (व) किसी ट्रेड युनियन के

कनने या उसके प्रशासन में इस्ताच्चिय करे, (स) किसी मान्यता प्राप्त देह यूनियन के अधिकारी की ट्रेंड यूनियन का अधिकारी होने के कारण मीकरी से निकाल दे या उसके साथ भेद-भाव की नीति वरते, और अभिकों को कान्त्न के अन्तर्गत चलने वाली किसी जाँच इत्यादि कार्यवाही में गवाही देने पर या आरोप लगाने पर निकाल दे, या (द) मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ समझीता वार्ता करने से इन्कार कर दे या कानून में दो गई सुविधाओं को देने से इन्कार कर दे तो उद्योगपित अथवा मालिक की यह कार्यवाही कानून की दृष्टि में अनुचित समझी जायगी। अनुचित कार्यवाही के लिए उस पर एक हजार रुपया जुर्माना करने. की व्यवस्था की गई है।

इस कानून से यद्यि ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिली श्रीर उनको कानूनी स्थापार दिया गया किर भी इससे भारत में ट्रेड यूनियन संगठन का विकास करने का उद्देश्य पूर्ण न हो सका । इसमें अनेक दोप हैं: (१) इस कानून के अनुसार ट्रेड यूनियन केवल मजरूरों के संगठनों तक हो सीमित नहीं है, जैसा कि होना चाहिए या, परन्तु इसमें मालिकों और उद्योगपतियों के संगठन भी सामिल किये गये हैं। इससे अनावश्यक गड़बड़ी पैदा हो जाती है; (२) कानून के अनुसार ट्रेड यूनियन का रिजस्ट्रेशन करना अनिवाय नहीं है। इस कानून में उन यूनियनों को भारतीय दसड़ विधान के अन्तर्गत कीजदारी के सुकदमें से छूट नहीं दो गई है जिनकी रिजस्ट्रेशन ही हुई है, इससे ट्रेड यूनियन संगठन कमजोर पड़ जाता है; और (३) कानून के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित कोष में अवैद्यानिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है। सामान्य कोष से ज्यय करने के लिए अत्यन्त संकीर्या ज्यवस्था की गई है।

आचरण-संहिता (code of conduct)—यद्यपि मारत में अम संघों की बाहुल्यता है तथा विभिन्न संघों (federations) के सामंजस्य सहित काम करने की कोई आशा नहीं है फिर भी मई, १६५८ में नैनीताल में भारतीय-अम-काफ्रेन्स में माग लेने वाले अम संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा, अपनाये गये आचरण संहिता से आशा का संचार होता है।

इस संहिता के अनुसार "(i) किसी उद्योग अथवा इकाई के कर्मनारी को अपनी इच्छा की यूनियन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता होगी। इस संबंध में कोई दबाव नहीं डाला जायगा। (ii) यूनियन की दोहरी सदस्यता नहीं होगी। प्रतिनिधि-यूनियनों के सम्बन्ध में यह तय किया गया कि उपर्युक्त नियम की और परीद्या की जाय। (iii) अम-संधों के प्रजातंत्रीय ढंग पर कार्य करने को स्वीकार किया जाय तथा श्रादर की हिन्द से देखा जाय। (1v) ट्रेंड यूनियन के पदाधिकारियों तथा प्रशासकीय निकायों के जुनाव नियमित तथा प्रजातंत्रीय ढंग पर होने चाहिये। (v) श्रमिकों की श्रज्ञानता श्रीर पिछड़ेपन का कोई संगठन कायदा नहीं उठायेगा। कोई संगठन श्रनावश्यक माँगे नहीं पेश करेगा। (vi) हर एक संघ जातीयता व प्रान्तीयता से दूर रहेगा। तथा (vii) श्रम संघीं के बीच कोई हिसा, दबाब, धमकी तथा व्यक्तिगत बदनामी श्रादि नहीं होगी।" यह सब बड़े ही श्रच्छे प्रस्ताव हैं किन्तु इनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि देड-यूनियन उन्हें कहाँ तक श्रपनावी हैं।

श्रम संघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ग्राभी तक कोई केन्द्रीय श्रिधिनियम नहीं है। भारतीय अस-काफेन्स नी ट्रेड यूनियन के मान्यता देने के सम्बन्ध में निम्न कसौटियाँ प्रस्तावित की । "(i) जहाँ एक से अधिक यूनियन हो वहाँ मान्यता प्राप्त करने वाली युनियन रजिल्ट्री के वाद कम से कम एक वर्ष तक काम करती रही हो किन्तु जहाँ एक ही यूनियन हो वहीं यह शर्त लागू नहीं होगी । (ii) सस्यान के कम से कम १५% अमिक उसके सदस्य हों । (iii) किसी स्थानीय चेत्र में एक यूनियन को किसी उद्योग का प्रतिनिधि यूनियन भाना जा सकता है बशर्ते कि चेत्र में उद्योग के २५% श्रमिक उसके सदस्य हों। (iv) यूनियन को मान्यता मिलने पर, दो वर्ष तक रियात में कोई सुधार नहीं होना चाहिये। (v) जब किसी उद्योग श्रथवा संस्थान में श्रनेक यूनियन हों तो सबसे श्रधिक . सदस्य-संख्या वाली यूनियन को मान्यता देनी चाहिये। (vi) किसी त्रेत्र में किसी उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन को देश भर के संस्थानों के श्रामकों का प्रति-निधित्व करने का श्रिधिकार है। किन्तु यदि किसी संस्थान के श्रीसकों की युनियन में उसके ५.% श्रमिक सदस्य है तो उसे केवल स्पानीय हित के मामलों पर कार्य-वाही करने का श्रिषिकार होना चाहिये। (vil) प्रतिनिधित्व का रूप निर्णय करने के लिये छानबीन करने के ढंग को श्रीर श्रधिक पर्याप्त कर देना चाहिये। जक इस सम्बन्ध में वैभागिक छान-बीन के परिगाम दलों को मान्य न हों तो केन्द्रीय श्रम संघ के प्रतिनिधियों से निर्मित एक समिति को इस प्रश्न की जाँच कर इसे इल करना चाहिये। इस कार्य के लिये केन्द्रीय श्रम संगठन विभिन्न भागों के लिये श्रावश्यक धन श्रीर व्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। यदि इससे काम नहीं होता तो प्रश्न का निर्णय न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिये। (viii) सिर्फ वे युनियन मान्यता पा सर्वेगी जो श्रीद्योगिक श्रनुशासन संहिता को मानेगी। (ix) उन अम-संघों के सम्बन्ध में जो अम के चार केन्द्रीय संगठनों से सम्बन्धित नहीं है, इस प्रकार श्रालग से विचार करना चाहिये।" यह कसौटियाँ

विस्तृत तथा सुविचारित हैं। यदि इनका अनुसरण किया गया तो ट्रेड यूनियनों की नींव दृढ़ हो जायँगी। प्राप्त अनुभव के आधार पर वे इस विषय पर अधि-नियम बनाने का आधार भी बन सकती हैं।

भविष्य की योजना-वर्तमान में भारतीय श्रमिक ग्रान्दोलन में कुछ. श्राघारभूत दोप हैं श्रीर स्थिति मुधारने के लिए इन दोशों की दूर करना बहुत श्रावश्यक है। इस समय एक ही उद्योग में एक ही चोत्र से श्रानेक ट्रेड यूनियनें हैं। बहुत ग्रिधिक ट्रेंड युनियन होने से श्रीमक का पश्च कमजोर पड़ जाता है श्रीर श्रमिक के श्रिधकारों की रच्चा में भी बाधार्ये श्रा जाती हैं। इसिलए ट्रेड यूनियनों के संगठन को संगठित करने और इनको एकता के सूत्र में बाँघने की अत्यन्त श्रावश्यकता है। यह त्रावश्यक है कि एक दोत्र में स्थित किसी मुख्य उद्योग में अभिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक से अधिक ट्रेड यूनियन न हो। यदि एक चेत्र के विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले सभी श्रामको का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ट्रेड युनियन होती तो सर्वोत्तम होता। परन्तु यह संमव नहीं है क्योंकि कभी-कभी विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले अमिकों की समस्याएँ भिन्न होती हैं। साथ ही विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले अभिक एकता के सूत्र में नहीं बँघ पाते हैं जब कि ट्रेड युनियन भ्रान्दोलन की सफलता इनकी एकात्मकता पर निर्भर करती है। मारत के ट्रेड यूनियन संगठन में दूसरा बड़ा दोष यह है कि यह अपनी सम्पूर्ण शक्ति पायः इंदताल में और मालिकों से सामूहिक माँगें करने में लगा देते हैं। बहुत कम ऐसी यूनियनें हैं जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र की व्यापक बनाया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सामृहिक रूप से माँग करना और इइताल करना ट्रेंड यूनियनों का महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु इसके साथ ही अन्य कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में ट्रेड युनियन का कार्यक्रम ग्रौर विस्तृत करने की श्रावश्यकता है। इसमें वयस्कों की शिज्ञा, सहकारी-श्रान्दोलन का संगठन, जनसेवा कार्यं इत्यादि भी सम्मिलित किये जाने चाहिये। इससे ट्रेड युनियनों की उपयोगिता बह जायगी।

ट्रेंड यूनियन श्रान्दोलन का एक बहुत बड़ा दोष केन्द्रीय संगठनों का बाहुल्य है। कुल १५३१ यूनियनों में से श्राई० एन० टी० यू० सी, ए० श्राई० टी० यू० सी० हिन्द मजदूर समा श्रीर यूनाइटेड टी० यू० सी० से संयोजित यूनियनों की संख्या कमशः ६१७, ५५८, ११६, श्रीर २३७ श्रीर उनके सदस्यों की संख्या कमशः ६'७२ लाख, ४'२३ लाख, २'०४ लाख, श्रीर १'५६ लाख १६५६ के श्रन्त में थी। इन केन्द्रीय संगठनों को एक शक्तिशाली संस्था में संगठित करना सम्मव है। इसमें संदेह नहीं कि इन केन्द्रीय संगठनों के राजनीतिक

उद्देश्यों में बहुत श्रिषक श्रंतर है परन्तु जहाँ तक श्रिमकों की स्थित में सुधार, करने श्रीर श्रिमकों के वास्तिविक हितों की रह्मा करने का प्रश्न है इनका श्राधारभूत श्रार्थिक कार्यक्रम समान है। यदि यह केन्द्रीय संगठन एक में मिल जाँय तो
श्रीमक के हितों की वर्तमान की श्रिमेन्ना कहीं श्रच्छे रूप में रह्मा की जा सकती
है। यदि इन संगठनों को श्रारंभ में पूर्णतया एक में मिला देना संभव न हो तो
कम से कम समान हितों की कुछ समस्याश्रों को हल करने के लिए इनमें परस्पर
सहयोग तो हो ही सकता है। इससे स्थिति में सुधार होगा श्रीर भविष्य में इन
संगठनों का एकीकरण करने के लिए मार्ग खुल जायगा।

अध्याय ३४

रेल यातायात

मारतीय रेलों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १८५३ में भारतीय रेलने लाइन की लम्बाई केवल २० मील थी, १६०० में यह २४,७५२ मील हुई श्रीर १६५१-५० में इसका प्रसार ३४,११६ मील श्रीर १६५६-५७ में ३४,७४४ मील हो गया, जिसमें ३४,६६१ मील सरकारी प्रवन्ध के अन्तर्गत था। १६०० में भारतीय रेलों से १७ करोड़ ५० लाख यात्रियों ने यात्रा की, ४ करोड़ ३० लाख टन सामान ढोया गया। १६५६-५७ में यात्रियों की संख्या १३८ करोड़ ३० लाख श्रीर ढोये जाने वाले माल की मात्रा १२ करोड़ ५० लाख टन हो गई। १६ अप्रैल १६५३ को भारतीय रेलों ने अपनी उपयोगी सेवाओं के १०० वर्ष पूरे किये। टीक १०० वर्ष पूर्व १६ श्रप्रैल १८५३ को भारतीय रेलों ने अपनी उपयोगी सेवाओं के १०० वर्ष पूरे किये। टीक १०० वर्ष पूर्व १६ श्रप्रैल १८५३ को भ्रायम भारतीय रेल ने वम्बई शहर से थाने तक २१३ मील की दूरी तय की थी। यद्यपि रेलवे संगठन में कुछ जुटियाँ है और कुछ दाष भी है परन्तु फिर भी जिस गति से उसने प्रगति की है उस पर भारतीय रेलवे गर्व कर सकती है।

मुख्य विशेषताएँ-मारतीय रेलवे के विकास में कुछ उल्लेखनीय विशेष-ताएँ हैं। (१) भारत में रेल का कार्य निजी उद्योग के रूप में प्रारम्भ किया गया। रेल-उद्योग करने वालों को सरकार ने कुछ सुविधाएँ दीं जैसे इन्हें भूमि मुफ्त दी गई ब्रौर पूँजी की वस्तुली की गारन्टी दी गई। इससे रेलवे निर्माण के व्यय में चृद्धि हुई श्रीर सारे देश को इसका भार वहन करना पड़ा। ऐसे समय में जब रेलों का निर्माण करने के लिए उद्योगपित पूँजी लगाने को प्रस्तुत नहीं ये यह सुविधार देना संभवतः अत्यन्त आवश्यक या परन्तु यदि इस और किंचित् सावधानी से कार्य लिया जाता तो इनको काफी कम भी किया जा सकता था। रेलों का प्रबन्ध निजी उद्योगपतियों के हाथ में होने से इसकी काफी आलोचना की गई है। श्रालोचकों ने प्रबन्धकों द्वारा पच्चपात किये जाने श्रीर कच्चे माल के निर्यात तथा तैयार माल के श्रायात के भाड़े में रियायतें देने की शिकायतें कीं, क्योंकि बन्दर-गाहों से देश के अन्दर सामान लाने और बन्दरगाहों तक सामान पहुँचाने के लिए रेल के भाड़े की दर श्रन्य दरों की श्रपेचा कम रखी गई थी। एकवर्ष समिति (Acworth Committee) ने युक्ताव दिया कि राष्ट्रीय हित में रेल के निजी उद्योगं को क्रमशः राज्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इस दिशा में १६२५ में प्रथम प्रयास किया गया। सरकार ने ईस्ट इंग्डिया और जी. म्राई, पी. रेलवे को अपने अधिकार में ले लिया परन्तु इस प्रक्रिया को पूरा होने में २० वर्ष लगे श्रीर जहाँ तक विटिश भारत का सम्बन्ध है १६४४ में निजी उद्योग समाप्त कर राज्य ने इसको पूर्णतया 'अपने श्रिधिकार में ले लिया। १६५० में संघीय वित्तीय एकोकरण के पश्चात् भूतपूर्व रियासतों की रेलों को भी भारत-सरकार ने अपने हाथ में ले लिया श्रीर श्रव रेलवे एकमात्र राजकीय उद्योग बन चुका है।

रेल उद्योग निजी उद्योगपितयों के हाथ में होने की अपे हा सरकार के हाथ में होने से अनेक लाम हैं—(श्र) इससे साधनों की अनावश्यक हानि और विभिन्न रेलवे-प्रबन्धों में प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। (ब) राजकीय उद्योग होने के कारण देश के औद्योगिक और कृषि साधनों के विकास के महत्व को हाइट में रखते हुए रेल के माहे की उचित दर निश्चित की जा सकती है और (स) इस उद्योग से जो लाम होगा वह केन्द्रीय प्रमु कोय में लगा हो सकता है।

- से जो लाम होगा वह केन्द्रीय घन कीष में जमा हो सकता है।

 (२) दो विश्वयुद्धों के कारण, १६३० की श्राधिक मंदी श्रीर १६४७ में
 देश के विमाजन से रेलों पर बहुत भार पड़ा है श्रीर उसका परस्पर सम्बन्ध मी
 विच्छिन्न हो गया। युद्ध के कारण रेलों की कार्यं जमता पर श्रिष्ठ ध्यान नहीं
 दिया गया, पुराने कल-पुजों इत्यादि को नहीं बदला गया श्रीर नई मशीनें लगाने
 की योजना स्थिगत कर दी गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय प्रतिशत मीटर-गेज
 के इज्जन, १५ प्रतिशत मीटर-गेज के वैगन, ४ हजार मील लम्बी पटरियाँ श्रीर
 ४० लाख स्लिपर मारतीय रेलों से लेकर मध्यपूर्वी देशों को मेजे गये। युद्ध के
 समय रेलों के सामान का श्रीर पर्टारयों का श्रत्यधिक उपयोग किया गया, उनको
 न बदला जा सका श्रीर न नया सामान लगाया जा सका। इससे रेलों की कार्यज्ञात का गया श्रीर शरणाधियों को लाने-पहुँचाने के कार्य में रेलों पर
 श्रीर श्रिष्ठिक मार पड़ा। गत कुछ वर्षों में रेलों पर श्रावश्यकता से श्रिष्ठिक भार
 कुछ कम किया गया है, पुराने सामान को बदला गया है श्रीर सामान की मात्रा
 वदाई गई है परन्त इस दिशा में श्रमी बहुत कुछ करना शेष है।
- (३) श्रतीत में इझनों, वायलरों, डिब्बों इत्यादि के लिए भारतीय रेलों को ग्रायात पर निर्भर करना पड़ता था। इससे देश का बहुत-सा धन विदेश चला जाता या श्रीर देश को विदेशों विनिमय साधनों को गम्भीर चित होती थी। परन्तु इघर कुछ वर्षों से स्थित में सुधार हुआ है श्रीर अब देश में ही इझन, डिब्बे इत्यादि बनने लगे हैं। भारतीय कारखानों में डिब्बों का उत्पादन बढ़ रहा है श्रीर रेलवे की श्रावश्यकता की श्रिधकाधिक पूर्ति की जा रही है। चित्र-रखन के इझन वनाने के कारखाने में इझन के लगमग ७० प्रतिशत कल पुनों

का उत्पादन किया जाता है श्रीर केवल ३० प्रतिशत का श्रायात करना पहता है।

- (४) भारत में श्रनेक रेलें थीं परन्तु पुनर्वर्गी-करण योजना लागू करके इनको ७ चेनों में संगठित किया गया है । एकीकरण से पहिले भारत में ३५ रेलवे थीं जिनमें से २२ सरकार के श्रिषकार में थीं। रेलवे वोर्ड की जाँच करने के लिये नियुक्त समिति (१६५०) की सिफारिश पर भारत सरकार ने भारतीय रेलों को ६ चेनों में संगठित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। दिल्ली रेलवे का १४ श्रमेल १६५१, पिश्वमी श्रीर केन्द्रीय रेलवे का ५ नवम्बर १६५१ को श्रीर श्रीप तीन उत्तरी, उत्तरी पूर्वीं तर श्रीर पूर्वी रेलवे का १४ श्रमेल १६५२ को उद्घाटन हुआ। पहली श्रमस्त १६५५ से सातवें चेन्न का निर्माण पूर्वी रेलवे को दो चेनों में विभाजित करके किया गया: (१) पूर्वी रेलवे जिसमें पुरानी ई० श्राई० श्रार० का सुगलसराय तक का भाग (सियालदह हिविजन को लेकर) समितित थी, श्रीर (२) दिल्ली पूर्वी रेलवे की निम्न सात चेनों में विभाजित कर दिया गया।
- (१) दिन्निणी रेलवे--- इसमें एम० एन्ड एस० एम०, एस० आई० और मैस्र राज्य रेलवे सम्मिलित है।
- (२) पश्चिमी रेलवे इसमें भूतपूर्व बी० बी० खी० छाई०, सौराष्ट्र, -राजस्थान तथा जैपुर रेलवे श्रीर जोधपुर रेलवे का कुछ माग सम्मिलित कर दिया नाया है।
- (३) केन्द्रीय रेलवे—इसमें जी० आई० पी०, एन० एस०, सिन्ध्या नाज्य और घोलपुर राज्य रेलवे सम्मिलित है।
- (४) उत्तरी रेलवे—इसमें ई० पी०, जोधपुर श्रीर बीकानेर रेलवे, ई० श्राई० श्रार० के इलाहाबाद, लखनऊ श्रीर मुरादाबाद हिवीजन श्रीर बी० बी० एन्ड सी० श्राई० रेलवे का दिल्ली रेवारी-फिलिलका चेत्र सम्मिलित है।
- (६) उत्तरी पूर्वी रेलवे—इसमें ओ॰ टी॰ एन्ड आसाम रेलवे, ६० आई० आर॰ का कुछ भाग और बी॰ वी॰ एन्ड सी॰ आई॰ रेलवे का फतेहगढ़ सेत्र है।
- (७) पूर्वी रेलवे—इसमें पुरानी ई॰ ग्राई॰ का मुगलसराय तक का भाग श्रीर सियालदह डिवीजन सम्मिलित है।
- ७ त्तेत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है कि जिसमें विभिन्न त्तेत्रों का कार्य कम व्यय के साथ चलाया जा सके और विभिन्न त्तेत्रों में यातायात की

उचित मुविधा प्राप्त हो। विभिन्न चेत्रों के रेल पथों का विस्तार २३३१ मील से लगाकर (जो कि पूर्वी रेलवे का है) ६३३६ मील तक है। (जो कि उत्तरी रेलवे का है) इस बात का ध्यान रखा गया है कि कर्मचारियों ग्रीर श्रन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम हटाना पड़े श्रीर केवल ईस्ट इडिया ग्रीर बी० बी० एन्ड सी० ग्राई० रेलवे को छोड़कर जहाँ तक सम्भव है वर्तमान रेलवे व्यवस्था को बिना छिन्न भिन्न किए एक या दूसरे माग में सम्मिलित कर लिया जाए।

रेलवे के पुनवंगीकरण योजना की श्रालोचना की गई है। कहा गया है कि (ग्र) पुनर्वर्गीकरण से एक रेलवे के कर्मचारियों को दूसरी रेलवे में परिवर्तित किया गया, उनमें अनेक को नौकरी से अलग कर दिया गया, (व) इससे कम से कम दो रेलवे-ईस्ट इन्डियन श्रौर बी० बी० एन्ड ० सी० श्राई० रेलवे-तोड़ी गई जिससे श्रमेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो गईं, श्रीर (स) इससे भारतीय व्यापार एवम् उद्योग को श्रानेक कठिनाइयाँ हुई हैं। रेलवे के पुनर्वर्गीकरण जैसे बड़े परिवर्तन में योड़ा-बहुत सम्बन्ध विच्छेद होना श्रीर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया जाना अनिवार्य था। उससे बचा नहीं जा सकता था। परन्तु इतने ते ही पुनर्वर्गीकरण की योजना श्रवांछनीय श्रीर श्रनुपयुक्त सिद्ध नहीं होती क्योंकि इस योजना के लागू हो जाने से जो लाम होंगे वह इससे होनेवाली हानियों की अपेदा कहीं अधिक हैं। यह भी कोई तर्क नहीं, जैसा कि कुछ सम-तियों ने सुक्ताव दिया था, कि यह योजना पाँच वर्ष बाद लागू की जाय श्रीर सरकार को इस समय इसे स्यगित कर देना चाहिए था। यदि पुनर्वर्गीकरण की नीति स्वीकार कर ली गई है तो इसे जितना शीष्ठ लागू किया जाय उतना ही श्रव्छा है। इस योजना के लागू करने से तीन निश्चित लाम है: -(क) इससे वह सभी लाम माप्त हो सकेंगे जो प्रबन्ध व्यवस्था बढ़े पेमाने पर संगठित करने से होते हैं। (ख) इससे एक ही काम अनेक बार करने से छुटकारा मिल जायगा त्रीर हानिकारक प्रतियोगिता मी नहीं हो चकेगी श्रीर (ग) इससे रेलवें की श्रार्थिक हिपति दृढ़ होगी श्रीर कार्य के स्वर में सुधार किया जा सकेगा। इस व्यवत्या के परचात् रेल के माड़े श्रीर किराये की दर, यात्रियों की सुविधाश्री, मलदूरों के वेतन और सुविषाओं इत्यादि के संम्वन्य में सारे देश में समान नीति लागृ की जा सकेगी। यह कोई छोटी सफलता नहीं।

(५) भारवीय रेलवे की कार्यचमता अभी भी बहुत नीचे स्तर की हैं। युद्ध आरंभ होने के पूर्व की कार्यचमता के स्तर तक भी अभी भारतीय रेलवे नहीं पहुँच सर्जा है। इस बात की प्रमाण माल के दिश्वों का चक्कर लगांकर अपने स्थान पर पहुंचने में दस अथवा ग्यारह दिन के समय का लगना है जब कि युद्ध के पूर्व केवल नी दिन लगते थे। रेल के सामान के अभाव के अतिरिक्त कार्य प्रवन्ध में देर लगना भी माल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर से पहुंचने का प्रधान कारण है। समय की पावन्दी तथा माल के ढिट्यों के प्रयोग सूचक अंक बहुत नीचे स्तर पर हैं। छोटी लाइन की स्थिति और भी विग्रही हुई है।

भारतीय रेलवे में कीयले का व्यय भी बहुत श्रिषक है। वर्तमान समय में १०५ लाख टन कीयला २०१ करोड़ रुपये की लागत का प्रयोग में श्राता है। रेलवे प्यूल जाँच कमेटी ने विभिन्न उपायों द्वारा २०% बचत करने का सुकाव दिया था। यदि यह सम्मव हो सका तो रेलवे की प्रति वर्ष ६ करोड़ रुपये की बचत श्रगले पाँच वर्षों में सम्मव हो सकेगी। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य मितव्यायता के उपायों की पूरी जाँच होनी चाहिए श्रीर इनका प्रयोग होना चाहिये जिसमें रेलवे का व्यय कम हो जाय तथा श्राय में वृद्धि हो जायगी।

रेलवे की वित्त ज्यवस्था-एकवर्यं समिति के सुकाव पर १६२४ में रेलवे की विच ज्यवस्था केन्द्रीय सरकार की सामान्य विच ज्यवस्था से भिन्न कर दी गई। १६२४ के प्रथक्करण समक्तीते में यह व्यवस्था की गई थी कि रेलवे में लगी हुई पूँजी पर ब्याज के साथ ही व्यवसाय में लगी पूँजी का एक प्रतिशत, श्रितिरिक्त लामाँश का है भाग श्रीर रेलवे के सुर्शचत कोष में ३ करोड़ रुपया जमा कर देने के बाद बंचे श्रात्यधिक श्राविरिक्त लागाँश का है भाग राजस्व के . नाम में जमा करेगी। महत्वपूर्ण रेलों की हानि का भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। रेलवे के सुरक्तित कीय में से सामान्य राजस्व दिया जायगा भ्रौर यदि श्रावश्यकता पड़ी तो टूट-फूट के लिये पूँजी श्रीर रेलवे की श्रार्थिक स्थिति को हृद् बनाने के लिए भी इसमें से धन लिया जायगा। रेलवे के सामान को बदलने श्रीर नया सामान मेंगाने के लिए १ अप्रैल १६२४ से टूट-फूट के लिए एक भिन सुरिक्कत कोप बनाया गया है। केन्द्रीय सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से रेलवे की वित्त व्यवस्था को भिन्न करने के दो लाभ हुये हैं: (श्र) श्रतीत में सामान्य वित्त की कठिनाइयों और श्रानिश्चितता पर ही रेलवे का भविष्य निर्मर करता था। इस कारण वह पहले से ही अपने विकास की योजनाः निर्माण नहीं ंकर पाते थे। अनुमान है कि पृथक्करण समसीते के अनुसार वित्त व्यवस्था:यकप्ट कर देने से रेलवे की स्थिति अधिक सुरिच्चत हो जायगी और इसके प्रसार करने के लिये तथा इसमें सुधार करने के लिए निश्चित धन राशि प्राप्त हो जायगी। (ब) श्रतीत में यह निश्चित नहीं था कि केन्द्रीय राजस्व को रेलवे से कितनी श्राय

होगी परन्तु पृथककरण सममौते के अनुसार इसके अन्तर्गत घन राशि निश्चित कर दी गई है।

पृयक्करण सममीते में संशोधन किया गया जो १ श्रप्रैल, १९५० से लागू हुआ। इस संशोधन के अनुसार (१) जनता को रेलवे का हिस्सेदार माना गया है श्रीर जो भ्राण ली गई पूँजी रेलवे में लगाई गई है उस पर सरकार की (श्रर्थात् जनता को) ४ प्रतिशत का निश्चित रूप से लाम मिलेगा । यह धन रेलवे की श्राय में से केन्द्रीय सरकार को दिया जाता है। पहले १६२४ के सममौते के अनुसार सामान्य राजस्व में दी जाने वाली धन राशि की कोई निश्चित निर्घारित मात्रा नहीं थी पर इस संशोधन से यह निश्चित कर दिया गया कि रेलवे में जो कुछ पूँ जी लगी है उसका एक निर्धारित प्रतिशत सामान्य राजस्व में दिया जायगा। (२) समझौते में रेलवे विकास कीप स्यापित करने की व्यवस्था की गई है। इस कोप से (अ) नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने में वित्तीय सहायता दी जायगी। इन नई लाइनों से आय होना आवश्यक नहीं है, (व) यात्रियों की सुविधा के लिए व्यय किया जायगा श्रीर (स) श्रम कल्याग कार्य इत्यादि में व्यय किया जायगा । (३) समफीते के संशोधन के अनुसार प्रथम पाँच वर्षों में रेलवे के टूट-फूट कोव में कम से कम १५ करोड़ न्पया संग्रह किया जाना चाहिए श्रीर शेप श्रतिरिक्त श्राय से एक ऐसे कोच का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे श्रार्थिक सन्तुलन रखा जाय। रेलवे का सामान अधिक महँगा होने के कारण १९५० के प्रयक्तरण समसीते के पश्चात् ते ट्रट-फूट के कोष में ३० करोड़ रुपये की नियत घनराशि संग्रह कर दी गई है।

पुराने उमक्तीते में सामान्य राजस्व के अन्तर्गत जमा की जानेवाली धन-राशि निश्चित नहीं थी परन्तु नये समक्तीते में यह रक्तम निश्चित कर दी गई है। इससे रेलवे का योजनाबद्ध विकास किया जा सकता है, सुरिह्नत कोप का निर्माण किया जा सकता है और पुनर्वास तथा प्रसार का कार्यक्रम कार्योन्वित किया जा सकता है। टूट-फूट के कोष में प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि में इस आधार पर वृद्धि कर दी गई है कि कल पुर्जों, मशीन, इखन इत्यादि बदलने के ज्यय का मूल व्यय से और उपयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के जीवन काल से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब तक इन्हीं दो आधारों पर टूट-फूट के कोष में योगदान निर्धारित किया जाता था। नये समक्तीते के अनुसार व्यय का मार बढ़ाने का उद्देश्य रेलवे को अत्यधिक पूर्जी संग्रह करने से रोकना है। विकास कोष की स्थापना के समय यह बात मान ली गई है कि भविष्य में रेलवे का विकास केवल व्यवसायिक दृष्टिकोण से सीमित नहीं रखा जा सकता है। देश के आर्थिक विकास में रेलवे को जिसका राष्ट्रीकरण किया जा चुका है एक महत्वपूर्ण त्रौर निश्चित योगदान देना है।

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् रेलवे की वित्तीय स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ है। वास्तविक आप जो कि १६४८-४६ में ४२ ३४ करोड़ रुपये थी १९५१-५२ में बढ़कर ६१.७५ करोड़ रुपया हो गई है और १९५८-५९ के वजट के अनुसार ७६ ६२ करोड़ रुपया अनुमान किया गया है। १६५१-५२ में सामान्य त्र्याय के प्रति ३३ ४१ करोड़ रुपया दिया गया था श्रीर १६५८-५६ में ४६ ५८ करोड़ रुपयों के दिये जाने का श्रनुमान किया गया है जब कि १६४८-४६ में केवल ७ ३४ करोड़ रुपये ही दिये गये थे। इतने पर भी रेलवे की अतिरिक्त आय को कि १९४८-४९ में १९ १८ करोड़ रुपये थी १९५१-५२ में बढकर २८ ३४ करोड़ रुपये और १६५८-५६ के बजट अनुमान के अनुसार २७ ३४ करोड़ रुपये मानी गई है। यह सारी रकम विकास कीय में जमा कर दी गई है जब कि १६४८-४६ में केवल १० करोड़ रुपये ही इस कोष में जमा किये गये ये। रेलवे की वित्त स्थिति में इस सुधार का कारण यह है कि (१) यात्रियों की संख्या में श्रीर माल के यातायात में वृद्धि हुई है श्रीर (२) रेलवे के किराये तथा माड़े में भी वृद्धि हुई है। देश के श्रीद्योगिक विकास में वृद्धि होने से श्रीर श्राधिक कारोबार बढ़ाने से रेलों द्वारा यातायात भी बढ़ा है। वास्तव में रेलों बढ़ते यातायात की माँग परी कर सकने में असमर्थ रही हैं. यातायात बढने के साय ही रेल का किराया भी बढ़ा है। १६४८-४६ में रेलवे को यात्रियों से ८४ करोड़ रुपयों श्लीर १९५१-५२ में १०९ पद करोड़ रुपयों की आय हुई। १९५८-५९ के बजट में लगाये हुए श्रनुमान के श्रनुसार यह श्राय १२४.७३ करोड़ ६० होगी। इसी प्रकार माल होने से त्याय जो कि १९४८-४९ में १०८-२६ करोड़ रुपये थी, १९५१-५२ में बहकर १५६ ७६ करोड़ रुपये हो गई और १६५८-५६ में अनुमान है कि २५० ५० करोड़ रुपये हो जायगी।

रेल से यातायात कम होने का वास्तिविक कारण १६५१-५२ और १६५५-५६ के बीच यह था कि १६५८ से रेल के किराये में और माड़े में अत्यिवक वृद्धि हुई है। युद्ध के तुरन्त पश्चात् रेल के किराये और माड़े में इतनी वृद्धि नहीं हुई जिसका यातायात पर प्रतिकृल प्रभाव पहता परन्तु १६५१ में रेल के किराये तथा भाड़े में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से यात्रियों और माल से होनेवाली आय कम हो गई।

:	यात्रियों से होनेवाली ग्राय	माल ढोने का ग्राय
	(करोड़ रुपयों में)	(करोइ रुपयों में)
१६४ ५-४६	۲۶.00	१०८:२६
१९४६-५०	द्ध २६	१३० ३७
१९५०-५१	<i>६७.</i> ८४ _.	१ ४३.०४
१९५१-५२	१०९-दद	१५६ ७६
१९५२-५३	१००′३⊏	१४६ *१२
१९५३-५४	१००⁴००	१ ४७. १ ⊏
१९५४-५५	१०२"६२	. १५ ⊏'६६
१९५५-५६	१०७'७१	१८०*२८
१९५६-५७	' ११६*३३	२०३.६६
१६५७-५८ (संशोधित)	१२०'६०	२३१°००
१ ६५ ⊏-५६ (वजट)	१२४'७३	२५०५०

पिछले तीन वर्षों में यात्रियों तथा माल के यातायात में श्रीद्योगिक विकास के कारण वृद्धि होने से स्थिति में उन्नित हुई है।

रेलवे के किराये और भांडे की दर सम्बन्धी नीति—रेलों के किराये श्रीर माहे का उद्योग, कृषि, व्यापार श्रीर वाणिज्य के विकास में श्रीर स्वयं रेली की विचीय स्थित को हढ कनाने में बहुत महत्व है। यद भाड़ा अधिक होगा तो उससे उत्पादन व्यय पर प्रभाव पढ़ेगा श्रीर उत्पादन व्यय में वृद्धि होगी। इससे देश के श्रीद्योगीकरण को प्रोत्सहन नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि माड़ें की दर निश्चित करने में त्रुटि वह गई है तो उससे उद्योगों के स्थाननिर्धारण पर श्रीर श्रीद्योगीकरण के दांचे पर बुरा प्रमाव पहता है। रेल का किराया श्रीर माहा श्रिधिक होने से यातायात को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, यातायात रेलों के द्वारा न होकर अन्य साधनों से होता है जिसमें रेलवे को ह्यात पहुँचती है। यदि भाड़ा कम है तो इसमे श्रीद्योगिक तथा कृषिक विकास में ग्रवश्य सहायता मिलेगी, परन्तु यदि इससे रेलवे को हानि पहुँचती है और वह अपना व्यय पूरा करने के पश्चात उचित लाम नहीं उठा सकती है तो यह व्यावसायिक सिद्धान्तों के प्रतिकृत तथा श्रन्चित है। इस लिए रेल के किराये तथा माड़े की दर सम्बन्धी नीति ऐसी होनी. चाहिए जिससे रेलवे के हित में और उद्योग तथा कृषि के हितों में सन्तुलन स्थापित किया जा सके और जिससे देश में प्राप्त साधनों के आधार पर देश का क्रांप तथा श्रीद्योगिक विकास पूरी तीवता से किया जा सके, पंचवर्षीय योजना में

निर्घारित लच्य पूरे किये जा सकें श्रीर रेलवे को वित्तीय स्थित पर्याप्त सुदृढ़ रखी जा सके।

१६४८ से पहले भारत में रेलवे के किराये तथा भाड़े की दर्रे इसके अनुकूल नहीं थीं श्रीर उसकी कड़ी श्रालोचना की गई है

- (१) भारतीय रेलवे में किराये तथा भाई की दर निर्धारित करते समय दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। इससे लम्बी यात्रा करने वालों को या काफी दूर सामान भेजने वालों को बहुत अधिक भाइन देना पहता था। इससे माल की खपत के लिए बाजार की स्थिति तथा अन्य कारणों के अनुकूल रहते हुए भी उद्योगों को कच्चे माल के खोतों से दूर स्थापित करने को प्रोत्साहन न मिला। उद्योगों को कच्चे माल के खोतों से दूर स्थापित करने को प्रोत्साहन न मिला। उद्योगों को किए रेलों के माई की दर कुछ कम थी, साथ ही विशेष स्टेशनों के बीच रियायतें भी दी गई थीं परन्तु इससे ब्यापार और उद्योगों को विशेष लाभ नहीं हुआ।
- (२) भारत से कच्चे माल को विदेशों को निर्यात श्रीर विदेशी माल के श्रायात को सस्ता करने के लिए रेलवे ने देश के किसी माग से बन्दरगाहों तक श्रीर बन्दरगाहों से देश के श्रान्य उपयोग के केन्द्रों तक का किराया कम रखा। भारत में विदेशी सरकार की इस श्रुटिपूर्ण नीति से भारतीय उद्योग को ज्ञांत पहुँची श्रीर विदेशी उद्योगों को श्राधिक प्रोत्साहन मिला।
- (३) भारतीय रेलवे के कुछ भागों में किराये की दरें मीलों के आधार पर निश्चित की गईं और ब्लाक रेट की प्रणालो अपनाई गई अर्थात् एक रेल द्वारा कम दूरी तक माल ढोने पर प्रांत मील अधिक किराया वस्त किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि माल कुछ दूर ढोने के बाद दूसरी रेल से न ढाया जाय बल्कि लम्बी यात्राओं में उसी रेल का उपयोग करें। इसके परिणामस्वरूप व्लाक-रेट नीति से बचने के लिए सामान को आवश्यकता से अधिक दूर तक ले जाना पहता था। इससे लागत बढ़ती थी और यातायात के साधनों पर भी अनुचित मार पहता था।
- (४) एक ही सामान के लिए विभिन्न रेलों की विभिन्न टरें थीं। इससे व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामनों के माड़े की दरों में भी काफी अंतर था।

१६४८ में रेल के किराये तथा भाड़े की दरों की कुछ त्रुटियाँ दूर कर दी गई। किराया प्रति मील की दर से निर्घारित किया गया, साय ही श्रनाज, दाल, श्राटा श्रीर बीज इत्यादि की दर्रे निश्चित कर दी गई। इसके लिए सर्वप्रयम दूसरे समूह की रेलों—श्रासाम, ईस्ट इन्डिया, जी॰ श्राई॰ पी॰ श्रीर श्रो॰ टी॰ रेलवे—

में दर निश्चित की गई श्रीर तत्पश्चात् पहले समूह की रेलों में। दोनो समूहों में इस ग्रंतर का कारण यह या कि दूसरे समूह की रेलों की दरें पहले समूह की रेलों की श्रपेक्षा पहले से ही कम थीं श्रीर यदि दोनों समूह की रेलों की दरें एक साय बढ़ा दी जातों तो इससे श्रिक कठिनाई होती है।

रेल के किराये तथा माड़े की दरों में इस प्रारम्भिक परिवर्तन के पूरे हो जाने के बाद १ अप्रैल १९५२ को कुछ और परिवर्तन किये गये। दूरी के आधार पर किराये की दर निर्धारित करने की नीति त्याग दी गई। शेष दरों का प्रमाणी- करण हुआ और इस प्रक्रिया में उनमें वृद्धि की गई। लोहे और इस्पात उद्योग के लिए निश्चित विशेष दरों को खत्म करके नई संशोधित दरें लागू की गई जो स्टैन्ड तटकर की दर से कम रखी गई। दिल्लिण को चीनी के यातायात की रियायती दरें खत्म कर दी गई। कोयले के माड़े में ३० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई शौर यह कहा गया कि पहले की दर व्यय से बहुत कम थी। १९५५-५६ के बजट में माड़े की दरों में अन्य परिवर्तन किये गये। अन्न तथा खाद का प्रति गाड़ी माड़ा कम कर दिया गया तथा विभिन्न श्रेणियों का यात्रियों के लिये किराया ६०० मील से अधिक दूरी के लिये कम कर दिया गया श्रीर प्रथम ३०० मील की यात्रा का किराया बढ़ा दिया गया पर ३०१ से ६०० मील की दूरी के किराये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

इससे रेलवे की श्रमावश्यक हानि उटानी पड़ी जब कि रेलों द्वारा कुल जितने सामान का यावायात होता है उसका ४० प्रतिशत कोयला होता है। यह सुमाव दिया गया कि कोयले के भाड़े की दर श्रिषक होने से रेलवे को लाम होगा इससे रेलवे के हितों की रज्ञा होगी।

रेलवे भाड़ा पर जांच कमेटी—जो कमेटी जून १६५५ में नियुक्त की गई थो उसने १६५० के श्रारम्भ में सरकार को श्रपनी रिपोर्ट दी। सरकार के विचाराधीन होने के कारण श्रमी तक वह कार्यान्वित नहीं की गई है। कमेटी यह सिपारिश की है कि किराये की दरे निम्मतर श्रेणी से उच्चतम श्रेणी तक वृद्धिमान श्राधार पर होनी चाहिये। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सबसे सरल श्रीर संतोषप्रद ढंग श्राधार रूप में एक दर निश्चित करना श्रीर श्रन्य दरें इसी पर के प्रतिशत वृद्धि के श्राधार पर नियत करना होगा। इसके लिये कमेटी ने एक सामान्य दर जो कि मान द्रस्ट होगा नियत किया है जिसे (Class 100 rate) वंग १०० दर कहा जायगा। कमेटी ने वर्तमान वर्ग ह को सबसे श्रिषक सुविधाजनक समान्य (Norm) श्रीर श्रन्य वर्गों को इसके कपर तथा नीचे माना है। इसी प्रकार गाइी भर माल की दरे

भी १०० के नये वर्ग के आधार पर प्रतिशत श्रंकों में व्यक्त किये गये हैं। प्रत्येक वर्ग कित ने प्रतिशत होगा व्यक्त कर दिया गया है। प्रत्येक वस्तु के लिये गाडो-भर माल के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिये और साथ ही साथ छोटी मात्राओं (smalls) का भी वर्गीकरण होना आवश्यक है। कमेटी ने छोटी मात्रा में. माल की दरों में गाड़ी भर माल की दरों की अपेक्ता १५ से लगाकर ३६ प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी है। "

कमेटी ने यह मत दिया था कि (i) सीमा कर रह कर दिये जाने चाहिये पर नये दरों के बनाते समय इस बात को विचाराधीन रखना चाहिये, (ii) थोड़ी दूरी के लिये अतिरिक्त माड़ा वस्ताना अनुचित सममा जाना चाहिये; (iii) घाट सम्बन्धी और स्थान।न्तरण सम्बन्धी वस्ती बन्दी कर दी जानी चाहिये। (iv) भाडा वस्ताने की न्यूनतम दूरी २५ मील तक बढ़ा दी जानी चाहिये और चाहे माल एक रेल अथवा कई रेलों द्वारा ले जाया जाय एक ही बार उसकी बुकिंग होनी चाहिये; (v) माल गांडियों द्वारा भेजे जाने के लिये न्यूनतम वजन २० सेर होना चाहिये; अरि (vi) जो १ ६० १२ आ० प्रांत गाड़ी माल पर न्यूनतम समिलित वस्ती की जाती है बन्द कर टी जानी चाहिये।

कमेटी ने यह भी खिपारिश का है कि ३०० मील की दूरी की प्रथम सीढ़ी को भाड़े की दर नियत करने के लिये चार भागों में बाट देना चाहिये; जैसे १ से २५ मील तक, २६ से ७५ मील तक; ७६ में १५० मील तक; और १५१ से ३०० मील तक । स्पष्ट रूप से उसने यह खिपारिश की है कि "कर्मचारियों की यह निश्चित नीति होनी चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो सके थोड़ी थोड़ी दूरी के लिये रेल का प्रयोग न किया जाय वरन् अन्य परिवहन के साधनों का उसके स्थान प्रयोग बढ़े।"

इस बात को विचाराधीन रखते हुये कि (१) दरे लम्बी दूरी तक लेजाने वाले माल पर भार स्वरूप न हो, (२) उनमें सीमा सम्बन्धी तथा श्रन्य सम्बन्धों में जो वस्ती की जाती है सिम्मिलित हो; (३) श्राय श्रीर व्यय के बीच जो ३०० करोड़ रुपयों का व्यवधान है उनसे पूरा हो जाय। कमेटी ने निम्म दरों के लागू किये जाने की सिपारिश की है:—

. ,,					
	मील—		प्रतिमील प्रतिमन पा	।इयो की इ काई में द	रे
?	से २५	तक	३°६०	•	
२६	से ७५	तक	१ ° ४०	•	
७६	से १५०	तक	?'?	•	
१४१	से ३००	तक	१.०५		

मील	प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई से दरे		
३०१ से ५०० तक	,	्र ५	
५०१ से ⊏०० तक	•••	0.90	
८०१ से १२०० तक	•••	o <u>.</u> Ęo	
१२०१ से ग्रागे तक	•••	०.५०	

कमेंटी की सिपारिशें (i) रेलवे की भाड़े की दरों को सरल श्रीर सुगम बना देगी श्रीर इस प्रकार उनकी श्रानेकों जिटलतायें श्रीर श्रमंगतायें दूर हो जायँगी; (ii) उनसे रेलवे की श्राय में वृद्धि होगी जिसकी बहुत श्रावश्यकता है; (iii) रेलवे को इसमें श्रावश्यक सुविधा प्राप्त होगी श्रीर सहक द्वारा छोटी दूरी क परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु उद्योगों की उत्पादन लागत पर रेल के किराये का श्रत्यिक श्रीर श्रमुचित मार पड़ेगा। वर्तमान मूदा स्कीति की दशा में इससे हानि होगी। वाहर मेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में तो किराये की बढ़ी हुई दरें भारतीय माल की विदेशी बाजारों में स्पर्धा शक्ति ज्ञीण कर देगी जिससे विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के श्रीर भी श्रधिक बढ़ जाने का भय होगा।

जनवरी १९४८ में यात्रियों के लिए भारतीय रेलों में प्रति मील किराये की समान दर निश्चित की गई। परन्तु कुछ रेलों में किराये की दर कम थी। उसे भी अन्य रेलों की किराये की दर के समान ही कर दिया गया। १९५१ में रेल का किराया २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

१९५५-५६ के वजट में किराये की दरें निम्न प्रकार निश्चित की गई हैं

	पाइ प्रांत माल प्रति यात्री		
	११५० माल	१५१-३०० मील	३०१ मील श्रीर इससे श्रिधिक
एयर कन्डोशन श्रेणी	şγ	ź&	३२
प्रथम श्रेणी	₹⊏	१६	ર ધ્
द्वितीय श्रेणी (मेल/एक्छप्रेस)	११	१०३	٤ ٩
,, ,, (साधारग्)	£ 3	٤	
त्रितीय श्रेणी (मेल/एवसप्रेस)) ६ <u>°</u>	६	પૂ
,, " (साधारण)	પ્રજ	પ્ર	88

रेलों का पुनः संगठन करने से रेल के किराये तथा साढ़े में जो सुधार किया जा सका उससे (१) रेल का किराया निर्धारित करने का आधार सरल हो गया, (२) रेल की दरों में जो अञ्यवस्था फैली हुई थो वह दूर हो गई, और (३) रेलवे का विकास कर मकने के लिए श्रिषिक घन भी प्राप्त हुआ। रेल के किराये के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि सुधार करने से किराये श्रीर माड़े में कुछ वृद्धि कर दी गई है। इससे उद्योगों का उत्पादन व्यय बढ़ा है श्रीर यात्रियों तथा सामान के यातायात से प्राप्त होनेवाली श्राय घटी है।

रेलों की कार्य प्रगाली में दोष — फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्ध आफ कामर्स ऐड इन्डस्ट्री ने अपने स्मारक पत्र में मारतीय रेलवे कार्य प्रणाली के अनेकों दोषों और वृद्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था, जैसे गाड़ी के डिब्बों का न मिलना, बहुत दिनों तक माल के यातायात में प्रतिवन्त का लगाना, यातायात में अधिक समय लगना, थोड़े सामान के यातायात की सुविधा में अभाव, माल के डिब्बों की माँग करने और प्राप्त करने में समय का लम्बा ज्यवधान, कुछ जंकशनों में लाइनों का अभाव, बड़ी और छोटो लाइनों में परस्पर अदला बदली की सुविधाओं का अभाव, कुछ रास्तों में लाइनों का अभाव, मार्ग में माल का चोरी होना और खो जाना या चोरी हुए माल की हानि निश्चित करने में अधिक देर लगना, और कर्मचारियों को कार्यज्ञमता में सामान्यतः अभाव इत्यादि। इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या तो यह है कि कृषि और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार रेलवे की सुविधा कम है। इस देश में आर्थिक ज्यवस्था विकासोन्मुख है, यहाँ कृषि एवं उद्योगों के उत्यादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है और वर्तमान यातायात सुविधाय पूर्णक्षेण अपर्याप्त हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में निम्न सिकारिश की है।

- (१) रेलवे के विस्तार श्रीर सुवार के लिए ४०० करोड़ रुपयों का प्रयम पंचवर्षीय योजना में नियत करना अपर्याप्त था और कम से कम १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष श्रीर श्रिधिक नियत करना चाहिये था। इस प्रकार द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत १४८० करोड़ रुपये व्यय किये जाने की माँग रेलवे बोर्ड ने की थी जिसे योजना आयोग ने घटा कर ११२५ करोड़ रुपये कर दिया है। यह घन भारतीय रेलवे की श्रावश्यकता के श्रनुसार पर्याप्त न होगा।
- (२) प्रथम योजना में रेलवे के वर्तमान सामान की मरम्मत पर श्रिषक जोर दिया गया था जो गत बीस वर्षों से बदले मी नहीं गये। यद्यपि यह बहुत श्रावश्यक है, फिर भी श्रव श्रिषक ध्यान रेलवे के विस्तार पर दिया जाना चाहिये। विस्तार इतना होना चाहिये कि न केवज यातायात की श्रावश्यकतार्ये ही पूर्यों हो सकें, वरन मिवज्य में बढ़ी हुई श्रावश्यकता को भी पूरा कर लेने की पर्याप्त शक्ति हो। यद्यपि द्वितीय योजना में श्रिषक जोर विस्तार पर दिया गया है फिर भी यह श्रयप्ति है।

- (३) रेलवे के कार्य करने की जमता में वृद्धि होनी चाहिए। देश के श्रीवोगीकरण में पोत्साहन देने के लिये श्रावश्यक है कि रेल द्वारा यातायात की मुविद्या सस्ती हो। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि रेलवे का चाल व्यय कम हो। भारतीय रेलवे की कुल किराये भाड़े से प्राप्त श्राय १९४८ की २१३ करोड़ रुपयों से बढ़कर ४०७ ४८ करोड़ रुपये १९५८ के बज़ में श्रातमान की गई है। कुल व्यय १७३ करोड़ से बढ़कर २६८ ३५ करोड़ रुपये हो। गया है। इससे वह पता लगता है कि बढ़ी हुई श्राय का श्राधकांश व्यय की वृद्धि में प्रयुक्त हुश्रा है श्रीर यह सम्भव है कि किराया श्रीर भाड़ा घटाया जा सके।
- (४) माल के यातायात में सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे अस्थायी उपायों से कार्य लेना चाहिए जैसे मुकामा घाट, आगरा और सोवरमती और अन्य स्थानों पर मशीनों द्वारा माल को स्थानान्तरित करना, कन्वेथर प्रणालों का प्रयोग करना और मुगलसराय वाल्टेथर, भागलपुर आदि जंकशनों पर माल की गाहियों की अदला-बदली की गांत में तीव्रता लाना क्यों कि इन स्थानों पर बड़ी भीड़ रहती है। जिन रास्तों पर लाहनों के अभाव के कारण किटनाई हो जाती है वहाँ अधिक लाहनों का खेलना और विशेष प्रकार के माल के डिन्बों की संख्या बढ़ाना।
- (५) ज्यापारियों को मार्ग में माल के चोरी हो जाने श्रीर खो जाने श्रीर बहुत देर में हानि मिलने के कारण बहुत कठिनाई उठानी पहती है। रेलवे ज्यवस्था को इस प्रकार की सभी हुई चोरियों के रोकने श्रीर रेलवे कर्मचारियों की श्रसावधानी श्रीर चरित्रहीनता के कारण गाड़ी में माल के जाने की रोक थाम के लिये विशेष प्रयनशील होना श्रावश्यक है। हानि जल्दी चुकाने के उपायों को भी सोचना श्रावश्यक होगा। विभाग का विकेन्द्रीय करणा करना, कुल माल के खो जाने पर हानि तुरन्त चुकाना, इस दशा पर कि यदि एक वर्ष के भीतर ही भीतर माल मिल गया तो पाया हुशा हर्जा रेलवे को वापिस दे देवें। ऐसी क्ले मस एडवाइसरी कमेटी की स्थापाना करना जिसके सदस्य उन उद्योगों श्रीर ज्यापारों के प्रतिनिधि हो जो क्लेंग्स विभाग के कर्मचारी से सम्मन्धित है श्रादि कुछ ऐसे उपाय है जिनके प्रयोग में लाने से रेलवे के दोष मिट सकते हैं।

रेलवे के कर्मचारी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि रेल के कार्य प्रणाली की समता बढ़ जाय श्रीर सुविधार्य भी बढ़ जाँय, माल की सघी चोरियों श्रीर उनके खोने पर रोक थाम करने के लिए रेलवे करपशन इनक्वारी कमेंटी की नियुक्ति की गई है जो शीष्ट्र ही श्रपनी रिपोर्ट सरकार के समंज्ञ उपस्थित करने वाली है। रेलवे के चालू व्यय पर रोक थाम में सहायता करने के लिये

स्त्रीर रेलवे का विकास करने के लिए, विकास में वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करने के लिये तथा बड़ी-बड़ी योजनास्त्रों को कार्यान्वित करने के लिये, जिन्हें पंचवर्षीय योजना के स्नन्तर्गत रेलवे को पूर्ण करना है, रेलवे बोर्ड की सदस्य संख्या चार के स्थान पर पाँच कर दी गई है।

योजना के अन्तर्गत-प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४०० करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताय रेलवे के नये सामान के क्रय करने तथा पुराने की भरम्मत के के लिये किया गया था। वास्तव में यह आशा की जाती है कि प्रथम योजना के समाप्त होने तक लगभग ४३२ करोड़ रुपया व्यय हो जायगा। गन्त्रयानादि ग्रीर भ्रीर सर्वाग सयंत्र पर व्यय प्रस्तावित घन से बहुत अधिक हो गया है। गन्त्रया-नादि पर श्रिधिक व्यय होने के कारण यात्रा श्रीर दुलाई १९५३-५४ श्रीर १९५४-५५ के बीच साढ़े आठ प्रतिशत बढ़ गई और आशा की जातो है कि योजना के आंन्तम वर्ष में नी प्रतिशत बढ़ जायेगी। प्रथम योजना के आरम्भ के समय रेलदे के पास ८२०६ इन्जन, १६२२५ यात्रियों के डिब्बे और २२२४४१ माल के हिन्दे थे। इनमें से २११२ इन्जन, ७०११ यात्रियों के हिन्दे और ३६५८४ माल के डिब्बे पुराने थे। प्रथम योजना में १०३८ इन्जनों श्रीर ५६७४ यात्रियों के डिब्बे श्रीर ४६१४३ माल के डिब्बों के क्रय करने का प्रबन्ध किया गया था। वास्तव में उपर्युक्त संख्या से कुछ अधिक इन्जन श्रीर माल के हिन्ने श्रीर कुछ कम यात्रियों के डिब्बे प्रथम योजना के अन्तर्गत क्रय किए जा सर्वेगे। इतनी अधिक मरम्मत श्रोर नये सामान के क्रय किए जाने के पश्चात् भी भारतीय रेलवे का सामान बहुत पुराना श्रीर पुराने ढंग का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रारम्भ में Eरहर इन्जन, २३७७E याधियों के बिब्बे श्रीर २६६०४E माल के डिब्बे काम में श्राते हुये होंगे जिनमें से २८१३ इन्जन श्रीर ६३०५ यात्रियों के डिब्बे श्रीर ४९५६८ माल के डिब्वे बहुत पुराने विसे हुये होंगे और उनके स्थान पर नये लाने त्रावश्यक होंगे। इससे यह पता लगता है कि रेलवे के विस्तार की इतनी श्रावश्यकता होते हुये भी उनकी मरम्मत श्रीर उनके स्थान पर नये सामान लाने की जरूरत बहुत बड़ी है।

का जरूरत बहुत वहा है।

हितीय योजना के अन्तर्गत ११२५ करोड़ क्यया भारतीय रेलवे पर व्यय
हितीय योजना के अन्तर्गत ११२५ करोड़ क्यया भारतीय रेलवे पर व्यय
किया जायगा जिसमें से ७५० करोड़ सामान्य आय में से, २२५ करोड़ रेलवे के
अवद्यर्ग कीव से, १५० करोड़ रेलवे की आय से पाप्त होगा। रेलवे बोर्ड के
अवद्यर्ग कोव से, १५० करोड़ रेलवे की अपस्ताव के, स्थान पर ११२५ के का
१४८० करोड़ क्यये के व्यय किये जाने के प्रस्ताव के, स्थान पर ११२५ के व्यय किया जायगा।

दितीय योजना में १६०७ मील के रंकाथ के दुगने किये जाने का, २६५

छोटी लाइन को बढ़ी लाइन में परिवर्तित कर देने का, लगभग ८२६ मील तक विजली पहुँचाने, १२६३ मील तक पीडच्चाल्स सुविधा देने का, ८४२ मील नई लाइन विछाने, २००० मील लाइन की मरम्मत करवाने छोर २२५८ इन्जनों को क्य करने तथा ११३६४ यात्रियों के डिन्बों छीर १०७,२४७ माल के डिन्बों को क्य करने का छायोजन किया गया है।

भारतीय रेलवे १२ करोड़ टन माल के ढोने के स्थान पर १६५५-५६ में ११ करोड़ ५० लाख टन माल ढोयेगी और इस प्रकार ५० लाख टन माल के ढाये जाने की कभी रह जायेगी। यदि द्वतीय योजना के अन्त तक जो ६ करोड़ २ लाख टन माल के ढोये जाने की आवश्यकना बढ़ जायेगी उसका विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि १६६०-६१ तक १८ करोड़ ८ लाख टन के ढोये जाने की आवश्यकता होगी। ऐसा भय है कि जितना घन रेलवे के विकास के लिये नियत कर दिया गया है उसके प्रयोग से रेलवे इतना माल न ढो सके और जिन नुविधाओं के प्रदान करने का इराटा किया गया है वे आवश्यकता से १०% गन्त्रयानादि के सम्बन्ध में और ५% अपनी शक्ति के सम्बन्ध में कम कर देनी पड़े।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर योजना आयोग के मतानुसार (मई १९५८) "जो कार्यकम ११२५ करोड़ कार्यों के ज्यय का बनाया गया था उसमें अब मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण १०० करोड़ रुग्यों के श्लीर अधिक ज्यय होने का अनुमान किया गया है। इस समय ११२५ करोड़ रुप्यों की मात्रा वृद्धि जा नहीं सकती। इसिलये रेलवे को योजना के अन्तर्गत कुछ विकास योजनाओं को स्थागत करना पड़ेगा। विदेशी विनिमय की किटनाइयाँ मी इसका एक कारण होगी। जिन विकास योजनाओं को स्थागत करने का इरादा है वे (१) तम्बाराम विल्युएस होत्र तथा कलकत्ते के अन्तर्गत सियालदा होत्र में विजली पहुँचाने की योजना; (२) मीटर गेज कोच फैक्ट्री (३); इन्टोगरल कोच फैक्ट्री के प्रसाधन विमाग तथा (४) गुना और उन्जीन के वीच नई रेल के लाइन बिछाने की योजनायें हैं।"

"श्राने ध्येय को पूरा कर लेने के प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है यह श्राशा की जाती है कि १६६०-६१ तक रेलवे ४२० लाख टन माल टोकर श्रातिरिक्त श्राय प्राप्त कर सकेगी। पर क्या यह श्राय पर्याप्त होगी। निश्चित रूप से कृहा नहीं जा सकता। विदेशी विनिमय तथा श्रम्य किठनाइयों के कारण विकास योजनाश्रों के कार्यान्वित करने में ढील देने के कारण दुलाई की मात्रा योजना के श्रान्तिम वर्ष तक श्रारम्भ में किये गये श्रमुमान से जो कि ६१० लाख टन था कम

हो जायगी पर हो सकता है कि ४२० लाख टन से अधिक हो। कुछ भी हो योजना में की गई रेल द्वारा माल ढोने की मात्रा के अनुमान में कुछ परिवर्तन तो अवश्य ही होगा। जहाँ तक यात्रियों के ढोने के च्येय से सम्बन्ध है—अर्थात् ३ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि—वह सम्भवतः पूरी हो जायगी। १६५५-५६ की अपेक्षा १६५६-५७ में रेल के यात्रियों में प्रतिशत वृद्धि ६% हुई थी। अगर यही रही तो रेल में भीइ की समस्या और भी अधिक खराब हो जायगी।"

दितीय योजना में भारतीय रेलवे की माल ढोने श्रीर यात्रियों के श्रानेजाने की शक्ति में वृद्धि की न्यवस्था की गई है। परन्तु वृद्धि देश की श्रावश्यकता
से बहुत कम सम्भय हो सकेंगी। केवल सरकार को ही नहीं वरन् जनता को भी
श्राधक मात्रा में यातायात की सुविधा की श्रावश्यकता पड़ेगी। प्रथम योजना में
भी जनता को यातायात की सुविधा में कमी का श्रानुमव हुश्रा था। दितीय
योजना में तो स्थिति श्रीर भी खराब होगी। रेलवे के सम्बन्ध में यही सर्व प्रधान
श्रालोचना है। विदेशी विनिमय की कठिनाइयों तथा मूल्यों में वृद्धि होने पर भी
योजना में रेलवे के विस्तार के प्रति ध्यान श्राधिक रखना चाहिये था श्रीर व्यय
के लिये श्राधिक धन नियत करना चाहिये था।

श्रध्याय ३४

सङ्क यातायात

भारत में सहकों का बहुत अभाव है। १६०० में सहकों की लम्बाई कुल १,७६,००० मील थी और १६५२ में २,५६,००० मील थी। प्रथम योजना के अन्त तक कुल सहकों की लम्बाई बहुकर ३१६,००० मील हो। गई जिसमें से १२१,००० मील पक्की सहक थी। इनमें से केवल है भाग पक्की सहकों हैं और शेप कच्ची। एक ऐसे देश में जिसका चेत्रफल १,१३६,००० वर्ग मील है, जिसकी जनसंख्या लगमग ३५ करोड़ ७० लाख है और जिसके उद्योग तथा कृषि का काफी चिकास हो चुका है २६५,००० मील सहकें बहुत कम हैं। आरत में प्रति वर्ग मील में बहुत ही कम सहकें हैं, अन्य देशों की तुलना में यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। भारत के प्रति वर्ग मोल चेत्रफल में सहकों की लम्बाई ०.२ है जब कि इन्गलैयड में २.०, वेल जियम में ३.३, फ्रांस में २.४ और अमरीका में १९ है।

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देश के आधिक विकास में सहकों का विशेष महत्व है। खड़कें होने से ही प्रामों से कच्चा माल ग्रीर कृषि उत्पादन कारखानों, कस्वो श्रीर नगरों तक पहुँचाया जाता है श्रीर बन्दरगाहों तथा कारखानी से माल यामों तक मेजा जाता है। देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियों के लिए सड़कें यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं। सड़कों की सुविधा से ही व्यक्ति एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान काल में परस्पर सम्पर्क स्थापित करने के लिए यातायात के द्रुवगामी साधनों की ओर अच्छी सङ्कों की अत्यन्त आव-रुएकता है। रेलों तथा विमाना की सहायता से देश के बड़े-इड़े नगरों श्रीर व्यापारी केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है परनतु देश के दूर-दूर के स्थानों तक पहुँचने के लिए श्रीर उनका लाम उठा सकने के लिए श्रव्छी सङ्कों का होना श्रात्यन्त श्रावश्यक है। युद्ध के समय यदि सङ्कें श्रच्छी हैं तो सेना को शीघ एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है, युद्ध-सामग्री आवश्यक स्थानों तक पहुँचाई जा सकती है और इस प्रकार देश की शत्रु के त्राक्रमण से रहा की जा सकती है। वास्तव में भारत की कुछ प्राचीन बड़ी सड़कें इसी उद्देश्य से बनाई गई थों। यदि देश में श्रव्छी सहकों का जाल विद्या हो तो उसका शांतिकाल में तथा युद्ध के समय हर स्थित में विशेष महत्व होता है।

श्रतीत में दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ते से मद्रास, मद्रास से वम्बई श्रीर यम्बई से दिल्ली को मिलाने वाली चार बड़ी सहकों के चारों श्रीर छोटी बड़ी सहकों का जाल फैला हुआ था। इन चार बड़ी सहकों को बारहों मास कार्य में नहीं लाया जा सकता है। पुल न होने के कारण श्रीर टूट-फूट तथा सामान्यतया स्थित खराब होने से इन सहकों का बरसात में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन बड़ी सहकों को देश के ग्रामों से मिलाने वाली प्रदेशीय सहकों तथा अन्य छोटी-छोटी सहकों की स्थिति श्रीर भी खराब है।

देश की ब्रान छन्से नही श्रावश्यकता यह है कि सहकें बहाई जायँ। राष्ट्रीय सहकें वर्तमान समय की भांति केवल पूर्व से पश्चिम तक के चित्र में ही न फीलें वरन इनका प्रसार उत्तर से दिन्ण तक भी किया जाय। इसके साथ ही इन सहकों को श्रीर प्रदेशीय तथा श्रन्य छोटी सहकों को सभी श्रृतुश्रों में कार्य में लाने योग्य बनाने की श्रावश्यकता है। मोटर यातायात के लिए भी कुछ सहकों का होना श्रावश्यक है। इसके लिए सहकों के मोइ सुगम होने चाहियें, जहाँ से सहक निकाली जाय वह भूमि पक्की होनी चाहिए श्रीर सहकों को कंकर तथा हामर या सिमेंट के प्रयोग से पक्का बनाना चाहिए। इन सहकों की सतह को चिकना होना चाहिये। इसके साथ ही वैलगाहियों तथा यातायात के श्रन्य साथनों के लिए भी ऐसी सहकों होनी चाहियें जो मोटर की सहक की भाँति श्राधक क्यथशील तो न ही परन्तु ऐसी हो जिनको वर्ष भर प्रयोग में लाया जा सकता है। यह बहुत श्रावश्यक है कि सहकों के निर्माण की सुसम्बद योजना निर्माण की जाय जिसमें बड़ी राष्ट्रीय सहकों को विशेष सहकों श्रीर मामों इत्यादि को भिलाने वाली छोटी-छोटी सहकों को विशेष महत्व दिया जाय।

भारत में चढ़कों के विकास की श्रीर बहुत कम ध्यान दिया गया है, इसके कई कारण हैं:—(१) सरकार ने श्रीर स्थानीय संस्थाशों ने सड़कों के विकास का महत्व नहीं समका। नगर पालिकाश्रों श्रीर जिला बोडों की देख-रेख में श्रनेक सड़कों हैं परन्तु इन संस्थाश्रों ने सड़कों के विकास की श्रोर उचित ध्यान नहीं दिया। प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने भी श्रन्य विकास कार्यों को इसकी श्रपेत्ता प्राथमिकता दी है। इधर कुछ वर्षों से ही सड़कों के विकास की श्रावश्यकता श्रीर इसके महत्व की श्रोर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान गया है श्रीर दोनों सरकारों ने इसके लिए योजनाएँ बनाई हैं, (२) सड़कों के निर्माण के लिए श्रावश्यक बहुत प्रकार के सामान श्रीर मशीनों का भारत में श्रमाव है श्रीर इनका श्रायात करने के लिए हमें विदेशों पर निर्मर करना पड़ता है। श्रव भारत में सिर्मेट तथा सड़क-निर्माण के श्रन्य समानों का उत्पादन होने लगा है साथ

हीं महक कूटनेवाले, भाप से चलनेवाले इखनों तथा ढिजिल इखनों का भी भारत में उत्पादन श्रारम्भ हो गया है परन्तु फिर भी एटफाल्ट के लिए विदेशों पर ही निर्भर करना पड़ता है। श्राशा है कि पेट्रोल शोधशालाश्रों का निर्माण पूरा हो जान पर देश की श्रावश्यकता पूर्ण करने के लिए एसफाल्ट प्राप्त हो जायगा; (३) देश में वित्त का श्रमाव है। नगर पालिकाश्रों श्रीर जिला बोडों की देख-रेख में जो सड़कों हैं वह वित्त के श्रमाव के कारण श्रच्छी दशा में नहीं रह पातीं। राज्य सरकारों के पास विकास के लिए कोष है परन्तु उनका उपयोग सड़कों के निर्माण में कम श्रीर श्रन्य कार्यों में श्रिधिक किया गया है। यही स्थित केन्द्रोय सरकार की भी है।

सड़क कोप—सड़क विकास समिति (१६२७) की सिफारिश पर १६२६ में सड़क विकास कोष स्थापित किया गया और प्रति गैलन पेट्रोल पर कर ४ आने से बढ़ाकर ६ आने कर दिया गया जिसमें से प्रति गैलन दो आना सड़क विकास कोप में जमा किया गया। बाद में पेट्रोल पर आतिरिक्त कर लगाकर सड़क विकास कोप में दो आने की जगह ढाई आना जमा किया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश सड़क विकास कोप के धन का उचित उपयोग नहीं किया गया है। सड़क विकास कीष स्थापित हो जाने के बाद राज्य सरकारों ने अन्तर-राज्य तथा अन्तर-जिला सड़कों के विकास में स्वयं अपने बजट से व्यय कम कर दिया। इसके साथ ही आमों को मिलाने वाली छोटी-छोटी सड़कों को अपने माग्य पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार सड़क विकास कोष निमाण का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया। सड़कों का विकास हरने के लिए उपलब्ध साधनों में अपनी ओर से सहायता देने की अपेद्धा राज्य सरकारों ने अपने व्यय में कटौती कर दी।

भारत वरकार ने वड़क विकास कीप के घन को व्यय करने में कुछ, प्रतिवन्ध लगा दिये। सरकार ने यह व्यवस्था की कि (१) इस कोष का घन सड़कां के निर्माण तथा सुधार में और पुलों के निर्माण तथा सुधार में व्यय किया जाय परन्तु इस कीप का वर्तमान सह कों की मरम्मत और देखमाल में उपयोग नहीं किया जा सकता है, और (२) सड़क विकास कीप में राज्य के योगदान का कम स कम २५ प्रतिशत छोटी-छोटी सड़कों में व्यय किया जाय और उन सह कों पर २५ प्रतिशत ते अधिक व्यय न किया जाय जो रेल मार्ग की प्रतियोगी हैं। यह सब होते हुए मी यह सत्य है कि सह क विकास कोष से प्राप्त होने वाला धन आवश्यकता से कम है और १६५०-५१ के अंत तक २० करोड़ रुपयो व्यय किया जा जुका था। १६५१-५२ से दिसम्बर १६५५ तक २७ करोड़ रुपयो व्यय किया जा जुका था।

योजनात्रों को स्वीकृति दी जा चुकी थी श्रीर मार्च १९५५ तक लगभग १२ करोड़ रूपया उनके कार्यान्वित करने में न्यय किया जा चुका था।

सरकार अपनी वर्तमान आय में से सड़कों के निर्माण में पर्याप्त व्यय नहीं कर सकती है साथ ही इस कार्य के लिए सहकों का उपयोग करने वालों पर. लगाए गये करों से भी पर्याप्त आय नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सङ्कों के निर्माण के लिए ऋग लिया जाय। यह सीचना विल्क्षल निरर्थक है कि सहकों पर ज्यय किये जाने वाले रुपयों से प्रत्यज्ञ का में ऐसी श्राय नहीं: होती है जिससे इस कार्य के लिए उपलब्ध ऋषा का ब्यान चुकाया जा सके. इसलिए यह व्यय अनुत्रादक है और इसकी नहीं करना चाहिए। यह संभव है कि सहकों के विकास से प्रत्यज्ञ रूप में कोई आय न हो परन्तु इससे निस्सन्देह देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और साथ ही जनता की कर देने की शक्ति में वृद्धि होती है। भारतीय सङ्क एवम् यातायात संघ ने कुछ वर्ष पहले एक जाँच की जिससे पता चला कि एक विशेष चेत्र में सहक का विकास करने से १२ लाख रुपये का वार्षिक लाभ हुन्ना जब कि सहक निर्माण में तथा उसकी देखभाल में केवल ४३ लाख रपया वार्षिक व्यय किया गया । इससे स्पन्ट है कि सहको पर व्यय किये गये प्रति १०० रुपयों पर जनता को २७७ रुपये का लाभ होता है। सङ्कों के विकास से जनता समृदिशाली वनती है, सरकार की आय में वृद्धि होती है, इस्लिए ऋगा लेकर सहको पर निर्माण करने में किसी प्रकार की छापति नहीं होनी चाहिए।

नागपुर योजना—१६४३ में विभिन्न राज्यों के मुख्य इङ्गीनियरों की नागपुर में एक वैठक हुई श्रीर देश की न्यूनतम श्रावश्यकताश्रों को श्यान में रखते हुए एक सड़क निर्माण-योजना निर्माण की गई। इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि इसके पश्चात भारत में सड़कों के निर्माण की सभी योजनाश्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। नागपुर योजना में सड़कों को चार श्रीणयों ने विभक्त किया गया है:—(१) राष्ट्रीय सड़कों, (२) राज्य की सड़कों, (३) जिलों की वड़ी छोटी सड़कों श्रीर (४) मामों का सड़कों। योजना में इन चार प्रकार की सड़कों का १० वर्ष के श्रान्दर सुनियोजित श्रीर सुसम्बद्ध श्राधार पर विकास करने का सुकाव दिया गया था जिससे पक्की सड़कों की लम्बाई लगभग ६६,४०० मोल से १,२२,००० मील तक श्रीर श्रान्य सड़कों को लम्बाई १,१२,००० से २,०७,५०० मील तक बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही योजना में वर्तमान सड़कों में सुधार करने का मी सुकाव दिया गया। नागपुर योजना का उद्देश्य यह था कि विकरित इिष चेत्र का कोई भी ग्राम मुख्य सड़क से ५ मील से श्रीषक दूर न पड़े श्रीर काई

मी गाँव चाहे कहीं हो सड़क से २० मील से अधिक दूर न पड़े। इस योजना के अनुसार युद्ध पूर्व के मूल्यों में ५० प्रतिशत वृद्धि के आधार पर निर्माण-कार्य में ३७२ करोड़ रुपया लगेगा जिसमें से ६६.५ करोड़ रुपया राष्ट्रीय सड़कों पर और ३०५.५ करोड़ रुपया अन्य सड़कों पर व्यय किया जायगा। यदि मूल्य युद्ध पूर्व के स्तर से २०० प्रतिशत बढ़े मान लिये जावें जिससे व्यय का अनुमान वर्तमान समय के मूल्य के अधिक निकट आ सके तो, जैसा कि योजना-आयोग ने बताया है, नागपुर योजना को कार्यान्वित करने में कुल ७४४ करोड़ रुपया व्यय होगा जिसमें से १३३ करोड़ रुपया राष्ट्रीय सड़कों के लिए और ६११ करोड़ रुपया अन्य सड़कों पर व्यय किया जायगा।

रेल मार्ग से सम्बन्ध—भारत में सहकें अपर्याप्त होने श्रीर सहकों की िर्धात दोप पूर्ण होते हुए भी १६३० के श्रासपास सहक यातायात से रेलवे को गहरी प्रांतयोगिता का सामना करना पड़ा। निजी वस सर्विसों की श्रीर रेल की श्रेपेक्ता श्राधक यात्री श्राक्षित हुए जिसमें श्राधिकतर कम श्राय वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही हलके सामान को लाने लेजाने के लिए भी मोटरों को सुविधाजनक समक्ता गया। मोटर यातायात प्रायः श्रीर सुगमता से हो जाता है इससे रेल को गहरी हानि उठानी पड़ी। अनेक रेलवे जाँच समितियों ने रेलवे तथा सहक याता-यात की प्रतियोगिता पर विचार किया श्रीर रेलवे को सहक की प्रतियोगिता से रज्ञा करने के श्रनेक सुकाव दिए। रेलवे ने सस्ते वापसी टिकटों के रूप में रियायत देनी श्रुरू कर दी, कुछ विशेष समय के लिये टिकट दिये, श्रच्छी सर्विस श्रीर कम किराये की व्यवस्था की। परन्तु इससे प्रतियोगिता का जोर कम नहीं हुआ श्रीर यह श्राशंका की जाने लगी कि सहक यातायात हो रेलवें को गहरी इति पहुँचेगी।

रेलवे के हितों की रज्ञा करने के लिए सरकार ने अनेक उपायों का आश्रय लिया और १६३६ में मोटर गाड़ी कान्न लागू किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि सभी मोटरों तथा वसों के लिए लाइसेन्स लिया जाय । कान्न में बसों को रखने तथा अधिक यात्री न बैठाने और वसों की चाल इत्यादि पर नियंत्रण की शतें माननी अनिवार्य कर दी गईं । बसों का वीमा आवश्यक कर दिया गया। इस कान्न से यात्रियों के हितों की रज्ञा के साथ ही हानिकारक प्रतियोगिता को रोकने का प्रयत्न करके रेलवे के हितों की रज्ञा की भी व्यवस्था की गई। परन्तु सदक यातायात की ओर से प्रतियोगिता प्रचलित रही और १६४६ में इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए एक त्रिदलीय संगठन का निर्माण करने की नीति अपनायी गई। इस संगठन में मोटर मालिकों, राज्य सरकार और रेलवे

के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। परन्तु इस योजना को आशा के अनुक्ल सफलता नहीं मिली। बाद में भारत सरकार ने सङ्क यातायात काणेरेशन कानून (१६४८) लागू किया निसके स्थान पर १६५० में एक और व्यापक कानून लागू किया गया।

वर्तमान में रेल श्रीर सहक की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है क्योंकि (१) यातायात का श्रमाव है श्रीर वर्तमान समय में रेल श्रीर मोटर यातायात को साथ साथ कार्य करके लाम उठाने का काफी श्रवसर है; (२) कुछ तो सरकार के प्रतिबन्धों के कारण श्रीर कुछ मोटरों के तथा उनके विभिन्न-कल-पुनों के मूल्य श्रिषक होने से सहक यातायात का व्यय बढ़ गया है; श्रीर (३) श्रनेक राज्यों में यातायात का राष्ट्रीकरण कर देने से रेलवे तथा रोडवेज में श्रिषक उचित समन्य स्थापित हो गया है।

राज्य द्वारा सचालित सङ्क यातायात के च्रेत्र निश्चित हैं श्रीर मोटरें यात्रियों तथा सामान को उसी च्रेत्र के श्रम्दर लाती ले नाती हैं। इस बात पर महत्व दिया गया है कि यातायात इस प्रकार संचालित किया जाय निससे रेल-सहक यातायात का सुसम्बद्ध विकास हो। यातायात इस प्रकार नियोजित हो कि यात्रियों तथा सामान को रेलवे केन्द्रों तक पहुँचाया जाय जहाँ से श्रामे का यातायात रेलवे सँमालेगी। जहाँ तक रोडवेज का सम्बन्ध है यात्रियों को दी जानेवाली सुविधाएँ बढ़ी हैं, श्रधिक भोड़-भाड़ पर नियंत्रण रखा गया है श्रीर गाड़ियाँ श्रच्छी दशा में रखी गई हैं।

यह योजना १६४६ में बम्बई में प्रारम्म की गई श्रीर १६४८ से १६५० तक ढाई वर्ष में यातायात के मार्गों की संख्या द से ४६५ तक बढ़ गई। श्रारम्म में २४० मील तक यातायात की व्यवस्था थी। १६५० में यह व्यवस्था १५,०३६ मील तक फैल गई श्रीर १६४८ से १६५० तक क्रमशः कुल १,०८,७७२ श्रीर २,६१६,२४७ मील के बीच यातायात किया गणा। इसके बाद के वर्षों में इस दिशा में प्रगति धीमी रही है परन्तु सभी हृष्टकोणों से रोडवेज ने उत्ति की है। उत्तर प्रदेश में १६४७-४८ में ३१ सरकारी रोडवेज सर्विसे चालू हुई जो १६५५-५६ में ३३७ हो गई। यह यातायात व्यवस्था ६,००० मील तक फैली हुई है। यह श्रनुमान लगाया गया है कि कुल १०,००० मील के चित्र में यात्रियों के यातायात का राष्ट्रीकरण करने में २,३०० वर्षों की श्रावश्यकता होगी। द्वितीय भोजना के श्रन्तगंत इस यातायात सुविधा का विस्तार ६६६४ मील हो जायगा श्रीर उसमें १६०० वर्षे होंगी।

बम्बई में राजकीय रोडवेज ने द से ६ पाई प्रति मील किराया वस्त

किया। इससे पहले इस द्वेत्र में किराये की यही दर वस्ली गई थी, परन्तु गुजरात में भोटर-मालिकों ने रेलवे की प्रतियोगिता में किराया कम वस्ता था। वस्वई में यद्यपि किराया कम नहीं किया गया है परन्तु रोडवेज की सविस में निस्सन्देह काफी सुधार हुआ है श्रीर जनता को राष्ट्रोकरण से पहले की श्रपेका अधिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है रोडवेज का अपर तथा लोग्रर बलास का किराया अवटूवर १६५२ में क्रमशः ६ पाई श्रीर ७ई पाई से बढ़ाकर १०३ पाई श्रीर पाई प्रति मील कर दिया गया। किराये में वृद्धि करने का उद्देश्य मोटर इत्यादि के कल-पुर्जों तथा श्रन्य सामानों की बढ़ी मृल्यों को पूर्ण करना था। परन्तु चूँकि केन्द्रीय कारखाने स्थापित कर देने से मरम्भत इत्यादि में पहले की अपेज्ञा कम न्यय करना पढ़ता है इसलिए १९५३ में किराये में कमी कर दी गई। अब किराये की दर अपर क्लास के लिए १०३ पाई मित मील से घटाकर ६ पाई मित मील कर दी गई और लोग्रर यलास के लिए किराये की दर प्रपाई से घटाकर ७३ पाई कर दी गई। अवत्वर १९५२ से पहले किराये की यही दर थी। लोक्चर क्लांच का किराया अब भी रेल के तीसरें दर्जें के किराये से श्राधिक है। रेल में तीसरे दर्जे का १५० मील का किराया यदि डाकगाड़ी या एवसप्रेस से सफर किया जाय तो ६० पाई प्रति मील है स्रोर यदि सामान्य गाड़ी से रुफ़र किया जाय तो दर ५३ पाई प्रति मील है परन्तु आशा की जाती है कि भविष्य में रोडवेज किराया और घटायेंगी।

राजकीय रोडवेज प्रणाली सन्तोषजनक रीति से चल रही है परन्तु (१) गाड़ियों को रखने तथा मरम्मत इत्यादि करने का ज्यय अधिक है और रोडवेज को उतना लाम नहीं होता है जितना की आशा थी। (२) अभी कुछ दिशाओं में यात्रियों को और अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। परन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि रोडदेज ने सड़क यातायात की अवस्था में काफी सुधार किया है और भारत में रोडवेज यातायात स्वयस्था का प्रसार करने के लिए कोई बाधा नहीं है।

निजी उद्योग की कठिनाइयाँ—मारत के सहक यातायात के विकास
में श्रानेको कारणों से बाघायें पहुंची हैं: (१) मोटर गाड़ियों को बहुत श्राधक'
कर देना पड़ता है जिससे व्यक्तियों की इस कार्य को करने की शक्ति टूट जाती
है। मोटर गाई। कर जाँच कमेटी ने यह बात नहीं थी कि भारत में मोटर
गाड़ियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों पर संसार भर में सब से श्राधक कर
लगाया जाता है। इसी रिपोर्ट के श्रानुसार प्रत्येक लारी पर प्रति वर्ष कुल कर
मद्रास में ६,०७७ कपये, वस्तई में ५,००० कपये से लगा कर ५,२५८ क० तक

श्रीर श्रन्य राज्यों में श्रीसत कर लगभग ५,१३४ ६० था। इस कमेटी ने यह भी श्रनुमान लगाया था कि माल ढोने वाली लारियाँ केन्द्रीय श्रीर स्वदेशीय ताल्यों को जितना कर देती हैं, (स्थानीय करों को छोड़ कर) यदि वे २० हजार मील से श्रिषक यात्रा करती हो तो वह रेल द्वारा प्रति टन प्रति मील दुलाई के श्रीसत किराये से सी प्रतिशत श्रिषक था। पिछले तीन वर्षों में लारियों पर यह भार वारतव में श्रनेकों राज्यों में श्रीर श्रिषक बढ़ा ही है।

- (२) प्रादेशिक सरकारों ने सहकों पर बहुत कम घन व्यय किया है श्रीर उनकी देख-रेख भी ठीक नहीं होती। इससे व्यक्तियों को बस चलाने के कार्य में बड़ी कठिनाई पड़ती है। "मोटर गाड़ी कर जाँच कमेटी ने पता लगाया था कि 'क' राज्यों को १६४६ में रिजस्टर की हुई मोटर गाड़ियों श्रीर वस्तुश्रों से प्राप्त २२'२६ करोड़ स्पयों के लगभग थी जब कि सड़कों की मरम्मत पर केवल ११'७ करोड़ स्पया व्यय किया गया था जो कि वस्तुल किये हुये कर के श्राचे से भी कम है। यह स्थिति बड़ी विचिन्न है। क सड़क यातायात पर कर इतना श्रीधक है कि यात्रियों श्रीर माल ढोने में उनका प्रयोग करने में बाधा पड़ती है, पर किर मी मोटर गाड़ियों से वस्तुल हुये कर के धन का पूरा प्रयोग सड़कों के बनाने में नहीं किया जाता।" सड़क की ठीक मरम्मत न होने से सड़क यातायात के व्यय में भी बृद्धि हो जाती है। कमेटी ने श्रतुमान लगाया था कि एक वस साधारण खराब श्रीर बहुत खराब सड़कों पर एक वर्ष में २५००० मील चलाने में व्यय श्रव्छी सड़क में चलाने में व्यय की श्रपेता २६०० ६० श्रिषक होगा।
- (३) १६३६ में मोटर गाड़ी एक्ट ने उन लंबी यात्राश्रों पर नो उस समय बम्बई श्रीर कलकत्ते, बम्बई श्रीर देहली, वंबई श्रीर पेशावर श्रीर बम्बई श्रीर महास श्रीद के बीच प्रचित्तत यी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इस एक्ट की योजना है कि सहक यातायात को राज्यों के छोटे-छोटे चेत्रों में ही सीमित कर दिया नाय जिससे कि कोई मोटर राज्य की एक सीमा से दूसरी सीमा तक बिना श्रमेकों यातायात श्रिधकारियों की श्राशा के न जा सके। ऐसी श्राशा बहुत ही कम दी जाती है। ऐसी स्थित में श्रन्तर प्रदेशीय यातायात की कोई सम्मावना ही नहीं हो सकती। मोटर गाड़ियों के चलाये जाने के चेत्र को सीमित करने के श्रितिरक्त चेत्रों के कर्मचारियों को यह श्रधकार मी प्रदान किया हुशा है कि वे श्रपनी इच्छा के श्रनुसार विभिन्न चेत्रों में चलाई जाने वाली मोटर वसों की संख्या भी सीमित कर सकते हैं। मोटर गाड़ी एक्ट ने छोटे-छोटे चेत्रों में श्रनंकों श्रिपकारियों को बनाकर सहक के यातायात को छोटे-छोटे मानों में विभाजित करके तथा प्रतिबन्ध लगा

कर निहित स्वायं का श्रवसर प्रदान कर दिया है । इसके परिणाम स्वरूप सङ्क यातायात के वैज्ञानिक ढंग पर विकास में वाचा पड़ी है।

(४) जिस प्रकार सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण विभिन्न राज्य द्वारा किया गया है उससे राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत अधिक महत्वशाली योजनाओं पर जो धन व्यय किया जाना चिह्नये था वही नहीं रोका गया वरत् व्यक्तियों को यह कार्य करने में बढ़ी भारी वाधा भी पहुँची है। इस दोष को रोकने के लिये योजना आयोग ने १६५३ में प्रादेशिक राज्यों से अपनी-अपनी लाइसेंस देने की नीति को सुधारने की आशा दो थी क्योंकि वह व्यक्तियों को सहक यातायात का कार्य करना आरम्भ करने में बहुत वाधक थी परन्तु ऐसा प्रवीत हाना है कि प्रादेशिक राज्यों ने इस आशा को अनसुनी कर दिया है क्योंकि कि इनक सदक यातायात के राष्ट्रीयकरण के कार्य-कम में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अपनी आशा को मनवा सकने के लिये योजना आयोग को अपनी आशा निश्चित शब्दों में निश्चित निर्देशों सिहत मेजनी चाहिये थो। स्थित के अपने अन्तिम परीज्ञण में योजना-आयोग केन्द्रीय मन्त्रालय के सहयोग से इस परिणाम पर पहुँचा है कि द्वितीय योजना में माल और यात्रियों के सम्बन्ध में कुछ सिद्दान्तों का अनुसरण आवश्यक है।

माल की दुलाई के उम्बन्ध में यह सिद्धान्त निम्न हैं:-

- सहक द्वारा ढोने वाली संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना
 १६६१ तक अर्थात् दितीय योजना के अन्त तक नहीं सोची जानी चाहिये।
- २. १६३६ के मोटरगाड़ी एक्ट के अनुसार कम से कम तीन वर्ष के लिये ऐसी संस्थाओं को जो पनप सकती हैं परिमट स्वतन्त्रता पूर्वक देना चाहिये। मोटरगाड़ी एक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक का परिमट देकर प्रोत्साहन देना चाहिये।

यात्रियों के यातायात के लिये निम्न सिदान्तों की सिफारिश की गई है-

- (१) जो प्रादेशिक राज्य यात्रियों के यातायात सेवा संस्थाओं का राष्ट्रीय-करण करना चाहें उन्हें योजना श्रायोग के समक्ष क्रिक कार्य-क्रम बनाकर विचार करने के लिये रखना चाहिये जिससे वह कार्यक्रम को योजना में सम्मिलित कर सके। इस कार्य-क्रम को उन्हें १६६०-६१ तक जिन च्रेत्रों में राष्ट्रीयकरण करना है उनका निश्चित रूप से विवरण दिया जाना चाहिये। इसका विचार श्रायोग द्वारा तभी हो सकता है जबिक शर्ते प्रादेशिक राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली जायें।
 - (२) राष्ट्रीयकरण योजना के बाहर की सद्दकों पर्वातायात के लिये

परिमट कम से कम तीन वर्षों के लिये १९३९ के मोटर गाड़ी एक्ट के अनुसार दिया जाय।

- (३) उन चेत्रों में जो स्वीकृत राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत आते हैं परिसट अधिक से अधिक समय तक के लिये, जो कि विस्तार के कार्य-कम के अन्तर्गत माटरगाड़ी एक्ट की सीमा के अन्दर हो है, दिये जाने चाहिये।
- (४) जहाँ पर सरकार के सहयोग की सम्मानना है एक त्रिदलीय संस्था स्थापित की जानी चाहिये जिसमें प्रादेशिक सरकारें, रेलने श्रीर इस कार्य मे संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हों।
- (५) उन चेत्रों में जिन्हें पूर्णतया व्यक्तिगत लोगों के ऋषिकार में छोड़ दिया जाय प्रतिस्पर्धा दलों को विशेष प्रोत्साइन दिया जाना चाहिये।

राज्यों में सहकों के विकास में बाधा डालने वाली श्रानेक कठिनाइयों में से एक तो निर्देशन करने वाले उपयुक्त कर्मचारियों का श्रभाव है जिनका कार्य मोटर द्वारां परिवद्दन की व्यवस्था पर ध्यान देना, सहकों के नियोजित विकास की अपेदा विशेष हो। १६५८ के आरम्भ में मारत सरकार ने एक कमेटी इस मामले की जाँच करने के लियें श्री एम ग्रार मसानी की श्रध्यज्ञता में नियुक्त की थी। सरकार ने १९५८ के ब्रारम्भ में एक अन्तर-राज्य यातायात स्रायोग की भी नियुक्ति की थी जिसको मोटरगाड़ो (संशोधित) एक्ट की ६३ ए घारा के श्रनुसार नियन्त्रण तथा निर्देशन के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत श्रिधकार प्राप्त है श्रीर जिससे यह श्राशा की जाती है कि (१) वह परिवहन की गाड़ियों के संचालन तथा उनके विकास सम्बन्धी योजनाश्चों को तैयार करे और श्रपनी योजनाश्चों में ेमाल लादने वाली गाड़ियों का जो कि श्रन्तर्राज्यों में यह कार्य कर रही है विशेष ध्यान रक्खें, (२) इस सम्बन्ध में जो कुछ भी मागड़े श्रयवा मतमेद उत्पन्न हो उन सन को निवटाँयें ख्रीर उन पर निर्शाय लें; (३) श्रीर दो आपवा दो से आधिक राज्यों में पड़ने वाले मार्गों पर मोटर गाड़ी चलाने, नये परमिट देने, पुरानों को फिर से चालू करने तथा रह करने के सम्बन्ध में राज्य विशेष के यातायात श्रिषिकारी को अथवा क्षेत्र विशेष के यातायात अधिकारी को निर्देश दें।" इस आयोग से श्राशा की जाती है कि यह अन्तर राज्य यातायात की सुविधाओं का प्रभावशाली रूप से विकास करने में सफल होगा।

योजना के अन्तर्गत—जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई भारत में १७५४६ मील पक्की सहकें और १५१००० मील कच्ची सहकें थी । योजना के अन्तर्गत पहिले ११० करोड़ रुपया व्यय करने के लिये रक्का गया या जो कि बाद में बहाकर १३५ करोड़ रुपया कर दिया गया जिसमें से प्रथम योजना काल में लगभग १३४६ करोड़ रुपये वास्तव में खर्च कर दिये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप २४००० मील नयी भूमि के समतल सड़कें, श्रीर ४४००० मील नीची सड़कें बनवाई गई श्रीर इस प्रकार सड़कों की लम्बाई १२१००० मील पक्की श्रीर १६५००० मील कच्ची श्रपांत् कुल ३१६००० मील हो गई जब कि नागपुर योजना का ध्येय केवल १२३००० मील पक्की तथा २०८००० मील कच्ची श्रपांत् कुल ३३१००० मील सड़कों का ही था।

इसके ग्रातिरक्त ग्रानेकों सङ्कों के बीच के व्यवधानों को मिलाने तथा पुलों के बनाने की भी व्यवस्था को गई थी। "पहली श्राप्रैल १६४७ को जब कि भारत सरकार ने राजपय कही जाने वाली सङ्कों के विकास तथा बनाये रखने का वित्तीय दायित्व श्रपने ऊपर लिया उस समय लम्बी लम्बी द्री तक सङ्कों के व्यववान पड़े हुये ये तथा मुख्य-मुख्य स्थानों पर ग्रानेकों सहकों पर पुल नहीं थे। प्रथम योजना के अ।रम्भ तक ११० मील एडकें दो सहकों के बीच के व्यवधान को जोड़ने के लिये तथा तान बड़े-बड़े पुल बनवाये गये और १००० मील सदकों को मरम्मत करवाई गई। प्रथम योजना काल के आरम्भ में ही केट्टीय सरकार ने सहकों के विकास तथा सुधार का कार्य कम ग्रारम्भ किया जिसके अन्तर्गत १२५० मील बीच की गायब सहको तथा ७५ बढ़े-बड़े पुलों का बनवाना तथा ६००० मील सहकों की मरम्मत करवाना सम्मालत था। इसमें से योजना काल में ६४० मोल बीच की गायब सड़के तथा ४० पुल तथा २५०० मील पुरानी सङ्कों की मरम्मत पूरी हो जाने की आशा की गई थी। योजना के खत्म होते-होते ६३६ मील बीच की गायब सङ्के, ३० वड़े-बड़े पुल श्रीर ४००० मील पुरानी सदकों की मरम्मत हो पाई थी। इस प्रकार इस देखते हैं कि जितनी चीच की गायत सड़कों के बनवाने का ध्येय बनाया गया था वह लग भग पूरा हो गया ख्रीर वर्तमान राजपर्थों की मरम्मत का काम सोची हुई मात्रा से लगमग द्रगना कर लिया गया। योजना में २७.८० करोड़ रुपये राजपयों पर व्यय के 'लिये नियत किये गये ये जिसमें से २७ ६२ करोड़ रुपये व्यय कर दिये गये।

प्रथम योजना में सहकों द्वारा यातायात पर १२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। राज्यों ने २००० मोटर गाड़ियों श्रीर वढ़ाई जिससे कुल मोटर गाड़ियों की संख्या जो सरकार की श्रोर से यातायात की सेवा में लगी हुई थी ११००० हो गई। प्रथम योजना के श्रन्त तक मोटर द्वारा जनता की यातायात सेवा का २५% सरकारी विभाग द्वारा किया जाने लगा था। माल परिवहन व्यक्तिगत एजेन्सियों के ही श्रिधकार में रहा।

द्वितीय योजना में (सड़कों के विकास के लिये) २४६ करो रुपयों के

च्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से ८२ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा और १६४ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा व्यय किया जायगा। यह रक्तम केन्द्रीय सड़क कोष से प्राप्त होने वाले १५ करोड़ रुपयों के श्रातिरिक्त है। द्वितीय, योजना के पूरे होने पर यह श्राशा की जाती है कि पक्की सड़के बहुकर १४३,००० मील स्रीर कच्ची सड़के २३५,००० मील श्रार्थात् कुल योग ३७८,००० मील हो जायगा। यह मात्रा नागपुर योजना से कहीं श्रिषक है।

द्वितीय योजना का कार्यक्रम पहिली योजना ही की तरह बड़े-बड़े पुलों का निर्माण तथा बड़े-बड़े राजनथों को मिला देने वाली सहकों के निर्माण का स्त्रीर पुरानी सहकों को मरम्मत का हो है । इस योजना के स्नन्तगंत स्त्रारंम किये हुये निर्माण कार्य पर कुत व्यय लगभग ८७५ करोड़ घरये का है । यह व्यय निम्न प्रकार का है ।

प्रथम योजना के ऋपूर्ण निर्माण कार्य पर		
जिसमें वनिहाल टनल सिम्मलित है-	₹0"0	करोड़ रुपया
वड़े-बड़े राज पथों को मिलाने वाली		
सङ्कों पर (६०० मील)	१० पू	,,
बड़े-बड़े पुलों के निर्माण पर (६०)	200	23
छोटे-छोटे पुलों के निर्माण पर	प्र.०	22
पुरानी सहकों की मरम्मत पर	6.0	93
सङ्कों के (१२ कीट से २२ फीट) चौड़ी		
कराने पर (३००० मील)	१५.०	٥
কুল	দ ৬ ' খ	0

द्वितीय योजना काल में वास्तिक व्यय लगभग ५५ करोड़ रुपये का श्रनु-मानित किया गया है। राष्ट्रीय राज्यपथां के श्रितिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ महत्वशाली सहकों का निर्माण प्रथम योजना में करवाना आरंम कर दिया था। बह कार्य इस योजना में प्रचलित रहेगा और लगभग ६ करोड़ रुपया इस पर स्थय हो जायगा। कुल मिला कर केवल १५० मील नई सड़क बनाई जार्येगी और लगभग ५०० मील सहकों को उच्चस्तल कर दिया जायगा।

दितीय योजना में १३६ करोड़ रुपयों की राज्यों की सड़क यातायात संबन्धी विकास काय-क्रमों के लिये ज्यवस्था की गई हैं। १९५० के रोड़ ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन प्रकट के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कारपोरेशन स्थापित करने की सलाइ दी गई दें और रेलवे योजना के अन्तर्गत १० करोड़ रुपयों की ज्यवस्था की गई है कि

रेलवे इन कारपोरेशनों में सम्मिलित हों। इसके श्रतिरिक्त यातायात मन्त्रालय की योजना में देहली ट्रान्सपोर्ट सरविस के लिये एक ३ करोड़ रुपये का कार्य-कम भी स्वीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार सरकारी सड़क यातायात पर कुल विनियोग द्वितीय योजना में १७ करोड़ रुपयों के लग भग होता है।"

१६५६-५७ में कुल सहकों के कार्य क्रम पर न्यय ४२.७१ करोड़ रुपया था और १६५७-५८ के लिये संशोधित अनुमान ४४.३२ करोड़ रुपयों का है इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों से कुल न्यय १२६.२६ करोड़ रुपया होता है। बचे हुये दो वर्षों के लिये ११६.८६ करोड़ रुपया होता है। बचे हुये दो वर्षों के लिये ११६.८६ करोड़ रुपया रह जायगा। अन्तिम दो वर्षों के लिये वजट में इस रकम की न्यवस्था सम्भव हो सकेगो इसमें संदेह मालूम पड़ता है। इसके अतिरिक्त लोहे की कमी के कारण पुलों के निर्माण में वाधा पड़ने का भय भी है। इस्रांलये इम यह कह सकते हैं कि योजना के विकास कार्य-क्रम में कुछ कमी अवश्य ही आयेगी।

श्रध्याय ३६

जल यातायात

भारतीय यावायात श्रमी श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत के पास १२,५०० जी० श्रार० टी० (श्रास र्राजस्टर्ड टनेज) के जलयान ये। प्रथम योजना के श्रारम्भ में भारत के पास ३,६०७०७ जी० श्रार० टी० के जलयान ये जिनमें से २,१७,२०२ जी० श्रार० टी० भारतीय तटों पर श्रीर जलयान ये जिनमें से २,१७,२०२ जी० श्रार० टी० भारतीय तटों पर श्रीर प्रथम योजना के श्रन्त में कुल टनेज ४,८०,००० जी० श्रार० टी० पा जिसमें से २,४०,००० जी० श्रार० टी० तटीय ज्यापार तथा समीपवर्ती देशों से ज्यापार का २,४०,००० जी० श्रार० टी० तटीय ज्यापार तथा समीपवर्ती देशों से ज्यापार का या श्रीर २४०००० जी० श्रार० टी० दूर विदेशी ज्यापार का। लायड के जलयान के रिजस्टर के श्रनुसार ३० जून, १६५७ को समस्त संसार का कुल टनेज १,१०२ करोइ जी० श्रार० टी० या जबकि १६५५ के श्रन्त में १,००६ करोइ जी० श्रार० टी० ही था। इस प्रकार भारत का कुल टनेज संसार के टनेज के ३% से कुछ श्राघक था जब कि भारत का विदेशी ज्यापार संसार के कुल ज्यापार का ३% से श्राधक था। श्रन्तर्रांक्ट्रीय समुद्री मार्गों के द्वारा भारतीय जलयान भारत के समुद्री ज्यापार का केवल ५०% ज्यापार कर पाते हैं। इसका यह श्र्यं है कि भारतीय जल यातायात के विकास में श्रमी बहुत लम्बा मार्ग पूर्ण करना है।

भारत के लिए जिसका समुद्री तट ४,१६० मील (अयहमन द्वीप सम्मिलित करके) तक विस्तृत हुआ है और जो बहुत बड़ी मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है वारतव में जलयान का बहुत अधिक महत्व है। यदि हमारे पास अपने सकता है वारतव में जलयान का बहुत अधिक महत्व है। यदि हमारे पास अपने जलयान हों तो मारतीय उद्योग का यावायात व्यय कम हो जायगा और विदेशी जलयानों में उसकी प्रांतयोगिता शक्ति में वृद्धि हो जायगी। यदि समान का भारवीय जलयानों के द्वारा यातायात किया जाय तो इम उतनी विदेशी विनिमय मुद्रा तीय जलयानों के द्वारा यातायात किया जाय तो इम उतनी विदेशी विनिमय मुद्रा सकते हैं जिसको अन्यया इन जलयानों में व्यय करना पहता है। इसके सचा सकते हैं जिसको अपने समुद्रतटीय देश की रज्ञा करने के लिये और युद्ध के समय अपने व्यापार की सुरज्ञा के लिए एक शक्तिशाली जल सेवा की आवश्य-कता है। संकट के समय व्यापारी जलयान प्रतिरज्ञा की दूसरी पंक्ति का कार्य कता है। संकट के समय व्यापारी जलयान प्रतिरज्ञा की दूसरी पंक्ति का कार्य कता है। यह सहायक सेना के रूप में ही सहायक नहीं होते बल्कि इनसे नी-सेना को शिज्ञा दो जा सकती है और युद्ध के समय आवश्यक सामन समुद्र पर पहुँचाने के लिए इनकी अत्यन्त आवश्यकता पढ़ सकती है।

मुख्य विशेषताएँ—भारतीय जल यातायात के विकास की कुछ उल्ले-खनीय विशेषताएँ हैं:—

- (१) भारत में ग्रेजी शासन के समय भारतीय जलयानों की ब्रिटिश तथा विदेशी जलयानों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और उसे विकास करने का अवसर हीं नहीं दिया गया । १६२० के लगभग अनेक जलयान -कम्पनियाँ बनी परन्त प्रतियोगिता का सामना न कर सकने के फलस्वरूप नष्ट हो गई। इन कम्पनियों के नष्ट होने में विदेशी जलयान कम्पनियों की भाड़े की दर सम्बन्धी नीति का भी बहुत योगदान रहा है। इन विदेशी कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के कारण भाड़े की दर घटा दी श्रीर जब यह कम्पनियाँ बन्द हो गई तब भी भाड़े की दर में पुन: वृद्धिकर ली। इसके साथ इत कंपनियों ने यह व्यवस्था की कि यदि किसी व्यापारी ने एक निश्चित समय तक निर्यामत लप से इनके जलयानों के द्वारा ही सामान मेजा श्रीर मँगाया तो उस श्रविध में यह जितना भाड़ा देगा उसका एक श्रंश उसे वापिस कर दिया जायगा । इन विदेशी कंपनियों की प्रतियोगिता का केवल सिंधिया स्टीम नेवी-गेशन कम्पनी ही समना कर सकी। विदेशी कम्पनियों ने हसे नष्ट करने की अनेक नार चेण्टा की परन्तु वह सफल नहीं हो सके। इससे सिंघिया कम्पनी की मारी न्त्रति उठानी पड़ी । सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के हृ रहने पर १६२४ में एक सममीता हुआ जिसके अनुसार इसे ७५ हजार टन सामान प्रतिवर्प ले जाने की श्रनुमित दी गईं। भारतीय जलयान कम्पनियों के नष्ट हो जाने को एक कारण यह या कि विदेशी कंपनियों की प्रतियोगिता शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी श्रीर द्सरा कारण यह या कि भारतीय कम्पनियों के पास वित्त की उपयुक्त -व्यवस्था नहीं थी श्रीर इनका कुल व्यय भी बहुत श्रिवक था। थोड़े बहुत परि-चर्तन के साथ यह प्रतियोगिता स्वतन्त्रता मिलने तक चलती रही श्रीर स्वतन्त्रता मिलने से भारतीय जल यातायात का भारत के तटीय व्यापार में महत्वे वद् गया है ख्रीर साथ ही विदेशी व्यापार में भी एक सीमा तक इसने श्रपना विशेष स्थान वना लिया है।
- (२) ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने भारतीय जल यातायात को कुछ भी सहायता नहीं दी श्रीर स्वतन्त्र ज्यापार नीति का बहाना लेकर भारतीय उद्योग को टाल दिया गया श्रीर अपने लिए स्वयं मार्ग बनाने को छोड़ दिया गया। इसका यह परिणाम हुश्रा कि इस श्रविध में भारतीय जल यातायात ने विशेष प्रगति नहीं की। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् भारत सरकार ने इस श्रोर ध्यान दिया है। भारत सरकार ने जलयान उद्योग को श्रृण तथा श्रन्य श्रार्थिक

सहायता दी। सरकार ने जलयान निर्माताओं से जिस मूल्य पर जलयान क्रय किए भारतीय जलयान कम्पनी को उससे कम मूल्य पर वेचे और अन्तर को अपने कोष से दिया। लाइ सेन्स की प्रथा लागू करके १६४८ में भारत के तटीय व्यापार पर नियंत्रण स्यापित किया गया और १६५० में तटीय व्यापार केवल मारतीय जलयानों के लिये सुरद्धित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप भारतीय समुद्र तट पर १६४८ में जितने टनों के जलयान व्यापार करते थे उसमें ५३ प्रतिशत की वृद्धि हो गई और १६५२५३ तक व्यापार में १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक जल यातायात बोर्ड स्थापित किया गया है जिसका कार्य जल यातायात के कार्य का संचालन करना है। सरकार की सहायता प्राप्त करके अत्र भारतीय कम्पनियाँ विश्व जल यातायात सम्मेलन की सदस्य हैं।

१६४७ में भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि तीन जल यातायात कार्षो-रेशन बनाये जायँ, प्रत्येक के पास १० करोड़ रुपये की पूँजी हो श्रीर तीनों कार्षोरेशन तीन मार्गों में ज्यापार हत्यादि करें। परन्तु १६५५ तक मार्च १६५० में १० करोड़ रुपये की श्रिधकृत पूँजी का केवल एक कार्पोरेशन, पूर्वी कार्पोरेशन लिमिटेड, स्थापित किया जा सका था। सरकार ने दो करोड़ रुपये की नियमित पूँजी का केवल है भाग दिया श्रीर शेष पूँजी मैनेजिंग एजेन्टों ने लगाई। जून १९५६ में दूसरे कार्पोरेशन (पश्चिमी शिपिंग कार्पोरेशन) की स्थापना हुई। यह पूर्ण रूप से राज्य के श्रिधकार में है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के ख्रन्तर्गत ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन से छागामी पांच वर्षों के ख्रन्दर यह खाशा की जाती थी कि ४०,००० जी॰ ख्रार० टी॰ व्यापार ख्रीर ख्रिधक कर चकेगा। परन्तु वह केवल २१,६०० जी॰ ख्रार॰ टी॰ व्यापार प्रथम तीन वर्षों में बढ़ा पाया। सरकार ने जलयान उद्योग को ख्रीर छिषक वित्तीय तथा ख्रन्य प्रकार की सहायता दी है। इसिलये यह ख्राशा करना सर्वया युक्ति संगत होगा कि कुछ समय में भारतीय जल यातायात उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच जायगा।

(३) प्रारम्भ में देश-विदेश व्यापार में भारतीय जलयानों ने भी भाग लिया। परन्तु उनमें से श्राधिकतर छोटे ये और श्राधिकतर सेलिंग वेसिल, टरस, बारजेज, कोस्टर्स इत्यादि थे। श्रातीत में एक सबसे वही कठिनाई यह थी कि देश में जलयान उद्योग नहीं था जिससे जलयानों का व्यय श्रत्यधिक हो गया थां। श्राव विशाखापट्टम् में जलयान कारखाना है। यह जून १६४१ में स्थापित किया गया था। यह श्राशा को जाती थी कि २,१५,००० जी० श्रार० टी० में से जो कि अथम योजना के प्रथम तीन वर्षों में प्राप्त कर लेना चाहिए था हिन्दुस्तान

शिषयार्ड १ लाख जी० श्रार० टी० की पूर्ति करेगा। परन्तु शिषयार्ड की उनित बड़ी घीमी रही है श्रीर प्रथम तीन वर्षों में वह केवल ३५,८०४ जी० श्रार० टी० ही की पूर्ति करने में समर्थ हो सका है। मारतीय जल यातायात कम्पनियों को विशाखाष्ट्रम् शिष्ट्र यार्ड से श्रधिकाधिक संख्या में जलयान के पाने की श्राशा की जा सकती है। इसमें सबसे कठिनाई जलयान के विभिन्न कल-पुजों की प्राप्ति में कठिनाई है जिन्हें विदेशों से मँगाना पड़ता है। जैसे ही यह कठिनाई दूर हो जायगी श्रीर शिषयार्ड की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो जायगी, भारतीय जलयानों के टनेज के विस्तार में वास्तविक सहायता पहुँच सकेगी।

(४) भारतीय जल यातायात के विकास में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे देश में जलयानों को बन्दरगाह की उचित सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। भारत के पाँच बड़े बन्दरगाहों, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कच्छ श्रीर विशाखापट्टम में पेट्रोल, जलयान में जलानेवाला कोयला इत्यादि को छोड़कर केवल दो करोड़ दन सामान प्रतिवर्ष उतारा लादा जा सकता है। १६४६-५० में पेट्रोल तथा जलयान में जलने वाले कोयले को सम्मिलित करके इन बन्दरगाहों में दो करोड़ दन सामान लादा उतारा गया। प्रथम योजना के श्रन्तर्गत विकास के कारण माल लादने उतारने की शक्ति बढ़कर दो करोड़ पचास लाख दन हो गई है। बन्दरगाहों पर यथाशक्ति कार्य हो रहा है। जलयानों को बहुत देर तक प्रतीहा करनी पड़ती है। माल डॉक में पड़ा रहता है इसके पूर्व कि लादा जा सके। यह प्रस्ताव किया गया है कि बन्दरगाह की सुविधाओं का विस्तार किया जाय श्रीर कारडला श्रीर मंगलीर के दो नये बन्दरगाह बनाये जा रहे हैं। बन्दरगाहों पर श्रावश्यक सामान, श्राकाशदीप तथा श्रन्य सुविधाओं बढ़ाई जा रही हैं।

पुनर्निर्मास नीति उपसमिति—पुनर्निर्मास नीति उपसमिति (१६४७) ने भारतीय जल यातायात की पूर्णतया जाँच की श्रीर निम्नलिखित सिकारिश की :-

- (१) भारत को प्रति वर्ष १ करोड़ टन सामान लाने ले जाने के लिये श्रीर ३० लाख यात्रियों को ले जाने के लिये छोटे जलयानों को छोड़कर २० लाख टन के जलयानों की श्रावश्यकता होगी।
- (२) इमारा उद्देश्य है कि १६५७ तक भारत के तटीय न्यापार का १०० प्रतिशत, भारत-वर्मा लंका तथा श्रन्य पड़ोसी देश से न्यापार का ७५ प्रतिशत, दूर देशों से भारत के न्यापार का ५० प्रतिशत और धुरी राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले न्यापार का ३० प्रतिशत सँभाला जाय।
- (३) भारत सरकार की नीति का उद्देश्य भारतीय जल यातायात का प्रसार होना चाहिए और दरों में कभी और वृद्धि होने से इसकी रज्ञा की जानी।

चादिए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बल यातायात बोर्ड को पूरे श्रीधकार देने चादिए।

पुनिर्माण नीति उपधिति ने जो लक्ष्य निर्धारित किये ये भारतीय जन यातायात का स्तर यदी तक नहीं वहुँच पाया है। यह निजी उद्योग तथा भारत सरकार के निव् अतमन्त केंद्र की पात है। यहंगान में भारतीय जल यातायात का दनेज केंग्रल ५ लारत दन है जब कि समिति ने २० लाख दन का सुक्ताय दिया था। भारतीय जलयान कुल निदेशी ज्यापार का केंग्रल ५ प्रतिरात पूरा करते हैं जब कि मार्गात ने मुक्ताय दिया था कि भारतीय जलयानों की अपने कुल विदेशी ज्यापार का प्रवत्त तटीय ज्यापार के सम्बन्ध में मार्गात की श्रीमलाधा पूर्ण हुई है।

भारतीय जल पातायात के प्रधार एयम् संगठन के सम्बन्ध में सरकार की परामग्रे हैने के लिये बल मातायात के मालिकी की परामग्रेदायी समिति की रहभर के मध्य में एक भेठक हुई। समिति ने समय ह्वाई जानी चाहिये परन्तु पंचयमिय दिया है कि मारत में जलयानी की संग्या बढ़ाई जानी चाहिये परन्तु पंचयमिय योजना में हस कार्य के लिए जितने भन की व्यवस्था की गई है वह स्वयंत्र है। सरकार को इतिक ने स्विक्त भन की व्यवस्था की गई है वह स्वयंत्र है। सरकार को इतिक ने स्विक्त प्रतिश्च व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूँची स्वयंत्र में की इत्या देना चाहिए स्वीर पेंसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूँची स्वयंत्र में के तुकाई जा सके। समिति ने यह भी सुमान दिये कि (१) पुराने बलयानों के रायान पर नये जलयानों को सरोहने के लिए जो लाभांश जमा किया गया है उस पर स्वाय कर न लगाया जाय, (२) भारतीय जलयानों में जलने याते तेल पर चुन्नो न लगाई जाय स्वार (३) जलयानों का सामान वेचने वाले रहोरी पर विकी-कर न लगाया जाय।

यह भी मुक्ताय दिया गया है कि तटीय न्यापार करनेवाला जलयान देशा सन्द्रालित होना चाहिये। इसमें विभिन्न श्राकार प्रकार के जलयान होने चाहिये जो तटीय न्यापार की विशेष यस्तुशों की नमक, की यला श्रीर तेल लाने ले जाने के उपयुक्त हो। कुछ लोगों का विचार है कि नमक श्रीर की यला ले जाने के लिए ६,००० से ८,००० ही० डब्लू० टी० के जलयान श्रीषक उपयुक्त होते हैं श्रीर खाषाल की सामग्री इत्यादि का यावायात करने के लिए छोटे श्राकार के जलयानों का प्रयोग किया जा सकता है।

इस समिति ने बताया कि भारतीय वन्दरमाहों में सामान लादने श्रीर उतारने की श्रन्थी व्यवस्था नहीं है। विशेषकर कोयला लादने के लिए वर्षों (जलयान खड़े होने का स्थान) का श्रभाव है श्रीर कुछ हुटी-फूटी स्थिति में ह श्रीर उससे कार्य श्रन्छी प्रकार नहीं लिया ना सकता है। समिति ने सुकाव दिया कि बन्दरगाहों में माल लादने श्रीर उतारने इत्यादि का कार्य तीन गति से करने के लिए मशीनें लगाने की श्रीर वर्तमान सामान को श्रीर बढ़ाने की श्रावश्यकता है।

पंचवर्पीय योजना के अन्तर्गत-प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय जलयानों की संख्या बढ़ाने पर श्रीर बन्दरगाहों इत्यादि की सुविधाएँ बढ़ाने पर जोर दिया गया था। योजना में कहा गया था कि तटीय व्यापार में जो पुराने श्रीर घिसे-पिटे जलयान प्रयुक्त किये जा रहे हैं जलयान कम्पनियों को उन्हें बदलने में उद्दायता देने के लिए केन्द्रीय चरकार ने विशाखापटनम में जलयानों के निर्माण हेत रुपया लगाया है। श्राशा की जाती है कि पंचवर्षीय योजनाकाल में ही विशाखापट्टम के कारखाने से कुल १ लाख जी० श्रार० टी० के जलयान प्राप्त किये जा सकेंगे। इनमें से ६० इजार जी० ग्रार० टी० के जलयानों से पुराने षिसे-पिटे जलयानों को बदला जायगा श्रांर शेष जलयान विशेष कर तटीय व्यापार में प्रयुक्त किये जायँगे। विशास्त्रापटनम कारखाने /से जलयान कम्पनियों के हाथ जलयान उचित मुल्यों पर वेचे जायेंगे। यदि निर्माण व्यय में श्रीर विक्री मूल्य में कुछ श्रन्तर रहेगा तो उसके लिए सरकार जलयान निर्माण उद्योग को श्रार्थिक महायता देगी। इस प्रकार जलयान निर्माण कार्य का प्रसार करने का विशाखा-पटनम कारखाने के विकास से गहरा सम्बन्ध है जिससे विशाखापटनम की उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जा सके। योजना के अनुसार तटीय व्यापार को त्ररिक्त बनाए रखने के लिए कम से कम ३ लाख जी ब्रार टी के जलवानों का होना अत्यन्त श्रावश्यक है। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि पाँच वर्ष के श्रन्दर भारतीय जलयान कम्पनियों को ४ करोड़ रुपया श्रृण दिया जायगा श्रौर जलयान कम्पनियाँ श्रपने साधनों से शेष २ करोड़ रुपया एकत्रित करेंगी। श्रतुमान था कि इस ६ करोड़ रुपये से मारतीय जलयान कम्पनियों के पास पर्यात जलयान हो जायेंगे। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विदेशी व्यापार के लिए १,००,००० डी॰ डन्लू॰ टी॰ के जलयानों की श्रौर श्रावश्यकता समसी गई थी जिसमें ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन के लिए श्रावश्यक ६० इनार डी० डब्लू० टी० के जलयानी को सम्मिलित नहीं किया गया या जिसके लिए सरकार ने अपने भाग के ४.४ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी।

प्रथम योजना में १६५५-५६ तक ६ लाख जी० ग्रार० टी० तक जलयानों के बढ़ाने का विचार किया गया था। पर वास्तव में योजना काल के ग्रन्त तक दुल ४,८०,००० जी० ग्रार० टी० का कार्य किया जा सका। जो ध्येय ६,००,००० !

जी० श्रार० टी० का सोचा गया था वह तो तभी पूरा हो सका जब कि योजनाः काल में ही मँगाये हुये जहाज प्राप्त हो सके।

जल यातायात उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रथम योजना के श्रन्तर्गत व्यवस्था की गई है उसकी लोगों ने निम्न श्रालोचना की है: (१) सन् १६५६ तक ६,००,००० जी० आर० टी० के जलयानों की वृद्धि पुनर्निर्माण नीति-उपसमिति की सिफारिश की तुलना में बहुत कम है। सिमिति ने सिफारिश की थी कि १६५० तक २० लाख टन के जलयान हो जाने चाहिएँ परन्तु इस कार्य में श्रनेक कटिनाइयों का समना करना पड़ा है। वित्त के साथ ही आवश्यक सामान का अभाव है श्रीर, व्यवहारिक दृष्टि से पंचवर्षीय योजना समिति के कार्यक्रम को श्रपना लक्ष्य 'नहीं बना सकती थी। योजना में व्यावहारिक दृष्टिकी गुके आधार पर लक्ष्य निर्घारित किये हैं। (२) भारतीय जलयान समिति ने सुमाव दिया है कि सरकार तटीय एवम् विदेशी न्यापार में जो रूपया न्यय करेगी वह जलयानों ग्रौर ग्रन्य सामान के बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए बहुत कम है। पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करने में मी कहीं अधिक रुपया लगेगा; (३) सरकार ऋण दी गई पूँची पर कितना ब्याज वस्त रही है श्रीर ऋण के साथ जो शतें लगी हैं उनसे ऋगा लेना उद्योग के लिए असुविधाजनक हो गया है। उद्योग को यह ऋग भँहगा पहता है। यह सुक्ताव दिया गया है कि सरकार को २० वर्ष के लिए ऋग देना चाहिए और पहले ५ वर्षों में उस पर कुछ व्यान नहीं लेना चाहिए। छठे वर्ष से ३ प्रतिशत वार्षिक ब्याज वस्त किया जा सकता है और हसी समय से ऋग ली गई पूँजी भी किश्तों में चुकानी आरम्म हो जायगी; (४) योजना की अन्य सुविधाओं की कुछ चर्चा नहीं की गई है, जैसे जलयान में जलने वाले तेल पर से खुङ्गी इटाना, जलयान सामान के स्टोर पर से विक्री-कर इटाना श्रीर त्राय-कर पर रियायत देना। जल यातायात उद्योग ने इन सुविधाश्री की माँग की है। इनके बिना भारतीय जल यातायात की तेजी से प्गति नहीं की जा सकती है।

दितीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि ६० हजार जी० श्रार० टी० के ििसे-पिटे जलयानों को निकाल कर ३० लाख जी० श्रार० टी० के जल-यानों की वृद्धि की जाय। इस प्रकार दूसरी योजना के श्रन्त तक कुल टनेज ६ लाख जी० श्रार० टी० हो जाना चाहिए। योजना का ध्येय है (१) तटीय न्यापार की श्रावश्यकताश्रों को रेलचे द्वारा प्राप्त माल श्रीर यात्रियों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करना; (२) भारत के विदेशी न्यापार का श्रिषक से श्रिषक माग

भारतीय जलयानों के लिए प्राप्त करना; (३) टैंकों का वेड़ा तैय्यार करने के लिए केन्द्र स्थापित करना ।

नीचे लिखे निश्चित ध्येय को पूरा कर लेने के पश्चात् भारत का १२ से १५ प्रतिशत समुद्रपार देशों से न्यापार श्रीर श्रास-पास के देशों से न्यापार का ५०% भारतीय जलयानों के भाग में श्रा जायगा जब कि वर्तमान में इन न्यापारों का केवल ५ श्रीर ४० प्रतिशत उनके भाग में हैं।

जी० ग्रार० टी॰

			41.0 ALCO CIO
	योजना के पहले	प्रथम योजना के श्रन्त में	द्वितीय योजना के श्रन्त में
तटीय श्रीर निकटस्य	२१७२०२	३१२२०२	४१२२००
समुद्र पार	१७३५०५	र⊏३५०५	४०५५०५
ट्रेम्प दैन्कर्स			६०००० '
र्क्स सेलवेन टग		५०००	23000
·			१०००
कु ल	७०७०३६	६००७०७	६०१७७७

प्रथम योजना में १६'५ करोड़ रुपया जल यातायात के लिये नियत किया गया था। बाद में यह घन बढ़ा कर २६'३ करोड़ रुपया कर दिया गया। योजना काल में वास्तिवक व्यय १८,७१ करोड़ रुपये किया गया। द्वितीय योजना में जल यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। जल यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवस्था यद्यपि की गई है फिर भी क्योंकि पिछली योजना का ८ करोड़ रुपया बचा हुआं है इसलियें केवल ३७ करोड़ रुपया ही इस योजना में विकास कार्यों के लिये प्राप्त. होगा।

योजना श्रायोग के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यों तथा यानीसफलता के मत के श्रनुसार (मई १६५८) जितने न्यय की द्वितीय योजना में न्यवस्था की गई है उसका न्यय तो हो ही जुका है श्रीर उसके फलस्वरूप जो जल यातायात का कार्य होगा (टनेज मिलेगा) वह लगभग १८०००० जी० श्रार० टी० होगा जनकि योजना का ध्येय ३६०,००० जी० श्रार० टी० टनेज प्राप्त करने का था, जिसमें ६०००० जी० श्रार० टी० टनेज पुराने जहाजों के स्थान पर नये प्रयोग में ले श्राने के कारण प्राप्त होने वाला था। श्रपने ध्येय को पूरा कर सकने के लिये लगभग ४५ करोड़ इपयों की श्रीर श्रावश्यकता होगी।

वन्द्रगाह—प्रथम योजना की रूपरेखा जब उपस्थित की गई थी उसमें बन्दरगाहों के विकास अथवा सुधार का कोई स्थान नहीं था। इस अभाव की पूर्ति की महत्ता समफी गई श्रीर जब योजना की संशोधित रूपरेखा बनाई गई तो उसमें ३३ करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गई थी। बाद में यह मात्रा बढ़ा कर ३६ १६ करोड़ कर दी गई थी। चूँकि बन्दरगाहों के सुधार का कार्यक्रम देर से आरम्म हुआ, इसलिये योजना-काल में व्यय की मात्रा केवल २७ ५७ करोड़ रूपयों की हो पाई। कुछ मी हो यह विकास कार्यक्रम जो आरम्म किया गया बड़े महत्व का था। कारहला के नये बन्दरगाह के बनवाने के आतिरिक्त जिस पर १२ १ करोड़ व्ययों की व्यवस्था की जा चुकी थी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य योजनाएँ बम्बई और कलकत्ता में थो जिनके लिये योजना में ११ तथा द्र करोड़ रूपयों की व्यवस्था क्रमशः की गई थी। योजना के अन्त तक काराहला पर द्र ५ करोड़ रूपये वस्बई पर ११ करोड़, और कलकत्ता पर ३ ५ करोड़ रूपये वस्वई पर ११ करोड़, और कलकत्ता पर ३ ५ करोड़ रूपये वस्वई पर ११ करोड़, और कलकत्ता पर ३ ५ करोड़ रूपये वस्वई वर्ष वस्वई वर्ष ११ करोड़ रूपये क्रम के थे।

"मुख्य मुख्य बन्दरगाहों की समता प्रथम योजना काल में २०० करोड़ टन से बढ़ कर २५० करोड़ टन हो गईं। १६५०-५१ में कुल माल जो इन मुख्य बन्दरगाहों द्वारा उतारा अथवा चढ़ाया गया १८० र करोड़ टन या जिसमें ११२ ५ करोड़ टन आयात का माल और ६७ ७ करोड़ टन निर्यात का माल समितित या। १६५५-५६ में अनुमान है कि उतारे और चढ़ाये जाने वाले कुल माल की मात्रा २२० करोड़ टन यी जिसमें १३० करोड़ टन आयात और ६० टन निर्यात का माल था।"

लगभग २२६ छोटे-छोटे बन्दरगाह २६०० मील के तट पर फैले हुये हैं जिनमें १५० बन्दरगाहों से माल ब्राता-जाता है। १६५१-५२ में इन बन्दरगाहों द्वारा ३७ ६ करोड़ टन माल उठाया गया, ब्रीर १६५४ तक यह मात्रा बढ़ कर ४१ ५ करोड़ टन हो गई। प्रथम योजना में इन छोटे-छोटे बन्दरगाहों के विकास कार्यक्रम में मद्रास, सीराष्ट्र, बम्बई, उड़ीसा ब्रादि मुख्य स्थान सम्मिलित किये गये थे। कल व्यय जो किया गया था वह २ कराड़ कार्यों से कुछ हो कम था।

द्वितीय योजना का साधारण ध्येय है कि प्रथम योजना में जो कार्य श्रारम्म किया जा जुका है उसे पूर्ण कर दिया जाय श्रीर सर्व सुविधाओं का प्रवन्ध करके हॉकों को श्राधुनिक रूप प्रदान कर दिया जाय ताकि देश के श्राधिक श्रीर श्रीचोगिक विकास के कारण जो श्रावश्यकतार्य हों पूर्ण की जा सकें। ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था बड़े-बड़े वन्दरगाहों के सुवार कार्य-क्रम के लिये की जा जुको है। जो निर्माण कार्य श्रारम्भ किये जार्यों, जिनमें प्रथम योजना के श्रव्रे कार्यों

को पूर्ण करने का कार्य भी सम्मिलित होगा, उनमें लगभग ७६ करोड़ रुपया व्यय होगा। योजना में व्यवस्थित ४० करोड़ रुपये के अितरिक्त कुछ घन बन्दर-गाहों के अपने निजी कोषों से भी प्राप्त होगा। योजना में निर्धारित घन सरकार की श्रोर से कारहला में लगाया जायगा और पोर्ट ट्रस्ट की सहायता के लिये दिया जायगा। वर्तमान रियायती अपृण की पोर्ट ट्रस्ट के लिये सुविधा दूसरी योजना काल में भी रहेगी। दितीय पंचवर्षीय योजना के बड़े-बड़े- बन्दरगाहों के सुधार के कार्यक्रम में कलकत्ते में १९ ६ करोड़ रुपया व्यय किये जाने वाली, बम्बई में १६ ३ करोड़ रुपया व्यय किये जाने वाली, कोचीन में ४ ० करोड़ रुपया व्यय किये जाने वाली, योजनाएँ हैं।

े भारत में लगभग १५० छोटे वन्दरगाह हैं जिनमें से १८ विशेष महत्व के हैं। उनका सुधार श्रस्यन्त श्रावश्यक है। प्रथम योजना में छोटे-छोटे बन्दरगाहों के सुधार की योजनाएँ सम्मिलित की गई थीं जिनका कुल व्यय २५४ करोड़ रुपया नियत था, इसमें से,१ करोड़ केन्द्रीय कोष से प्राप्त होना था श्रीर शेष वन्दरगाहों के कर्मचारियों को श्रपनी श्रोर से एकत्रित करना था। द्वितीय योजना में छोटे-छोटे वन्दरगाहों के सुधार के लिए ५ करोड़ रुपया नियत किया गया है।

श्रध्याय ३७

: .

इवाई यातायात

वर्तमान युग में देश के श्रीद्योगिक,श्राधिक श्रीर श्रन्य कार्यों का मूलाधार 'गति' है श्रीर यातायात के मूलाधार हैं यात्रियों एवम् सामान का तीव गति से ं यातायात कर सकने वाले साधन । भारत जैसे विशाल देश में इवाई यातायात का विशेष महत्व है। विमानों द्वारा यात्रा करने से समय की बहुत बचत होती है, श्चनेक श्रमुविघाओं से बचा ना सकता है; न्यापारी, सरकारी कर्मचारी तथा श्चन्य लोग बड़ी कुशलता से कार्य कर सकते हैं, श्रपने कारखानों से सम्पर्क रख सकते हैं, दूर-दूर स्थित कार्यालयों से सम्बन्ध बना रह सकता है और नियंत्रण के साथ ही साय उनका श्रच्छी प्रकार निरीक्षण किया जा सकता है। संकटकाल में, बाढ़ श्रयवा भूकम्प के समय हवाई यातायात का महत्व श्रीर भी श्रिधिक हो जाता है। इसके श्राविरक्त शांविकाल में नागरिक उडुयन के कर्मचारी जो अनुभव पाष्ठ करते हैं उसका युद्ध के समय सदुपयोग किया जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय श्रीर देश विमाजन के पश्चात भारत की हवाई कम्पनियों ने यात्रियों तथा चामान का यातायात करने में, निरीक्ण करने में श्रीर चरकार के निर्देश पर शरणार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ते जाने में प्रशंसनीय कार्य किया। हवाई यातायात का यथासंभव विकास करने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है; इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं।

विकास—यह खेद का विषय है कि मारत में ह्वाई यातायात अमी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। यद्यपि मारत में १६११ से ही विमानों का उपयोग आरम्भ हो गया था श्रीर प्रथम विश्वयुद्ध के समय इस दिशा में कुछ प्रगति मी की गई थी परन्तु भारतीय हवाई यातायात में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और उसके पश्चात् ही विशेष प्रगति की जा सकी। भारत के हवाई यातायात के विकास में कुछ उल्लेखनीय वार्ते हुई हैं: (१) १६२७ में नागरिक उद्भुयन विमाग स्थापित किया गया और १६२८ में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई श्रीर कराँची में 'फ्लाइंग क्लव' खोले गये। विमान-चालकों श्रीर टेकनीशियनों के शिक्षण की व्यवस्था की गई श्रीर इम्पीरियल एयरवेज सर्विस का १६२६ में दिल्ली तक प्रसार करने का प्रवन्ध किया गया। भारत में हवाई यातायात के विकास का यही प्रारमकाल था; (२) १६३२ में टाटा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद,

कलकत्ता श्रीर कोलम्बों के मध्य इवाई यातायात श्रारंभ किया श्रीर तत्पश्चात् कराँची और मद्रास तक इसका प्रसार कर दिया । देश के कुछ मार्गों पर इण्डियन नेशनल एयरवेज ने भी यातायात कार्य शुरू कर दिया; (३) १६३८ में एम्पायर एयरमेल योजना लागू की गई जो युद्ध प्रारम्म होने पर स्थगित कर दी गई परन्छ तत्पश्चात् बहुत सीमित पैमाने पर इसे फिर लागू किया गया; (४) १६४६ में कुछ मुसंगठित विश्वासनीय निजी व्यवसायिक संस्थाओं को आवश्यक सरकारी सहायता देकर देश के श्रन्दर तथा विदेश से इवाई यातायात की सुविधा का विकास एवम् प्रचार करने को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक निश्चित उद्भयन नीति निर्धारित की । १९४६ में हवाई यातायात लाइसेंसिंग बीर्ड स्थापित किया गया। यह निश्चित किया गया कि लाहसेन्स देते समय बोर्ड इन बातों पर पर विचार करेगा: (ग्र) कम्पनी की विच स्थिति, (व) कार्यज्ञमता का उचित स्तर, (स) यातायात की माँग ग्रीर (द) जनता की ग्रावश्यकता के श्रनुकूल कम्पनी की इवाई यातायात का विकास कर सकने की जमता। बोर्ड को लाइसन्स-प्राप्त कम्पनियों के किराये तथा भाड़े की अधिकतम तथा न्यूनतम दर निर्घारित करने का श्रांधकार दिया गया। बोर्ड ने श्रापने कार्यकाल में श्रानेक कम्पनियों को लाइसेन्स दिये। इसका परिसाम यह हुआ कि इवाई यातायात में बहुत सी कम्पनियाँ चालु हो जाने से बटिलत। ग्रा गई ग्रीर इनमें परस्पर हानिकारक प्रतियोगिता चलने लगी। इससे कम्पनियों को चृति भी उठानी पड़ी: (५) भारत . सरकार ने टाटा के सहयोग से विदेशी हवाई यातायात के लिए एयर हांगडया इन्टरनेशनल की स्थापना की। टाटा के साथ यह समझीता किया गया कि इस नई कम्पनी में ४६ प्रतिशत शेयर सरकार लेगी जो ५१ प्रतिशत तक बढाये जा सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त ५ वर्ष तक यदि बाटा हुशा तो इस घाटे को भी सरकार पूर्ण करेगी।

ह्वाई यातायात जाँच समिति (१६५२)—हवाई यातायात जाँच समिति ने, जो राजाध्यक्त कमेटी के नाम से श्रिषक प्रसिद्ध है, भारतीय हवाई कम्पनियों की स्थिति श्रीर उनकी समस्याश्रों की पूर्ण जाँच की श्रीर इस परिणाम पर पहुँची कि हवाई यातायात लाइसेम्सिंग बोर्ड ने श्रपना कार्य सन्तोष-जनक रीति से नहीं किया श्रीर बिना किसी प्रकार का मेद किये कम्पनियों को लाइसेन्स दिये, जिसका परिणाम यह हुआ कि दो वर्ष के अन्दर ११ कम्पनियों को लाइन्सेस मिल गये जब कि संपूर्ण कार्य केवल चार कम्पनियाँ अञ्छी प्रकार चला सकती थीं। इतनी श्रिषक कम्पनियाँ होने से उन्हें हानि उठानी पढ़ी, इसके साथ ही हवाई कम्पनियों ने सतर्कता से कार्य नहीं किया श्रीर कम्पनी के सन्नठन इत्यादि में बहुत श्रिषक रुपया न्यय किया जब कि यातायात की स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं या। कम्पनियों का उत्पादन न्यय भी पेट्रोल के मूल्य १ रुपया १४ ग्राना प्रति गैलन (१९४६) से बदकर १९४६ में २ रुपया ९ ग्राना प्रति गैलन हो जाने से, बढ़ गया।

समित हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के पत्त में नहीं थी। समित का मत्य था कि हवाई यातायात के चेत्र में समय के अनुकृत परिवर्तनशील नींत की श्रीर साहस-पूर्वक नयी योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता है परन्तु यदि हवाई कम्पनियों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी तो इसकी संमावना कम हो जायगी। इस कारण स्थित ने सिफारिश की कि वर्तमान कम्पनियों का चार कम्पनियों में एकीकरण किया जाय और वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में उनके अब्दे स्थापित हों। इससे हानिकारक प्रतियोगिता कम हो जायगी और कम्पनियों में कार्य का वितरण भी वैशानिक तथा चेत्रीय आधार पर किया जा सकेगा। सीमित ने सुकाव दिया कि उद्दान के घरटों में कमी करने के लिए वर्तमान कम्पनियों की मार्गों को विधारित कर दिया जाय, विमानों की संख्या चंटा दी जाय, आतिरक्त कमेचारियों की छटनी की जाय, और हवाई यातायात के संचालन-व्यय, उचित लामांश और विमानों का प्रयोग करनेवाले यात्रियों की क्यय शक्ति पर विचार करके किराये तथा भाई की दर में वृद्धि की जाय। सिमित ने सिफारिश की कि स्टैन्डर्ड व्यय के आधार पर हवाई कम्पनियों को सरकार आर्थिक सहायता दे।

राष्ट्रीयकरण्—हवाई कंपनियाँ स्वेच्छा से एकीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं हुई जैसी कि हवाई यातायात जाँच समिति को आशा थी। हवाई यातायात में अन्यवस्था के कारण कम्पनियों की भारी चित उठानी पड़ी और उनकी स्थित हाँचाहोल होने लगी। यद्याप जाँच समिति ने राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अपनी राय प्रकट की थी परन्तु हवाई कम्पनियों की विगवती दशा को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय करण करने का निश्चय किया। यह तर्क किया गया कि (१) राष्ट्रीयकरण हो जाने से उड़ान में जो समय व्यर्थ नष्ट होता है वह कम हो जायगा, एक ही कार्य अनेक बार नहीं करना पड़ेगा और हानि भी कम हो जायगी; (२) राष्ट्रीयकरण से संयुक्त प्रमन्ध होने से हवाई यातायात की कार्यच्चमता बढ़ेगी और (३) नागरिक उहुयन का अच्छा सङ्गठन किया जा सकेगा जिससे युद्ध जैसे संकट काल में विमान चालकों, टेकनीशियनों इत्यादि के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये संसद ने १६५३ का हवाई यातायात कार्पोरेशन कानून पास किया है जिसके अन्तर्गत १ अगस्त १६५३ को दो कार्पोरेशन स्थापित किये गये जिनमें से एक देश के अन्दर के हवाई यातायात श्रीर दूसरा विदेशी यातायात सर्विसों का प्रबन्ध करेगा । मुश्रावजे के सम्बन्ध में बहुत विवाद चला । यह कहां गया कि मुश्रावजा मूल मूल्य में से टूट-फूट का व्यय घटाकर नहीं वरन् विमानों, विमान के श्राविरिक्त कल-पुजों हत्यादि के वर्तमान बाजार-भाव के श्राधार पर दिया जाय । श्रनुमान था कि मुश्रावजे के वर्तमान श्राधार पर डेकोटा विमान लगभग ५०,००० रुपये में लिया जा सकता है जब कि उसका बाजार-भाव तीन लाख रुपया है, श्रीर स्काई मास्टर विमान ४ से ६ लाख रुपयों में लिया जा सकता है जबिक बाजार में उसकी वर्तमान कीमत ३० लाख रुपयों है। कानून में 'गुडविल' के लिए, कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की शिचा में श्रीर नवीन मार्ग खोलने इत्यादि में व्यय किए गए धन का उचित मुश्रावजा दियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु यदि इन सब के लिए मुश्रावजा दिया जाय तो व्यय बहुत बढ़ जायगा श्रीर राष्ट्रीयकरण से इवाई यातायात में सुधार करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। साथ ही राष्ट्रीयकरण से उस घाटे की पूर्ति नहीं की जा सकेगी जिससे वर्तमान कंपनियाँ पोड़ित हैं।

मुश्रावजे की समस्या १६५५ में ६ ०१ करोड़ रुपया देकर सदा के लिये निश्चित कर दी गई। जहाँ तक राष्ट्रीयकरणा के पिश्णामस्वरूप वेकारी का प्रश्न या, यह निश्चित कर लिया गया कि वे सब कमैचारी जो ३० जून १६५२ के पूर्व कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गये ये उनकी बदली कारपोरेशन में कर दी गई श्रौर इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि कमैचारियों को पुर्नव्यवस्था श्रौर विस्तार के कार्य-कम में खपा लिया जाय।

घर्तमान स्थिति—१९५३ के श्रारम्म में भारत में ६ इवाई कंपनियाँ थीं जिनके पास २१६ करोड़ रुपये की श्रिधकृत पूँजी श्रीर ट्रट-फूट के कीम में ३ करोड़ रुपये से कुछ कम थे। इन कम्पनियों के विमान कुल २८,००० मील के चेत्र में चलते थे। जून १९५२ के श्रन्त तक भारत में ६७७ रजिस्टर्ड विमान थे, जिनमें २०३ विमानों की योग्यता के प्रमाण-पत्र दिये जा चुके थे। इवाई श्रृङ्खों पर कार्य करने वाले लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकों की संख्या ५५७ थी तथा ए लाइसेन्स प्राप्त चालकों की संख्या ५६२, ए-१ के लाइसेंस-प्राप्त विमान चालकों की संख्या ४२६ थी। इससे पहले वर्ष की तुलना में इखीनियरों तथा 'ए' लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकों की संख्या में वृदि हुई परन्तु ए—१ चालकों श्रीर बी. लाइसेन्स प्राप्त चालकों की संख्या घटी।

ें रहपूर श्रीर पूर में हवाई यात्रा की स्थित में श्रवनित होती रही श्रीर यात्रियोंकी संख्या श्रीर यातायात के माल की मात्रा में कमी ब्राई जिसके कारण १९५३ में यात्रियों की संख्या घटकर ४'०४ लाख श्रीर दुलाई के माल की माना घट कर ८४'८ लाख पींड हो गई जबकि यह संख्या १९५२ में क्रमशः ४'३ लाख एवं ८६'०४ लाख पींड थी। इसका कारण कुछ तो जनता के पास घन की कमी श्रीर फुछ मारतीय इवाई सर्विस को दुर्व्यक्त्या थी। यद्यपि डाक की माना १९५२ में बहुकर ८४ लाख पींड श्रीर १९५३ में ८८ लाख पींड हो गई फिर भी यात्रियों श्रीर यात्रायात के माल की कमो का घाटा इससे पूर्ण न हो सका।

मारत में हवाई कम्पनियों के कार्य के अवंतीपजनक होने के अनेक कारण हैं: (१) हवाई फम्पनियों के कार्य-छंचालन का न्यय बहुत श्रधिक है। इसमें विमानों में प्रयुक्त होनेवाले पेट्रोल श्रीर विमानों की देख-रेख इत्यादि का व्यय सम्मिलित है। कुल संचालन व्यय का ५० प्रतिशत पेट्रोल, विमान के कल-पुजी श्रीर स्टोर में न्यय होता है श्रीर ४० प्रतिशत पारिश्रमिक तथा वेतन में । अम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पारिश्रमिक और वेतन अधिक निर्धारित किये गये हैं श्रीर पेट्रोल, स्टार इत्यादि के न्यय में वृद्धि इवाई कम्यतियों की शक्ति के बाहर है। संचालन व्यय श्रधिक होने का एक कारण तो सरकार की नीति का दोष है श्रीर कुछ दोप उन परिस्पितियों का है जिन पर हवाई कंपनियों का कोई नियंत्रण नहीं और इसके लिए कम्पनियों को दोषी भी नहीं उदराया जा सकता है: (२) इवाई कम्पनियां की संख्या यातायात की देखते हुए आवश्यकता से अधिक है. इस कारण किसी भी कम्पनी को पर्याप्त कार्य नहीं प्राप्त होता। इस दोष के लिए इवाई यातायात लाइसेन्छिंग बोर्ड उत्तरदायी है। बोर्ड ने छानेक कम्पनियों को उद्योग चालू करने की अनुमति दी श्रीर श्रावश्यकता का ध्यान रखे विना विमानों की संख्या बद्धाने दी; (३) कम्यनियों की कार्यक्रमता को देखते हुए कार्य पर्याप्त नहीं है परन्तु यह व्यवसाय ऐसा है जिसमें कुछ विमान चालकी. इझीनियरों ग्रीर टेकनीशियनों को नियुक्त करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप कम्पनियों को श्रावश्यकता से श्राधक कर्मचारियों का भार वहन करना पड़ता है, (४) किराये श्रीर साड़े की जो न्यूनतम श्रीर श्रधिकतम दरें सरकार ने निश्चित कर दी हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। प्रति यात्री से प्रत्येक मील के लिए अधिक से अधिक ४ भ्राना किराया वसूल किया जा सकता है परन्तु रात में चलनेवाली द्धांक सर्विस के लिए किराये की दर २६ ग्राना प्रति मील है। यह किराया मार-तीय वायुपान कम्पनी के न्यय से बहुत कम है। यदि एक विमान पूर्ण वर्ध में १५०० घरटे चलाया जाय तो प्रति घरटे का स्टेन्डर्ड न्यय ५८६ रुपया होता है। इस्र प्रत्येक सीट का प्रति मील का किराया विमान की ७ प्रतिशत जगह भरने

तालिका नं० १ श्रतुसुचित भारतीय इवाई सेवाओं के आंकड़े

		.0.0			
~	वर्ष	यात्रा मीलों में (दस- लाख में)	यात्रियों को संख्या	यातायात माल की मात्रा (दस लाख पैं॰ में)	हाक की मात्रा (दसं लाख पींड में)
	ै १६ ४६	४-५२	१०५२५१	१°दद	१०३
	१९४७	€•३६	२५४६६०	प् -६प्	8.80
	\$£¥=	ૃશર*६થ	३४११⊏६	45.50	१•५८:
	\$EXE	₹4.50	३५७४१ ५	२२.त.	. d.o.s
	१६५०	१८६०	४५.२८६६	20.05	द: ३ ६
	१९५१	१६'५०	४४६४६२	<u>८७.६६</u>	0.8=
	१६५२	१६.४६	४३४४८०	======================================	⊏.∮⊏,
	१९५३	१६.५०	\$33€0¥	८४'दर	5,24
	१६५४	१६८०	८ ई१४६४	न्द'४१	१०.६७
	१९५५	२१-२७	¥€€000	६८.५०	११%न
	१९५६	२३.४८	सॅसॅ६०००	६६.५३	१२.६६
	१६५७	₹३∙३४	4E8000	द 4.0€	83.58

के आधार पर ४६ -आना होना चाहिए । चूँकि किराया कम है इसलिए हवाई कम्पनियों को हानि होना स्वाभाविक ही है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् हवाई सेवाओं की स्थिति में बहुत सुघार हुआ है। उड़ने का विस्तार १९५४ को १९८ करोड़ मी० से बहुकर १९५७ में २३३४ करोड़ मील हो गया। मेल तथा यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। मेल की मात्रा १९५४ में १०६७ करोड़ पींड यी जो कि १९५७ में बढ़ कर १२६४ करोड़ पोंड हो गई और यात्रियों की संख्या जो कि १९५४ में ४३१५९५ थी बढ़ कर १२५७ में

प्रह्म अर्थ हो गई। लादने वाले माल की मात्रा १६५६ में ६६२ र करोड़ पींड यो जो कि १६५७ में थोड़ा घट गई और प्रश् करोड़ पींड हो गईं। इस उन्नित का श्रंशतः कारण आपसी विनाशकारी प्रतिद्वन्द्विता का समाप्त हो जाना तथा कुशलता संगठन रहा है जो कि कारपोरेशन की व्यवस्था के कारण संभव हो सका है, और श्रंशतः शौद्योगिक और आधिक विकाश रहा है जिसके कारण इवांई सेवाओं की श्रधिक माँग की गई हैं।

दोनों एयर कारपोरेशनों ने बहुत ही सन्तोषजनक उनित की है। उन्होंने कार्य-चेत्र बहाया है और जनता का बहुत सी सुविधायें प्रदान की हैं। "ये कारपोशन अपनी वायुयान संबन्धी कार्यों के एकीकरण तथा उनके कुशल संगठन में व्यस्त रहे हैं। इण्डियन एश्चर लाइन्स अपने ६३ इवाई जहाजों, ६७ डकोटा, १२ वाहिका, ६ स्काई मास्टर और ८ हरीन्स के द्वारा देश के प्रमुख केन्द्रों को सम्बन्धित करते हैं और उसके हवाई मार्गों का विस्तार १६,६८५ मील है। दि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल अपने वायुयानों द्वारा जिसमें ५ सुपर कान्सटेलेशन्स, ३ कान्सटेलेशन्स और १ डकोटा है १५ देशों तक अपने कार्यों को प्रसारित किये हुये हैं। उसके हवाई मार्ग का विस्तार २३,४८३ मील है।"

इण्डियन एश्रर लाइन्छ कारपोरेशन का कुल कार्य-चेत्र तीन मागों में विमाजित कर दिया गया है। प्रत्येक भाग एक मैनेजर के श्रिष्ठकार में है श्रीरं बम्बई, कलकत्ता श्रीर देहली के किसी न किसी श्रुड्डे से नियंत्रित होगा। श्राई० ए० सी० को निरन्तर घाटा हो रहा है। १६५४-५५ में इस घाटे की रकम ६०'१५ लाख रुपया, १६५५-५६ में ११६'४० लाख रु० श्रीर १६५६-५७ में १०० एं६ रुपया थी। परन्तु इसके विपरीत एयर इन्डिया इन्टरनेशनल को निरन्तर लाभ होता रहा है। श्राई० ए० सी० के घाटे का कारण श्रंशतः कर्मचारियों की' श्रत्यिक सख्या का होना है तथा श्रंशतः सेवा की श्रत्यधिक लागत श्रीर वे किटिनाइयाँ है, जो इसे उन प्राइवेट कम्पनियों से मिली थी जिन्हें इसने लें लिया था।

ह्वाई भाड़ा—श्रपनी श्रार्थिक स्थिति को सुधारने के लिये तथा हानि वचाने के लिये ए० श्राई० सी० ने श्रपने भाड़े की दर में वृद्धि की घोषणा १५ जून, १६५८ से एश्रर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की सलाह के श्रनुसार की। किसी-किसी मार्ग के भाड़े में वृद्धि १०% हुई है श्रीर श्रव बम्बई से कलकत्ते का किराया बजाय २२० र० के २४२ र० हो गया है। इस माड़े की वृद्धि से ए० श्राई० सी० को २० लाख रुपये वार्षिक श्रातिरिक्त श्राय होगी। इससे हवाई सेवा पर लगाये

टेक्स के कारण तथा पेट्रोल पर लगाये टेक्स तथा श्रन्य टेक्सों के कारण इवाई सेवा की लागत में वृद्धि का प्रभाव घटाया जा सकेगा—

ए० श्राई० सी० के लिये एश्रर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल ने हवाई भाड़े में नृद्धि की सिपारिश की श्रीर निम्न दरों का सुकाब दिया:

मील		े प्रति मील प्रति यात्री भाड़ा
	•	श्राना पाई में
१ से ३० तक	•••	o
३१ से १०० तक	•••	o
२०१ से २०० तक	****	3-8-0
२०१ से ५०० तक	•••	o-8-E
५०१ से ६०० तक	***	o-8-3
६०० से ऊपर	***	· 0

काउन्सिल की सिकारिश का श्राधार—"श्राधिक दृष्टिकीण से श्रधिकतम संख्या में यात्रियों को श्रधिक काम में श्राने वाले मार्गों की सेवा का प्रयोग करने का प्रोत्साहन देना या ताकि कम प्रयोग में लाये जाने वाले मार्गों से होने वाले घाटे के कारण जो सेवा की लागत श्रीर श्राय में श्रन्तर होता या वह न रहे श्रीर ह्वाई यात्रा के लामों के कारण लोगों के मन में हवाई यात्रा करने की इच्छा स्यायी रूप से उत्पन्न हो जाय।" श्रधिक श्रच्छा होता यदि सरकार टेक्सों की मात्रा कम करके उनकी सहायता करती श्रीर कारपोरेशन श्रपना खर्च कम करने का प्रयत्न करते। हवाई यात्रा के माड़े के बढ़ जाने से उसकी सर्वियता के घट जाने का मय है। एयर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की श्रत्यसंख्यक रिपोर्ट ने भी यह संकेत किया है कि, "भारत में हवाई यात्रा की केंची दरों के कारण हवाई यात्रा के प्रति श्राकर्षण के नष्ट होने का भय है श्रीर इस बात की श्राशंका है कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में हवाई जहाजों द्वारा यात्रा के स्थान पर रेल द्वारा यात्रा करना श्रधिक पसन्द करने लगेंगे।"

योजना के श्वन्तर्गत—प्रथम योजना के श्वन्तर्गत वायुपान कारपोरेशन के निमित्त हि भ करोड़ रुपयों का ज्यय नियत किया गया था। पर वास्तव में प्रथम योजना में १५ ४ करोड़ रुपयों ज्या ज्यय किया गया था जिसमें ह करोड़ रुपयों की रकम एयर काफट खरीदने के लिये सम्मिलित थी। कुछ धन की मात्रा भूमि पर यातामात के साधन खरीदने, वर्तमान दफ्तरों के सुधार तथा नये दफ्तरों के खोलने पर मी ज्यय की गई थी।

हितीय योजना में २० प् करोड़ रुपये व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है जिसमें से १६ करोड़ रुपया तो इन्डियन एश्रर लाइन्स कारपोरेशन पर श्रीर १४ प्र इन्डिया इन्टरनेशनल पर व्यय किया जायगा। व्यय के मुख्य शीर्षक निम्न हैं:—

	करोड़ रूपये में
मुश्रावजे का चुकाना	ሂ ' १ ४
एश्रर काफ्टों का कय	१५ °३४
इन्डियन एम्रर लाइन्स के कार्य में हानि	60.0
इन्डियन एख्रर लाइन्स के दफ्तर श्रीर कर्मचारियों के श्रावास	, ৽ৠ৽
रम्भर इन्डिया इन्टरनेशनल के कारखाने का विस्तार	· १ •દપ્
इन्डियन एअर लाइन्छ के आवश्यक सामान	৽ ৺৴৽
एग्रर इन्डिया इन्टरनेशनल के ऋणपत्रों का नुकाना	30.0
, স্কুল	३०५३

इन्हियन एश्रर लाइन्स के बेढ़े को श्राधुनिक बनाने के निमित्त न्यय का प्रक्रम किया जा रहा है। कारपोरेशन ने ५ वाई काउन्टों के क्रय करने के लिए प्रथम योजना में ही श्रार्डर दे रक्खा था श्रीर श्राशा की जाती है कि १६५७ के मध्य तक वे श्रा जायेंगे श्रीर श्रन्य जहाजों के क्रय करने के लिये श्रार्डर दिये जाने के सम्बन्य में छानशीन की जा रही है। इन्हिया इन्टरनेशनल के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कुछ टवीं-प्राप या जेट एश्रर काफ्ट बढ़ी हुई माँग को पूर्ण करने के लिये तथा श्रितिक सेवा के लिये क्रय किए जायें। इवाई सेवाशों के विस्तार के कार्यक्रम को निश्चित करते समय श्रनेकों बातों का ध्यान में रखना श्रावश्यक होगा जैसे कि क्रय किये जाने वाले एश्ररकाफ्टों के प्रकार, उनको चलाने का व्यय, किराये-भाड़े की दर, संगठन की कुशलता, हानि रोकने की सम्भावना, सेवाशों की सुरत्ता, श्रीर देश के सभी मार्गों को कुशल इवाई सेवा द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित कर देने की श्रावश्यकता इत्यादि।

अध्याय ३८

यातायात का परस्पर सम्वन्ध और नियोजन

भारतीय यातायात व्यवस्था में सुमम्बन्ध स्थापित करने श्रीर उसका. नियोजन करने की दृष्टि से यातायात की सभी प्रकार की सुनिधाश्रों का प्रसार होना चाहिए, यातायात के निभिन्न साधनों में होने वाली श्रनुचित प्रतियोगिता को रोकना चाहिए श्रीर उपभोक्ता के लिए यातायात के व्यय को कम किया जाना चाहिए।

भारत की उनसे बड़ी उमस्या यह है कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यातायात के वर्तमान छावन पूर्णतया अपर्याप्त हैं। यदि प्रति व्यक्ति को प्राप्त यातायात की सुविधा की भारत के बराबर चेत्रफल और जनसंख्या वाले अन्य देशों से तुलना की जाय तो ज्ञान होगा की भारतीयों को अन्य देशों के नागरिकों की अपेचा यातायात की बहुत कम सुविधा प्राप्त है। यदि रेलवे और हवाई मार्ग की लम्बाई दूनी कर दी जाय और जलयानों की माल ढोने की शक्ति को चार गुना बढ़ा दिया जाय तब भी इसे बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है, हाँ इससे देश की आवश्यकता अवश्य पूर्ण हो सकती है।

किसी मी देश के यातायात की सुविधा में वृद्धि का उसके श्रीद्योगिक श्रीर श्रार्थिक विकास से निकट सम्बन्ध होता है। देश के श्रार्थिक विकास के लिए यह श्रावश्यक है कि उसमें यातायात की सुविधा पर्याप्त हो, सस्ती हो श्रीर यातायात की गति तीव हो। उद्योगों के लिए यातायात व्यय उत्पादन का महत्वपूर्ण श्रंग है इसलिए उद्योगों का व्यय घटाने के लिए यातायात का व्यय घटाने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। यातायात व्यय कम होने से उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति वढ़ेगी श्रीर माल का उपमोग भी बढ़ेगा। किसी भी देश की प्रगति में उसके यातायात की व्यवस्था, रेलवे, सक्कों श्रीर हवाई जहांनों तथा जलयान कम्पनियों की किराया एवं भाइन नीति श्रीर उसमें विभिन्न प्रकार के सामानों के यातायात की सुविधा का विशेष योग होता है। यदि यातायात नीति दोषपूर्ण है तो उद्योगों का स्थानीकरण भी दोषपूर्ण होगा। यातायात पर केवल उद्योगों का विकास निर्मंर नहीं करता है किन्तु श्रीद्योगिक विकास के प्रकार पर भी यातायात का प्रकार श्रीर उसका विकास निर्मंर करता है।

पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि आगामी कुछ वर्षों में देश में

खाद्याल का उत्पादन बहुने से श्रीर िम्द्री में रसायनिक खाद का श्रिषक उत्पादन होने से इन वस्तुश्रों का श्रायात कम करना पड़ेगा, जिसके कारण वन्दरगाहों से इन वस्तुश्रों को देश के विभिन्न भागों में पहुँचाने के लिए यातायात की कम स्त्रावश्यकता होगी श्रीर ऐसी स्थित में देश के श्रान्दर हुए उत्पादन को नियत स्थानों तक पहुँचाने के लिए यातायात को व्यवस्था में वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरी श्रीर राजगंगपुर के सिमेंट के कारखाने से जिसने १९५२ के श्रारम्भ से उत्पादन श्रारम्भ कर दिया है श्रीर विजयवाडा में स्थित श्रान्ध्र सिमेंट कम्पनी के प्रसार से उपभोग के केन्द्रों में ही उत्पादन व्यवस्था का प्रसार होने के फलस्वरूप यातायात की सुविधा की मौंग कम हो जायगी। साधारणतया योजना को कार्यान्वित करने का प्रभाव यह होगा कि यातायात की सुविधा श्रों को बढ़ाने की मौंग बढ़ेगी। इसलिए यह श्रावश्यक है कि (श्र) यातायात की सुविधा का प्रसार किया जाय, (व), यातायात की सुविधा श्रों को बढ़ाने के कारखों का पता लगाया जाय श्रीर सि दातायात की सुविधा श्रों को बढ़ाने के कारखों का पता लगाया जाय श्रीर सि क्रायात की सुविधा लाय।

भारत में वास्तविक कठिनाई यह है कि पंचवर्षीय योजना के होते हुए भी विक्रास ही गति बहुत धीमी है। पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी बातायात की सुविधाएँ देश की आवश्यकता को देखते हुए कम ही रहेंगी। याता यात के सुविधा में तीव्र गति से प्रगति न होने के अनेक कारण हैं:

(१) दित्त का अमाव है, इस कारण अधिक सहकों का निर्माण करने में, अधि क रेलवे लाइन विछाने में और रेलवे के लिए अधिक रोलिंग स्टाक क्रय करने में, सहकों के लिए मोटर तथा वस क्रय करने में और विमान तथा जलयानों को क्रय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केवल प्रसार योजना की माँग पूर्ण करने के लिए ही नहीं किन्तु वर्तमान में चालू गाड़ियों, वसों और जलयानों की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने सभी उपलब्ध विस्त सामनों का वातायत की वर्तमान स्थित के सुधार में और उसके प्रसार में सुसम्बद्ध उपाय से व्यय करना चाहिए। दूसरी कठिनाई यह है कि यातायात के सामनों के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं। यदि वित्त आवश्यकता पूर्ण भी हो जाय तब मी उससे इतनी अधिक मूल्यों पर सभी आवश्यक सामग्री नहीं क्रय की जा सकती। वित्त अभाव और सामानों का अधिक मूल्य होने के कारण मारत में यातायात की सुविधा के प्रसार में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

- (२) सहक बनाने और रेलवे लाइन विछाने के लिए आवश्यक सामान का अमाव है। इसके साथ ही मोटरों, रेलों के हिन्बों, इझनों, जलयानों, विमानीं और इनके अलग कल पुजों तथा स्टोर का भी बहुत अभाव है। इनमें से अधिकांग के लिए भारत को विदेशों से आयात पर निर्मर करना पड़ता है। इघर कुछ वर्षों से भारत में इझनों, जलयानों इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु अभी बहुत लम्बा मार्ग तय करना है। मारतीय यातायात के विकास की समस्या का (अ) सहक अथवा रेल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करनेवाले उद्योगों के विकास से और (व) मोटर तथा जलयानों का निर्माण करनेवाले उद्योगों के विकास से ग्रहरा सम्बन्च है। उद्योगों के घीरे-घीरे विकास होने से यातायात की सुविधा की प्रगति भी सीमित हो गई है।
 - (३) कुशल कारीगरों, इंजीनियरों, विमान चालकों इत्यादि का बहुत श्रमाव है, यातायात की व्यवस्था का विकास करने के लिए इनका श्रमाव नहीं होना चाहिए। इसलए इनकी संख्या को बहुत श्रिषक बढ़ाने की श्रावश्य ता है। सरकार ने कारीगरी की शिक्षा के लिए। वशेष व्यवस्था की है श्रीर याद्धी गत की सुविधाओं का प्रसार उसी गति से होगा जिस गति से कारीगरों श्रीर श्री त्य कुशल कर्मचारियों के श्रमाव की पूर्ति होगी।

यातायात में सुसम्बन्ध स्थापित करने की नीति का उद्देश्य है क्डिपरं को यातायात में कम से कम न्यय करना पड़े। इसका तर्कसंगत हिरणाम १ यह निकला कि हमें यावायात के उन सभी साधनों को समाप्त कर नचे साधनों उपयोग करना पड़ेगा नो उपयुक्त नहीं हैं: समय की माँग पूर्ण नहीं कर हैं श्रीर पुराने हैं। उपमोक्ता के लिए सहक यातायात रेलवे की अपेद्धा श्राह्मीक सत्ता और सुविधाजनक है क्योंकि सहकों से आसपास के समी सेत्र लाम सकते हैं श्रीर रेलवे स्टेशन तक माल ले जाने श्रीर वहाँ से लाने में जो श्रनाव स्पर्क व्यय होता है उसकी वचत हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है चि सदक यात पाव के प्रसार और विकास से या तो रेल यातायात बन्द हो जायगा या उसका वित्र संकुचित हो जायगा। यदि मोटर, ट्रक श्रीर वसे बैलगाहियों से श्रिधिक विचत वाले श्रीर तीव्रगति चल सकने वाले साधन हैं तो इसका तित्यर्थ है कि भागरें अरि कस्त्रों में वैलगाहियों का श्रस्तित्व ही रह जायगा। यदि भाप से चलने वाले जलयान हवा से चलने वाले जलयानो से अधिक बचत वाले हैं तो हवा से चलने वाले जलयानों की श्रावश्यकता हो नहीं रह जाती। परन्तु व्यवहपरिक चेत्र में इस प्रकार का तीन परिवर्तन न तो संमव है श्रीर न इसकी सलाह दो जा सकती है क्योंकि (१) पूँजी इस समय ऐसे सामनों में लगी हुई है जो श्राधिन क

सामनों की तुलना में कुशल सामन नहीं कहे जा सकते। यदि इन सामनों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय या इनका कार्यनेत्र संकुचित कर, दिया जाय तो इसके परिशामस्वरूप राष्ट्र को गहरी क्षित पहुँचेगी। ऐसी स्थित में यातायात के पुराने साधनों के स्थान पर नये साधनों का उपयोग करना एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें काकी श्रिषक समय लगेगा। यातायात के कुशल श्रीर उपयुक्त साधनों का धीरे-धीरे उपयोग बढ़ाया जायगा श्रीर श्रकुशल तथा श्रपेनाकृत कम उपयुक्त साधनों को धीरे धीरे हटाया जायगा। यह प्रक्रिया तब तक प्रचलित रहेगी जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता; (२) भारत में कुछ समय तक हवा से चलने वाले जलयानों श्रीर वैलगादियों का उपयोग करना पढ़ेगा श्रन्यथा यातायात की माँग श्रीर उसकी पूर्ति का श्रन्तर श्रीर बढ़ता जायगा। मारत में यातायात की कुल व्यवस्था ऐसी है कि हम श्रमी काफी समय तक श्रकुशल श्रीर पुराने साधनों को समाप्त नहीं कर सकते।

इस स्पिति को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सर्वोत्तम नीति यह होगी कि वर्तमान के यातायात के साधनों को प्रचित्तत रखा जाय और (श्र) कार्य को सुनियोजित करके, कुछ साधनों के श्रत्यधिक कार्य भार को हल्का करके श्रीर श्रनेक साधनों की उपयुक्त शक्ति का उपयोग करके यातायात की वर्तमान न्यवस्था का दुश्पयोग बचाया जाय; (ब) यातायात से विभिन्न साधनों की परस्पर श्रनुचित प्रतियोगिता को रोका जाय, साथ ही एक ही प्रकार के साधन की विभिन्न इकाइयों की श्रनुचित प्रतियोगिता को समाप्त किया जाय; श्रीर (स) रेलवे, सदक, जल यातायात तथा हवाई कंपनियों को उचित लाम के साथ ही साथ उपभोक्ताश्रों के लिये यातायात सस्ता किया जाय।

वर्तमान में रोडवेज और रेलवे, रेलवे और जल यातायात और रेलवे तया वायु यातायात में तीज प्रतियोगिता नहीं है। यातायात के सभी साधनों का अभाव है और सभी साधनों के कार्य तेज पर्याप्त हैं हस्तिए कुछ अपवादों को छोड़कर व्यापार हिययाने के लिए इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसके साथ, ही विभिन्न साधनों का किराया इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि प्रतियोगिता नहीं हो। सरकारी वर्से वर्तमान में वस्त्रई तथा उत्तर प्रदेश में भिन्नभिन्न किराया वस्त्रती हैं। बस्त्रई का किराया द से ह पाई प्रति मील है और उत्तर प्रदेश का ७३ से ह पाई प्रति मील है, जब कि रेल की तीसरी अधी का किराया साधारण या डाक गाड़ी से १५० मील तक कमशः ५३ और ६५ पाई प्रतिमील है। वायुयान का किराया प्रायः ४ आना प्रति मील है और रात की डाक सर्विस से किराया २३ आना प्रति मील है। जब कि रेलवे की प्रथम

श्रेणी का किराया २ है से २ इशाना प्रति मील है। वसों श्रीर रेलों में कुछ चेत्रों में ख्रवश्य प्रित्मोगिता चलती है पर बड़े पैमाने पर कोई श्रमुचित प्रतियोगिता नहीं है। वायुयान से यात्रा श्रमी श्रवश्य कुछ महंगी है श्रीर रेलवे यात्रा से छुछ श्रिक भयपद भी है। कुछ उच्च श्रेणी के यात्रियों के श्रांतिरिक्त वायु यातायात से रेलवे को कुछ हानि नहीं है परन्तु भविष्य में जैसे-जैसे सदक श्रोर वायु यातायात श्रिक सहता श्रीर कम भयपद होता जायगा वैसे-वैसे रेलवे से श्रांतियोगिता भी बहती जायगी।

मारत के कुछ भागों में जलयानों द्वारा तटीय यातायात में श्रीर रेल के यातायात में प्रतियोगिता चलती है श्रीर देश के विमानों की तटीय व्यापार में जलयानों से प्रतियोगिता चलती है परन्तु तटीय जलयान व्यापार को नियमित कर देने से यह प्रतियोगिता कम हो गई है। भविष्य में पुनः प्रतियोगिता बढ़ने की सम्भावना है, परन्तु इनमें श्रनुचित प्रतियोगिता बढ़ने का कोई कारण नहीं है। भविष्य में रेल वे लाइन से समकीण बनाती हुई सदकों का निर्माण करके श्रीर सइकों के प्रसार की ऐसी योजना बनाकर कि उनसे विभिन्न बन्दरगाही में जल ये।तायात की श्रावश्यकताश्रों की पूर्वि हो सके यातायात के विभिन्न साधनों के वीच उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकने की पूर्ण सम्भावना है। रेल वे तथा जल यातायात के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें व्यवस्था की गई है कि मँगलीर वन्दर से रेल सम्बन्ध चिकामगलुर होते हुए मद्रास से सम्बन्ध किया जाय।

यदि यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण किया जाय तो इनमें परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकना सुगम हो जायगा। यदि सभी साधनों की स्वामी सरकार हो श्रीर वही इनको चलाये तो सइकों को जोइने श्रीर एक स्थान पर कई प्रकार के यातायात उपलब्ध होने इत्यादि में व्यर्थ रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। निजी उद्योग होने पर ऐसा त्रावश्यक हो जाता है। सरकार ने सहक यातायात का एक सीमित चेत्र में राष्ट्रीयकरण किया है जिसके कारण इन चेत्रों में रोडवेज श्रीर रेलवे के मध्य कोई श्रन्जांचत प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीयकरण किये हुये सहक यातायात से रेलवे को सहायता मिलती है। यह सबकें विमिन्न चेत्रों को रेलवे मार्ग से सम्बन्धित करती है। सहक यातायात को निश्चत चेत्र में एक विशेष दूरी तक सीमित करके श्रीर रोडवेज सिर्व को उन सहकों पर चालू करके जहाँ रेलवे यातायात की सुविधा नहीं है यह परिणाम निकला है। रेलों से यात्रियों की सुविधा का प्रवन्य बद्दा है श्रीर किराये में भी वृदि हुई है श्रीर इससे दोनों में श्रनुचित प्रतियोगिता की हानियों को समाप्त कर दिया गया

है। यद्यपि राष्ट्रीकरण कर देने से अनुचित प्रतियोगिता तो समाप्त की जा सकती है परन्तु यह न्यनस्था सभी स्थितियों में सुविधाननंक सिद्ध नहीं हो सकती। भारतीय रेलों और वायुयान कम्पनियों का कुछ धोड़े छोटे मार्गों को छोड़ कर पूरी तरह राष्ट्रीकरण किया जा चुका है और सहक यातायात का बहुत सा भाग भी राज्य सरकारें ले चुकी हैं, परन्तु कुछ चोजों में सहक यातायात और पूरा जल यातायात अभी निजी उद्योगपितयों के हाथ में है। यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण करना सम्भव नहीं है क्योंकि (१) आवश्यक कर्मचारियों का अभाव है और (२) हानि हन्ने का हर है। यह हानि विशेषकर जल यातायात में अधिक हो सकती है क्योंकि इसका पूर्ण विकास नहीं हो सका है और उसे विदेशी जलयान कम्पनियों की कड़ी प्रतियोगिता का समाना करना पड़ता है। यह कहना अनुचित न होगा कि राष्ट्रीकरण से हानिकारक प्रतियोगिता की समस्या सुलकाई जा सकती है। इसके साथ ही इसमें एकाधिकार के दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं जैसे उपमोक्ता के हितों की उपेका, कार्य व्यय में वृद्धि और अकुशल कार्य। यदि हानिकारक प्रतियोगिता को समाप्त करने से नई समस्याएँ उत्पन्न हो जायँ तो इस व्यवस्था को उपसुक्त नहीं कहा जा सकता।

यातायात का पूर्ण राष्ट्रीकरण न हो छकने पर भी यातायात के विभिन्न छाधनों में निम्निल्लित उपायों से परस्पर उचित छम्बन्ध स्थापित किया जा छकता है:—(१) कानून द्वारा प्रत्येक प्रकार के यातायात के कार्यचेत्र को निर्धारित करके, विभिन्न छाधनों के श्राधिकतम श्रीर न्यूनतम किराये की दर निश्चित करके श्रीर विभिन्न छाधनों होरा यात्रियों को दी जानेवाली न्यूनतम धुविधाशों श्रीर सामान के यातायात की सुविधाशों को निश्चित करके; (२) यातायात के विभिन्न छाधनों के कार्य के निरीक्षण के लिए श्रीर उनमें उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये केन्द्रीय यातायात परिषद् स्थापित करके। यातायात की व्यवस्था में परिस्थितियों के श्रनुष्ठार धीन्न परिवर्तन हो जाता है इर्धालये यातायात के विभिन्न छाधनों के तथा उपभोक्ताशों के हितों की केवल कानून द्वारा ही रज्ञा की जा सकती है। इसि किराये की दरों में घटने-बद्धने की सम्भावना समाप्त हो सकती है श्रीर जनता को श्रमुविधा हो सकती है परन्तु यह कठिनाहयाँ पर्याप्त श्रीषकार दिये जाने पर श्रीर सन्तोषजनक रीति से कार्य कर सकने के लिए व्याप्त चेत्र देने पर राज्य यातायात परिषद् दूर कर सकती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५५७ करोड़ क्ष्या यातायात श्रीर संचार विमाग के लिये नियत किया गया था। यह धन योजना के कुल व्यय का २३.६% या। द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत १३८५ करोड़ रुपया, जा कि कुल योजना के क्यय का रू है, यातायात श्रीर संचार विभाग पर व्यय करने के लिये नियत किया गया है। इस १३८५ करोड़ रुपये में से रेलवे, सड़क, सड़क यातायात, बन्दरगाहों, जल यातायात श्रीर हवाई यातायात पर क्रमश: ६०० करोड़ (कुल व्यय का १८५८%), २४६ करोड़ (५°१%), १७ करोड़ (०°६%), ४५ करोड़ (०.६%), ४८ करोड़ (१°०%) श्रीर ४३ करोड़ (०°६%) व्यय किया जायगा। प्रथम योजना के श्रन्तर्गत ५५७ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इन्हीं शीर्पकों पर क्रमश: २६८ करोड़ (११°४%), १३० करोड़ (५°५%), १२ करोड़ (०°५%), ३४ करोड़ (१°४); २६ करोड़ (११%) श्रीर २४ करोड़ दुपया (१°०%) व्यय किया गया था। इन श्रांकड़ों से जात होता है कि कुल व्यय का प्रतिशत व्यय रेलवे पर बढ़ा दिया गया है श्रीर श्रन्य साधनों पर कुछ घटा दिया गया है।

	१९५०-५१ की स्थिति	१९५५-५६ में : श्रनुमानित स्थिति	१६६०-६१ तक ध्येय
रेलवे		1.	
(१) पैसेन्जर गाड़ियाँ (मील दस लाख में) (२) माल जो लादा गया(दस लाख टनों में)	દ્યું	१०८	१२४
सङ्क- -	٤٤ ;	१२०	१६२
(१) राष्ट्रीय राजपय (इजार मीलों में)	१ २.३	17E	े१३ ग्द
(२) सरफेरड रोड्स (हनार मीलों में)	89	१०७	१२५
जहाज— (१) तटीय श्रीर पड़ोछी से सम्बन्धित टेन्करों को सम्मिलित करते हुये		, ,	,
(लाख नी. श्रार. टी.)	₹.₹	₹.₹-	४°३
(२) समुद्र पार ट्रैम्प टनेज को सम्मिलित करते हुये (लाख जी. श्रार. टी.)			
	\$.0	२.८	8.0
बन्दरगाह— स्वा करने की शक्ति (दस लाख टर्नो में)	२०	्रथ्र ०	इर्प

कपर दिये गये आँकड़ों से यह जात होता है कि द्वितीय योजना के अन्त-गंत सर्वतीन्मुखी विकास का प्रयत्न किया जायगा। १९५५-५६ की तुलना में सब से अधिक प्रतिशत् वृद्धि १९६०-६१ में समुद्र पार की जल प्रातायात के सम्बन्ध में की जायगी। जल यातायात के सम्बन्ध में ६८%, रेलवे में १५%, तटीय जल यातायात में २४% थ्रीर बन्दरगाहों पर माल उतारने चढ़ाने की शक्ति में २०% की चृद्धि की जायगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय यातायात सम्बन्ध में यह था, कि यथासम्भव गत १० वर्षों से ब्रात्यविक कार्य में ब्राने वाले प्रसाधनों को बदल कर नया कर दिया नाय। रेलवे के सम्बन्ध में यह कार्य बहुत कठिन या। जल यातायात, बन्दरगाहों, प्रकाशस्तम्भों, वायु यातायात आदि के सम्बन्ध में भी इस कार्य के लिए बहुत बड़ी घनराशि नियत करनी श्रावश्यक थी। प्रथम योजना काल में क्योंकि कृषि श्रीर उद्योगों की उत्पत्ति में वृद्धि हो गई थी इसलिये याता-यात की सुविधा के अमान का अनुमन विशेषकर योजना के तीसरे वर्ष से होने लगा था। इस स्थिति को सम्भालने के लिये अतिरिक्त धन का श्रनुमान रेलवे, सदकों, जल यातायात, नदियों श्रीर वायु यातायात के लिये किया गया श्रीर इनके विकास के कार्य-कम में भी वृद्धि की गई। रेलवे के गंत्रयानादि के क्रय का कार्य-क्रम बढाया गया और उन चेत्रों में लाइने बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न किया गया जहाँ रेल यातायात की माँग अधिक थी। एक अन्तर्विभागीय अन्वेषण वर्ग द्वारा यातायात के सभी साधनों के पारस्परिक विकास सम्बन्धी प्रश्न पर श्रीर मुख्यतः सड्क यातायात के विकास सम्बन्धी प्रश्न पर जो बढ़ती हुई माँग के हिरान से बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ था विचार किया गया । सहक यातायात के व्यक्तिगत भाग में विकास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के सिये उपाय किये गए श्रौर लाइसेन्स देने की नीति को श्रिवक उदार बनाया गया । भारतीय जल यातायात की सहायता के उपाय भी किये गये।

यद्यपि प्रकाधनों के नवीनतम करने के कार्य अपी शेष हैं फिर मी द्वितीय योजना में देश के यातायात छाधनों के समुचित विकास की (विशेष कर रेखवे की जिसके द्वारा सदा से अधिकतम यातायात की सुविधा प्रदान की गई हैं) व्यवस्था की जा रही है। रेलवे के विकास के कार्य-कम का देश के अधिगिक विकास के साथ विशेषकर बढ़े-बढ़े उद्योगों, जैसे स्थात, कोयला, सिमेंट आदि, के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखना आवश्यक होगा। द्वितीय योजना विभिन्न यातायात के साथनों के बीच पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयत्न करती है। सक्क यातायात की सुविधा में जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है रेलवे द्वारा अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे और तटीय जल यातायात तथा रेलवे और नदी द्वारा यातायात के सामंजस्य पर और भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्तर्गत मुख्य-मुख्य

यातायात साधनों श्रीर उनके पारस्परिक सामंगस्य के श्रविकतम विकास की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि प्रत्येक श्रपने-श्रपने चेत्र के कार्य को श्रच्छे से श्रच्छे दक्त से पूर्ण कर सके। इस स्थिति का निष्कर्ष यह है कि श्रागामी: पाँच वर्षों में सभी प्रकार के यातायात साधनों की माँग बहुत श्रिषक बढ़ेगी, इसलिय यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिवर्ष यातायात श्रीर संचार के विकास के कार्य-क्रम पर विचार किया जाये ताकि नहीं कहीं श्रावश्यक हो ऐसे उपायों को श्रप-नाया जाय जिनसे यातायात की कठिनाहयों के कारण योजना के श्रन्य कोई कार्य-क्रम में बाधा न पड़े।

अध्याय ३६

विदेशो च्यापार

भारत के विदेशी व्यापार को युद्धकाल में श्रीर युद्धकाल के पश्चात् श्रनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है। द्वितीय विश्वयुद के समय यातामात की कमी होने से, कच्चे माल, रसायनिक इत्यादि का श्रभाव होने से, विदेशी विनिमय मुद्रा की कठिनाई श्रीर सरकार के श्रानेक नियंत्रण श्रादेशों से भारत के विदेशी व्यापार में बहुत बाघा हुई। युद्ध के पश्चात्काल में अगस्त १६४७ को देश का विभाजन हो जाने से भारत का विदेशी व्यापार छिन्न-मिन्न हो गया। विभाजन के पूर्व मारत में कपास, जूट, तिलहन, खाल, चमझा इत्यादि का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था ख्रीर देश की ख्रावश्यकता पूरी करने के उपरान्त इनका निर्यात किया जाता था। विभाजन के पश्चात् भारत में इनमें से श्रिधिक-तर कच्चे माल की कमी हो गई। इसका परियाम यह हुआ कि इनका निर्मात घट गया, जो उद्योग इन पर निर्भर करते ये वह श्रपना उत्पादन नहीं बढ़ा सके श्रीर हमें श्रपनी श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक मूल्य पर कपास श्रीर श्रन्य श्रावश्यक करचा माल विदेशों से श्रायात करना पड़ा । विभाजन के पूर्व पाकिस्तान के कुछ भागों से देश की खाद्यान की श्रावश्यकता की पूर्ति होती थी। विभाजन से देश के कुछ सबसे अधिक उपजाक चेत्र पाकिस्तान के माग में चले गये जिससे देश को खाद्याल की कमी का भी सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप भारत को खाद्यान का बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से श्रायात करना पड़ा। विमाजन के पूर्व पाकिस्तान भारत का एक श्रंग था श्रौर पाकिस्तान के चेत्र मारत के स्वदेशी व्यापार चित्र ये परन्त विभाजन से वह चेत्र विदेशी बन गये। यद्यपि स्वदेशी व्यापार श्रव भी विदेशी व्यापार की अपेचा अधिक है फिर भी उक्त परिवर्तनों से घरेला तथा विदेशी ज्यापार के सापेश्विक महत्व में काफी परिवर्तन आ गया है ।

श्रायात-निर्यात व्यापार का सन्तुलन—विश्वयुद्ध से पहले श्रौर विश्वयुद्ध के समय मारत के विदेशी व्यापार की स्थिति श्रनुकूल थी। इसमें श्रतिरिक्त बचत हुई यी परन्तु युद्ध के पश्चात् काल में विदेशी व्यापार का सन्तुलन निरन्तर प्रतिकृत होता गया। जैसा तालिका १ में दर्शाया गया है, १६५१-५२ में श्रायात-निर्यात की यह प्रतिकृत स्थिति २२१'६५ करोड़ कपये तक पहुँच गई। पर सीमाग्यवश १६५२-५३ से लगाकर १६५५-५६ तक श्रसंतुलन २०० करोड़ इपये

से कम का ही रहा श्रीर १९५६-५७ में ही केवल पुन: वढ़ कर २३१ ३३ करोड़ रुपया हो गया। युद्ध से पूर्व यह श्रावश्यक था कि विदेशी व्यापार की स्थिति श्रातुक्ल हो श्रीर श्रातिरिक्त बचत रहे जिससे श्राण का व्याज चुकाया जाय, रेलवे श्रीर सिंचाई के साधनों का वार्षिक भक्ता दिया जाय, श्रीनिक कार्यालयों का,

तालिका नं ० (१) भारत का कुल आयात और निर्यात (करोड़ क्यों में)

वर्ष	श्रायात	निर्यात	त्रसंतुलन		
१९५१-५२	हत्र ४. तह	४३.६६	२२१•६५		
१९५२ ५३	६७० °०७	४७८'०७	- 62.00		
१९५६-५४	५७२॰०७	५३०°६६	84.5E		
રદય૪- યથ	६५६'४४	4€३.€⊏	६२.४६		
१९५५.५६	33703	प्रह७.८ई	८१.प्रेह		
१९५६-५७क	⊏₹₹ %₹	€02.0€	—-२३ १ '३३		

*श्रनुमानित

तालिका नं० (२)

मात्रा, मूल्य तथा आयात निर्यात व्यापार संबंधी श्रतुपातिक निर्देशांक श्राधार १९५२-५३=१००

2	१६५२-	१९५३-	१६५४-	१९५५-	१९५६-	१६५७-
•	યુર્	પુજ	યુપ્	मू ह	मू७	પ્રદ
श्रायात						
मात्रा निर्देशांक	१००	€३	११०	. ११६	१३७	१५२
मूल्य निर्देशाक	१००	દર	SE.	50	80	33
निर्यात		ĺ				
मात्रा निर्देशाक	200	200	१०५	११प्	११०	१ २०
मूल्य निर्देशाक	200	F3	ĘĘ	8.	8.3	£X
श्रायात निर्यात						
व्यापार के श्रनुपातिक						
सम्बन्ध का निर्देशांक	200	₹00	११०	₹ ०₹.	१०४	. <u>E</u> ¥

सेना श्रीर जहाजों का, इषिडया श्राफिस श्रीर मारत के लिये स्टोर खरीदने का ज्यय दिया जाय श्रीर लुटी के भत्ते का भ्रातान किया जाय। युद्ध श्रारम्म होने के पहले के चार वर्षों में हन मदों में श्रीसतन कुत्त ३ करोड़ ५ लाख पींड ज्यय हुशा।

परन्तु श्रव यह श्रावश्यक नहीं है कि श्रायात-निर्यात न्यापार का सन्तुलन बरावर श्रन्तुल्ल ही हो क्योंकि (१) पंचवर्षीय योजना के बहे पैमाने पर श्राधिक नियोजन करने पर प्रतिकृत न्यापार सन्तुलन श्रसंनय नहीं है। योजना सफल बनाने के लिए देश को बड़ी संख्या में मशीनों, कच्चे माल हत्यादि का श्रायात करना पड़ता है। बिना हस सामग्री के योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। (२) युद्ध काल में भारत के नाम काफी पीयड-पावना जमा हो गया। एक बार कुल पावना १७३३ करोड़ क्या हो गया था। (३) भारत ने श्रमरीकी सरकार, श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप हत्यादि से जो श्र्मण लिये हैं उनकी रकम में से भी प्रतिकृत व्यापार सन्तुलन के घाटे की पूर्ति की जाती है। परन्तु हसमें कुछ सन्देह नहीं कि प्रतिकृत व्यापार सन्तुलन देश की दुर्वलता का चिन्ह है श्रीर यदि इसमें एक सीमा से श्रधिक बृद्धि होती है या घाटा काकी लम्बे समय तक चलता है तब श्रवश्य यह चिन्ता का विषय बन जाता है।

भारत सरकार ने १६४= में मुद्रास्कीति को रोकने के लिए श्रीर उपमो-काश्रों एउम् उद्योगों की मांगों की पूर्त करने के लिए उदार श्रामात नोति श्रपनायी। इसका परिखाम यह हुश्रा कि श्रायात की माशा बढ़ गई श्रीर १६४८-' ४६ में ६४३:८५ करोड़ काये का श्रायात किया गया। इसके विपरीत श्रीद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने से, कच्चे माल की कमी होने से श्रीर निर्यात की जाने याली श्रन्य वस्तुश्रों के श्रभाव से मारत का निर्यात व्यापार न बढ़ सका।

ये सब अनुक्ल परिस्थितियाँ १६५१ के आरम्भ में प्रायः समाप्त होने लगी । कुछ मामलों में तो पहले ही समाप्त होने लगी थीं । अवमूल्यन का लाभ अस्पायी सिद्ध हुआ । सरकार ने १६५१ के आरम्भ में अपनी न्यागर नीति बदली और निर्यात को प्रोत्साहन देने की अपेदा जो कुछ साधन उपलब्ध ये उनका उपयोग स्वदेश की माँग पूरी करने में किया जाने लगा । कुछ वस्तुओं का जैसे अलीह-धातुओं और कचो खाल का निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया गया; अनेक वस्तुओं जैसे सूनी कपड़े, कपास, तेल और तिलद्दन के निर्यात पर प्रतिवन्ध लगा दिये । कुछ वस्तुओं जैसे जूर के सामान, सूनी करड़े हरयादि पर निर्यात कर लागू कर दिये गये । विश्व में शान्ति स्थापित होने को सम्मावना के बदने के साथ हो प १ चमी

देशों को पुनः शास्त्रीकरण की श्रीर स्टाक एकत्र करने की योजना को कार्यान्वित करने की गति मंद पड़ गई श्रीर १९५१ के मध्य तक भारतीय वस्तुस्रों की माँग में हुई वृद्धि समाप्त हो गई। कुछ भारतीय वस्तुश्रों की माँग में संकुचन श्राने से मन्दी के लक्त्या दृष्टिगोचर हुए इससे भारतीय निर्यात व्यापार बहुत घट गया। १९५२ के ग्रारम्भ में कीमर्ते वास्तव में गिर गईं। १९४९-५० श्रीर १९५१-५२ में व्यापार सन्त्रलन की श्रमुकुल स्थित अब प्रतिकृल हो गई। निर्यात की जाने वाली वस्तुस्रों की कीमतें भी घट गई इससे १६५१-५२ में व्यापार सन्तुलन की स्थिति श्रीर बिगड़ी श्रीर २२१ ६ भ करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा । १६५२-५३ ते स्पिति कुछ सुघरी क्योंकि कुछ तो सरकार की नीति से श्रीर कुछ स्टाक जमा हो जाने के करण खादाल तथा श्रान्य वस्तुश्रों के श्रायात में कमी कर दी गई। यद्यपि भारत को श्रायात की गई वस्तुत्रों की कीमत निर्यात की जाने वाली वस्तुत्रों की कीमत की त्रपेद्या श्रधिक चुकानी पड़ी फिर भी न्यापार-छन्तुलन में (जैसा तालिका र में दर्शाया गया है) १९५२-५३ में केवल ६२ ०० करोड़ रुपये का ही घाटा उठाना पड़ा। १९५३-५४ श्रौर १९५४-५५ में व्यापार का हमारे विरुद्ध श्रसन्त्रलन श्रीर श्रधिक घट कर ४१ ३६ करोड़ उपये तथा ६२ ४६ करोड़ उपये क्रमशः हो गया । परन्तु फिर स्थिति ने प्लट खाया । श्रीर हमारे विरुद्ध श्रसंतुलन की मात्रा १६५५-५६ में ८१'५६ करोड़ तथा १६५६-५७ में २३१'३३ हो गई श्रीर ऐसा अनुमान है कि १६५७-५८ में यह मात्रा बढ़कर ख्रीर भी अधिक हो बायगी। इस वृद्धि का कारण प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष में तथा द्वितीय योजना के प्रयम दो वर्षों में आयात की मात्रा में अल्यधिक वृद्धि है जो कि विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये की गई थी और आयात के नीति के दहता से संशोधित करने के पहिले बड़ी अरलता श्रीर उदारता से श्रायात लाइसेन्स देना था। यदि श्रायात के साय-साथ निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हुई होती तो भी कोई लाम न होता परन्तु यह सम्भव न हो सकता था क्योंकि, भारत में ही निर्यात की वस्तुश्रों के अतिरेक की मात्रा में कमी आ गई थी, (२) कर के आधिक्य तथा मजदूरी बढ़ने से निर्यात की कुछ वस्तुश्रों का मूल्य श्रन्य वस्तुश्रों की श्रपेस्ना श्रिघिक बढ़ गया था, श्रीर (३) विदेश की वाजारों में तीव स्पर्धा के कारण तथा श्रन्य कारणों में भारतीय वस्तुत्रों की मांग घट गई थी। सबसे श्रिधिक श्रिहित की बात तो यह थी कि श्रायात निर्यात त्रनुयात निर्देशांक इमारे विपक्त सेवढ़ रहा था। १६५४-५५ में ११० या (तालिका न॰ २) श्रीर १६५६-५७ में १०४ हो गया तथा १६५७-५८ में उससे घट कर ६५ होने का मय था। इसका कारण यह था कि भारत को ग्रायात माल की ग्रीसत कीमत निर्यात माल से प्राप्त श्रीसत कीमत की श्रपेचा श्रधिक देनी पड़ी।

भुगतान का सन्तुलन (Balance of Payment)—प्रत्यक् श्रायात श्रीर निर्यात के श्राघार पर सुगतान का सन्तुलन निश्चित किया जा सकता है। इसमें वस्तुश्रों का श्रायात-निर्णत, श्रप्रत्यक् श्रायात श्रीर निर्यात जैसे श्रुण श्रीर दान, यातायात का न्यय, हाक, भीमा तथा श्रन्य कार्यों के लिए न्यय, अमगापियों श्रीर विदेशी लोगों हारा खर्च की गई मुद्रा इत्यादि सम्मिलित है। श्रप्रत्यक्त मदों में युद्र के बाद के वर्षों में वृद्धि हुई है श्रीर इससे सुगतान के सन्तुलन में कुल जितना घाटा है उसमें कुछ कमी हुई जैसा निम्न तालिका में दर्शाया गया है —

तालिका २ सुगतान का सन्तुलन (करोड़ रुपर्थों में)

	१ ६ ५१-	१९५२-	१९५३-	१९५४-	१६५५-	१६५६-
	પ્રર	પ્રર	યુષ્ટ	પ્રય	પ્દ	प्र७
बास्तविक ग्यापार बचत	~२ ३२′⊏	-38.8	~પ્રર∙₹	=0.5	-\$08.4	-¥\$£.#
श्रप्रत्यन्त मदो से बारतयिक बचत	+60.5	+€१'₹	+ <i>६६'</i> ५	+ ٤३ • २	+ १२६~	+ १४७.०
वर्तमान स्थित	<u> </u>	+60.5	+40.8	+4.0	+ १६%	-2E 2.4

"भुगतान के संतुलन पर वहुत श्रिक प्रभाव भारतीय श्रिर्धिक व्यवस्था की विकास योजनाश्रों की प्रगति पर लिंचत हुआ। प्रथम योजना के श्रिष्ठ श्रिष्ठ काल में भुगतान के संतुलन के हिताब में निरन्तर श्रितिरेक होता रहा। १६५६-५७ में यह प्रवृत्ति पूर्ण्रू पेया उलट गई श्रीर चालू हिसाब में २६२ ५५ करोड़ रुपयें का धाटा हुआ और देश के विदेशी विनियम कीय से २१६ करोड़ रुपये लेने पड़े। इसका मुख्य कारया श्रायात में वृद्धि यी विशेषकर मशीन श्रादि के मगाने के कारया जो कि विनियोग की दर में श्रायधिक वृद्धि का परियाम थी। राजकीय चेत्र में विनियोग का स्तर पहिले की श्रपेद्धा निरुचय ही बहुत बढ़ा हुआ था श्रीर साथ ही साथ लोगों के मन में सफलता की श्राशा भी भरी हुई थी श्रीर इसके कारया व्यक्तिगत चेत्र में भी विनियोग श्रिष्ठ मात्रा में हुआ था। इस विनियोग व्यय के कारया हुआ विदेशों में व्यय श्रिष्ठ श्रवधि के सरकार द्वारा लिये सुगों के द्वारा श्रीर श्रिष्ठ तो रिच्त कोप को कम करके पूरा किया गया।"

श्रायात 📑

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भारत में निर्यात की श्रपेक्षा श्रायात पर श्रपिक रोक लगी क्योंकि भारत सरकार ने विनिमय नियंत्रण की कठोर नीति अपनायी श्रीर कुछ वस्तुश्री के श्रायात पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। इसके साथ ही एक कारण यह भी था कि भारतीय उत्पादक युद्ध सामग्री के और स्वदेश की श्रावश्य-कता पूर्ति के लिए श्रन्य वस्तुत्रों के उत्पादन में न्यस्त थे। निर्यात के लिए भारत के पास कुछ बचता नहीं था। इसके साथ ही यातायात के साधनों की कमी श्रीर अधिक माड़े के कारण भी भारत में यातायात घट गया। १६४२-४३ में समुद्री मार्ग से मारत का आयात सबसे कम केवल ११० ५ करोड़ रुपये का रहा। जैसे ही विदेशों की युद्ध-कालीन माँग कम हुई श्रीर श्रौद्योगिक उत्पादन वढ़ने लगा तो भारत को निर्यात करने के लिए वस्तुएँ उपलब्ध हो गईं। इसी बीच यातायात की स्थिति में भी सुधार हुआ और भारत को सामान पहुँचाने के लिए जहाज मी मिलने लगे। १६४८ में मारत सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीर भारतीय उपमोक्तात्रों तथा उद्योगों की माँगों की पूर्ति करने के लिए उदार आयात नीति अपनायी । इसके फलस्वरूप १६४८-४६ में भारत ने ६४३ ८५ करोड़ रुपये के माल का आयात किया और १६५१-५२ में आयात ६५४ ५६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया तालिका १ के अनुसार । १६५२-५३ में और १६५३-५४ में स्थिति वदली श्रीर श्रायात क्रमशः ६७०'०७ करोइ श्रीर ५७२'०६ करोइ रुपये तक घट गया। इन दो वर्षों में श्रायात में कमी होने का कारण यह है कि (१) छितम्बर १९४६ में रुपये का श्रवमूल्यन कर देने से श्रायात की कीमत बढ़ गई श्रांर (२)

१६४६ में रुपये का श्रवम्त्यन कर देने से श्रायात की कीमत बढ़ गई श्रार (२) लन्दन में राष्ट्र मण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के निश्चय के श्रनुसार, जिसमें यह तय किया गया था कि डालर श्रमान की पूर्ति करने के लिये राष्ट्रमण्डलीय देश श्रायात घटाकर निर्यात बढ़ाने के लिए यथा सम्मव प्रयक्त करेंगे, भारत सरकार ने भी श्रायात पर प्रतिवन्ध लगा दिए । १६५१-५२ में श्रायात सरकार ने भी श्रायात पर प्रतिवन्ध लगा दिए । १६५१-५२ में श्रायात सरकार पूरी करने के लिये बड़ी मात्रा में खाद्यान श्रीर कपास का श्रायात किया गया। इसके पश्चात के दो वर्षों में स्थिति सुधरी। इसका मुख्य कारण यह था कि खाद्यान तथा श्रन्य वस्तुश्रों के श्रायात में कमी हुई। १६५४-५५, १६५५-५६ श्रीर १६५६-५७ में श्रायात की मात्रा बढ़ा कर ६५६ ४४ करोड़ रुपया ६७८-६६ करोड़ रुपया श्रीर दहतेय योजना के श्रन्तर्गत श्रार्थिक विकास था। मात्रा के निर्देशांक १६५४-५५ में ११०, १६५५-५६ में ११०, १६५५-५६ में ११०, १६५५-५६ में ११० हो गये श्रीर ऐसी

सम्मावना है कि १६५७-५८ में १५२ हो जात्या। ब्रारम्भ में ब्रयीत् १६५४-५५ श्रीर १६५५-५६ में मूल्यों के निर्देशांक में इतनी वृद्धि नहीं हुई यी क्योंकि ब्रायात निर्यात कुनुवात के निर्देशांक भारत के पन्न में थे।

खादान्न-विभाजन के पूर्व भारत को कुछ खादाज का वर्मा तथा श्रन्य देशों से श्रायात करना पहता था। परन्तु विभाजन के पश्चात् खादान के लिए विदेशों पर ही हमें श्रविक निर्मर करना पड़ा। यदाप भारत कृषि प्रधान देश है श्रीर यहाँ देश की खादाज की श्रावश्यकता पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होती चाहिए यी परन्तु कृषि उत्पादन में गिरावट श्राने से श्रीर सरकार का 'श्रिधिक श्रव उगाश्रो' श्रान्दोलन श्रस्पल हो जाने से हम श्रपनी श्रावश्यकता पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्मर करने लगे। खादाज का श्रायात १८४८ में २०५ लाख टन हो गया। १८४८ में ३०५ लाख टन श्रीर १८५१ में ४०५ लाख टन खादाज का श्रायात किया गया। १८५० में खादाज का श्रायात किया गया। १८५० में खादाज का श्रायात किया गया। १८५० में खादाज का श्रायात २३०३ लाख टन तक घट गया परन्तु देश की घरेलू माँग पूरी करने में कांटनाई होने से १८५१ में श्रायात बढ़ाना पड़ा। योजना श्रायोग इस परिस्ताम पर पहुंचा कि कुछ समय तक भारत में लगभग ३० लाख टन खादाज की कमी रहेगी श्रीर यदि सरकार का 'श्रिधिक श्रव उगाश्रो' श्रान्दोन्तन सफल नहीं हुया ता भारत को कम से कम इस कमी को पूरा करने के लिए श्रायात पर निर्मर करना ही पड़ेगा।

यह बड़े सीभाग्य की बात थी कि भारत में खाधान की पैदाबार १६५३-५४ में ६८८७ करोड़ टन श्रीर १६५४-५५ में ६७१.१ करोड़ टन हुई जिसके कारण श्रायात की मात्रा में ७५ लाख टन से श्रिधिक की कभी १६५४ में श्रीर ७५ लाख टन से झुछ कम की कभी १६५५ में सम्भव हो सकी परन्तु क्योंकि श्राणे चल कर देश की ही पैदाबार में कभी श्रा गई श्रीर विभिन्न भागों के श्रन्न की कभी के लज्ज्य दिखाई पड़ने लगे इसलिये श्रायात में १५ लाख टन से झुछ ही कम की वृद्धि १६५६ में श्रीर ३७५ लाख टन की वृद्धि १६५७ में हुई। यह श्राशा की जाती है कि १६५८ में २५ लाख टन के लगभग श्रायात किया जायगा।

कपास और एत्पादित साल—देश का विमाजन हो जाने से भारत में कपास की कमी हो गई। मारत की मिलों में १६४६ में ४३ लाख गाँठों की छीर १६५१ में ३८ लाख गाँठों की खपत हुई परन्तु इस ग्रविध में उत्पादन २२५ लाख से ३० लाख गाँठ तक ही बढ़ सका। इस कारण मारत को ; आयात पर निर्मर करना पड़ता है। आयात की मात्रा प्रतिवर्ष १० लाख से १२५ लाख गाँठों तक रही है। परन्तु कपास का उत्पादन बढ़ाकर आयात में कमी सम्भव

हो सकी है। भारत में घटिया प्रकार की कपास पैदा होती है परन्तु मिलों में अधिकतर श्रन्छे प्रकार की कपास का उद्योग होता है। इसीलिए यह श्रावश्यक है कि श्रन्छी कपास का उत्पादन बढ़ाया जाय जिससे इसका श्रायात घटाया जा सके। कपास का श्रायात भारत को बहुत महुँगा पड़ा है।

श्रतीत में भारत ने स्त और कपड़े का बहुत बड़ी मात्रा में श्रायात किया।
युद्दकाल में श्रीर युद्द के पश्चात् काल में स्त श्रीर कपड़े का बहुत कम मात्रा में
श्रायात किया गया है श्रीर भारत के श्रायात न्यापार की यह प्रमुख वस्तुएँ भी
नहीं रहीं। इससे भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग के बढ़ते महत्व पर पर्याप्त प्रकाश
पड़ता है। सरकार की नीति है कि सभी प्रकार के कपडों श्रीर स्त हत्यादि के श्रायात
को प्रोत्साहन न दिया जाय केवल (१) छाते का श्रीर कुछ विशेष प्रकार का कपड़ा
श्रीर (२) कहीं हत्यादि के लिए श्रावश्यक स्त का ही श्रायात किया जाय। इस
नीति के परिणाम स्वरूप भारत ने बहुत कम कपड़े श्रीर स्त का श्रायात किया।

मशीनें-मारत को मशीनों तथा श्रन्य टेकनिकल सामानों के लिए विदेशों पर निर्मर रहना पहता है। १६३८-३६ में मारत ने १६'७ करोड़ राये की मशीनों का आयात किया, १६४७-४८ में ५६ १ करोड़ रुपये की और १६४८-४६ में ८०'६ करोड़ रुपये मशीनों का श्रायात किया गया। यह श्रायात युद्धकाल के उद्योगों की श्रावश्यकता पूरी करने और उनके प्रसार तथा उनको नया रूप देने के लिए किया गया। श्रीद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रीर देश का श्रीद्यो-गीकरण करने के लिए वड़ी मात्रा में मशीनो श्रायात.करना श्रावश्यक है। १६५५-५६ में भारत ने रेल के इन्जनों को सम्मिलित करते हुये १२० २ करोड़ रुपये की मशीनों का आयात किया और १९५६-५७ में यह सख्या बहुकर ११५ द करोड़ रुपये हो गई। मशीनों का श्रायात करने में कई किटनाई हैं: (१) श्रायात की गई मशीनों के दाम बहुत ऊँचे हैं, भारतीय उद्योग इतना रूपया लगा सकने की स्थिति में नहीं हैं, (२) मशीनों के नियत स्थान में पहुँचाने तक बहुत समय लग जाता है, श्रीर (३) वित्त की कमी होने के कारण बहुत से भारतीय उद्योग कार-खानों में लगी मशीनें पुरानी श्रीर वेकार हो जाने पर भी नई मशीनें खरीद सकने में असमर्थ है। मनिष्य में जब भारत अपनी श्रावश्यकता की मशीनों का स्वयं उत्पादन करने लगेगा तब मशीनों का आयात कम किया जा सकेगा। यह खेद की बात है कि मारत में श्रमी तक मशीनों का उत्पादन करने के लिए कोई संग-ठित उद्योग नहीं है। वर्तमान में भारत में केवल स्ती कपड़ा उद्योग की श्रीर कृषि की कुछ मशीनों और श्रीनारों का उत्पादन होता है। देश के तेजी से श्रीदी-गीकरण करने के लिए यह श्रावश्यक है कि मशीनों का उत्पादन करनेवाला

उद्योग स्थापित किया जाय | द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस दिशा में कार्य स्थारम्भ कर दिया है ।

व्यापार का संगठन (Compositon of Trade) — मारत के आयात व्यापार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। १६३८-३६ में आयात क्यापार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। १६३८-३६ में आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्री में प्राप्त आँक को अनुसार मशीनें, तेल, सत तथा सती कपड़े, खाद्याव तथा आटा, और कपास प्रमुख थे। १६४८-४६ में खाद्याव का अधिकतम आयात हुआ और मशीनें दूसरी श्रेणी में आती हैं। आटा, सत तथा सती कपड़े का विशेष आयात नहीं हुआ जब की जूट और कपास के आयात में वृद्ध हुई। १६५१-५२ में कपास का कम मशीनों के बाद हो गया परन्तु १६५२-५३ में कपास को पुनः पूर्व महत्व प्राप्त हो गया। १६५३-५४ में खाद्याव अधिक उत्पन्न होने के कारण इनका आयात बहुत कम हो गया। इस समय मारत के आयात में मशीनों का प्रथम स्थान है, इसके बाद बाद और तेल (Mineral oils) आते हैं। इसका कारण यह है कि अब मारत में औद्योगीकरण को अधिक महत्व दिया जा रहा हैं। कपास, रसायनिक द्रव, और औषधियों को अब तीसरा चौथा और पाचवाँ स्थान आयात व्यापार में कमशः हो गया है।

दितीय विश्वयुद्ध के पहले कुछ, वधों में लाद्यान, पेय, तम्बाक् श्रीर श्रन्य तैयार माल का महत्व कुछ गिरने लगा था श्रीर कच्चे माल का श्रायात-व्यापार में महत्व श्रिषक बढ़ रहा था। १६४६-५० में कच्चे माल के श्रायात में कुछ कमी हुई श्रीर तैयार माल का श्रायात बढ़ा। १६४६-५० में इस प्रकार के किंचित परिवर्तन होने के श्रातिरक्त प्रकृति प्रायः कच्चे माल के महत्व को बढ़ाने श्रीर तैयार माल के श्रायात में कमी करने की रही है। युद्ध काल की प्रवृति से इसमें केवल इतना श्रंतर है कि लाद्यान पेय श्रीर तम्बाक् का श्रायात घटने की अपेक्ता श्रिषक बढ़ा है। तैयार माल के महत्व में कमी होने श्रीर कच्चे माल के श्रायात में वृद्धि होने के लच्च्या भारत के बिदेशी व्यापार के सन्तोषजनक लच्च्या है। इसका तात्यर्थ यह है कि देश के श्रीद्योगीकरण में वृद्धि हो रही है। पहले भारत श्रपने कच्चे माल का निर्यात उसके कच्चे रूप में ही कर दिया करता था परन्तु श्रव श्रिषकतर कच्चे माल को तैयार वस्तु के रूप में निर्यात किया जाता है। मारत का क्रमशः श्रीद्योगीकरण होने से यह प्रवृति श्रीर श्रिषक हु होगी।

विभिन्न देशों के साथ ज्यापार—मारत के आयात-ज्यापार में विभिन्न देशों के सापेश्विक महत्व में कुछ परिवर्तन हुआ है। १६३८-३६ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ब्रिटेन का या और उसके बाद बर्मा, बापान इत्यदि देशों का। इमारे देश के ज्यापार में अमरीका का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। परन्तु

युद्धकाल में अमरीका का महत्व अन्यं देशों की अपेद्धा अधिक वहा लिया। कि १६४८-४६ में यह स्थिति किर बदली और भारत के आयात-ज्यापार में बिटेन ने पुनः प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। परन्तु १६५१-५२ और १६५२-५३ में अमरीका ने पुनः भारत के आयात ज्यापार में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया और १६५२-५३ में हमारे आयात का २८५% माल अमरीका से और २९५% ब्रिटेन से देशों में आया। इसी अवाध में अमरीका के इस प्रमुख का काग्या केवल यह है कि भारत ने अपने खाद्याल का अमाव दूर करने के लिये वहाँ से खाद्याल का आयात किया। क्योंकि १६५४-५५ में खाद्याल का आयात घट गया इसंलिए अब आयात में प्रथम स्थान अमरीका के बजाय ब्रिटेन का हो गया है।

यदि मिवष्य में खाद्यान्नों के आयात को बढ़ाना हमारे लिये आवश्यक है तो अमेरिका का स्थान हमारे आयात ब्यागर अधिक महत्वपूर्ण ही सकता है।

निर्यात

अनेक कठिनाइयाँ होते हुए मी युद्ध के समय भारत का निर्यात व्यापार उतना नहीं गिरा जितना उसका स्रायात व्यापार गिरा । यद्यपि निर्यात (पुनः निर्यात को अंलग करके) १९४२-४३ में १८७ ६ करोड़ रुपयों तक गिर गया परन्तु स्थिति में सुवार होते ही १६४७-४८ में ३६५.३ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसका कारण यह या कि (१) युद्ध सामग्री के लिए भारत में उत्पन्न कच्चे माल स्रीर तैयार माल की स्नावश्यकता थी स्त्रीर (२) विश्व के बाजार से जापान का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने से भारतीय उत्पादकों को विदेशी बाजार पर स्त्रीर विशेषकर स्ती कपड़े के वाजार पर अपना अधिकार जमाने का अवसर मिल गया। १६४८-४६ में भारत के ४५८ ७२ करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया (तालिका १), १६४६-५० में ५०६ ०२ करोड़ रुपये का, १६५०-५१ में ६०१ ३५ करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया। १९५१-५२ में ७३२-६४ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, यह निर्यात की सर्विषक मात्रा थी। बाद में यह स्थित बदली श्रीर निर्यात च्यापार में कमी श्राई। १९५३-५४ में निर्यात केवल ५३० ६६ करोड़ रुपये की ही हुआ। यद्यपि आगे चलं कर निर्यात की मात्रा १९५६-५७ में बढ़ कर ६०२ ०६ करोड़ रुपया हो गई (तालिका नं० १) फिर भी आमात की अभेदा इसमें कम वृद्धि हुई है। इसका कारण (१) देश में निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुत्रों की कमी (२) निर्यात पर सरकार द्वारा लगाये अनेक प्रतिबन्ध श्रीर (३) सरकार की निर्यात नीति है जिसके श्रन्तर्गत श्रनेक वस्तुश्रों पर, जैसे जूट के सामान पर, निर्यात-कर की दर घटा दी गई है, निर्यात के लिए अनेक वस्तुओं

की जैसे तिलहन तथा कपास की मात्रा निर्धारित कर दी है श्रीर श्रन्य वस्तुश्रों के निर्यात के लिए सुविधाएँ दी गईं हैं।

जूट का सामान—भारत के निर्यात न्वापार में जूट के सामान का सदा से प्रथम स्थान रहा है परन्तु १६५६-५७ में वह स्थान चाय द्वारा ले लिया गया क्योंकि इस वर्ष जूट का निर्यात केवल ६० करोड़ रुपये का हुआ जब कि चाय का १०८-२ करोड़ रुपयों का इसका कारण (१) भारतीय उद्योग की कठिनाइयाँ; (२) सरकार की दोष पूर्ण कर नीति श्रीर (३) विदेशों की माँग में कमी इत्यादिथे।

विदेशी विनिमय मुद्रा कमाने में भारतीय जूट उद्योग का प्रमुख स्थान है परन्तु खेद का विषय है कि उद्योग को अपना निर्यात बढ़ा सकने में अने क किताइयों का सामना करना पढ़ रहा है: (१) सरकार ने इस पर बहुत अधिक निर्यात कर लगाया जिसे हाल में ही कम किया गया है, (२) मजदूरी अधिक होने से और मजदूरों को दी जानेवाली सुविधाओं की लागत अधिक होने से जूट के माल का उत्पादन व्यय भी बहुत अधिक है, और (३) अन्य देशों के उत्पादकों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ता है। एक समय ऐसा या जब लूट के उत्पादन में मारत का एकाधिकार था, परन्तु अब वह स्थित नहीं रही क्यों कि विश्व में कुल जूट उद्योग का से माग मारत के बाहर अन्य देशों में स्थित है। कागज, कपड़ा इत्यादि का उपयोग होने से भी जूट के सामान की माँग कम हो गई है परन्तु किर भी पैकिंग के लिए जूट के यैले सबसे सस्ते पढ़ते हैं। जूट उद्योग काफी समय पहले स्थापित होने और सुसंगठित होने के कारण विश्व बाजार में अब भी अपना उचित स्थान बनाये रखने में समर्थ है। यदि इस ओर सतकता से कार्य किया गया तो उद्योग की शिक्त बढ़ने से उत्पादित माल के प्रकार में सुधार हो सकने की और उत्पादन व्यय कम होने की पूरी संभावना है।

चाय-चाय का भी भारत के निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। १९५६-५७ में चाय का निर्यात १०८% करोड़ रुपयों का हुआ जब कि १९५५-५६ में १०६% करोड़ रुपयों का, १९५४-५५ में १४७% करोड़ रुपयों का और १९५२-५५ में ८४ करोड़ रुपयों का ही हुआ था।

मारत ने अपने को १९५३ में अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार विस्तार बोर्ड से अलग कर लिया और मारत धरकार ने उसके स्थान पर अमरीका में एक चाय काउन्सिल की स्थापना की है जो कि भारतीय चाय की विकी बढ़ाने का प्रयास करेगी। इस संस्था के प्रयन्न से ही अंशतः १९५६-५४ में चाय का निर्यात बढ़ा। यद्यपि भारत अब अन्तर्राष्ट्रीय चाय विकी विस्तार बोर्ड का सदस्य नहीं है फिर चाय समिति द्वारा चाय के निर्यात की मात्रा जो हमारे देश के लिये नियत की

गई है वह प्रतिबन्ध लागू है। ३१ मार्च १६५५ को अन्तर्राष्ट्रीय चाय समसीता जिसका भारत भी एक सदस्य रहा है समाप्त हो गया। यह आशा की जाती है कि यह समसीता पाँच वर्ष के लिये किर मे लागू कर दिया जायगा। १६५३ ५४ में भिन्न देशों के लिये निर्यात की मात्रा स्टेन्डर्ड निर्यात के १३५% पर नियत कर दी गई थी जिस के आधार पर भारत को ४७ करोड़ १ लाख १० हजार पीएड, पाकिस्तान को ४ करोड़ ७२ लाख ६० हजार पीएड, लंका को ३३ करोड़ ६६ लाख ४० हजार पीएड और इन्डोनेशिया को २३ करोड़ ४३ लाख ६० हजार पीएड चाय निर्यात करने का अधिकार प्राप्त था। अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति ने यह निश्चय किया है कि १६५४-५५ में भन्न देशों की निर्यात मात्रा स्टेन्डर्ड निर्यात की १३५% ही रहेगी। १६५५-५६ में अन्तर्राष्ट्रीय चाय समसीते के अन्तर्रात जो निर्यात की मात्रा नियत की जायगी उसके आधार पर ४१ करोड़ पीएड का निर्यात कर दिया गया था। भारत सरकार ने निर्यात की मात्रा १६५६-५७ और १६५७-५८ के लिये ४५'३३ करोड़ पीएड और ४६४७-६ करोड़ पीएड कमाशः नियत कर दी थी।

सुत और सुती सामान-स्ती समान के निर्यात में वृद्धि हुई है। १६४८-४६ में ३४ करोड़ १० लाख गज कपड़े का निर्यात किया गया, १६४६-५० में ७० करोड़ १० लाख गन श्रीर १६५०-५१ में १ श्ररव २७ करोड़ गन कपड़े का निर्यात कियां गया। निर्यात की वृद्धि के लिए प्रोत्साइन देनेवाली समिति (Export Promotion Committee) ने सिफारिश की है कि प्रतिवर्ष द० करोड़ गज कपड़े का निर्यात किया जाय परन्तु १६५०-५१ में निर्यात इससे कहीं अधिक बढ़ गया। भारत सरकार ने लाइसेन्स देने में उदार नीति ग्रापनाकर तथा श्रन्य सुवि-धाएँ भदान कर निर्यात को प्रोत्छ।इन दिया है। १९५०-५१ में किये गये निर्यात से यह आशा हुई कि भारत स्ती कपड़ी का निर्यात करने वाले देशों में प्रमुख हो जायगा परन्तु श्रभाग्यंवश स्वदेशी बाबार में कपड़े की श्रधिक कीमत हो जाने श्रीर कपड़े का प्रायः श्रमाव हो जाने से सरकार वनरा गई श्रीर कपड़े के निर्यात व्यापार को इतोत्साह किया नाने लगा जिसके फलस्वरूप १६५१-५२ में केवल ३८ करोड़ ३७ लाख १० इनार गन कपड़े का निर्यात किया जा सका। निर्यात घटने का एक कारण यह भी है कि भारतीय माल अपेनाकृत घटिया या, पैकिंग अन्धी नहीं या श्रीर भारतीय उत्पादक नमूने के श्रनुसार कपड़ा मेज सकने में श्रसकल रंहे । मजदूरी अधिक होने से, मशोनें पुरानी और विसी-पिटी होने से और उत्पादन के श्रक्तशाल तरीकों का उपयोग हाने से भारत मं कपड़े का उत्पादन व्यय श्रन्य देशों की अपेता अधिक है जिस्से भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति कम हो गई। यदि कपड़ा उद्योग श्रपना उत्पादन व्यय कम कर ले श्रीर उत्पादन के प्रकार

में सुधार कर ले तो निर्यात की मात्रा बढ़ सकने की बहुत संमावना है। विश्व कपड़ा समोलन (१६५२) में भारतीय प्रतिनिधि म्यडल ने प्रतिवर्ष एक अरब गज कपड़े का निर्यात करने की इच्छा प्रकट की थी।

यद्यि हाल में निर्यात की मात्रा बहुकर ८५ करोड़ गज १६५७ में हो गई फिर भी चाहे हुये ध्येय १०० करोड़ गल से कम ही है इसके श्रातिरक्त १६५८ में निर्यात के घटने की श्राशंका है जो कि किसी तरह ६५ करोड़ गज से बहु नहीं सकता । श्रिक्त भारतीय निर्यात संघ के मतानुसार, "स्डान के द्वारा स्ती कपड़े बनाने के लिये श्रो० जी० एल० के० प्रयोग को बन्द कर देने के कारण भारत के उस देश से कपड़े के ज्यापार पर विशेष प्रभाव पड़े। इन्होनेशिया से राजनीतिक मन्दे चल रहे हैं। जिसके कारण भारत से निर्यात की यात्रा कर पिछुत स्तर पर कायम रखने की कम सम्मावना है। कनाडा ने श्रपनी कपड़ा श्रायात नीति की संकुचित बना दिया है। बिटेन निरन्तर भारत पाकिस्तान श्रीर हांगकांग से कपड़े के निर्यात को कम करने का प्रयक्त कर रहा है"। इन सब कारणों के फलस्वरूप भारत से स्ती कपड़े के निर्यात की मात्रा कम ही रहेगी।

व्यापार का संगठन-भारत के निर्यात व्यापार संगठन में आयात की अपेना कम परिवर्तन हुए हैं। भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के महत्व की दृष्टि से क्रम इस प्रकार रहा - १६३८-३६ में जूट का सामान, कपास, चाय, बीज श्रीर परसन; १६४८-४६ में जूट का सामान, चाय, स्त श्रीर स्ती सामान, कपास, तेल श्रीर चमड़ा श्रीर १९५२-५३ में जूट का सामान, चाय, सूत श्रीर सूतीं सामान, कच्ची घातु, कपास श्रीर तेल, १९५३-५४ तथा १९५५-५६ में जूट श्रीर जूद का सामान, चाय, सूत और सूती कपड़े, कच्ची घात, कामाया चमड़ा श्रीर खाल, कपास । १९६५६-५७ में जूट के सामान का स्थान चाय ने ले लिया। िषयाय इसके बस्तुश्रों के निर्यात व्यापार की महत्त के कम में श्रन्य कोई परिवर्तन ंनहीं हुआ। इससे यह प्रकट होता है कि भारत के निर्यात व्यापार में जूट के सामान श्रीर चाय का सदा प्रमुल रहा है; निर्यात की दूसरी विशेषता यह है कि कपास श्रीर पटसन श्रपना महत्व खो चुके हैं श्रीर ऐसी श्राशा भी की जाती थी क्योंकि देश विभाजन के पश्चात भारत में इन दोनों वस्तुत्रों की कमी पड़ गई श्रीर श्रव मारत को इनके श्रायात पर निर्मर करना पढ़ता है। यदाप कुछ वस्तुश्रों का, जैसे सूरी सामान श्रीर सूत, चमड़ा श्रीर तेल, निर्मात की दृष्टि से महत्व कम हो गया है श्रीर यह निर्यात की प्रमुख वस्तु नहीं रहे परन्तु किर भी इन की स्थिति में श्रन्य की श्रपेचा श्रधिक सुधार हुश्रा है श्रीर श्रव मारत के निर्यात में इनका महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। परन्तु यह बात घ्यान देने योग्य है कि निर्यात व्यापार कुछ विशेष वस्तुयों पर धी निर्मर करता है श्रीर विदेशों की भांति इसका कार्यक्रम विस्तृत नहीं है। जहाँ श्रनेक वस्तुश्रों का निर्यात किया जाता है।

विभिन्न देशों से व्यापार—भारत के निर्यात व्यापार में ब्रिटेन श्रीर श्रन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों का निरन्तर प्रमुख रहा है। १६३८-३६ में हमारे निर्यात ह्यापार का ५२'१% राष्ट्र मण्डलीय देशों से श्रीर ४७'७ प्रतिशत श्रन्य देशों से हुआ। इसके परचात श्रन्य देशों की खपत में कुछ दृदि हुई श्रीर राष्ट्र मण्डलीय देशों की खपत घटी। १६४७-४८ तक कुल भारतीय निर्यात व्यापार का ५१'३% व्यापार राष्ट्रमण्डलीय देशों से किया गया श्रीर ४८% श्रन्य देशों के साथ। तब से बरावर यही हिथित रही है श्रीर इसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। १६५६-५७ में मारत ने श्रपने कुल निर्यात का ५२% राष्ट्र मण्डलीय देशों को भेना श्रीर ४८% श्रन्य देशों को भेना। राष्ट्र मण्डलीय देशों में भी ब्रिटेन का प्रमुख स्थान है। ब्रिटेन के श्रातिश्क श्रन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों में भी ब्रिटेन का प्रमुख स्थान है। ब्रिटेन के श्रातिश्क श्रन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों को निर्यात करने में भारत को (१) इन देशों में श्रायात पर लगे हुए श्रनेक प्रतिवन्धों श्रीर (२) श्रन्य उत्पादकों की भी निर्यात का सामना करना पड़ता है। इससे निर्यात व्यापार में काफी नाधा पड़ती है।

सरकार की आयात नीति

सरकार की श्रायात नीति श्रनेक वातों से प्रभावित है, (१) भारत के नियंत न्यापार से विदेशी विनिमय के सीमित साधन जुट पाते हैं। सरकार की नीति यह रही है कि श्रायात विदेशी मुद्रा विनिमय के उपलब्ध सोतों तक ही सीमित रहे। यह नीति किल्कुल उचित है क्योंकि ऐसा न होने पर सरकार या तो विदेशी मुद्रा का श्र्य लेने के लिए विवश हो जाती श्रयवा सपये का विनिमय श्रयं घटाने के लिए। यह दोनों ही बातें देश के लिए घातक सिद्ध होतीं। (१) सरकार ने मुद्रास्प्रीति-निरोधक नीति श्रयनायी जिसके श्रनुसार भारत में मूल्य घटाने के लिए श्रायात को मोत्साहन दिया गया है। (१) देश के श्रीशोगिक श्रीर कांप सामनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों का विकास करने की श्रावश्यकता है। देश के साधनों अध्यात को विदेशी प्रतियोगियों से रहा करने की हिए से उपभोग की वस्तुश्रों के श्रायात को नियंत्रत किया गया है श्रीर उन वस्तुश्रों के श्रायात पर प्रतिवन्ध लगा दिया है जिनका भारत में उत्पादन किया जा सकता है श्रीर जिनकी लागत विदेशी माल

की लागत से श्रिधिक नहीं है। इस प्रकार केवल तटकर संरच्या की नीति को ही नहीं किन्तु श्रायात नीति के द्वारा भारतीय उद्योग की रच्चा करने की नीति को भी मान्यता दी गई है। (४) यह नीति भी श्रानायी गई है कि उपभोक्ता को श्रापनी श्रावश्यकता की पूर्ति के लिये श्रिधिक से श्रिधिक प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें।

सरकार की खायात नीति में अनेक परिवर्नन हुए हैं। पहले उदार नीति श्रपनाई गई, फिर प्रतिबन्ध लगाये गये और पुनः उदार नीति श्रपनाई जा रही है। १६४८ में 'ग्रामान्य लाइसेन्स ११' (Open General Licence XI) लागू किया गया जिसमें सलभ मुद्रा के देशों से उपभोग की अनेक आवश्यक वस्तुश्रों के श्रायात करने की श्रनुमति दी गई। भारत में बढती कीमतों को रोकने के उद्देश्य से सितम्बर १९४८ में श्रायात नीति में श्रीर श्रधिक उदारता लाई गई। परन्तु इस नीति के अनुसार आयात की मात्रा वित्तीय साधनों की अपेक्ता कहीं अधिक बढ़ गई इसलिए आयात पर प्रतिबन्घ लगाना पड़ा। मई १६४६ में सामान्य लाइसेन्स प्रशाली (O G L XI) रह कर दी गई और संशोधित सामान्य लाइसेन्स प्रणाली (O. G. L. XV) लागू की गई निसके अनुसार मुलभ मुद्रा के देशों से कुछ ही वस्तुत्रों का विना लाइसेन्स आयात करने की श्रतमति दी गई। पौरङपायने के समक्तीते (Sterling Balances Agrement) के ब्राघार पर सारी रिथति की पुनः सभीज्ञा की गई ख्रीर इस बात के प्रयत्न किये गये कि आयात उतना ही किया जाय जितनी निर्यात से आय हो और जितनी धनराशि विटेन से पौरह पावने के हिसाब में भारत को वापस मिले । अगस्त १६४६ में सामान्य लाइसेन्स प्रणाली (O. G. L. XV) रह कर दी गई श्रीर इसके स्थान पर नई सामान्य लाइसेन्स प्रयाली (O, G, L, XVI) लाग की गई। इससे भारत में आयात पर पहले से भी अधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये निससे आयात और कम हो गये।

१६५०-५१ में आयत नीति में फिर परिवर्तन हुआ। सामान्य लाइसेन्स प्रसाली (O. G. L. X) जिसके अनुसार पाकिस्तान से आयात की अनुमति दी गई थी सितम्बर १६४६ में रह कर दी गई थी परन्तु पाकिस्तान से युनः न्यापार आरम्भ किया गया। उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत सी वस्तुओं के लिए दीर्घकालीन आयात नीति बनाई गई। साद्याक और कच्चे माल इत्यादि के लिये सामान्य लाइसेन्स २० और २१ लागू किये गये। क्योंकि प्रतिबन्धित आयात नीति से देश को हानि पहुँच रही थी इसलिए उसमें संशोधन किया गया और आयात के प्रति उदार नीति अपनाई गई और

जून १६५१ में सामान्य लाइसेन्स २३ जारी किया गया जिसमें ऐसी वस्तुएँ सिम्मिलित कर ली गईं जिनका या तो भारत में बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं होता या या जो देश की आवश्यकता पूर्ति के लिये आवश्यक थीं। सामान्य लाइसेन्स २३ में लोहा तथा इस्पात, तारों के रस्सों, पीतल के सामान, ताँव का तार, बोतल, लिखने का कागज, बिजली के तार इत्यादि सम्मिलित करके लाइसेन्स देने का स्त्रेत बढ़ा दिया गया।

१९५३ की श्रायात नीति में सरकार ने कुछ वस्तुश्रों के 'लाज्ञणिक श्चायात' की प्रणाली लागू की जिसका उद्देश्य उद्योगपतियों का ध्यान उत्पादित माल की किस्म सुघारने स्त्रोर लागत कम करने की स्त्रीर स्त्राकर्षित करना था। लाइणिक त्रायात की नीति कुल चुनी हुई वस्तुत्रों के सम्बन्ध में १६५४ तक चलती रही। बहुत वस्तुश्रों के श्रायात में बहुत उदार नीति वर्ती गई श्रीर इससे यह श्राशा की जाती थी कि इस उदारता के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा का व्यय प्रति वर्ष लगभग = करोड़ रुपये के श्रीर बह जायगा । श्रायात नियंत्रण की प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन किया गया। मात्रा के नियंत्रण से अधिक आयातकर का प्रयोग भारत के श्रायात व्यापार के नियंत्रण में किया गया। इस दृष्टिकोण से बहुत सी वस्तुाों की श्रायात मात्रा में उदारता दिखाते हुये भी ऐसी वस्तुश्रों पर जैसे पेन्सिल, पुराने श्रखवार, देशी शराब, ऊनी कपहे, वेकुश्राम फ्लास्क, ब्लेड श्रीर खेलनं के ताश श्रादि पर श्रायात कर बढ़ा दिया गया। १६५४-५५ के प्रथम पाँच महीन। की आयात कर वस्ली की आय ६० करोड़ रुपया हुई जिससे पूरे वर्ष भर में १४४ कराइ रुपये पाप्त होते जब कि वजट का ग्रानुमान १७७ ५ करोड़ रुपयों की श्र'य का किया गया था। श्रातिरिक्त श्रायात कारों से सरकार की श्राय में वृद्धि की, तथा उद्योगों को परोज्ञ रूप से सहायता मिलने की श्राशा की जाती यी पर उनसे उपभोक्ताश्रों को कोई लाम नहीं या क्योंकि उन्हें घाटा पूरा करने के लिये श्रायात की हुई वस्तुत्रों का ग्रीर देश में निर्मित वस्तुत्रों का श्रिधिक मूल्य देना पड़ता था। प्रति वर्ष ८ करोड़ रुपये तक के श्रायात किये हुए माल के कारण भारतीय वाजार में विदेशी वस्तुश्रों की वृद्धि तो श्रवश्य हुई पर इतनी नहीं कि देश मं उन वस्तुश्रों की कमी पूरी हो सकती।

श्रायात नियंत्रण जाँच समिति की सिफारिशों के श्रनुसार श्रायात नियंत्रण में काफी सुधार किया गया है। जाँच समिति का मत है कि श्रायात नियंत्रण का श्राधार उद्देश्य यह होना चाहिए कि (१) उतना ही श्रायात किया नाय जितनी विदेशी मुद्रा है, (२) विदेशी मुद्रा विनिमय के साधनों का कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए श्रीर उपमोक्ताश्रों की श्रवश्यकता पूरी करने के लिए

त्रावरयक वस्तुश्रों में सामान रूप से वितरणा हो, श्रीर (३) विशेष वस्तुश्रों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जा छके; सिमित ने सुमाव दिया कि व्यवसायिक वस्तुश्रों का ४०० करोड़ रुपये तक श्रायात किया जाना चाहिये जो शांति काल का निम्नतम स्तर है। विदेशी मुद्रा विनिमय के साधनों की दृष्टि से समिति ने श्रायात को ह भागों में विभाजित किया है। सरकार ने समिति के साधारण अभिस्तावों को मान लिया है परन्तु ४०० करोड़ रुपये की सीमा की स्वीकर नहीं किया है, साथ हो सरकार ने अपनी आयात नीति के आघारस्वरूप श्रायात के ६ नहीं किन्तु सुविधा की दृष्टि से कम भाग किए हैं। समिति की िकारिशों के आधार पर आयात लाइसेन्ट प्रणाली को सरल बनाया है और व्यर्थ समय नष्ट होने से बचने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि (अ) पहले जितने लाइसेन्छ दिये गये थे अब उसके कई गुने अधिक लाइसेन्स दिये जायँगे; (व) लाइसेन्स के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। श्रव बन्दरगाह वाले शहरों से आयात लाइसेन्छ प्राप्त किया जा सकता है। चुङ्गी के अधिकारियों को नियमों का अर्थ लगाने के सम्बन्ध में न्यापक अधिकार दिये गए हैं; (स) अब चुकी श्रिषकारियों तथा आयात-नियंत्रण श्रिषकारियों के कार्यों में उचित सम्बन्ध स्यापित हो गया है। अतीत में चुङ्गी अधिकारी आयात लाइसेन्स देने वाले श्रिधिकारिश्रों द्वारा किये गये सामान के वर्गीकरण को सदैव स्वीकार नहीं करते ये। इससे इस कार्य में काफी देर लग जाती थी श्रीर व्यापारियों को दानि होती थी। परन्तु वित्त श्रीर वाशिज्य मंत्रालय के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने से श्रीर चुङ्गी श्रधिकारी की सहायता के लिए बन्दरगाह सलाहकार समिति नियुक्त करने से स्थिति काफी सुधर गई है।

१६५५-५६ की श्रायात नीति की विशेषता यह थी कि आयात की मात्रा के सम्बन्ध में प्राप्त विदेशी मुद्रा के श्रन्तर्गत उदारता दिखाई गई थी श्रीर इस बात का ध्यान रख्खा गया था कि (१) श्रीयोगीकरण के विस्तार कार्य को चालू रखने के लिये मशीनें श्रीर कचा माल श्रिषक मात्रा से मँगाया जाय; (२) उन वस्तुओं की श्रायात मात्रा जिनका श्रिषकाधिक उत्पादन श्रपने देश में बढ़ता जा रहा है कय से निरन्तर धटाई जाय; श्रीर (३) छोटे उद्योगों की श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए छोटे-छोटे श्रीजारों की मँगाने की श्रनुमित दी जाय। १६५४ के श्रंत से 'एकाधिकार श्रायात' (Monopoly Imports) की नीति वर्ती जा रही है। इसके श्रनुसार कुछ चुनी हुई वस्तुयें विशेष मात्रा में ज्यापार के श्रन्तर्गत मँगाई जाती हैं। वस्तुश्रों का चुनाव श्रीर मात्रा सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं। इसके निश्चित करने में उपमोक्ताओं का हित श्रीर घरेलू उत्पादकों का हित ध्यान

में बरावर रक्खा गया था। श्रीर नये श्रीर पुराने श्रायात करने वाली तथा उप-भोकाश्री के हितों में श्रिषिक श्रन्छ। चंत्रलन स्थापित हो गया था।

क्योंकि भारत में विदेशी विनिमय की कठिनाइयों ने गमीर रूप घारण कर लिया और पीरह पावने की मात्रा १६५६ के अप्रैल के आरम्म में ७४८ करोड़ स्पये थी घट कर मार्च १९५७ में ५२७ करोड़ स्पये श्रीर १९५७ के दिसम्बर तक २९८ करोड़ रुपये ही रह गई स्त्रायात पर प्रतिबन्ध लगाना श्रत्यावश्यक हो गया। जनवरी से जून १६५० तक की श्रायात नीति के श्रन्तर्गत प्रत्येक वस्त पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। ये प्रतिबन्ध कन्चे माल, मशीनरी तथा उत्पादन के प्रयोग में आने वाली लगमग सभी वस्तुओं पर लगा दिये गये थे। परन्तु पहिले के किये गये सीदे इतनी अधिक मात्रा में थे कि आयात प्रतिबन्ध की यह नीति विशेष सफल न हो सकी। इसका प्रभाव श्रीयोगिक उत्पादन पर पढ़ा श्रीर उनको मात्रा घट गई जिससे निर्यात की मात्रा के भी घट जाने की छ। शंका होने लगी। इसका परिणाम यह हुन्ना कि १९५८ में न्नायात नीति की कुछ उदार बना दिया गया श्रीर ऐसी वस्तुश्रों के श्रायात की मात्रा की सीमा जैसे कपड़े, रसायनिक वस्तुयें मशीन के पुर्जे, कुछ रसायनिक द्रव, श्रीद्योगिक गोट, रेजिन, श्रीर मिटाने वाले रवड़ श्रादि वढ़ा दी गई। किन्ही कच्चे मालों के प्रति श्रधिक उदारता दिखाई गई। उपभोक्ताओं की वस्तुश्रों तथा उत्पादन के काम श्राने वाली वस्तुश्रों के प्रति नियत्रित मात्रा की नीति चालू रक्खी गई। कुछ वस्तुत्रों की मात्रा श्रवश्य बढ़ा दी गई जैसे फोटोमाफी के सम्बन्ध की वस्तुर्ये तथा कागज श्रादि । साथ ही साथ कछ वस्तुत्रों की मात्रा घटा भी दी गई घी जैसे तारकोल से वने रंग। किन्हीं मोटर गाड़ियों के पुर्जे इस्पात के श्रीजार इत्यादि क्योंकि देशी कारलाने इन वस्तुश्रों की मांग पूरी कर सकते ये। इसके अतिरिक्त दो और आवश्यक परिवर्तन हुये। पहिला कि विदेशी विनिमय के वजट बनाने की रीति फिर से चालू कर दी गई श्रीर 'वास्तव में प्रयोग करने वालों' के लिये तथा 'नये लोगों' के लिये वस्तुश्रों के अप्रायातं की मात्रा की सीमा अधिक उदारता से नियत की गई। विदेशी विनिमय सम्बन्दी बजट के कारण व्यापार का नियोजन श्राधिक श्रव्छी तरह करना सम्मव सकेगा श्रीर वास्तव में प्रयोग करने वालों को उदारता से लाइसेन्छ देने के कारण उत्पादकों की कठिनाइयाँ घट जायगी।

पहले सरकार की आयात नीति की आलोचना इस बात पर की जाती थी कि उसमें बार बार परिवर्तन किया जाता है और कोई दीर्घकालीन नीति भी नहीं है। यह भी दोष सरकार की नीति पर आरोप किया गया है कि देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी हितों का भी ध्यान इसमें नहीं रक्खा गया है। इन

दोशों को बहुत कुछ दूर कर दिया गया है श्रीर सरकार की श्रायात नीति बहुत कुछ स्थिर श्रीर विचारपूर्ण बना दी गई है। श्रावेदनों का ढंग सरल कर दिया गया है श्रीर उन पर कार्यवाही जल्दी की जाने लगी है। श्रायात नियंत्रण की तालिकाश्रों को श्रीर श्रधिक युक्ति संगत बना दिया गया है। पुराने 'कोटा सार्टिफिकेट! के स्थान पर अब नये 'कोटा सार्टिफिकेट! दिये जाने लगे हैं जिन पर साफ-साफ 'सुपर राइटर गोथिक पिन 'चाइन्ट' छापों से छपा रहता है जिस पर कोई श्रदला-बदली नहीं की जा सकती। श्रायात लाइसेन्सों का इस प्रकार कोई दुरुपयोग नहीं किया जा सकता । देश के श्रायात व्यापार में नये श्रायात करने वालों का भाग वढा दिया गया है और उन्हें भी श्रिधिक प्रकार की वस्तुश्रों के श्रायात के लिये जिनका वे पहिले श्रायात नहीं कर एकते ये लाह सेन्स दिया जाने लगा है। इससे यह दोष कि नये श्रायात व्यापारियों के साथ न्यायपूर्ण वर्ताव नहीं किया जाता निराधार हो गया है। वस्तुन्त्रों का वास्तियक प्रयोग करने वालों को भी लाहसेन्स दिया जाता है जिससे उन उत्पादकों का कार्य जो कचा माल मंगाते हैं सरल हो गया है श्रीर नये श्रायात करने वालों की अछ मात्रा निश्चित कर दी जाती है ताकि श्रायात व्यापार में प्रतियोगिता की भावना किसी सीमा त्तक बनी रहे। पुराने श्रायात करने वाले व्यापारियों को लाइसेन्स प्राप्त करने का श्राधिकार है क्यांकि उनके पाछ श्रावश्यक व्यवस्था तथा श्रनुमव है। पर श्रव तीनों के हितों का इस ढंग से संतुलन कर दिया गया है कि उनमें पारस्परिक विरोध नहीं उठता। श्रायात लाइसेन्ड देने के पहिले श्रौर श्रायात की मात्रा निश्चित करने के पहिले विदेशी विनिमय का बजट न बनाना बड़ी भारी भूल थी। यह श्रन्य कारणों में से यह भी श्रत्यिषक श्रायात का तथा विदेशी विनिमय के संकट का एक कारण था। श्राशा की जाती है कि विदेशी विनिमय के वजट बनाने की रीति के फिरसे चालू हो जाने के कारण मविष्य में इस प्रकार का संकट न पडेगा।

निर्यात को बड़ावा

विदेशों को भारतीय सामान का निर्यात उतना नहीं बढ़ा है जितनी बढ़ सकता था क्योंकि भारतीय न्यापारी इस बात को नहीं समकते हैं कि इस समय सिदेशी बाजार को प्रभावित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार को निर्यात नीति भी अनिश्चित और प्रतिगामी रही है। हमारे निर्यात न्यापार में एक प्रमुख शुटि यह है कि मुख्यतः तीन-चार वस्तुएँ निर्यात को जाती हैं जैसे जूट और जूट का बना सामान, सूत और सूत का बना सामान तथा चाय जिसके परिशाम स्वरूप याँद किसी एक वस्तु के निर्यात में कभी श्राई तो देश को भारी इति उठानी पढ़ती है। इसलिए निर्यात नीति में सर्वप्रथम श्रीर सबसे बड़ा सुवार यह होना चाहिए कि निर्यात की नाने वाली वस्तुश्रों की संख्या बढ़ाई जाय। इसमें चीनी, सामान्य विजली का सामान, विजली की मोटर श्रीर ट्रान्स्फार्मर, बाईसिकिल, बीलल इंजिन, कृषि सम्बन्धी श्रीजार इत्यादि को सम्मिलित करना चाहिए। विदेशी माजार में इनमें से बहुत सी वस्तुश्रों को बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पहेंगा परन्तु कुछ सावधानी वरतने से इन वस्तुश्रों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है श्रीर इस प्रकार व्यापार की त्थित को स्थायी बनाया जा सकता है।

श्रवीत में नियांत प्राय: घटता रहा है क्योंकि भारतीय उत्पादकों ने क्खुश्रों की किस्म का ध्यान नहीं रखा और जो सामान निर्यात किया वह नम्ने के अनुकूल नहीं या। सामान का पैक्तिंग भी घटिया प्रकार का या श्रीर साथ ही कीमत भी श्रिपिक थी। निर्यात बढ़ाने के लिए मारतीय उत्पादकों को विदेशों में उपभोक्ताओं की माँग का श्रध्ययन करना पहेगा श्रीर विदेशी बाजार से निरन्तर सम्पर्क रखना पड़ेगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त समिति (जो गोरवाला समिति के नाम से विख्यात है) ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए श्रनेक सुमाव दिए। सरकार तथा न्यापारियों दोनों को इन सुकावों के अनुसार कार्य करना चाहिए। विदेशों में मारतीय व्यापार कमिश्नर नियुक्त है और सरकार तथा भारतीय उत्पा-दक कमी-कमी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल विदेश मेला करते हैं परन्त इतना होते हुए भी विदेशी बाजार से निरन्तर सम्पर्क नहीं रहता। जब तक विदेशी बाजार से प्रत्यज्ञ ग्रीर नियमित सम्पर्क स्यापित नहीं होता तब तक निर्यात को प्रोत्साहित कर सकना संमन नहीं है। यह सुकान दिया गया है कि निर्यात प्रवर्त्तक संचालक मण्डल स्थापित किया जाय जो इन सब वातों की देख रेख करे और निर्यात के सम्बन्ध में खोलकार्य संगठित करे। गोरवाला समिति ब्रिटिश निर्यात ज्यापार खोजकार्य संगटन जैसी संस्था की स्थापना के पक्ष में नहीं है। परन्तु यह ब्रिटिश संगठन बहुत श्रच्छा कार्य कर रहा है श्रीर यदि इस प्रकार का एक संगठन भारत में मी स्थापित कर दिया जाय तो इससे निर्यात न्यापार को बढ़ाने में बहुत सहा-यता मिलेगी। निर्यात ब्यापार को मोत्साहित करने के लिए ग्रीर उसका विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय श्राने पर उचित श्रीर शीम कार्यवाही हो, कार्य की विधि सरल हो और खोज कार्य की सहायता से निर्यात में वृद्धि की नाय।

कुछ वस्तुओं पर निर्यात कर लगा देने से, उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल पर और मशीनों पर आयात कर लगा देने और श्रीद्योगिक कच्चे माल तथा विजली इत्यादि पर विक्री कर लगा देने से भारतीय निर्यात व्यागर में काफी गांधा हो गई है। अन्य देशों में सरकार निर्यात को भोत्साहन देने के लिए आयात कर वापस कर देती है और अन्य आर्थिक सहायता देती हैं। गोरवाला समिति ने शिफारिश की है कि यांद आयात किए गए कच्चे माल की सहायता से तैयार माल का पुनः निर्यात किया जाय तो आयात कर वापस कर देना चाहए। निर्यात कर को सरकारी आय का स्थायी स्रोत नहीं बनाना चाहिए। निर्यात कर का उद्देश्य सरकार की आय बढ़ाना नहीं बल्कि देश के व्यापक हितों की रह्मा करना होना चाहिए।

निर्यात संवर्धन कमेटी की रिपोर्ट अगस्त १९५७ में निकली। उसने यह सिपारिश की कि सतत प्रयन द्वारा भारत के निर्यात की ७०० या ७५० करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष निकट भविष्य में बढाया जा सकता है यद्यपि द्वितीय योजना में ६१५ करोड़ रुपये तक ही बढाने का ध्येय बनाया गया था। इसके लिये कमेटी ने सुकाव दिया कि निर्यात कर कम मात्रा में लगाना चाहिये श्रीर जल्दी जल्दी उसकी वसूली नहीं की जानी चाहिये। निर्यात की जाने वाली वस्तु थ्रों पर वस्ते हुये विक्री कर तथा उत्पादन कर किसी एक निश्चित दर के हिसाब से लौटा देना चाहिये। निर्यात किसी एक एजेन्सी द्वारा नियत कर देना चाहिये, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा सरकारी। निर्यात के लिये साल की सविधा का प्रदन्ध किया जाना चाहिये। भारतीय जहाजी को भारतीय माल के ले जाने तथा विदेशों से ले श्राने में उत्तरोत्तर श्राधिक माग लेना चाहिये वाकि परीज्ञा निर्यात की मात्रा भी वह सके। कमेटी ने निर्यात किये जाने वाले माल के गुणों पर विशेष जोर दिया । कमेटी ने निम्न बातों का निर्यात नीति में समावेश करने के लिये. िपा-रिश की। (१) सभी चेत्रों में उत्पादन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि करना विशेष कर कृषि उद्योग में । (२) मूल्यों को पूर्ण स्पर्ध के स्तर पर रखना, (३) देश के उप-भोग की चिन्ता न करते हुये निर्यात को प्रोत्साइन देना, (४) निर्यात बाजागें श्रौर निर्यात माल में परिवर्तन करना, (५) निर्यात की जाने वाली वस्तुश्रों के नये प्रयोगों के सम्बन्ध में खोज करना तथा उनके श्रनुसार वस्तुश्रों का प्रयोग करना ।

निर्यात संवर्षन कमेटी की सिपारिशों का ध्येय भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देना है। जिन सहायताश्रों के दिये जाने की सिपारिश कमेटी ने की है यदि उचित रीति से सरकार द्वारा दी जायगी तो निर्यात एजेन्सियाँ तथा भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय निर्यात में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। परन्तु कमेटी की सिपारिशे दो हिसकोशों से श्रवास्तविक प्रतीत होती हैं। (१) भारतीय

निर्यात की मात्रा ७०० करोइ से लगा कर ७५० करोइ रुपयों तक निकट मिवष्य में बढ़ जायगी, ऐसी सम्मावना तो भारतीय माल की तुलना में विदेशी माल के मूल्यों तथा उसके विरुद्ध विदेशो बाजारों की प्रतिस्पर्धा को देखते हुये मालूम नहों पहती, श्रीर (२) देश के मीतर उपमोग की मात्रा जिसकी चिन्ता न करते हुये निर्यात बढ़ाया जा सकता है वह मी तो बहुत सीमित ही है। मारत में उपमोक्ताश्रों के त्याग की बात करना तो बड़ा सरल है परन्तु जब श्रिषकांश उपमोक्ता जीवन स्तर के सामान्य मापदयद से निम्न स्तर पर पहिले ही से रह रहे है तो श्रब श्रीर श्रीषक त्याग का श्रवसर नहीं हो सकता। हाँ यदि उन वस्तुश्रों का उत्पादन बढ़ा दिया जाय जिनकी मांग विदेशों में है श्रीर उनकी उत्पादन लागत कम रक्खी जाय तब निश्चय ही हमारा निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ सकता है।

निर्यात संवर्धन कार्डासन्ल (Export Promotion Councils) निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये अनेकों निर्यात संवर्धन कार्डान्सलें अनेक वस्तुओं के लिये स्पापित कर दी गई है जैसे स्ती कपड़े, रेशम, रेयन, प्लास्टिक, इन्जिनियरिंग का सामान, कालीमिर्च, तम्बाक्, चमड़ा और चमड़े के बने सामान, लाख अवस्क इत्यादि। कुछ निर्यात संवर्धन कार्जान्सलों ने अपने डेलीगेशन विदेशों में भेजे है और विदेश की बाजारों के सम्बन्ध में बातों की जानकारी प्राप्त की है और उसे व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधियों को इसकी स्चना दी है। कुछ ने अपने शाखा कार्यालय विदेशों में खोले हैं। वे ऐसे उपायों को पता लगाते हैं जिनके द्वारा निर्यात में वृद्धि की जा सकती है।

निर्यात जोखिम बीमा कारपोरेशन (Export Risks Insurance Corporations) मारतीय निर्यात की बृद्धि में बाधा डालने वाली एक किटनाई निर्यात सम्बन्धी बीमा सुविधा का श्रामाव था। इस श्रभाव की पूर्ति के लिये ४ अवद्वतर १६५७ को निर्यात जोखिम बीमा कारपोरेशन की स्थापना ५ करोड़ अपये की पूजी से जो कि सरकार द्वारा ही दिया गया हुई। इसके डाइरेक्टरों के बोर्ड में सात सदस्य हैं एक इसका चेयरमैन है श्रीर एक मैनेजिंग डाइरेक्टर। यह कारपोरेशन सामान्य बीमा करने वालों की तरह जोखिम का बीमा नहीं करता वरन विदेशी श्रायात करने वालों का खास कर गारन्टी करता है श्रीर उस सम्बन्ध में जो जोखिम हो उसकी जिम्मेदारी लेता है। इसका सारे कार्य का श्राधार लाम हानि की मावना से युक्त है श्रीर इसका मुख्य श्राश्य मारतीय माल के निर्यात को प्रोतसहन देता है।

मार्च १६५८ के अन्त तक कारपोरेशन ने ११ २३ करोड़ रुपये के मूल्य का काम १६५ प्रस्तावों द्वारा प्राप्त किये जो कि ४६ २० करोड़ रुपये के निर्यात के सम्बन्ध में थे। इनमें से ७ प्रस्तानों को स्वीकार किया गया श्रीर ३ प्र करोड़ क्यमें के श्रंकित मूल्य की पालिसियाँ दी गई जो १७ ३ प्र करोड़ क्यमें के निर्यात के सम्बन्ध में थी। समसे बड़ी विशेषता यह रही है कि श्रमी तक कारपोरेशन की सेवाश्रों का उपयोग मध्यम श्रीर निम्न स्तर के निर्यात करने वालों द्वारा ही किया गया है, इनका बड़े निर्यात करने वालों के समान विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध श्रयवा साल प्रवन्ध नहीं है। ७ पालिसियों में से ३० पालिसिया १ से लगाकर २ लाख क्यये तक की, २१ पालिसियों २ लाख से ५ लाख क्यये तक की, श्रीर १२ पालिसियों ५ लाख क्यये तक की, श्रीर १२ पालिसियों ५ लाख क्यये तक की, श्रीर १२ पालिसियों भे लाख क्यये तक की, श्रीर १२ पालिसियों भे लाख क्यये तक की, निर्यात करने वाले लोग भी कारपोरेशन की जाती है कि किसी निर्यात में बड़े निर्यात करने वाले लोग भी कारपोरेशन की नेवाश्रों का उपयोग करेंगे। कारपोरेशन के कार्य के सम्बन्ध में ये श्रालोचनायें की जाती है कि (१) इसने प्रीपियम की बहुत श्रभी दर लागाई है श्रीर (२) साधारण कारणों पर श्रावेदन श्रस्तीकार कर दिये गये हैं।

सरकारी ज्यापार कारपोरेशन (State Trading Corporation) सरकारी ज्यापार कारपोरेशन की स्थापना मई १६५६ में पूर्णत्या सरकारी संस्था के रूप में १ करोड़ कपये की श्रिषकृत पूंजी से की गई। इसकी स्थापना इसलिये की गई कि वह "समय समय पर जिन वस्तुश्रों के सम्बन्ध में कम्पनी निश्चय करे उनके भारत में श्रायात मारत से निर्यात की ज्यवस्था करे स्वयं उनका श्रायात निर्यात करे, उन वस्तुश्रां का क्रय निक्रय तथा परिवहन श्रीर सामान्य। ज्यापार मारत में श्रयवा संसार के श्रन्य देशों में करे तथा वे सब कार्य करे जो उनसे सम्बन्धित रखती हो या जो उपर्युक्त ध्येय की पृति में सहायक हों।" सरकारी ज्यापार कारपोरेशन से निम्न लाभों की श्राशा की जाती है—(१) साम्यवादी देशों से ज्यापार एक नये ढंग का कार्य है जिसे ज्यक्तिगत ज्यापारिक संस्थाय करने की श्रादी नहीं है; (२) देश की वर्तमान विदेशी ज्यापार ज्यवस्था नई परिस्थितियों को जो उत्यन हो गई है सम्भाल नहीं सकती इसलिये इस श्रमाव की पूर्ति सरकारी ज्यापार कारपोरेशन से होगी; (३) कारपोरेशन को एक बहुत बड़ी संस्था के ज्यापार करने की सुविधाय प्राप्त है; श्रीर (४) कारपोरेशन के समान बड़ी संस्था जब कि निर्यात ज्यापार से लाम न हो श्रीर श्रल्प काम में हान हो रही हो तो भी निर्यात कर सकती है श्रीर विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकती है।

है श्रीर विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकती है। सरकारी व्यापार कारपोरेशन लोहा श्रीर मैगनीज़ का निर्यात कर रहा है श्रीर श्रानेकों वस्तुश्रों का जैसे सीमेन्ट, सोहाऐश, कास्टिक सोहा, कचा रेशम खाद श्रीर जिप्तम श्रायात निर्यात कर रहा है। यह सीमेन्ट के वितरण में सरकारी ऐजेन्ट का काम कर रहा है। श्रापने कार्य के प्रथम वर्ष में ३० जून १६५७ तक कारपोरेशन ने कुल १० करोड़ रुपयों का कार्य किया था। यह रकम कमीशन ऐजेन्सी के श्राधार पर किये गये कार्यों जैसे सीमेन्ट का वितरण के श्रितिरिक्त था। इसका कुल लाभ ३५ ४२ लाख रुपयों का हुआ था जिसका न्योरा निम्न प्रकार है—

•••	२१'६२	नाख	रुपया
•••	\$0.8 <i>त</i>	1)	23
***	०°३६	"	3)
•••	१'५६	"	"
•••	8.50	23	22
***	₹*१६	"	"
	8.58	12	17
***	१°६४	31	37
	***	१० ४५ ० ३६ १ ५६ १ २०	१०°४५ ,, ०°३६ ,, १°५६ ,, १°१० ,, १°१४ ,,

सोडा ऐश श्रीर श्रन्य कपड़ों पर ३º८२ लाख रुपयों का घाटा हुआ। वास्तविक लाम ३२.६३ लाख रुपयों का हुआ।

सरकारी एजेन्सी के रूप में सीमेन्ट वितरण का ५५ करोड़ कपयी का कार्य कारपोरेशन ने किया जिस पर ६६ लाख रूपया कमीशन प्राप्त हुआ। "भारत सरकार ने कारपोरेशन को निर्माण करने वालों से तथा विदेशों से आयात करके प्राप्त करने तथा देशी और विदेशी सीमेन्ट को समान मूल्य पर (गन्तव्य स्थान के रेल के माड़े को सम्मिलित करते हुये) वितरित करने का कार्य दिया था। इस सेवा के लिये कारपोरेशन को कुल कार्य के १५% दिया गया था। विदेशों से आयात किये सीमेन्ट पर कुल घाटा ४८ लाख कपयों का हुआ जो कि अनुमान से इसलिये बहुत कम था कि आयात की मात्रा बहुत काफी मात्रा में घट गई। इसलिये सीमेन्ट के हिसाब में ५०१ करोड़ रूपयों का अतिरेक दिखलाई पहता है।"

सरकारी ज्यापार कारपोरेशन के काम करने के सम्बन्ध में निम्न आलोचनायें की गई हैं—(१) मारतीय निर्यात को बताने में इसने कोई कार्य नहीं किया है बरन् इसने वर्तमान ज्यापार के ढंगों को विनाश कर दिया है जिससे देश की बहुत बड़ी हानि हुई है; (२) इसके कार्य करने का ज्यय अनुमान से कहीं अधिक हुआ है; और (३) इस प्रकार की संस्थाओं का जो अत्यन्त आवश्यक गुण अपने को परिस्थिति के अनुकूल बना लेने का बदलने का है इसमें नहीं दिखाई पड़ा है। यदि सरकारी ज्यापार कारपोरेशन को सीमेन्ट के आयात करने तथा वितरण करने का कार्य न दिया गया होता तो वह मारत के आयात

निर्यात की व्यवस्था करने के श्रपने कर्त्तव्य का जिसके लिये उसकी स्थापना की गई थी कोई उदाहरख न दे सकता।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—पिछते कुछ वर्षों में मारत के विदेशी व्यापार की मवृति पर विचार करके उपयुक्त व्यापार नीति निर्धारित करने के लिए प्रयम पंचवर्षीय योजना में पाँच िखान्तों का प्रतिपादन किया गया था-(१) योजना में निर्धारित उत्पादन श्रीर उपभोग के लक्ष्यों को पूरा किया जाय; (२) निर्यात का उच्च स्तर रखा जाय; (३) निर्यात व्यापार में जो घाटा हो उसको देश के विदेशी मुद्रा विनिमय के सामनों से पूरा किया जा सके; (४) निर्यात श्रीर श्रायात को सरकार की विच तथा मूल्य सम्बन्धी नीति के श्रनुरूप किया जाय; श्रीर (५) निश्चत व्यापार नीति निर्धारित की जाय।

यह श्राशा की जाती थी कि योजना की श्रवि में कृषि सम्बन्धी कच्चे माल, जैसे जूट श्रीर कपास, श्रीर स्ती सामान, जूट के स्त, जूट का सामान, कथा मेंगनीज, तेल, कोयला, काली मिर्च, तम्बाक्, नारियल की जटा से उत्पादत माल श्रीर ऊर्ना माल का उत्पादन बढ़ेगा। इससे भारत को निर्यात करने के लिए प्यांप्त माल उपलब्ध होगा श्रीर विदेशी मुद्रा भी श्रीषक मात्रा में प्राप्त की जा सकेती। इसके श्रातिरक्त उद्योगों का विकास होने से बिजली के सामान, मशीनों के श्रीजार, साइकिल, कुछ रस्तायनों, दियासलाई, सिमेंट, साबुन श्रीर कागज इत्यादि का निर्यात किया जा सकेगा। यह सुक्ताव भी दिया गया है कि उभय पत्तीय ब्यापार समक्तीतों श्रीर चेत्रीय ब्यागर समक्तीतों के द्वारा भी निर्यात की मात्रा बढ़ाई नाय परन्तु वर्तमान परिस्थितयों में इन समक्तीतों का कार्यचेत्र सीमित है

योजना श्रायोग का श्रनुमान था कि १६५०-५१ श्रीर १६५५-५६ के बीच मारत के निर्यात व्यापार में १० प्रतिशत की श्रीर श्रायात में १० प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका श्रयं यह है कि विदेशी मुद्रा विनिमय के बाटे को देश के साधनों की सीमा के श्रन्दर रखने के लिए निर्यात तथा श्रायात पर कड़ा निर्यंत्रण होना चाहिये। यह श्रनुमान लगाया गया है कि १६५१ की कीमतों के श्राधार पर पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में विदेशी मुद्रा में १३३ करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी श्रार श्रायात बढ़ने के कारण १०८ करोड़ रुपयों की कमी भी होगी इस प्रकार विदेशी मुद्रा में २५ करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी। परन्तु इसमें उस विदेशी मुद्रा की बचत सम्मिलित नहीं है जो तेल शोधशालाश्रों से श्रीर दिल्ली पूर्वी पृत्रीया के साथ व्यापर बढ़ने से प्राप्त होगी, न विदेशी मुद्रा की वह घनराशि सम्मिलित है जिसकी योजना के श्रांतम वर्ष में मशीनों तथा श्रन्य सामानों का श्रायात करने में

आवश्यकता होगी । इसलिए योजना आयोग का अनुमान था कि १६५५-५६ तक विदेशी मुद्रा विनिमय की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दितीय योजना में निर्यात की मात्रा में तुरन्त वृद्धि के सम्बन्ध में यह संब्ध रूप से ज्ञात है कि योजना काल में कोई विशेष उन्नति की सम्मावना नहीं है। भारत की निर्यात श्राय धोड़ी सी वस्तुश्रों से ही प्राप्त होती है। उनमें से तीन-चाय, जूट का सामान, श्रीर सती कपड़े मिलाकर कुल निर्यात का श्राधे के बरावर हैं। मुख्य निर्यात की वस्तुत्रों की बढ़ती हुई विदेशों की प्रतिशोगिता का सामना करना पढ़ रहा है। इससे श्राल्य काल में निर्यात की मात्रा में वृद्धि की सम्भावना बहुत सीमित है। यद्यपि नई वस्तुश्रों के निर्यात का प्रयन्न करना चाहिये श्रीर निर्यात की मुख्य वस्तुश्रों के बाजारों के विस्तृत करने का प्रयन्न करना चाहिये पर यह ध्यान में रखना श्रावश्यक है कि जब तक देश का श्रीदांगीकरण किसी चीमा तक नहीं हो जाता श्रीर देश में उत्पादन की मात्रा भी नहीं बढ जाती तब तक निर्यात की मात्रा में वृद्धि नहीं हो एकती। इसिलये द्वितीय योजना में श्रीद्यो-गीकरण की तीव्र गति को विचाराधीन रखते हुये ग्रायात की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर लाने में श्रीर निर्यात की मात्रा बढ़ाने में विशेष सावधानी की श्रावश्य-कता है द्वितीय योजना के अनुसार भारत के निर्यात को १९६०-६१ तक ६१५ करोड़ रुपयों तक बढ़ाना सम्भव हो सकता है। इस वर्ष योजना के अनुसार त्रायात की मात्रा ६५५ करोड़ रुपयों की होगी।

श्रध्याय ४०

तटकर नीति और संरक्षण

१६२३ से पहले भारत सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार (free trade) की नीति श्रपनायी। इसकी वित्त-नीति (fiscal policy) राजस्व की श्राय की श्रावरुयकता के श्राधार पर निर्धारित की जाती थी। १९२३ में पहली बार श्रनेक उद्योगों को तटकर-संरक्तण दिया गया । स्वतन्त्र न्यापार की नीति को संरक्तण देने की नीति में बदलने के श्रानेक कारण है। (१) प्रथम विश्वसुद्ध से भारत के श्रीद्यी-गिक विकास की संभावनाध्यों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा । सरकार द्वारा राजस्व की श्राय बढाने के लिये श्रिधिक श्रायात कर लगाने से श्रनेक नवीन श्रीर पहले से ही स्थापित उद्योगों ने तेजी से प्रगति की । इससे इस बात पर प्रकाश पड़ा कि तटकर संरक्षण मिलने पर भारत में उद्योगों का विकास किस सीमा तक संभव है। ऋौद्यो-गिक आयोग (१९१६-१८) ने भारत के श्रीवीगिक विकास की संभावनाओं की जाँच की ग्रीर वह इस परिणाम पर पहुँचा कि लोहे ग्रीर इस्पात ग्रीर मशीनों के लिए विदेशों के आयात पर निर्भर करने के कारण, पूँजी लगाने में संकोच होने, वैज्ञातिक शान का अमाब होने और टेकनिशियनों की कभी होने के कारण देश का श्रीद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है । श्रायोग ने इस बात का संकेत किया कि देश के श्रीद्योगिक साधनों का विकास करने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। 'परन्तु चँकि भारत की वित्त नीति का विषय श्रायोग के कार्यचेत्र के श्रन्तर्गत नहीं या इसिलए श्रायोग ने यह िक्फारिश नहीं की कि भारत सरकार को तटकर संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। इस पर भी आयोग ने अपनी जाँच में जिन तथ्यों पर प्रकाश दाला उनसे तटकर संरक्षण की राष्ट्र की सौंग को श्रीर मारतीय श्रीद्योगिक साधनों के पूर्ण विकास की माँग को बहुत बल मिला। (२) १९१६ के राजनीतिक सघारों से यह जात हुआ कि जब तक वित्त नीति निर्धारित करने की स्वतन्त्रता नहीं है और देश को आर्थिक तथा औद्योगिक साधनों के विकास का अधिकार नहीं है तब तक राजनीतिक प्रगति संभव नहीं । राजनीतिक सुधारों के पश्चात् १६२१ में ब्रिटिश खरकार ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर-समिति की सिफारिश के श्रनुसार विक्त सम्बन्धी स्वशासन सममौते (Fiscal Autonomy Convention) को स्वीकार कर लिया। इस समझौते के श्चनुसार यह निश्चित दुश्रा कि यदि मारत सरकार श्रीर विधान मगढल एक विशेष

वित्त निर्धारित कर लें तो, विशेष परिस्पितियों को छोड़कर, अन्यया ब्रिटिश सरकार का मारत-मंत्री (Secretary of State for India) भारतीय वित्त नीति में किसी प्रकार का इस्तचेष नहीं करेगा। इस व्यवास्था से मारत सरकार द्वारा १६२३ में तटकर संरच्च्य की नीति अपनाने के लिए मार्ग वन गया श्रीर (३) अनेक यूरोपीय देशों में तटकर नीति एफल रही और स्वतन्त्र व्यापार नीति धरि-धीरे खत्म हो रही यो। सारी दुनिया में यह अनुभव किया गया कि स्वतन्त्र व्यापार नीति से पिछड़े हुए देशों का श्रीद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता है चिल्क यदि कुछ परिस्थितियों में उदीयमान और नये विकासशील उद्योगों को तटकर संरच्या दिया जाय तो उनके विकास कर सकने की संभावना है। उद्योगों को संरच्या देने के विश्वव्यापी आन्दोलन से मारत के तटकर संरच्या की माँग को पर्यात बल मिला।

वित्ता ध्ययोग (१६२१)—१६२१ में सर इब्राहीम रहीमतुल्ला की श्रध्यक्षता में वित ग्रायोग नियुक्त किया गया। इस श्रायोग को भारत सरकार की तटकर नीति की श्रीर 'इम्पीरियल पिकरेंस' के सिदान्त को लागू करने की संभावनाश्रों की लाँच करने का कार्य सींग गया। श्रायोग ने बताया कि यद्यपि भारत कृषि प्रधान देश है परन्तु उत्पादन करने के लिए इसमें ग्रानेक प्राकृतिक सुविधाएँ हैं। यहाँ कच्चा माल बहुतायत से है, श्रम सस्ता है श्रीर उद्योगों का विकास करने के लिए पर्यात विजली प्राप्त की जा सकती है। स्ती कपड़े श्रीर जूड के दो बड़े उद्योगों के श्रनुभव से यह शात हो गया कि भारत श्रपने प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा लाम उठा सकने में समर्थ है। उद्योगों में संरत्त्वण सम्बन्धी मेद करने के लिए श्रायोग ने निम्नलिखित समाब टिये—

(१) उद्योग को प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हों, जैसे कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में हों, विजली स्ती हों, श्रम पर्याप्त मात्रा में मिले या उत्पादित माल की स्वदेश में काफी खपत हो सकती हो। ये मुविधाएँ विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न सापै- हिक महत्व की होंगी परन्तु इसकी उचित जाँच की जाय और इनके सापे हिक महत्व की निर्धारित किया जाय। विश्व के सफल उद्योगों को श्रम्य उद्योगों की श्रपे हा कुछ विशेष मुविधाएँ हैं जिन पर उनकी सफलता निर्मर करती है। कोई मी उद्योग जिसे श्रम्य की श्रपे हा विशेष मुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं उनसे समान स्तर पर प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय उद्योग को प्राप्त प्राकृतिक मुविधाओं की सावधानी से जाँच करनी चाहिए जिससे यह निश्चित हो जाय कि किसी भी ऐसे उद्योग को संरक्षण नहीं मिलेगा जो बाद में देश पर स्थायी भार वन जाय।

- (२) संरच्या प्राप्त करने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिए जो संरच्या न मिलने पर या तो विल्कुल विकास नहीं करेगा या देश की स्थित को देखते हुए जितनी शीवता से उसका विकास श्रपेक्षित है नहीं हो पायेगा। जिस सिद्धान्त के आधार पर संरच्या देने की सिकारिश की गई है यह उसी का उप सिद्धान्त कहा जा सकता है। संरच्या देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि या तो ऐसे उद्योगों का विकास किया जाय जो बिना संरच्या के विकास नहीं कर सकते हैं या विकासशील उद्योगों का तीव गति से विकास हो।
- (३) ऐसे उद्योग को संरक्षण दिया जाय जो श्रंत में बिना संरक्षण के भी विश्व-वाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सके। इस शत के पूरे होने की संमावना का अनुमान लगाने के लिए प्रथम सुकाव में वर्णित प्राकृतिक संविधाओं पर सावधानी से विचार करना चाहिए। इस सुकाव का महत्व बिल्कुल स्पष्ट है। संरक्षण से हमारा ताल्पर्य ऐसे उद्योगों को श्रस्थायी संस्तृण देने से है जो श्रंत में बिना संरक्षण के चलाये जा सकते हैं।

इन तीन प्रमुख सुकावों के साथ ही वित्त आयोग ने तटकर संरत्तण देने के लिए कुछ अन्य आवश्यक बातों पर भी प्रकाश डाला है। आयोग का मत या कि ऐसे उद्योगों को संरत्तण के सम्बन्ध में प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका उत्पादन व्यय कम हो सकता हो और जिनके द्वारा बढ़े पैमाने पर उत्पादन किये जाने की संमावना हो। इसके साथ ही ऐसे उद्योगों को जो एक निश्चित समय में देश की पूरी आवश्यकता की पूर्ति कर सकने में समर्थ हो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पूर्व विश्वित तीनों सुकावों को पूर्ति न होते हुए भी राष्ट्रीय प्रातरत्ता और विश्वित सैनिक महत्व के उद्योगों को और साथ ही आवार मूल एवम मुख्य उद्योगों को संरत्त्वण दिया जाना चाहिए। आयोग ने बाजार में आवश्यकता से कहीं अधिक विदेशी माल जमा होने और सहायता प्राप्त आयातों से देशी उद्योग को होने वाली हानि को रोकने के लिए भी संरत्त्वण देने की सिकारिश की श्लीर सुकाव दिया कि संरत्त्वण के लिए आवेदन-पत्र देने वाले उद्योगों की स्थित की जाँच करने के लिए और इस सम्बन्ध में सरकार का परामर्श देने के लिए तृटकर-बोर्ड नियुक्त किया जाय।

वित्त श्रायोग द्वारा निश्चित संग्राण नीति श्रमङ्गत है। संरक्षण देने के लिए उद्योगों में मेद करने के सुमान की कड़ी श्रालीचना की गई है —

(१) यदि कोई उद्योग पहले सुमाव की पूर्ति करता है कि उसको प्राकृतिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं तो इसके साथ हा उसका विना संरक्ष्या के विकास न कर सकना श्रयवा जिस प्रगति से देश के हित के लिए उसका विकास होना चाहिये न हो सकना आवश्यक नहीं है। ऐसा उद्योग विना संरच्या के भी विकास कर सकता है। यदि किसी उद्योग को वह सभी प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हैं जिनकी आयोग अपेचा करता है तो विना तटकर संरच्या के उसकी स्थापना न हो सकने का कोई कारया नहीं। दूसरा सुक्ताव लागू होने के लिए उद्योग को कुछ असुविधाएँ होनी चाहिएँ जिनको विना संरच्या के दूर नहीं किया जा सकता है और ये असुविधाएँ ऐसी हो सकती हैं जिससे पहला सुक्ताव हस उद्योग पर लागू न हो। व्यवहारिक जगत में तटकर-बोर्ड के लिए दोनों सुक्तावों का अलग करना और लागू करना;कटिन हो गया इसलिए इन सुक्तावों को केवल सामान्य रूप में ही लागू किया गया। यदि इन दोनों सुक्तावों को पूर्णतया लागू किया जाय तो किसी भी भारतीय उद्योग को तटकर संरच्या प्राप्त नहीं हो सकता।

- (२) नहाँ तक तीसरे सुमान का सम्बन्ध है, जिसमें कहा गया है कि
 उद्योग को अंत में बिना संरक्षण के विश्व बाजार की प्रतियोगिता का सामना
 करने योग्य होना चाहिए, यह कहा जा सकता है कि यह सुमान या तो बिल्कुल
 व्यर्थ है या बिल्कुल असङ्गत। यदि प्रथम सुमान उद्योग पर लागू हो जाता है
 तो यह सुमान पूर्णतया व्यर्थ है क्योंकि उस स्थित में तटकर बोर्ड की भविष्यवाणी का कोई महत्व नहीं रहता। यदि तटकर बोर्ड दूसरे सुमान पर जोर देता
 है कि उद्योग की रिर्थात अत्यन्त खरान है और उसे संरक्षण की अत्यन्त
 आवश्यकता है तो ऐसी स्थित में बोर्ड की यह आशावादी घोषणा कि एक निश्चित
 अविध में उद्योग विना संरक्षण के भी चल निकलेगा केवल भविष्यवाणी ही
 रह जाती।
- (३) आयोग के पूर्व वर्णित तीनों सुमानों में उन उद्योगों के विकास के महत्व पर ध्यान नहीं दिया गया है जिनका अभी पूर्ण उद्भव नहीं हो पाया है या जो अभी अपरिपक्व स्थित में हैं। संरच्चण देने का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि जो उद्योग वर्तमान समय में चल रहे हैं उनका विकास किया जाय और उनको सहायता दी जाय। इसका उद्देश्य यह भी है कि जो उद्योग अभी चाल नहीं किये गये हैं परन्तु जिनको चालू किया जा सकता है उनकी स्थापना की जाय और विकास में सहायता दी जाय। तटकर संरच्चण का उद्देश्य देश का अदिशिक विकास करने के लिए सभी औद्योगिक संभावनाओं का पूर्ण उपयोग करना है। ऐसे नये उद्योगों को छोड़ देने से भारत में तटकर संरच्चण का कार्यचेत्र बहुत संकीर्ण कर दिया गया है।
 - (४) वित्त श्रायोग ने सुकाव दिया है कि केवल तदर्थ तटकर-बोर्ड स्थापित किये जार्य । श्रायोग ने स्थायी तीर पर तटकर-बोर्ड स्थापित करने की लिफारिश

नहीं की जो केवल उद्योगों के संरच्चा के दावों की जाँच नहीं करता विलक संरचित उद्योगों की देख-रेख भी करता।

स्तार ने वित्त श्रायोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया श्रीर इन्हीं सुमावों पर श्राधारित तटकर संरक्षण नीति फरवरी १६२३ को श्रपना ली गई श्रीर जुलाई १६२३ में तटकर-बोर्ड स्थापित किया गया। तटकर-बोर्ड ने श्रनेक उद्योगों के संरक्षण प्राप्त करने के दावों की जाँच की श्रीर इसकी सिफारिशों के श्रनुसार लोहे तथा इस्पात श्रीर श्रन्य सम्बन्धित उद्योगों को, सूती कपड़ा श्रीर रेशम के कीड़े पालन के उद्योगों को, वाँस, कागज, दियासलाई, चीनी, भारी रसायनिकों श्रीर सोने के तार खींचने वाले उद्योगों को संरक्षण दिया गया। कोयला, सिमेंट, काँच श्रीर तेल उद्योगों को तटकर संरक्षण नहीं दिया गया।

उद्योगों में मेद करके संरक्षण देने की नीति से कई प्रतिबन्धों एवं असंग-ताओं के होते हुए भी बहुत अञ्छा परिणाम निकला । मारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, चीनी तथा श्रन्य उद्योगों की श्राज की पर्गात का श्रेय संरक्षण की इसी नीति को है। तटकर संरक्षण नीति की सफलता इस बात से प्रकट होती है कि इन उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है श्रीर कुछ, कारखानों को छोड़कर अन्य भारतीय कारखानों का उत्पादन न्यय विदेशी कारखानों के उत्पादन व्यय की प्रतियोगिता का सामना कर सकता है (इनके विकास के कारण १६४१ में लोहा तथा इस्पात उद्योग का, १६४७ में कागज उद्योग का और १६५० में चीनी तथा सूती कपड़ा उद्योग का संरक्षण वापिस ले लिया गया) परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वित्त श्रायोग के तीनों सुमाव विशेष सफल रहे। वास्तव में इनको लागू करने पर अनेक दोष प्रकट हुए और उनके कारण उद्योगों के विकास में बहुत बाघा हुई। सिमेंट, काँच श्रीर कोयला जैसे श्रनेक ऐसे उद्योगी को संरक्षण नहीं दिया गया जिनको वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता थी। रकायनिक उद्योग को बहुत कम समय के लिए संस्क्षण दिया गया श्रीर इसलिए उसे विकास कर सकते का पूरा श्रवसर नहीं मिला । सरकार ने श्रधिकतर श्रायात करों के रूप में संरक्ष्या दिया, केवल लोहे तथा इस्पात उद्योग की आर्थिक सहायता दी गई है। अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार ने वित्तीय सहायता देने या रेलवे का भाड़ा कम करने के तटकर बोर्ड के दिये सुकावों को बिल्कुल श्रस्वीकार कर दिया जिससे भारत में तटकर संरक्षण का कार्यक्षेत्र बहुत संक्रचित हो गया । इसके साथ ही श्रोटावा समझौते के अन्तर्गत इम्पीरियल पिफरेंस स्वीकार करके तटकर संरक्षण का चेत्र श्रीर भी संकुचित कर दिया।

संरक्ष्य का भार-तटकर की नीति की भी कड़ी श्रालोचना की गई

हैं। यह कहा गया है कि (१) संरत्त्त्रण के देने से भारत की राजस्य की आय में काफी कमी आ गई। (२) श्रायात-कर के रूप में श्रप्रत्यज्ञ करों में वृदि होने से भारतीय कर प्रणाली श्रीर श्रिधक प्रतिगामी (regressive) हो गई है । (३) तटकर संरक्षण से उपमोक्ताश्रों को स्ति पहुँची। यदि संरक्षण न दिया जाता तो वह श्रायात किये गये सामान को सस्ते मूल्य में कय कर सकता था। चूँकि निर्धन जनता को श्रपनी श्राय का श्रधिकांश श्रायात किये गये सामान पर व्यय करना पदा जिसकी कीमतें तटकर संरच्या होने से बढ़ गई थीं इसलिए भारत में सम्पत्ति के श्रममान वितरण की स्थिति श्रीर विगड़ गई। इन तकों को शीव ही स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में दोनों पत्तों से बहुत कुछ कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि गरीय जनता, विशेषकर गाँव में रहने वाली जनता. अपनी आय का अधिकांश आयात किये गये सामान पर व्यव करती है श्रीर इसलिए तटकर संरक्षण नीति ने उसे श्रीर श्रधिक निर्धन जना दिया है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि उपभोक्ता वर्ग को इस संरक्तण से महँगा सामान खरीदने के फलस्वरूप द्यानि उठानी पड़ी क्यांकि संरच्चरा न होने पर श्रायात किये गये माल को वह सस्ती कीमत में खरीद सकते थे। परस्त यह कहना सही नहीं कि इससे सम्पत्ति के असमान वितरण की स्थिति श्रीर बिगड़ गई।

संरच्या की नीति के प्रभाव से सरकार की चुद्धी (customs) से प्राप्त होने वाली श्राय घट गई है श्रीर श्रायात कर लगाने से कर प्रणाली भी कुछ प्रतिगामी हो गई है परन्तु इन वातों पर श्रन्य सम्बन्धित बातों से श्रलग करके विचार नहीं किया जा सकता है। सारी स्थिति को समझने के लिए हमें सभी परिस्थितयों पर विचार करना पड़ेगा। यदि ऐसा किया जाय ता स्थिति इतनी दयनीय मालूम नहीं होगी जितनी तटकर संरच्चण के आलोचकों ने अंकिक की है। तटकर संरच्या से देश के श्रीदांगिक सावनों का विकास हाता है श्रीर इसके साथ ही संरक्षित उद्योगों में श्रीर श्रन्य उद्योगों में रोजगार बढ़ता है। इससे राष्ट्रीय आय (national dividend) बहती है, उपभोक्ता की आप बहती है श्रीर सरकार का राजस्व बढ़ता है। देश के विकास के लिए सरकार तथा उपभोक्ताओं को कुछ काल के लिए त्याग करना पहता है परन्तु प्रश्न यह है कि संरक्षण नीति लागू करने से क्या दीर्घकाल में भी वह हानि उठाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि तटकर संरच्या का अन्तिम उद्देश्य केवल उत्पादकों को नहीं बल्कि उपमोक्ताश्रों को भी सहायता देना है। इसलिए संरक्त्य नीति के कारंग जो त्याग करना पड़ता है उसे इस नीति के विरुद्ध तर्क के रूप में नहीं दिया जा सकता है।

श्रस्थाई तटकर-बोर्ड--दितीय विश्वयुद्ध के त्रारंभकाल से यह अनुभव किया गया कि भारत में अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों का अभाव है। चुँकि युद्धकाल की श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए इन उद्योगों को स्थापित करना त्रावश्यक था इसलिए सरकार ने १६४० में घोषित किया कि युद्धकाल में स्थापित उद्योगों का यदि ठोस व्यवसायिक श्राधार पर संगठन किया गया तो उन्हें उपयुक्त संरक्षण दिया जायगा। इससे भारत में तटकर संरक्षण का कार्यक्रेत्र बढ गया श्रीर सरकार की तटकर नोति को भी बिल्कुल नया रूप मिल गया। परनत दीर्घकालीन तटकर नाति निर्घारित करने में और इसका संचालन करने के लिए स्थाई संस्था का निर्माण करने में काफी समय लग जाता इसलिए भारत-सरकार ने ३ नवम्बर १६४४ को श्रस्थाई तटकर-बोर्ड स्थापित किया श्रीर इसे युदकाल में स्थापित किये गये उद्योगों के संरक्षण दिये जाने के दावों की जाँच-पहताल करने का कार्य मींपा। यह बोर्ड दो वर्ष के लिए स्थापित किया गया श्रीर इसे किसी भी उद्योग को ३ वर्ष तक संरक्षण देने की सिफारिश करने का ऋषिकार प्राप्त था। उद्योगी को संरच्चण देने की सिफारिश करने में बोर्ड की सहायता के लिए कुछ शर्ते निर्घारित कर दी गई, जैसे (१) उद्योग व्यवसायिक श्राधार पर संगठिन किया गया हो श्रीर हसी हिन्द से चलाया जाता हो श्रीर (२) (श्र) उद्योग की प्राकृतिक एवम् ऋार्थिक सुविधात्रों तथा इनकी लागत को ध्यान में रखते हुए यह संभव प्रतीत होता हो कि निश्चित समय में उद्योग पर्याप्त विकास कर लेगा और उसे राज्य की सहायता या तटकर संरक्षण की श्रावश्यकता नहीं रहेगी, (ब) उद्योग पेसा है जिसे राष्ट्रीय हित में सहायता एवम् संस्तृश देना वांछित है अरीर इस सहायता का जनता पर अधिक भार नहीं पहेगा। यदि उद्योग की संरक्षण की माँग उचित सिद हुई श्रंथांत् जन (१) श्रीर (२) शर्ते लागू हो गई तो बोर्ड यह विकारिश करेगा कि (क) उद्योग को किस दर पर ब्रीर किस वस्तु के सम्बन्ध में संरक्षण दिया जाय, (ख) उद्योग को संरक्षण देने के लिए या सहायता देने के लिए और क्या श्रतिारक्त उपाय हो सकता है, श्रीर (ग) सरच्चा या श्रन्य उपाय किस अविध तक (३ वर्ष से अधिक नहीं) लागू रखे जा सकते हैं।

श्रस्थाई तटकर-बोर्ड का पथ-पदर्शन करने के लिए भारत सरकार ने जो नया सूत्र निकाला वह पूर्व-नीति से काफी भिन्न था जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि श्रपनी श्राधिक सुविधाओं पर श्राधारित उद्योग की वास्त्विक या संभावित लागत क्या होगी। यह कहा गया है कि यह सूत्र काफी व्यापक है श्रीर तटकर सरज्ञ्या देने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित को प्रमुख स्थान देता है।

संरच्या के लिए अस्थायी तटकर बोर्ड के पास ४६ मामले आये। बोर्ड ने

इनमें से ४२ मामलों को अपनी सिफारिश के साथ सरकार के पास मेजा। इनमें से ३८ उद्योग युद्धकाल में स्थापित किये गये थे और ४ उद्योग—स्ती कपड़ा, इस्पात, कागज और चीनी उद्योग—युद्ध के पहले से चालू थे। युद्धकाल में स्थापित उद्योगों के लिये बोर्ड ने उचित संरक्षण की सिफारिश की। बोर्ड ने यह सिफारिश की कि चीनी उद्योग की संरक्षण दिया जाय और स्ती कपड़ा उद्योग, इत्पात तथा कागज उद्योगों का संरक्षण वापस ले लिया जाय।

पुनः संगठित तटकर-बोर्ड — नवम्बर १६४७ में तटकर बोर्ड का पुनः सङ्गठन किया गया और स्थायो तटकर बोर्ड के कार्यों के अतिरिक्त इसको कुछ नये कार्य भी संपे गये जैसे (१) बोर्ड देश में उत्पादित माल के उत्पादन व्यय की जाँच करेगा, इसको योक, फुटकर तथा अन्य कीमतों को निर्घारित करेगा और सरकार को आवश्यकता पड़ने पर इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देगा, (२) बोर्ड सस्ते विदेशी माल के विद्यागरतीय उद्योग को संरक्षण देने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देगा; (३) बोर्ड संरक्षण के प्रमावों की या सरकार द्वारा दी गई अन्य सहायताओं के प्रमाव की आवश्यकता पड़ने पर जाँच पढ़ताल करके सरिचित उद्योग की प्रगति पर सदैव दिष्ट रखेगा। बोर्ड इस की जाँच करता रहेगा कि संरक्षण देने की सभी शतों को पूरी तरह से लागू किया गया है और संरक्षित उद्योग कुशलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं।

पुनः सङ्गठित तटकर बोर्ड के कार्य की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- (१) बहुत से ऐसे उद्योगों को तीन वर्ष तक के लिए संरत्त्रण दिया गया जिन्हें पहले भी संरक्षण दिया गया था। अनेक उद्योगों को सरकार ने एक या दो वर्ष तक के लिए और संरक्षण दिया और कुछ उद्योगों को तीन वर्ष तक के लिए। इससे बहुत कुछ अंश में संरक्षण का उद्देश्य ही नध्ट हो गया क्योंकि उद्योगपति इस बात के प्रति निश्चित नहीं ये कि भविष्य में भी तटकर संरक्षण मिलेगा और इसी अनिश्चितता के कारण उन्होंने कोई उद्योग स्थापित नहीं किया यद्यपि वह लाभदायक सिद्ध हो सकता था। इसी कारण सरकार की अल्पकाल के लिए संरक्षण देने की नीति वहत हानिकारक सिद्ध हई।
 - (२) पुन: सङ्गटित तटकर बोर्ड ने श्रानेक नए उद्योगों को भी संरक्षण देने की सिफारिश की जैसे साइकिल के पुर्जे, श्राटा पीसने की चक्की (Grinding wheels), काँच, काँच के वर्तन, सोसा ऐश, स्ती कपड़ा उद्योग की मशीने, मशीन स्कू, जिपफास्टनर, प्लास्टिक, पेन्सिल श्रीर वटन इत्यादि बनाने के उद्योग। इससे भारत के श्रीद्योगिक विकास की एक कभी पूरी हो गई।
 - (३) अनेक उद्योगों को विभिन्न कारण बताकर संरक्षण देने से इन्कार कर

दिया गया जैसे लिवर एक्सट्रेक्ट, कीपर सल्फेट, स्लेट और स्लेट पेनिस की इस कारण संरच्या नहीं दिया गया कि इन वस्तुओं की भारत में 'विक्री कीमत' श्रायात किए गए सामान की कीमत से कम हैं। स्टर्लाइस्ड कैटमट (Sterlized Catgut) श्रीर विजली के पंखों के उद्योगों को इस कारण संरच्या नहीं दिया गया कि वर्तमान में राजस्व कर से इन उद्योगों को पर्याप्त संरच्या मिला हुआ है श्रीर यदि उद्योगपित चाई तो इन उद्योगों का वर्तमान स्थिति में विकास कर सकते हैं। मिलक पाउडर श्रीर छोटे श्रीनार इत्यादि बनाने के उद्योगों को इस श्राधार पर संरच्या नहीं दिया गया कि वर्तमान स्थिति में इन उद्योगों को किसी भी दशा में संरच्या की श्रावश्यकता नहीं है।

(४) श्रनेक उद्यंगों, जैसे फासफोरस, फासफोरिक एसिंह, पोटेसियम परमंगनेट. स्टील बेल्ट एएड लेखिंग श्रीर चीनी उद्योगों को जिन्हें पहले संरक्षण दिया गया था श्रव उनकी यह सुविधा वापस कर ली गई। जहाँ तक चीनी उद्योग का सम्यन्य है तटकर बोर्ड ने ग्रुगर सिन्डीकेट की कड़ी श्रालोचना करते हए बताया कि चीनी उद्योग ने अपने एकाधिकार का पूरा लाम उठाया श्रीर ग्रपने सदस्यों की उपमोक्ताग्रों की हानि करके खुब लाम दिया, इसके साथ ही विन्होकेट ने उत्तर प्रदेश श्रीर विहार श्रगर कमीशन के नियन्त्रण का विरोध किया, विकास कर सकने तथा कुशलता बढ़ा सकने में श्रसफल रहा श्रीर कई बार अमान की आशंका पैदा कर दी। अस्पायी तटकर बोर्ड की सिकारिश के श्राधार पर लोहा तथा इस्पात, स्ती कपड़ा श्रीर कागज उद्योगों का संरक्षण पहले ही समाप्त कर दिया गया था। चीनी उद्योग की संरच्या सुविधा खत्म करने के साथ ही संरक्त्या खत्म करने की प्रवृति भी जोर पकड़ गई । कुछ मामलों में यह तर्क दिया गया कि उद्योग श्रपना पर्याप्त विकास कर चुका है श्रीर श्रव संरक्षण की श्रावश्यकता नहीं रही । कुछ के बारे में यह कहा गया कि श्रभी तो वर्तमान राजस्व कर पर्याप्त संरक्षण है श्रीर श्रपनी श्रन्य सुविधायों का प्रवन्य कर के त्रसादन व्यय घटाना उत्पादकों का कार्य है। संरक्तण खत्म करने से यह श्राशा की जाती थी कि उपभोक्ता को लाभ होगा श्रीर उसे रस्ती कीमत पर चीजें मिल लायँगी। संरच्या खत्म करने की प्रवृत्ति को १६२३ के वित्त आयोग की सिफारिश से काफी वल मिला। विच श्रायोग ने ििफारिश की थी कि संरच्चण प्राप्त करने वाले उद्योग एक निश्चित श्रवधि में श्रापना पर्याप्त विकास कर सकते हैं श्रीर उस श्रवधि के बाद उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परन्तु कुछ विशेषज्ञों का मत है कि संरक्षण प्राप्त उद्योग को श्रपना विकास करने के लिए २५ से ३० वर्ष का समय चाहिए श्रीर इससे पहले ही संरक्षण खत्म कर देना श्रनुचित है।

- (५) तटकर बोर्ड ने केवल आयात कर के द्वारा ही नहीं बल्कि आर्थिक तथा अन्य सरकारी सहायता, जैसे कुछ उद्योगों की मदद के लिए विकास कोप का निर्माण इत्यादि करने की ज्यवस्था करके संरक्षण देने की सिकारिश की। इससे भारत के तटकर संरक्षण का कार्यचेत्र काफी ज्यायक हो गया।
- (६) तटकर बोर्ड ने श्रनेक उद्योगों में जॉच पहताल की श्रीर श्रीयोगिक उत्पादन बहाने, उद्योगों का विकास करने श्रीर श्रष्टाचार रोकने के लिए श्रनेक मुक्ताव दिये।

वित्त आयोग (१६५०)—नये वित्त आयोग नं तटवर संग्छण की समस्या पर अधिक सन्तुलित और विस्तृत दृष्टिकोण से विचार किया और मुक्ताया कि तटकर संरच्छा के प्रश्न पर पृषक रूप से विचार नहीं किया जा सकता है। चूँकि तटकर संरच्छा उद्योग और कृषि नियोजन का एक श्रंग है इसलिए इस पर श्रन्य सम्बन्धित समस्याओं के साथ ही विचार किया जा सम्ता है। वित्त आयोग ने तटकर-संरच्छा की सिकारिश की और इस उद्देश्य से उद्योगों की तीन अधियों में विभक्त किया—

- (१) प्रतिरक्षा तथा तत्सम्बन्धित उद्योग।
- (२) श्राघारभ्त श्रीर प्रमुख उद्योग ।
- (३) 'त्रम्य उद्योग'।

उद्योग के प्रथम श्रेणी के सम्बन्ध में आयोग ने तटकर-संरक्षण प्रदान करने की सिकारिश की, चाहे जनता पर इसका कितना ही भार वयो न पड़े। इस स्वकृष्ध में यही 'नीत उचित भी है। देश में शान्ति और समृद्धि के लिए ये उद्योग अत्यन्त महत्व के हैं और लागत चाहे कितनी ही हो इन उद्योगों का किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूर्ण विकास होना जरूरी है। दूसरी श्रेणी के आधारभूत और प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में आयोग ने सिकारिश की कि इन उद्योगों को दिये जाने वाले संरक्षण का प्रकार, उसकी मात्रा और शतों को निर्धारित करने का तटकर अधिकारियों को पूर्ण अधिकार देना चाहिए। इन उद्योगों का अधिक महत्व होने के कारण आयोग ने तटकर-संरक्षण को करने की शतों की सिकारिश नहीं की। तीसरे श्रेणी के अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न दो अते दीं, कि (अ) उद्योग की आर्थिक मुविधाओं और उनकी वास्तविक या संभावित लागत को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित हो कि उचित अवधि में उद्योग अपना पर्याप्त विकास कर लेगा और विना संरक्षण तथा सहायता के स्कलतापूर्वक चलाया जा सकेगा। (व) इस प्रकार के उद्योग को संरक्षण देना राष्ट्रीय हित में है और उसकी प्रत्यक्ष एवम परोक्ष मुविधाओं को संरक्षण देना राष्ट्रीय हित में है और उसकी प्रत्यक्ष एवम परोक्ष मुविधाओं को संरक्षण देना राष्ट्रीय हित में है और उसकी प्रत्यक्ष एवम परोक्ष मुविधाओं को

ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के संरक्त्य का श्रयवा श्रन्य प्रकार की सहायता का जनता पर श्रिधक मार न पड़िया। श्रन्य उद्योगों के सम्बन्ध में निम्न दो शर्तों की श्रायोग ने सिफारिश की—

- (क) उद्योग को प्राप्त श्राप्तिक सुविधाओं श्रीर उसके सम्भावित श्रयवाः वास्तविक उत्पादन लागत को विचाराधीन रखते हुए यह श्राशा की जा सके कि उपयुक्त समयाविध में वह उद्योग हतना विकसित हो जायगा कि बिना संरच्चगः श्रयवा सहायता के वह सफलतापूर्वक चलता रहे; श्रीर श्रयवा,
- (ल) वह ऐसा उद्योग हो जिसके लिये राष्ट्रीय हित के दृष्टिकीण से उसे सहायता श्रयवा संरक्षण प्रदान करना वाँच्छनीय हो श्रीर उससे प्राप्त प्रत्यक्ष श्रयवा परोक्ष लामों की तुलना में सहायता श्रयवा संरक्षण का भार जनता पर श्रत्यधिक न हो।

श्चायोग ने श्चनेक श्चन्य वातों पर भी श्चपनी राय प्रकट की है जिससे। तटकर श्चिकारियों को मामले सुलमाने में सहायता मिलेगी—

- (१) आयोग ने सुकाव दिया है कि यदि उद्योग को श्रन्य आर्थिक सुविधाएँ पा हैं, जैसे स्वदेश का वाजार, अम इत्यादि तो संरज्ञ्य देने के लिए यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि उद्योग को श्रपने चेत्र में ही कच्चा माल प्राप्त हो जाय।
- (२) यद्यपि साधारण तौर पर एक संरच्या प्राप्त उद्योग को अपनी स्वदेशी बाजार की आवश्यकता पूरी करने मं समर्थ होनी चाहिए परन्तु इसे संरच्या देने की आवश्यक शर्त नहीं बना देना चाहिए। तटकर अधिकारियों को अल्पकाल में केवल इस बात पर ही विचार करना उचित होगा कि उद्योग के विकास की संमानना कैसी है ताकि निश्चित अवधि में वह स्वदेश की माँग के अधिकांश की पूर्ति कर सके।
- (३) यदि कब्चे माल का उत्पादन करनेवाले उद्योगों को संरच्या देने से श्रन्यः उद्योगों के मार्ग में बाघा श्रा जाती है तो इन संरचित उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की खपत करने वाले उद्योगों की हानि को पूरा करने के लिए कोई नियमः नहीं बनाया जा सकता है। यदि उद्योग संरचित है तो कब्चे माल का उत्पादन करनेवाले उद्योग को संरक्षण देने से उत्पन्न श्रमुविधाशों को पहले से दिये हुए सरक्षण के श्रतिरिक्त 'पूरक संरच्चण' देकर दूर किया जा सकता है।
- (४) जिन उद्योगों की पूर्ण रूप से स्थापना नहीं की गई है या जो अभी निल्कुल आरम्भिक स्थिति में है उन्हें भी उसी मकार संरक्षण की सुविधा दी जानी। चाहिए जैसी पहले से ही स्थापित उद्योगों को दी जाती है।

वित्त श्रायोग ने सिकारिश की है कि 'तटकर श्रायोग' नाम की स्थायी संस्था स्थायित की जाय। इस प्रकार की स्थाई संस्था विभिन्न परिस्थितिश्रों ते श्रानुभव प्राप्त करेगी, संरक्तित उद्योग की देख-रेख करेगी श्रीर सरकार की संरक्षण नीति जारी रखने या श्रान्य सम्बन्धित निर्णय करने में सलाहकार का काम भी करेगी। वित्त श्रायोग इस पन्न में नहीं है कि 'तटकर श्रयोग' योजना श्रायोग का एक विभाग वन जाय। श्रायोग ने नुकाव दिया है कि तटकर श्रायोग का एक श्रयं-श्रदालतो रूप होने के कारण इसका सङ्गठन प्रयक् होना चाहिए। सटकर श्रायोग की सिकारिशों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए वित्त श्रायोग ने यह सिकारिश की है कि श्रायोग की रिगोर्ट पर सरकारी निर्णय तथा उसके प्रकाशन हत्याद के सम्बन्ध में एक विशेष विधि श्रपनानी चाहिए।

वित्त श्रायोग की निर्फारश काफी व्यापक हैं। श्रायोग ने प्रतिरह्म तथा श्रम्य फीकी उद्योगों की श्रीर इसमें साय ही श्राधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों की सवंधा उचित महत्व दिया है। ये उद्योग देश के श्राधिक विकास के लिए श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। श्रायोग ने साब्द शब्दों में ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने की श्रावश्यकता बताई है जो श्रमों श्रारंभिक स्थिति में हैं या जिनको श्रमी स्थापित नहीं किया जा सका है। इससे यह बात निश्चित हो गई कि ऐसे उद्योगों की त्यापना हो सकती है जिनकी भविष्य में विकास कर सकने की वहीं सम्भावनाएँ हैं परन्तु जो संरक्षण के श्रमाव में स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। विच श्रयोग ने न केवल उद्योगों को संरक्षण देने पर जोर दिया है विक्त स्पष्ट शब्दों में इस बात की श्रावश्यकता बताई है कि संरक्षण देने के बाद उन उद्योगों के विकाश श्रीर उन्नित की देख-भाल की जाय श्रीर संरक्षण प्राप्त करने के बाद उत्तरदायित्व का निर्वाह कराया जाय।

'श्रन्य उद्योगों' के सम्बन्ध में संरक्षण देने की जो दो शर्ते दी गई हैं यद्यपि वह १६२१ के विच श्रायोग द्वारा दिये गये संरक्षण सम्बन्धी भेद करने के तीनों सुकावों से श्रिषक व्यापक हैं श्रीर उनकी विशेष श्रालोचना भी नहीं की जा सकती हैं किर भी उन्हें सन्तोप जनक नहीं कहा जा सकता है। श्रतीत की भाँति विच श्रायोग ने भी दो वार्तो पर विशेष जोर दिया है कि इस प्रकार संरक्षण का श्रयवा श्रन्य प्रकार की सहायता का जनता पर श्रिषक भार न पड़े श्रीर उद्योग एक निश्चित श्रविध में श्रपना पर्याप्त विकास कर ले जिससे बिना संरक्षण एवम् सहायता के चलाया जा सके। पर कोई भी तटकर श्रिषकारी इस प्रश्न पर निश्चित निर्णय नहीं दे सकता है।

तटकर आयोग-१९५१ के तटकर आयोग कानून के अन्तर्गत एक

स्थायी तटकर-आयोग स्थापित करने की न्यवस्था की गई है जिसमें अध्यक्त सहित तीन सदस्य होंगे। मारत सरकार ने २१ जनवरी १९५२ को तटकर-आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग को अतीत की सभी तटकर-निर्धारण समितियों से अधिक अधिकार दिये गये हैं। तटकर आयोग की मुख्य विशेषताएँ निम्न-लिखित हैं—

(१) तटकर श्रायोग पहले से ही स्थापित उद्योगों के श्रितिरिक्त उन उद्योगों की संरक्षण प्राप्त करने की माँग पर भी विचार करने का श्रिषकारी है जिनमें श्रिभी उत्पादन श्रारंभ नहीं हुआ है परन्तु संरक्षण मिलने पर उत्पादन श्रारंभ कर सकने की संभायना है। श्रायोग श्रितीत में केवल पूर्व-स्थापित उद्योगों की माँग पर ही विचार कर सकता था।

(२) प्राथमिक संरच्या श्रीर विशेष वस्तुश्रों की कीमतों के श्रातिरिक्त, चाहे वह वस्तुएँ संरच्तित उद्योग की हों या श्रासंरच्तित उद्योग की, श्रायोग श्रम्य मामलों में स्वयं जीच पड़ताल श्रारंभ कर सकता है। पहले दो श्रपवादों के सम्बन्ध में

जाँच केवल सरकार के कहने पर ही की जा सकती है।

(३) श्रायोग संरक्षण कार्य की जाँच करेगा श्रीर समय पर इसकी रिपोर्ट सरकार को देगा।

- (४) तटकर निर्धारित करने के श्रौर संरक्षित उद्योगों के कर्तव्यों को विश्चित करने के सामान्य नियमों को बनाने श्रौर उनमें संशोधन इत्यादि करने का श्रायोग को पूर्ण श्रिषकार दिया गया है। तटकर-बोर्डों को यह व्यापक श्रीषकार प्राप्त नहीं था।
- (५) श्रायोग मत्येक उद्योग की श्रावश्यकतात्रों के श्रनुसार संरक्षण की श्रविधि निश्चित करने को स्वतंत्र है और इस पर युद्ध के पश्चात् नियुक्त तटकर-श्रोडों की तरह यह प्रतिवन्ध नहीं लगा है कि संरक्षण की श्रविध तीन वर्ष से श्रिषक न हो।
- (६) तटकर श्रायोग कानून में यह व्यवस्था की गई है कि श्रायोग द्वारा रिपंट दिये जाने के तीन महीने के श्रन्दर सरकार संसद को स्चित करे कि उसने रिपोट पर क्या कार्यवाही की है श्रीर कोई कार्यवाही न करने पर सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकी।

कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकार अने के ऐसे मामलों को जाँच करने श्रीर रिपार्ट देने के लिए आयोग को सौंप सकती है, जैसे (१) उद्योग को आत्साहन देने के लिए संरक्त्या, (२) आयात-निर्यात पर चुंगी (Customs) तथा अन्य करों में भेद, (३) सस्ते मूल्य पर माल से बाजार पाट देने और संरक्तित उद्योगों द्वारा संरच्या का दुरुपयोग करने के विश्वद कार्यवाई, (४) संरच्या का कीमतों के सामान्य स्तर पर और जीवन-निर्वाह की लागत पर प्रमाव, (५) व्यापार एवम् वाणिव्य समझीतों के अन्तर्गत तटकर में रियायत करने का किसी विशेष उद्योग के विकास पर प्रमाव और (६) संरच्या देने से उत्यव अव्यवस्था। इससे स्पष्ट है कि तटकर आयोग को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कार्य से देश को लाम होना चाहिए।

श्रायोग के कार्य की सबसे कड़ी श्रालोचना यह की गई है कि श्रायोग ने संरक्षण मात्रा का निर्धारण करने में बड़ी संकीणता का प्रदर्शन किया है, क्यों कि प्राय: उसकी मात्रा स्वदेशीय उत्पत्तियों के कारखाने के बाहर के उपयुक्त मूल्य तथा उसके सी॰ श्राई० एफ० मूल्य, तथा श्रायात किये हुये माल के जहाज से उतरने पर के मूल्य की द्वलना के श्राधार पर निश्चित की गई है। इन बातों को श्रीर उपमोक्ताश्रों की दिच को विचाराधीन रख कर श्रायोग कमी-कभी संरच्या की मात्रा निश्चित करते में जैसा कि कच्चे रेशम, हाइड्रो क्वीनीन. ग्लूकोज इत्यादि के सम्बन्ध में किया गया है, विकासवादी श्राधिक व्यवस्था के लिये श्रावश्यक सुविधाश्रों का ध्यान रखना कठिन है। इससे तटकर नीति के पुनर्परीच्या की श्रावश्यकता प्रतीत होती है। दितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत बड़ी मात्रा तथा छोटी मात्रा में उत्यादन करने वाले उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है; इसलिये तटकर नीति के वदलने की तो श्रीर भी श्रावक श्रावश्यकता प्रतीत होती है।

तटकर श्रायोग के कार्यों की परीक्षा करने से पता लगेगा कि ४० से अधिक उद्योगों में से जिन्हें संरक्षण प्राप्त था, लगमग श्रावे से श्रधिक को संरक्षण श्राय-कर (Revenue duty) को समान मात्रा के संरक्षण कर के रूप में परि-वर्तित करके दिया गया है। श्रन्य उद्योगों के सम्बन्ध में जैसे सोडा ऐश, पेन्सिल, फाउन्टेन पेन की स्याही, रेशम के कीड़े पालना, श्राटंसिल्क श्रीर कई, वाईसिक्ल, स्टाच, विशेष प्रकार की चिक्कियों को प्रचलित श्राय कर में वृद्धि द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है।

"१६५६-५७ में तटकर आयोग ने ६ तटकर सम्बन्धी श्रीर चार मूल्य सम्बन्धी जीच की। तटकर जाँचों में से दो ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में थी जो प्रथम बार संरक्षण चाइती थी श्रीर बाकी ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में थी जिन्हें पहिले से ही संरक्षण प्राप्त था। सरकार ने कर संरक्षण जारी रखने तथा श्रीर बहुत साधारण परिवर्तनों के साथ उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की सिफारिशों

को पूर्णतया स्वीकार कर लिया। "हाल में जो दो जाँच तटकर आयोग ने की है वे मोटरों श्रीर इस्पात के मूल्यों के सम्बन्ध में की गई है। इस समय जिन मुख्य उद्योगों को संरच्या भारत में प्राप्त है वे मोटर, वाइसिकिल निर्माण, रई के कपड़े बनाने की मशीनों के निर्माण का उद्योग, चक्की के पाट बनाने का उद्योग, रई श्रीर अन लपेटने का उद्योग, लकड़ी के स्कूबनाने का उद्योग तथा प्लाई बुह श्रीर टी चेस्ट बनाने के उद्योग हैं।

भारत और हैवना चार्टर—वित्त आयोग ने इस बात पर विचार किया है कि हैवना चार्टर की पुष्टि की जाय या नहीं। सारी सम्बन्धित वातों पर विचार करने के परचात आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि भारत को चार्टर की पुष्टि तभी करनी चाहिए जब (१) अन्य आर्थिक महत्त्व के देशों ने जिनमें अमरीका और बिटेन मी सम्मिलित हैं इसकी पुष्टि कर ली हो और (२) यह उस समय की देश की आर्थिक स्थित के अनुकुल कार्यवाई हो।

श्रम्तर्राष्ट्रीय न्यापार संघ के हैवना चार्टर श्रीर तटकर तथा न्यापार समकीते (General Agreement on Tariff and Trade) में श्रम्य देशों के साथ भारत ने भी इस्ताक्तर किये हैं। तटकर तथा न्यापार समकीते का उद्देश्य स्वतन्त्र न्यापार का विकास करना श्रीर श्रम्तर्राष्ट्रीय न्यापार में भेदभाव के न्यवदार की दूर करना है। इस समकीते में यह न्यवस्था की गई है कि समकीता करनेवाले पन्न यदि किसी विशेष वस्तु के सम्बन्ध में परस्पर सुविधाएँ हैं तो दुरन्त ही ये सुविधाएँ सभी सदस्यों को बिना किसी शर्त के समान रूप से दी जायँगी। परस्पर समकीता-वार्ता करके जो सुविधाएँ प्राप्त की जायँ वह सभी सम्मिलित देशों के लिए भी हो। इस प्रकार तटकर तथा न्यापार समकीते के श्रम्तर्गत सब से श्रिविक लाभ उठाने वाले राष्ट्र द्वारा बहुपन्नीय कार्यवाही की न्यवस्था की गई है। इस्पीरियल प्रिकरेन्स प्रणाली को तटकर तथा न्यापार समकीते में सम्मिलित नहीं किया गया है।

हैवना चार्टर श्रीर तरकर तथा व्यापार समझौता श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे हुए अनेक प्रतिवन्धों श्रीर तरकर व्यवस्थाओं को दूर करने के प्रशंसनीय प्रयक्ष हैं। यदि ये बाधाएँ दूर हो जाँय तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी स्वतन्त्रता श्रा जायगी श्रीर इससे विश्व का श्रार्थिक विकास श्रीषक सन्तुलित हो जायगा। इससे विदेशी विनिमय मुद्रा को किटनाई भी इल हो जायगी। यदि व्यापार की स्वतन्त्रता नहीं है तो अनेक देशों को विदेशी विनिमय मुद्रा की किटनाई का सामना करना पहता है। यद्यपि श्रमरीका, कनाडा श्रीर श्रन्य देशों ने श्रपने तरकर (श्रायात निर्यात कर) कुछ सीमा तक कम कर दिए हैं श्रीर इसके लिये

श्रनेक देशों ने तटकर घटाने के उद्देश्य से पारस्परिक न्यापार सममीते भी किये हैं जिनकी सन देशों ने पुष्टि नहीं की है नयोंकि (श्र) तटकर संरक्षण हटा देने से राष्ट्रीय अर्थ-न्यवस्था पर प्रतिकृत प्रभाव पहता है जो सम्बन्धित देश प्रायः सहन नहीं कर सकते हैं श्रीर (ब) हैवना चार्टर के पश्चात् भी परस्पर सन्देह श्रीर अविश्वास बना हुआ है।

स्तम्बर १६५० में इंगलैंड के टोरक्वे सम्मेलन (Torquay Conference) में जो कि तीसरा सम्मेलन था—प्रथम श्रीर द्वितीय सम्मेलन जेनेवा (१६४७) श्रीर श्रमेकी (Annecy) में हुये ये— भारतीय प्रतिनिधि ने बताया कि तटकर तथा श्रम्य सुविधाशों पर समझीता करते समय भारत तीन स्द्वान्तों से प्रभावित होता है, (१) सुविधायों ऐसी हो जो घरेलू श्रयं-व्यवस्था के हित में हों, (२) सुविधाशों का ऐसी वस्तुशों से सम्बन्ध न हो जो पहले से ही संरक्तित हैं या जिनको श्रगले वीन वर्षों में संरक्तिण दिया जानेवाला है श्रीर (३) मुविधाशों से सरकार की श्राय को भारी ज्ञति न पहुँचे !

टोरविषे में तटकर समसीते के फलस्करण भारत को १६४=-४६ के व्यापार सम्बन्धी श्रांकरों के श्राधार पर निर्यात पर प्रत्यक्त श्रीर परोज्ञ रूप में क्रमशः १८५ लाख श्रोर १५३ लाख रुपए का तटकर संरक्षण मिला। इसके बदले में भागत ने भी ८६ लाख श्रीर ३७७ लाख रुपये का क्रमशः प्रत्यक्त एवं परोज्ञ तटकर संरक्षण दिया। तटकर तथा व्यापार समझीता सम्मेलन में, जिसका सातवाँ श्रिधवेशन नवम्बर १६५२ में जेनेवा में हुआ था, भारत को बहुत कम तटकर संरक्षण दिया।

श्रनेकी, जनेवा श्रीर टोरक्वे में जिस समय वातचीत हो रही थी भारतीय प्रतिनिधि देश के भावी श्रीद्योगिक विकास की प्रगति का श्रनुमान न लगा सके। इसका परिणाम यह हुश्रा कि बहुत सी वस्तुश्रों के सम्बन्ध में जैसे कृषि में काम श्राने वाले ट्रक्टर, सेफटीरेजर ब्लेड, वायरलेस रिसीवर, कोलतार से बने रग, श्रीर मोटरों श्रीर टाचों में काम श्राने वाले विजली के बल्व इत्यादि के सम्बन्ध में तत्कालीन तटकर स्थिति को ही लागू मान लिया गया। कुछ ही दिनों में पिछले समक्तीते के श्रन्वर्गत प्रतिबन्धों से मुक्ति प्राप्त करने की श्रावश्यकता का श्रनुभव हुश्रा। करवरी १६५४ में सरकार ने तटकर तथा व्यापार समक्तीते सम्बन्धी श्राधकारियों से प्रार्थना की कि उन्हें श्राठ वस्तुश्रों के सम्बन्ध में समक्तीते के श्रनुसार जो प्रतिबन्ध लागू हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेने के लिये बातचीत करने का श्रिषकार प्रदान किया जाय। वे श्राठ वस्तुएँ निम्न थीं: मछली, श्रराब, दृधपेस्ट श्रीर पाउडर, लीयोकोन, तारकोल से बने रंग, फाउन्टेन पेन, शीरों के

दाने श्रीर नकली मोती, श्रीर सेफ्टीरेजर ब्लेड। सरकार को समसौते के प्रतिबन्धों से मुक्ति केवल शराब, तारकोल से बने रंग, शिशे के दाने तथा नकली मोती श्रीर सेफ्टीरेजर ब्लेड के सम्बन्ध में ही मिल पाई। इन चार में से तीन वस्तुश्रों पर १९५४ के मारतीय (तटकर द्वितीय बार संशोधित) ऐक्ट के श्रन्तर्गत श्रायात कर बढ़ा दिया गया है। मारतीय उद्योगों के उपयुक्त विकास के लिये जितनी छूट दी गई श्रपर्यात थी। इन वस्तुश्रों के सम्बन्ध में मिली छूट के बदले में भारत को भी कुछ वस्तुश्रों के लिये छूट देनी पड़ी।

तटकर तथा व्यापार समसौते के एक बहुत बढ़े दीप की जेनेवा में हुए नवें सम्मेलन में जो कि १६५५ में २८ अक्टूबर से १० मार्च तक हुआ था दूर किया गया। इस पुनर्परीचित सममौते के अनुसार उन देशों को जिनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है इस बात की अनुमति प्रदान की गई कि वे कुछ शतीं पर अपनी दी हुई छूटों को यदि ऐसा करना उनके आधिक विकास के लिए श्रावश्यक है तो वापस कर सकते हैं। दूसरा दोष जो मिटाया गया वह यह या कि पहले व्यापार की मात्रा पर नियंत्रण केवल मुगतान संतुलित सम्बन्धी काठ-नाइयों को दर करने के लिये किया जाता था, परन्तु अब पिछड़े हुये देश अपने त्रार्थिक विकास के लिये भी उस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। १६५५ के िखनवर में भारतीय संसद ने तटकर तथा व्यापार समझौते को स्वीकार कर लिया | इस सम्बन्ध में बातचीत के फल स्वरूप समझौते को मानने वाले लगभग २२ देशों ने ६० श्रन्य देशों से मई १९५६ में पारत्परिक व्यापार समझौते किये निसके अन्तर्गत २ अरव ५० करोड़ डालर के मूल्य का व्यापार आता है। अब समस्त संसार के कुल व्यापार का तीन चौथाई तटकर तथा व्यापार समसौते के अन्तर्गत आ गया है। यह सममीता वास्तव में व्यापार प्रतिबन्धों के घटाने तथा उसे अधिक स्वतंत्र बनाने में बहुत प्रमावशाली सिद्ध हुआ है।

"१६५७ के जनेवा सेसन में जी० ए० टी० टी० ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह निर्णय तीन श्रथना चार श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के एक पेनेल की स्थापना के सम्बन्ध में या निसका काम संसार के न्यापार की प्रकृतियों की जाँच करना, उसकी न्याख्या करना तथा विशेष रूप से मध्यवर्ती काल में संसार के न्यापार की सफलता की सम्मावनायें बतलाना था।" यह निर्णय श्रीद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों की श्रपेशा पिछड़े हुए देशों की निर्यात न्यापार विकास की गति के घीमी होने पर चिन्ता प्रकट करने का परिणास था।

श्रध्याय ४१

भारतीय चलन मुद्रा का इतिहास

मुगल थाल से भारत में छोने, चाँदी श्रोर तांने के छिक्के प्रयोग में श्राते ये। कीई भी ज्यापारी उछ काल में छोना चाँदो या ताना देकर टकसाल से छिक्के वास्तिवक ढलाई ज्यय के उपरान्त ५% मुद्रण लाभ देकर वनवा सकता था। इससे हुत्रा लाम निश्चित दर से ज्यापारी श्रीर सरकार के बीच वाट किया जाता था। मुगल कालीन भारत में चाँदी का रुपया हो प्रधान मूल्य का मान दशह था श्रीर कानून द्वारा श्रमीमित मात्रा में ग्राहय था। मुगल शासन ज्यवस्था ने कोई प्रयत्न सोने श्रीर चाँदी के बोच तथा चाँदी श्रीर ताँव के बीच विनिमय दर के निश्चित करने का नहीं किया गया उस जमाने में ताँवा सांकेतिक मुद्रा के रूप में श्राजकल की तरह काम में नहीं लाया जाता था। चाँदी श्रीर ताँवा का विनिमय दर बाजार की श्रवस्था पर निर्मर रहता था जिससे ज्यापार, मूल्यों, श्रीर सामान्य श्राधिक सम्बन्ध में बरावर परिवर्तन होते रहते थे। मुद्रा के मूल्य में निरन्तर परिवर्तन होते थे क्योंकि वरावर मूल्यवान धातुश्रों का श्रायात श्रीर नियांत होता रहता था श्रीर मुगल शासन मूल्य स्तर में स्थिरता स्थापित करने में श्रसमर्थ था।

जब मुगल राज्य का विश्वंश हुन्ना बहुत सी स्वतंत्र रियासतें कायम हो गई। प्रत्येक राज्य ने अपने निजी सिक्के चलाकर न्नपनी स्वतंत्रता का परिचय दिया। जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी का भारत में श्रागमन हुन्ना तो उसे यह अनुभ्यव हुन्ना कि वह न्नपना व्यापार स्वतंत्र सिक्कों के बाहुल्य के बीच कर नहीं सकती। इसलिये कम्पनी ने सोने श्रीर चाँदी के सिक्के स्वयं चालू किये। इन सिक्कों का निश्चित भार या श्रीर उनके बीच विनिमय दर कानून द्वारा निश्चित यी। व्यवहार में सोने श्रीर चाँदी के सिक्कों का एक साथ चलन सकल सिद्ध न हुन्ना श्रीर १८०६ में कम्पनी ने लन्डन एक प्रपत्न मेचा जिससे यह बताया गया या कि सोना श्रात मूल्य न या। इस्टइन्डिया कम्पनी ने यह श्रानुमव किया कि उस स्थित में चाँदी की एक धातुमान मुद्रा ही भारत के लिये श्रादर्श होगी। इसलिये चाँदी के स्वतंत्र मुद्रया के लिये टकसाल खोल दी गई। चाँदी के प्रमाणिक सिक्के में देने श्रुद्ध चाँदी रक्खी गई श्रीर उसका वास्तविक मूल्य श्रेकित मूल्य के बराबर रक्खा गया।

एक चार्त्विक रजत मुद्रा

प्रत्येक प्रेमं हेन्स को अनग-अलग मुद्रायें चलन में थीं जो कि अपनी ही सीमा में कान्नी प्राप्त थीं। इससे राज्यों के पारस्परिक ज्यापार में बहुत बाधा पड़ी। १८३३ में चार्टर एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार कान्नी और अधिशासी अधिकारियों का केन्द्रीकरण कर दिया गया। इसका देश की सुद्रा चलन पर बहुत हा अच्छा प्रमाव पड़ा और स्थानीय सुद्राओं का स्थान एक केन्द्रीय सुद्रा ने करेन्स। एक्ट १८३५ के अनुसार ले लिया। इस नियम के अन्तर्गत: (क) टकसालें चाँदो को स्वतंत्र दलाई के लिये खोल दो गई। (ख) समस्त अंग्रेजी मारत में कपया (देने शुद्ध चाँदो वाला) प्रमाणिक सुद्रा घोषित कर दिया गया। (ग) कपये का वास्तविक मूल्य उसके श्रेकित मूल्य के बरायर रखा गया, (ध) स्वर्ण सुद्रा कान्नी ग्राह्य नहीं मानी गई परन्तु (ङ) स्वर्ण के स्वतंत्र मुद्रण की श्राज्ञा दें दी गई श्रोर सोने की मुहरे ५,१०,१५ और ३० क्यये मूल्य की दाली जा सकती थी।

स्वर्ण के स्वतंत्र मुद्रण की आशा सम्भवतः इसलिये दे दो गई थी कि सरकार की सोने के मुद्रणलाम का घाटा न उठाना पहें। परन्त क्योंकि स्वर्ण यात्र कानूनी प्राप्त नहीं था इंग्रिलिये स्वर्ण से प्राप्त मुद्रण लाभ धीरे धारे घटने लगा। इस लाभ को न जाने देने के लिये सरकार ने स्वर्ष मुद्रा को दलाई को प्रोत्साहित करने का प्रयन्न श्रारम्भ किया। इस सम्बन्ध ने सर्वप्रथम कार्य मुद्रण लाभ को २% से घटाकर १%, १८३७ में किया गया। परन्तु इतने से आवश्यक प्रोत्छाइन न मिल छका इसलिये १८४१ में में यह घोपणा कर दो गई कि सरकारी खजानों में १ स्वर्ण मोहर १५ चाँदी के करयों के बदते में न्स्वीकार कर ली जायगी इस घोषणा से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं श्राया। श्रास्ट्रेलिया श्रीर कैलीकोर्निया में सोने की नई नई स्तानों का पता लग जाने से भारत की मुदास्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्वर्ण जो अभी तक अवमूल्यत था (१ सोने की मुहर के बदले १५ रुपया मिलता था) श्रव श्रिवमूल्यत हो गया श्रीर सरकार को इससे बहुत घाटा हुआ श्रीर १८३५ के फरेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जो भगतान करने थे उनके कारण भी हानि उठानी पड़ी। स्पर्ण यदापि कानूनी माह्य नहीं या परन्तु घोपणा के अनुसार सरकार स्वीकार करने के लिये वाध्य थी। स्वर्ण के बाहुल्य तथा उसके चादी में बदले जाने की बढ़ती हुई माग के कारण कठिनाई में पह जाने से सरकार ने १८४१ की घोषणा को १८५८ में रह करने की घोषणा कर दी।

मारत में कृषि, वन, खनिज तथा श्रम श्रादि साधनों का बाहुल्य या परन्तु

उसका इन साधनों के अनुकूल श्रीशोगिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास नहीं हुआ या वयोंकि देश में राजनैतिक स्थिरता, जनता में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति की बहुत श्रीधक कभी भी तथा देश का श्राधिक संगठन नितान्त, श्रव्यवस्थित था। रेट्नी शतान्दी में जब कि भारत की श्राधिक स्थिति विगर रही थी इंगलैपर श्रीयोगिक क्रान्ति के कारण बड़ी तीव गति से श्रागे बढ़ रहा था श्रीर इस श्रोर उसे श्राशातीति स्कलता भी इसलिये मिल रही थी कि न्यापार के कारण देश में श्रिपार सम्पत्ति एकत्रित थी, यातायात तथा दिका प्रणाली उत्तरशील थी, श्रीमें जो लिम उठाने का उत्साह था श्रीर सरकार की नीति सहायक थी।

१८५० श्रीर १६१४ की समयावधि में भारतीय श्रर्य व्यवस्था में श्रानेकों परिवर्तन हुये जिसके कारण देश की मुद्राचलन पदित में परिवर्तन करना श्रावश्यक हो गया। देश में हुये अनेको आधिक परिवर्तनों में से पहिला वो यही या कि देश प्रचलित श्राधिक वस्तु व्यवस्था का स्थान द्रव्य व्यवस्था ले रही थी। पहिले जागीरदार लोग श्रपने श्रमामियों से श्रज तथा श्रन्य वस्तुयें प्राप्त करते ये। परन्तु श्रव नकद देने की श्रेग्रेजी पदित सरकार द्वारा प्रचलित कर दी गई थी। ज्यों ज्यों श्रंग्रेजों के श्रिधिकार में श्रिधिकधिक राज्य श्राते गये त्यों त्यों भुगतान द्रव्य में बढ़ता गया । दूखरे भारत की सरकार की प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार को 'होम चार्ज' का व्यय भुगतान करना पढ़ता या श्रीर इसके लिये नकद की आवश्यकता पड़ती थी। इन कारणों से यह आवश्यक हो गया कि लगान नकद वस्ल किया जाया। श्रन्त में इस काल में भारत के विदेशी व्यापार को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला जिसके कारण भी नकद द्रव्य की मात्रा बढ़ गई। यद्यपि चलन मुद्रा की माँग बहुत बढ़ी हुई थी परन्तु उसकी पूर्ति माँग के अनु-क्ल नहीं हो सकी क्योंकि विभिन्न देशों की मुद्रा की आवश्यकता के बराबर चाँदी की उत्पत्ति नहीं थी। भारत में मुद्रा का इस प्रकार को आभाव या वह इस बात से श्रीर भी बढ़ गया कि देश में साख मुद्रा थी ही नहीं। इस कठिनाई को पार करने के लिये सरकार ने व्याज कमाने वाले ट्रेजरी नोट प्रचलित किये। परन्त्र ये सफल न हुये क्योंकि पहिले तो उनका मूल्य बहुत श्रधिक या श्रीर दूसरे वे जिस कार्यालय से निर्गमित किये गये ये उसी में ही केवल स्वीकार किये जा सकते ये (कलकत्ता, बमबई और मदास)।

स्वर्ण विनिमय मान

क्योंकि चौंदी का एक घातुमान देश की श्रावश्यकता के श्रनुसार श्रपर्याप्त या इसलिये सरकार के समज्ज दो उपाय इस कठिनाई को पार करने के लिये थे

एक स्वर्ण को चलन में ले आना और दूसरे देश में पत्र मुद्रा का प्रयोग आरम्भ कर देना । सरकार ने स्वर्ण को चलन में लाने तक अनेकी प्रणालियों पर विचार किया परन्तु वे सब श्रनुपयुक्त प्रतीत हुये क्योंकि द्विचातुमान की स्थिति में स्वर्ण श्रीर चौदी के मूल्यों में श्रन्तर श्राने पर दोनों प्रकार की मुद्राश्रों के बीच निश्चित विनियय अनुपात में आवश्यक परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता । ऐसे परिवर्तन सगम नहीं होते और उनके करने में बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। स्वर्ण को रजत मुद्रा का सहायक मुद्रा के रूप में प्रचलित तो किया नहीं जा सकता या क्योंकि सारे लेन देन की बातें तो चाँदी के मूल्य के आधार पर की जा चुकी थी श्रीर स्वर्ण का अनायास ही प्रयोग आरम्म कर देने में किसी न किसी पार्टी के लिये हानिकारक श्रवस्य सिद्ध होता। इन वातों को विचाराधीन रखते हुये सरकार ने पत्र मुद्रा के निकासी की बात चाँदी की मुद्रा के सहायतार्थं निश्चित की। परन्तु पत्र मुद्रा की निकासी से भी कोई विशेष मुद्रास्थिति में लाम नहीं हुआ श्रीर स्वर्ण मुद्रा की माँग जारी रही श्रीर श्रन्त में वरकार को श्रद्ध में यह विज्ञात जारी की (i) पीएड और श्रर्घ पीएड जिनकी श्रास्ट्रेलिया और इगलैएड के टकराल से निकासी होती थी उनको मारत श्रीर श्रन्य ब्रिटिश श्राचीनस्य राज्यों में १० ६० ग्रीर ५ ६० पर कमश: स्वीकार किया जायगा श्रीर (ii) श्रीर यदि कोई व्यक्ति पीएड श्रीर श्रवंपीएड को सरकार से श्रपने पालने के सम्बन्ध में स्वीकार करेगा उनकी भी १० ६० श्रीर ५ ६० की दर पर सुगतान कर दिया जायगा। परन्त क्योंकि पौरह का विनिमय दर १० ६० श्रीर ५ ६० से श्राधक या इसलिये इस विश्वित का कोई प्रभाव न पड़ा श्रीर मुद्रा की कमी बनी रही। सरकार ने इसलिये एक आयोग की नियुक्ति की ताकि वह इस मामले की जाँच करें।

मेन्सफील्ड आयोग १८६६—इस आयोग ने देश की मुद्रा की माँग की पूर्ति करने के उपायों पर विचार किया और सिफारिश की कि (i) १५ ६०, १० ६० और ५ ६० के मुल्य के सोने के सिक्कों की निकासी की जाय (ii) चलन में सोने चाँदी और पत्र मुद्रा रक्खी जाय और (iii) सरकार सर्वत्र स्वीकार किये जाने वाले नोटों के अचलित करने की सम्भावना पर विचार करें। सरकार ने मेन्सफील्ड आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। केवल इतना ही किया कि पीण्ड की विनिमय दर १० ६० द आना कर दी। परन्तु यह सोने के मारत में प्रवाहित होने के लिये प्रयाप्त कारण सिद्ध न हुआ और मुद्रा की किटनाहर्यों ज्यों कि त्यों बनी रही।

१८७३ तक रुपये का विदेशी मूल्य लगभग १ शि १०३ पेन्स पर स्थिर

वना रहा परन्तु १८७३ के पश्चात् त्रिनिमय मूल्य में श्रनायास संसार के मुख्य देशां द्वारा चाँदी का मुद्रा के लिये प्रयोग छोड़ देने के कारण तथा सोने की त्रलना में चाँदी की उत्पत्ति बढ़ जाने के कारण बहुत उथल पुथल हुई। परन्तु इंगलैगड के स्वर्णमान पर रहते हुये भी भारत रजत-मान पर स्थिर रहा जिसका परिणाम यह हुश्रा कि भारत को चाँदी श्रयता सोने या दोनों घातुश्रों के मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण श्रपनी श्राधिक स्थिति में बहुत श्रनावश्यक परिवर्तन श्रनुभव करने पड़े। १८७३ के पश्चात् सोने की इकाई में चाँदी के मूल्य के गिरने के कारण सरकार की वित्त ज्यवस्था पर बहुत श्रिषक भार पढ़ा। ऐसी श्रवस्था में लोगों की यही भावना थी कि देश में स्थायी मुद्रामान स्थापित होना चाहिये श्रीर इसके लिये एक कमेटी नियुक्त की गई।

हरशैल कमेटी १८६२—इस कमेटी ने सिकारिश की कि (i) रुपया भारत में पूर्ण रूप से कानूनी प्राह्म सुद्रा रहनी चाहिये (ii) सोने ख्रीर चाँदी के स्वतंत्र सुद्रण के लिये टकसाल बन्द की जानी चाहिये, श्रीर (iii) सरकार को यह स्वतंत्रता रहनी चाहिये कि यदि जनता को श्रावश्यकता है तो १ शि॰ ४ पेन्स प्रति रुपये की दर से सरकारी खनानों से स्वर्ण लेकर रुपये सुद्रण करें। १८६३ का एक्ट हरशैल कमेटी की सिकारिशों को सम्मिलित करते हुये पास किया गया परन्तु १८६३ के पश्चात् सरकार की नीति भारत में मुद्रामान के सम्बन्ध में श्रस्थायी श्रीर श्रानिश्चत ही रही। इसका व्यापारियों पर बुरा प्रभाव पड़ा श्रीर टकसालों के बन्द कर देने से मुद्रा श्रमाव का संकट वट गया। चाँदी के मूल्य में कमी होने से सपये के विनिमय दर में गड़वड़ी पड़ गयी।

इसके परिणाम में १८६८ में फाउलर कमेटी की नियुक्ति की गई श्रीर उसने यह सिफारिश की कि (i) श्रंग्रेजी पीयड का फिर से भारत के चलन पद्धित में स्पान दिया जाय श्रीर उसे फानूनी ग्राह्य कर दिया जाय; (ii) मारतीय टकसालों को सोने का श्रपरिमत सुद्रण करने के लिये खोल दिया जाय श्रीर उन पर वे ही शर्ते लागू की बाय जो कि रायल िमन्ट की श्रास्ट्रेलिया स्थित शाखाश्रों पर लागू किये गये हैं, (iii) रुपये की विनिमय दर १ शि० ४ पेन्स पर स्थिर कर दी जाय, (iv) रुपये को श्रपरिमित कानूनी ग्राहय मुद्रा रक्खा जाय, (v) सरकार सोने के बदले में रुपया दे श्रवश्य पर नये रुपयों की दलाई तब तक न की जाय जब तक कि सोने का श्रंश चलन पद्धित में जनता की श्रावश्यकता से श्रिषक न समक्ता जाय श्रीर (vi) सरकार निर्यात के लिये सोना दे यदि रुपये के विनिमय मूल्य की प्रवृत्ति स्वर्ण विन्दु के नीचे गिरने की लिखत होने लगे। इस कमेटी के सिफारिशों के श्राधार पर १८६६ का एक्ट पास कर दिया गया। श्रीर उसके

श्रंतर्गत (क) पीएड श्रीर श्रर्धपीन्ड समस्त श्रंभेजी भारत में कानूनी माहण कर दिये गये, (ख) सोने के मुद्रण के लिये एक टकसाल खोली गई, श्रीर (ग) रुपये के मुद्रण लाम को श्रलग रखने के दृष्टिकीण से एक स्वर्ण कीय की स्थापना की गई।

इस प्रकार मारत में मुद्रामान धीरे धीरे श्रपने श्रादर्श स्वर्णमान से हटता गया श्रीर ऐसा रूप धारण करता गया कि उसे हम स्टर्लिंग विनिमय मान कह सकते हैं परन्तु उसे स्वर्ण विनिमय मान का नाम प्रदान किया गया है (पंगु-मान भी कहा गया है)। १९०२ में स्वर्ण मुद्रण टकसाल स्थापित करने की योजना को खत्म कर दिया गया श्रीर १६०४ में स्वर्ण कोप को लन्डन मेज दिया गया। वहाँ इसे स्टलिंग विम्यृरिटीज में रक्ला गया श्रीर इससे श्रलग एक पत्र मुद्रा कीव की स्थापना की गई जो श्रांशिक रूप में भारत में तथा इगलैन्ड में रक्खा गया। इससे यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-विनिमय मान की स्थापना वैज्ञानिक श्रीर नियोजित ढंग पर नहीं हुई श्रीर जो हुआ वह भारत के मुद्रा-पान में श्रनेकानेक परिवर्तनों का परियास है। इस प्रयाली का कार्य काउन्सिल बिलो तथा रिवर्स काउन्सिल विलों के क्रम विकय पर निर्मर था। १८६३ के पहिले काउन्सिल विला केवल 'घरेलू व्यय' (Home charges) का भुगतान करने के लिये वेचे जाते ये परन्तु १८६३ के बाद उनकी विकी सामान्य व्यापारिक श्रावश्यकता के लिये भी होने लगी। भारतीय माल का श्रायात करने वाला श्रंग्रेज सेक्रेटरी श्राफ स्टेट को पहिले पीएड में भुगतान करता था तब सेकेटरी एक उसके बराबर के मूल्य का काउन्तिल ड्राफ्ट देता या श्रीर मारतीय निर्यात करने वाले को मारत में स्थित (Paper currency reserve) पत्र मुद्रा कोप के दूबरे श्रंश से जिसे स्वर्ण मान कीय का रुपये वाली शाखा भी कहा जाता था भुगतान कर दिया जाता था। १६०४ में सेकेटरी आफ स्टेट ने यह घोषणा की कि काउन्तिल विल अपरिमितं मात्रा में १ शि० ४% पेन्स प्रति रुपये की दर से विक्रय किये जायगे। इस प्रकार रुपये की विनिमय पर इस स्तर से आगे बढ़ने न दी गई। तात्कालिक भुगतान के लिये टेलीग्राफिक फार्म में भी विल प्राप्त ये श्रीर इस प्रकार के स्यतान को टेली-ग्राफिक ट्रान्सफर कहते थे। रिवर्स काउन्सिल एक ऐसी हुन्डिया थी जिन्हें भारत सरकार सेक्षेटरी आफ स्टेट के नाम लिखती थी और वे १ शि० ३३९ पेन्स प्रति रुपया की दर से बेची जाती थी।

चेम्बर तोन आयोग १६१३—जोजेफ आस्टिन चेम्बरलेन की श्रध्यज्ञता में इस श्रायोग की नियुक्ति इसलिये की गई कि वह विभिन्न निधियों तथा श्रवरोषों (reserves and balances) रखने के स्थान, विनिमय प्रणाली तथा प्रयोगों के सम्बन्ध में बाँच करे श्रीर बतायेकि वर्तमान दंग भारत के हित में लाभकारी है श्रथना नहीं । श्रायोग के मत में स्वर्ण निनमय मान भारत के लिये सबसे श्रिषक उपयुक्त था । उनकी यह बारणा थी कि देश के श्रन्दर स्वर्ण के चलन को प्रोत्साहन देना भारत के लिये हितकर नहीं था श्रीर मारत की जनता न तो स्वर्ण मुद्रा चाहती ही थी श्रीर न उसकी श्रावश्यकता ही थी। भारत में स्वर्ण के मुद्रण के लिये टकसाल की श्रावश्यकता नहीं थी परन्तु यदि भावुकता उसके पन्न में थी श्रीर यदि सरकार उसका व्यय उठाने के लिये तत्यर थी तो पीएड श्रीर श्रधीएड के मुद्रण के लिये एक टकसाल खोली जा सकती है। यदि टकसाल खोलना सम्भव न हो सके तो सरकार को श्रयनी विज्ञित को जिसे १६०६ में नापस ले लिया गया था पुनः लागू कर देना चाहिये ताकि बम्बई की टकसाल पत्र-मुद्रा तथा रुपये के बदले में स्वर्ण स्वीकार करने लगे।

जहाँ तक स्वर्ण-मान निधि का सम्बन्ध या उसके लिये कोई श्रिषकतम मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती पर उसका श्रिषकांश स्वर्ण में ही होना चाहिये। उनके मतानुसार इस निधि को रखने का सबसे उपयुक्त स्थान लन्डन या। उन्होंने यह सिफारिश की कि इस निधि की रूपये वाली शाखा को खत्म कर दिया जाय। उन्होंने सिफारिश की कि पत्र-मुद्रा पद्धित को प्रतिभूतियों (securyties) के श्राधार पर श्रिषक पत्र मुद्रा की निकासी कर के बना देना चाहिये। चलन पद्धित के एक श्रंश के रूप में पत्र-मुद्रा का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिये श्रीर ५०० रु के नोटों को देश भर में चालू कर देना चाहिये। श्रायोग ने यह भी सिफारिश की कि जब श्रावश्यकता पढ़े भारत सरकार सेक्रेटरी श्राफ स्टेट के नाम हुख्डियों १ शि० १३६ पे० प्रति रुपया की दर से विकय करे। फरवरी १६१४ में इस श्रायोग की रिपोर्ट छुपी श्रीर जुलाई १६१४ में युद्ध छिड़ गया। इसलिये श्रायोग की बहुत सी सिफारिशों को सरकार कार्यान्वित नहीं कर सकी, परन्तु स्वर्ण मान कोष की रजत शाखा को हटा दिया। श्रीर युद्ध छिड़ जाने के कारण रिवर्स काउन्सिल विलों की माँग बढ़ जाने से उनको विकय करने के लिये बड़ी तत्यरता से तैयार हो गयी।

भारत सरकार की त्रुटिपूर्ण मुद्राचलन नीति प्रथम महासमर काल में तथा उत्तर महासमर काल में १९१४-१९३६ उद्योग तथा व्यापार के लिये बहुत बड़े भार का कारण बन गयी। चेम्बर लेन श्रायोग ने जैसा कि इम ऊपर बता चुके हैं स्वर्ण विनिमय मान के प्रयोग को सुधारने की सिफारिश की थी परन्तु वे कार्यान्वित न हो सकी क्योंकि श्रायोग की रिपोर्ट फरवरी १९१४ में छपी श्रीर प्रथम

महासमर जुलाई १६१४ में श्रारम्भ हो चुका या। स्वर्ण विनिमय मान लो १६१७ तक चालू रहा संतोषप्रद ढंग से कार्य न कर सका। संसार की चाँदी की उत्पत्ति में कमी आ जाने से और मुद्रा के लिये उसकी माँग बढ़ जाने से चाँदी का मूल्य २७ रे पेन्स प्रति आउन्स १६१४ में हो गया, १६१७ के अगस्त में ४३ पेन्स हुआ श्रीर उसी वर्ष सितम्बर में ५५ पेन्स तक बह गया। "४३ पेम्स प्रति श्राउन्स मूल्य जरा विचारणीय है क्योंकि इस मूल्य पर रुपये का विनिमय मूल्य उसके पाटमान के बराबर हो गया था। यदि मूल्य ४३ पेन्स प्रति आउन्स से कार बढ़ता तो काये का विनिमय मूल्य १ शि० ४ पेन्स पर स्थिर नहीं रक्खा जा सकता था रुपये का मूल्य स्वर्ण में इससे कहीं ऋषिक होता और यदि सरकार १ शि०४ पेन्स से ऋषिक प्रत्येक क्पये के लिये न देती तो क्पया या तो गला लिया जाता या निर्यात कर दिया जाता । ४३ पेन्स के उपरान्त चाँदी के मूल्य में प्रत्येक वृद्धि पर सरकार की विनिमय दर उसी के अनुसार बढ़ानी पड़ती। स्वर्ण विनिमय मान निसका संतोष जनक रीति से काम में आना काउन्सिल ड्राफ्ट की अपरिमित विक्री पर और रुपये के साकितिक मुद्रा बने रहने पर निर्भर करता या नष्ट भ्रष्ट हो गया। रुपये का विनिमय मूल्य भ्रव उसके वास्तविक मूल्य के साथ साथ उसी तरह बढ़ने लगा जैसा कि १८७३-१८६३ में बहा था।" इसका परिखाम यह हुआ कि रुपये की विनिमय दर बहुकर अगस्त १९१७ में १ शि० ५ पे०, अप्रैल १९१८ में १ शि० ६ पे॰ मई १६१६ में १ शि॰ = पे॰ अगस्त १६१६ में १ शि॰ १० पे॰, सिम्बर १६-१६ में २ शि० श्रीर दिसम्बर १६१९ में २ शि०४ पे० बढ़कर हो गयी। सरकार को १६१७ में लाचार होकर स्वर्ण विनिमय मान का त्याग करना पड़ा और निरन्तर बढ़ने वाली रुपये की विनिमय दर ने देश के व्यापार श्रीर उद्योग की महान घक्का पहुँचाया तया भारतीय चलन का श्राघार निधि के घात्विक श्रंश को जो ७६% १६१४ में थी घटाकर १६१६ में ५०% कर दिया।

वैधिन्गटन स्मिथ कमेटी १९१९—विकिगटन कमेटी ने जिसकी नियुक्ति भारत की चलन पद्धित और विनिमय युद्ध के प्रमानों की जाँच करने के लिये की गई थी निम्न सिकारिशें की —(१) समय का विनिमय मूल्य २ शि० (स्वर्ण) पर निश्चित कर दिया जाय; (२) रुपये को अपरिमित कानूनी शाह्य मुद्रा बनाये रखना चाहिये परन्तु उसके साथ ही साथ पींड को भी १० रु० प्रति पींड की दर से अपरिमित कानूनी शाह्य मुद्रा वोषित कर देना चाहिये यद्यपि सरकार पींड के बदले में रुग्या देने के लिये वाध्य न होगी, (३) देश के यह अधिक हित में न होगा कि स्थर्ण मुद्रा का प्रयोग प्रोत्सा-हित किया जाय फिर भी एक स्वर्ण टक्षवाल की स्थापना वम्बई में कर देनी

चाहिये ग्रीर स्वर्ण मुद्रा को थोगी-धोड़ी मात्रा में निकासी करनी चाहिये; (४) रुपये के मुद्रण से प्राप्त लाभ को स्वर्ण मान निधि में रखते लाना चाहिये जिसका श्राधा मारत में रखला लाना चाहिये, (५) पद मुद्रा का घात्विक श्राधार कम से कम कुल पत्र मुद्रा चलन के ४०% नियत कर देना चाहिये श्रीर श्रधिकतम विश्वासाधित निकासी को १२० करोड़ रुपयों पर निश्चित कर देना चाहिये, श्रीर (६) चाँदी के स्वतंत्र रूप से श्रायात तथा निर्यात को श्रनुमित दे दी जानी चाहिये।

थी डी॰ एम॰ दयाल ने श्रपने श्रस्वीकृति सूचक प्रपन्न में रुपये के विनि॰ मय मूल्य को २ शि॰ (ध्वर्ग) पर निश्चित करने का विरोध किया क्योंकि उनके मत से यह भारत के व्यापार तथा उद्योग के लिये हानिकारक थी छीर उसके स्यान पर उन्होंने यह खिपारिश की कि पुरानी दर १ शि० ४ पेन्स वाली लागू की जानी चाहिए। भारत सरकार ने फ्रांघक संख्या से श्रनमित प्राप्त रिपोर्ट को हुमांग्यवश स्वीकार कर लिया श्रीर रुपये की विनिमय दर २ शि॰ पर नियत कर दी श्रीर इसी दर पर रिवर्स काउन्सिल वेचने का निश्चिय किया। इस दर पर पींड की माँग रुपये के बदले बहुत श्रधिक बद गयी श्रीर उसे कायम रखने के श्रपने निष्फल प्रयत्न में भारतीय खजाने को ४० करोड़ रुपयों का घाटा हुन्ना भ्रीर इसमें श्रतिरिक्त श्रर्य व्यवस्था भी संकट में पड़ी। "पहिले तो खरकार ने २ शि० (स्वर्य) की दर को कायम रखना चाहा बाद में १६२० की २४ जून से २८ सितम्बर तक २ शि॰ (पीन्ड) की दर कायम रखने का प्रयत्न किया जब कि रुपये का बाजार मूल्य नीचे गिर चुका था।" श्रन्त में रुपये की विनिमय दर को २ शि० (स्वर्ण) पर कायम रखने के सारे प्रयत्न त्याग दिये गये श्रीर सरकार ने श्रपने प्रयत्न इस वातः पर सीमित कर दिया कि भारत में मुद्रा का संकुचन किया जाय ताकि श्रान्तरिक श्रीर वाह्य मूल्यों में कुछ समानता श्रा सके। परिगाम स्वरूप रुपये का विनिमय मूल्य गिरा "ग्रीर विनिमय दर जो कि दिसम्बर १६५० में १ शि० ५ पे० तक गिर जुकी थी मार्च १६२१ में श्रीर श्रधिक गिर कर १ शि० २५ पे० (श्रर्थात् १ शि० स्वर्ण से कम) हो गयी। १६२२ से व्यापार कर, संतुलन भारत के पद्म में लिबत्र,होने लगा श्रीर रुपये का पीन्ड में मूल्य बढ़ने लगा श्रीर घीरे-घीरे युद्ध से पूर्व का स्तर श्रर्थात् १ शि० ४ पेन्स (पौन्ड में) जनवरी १६२३ में हो गया। श्रमद्भर १६२४ में श्रीर श्रिषिक बढ़ा श्रीर १ शि० ६ पे० (श्रर्थात् १ शि० ४ पे वस्त्री) हो गया और सरकार का प्रयत्न इसकी वृद्धि को इस दर के आगे बढ़ने से रोकने की दिशा में निर्देशित हुआ। " यह घोर निष्क्रियता की भौति १६२५ तक जब कि इक्कलैन्ड स्वर्ण मान पर आ गया चलती रही।

हिलटन यंग कमीशन १९४४ :-- इस भ्रायोग ने भारत के लिये स्वर्ण पाट मान की सिफारिश की । जिसकी मुख्य विशेषतार्थे निम्न थी ---(i) मुद्रा श्रिधकारियों के लिये यह श्रिनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि वे स्वर्ण का क्रय विकय एक निश्चित पद पर श्रीर कम से कम ४०० श्राउन्स (१०६५ तोला) की इकाइयों में करे। किस कार्य के लिये स्वर्ण की ग्रावश्यकता है इस बात पर कोई प्रतिबन्ध न हो परन्तु स्वर्ण के विकयं के सम्बन्ध में ऐसी शर्ते होनी चाहिये कि सामान्यतः मुद्रा श्रिधकारियों को मुद्रा के भी अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं के लिये स्वर्ण देने की आवश्यकता न पड़े: पीन्ड श्रीर (ii) श्रर्धपीन्ड कानूनी प्राह्म बने रहे परन्तु रुपया पूर्ण रूप से कानूनी ब्राह्म रहे; (iii) घरकारी ऐविंग सार्टिक केट निर्गमित किये जाँय ताकि श्राम जनता की समक्त में यह चात श्रा जाय कि स्वर्ण मूल्य का मानदराह हो स्त्रीर स्वर्ग स्रीर रुपया परस्पर परिवर्तनीय है। लोग इन सर्टिफिकेटों को खरीद कर श्रपनी बचत का विनियोग कर सकते हैं। ३ श्रधवा ५ वर्ष पश्चात वे श्रपना मूल धन मय ब्याज के रुपयों, अथवा स्वर्ण के रूप में अपनी इच्छानुक्ल प्राप्त कर एकते हैं; (iv) वर्तमान पत्र-मद्रा रुपयों में परिवर्तनीय रहे परन्तु अब जो नये नोटों की निकासी होगी वे कानूनी तौर पर रुपयों में परिवर्तित न किये जायाँ। पत्र मुद्रा की रुपयों में परि-वर्तित करने की सुविधा बराबर दी जाय; (४) एक रुपये के नोटों की जो कि पूर्या-तया कानूनी प्राध्य होंगे पर कानूनी तौर पर रुपये में परिवर्तित न किये जायंगे निकासी की जाय: श्रीर (vi) स्वर्णमान निधि तथा पत्र-मुद्रा निधि एक साथ मिला दिये जायें। श्रायोग ने िक्फारिस की कि रुपये की विनियोग दर १ शि ६ पेन्स (स्वर्ण) पर नियत कर दी जाय जिससे रुपये का मूल्य स्वर्ण की सात्रा में दाप्रथम १२ ग्रेन शुद्ध सोने के बराबर हो जायगा । वर परवीत्तमदास ठाकुरदास ने श्रपने श्रस्वीकृति सूचक प्रपत्र में यह सुमाव दिया कि रुपये की विनियम पर १ शि० ४ पे० पर नियत की जानी चाहिये न कि १ शि० ६ पे० पर जैसा कि श्रायोग ने सिफारिस की है।

सरकार ने आयोग की सिफारिसों को स्वीकार कर लिया और १६२७ के करेन्सी एक्ट में वे सब सिम्मिलित कर लिये गये जिसके अनुसार कृपये की विनिमय दर १ शि० ६ पे० पर नियत हो गई। इसके लिये सरकार को कानूनी तीर पर इस बात के लिये बाध्य किया गया कि (1) २१ ६० ३ आ. १० पा० प्रति तीला की दर से चालीस तोले बजन की (१५ आउन्स) सोने की ईटे सरीदे और (11) बम्बई में सुगतान करने के लिये शुद्ध सोना अथवा जन्दन में

मुगतान करने के लिये पीन्ड जो १०६५ तोला (४०० श्रीन्छ) से कम मात्रा में न हो वेचे। मुद्रा नियंत्रक को इस बात की श्रानुमति होगी कि वह चाहे सोना या पीन्ड वेचे। एक्ट ने पीन्ड श्रीर श्रर्घगीन्ड को चलन पद्धति से विहण्हत कर दिया परन्तु सरकार को इस बात के लिये बाह्य किया कि मुद्रा कार्यालयों से तथा खजानों में उनको उनके पाट मान पर स्वीकार करे।

पौएड विनिमय-मान

१६२७ के करेन्सी एकट ने स्वर्ण पाटमान की स्थापना वास्तव में नहीं की जैसा कि हिल्टनयँग आयोग की सिफारिश यी वरन् यथार्थ ये पौगढ विनिमय-मान की स्थापना की थी। २१ सितम्बर १६३१ तक जब कि इंगलैएड ने स्वर्ष विनिमय मान का परित्याग किया पौरह स्वर्ण में परिवर्तनीय या इसलिये इस काल में यह उसे स्वर्ण विनिमय मान भी कह सकते हैं। इस प्रकार श्रायोग की विफारिश का वास्तविक परिणाम स्वर्ण विनिमय मान की स्पापना की। जिसकी उसने कट स्रालोचना की थी। इंगलैगड के स्वर्ण मान के परित्याग कर देने के पश्चात् भारत पीएड विनिमय मान पर था श्रीर सरकार ने रुपये के विनिमय मूल्य का राशि ६ पेन्स (पीयड) पर स्थिर रखने का प्रयस्न किया था। श्रायीग की िफारिश के अनुसार सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का वहा ही मयंकर परिगाम मारतीय श्रार्थिक न्यवस्था को उठाना पड़ा (i) क्पये का श्रिधमूल्यन चगाया, १२३% हो गया या जिससे भारतीय निर्यात करने वालों को घाटा उठाना पहा श्रीर उसका परिणाम यह हुआ कि निर्यात घट गया। (ii) इस काल में बहुत बड़ी मात्रा में सोने का मारत से निर्यात हुआ। इसका कारए यह था कि सोने का मूल्य रुपयों की इकाइयों में बढ़ गया था क्योंकि पींड का मूल्य स्वर्णं की मात्रा घट गया था त्रीर क्षये का विनिमय मूल्य पींड की इकाइयों में स्पिर रक्ला गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना ही अधिक पींड प्रत्येक वोला सोने के लिये दिया जाता उत्तने ही अधिक रुपये उसके बद्दे में प्राप्त इोते क्योंकि रूपये श्रौर पींड का विनिमय दर स्थिर रक्खा गया था। २१ वितम्बर १६३१ को इंगलैयड के स्वर्ण-मान में परित्याग कर देने के पश्चात् तथा रूपये के विनिसय दर के १ शि॰ ६ पेन्स पर स्थिर कर देने के पश्चात् सोने का मूल्य २१ रु प्रति तोला से २५ रु प्रति तोला हो गया और १९३१ का दिसम्बर में ३० ६० प्रति तीला के श्रंदर ही मूल्य पहुँच गया था। सरकार के श्रिककारियों ने उस समय यह बताया कि सोने के निर्यात के कारण घरेलू न्यय का भुगतान सगतान करने में तथा सुगतान संतुलन को देश के पन्न में रखने में बड़ी सहायता

मिली, परन्तु जनता ने सोने के निर्यात की आलोचना की क्योंकि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था इरीण होती थी। इस प्रकार का किठनाई में किये हुये सोने के निर्यात से यह प्रकट होता था कि देशवासियों की आर्थिक स्थिति बिगइ रही थी और वे अपने पास के सोने को अपनी जीविका चलाने के लिये वेच रहे थे। यदि सरकार ने यह सोना खरीद लिया होता तो उसका प्रयोग भविष्य में मुद्रा के आधार के लिये काम में ला सकती थी; और (iii) १६२७ में एक्ट ने दोहरी निषियों की स्थापना की और मुद्राचलन को साख नियंत्रण से बिलग कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप देश में ऐसे समय में जब कि अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती थी मुद्रा का अभाव होता था और जब मुद्रा की आवश्यकता कम होती थी ता मुद्रा का बाहुल्य होता था। १६३५ के पश्चात् ही जब कि आयोग की सेन्ट्रल बैंक के स्थापना की सिकारिश कलवती हुई और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई मारतीय मुद्रा की सोच हीनता मिट पायी और व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकता के अनुसार चलन में मुद्रा की मात्रा नियोजित की जा सकी।

रिजर्न वैंक स्नाफ इंडिया एक्ट १६३४ के अनुसार वैंक के लिये यह . स्रानिवार्य कर दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति से तुरन्त लन्दन में सुगतान करने के लिये १ शि० ५६% पेन्स कम से कम और १ शि० ६३ पेन्स अधिक से श्रिधिक प्रति रुपया की दर से, कम से कम १०००० पौगड की मात्रा में खरीदें श्रीर बेंचे। ब्रिटिश सरकार ने इस सुविधा का लाम मारत में युद्ध सम्बन्धी न्यय की व्यवस्था करने में उठाया श्रीर रिजर्व बैंक को पीएड दे कर उसके बदले में रुपये लिये। इसका परिणाम यह हुआ कि लन्दन में बहुत सा पीएड भारत के श्रादेय के रूप में इकटा हो गया जिसका एक रुपया मूल्य १७३३ करोड़ रुपया हो गया था तथा भारत के चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। भारत के चलन में पत्र-मुद्रा जिसकी मात्रा १९४२-४३ में ६४४ करोड़ रुपया बद्द कर १९४४-४५ में १०८५ करोड़ रुपया, श्रीर १६४७-४८ में १३०४ करोड़ रुपया हो गई। इस काल में मुद्रा की कुल मात्रा की पूर्ति ११६८ करोड़ रुपयों से १६२२ करोड़ रुपये ब्रौर फिर २३०३ करोड़ रुपये बढ़कर हो गई। इसके परिखाम स्वरूप मारत में मुद्रा स्फीति हो गयी श्रीर थोक मूल्यों का निर्देशांक यदि १६३६ श्रगस्त को श्राचार मान ले तो १९४०-४१ में ११४०८, १९४३-४४ में २१६.५ श्रीर १९४७-४८ में ३०७.० हो गया। यदि ब्रिटिश सरकार कोई दूसरा उपाय युद्ध सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था करने का किया होता जैसे भारतीय पूँजी श्रीर द्रव्य नाजार में ऋ ग लेकर तो रुपये के विनिमंय मूल्य में इतनी अधिक कमी और उसके परिणाम में मूल्य स्तर का इतना श्रिधिक बढ़ना बचाया जा सकता था।

मुद्रा की पूर्ति श्रव मारत में लचीली हो गई है श्रीर नवम्बर से मई तक जब मुद्रा की श्रिधक श्रावश्यकता होती है उसका प्रसार हो जाता है श्रीर जून से श्रवह्वर तक जब मुद्रा की माँग कम होती है उसका संकुचन हो जाता है रिजर्व वैंक की स्थापना के पहिले भारत का इम्पीरियल बैंक जिसे श्रव स्टेटवैंक श्राफ-इन्हिया कहा जाता है पत्र मुद्रा विभाग से श्रृण ले लिया करता था। ताकि उससे वह बाजार में मुद्रा श्रमाव जनित संकट को पार कर ले परन्तु यह प्रणाली सुगमता से नहीं चल पाती थी। रिजर्वबैंक के श्रिष्ठकार में साख तथा मुद्रा के एक साथ श्रा जाने से श्रीर उसके द्वारा कुशलता पूर्वक साख तथा मुद्रा चलने का प्रवन्ध किये जाने से सामयिक उतार चढ़ाव में बहुत कमी श्रा गई है।

१६४६ के आर्डिनेन्स द्वारा ५०० रु से आधिक मूल्य वाले वेंक के नीटो के चलन से विहिंक्तत किये जाने के कारण भारतीय चलन पदित को वहा आवाञ्छनीय घक्का एहना पड़ा। १६४० दिसम्बर में इन नीटों की मात्रा निम्न प्रकार थी ५०० रु के मूल्य वाले नीट ३ लाख रुपयों के, १००० रु के मूल्य वाले नीट २१ लाख रुपयों के इन्हीं मृल्यों के नीटों की मात्रा १६४५ में २६ लाख रुपयों के इन्हीं मृल्यों के नीटों की मात्रा १६४५ में २६ लाख रुपयें, ११३.३७ करोड़ रुपये और १२'४६ करोड़ रुपये क्रमशः थी ' केंचे मूल्य वाले नीटों के वापस ले लेने से जनता के भारतीय सुद्रा चलन में विश्वास को गहरा धक्का पहुँचा और ज्यापारियों को वड़ी कठिनाई हुई जिनको सी-सी रुपये के नीटों के बएडलों का एक स्थान से दूसरे स्थान लादे हुये जाना पड़ा।

स्त्रर्ण समानता मान

२१ सितम्पर १६३१ से १ मार्च १६४७ तक भारतवर्ष में पौन्ड विनिभय मान प्रचलित रही क्योंकि रुपये को पौन्ड से संप्रधित कर दिया गया था श्रीर ब्रिटेन से स्वर्ण मान नहीं था। जब भारतवर्ण १ मार्च १६४७ को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो गया भारत में स्वर्ण समानता मान लागू हो गया क्योंकि भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्ण की मात्रा में तथा अमरीका के डालरों की इकाइयों से नियत किया गया। इस प्रणाली में भारत के रिजर्व वैंक के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि रुपये के बदले में कई विदेशी मुद्रा जो स्वर्ण में परिवर्तनीय हो, परन्तु चूकि रुपये का विदेशी मूल्य स्वर्ण के मूल्य पर आधारित है इसलिये इस प्रणाली को स्वर्ण समानता मान कहना अक्ति संगत प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रणाली में स्वर्ण मान के सभी लाभ प्राप्त है और शुद्ध स्वर्ण मान की तरह इसमें न तो प्रत्यन्न रूप से स्वर्ण को आवश्यकता है और न स्वर्ण मान की तरह इसमें न तो प्रत्यन्न रूप से स्वर्ण को आवश्यकता है और न स्वर्ण

विनिमय मान की तरह श्रप्रत्यज्ञ रूप से ही स्वर्ण की श्रावश्यकता है क्योंकि (i) भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्ण की मात्रा में नियत कर दिया गयां है स्त्रीर उसके द्वारा श्रन्थ देशों की सुद्राश्रों में भी जो श्रन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष के सदस्य है नियत हो गया है, (ii) चुँकि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं अपनी मुद्रा का विनिमय मूल्य परिवर्तित कर ते खिवाय बहुत साधारण सीमा के बीच के अणाली से वैटी ही विनिमय स्थिरता प्राप्त होती है जैसी कि स्वर्ण पान में प्राप्त होती थी, (iii) यदि किसी देश के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की राय से नियत किये हुये विनिमय दर के बनाये रखने से कठिनाई का अनुभव होता है है तो यह कोप उसकी सहायता आवश्यक विदेशी मुद्रा उचार देकर करता है ताकि वह श्रपनी मुद्रा का विनिमय मूल्य रियर रख चके श्रीर विदेशी सुगतान ठीक उसी प्रकार कर सके जैसे कि स्वर्ण मान के अर्न्तगत कर सकता था। (iv) इस प्रणाली में सबसे बड़ा लाम यह है कि एक देश से दूसरे देश विनिमय दर से स्थिरता बनाये रखने के लिये जो सोना भेजने को जोखिम तथा व्यय उठाना पड़ता था उसकी ख्रव आवश्यकता ही नहीं रह गई है और भारत का रिजर्व बैंक आवश्यक विदेशी विनिमय या तो अपने साधनों के आधार पर श्रयवा श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उचार लेकर दे देता है श्रौर (v) यद्यपि विनिमय दर में वैसी स्थिरता प्राप्त है जैसा कि स्वर्ण मान के अन्तर्गत होती फिर भी उसमें लचीलापन इस बात से ले आया गया है कि प्रत्येक देश एक निश्चित सीमा के अन्दर यदि चाहे तो स्वयं विनिमय दर में परिवर्तन कर सकता है और यदि अन्तर राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चलाइ लेकर करना चाहे तो किसी भी सीमा तक परिवर्तन कर सकता है। यह सुविधा स्वर्ण मान के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हो सकती थी। इस प्रकार स्वर्ण समानता मान में ग्रह स्वर्ण मान के सब गुण ही मौजूद नहीं है वरन कुछ श्रधिक गुण भी है श्रीर उसके कोई भी श्रवगुण जैसे स्वर्ण के जमा करने के सम्बन्ध में कीष रखना तथा एक देश से दूसरे देश भेजने का व्यय उठाना श्रादि नहीं है।

मारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सदस्य वन जाने के कारण रिजर्व वैंक एक्ट की ४० वी और ४१ वी धाराओं में अभैल १६४७ में संशोधन द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है और अब रिजर्व के के अपिरिमित मात्रा में निश्चित दर पर पीन्ड वेचने और खरीदने के लिये बाध्य होने के स्थान पर उसे विदेशी विनिमय ऐसी दर पर और ऐसी शर्तो पर वेचने तथा खरीदने का अवसर दिया गया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जावे। वृटिश सरकार ने इस सुविधा का अनैतिक प्रयोग भारत पर पीन्ड पावने का मार लादने के लिये तथा

देश में मुद्रा स्थिति लाने के लिये किया था इसलिये इस संशोधन का भारत में स्वागत हुआ । भूत काल में रिजर्वर्ने को ४०० की मुद्रानिधि में जो उसे रखना पहता या स्वर्ण पाट, स्वर्ण मुद्रा तथा पौन्ड प्रतिभृतियाँ सम्मिलित करनी पढ़ती थीं। जब से भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो गया रिजर्वर्ने को यह अधिकार में दिया गया कि वह पौन्ड प्रतिभृतियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभृतियों भी मुद्राकोष में रख सकता है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रकोप द्वारा रुपये का विनिमय मूल्य प्रचलित १ शि० ६ पेन्स की दर पर स्वीकार कर लिया गया परन्तु उसे अब स्वर्ण से संप्रियत कर दिया गया और भारतीय रुपया अब ३० २२५ सेन्ट के वरावर अभरीकी डालर की इकाइयो में और ० २६८६०१ प्राम शुद्र सोने की माना में समका गया।

चपये की विनिमय दर बहुत कुछ स्थिर रही यद्यपि उस पर समय-समय पर दवाव पहता रहा श्रीर इसका श्रेय रिजर्व वैंक के श्रिधकारियों को तथा मारत की श्रन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता को है क्यों कि इस कोष ने बड़ी उदारता के साथ विदेशी मुद्रायें रिजर्व वैंक को रुपये का विनिमय मूल्य स्थिर रखने के लिये दिया। २० सितम्बर १६४६ को भारतीय रुपये का पौन्ड के तथा पौन्ड जेत्र की मुद्राश्रों (पाकिस्तान को छोड़ कर) के साथ ही साथ श्रवमूल्यन हुश्रा इसका कारण यह नहीं या कि रुपये के मूल्य में कोई गड़बड़ी थी श्रयवा रिजर्व वैंक के लिये रुपये के विनिमय दर को बनाये रखना श्रसम्मव हो गया था वरन् यह या कि वृटिश सरकार ने पौन्ड का श्रवमूल्यन करने का निश्चय किया श्रीर मारत ने उसका कामनवेल्य का एक विश्वस्त सदस्य होने के नाते श्रनुकरण किया। लगभग २०१% के श्रवमूल्यन के पश्चात् भारतीय रुपया श्रमरीकी मुद्रा की इकाइयों में २१ सेन्ट में बराबर श्रीर ०१८६६२१ ग्राम शुद्ध स्वर्ण के बराबर हो गया। रुपये का विनिमय मूल्य पौन्ड की इकाइयों में स्थों का त्यों १ शि० ६ पेन्स प्रति रुपया वना रह गया।

भारत की दितीय योजना का प्रवन्ध करने के लिये देश की श्रार्थिक व्यवस्था को उसके श्रनुरूप वनाने के विचार से रिजर्व वैंक श्राफ इन्हिया एक्ट वैंकिंग कम्पनी एक्ट का संशोधन १६५६ में किया गया। इस संशोधन के श्रनुसार (i) पंच मुद्रा निकासी को मुद्रा निष्ठि को उत्तनी ही मात्रा के श्राधार श्रिषक मुद्रा की निकासी द्वारा श्रिषक लचीला बना दिया गया श्रीर (ii) रिजर्व वैंक को व्यापारी वैंको की साख पर श्राधक नियंत्रण रखने का श्राधकार मुद्रास्कीति की स्यति के उत्पन्न हो जाने पर उसे रोकने के लिये दिया गया। इस ध्येय से श्रनु-पातिक निधि प्रणाली को बदल कर उसके स्थान पर 'न्यूनतम निधि प्रणाली को

भारतीय चलन पद्धति का स्वरा पाट स्वर्ण मुद्रा तथा विदेशी प्रभृतियों की इका-इयों में आधार बनाना स्वीकार किया गया। इस संशोधन के पहिले रिजर्व बैंक श्राफ इन्डिया एक्ट् के सेक्सन ३२ (२) के श्रनुसार निकासी विभाग के श्रादेश का कम से कम राध्र माग (४०%) स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण पाट अथवा विदेशी प्रमृतियों को रखना श्रनिवार्य था। स्वर्ण मुद्रा श्रीर स्वर्ण पाट का मूल्य किसी भी दशा में ४० करोड़ रुपये से कम न होना चाहिये। स्वर्ण का मूल्य २१.२४ रुपये प्रति तोला (द तोला बराबर ३ अर्थींच के) या । द्वितीय योजना की आवश्यकता के एंदर्भ में इस नियंत्रण प्रद व्यवस्था के दृष्टिकोण से संशोधित एक्ट ने अनुपातिक निषि प्रणाली को बदल कर न्यूनतम निश्चित प्रणाली की स्थापना की श्रीर यह नियत कर दिया कि विदेशी प्रमृतियाँ कम से कम ४०० करोड़ रुपयों के मूल्य की श्रोर स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण पाट ११५ करोड़ क्ययों के मूल्य के रक्खे जा सकते हैं जब कि र्स्वया कर मूल्य ६२ ५० ६० प्रति तोला माना जाय जो कि समानता दर के अनुसार (३५ हालर प्रति औन्स शुद्ध स्वर्श) था और जो अन्तर राष्ट्रीय कीष द्वारा स्वीकृत थी। संशोधित एक्ट ने यह भी प्रतिबन्ध हटा लिया कि अधिक से अधिक १०० करोड़ ६० के मूल्य की विदेशी प्रमृतियाँ कम से कम ६ महीने की श्रवधि तक जो कि समय समय पर बढ़ाई जा सकती थी पर ३ महीने से श्रिधक काल के लिये एक बार में नहीं केन्द्रीय सरकार की श्रनुमित से श्रवश्य रक्खी जाय । इस संशोधन का वास्तविक प्रभाव यह था कि रिजर्व वैंक अधिक मात्रा में मुद्रा की निकासी करने में समर्थ है श्रयना उसमें स्थान पर कम से कम श्रपनी कुछ विदेशी प्रसृतियों का जिनका मूल्य ३०० करोड़ रुपयों से कम नहीं हो सकता या परित्याग करे । परन्तु भारत में बड़ा ही गंभीर विनिमय संकट १६५६ के ख्रन्त तक उत्पन्न हो गया। जिसके कारण मुद्रा निधि को फिर परिवर्तित करना पड़ा ताकि रिजर्व बैंक अपने पास की कुछ विदेशी प्रभृतियों को मुद्रा निधि में रक्खे जाने के लिये निकाल सके जिससे विदेशी विनिमय का व्यव्यान पूरा किया जा संके । इसलिये ३१ अवट्रवर १६५७ को जिर्द मैंक आफ इन्डिया एक्ट का संशोधन रिजर्व वैंक आफ इन्डिया अमेन्डमेन्ट आहिनेन्स १६५७ की घोषणा द्वारा किया गया और उसे रिजर्व बैंक आफ इन्डिया (दितीय, संशोधन) एक्ट १६५७ में सम्मिलित कर लिया गया। सेक्सन ३३ के संशोधित रूप के अनुसार स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण पाट श्रीर विदेशी प्रमृतियों का मूल्य जो किसी भी समय दैंक के निकासी विभाग में जमा हैं किसी भी स्थित में २०० करोड़ क्ययों से कम नहीं होना चाहिये और साथ ही साथ स्वर्ण मुद्रा श्रीर स्वर्ण पाट का मूल्य कभी भी ११५ करोड़ रुपयों के नीचे न जाने पाये । सेक्सन ३७ में दी शर्ते जिसके अनुसार

निकासी विमाग में कम से कम ३०० करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी प्रमृतियों को रखना अनिवार्य था इटा दी गई। इस संशोधन का प्रमाव विदेशी प्रमृतियों के रखने की न्यूनतम मात्रा को घटा कर दथ करोड़ रुपया करना था जो कि स्वर्ण मुद्रा और स्वर्ण पाट को मिला कर जिसकी सीमा ११५ करोड़ रुपया थी २०० करोड़ रुपया हो जाता है। १९५६ का संशोधन इसलिये ठीक नहीं था कि उसने मुद्रा निधि को घटा दिया था श्रीर उससे रुपये के विनिमय मूल्य के लिये खतरा था, क्योंकि जनता का विश्वास मुद्रा के प्रति ग्रंशतः मुद्रा के श्राधार रूप में रक्खी निधि पर निर्भर करता है और १९५७ के संशोधन ने स्थिति निगाइ दी थी। यह तर्क उपस्पित करना श्रनुचित है जैसा कि रिजर्व बैंक के श्रिधकारियों ने किया है कि मुद्रानिधि एक प्राचीन प्रया का प्रवीक मात्र है श्रीर विल्कल श्रावस्यक नहीं है, अथवा जैसा कि उस समय के वित मंत्री ने लोक सभा में कहा कि सुद्रा निधि श्रपने वर्तमान रूप में मेरे विचार से सरकार की परम्परागत निष्क्रियता के कारण चलाई जा रही है। यह बड़े सीमारय की बात है कि भारतीय रुप्ये की विदेशों में साल श्रायी है श्रीर उसका मूल्य स्थिर है। इमें उसकी रहा इस बात से करनी है कि स्पिति संकट का रूप न धारण कर ले। सरकार और रिजर्व बैंक ने इस सम्मावना की श्रीर से श्रांखे बन्द रक्खी है।

दूबरी विचारणोय वात भारतीय मुद्रा त्रेत्र में जो हुई वह यह थी कि रिजर्व वैंक श्राफ इन्डिया एक्ट १६५३ ने (मंशोधित) श्रमी मूल्य वाले नोटें फिर से चालू कर दिया श्रीर जो कठिनाई उनके हटा देने से उत्तब हो गई थी दूर हो गई। रिजर्व वैंक श्राफ इन्डिया ने फिर से १००० ६०, ५००० ६० श्रीर १००० ६० के नूल्य के नोटों की निकासी १ श्रमेल १६५४ से कर दी।

यहाँ इस बात का याद दिलाना श्रावश्यक होगा कि विकटोरिया तथा सप्तम एडवर्ड के रूपये श्रीर श्रटिश्यां जो श्रुद्ध चाँदी के ये पहिली श्रप्रेल १६४१ श्रीर ३१ मई १६४२ से क्रमशः विहच्छत कर दिये गये श्रीर जार्ज वच्ठव के चाँदी के रुपये श्रीर श्रटिश्यों १ मई १६४३ से विहच्छत कर दी गई। उनका स्थान ऐसे रुपयों श्रटिलयों श्रीर चविलयों हारा ले लिया गया जिनकी निकासी १६४० में इसिलये की गई कि सिक्कों का मुद्रया व्यय घट जाय। ये सिक्के जिनमें केवल ५०१० श्रुद्ध घातु थी श्रीर जिनका वास्तिवक मूल्य उनके श्रंकित मूल्य से बहुत कम था वाद में हटा दिये गये श्रीर निकासी के सांकेतिक सिक्कों ने उनका स्थान ले लिया। चाँदी की पूर्ति के श्रप्याप्त होने, चाँदी के वर्तमान मूल्य स्तर तथा २२६०००००० श्रीन्स चाँदी के जिस भारत ने यूनाइटेड स्टेट से १६४३-४५ में उधार लिया या लौटाने के हिएकोग्र से मारत सरकार ने १६४६ की मई से

चौपाई मूल्य वाकी अठित्रयों और चवित्रयों की निकासी बन्द कर दी (ऐसे इपयों की भी) और यह निर्धाय किया कि शुद्ध निकिल के सिक्के उनका स्पान लें। ये सिक्के चौयाई मूल्य वाले रुपयों के ही बजन के ये (१८० ग्रेन ट्राय) पर उनका ज्यास कुछ कम है। मुख्य बात यह है कि ये वैसे ही सौकेतिक सिक्के हैं जैसे कि पन मुद्रा और उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इस उपाय से इसमें संदेह नहीं छछ चौदी की बचत हो गई परन्त्र हसे भारतीय मुद्रा चलन हीन हो गई यद्यपि सौमान्य से भारतीय जनता का उस पर विश्वास कम नहीं हुआ। है। दूसरा उल्लेनीय परिवर्तन भारतीय चलन पद्धति में दशमिक सिक्कों का १ अप्रैल १६५७ से प्रचलन था।

मध्याय ४२

रुपये का विनिमय अर्घ

देश के विदेशी व्यापार का प्रसार करने के लिए, देश की श्रार्थिक समृद्धि बढ़ाने श्रीर रोजगार बढ़ाने के लिए रुपये के विनिमय श्रर्ध का बहुत श्रिषक महत्व है। व्यापार श्रीर लेन देन का कार्य सुचार रूप से चलाने के लिए यह भ्रावश्यक है कि विनिमय अर्घ में स्थायित्व हो। यदि रुपये के विनिमय अर्घ में कमी श्राए तो भारत के श्रन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले सामान के बदले में पहिले की श्रपेका श्राधक रुपया प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि निर्यात कर्ता श्रपने माल के मूल्य में किसी प्रकार का परिवैतन न कर उन्हें पूर्व स्तर पर ही बनाए रखें तो इससे विदेश के बाबारों में उनकी प्रतियोगिता शक्ति बद्द सकती है। यदि रुपये का विनिमय श्रर्ध श शिलिंग ६ पेन्स से घटाकर १ शिलिंग ४ पेन्छ प्रति रुपया कर दिया नाय तो इसका भारतीय निर्यात कर्ता के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। भारत के निर्यात कर्ता वहाँ जो वस्तु १ शिलिंग ६ पेन्स में वेचकर एक रुपया प्राप्त करते ये वह विनिमय के अर्ध में परिर्धतन हो जाने से १ रुपया २ त्राना प्राप्त कर सहेंगे। परन्तु यदि निर्यात कर्ता उस वस्तु की केवल एक रुपया कीमत वसूल करने से सन्तुष्ट हो तो वह विदेशों में श्रपने माल की कीमत घटा कर १ शिलिंग ४ पेन्स कर सकता है। ऐसा करने से अन्य देशों की अपेद्या उसकी प्रतियोगिता शक्ति बढ़ेगी । यदि रुपये के विनिमय अर्घ में वृद्धि हुई तो इसका परिणाम उल्टा होगा। इसके फलस्वरूप मारतीय निर्यात कर्ता को श्रपने माल का दाम पहले की श्रपेचा रुपये के रूप में कम मिलेगा, यदि पहले के बरावर रुपये प्राप्त करना चाहेगा तो विदेशों में उसके माल की कीमत बढ जायेगी, श्रौर उसकी प्रतियोगिता शक्ति शिथिल पड़ जायगी। रुपये के विनिमय श्चर्ष परिवेतन का भारत के श्रायात पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। किस समय कौन सी विनिमय अर्ध की दर उपयुक्त होगी यह अनेक बातों पर निर्भर है। विनिमंय श्रर्घ की दर में परिवर्तन से आयात और निर्यात, मुगतान के सन्तुलन श्रीर देश की श्रार्थिक स्थिति की दृढ़ता पर प्रभाव पद्भता है। देश को श्रर्थिक दृष्टि से समृद्रिशाली बनाने में इन सब का विशेष स्थान होता है। इसलिए जब कभी विनिमय श्रर्ध की दर में परिवर्तन किया जाता है तो पहले सारी स्थित पर विस्तार से गम्मीरता पूर्वक विचार कर लिया जाता है।

हिल्टत-यंग कभीशन की रिपोर्ट-भारत में विनिमय के अनुपात के

परन पर १६ वी शतान्दी से ही विवाद चलता आ रहा या परन्तु १६२६ में हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात यह विवाद का मुख्य विषय यन गया। हिल्टन-यंग कमीशन ने िएकारिश की कि क्येय का विनिमय अर्घ १ शिलिंग ६ पेन्स प्रति चपया निश्चित किया जाय। इससे स्वर्ण के मान में एक क्पया क्र. ४७५१२ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण के वराचर होगा। अपनी इस सिकारिश के समर्थन में कभीशन ने निग्नलियित तर्क दिये —

- (१) भारतीय तथा विश्व-भाजार में विनिमय इस अनुपात पर पहले ही निश्चित हो जुका है और इसी अनुपात पर भारतीय तथा विश्व-भाजार में काफी लेन देन हो जुका है। यदि विनिमय की दर में कुछ परिवर्तन किया गया तो इससे कुछ समय तक एक विषय स्थिति उत्पन्न हो नायेगी और व्यापक अर्थांति और अव्ययस्था फैल जायगी। प्योक्ति जून १६२५ से विनिमय का अनुपात इसी स्तर पर रहा है इसिए बिना किसी परिवर्तन के इसी अनुपात को मान लेना चाहिए।
- (२) भारत में वेतनों श्रीर मूल्यों में इसी श्रनुपात के श्रनुसार परिवर्तन हो गया है इसलिए यही उपयुक्त श्रनुपात है।
- (३) वस्तुश्रों के मूल्य के श्रनुपात में लगान श्रवश्य कम हो गया है पर संविदा (contract) इसी नए श्रनुपात के श्रनुसार निश्चित हो गये हैं।
- (४) यह कहना ठीक नहीं है कि १ शिलिंग ४ पेन्स विनिभय का स्वाभ-विक (natural) अनुपात है पर्योकि अवीत में काफी लग्ने समय तक इसी के अनुसार कारोगर चलता रहा है। विनिमय का अनुपात उस समय की परिस्थि-तियों पर निर्भर करता है और अब परिस्थितियों के अनुसार उसे १ शिलिंग ६ पेन्स प्रति क्पया होना चाहिए। यदि विनिभय का अनुपात १ शिलिंग ४ पेन्स कर दिया जाय तो इससे भारत सरकार की वित्त-स्थित पर प्रभाव परेगा और स्थय की रकम पूरी करने के लिए सरकार की अधिक कर लगाने परेगे।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने कमीशन की रिपोर्ट पर श्रापित प्रकट की श्रीर सुमान दिया कि विनिमय का श्रनुपात १ शिलिंग ४ पेन्स ही निश्चित किया जाय वर्षों श्रि श्रीत में काफी लम्बे समय तक इसके श्रनुसार कारोगार चलाया जाता रहा है श्रीर श्रव इसे स्वाभाविक विनिमय श्रनुपात सममाना चाहिये। यदि श्रनुपात १ शिलिंग ६ पेन्स निश्चित किया गया तो इसका श्रमिपाय यह होगा कि रुपये के विनिमय श्र्म में १२६ प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे विदेशी उत्पादकों को भारतीय बाजार में प्रतियोगिता बदाने में सहायता मिलेगी श्रीर भारत के निर्यात व्यापार को ज्ञीत पहुँचेगी।

भारत सरकार ने हिल्टन-यंग कमीशन की सिकारिशों को स्वीकार कर लिया श्रीर १६२७ का मुद्रा कानून पारित किया। इसके श्रनुसार चपये का विनिमय श्रनुपात १ शिलिंग ६ पेन्स प्रति चपया निश्चित किया गया श्रीर सरकार को निम्न उत्तरदायित्व दिये गये, (१) सरकार को २१ चपया ३ श्राना १० पाई प्रति तोले के दिसाब से सोने की कम से कम चालीस तोले की सिल्जियाँ खरीदनी चाहिए। (१) सरकार वम्बई में निकासी के लिए जो सोना वेचेगी या लन्दन में निकासी के लिए स्टर्लिङ्ग बेचेगी उसकी मात्रा कम से कम ४०० श्रीस श्रुद सोना श्रथवा इतना ही स्टर्लिङ्ग होना चाहिए।

इसके उपरान्त १० वर्ष ने श्रिधिक समय तक भारतीय जनता बराबर क्यये का श्रवमूल्यन करने की माँग करती रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी श्राश्य का एक प्रस्ताव स्वीकार किया श्रीर श्रमेक श्रार्थशास्त्रियों ने भी सुमाव दिया कि रुपये का श्रवमूल्यन किया जाना चाहिये। रुपये के विनिभय श्रर्भ में वृद्धि (Overvaluation) कर देने से भारत को श्रमेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसकी संज्ञिस रूप रेखा नीचे दी गई है —

- (१) विनिमय श्रनुपात की इस कृष्ट्रिम दर को बनाए रखने के लिए सरकार को १६३०-३१ तक ५ वर्षों में लगभग १०६ करोड़ उपये का मुद्रा-संकुचन करना पड़ा। इससे भारतीय वस्तुश्रों के मूल्य गिर गये जिससे भारतीय किसानों श्रीर उत्पादकों को बहुत हानि हुई।
- (२) इस नीति को लागू करने के फलस्वरूप देश का मुद्रा सुरिज्ञत कोष (currency reserve) खाली हो गया और इस दर को बनाये रखने के लिये सरकार को विशेष प्रयत्न करने पड़े।
- (३) कृतिम विनिमय अर्घ के कारण १६२६ की आर्थिक मन्दी का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। विदेशों की अपेक्षा भारत की कीमतों में अधिक कमी आई, ज्यापार की शर्ते भारत के अनुकूल न रहीं और ज्यापार का सन्तुलन (balance of trade) भारत के अनुकूल होते हुए भी बचत पहले की अपेक्षा बहुत कम रही। इसमें सन्देह नहीं कि देश की आर्थिक स्थित और मूल्यों का परस्पर सम्बन्ध और ज्यापार सन्तुलन अनेक वार्तों पर निर्भर करते हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति विगड़ने का कारण केवल रुपये के विनिमय अर्घ में अवांछित वृद्धि कर देना था। परन्तु यह बिल्कुल सही है कि देश की स्थिति विगाइने के लिए अन्य कारणों के साथ यह कारण भी उत्तरदायी है। यदि विनिमय अर्घ की दर १ शिलिंग ४ पेन्स निश्चित की गई होती तो सम्भवत: इतने गम्भीर संकट का सामना न करना पड़ता। १६३१ में जब ब्रिटिश

सरकार ने स्वर्ण-मान का त्याग कर दिया तब क्ष्ये का सम्बन्ध स्वर्ण की बजाय स्टिलिं से जोड़ दिया गया परनतु विनिमय का अनुपात १ शिलिं से पेन्स स्टिलं प्रति क्ष्या ही रखा गया। क्ष्ये का विनिमय अनुपात धटाने के लिए सरकार के पास यह स्वर्ण अवसर या पर सरकार इस अवसर का लाभ उठाने से चूक गई और देश को भारी कृति उठानी पड़ी।

सितम्बर १६४६ में रुपये का श्रवमूल्यन कर दिया गया। इस समय तक विनिमय के श्रनुपात के सम्बन्ध में श्रीर रुपये का श्रवमूल्यन करने की माँग पर विवाद चलता रहा। श्रवमूल्यन की श्रावश्यकता इसलिए थी कि निर्यात की अपेचा इमारा श्रायात अधिक या अर्थात् व्यापार चन्त्रलन प्रतिकृल या जिसको श्रनुकूल बनाने के लिए निर्यात बढ़ाना श्रीर श्रायात कम करना श्रावश्यक था। सरकारी नियंत्रण द्वारा श्रायात की मात्रा घटाई जा सकती है और उत्पादन न्यय घटाकर निर्यात बढाया जा सकता है परन्तु यदि उत्पादन व्यय में कमी कर सकना सम्मव न हो, जैसा कि दितीय विश्व युद्ध के वाद भारत में हुआ, तो निर्यात की मात्रा बहाने का एक मात्र उपाय श्रवमूल्यन करना है। यह दावा किया गया कि निर्यात में वृद्धि करके श्रीर श्रायात को कम करके श्रवमूल्यन के द्वारा प्रतिकृत व्यापार- अनुतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है। अवमूल्यन के विरोध में यह कहा गया कि विश्वयुद्ध के बाद भारत के निर्यात व्यापार में जो हास हुआ है श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय खाते में निरन्तर जो घाटा सहना पड़ा है उसका कारण जापान श्रीर जर्मन बाजार का हाथ से निकल जाना, देश का विमाजन श्रीर विमाजन से विनिमय मुद्रा कमाने के साधन जूट और रुई की ज्ञति, भारतीय वस्तुओं के लिए पर्यात बाजार का श्रमान, स्वदेश तथा विदेश में यातायात के साधनों की कठिनाइयाँ श्रीर उत्पादन प्रणाली की बुराइयाँ इत्यादि है तथा श्रवमूल्यन कर देने से इन कारणों को दूर नहीं किया जा सकता है। निस्पन्देह यह सच है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था की सभी बुराइयों को अवमूल्यन से दूर नहीं किया जा सकता है परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कठिनाइयों को श्रीर बढ़ा देने में विनिमय श्रर्घ में वृक्षि करने का भी बहुत श्रिधक हाथ रहा है श्रीर यदि १६३१ में ही या उसके बाद रुपये का श्रवमूल्यन कर दिया जाता तो भारत को इतनी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।

यह भी कहा गया है कि 'मुलभ मुद्रा चेत्र' (soft currency areas) से श्रायात घटाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी श्रीर कुछ सीमा तक दुर्लम मुद्रा चेत्र (hard currency areas) से भी श्रायात घटाया जा सकता है। श्रायात पर उचित प्रतिबन्ध लगा देने से भी उक्त चेत्रों से श्रायात घटाया जा सकता है

जैसा कि भारत सरकार ने निश्चय किया है। इसलिए ग्रायात घटाने के लिए श्रवमूल्यन के श्रवांछित उपाय को श्रपनाने की कुछ श्रावश्यकता नहीं है। श्रव-मूल्यन के विरुद्ध यह भी कहा गया कि इससे भारत में श्रायात की जाने वाली वस्तश्रों की कीमतों में वृद्धि हो जायगी श्रीर इसका प्रमाव विशेषकर खाद्यास पर पड़ेगा निसके लिए भारत को बहुत श्रंशों में विदेशों पर ही निर्भर करना पड़ता हैं। इससे भारत के वाजार में वस्तुत्रों की पूर्ति घट जाने से मुद्रास्कीति की दिपति श्रीर त्रिगड़ जायगी। इसके विरुद्ध यह कहा गया कि राये के विनिमय श्रर्घ में कमी होने से निर्यात की मात्रा बढ़ेगी श्रीर श्रायात महँगा पड़ेगा, साथ ही हवमें कठिनाई भी होगी परन्तु इस सम्बन्ध में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कुल कितना लाभ होता है। यह बात अवमूल्यन के पन्त में प्रतीत होती है। इस तर्क में कुछ सत्य नहीं है कि श्रायात के सम्बन्य में उदार नीति श्रपनाने से भारत में मुद्रास्कीति का जोर कम हो गया। कीमतों की दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि श्रायात के सम्बन्य में उदार नीति श्रपनाने के एक वर्ष बाद ही मुद्रास्कीति की स्थिति श्रीर विगड़ गई। श्रायात करने में किसी भी प्रकार उन शक्तियों की रोका नहीं जा सकता है जिन्होंने भारत में मुद्रास्फीति की हिपति उत्तक कर दी। यह भी कहा गया कि रुपये का श्रावमृत्यन कर देने से मशीनें, खाद्यान, कंमिकल तथा उपभोग की श्रन्य सामियाँ मह्गी हो जायँगी श्रीर इन सामियों का भारत की श्रायात करना पड़ता है। जहाँ तक उद्योगों का सम्बन्ध है साधनों के महेंगे होने के कारण उत्पादन व्यय में वृद्धि होगी, परन्त निर्यात बढ़ने श्रीर विदेशों के बाजार में भारतीय माल की श्रधिक खपत होने से उद्योग को श्रधिक लाम पहुँचेगा।

यह भी कहा गया है कि भारत के नाम पीएड पावना जमा है श्रीर हर ये का श्रवमृत्यन हो जाने से भारत को पीएड पावने के बदले जो वस्तुएँ श्रीर जो सेवाएँ प्राप्त होती हैं उनकी मात्रा घट जायगी। परन्तु यह संकीर्ण दृष्टिकोण है। किसी भी मुद्रा के विनिमय अर्थ को निर्धारित करने में सारी परिस्पितियों पर विचार करना होता है इसिलए योड़ी बहुत च्वित का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि श्रवमृत्यन से देश समुद्रशाली वने तो पीएड पावने के रूप में जो योड़ी बहुत च्वित होगी वह श्राधानी से पूरी हो जायगी।

े अवमूल्यन—२० धितम्बर १६४६ को रुपये का श्रवमूल्यन किया गया। भारत सरकार ने घोषित किया कि श्रमरीकी सुद्रा में भारतीय रुपये का विनिमय श्रम ३० २२५ सेन्ट से घटाकर २१ सेन्ट और सोने में ० २६२६०१ प्राम से घटा-कर ० १८६६२१ प्राम शुद्ध स्वर्ण कर दिया गया परन्तु पौएड स्टर्लिङ्क में रुपये का विनिमय श्रर्घ पूर्वमान के श्रानुसार १ शिलिख ६ पेन्स ही रखा गया। भारत सरकार के इस निश्चय का कारण यह था कि ब्रिटेन तथा श्रान्य राष्ट्र मण्डलीय सरकारों ने श्रपनी मुद्राश्चों का श्रवपूल्यन कर दिया था। डालर चेत्र में इन देशों का ज्यापार-सन्तुलन निरन्तर प्रतिकृल होता जा रहा था श्रीर इस कठिनाई का सामना करने के लिए डालर में इन देशों की मुद्राश्चों का विनिमय श्रर्घ घटाना श्रावश्यक था।

राष्ट्रमण्डलीय देशों में से केवल पाकिस्तान ने अपने राये का अवमूल्यन नहीं किया और पाकिस्तानी रुपये का मूल्य जो ३० २२५ सेन्ट प्रति रुपया था ज्यों का त्यों वना रहा। पाकिस्तान की सरकार को बहुत घाटा सहने पर अपनी भूल मालूम हुई और सितम्बर १९५५ में पाकिस्तानी रुपये का भी मूल्य घटाकर २१ सेन्ट प्रति रुपया कर दिया गया।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि रुपये का केवल डाशर में अवमूल्यन किया गया परन्त पौरह स्टलिंग में रुपये का विनिमय अर्घ विना किसी परिवर्तन के वही रखा गया जो पहले था, परन्तु भारतीय जनता की माँग से भिन्न था। जनता ने माँग की कि रुपये का डालर, स्टर्लिंग तथा श्रन्य मुद्राश्रों में श्रवमूल्यन किया जाय । इस सम्बन्ध में भारत सरकार की कड़ी श्रालोचना की गई है श्रीर कहा गया कि रुपये का अवमूल्यन भारत सरकार ने स्वयं नहीं किया: किन्त क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपना निर्णय पहले ही ले लिया था इसलिए भारत को मी विवश होकर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। यह भी कहा गया कि भारत सरकार को रुपये का श्रवमूल्यन पौरड स्टर्लिङ्ग की श्रपेत्ता श्रिधिक करना चाहिये था। मारत सरकार की नीति के समर्थन में यह कहा गया कि भारत का ७५ प्रतिशत निर्यात व्यापार उन देशों से होता है जिन्होंने अपनी सद्वाओं का अब-मुल्यन कर दिया है. श्रीर इन देशों में भारत के श्रानेक प्रतिद्वन्द्वी थे, जैसे लंका-शायर का कपड़ा, लंका की चाय, पूर्वी अफ्रीका की मूक्क लियाँ, दिन्तणी अफ्रीका का मैगनीज श्रीर हराही का जुट का सामान इत्यादि । ऐसी स्थिति में यदि श्रव-मूल्यन न किया जाता तो सुगतान के सन्तुलन में घाटे की स्थिति श्रीर बिगड गई होती जो पहले ही से खराव थी। इसलिए भारत को श्रपने बचाव के लिए रुपये का श्रवमूल्यन करना श्रावश्यक हो गया । यह कहना सही है कि भारत में अवमुल्यन का अपना एक विशेष महत्व हैं। यह भी बताया गया है कि भारत सरकार पौराड स्टर्लिझ से अधिक मात्रा में रुपये अवमूल्यन कर सकने में असमर्थ थी। पौरह स्टर्लिङ्ग का २०ई प्रतिशत तक अनमूल्यन किया गया। यदि भारत

ने रुपये का इससे अधिक श्रवमूल्यन किया होता तो उससे भारत के व्यापार पर दुरा प्रभाव पड़ता श्रीर श्रार्थिक ज्ञति पहुँचती।

श्रवमृत्यत का प्रभाव-शाशा के अनुसार ही भारतीय न्यापार सन्तुलन पर श्रवमूल्यन का श्रनुकूल प्रभाव पड़ा । सुगतान का संतुलन जो कि १६४८-४६ में १८३.४५ करोड़ रुपया से प्रतिकृत था, अब भी प्रतिकृत ही रहा परन्तु घाटा १९४६-५० में कम होकर ११८०८६ करोड़ रुपया श्रीर १६५०-५१ में घट कर केवल २२'०१ करोड़ रह गया। इस सुधार का कारण केवल श्रवमूल्यन ही नहीं है। इस पर भारत सरकार की न्यापार नीति का भी प्रभाव पड़ा जिसके श्रनुसार श्रायात व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। परन्तु यह कहा जा सकता है कि स्थिति श्रीर कीमतों में सुधार करने में श्रवमुल्यन का विशेष योगदान रहा। श्रमाग्यवश भारत धोड़े समय तक ही श्रवमूल्यन का लाभ उठा सका । सुगतान की प्रतिकृत्तता फिर १६५१-५२ में बढ़कर २०६ ६३ करोड़ रुपये हो गई। इसका एक कारण यह भी था कि पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया था जिसका परिसाम यह हुआ कि आयात किए गये सामान, विशेषकर जूट और र्च्ड, के लिए कीमतें अधिक देनी पड़ीं । इन वस्तुत्रों का आयात घटा देना पड़ा। इसका परिखाम यह हुन्ना आयात की गई इन वस्तुन्नों से निर्मित माल का उत्पादन व्यय बढ़ गया श्रीर उनका पर्याप्त मात्रा में न उत्पादन हो सका श्रीर न निर्यात । इससे भारत श्राशा के अनुसार अवमूल्यन का लाभ उठा सकने से वंचित रह गया।

यह विचारणीय बात है कि भारत के सम्बन्ध में श्रवमूल्यन से प्राप्त लाभ का इतना शीम श्रन्त हो गया पर श्रन्य २८ राष्ट्र जिन्होंने भी श्रवमूल्यन किया था निरन्तर लाम उठाते रहें हैं। श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने श्रपनी ३० श्रप्रैल १६५० की रिपोर्ट में यह संकेत किया है कि श्रवमूल्यन के ६ महीने पश्चात् विश्व के श्रन्य राष्ट्रों ने ७० करोड़ ढालर स्वर्ण श्रयवा ढालर रिजर्व के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स से प्राप्त किये। स्टर्लिझ चेत्र का ही स्वर्ण श्रीर ढालर रिजर्व जून १६४६ में १ श्ररव ६८ करोड़ ८० लाख ढालर की मात्रा से २ श्ररव ४२ करोड़ २० लाख ढालर १६५० की जून में हो गया। यूरोपीय तथा श्रन्य राष्ट्र मगडलीय देशों को श्रवमूल्यन का लाभ इसलिये मिलता रहा कि इन देशों में उत्पादन की मात्रा बराबर बढ़ती रही श्रीर वे मारत के विपरीत निर्यात बढ़ाते रहे। मारत में श्रायात किये हुये माल की ऊँची कीमत, मुद्रास्कीति की स्थित, सरकार की दोषपूर्ण श्रीद्योगिक नीति तथा श्रन्य ऐसे कारणों से श्रीद्योगिक उत्पादन श्रिषक नहीं बढ़ाया ला सका श्रीर पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं किया जा सका।

सरकार का आठ-सूत्री कार्यक्रम-रुपये के अवमूल्यन के साथ ही

धरकार ने आठ ध्री कार्यक्रम की घोपणा की जिसमें निम्नलिखित बातें सिमालित यीं - (१) विदेशी-विनिमय में देश के व्यय की न्युनतम करने के उद्देश्य से व्यापार की नई नीति अपनाई जाय: (२) १६४६-५० के वालू वर्ष में वजट के व्यय की रकस में ४० करोड़ रुपये की कभी की जाय छीर छागामी वर्ष ८० करोड़ रुपये की कमी की जाय; (३) श्रावश्यक वस्तुस्रो, खाद्यान्न इत्यादि की कीमत में १० मितरात की कमी की जाय: (४) उन देशों से श्रायात किए गये श्रीयोगिक सामान की कीमतों को घटाने के लिए देश की लेन देन की शक्ति का पूरा लाभ उठाया जाय जिन देशों की मुदा की कीमत भारत की तुलना में बढ़ गई है, (५) राष्ट्रीय वचत श्रीर उसको उद्योग में लगाने के श्रान्दोलन को बढ़ाया जाय श्रीर शास्य चेत्रों में वैंकिंग की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए सरकारी सहायता की व्यवस्था की जाय; (६) युद्ध के समय कमाये गये लाम पर कर की अदायगी के क्तगड़ों को स्वेन्छापूर्वक इल कर सकने की सुविधा बढ़ाई जाय; (७) दुर्लम सुद्रा चैत्र को निर्यात किए जानेवाले सामान पर चुंगी (customs) लगाई जाय; (प) कानूनी तथा श्रन्य उपायों से साख निर्माण की सुविधात्रों पर प्रतिबन्ध लगाकर सहेवाजी से कीमतों के बहुने की प्रवृत्ति को रोका जाय। इस विस्तृत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में मुद्रास्प्रीति को रोकना था जो ब्रायात नीति के सरकारी प्रतिबन्धों श्रीर रुपये का अवमूल्यन करने से आयात घट जाने के कारण जोर पकड़ती जा रही यी। परन्तु यह श्राट सूत्री कार्यक्रम कागर्जी-योजना मात्र रहा। इसे कभी व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सका । श्रवमूल्यन के पश्चात भारत में मुद्रास्कीति श्रीर श्रधिक वह गई श्रीर उपमोक्ताश्रों को बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। मारत सरकार का अधिक-श्रव-उपजाश्री श्रान्दोलन उतना सफल नहीं हुश्रा जितनी श्राशा की जाती थी। मारत को विदेशों से खाद्याक सँगाने में बहुत श्रिधिक व्यय करना पड़ा। अवमूल्यन से आयात की गई वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ गई।

पुनर्मूल्यन (Revaluation)—श्रवमूल्यन के पश्चात भारत की श्रापिक स्थिति पहले की श्रपेका श्राधिक विगढ़ गई श्रीर गुद्रास्फीति की समस्या को इल करना ही प्रमुख समस्या बन गई। मुद्रास्फीति के कारणों को दूर करने के लिये यह सुक्ताव दिया गया कि रुपये का पुनर्मूल्यन किया जाना चाहिये श्रप्यांत रुपये के विनिमय श्र्म में वृद्धि की जानी चाहिए। डाक्टर जान मथाई ने यह तर्क दिया कि यदि रुपये के पुनर्मूल्यन का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को रोकना है तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इसके लिए देश के श्रन्दर ही कोई कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं होगा ! इसका उत्तर यह है कि वर्तमान में मुद्रास्फीति को रोकने के

लिए स्वदेश में जिन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है सम्भवतः वह उपयोग शीव ही लागू नहीं किये जा सकते । कर इतने अधिक लगा दिये गये हैं कि अब उनसे हानि होने लगी है, स्वेच्छा से बचत करने की योजना सफल होना श्रत्यन्त कठिन है श्रीर श्रनिवार्य बचत की योजना लागू करने में श्रनेक प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सरकार द्वारा श्रिधिक प्रयत्न करने पर भी सरकारी व्यय में बचत कर सकने की कोई सम्भावना नहीं है। साख पर नियंत्रण रखकर श्रन्य देशों ने मुद्रारफीति को रोकने का प्रयत्न किया परन्तु इस प्रश्न को भारत में लागू करने की सम्मावना बहुत कम है। स्ट्रेबाजी में स्पया विशेष रूप से ऐसे सूत्रों में लगाया जाता है जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके लिए प्राय: बुलियन वेचकर या वैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत न आनेवाले साहकारों से रुपया उधार लेकर लगाया जाता है। कर से बचने की नियत से छिपाकर रखा हुया रुपया भी प्राय: सट्टेबाजी के ही काम में लाया जाता है। यदि सरकार या रिजर्व वैंक इन सूत्रों से प्राप्त होने वाले रुपयों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करे तो उफलता मिलना संभव नहीं है। जिन विकास योजनाओं को इस समय लागू किया गया है उनके उत्पादन की स्पिति तक पहुँचने में काफी समय लगेगा श्रीर दूसरी श्रोर कञ्चे माल के श्रभाव से श्रीर पूँजीं के श्रभाव से वर्तमान उद्योगों के प्रसार में रुकावट पैदा हो गई है। कीमतों पर नियंत्रण रखने की नीति प्रशासन की दृष्टि से श्रत्यन्त कठिन है परन्तु वास्तव में यह मुद्रास्कीति को रोकने का उपाय नहीं है यह केवल मुद्रास्तीति के कुछ लच्चाों को दूर करता है। इन सारी वालों को ध्यान में रखते हुए भारत में मुद्रास्फीति की रोकने के लिए डाक्टर मधाई ने रुपये के पुनर्मूल्यन का सुक्ताव दिया।

रपये के पुनर्मूल्यन के विरोधियों का मत है कि विश्व की वर्तमान श्रस्थिर स्थिति इसके लिए उपर्युक्त नहीं है और मारत इस सम्बन्ध में श्रलग कोई निर्णय नहीं कर सकता। श्री चिन्तामणि देशमुख ने श्रप्रैल १६५१ में संसद में बताया कि रिजर्व वैंक के विशेषशों का मत है कि रुपये का १५ प्रतिशत पुनर्मूल्यन करने से सुगतान के सन्तुलन में लगमग ५० करोड़ रुपये का घटा होगा, यदि ३० प्रतिशत पुनर्मूल्यन किया जाय तो प्रायः १ श्रद्ध ३५ करोड़ रुपये का बाटा होगा। यदि मुद्रा का पुनर्मूल्यन न किया जाय तो सम्भवतः स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यह खेद की बात है कि वित्त मन्त्री ने उन बातों पर प्रकाश नहीं डाला जिनके श्रघार पर रिजर्व वैंक के विशेषश उक्त निराशाजनक परिणाम पर पहुँचे। सम्भवतः मारत के निर्यात को वेजितना वास्तव में है उससे श्रिषक परिवर्तन-शील (Elastic) समके थे। जिन वस्तुश्रों का भारत निर्यात करता है उनमें से कुछ

निम्नलिखित हैं- जूट का सामान, स्ती कपड़ा, चाय, चमड़ा, 'तिलहन, मसले, श्रवरक. मैगनीज श्रीर लाख। १६५१ में जूट श्रीर रई की वस्तुश्रों की माँग की काफी संभावना थी और विश्व बाजार की कीमतें भारतीय कीमतों से कहीं ऊँची थीं । जूट श्रीर रुई की वस्तुत्रों का बाजार भारत के लिए खला था। इसी कारण भारत सरकार निर्यात की मात्रा में भारी कभी किए बिना इन वस्तुओं पर अधिक निर्यात कर लगा सकी। यदि रुपये का पुनर्मल्यन करने से रुपये में इन वस्तुश्रों की कीमतों में बृद्धि होती है श्रौर निर्यात कर या तो नहीं लगाया जाता या उसकी दर में कमी कर दो बातो है तो ऐसी संमावना है कि इन वस्तुश्रों की भारतीय कीमते फिर भी विश्व बाजार को कीमतों के अन्दर ही रहती। इस सम्बन्ध में एक यह महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि रुपये का पुनर्मृत्यन करने से इन वस्तु औ का उत्पादन करने के लिए पाकिस्तान से कच्चा माल सस्ते दामों में मिल सकता था। इससे उत्पादन व्यय कम हो जाता और यह आवश्यक नहीं था कि इनकी नियात कीमर्ते रुपये के विनिमय अर्थ के बराबर ही बढ़तीं। यही बात कुछ सीमा तक चमड़े और तिलहन पर लागू होती थी। यह संभव था कि हमारी चाय स्रीर कछ छोटी-मोटी वस्तुत्रों की निर्यात-मात्रा गिर जाती। परन्तु फिर मी यह श्रसंभव था कि रुपये का ३०% पुनर्मेल्यन करने से भारत को सुगतान की ऋदायगी में १३५ करोड़ रुपये का बाटा उठाना पड़ता।

पुनर्मृल्यन की नीति के विरुद्ध यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने कच्चे माल की कीमतें वहा देना और इससे भारत रुपये का पुनर्मृल्यन करने के लाभ से बंचित रह जायग; मशीनों इत्यादि का विक्रय करनेवाले देश जिनके माल की व्यक्तिगत और सरकारी योजनाओं के लिये अत्यन्त आवश्यकता है और जो मूल्य वस्ताने में मेदभाव करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है, रुपये के पुनर्मृल्यन के लाभ का अधिकांश स्वयं ले लेंगे और भारत को अधिक लाभ नहीं हो सकेगा। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि दाये का पुनर्मृल्यन हो जाने से ही उक्त परिणाम होंगे। वर्तमान समय में भारत को मशीन इत्यादि सामान का निर्यात करने वाले और जूट तथा हई का निर्यात करनेवाले पाकिस्तानी व्यापारी जो कच्चा माल देते हैं अपनर्मृल्यन हो जाने से वह कीमतों को और अधिक बढ़ा सकने में असमर्थ होंगे।

रुपये का वर्तमान मूल्य चाहे वह उचित या अनुचित को कुछ भी रहा हो अब स्थिर सा हो गया है। अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ पाकिस्तान द्वारा रुपये के अवमूल्यन न करने से भारत के लिये कुछ कठिनाई अवस्य हो गई थी। पर यह कठिनाई भी सितम्बर १६५५ में पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन से और भारत के रुपये के वरावर श्रा जाने से दूर हो गईं। वर्तमान परिस्थित में रुपये के पूनर्मूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता, जब तक कि भारत के विदेशी व्यापार की स्थित में ऐसा परिवर्तन न हो जाय कि पूनर्मूल्यन करना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो । जाय श्रथमा विश्व के श्रन्य देश श्रपनी मुद्रा का मूल्य बदल दें श्रीर उसके परिखाम स्वरूप भारत के लिये भी पुर्नमूल्यन पर फिर से विचार करना श्रावश्यक न हो जाय । वर्तमान परिस्थित में तो रुपये के विनिमय मूल्य का प्रश्न ऐतिहासिक महत्व का ही रह गया है।

श्रध्याय ४३

विदेशी विनिमय संकट

भारतीय विदेशी विनिमय संकट का अर्थ यह है कि जितना धन हमें विदेशों से अपने निर्मात, प्राप्त अग्रुण, सहायतार्थ प्राप्त धन तथा विदेशियों द्वारा भारत में किये गये व्यय के लिये प्राप्त होना है उससे कहीं अधिक मात्रा में धन का विदेशों को उनसे किये गये आयात, श्रुण के सुगतान, श्रुन्य सुगतान तथा भारत द्वारा विदेशों में किये गये व्यय के लिये देने का प्रवन्ध करना है। पिछले दो वर्षों से भारत में ऐसा ही संकट उत्पन्न हो। गया है। १६५६-५७ में जब कि भारत का दायित्व पद्य १२०५ करोड़ रूपया और आदेय पद्य ८६८,६ करोड़ रूपया था भारत के सुगतान संवतन में २०६ करोड़ रूपयों का घाटा था, जो कि १६५७-५८ में श्रीर अधिक वहकर ३७६ करोड़ रूपयों का घाटा था, जो कि १६५७-५८ में श्रीर अधिक वहकर ३७६ करोड़ रूपया हो गया क्योंकि दायित्व पद्य में १२८५ करोड़ रूपया श्रीर आदेय पद्य में १०८-२ करोड़ रूपया हो गया था। इसके परिखामस्वरूप विदेशी आदेय पद्य १६५६-५७ में २३० करोड़ रूपयों से और १६५७-५८ में २४२ करोड़ रूपयों से कभी आ गयी।

भारत के पींड पावने की मात्रा जो कि देश के विभाजन के पहिले १७३३ करोड़ रुपये श्रीर विभाजन के पश्चात् १५१६ करोड़ रुपये थी धीरे-धीरे घटती रही है। फिर भी १६५५ के श्रन्त में उसकी मात्रा ७३५ करोड़ रुपये श्रीर १६५६ के मार्च महीने के श्रन्त में ७४६ करोड़ रुपये थी। परन्तु विदेशी विनिमय संकट के कारण पींड पावने की मात्रा घट कर २६७ करोड़ रुपया १६५८ के मार्च के श्रन्त में श्रीर श्रगस्त १६५८ के श्रन्त में १८७ करोड़ रुपया हो गयी।

यह आशा की जाती थी कि द्वितीय पंचवर्णीय योजना द्वारा दिये गये श्रीधीकरण पर जोर के कारण व्यक्तिगत चेत्रों द्वारा सरकारी तथा मशीनरी, कब्चे माल तथा तांत्रिक ज्ञान के आयात में वृद्धि होने से भारत के विदेशी विनिमय साधनों पर भार आदि श्रिधिक बढ़ जायगा। योजना आयोग की आशा थी कि सम्पूर्ण योजना अवधि में अर्थात् १९५६-५७ से १९६०-६१ तक में कुल विदेशी विनिमय घाटा ११०० करोड़ रुग्यों का होगा। द्वितीय योजना ने हस घाटे को २०० करोड़ रुपयों तक भारत के पींढ पावने की सहायता से पूरा करने का विचार किया था। यह आशा की जाती थी कि लगभग १०० करोड़ रुपयों का विनियोग विदेशी पूँजीपतियों द्वारा भारत के व्यक्तिगत चेत्र में किया जायगा और सरकार

योजना काल में ८०० करोड़ रुपये ऋगा लेने में निदेशी सरकारों तथा संस्थाओं से निदेशों से प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी।

यह संकट योजना बनाने वालों द्वारा श्रव द्वितीय योजना काल में विदेशी विनिमय की मात्रा का अनुमान कम लगाने तथा विदेशों से प्राप्त विदेशी विनिमय के साधनों का अनुमान अधिक लगाने के कारण की गई भूल का परिणाम है। यहाँ यह बता देना श्रावश्यक होगा कि योजना श्रायोग के श्रनुमान श्रंशतः स्वेज संकट, जिसके कारण श्रधिकांश योजनाश्रों की लागत बढ़ गई थी तथा पाकिस्तान श्रीर भारत के पारस्परिक सम्बन्ध में श्रनायास तनाव श्रा जाने के कारण भारत की सुरत्ता पर विदेशी विनिमय के श्राधार पर अधिक व्यय करने से प्रमावित हुये थे। परन्तु इन दोनों वातों का पूरा विचार रक्खा जाय फिर मी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी विदेशी विनिमय की मात्रा का श्रतुमान, नितान्तं निराधार है। प्रथम योजना काल में २६ करोड़ रुपये भारत को विदेशी छाधन के रूप में कोलम्बो प्लान, फोर्ड फाउन्डेशन, वर्ल्ड वैंक तथा कुछ विदेशों द्वारा सहाय्य के अन्तर्गत प्राप्त हुये ये जिसमें से भारत केयल २०४ करोड़ रुपयों की ही प्रयोग मार्च १९५६ तक कर सका यह आशा करना कि ८०० करोड़ रुपये विदेशी स्रोतों के रूप में द्वितीय योजना काला में प्राप्त होंगे जबकि प्रथम योजनो काल में २९८ करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये ये उचित नहीं मालूम पहुंता । योजना श्रायोग मी यह समफने में भूल कर गया कि खाद्यान का श्रायात भारत के विदेशी विनिमय स्त्रोतों के लिये श्रत्यधिक भार उपस्थित करेगा जैसा कि द्वितीय योजना के मयम श्रीर द्वितीय वर्ष में ही लक्कित होता था।

योजना आयोग तथा सरकार की दूसरी वही भूल जिसने इतना हमें इतने संकट में डाल दिया वह विधिक विदेशी विनिमय वजट का न होना था। योजना बनाने वालों को यह बात स्पष्टता सममानी चाहिये थी कि दितीय योजना में जिस मात्रा के विनियोग की आशा की गई थी उससे योजना के प्रारम्मिक काल में विदेशी विनिमय की माँग बहुत अधिक वह जायगी। यदि विदेशी विनिमय का वार्षिक यजट बना लिया गया होता तो यह सम्भव होता कि हम अपने आयात का एक निश्चित कम बना लेते ताकि वे सारी गहविदयों जो उपस्थित हुई न होने पातीं। यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि १६५५ के मध्य तथा १६५६ में मशीनों, कच्चे माल तथा उपमोक्ता की बस्तुओं के आयात के लिये व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा बड़ी सात्रा के लाइसेन्स प्राप्त कर लिये गये थे और यही सारे संकट का कारण था। व्यक्तिगत व्यापारियों को इसके लिये दोषी उहराना अनुनित है क्योंकि वस्तु का निर्माण करने वालों तथा व्यापारियों के

लिये श्रावश्यक लाइसेन्छ लेना नितान्त स्वामाविक या जविक दितीय योजना ने वृद्धिमान श्रापिक क्रियाश्रों की श्राशा दिलाई थी। भारतीय व्यापारियों ने सरकार को व्यक्तिगत चेन्न में विनियोग की मात्रा बढ़ा कर पूर्ण सहयोग दिया इसलिये मशीनरी कञ्चा माल तथा उपभोक्ता की वस्तुश्रों का श्रापिक श्रायात होना स्वामाविक था। सारी किटनाई इसलिये उत्पन्न हुई कि सरकार ने १६५६-५७ तथा १६५७-५८ के लिये विदेशी विनिमय बजट नहीं बनाया श्रीर इसलिये श्रायात तथा श्रायात लाइसेन्स देने का कोई उपभुक्त कम नहीं बना सका! इसका परिणाम इसलिये मारत के विदेशी विनिमय स्रोतों को महान घाटा हुशा। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत को माल की पूर्त करने वाले विदेशों को दिसम्बर १६५७ के श्रन्त तक ८०० करोड़ रुपयों से लगाकर १००० करोड़ रुपयों तक देता था। यह मुगतान विदेशी विनिमय में श्रगले ३ वर्षों में करना ही होगा। इमारे सामने श्रव समस्या ३५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेशी विनिमय के रूप में इन दायित्वों का मुगतान करने के लिये विदेशो विनिमय की चालू श्रावश्यकता की मान्ना के श्रातिरक्त प्राप्त करने की थी।

गम्भीर प्रश्न तो यह है कि इस संकट से मुक्ति पाने के लिये किया क्या जाना चाहिये ? श्रांखल मारतीय श्रार्थिक सम्मेलन के ४० वें श्राधवेशन में जो कि १६५७ में दिसम्बर के श्रन्तिम सप्ताह में हुई थी जी० बी० श्रार० शिनाय ने यह तर्क उपस्पित किया था कि विदेशी विनिमय के संकट की दूर करने के लिये भारतीय रुपये का श्रवमूल्यन किया जाना चाहिये। यह उन्होंने इस विचार से कहा था कि रुपये के आ्रान्तरिक मूल्य में, जो कि बहुत अधिक मात्रा में गिर गया था क्योंकि विभिन्न वर्गकी वस्तुष्ठों का मूल्य भारत में ३ है से लगा कर ६ गुना तक युद्ध काल के पूर्व के मूल्यों की तुलना में बढ़ गया था और वास्य मूल्य में जो कि १ शि०६ पैन्स पर जो कि १६२७ में नियत्त कर दिया गया था श्थिर रहा है समानता होनी चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि रुपये का श्रवमूल्यन रुपये के वाह्य और श्रान्तरिक मूल्यों में समानता ले श्रायेगा परन्तु हमें तो भारतीय विदेशी विनिमय संकट को दूर करना है। रुपये का श्रवमूल्यन इस समस्या को इल नहीं कर सकेगा वरन् उसे श्रीर श्रधिक जटिल बना देगा क्योंकि श्रायात की हुई मशीनों कच्चे माल श्रीर खाद्याच का मूल्य क्पयों में बढ जायगा श्रीर इस प्रकार द्वितीय योजना की वित्त व्यवस्था करने में श्रिधिक वाघार उपस्थित हो जायगी। यह भी कहा गया है कि श्रायात की वस्तुश्रो का भारत भूमि पर आ जाने पर मूल्य और उनके बाजार मूल्य में अन्तर है और रुपये का अवमूल्यन इस अन्तर को दूर कर देगा और आयात की हुई वस्तुओं

का मूल्य वढ़ न पायेगा। परन्तु आयात की हुई वस्तुओं के मारत में आ जाने पर मूल्य तथा उनके विक्री मूल्य में अन्तर सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में तो है नहीं श्रीर यदि रुपये का अवमूल्यन किया गया तो उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनमें यह अन्तर नहीं है द्वितीय योजना की लागत बढ़ा देगा। क्योंकि अधिकांश वस्तुयें जैसे मशीने, कच्चा माल और खादान्न इस वर्ग में आती हैं रुपये का अवमूल्यन इसलिये कोई संतोष पद इल इस समस्या का नहीं है। इससे किसी सोमा तक नियात बढ़ सकता है क्योंकि भारतीय वस्तुओं का रुपये में बढ़ा हुआ मूल्य निश्चय ही उनके नियात में बाधक हैं। परन्तु भारतीय मूल्यों का ऊँचा स्तर एक मात्र अथवा मुख्य कारण भारतीय निर्यात के कमी का नहीं है। वस्तुओं के गुण तथा रूप को मी बालारों में लहाँ भारतीय माल विकता है आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह मी प्रश्न है कि क्या हम जितनी मात्रा चाहिये उतना निर्यात कर मी सकते हैं। अवमूल्यन इन मामलों में सहायक नहीं हो सकता और सम्भवतः विगति मी अधिक नहीं बढ़ा सकता। जो कुछ भी हो अवमूल्यन वड़ा ही निराशावादी उपाय है और उसका प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिये जब तक रियति उतनी निराशावनक न हो जाय। वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं मालूम होती।

मारत सरकार एक श्रोर उपमोक्ताश्रों की तथा श्रनावश्यक वस्तुश्रों के श्रायात को कम करने तथा निर्यात को बढ़ाने की दोइरी नीति का श्रनुसरण कर रही है श्रीर दूसरी श्रोर विदेशी सहायता ने श्रपने विदेशी विनिमय के साधनों को बढ़ा रही है। इसमें संदेह नहीं कि यह नीति विदेशी विनिमय की कमी को पूरा कर देगी। परन्तु श्रायात पर प्रतिवन्ध वस्तुश्रों का श्राधिक्य निर्यात करने के लिये न होने देगा क्योंकि ऐसी दशा में लोग देश में ही उत्पादित वस्तुश्रों का उपमोग श्रायात की हुई वस्तुश्रों के स्थान पर करेगे श्रीर इससे विदेशी विनिमय की श्रामद्ती इमारी घट नायगी। इसके श्रातिरिक्त मशीन कच्चे माल तथा उपमोक्ताश्रों की श्रावश्यक वस्तुश्रों का श्रायात घटाने की एक सीमा है जिसके श्रागे यदि द्वितीय योजना को कार्यान्वित करना है श्रोर लोगों को उपमोक्ता की वस्तुश्रों की न्यूनतम श्रावश्यकताश्रों को पूरा करना है। इस सीमा पर तो हम पहिले से ही पहुँच जुके है।

नहीं तक निर्यात का सम्बन्ध है इनको बहाने के लिये न्यक्तिगत श्रीर -सरकारी प्रयक्त किये गये हैं। "सरकार ने श्रानेकों उपाय निर्यात बहाने के किये हैं जिनमें से बहुत सी वस्तुश्रों पर निर्यात कर में कमी करना श्रायवा इटा देना, स्ती कपहों श्रीर श्रायडी तथा श्रातसी के बीनों के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से लाइसेन्स देना, मूँगफली की मात्रा का जिसके निर्यात पर श्रामी तक रोक लगी हुई थी

निश्चित करना, तथा श्रायातं की वस्तुश्रों के लिये श्रावश्यक वस्तुश्रों पर वस्ते तटकर तथा वस्तु कर की वापसी की कार्य प्रणाली को खरल करना आदि श्रिधिक प्रभाव शाली उपाय थे। एक निर्यात जोखिम बीमा कारपोरेशन की भी स्थापना की गई।" परन्तु ये उपाय पर्याप्त सिद्ध नहीं हुये श्रीर भारत के निर्यात को उसके वर्तमान स्तर से जो कि ६०० करोड़ ६० से लगाकर ७५० करोड़ रुपये तक प्रति वर्ष बढ़ाया नहीं जा सका जैसा कि द्वितिय योजना में सोचा गया था। इसके कारण निम्न थे-(i) भारत में श्रारोपित ऊँचे करके कारण निर्मात की भारतीय वस्तुश्रों के मूल्य में वृद्धि (ii) निर्यात वस्तुश्रों के निर्माण के लिये कच्चे माल, रसायनिक द्रव्य तथा मशीनरी की आवश्यक माला में अप्राप्यता, (iii) भारतीय काल की गुर्यों की दृष्टि से दीनता तथा उत्पादकों श्रीर निर्यात करने वालों की निर्यात भी वस्तुत्रों की पैकिंग तथा अन्य निर्यात बढ़ाने के लिये आवश्यक वातों के सम्बन्ध में श्रासावधानी, (iv) यू० एस० ए० तथा योरण द्वारा श्रापन श्रायात इन दिनों घटाने की नीति तथा पूर्वीय तथा दिल्लाण पूर्वीय देशों की निर्यात द्वारा स्त्राय की कमी, श्रीर (v) चीन तथा जापान द्वारा विरिष रूप से विदेशी वाजार में गहरी प्रति द्वन्दता का उपस्थित करना आदि । फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय निर्यात के वह जाने की पूरी खम्भावना है यदि (क) निर्यात वस्तुश्रों को श्रीर भी श्रधिक छूट तटकरों श्रीर केन्द्रिय वस्तुकरों से प्रदान की जाय, (ख) कम्पनियों की श्राय पर श्रारोपित करों को घटा दिया जाय, (ग) उपयुक्त वस्तुश्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा सहायता दी जाय श्रीर (ध) श्रायात किये हुये कच्चे माल तथा मशीनों पर जिनकी निर्यात वस्तुत्रों के उत्पादन में श्रावश्यकता है तथा श्रन्य निर्यात की जाने वाली वस्तुश्रों का रेल का भाड़ा उपयुक्त सीमा तक कम कर दिया जाय।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकीय वर्ल्डवैंक तथा विदेशी सरकारों से उपयुक्त मात्रा में ऋगा दिया गया है। सितम्बर १६५६ में योजना मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्द ने लोक सभा में कहा था कि भारत को अपनी दिवीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये विदेशों से ६५६ करोड़ रुपयों की सहायता मिल गई हैं जिसमें से ४०० करोड़ रुपये यू० एस० ए० से, १२३ करोड़ रुपये सोवियट संघ से, और ७५ करोड़ रुपये पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त हुये हैं। परन्तु इतने पर भी हमारे विदेशी विनिमय की कमी पूरी नहीं हा पाई और वह ग्राज भी चल रही है।

इस समस्या को सुलक्ताने का एक प्रमावशालो ढंग भारत में विदेशो पूँजी के प्रवाह को प्रोत्साहन देना होगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हाल के वर्षों में विदेशी पूँजी का भारत में प्रवाह बहुत कम हुआ है। रिजर्व बैंक आफ हन्द्रिया की गर्गाना के अनुसार १९५५ के दिसम्बर महीने के अन्त में विदेशी व्यापार विनियोग की मात्रा ४८१ करोड़ रुपये थी जो कि १६४८ के जुलाई के कारणों से १६३ करोड़ रुपये से अधिक थी। इसमें से १६५४ और १६५५ में हुई वृक्षि की मात्रा ६१ करोड़ रुपये थी। विदेशी व्यापार विनियोग के १९३ करोड़ रुपयों की वृद्धि जो कि वास्तव में वेवल १६० करोड़ रुपयों की वृद्धि थी क्योंकि ३५ करोड़ की वृद्धि तो कम्पनियों के आदेयों के पुनमूल्यन का परिणाम था-७ वर्ष की श्रविध में होने से वाधिक श्रीसत बहुत ही कम ठहरता है। परन्तु जैसा कि भारतीय श्रीद्योगिक हेलीगेशन ने-जिसने हाल में ही यू० एस० ए० कनाहा यू० के० फान्त श्रीर पश्चिमी जरंनी का दौरा किया है-वताया है कि यदि भारत में विदेशी पॅजी के लिये उन्तत वातावरण उत्पन्न कर दिया जाय तो विदेशी पँजी के भारत में श्रीधक मात्रा मे प्रवाहित होने की बहुत सम्भावना है। यह सुकाव भारत सरकार के समज्ञ एक बड़ी दिविधा की वात उपस्थित करता है। यदि विदेशी पँजी की श्राकार्षत करने के लिये करों को घटा दिया जाय तो योजना का श्रपने वर्तमान् रूप में कार्यान्वत किया जाना श्रीर भी श्रांधक कठिन हो जायगा वयों कि सरकार की श्राय घट जायगी श्रीर यदि करों को घटाया नहीं जाता तो विदेशी पंजी के मारत में प्रवाहित होने की सम्भावना नहीं होती और योजना का कार्यान्वित होना कटिन हो जायगा। इस समस्या का सुकाव यह है कि दितीय योजना को विक्षां की दर घटा कर काट देना चाहिये ताकि सरकार की कम श्राय डिर्ताय शेजना के कार्यान्यत करने के लिये पर्याप्त हो चके। दितीय योजना को काट देने से सरकार के 'लये यह सम्भव हो सकेगा कि वह करों में ऐसी कमी कर सके जिससे विदेशी पंजी आकर्षित हो। एक बार यदि भारत सरकार कर घटाने की आवश्यकता मान लेती है तब फिर कौन-कौन से कर घटाये जाने चाहिये इसका सुमाव उपस्थित कठिन न होगा। एसाइड इकनमिक रिसर्च की नेशनल काउन्सिल ने हाल के श्रामे एक श्राध्ययन में बताया है कि विदेशी व्यवसायिक संस्थात्रों में व्यवस्था सम्बन्धी कर्मचारियों पर कर भार इल्का होना चाहिये र्ह्यार करों से मुक्ति प्रदान करने वालों उपायों जैसे घर जाने का श्रवकाश श्रार विना किराये के रहने का स्थान देना श्रादि पर से प्रतिवन्ध हटा लेना चाहिये। क्योंकि विदेशी कम्पनियों के विनियोग पर कर भारत में संसार भर से अधिक है इसलिये काउन्सिल ने यह सुमाव उपस्थित किया है कि विदेशी कम्पनियों पर आरोपित सूपरटैक्स की रे छाना प्रति रुपया घटा देना चाहिये छीर विदेशी कम्पनियों के लाभ द्वारा णास ज्ञाय पर से तो सुपरटेक्स को पृर्ण रूप से हटा देना चाहिये। अधिक आयू पर, बोनस पर, सम्पत्ति कर तथा सनसन २३ ए० के अनुसार कम्पनियों पर आरोपित करों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। विदेशी पृंजीपितयों ने
भारतीय औद्योगिक ढेलीगेशन ने बताया था कि अपनी सरकार को भारतीय
करों को देने के पश्चात् जो ५% की रायल्टी सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई
थी उससे उनके हिस्से में आय का केवल १'८% ही बचताथा। यह आय विदेशी
विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिये बहुत ही नगराय था। यदि आवश्यक कर
छूट प्रदान कर दी जाय, और यदि विदेशी पृंजीपितयों के अधिकारियों द्वारा
अनावश्यक परेशानियों से रक्षा की जाय, तो यह सम्भव है कि भारत में विदेशी
पूंजी का प्रवाह बढ़ जाय। यह एक प्रभावशाली ढंग से हमारी विदेशी विभिन्नय
कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो सकेगा।

श्रध्याय ४४

पोएड पावना

द्वितीय विश्व युद्ध के समय श्रीर उसके बाद भारत के नाम पीएड पावना जमा होता गया जो भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब में लन्दन में जमा है। साधारण तौर पर केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रा रखते हैं परन्तु पीएड पावने की स्पिति इस विदेशी मुद्रा से कुछ भिन्न है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक श्रासानी से पीएड पावने को खर्च नहीं कर सकता। यह राशि भारत श्रीर ब्रिटेन की सरकारों की सहमति से ही खर्च की जा सकती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय श्रीर उसके वाद मारत के नाम पीयह पावना जमा होने के श्रनेक कारण हैं (१) ब्रिटिश सरकार ने मारतीय रिजर्व वैंक कानून की एक व्यवस्था का उपयोग किया जिसके श्रनुसार रिजर्व वैंक पीयहों का रुपयों में विनिमय करने को विवश था। ब्रिटिश सरकार ने यह धनराशि श्रपने युद्ध के लिए मारत में व्यय की। इस प्रकार लन्दन में पीयह मारत के हिसाद में जमा होते गये श्रीर इसके परिणामस्वरूप जो मुद्रास्त्रीति बढ़ी उससे भारतीय जनता को श्रनेकों कहां का सामना करना पड़ा। (२) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार की श्रीर से जो कुछ व्यय किया वह पीयहों में चुकाया गया,। यह पीयह भी मारत के पीयह पावने के हिसाद में जमा हो गये। (३) युद्धकाल में भारत के श्रनुक्ल व्यापार सन्तुलन से श्रीर विनिमय नियंत्रण से जिसके श्रनुसार भारत को श्रपनी विदेशी मुद्रा का हिसाद रिजर्व वैंक को सौंप देना पड़ता था मारत के पीयह पावने के हिसाद में श्रीर विनिमय नियंत्रण से जिसके श्रनुसार मारत को श्रपनी विदेशी मुद्रा का हिसाद रिजर्व वैंक को सौंप देना पड़ता था मारत के पीयह पावने के हिसाद में श्रीर वृद्धि हुई। इस प्रकार यह पींह पावने की राशि मारत हारा विवश होकर की गई बचत के समान है क्योंकि भारतीयों को पीयह पावना जमा होने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप फैली मुद्रास्क्रीति के कारण श्रपने रुपयों के मूल्य के बरादर पर्याप्त सामान नहीं मिल सकता था।

पावना घटाने का प्रयत्न—ब्रिटिश सरकार ने पौरह पावने की राशि को कम करने का प्रयत्न किया परन्तु वह असफल रही। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से देश में काफी असन्तोष फैला। वास्तव में पौंड पावने को घटाने की माँग का आँग्ल-अमरीकी ऋग्य सममौते में निहित अमरीकी मस्ताव ने समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने पावना घटाने के सम्बन्ध में अपने पज्ञ में यह तर्क दिये कि— (१) युद का मार भारत की अपेज्ञा ब्रिटेन पर कहीं अधिक पड़ा और चूँकि

युद्ध में दोनों साथ साथ थे श्रीर जापान के विरुद्ध लड़ाई में भारत की सुरज्ञा का ही प्रश्न मुख्य रूप से निहित था इसलिये भारत सरकार को ही युद्ध के व्यय का श्रिधिकांश भार स्वयं वहन करना चाहिये। चूँ कि युद्ध में न्यय होने के कारण पौंड पावना जमा हम्रा इसलिए उसमें कटौती करनी चाहिए जिससे न्यय का ऋधिकांश मार भारत वहन करे । परन्तु यह तर्क नहीं है । यह सत्य है कि युद्ध भारत श्रीर ब्रिटेन ने साथ-साथ लड़ा श्रीर भारत की जापानी श्राक्रमण से रज्ञा की गयी। परन्तु यह भी उतना ही सत्य है, जैसा कि तब मारत के वायसराय ने भी स्वीकार किया, कि बिना भारत के सहयोग के ब्रिटेन की हार हो सकती थी और इसके भयंकर परिणाम होते। इसके साथ ही त्याग की समानता का मान देश की आर्थिक स्यिति होनी चाहिए निसका ज्ञान देश के प्रति न्यक्ति की श्रीसत स्राय स्रीर उसके रहन-सहन के स्तर से होता है। यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन की जनता का स्तर भारतीय जनता से ऋषिक ऊँचा है। १६३६-४० में भारत का युद्ध सम्बन्धी व्यय केवल ५० करोड़ रुपया था और जापान के युद्ध में शामिल होने से पहले यह व्यय बहुकर ७५ करोड़ रुपये हो गया। जापान के युद में शामिल होने से भारत का युद्ध सम्बन्धी व्यय बहुत बद्धा श्रीर १६४४-४५ में ४५० करोड़ रुपया हो गया। इससे स्पष्ट है कि जापान के युद्ध में भाग लेने के बाद भारत ने बहुत श्रिधिक व्यय का भार वहन किया।

- (२) ब्रिटिश सरकार का दूसरा तर्क यह था कि मारत ने ब्रिटिश सरकार को अधिक कीमत पर सामान वेचा जिससे यह पावना जमा होता गया और चूँ कि यह कार्य अनुचित था इसिलिये इसे पींड पावना घटाकर ही ठीक किया जाना चाहिए। ब्रिटेन की राष्ट्रीय व्यय की जाँच करनेवाली संसदीय समिति ने पींड पावने के प्रश्न की जाँच की और यह बात स्वीकार की कि भारत ने ब्रिटिश सरकार को उचित कीमत पर सामान वेचा है और इसमें किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं लिया गया है। वास्तव में भारत ने ब्रिटिश सरकार को सामान बाजार-कीमत पर नहीं बल्कि बाजार कीमत से कम और नियंत्रित कीमत पर दिया। मारत को पहले सामान प्राप्त करना पड़ता था और तब ब्रिटिश सरकार के हाथ वेचना पड़ता था। इसलिए इस तर्क के आधार पर पींड पावना घटाना किसी भी रूप में उचित नहीं है।
- (३) पौरड पावना घटाने के सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि ब्रिटेन को श्रानेक किटनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है और वह पौरड पावना चुका सकने की स्थिति में नहीं है। यह बताया गया कि ब्रिटेन ऐसा निर्यात कर सकने में श्रासमर्व है जिसका उसको कुछ, प्रतिफल न मिले। यह सत्य है कि युद्ध के

पश्चात् ब्रिटेन को बहुत किनाइयों का सामना करना पड़ा, परन्तु यदि भारत श्रीर ब्रिटेन का मिलान किया जाय तो पता चलेगा कि भारत की स्थिति श्रपेका- कृत बहुत खराब है। इसलिए पौरड पावना घटाने का प्रश्न हो नहीं उठता है। इस बीच में ब्रिटेन की राष्ट्रीय श्राय मारत की राष्ट्रीय श्राय से काफी श्रिषक बढ़ी। यह श्रनुमान लगाया गया है कि यदि पींड पावने की मद में से १० से १२ करोड़ पींड प्रतिवर्ष चुकाया जाय तो इससे ब्रिटेन की राष्ट्रीय श्राय में १ से १३ प्रतिशत की कमी श्राती है। यह कमी बहुत श्रिषक नहीं।

पौड पावने के सम्बन्ध में बारवार जो प्रयत्न किये गये उनसे भारत में भारी असन्तोप फैला परन्तु ग्रंत में ब्रिटिश सरकार की चेतना लीटी श्रौर श्रगस्त १६४८ में वित्त मंत्री ने मारतीय संसद को बताया कि ब्रिटिश सरकार ने पौंड पावने के विवाद को समाप्त कर भारत को सुद्ध कार्य में न्यय हुई ५ करोड़ ५० लाख पौंड की राशि चुकाना स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने इसका यह ठीक श्र्य लगाया है कि इस धन राश्य की बस्ली द्वारा दोनों सरकारों के बीच पौंड पावने का हिसाब पूर्ण रूप से चुकता हो जायगा श्रीर पौंड पावना घटाने का प्रश्न फिर भविष्य में कभी नहीं उठेगा।

पौंड पावना सममौते

विटिश सरका के साथ सममौते के अनुसार ग्रेटिबिटेन में भारत का जो हिसाब सका हुआ था वह चालू खर्च के लिए खोल दिया गया। पींड पावने की इस राशि में प्रतिवर्ष खर्च के लिए कुछ अंश देने के सम्बन्ध में १६४७ से अनेक सममौते किये गये।

१६४७ का सममौता—१४ श्रगस्त १६४७ को भारत सरकार श्रीर विटेन की सरकार के बीच ३१ दिसम्बर १६४७ तक के लिये एक वित्त सममौता किया गया। सममौते की शतों के श्रनुसार, जो १५ जुलाई से लागू हुई, रिजर्व बैंक ने वैंक श्राफ इंगलैंड में दो खाते खोले ये—नम्बर १ (यह चालू खाता था) श्रीर नम्बर २ (यह चन्द खाता था)। १४ जुलाई १६४७ को भारतीय रिजर्व वैंक के नाम में कुल १ श्ररब १६ करोड़ पींड जमा कर दिये गये। यह राशि नम्बर २ खाते में जमा हो गयी। शेष राशि ६ करोड़ ५० लाख पींड नम्बर १ खाते में जमा कर दी गयी। इनमें से ३ करोड़ ५० लाख पींड वालू खर्च के लिए श्रीर ३ करोड़ पींड सुरहित कोष में जमा कर दिये गये। सममौते में यह व्यवस्था की गयी कि नम्बर १ खाते की राशि किसी भी सुलम या दुर्लम मुद्रा च्रित्र से लेन-देन में काम लायी जा सकेगी श्रीर वर्तमान की श्रावश्यकता पूर्ति के लिए इसका

पूरा उपयोग किया जा सकेगा। यदि समकीते की तिथि के बाद चालू लेन-देन के लिए कुछ भी रकम पींड में मास हो और यदि नम्बर र खाते में से समकीते की धारा ४ और ७ के अनुसार कोई भी रकम मशीनों इत्यादि में न्यय की गई हो तो उसे नम्बर १ खाते में जमा कर दिया जायगा। नम्बर २ खाते की रकम चालू कारोबार में खर्च नहीं की जा सकती है। उसे केवल कुछ पूँजी की अदला-बदली में ही प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके लिए दोनों देशों की सरकार सहमत हो। इस व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक हो गया कि नम्बर १ खाते के व्यय पर नियंत्रण रखा जाय। यद्यपि भारत स्टिलंग चेत्र में ही रहा है फिर भी पींड और पींड चेत्र की मुद्राओं की अदायगी पर वही प्रतिबन्ध लगाये गये जो उन चेत्रों पर लम्मू हैं जन्हें पींड चेत्र नहीं कहा जाता है।

१६४८ को सममांता—१५ फरवरी १६४८ को ब्रिटिश तथा भारत सरकार के बीच पत्र-व्यवहार के द्वारा १६४७ के बित्त समभौते की अवधि ३० जून १६४८ तक बढ़ा दी गईं। अवधि बढ़ाने के सममौते के अनुसार नम्बर २ खाते में जमा से १ करोड़ ८० लाख पीन्ड ३० जून १६४८ तक चालू खर्च के लिए नम्बर १ खाते में जमाकर दिया गया। पौरड पावना सममौता जिस पर १५ फरवरी १६४८ को हस्ता च्चर किये गये थे कुछ परिवर्तनों के साथ पुन: ३० जून १६५१ तक बढ़ा दिया गया।

जिस समय १६४८ का समकीता तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया तब यह निश्चय किया गया कि म करोड़ पौंड जो नम्बर १ खाते में जमा है ३० जून १६४२ को समाप्त होने वाले वर्ष के चालू खर्च के लिए दिया जायगा और जुलाई १६४८ से जून १६४६ तक कोई नयी रकम नहीं दी जायगी। इस बात पर दानों पक्ष सहमत हुए कि अगले हर वर्ष में अर्थात् जुलाई १९४६ से जून १९५० और जुलाई १६५० से जून १६५१ तक ४ करोड़ पींड चालू खर्च के लिए दिया जायगा। इस प्रकार भारत ने यह सोचा कि तीन वर्ष के अन्दर चालू खर्च के लिए १६ करोइ पींड की प्राप्ति हो जायगी। परन्तु श्रप्रत्याशित रूप से श्रत्यधिक श्रायात हो जाने के कारण चाल खर्च के लिए जो रकम बची वह अपर्याप्त रही। भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मरहल इंगलैंड गया और ब्रिटिश सरकार जून १६४६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए = करोड़ १० लाख पींड चुकाने के लिए सहमत हो गयी। पूर्व सममीते में इस वर्ष के लिए कोई रकम नहीं रखी गई थी। यह भी निश्चय किया गया कि मई १६४६ में रह हो जाने से पूर्व सरकारी लाइसेंस नम्बर ११ (O. G. L. XI) के श्रन्तर्गत देयधन सुकाने को ५ करोड़ पींड श्रीर दिया जायगा । इसके साथ ही जून १६५० और जून १६५१ को समाप्त होनेवाले प्रतिवर्ष के लिए दी जाने वाली धनराशि ४ करोड़ पौंड से ५ करोड़ पौंड कर दी गयी।

मारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को गोदामों और कारखानों के लिए जिनकी कीमत ३७ करोड़ ५० लाख पाँड आँकी गयी है १० करोड़ पाँड कीमत चुकाई। इसके साथ ही केन्द्रीय और पादेशिक सरकारों द्वारा दी जाने वालों पेन्शनों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कमशः १४ करोड़ ७६ लाख पाँड और २ करोड़ ५ लाख पाँड के साठ साल में अदा होने वाले वार्षिकी-पत्रों को पूँजी रूप में खरीदकर चुकाया। यह रकम भारतीय पाँड पावने की राशि में से चुकायी जिसके फलस्वरूप पावना हतना ही कम हो गया।

१६५१ का समझाता-पींड पावना सममीते की श्रवि जो जून १६५१ को समाप्त हो गयी थी, ३० जून १९५७ तक बढ़ा दी गई। इसके बाद यह सम-भौता समाप्त हो गया। इस समझौते के अन्तर्गत (१) ३१ करोड़ पींड की रकम नम्बर २ खाते में से नम्बर १ खाते में जमा की गई। यह रकम भारतीय रिजर्व वैंक के नाम मुद्रा के सुरिच्चत कांप के रूप में जमा हुई। (२) यह भी व्यवस्था की गयी कि १ जुलाई १६५१ से श्रारम्म होने वाले वर्ष के बाद श्रगले ६ वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में श्रीवक से श्रीवक ३ करोड़ ५० लाख पींड नम्बर २ से नम्बर १ खाते में जमा किया जायगा। परन्तु इसमें यह शर्तें लगायी गर्यी कि (श्र) इस रकम की अदला-बटली इस उद्देश्य से की जायगी कि नम्बर १ खाते में न्यूनतम रकम ३४ करोड़ पींडवनी रहें या दोनों सरकारों के बीच वातचीत होने के बाद इसमें कम राशि भी जमा रह सकती है, (व) यदि ३ करोड़ ५० लाख पींड में से कुछ श्रंश १२ महीने की श्रविध में नम्बर १ खाते में जमा नहीं की गई तो उसे श्रम खे वर्ष में जमा की रकम में जोड़ दिया जायगा, (७) यदि भारत चरकार को यह अनुमन हो कि १२ महीनों के अन्दर किसी समय नम्बर २ खाते से ३ करोड़ ५० लाख पींड से अधिक जाने वाली रकम की श्रावश्यकता है तो श्रगले वर्प में नम्बर १ खाते में जमा की जाने वाली रकम में से ५० लाख पींड तक दोनों सरकारों में विना किसी प्रकार के विचारं विमर्श के लिया जा सकता है। यदि भारत सरकार का श्रवुमान हो कि इससे श्रधिक रकम की श्रावश्यकता होगी तो इस सम्बन्ध में दोनों सरकार परस्पर विचार विमर्श करेंगी श्रीर (द) ३० जून १९५७ को नम्बर २ खाते में जो जमा रकम बचेगा वह स्वामाविक है। नम्बर १ खाते में जमा कर दी जायगी।

१६५१ के सममौते के श्रनुसार जो कार्य हुशा उससे पता चलता है कि चालू खर्च के लिए जो पींड प्राप्त थे उनका उपयोग नहीं किया जा सका। जून १६५१ के श्रंत तक जो रकम जमा की गई थी उसमें से १ जुलाई १६५१ को नम्बर १ खाते में ६ करोड़ पींड की रकम खर्च न हो सकने से बच गयी थी। इसके बाद जून १६५२ श्रीर जून १६५३ में ३ करोड़ ५० लाख पींड श्रीर जमा कर देने से चालू खर्च के नम्बर १ खाते में १६ करोड़ पींड की रकम जमा हो गयी। यदि भारत ने इस सारी रकम का उपयोग कर लिया होता तो पींड पावने की कुल रकम जो १ जुलाई १६५१ को लगभग प्पूछ करोड़ रुपये (६४ करोड़ ३० लाख ६० हजार पींड) थी, ६४४ करोड़ रुपये (४८ करोड़ ३० लाख ६० हजार पींड) रह जाती। परन्तु ३ जुलाई १६५३ को भारत के नाम पींड पावने की वास्तविक रकम ७१२ करोड़ रुपया (५३ करोड़ ३६ लाख ८० हजार पींड) जमा थी। इस प्रकार नम्बर १ खाते में ५ करोड़ ६ लाख २० हजार पींड की रकम खर्च होने से बच रही। ३ करोड़ ५० लाख पींड प्रतिवर्ष के हिसाब से चार वर्ष में नम्बर २ खाते से नम्बर १ खाते में जून १६५७ तक १४ करोड पींड जमा हो जायँगे। इस तरह जून १६५७ के अरंत तक चालू खर्च के लिये १६ करोड़ ६ लाख २० हजार पींड की रकम मिलेगी।

फरवरी १६५२ में भारत तथा ब्रिटिश सरकार के बीच पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप १६५१ के पींड पावना समसीते की अवधि ३० जून १६५७ तक बढ़ा ही गयी थी। जुलाई १६५३ में दोनों सरकारों ने विधिवत समसीते पर इस्ताद्धर करके वर्तभान समसीतों को निश्चित रूप दे दिया। १६५३ का समसीता केवल विधि के निर्वाह के लिए किया गया। इसमें पींड पावने की अदायगी के सम्बन्ध में पूर्व समनीतों में किसी मकार का परिवर्तन नहीं किया गया। नम्बर २ खाते से नम्बर १ खाते में पींड की राशि १६५१ के समसीते के अनुसार बदली जायगी और ३० जून १६५७ को नम्बर २ खाते में जो कुछ रकम शेप होगी वह स्वभाविक ही चालू खर्च के लिए नम्बर १ खाते में जमा हा जायगी।

ख्रालोचनाएँ—पींड पावना सममीते के सम्बन्ध में ब्रालोचकों का मत है कि चालू ध्यय के लिए जो रकम निर्धारित की गई है वह भारत की ख्रावश्य-कताख्रों को देखते हुए अपर्याप्त है। पूर्व के सममौते अल्पकालिक ये जिस्से इस राशि का उपयोग करने के लिए दीर्घकालिक योजना नहीं बनायी जा सकी थी। परिशाम यह हुआ है कि भारत की जनता के अपार कष्ट सहने के बाद जो पींड पावने की राशि जमा हुई वह उपभोग के सामान का क्रय करने में या कुछ अन्य कार्यों में च्यय होती गयी और इसका उपभोग मशीनों, टेकनिकल सामान श्रीर अन्य उत्पादन में सहायक सामानों का आयात करने में नहीं किया जा सका। १६५३ का सममौता दीर्घकालिक है और इस रूप में पूर्व सममौतों से अधिक अच्छा है। परन्तु इसके अन्तर्गत भी चालू खर्च के लिये जो वार्षिक रकम निर्धारित की गई है वह पर्याप्त नहीं हैं। कुछ वर्षों में तो भारत को जो थोड़ी-बहुत रकम पर्याप्त हुई उसका भी उपयोग नहीं किया जा सका। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह रकम ग्रावश्यकता से श्रिधिक थी। इसके केवल यह पता चलता है कि समसीता श्रह्मकालिक होने के कारण मारत इस राशि के त्यय की कोई योजना नहीं बना सका इसलिए यह वकाया बच रही। भारत में यह प्रायः सुसाया गया है कि पौड पावना समसीते में यह शर्त भी रखी जाय कि भारत को चालू खर्च के लिए प्रति वर्ष जो राशि दी जायगी उसके कुछ श्रंश से विटिश सरकार उचित कीमत पर बड़ी मशीनें इत्यादि खरीद कर भारत को दे। परन्तु विटिश सरकार ने यह शर्त कभी स्वीकार नहीं की। इस कारण इस पौड पावने की राशि का भारत के श्रीखोगिक विकास की प्रोत्साहन देने में उपयोग नहीं किया जा सका।

पूर्व सममीतों के श्रनुसार प्रतिवर्ष जितनी राशि भारत को चालू खर्च के लिए दी गई यदि उसका निश्चित श्रविध के भीतर उपयोग नहीं किया गया तो बाद में श्रावश्यकता पहने पर उस धन को व्यय नहीं किया जा सकता था श्रीर न तो श्रावश्यकता पहने पर श्रिधिक धन दिया जाता था। इससे सममीता कुछ रिथर सा हो गया था इसमें श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। बाद के सममीतों में यह दोनों दीप दूर कर दिए गये हैं श्रीर यदि एक वर्ष में निर्धारित रकम खर्च न की जा सकी तो उसे श्रगले वर्ष के लिए निर्धारित चालू खर्च की रकम में जोड़ दिया जाता है श्रीर कमी श्रावश्यकता पढ़ने पर निर्धारित राशि से श्रिक भी पाप्त किया जा सकता है।

सममीतों के विरुद्ध एक गंभीर श्रारोप यह लगाया जाता है कि भारत के नाम जमा पींड पावने की राशि पर भारत को बहुत कम व्याज दिया जाता है। व्याज की श्रीसत दर ०'७८ प्रतिशत प्रतिवयं पड़ती है। श्राज जब कि भारत तथा ब्रिटेन में वैंक के व्याज की दर बढ़ा दी गई है श्रीर प्राय: सभी व्याज बढ़े हैं तब पींड पावने की राशि पर भारत को दिया जाने वाला व्याज बहुत कम है। भारत सरकार ब्रिटिश सरकार से यह व्याज की दर बढ़वाने में श्रिस्त रही है श्रीर न वह यह श्रनुमित प्राप्त कर सकी है कि इस पावने को श्रिमिक श्राय वाले ऋग्रपात्रों में लगाया जाय।

यह कहा गया है कि भारत में ब्रिटेन के युद्ध सम्बन्धी कार्यों में श्रीर पेन्शन इत्यादि में बहुत श्रिधिक धन खर्च किया गया है जिससे पींड पावने की राशि घट गई है। परन्तु इस श्रालोचना में विशेष तथ्य नहीं है।

वार-वार यह मुक्ताव दिया जाता रहा है कि पौंड पावने राशि को भारत में ब्रिटिश कारखान इत्यादि को अनिवार्य रूप से लेने (Compulsory acquisition) में खर्च किया जाय परन्तु यह कार्य भारत की श्रोद्योगिक नंति क विषद है भारत की श्रीद्योगिक नीति में देश के विकास के लिए विदेशी उद्योगों को उपयुक्त स्थान दिया गया है। इस सुकाव का भारत सरकार पर कोई प्रमाव नहीं पड़ा।

भारत के नाम जमा पौंड पावने को कुल रकम विभाजन से पहले १,७३३ करोड़ रुपये थी श्रीर विभाजन के पश्चात् १,५१६ करोड़ रुपये थी। इसमें से अधिकांश उपभोग के सामानो श्रीर श्रन्य सामानो पर खर्च किया गया श्रीर दिसम्बर १६५१-५२ में रिजर्व वैंक के हिसाब में पौंड पावने के रकम १६१ करोड़ रुपयों से घट गई। यह कमी होने की प्रवृति जुलाई १६५२ तक चलती रही श्रीर पौरड पावना केवल ६७३ करोड़ रुपयों का हो गई गया। इसके बाद से स्थिति बदली श्रीर १६५३ के तीसरे चरण में पौंड पावना लगभग ७०० करोड़ रुपया हो गया। १६५५ के श्रन्त में पौंड पावना ७३५ करोड़ रुपया हो गया था जबिक १६५४ में कवल ७३१ करोड़ रुपया था। हाल के विदेशी विनिमय के संकट के फलस्वरूप करेन्सी के सुरिचत कोष को छोड़ कर भारत के पौरड पावने लगभग समाप्त हो गये हैं। १६५६-५७ के प्रारम्भ में पौरड पावने की राशा ७४८ करोड़ रुपया थी किन्तु १६५६-५७ के प्रारम्भ में पौरड पावने की राशा ७४८ करोड़ रुपया थी किन्तु १६५६-५७ के प्रारम्भ में पौरड पावने की राशा ७४८ करोड़ रुपया थी किन्तु १६५६-५७ के प्रारम्भ में पौरड पावने की राशा ७४८ करोड़ रुपया थी किन्तु १६५६-५६ के प्रेरणा में यह घटकर २६७ करोड़ रुपया की हो गई।

भ्रध्याय ४५

हुएडी वाजार

श्रवीत में भारतीय द्रव्य वाजार में उचित रीति से संगठित हुगडी वाजार का श्रमाव रहा है। हुगडी वाजार का किसानों तथा व्यापारिक वैंकों के लिए वहुत श्रिषक महत्व है। हुगडी वाजार से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ते जाने में सहायता मिलती है क्योंकि सामान के विकेता को खरीद से कीमत मिलने के पहले ही उसके सामान की कीमत मिल जाती है। फसल को श्रन्यत्र मेजने के लिए किसानों को श्रन्यत्रालिक वित्त सहायता दी जाती है। वैंक व्यवस्था में श्रन्यकाल के लिए जमाधन को हुएडी वाजार के द्वारा कई कार्यों में लगाया जा सकता है। भारतीय केन्द्रीय वैंकिंग जाँच समिति (१६३१) ने हुएडी वाजार के महत्व को सममकर उसका विकास करने के लिए श्रनेक सुकाव दिये परन्तु कुछ समय पहले तक भारतीय विवर्ष वैंक ने इसे बढ़ावा देने के सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की। हुएडियों के लिए पहले मुलतानी हुएडी के रूप में स्वदेशी वाजार की सुविधा प्राप्त थी परन्तु श्रनुमान है कि इस प्रकार की हुएडियों का कुल कारोवार किसी समय भी १० करोड़ रूपये से श्रिषक नहीं बढ़ सका जव-कि व्यस्त कारोवार के समय मारतीय द्रव्य वाजार को १५० करोड़ रुपये की स्थावश्यकता होती है।

उचित रीति से संगिटत हुएडी बाजार का श्रव तक विकास नहीं हो पाया है क्योंकि (१) १६३७ श्रीर १६४१ में रिजर्व बैंक ने स्वदेशी बैंकरों को हुएडियों के मुनाने की इस शतं पर मुविधा देने की स्वीकृति दी कि वे श्रपना श्रन्य कार्य लेन देन से श्रलग करलें, श्रीर एक निश्चित श्रविध के मीतर श्रन्य कार्य करना छोड़ दें, तथा श्रपना हिसाब किताब इस ढंग पर लिखकर तैयार करें कि उनका परीच्या श्राहिटर द्वारा हो सके श्रीर रिजर्व बैंक भी उसे देख सके। ये प्रस्ताव बैंकरों को स्वीकार नहीं हुए क्योंकि वे श्रपना श्रन्य कार्य छोड़ने को तैयार न थे। स्टेन्डर्ड मुद्दती हुएडी (Usance bill) न होने से श्रीर विभिन्न प्रकार की हुएडियों को जारी करने के तरीकों श्रीर शतों में बहुत अधिक विभिन्नता होने से रिजर्व बैंक हुएडी बाजार का विकास कर सकने में श्रमभर्थ रहा है। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक को केवल श्रनुकूल परिस्थितियों की प्रतीद्या करने की श्रपेद्या हुएडी के प्रामाणिक रूप का विकास करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। रिजर्व बैंक ने इस प्रकार का बिकास करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। रिजर्व बैंक ने इस प्रकार का बीई प्रयक्त नहीं किया श्रीर हुएडी बाजार का विकास न हो सका,

(२) रिजर्व वें क की स्थापना के पहले भी हुण्डी बाज़ार का विकास नहीं हो सका क्यों के भारत में इम्पीरियल बैंक तब केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के कार्य करता या और इस कारण अन्य व्यापारिक बैंक व्यापार नीति के कारण अपने प्रिविद्यों वेंक को बताना नहीं चाहते थे; (३) नकद रुपया उधार देने (Cash Credits) की प्रणाली ने, जिसके अन्तर्गत व्यापारिक बैंक अपने प्राहकों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, हुण्डी बाजार के अभाव का अनुमव नहीं होने दिया। यह व्यवस्था ऋणा देने और लेने वाले के लिए सुविधाजनक होती है। इन सब कारणों ने मिलकर भारत में एक सुव्यवस्थित हुण्डी बाजार के विकास में बाधा डाली है।

विछले कुछ वर्षों में हुण्डो चेत्र की प्रवृति, यथासम्भव स्वयं भुगतान हो जाने वाली हुण्डियों के द्वारा समियिक मुद्रा के प्रसार करने को महत्ता देने की रही है। बचत कम होने, कीमर्ते ऊँची होने, श्रायात श्रिषक मात्रा में होने श्रीर सामियक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए सरकारी ऋणपत्रों (Securities) को रिजर्व बैंक के हाथ वेच देने से श्रमुस्चित वैंकों की स्थित ऐसी नहीं रही कि व्यापार सम्बन्धी मांगों की पूर्ति कर सर्वे। ऐसा करने के लिए श्रमुस्चित वैंक को श्रमेक-कठिनाहयों का सामना करना पड़ा है। इसलिए यह श्रावश्यक हैं कि स्टेंडर्ड हुण्डियों का विकास करके हन कठिनाहयों को दूर करने का हद प्रयत्न किया जाय।

रिजवे वैंक की योजना—जनवरी १६५२ में रिजवे वैंक ने भारत में सीमित हुएडी बाजार स्थापित करने की योजना बोबित की । रिजवे वैंक की योजना का उद्देश्य भारतीय द्रव्य बाजार को कुछ साख सम्बन्धी सुविधा देना था। अतीत में अनुस्चित वैंक अपनी सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी तथा अन्य मान्यता प्राप्त ऋगुपपत्रों को रिजवे वैंक के हाथ वेचकर कर दिया करते थे या भारतीय रिजवे वैंक कान्न की घारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत सरकारी ऋगुपपत्रों के बदले रिजवे वैंक से कुछ धन उधार ले लिया करते थे। नई योजना के अनुसार भारतीय रिजवे वैंक कान्न की धारा १७ (४) (सी) के अन्तर्गत अनुस्चित वैंकों को रिजवे वैंक से सहायता प्राप्त होती है।

योजना की मुख्य विशेषता यह है कि श्रनुस्चित बैंक ऋगा, श्रोवर ड्राफ्ट इत्यादि के बदले जो डिमांड प्रामेसरी नोट्स प्राप्त करते हैं उनका एक श्रंश मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र में बदल सकते हैं जिनके मुगतान की श्रवधि १० दिन होती है। व्यापारिक बैंक सामान्यतः ऐसे ऋगों के सम्बन्ध में श्रांशिक पुन्सुगतान की श्रनुमित प्रदान करते हैं। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि श्रनुस्चित बैंकों द्वारा दी गई ऋगु इत्यादि की रकम के एक ग्रंश के बदले बैंक डिमांड प्रामेस्री नोट्स ले लें जिस से भूगो भविष्य में अपनो श्रावश्य म्तानुसार उस रुपये में लेन-देन कर सके। साथ ही ऋगा के शेप छंशा के बटले बँक छागामी तीन महीनों में भूगी की न्यूनतम श्रावश्यकना की पूर्ति के लिए उसमें मृद्ती प्रतिशा पत्र लेने हैं जिनकी भुगतान की अवधि ६० दिन हीती है। अनुस्चित वैंक रिजर्व वैंक से भारतीय रिजर्व वैंक की कानून की घारा १७ (४) (छी) के श्रन्तर्गत मुद्दती ह्यडी के ब्राघार पर ऋग ले सकता है। ब्रनुस्चित बैंको को इस प्रकार की हरिएडयाँ रिजर्व वैंक को सीपते समय (७) प्रत्येक हुएडीं का विवन्ग देना पड़ता है जिसमें हुएडी खेने वाले का नाम, रक्षम, भुगतान की तिथि श्रीर मिति कांटे की टर इत्यादि होती हैं; (व) यह प्रमाणित करना पड़ता है कि हुण्डीवाला हुन्ही की नकम का सुगतान करने में समर्थ है। रिजर्व वैंक श्रनुस्चित वैंकों के साथ साख व्यापार श्रारंभ करते समय केवल जमानत की ही जाँच नहीं करता वान, यह भी जाँच करता है कि वैंक का कार्य किस प्रकार चलाया जा रहा है श्रीर इस वात की देख-रेख करता है कि मन्दे कारोबार के समय बैंक अपनी समता मे अधिक व्यापार तो नहीं करता। रिजर्व वैंक विना कारण वताये किसी भी श्रवसुचित वैंक की हन्डी लेने से इन्कार कर सकता है।

श्रारम्म में यह योजना केवल उन्हों बैंकों तक सीमित रखी गई थी जिनका जमाधन १० करोड़ काये से कम नहीं या। प्रत्येक श्रृण की रकम कम से कम २५ लाख क्यये निर्घारित की गई थी श्रीर इसी प्रकार प्रत्येक हुन्डी की न्यूनतम रकम एक लाख क्यये निर्घारित की गई थी। जून १६५३ में यह योजना ऐसे श्रृनुस्चित वैंकों तक प्रसारित कर दी गई जिनका जमा धन (जिसमें विदेश में जमा धन भी सम्मिलित किया गया है) ५ कगेड़ श्र्यया इससे श्रीक है श्रीर उमे १६४६ के वैंकिंग कम्पनी ऐक्ट की २२ वी घाग के श्रृनुसार लाइसेन्स प्राप्त है। जुनाई १६५४ में यह योजना उन सब श्रृनुस्चित वैंकी तक प्रसारित कर दी गई जिन्हें १६४६ से वैंकिंग कम्पनी ऐक्ट क श्रृनुस्चित वैंकी तक प्रसारित कर दी गई जिन्हें १६४६ से वैंकिंग कम्पनी ऐक्ट क श्रृनुस्चित वैंकी तक प्रसारित कर दी गई जिन्हें १६४६ से वैंकिंग कम्पनी ऐक्ट क श्रृनुस्चित वैंकी तक प्रसारित कर दी गई जिन्हें १६४६ से वेंकिंग कम्पनी ऐक्ट क श्रृनुस्चित वैंकी तक प्रसारित कर दी गई जिन्हें १६४६ से वेंकिंग कम्पनी ऐक्ट क श्रृनुस्चित मात्रा २५ लाख से घटाकर १० लाख क्यये कर दी गई श्रीर प्रत्येक श्रुण की न्यूनतम मात्रा २५ लाख से घटाकर ५०,००० क्यया कर दी गई श्रीर प्रत्येक हुन्ही का मात्रा एक लाख से घटा कर ५०,००० क्यया कर दी गई श्रीर प्रत्येक हुन्ही का मात्रा एक लाख से घटा कर ५०,००० क्यया कर दी गई श्रीर प्रत्येक हुन्ही का मात्रा एक लाख से घटा कर ५०,००० क्यया कर दी गई श्रीर प्रत्येक हुन्ही का मात्रा एक लाख से घटा कर ५०,००० क्यया कर ही गई गिर हिससे वह योजना श्रियक लोकप्रिय हो गई श्रीर एक्ट की घारा १७ (४) (स) के द्वारा टी गई सुविधाश्रों का तब में प्रयोग भी श्रिषक हुत्रा है श्रीर १६५६ के श्रारम्भ में लगभग ४५ वैंक उसमें सम्मिलत हो सकते थे जब कि केवल २७ वैंक ही योजना के श्रारम्भ में भाग ले सकते थे।

इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए छीर इन्ही बाजार का शीध

विकास करने के लिए रिजर्व बैंक ने इस योजना के श्रनुसार श्रनुस्चित बैंकों को बैंक दर से है प्रतिशंत कम में द्रार्थात ३ प्रतिशत अपूर्ण दिया। अपूर्ण को मुद्दती हन्ही में बदलने के लिए जितने रुपये के स्टाम्प लगाये जाते हैं रिजर्व बैंक उपका श्राधा व्यय स्वयं देता है जिससे हुन्डी बाजार के विकास को श्रीर प्रोत्साहन मिल सके। यद्यपि २ श्राना प्रति हजार रुपये के हिसान से स्टाम्प सस्ता है पर रिजर्व वैंक ने इसका श्राधा व्यय अपने ऊपर लेकर सुविधा प्रदान की जिससे हुन्ही बाजार के विकास को प्रोत्साइन मिले । पर दुर्भाग्य से ये सुविधार्ये पहिली मार्च १९५५ से ग्रंशत: वापस ले ली गई ग्रीर ग्रब श्रमुखित वैंकों को इस योजना के श्चन्तर्गत बैंक दर से है प्रतिशत कम टर पर श्चर्यात ३ई प्रतिशत पर ऋग् मिलेगा श्रीर रिजर्व बैंक स्टाम्प पर व्यय नहीं देगा । १६५६ के मन्दी काल में (मई से लेकर िस्तम्बर तक) अनुसूचित बैंको के साल में बहुत कम संक्रचन हुआ अतएव बैंक ने नवम्बर १९५६ में उधार देने की दर में है% की वृद्धि करके उसे ३ ई% की दर के बराबर कर दिया जो सरकारी तथा श्रन्य स्वीकृति प्रांतभृतियों पर ली जाती है। मामिसरी नोट पर स्टाम्प ह्यूटी बहु जाने के फलस्वरूप उधार लेने की प्रमावपूर्य दर बद कर ४% हो गई। मई १६५७ में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि वैंक रैट फिर से बढ़ाकर ४% कर दी गईं। परिगामत: बैंकी द्वारा उचार लेने की दर में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई । इस प्रकार की उधार ली हुई राशि में वास्तविक बृद्धि ० २ ० % हुई क्योंकि तीन महीने की अविध वाले प्रामिसरी नोट की स्टाम्प ह्युटी एक हजार रूखे या उसके किसी ब्रंश पर घटाकर ५० नया पैसा कर दी गई। इन परिवर्तनो के फलस्वरूप, इस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा अन्य स्वीकृति प्रतिभृतियों के बल पर ऋगा लेने की श्रपेता उधार लेने की लागत बढ गई है। सरकार तथा श्रन्य प्रातभृतियों के श्राधार पर उधार लेने की दर ४% ही रही।

रिजर्व वैंक की योजना १६५३ की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न हैं जिसके अनुसार हम्पीरियल बैंक सरकार के मुद्रा विभाग से ऋषा को मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र में बदलकर १२ करोड़ रुपया उधार ले सकता था। परन्तु रिजर्व बैंक की योजना का आधार पूर्व व्यवस्था ही है जिससे उसे प्रेरणा मिलती रही। पहली योजना के अनुसार हम्पीरियल बैंक को ऋषा देते समय सरकार का मुद्रा विभाग यह प्रतिबन्ध लगाता था कि (अ) हुन्ही स्वदेशी होनी चाहिये जिसका उद्देश्य व्यापार हो, (व) यदि हुन्ही में उसके उद्देश्य उल्लेख न हो तो हम्पीरियल बैंक को यह प्रमाणित करना चाहिये कि यह मुनिधा व्यापार के लिए दी जा रही है, और (स) अमुण विभागती क्याज पर दिया गया हो, जिसकी दर परिवर्तनशीन हो।

योजना १६ जनवरी १६५२ को घोषित की गई। उसके बाद अनुस्चित बैंकों को इस योजना का कार्य समम्मने में कुछ समय लगा श्रोर कुछ देर भी हुई। परन्तु १६५२ में श्रन्युचित बैंकों ने रिजर्व बैंक से १०० अपूण लिए जिनकी कुल रकम ८१ ४५ करोड़ रुपये थी। १६५३ में रिजर्व बैंक ने श्रनुस्चित वैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक कानून की घारा १७ (४) (सी) के श्रनुसार केयल ६५ ८४ करोड़ रुपया ऋगा दिया। यह कहना कि "श्रनुस्चित बैंकों ने स्थिति श्रपेचाकृत श्राधिक श्रव्ही होने के कारण रिजर्व बैंक से ऋगा नहीं लिया" पर्याप्त नहीं है। यह योजना श्रपने सीमित विस्तार श्रीर महँगी होने के कारण श्रिषक लोकि।य नहीं हुई। यह इस बात से स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक को योजना श्रिषक पिय बनाने के लिए उसका विस्तार करना पहा ।

यद्यि योजना के ज्ञन्तर्गत उघार लेना ग्रधिक महँगा था किर भी १६५६ व १६५७ में रिजर्व बैंक द्वारा श्रनुष्चित वैंकों को उचार दिया गया ऋगा कमरा: ४३६°८२ करोड़ ६० तथा ४१४.८१ करोड़ ६० था जो भूत काल की श्रपेका कहीं श्रधिक है। रिजर्व बैंक के श्रनुसार इसका कारण यह था कि वैंके सरकारी तथा ज्ञन्य स्वीकृति प्रति भूतियों के श्रावार पर यथा सम्भव उघार नहीं लेना चाइती थी। तथा निम्नतम तरल सम्पत्ति सम्बन्धी परिनियत दाथित्वों को गुरा करना चाइती थी।

श्रालोचना—श्रालोचना को रिजर्व वैंक की इस योजना में श्रनेक दोप दिखाई दिये है—(१) यह कहा गया है कि हुन्ही वाजार के लिये यह उपयुक्त योजना नहीं है। यह योजना व्यापारिक हुन्हियों पर नहीं बल्कि श्रनुस्चित वैंकों के ऋणा के बदले ली गई मुदती हुन्हियों पर श्राघारित है। यह व्यस्त कारोवारी समय में साख का प्रधार करने का केवल उपाय मात्र है। मंहाजनी इत्यादि की हुन्हियों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है जब कि Shroff Committee ने ऐसा करने का सुमाव दिया था। जब तक उनकी इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता श्रीर श्रनुस्चित वैंकों को उनकी हुन्हियों स्वीकार करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता श्रीर रिजर्व वैंक से इनको मुनाने की मुविधा नहीं दी जाती तब तक भारत में उपयुक्त हुन्ही बाजार का विकास नहीं हो पायेगा। (२) यह योजना श्रनुस्चित वैंकों के लिए श्रधिक खर्चीली है। श्रमुखों (Demand loans) को मुदती हुन्हियों में बदलना श्रीर सभी प्रकार की रिजर्व वैंक को देना श्रनुस्चित वैंकों के लिये बहुत श्रमुविधाजनक कार्य है; साथ ही इसमें व्यय मी श्रिषक होता है। श्रनुस्चित वेंकों को जो हानि श्रीर श्रमुविधा सहनी पहती है उसको व्याज या स्टाम्प में दी गई रियायत से पूरा नहीं किया जा सकता है।

१ मार्च १६५६ से इन सुविघाओं को आंशिक वापसी तथा तदनन्तर वैंक दर की वृद्धि ने उधार लेना और भी महँगा कर दिया। (३) रिजर्व वैंक को ऋषा देने की नीति ऐसी है जिससे रिजर्व वैंक द्वारा कुछ वैंकों में भेदभाव करने और उनके साथ अनुस्चित व्यवहार किये जाने की सम्मावना रहती है। रिजर्व वैंक ऋषा देते समय केवल जमानत और विनियोग की ही नहीं बल्कि वैंक के कार्य संचालन की भी जाँच करता है। इससे भारत में सुसम्बन्धित हुन्ही बाजार के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण नहीं हो पाता है।

प्रथम श्रीर द्वितीय योजना के कारण श्रार्थिक कार्यों में वृद्धि होने से श्रमुस्चित बैंकों ने जो श्रमुण रिजर्व बैंक से लिया है उसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। परन्तु यह कहना ठीक न होगा कि क्योंकि यह योजना बहुत एकल हुई है श्रीर क्योंकि श्रमुस्चित बैंकों के श्राय स्रोतों में वृद्धि हुई हसलिये जो सुविधार्ये रिजर्व बैंक ने इसके प्रोत्साहन के लिये दी थीं उनका वापस तो लेना उचित होगा।

अध्याय ४६ रिजर्व वैंक

भारत में रिजर्व वेंक का कार्य शेयर होल्डरों (हिस्सेदारों) के वेंक के रूप में श्रिप्रेल १६३५ से चालू हुआ। १६३४ में भारतीय रिजर्व वेंक कानून स्वीकृत हुआ था। इससे पहले प्राय: इस प्रश्न पर विशेष रूप से विवाद चला कि क्या वास्तव में भारतीय इम्पीरियल वेंक से सारा काम नहीं चलाया जा सकता है? पहले इन्पीरियल वेंक केन्द्रीय वेंक के कुछ कार्यों को करता था। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठा कि रिजर्व वेंक शेयर होल्डरों का वेंक हो या राजकीय वेंक हो।

आवश्यकता— मुद्रा पर सरकार के दोहरे नियंत्रण श्रीर इम्पीरियल बैंक के श्रस्तोपजनक कार्य के कारण केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का श्रनुभव हुआ। हिल्टनयंग आयोग ने वैंकिंग की उस प्रणाली में निहित दोषों पर प्रकाश हाला जिसमें मुद्रा श्रीर साख पर दो भिन्न संस्थाओं का नियंत्रण होता है जिनकी नीतियों में काफी मेद होना संभव है श्रीर जिसमें मुद्रा तथा बैंकिंग के सुरिहत कोषों की श्रलग-श्रलग न्यवस्था की जाती है। यह सुम्माया गया कि केन्द्रीय बैंक न्यवस्था लागू हो जाने से यह दोष दूर हो जायगा।

दूसरी श्रोर १६३५ में जो वैधानिक परिवर्तन किये गये उनसे यह श्रावश्यक प्रतीत होने लगा कि देश की वित्तीय व्यवस्था को हद बनाना चाहिये। विधान की सकलता इस बात पर निर्भर करती थी कि भारत स्वदेश तथा विदेश में श्रपनी वित्ताय स्थित सुहदू बनाये श्रीर साथ ही साख बनाये रखने में पूर्ण्तया समर्थ सिद्धि हो।

यदि इग्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक के पूर्ण श्रधिकार दे मी दिए जाते तब भी वह इस कार्य को पूरी तरह सन्तोषजनक रींत से नहीं चला पाता क्यों कि भारतीय ज्वाइंट स्टाक तथा श्रन्य बैंकों को उस पर पूरा विश्वास नहीं था श्रीर इस्पीरियल बैंक इन बैंकों से प्रांतयोगिता करता रहता था। केन्द्रीय बैंक के श्रधिकार मिल जाने से इग्पीरियल बैंक इन ही बैंकों का एक प्रकार से संरच्चण श्रीर श्र्या लेने का श्रन्तिम सहारा बन जाता। केन्द्रीय बैंक तमी सफल हो सकता है जब उसका श्रन्य बैंकों पर प्रभाव हो श्रीर श्रन्य बैंकों को उसकी कार्यज्ञमता पर प्ररा विश्वास हो। यदि इग्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक वन जाता तो वह श्रपने

सायारण वैंकिंग कारोबार को चालू नहीं रख सकता था परन्तु इस बैंक का संचालन मरहल इस कारोबार को छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। इसीलिये यह निश्चय किया गया कि भारत में रिजर्व बैंक स्थापित किया जाय। रिजर्व र्वेंक ने बिल्कुल नये सिरेसे कार्य श्रारम्भ किया श्रौर श्रपनी एक परम्परा स्थापित की।

ं विधान-रिजर्व वैंक ने श्रपना कार्य शेयर होल्डरों के बैंक के रूप में त्रारम्म किया । इसके रोयरों की कुल पूँजी ५ करोइ रुपये थी । प्रत्येक रोयर १०० रुपये का या जिसका पहले ही पूरा भुगतान कर देना पहला था। यह आवश्यक था कि बैंक की संचालन शक्ति कुछ लोगों के हाथों में जाने से रोकी जाय। इसके लिये यह योजना बनाई गई कि देश के पाँच चेंत्रों (बाद में बर्मा से श्रलग हो जाने से केवल बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, श्रीर मद्रास, के चार चेत्र रह गये) में दर्ज शेयर होल्डरों का बरावर मूल्य के शेयर वेचे जायें। परन्तु इतना होते हुए भी धीरे-धारे सारे शेयर बम्बई चेत्र में ही केन्द्रित हो गये। मार्च १६४० में रिजर्व वैंक ऐक्ट में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार संशोधन की तिथि के बाद यदि नये शेयर खरीद कर किसी व्यक्ति के पास कुल शेयर २०,००० रुपये से श्रिषिक के हो जायेंगे तो उनका नाम शेषर होल्डर की सूची में दर्ज नहीं किया जायेगा। परन्तु इससे शेयरों को बम्बई चेत्र में केन्द्रित होने से नहीं रोका जा सकता। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीकरण से यह दोष दूर हो गया।

वैंक का सारा कार्य केन्द्रीय संचालन मरहल चलाता है जिसमें एक गवर्नर, दो हिप्टी गवर्नर, १० संचालक या हाइरेक्टर (जिनमें से चार संचालन चार स्थानीय मण्डलों का प्रतिनिधित्व करते हैं) और एक चरकारी अफसर होता है। इन सबको केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है। चारों चेत्रों (बम्बई,कलक सा दिल्ली, मद्रास) में चार स्थानीय मण्डल हैं जिनमें तीन-तीन चदस्य होते हैं। ये सदस्य चेत्रीय, ऋार्थिक, सहकारिता और साहुकारी के हितों का प्रतिनिधित्य करते हैं। राष्ट्रीकरण से पहले केन्द्रीय संचालक मण्डल में १६ सदस्य पे जिसमें एक गवर्नर और दो डिप्टो गवर्नर वेन्द्रीय सरकार नियुक्त करती थी, सरकार द्वारा नियक्त चार संचालक, विभिन्न क्षेत्रों में शैयर होल्डरों द्वारा निर्वाचित आठ संचालक श्रीर एक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी श्रक्तसर होते थे। पहले स्थानीय मण्डलों में आठ सदस्य होते थे जिनमें से पाँच उस जेन के शेयर होल्डरों में से चुने जाते थे श्रीर तीन सदस्यों को केन्द्रीय सरकार नियक्त करती थी।

कार्य

किसी भी अन्य केन्द्रीय दैंक की तरह रिजर्व दैंक का मुख्य कार्य देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखना, रुपये के विनिमय मूल्य की व्यवस्था करना और सरकार के वैंकिंग के कारीबार को चलाना है।

वैंक का सबसे महत्व पूर्ण श्रीर किठन कार्य देश में मुद्रा तथा साल पर नियंत्रण रखना है। रिजर्व वैंक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि चलन (Circulation) में रुपये की मात्रा न तो बहुत कम हो श्रीर न बहुत श्रिषक। रिजर्व वैंक व्यवस्था वैंकों के साख-प्रसार के कार्य का निरीच्या करता रहता है श्रीर ऐसी व्यवस्था करता है जिससे संकट काल में योग्य सदस्य वैंकों को सहायता देकर बन्द होने से बचाया जा सके।

नोटों का निर्गम—नोटों के निर्गम का केवल भारतीय रिजर्व वैंक को श्राधकार है। वैंक श्राफ इंगलेंड की भाँति भारतीय रिजर्व वैंक के भी दो विमाग हैं—निर्गम विमाग श्रीर वैंकिंग विभाग। नोटों के निर्गम में सबसे महत्वपूर्ण श्रीर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्राप्रणाली में जनता का कितना विश्वास है। इसलिए भारत के रिजर्व वैंक कानून में यह न्यवस्था की गई है कि जितने नोटों के निर्गम हो उसके ४० प्रतिशत के बरावर सोने के सिक्के, स्वर्ण पाटमान (बुलियन) श्रीर स्टर्लिंग (पींड) होने चाहिएँ जिसमें २१ ६० ३ श्राना पाई प्रति तोले के हिसाव से किसी भी समय कम से कम ४० करोड़ रुपये का सोना हीना चाहिए। शेप ६० प्रतिशत रुपये की प्रतिभृतियों (Rupee Securities), सिक्कों श्रीर विनिमय-पत्रों (Bills of Fxchange) इत्यदि के रूप में होना चाहिए। परन्तु भारत सरकार को रुपयों की प्रतिभृतियों ५० करोड़ रुपये या कुल के एक चौथाई (हनमें जो श्रीसक हो) से श्रीसक नहीं होनी चाहिए।

दितीय पंचवर्षीय योजना के अर्थ प्रबन्धन की सुविधाजनक बनाने लिये रिजर्व वैंक (संशोधन) अधिनियम १६५६ ने अनुपातिक व्यवस्था के स्थान पर निम्नतम सुरिक्त कीप निश्चित कर दिया। इसके अनुसार वैंक कम-से-कम ४०० करोड़ ६० की विदेशी प्रतिभृतियाँ (जो सरकार की पूर्व अनुमति से कठिनाई के समय ३०० करोड़ ६० तक की जा सकती थी) तथा ११५ करोड़ की स्वर्ण सुद्रा व स्वर्ण (अर्थात कुल ५१५ करोड़ ६०) रखने के लिये वास्य थी। स्वर्ण की कीमत ६२५५० ६० प्रति तोला थी जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमित के अनुसार था। ३१ अक्टूबर १६५७ को एक अध्या देश द्वारा उपयुक्त अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया। वाद में इसका स्थान रिजर्व वैंक आफ इरिडया

दितीय संशोधन) श्रिधिनयम १६५७ ने ले लिया।" इस नई न्यवस्था के श्रन्तर्गत निर्गम विभाग में स्वर्ण-मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभृतियों का कुल मृत्य २०० करोड़ र० से कम नहीं होना चाहिये। इसमें से स्वर्ण मुद्रा-श्रीर स्वर्ण मृत्य किसी भी समय ११५ करोड़ र० से कम नहीं होना चाहिये। घारा ३७ की यह न्यवस्था कि निर्गम विभाग में विदेशी प्रविभृतियों की मात्रा ३०० करोड़ र० से कम न होनी चाहिये, हटा दी गई। विदेशी विनिमय संकट का सामना करने लिये ऐसा किया गया। किन्तु यह बहुत ही सस्त कदम था तथा जनता के विश्वास खोने या कम होने पर स्थये के मृत्य के लिये गंगीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

नोटों के निर्भम के सम्बन्ध में एक गम्भीर दोप यह रहा है कि १६४५-४६ से उनकी रकम में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। १६५१ में १२०५ है करोड़ र० के नोट प्रचलन में थे। १६५७ में कुलचालू नोट १५१८ करोड़ र० के थे। इसका / उत्तरदायित्व वास्तव में रिजर्व वैंक पर नहीं है। रिजर्व वैंक कानून में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके श्रन्तर्गत ब्रिटिश सरकार श्रपना युद्ध का खर्च चलाने के लिए भारत में स्टलिङ्ग (पींड) के बदले रुपये ले सकती थी। ब्रिटिश सहकार ने इसका लाभ उठाया श्रीर रिजर्व बैंक को परिणाम-स्वरूप में अधिक नोट जारी करने पड़े। इसके साथ ही ख़ौदोगिक तथा ख्रन्य ख़ार्यिक कार्यों में वृद्धि हुई ख़ौर देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ी। इस स्थिति में आर्थिक विकास के कार्यों को आगे बढाने के लिए नोटों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। रिजर्व बैंक का वास्तविक दोप यह है कि उसने उस समय जनता को यह नहीं बताया कि विटिश सरकार स्टलिङ्क को कायों में सुनाने के लिए रिजर्व वैंक कानून की उक्त धारा का लाम उठा रही है। रिजर्व वैंक ने जनता को इस तथ्य से अनिमन्न रखा श्रीर पर्याप्त ज्ञित हो जाने के पश्चात् ही जनता को यह घटना मालूम हो सकी । इसके साथ ही यह कहना अनुचित न होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद रिजर्व वैंक अपनी मुद्रास्फीति को रोकने की नीति के होते हुए भी चलन में आए नोटों की संख्या त्रावश्यकतानुसार कम कर सकने में असमर्थ रहा है।

साख पर नियंशत्र—कानून के श्रनुसार यह श्रावश्यक है कि श्रनुस्चित
वें के चालू देयधन का ५ प्रतिशत श्रीर निश्चितकालीन देयधन का २ प्रतिशत
रिजर्व वें के के जमा खाते में रखें। इस व्यवस्था का उद्देश्य व्यवसायी वें को
द्वारा दिये गये माल पर नियंत्रया रखना है। परन्तु भारत में व्यवसायी वें के
इस व्यवस्था के श्रनुसार निर्धारित प्रतिशत से कहीं श्रधिक नकदी श्रपने पास श्रीर
रिजर्व वें के में जमा रखते हैं; इससे यह व्यवस्था साख पर नियंत्रया रखने में विशेष
लामकर सिद्ध नहीं हुई है। १६४६ के वैंकिंग कम्पनी कानून में गैर श्रनुस्चित

वैंकों के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह भी अपने चालू और निश्चित कालीन देयधन (demand and time liabilities) का अनुस्चित वैंकों के बराबर प्रतिशत अपने पास रोकड़ में रक्खें। कानून के लागू होने के दो वर्ष बाद बेंकिंग कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने चालू और निश्चित कालीन देयधन का २० प्रतिशत नकदी, स्वर्ण या किसी भी कानूनी तीर पर स्वीकृति अनुस्पपत्र में जमा रखें। कानून में संशोधन करने के बाद रिचवं वैंक को कुछ अधिकार दिये गए हैं। इन अधिकारों के अन्तर्गत रिजवं वैंक कि कि वह अपने चालू और निश्चित कालीन देयधन का कमशः ५ प्रतिशत और २ प्रतिशत कोष में यदि नहीं रख सकते तो न रखें। यह सुमाव दिया गया है कि कानून को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देयधन के इस प्रतिशत को शिध बदला जा सके। यदि केन्द्रीय वैंक चाहता है कि साख का कारोबार संकुचित किया जाय तो धना पूर्व स्चना दिये यह प्रतिशत बदाया जा सके और यदि साख के ब्यापार का अधिक प्रसार करना है तो प्रतिशत बदाया जा सके ।

रिजर्व वैंक को इस वात का श्रिषकार है कि वह रिश्चय कीप का श्रिनुपत तत्कालीन देयधन (Demand Liabilities) का २०% श्रीर निश्चित कालीन देयधन का द्र% कर ले श्रीर यदि रिजर्व बैंक श्रावश्यक समके तो विशेष परिस्थित में जमाधन को रोक ले। इस श्रिषकार के कारण केन्द्रीय वैंकिंग संस्था को भारत में वैंको की साख पर श्रिषक प्रभावशाली नियंत्रण प्राप्त हो सकेगा! इसते जब घाटे का श्रर्थ प्रबन्धन (deficit financing) के कारण सुद्रास्कीति होगी तब उस दशा में वैंकों की साख में श्रानावश्यक वृद्धि पर रोक लगाना सम्भव हो सकेगा!

वाजार में क्रय-विक्रय (Open Market Operations)—िरजर्व वैंक श्रपनी बाजार में क्रय विक्रय करने की नीर्ति से, श्रय्यात् बाजार में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय श्रीर वैंक-दर की नीति से व्यवसायी वैंकों श्रीर मुद्रा बाजार पर यास्तिक नियन्त्रण रखता है। रिजर्व वैंक कानून के श्रन्वर्गत रिजर्व वैंक को उन विनिमय-पत्रों या हुन्हियों श्रीर प्रतिशा पत्रों को खरीदने, वेचने श्रीर उन पर श्रृण देने का पूरा श्रविकार है। रिजर्व वैंक श्राफ इिएडया ऐक्ट के श्रन्वर्गत रिजर्व वैंक को उन हुन्हियों श्रयवाप्रतिशा पत्रों को वेचने, खरीदने श्रीर पूर्व प्रापण (discounting) करने का श्रविकार है जो मान्य व्यापार के कारण उद्मुत हैं श्रीर जिनका भुगतान भारत में हो सकता है, तथा जिन पर दो या दो से श्रविक मान्य इस्ताच्रर ही जिनमें से एक हस्ताच्यर श्रनुस्चित वैंक या सहकारी वैंक के होने श्रावश्यक हैं। इन हुन्हियों इत्यादि को ६० दिन के अन्दर सुनाया जा सकता है। रिजर्व वैंक को कृषि तथा श्रम्भ के विकय के लिए वित्तीय व्यवस्था करने को प्रमुक्त की जाने वाला ६ महीने के मियाद की हुन्हियों के कय-विकय का श्रिषकार है। परन्तु यह हुन्हियों भारतीय होनी चाहिएँ। श्रम ६ महीने की श्रविध बहा कर २५ महीने कर दी गई है। इसके साथ ही रिजर्व वैंक को केन्द्रीय एवम् राज्य सरकारों द्वारा जारी श्रम्यापत्रों के व्यापार में ६० दिन की श्रविध वाली हुन्हियों को खारीदने तथा वेचने का श्रिषकार है।

रिजर्य वेंक साख पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखने के लिये खुले वाजार में क्रय-विक्रय करने की प्राक्रया का पूरा लाम उठाता है। इस ग्रिथिकार की भी कुछ सीमाएँ हैं:— (१) भारत द्रव्य वाजार (Money Market) ग्रामी श्रविकित्ति में है श्रीर (२) रिजर्य वेंक कुछ खास प्रकार की प्रतिभृतिश्रों की ही खरीद एयम् वेच सकता है श्रीर चूँकि श्रिथिकाँग प्रतिभृतिश्रों सरकारी है इसील इनके क्रय-विक्रय में रिजर्व वेंक पूर्ण स्वतन्त्र नहीं है। रिजर्व वेंक सरकार की साख नष्ट होने के भय से सरकारी ऋण्यायों को बड़ी मात्रा में नहीं वेच सकता।

वैंक द्र-नीति चैंक दर की नीति पहले विशेष सफल सिद्ध न हो सकी क्योंकि ब्रारम्म से ही रिजर्व वैंक को परिस्थित यश वैंक दर निरन्तर ३ मितशत बनाए रखनी पड़ी। चूँकि रिजर्व वैंक दर बढ़ाने में ब्रासमर्थ था इसलिए यह साधन एक प्रकार से व्यर्थ हो रहा। यदि रिजर्व वैंक को बैंक दर में परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता भी होती तब भी मारत का द्रव्य बाजार ऐसी स्थिति में नहीं था जिससे वह इस परिवर्तन का द्रव्य बाजार की श्रम्य दरों पर प्रभाव दाल पाता।

वैंक की दर १५ नवम्बर १६५१ को ३ प्रतिशत से वहाकर ३ प्रतिशत कर दी गयी। इसका एक कारण यह भी था कि ब्रिटेन तथा अन्य सरकारों ने भी अपने वैंक की दरों को बहा दिया था। १६ मई १६५७ से यह दर बहा कर ४ प्रतिशत कर दी गई। यह आशा करना अनुचित न होगा कि भावव्य में भारत में वैंकों की दर की नीति पहले से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगी। वैंक दर को अधिक प्रभावशाली स्वान के लिए रिजर्व वैंक की व्यापारिक वैंकों को वित्तीय सहायता देने की नीति में भारी परिवर्तन किया गया है। पहले रिजर्व वैंक बाजार भाव पर अनुस्चित तथा सहकारी वैंकों से सरकारी प्रतिभृतियाँ हत्यादि खरीद लिया करता था। इस प्रक्रिया से इन वैंकों को धन मिलता था और यह साधन उनके लिये बहुत सत्ता और सुविधाजनक था। अनुस्चित और सहकारी वैंकों ने भी भारतीय रिजर्व वैंक कानून की घारा १७ (४) (ए) के अन्तर्गत सरकारी तथा

श्रान्य मान्यता प्राप्त प्रतिभृतियों को भुनाने का कार्य किया; इन प्रतिभृतियों के श्राचार पर रिजर्व वैंक से श्राण प्राप्त किया। परन्तु यह साधन बहुत सीमित चेत्र में श्रपनाया गया। वैंक दर में परिवर्तन होने के साथ ही रिजर्व वैंक नें घोषित किया कि वह श्रनुस्चित वैंकों की सामयिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए सरकारी प्रतिभृतियों नहीं खरीदेगा परन्तु भारतीय रिजर्व वैंक कानून की घारा १७ (४) (ए) के श्रन्तर्गत सरकारी तथा श्रन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभृतियों पर वैंक दर के श्रनुसार श्रुण देगा। इस तरीके से श्रनुस्चित तथा सहकारी वैंकों ने रिजर्व वैंक से १९५७ में क्रमशः ३५३ ७८ करोड़ रुपये श्रीर ६ ६८ करोड़ रुपये श्रुण लिये जर्वाक १९५१ में ७६ करोड़ श्रीर ५ करोड़ रुपया लिया था। पिछले दो वर्षों में श्रुण की मात्रा बहुत श्रिषक बढ़ गई है क्योंकि श्रार्थिक कार्य बहुत बढ़ गया है।

विशेष साख नियंत्रस्—रिजर्व वेंक के अधिकारी इस निर्माय पर पहुँचे कि मूल्यों-विशेष कर खाद्यान्न के मूल्यों की मुद्रा-स्पीति जनक वृद्धि इन वस्तुओं की जमानत पर व्यापारिक वेंकों को अत्यधिक उधार देने के कारण हुई हैं। साख की मान्ना पर लगे सामान्य प्रतिवन्ध तथा उधार का महँगा होना भी जब पर्याप्त सिद्ध न हुआ तो उन्होंने साख नियंत्रण की योजना लागू की। इस नीति को लागू करने के लिये अनुस्चित वेंकों को वेंकिंग कम्पनीज (संशोधन) अधिनयम, १६५६ के अन्तर्गत निर्देश दिये गये। सबसे पहले १७ मई १६५६ को समी अनुस्चित वेंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे मंजूर किये गये अपूर्णों की मान्ना न बढ़ायें तथा किसी भी दल को चावल और धान के बल पर ५०,००० रू० से अधिक उधार न दें। बाद में खाद्यान्न, चीनी तथा स्ती यस्त्र जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्य अनेक निर्देश जारी किये गये, वाषिस लिये गये तथा पुन: जारी किये गये।

रिजर्व वैंक के श्रिधिकारियों के श्रानुसार, साल-नियंत्रण की उपर्युक्त नीति निम्न कारणों से उचित थी। (i) १९५६ में वैंक साख १५३ करोड़ र० के उच्च स्तर से बढ़ गया था, श्रीर इससे मुद्रा स्क्षीत का प्रभाव बढ़ रहा था। (ii) १९५५-५६ को मन्दी में (मई-श्रवह्वर) वैंक द्वारा उधार दी गई राशि घटने के बजाय बढ़ गई। (iii) ७ जून १९५७ को वैंकों द्वारा उधार दी गई राशि ६४० करोड़ र० तक पहुँच गयी। जून १९५५ में यह राशि ६१३ करोड़ र० थी। रिजर्व वैंक के श्रनुसार मन्दी के समय में उधार दी गई राशि ८०० करोड़ र० से श्रिषक नहीं होनी चाहिये। श्रनुस्चित वैंकों से यह श्राशा की गई कि वे उसे घटाकर इस स्तर तक ले श्रायेगी। श्रनुस्चित वैंकों के पन्न में यह कहा जा सकता

है कि उनमें से श्रनेकों के इस नीति के पत्त में न होने पर भी उन्होंने खाल कम करने का भरसक प्रयक्ष किया। फलतः सितम्बर १९५७ में यह राशि घट कर ८४५ करोड़ रु० हो गई। १९५७-५८ को किया शील श्रविध (नवस्वर् से श्रप्रेल तक) वैंकों द्वारा उधार दी गई राशि धीरे धीरे बढ़कर जनवरी १९५८ में ६१० करोड़ रु० फरवरी १९५८ में ६३२करोड़ रु० तथा मार्च १९५८ में ६६२ई करोड़ रु० हो गई।

साल नियंत्रण की इस नीति से मुद्रास्तीति जनक प्रभाव कम नहीं हुआ। इसके कारण निम्निल्लित ये, (i) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रीद्योगिक तथा श्रायंक क्रियाशों के विस्तार के फलस्करण वैंकों द्वारा उधार दी गई राशि में वृद्धि होना स्वामाविक था। श्रतएव १६५६ में उधार में १५३ करोड़ द० की वृद्धि कोई श्राश्चर्यजनक बात नहीं थी। १६५७ में तो इसे श्रीर श्रिषक बढ़ना चाहिये था। (ii) खाद्यान, चीनी तथा स्ती वस्त्र के श्राधार पर दिया गया उधार सहेनाजी के लिये नहीं था। उसका उद्देश्य खाद्यान्नों के स्थानान्तरण का अर्थ प्रवन्धन तथा चीनी श्रीर स्ती वस्त्रों में बिना किये भरडारों का श्रथप्रवन्धन था। सहे वाजी के लिये उधार पर नियंत्रण करने से उत्पादक उद्देश्यों के लिये भी खाल कम हो जायगी। भारत में सामान्य साल नियंत्रण तथा विशिष्ट साल नियंत्रण का मेद बनावटी तथा श्रवास्तिवक है।

यदि यह मान भी लिया जाय कि उघार श्रिषकतर चट्टेबाजी के लिये लिया जाता है तो भी निम्न कारणों से विशिष्ट-साख नियंत्रण की नीति छही नहीं यी। (1) इस प्रकार के विनियोग के लिये वैंक ५-६ प्रतिशत या श्रिषक से श्रिषक १०% तक उधार देते हैं। यदि वे उधार देना बिल्कुल बन्द भी कर दें तो इसते कोई महत्व पूर्ण श्रन्तर नहीं पढ़ेगा। (1i) खाद्यांत्रों का श्रासंचयन देश के इस चेत्र में होता है जो वैंक प्रणाली से दूर है। बैकों का साख केवल वहीं प्रभाव डाल सकता है जहाँ उनके द्वारा करना होता हो। (iii) इस नीति के पीछे यह श्रनुमान या कि भारत में मूल्यों की वृद्धि श्रिषक मुद्रा प्रसार के कारण थी। यह श्रनुमान ही गलत या श्रतएव उस पर श्राधारित नीति का श्रसफल होना स्वाभाविक ही था। यह नीति जिन बस्तुश्रों पर लागू की गईं उनके मूल्य भी कम नहीं हुये तथा उद्योग श्रीर वैकिंग व्यवस्था के व्यर्थ ही कृठिनाहयाँ उठानी पड़ी।

हुँडी वाजार—रिजर्व बैंक ने हुँडियों के क्रय विक्रय की योजना जनवरी १६५२ में लागू की जिसकी पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। १६५७ में इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने अनुस्चित बैह्नों को ४१४ ८१ करोड़ रुपये का ऋरा दिया जब कि १६५३ में ६५ ८४ करोड़ रुपया दिया था। रिजर्व वैङ्क के विरुद्ध यह गंभीर त्रारोप लगाया गया कि वह देश में हुँडी वाजार का विकास कर सकते में असफल रहा। उक्त कार्यवाही यद्यपि काफी देर से त्रारंभ की गई है परन्तु कालान्तर भारतीय द्रव्य वाजार की संगठित करने में सहायक होगी।

विनिसय श्रघे—कानून के श्रनुसार रिजर्व बैक्क पर कपये के विनिसय श्रघं का स्तर बनाए रखने का विशेष उत्तरदायित्व है। रिजर्व वैंक लन्दन में तुर्तत निकासी करने के लिए किसी भी व्यक्ति से स्टर्लिक्क (पींड) एक निश्चित दर पर खरीद श्रीर वेच सकता है। यह निर्धारित किया गया है कि क्पये की पींग्रड में विनिसय दर एक शिलिंग ५ हें पैन्स से कम श्रीर एक शिलिंग ६ हे पेन्स से श्रधिक न हो श्रीर विनिसय १० हजार पीग्रड स्टर्लिक्क की राशि से कम एक वार में न हो। इसी व्यवस्था के श्राधार पर ब्रिटिश सरकार ने रिजर्व वैंक को पीग्रड दिए और भारत में युद्ध का व्यय पूरा करने के लिए विनिसय में कपये लिए। इससे भारत में युद्ध का व्यय पूरा करने के लिए विनिसय में कपये लिए। इससे भारत में युद्ध का व्यवस्था से देश को भारी ज्ञति पहुँची। भारत के श्रन्त-र्राष्ट्रीय युद्धा कोय स सदस्य वन जाने मे १६४७ में इस कानून में संशोधन किया गया। कानून की इस व्यवस्था से देश को भारी ज्ञति पहुँची। भारत के श्रन्त-र्राष्ट्रीय युद्धा कोय का सदस्य वन जाने मे १६४७ में इस कानून में संशोधन किया गया। श्रव रिजर्व वैंक विदेशी युद्धा विनिसय केवल उन्हीं दरों पर कर सकता है जिनका केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है। इसलिए श्रव पहले की तरह एक निश्चत दर में स्टर्लिक्क का कथ विकय करना श्रनिवार्य नहीं रहा है।

सरकारी कारोवार—रिजर्व वैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ऋण (ways and means advances) दे जिसे ६० दिन के अन्दर वापस कर दिया जाना चाहिए, सरकारी ऋणपत्रों को खरीदे श्रीर वेचे, जनता से कर्ज लेने का प्रबन्ध करे श्रीर सरकार की श्रीर से द्रव्य प्राप्त करे। सरकार अपने कोष का कुछ माग बिना व्याज के रिजर्व वैंक में रखती है। वैंक ने सरकारी लेन-देन का कार्य बढ़ी सफलता पूर्वक किया है। रिजर्व वैंक ने जिस तरीके से इस कार्य को किया है उसके प्रति सरकार श्रीर जनता को एक वार भी असन्तोप प्रकट करने का अवसर नहीं मिला।

कृपि साख विभाग—यह रिजर्व वैंक का एक विशेष विभाग है जिसके कार्य निम्न हैं; (१) कृषि-साख सम्बन्धीः प्रश्नों का श्रध्ययन करने के लिए कुछ विशेषज्ञां को नियुक्त करे जिनसे केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारें, प्रदेशीय सहकारी वैंक तथा श्रन्य वैंक समय-समय पर विचार विमर्श कर सकें श्रीर (२) कृपि साख से सम्बन्धित वैंक के कार्यों, राजकीय सहकारी वैंकों श्रीर कृषि साख से सम्बन्धित किसी भी श्रन्य वैंक या संगठन से श्रपनें सम्बन्धों का उचित सामझस्य स्थापित करे। पहले रिजर्व वैंक का यह विभाग केवल कुछ रिपोर्ट जारी किया करता या श्रीर कृषि छाख के पुनर्षगठन के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। इस कभी के कारण रिजर्व बैंक की कही श्रालोचना हुई है कि इसने कृषि साख को उचित रीति से संगठित करने के कार्य की श्रीर उचित स्थान नहीं दिया जब कि कानून के श्रनुसार यह उसका उत्तरदायित्व था। पिछले दो वर्षों में वैंक ने इस क्मी को पूरा करने के लिए कुछ प्रयत्न किये हैं।

कृषि कार्य से सम्बन्धित विनिमय अधिपत्रों या हुन्डियों के मुगतान का समय ६ से १५ महीने कर दिया गया है। साथ ही अब इस बात की आवश्यकता नहीं रहा कि सहकारी बैंक रिजर्व बैंक से लिए गए ऋगों का निश्चित तिथि तक भगतान कर दें अर्थात अब यह जरूरी नहीं है कि बिना ऋगा की अवधि का विचार किये भुगतान ३० सितम्बर तक कर दिया जाय । भ्रव प्रत्येक भ्रम्या का सगतान प्रायः १२ महीने में हो जाना चाहिये परन्त विशेष परिस्थितियों में यह अविध १५ महीने कर दी जाती है। साख शेष ऋग की रकम तक ही सीमित है। पहले इसका सम्बन्ध ऋण की कुल रकम से होता या। सहकारी संस्थाओं के लिए व्याज की दर वैंक दर के वढने पर भी डेढ प्रतिशत रखी गई है। ग्राम्य वैंकिंग जाँच समिति के सुकाव के अनुसार स्टेट वैंक आफ इन्डिया को और अधिक शाखायें खोलने की श्रनुमति दी गई है और रुपये की निकासी की भी सुविधाएँ बढ गई हैं। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ऐक्ट के १९५२ और १९५३ के संशोधन से आम्य ऋण के त्रेत्र में रिजर्व बैंक का कार्य श्रीर श्राधिक विस्तृत हो गया है। ऐक्ट के संशोधन में "कृषि सम्बन्धी फसली प्रक्रियार्ये तथा कृषि उत्पत्ति की विक्री" का अर्थ अधिक विरत्त कर दिया गया है और अब इसके अन्तर्गत मिश्रित कृषि कार्य तथा किसानों श्रथवा किसानों की संस्याश्रों द्वारा कृषि उत्पत्ति का विधायन (Processing) भी सम्मिलित कर लिया गया है। ऋत्पकालीन ऋग की भ्रविष बढ़ाकर १५ महाने कर दी गई है श्रीर बैंक की यह श्रिषकार दे दिया गया है कि वह मध्यकालीन ऋग ग्राधिक से श्राधिक पांच वर्ष की श्रवधि तक का दे सकता है। इसके श्रतिरिक्त सहकारी बैंकों के श्रिधिपात्रों श्रादि का पुनःपूर्वप्रापस (Rediscounting) करने का श्रिषकार मी रिजर्व वैंक की पास हो गया है श्रीर कुटीर उद्योगों तथा छाटे उद्योगों के उत्पादन तथा विकी कार्यों को विचीय सहायता देने की श्रातमित भी प्रदान कर दी गई है।

उपयुक्त सुविधार्ये देने के श्रातिरिक्त रिजर्व बैंक परोज्ञरूप से खेती के लिये दीर्घकालीन ऋण का भी प्रबन्ध करता है। रिजर्व वैंक १९४८ में सूमि बन्धक बैकों के ऋण पत्रों (Debentures) को कुछ शतों पर १०% तक खरीदने के लिये तैयार था। १६५० में यह सीमा भी बढ़ा कर २०% तक कर दी गई। यह योजना अप श्रीर श्रिषक विस्तृत कर दी गई है।

१९५५ के रिजर्व वेंक ग्राफ इन्डिया ऐक्ट (संशोधन) के ग्रन्तर्गत रिजर्व वैंक श्राफ इन्डिया ने (१) राष्ट्रीय-कृषि साख-कोप (दीर्घकालीन कार्यों के लिये) ग्रौर (२) राष्ट्रीय कृषि-साख (स्यायित्व) कोष स्थापित कर दिया है । दीर्घकालीन कार्य कोप में आरम्भ में हा १० करोड़ रुपया, जो कि सरकार से पाप्त होगा, जमा कर दिया जायगा श्रीर जुलाई १९५५ से ५ वर्ष तक प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपया रिजर्व वैंक द्वारा जमा किया जायगा । यह कोष राज्य सरकारों को प्रत्यज्ञ अयवा . ग्रमत्यत्त रूप में सहकारी समितियों को शेयर पूँजी प्रदान करने के लिये, राज्य सहकारी वैंकों को कृषि कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को, श्रीर केन्द्रीय मूमि बन्धक वैंकों के ऋण पत्रों के खरीदने के लिए ऋण रूप में दिया जायगा । ३० जून १९५७ के ग्रन्त में यह कीप २० करोड़ रुपया था तथा सह-कारी संत्यास्त्रों की हिस्सा पँजो में योगदान देने के लिये १२ राज्य-सहकारी के कुल ४५८ करोड़ ६० का ऋण दिया गया। स्थायित्व प्रदान करने वाला कोप, जिसमें प्रति वर्ष १ करोड़ रुपया पांच वर्षों तक ३० जुन १६५६ से जमा किया जाया करेगा राज्य सहकारी वैंकों को ऋगा रूप में कम से कम १५ महीने की श्रवधि के लिये और श्रिमिक से श्रिधिक भ वर्ष की श्रवधि के लिये दिया जायगा ताकि उससे वे वैंक विनिमय अधिपत्रों और प्रतिका पात्रों के सम्बन्ध में जिनकी पूर्वप्रापण रिजर्व वैंक में कराया है, यदि कुछ अकाल, स्खा तथा अन्य किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण देना वाकी रह गया हो तो वे अदा कर सकें। ३० जून १६५७ को इसके द्वारा उधार दी गयी राशि २ करोड़ द० थी। यह कीव मारतीय कृषि की दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पूरी करेंगे।

व्यक्तिगत क्षेत्र में वित्तीय सहायता—व्यक्तिगत चेत्र के लिये वित्तीय सहायता सम्बन्धी कमेटी ने, जिसे प्रायः शर्राफ कमेटी कहते हैं, जो रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर १९५३ में नियुक्त की गई थी और जिसने मई १९५४ में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसने पंचवर्षीय योजना के व्यक्तिगत चेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में अनेकों अभिस्ताव किये हैं। जहाँ तक भारतीय रिजर्व वैंक का सम्बन्ध है कमेटी ने यह सिफारिश की है कि (१) हुन्ही बाजार योजना के अन्तर्गत इसे सुविधाओं का विस्तार बढ़ा देना चाहिये; (२) निकासी की सुविधाओं के सम्बन्ध की योजना जो उसने तैयार की है अधिक विस्तृत की जानी चाहिये; (३) सरकार की सलाह से उसे उन लाइकेन्स मास अनुस्चित वैंकों को विचीय सहायता-देने की एक योजना बनानी चाहिये जो अपने पूर्व निश्चित प्रसार कार्य-

क्रम के श्रनुसार जिसे रिजर्व वैंक ने स्वीकार कर लिया है नई शाखारें खोलने जा रहे है; (४) देशी वेंकरों तथा शर्राफों के रिजर्व वेंक से सीधे-सीधे सम्बन्धित किये जाने के प्रश्न पर सिक्रय रूप से विचार किया जाना चाहिये; (५) जब तक इस प्रकार का देशी बैंकों का सम्बन्ध रिजर्व बैंक से स्थापित नहीं हो जाता, रिजर्व र्वेंक द्वारा देशी वेंकरों की मुद्दती हुन्हियों के अनुसूचित वैंकों के माध्यम से पूर्व-प्रापणी करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए: (६) रिजर्व वैंक को चाहिये कि जो नियम श्रादि उसने वैंकिंग के सिद्धान्तानुसार बनाये हैं श्रीर जो निर्देश जारी किये हैं उनके छोटे-छोटे देंकों के सम्बन्ध में प्रयोग करने में किस सीमा तक शिथिल करना बांच्छनीय हो सकता है, इस बात पर विचार करें (७) रिजर्व वेंक को भारतीय श्रीहोगिक वित्तीय नियम श्रीर राज्य वित्तीय निगम के शेयरों श्रीर वैंक को सहकारी श्रधिपत्रों के समकत्त रिजर्व वेंक श्राफ इन्डिया ऐक्ट की धारा १७ (४) (क) के श्रन्तर्गत ऋगा देने के लिये समक्तना चाहिये; (८) हुन्डी वाजार योजना के अनुरूप मध्यवती अवधि के लिये वैंकों के पूजी सोतों की वृद्धि की सम्मावनाश्चों का विस्तार करने के लिये रिजर्व बैंक को प्रयत्न करना चाहिए: श्रीर (E) वैंक को छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट विकास निगम की स्थापना के लिये आगे आना चाहिये। यदि ये सिफारिशें कार्यान्वत कर दी जींय तो व्यक्तिगत चेत्र के लिये प्राप्त वित्तीय सहायवा की मात्रा बहुत श्रधिक बढ जायगी।

परन्तु श्रभी तक रिजर्व चैंक के लिये यह सम्भव नहीं हो सका है कि उपर्युक्त िफारिशों को कार्यान्वित कर छके। हुन्डो बाजार योजना श्रौर श्रिक विस्तृत कर दी गई श्रौर भारतीय श्रौद्योगिक वित्तीय निगम तथा राज्य वित्तीय निगम के शेयर श्रौर वांड श्रादि धारा १७ (४) (क) के श्रन्तर्गत ऋण देने के लिये समकत्त समक्ते जाने लगे हैं। व्यक्तिगत उद्योग त्तेत्र में मध्यम श्राकार के उद्योगों के वित्त प्रदान करने के लिये ५ जून १६५८ को एक पुनंवित्त निगम (Refinance Corporation) की स्थापना की गई जिसका विस्तृत विवरण 'श्रौद्योगिक वित्त निगम' श्रध्याय में दिया गया है। श्रव श्रौद्योगिक वित्त में रिजर्व वैंक के लिये काफी कार्य-तेन्न है।

राष्ट्रीयकर्ण

१६४८ के भारतीय रिजर्व वैंक कानून के ख्रन्तर्गत पहली जनवरी १६४६ को रिजर्व वैंक का राष्ट्रीकरण किया गया छौर तब से यह वैंक सर-कारी संस्था वन गयी। इसका तात्पर्य यह है कि रिजर्व वैंक की स्थापना से पहले जो लोग सरकारी केन्द्रीय वैंक का समर्थन करते थे, सही सिद्ध हुए। परन्तु गैर सरकारी की अपेत्ता सरकारी वैंक की विशेषताओं के सम्बन्ध में पहले के इन समर्थकों ने जो तर्क दिये थे उनकी अपेत्ता अब अन्य कारणों के आधार पर सरकारी केन्द्रीय वैंक का समर्थन किया जाता है। यह सत्य है कि रिजर्व बैंक के राष्ट्रीकरण से उनको जिस परिणाम की आशा थी वह प्रा हुआ।

रिजर्व वैंक के राष्ट्रीकरण का श्रनेक कारणों से समर्थन किया गया है-(१) राष्ट्रमग्रडल के अनेक देशों में, जिनमें बिटेश भी शामिल हैं, केन्द्रीय वैंकी का राष्ट्रीकरण हो चुका है थ्रीर वेन्द्रीय वैंकों को सरकारी बैंकों का रूप देने के लिए विश्वव्यापी आन्दोलन भी है। भारतीय रिजर्व वैंक का इसी आघार पर राष्ट्रीकरण किया गया। (२) युद्ध काल के श्रानुभव ने भारतीय रिजवे वैंक की स्वतंत्रता का श्रमली चित्र प्रस्तुत किया। रिजर्च वैंक वित्त मंत्रालय के श्राधीन सरकारी विभाग सा वन गया। रिजर्व वैंक का राष्ट्रीकरण हो जाने से उस हियति को कानूनी मान्यता मिल गर्या। (३) जब रिजर्व बैंक निभी संस्था थी तब बैंक के शेयर कुछ ही लोगा के श्रविकार में आ गये ये और द्रव्य तथा वैंकिंग का संचा-लन करने के लिए बैंक को जो बहुत ग्राधिक ग्राधिकार प्राप्त है, उनके दुरुपयोग की पूरी संभावना थी। १६४६ के वैकिंग कम्पनी कानून में रिजर्व बैंक की नियं-त्रण तथा संचालन के अनेक अधिकार प्राप्त हैं और यदि बैंक एक निजी संस्था के रूप में होता तो इन श्रिधकारों के दुरुपयोग की श्रिधक श्राशंका थी। (४) पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए यह श्रावश्यक है कि योजना श्रायोग त्रीर मारतीय रिजर्व वैंक के सम्बन्ध किल्कुल स्पष्ट ग्रीर सुलके हुए हों। यह तत्र तक संमव नहीं था जब तक वैंक सरकारी संस्था के रूप में कार्य न करता। द्रव्य संग्रहीत करने में श्रीर मुद्रा श्रीर साख का नियंत्रण करने में रिजर्व बैंक विशेष योगदान देता है जिसकी योजना की वित्तीय श्रावश्यकता की पूर्ति करने में विशेष महत्व है।

इसके विरुद्ध मारतीय रिजर्व वैंक के राष्ट्रीकरण की आलोचना भी की गई है। यह कहा गरा है कि (१) यह भारत सरकार की सामान्य नीति के अनुकूल नहीं है। १९४८ में सरकार की श्रीद्योगिक नीति यह थी कि राष्ट्रीकरण किया जाय परन्तु, जैसा हम अन्यत्र लिख चुके हैं, बाद में इस नीति को बदल दिया गया श्रीर राष्ट्रीकरण हमारा मुख्य आधार नहीं रहा। यदि उद्योगी और अन्य संस्थाओं का राष्ट्रीकरण किया गया होता तो रिजर्व वैंक का राष्ट्रीकरण विलक्जल उचित होता; (२) रिजर्व वैंक का राष्ट्रीकरण करके हम वैंक का कार्य चलाने वाले अनुभवी व्यापारियों वे पथ प्रदर्शन का लाभ उठाने से वंचित रह गये। अतीत

की मांति एक केन्द्रीय संचालन मगडल है श्रीर च्रेत्रीय परिषदें तो हैं परन्तु इनके सदस्य सभी सरकार से नियुक्त होते हैं श्रीर विच सम्बन्धी विशेष श्रानुभव प्राप्त गैर सरकारी व्यक्ति नहीं हैं; (३) श्रातीत में रिजर्व वैंक का कार्य स्वतन्त्र दृष्टिकोण से प्रमावित होता था श्रीर श्रानेक बार वैंक द्वारा विरोध किए जाने पर विच मंत्रालय की भूलें सुधारी गई। इससे दोनों संन्थाश्रों में सुन्दर सन्तुलन रहता था। परन्तु श्रव वैसे रिजर्व वैंक को स्वशासन का श्रिषकार प्राप्त है पर वास्तव में उसकी स्वन्तन्त्रता नष्ट हो चुकी है। श्रव यह विच मन्त्रालय के द्वांथों में है श्रीर वह इसका जैसा प्रयोग चाहता है कर सकता है। इससे यह मय है कि मन्त्रालय की भूल फी वैंक पर प्रतिक्रिया होने से राष्ट्र की हानि हो सकती है।

श्रध्याय ४७

व्यापारिक वैंक

स्टेट वैंक श्रॉफ इन्डिया एक्सचेंज वैंक, भारतीय श्रनुस्चित श्रीर गैर श्रनुस्चित वैंक सभी व्यापारिक वैंकों की श्रेणी में श्राते हैं। इन समी वैंकों में वैकिंग के साधारण कार्य, जैसे रुपया जमा करना, एक व्यक्ति या कार्पोरेशन के नाम जमाधन को दूसरे व्यक्ति अथवा कार्परिशन के नाम बदलना, भुगतान के लिए विनिमय पत्रों, सरकारी बोंडों को श्रौर व्यापारियों की जमानतों को जमाधन में बदलना, इत्यादि किये जाते हैं। इसके साथ ही यह बैंक जेवरात इत्यादि की सुरज्ञा श्रीर ट्रन्टी इत्यादि का कार्य भार सँभालते हैं। यद्यपि भारतीय इम्पीरियल वैंक केन्द्रीय वैंक नहीं हैं परन्तु भारतीय वैंकिंग व्यवस्था में इसका एक विशेष स्थान है। यह वैंक सरकारी कारोवार करता है, जहाँ रिजर्व वैंक की शाखार्य नहीं है यहाँ रिजर्व वैंक की छोर से कार्य करता है छीर भारतीय मुद्रा वाजार में लोच बनाये रखने में सहायता देता है। एक्सचेंज बैंक श्रिषकतर मारत के विदेशी न्यापार, वन्दरगाह से उपभोग के केन्द्रों तक के स्वदेशी न्यापार श्रीर देश के अन्दर कच्चे माल के उत्पादन केन्द्रों तक के न्यापार को ही विचीय सुविधा देते हैं। एक्सचेंन वेंकों, मारतीय अनुस्चित वैंकों श्रीर गैर अनुस्चित वेंकों के कार्य के ढंग में कुछ श्रन्तर है परन्तु मूल रूप में यह समान प्रकार के कार्य करते हैं श्रीर इनकी प्रवृत्तियाँ भी प्रायः संमान ही है।

१९५७ के अन्त में स्टेट वैंक आँफ इन्डिया के ६२०, विनिसय वैंक के ६७, अप्रत्य अनुस्चित वैंकों के २५७६ तथा गैर-अनुस्चित (non-scheduled) वैंकों के १११३ कार्यालय थे, जिनमें इनके प्रधान कार्यालयों और शाखाओं की संख्या भी सम्मिलित हैं। सन् १९५१ के अन्त में इनकी संख्यायें क्रमशः ३९१, ६४, २१६१ तथा १४७३ थीं। इस प्रकार मारत में सभी वैंकों के कुल कार्यालयों की संख्या सन् १९५७ के अन्त में ४,३७६ हो गई जब कि १९५१ में इनकी संख्या ४११६ थी।

१६५१ और १६५७ के बीच स्टेट वैंक श्राफ इन्हिया के कार्यालयों की संख्या २२६ श्रीर बढ़ गई, एक्सचेन्ज वेंकों की तथा श्रन्य श्रनुस्चित वेंकों की संख्या भी क्रमशः ३ श्रीर ३८५ बढ़ गई। इसी बीच में गैर-श्रनुस्चित वेंकों की संख्या ३६० कम हो गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् जो वैंकों के कार्यालयों की संख्या

में कमी की प्रवृत्ति श्रा गई थी वह १६५४ में बदल गई जब वर्ष के श्रन्त तक कार्यालयों की संख्या बढ़ कर ४०३२ हो गई जबिक १६५३ के श्रन्त तक केवल ४०२१ कार्यालय ही थे। सभी वैंकों के कुल कार्यालयों की संख्या में वृद्धि होने की प्रतिगामी प्रवृत्ति १६५७ तक जारी रही जब कुल संख्या ४३७६ थी। भविष्य में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति सम्भाव्य है।

चैंकों की संख्या में कभी के कारण लोगों को चैंक की सेवाओं की सुविधा में तो अवश्य कभी आई पर वास्तव में इससे वैंकों ने शक्ति संग्रह की। जैस निम्न वालिका में दर्शाया गया है, १६४६ और १६५३ केवीच यदि इम वैंकों के जमा धन, प्राप्त पूँजो, रिच्चित कोष आदि को देखें तो हमें उनकी प्रगति का अनुमान हो जायगा। (करोड़ रुग्यों में)

383\$ १६५३ 8£48 १६५५ श्रनुस्चित वैंक ३२'६ जमा धन 33.5 \$ 2.0 ३२.0 रिच्चत कोष 3.2€ २७५ ३७१६ रद'र कुल जमा 680.0 3.883 682.5 **5199** गैर-श्रनुस्चित वैंक **⊏**'₹ 3'0 जमा घन 4°७ 4 रज्ञित कोष 2.5 3.8 818 8+5

तालिका से यह पता लगता है कि अनुस्चित बैंकों की प्रगति गैर अनुस्चित वैंकों की अपेक्ष अधिक अच्छी रही। १६५३ में दोनों प्रकार के बैंकों की स्थित १६४६ की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। उनके रिक्त कोष प्राप्त पूँजी से अधिक थे। १६५३ में मारतीय अनुस्चित बैंकों का रिक्त कोष प्राप्त पूँजी के अनुपात में ८४% था। १६५१ में रिक्त कोष कु, १६४६ में हु से कुछ अधिक था। गैर अनुस्चित बैंकों के सम्बन्ध में रिक्त कोष का प्राप्त पूँजी से अनुपात कोई विशेष नहीं बदला है और है के लगभग है।

46.8

६४'७

3'73

१६५३ के अन्त और १६५७ के अन्त के बीच के समय में मारतीय वैंकों की हिपति और अधिक सुदृढ़ हुई। मारतीय अनुस्चित वैंकों की प्रदत्त पूँजी, रिह्मत कोष तथा वास्तविक निचेपों में पुनः वृद्धि होकर क्रमशः ३४५, ३०६ तथा ११०११ करोड़ रुपये सन् १६५७ के अन्त तक हो गई। गैर अनुद्धित वैंकों की प्रदत्त पूँजी, रिह्मत कोष तथा वास्तविक निचेपों में सन् १६५७ के अन्त तक

कुल जमा

X0.0

क्रमशः ६'०, २'६ तथा ४८'५ करोइ रुपयों की कमी हो गई। यह गैर श्रातुष्चित वैंकों की संख्या में तीवगति से कमी होने के कारण थी। भारतीय श्रातुष्चित तथा गैरः श्रातुष्चित वैंकों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुश्रा है, क्योंकि सन् १६५७ के श्रन्त तक श्रातुष्चित वैंकों का रिच्चत कोप प्रदत्त पूँजी का ८८% से श्रिषक तथा गैर श्रातुष्चित वैंकों का रिच्चत कोप प्रदत्त पूँजी का ४८% था।

मुख्य विशेषताएँ—भारत में कुछ बड़े-बड़े वैंक हैं श्रीर श्रन्य-छोटे-छोटे वैंक हैं जिनमें बहुत श्राधिक अन्तर है। सन् १६५७ के अन्त तक २८ बढ़े अनु-स्चित वैंको (जिनकी पूँजी तथा रिवत घन ५० लाख रुपये या श्रधिक यी) की प्रदत्त पूँजी श्रीर सुरिज्ञतकोप ५६ ३ करोड़ तथा कुल जमा १०७१ ७ करोड़ रुपये थी जब कि शेप ४८ वैंकों के पास कुल प्रदत्त पूर्जा श्रीर मुराह्यतधन ८ ८ करोड़ तथा कुल जमा ८३% करोड़ रुपये थी। गैर अनुस्चित बैंको की स्थिति यह है कि ५० लाख या श्रधिक पँजी अथवा सुरिज्ञत कीप वाले श्रींक की कुल पंजी श्रीर. र्श्चित कीय ६० लाख रुपये श्रीर जमा धन ६० लाख रुपये थी। ५ लाख से ५० लाख के बीच पँजी श्रीर सुरिच्चत कीप वाले ५५ बैंको में ४ ३ कराड़ रुपये की पूँजी श्रीर सुरह्मित कोप था, श्रीर १ ४ वरोड़ रुपये जमाधन था श्रीर रोप्न २६२ .. गैर श्रतुस्चित वैंकों के पास पाप्त पूँजी श्रीर राज्यत कोप ४ १ करोड़ रूप्या श्रीर कुल जमाधन २१.२ करोड़ रुपया था। भारतीय श्रनुस्चित श्रीर गैर श्रनुस्चित वैंकों के सम्बन्ध में एक साथ विचार करने पर पता चलेगा कि सन् १६५७ में ६६% वैंकों में से प्रत्येक की पूँजी श्रीर प्रारच्या (reserve) प्र लाख रुपये से कम तथा कुल पूँजी एवं प्रारक्ति की केवल ५% श्रीर कुल वैंकी के जमा धन की रिङ्के प्रतिशत ही थी। जर्बाक ऐसे बैंकों-जिनकी पूँजी तथा प्रारच्या ५० लाख रपये अथवा श्रिधक यी की मात्रा दुःल वैंको की संख्या का ७ र प्रतिशत श्रीर कुल पूँजी तथा प्रारच्या की ७६३% तथा कुल जमा का ८८% थी। वैंकिंग की शक्ति के वेन्द्रीयकरण से यह आभास मिलता है कि भारत आर्थिक दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है श्रीर यह स्थित भारत में वैंकिंग व्यवस्था के विकां के अनुक्ल नहीं है। यदि कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे बैंकों की अपेचा, जैसा कि वर्तमान में है, समान आकार के अनेक वैंक होते तो उससे देश का श्रिधिक हित संभव था।

दूसरी विशेषता यह है कि देश के हर भाग में वैंकिंग की सुविधा समान रूप से विकसित नहीं हो पाई। कुछ राज्यों में श्रीषक वैंक हें श्रीर श्रन्य में श्रावश्यकता से कम हैं। इसके साथ ही वैंक श्रधिकतर बड़े कस्बों श्रीर शहरों, में केन्द्रित हैं श्रीर छोटे कस्बों तथा ग्राम्य दोत्रों की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। निम्न तालिका १ से स्पष्ट होता है कि वैंकिंग की सुविधा खरह 'क' राज्यों में खरह 'ख' और 'ग' राज्यों की अपेन्ना अधिक विकसित है। खरह 'क'

वालिका १ १६५५ में विभिन्न राज्यों में बैंकों की शाखार्त्रों का विवरस

राज्य .	शाखार्ये	राज्य	शाखाय	राज्य	शाखार्ये
वर्ग १		वर्ग वर्ग	२) वर्ग ३	
ग्रान्म	१८२	{	•	श्रनमेर	१२
श्रासाम	₹७	हैदराबाद	७३	भोपाल	Ę
बिहार	१५६	मध्यभारत	६४	कुर्ग	ક્
बम्बई:	200	मैस्र	8 \$ 8	कच्छ	Ę
मध्य प्रदेश	१६९	पटियाला संघ	હિ	दिल्ली	१०८
मदास	6 20	राजस्थान	११८	हिमां चल प्रदेश	ą
ਤ ਵੀ ਗ	१७	धौराष्ट्र	<i>७3</i>	मगिपुर	१
पंजाब	२१५	त्रिवांकुर कोची	न ५७१	पान्डिचेरी	8
उत्तर मदेश	४२६	•		त्रिपुरा	곡
पश्चिमी वंगाल	२४६			विनध्य प्रदेश	3
कुल	रद्भ	कु ल	११५४	कुल	१५८

के राज्यों बस्बई, मद्रास श्रीर उत्तर प्रदेश में सबसे श्राधक बैंक हैं। इसके बाद पश्चिमी बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार का नम्बर खाता है। खरह 'ख राज्यों में से त्रिवांकुर-कोचीन, राजस्थान ख्रीर मैसूर में वैंक व्यवस्था अपेचाकृत श्रिधिक विकसित है जबकि खरड 'ग' राज्यों में दिल्ली, अनमेर श्रीर दिमांचल प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेज्ञा वैंक व्यवस्था की अधिक सुविधा है यदि इस वैंक के कार्यालयों पर जनसंख्या के हिन्दकी या से विचार करते हैं तब हमें यह जात होता है कि ऐसे कस्त्रों में जिनकी जनसंख्या २५ हजार अथवा इससे अधिक है २६५७ कार्यालय (श्रर्थात् कुल का केवल ६१३%) तथा उन कस्बों में जिनकी जन-संख्या ५ हजार श्रीर २५ हजार के बीच में हैं केवल १३४० कार्यालय हैं। सन् १६५७ के अन्त में ५० इजार से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में २०२२ कार्या-लय १७६ स्थानों पर थे तथा ५० हजार से कम जनसंख्या वाले कस्बों में २३५४ कार्यालय ११५८ स्थानो पर थे। छांटे करनो और आम्य होत्रों की स्रोर उचित ध्यान न देकर बैंकों के बड़े करवों श्रीर शहरों में केन्द्रित हो जाने से (१) करवों के वैंकों में परस्पर गहरी प्रतियोगिता हुई है, (२) ग्राम्य चेत्रों के प्रति उदासीनता अपनायी गयी है और (३) देश के आर्थिक विकास के लिए ग्राम्य जनता की बचत का संग्रह कर सकने में बैंक ब्रासफल रहे हैं।

अध्याय ४५ एक्सचेंज वेंक

मारत में जितने भी एक्सचेंज वेंक हैं सभी विदेशी वैंकों की शाखार्य हैं। इन वेंकों से (१) भारत के श्रायात श्रीर नियांत व्यापार की वित्तीय श्रावश्यकता की पूर्ति की जाती है, (२) वन्दरगाहों से देश के श्रन्दर उपभोग के केन्द्रों तक श्रीर केन्द्रों तक माल लाने ले जाने का श्रान्तरिक व्यापार किया जाता है श्रीर (३) इन वेंकों में वचत जमा की जाती है, हुए हर्या मुनाई जाती हैं श्रीर श्रन्य व्यापारिक वेंकों की तरह व्यापार, उद्योग एवम् वाणिज्य के लिए श्रूण भी दिया जाता है। १६५७ के श्रन्त में भारत में १७ एक्सचेन्ज वेंक ये जिन्हें श्रव विदेशी वैंक कहते हैं, जिनकी ६७ शालायें थी। इनके पास १६६४ करोड़ वपये जमा धन या जिसमें से चालू पूँजी १२० ६ करोड़ उपये श्रीर स्थायी पूँजी ७५ द करोड़ वपया थी। श्रवीत में एवसचेन्ज वेंक भारत में लेनदेन के लिए शावश्यक धन की पूर्ति विदेशों में प्राप्त जमाधन से करते थे परन्तु कुछ वपों से भारत की वचत को श्राकर्यित करने के लिए इन वेंकों ने भारतीय जनता को सुविधाएँ दी हैं।

१६५७ में एवसचेन्ज वैंकों के पास नकद तथा रिजर्व वैंक में जमा जितनी रकम यी वह कुल नमाधन का केवल ह प्रतिशत थी। यह रिपति भारतीय श्रानुद्धित वैंकों की स्थिति से भी गिरी हुई है, परन्तु यह कोई दुर्वलता का लच्च महीं है, इसके विपरीत इससे प्रकट होता है कि एक्सचेन्ज वैंक ऐसी रक्षम नहीं रखते हैं जो न्यर्थ पड़ी रहे। वह श्रपने साधनों का उचित प्रयोग करते हैं। इन वैंकों की विचीय स्थित काफी हद्ध है। १६५७ में एक्सचेन्ज वेंकों ने ऋष (Loans and advances) श्रोर हुगही भुनाने से सम्बन्धित १८४'४ करोड़ रुपये (श्रपात कुल नमाधन के ६४ प्रतिशत) का कारोबार किया श्रोर ४४'४ करोड़ रुपये (श्रपात कुल नमाधन के १४ प्रतिशत) का कारोबार किया श्रोर ४४'४ करोड़ रुपये (श्रपात कुल नमाधन का २२.६ प्रतिशत) का विनियोग किया। इसके विपरीत भारतीय श्रनुस्चित वैंकों के विनियोग श्रीर श्रुण का है। इन वैंकों ने विनियोग श्रीर श्रुण में कुल नमाधन का कमश: ३६.६ श्रीर ५७.७ प्रतिशत कमश: लगाया। १६४६ श्रोर १६४२ के बीच एक्सचेन्ज वैंकों के पास नमाधन सभी वैंकों के कुल जमाधन का १८ प्रतिशत से बद्कर २० प्रतिशत हो गया श्रीर इनके द्वारा दिया गया श्रुण २४ से २६ प्रतिशत तक बढ़ गया परन्तु विनियोग

सभी न्यापारिक बैंकों के कुल विनियोग का पहले १३ प्रतिशत या जो उक्त श्रविध में गिरकर १२ प्रतिशत रह गया। १६५३ के श्रन्त में कुल बैंकों का जमाधन १८%, उधार दिया हुश्रा धन २४% श्रीर विनियोग १२% हो गया। १६५७ के श्रन्त में हिथति कुछ विगड़ी जब कि विदेशी विनियय बैंकों के पास सब श्राप्त विनियोग के श्रनुपात में कुल जमाधन का लगभग १५% कुल श्रमुण का २२% श्रीर कुल विनियोग का ६% ही रह गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि पिछले दो वर्षों में भारतीय श्रनुस्चित वैंकों ने श्रयने जमाधन विनियोग तथा श्रमुण में ही हुई रकम में तीव गित से वृद्धि की है। इससे प्रकट होता है कि श्रन्य व्यापारिक बैंकों की श्रपेत्ता श्रव एक्सचेन्ज बैंकों के जमाधन श्रीर उनके द्वारा दिये गये श्रमुण की रकम से श्रिषक वृद्धि हुई। इन एक्सचेन्ज बैंकों में से दो बैंक श्रिषकतर भ्रमणाधियों के यातायात से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ श्रपना श्रिषकांश कारोबार मारत में ही करते हें श्रीर शेष बैंक जिनकी संख्या अपेत्राष्ट्रत श्रीक है श्रपना श्रीक वार विदेशों में करते हैं श्रीर भारत में उनकी पूँजी का बहुत भोड़ा श्रंश लगा हुश्रा है। इन एक्सचेन्ज बैंकों में सबसे बड़े बैंक लायड बैंक, चार्टड बैंक श्राफ हिएडया श्रास्ट्रेलिया एन्ड चाइना, नेशनल बैंक श्राव इरिडया श्रार हिल्या एन्ड चाइना, नेशनल बैंक श्राव इरिडया श्रीर मर्केन्टायल बैंक श्राफ हिएडया श्रास्ट्रेलिया एन्ड चाइना, नेशनल बैंक श्राव इरिडया श्रीर मर्केन्टायल बैंक श्राफ हिएडया श्रास्ट्रेलिया एन्ड चाइना, नेशनल बैंक श्राव इरिडया श्रीर मर्केन्टायल बैंक श्राफ हिएडया है।

व्यापार के वित्तीय साधन-एक्सचेन्ज वैंक यद्यपि भारत में सभी प्रकार के बैिकंग के कार्य करते हैं परन्तु इनका मुख्य कार्य भारत के श्रायात-निर्यात व्या-पार को विचीय ग्रहायता देना है। यद्यपि श्राधारभूत चिद्वान्त समान है फिर मी श्रायात तथा निर्यात न्यापर को विचीय सहायता देने में कुछ मिन्नता है। निर्यात न्यापार के कागनात (Documents on Acceptance) श्रिषिकतर बैंक श्रीर श्चायात कर्ता की स्वीकृति मिल जाने पर श्रायात कर्ता को दे दिये जाते हैं। कमी-कभी कागजात (Documents on Payment) नकद रुपया मिलने पर दिये जाते हैं। निर्यात ज्यापार में मारतीय निर्यातकर्ता इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके माल का खरीदार लन्दन के किसी एक बैंक द्वारा भारत में श्रपनी साख स्मापित करे । निर्यातकर्ता ऐसी साख व्यवस्था की मांग करता है जिसका उल्ल-इन न किया जा सके क्योंकि इस रीति से जब तक वह माल मेजने का प्रवन्य करे तब तक खरीदार श्रपना निश्चय नहीं बदल सकता है। जब खरीदार साख स्थापित कर लेता है तब लन्दन बैंक की भारतीय शाखा या उसका प्रतिनिधि जो इस सम्बन्ध में सारी व्यवस्था करता है निर्यात कर्ता की सलाह देता है। तब निर्यात कर्ता साख के अन्तर्गत हुन्ही तैयार करता है और आवश्यक कागजात के साथ भारत में अपने वैंक को देता है। अधिकतर इन्ही वैंक और आयात कर्ता की

स्वीकृति मिल जाने पर लन्दन वैंक के द्वारा विदेशी श्रायात कर्तां को दे दी नावी हैं श्रीर कभी-कभी यह हुन्हियाँ नकद रुपया मिलने पर भी दी जाती हैं। हुन्हीं की श्रविध प्रायः ६० दिन की होती है। परन्तु इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। भारतीय वैंक इन हुन्हियों को साख स्थापित करनेयाले वैंक को मेज देता है। फिर यह हुन्डियाँ स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, इनमें सम्बन्धित एसस्वेन्ज वैंक की श्रीर से इस्ताचर किये जाते हैं श्रीर लन्दन द्रव्य बाजार में इन्हें सुनाया जाता है। इस प्रकार वैंकों का धन परावर काम में लगा रहता है। यह वैंकों के पास नकदी पर्याप्त हो तो यह वैंक इन हुन्हियों को सामान्य कर से सुनाने की पूरी श्रवध तक रोक रखते हैं।

दूधरी श्रोर श्रायात व्यापार के कागजात श्रधिकतर नकद करया लेकर दिये जाते हैं। भारत में जो श्रायात किया जाता है यह निर्यात करनेवाले देश में भारत की साख के अन्तर्गत दर्शनी या मुद्दी हुन्हों के द्वारा इंता है। सुद्दती हुन्ही की ३० दिन की श्रवधि काफी लोकप्रिय है क्योंकि इस भीच माल के श्राव-श्यक कागजात दवाई जहाज द्वारा प्राप्त हो जाते हैं श्रीर जहाज भी माल लेकर नियत स्थान पर पहुँच जाता है। इसकी सामान्य विधि यह है कि निर्यातकर्त्ती किसी विदेशी एक्सचेन्ज वैंक, जैसे लन्डन के एक्सचेन्ज वैंक, में माल बन्बक रख कर हुन्डी की भुना लेता है जिसके फलस्यरूप हुन्डी का मालिक एक्सचेन्ज बैंक वन जाता है। इसके बाद यह हुन्ही यदि मुद्दती हुन्ही है तो एक्सचेन्ज वैंक की भारतीय शाखा को मेज टी जाती है। भारतीय शाखा इसं श्रायातकर्चा की स्वी-क्रित के लिए मेजती है (इसमें हुन्डी वैंक की भारतीय शाखा में रहती है और त्रायात कर्चा को नहीं दी जाती है) श्रीर यदि हुन्ही दर्शनी है तो श्रायात कर्चा को रुपये का भुगतान करने पर दे दी वाती है। श्रायातकर्ता प्राय: हुन्डी की स्वीकार करके वैंक से सुगतान के पहले माल दे देन के लिए श्रावेदन पन्न भेवता है। इसके लिए उसे जमानत (Trust receipt) देनी पहती है। इसके बाद विल्टी तया श्रन्य कागजात श्रायात कर्ता को दे दिये जाते हैं जो एक्सचेन्ज वें क के ट्रस्टी रूप में माल पर श्रपना कब्जा कर सकते हैं। माल गोटाम में रख दिया जाता है श्रीर उसके बिक जाने पर हुन्ही का मुगतान कर दिया जाता है। यह ध्यान देने योग्य वात है कि माल को बन्वक रखने की व्यवस्था करने के बाद ही आयात-कर्चा को उस पर श्रिधिकार दिया जाता है। जिन फर्मों की प्रसिद्ध श्रिपेज्ञाकृत कम है उनका सामान वैंक में रख लिया जाता है जिस पर श्राधिकार नियंत्रण वैंक का ही रहता है श्रीर वही उसकी विक्री करता है। विक्री के इस रुपये से वैंक उघार दिये गये रुपये का युगतान करता है। एक्सचेन्ज वैंक प्रायः उन्हीं फर्मों को अपना ब्राहक बनाते हैं जिनकी स्थिति श्रव्छी होती है श्रीर व्यापार चेत्र में जिनकी कुछ प्रसिद्धि भी होती। उनका माल रेहन रख लिया जाता है श्रीर श्रायात कर्ता जैस-जैसे रुपया चुकाता है वैसे-वैसे श्रपना माल उठाता जाता है।

. आलोचना-भारत में एक्सचेन्ज वैंकों के कार्य की कड़ी श्रालोचना की गई है। यह कहा जाता है कि (१) यह वैंक विदेशी हैं श्रीर इन पर विदेशियों का ही नियंत्रण है। इनके कारण भारतीय श्रायात एवम् निर्यात व्यापार की यित्तीय त्रावश्यकता की पूर्ति करने के वैद्यानिक श्राविकार से भारतीय वंचित रह जाते हैं। कुछ भारतीय वैंक, जैसे इम्पीरियल चैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य भी करते हैं परन्तु उनका यह कारोबार बहुत कम है। इस दोत्र में कुल जितना कारीबार है यह बैंक उसका केवल १५ प्रतिशत संमालते हैं; (२) एक्सचेन्ज बैंकों ने मारतीय कम्पनियों की श्रपेता भारत में विदेशी कम्पनियों को विशेष सुविधा दी । भारतीय कम्पनियों को सुविधा देने से पहले इन्होंने बराबर इस बात पर जोर दिया कि कारोबार विदेशी नहाजी कम्पनी, बीमा कम्पनी इत्यादि को दिया जाय। इससे भारतीय श्रीर विदेशी कम्पनियों में भेद किया जाने लगा जबकि भारतीय कम्पनियों को श्रधिक सुविधायें मिलनी चाहिये थीं; श्रीर (३) कुछ समय पहले तक एवसचेन्ज बैंकों पर श्रान्य भारतीय व्यापारिक बैंकों की श्रापेछा रिजर्व बैंक का श्रिधिक नियंत्रण नहीं था। इससे उन एक्छन्वेज वैंकों से लेन-देन करने वाली को श्रमुविधा का सामना करना पड़ा। परन्तु वैंकिंग कम्पनी का कानून द्वारा विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में विशेष ज्यवस्था करके उक्त दोष को दूर कर दिया गया है।

वैंकिंग कम्पनी कानून (१६४६)—इस कानून की श्रानेक व्यवस्थायें जैसे लाइसेन्स, श्राण पर प्रतिबन्ध, नई शाखाश्रों की स्थापना, जाँच इत्यादि एकसचेंज वेंकों पर भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी श्रान्य व्यापारिक वेंकों पर । इसके श्रातिरिक्त भारतीय लेन-देन करने वालो के हितों की रक्ता करने के उद्देश्य से विदेशी वेंकों के सम्बन्ध में कुछ विशेष व्यवस्थायें की गई हैं, (१) भारत के बाहर जो वेंक रजिस्टर हुए हैं (incorporated) उनकी पूरी खुकता पूँजी श्रोर सुरिब्वित कोष कम से कम १५ लाख रुपये होना चाहिए; परन्तु यदि इनकी शाखायें वम्बई या कलकत्ते में हैं तो उनके पास कम से कम २० लाख की पूँजी श्रोर सुरिब्वित कोष होना चाहिए। इस प्रकार खुकता पूँजी श्रोर सुरब्वित कोष की न्यूनतम रकम भारतीय व्यापारिक वेंकों की श्रपेबा एक्सचेंज वेंकों के लिए श्रिष्क निर्धारित की गई है। (२) भारत के बाहर रजिस्टर हुए वेंकों के बन्द हो जाने (liquidation) पर रिजर्व वेंक में उसका जितना धन जमा है उस पर स्वसे पहले भारतीय लेन-देन-कर्चाश्रों का श्रष्कार होगा। (३) भारत के बाहर रजिस्टर

हुए वैंकों में से प्रत्येक को वर्ष के श्रन्त में श्रपनी भारतीय शाखा द्वारा किये गये लेन-देन तथा शिन-लाभ का ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा। श्रीर (४) प्रति तिमाही के श्रन्तिम दिन इस प्रकार के सभी वैंको के पास उनके चालू श्रीर मुद्दती देय का ७५ प्रतिशत पावना शेना चाहिए।

इस न्यवस्थाश्रों से मारतीय लेनदेन कत्तांश्रों के हितों की रज्ञा की गई है। इससे एवसचेंज बैंकों का कार्य भी पहले से श्रन्छी प्रकार चला परन्तु वर्तमान परिस्थिति में भारतीय न्यापारिक वैंक विदेशी एवसचेंज बैंकों का स्थान प्रह्मा कर सकते में समर्थ नहीं हैं क्योंकि (१) पूँजी की कमी है, (२) कुशल कर्मचारियों का श्रमाय है श्रीर (३) यदि भारतीय वैंक विदेशों में श्रपनी शाखाएँ स्थापित करें तो वहीं की पूँजी को श्राक्षित कर सकता संभव नहीं है। इन सब बातों को प्यान में रखते हुए दुःख समय तक विदेशी एवसचेंज बैंकों को भारत से श्रलग नहीं किया जा सकता है श्रीर भारतीय वैंकिंग, न्यापार तथा उद्योग के हितों की रज्ञा केवल रिजर्व बैंक द्वारा इन एवसचेंज बैंकों के कार्य का सावधानी से संवालन करके ही की जा सकती है।

श्रध्याय ४६

स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना पहिली जुलाई १६५५ को स्टेट बैंक श्राफ इन्डिया एकट १६५५ के अनुसार जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति द मई १६५५ को मिली थी, हुई। स्टेट बैंक की जिसने इम्पीरियल बैंक का स्थान ले लिया है स्वीकृत पूंजी ५० करोड़ रुपया श्रीर पहिली जुलाई १६५५ को निर्गमित पूंजी ५ ६२५ करोड़ रुपया थी। एकट के अनुसार इम्पीरियल बैंक के शेयर होल्डरों को उनके पूरा मूल्य देकर प्रत्येक खरीदे शेयर के लिये १७६५ ६० १० आना और श्रांशिक मूल्य देकर खरीदे शेयर के लिये ४३१ ६० १२ आना ४ पाई हरजाने के तौर पर देने की आशा है। स्टेट बैंक के शेयरों का मूल्य ३५० ६० प्रति शेयर निश्चित कर दिया गया है। भारत का रिजर्व बैंक ५५% शेयर स्वयं खरीदेगा और ४५% शेयर दूसरों को बेचेगा।

इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया—इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया जिसका स्थान स्टेट बैंक ने लिया, देश का सबसे बड़ा व्यापारी बैंक १६२१—१६५५ के काम में अपने सम्मानित स्थान पूंजी, जमाधन, उधार दिये भ्राण आदि के हिन्दिकोण से माना जाता था। इसकी स्थापना १६२१ में कलकत्ता बम्बई और मद्रास के प्रेसीडेन्सी बैंकों के एकीकरण के द्वारा हुई थी। एकीकरण के समय बैंक की पूंजी ३ ७५ करोड़ रुपयों से बद्कर ५ ६२ करोड़ रुपये हो गई और व्यापारिक बैंकों के कार्यों के अतिरिक्त उसे कुछ सेन्ट्रल बैंक के कार्य भी करने पड़ते थे पहिली जुलाई १६५५ से यह बैंक स्टेट बैंक द्वारा अधिकृत कर लिया गया।

१६२१-३४---१६२१ से १६३५ के बीच मारतीय इम्पीरियल बैंक ने (१) साधारण व्यापारिक बैंकों के कार्य जैसे बचत जमा करना, ष्ट्र्या देना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुपया मेजना और जेवरात इत्यादि कीमती सामान को सुरिक्षित रखना इत्यादि किये परन्तु कुछ विशेषता होने के कारण सरकार ने इसके व्यापारिक वैंकिंग कार्य में कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये और यह निर्धारित कर दिया कि यह बैंक ६ महीने से अधिक समय के लिए अप्रुण नहीं दे सकेगा, अचल सम्पत्ति के आधार पर श्रुण नहीं देगा, और अपने ही शेयरों की जमानत पर भी अप्रुण नहीं देगा। यह भी निश्चित कर दिया कि यह बैंक अपने आइक

की उचित मांग की पूर्वि के श्रातिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार नहीं करेगा।

- (२) बहाँ तक यह मुद्रा की व्यवस्था कर सकता या ह्रीर द्रव्य बाजार की दर का संचालन कर सकता या इसने केन्द्रीय वैंकिंग संस्था का कार्य किया। भारतीय व्यापारिक वैंक ग्रीर एक्सचेंज वैंक ग्रपना धन इम्पीरियल वेंक में जमा रखते थे। इसने देश के निकास गृहों (Clearing houses) की भी व्यवस्था की। यद्यपि इम्पीरियल वैंक ने एक निश्चित वैंक दर घोषित की थी श्रीर व्यापारिक वैंक ग्रपना धन उसके पास जमा रखते थे किर भी वह एक पूर्ण श्रधिकार प्राप्त केन्द्रीय वैंक नहीं था श्रीर इसका द्रव्य बाजार पर उतना नियंत्रण नहीं था जितना पूर्णतया केन्द्रीय वैंक होने के लिए श्रावश्यक है। भारत के व्यापारिक वैंक काकी शक्तिशाली थे श्रीर एक्सचेंज वैंक के श्रविरिक्त सभी वैंकों का इम्पीरियल वैंक पर विश्वास नहीं था क्योंकि इसके मालिक विदेशी थे श्रीर इसका प्रवन्य मी विदेशियों के हाथ में था। इसके इम्पीरियल वैंक केन्द्रीय वैंक का स्थान न ले सका।
 - (३) इम्पीरियल वैंक ने सरकारी कारोबार की भी व्यवस्था की । इसमें सरकारी दिवया जमा होता था, सरकार की ग्रोर से यह दिवये का लेन देन करता था, सरकार को ऋग् (ways and means advances) देता था । सरकारी ऋग की व्यवस्था करता था श्रोर वह सभी कार्य करता था जो सरकारी कारो-बार के सम्बन्ध में श्रावश्यक होते हैं । इससे इम्पीरियल वैंक के पास बहुत सी ऐसी रक्षम जमा रहती थी निस पर व्याज नहीं देना पढ़ता था इससे इस वैंक की काफी श्रालोचना की गई।

१६३४-४४—भारतीय रिजर्व वैंक की. स्थापना के पश्चात इम्पीरियल वैंक के महत्व श्रीर कारोबार में काफी परिवर्तन हुश्रा है। इम्पीरियल वैंक श्राफ इण्डिया संशोधन कानून (१६३४) से श्रन्तंगत इम्पीरियल वैंक के भ्रष्टण देने के कारोबार में को प्रतिवन्घ लगे हुये थे इटा दिये गये। इसके श्रनुसार इम्पीरियल वैंक श्रव ६ महीने से श्रिषक समय के लिए श्रृण दे सकता है श्रीर श्रपने शेयरी तथा श्रचल सम्पत्ति के श्राधार पर मी भ्रुण दे सकता है इसके साथ ही इम्पीरियल वैंक श्रव विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य भी कर सकता है।

जहाँ रिजव वैंक की शाखायें नहीं हैं इम्पीरियल वैंक रिजर्व वैंक के एजेन्ट का कार्य करता है और चूँकि यह सबसे वड़ा वैंक है और अन्य वैंकों में इसका एक विशेष स्थान है इसलिए यह भारतीय द्रव्य वाजार का मुख्य संवालक भी है। व्यापारिक संस्याएँ, व्यागारिक वैंक और व्यक्ति निजी आवश्यकता पूर्ति के लिए इंग्लीरियल बैंक से भ्रुग्ण (Advances and loans) और हुन्ही मुनाने इत्यादि की मुविधा प्राप्त करते हैं। भारतीय द्रव्य बाजार की दर में इम्पीरियल बैंक की इन्ही दर और भ्रुग्ण की दर का विशेष स्थान है।

सरकारी कारोबार चलाने के लिए इम्पीरियल बैंक की कमीशन मिलता है १६३५ से १६४५ तक के लिए १० वर्ष का पहला सममौता किया गया था। इस सममौते के श्रनुसार कुल लेन-देन पर प्रतिवर्ष पहले २५० करोड़ रुपयों की रकम पर कमीशन की दर १ प्रतिशत का वह श्रीर शेष के लिए १ प्रतिशत का है निर्धारित की गई। १९४५ में इन दरों में संशोधन किया गया। १९४५-५० के ५ वर्षों के लिए यह निश्चित किया गया कि इम्पीरियल बैंक को वार्षिक लेन-दैन की कुल रकम के प्रथम १५० करोड़ रुपये के लिए १ प्रांतशत का है दूसरे १५० करोड़ स्पर्यों के लिए १ प्रतिशत का है है, फिर अगले ३०० करोड़ स्परे पर एक प्रतिशत का है श्रीर शेष रकम पर १ प्रतिशत का है ह कमीशन दिया जायगा। इम्पीरियल बैंक की इस आधार पर कड़ी आलोचना की गई है कि इसे सरकारी कारोबार से बहुत कमीशन प्राप्त होता है जो अन्य ज्यापारिक बैंकों को नहीं मिलता है। ग्राम्य बैंक व्यवस्था जाँच समिति (१९५०) ने इसकी जाँच की श्रीर यह पता लगाया कि १६४५ के सममीते के श्रन्तर्गत कमीशन की दर बहुत कम है श्रीर सरकारी कारोबार को चलाने में इम्पीरियल बैंक की भारतीय रिजर्व वैंक से प्राप्त कमीशन से कहीं अधिक खर्च करना पड़ता है। मार्च १६४६ को समास होने वाले ३ वर्षों में इम्पीरियल बैंक को सरकारी कारोबार में द्र'प्पष्ठ लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा जब कि मार्च १६४५ को समाप्त होने वाले ३ वधीं में इसे ५५'८५ लाख रुपये का लाभ हन्ना।

इसको दृष्टि में रखते हुये और भारतीय इम्पीरियल बैंक को उन छोटे २०० वेन्द्रों में अपनी याखायें खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए जहाँ सरकारी लेन देन का कार्य काफी होता है आम्य बैंक व्यवस्था जाँच सिमित ने कमीशन की दर बढ़ाने की सिफारिश की। परियाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक इस बात के लिए सहमत हो गया कि १६५० के सममौते के अन्तर्गत १६५० से १६५५ तक के ५ वर्षों में इम्पीरियल बैंक को दिये जाने वाले कमीशन की दर बढ़ा दी जाय। इसके अनुसार अब कमीशन की दर पहले १५० करोड़ रुपयों के लिए एक प्रतिशत का देह दूसरे ३०० करोड़ रुपयों के लिए १ प्रतिशत का बेह, ३०० करोड़ रुपयों से १२०० करोड़ रुपयों के लिए एक प्रतिशत का कि एक प्रतिशत का कि अब १५१ करोड़ स्था के लिए १ प्रतिशत का कि प्राप्त के लिए १ प्रतिशत का कि एक प्रतिशत का स्वित्र के लिए १ प्रतिशत का कि प्राप्त के कि लिए १ प्रतिशत का कि प्राप्त के कि करोड़ रुपयों के कारोबार के

लिए कमीशन की दर १ प्रतिशत का है र रहेगी जन कि १६४५ के समसीते के अन्तर्गत यह दर केवल ३०० करोड़ रुपयों तक ही सीमित थी। इसके साथ ही सबसे कम कमीशन दर अर्थात १ प्रतिशत का करेट अब १,२०० करोड़ रुपयों से अधिक के लेन देन पर लागू होगी जनकि १६४५ के समसीते के अनुसार यह ६०० करोड़ रुपयों से अधिक के लेन देन पर लागू थी।

जुलाई १६५५ में जिस समय इम्पीरियल वैंक स्टेट वैंक श्राफ इन्डिया को समर्पित किया गया इम्पीरियल वैंक की ४६१ शाखायें थी जनकि १६५१ में केवल ४२२ शाखायें थीं, १६५२ में ४०८ श्रीर १६५१ में ३६१ श्रीर १६५० में ३८२ थीं श्रीर श्रकेले इस बैंक के पास कुल बैंकों के जमाधन का २३ प्रतिशत, कुल वैंकों द्वारा दिये श्राण (advances) श्रीर हुणिडयों का २० प्रतिशत श्रीर कुल विनियोग का २५ प्रतिशत विनियोग था। इम्पीरियल वैंक के पास ५१२ करोड़ सपया शेयरों की पूँजी श्रीर ६१३५ करोड़ सपया शेयरों की पूँजी श्रीर ६१३५ करोड़ सपयां का सुरिच्चत कोप था। इस प्रकार इम्पीरियल वैंक के पास कुल ११:६७ करोड़ की पूँजी श्रीर सुरिच्चत कोप था। इससे भारतीय द्रव्य बाजार में इम्पीरियल वैंक के प्रमुख स्थान का श्रामास हो जाता है।

स्टेट वैंक आफ इरिडया

स्टेट वैंक का प्रबन्ध कार्य एक केन्द्रीय परिषद द्वारा किया जायगा जिसमें एक प्रधान एक उप प्रधान २ मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा १६ श्रन्य डाइरेक्टर होंगे। इन १६ डाइरेक्टरों में से ६ शेयर होल्डरों द्वारा जिनमें रिजर्व वैंक सिम्मिलित किया जायगा श्रीर प्र सरकार द्वारा रिजर्व वैंक की राय से प्रादेशिक तथा श्रार्थिक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिये मनोनीति किये जायेंगे इनमें से दो कम से कम ऐसे न्यक्ति होंगे जिन्हें सहकारी संस्थाश्रों की कार्य प्रयाली का तथा प्राम्य श्रार्थिक समस्याश्रों का विशिष्ट ज्ञान होना श्रावश्यक होगा श्रीर उनमें से एक एक केन्द्रिय सरकार तथा रिजर्व वैंक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इसके श्रातिरिक्त स्थानीय परिषद भी होंगे जैसे कि वर्तमान में बम्बई कलकत्ता श्रीर मद्रास्थ में स्थापित है।

ऐक्ट की वे व्यवस्थायें जो कि स्टेट वैंक को कुछ कार्यों के करने अथवा श्रन्य के न करने के सम्बन्ध में निर्देश देती हैं, प्रधानत: इम्पीरियल वैंक श्राफ इन्डिया एक्ट की व्यवस्थाश्रों के ही श्राधार पर बनाई गई हैं जिनके श्रनुसार स्टेट वैंक को एक व्यापारिक वैंक की तरह काम करने की सुविधायें प्रदान की गई हैं। जहाँ तक श्रावश्यक समक्ता गया है संशोधन श्रीर परिवर्तन इस हिंटकोण से नियमों में कर लिया गया है कि सुर वैंक श्राम्य श्र्ष प्रबन्ध के चेत्र में वैंकिंग के सिद्दानों का विना उलाइन किये हुये इस नई स्थिति में श्रपना कर्त्तव्य पूरा कर

सके, श्रीर साथ ही साय श्रन्य वैकिंग संस्थाओं के शेयरों की खरीद कर उनकी पूँजी सम्बन्धी कारोबार में गौण रूप से सहयोग दे सके। इस एक्ट में श्रन्य वैंकों के स्टेट वैंक में मिल जाने की सुविधा जनक सरल व्यवस्था भी दी गई है। इस व्यवस्था का तात्पर्य ऐसे वैंकों को स्टेट वैंक द्वारा श्रपने में विलयन कर लेने की सुविधा प्रदान करना है जो कि भूतकाल में विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग में उत्पन्न हो गये हैं श्रीर चल रहे हैं श्रथवा जो स्वतंत्र इकाइयों की स्थित में श्राम चल नहीं सकते। स्टेट वैंक रिजर्व वैंक का ऐकाकी प्रतिनिधि के रूप में ऐसे स्थानों पर काम करेगा जहाँ पर रिजर्व वैंक की शाखा नहीं है श्रीर स्टेट वैंक की शाखा है।

इम्पीरियल वैंक श्राफ इन्डिया का राष्ट्रीयकरण इसलिये किया गया क्योंकि (१) जनता यह श्रालोचना करती थी कि वह उस प्राचीन युग की व्यवस्था का प्रतीक था जबिक इम्पीरियल बैंक विदेशियों के हित साधन के लिये उन्हीं के नियंत्रण में कारोबार करता था, (२) प्राप्य चेत्रों तक वैंकिंग सुविधास्त्रों के पहुँचाने की ब्रावश्यकता समकी जा रही थी जो कि इम्पीरियल वैंक नहीं कर सकता था। १९५० में प्राप्य वैंकिंग जाँच कमेटी ने यह लिफारिश की थी कि इस कार्य का श्चारम्भ करने के लिये इम्पीरियल वैंक को ५ वर्ष के भीतर २७४ शाखायें खोलने के जिये सलाह दी जाय। यह सफल न हो सका। रिजर्व वैंक की सलाह से इंग्पीरियल वैंक १ जुलाई १६५१ से ३० जून १६५५ तक के ५ वर्षों के भीतर ११४ सालायें खोलने के लिये राजी हुन्ना इसमें नई शाखायें श्रीर ट्रेजरी कार्यालय सम्मितित समके जायँगे। परन्तु ३० जून १६५५ तक अर्थात् राष्ट्रीयकरण के ठीक पहिले तक इम्पीरियल वैंक केवल ६३ कार्यालय खोल सका श्रीर ५१ खलने से रह गये। यह त्राशा की जाती है कि राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप नई शाखाओं के खोलने के कार्य में शीवता की जायगी; श्रीर (३) भारतीय वैंकिंग छंस्याश्रों तथा द्रव्य बाजार का विकास करना भी श्रावश्यक समस्ता गया जो कि सरकारी संस्था द्वारा ही कुशलता पूर्वक किया जा सकता था।

यद्यपि स्टेट बैंक की कार्य प्रणाली इम्पीरियल बैंक पर मुख्यतः श्राधारित है फिर भी इसकी कुछ विशेषतायें हैं जैसे (१) एक्ट में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक को जनता के हित सम्बन्धी नीतियों के सम्बन्ध में श्रावश्यक उपयुक्त निर्देश दे सकती है; (२) स्टेट बैंक पर नियम के श्रनुसार यह श्रनिवार्य कर दिया गया है कि प्रथम ५ वर्षों के भीतर ४०० नई शाखार्ये खोले, पर सरकार को यह श्रधिकार प्रदान किया गया है कि यदि वह श्रावश्यक समसे तो यह श्रवधि बढ़ा सकती है; श्रीर (३) एक "श्रनुकलन तथा विकास कोष" की स्थापना कर दी गई है निसमें ५५% स्टेट वैंक के शेयर रिजर्व वैंक के पास होने के कारण को लामांश (dividend) मिलेगा जमा किया जायगा। इस रकम में से निश्चित सीमा के श्रांतरिक जो घाटा शाखाश्रों के कार्यालयं को होगा पूरा किया जायगा। इस्पीरियल वैंक घाटा सहने के कारण नई शाखार्य श्रिष्ठक नहीं खोल सका। यह किटनाई इस कीप की स्थापना से दूर कर दी गई है।

विकास कार्य क्रम—स्टेट वेंक आफ इन्हिया एक्ट के सेक्स १६ (५) के अनुसार सरकार ने २७२ केन्द्रों के स्थापना की, १६५७ के अन्त तक स्टेट वेंक की शाखाओं के सोचने के लिये व्यवस्था रक्खी है। ये प्राय: ऐसे स्थान है जहाँ पर या तो जिले का खनाना है अथवा विशिष्ट सरकारी खनाना है। इनके अवि-रिक्त स्टेट वेंक ने भारतीय इन्पीरियल वेंक से ५१ अपूर्ण रूप से स्थापित केन्द्रों को ले लिया था। १६५७ में स्टेट वेंक ने शाखा कार्यालय ६१ केन्द्रों में खोले। इस प्रकार १ जुकाई १६५५ से कुल खोली गई शाखाओं की संख्या १५७ हो गई। इनमें से ११३ तो सरकार द्वारा स्वाकृति प्रदान २०२ शाखाओं में से है और ४४ इम्पीरियल वेंक से लिये हुये अपूर्ण रूप से व्यवस्थित ५१ शाखाओं में से हैं। १६५७ के दिसम्बर के अन्त तक स्टेट वेंक आफ इन्हिया के ६२० कार्यालय हो गये थे जिनमें प्रधान कार्यालयों की संख्या भी सम्मिलित हैं। १६५६ में इनकी संख्या ५३६;१६५५ में ४८० और १६५१ में ३६१ थी। विकास का कार्य क्रम बन रहा है पर जैसी आशा की गई थी उस गति से नहीं।

उत्तरीय शालाक्षो पर आधिक प्रभावशाली नियंत्रण रखने के दृष्टिकीण से तथा अधिक विस्तृत रूप से वैकिंग सुविधा जनता का प्रदान करने के लिये स्टेट वैंक ने वेन्द्रीय सरकार की अनुमित से अपने कार्य व्यवस्था की १ जनवरी १९५८ से एक नया केन्द्र बना कर तथा नई दिल्ली से एक प्रधान कार्यालय की स्थापना करके की है इस नये केन्द्र के अन्तर्गत जभ्मू काश्मीर राज्य पंजाब, राजस्थान, उ० प्र० के पश्चिमी इलाके और दिल्ली तथा दिमांचल प्रदेश के केन्द्रीय राज्य आते हैं।

किन्ही बड़े बड़े स्टेट-एशोशियेट के वैद्धों के स्टेट बैंक मिला लेने का प्रस्ताव जिसकी सिफारिश आफ इन्हिया करल केंडिट सर्वे कमेटी ने की थी। सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार छोटे-छोटे स्टेट-एशोशियेट वैंकों के भी मिलाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

शास्य वित्त व्यवस्था—स्टेट वैंक श्राफ इन्डिया ग्राम्य वित्त व्यवस्था में उत्तरीत्तर श्रपनी रुचि ग्रदर्शित कर रहा है। कृषि सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में स्टेट बैंक के कार्यों की जाँच रिजर्व वैंक द्वारा निर्मित गैर सरकारी कमेंगी ने १९५७ में की थी जिमका श्येय स्टेट वैंक के लिये सहकारी श्रीर कृषि सम्बन्धी विकास वित्तीय व्यवस्था के प्रति विकास कार्य की योजना बनाना था। श्रपनी रिपोर्ट में कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि कृषि के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में, सलाह कार्य तथा समायोजन कार्य पूर्ववत रिजर्व बैंक श्राफ इन्हिया का उत्तरदिया सममा जाना चाहिये श्रीर स्टेट बैंक को कृषि उत्तरि के विनिमय सम्बन्धी बढ़ते हुये खर्च को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये। भारत का स्टेट बैंक इस कार्य को पहिले से ही कर रहा है।

श्रौद्योगिक वित्त व्यवस्था—स्टेट बैंक ने श्रन्य संध्याश्रों के सहयोग से जो अग्रगामी योजना ६ केन्द्रों में प्रारम्म की थी वह २७ अन्य केन्द्रों में भी लागू कर दी गई। इसके श्रतिरिक्त स्टेट बैंक ने एक श्रति उदार श्रूषा योजना भी श्रारम्म की जिसके श्रन्तर्गत उघार लेने की विधि को बहुत सरल कर दिया गया ताकि छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाली श्रौद्योगिक इकाइयाँ इस सुविधा का श्रमगामी केन्द्रों में श्रधिकाधिक लाम उठा सके। स्टेट वैंक अब कुछ श्रीद्योगक इकाइयों को सहायता देने के लिये तैयार है यदि उसे यह विश्वास दिला दिया जाय कि वे ऐसी जमानते दे सकेंगे। जिन्हें स्टेट बैंक स्त्रीकार कर लेना जब कि वे किन्हीं तांत्रिक तथा व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तन कर ले । नेशनल स्माल स्केवा इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग में बनाई हुई स्टेट बैंक की योजना के अन्तर्गत यह सम्भव है कि कोई छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाली उद्योग संस्था जिसे कारपोरेशन के द्वारा सरकार के अधिकार में किसी कम्पनी को अधवा सरकार के किसी विभाग को श्रयवा सरकारी एजेन्सी को या श्रन्य एजेन्सियों को माल देने की श्राचा प्राप्त हो गई है इसके लिये कच्चे माल के मूल्य के बराबर पूरी द्रव्य की सान्ना बैंक के नाम कर देने पर प्राप्त कर सके। यह इस लिये सम्भव भी है क्यों कि भूरण का वह अश जो बैंक देगा यदि साधारण तया दिये जाने वाले आरुष की मात्रा से अधिक है तो कारपोरेशन द्वारा उसकी गारन्टी मिलनी आवश्यक मी है। इसके श्रातिरिक्त यह प्रस्ताव भी किया गया है कि यह बैङ्क अनुभव प्राप्त करने के लिये स्टेट फाइनेन्छियल कारपोरेशन के एजेन्ट की तरह श्रमगामी केन्द्रों में छोटी मात्रा में उत्पादन करने वालें उद्योगों के लिये अम करेगा ।

इस ऋण सम्बन्धी उदार योजना के आरम्भ होने के बाद से आग्रगामी केन्द्रों में स्टेट बैझ द्वारा दिये गये आरूगों की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई है। इस प्रकार दिसम्बर १६५७ में बैझ ने १८६ ऋगों के देने की अनुमति दी थी। कुल ८०.२४ लाख रुपयों का यह ऋगा था जबकि १६५६ के दिसम्बर के अन्त में केवल २५ ऋगा १०.६५ लाख रुपयों के दिये गये थे। १६५७ में स्टेट वैंक आफ इन्हिया एक्ट का संशोधन किया गया जिसके अनुसार उद्योगों को न्यक्तिगत चेत्र से मी स्टेट वेंक साधारण अविध के लिये अनुसार देश के औद्योगीकरण को द्वितीय योजना के अनुसार प्रोत्ताहन मिल सकेगा। इस संशोधन के पहिले स्टेट वैंक आफ इन्हिया को ६ महीने से अधिक अविध के लिये अनुशा देने का अधिकार नहीं था और न स्यायो सम्पत्ति के आधार पर अनुशा देने का ही अधिकार था। इल के संशोधन ने इन प्रतिवन्यों को मिटा दिया है और स्टेट वैंक को ६ महीने से अधिक काल के लिये अनुशा दिने का अधिकार प्रदान कर दिया है। फिर भी स्टेट वैंक ७ वर्ष से अधिक काल के लिये अनुशा अन भी नहीं दे सकता। इस प्रतिवन्य की आवश्यकता इसलिय पड़ी कि रीकाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा अनुशों की सुविधा ३ से लगाकर ७ वर्ष तक के लिये निश्चत थी। यह संशोधन, स्टेट वैंक को यह भी अनुमांत देता है कि रिजर्व वैंक की सलाह से केन्द्रीय परिषद के निर्देशानुसार किसी भी आर्थिक संस्था के लो केन्द्रीय सरकार द्वारा विजत है शेयर तथा डिवेन्चर खरीद सकता है। इस संशोधन का तात्कालिक ध्येय यह है कि स्टेट वैंक को रीकाइनेन्स कारपोरेशन के शेयर पूजी में योगदान दे सर्के।

जमाधन-ऋग तथा विनियोग

स्टेट वैंक भारत का श्रकेला सबसे वहा न्यापारिक वैंक है। १६५७ के दिसम्बर माह के अन्त तक इसका जमाधन विनियोग और श्रुण की मात्रा कमशः ३६६ के करोड़ रुपया, १८३ करोड़ रुपया, तथा १७३ करोड़ रुपया थी, जबकि सब अनुस्चित वैंकों को मिलाकर इन मदों की मात्रा कमशः १२६७ करोड़ रुपया थी। १८५७ में नकद विनियोग और श्रुण का जमाधन से श्रनुपात स्टेट वैंक के सम्बन्ध में ११६% ५०% और ४०%% कमशः था। श्रन्य श्रनुस्चित वैंकों की तुलना में यह स्थिति श्रिधक श्रन्छी थी।

१६५७ में स्टेट वैंक श्राफ इन्डिया के जमा धन १२४ करोड़ रुपयों से बद् गया (२४२ करोड़ रुपयों से ३६६ करोड़ रुपये हो गया।) यह वृद्धि किसी एक वैद्ध के सम्बन्ध में बहुत बड़ी वृद्धि है। इसका कारण यह है कि यू॰ एस॰ पव-लिक ला ४८० फराड के अन्तर्गत भारतीय रुपये इस वैद्ध के पास जमा कर दिये गये वैद्ध के स्टेट के अन्तर्गत अप्टण तथा खरीदी हुँडियो में लगमग ३३ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है जब कि १६५६ में केवल ३४ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य व्यापारिक वैद्धों के विरुद्ध स्टेट वैद्ध की उन्नित किसी भी तरह घट कर नहीं रही। इसके अतिरिक्त जमाधन की माना में अप्रण की रकम से अधिक वृद्धि होने के कारण बैद्ध अपनी विनियोग तथा नकद कर स्थिति अधिक सुदृद्ध बनाने में सफल हुआ है (विनियोग ७६ ५ करोइ रुपये और नकद १२ ६ करोइ रुपये)।

करोड़ रूपयों में 🖟 🗥

	२९ । दसम्बर्भ	1	
	१६५५.	. १९५६	१९५७
पूँजी	५ '६ ह	५.६२	प्-६२
र नितकोष	ह १ ३५	६•३७	६ •६२
जमाधन	२२५.६६	रे४२°१२	३६६५५२
दूसरे बैंकों से लिया ऋग	4.00	१७•२७	'१६ प्
उँघार दिया ऋग तथा स्तरीदी हुरिडयाँ	१०५°८१	१४०°१६	१ ७३'४८
विनियोग ँ	११६ १७	१०६९⊏७	१ ८३.२३
नकद	\$3.08	रदाद४	४१भूर
जमाधन का श्रनुपात			
ऋग से	४६. ⊏%	₹0.5%	80.4%
विनियोग से	48.0%	AA.5%	40.0%
नकद	83.0%	88.6%	18.1%
` ** ·			5

लाम-स्टेट वैंक को १९५७ में १ ८७ करोड़ क्पयों का लाभ मिला। यह मात्रा १९५६ के लाभ की तुलना में ३१ करोड़ रुपयों से श्रिषिक है। इस लाभ का कारण यह है कि बैंक की कुल श्राय = द६ करोड़ रुपयों से जो कि १६५६ में थी १९५७ में बढ़कर ११५८२ करोड़ रुपये हो गई। इस आय में से द'२५ करोड़ रुपये न्यान तथा (discount) द्वारा प्राप्त हुये थे। न्यान की दर अभी होने के कारण स्टेटवैंक ने अन्य बैंकों के समान अधिक लाभ प्राप्त किया। डिविडेन्ड की मात्रा १६% प्रतिवर्ष ही बनी रही। जिसमें केवल ६० लाख र्पया खर्च हुआ। इस लाम में से २५ लाख रुपये रिज्ञतकोष में स्थानान्तरित कर दिये गये जब कि १९५६ में केवल २.५ लाख रुपये ही स्थानान्तरित किये गये थे। रिज्ञत कीय इस प्रकार ६ ३७ करोइ रुपयों से बहुकर ६ ६२ करोइ रुपये हो गया। जब कि कर्मचारियों का बोनस ४० लाख रुपयों से घटा कर ३२ लाख रुपये कर दिया गया उनके हित कोपं की रकम १० लाख ही कायम 'रक्खी गई। बैंक के हाइरेक्टरों ने एक स्टांफ की श्रापरेटिव हाउसिंग फन्ड कायम किया है जिसमें ब्रारम्भ में ही १० लाख रुपया रक्खां गया है। इसका प्रयोग कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋगा देना है। यह ऋगा कम वेतन वालों को दिया जायगा इसलिये न्याज की दर बहुत ही साधारण रक्खी जायगी।

श्रध्याय ५०

भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक वैंक

मारतीय ज्वाह्न्ट स्टाक वैंक मारतीय कम्पनी कानून के श्रन्तर्गत रिजरटर्ड संस्थायें हैं। मारतीय कम्पनी कानून की व्याख्या के श्रनुसार वैंकिंग कम्पनी का मुख्य कार्य चालू खाते में या श्रन्य खातों में रुपया जमा करना श्रीर चेक, ड्राफ्ट तथा श्रार्डर द्वारा जमा रुपया वापस करना है। १६४६ के कानून में वैंकिंग कम्पनी की परिभाषा श्रीर स्पष्ट रूप से दी गई है। इसके श्रनुसार वैंकिंग का श्रर्य है जनता का जमाधन श्रूषा देने श्रीर विनियोग के लिए स्वीकार करना जिसे माँग करने पर चेक, ड्राफ्ट या श्रार्डर इत्यादि के द्वारा वापस किया जाता है।

भारतीय ज्वाहन्ट स्टाक वैंकों में इम्पीरियल वैंक, श्रन्य श्रनुस्चित वैंक (श्रमांत् ऐसे वैंक जिनकी पूंजी श्रीर सुरिक्षित कीप ५ लाल कपये या श्रिषक हैं) श्रीर गैर-श्रनुस्चित वैंक शामिल हैं। भारतीय ज्वाहन्ट स्टाक वैंक वह सभी कार्य करते हैं जो विदेशों में इयाणारिक वैंक करते हैं। यह (१) दीर्घकालीन (fixed), चालू (curfent) श्रीर वचत जमाधन (Savings deposits) स्वीकार करते हैं; (२) हुण्डियों को भुनाते हैं, सामान, स्टाक, सोना, जेवरात, बुलियन श्रीर श्रचल सम्पत्ति इत्यादि पर श्र्यण (advances) देते हैं श्रीर सरकारी श्रयणपत्रों श्राहि में रुपया लगाते हैं; (३) श्रपने श्राहक की श्रीर से रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को मेजते हैं; साथ ही एक खाते से दूसरे खाते में जमा करते हैं; (४) श्रपने श्राहकों की श्रीर से श्र्यपत्र, श्रेयर इत्यादि वेचते-खरीदते हैं श्रीर (५) जेवरात, बहुमूल्य कागजात इत्यादि श्रपने पास सुरिक्त रखते हैं।

शेयरों की पूंजी, सुरिज्ञत कीप और जमाधन भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक वैंकों के मुख्य देय हैं और नकद रुपया, ऋगा, सुनाई हुई हुन्डियाँ, सरकारी तथा अन्म ऋगापत्र और अन्य अचल सम्पत्ति इनके मुख्य पावने हैं। व्यापारिक वेंकों को अपने पावने छीर देय में सन्तुलन स्थापित करना पड़ता है। जमाधन के नकदी ऋगा तथा विनियोग के अनुपात से व्यापारिक वेंकों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यदि पूंजी तथा सुरिज्ञत कोप का जमाधन से अनुपात अधिक है तो स्पष्ट है कि वेंक की स्थित मजबूत है। कुल जमाधन और नकदी के अनुपात से मी वेंक की ज्ञमता जानी जाती है। यदि अन्य वार्ते समान रहें तो जिस वेंक के पास नकद द्वय अधिक होगा स्पया जमा करने वाले व्यक्तियों का उस पर ही अधिक

विश्वास भी होगा। परन्तु नकद द्रव्य श्रिषिक होने का श्रर्थ यह है कि नकद घन जमा रखा जाय श्रीर उससे कुछ श्रायन हो। इसीलिए वैंक श्रपनी नकदी, विनियोग श्रीर श्रुण इत्यादि में सन्तुलन रखते हैं।

मुख्य पश्चित्तयाँ —देश की आर्थिक स्थिति तथा अन्य अनेक कारणों पर निर्मर होने के कारण भारतीय ज्वाहंट स्टाक वैंकों में अपने विकास की अविध में अनेक परिवर्तन हए:—

- (१) श्रारम्म में विदेशी ज्यापारिक संस्थाश्चों ने श्रपने ज्यापार का संचालन करने के लिए ज्यापारिक वैंकों का कार्य किया श्रीर इस प्रकार ज्यापारिक वैंकिंग का कार्य विदेशी संस्थाश्चों के हाथ में रहा। तराइचात् वैंकों की प्रयक रूप से स्थापना हुई। वीसवीं शताब्दों के श्रारम्भ में भारत में केवल ६ ज्वाइंट स्टाक वैंक थे। जिनकी पूंजी श्रीर सुरिक्तित कोप ५ लाख रुपये या श्रीर जमाधन में करोड़ रुपये था। इन ह वैंकों में से केवल दो वैंक, इलीहाबाद वैंक श्रीर पंजाब नेशनल वैंक जिनकी स्थापना क्रमशः १८६५ श्रीर १८६४ में हुई, श्राज तक कार्य कर रहे हें श्रीर भारत के बड़े वैंकों में से हैं। इलाहाबाद वैंक का प्रवन्ध श्रारम्म से ही श्रमारतीयों के हाथ में रहा ई श्रीर १८२७ से इसका प्रवन्ध चार्टर्ड वैंक श्राफ इन्डिया, श्रास्ट्रेलिया ऐन्ड चाइना करता है जो स्वयं एक्सचेंन्ज वेंक है। इन ६ वैंकों में से केवल तीन वैंकों का प्रवन्ध भारतीयों के हाथ में था जिनमें पंजाब नेशनल वैंक भी शामिल है।
- (२) भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बैंकों को स्वदेशी आन्दोलन से प्रेरणा मिली। इसके साथ ही प्रथम श्रोर दितीय विश्व युद्धों श्रीर देश के श्रार्थिक विकास से भी इनको प्रोत्साहन मिला। '१६०६ श्रीर १६१३ के बीच उन बैंकों की संख्या जिनकी पूँजी श्रीर सुरिह्नत कोष ५ लाख रुपये से श्रीष्टक था ६ से १८ हो गयी। इन बैंकों की कुल चुकता पूँजी श्रीर सुरिह्नत कोष ४ करोड़ रुपये श्रीर कुल जमाधन २२ करोड़ रुपये था। १६२१ तक इस प्रकार के बैंकों की संख्या २५ तक बढ़ गयी जिनकी कुल चुकता पूँजी श्रीर सुरिह्नत कोष ११ करोड़ रुपये श्रीर कुल जमाधन ७१ करोड़ रुपये था। १६३६ तक इनकी संख्या ५१ तक पहुँच गई जिनकी कुल चुकता पूँजी श्रीर सुरिह्नत कोष १३६ करोड़ रुपये श्रीर जमाधन लगभग १०१ करोड़ रुपये था। दितीय विश्व युद्ध का भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बैंक व्यवस्था के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा। १६३६-४१ में इन बैंकों की प्रगति धीमी रही। यदि नये खुलने से बैंकों की संख्या में वृद्धि, उनकी नयी शाखाएँ श्रीर उनके जमाधन की दिष्ट से देखा नाय तो १६४२-४६ में प्रगति विशेष तेज रही।

श्रनुस्चित बैंकों की संख्या, जिसमें इम्पीरियल बैंक श्रीर एक्सचेंन्ज बैंक भी शामिल हैं, जून १६३६ में ५१ से, जून १६४६ में ६३ हो गयी श्रीर इनकी शाखाश्रों की संख्या जिनमें इनके प्रधान कार्यालय भी शामिल हैं १,३२८ से ३,१०६ हो गई। युद्ध श्रारम्भ होते समय इनका जमाधन २३८ करोड़ रुपये या जो बढ़कर १६४६ में १,०६७ करोड़ रुपये हो गया।

(३) भारत में स्वाइन्ट स्टाक वैंक की प्रगति के साथ ही श्रमेक कारणों से. बहुत से वैंक फेल हो गये क्योंकि (ग्रा) उनके पास पूँजी श्रीर सुरिक्ति कोष पर्याप्त नहीं या, (व) प्रवन्ध बुटिपूर्ण या श्रीर श्रनुभवी कुशल कर्मचारियों का श्रमाव या, (स) शीव लाम कमाने की इच्छा से ऐसी मदों में रुपया लगाया गया जिनमें हानि की श्रविक संमावना थी, श्रीर (द) कारोवार का श्रव्छी तरह संचालन करते रहने पर भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। ३१ दिसम्बर १६४६ श्रीर ३१ दिस-म्बर १९५२ के बीच इम्पीरियल वैंक की शाखाओं की संख्या ६४ तक बढ़ गई। पहले कुल ३५८ गालाएँ यीं नो बहर्कर ४२२ हो गई। परन्तु अनुस्चित वैंकों की संख्या में २६० की कमी हुई (२,४४१ ते घट कर २१८1 रह गये) । इसी प्रकार गैर-अनुस्चित वेंकों की संख्या २,०२६ से घटकर १३५१ हो गई अर्थात् ६७८ की कमी हुई। त्वेच्छापूर्वक श्रीर श्रनिवार्यवः शालाएँ वन्द कर देने से श्रीर कई ग्रन्य कारणों से शालाग्रों की संख्या घट गयी। इघर कुछ वर्षों से १६४६ के वैंकिंग कम्पनी कानून के अन्तर्गत कड़े प्रतिवन्य लगा देने से श्रीर रिजर्व वैंक द्वारा मली प्रकार देख-रेख के कारण वैंकों के फेल होने की गति मन्द हो गई है। मार्च १९५० से रिनर्व वैंक ने इन वैंकों का नियमित रूप से निरीच्या करना आरम्म किया और १६५५ के अन्त तक ४५३ वैंकी का निरीच्च पूरा किया जिसमें से २४० वैंकों का पुनर्परीच्च भी एक से अधिक बार हुआ। रिजर्व वैंक ने इन वैंकों को श्रपनी रिर्पात चुघारने के लिए श्रानी कार्य प्रचाली में सुधार करने का सुकाव दिया। रिजर्व वैंक के इस सतर्क निरीक्षण से फेल होने वाले वैंकों की संख्या घट गई। १६५७ के श्रन्त में ३३५ वैंक अपने विकास कम की रिपोर्ट देते ये जिनमें चे २४२ भतिमाइ श्रीर वाकी हर तीसरे महीने।

यद्याप फेल होने वाले वैंकों की संख्या घट गई और वैकिंग-कार्य की स्थिति में सुघार हुआ है परन्तु रिजर्व वैंक की जाँच से पता चलता है कि कुछ दोप अब भी है जिनमें प्रमुख यह हैं: अनुभवी और शिच्चित कर्मचारियों की कमी है, हिसाव उचित रीति से नहीं रखा जाता है, संचालन मन्डल वैंकों के मामलों की ओर उचित घ्यान नहीं देता है, प्रधान कार्यालय का विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण दीला पद गया है, वैंक काफी पुराना होते हुए भी उसकी सुरच्चित पूँजी की स्थिति श्रयन्तोषजनक रही है, विनियोग की स्थिति श्रम्छी न रही श्रीर बचत को श्राक-पित करने के लिए श्रन्य बैंकों की श्रपेचा ब्याज की दर बढ़ा दी है। लगातार श्रूण लेते रहने से कुछ बैंकों के पास नकद द्रव्य की स्थिति बिगड़ गई। कुछ, बैंकों न, विशेषकर गैर-श्रनुस्चित बैंकों ने, श्रपने साधनों की श्रपेचा कहीं श्रिषिक श्रूण दिये।

वेंकों का फेल होना बहुत घातक है क्योंकि (१) वेंक से लेन-देन करने वालों को गहरी चृति उठानी पढ़ती है, श्रीर (२) बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है जो भारत जैसी पिछड़ी हुई श्रार्थिक व्यवस्था वाले देश के लिए, जहाँ साख को चृति पहुँचने से सारा कारोबार छिन्न-भिन्न हो जाता है, बहुत हानिकारक है। बैंकों को बन्द होने से बचाने के लिए श्रीर व्यापारिक वैंकों को बैंकिंग के मान्य सिद्धान्तों के श्रानुकृत कार्य कराने के लिए रिजर्व बैंक को बहुत श्रिषक प्रयन्त करना पढ़ेगा। बैंकों को बन्द होने से बचाने जौर उनकी स्थित में सुधार करने की ज्ञमता ही केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्फलता की कसीटी है।

वतमान स्थिति—१६५७ के अन्त में भारत में ४०६ ज्वाइन्ट स्टाक वैंकिंग कम्पनियाँ यो जबकि १६५३ में उनकी संख्या ५०४ थी और १६५१ में केवल ३६८। १६५७ में उनके कुल कार्यालयों की संख्या जिनमें स्टेट वैंक आफ इन्डिया के अन्य अनुस्चित वैंकों के प्रधान कार्यालयों की संख्या सम्मिलित हैं ६२०, २५७६ तथा १११३ कमशाः थी। १६५३ यही संख्या के ममाः ४२२,२१८१ और १३५७ थी आरे १६५५ में ३६१,२,१६१ और १४७३ थी। मारतीय अनुस्चित वैंकों की अपने कार्यालयों की संख्या घटाने की प्रवृत्ति जो कि १६५३ तक चालू रही—वह १६५३ से १६५७ के बीच उलट गई और उनके कार्यालयों की संख्या ३६५ अदद से बढ़ गये। स्टेट वैंक आफ इन्डिया के कार्यालयों की संख्या मी १६८ अदद से बढ़ गई। जो अनुस्चित वैंक नहीं थे उनमें कार्यालयों की संख्या पिहले की तरह ही इस काल में २५३ अदद से घट गई।

तालिका नं १ श्रीर नं २ के श्रनुसार भारतीय श्रनुस्चित वैंकों ने उन्नति की है जैसा कि उनके पूँजी श्रीर रिच्ति कोष के श्रांकर्सों से विदित होता है। १६५३ में पूँजी तथा रिच्ति कोष ६० १ करोड़ रुपया था श्रीर १६५७ में बढ़कर यह ६५ १ करोड़ रुपया हो गया। परन्तु गैर श्रनुस्चित वैंकों की स्थिति इसके विपरीत रही क्योंकि वैंकों की संख्या घट गई थी इसिलिये उनकी पूँजी श्रीर रिच्ति कोष की रकम भी १२ ४ करोड़ रुपयों से जो कि १६५३ में थी घटकर १६५७ में ६८६ करोड़ रुपये रह गई।

१६५७ के अन्त में मारतीय अनुस्चित वैंको के रिक्त कोप उनकी प्राप्त पूँजी के अनुपात में ४% से लगाकर प्रप्र'७% के लगभग बढ़ गये। परन्तु गैर अनुस्चित वैंकों के सम्बन्ध में यह वृद्धि २३% से लगाकर ४८ ३% तक ही हुई। यद्यपि रिक्त कोप रखने की मान्ना के सम्बन्ध में हमारे देश में कोई कानून लागू नहीं है फिर भी प्रचलित नियम एक न्यूनतम सीमा प्राप्त पूँजी और रिक्षत कोप के बराबर इंगित करते हैं।

तालिका १ अनुसूचित वैंकों का विकास ३१ दिसम्बर को करोड़ की इकाइयों में

	१९५३	\$£7.8	१६५५	१६५६	१६५७
पू ँजी	३२.६	३२.७	३२ ७	₹ १.१	३४'५
रिक्ति कीष	२७'५	२७•६	२६∙द	२८.०	३०'६
जमाधन	इ४४१६	७१६.६	<i>७⊏</i> £.0	८१ ७	११०१'१
नकद्	६४.६	€0'₹	द प्र.८	७६ ६	६० १३
विनियोग:					
(i) सरकारी सेक्यूरिटीज	<i>২</i> ८७ -শু	२ <u>१</u> ६ १३	३३५•६	३२३ .७	३६२'७
(ii) श्रन्य	२२'०	२३∙७	२६•७	२⊏ृ१	४६'६
ऋण श्रौर हुन्डिया	३३५.६	3.005	४३६७	प्प्रह्.७	६३५.१
जमा से श्रनुपात	d				1
नकद	20.5%	१२·६%	₹0.2%	5'5%	₹%
उधार	५२'१%	42.6%	५५.७%	६३.4%	40.0%
विनियोग	82.0%	84.5%	४४.६%	80.5%	₹3°3\$

कुल जमाधन के अनुपात में नकद रकम का अनुपात १६५० की तुलना में १६५१ में घट गया था श्रीर १६५४ में बढ़ गया था श्रीर श्रागे चलकर फिर घटा (तालिका नं० १ श्रीर नं० २) १६५७ में मारतीय श्रनुस्चित बैंकों के सम्बन्ध में उसका श्रनुपात द'२% श्रीर गैर श्रनुस्चित बैंकों के सम्बन्ध में केवल ७.६%

जमाधन—िष्छले कुछ वर्षों में इन वैंकों के जमाधन, ऋग श्रीर विनियोग में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। युद्ध के समय श्रनुस्चित वैंक श्रपनी समृद्धि की चरमसीमा पर थे। १६४७-४८ में इनमें जमाधन की रकम १,०५०३ करोड़ रणया थी जबकि १६३६-४० में यह रक्षम २३४६ करोड करवा थी। जमाधन की रक्षम में गिरायट आयी है। भारतीय अनुस्थित बैंकों का जमाधन १६५० में ६८२५ और १६५१ में ६६२६ करोड़ काये में घटकर १६५२ में ६५१ करोड़ क्ष्या हो गया। १६५५ वर्ष ध्यम यह बैंको की जमाधन की गाला १००० करोड़ क्ष्यो

तालिका नं • २ गैर-त्र्यनुसूचित वैंकी का विकास ३१ दिसम्बर को करोड़ रुपयों की इकाइयों में

	१६५६	१६५४	१९५५) १६५६	1 1840
पूँच ी	द्रभू	E.\$	3.0	0.0	€'e
रशित कीप	3.€	rt	٧₹	Y'Y	₹1€
जमाधन	4.3%	3.83	६८ १	৬২'৬	84.A
नकद	¥'Ę	y'E	६•२	ξ•0	₹:⊏
विनियोग:-		, and company			
(i)सरकारी	२०१	२१:३	3.82	रप्रभ	- १३।३
सिपग् रिटींग					1
(॥) श्रन्य	٧'٦	4.0	4.0	इ.६	Χ,≱
ऋण श्रीर	35.4	३दार	३८∵०	¥?'Ę	३३. २
पूरिस्यौ					
नमाधन स		1		1	1
श्रनुपात					
नकद	2.0%	€.4%	8.1%	E-8%	4.E%
সূ য	€0°0%	48.6%	५५.८%	५८.६%	६८५%
<u>यित्यांग</u>	80.0%	X4.5%	88.E%	XX.5%	३६.३%

में क्यर ग्रहकर १०४४ करोड़ काया हो गई यदापि भारतीय अनुस्चित वैंकों के सम्बन्ध में उसकी माधा फैबल ७८६ करोड़ काया हुई थी। युद के समय जमाधन में काफी वृद्धि हुई वयीधि सरकार न युद्ध के सामान पर अधिक खर्च किया और इससे ठेकेदारों, औदाध्यक फर्मों तथा अन्य संस्थाओं के द्वाय में अधिक नकद क्यया ग्रहा। इध्य कुछ वर्षों से जमाधन में गिरावट आने लगा है घरोकि (१) भारतीय इच्य वाजार में इच्य का अभाव है और जिन व्यक्तियों ने क्यया जमा किया या उन्होंने औदोगिक तथा अन्य कार्यों के लिए अपना क्या साम

निकाल लिया है; (२) मशीन इत्यादि खरीदने के लिए जो रुपया वैंकों में जमा किया गया था उसकी मशीनें खरीद ली गयी हैं और (३) औद्योगिक तथा आर्थिक कारोबार में तेजी आने से रुपया विनियोग में लगा दिया गया।

वैंकों के जमाधन में १६५७ में अपत्याशित वृद्धि हुई और उसकी मात्रा २४५ करोड़ रुपया हो गई जब कि १९५६ में यह मात्रा केन्ल ७७ करोड़ रुपया थी। इस मात्रा में से २२४ करोड़ रुपयों की वृद्धि भारतीय श्रनुसचित वैंकों के सम्बन्ध में थी। १६५७ में यही नहीं हुआ कि कुल वैंकों का मिलाकर जमाधन १००० करोड़ रुपयों की सीमा पार कर गया वरन् पहिली बार भारतीय श्रमुस्चित बेंकों के जमाधन की मात्रा भी ,इस सीमा के आगे हो गई (११०१ करोड़ रुपये)। यह जिमाधन में वृद्धि निम्न कारणां से हुई—(१) सरकारी त्रीर व्यक्तिगत चेत्रों में द्रव्य की श्राधिक मात्रा व्यय करने के कारण वैंकों का जमाधन भी बढ़ा, (२) श्चमरीका के चयुक्त राज्य श्रधिकारियों द्वारा भारत के श्रधिकार में ऐसे कीपों के रख देने के कारण जो कि भारतीय चरकार ने अमरीका से आयात किये हुये श्रम के मूल्य में दिया था, (३) श्रायात सम्बन्धी कड़े नियंत्रण के कारण व्यापारिक संस्थाओं के रिहत कोषों के धन को श्रस्थायी रूप से नियत समय के लिये बैंकों में जमा करने के कारण, तथा (४) उसी वर्ष न्याज की दर के नियत समय के जमाधन तथा बचत के जमाधन पर बढ़ जाने के कारण चालू जमाधन से रकम निकाल कर नियत समय के जमाधन के खाते में रखन की लोगों की प्रवृति के कारण।

कुल जमाधन में कभी की अपेद्धा कुल जमाधन के अनुपात में स्थायी जमाधन की मात्रा में विशेष महत्वशाली परिवर्तन हुआ है। "१९३६ और १६४४ के बीच स्थायी जमाधन का और कुल जमाधन का अनुपात है से गिरकर है के भी कम हो गया क्यांक स्थायी जमा खाते में चालू जमाखाते की अपेद्धा कम रुपया जमा हुआ। इसका एक कारण यह है कि युद्ध के समय स्थायी जमाधन पर व्याज की दर कम हो गयी। यही प्रवृत्ति युद्ध पूर्व की मेंदी के समय भी थी। इसका उद्देश्य प्राय: यही था कि जनता स्थायी जमाखाता न खोलकर अपना घन चालू जमाखाते में जमा करे। दूसरा कारण यह है कि जनता अपनी चचत को ऐसी सम्पत्ति जैसे सोना, शेयर या भू-सम्पत्ति हत्यादि में बदलना नहीं चाहती थी क्योंकि इनके दाम चढ़े हुए थे। इसलिए बचत बिल्कुल नकद में रखी गई जिससे दाम घटने पर उक्त सम्पत्ति खरीदी जा सके। इस प्रवृत्ति को इस आशा से अगर भी बल मिला कि युद्ध समाप्त होने के बाद इन सम्पत्तियों के भाव घटेंगे। तीसरा कारण यह है कि युद्धकाल में उद्योगों को उपयुक्त मशीन हत्यादि सामान मिलने की किटनाई के कारण बचत को श्रीद्योगिक प्रसार में नहीं लगाया जा सका श्रीर वर्तमान कारखानों की उत्पादन शक्ति का उपयोग कर श्रीषक उत्पादन करने में ही यह रूपया लगाया गया। पिछले कुछ वर्षों में स्थायी जमाधन की रकम में कुछ नृद्धि हुई है। १६५७ में श्रस्थायी श्रीर स्थायी जमाधन की मात्रा एव वैंकों को विचाराधीन रखते हुये बराबर बराबर थी जबकि १६५६ में स्थायी ४४% श्रीर श्रस्थायी ५६% थी। भारतीय श्रनुस्तित बैंकों के सम्बन्ध में स्थायी जमाधन का कुल जमाधन सर्वत्र की तुलना में श्रनुपात १६५७ में ५२% या जब कि १६५६ में यह श्रनुपात ४४% श्रीर श्रस्थायी जमाधन का कुल जमाधन के सम्बन्ध में श्रत्यात ४६% श्रीर ५६% कमशः थे। गैर श्रनुस्तित वैंकों के सम्बन्ध में श्रत्यायी जमाधन के सम्बन्ध में श्रत्यायी जमाधन के सम्बन्ध में श्रत्यायी जमाधन के श्रेष्ट भी श्रत्यायी जमाधन के सम्बन्ध में श्रत्यायी जमाधन की मात्रा गढ़ गयी श्रीर उन्हें व्यापार तथा उद्योगों की सहायता करने के लिए श्रावश्वक एँजी प्राप्त हो गयी लिसके लिए उन्होंने सुविधाएँ वढ़ाई थीं।

भारतीय रिजर्व वैंक ने इस विषय में जाँच की कि जमाधन के मालिक कौन-कौन हैं। १६५७ में ग्रस्थायी जमाधन का ४७% रुपया व्यापारिक श्रार्थिक, कार-खाने चलाने वाली संस्थान्त्रों का था, सरकार श्रीर अर्ध सरकारी संस्थान्त्रों का १२ई% श्रीर व्यक्तिगत २३% था। परन्तु स्थायी जमाधन में व्यापारिक संस्थान्त्रों का २२% सरकारी तथा श्रर्थ सरकारी संस्थान्त्रों का २६ई% तथा व्यक्तिगत लोगों का ४३६% से ऊपर था। बचत का जमाधन प्रायः व्यक्तिगत था श्रीर कुल योग का ६५६% था।

ऋष और विनियोग—१९५० में अनुस्चित वैंकों की ऋण और विनियोग की रकम लगभग बराबर थी। यह जमाधन की कमशः ४७५ और ४८६ मितशत थी। १६५१ में स्थिति बदली और ऋण की रकम कुल जमाधन की ६० मितशत तक बढ़ गई और विनियोग की रकम ४२ मंतशत तक घट गई। १९५२ में ऋण की रकम के अनुपात में कुछ गिराबट छाई और विनियोग की रकम में वृद्धि हुई परन्तु अनुस्चित वैंकों का ऋण और हुन्ही मुनाने का कागेबार कुल जमाधन की दुलना में कमी के कारण भी बैंकों के विनियोग की मात्रा के बढ़ाने में सहायक हुआ है। १९५६ में इसमें १८ करोड़ स्पयों की कमी आ गई थी (४१३ करोड़ से घटकर ३९४८ करोड़ हो गया था) परन्तु १९५७ में उसमें ८९ करोड़ स्पयों की वृद्धि हुई (३९४८ करोड़ हो गया था) परन्तु १९५७ में उसमें ८९ करोड़ स्पयों की वृद्धि हुई (३९४८ करोड़ स्पया से बढ़ कर ४८३७ करोड़ रूपया हो गई)। यह

वृद्धि वर्ष के श्रान्तिम माग में हुई। जमाधन के श्रानुपात में यह वृद्धि नगएय थी। मारतीय वेंक जिनके यहाँ श्रिषकांश जमाधन रक्खा गया था इस वृद्धि के लिये उत्तरदायी थे। भारतीय वेंकों के सम्बन्ध में इस वृद्धि का श्रिषकांश मारतीय स्टेट वेंक के विनियोग की मात्रा में हुश्रा था विसके कारण जमाधन में इतनी श्रिषक वृद्धि हुई थी। श्रम्य वेंकों के विनियोग में बहुत साधारण वृद्धि हुई थी। देश में श्रायिक तथा श्रीद्योगिक सिक्यता बढ़ने श्रीर वेंक साख की श्रिषक मांग होने से श्रमुद्धित वेंकों के श्रमुण तथा हुन्ही सुनाने के कारोबार में भी वृद्धि हो गई। श्रमुण पत्रों के श्राधार पर इसका वर्गीकरण किया जाय तो पता चलेगा कि श्रमुण के वितरण का दाँचा पहिले के समान ही रहा। १६५७ के श्रम्त में उद्योगों को ४३.६%, ज्यापार को ४२.७%, ज्यक्तिगत लोगों को ७% तथा कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में दिया हुशा श्रमुण २.७% या जब कि १६५५ के श्रम्त में इन मदों के सम्बन्ध में दिया हुशा श्रमुण २.७% या जब कि १६५५ के श्रम्त में इन मदों के सम्बन्ध के श्रांकड़े कमशः ३४.३%, ५०.१%, ८.६% श्रीर १.८% थे। १६५७ के श्रम्त में दिये हुये कुल श्रमुण का ४३३% निर्मत बत्तुश्रों श्रीर खनिजों के श्राधार पर, १०३% ज्वाहन्ट स्टाक कम्पनी के शेयरों के श्राधार पर श्रीर ५.३% सरकारी तथा द्रस्टी सिक्योरिटीज के श्राधार पर दिया गया था।

नहीं तक विनियोग का प्रश्न है अनुस्चित श्रीर गैर-अनुस्चित वैंकों के सम्बन्ध में सरकारी अग्रुस्पन का स्थान प्रधान है। यद्यपि अनुस्चि वेंकों की विनियोग की मात्रा १६५७ में दह करोड़ रूपयों से १६५६ के मुकाबले में बढ़ गई फिर भी नमानत की हिंद से अग्रुसों की प्रवृत्ति पिछले वधों के समान ही रही। विनियोग का ८७% सरकार। सिक्योरिटीन में लगाया गया। गैर-अनुस्चित वेंकों के सम्बन्ध में स्थित लगभग समान ही रही श्रीर सरकारी सिक्योरिटीन में विनियोग की मात्रा कुल विनियोग की ७२% रही।

खध्याय ४१ राष्ट्रीय श्राय

राष्ट्रीय श्राय का श्रध्ययन श्रानेक प्रकार से लामदायक है। सर्व प्रथम उसके श्रध्ययन से हमें यह पता लगता है कि देश की स्थिति किसी समय क्या है, श्रीर लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय कितनी है। इससे उनकी श्राधिक स्थिति का पता लग जाता है श्रीर यह भी श्रानुमान लग जाता है कि किस स्तर का उनका रहन सहन हो सकता है। दूसरे, राष्ट्रीय श्राय के श्रध्ययन से देश के श्राधिक विकास की उन्मुखता जात होती है। राष्ट्रीय श्राय, जनसंख्या की वृद्धि, मूल्य के स्तर हत्यादि का श्रध्ययन करने से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि देश के लोग श्रायिक हिंग्योग से उन्नित कर रहे हैं श्रयवा नहीं। राष्ट्रीय श्राय के श्राक देश के लोग श्रायिक विकास की उन्मुखता बताने के प्रमुख साधनों में से एक हैं। श्रन्त में, राष्ट्रीय श्राय का श्रध्ययन श्राधिक योजनाश्रों के लिये बहुत महत्व की बात है। योजना बनाने वालों का ध्येय विनियोग द्वारा एक निश्चित समय में राष्ट्रीय श्राय के बहुने का होता है।

पूँजी श्रीर श्राय का कोई विशेष अनुपात सन देशों पर सदैव के लिये नहीं लागू हो सकता। यह तो प्राय: श्रार्थिक विकास की स्थिति तथा मिलध्य में विकास के निश्चित ढंग पर निर्भर होता है। जापान का उदाहरण ऐसा है कि जहाँ एक पीढ़ी के काल में ही (१८८५-१६१५ के बीच) कृषि के अमिकों की उत्पादकता बिना पूँजी और उसके प्रशासनों में वृद्धि किये ही खाद, अच्छे बीज, सिंचाई के प्रभाव-धाली उपायों तथा विनाशी करों की रोक याम आदि उपायों के प्रयोग से ही दुगना हो गई। संसार के अन्य श्रधक उजितशील देशों में राष्ट्रीय आय में एक इकाई की वृद्धि के लिये दीर्घकाल में तीन या साढ़े तीन गुना पूँजी के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी है। परन्तु विशेष देशों में कम समय में निस्तन्देह अनुपात बदला है।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूँजी आय का अनुपात ३:१ पूँची के विनियोग और उत्पत्ति की वृद्धि के बीच दो वर्ष की काल विलम्बना (Time-lag) के हिसाब से माना गया था। १६५०-५१ में राष्ट्रीय बचत (राष्ट्रीय विनियोग) दर ५% आँकी गई थी और यह अनुमान लगाया गया था कि १६५५-५६ तक ६ अपितात और १६६०-६१ तक ११% और १६६७-६८ तक ७०% हो जायेगी।

इस श्रनुमान पर श्रीर इस श्राघार पर कि भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष १ रे प्रति- , शत वढ़ रही है यह श्राशा की गई यी कि १६७७ तक, श्रयांत् प्रयम पंचवर्षिय योजना के श्रारम्म काल से २७ वर्ष के बाद, लोगों की वार्षिक श्राय प्रति व्यक्ति दुगुनी हो जायगी श्रीर इसके परिणाम स्त्रस्प उपमोग का स्तर ७० प्रतिशत से कुछ श्रधिक बढ़ जायगा। पर वास्तविक परिणाम श्राशा से कहीं श्रधिक श्रव्छा दुश्रा। प्रयम योजना काल में राष्ट्रिय श्राय में वृद्धि १८ प्रतिशत हुई जो कि श्रनुमान से ७% श्रधिक श्रव्छी हुई। इसके श्रतिरिक्त प्रयम योजना काल में पूँजी उत्पत्ति श्रनुपात १९८८:१ हुश्रा, न कि ३:१ जितने का श्रारम्म में श्रनुमान लगाया या। इस श्राशातीत सफलता का कारण श्रव्छी वर्षा तथा वेकार जाने वाली शक्ति के उचित उपयोग के कारण श्रीवोगिक उत्पत्ति में वृद्धि रही है।

मारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६,२०० करोड़ रुपये के विनियोग का विचार किया गया है। इसके परिणाम स्तरूप यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय आय प्रथम योजना के अन्त में १०,८०० करोड़ रुपये से द्वितीय योजना के अन्त में १३,४८० करोड़ रूपये ही जायगी अर्थात् २७०० करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इससे पूंजी-उत्पत्ति का अनुपात २,३:१ आता है; तीसरी, चौयी और पाँचवी योजना में यह अनुपात नढ़कर कमशः २.६२:१, ३:३६:१ और ३.७०:१ हो जायगा।

प्रणाली— किसी देश की राष्ट्रीय श्राय की गणना श्रनेकों प्रकार से की जा सकती हैं: (क) उत्पादन की श्रागणन प्रणाली द्वारा (Census of Products Method) । इस प्रणाली में किसी विशेष काल की वास्तविक राष्ट्रीय उत्पित श्रयवा सब प्रकार के उत्पादनों के मूल्य (सेवाश्रों को सिम्मालत करते हुये) का योग मालूम कर लिया जाता है । माल श्रयवा सेवाश्रों जिनका उत्पादन किया जाता है उनका या तो विक्री मूल्य श्रयवा लागत, जिसका श्रयं विभिन्न उत्पादन के साधनों का परिश्रमिक है, लगाया जा सकता है । यदि विक्री मूल्य लगाया गया तब तो राष्ट्रीय श्राय विक्री के मूल्य के हिसाब से श्रांकी जायगी श्रीर यदि दूसरे दंग से हिसाब लगाया गया तब राष्ट्रीय श्राय साधनों की लागत के श्राधार पर श्रांकी जायगी । (ख) श्राय श्रागणन प्रणाली (Census of Incomes Method) । इस प्रणाली में किसी देश के निवासियों की श्राय श्रयवा प्राप्ति, पारिश्रमिक, व्याल, लगान, लाम इत्यादि चाहे जिस रूप में हो जोड़ ली जाती है । (ग) व्यय, विनियोग श्रीर बचत श्रागणन प्रणाली। Census of Expenditure, Investment and Savings Method)। इस प्रणाली में हम व्यक्तियों की श्राय को नहीं जोड़ते वरन् उनके व्यय को जोड़ते हैं। लोगों द्वारा उपयोग की

चस्तश्रों पर किये गये व्यय विनियोग तथा बचाकर रक्खी हुई रकम की गणना कर ली जाती है, श्रीर इन सब का योग राष्ट्रीय श्राय के बरावर होता है। परन्तु ऊपर बताई हुई प्रणालियों में 'से केवल किसी एक का ही प्रयोग करना श्रीर श्रन्य को छोड़ देना सदा सम्भव नहीं हो सकता। मारत ऐसे पिछड़े देश में जहाँ सचनात्रों का आवश्यक आगंगन नहीं हुआ है, तीनों प्रणालियों का प्रयोग एक साथ होता है। भारत सरकार द्वारा श्रगस्त १६४६ में जो नेशनल इनकम कमेटी की नियुक्ति हुई थी, और जिसके प्रधान प्रोफेसर पी॰ सी महजीनोविस थे, उसने फरवरी १६५४ में अपनी रिपोर्ट दी | उसमें उत्मित्त आगणन प्रणाली श्रीर श्राय श्रागणन प्रणाली का प्रयोग किया है। उत्पत्ति श्रागणन प्रणाली का प्रयोग कृषि. बन, परा पालन, आखेट, मछली मारना, खनिज पदार्थ खोदना और उद्योगों के सम्बन्ध में किया है। श्रीर श्राय श्रागणन प्रणाली का प्रयोग व्यापार, यातायात. राज्य प्रवत्थ, व्यवसायिक कला और घरेलू सेवायों आदि के सम्बन्ध में किया गया है। बहुत सी बातों के सम्बन्ध में कमेटी को श्रपने निजी अनुमान लगाने पड़े क्यों कि उन विषयों की गणना नहीं हुई थी। कमेटी को वर्गीकरण सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, श्रीर श्रनेकों विषयों के राष्ट्रीय श्राय की गणना करने में सम्मिलित करने श्रथना छोड़ देने के सम्बन्ध में निर्णय करने में भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं।

राष्ट्रीय आय का अनुमान — भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान गतवर्षों में अनेकों सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों ने किया है पर वे अनुमान विश्वसनीय नहीं हैं। दादा भाई नैरोजी ने अनुमान लगाया था कि १८६ में भारत में प्रतिब्यक्ति वार्षिक आय २० ६० थी। लाई कर्जन ने १८६७ ६८ में प्रतिब्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान ३० ६० लगाया था। किन्डले शिराज ने १६११ में ४६ ६० और १६२१ में १०७ ६०, १६२२ में ११६ ६० और १६३१ में ६३ ६० अनुमान किया। साहमन कमीशन रिपोर्ट में ११६ ६० का अनुमान किया गया। डा० वी० के० आर० वी० राव ने १६३१-३२ में ६५ ६० और १६४२-४३ में ११४ ६० का अनुमान किया। इस प्रकार के अने क अनुमान हैं पर सिवाय डा० राव के अनुमान के शेष सब अन्दाज लगाये गये हैं और इसलिय भारतवर्ष की आर्थिक स्थित का ठीक-ठीक चित्र उपस्थित नहीं करते। इन अनुमानों की अपेक्षाद्ध से भी नहीं परीक्षा की जा सकती क्योंकि प्रत्येक अनुमान विभिन्न मान्यताओं के आधार पर आँका गया है।

नेशनल इनकम कमेटी ने पहिली बार विश्वसनीय और सापेच परीच्या योग्य सूचना राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में दी है। कमेटी ने अपने राष्ट्रीय आय के आनु- मान के श्रागण्यन में १०% गलती की सम्भावना रक्खी है। इससे उसके श्रनुमान श्रिषक सीमा तक ठीक श्राते हैं।

भारतवर्ष की जनसंख्या १६४८-४६ में ३५.०३८ करीड़ से बहकर १६५६-पु७ में ३८'७६८ करोड़ हो गई श्रीर इसी श्रविष में राष्ट्रीय श्राय (१९४८-४६ के मूल्य स्तर को स्थिर मानते हुये) ८,६५० करोड़ क्यये से बदकर ११,०१० करोड़ रुपये हो गई । प्रांत व्यक्ति की वार्षिक आय २४६% ६० से बहुकर २८४ ६० हो गई | नेशनल इनकम कमेटी की गणना श्रनेक वातों पर प्रकाश हालती है । इन श्रांकड़ों से एक यह परिणाम निकाला जा सकता है कि कृषि उत्पत्ति के मूल्य के बद्द जाने से किसानों को श्रविक लाम हुआ श्रीर श्रीद्योगिक तथा व्यवसापिक कार्य में संलग्न लोगों को कर भार, अमिकों का पारिश्रमिक तथा कड़चे माल के मुल्य में वृक्षि होने के कारण कुछ कठिनाई हुई। दूसरा श्रावर्षक बात जो इन श्रांकड़ों से प्रकट होती है वह घरेलू उत्पादन में छरकार का भाग है। १६५३-५४ में सरकारी ह्यार्थिक उपक्रमों ह्योर प्रशासन की वास्तविक उत्पत्ति १६४८-४६ वी वुलना में २६%% ग्राधिक भी जबिक व्यक्तिगत वृत्त में केवल २०३% की वृद्धि हुई। इनके श्रतिरिक्त उन श्राँकड़ों के सम्बन्ध में श्रन्य विशेष बात व्यक्तिगत श्राय पर सरकारी ड्राफ्टों का २०% वृद्धि है। इस वृद्धि का प्रधान कारण परोच्च कर है क्योंकि प्रत्यक्ष करों की वर्तमान मात्रा को देखते हुये श्रधिकाधिक श्राक्षय परोत्त करों का ही लिया गया है।

१६५४-५५ में प्रवृत्ति विपरीत हो गई क्योंकि कृषि हारा प्राप्ति लगमग ० ६ प्रतिशत कम हो गई क्योंकि इनके उत्पादन तथा मूल्य में भी कमी हो गई थी। खान खोदने, कारखानों तथा छोटे-छोटे उपायों तथा श्रन्य सेवाश्रों से प्राप्त श्राय २% वह गई; ज्यापार, यातायात श्रीर सूचना से प्राप्त श्राय २% वह गई। इस परिवर्तन का मुख्य कारण कृषि उत्पत्ति के मूल्य का बहुत श्रधिक गिरना तथा मध्यत्थ श्रीर तृतीय वर्ग के लोगों की श्राय में सापेन्तित श्रधिक वृह्दि हो जाना है। १६४८-४६ के मूल्य स्तर के श्राधार पर ही कृषि श्राय में कमी दिखाई पहती है, जबकि श्रन्य वर्गों में कुछ वृह्दि हुई है। इससे राष्ट्रीय श्राय की वृद्दि की दर में कमी का मी एक कारण शात होता है जो कि १६४८-४६ के मूल्य स्तर के श्राधार पर १६५४-५५ में पूछ करोड़ र० से बढ़ी जबकि १६५६-५४ में ५७० करोड़ र० से बढ़ी थी।

१६५४-५५ में राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि (१६४८-४६ के मूल्यों के श्राधार पर) सभी चेत्रों के योग से हुई थी। १६५५-५६ में इस वृद्धि के लिये निग्न चेत्र उत्तरटायी थे-(1) खदान, निर्माण तथा श्लीटे उपक्यों ने ६० करोड़ ६० की वृद्धि की; (ii) वाणिज्य, परिवहन तथा संचार ने ६० करोड़ र० की वृद्धि की तथा (iii) श्रन्य सेवाश्रों, जिनमें विभिन्न पेशे तथा सरकारी नौकरियाँ सम्मिलित हैं, ६० करोड़ र० की वृद्धि की। १६५३-५४ की तुलना में १६५४-५५ में यह वृद्धि कमशः ५० करोड़ र०, ६० करोड़ र० तथा ७० करोड़ र० हुई। किन्तु १६५५-५६ में कृपि, पशु-पालन तथा गौण कियाश्रों से माप्त श्राय में १० करोड़ र० की कमी हुई जबकि १६५४-५५ में १६५३-५४ की तुलना में ५० करोड़ र० की वृद्धि हुई। यदि चालू मूल्यों के आधार पर देखा जाय तो कृषि, पशु-पालन तथा गौण कियाश्रों में भी १८० करोड़ र० की वृद्धि हुई है।

१६५५-५६ की तुलना में १६५६-५७ में राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि में कृषि तथा गैर कृषि चेत्र का योगदान बरावर था। कृषि, पशु-पालन तथा गौग कियाश्रों से २४० करोड़ ६० की वृद्धि हुई। वाणिज्य, परिवहन तथा संचार से ११० करोड़ ६० की, खदान, निर्माण तथा छोटे उपक्रमां से =० करोड़ ६० तथा श्रन्य सेवाश्रों— सरकारी नौकरियों तथा पेशे श्रादि—से ६० करोड़ ६० की वृद्धि हुई। यदि इम चालू मूल्यों को देखें तो यह वृद्धि क्रमशः ११६० करोड़ ६०, ५० करोड़ ६०, १२० करोड़ ६० तथा ८० करोड़ ६० थी।

विचारणीय महत्वशाली बात तो यह है कि क्या इस काल में लोगों की वास्तविक आय की भी वृद्धि हुई अपवा नहीं। भारत की राष्ट्रीय आय जो कि १६४८-४६ में ८,६५० करोड़ रुपये थी, और १६५६-५७ में बहकर ११,४१० करोड़ द० हो गई (प्रचलित मूल्यों के आघार पर) परन्तु यदि गणना १६४८-४६ में मूल्य स्तर के आधार पर की जाय तो यह आय ८,६५० करोड़ र० से बढ़कर १०,०१० करोड़ ६० हो गई। श्रधिक स्पष्ट रूप से यह बात प्रति व्यक्ति वार्षिक श्चाय के श्रध्ययन से प्रकट होती है। चालू मूल्यों के श्राधार पर राष्ट्रीय श्रायः १९५३ ५४ में २८१ क० तक बढ़ गई किन्तु १९५४ ५५ व १९५५ ५६ में घटकर २५४ च० तथा २६१ च० रह गई । १९५६-५७ में यह पुनः बढकर २६४ च० हो गई। १६४८-४६ के मूल्य के आधार पर १६५३-५४ को तुलना में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि १६५४-५५ में नगस्य थी। इसका कारण यह था कि ग्राय संख्या की वृद्धि राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि की तुलना में श्रधिक तेजी से हुई । १९५६-५७ में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़कर २८४ रु० हो गई। इसका कारण यह था कि १९५६-५७ में राष्ट्रीय आय में ५.१% की वृद्धि हुई जनकि पिछले वर्ष यह वृद्धि १.९% थी तथा १९५६-५७ में जन संख्या की वृद्धि दर १.२१% थी जबिक पिछले वर्ष में यह १'२८% थी।

अन्य देशों से तुलना-- भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय संसार में

सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न देशों की राष्ट्रीय छाय के छम्ययन के अनुसार जिसमें संसार के देशों को तीन—उन्न, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभा-जित किया गया है—उन्न श्रेणी वाले देशों (जैसे यू० एस० ए०, कैनाहा, पिंच्चमी योक्तर, छास्ट्रेलिया, न्यूनीलेंड) जिनके छंतर्गत संसार की कुल जनसंख्या का १८% छा जाता है उनकी छीसत प्रति न्यक्ति वार्षिक छाय १,००० डालर से कुछ हो कम है। छजेंन्टाइना, यूक्युने, दिल्लिणी छफ्तोका, इसराहल, सोवियट रूस, छोर कुछ पूर्वी योक्त के देशों, (जो कि मध्य श्रेणी में छाते हैं छोर जिनके छन्तर्गत १५% संसार को जन संख्या छाती है) की प्रति न्यक्ति वार्षिक छाय १०० डालर से छुछ कम है। निम्न श्रेणी के देशों में एशिया के निर्धन छोर पिछड़े हुचे देश जिसमें भारतवर्ष, दिल्लिणी छफ्तोका, श्रीर पूर्वी योक्त, लेटिन छमरोका छादि समिलित है जिनके छन्तर्गत संसार की जनसंख्या का ६० प्रतिशत छाता है उनकी प्रति न्यक्ति वार्षिक छाय ५४ डालर से कुछ छिक है। इसलिए भारत वर्ष के सम्बन्य में सबसे छाविक महत्व की बात तो यह है कि प्रति न्यक्ति वारत-विक तथा द्रान्थिक छाय बढ़ाई जाय।

अध्याय ४२ घाटे का अर्थ प्रवन्धन

मारत के द्वित य पंचवर्षीय योजना में १२०० करोड़ कपये के बाटे के श्रर्थ अवन्धन का आयोजन १६५६-१६६१ तक के पाँच वर्ष के काल में किया गया है। इस नीति के अनुसार ही १६५६-५७, १६५७-५८, तथा १६५८-५६ के केन्द्रीय बजट में नये करों से प्राप्त आय को विचाराधीन रखते हुये भी क्रमशः १८४.७५ करोड़ रुपया (वास्तविक), ३८०.४६ करोड़ रुपया (वंशोधित) तथा १६६-३४ करोड़ रुपया (वजट अनुमान) का घाटा रहेगा। इन वर्षों के राज्यीय बजटों का घाटा कमशः १०४.७ करोड़ रुपया (वजट अनुमान) का घाटा रहेगा। इन वर्षों के राज्यीय बजटों का घाटा कमशः १०४.७ करोड़ रुपया (वजट अनुमान) है। घाटे के अर्थ प्रवन्धन का टीक टीक अनुमान लगाने के लिये यह आवश्यक होगा कि केन्द्रीय तथा 'क' और 'ल' राज्यों ने कुल मिलाकर प्रथम योजना काल में कितना घाटा सहन किया है उसे हम समक्त लें।

प्रयम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार का कल घाटा ३९६ ३ करोड़ रुपया था जब कि राज्य सरकारों का घाटा ४६'६ करोड़ रूपया था। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य तीन बातें हैं। (१) घाटे की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में १९५४-५५ से श्रीर राज्य सरकारों के सम्बन्ध में १९५५-५६ से व्यापक हो गई। (२) नहीं तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है प्रथम योजना काल के ३६६ करोड़ रुपये के कुल घाटे में से १६६ करोड़ रुपया तो रोकड़ बचत (Cash balance) से पूरा कर दिया गया । राज्य सरकारों के कुल ५० करोड़ रूपये के बाटे में से ३६ १३५ करोड़ रुपये की इस प्रकार पूर्ति की गई। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की रोकड़ बचत की मात्रा बहुत कम हो गई श्रीर भविष्य में घाटे को पूरा करने के लिये अन्य उपायों का सहारा लेना होगा है। (३) दितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों का ६५० करोड़ रुपयों का घाटा प्रथम योजना काल में कुल धाटे की मात्रा के दने से श्रिधिक है। सरकारी मतानुसार द्वितीय योजना के शेष दो वर्षों में २८३ करोइ रूपया के घाटे का श्रानुमान किया गया है किन्तु यह अप करोड़ रुपयों से लेकर ५०० करोड़ रुपयो तक होगा। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल बाटा १४००--१४५० करोड़ रुपया होगा जब कि योजना में केवल १२०० करोड़ रुपयों के घाटे की ज्यवस्था की गई है। संशोधित श्रनुमान के श्रनुसार यह घाटा केवल ६०० करोड़ दनया ही था।

क्या इस सीमा तक बाटे का अर्थ प्रबन्धन देश के लिये अभीष्ठ है । यदि मुद्रा प्रसार का चक शिक्तशाली हो गया तो क्या भारत सरकार इस रिथित में होगी कि इसके पहिले कि वे देश की आर्थिक व्यवस्था को अपूर्व (irreparable) हानि पहुँचा सके उनका नियंत्रण कर सके । ये कुछ महत्वशाली प्रश्न है जिन पर सावधानी से विचार कर लेना चाहिये।

घाटे के वजट का अर्थ वह स्थिति है जब कि सरकार के आय और पूँजी के वजट में कुल व्यय की मात्रा इन वजटों में बताये हुये आय के खोतों से वह जाय। मारतवर्ष के सम्बन्ध में इसका अर्थ यह होगा कि ३५५ करोड़ रुपये की कुल कमी (deficit) आय के सभी खोतों के, जैसे कर आय, व्यापारिक सेवाओं द्वारा आस अनुदान, ऋण, वचत की छोटी छोटी रक्षन इत्यादि जिन में केन्द्रीय सरकार आय प्राप्त कर सकती है, उपरान्त होगी। यह कभी या तो बचत की रोकड़ में कमी करके अथवा रिजर्व बैंक के हाथ ट्रेजरी बिल्स वेच कर पूरी की जा सकती है। चूँकि सरकारी रोकड़ बजट की मात्रा पहिले से ही न्यूनतम स्तर पर पहुँच चुकी है इसिलये इसकी सहायता से घाटा दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसिलये अब केवल एक ही रास्ता, जो खुला हुआ है, वह ट्रेजरी बिल्स को रिजर्व बैंक के हाथ वेचने का है।

सामान्यतया इसका अर्थ यह होगा कि रिजर्व वैंक और अधिक कागजी मुद्रा छापे श्रीर इस प्रकार परिचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ाये। इस प्रकार घाटे के श्चर्य प्रवन्धन से चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जायगी श्रीर यदि समान रूप से वस्तु के उत्पादन में वृद्धिन हुई तो परिणाम स्वरूप मूल्यों में स्कीतिकारी वृद्धि होगी, परन्तु मुख्य वात जिस पर श्रमी हम विचार करेंगे, वह यह है कि इस सीमा तक घाटे के अर्थ प्रवन्धन का जो कि सरकार करने जा रही है स्वामाविक परिखाम मुद्रास्फीति होगी। चाहे मुद्रा की मात्रा में कोई वास्तविक वृद्धि भी न हो जब घाटे के श्रर्य प्रवश्वन द्वारा विनियोग किया जाता है तो लोगों की श्राय बढ़ता है। इस श्चर्तारक्त श्चाय से लोग वस्तुश्चों की खरीदारी करते हैं। श्चीर यदि उपयोग की वस्तुस्रों तथा श्चन्य वस्तुस्रों की पृति जिनपर लोग श्रपनी स्राय का व्यय करते हैं नहीं बढ़ी है तब तो मूल्य में स्फीतिकारी वृद्धि होना श्रवश्यमभावी हो, जायगा। परन्तु यदि सरकार ने यह विनियोग घाटे के अर्थ प्रवन्धन द्वारा नहीं वरन् आय स्रोतों की वृद्धि द्वारा, चाहे श्रांतिश्क श्रृण लेकर श्रथना नये करों के श्रारोप द्वारा; किया है तो मूल्यों में स्फीतिकारी वृद्धि न होगी, क्योंकि जिस आय पर सरकार कर का श्रारोप करेगी या ऋण रूप में ले लेगी उसके हिसाब से वस्तुश्रों का उत्पादन हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह होगा कि जनता के धन ब्यय करने के स्थान पर

सरकार न्यय करेगी। घाटे के श्रर्थ प्रबन्धन की स्थित ही दूसरी है क्योंकि ऐसी हालत में वस्तुओं की पूर्ति को उसी मात्रा में निरन्तर इसीलिये बढ़ाया जाता है ताकि मूल्यों में स्फीतिकारी वृद्धिन होने पाने।

सिद्धान्ततः श्रतिरिक्त मात्रा में घन के विनियोग के कार्ण वस्तुश्रों की पूर्ति बढ़ती है श्रीर इस प्रकार मूल्य स्तर में स्कीतिकारी वृद्धि को रोकती है। परन्तु भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुये यह श्राशा करना कि १६५६-५७ के श्चार्थिक वर्ष में वस्तुश्रों का उत्पादन इस सीमा तक बढ़ेगा कि ३५५ करोड़ इपयों के घाटे के अर्थ प्रबन्धन द्वारा उत्पन्न उपभोकाओं की माँग पूरी होगी, युक्तिसंगत नहीं लगता। इसके कई कारण हैं। (१) दितीय पंचवर्षीय योजना का श्रिधिक जोर श्रीयोगिक विकास की दीर्घकालीन योजनाश्रो पर है। इसके कारण उपमोग की वस्तुत्रों तथा श्रन्य वस्तुश्रों की उत्पत्ति काफी समय के पश्चात् ही बढ पायेगी। १९५६-1७ में ही वस्तुः श्रों की श्रातिरिक्त मात्रा नहीं प्राप्त हो चकेगी। इसिल्ये मूल्यों में स्फीतिकारी वृद्धि होगी । (२) प्रथम योजना काल में ही उद्योगों की श्रति-रिक्त शक्ति का प्रयोग हो चुका है। ग्रीर ग्रप्रयुक्त शक्ति के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने की अधिक सम्भावना नहीं है (३) यद्यपि साधारण प्रकार के अमिकों के पूर्ति का बाहुल्य है, फिर भी दच्च अमिकों, पूँजी के प्रशायनों, विशेष रक्षायनों श्रीर कच्चे माल की बहुत कभी है। इसके कारण उपयोग की वस्तु श्रों तथा श्रन्य प्रकार की ऐसी वस्तुत्रों के उत्पादन में विलम्ब होगा जिन पर लोग श्रपनी बढ़ी हुई श्राय जो घाटे के श्रर्थ प्रवन्धन के कारण उनके हाथ श्रा जायेग़ी खर्च किया करते हैं। इससे, प्रभावशाली स्कीतिकारी चक्र आरम्भ हो जायेगा। इस बात पर यहाँ जीर देना श्रावरयक है कि चाहे चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि न भी हो परिणाम यह श्रवश्य होगा कि चलन में मुद्रा की यही मात्रा होते हुये भी लोग श्रधिक मात्रा में वस्तुत्र्यों का उपभोग कर सकते हैं। इस स्थिति में मुद्रा की कुल मात्रा जिसकी उत्पादित वस्तु कुल मात्रा से अनुपातिक सम्बन्ध जोड़ा जाता है अपने परिचलन पवेश के कारण मात्रा में बढ़ जायगी।

मूल्य में स्फीतिकारी वृद्धि का दूसरा कारण उत्पादन की वृद्धिमान लागत होगी जो कि वर्तमान उद्योगों में प्रयुक्त सर्वाङ्ग, तथा प्रसाधनों के धिसे पिटे होने के कारण तथा उनको पहले से ही अम्पूर्ण शक्ति मर काम करने के कारण लागू होगा। एक वार जब मूल्यों में स्फीतिकारी प्रवृत्ति का आरम्भ हो जाता है तब गजदूरी में वृद्धि हो जाती है और उसके कारण उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में भी दि निश्चय ही होती है। इस वृद्धि का प्रमाव संचयी (cumulative) हो जाता है। भारत में पहिले से ही मजदूर अधिक मजदूरी के लिये आन्दोलन कर रहें है। जो कुछ भी हो हमारे देश के मजदूर इस अवस्था में नहीं हैं कि अपनी वास्तविक मजदूरी को किसी प्रकार भी कम होने दें, अर्थात् अपने उपभोग की वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य दें और मजदूरी उतनी ही पाते रहें। यही भारतवर्ष की स्थिति में और केन्स (Keynes) की आर्थिक मान्यताओं में महान अन्तर है जिसके आधार पर हमारे देश में घाटे के अर्थ प्रबन्धन का प्रयोग किया जा रहा है।

इन परिस्थितिश्रों के कारण यह समस्या, जैसा कि श्रिधिकतर लोग घाटे के अर्थ प्रवन्धन पर विचार करते समय सोचते हैं, विशुद्ध रूप से द्रव्यात्मक ही नहीं है। वास्तव में यह तो मारतीय कृषि श्रीर उद्योग की श्रिधिक मात्रा में उपयोग की तथा श्रम्य प्रकार की वस्तुश्रों के उत्पादन करने की शक्ति की समस्या है। घाटे के अर्थ प्रवन्धन की सीमा श्रावश्यक मात्रा में वित्त न प्राप्त कर सकना नहीं है, वरन देश की श्र्म व्यवस्था की एक वर्ष श्रयवा कुछ वर्षों की श्रविध में उत्पादन की मात्रा बढ़ाते रहने की योग्यता है। चूँ कि घाटे के अर्थ प्रवन्ध से लोगों की श्राय श्रीर व्यय तुरन्त बढ़ जाते हैं श्रीर उनका उत्पादन नहीं बढ़ पाता, इसलिए पाँच वर्ष के श्रीस्त श्रावह के श्राधार पर तर्क उपस्थित करना ठीक नहीं है। हमें प्रत्येक वर्ष की स्थित को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें श्रीर होते होते होते हैं।

इसमें जीखिम साधारण तथा आकरिमक ही नहीं है जैसा कि वित्त मन्त्र ने हमें विश्वास दिलाया है, वरन् अत्यिषक है। यदि मारत की दशा सामान्य होती तब तो हतना बड़ा जाखिम उठाना किसी सीमा तक न्यायसंगत होता, पर चूँकि मूल्य-स्तर पहिले से ही असमान्य रूप से ऊँचा है इसिलये हमें इतनी अधिक मात्रा के अर्थ अवन्धन का विचार नहीं करना चाहिये जितना कि १६५६-५७ वे बजट में दिखाया गया है। घाटे के अर्थ अवन्धन की मय रहित सीमा बता देन कठिन है। मोफेसर बी० आर० शिनीय ने ३५ से ४७ करोड़ तक की सीम निर्घारित की है। परन्तु किसी भी दशा में, यदि हम आर्थिक दुर्घटना के लिये तैयार नहीं हैं तो अधिक से अधिक १०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष तक बाटे वे अर्थ प्रवन्यन की सीमा नियत कर सकते हैं।

मारत के वित्त मंत्री ने बजट पर विवाद का उत्तर देते हुये लोक समा व यह बताया या कि यदि स्थिति अधिकार के बाहर निकल जायगी तो सरकार के उसके सम्मालने के उपाय मालूम हैं। पर ऐसा करना असगंत और निराधा है। मूल्यों में स्कीतिकारी वृद्धि के हो जाने पर जो उपाय सरकार करेगी उनक परीज्ञा करना यहाँ असंगत न होगा। सर्वप्रथम उपाय वस्तुओं के मूल्य, उत्पाद तया वितरण श्रादि के नियंत्रण का है। सरकारी नियंत्रण केवल एक ही बात में पूर्णतया सफल हो सकते हैं श्रीर वह उत्पादित वस्तुश्रों का श्रिषक श्रन्छा वितरण है। यदि श्रर्थ न्यवस्था के मीतर से ही न्वालामुखी के समान श्राक्तियाँ मूल्यों को उँचा उठा रही हो तो यह नियंत्रण मूल्य की वृद्धि नहीं रोक सकते। होता यह है कि ऐसी स्थित में दो बाजार प्रचलित हो जाते हैं, एक तो ऐसा बाजार जिसमें नियंत्रित मूल्य चालू होता है श्रीर दूसरा चोर बाजार जहाँ श्रसमान रूप से बढ़े हुये मूल्य चालू होता है श्रीर दूसरा चोर बाजार जहाँ श्रसमान रूप से बढ़े हुये मूल्य चालू रहते हैं। इसके श्रितिस्क सरकारी नियंत्रण के कारण माजार में बस्तुश्रों की पूर्ति में भी छिपा कर रख लेने के कारण कमी श्रा जाती है। घाटे के श्रर्थ प्रवन्यन हारा बढ़ी हुई श्राय के उपयोग की वस्तुश्रों पर खर्च किये जाने से मूल्यों का स्तर श्रीर भी ऊपर उठता है। इसके स्थित सुधरने के स्थान पर श्रीर श्रीषक विगइती जाती है। यदि हम सब सचरित्र होते श्रीर प्रशासन प्रणाली दोष रहित होती श्रीर स्कीतिकारी शक्तियाँ श्रीषक शक्तिशाला न होतीं तब तो सरकारी नियंत्रण किसी सीमा तक सफल न हो सकते थे, श्रन्थपा मूल्यों में स्कीतिकारी प्रभाव को रोकने के लिये वे श्रशक है।

करों में वृद्धि तथा साख नियंत्रण श्रादि उपाय भी स्कीतिकारी प्रभाव के रोकने में श्रवमर्थ हैं। यदि मूल्य को स्कीतिकारी वृद्धि ऋण सुविधा तथा मुद्रा में प्रसार के कारण होती तब तो साख नियंत्रण का उपाय किसी सीमा तक मूल्यों की वृद्धि रोकने में सफल होता। परन्तु जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं मूल्यों में वृद्धि मुद्रा की मात्रा श्रीर ऋगा मुविधा के उतने ही बने रहने पर भी मुद्रा के परिचलन प्रवेश में परिवर्तन के कारण हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थित में साख नियंत्रण निरर्थक है। करों में वृद्धि के फलस्वरूप जनता के द्वाप से उनकी श्राय में हुई वृद्धि छीन ली जा सकती है श्रीर मूल्यों पर उसका भार घटाया जा सकता है। पर इस पिरणाम के लिये करारोप बहुत श्रधिक मात्रा में करना श्रावश्यक होगा। ऐसे करारोप के कारण उद्योगों की उत्पादन श्रीर लागत वढ़ जाती है क्योंकि इन करों का भार कच्चे माल तथा शक्ति साधनों आदि पर पहता है, श्रीर इससे मूल्य स्तर नीचे गिरने के स्थान पर ऊपर उठता है। इसके श्रांतिरक्त इसका प्रभाव व्यापारिक मनोवैज्ञानिक स्थिति पर इतोत्साहित होता है श्रीर लाम की श्राशा घट जाती है। इसे श्रर्थशास्त्र की पारस्परिक शब्दावली में देय-पूँजी की सीमान्त कुशलता में हास कह सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत दोज में विनियोग की मात्रा घट जाती है। मिश्रित आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत यह एक महत्वशाली प्रश्न है और श्रातिरिक्त करारोप की योजना श्रास्पक्त होती है।

यदि स्फीतिकारी शक्तियाँ प्रवल होती दिखाई पहें तो सरकार उदार

श्रायात नीति का भी श्रनुसरण कर सकती है। परन्तु भूतकाल के श्रनुमन से यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में ठीक ढंग की वस्तुएँ उपयुक्त मूल्य पर सम्भवतः श्रमाप्य हो सकती हैं। कुछ भी हो श्रायात में वृद्धि द्वारा देश के श्रार्थिक साधनों में वृद्धि, जिस ध्येय से ऐसा किया गया है, सम्भव नहीं हो सकती क्योंकि विदेशी वस्तुएँ देश में निर्मित वस्तुश्रों से घोर प्रतिद्वन्दिता करेंगी। इस प्रकार हमें विदेशी विनिमय का भी श्रिधिक प्रयोग करना श्रावश्यक होगा जिसकी पहिले से ही कमी है।

इमारा ध्येय द्रुतगित से श्रार्थिक विकास करना है। पर यह कार्य कल्पना-तमक नहीं है। मारत ऐसे पिछड़ी श्रर्थ व्यवस्था वाले देश में विकास की प्रगति द्रव्यिक तथा वित्तीय कारणों की श्रपेक्षा प्रीद्योगिक कारणों पर श्रधिक निर्मर है। चाहे पसन्द करें यान करें, हमें विकास की धीमी प्रगति पर ही सन्तोष करना पड़ेगा श्रन्थथा श्रार्थिक संकट निश्चित है। यह भय श्राकिस्मक नहीं वरन् ऐसा है कि महान् स्फीतिकारी शक्तियाँ देश की श्राधिक व्यवस्था को श्रपने नियंत स्थान से हटा कर उसे छिन्न-मिन्न करके विनष्ट कर टेंगी।

श्रष्याय ४३ मुद्रास्फीति

भारत को मुद्रास्फीति द्वितीय विश्वयुद्ध की देन है। युद्ध के समय भारत सरकार तथा मित्र राष्ट्रों ने मारत में काफी धन ब्यय किया जिससे प्रचलित मुद्रा की राशि बढ़ी परन्तु जिस तेजी से यह राशि बढ़ी उसी गति से माल एवम् श्रन्य सेवाश्रों में वृद्ध न हो सकी। इसके फलस्वरूप वस्तुश्रों की कीमतें वह गई श्रीर थोक माव के देशनांक में वृद्धि हुई है। १९३९ ४० में थोक माव का देशनांक १२५'६ था जो १९४३-४४ में बहकर २३६'५ स्त्रीर १९४७-४८ में ३०७ हो गया। १६४३-४४ से वस्तुन्त्रों के भाव में विशेष वृद्धि हुई न्त्रीर पहली बार देशनांक २३६ ५ तक पहुँचा । ब्रिटिश सरकार ने मारतीय रिजर्व वैंक कानून में स्टलिंग को रुपयों में बदल सकने की ब्यवस्था का लाम उठाया, स्टर्लिंग का रुपयों में विनिमय किया श्रीर इस रुपये को यह सामग्री पर भारत में ही खर्च कर दिया। इससे भारत में प्रचितित मुद्रा की राशि बढ़ी और परियाम स्वरूप मुद्रास्भीति की समस्या उत्पन्न हो गई। १६४२-४३ में कुल ६४३ ६ करोड़ रुपये के नोट चलन में ये जबकि एक वर्ष पूर्व ३८१ द करोड़ रुपये के नोट चलन में रहे थे। इस एक वर्ष में २६१ द करोड़ रुपये क अधिक तांट चलन में आए । १६४२-४३ में २३८-६ करोड़ रुपये के नोट श्रीर चलन में श्राए जिससे कुल प्रचलित मुद्रा ८८२ ५ करोड़ रुपया हो गई। १६४२-४३ में कुल प्रचलित मुद्रा में पहले वर्ष की अपेना ४६५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई श्रीर १६४३-४४ में इसमें ४२१ करोड़ रुपये की श्रीर वृद्धि हो गई । इसके साथ ही फेन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों के कुल चालू व्यय (revenue expenditure) में भी वृद्धि हुई। १६४२-४३ में केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों (जो श्रव लग्रह 'क' के राज्य कहलाते हैं) के व्यय में १५६ १६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिससे कुल ब्यय की मात्रा ४०७'०५ करोड़ रू हो गई । १६४३-४४ में द्रहर ह करोड़ रुपये का व्यय और बढ़ा श्रीर कुल व्यय ५६३ ७१ करोड़ रुपया हो गया। प्रचलित मद्रा में श्रीर सरकार के ज्यय में वृद्धि होने से वस्तुश्रों की कीमतें बढ़ गई'। इसमें कुछ संदेह नहीं कि आरम्भ में मुद्रास्कोति द्रान्यिक यी क्योंकि कीमतों में वृद्धि हाने का प्रत्यक्त कारण यह या कि प्रचलित मुद्रा में वृद्धि हुई थी। परन्तु इधर कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण केवल द्रव्य नहीं रह गया है क्यों कि सरकार के कुल व्यय की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होते हुए. भी कीमतों के

देशनांक में गिरावट प्रारम्म हो गई है। गत कुछ, वर्षों में सरकार द्वारा चालू न्यय में ही वृद्धि नहीं हुई है विल्क पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सरकार ने नई पूँजी भी लगाई है। १६५०-५१ में विगत वर्षों की श्रपेज्ञा प्रचलित मुद्रा बढ़ कर २००५ ६ करोड़ रुपया हो गई। केवल १६५१-५२ में पहली बार घट कर १८०३ ७६ करोड़ स्पया और १९५२-५३ में घटकर १७६४ ७१ करोड़ स्पया हो गई। यह कमी की प्रवृत्ति श्रस्यायी सिद्ध हुई। १९५३-५४ में फिर मुद्रा की मात्रा बह कर १७६३ ६७ करोड़ रुपया, १६५४ ५५५ में १६२० ६३ करोड़ रुपया, १६५५ पूर् में २१८४ ३२ करोड़ काया, १९५६-५७ में २३१२ दि करोड़ रुपया तथा १९५७-पूर्म में २२८७ ६२ करोड़ रुपया हो गई। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि मुद्रा के प्रचं-लन का वस्तुओं की कीमतों पर प्रमाव पहता है ऋौर एक निश्चित समय में प्रचलित मुदाराशि में वृद्धि होने से वस्तुश्रों की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती हैं। इसके विपरीत प्रचलित गुद्रा राशि में वृद्धि रोकने से वस्तुश्रों की कीमतों का स्तरं मी गिरता है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से मुद्रारफीति की मुख्य विशेषता यह है कि भारतीय उद्योग तथा कृषि चेत्र के उत्पादन व्यय में किसी प्रकार की कभी नहीं श्रायी है ख़ीर उत्पादन में भी विशेष वृद्धि नहीं हुई है। मजदूरी, खाद्यांन की कीमतों श्रीर कच्चे माल के माव में वृद्धि हुई है श्रीर इससे उत्पादन व्यय बढ़ गया है। इसके परिगाम स्वरूप वस्तुश्रों की कीमतें बढ़ी हैं श्रीर इसके फल-स्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो गई है। वस्तुश्रा की कीमत घटाने श्रीर मद्रास्पीति पर नियंत्रण रखने के लिए यह श्रावश्यक है कि उत्पादक का उत्पादन व्यय कम हो श्रौर उत्पादन वढ़ें । हमारे देश में मुद्रास्फीति के प्रसार को रोकने के लिए यही एक उपयुक्त उपाय है।

कीमतों की प्रवृत्ति—भारत में वस्तुश्रों की अपेद्धा मुद्रा-पूर्ति में अधिक वृद्धि होने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतें बढ़ी हैं। जून १६५० के बाद कीमतों के देशनांक में विशेष वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों को जन्म देने में कोरियाई युद्ध का विशेष हाथ है। अमरीका तथा अन्य प्राचत्य देशों में युद्ध की तैयारी के लिये अधिक कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सारे विश्व में खींचतान मची, इससे भारत द्वारा निर्यात किए जानेवाले सामान की और देश में विकने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। मारत में सहे बाजी से भी कीमतों वढ़ीं। जून और अगस्त १६५० के बीच कीमतों का देशनांक ३६५ ६ से ४०६ २ हो गया परन्तु अनेक वस्तुओं के मूल्य में प्रायः कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इस बीच खाद्य सामग्री की कीमतों का देशनांक ४६० ७

से ५१३.१ स्रीर विविध वस्तुस्रों का देशनांक जिनमें. निर्यात किए जानेवाले सामान भी हैं ६६२ ० से ७२७ ३ तक बढ गया । कोरियाई युद्ध के बाद वस्तुन्त्री के भाव में वृद्धि हुई जिसका एकमात्र कारण श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थीं। भारत में वस्तुन्त्रों की कीमतों में अन्य देशों की अपेद्या कम वृद्धि हुई। मूल्यों का देशनांक श्रप्रैल १६५१ में ४५७.५ तक पहुँच गया। यह वृद्धि उद्योग के लिए श्रावश्यक करूचे माल की कीमतों के बढ जाने से हुई। करूचे माल की कीमत बढ़ने का कार्गा यह था कि सारे जग में कच्चे माल की मांग बढ़ गई परन्तु पूर्ति श्रपेज्ञा-कृत बहुत कम हुई । उद्योग के लिए श्रावश्यक कच्चे माल की कीमतों में गिरावट श्राने के साथ ही दिसम्बर १९५१ तक सूचकांक भी ४३३.१ तक गिर गया। फरवरी १६५२ में कीमतें एकाएक घट गईं ख्रीर भारत तथा खन्य देशों में एक प्रकार से मन्दी आ गई। भारत में कीमतों का सूचकांक जनवरी में ४३० या जो फरवरी में ४१६ श्रीर मार्च १९५२ में ३७७३ हो गया। श्रस्थायी मनदी श्राने का मुख्य कार्या यह या कि अमरीका सरकार ने अपनी माल संग्रह की योजना में कभी कर दी। यह विराम वार्ता चलने से यह श्राशा की जाने लगी कि कोरियाई युद शीघ समाप्त हो जायगा । इसका कीमतों पर प्रभाव पड़ा और मन्दी छा गई। दुसरा कारण यह या कि भारत में कोरियाई युद्ध के समय सट्टेबानी से कीमतें बढ़ी थीं श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन होने से सट्टेबाजों को धनका लगा। इस प्रतिकृत परिस्थिति से कीमर्ते श्रीर घटीं। तीसरा कारण यह या कि भारत सरकार ने मुद्रास्फोति-निरोधक नीति लाग की थी जिसका श्रब प्रभाव प्रकट होने लगा था। इससे कीमतों का स्तर और नीचे गिर गया। ऐसी स्थिति में जब कि श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतें गिर रही थीं उस समय सरकार कीमतों के निम्न स्तर को बनाये रखने के लिए अनेक उपाय कर रही थी। इस प्रयन का भी प्रभाव प्रकट हो रहा था।

परन्तु जैसे ही कोरियाई युद्ध विराम वार्चा श्रसफल होने के चिन्ह प्रकट

१ यह उपाय इस प्रकार हैं: (१) सरकार की ज्यापार नीति जिससे स्वदेश में उत्पादन बदने के साथ ही बाजार में सामान की पूर्ति बढ़े, (२) कुछ संशोधनों के साथ नियंत्रण लागू रखना, (३) कुछ वस्तुओं पर जैसे तिलहन, वनस्पति तेल, मध्यम और मोटी किस्म के कपड़े पर निर्यात कर लगाना और लगे हुए कर में चृद्धि करना, (४) सरकार की चालू आय (Revenue budgets) में वृद्धि, (५) बैंक की ब्याज की दर में चृद्धि और नेवस्वर १९५१ से साख पर अधिक कड़े नियंत्रण की नीति।

होने लगे श्रीर शीव्र समसीता हो सकने की संमावना घटने लगी कीमतों में पुनः वांद्र होने लगी और सूचकांक जुलाई १९५२ तक ३८४ पर पहुँच गया। १९५२-पूरे में सूचकांक ३८० ६ हो गया श्रीर नव से ३८५ से लगाकर ३६५ तक में ही बदलता रहा है, केवल नवम्बर १९५२ से फरवरी १९५३ तक के काल में जबकि इस स्तर से कम हो गया या श्रीर १९५३ के बून से लगाकर सितम्बरतक के काल के तब कि वह इस स्तर से बढ़ गया था। "त्रार्थिक सलाहकार द्वारा दिये गये थोक मूल्यों का सूचकांक १९५३ के मार्च के अन्त में ३८५० या और अगस्त महीन के मध्य तक बढ़कर ४११ ६ हो गया। यह स्तर केवल १६५३-५४ में ही श्रांबक्तम नहीं या वरन १९५२ की फरवरी से लगाकर उस समय तक के बीच श्रीवकतम था। इस काल में मूल्य स्तर में वृद्धि श्रान्तरिक कारणों से हुई थी लां कि मद्रा से सम्बन्धित नहीं थे, जैसे १९५२-५३ में रुड़े, चीनी श्रीर चाय श्रादि फसलों से कम उत्पादन की श्राशंका"। मुल्य की वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया। ये उपाय चीनी का श्रायात करने का निश्चय, मॅगफली के तेल के निर्यात पर नियंत्रण, गरी तथा गरी के तल के श्रायात के प्रति उदार नीति का श्रनुसरण, खजूर के तेल, गरी, चीनी तथा विनोले के तेल पर लगाये हये आयात कर में कमी. खाद्यान देचने के लिये सरकारी उचित मूल्य वाली दुकानें खुलवाने का निर्णय, राशन की मात्रा में वृद्धि, तथा केन्द्र से आयात किये हुये पात गेहूँ का मूल्य जुलाई में १ र० प्रति मन घटा देना आदि थे। इन उपायों से मूल्यों की वृद्धि में रोक हुई श्रीर इसके साय-साय श्रायात में वृद्धि होने से, विशेष कर चीनी तथा स्थानापन वनस्पति तेल श्रादि के श्रीर नई फलल के श्रागमन से, योक मूल्यों में घटने की प्रवृत्ति लिहत होने लगी। २ अवटूबर १६५४ को समाप्त होने वाले सप्ताह में योक मूल्यों का स्वकांक ३८० ६ हो गया। यह अंक १९५२-५३ के श्रीसत के ठीक नरावर या। योड़ी सी अस्यायी वृद्धि के बाद सूचकांक निरन्तर घटता रहा भ्रोर मई १९५५ में ३४२ हो गवा।

१९४२ की सरकार की मुद्रास्कीति निरोधक नीति—मुद्रास्कीति रोकने श्रीर कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए मारत सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। सावारण रूप से इन उपायों को दो मानों में निमक्त किया जा सकता है—(१) ऐसे उपाय जिनका उद्देश्य कार्य कुशलता बनाए रखने के साथ ही सरकारी व्यय को यथा-संमव कम करना और जनता की अतिरिक्त कय शक्ति को कुन्ठित करना या और (२) ऐसे उपाय जिनका उद्देश्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाना था। सरकारी नीति में विशेष रूप से प्रचलित मुद्रा राशि को कम करने,

कर बहाने, साख पर नियंत्रण रखने श्रीर जनता को श्रिषक बचत करने की पेरणा देने पर जोर दिया गया है, सरकार ने श्रपनी मुद्रास्फीति निरोधक नीति को सफल बनाने के लिए प्रत्यच्च श्रीर श्रप्रत्यच्च करों में वृद्धि की है। बैंक के ब्याज की दर में वृद्धि होने के साथ ही सरकारी साख-नीति पर नियंत्रण लगाया। इसका परिणाम यह हुश्रा कि १६५१-५२ में (श्रक्टूबर से श्रप्रेल तक) चलन में केवल ५४ करोड़ सपयों की वृद्धि हुई जबकि १६५०-५१ की इस श्रविध में २३५ ५ करोड़ की वृद्धि हुई थी।

सरकार की मुद्रास्कीति निरोधक नीति को कुछ उफलवा मिली है परन्तु यह सफलता आशा से बहुत कम रही। इसका एक कारण यह है कि सरकारी नीति में मुद्रा पर विशेष जोर दिया गया है परन्तु अब मारत में मुद्रास्क्रीति का कारण केवल मुद्रा ही नहीं रहा है। दूसरा कारण यह है कि सरकार की श्रिधिक कर लगाने श्रीर साख का संक्रचन करने की नीति से, जो कि मारतीय मुद्रास्फीति तिरोधक उपायों का मुख्य श्राधार है, श्रप्रत्यच्च रूप से उत्पादन पर विपरीत अभाव पढ़ा है। इन उपायों से उत्पादन की वृद्धि एक गई। इनके परिग्राम स्वरूप बाजार में वस्तुओं की पूर्ति में माँग की श्रपेज्ञा बहुत कमी पड़ गई श्रीर इससे देश में मुद्रास्कीत की ही बल मिला है। अधिक कर लगाने से, चाहे वह प्रत्यन कर हो या श्रमत्यज्ञ, उत्पादन व्यय बढता है श्रीर इससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। साख पर नियंत्रण रखने की नीति का और भी बुरा प्रमांव पड़ा है। साख पर नियंत्रण लगा देने से बहुत सी मिलों को कञ्चे माल का स्टाक जमा करने के लिए पर्यात वित्त महायता नहीं मिल पाती और साथ ही वह तैयार माल का स्टाक भी जमा नहीं कर पाती हैं। कुछ मिलें बन्द हो गई और अन्य का उत्पादन घट गया है। महास्फीति रोकने के लिए श्राधक कर श्रीर साख-संक्रचन को उपयुक्त उपाय समका जाता है परन्तु भारत की विशेष स्थिति होने क कारण इन उपायों से मुद्रास्फीति की अधिक बल मिला है। इन उपायों की लागू करते समय सरकार को उद्योगों पर श्रिधिक मार नहीं हालना चाहिये था। परन्त सरकार ने इस बात की श्रोर ध्यान नहीं दिया जिससे सुद्रास्कीति की स्थिति सुभरने की अपेका श्रीर निगड़ गई। इसके साथ ही भारत सरकार पंचवर्षीय योजना के कारण घाटे के वजट की नीति आपना रही है। घाटे के बजट की नींत से जनता की कय शक्ति में वृद्धि होती है और इससे मुद्रास्कीति बढ़ती है।

यद्यपि सरकारी स्फीति निरोधक नीति में सफलता की श्रोर प्रगति रुक रुक कर हुई पर उसे सफलता श्रवश्य प्राप्त हुई है। "जुलाई १९५२ से मारत की श्रार्थिक स्थिति में एक विशेष परिवर्तन हो गया है। मुद्रास्फीति बहुत कुछ समाप्त हो गई यी श्रीर पहिली बार युद्ध की समाप्ति के बाद विकास योजनाश्रों को प्रोत्धान्त हन देने की श्रीर ध्यान देना सम्मव हो गया। १६५१-५२ के बढ़े हुये कारोबार वाले काल में युद्रा प्रसार पर नियंत्रण श्रीर मन्दे कारोबार वाले बाद के काल में वापस पाये हुये धन ने जनता के हाथ में क्य शक्ति की मात्रा घटा दी थी किर मी वस्तुश्रों की पूर्ति कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि तथा श्रायात में वृद्धि के कारण बढ़ गई थी। इस प्रकार कुत्त मांग श्रीर पूर्ति में श्रन्तर कम रह गया था। इसिलिये खाद्य वस्तुश्रों तथा श्रन्थ वस्तुश्रों पर नियंत्रण शिथिल करने का तथा सरकारी चेत्र में विकास योजनाश्रों पर व्यय बढ़ाने का श्रवसर प्राप्त हो गया थां।

मई १६४४ से मृल्यों में वृद्धि-मई १६५५ मे योक मूल्यों का देशनांक घटकर ३४२ हो गया था परन्तु तब से निरन्तर उसमें वृद्धि होती। गई श्रीर १६५६ के ब्रारम्भ में विशेष रूप से प्रगट हुई। खाद्यानों के सम्बन्ध में मूल्य में वृद्धि विशेष रूप से दिखाई पड़ती है जो कि =४' अर्थ श्रेकों से बढ़ गई (मई १६५५ में २७६' १ यी श्रीर अप्रैल १९५६ में बढ़कर ३६० ९ हो गई), दूसरा नम्बर श्रीचांशिक कच्चे माल का या जो कि ७६ ४ श्रेकों से बढ़ गया था (३६३ ४ से ४७२ ८ हो गया था) श्रीर श्रर्घनिर्मित वस्तुश्रों के मूल्यों में वृद्धि ४७ ४ श्रंकों की हुई (३२६ ६ से ३७७ ही गया था)। निर्मित माल के मूल्य में बहुत साधारण वृद्धि हुई (३७४६ से वढ़कर ३७५:६ हो गया) और विविध वत्तुओं के सम्बन्ध में तो वास्तव में मूल्य ५४४ ६ से घट कर ४६६ ७ हो गवा। मूल ों में इस वृद्धि के कारण निम्न थे-(१) सरकार की ज्वार, बाजरा, मक्का श्रादि कृषि उत्पत्तियों के मूल्यों की गिरने से बचाने की नीति जिससे मूल्य में कमी ही नहीं क्की वरन् उसमें वृद्धि हुई; (२) सरकारी श्रन्य उपाय जैसे रुई, तिलहन, वनस्पति तेल श्रीर कहवा श्रादि के निर्यात मात्रा में वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के स्ती कपड़ों, तिलहन, उदार श्रीर वनस्रित तेल आदि के निर्यात के लिये निशुल्क लाइसेन्स प्रदान करने की नीति का लागू करना, तथा चावल, दाल, मनका, श्रीर खली के निर्यात की श्रनुमित मदान करना तथा कपास, जूट, काली मिर्च, वनस्पति तेल श्रीर खली पर लगाये हुये नियात कर का हटा लेना आदि, जिससे निर्यात की प्रोत्साहन मिला। इनसे भारतीय वाजार की पूर्ति कम हो गई श्रीर मूल्य वढ़ गये, (३) मूल्यों में यह वृदि त्रीर मी श्रिधिक प्रथम श्रीर द्वितीय पंचवर्षीय योजनात्रों पर व्यय बढ़ाने से हुई। केरदीय ख्रीर राष्ट्रीय सरकार की कुल ख्राय तथा पूँजी व्यय निरन्तर बढ़ रहें हैं। इससे जनता के इाथ में क्रय शक्ति भी बढ़ गई। जनता के लिये द्रव्य की मात्रा में भी वृद्धि की गई थी। इन सब कारणों ने मुद्रास्कीति को बहुत श्राधिक प्रोत्साहन

दिया; श्रीर (४) "व्यापारिक च्रेत्र में यह शंका वनीं ही रही कि श्रेगले महीनों में श्रत्र का तथा श्रीद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन उतनी ही प्रगति के साथ जितनी प्रगति से द्वितीय योजना में व्यय करने का विचार है बढाया भी जा सकता है श्रथवा नहीं। इन कारगों को विचाराधीन रखते हुये व्यापारी श्रधिक मात्रा में वस्तुश्रों की बिकी करने में बड़े धोच विचार से काम ले रहे थे। इतना ही नहीं उनके मन में इंस बात की इच्छा प्रवल थी कि वे यथा सम्मव वस्तुत्रों का संचय कर लें"। १६५६ के आरम्म में ही वित्त मन्त्री ने लोक सभा में कहा था कि सरकार मुद्रास्फीति को ठीक करने की शक्ति रखती है श्रीर उसे दूसरे देशों के उपायों का जो वे मुद्रारफीति से उत्पन्न श्रपने देश की समस्याश्रों का निराकरण करने में कर रहे हैं प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार "श्रव पूर्णतया उन वित्तीय, द्राव्ययिक तथा मौतिक उपायों से परिचित हो गई है जो प्रारम्भिक सद्रास्फोति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये काम में लाये गये हैं। हमें कुछ निजी श्रातुमव भी इस सम्बन्ध में प्राप्त हो गया है। १६५२ में यह दोष लगाया गया था कि इमने मुद्रास्कीति निरोधक नीति का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया है। इसिल्ये हमें विश्वास है कि जब इसका अवसर आयेगा तब हम इसके पहिले कि देश की आर्थिक स्थित को जाति पहुँचे मुदारफीति की प्रवृत्ति को रोकने में समर्थ होंगे"। यदि प्रचलित स्थिति का विश्लेषण करें तो हम यह कह एकते हैं कि इसका प्रा करना सम्भव नहीं है।

मुद्रास्फीति रोकने के लिये पारचात्य देशों ने द्राब्यिक श्रीर विचीय उपायों पर नियंत्रण की नीति लागू करने के उपायों पर श्रीषक मरोसा किया है। उनकी द्राब्यिक नीति के श्रन्तर्गत निम्न वार्ते श्राती हैं जैसे (१) बैंक रेट में वृद्धि करना, (२) विनिमय कार्य निशुलक करना, (३) सेन्द्रल बैंकिंग संस्थाश्रों के पास बैंकों के जमाधन का श्रनुपात बढ़ाना, (४) विदेशी श्रीधपत्रों के कारोबार पर नियंत्रण दीला करना श्रीर (५) कय-विकय (hire-purchase) के श्राध र पर श्रूण प्राप्त करना कठिन कर देना हत्यादि। विचीय उपायों के श्रन्तर्गत निम्न बातें श्राती हैं जैसे (1) विनियोग पर कर की दर में वृद्धि, (11) क्रय पर तथा श्रन्य बातों पर कर की दर बढ़ाना, श्रीर (111) विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिये जो करों से की गई थी उसको वापस कर लेना हत्यादि।

उपर्युक्त उपायों से उन देशों को सफलता मिली पर वे मारत के लिये उपयुक्त नहीं हैं क्यों कि—(१) उन देशों में कोई मी वेकार नहीं है पर भारत में बहुत अधिक संख्या में लोग बेकार हैं। विनियोग रोकने का कोई भी उपाय वेकारी बहुत अधिक मान्ना में बढ़ा देगा (२) उन देशों में सब प्रकार की वस्तुओं को कमी है श्रीर उनकी समस्या उपभोग घटाने की है पर भारत में उपभोग का स्तर पहिले से ही नीचा है श्रीर उसे श्रधिक कम करने का श्रवसर नहीं है। भारत की सबसे श्रिधक गंभीर समस्या कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन को वेचने का वाजार चाहिये, यदि उपभोग में किंचित मात्र भी कमी की गई तो उत्पादन वृद्धि कभी भी नहीं सम्मव है जो कि योजना का ख्रादर्श है; ख्रीर (३ भारत में साख घटाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि साख का भाग द्रन्य की पूर्ति में बहुत छोटा है। इसलिये भारत सरकार के समस द्रान्यिक, वित्तीय श्रीर भौतिक नियंत्रण में से श्रकेला उपाय जिसका वे प्रयोग कर सकते हैं वह उत्पादन, वितरण तथा वस्तुश्री के मूल्यों का मीतिक नियंत्रण ही है। इस देश ख़ीर विदेशों का ख़नुभव यह बताता है कि मौतिक नियंत्रण से केवल उपभोक्ताश्रों के वर्ग विशेष को विशेषकर राजकीय विमार्गो की नियंत्रित मूल्य पर वस्तुर्ये प्राप्त होती हैं। श्रम्य उपभोक्ताओं के लिये वस्तुय्रों की दुर्लभता बड़ी भयानक श्रीर कप्टकर हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप चोर वाजारी थ्रौर मुनाफा खोरी को प्रोत्माहन मिलता है श्रौर मूल्य श्रीर श्रिषिक ऊँचा हो जाता है। विछत्ते श्रानुमय से हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम है कि मीनिक नियंत्रण पर्याप्त न होगा; भारत ऐसे वित्तृत देश के लिये यह उपाय प्रभावशाली नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्रशासन श्रधिकारी प्रमाय-शाली नहीं हैं श्रीर इसके श्रतिरक्त उन्हें देसे श्राधिक कार्यों को करने के लिये कहा जा रहा है जिसे उन्होंने पहिले जबिक नियंत्रण का कोई भी प्रश्न नहीं या कभी नहीं किया या। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का नियंत्रण देश की नैतिकता पर श्राधात पहुँचावेगा जो कि युद्ध के श्रीर युद्ध के पश्चात मुद्रास्कीति के प्रमावों से पहिले से ही जतिवज्ञत हो जुका है।

सरकार की मुद्रास्कीति निरोधक नीति को १९५२ में कुछ सफलता प्राप्त हुई थी पर १९५६ में स्थिति नितांत भिन्न हो गई थी इसलिये वे उपाय सफल नहीं हो सकते ये क्योंकि: (१) द्वितीय योजना में घाटे का ग्रथं प्रवन्वन पहिलो योजना से कहीं श्रिषक है श्रीर मुद्रा स्कीति की प्रवृत्ति को किसी भी ढंग का वित्तीय, द्राव्ययिक श्रयवा मौतिक नियंत्रण का उपाय रोक नहीं सकता जमकि व्वालामुखी के समान शक्तियाँ मूल्य को ऊपर की श्रोर दकेल रही हैं, (२) १९५२ में तथा बाद के वर्षों में विश्व व्यापी मन्दी फैल गई थी जिसके कारण भारत में भी मूल्यों का स्तर नीचे गिर गया था; श्रीर (३) १९५२, १९५३ श्रीर १९५४ में मानसून बहुत लाभकर थी जिससे कृषि उत्पादन में श्रारचर्यजनक वृद्धि हुई जिससे सरकार की मुद्रा स्कीति निरोधक नीति को कुछ सफलता मिली थी। १९५६ में ये सहायक उपाय तो प्राप्त नहीं थे जो सरकार की मुद्रास्कीति निरोधक नीति को

सफलता प्रदान करते इसलिये वे उत्तने प्रमावशाली सिद्ध नहीं हो .सके जितने कि १६५२ में हुये थे। इसके अतिरिक्त हमारे सम्मुख आज नई समस्याएँ उपस्थितः हैं जो कि १६५२ में नहीं थीं। इमारी आर्थिक नीति में ऐसी विरोधी बातें दिखाई पड़ती हैं जैसे "कुटीर उद्योगों के साथ-साथ बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों की उप्तित का विचार तथा तीन गति से श्रीद्योगीकरण को इच्छा के साथ-साथ धनवानों को मिटा देने की भावना श्रथवा घनी होने की भावना का विरोध करना"। इन सब बातों के अतिरिक्त हमारी नीति में ऐसी आदर्शवादी बातें भी हैं जैसे मद्यनिषेध जिनके कारण अनुत्पादक कार्य में संलग्न होने से तथा नियम के प्रति सम्मान की मावना घटने से सरकार को एक बड़े आय के स्रोत की हानि होती है।

सितम्बर १६५७ से मूल्य स्तर कुछ कम हुये हैं जब कि १६५२-५३ को आवार मानकर थोक मूल्यों का सामान्य देशनांक १०८७ हो गया। यह देशनांक यास्त १६५७ में ११००६ और जुलाई १६५७ में ११२९ था। देशनांक का यह गिराव १६५८ में ११००६ और जुलाई १६५७ में ११२९ था। देशनांक का यह गिराव १६५८ में भी रहा किन्द्र हसका कारण यह मुद्रा स्कीति विरोधी सरकारी उपाय तथा रिजर्व बैंक की विशिष्ट साख नियंत्रण की नीति न होकर खाद्य स्थिति में हुआ व्यक्तिगत सुधार था। १६५५-५६ की तुलना में १६५६-५७ में खाद्याक की उत्यक्ति तथा आयात दोनों में ही वृद्धि हुई। इस सम्बन्ध में निग्न आँकड़े स्थित स्पष्ट करते हैं।

थोक मूल्यों के देशनांक (आधार १६४२-४३ = १००)

·_	4/		-				
	सम बस्तुऍ	खाद्य मसाएँ	मद्य तथा तम्बाकू	इंधन शक्ति तथा सरल स्निग्य-पदार्थ	ऋोद्योगिक कचा माल	मध्य- उत्पत्ति (Intermediate Products)	निर्मित बस्तुएँ (तैयार बस्तुएँ)
जुलाई १६५७	११२ .8	११२.६	£3.0	३.४.६	१२२.३	305.0	₹0€.0
दिसम्बर १९५७	१०६'३	१०२.६	€७•३	₹ ₹४° ⊆	११ ४%	१०५'६	e'eo\$
मार्च १६५८	१०६ "१	१०३४	8.83	११४ ५	११२६	१०७'१	१०७४
जुलाई १६५८	\$ \$8.0	११५४	६२.६	११६'४	११७•६	१११७	१०७.त
_	_						

जुलाई १९५७ से मार्च १९५८ तक मदा और तम्बाकू के मृल्यों में वृद्धि हुई; ईघन, शक्ति, सरल स्निग्ध पदार्थ, तथा मध्य-उत्पत्ति और निर्मित वस्तुओं

के मूल्य घट गये। इससे स्वष्ट है कि मूल्यों के सामान्य देशनांक को यह कभी अधिकांशन: खादा पदार्थों तथा श्रीद्योगिक कब्चे माल के सम्बन्ध में ही हुई जिनके उत्पादन श्रीर श्रमुपात में वृद्धि हुई थी। इस नात के संकेत विद्यमान हैं कि मूल्यों कि यह कभी श्रस्थायी सिद्ध होगी तथा मूल्य फिर बढ़ने लगेंगे।

उपर्युक्त बात। को विचाराधीन रखते हुये हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घाटे का श्रयं प्रवन्यन १२०० करोड़ रुपयों से घटाकर इतना कर देना चाहिये कि जिसका श्रासानी से प्रवन्यन किया जा नके (उदाहरणार्थ श्रिषक से श्रिषक ५०० करोड़ रुपया) श्रीर इस बात का मरपूर प्रयत्न करना चाहिये कि (१) कृषि तथा श्रीशोगिक उत्पादन जितना श्रिषक से श्रिषक बढ़ाया जा सके उतना कम से कम समय में बढ़ाया जाय, (२) व्यर्थ जाने वाला सरकारी व्यय बन्द कर दिया जाय श्रीर (३) विकास सम्बन्धी व्यय की मात्रा मा जो विभिन्न योजना श्रों के श्रन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की जा रही है कम कर के युक्तिसंगत सोमा तक निश्चित कर दो जाय। धीमी गति से विकास, श्रीषकार के बाहर मुद्रास्कीत के कारण भयानक हानि उठाने की श्रिपेता श्रीषक चाव्छनीय है।

श्रध्याय ४४

वित्त आयोग रिपोट्

संविधान के अनुब्केंद्र २८० (१) के अन्तर्गत २२ नवम्बर, १६५१ को राष्ट्रपति ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यस्ता में एक वित्त आयोग नियुक्त किया।
श्री बी० पी० मेनन, १ न्यायाधीश आर० के० राव और डाक्टर बी० के० मदन
आयोग के सदस्य तथा श्री एम० बी० रँगाचारी सदस्य एवम् मन्त्री नियुक्त हुए!
आयोग नियुक्त करने का उद्देश्य उन सिक्षान्तों को निर्धारित करना या जिनके
आधार पर कुछ करों से प्राप्त होने वाली आय को केन्द्रीय एवम् राज्य सरकारों
में बाँटा जा सके और भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिये जानेवाले
सहायता अनुदानों को निश्चित किया जा सके। आयोग को यह कार्य मी सौंपा
गया कि वह इस सम्बन्ध में अपना सुक्ताब दे कि संविधान के अनुब्छेद २७८
(१) और २०६ के अन्तर्गत भारत सरकार ने कुछ राज्य सरकारों से जो सम्मौते
किये हैं उनको जारी रखा जाय या उनमें कुछ संशोधन किया जाय। आयोग
ने ३१ दिसम्बर, १६५२ को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी जिसे भारत सरकार ने

पहला वित्त श्रायोग

सिद्धान्त—पहले वित्त स्रायोग ने यह मानकर अपना कार्य आरम्भ किया कि कुछ करों से पाप्त होने वाली आय को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में बॉटना पढ़ेगा। आयोग ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि आय के कुछ साधन केन्द्रीय सरकार से लेकर राज्य सरकारों को सींप देने चाहिएँ। यद्यपि अपनी रिपोर्ट में आयोग ने यह दोनों सुकाव दिये कि कुछ करों की आय राज्य सरकारों को दी जाय और राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान भी दिए जायँ, परन्तु आयोग ने अपने निष्कर्षों को मुख्यत: पहले सुकाव पर आधारित किया कि कुछ करों की आय केन्द्र से लेकर राज्यों को दे दी जाय। अतीत में आय-कर को विशेष महत्व दिया गया था परन्तु आयोग ने केन्द्राय तथा राज्य सरकारों के वीच आय के साधनों का वितरण करने में आय-कर को सन्द्रालन स्थापित करने

१ —श्री वी० पी० मेनन ने १८ फरवरी, १६५२ को श्रायोग से इस्तीका दे दिया श्रीर श्रापके रिक्त स्थान पर श्री बी० एक० मेहता नियुक्त किये गये।

वाला सामना अनुचित समका। राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्य में एक सीमा तक लोच की संभावना रखने छीर एक सन्तुलित योजना प्रस्तुत करने के लिए श्रायोग ने प्राप्त श्राय के वितरण के चेत्र को व्यापक वनाने का प्रयक्त किया। श्रायोग ने सिफारिश की कि श्राय-कर से प्राप्त होने वाली वास्तविक श्राय में राज्यों का भाग बढ़ा देना चाहिये परन्तु इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार -द्वारा वस्त् किये जाने वाले कुछ उत्पादन-करों की श्राय में से भी राज्यों को हिस्सा मिलना चाहिए।

राज्य सरकारों के लिए सहायता योजना प्रस्तुत करते समय वित्त आयोग ने तीन वितों पर स्थान रखा: (१) श्राय के साधन राज्य सरकारों को सींप देने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के पास इतनी श्राय बचनी चाहिये जिससे वह देश की प्रतिरचा और श्राधिक स्थिति को हद बनाने इत्यादि के उत्तरदायित्व का सफलता-पूर्वक निर्वाह कर सके; (२) राजस्य के वितरण में श्रीर सहायता-श्रनुदान निर्धारित करने में सभी राज्यों के लिए एक ही सिद्धान्त लागू हो; श्रीर (३) वितरण योजना इस प्रकार की हो जिससे विभिन्न राज्यों की श्रसमानता को कम किया जा सके।

श्राय-कर—संविधान के श्रनुच्छेद २७० के श्रन्तर्गत श्रायोग से निम्न-लिखित सिफारिशें करने को कहा गया था: (१) श्राय-कर से प्राप्त होने वाली कुल राशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिये; (२) राज्य सरकारों को दी जाने वाली रकम का बँटवारा किस प्रकार किया जाय; श्रीर (३) कर से प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि का कितना प्रतिशत खरह 'ग' राज्यों को दिया जाय।

इस विषय पैर काफी विवाद हुआ कि राज्यों के श्रंश का विभिन्न राज्यों में किस आधार पर वितरण किया जाय। इस सम्बन्ध में अनेक सुक्ताय दिये गये। कुछ राज्यों का सुक्ताव था कि वितरण कर-वस्ती के खोत, आय के उद्गम, करदाताओं के निवास-स्थान, जनसंख्या या श्रीयोगिक अम के आधार पर किया जाय। साथ ही यह भी सुक्ताव रखा गया कि वितरण प्रति ज्यक्ति की आय या राज्य की आधिक स्थिति के आधार पर किया जाय। पश्चिम वङ्गाल की सरकार का मत था कि संविधान की २७० वी धारा के अभिपाय के अनुसार भारत सरकार को कुल आय में अपना माग ले लेने के पश्चात शेष उन्हीं राज्यों को वापस कर देना चिहिए जिनमें उसकी वस्ती की गई है। वित्त आयोग ने इस दावे को निम्निलिखत कारणों से मानने से इन्कार कर दिया।—

(१) ''संविधान में इस वात को मान्यता नहीं दी गई कि वसूल किये गये आय कर में किसी भी राज्य का अधिकार है और न इस वात को ही माना गया है कि राज्य को अपने त्रेत्र में वस्ल किये गये आय-कर पर अधिकार है। वितरण कोष के एक निश्चित अंश पर राज्य को तब ही अधिकार मिल सकता है जब राष्ट्रपति यह निर्घारित कर दें कि वितरण किस आधार पर किया जायगा? ।

- (२) ''हम इसे टीक नहीं समक्ति कि आस्ट्रेलिया और कनाडा में प्रचलित 'मुआविजे' अथवा 'वापसी' के सिद्धान्तों के आधार पर उन सभी संघीय प्रणालियों में लागू करने योग्य कोई 'वैद्यानिक' सिद्धान्त निकाला जाय जहाँ केन्द्र द्वारा एक सा आय-कर लगाया जाता है लेकिन जिसका एक अंश इकाइयों में बाँटा जाता है। मारत में मुआवजे अथवा वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यहाँ के भूतपूर्व प्रान्तों को, जो अब खरड 'क' के राज्य कहलाते हैं, आय पर कर लगाने का कभी भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि खरड 'ख' के राज्यों में भी विलय होने से मुआवजे के सिद्धान्त को मान्यता नहीं मिली चाहे संघीय सम्पत्ति का प्रश्न हो चाहे केन्द्र को मिलने वाले संघीय राजस्व का"।
- (३) "बहुत से राज्यों को कर लगाने का श्रिषकार प्राप्त होने के कारण बम्बई श्रीर कलकत्ते में जो श्रायकर वस्त किया जाता है वह इन दो राज्यों की कर-श्राय नहीं कहलाई जा सकती"।

संविधान की २७० वीं घारा की विच आयोग ने.ज्याख्या की है। आयोग का मत है कि इस धारा के अनुसार जिस राज्य में आय-कर नहीं लगाया जा सकता उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। वर्तमान में जम्मू और काश्मीर की ऐसी ही स्थिति है। वहाँ आयकर लागू नहीं है और इसीलिए जम्मू और काश्मीर राज्य का आय-कर वितरण-कोष पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।

श्रायोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि वितरण कोष का विभिन्न राज्यों में वितरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि संप्रहीत कोष में राज्य ने कुल कितनी रकम दी है श्रीर उनको कितनी श्रावश्यकता है। राज्यों का हिस्सा निश्चित करने के लिए केवल राज्य द्वारा वस्ल किये गये कर की सान्ना को श्राधार मानना उचित नहीं होगा। श्राय-कर से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि का ७५ प्रतिशत वम्बई श्रीर पश्चिमी बङ्गाल के दो राज्यों में वस्ल किया जाता है श्रीर इस धन राशि का श्राधकतर श्रंश वम्बई श्रीर कलकत्ता के दो शहरों से वस्ल होता है परन्तु इसका यह श्रार्थ नहीं है कि श्राय के जिन सिक्य साधनों पर कर लगाय गया है वह इन्हों दो राज्यों या इन्हों दो शहरों में केन्द्रित हैं।

प्रत्येक राज्य की आवश्यकता की जानकारी करने के लिए विच आयोग् ने न तो औद्योगिक अम को आघार माना है और न प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय को। इसका कारण यह है कि संग्रहीत कोष में राज्य जितना योगदान देता है या राज्य को जितनी श्रावश्यकता है उसका श्रीद्योगिक श्रम के श्राधार पर ठीक ठीक पता नहीं चलाया जा सकता है। इससे केवल श्राधिक संकृत मिल सकता है। जहाँ तक प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय श्राय का प्रश्न है इस सम्बन्ध में उपयुक्त श्राकृड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए श्रायोग ने यह माना है कि वर्तमान हिपति में राज्य की श्रावश्यकता का पता लगाने के लिए उसकी जनसंख्या ही उपयुक्त साधन है।

भविष्य में वितरण-कीप में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या है के बजाय १६ होने के कारण तथा संक्रमण्काल में खंड 'ख' के कुछ राज्यों को स्राय कर की पूर्ण दरों को लागू करने के सम्बन्ध में दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुये श्रायोग की इस सिफारिश को भारत सरकार ने मान लिया कि वितरण कोप में राज्यों का भाग ५०% से बढ़कर ५५% कर दिया जाय । श्रायोग की यह सिफारिश भी मान ली गयी कि राज्य को दिये जाने वाले भाग का २० प्रतिशत उसी श्रनुपात में बाँटा जाय जिस श्रनुपात में राज्यों से श्रायकर संग्रहीत किया गया है । शेप ८० प्रतिशत १६५१ की जनगणना के श्रनुसार राज्यों की जनसंख्या के श्राधार पर बाँटा जाय । इसके श्रनुसार प्रत्येक राज्य के हिस्से का वितरण निग्न तालिका में दिया गया है । तालिका में तुलनात्मक श्रम्ययन के लिए श्रीटो नेमियर के स्त्र के श्रनुसार खरड 'क' के राज्यों को प्राप्त होने वाले प्रतिशत-ग्रंश का भी ब्यौरा दिया गया है ।

श्रीटो नेमियर के सूत्र श्रीर वित्त श्रायोग की योजना के श्रनुसार निर्धारित प्रतिशत-श्रंश का तुलनात्मक श्रध्ययन करने से पता चलेगा कि वित्त श्रायोग की सिफारिश के श्रनुसार केवल वम्बई श्रीर विहार राज्यों के प्रतिशत हिस्से में कमी श्राई। वैसे पश्चिम बङ्गाल श्रीर पखाव के प्रतिशत श्रंश में भी काफी कमी हुई परन्त उसका कारण विभाजन के पश्चात उनकी जनसंख्या में हुई कमी है। इसके बावजूद कि श्रव ६ राज्यों के बजाय १६ राज्य हिस्सेदार हैं, बम्बई श्रीर विहार को छोड़कर खएड 'क' के शेष राज्यों के प्रतिशत श्रंश में वृद्धि हुई।

खरह 'ग' के राज्यों को श्राय-कर की कुल श्रामदनी का एक प्रतिशत मिलता या परन्तु वित्त श्रायोग की विकारिश के श्रनुवार इन राज्यों का हिस्सा एक प्रतिशत से बढ़ाकर रहे प्रतिशत कर दिया गया।

चूँ कि श्रव सभी राज्यों को एक ही श्राधार पर श्राना-श्रपना हिस्सा मिलता है इसलिए 'विलीन चेत्रों' के सम्बन्ध में विहार, वम्बई, मध्य प्रदेश श्रीर पश्चिम बङ्गाल को जो श्रितिरिक्त सहायता श्रनुदान मिल रहे थे उन्हें श्रायोग की सिकारिश के श्रनुसार १ श्रप्रैल, १९५२ से देना बन्द कर दिया गया।

राज्य	श्रीटो नेमियर सूत्र के	वित्त आयोग की योजना
	श्रनुसार प्रतिशत श्रंश	के अनुसार प्रतिशत श्रंश
खन्ड 'क' राज्य		`
मद्रास*	१५	१५.२५
बग्वई ्	२०	१७.५०
पश्चिम बङ्गाल	२० (ग्र)	१ १.२५
उत्तर प्रदेश	શ પૂ	શ્પ્ર. હંપ્
पंजाब	¤ (শ্ব)	≨ *रत्
विहार	20	<i>દ્ર.</i> હયૂ
सध्य प्रदेश	ų	ય .રપ્
श्रासाम	२	२,२५
उद्रीस	२	₹,५०
खन्ड 'ख' राज्य		
हैदराबाद	-	8,40
राजस्थान	-	₹,५०
त्रिवांकु (-कोचीन	_	२,५०
मैसूर	-	२,२५
मध्य भारत	•••	<i>ર.હપ્ર</i>
सीराष्ट्र	mate	2,00
पटियाला संघ	-	o.6X

*मदास राज्य की कुल आय का ३६% आनम के लिये निश्चित कर दिया गया है।

(अ) यह प्रतिशत प्रांत के विभाजन के पूर्व के हैं।

केन्द्रीय उत्पादन कर — संविधान से संसद को यह अधिकार मिला है कि वह अपने द्वारा निर्धारित योगदान के नियमों के अनुसार मारत को संचित-निधि में से केन्द्रीय उत्पादन कर से प्राप्त होने वाली सारी आय या उसका कुछ अंश राज्यों में बाँट सकती है। केन्द्रीय उत्पादन कर पहले आय के महत्वपूर्य खोत नहीं माने जाते ये और १६३७-३८ में इनसे कुल ७.६६ करोड़ रुपये की आय हुई परन्तु इनका महत्व यास्तव में द्वितीय महायुद्ध में बढ़ा। १६५१-५२ में इनसे केन्द्र को ८६ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। उत्पादन कर की बढ़ती आय देखकर राज्य सरकारों ने उसमें से अपने हिस्से की माँग की।

अायोग इस परिजाम पर पहुँचा कि ''कम से कम आरम्म में श्रत्यधिक संख्या के उत्पादन करों का वितरण ठीक नहीं, विशेषकर इसलिए कि उनमें से कुछ से श्रुपेज्ञाकृत कम श्राय होती है श्रीर कुछ चुनिन्दा उत्पादन करों का वितरण ठीक है। चिनन्दा उत्पादन कर ऐसे होने चाहिएँ जो ऐसी वस्तुश्रों पर लगते हैं जो साधारणतया विस्तृत रूप से उपभोग में श्राती हैं श्रीर जिनसे त्रितरण के लिए एक श्रद्धी खासी श्रामदनी होती है। श्राय में पर्याप्त सुदृहता तथा चंगी करों के उतार-चढाव से श्रपेज्ञाकृत बचाव होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इम इस परिखाम पर पहुँचे हैं कि तम्बाकू (सिगरेट, सिगार श्रादि समेत), रियासलाई तथा वनस्पति पर लगने वाले कर वितरण के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। हमारी िकतारिश है कि करों की आय का ४० प्रतिशत राज्यों को दिया जाय। इमने उस रकम के आधार पर राज्यों का हिस्सा निश्चित किया है जो हमारी पूरी योजना के श्रतसार उत्पादन करों के वितरण के कारण राज्यों को ही जानी चाहिए"। वित्त श्रायोग ने इन चुनिन्दा वस्तुःश्रों जैसे तम्बाक् (जिसमें सिगरेट, सिगार इत्यादि समिनित हैं), दियासलाई श्रीर वनस्पति पदार्थों पर ही लगाये गये उत्पादन करों से प्राप्त होने वाली आय के ४० प्रतिशत के वितर्ण की सिफारिश विभिन्न राज्यों की १९५१ की जनगणना के आधार पर की जो निम्न तालिका से स्पष्ट है।

सरकार ने इन सुकावों को स्वीकार कर लिया और इन पर आधारित मार्च १९५३ में केन्द्रीय उत्पादन कर (वितरण कानून) पारित हुआ।

राज्य	कुल श्राय में से प्रतिशत श्रंश	राज्य	कुल श्राय में से प्रतिशत श्रंश
श्राचाम	२.६१	उद्गीसा	४.२२
विहार	११.६०	परियाला संघ	₹.00
वम्बई	१०. ३७	पंजाब	३.६६
है दराबा द	ય.રદ	राजस्थान	४.४१
मध्य भारत	२.२६	चौ राष्ट्र	१. १ ६
मध्य प्रदेश	६.१ ३	त्रिवांकुर-कोचीन	२.६=
मद्रास≇	१६.४४	उत्तर प्रदेश	१३.२८
मैस्र	२.६२	पश्चिम बंगाल	७.१६

^{*}संयुक्त मद्रास राज्य के हिस्से का ३६% श्रान्त्र के लिये निश्चित कर दिया गया।

जूट निर्यात कर—संविधान के अनुसार जूट के निर्यात कर से प्राप्त आय में राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता परन्तु अनुंच्छेद २७३ के अनुसार पश्चिम बंगाल, आसाम, विहार और उदीसा चार राज्यों को संक्रमण काल के लिए कुछ सुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। देशमुख निर्णय (Deshmukh Award) के आधार पर राष्ट्रपति ने इस मुआवजे की रकम निश्चित की थी परन्तु राज्य इतने से सन्तुष्ट नहीं थे। राज्यों की मांग थी कि मुआवजा बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में वित्त आयोग इस परिणाम पर पहुँचा है कि संविधान के अनुच्छेद २७३ का यह अभिपाय नहीं है कि जूट के निर्यात कर से प्राप्त होने वाली आय में से राज्यों को उनके हिस्से के बदले जो सहायता अनुदान दिया जाता है उसका निर्यात कर से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली आय से सम्बन्ध होना चाहिए। आयोग ने इसके लिए निम्नलिखित कारण दिये:—

पहले, यदि संविधान का यह अभिप्राय होता कि अनुच्छेद २७३ में उल्लिखत सीमित अवधि में उस अनुच्छेद में उल्लिखत राज्यों को जुड़ और जुड़ से निर्मित वस्तुओं के निर्यात कर के हिस्से की राशि के बराबर सहायता पाने का अधिकार है तो इसके लिए संविधान में स्पष्ट व्यवस्था की गयी होती।

दूसरे, यह अनुक्छेद राष्ट्रपति को धन-राशि निश्चित करने का श्राधिकार देता है राजस्व का हिस्सा नहीं।

तीसरे, चूँकि जूट कुछ श्रन्य राज्यों में भी पैदा किया जाता है इसिलए संविधान का यह कभी हरादा नहीं हो सकता कि सहायता-श्रनुदान का दिया जाना इन्हीं चार राज्यों तक सीमित रखा जाय । उनको सहायता-श्रनुदान देने का सिर्फ यही कारण था कि श्राय की उस रकम का मुश्राविजा दे दिया जाय जो उन्हें पहले मिलती थी।

वित्त श्रायोग ने पिश्चम बङ्गाल के इस दावे को अस्वीकार किया कि सहायता अनुदान का सम्बन्ध १६५१-५२ में प्राप्त राजस्व से होना चाहिए । वित्त श्रायोग का मत था कि १६४६-५० में (जो जूट के निर्यात कर में राज्यों को मिलने वाले हिस्से का श्रांतम वर्ष है) यदि इन राज्यों के हिस्सों की राशि १६४७ में भारत सरकार द्वारा संशोधन किये जाने से पहले निर्धारित आधार पर निश्चित कर ली जाय और उसी के अनुसार सहायता-अनुदान मी निश्चित कर लिये जाएँ तो श्राधक उपयुक्त होगा । इस श्राधार पर वित्त आयोग ने सिफारिश की कि जूट के निर्यात-कर के हिस्से के बदले १६५२-५३ से राज्यों को निम्न तालिका के अनुसार सहायता अनुदान दिए जायँ जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया :—

सहायता अनुदान संविधान में केन्द्रीय राजस्व की श्राय में से राज्यों

को श्रनेक सहायता श्रनुदान देने की व्यवस्था की गई है। संविधान में 'राजस्व से सहायता श्रनुदान' की व्याख्या नहीं की गई है। संविधान के श्रनुच्छेद २८० में कहा गया है कि विच श्रायोग ऐसे नियमों की सिमारिश करेगा जिनके श्रनुसार भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता श्रनुदान दिए जायँगे।

राच्य	देशमुख-निर्माण के श्रनुसार दी गई धनराशि (क्पये लाखों में)	वित्त श्रायोग द्वारा निर्घारित घनराशि (रुपये लाखों में)	
पश्चिम बङ्गाल	₹,०५	₹, ५०	
त्रासाम	५०	ંહપ્	
विद्यार	₹પ	હયૂ	
उड़ीसा	પૂ	१५	

विदेशों में वेन्द्रीय सरकारें राज्यों को विना किसी शर्त के या शर्त के साथ विशेष श्रनुदान दिया करती हैं। इस सम्बन्ध में कुछ देशों ने जो श्रनुभव प्राप्त किये हैं उनका वित्त श्रायोग की सिफारिशों पर प्रभाव पड़ा है।

''कनाडा श्रौर श्रास्ट्रेलिया में विना शर्त के श्रनुदानों का परीच्या किया गया है श्रीर ये वहाँ प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। इनमें से एक जो हमारे लिए विशेष रुचि का कारण है शास्ट्रेलिया में प्रचलित 'विशेष' श्रनुदान है। इस देश में, जहाँ इकदार राज्य कहलाने वाले तीन राज्यों की विशेष अनुदान दिये जाते हैं, श्राम सहायता श्रनुदान के सिदान्तों को जिस हद तक विस्तृत श्रीर संवारा गया है उतना शायद और किसी दूसरे देश में नहीं किया गया। ऐसे श्रनुदानों की पूरी प्रक्रिया के पीछे बजट के स्टेंडर्ड का सिद्धान्त है। यह बुनियादी तीर पर श्रावश्यकता की कसौटी पर त्राघारित है लेकिन साथ ही यह व्यवस्था की गयी है कि सहायता पाने वाला राज्य फिज्लखर्ची न करे श्रीर श्राय के श्रपने साधनों का उपयोग करने के लिए पूर्ण कोशिश करे। यह व्यवस्था प्रदत्त ऋनुदानों में व्यय को कम करने श्रथवा कर से श्राय को बढ़ाने की सम्मावना को ध्यान में रखकर लागू की चाती है। इस व्यवस्था के साथ इन श्रनुदानों का उद्देश्य यह है कि अनुदान पाने वाले राल्य श्रपना कार्य सहायता पाने का दावा न करने वाले राज्यों के स्तर से श्रिधिक नीचे न करें। थोड़ा सा श्रन्तर इस श्राघार पर रखा जाता है कि किसी राज्य को यह श्राशा नहीं करनी चाहिए कि उसको उन राब्यों के स्तर के बराबर लाया जाना चाहिए जो श्रपने ही साधनों पर निर्मर रहते हैं। दूसरे, श्रपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करने के लिए राज्य

को श्रवसर दिया जाना चाहिये। लेकिन इस प्रणाली का सफल कार्यान्वयन 'राष्ट्र-मंडल श्रनुदान श्रायोग' (Commonwealth Grants Commission) द्वारा राज्यों की सफलता तथा उनकी श्रावश्यकताश्चों की वार्षिक जाँच श्लीर निर्धारण पर निर्भर है"।

"दूसरे देशों में राष्ट्रीय महत्व की समकी जाने वाली विशेष सेवाओं श्रीर कायों के विकास के लिए भी कुछ निश्चित श्रनुदान दिये जाते हैं। सधारणतया हन श्रनुदानों के साथ यह शर्त रहती है कि राज्य संघीय श्रनुदानों के बरावर श्रयवा कस-ज्यादा श्रयने पास से धन राशि लगायें। एक श्रोर जहाँ कनाडा श्रीर श्रास्ट्रेलिया से शर्त सहित श्रनुदान विना शर्त श्रनुदानों के साथ-साथ चलते हैं वहीं दूसरी श्रोर संयुक्त राज्य श्रमेरिका में राज्यों को सहायता देने का तरीका सिर्फ शर्त श्रुदा श्रनुदान है। वहाँ विशेष कार्य-कमों को सहारा देने के लिए संघीय सहायता दी जाती है"।

'शर्त सहित अनुदानों के चेत्र से सम्मन्ध नीति पर जिन अत्यधिक महत्वपूर्ण कारणों का असर पड़ता नजर आता है वे इस प्रकार हैं—एक ओर इन
अनुदानों का इकाइयों की चम्मता अयवा आर्थिक सामर्थ्य के साथ और दूसरी
ओर निश्चित सेवाओं के सम्मन्ध में उनकी सापेचिक आवश्यकताओं के साथ
धीरे धीरे संतुलन स्थापित करना। पहले कारण के अन्तर्गत संधीय अनुदान को
राज्य के अंशदान के साथ "संतुलित करने के लिए आवश्यकताओं में परिवर्तन
हो सकता है जिससे आर्थिक दृष्टि से कमनोर राज्यों के अंशदान को घटाया ना
सके। यह सही है कि अनुदान के पीछे आवश्यकता का सिद्धान्त है और इसका
यह अर्थ होता है कि उन राज्यों को जिनमें शिच्चा अथवा सड़क ऐसी विशेष
सेवा की कमी है, उन राज्यों की अपेचाकृत ज्यादा सहायता मिलेगी जिनकी
रिथति इनसे ज्यादा अन्छी है"।

वित्त त्रायोग ने भारत के लिए शर्त सहित श्रीर विना शर्त दोनों प्रकार के सहायता अनुदानों की सिफारिश की श्रीर कुछ निश्चित सिद्धान्त सुक्ताये जिनके अनुसार यह श्रनुदान निश्चित किये जाने चाहिएँ। वित्त श्रायोग द्वारा सुक्ताये गये नियमों की संज्ञिस रूपरेखा निम्नलिखित है:—

- (१) राज्यों को सहायता श्रनुदान देने के लिए श्रीर उसकी मात्रा निश्चित करने के लिए श्रावश्यकता का श्राधार बहुत उचित श्राधार है। इसलिए यह श्रावश्यक है कि भिन्न राज्यों के नजट एक निष्ध से बनाये जायेँ जिससे उनकी दुलना की जासके।
 - (२) प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर निश्चित की जाने वाली किसी

राज्य की श्रन्य राज्यों की श्रपेक्षा गरीवी श्रयवा सम्पन्नता को सहायता श्रनुदान का श्राधार नहीं बनाना चाहिए। 'यदि कोई राज्य कर लगाकर श्रधिकतम राजस्व वस्त् करने के लिए तैयार है तो केन्द्रीय सरकार की सहायता का वह उस राज्य को श्रपेक्षा श्रिधिक श्रधिकारी है जो इस दिशा में स्वयं पर्याप्त प्रयत्न नहीं करता है'।

- (३) उन राज्यों को सहायता श्रनुदान देने की प्राथमिकता देनी चाहिए जो केन्द्र से सहायता की माँग करने के पूर्व श्रपनी श्राय के साधनों का पूरा उपयोग कर लेते हैं श्रीर श्रपने ज्यय में कभी कर लेते हैं। 'श्राधिक सहायता देने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे यह श्रामास न होने लगे कि केन्द्रीय सरकार ने प्रतिवर्ष राज्यों को वजट सन्तुलित करने में सहायता देने का भार स्वयं श्रपने कपर ले लिया है। यदि सहायता श्रनुदान केवल राज्यों की पिछड़ी वित्तीय स्थित के श्रनुतात में ही दिये जाय तो इसका श्रर्थ है कि सहायता श्रनुदानों के द्वारा सरकार श्राधिक स्थिति को कमजोर श्रीर दिवालिया बनाने की नीतियों को प्रोत्साहन देती है श्रीर उन राज्यों को जिनकी वित्त स्थिति श्रन्छी है उनको सतर्क श्रीर उपयुक्त वित्त नीतियों के जिए दिखड़त करती है'।
- (४) 'सहायता अनुदान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विभिन्न राज्यों के बुनियादी समाज सेवा कार्यों का स्तर समान करने में मदद की जाय'। समाज-सेवा कार्य के स्तर के आधार पर सहायता अनुदान दिये जा सकते हैं। समाज सेवा-कार्य का स्तर निश्चित करने के लिए राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखकर उसके चेत्रफल, उसकी पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति इत्यादि पर विचार किया जाना चाहिए।
- (५) 'यदि सारे राष्ट्र के सम्बन्ध रखने नाले कार्य राज्य की सीमा के अन्दर पड़ते हों और उनको पूरा करने में राज्य की नित्त स्थित पर अनुनित मार पड़ता हो तो ऐसी स्थित में राज्य की सहायता के लिए भी सहायता अनुदान दिये जा सकते हैं'। देश के निमाजन जैसी असामान्य स्थिति में राज्य से जिन कार्यों को पूरा करने की अपेद्धा की जाती है उन पर निचार किया जा सकता है।
- (६) 'वजट के आधार पर विचार न करके आनुदान किसी बुनियादी महत्व की सेवा के विकास के लिये दिया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकीण से अविकसित राष्ट्रों में उस सेवा सुविधा को बढ़ाना आवश्यक है?।

वित्त स्रायोग ने विभिन्न राज्यों के दावों पर विचार किया श्रीर उसने इन राज्यों की वजट की सामान्य श्रावर्यकताश्रों, देश विभाजन से उत्पन्न विशेष समस्याश्रों श्रीर पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की वास्तविक श्राय श्रीर व्यय से परि- लिस्ति विचीय स्थिति ऐसी दो-तीन बातों पर विचार करने के बाद कुछ राज्यों को सहायता श्रनुदान देने की सिफारिश की।

उक्त श्राधार पर श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि मद्रास, उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान, मध्य मारत श्रीर पटियाला संघ सहायता श्रनुदान पाने के श्रधिकारी नहीं हैं श्रीर इसीलिये इसने सिकारिश की कि इन राध्यों को कोई सहायता श्रनुदान न दिया जाय । बम्बई, पिरचम बंगाल श्रीर सौराष्ट्र श्रनुदान पाने के श्रधिकार के निकट समके गये । बम्बई के सम्बन्ध में श्रायोग ने सिकारिश की कि तम्बाक् पर कर लगाने में जो प्रतिबन्ध है उसे दूर कर दिया जाय जिससे बिक्ती कर द्वारा राज्य का राजस्व बढ़ेगा श्रीर चूँ कि यह श्रन्य राज्यों की श्रपेचा श्रधिक विकसित है श्रतएव उसे किसी प्रकार की सहायता श्रनुदान की श्रावश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में श्रायोग का मत या कि विभाजन के कारण व्यय की मदों में कुछ वृद्धि हो गई है इसिलाए उसने सिकारिश की कि पश्चिमी बंगाल को ८० लाख रुपये का प्रतिवर्ष सहायता श्रनुदान दिया जाय । पिछड़ा हुश्रा राज्य होने के कारण उड़ीसा को दिया जाने वाला सहायता श्रनुदान ४० लाख से बढ़ा कर ७५ लाख कर दिया गया। सीराष्ट्र को राज्य विस्तार के श्रनुपात में श्राय कम होने के कारण श्रायोग ने ४० लाख रुपये का सहायता श्रनुदान देने की सिकारिश की।

वित्त स्रायोग का मत था कि पंजाब श्रीर श्रासाम को सहायता की निश्चय ही बहुत श्रिधिक श्रावश्यकता है। देश के विभाजन होने से पंजाब की वजट की स्थित कमजोर हो गई थी श्रीर कान्न तथा ज्यवस्था के चेत्र में राज्य पर श्रीर नये उत्तरदायित्व श्रा गये। इन बातों को ध्यान रखते हुये श्रायोग ने सिफारिश की कि पंजाब को मित वर्ष १ करोड़ २५ लाख रुपये का सहायता श्रनुदान दिया जाय। इसी प्रकार विभाजन के कारण ज्यय की मदों में वृद्धि हो जाने से श्रासाम की बजट की स्थिति भी नाजुक हो गई थी, इस्र लिए श्रायोग ने सिफारिश की कि श्रासाम को दिया जाने वाला ३० लाख रुपये का सहायता श्रनुदान बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया जाय। मैसूर श्रीर त्रिवांकुर-कोचीन की श्राय के साधन सीमित होने के कारण श्रीर इनकी प्रगति की गति बनाए रखने के लिए श्रायोग ने सिफारिश की कि मैसूर को प्रति वर्ष ४० लाख रुपये के श्रीर त्रिवांकुर-कोचीन की अप्र लाख रुपये के सहायता श्रनुदान दिए जायँ।

पायमरी शिक्षा के महत्व को देखते हुए श्रायोग ने इसके लिए राज्यों को सहायता अनुदान देने की सिफारिश की । ६ श्रीर ११ वर्ष के बीच की उम्र वाले स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या के श्रनुपात पर विचार करते हुए यह

विफारिश की गयी कि जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते उनकी संख्या के श्रनुपात में श्रमले हर चार वर्ष में यानी १६५३-५४ में १५५ करोड़ रुपये से लेकर १६५६-५७ तक ३ करोड़ क्पये श्राठ राज्यों में वितरित किये जायें।

वम्बई और पश्चिम बंगाल ने वित्त श्रायोग की िक्फारिशों की विशेष श्रालोचना की। उनका मत या कि श्रायोग ने कर-संग्रह के स्रोत की उनकी इच्छा के विपरीत बहुत कम महत्त्व पदान किया है। कुछ राज्य फेन्द्रीय उत्पादन कर की श्राय में श्राधिक हिस्सा चाहते थे। सहायता श्रनुदानों के सम्बन्ध में यह सकाव दिया गया कि वजट ज्यवस्था की श्रपेन्ना राज्य की श्रावश्यकताश्रों पर श्रिक ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि श्रायोग ने श्रपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि सहायता श्रनुदानों श्रीर राजस्व के वितरण के सम्बन्ध में श्रन्य योजनाएँ भी हो सकती हैं परन्तु भारत की वर्तमान स्पित को श्रीर संघीय वित्त ज्यवस्था को घ्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वित्त श्रायोग ने बो योजना प्रस्तुत की है वह उपयुक्त है।

द्वितीय वित्त आयोग

द्वितीय वित्त श्रायोग जून १६५६ में नियुक्त किया गया। इसके श्रध्यन्त श्री कें वन्थानम् ये, श्रीर इसने श्रपनी श्रन्तरिम रिपोर्ट सरकार को नवम्बर, १६५६ में तथा श्रन्तिम रिपोर्ट सितम्बर, १६५७ में दी। फेन्द्र श्रीर राज्यों के बीच कर श्राय को विभाजित करने के ढंग तथा नियमी के बारे में यह श्रायोग सामान्यतः पहले श्रायोग से सहमत या यद्यांप इसने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित किये। दृसरा श्रायोग राज्यों के प्रांत श्रधिक उदार था श्रीर उसने राज्यों को देश की कुल द्याय में से क्रिधिक माग दिया। दितीय क्रायोग की सिफारिश थी कि राज्यों को १४० करोड़ र॰ (जिसमें रेल भाड़े की एक वर्ष की १५ करोड़ रुपये की कर प्राय समिलित नहीं थी) दिया नाय जबिक पहले ख्रायोग की सिफारिश के अनुसार ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले पाँच वर्षी' में श्रीसत ६३ करोड़ रुपये दिये गये थे। राज्यों की आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रतिरचा श्रीर राष्ट्रीय विकास के प्रति केन्द्र के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुये राज्यों के साधन हस्तान्तरित करने के लिये एक संगठित योजना प्रस्तावित की गयी। प्रस्तावित योजना में कर श्राय में से दिये जाने वाले भाग तथा निश्चित सहायता-श्रनुदानों से प्राप्त राशि के बीच सन्तुलन रखा गया। पहली श्राप्रेल, १९५७ से राज्यों को मिलने वाली राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है यद्यपि प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली निश्चित राशि कर त्राय पर निर्भर करेगी।

उपभोग को श्रिविक महस्व दिया है। इसने श्राय-कर, केन्द्रीय उत्पादन कर तथा रेल भाड़े पर लगे कर के लिये पहले श्रायोग से मिन्न श्रावार श्रपनाया।

श्राय-कर—दितीय श्रायोग ने सिफारिश की कि (१) 'वितरण कोप में'
राज्यों का माग ५५% से बढ़ाकर ६०% कर दिया जाय क्योंकि सभी राज्यों ने एक
स्वर से इसकी माँग की थी। (२) राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से का निर्धारण
जनसंख्या के श्राधार पर होना चाहिये। उसने कर संग्रह को विभाजन के श्राधार
के रूप में कमशः हटाने की सिफारिश की। उसने कहा कि श्रारम्भ में राज्यों के
हिस्से का वितरण १०% कर संग्रह के श्राधार पर श्रीर ६०% जनसंख्या के श्राधार
पर किया जाय जबिक पहले श्रायोग में कमशः २०% श्रीर ८०% की सिफारिश की
थी। केन्द्रीय प्रदेशों को दी जाने वाली राशि श्रायकर की श्रमली श्रामदनी ना १%
निश्चित की गई। श्रायकर वितरित करने का श्राधार श्रव श्रिक वैद्यानिक तथा
सभी राज्यों के लिये श्रिषक न्यायपूर्ण हो गया है क्योंकि श्रावर्यकता का सरी
स्वक जनसंख्या है, कर संग्रह का स्रोत नहीं।

केन्द्रीय उत्पादनकर—पहली ग्रप्रेल, १६५२ से पहले केन्द्र ग्रीर राज्यों के बीच कोई उत्पदानकर नहीं बाँटा जाता या लेकिन प्रथम ग्रायोग ने यह िक्सारिश की कि १६५२-५३ से तम्बाक् (जिसमें निर्मित तम्बाक् शामिल है), दिया-सलाई, वनस्पति पदार्थ पर लगे केन्द्रीय उत्पादनकर की वास्तिवक ग्राय का ४०% राज्यों में जनसंख्या के ग्राधार पर बाँटना चाहिये। द्वितीय ग्रायोग ने यह िक्सारिश की कि इन तीन करों के ग्रलावा, चीनी, चाय, कहवा, कागज तथा वनस्पति तेल के करों में से भी राज्यों को भाग मिले किन्तु राज्यों का भाग २५% कर दिया जाय। राज्यों के भाग में लो कभी की गई है उसकी पूर्ति बाँदने वाले करों की वृद्धि से हो जायगी श्रीर वर्तमान की तुलना में प्रत्येक राज्य को ग्राधिक मिलेगा। ग्रायोग ने यह भी किफारिश की कि राज्यों को दिये जाने वाले माग का ६०% जनसंख्या के ग्राधार पर वितरित किया जाय तथा श्रेष का प्रयोग सन्तुलन के लिये किया जाय।

राज्य सरकारों द्वारा पहले लगाये हुये विक्री-कर के स्थान पर अब मिल के बने सूती वस्त्र, चीनी और तम्बाक् (निर्मित तम्बाक् सम्मिलित है) पर अतिरक्त उत्पादनकर लगाये गये। आयोग ने सिकारिश की है कि प्राप्त राशि का १% केन्द्रीय प्रदेशों को, १६% जम्मू और काश्मीर को दिया जाय तथा अन्य राज्यों को वर्तमान आय का आश्वासन दिया जाय अर्थात् विक्री कर हटाने से पहले की आय जो सभी राज्यों की कुल मिलाकर ३२६ करोड़ द० थी। ३२६ करोड़ के बाद शेष धन प्रतिशत के आधार पर वितरित किया जाय। आयोग ने यह प्रतिशत अधि-

कांशत: उपभोग के श्रांकिहों के श्राधार पर निकाले हैं। लेकिन उपभोग के श्रांकिहें सदोप थे इसलिए दोष को दूर करने के लिए साथ साथ जनसंख्या पर भी विचार किया गया।

सम्पत्तिकर (Estate Duty)—कृषि भूमि को छोइकर शेष सम्पत्ति पर लगी शुल्क से प्राप्त अधली श्राय राज्यों के बीच उसी श्रानुपात में श्रस्थायी लक्ष्य से वाँटी जाती थी जिस श्रनुपात में 'वितरण कोष' से श्रायकर बाँटा जाता था। श्रायोग ने यह प्रस्तावित किया कि असली श्राय का एक प्रतिशत केन्द्रीय प्रदेशों का भाग होना चाहिये तथा शेष श्रचल तथा श्रन्य संपत्ति के बीच उस वर्ष निर्धारित मूल्य उनके कुल के श्रनुपात में बाँट देना चाहिये। इस प्रकार श्रचल सम्पत्ति के लिए निश्चित भाग को विभिन्न राज्यों में उनमें स्थित श्रचल सम्पत्ति के क्ष्रनुपात में बाँट देना चाहिये। श्रम को विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के श्रनुपात में बाँट देना चाहिये। श्रम्य सम्पत्ति का भाग विभिन्न राज्यों के बीच इस श्रनुपात में बाँट देना चाहिये। श्रम्य सम्पत्ति का भाग विभिन्न राज्यों के बीच इस श्रनुपात में बाँटना चाहिये।

राज्य	प्रतिशत	
श्रान्ध्र प्रदेश	िन:७६	
श्रासाम	ૂં ર પ્ર	
विद्यार	१०•८६	
वस्बई	१३'५२	
केरल	A.0E	
मध्य प्रदेश	७ ३०	
मद्रास	5.80	
मैस्र	ી મુજર	
ਤ ਫ਼ੀਗ	X.50	
पंजाब	V 8.45	
राजस्थान '	૪ ɨ૪७	
उत्तर प्रदेश	\$ 60.08	
पश्चिमी बंगाल	७॰३७	Į.
जम्मू श्रीर काश्मीर	१.५४	

रेल भाड़े पर कर-"रेल भाड़े पर लगे कर के सम्बन्ध में श्रायोग का मत यह था कि इस राशि में राज्य का भाग यथासम्मव राज्य की सीमा के भीतर हुई रेल यात्रा से हुई श्रष्ठली श्राय के श्राघार पर निश्चित होनी चाहिये। चूँ कि विभिन्न राज्यों की सीमाश्रों के श्रन्दर होने वाली रेल यात्रा के सभी श्राँकड़े सुलभ नहीं है इसीलिए श्रायोग ने इन श्राँकड़ों को कुछ श्रनुमानों पर श्राघारित किया है। इस कर से होने वाली श्रमली श्राय का वितरण केन्द्रीय प्रदेशों को देने के लिए है प्रतिशत निकाल लेने के बाद होगा।

सहायता-श्रनुदान

सिद्धान्त—द्वितीय वित्त आयोग ने सहायता-अनुदानों के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया और ऐसे अनुदानों को निर्घारित करने के लिए कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये:

- (१) "सहायता-अनुदान पाने के लिए किसी राज्य का हक तथा इस प्रकार की सहायता की रक्षम का निर्धारण विस्तृत रूप से उसकी आर्थिक आव-श्यकता पर निर्मर होनी चाहिए। एक ऐसे देश में जहाँ केन्द्र और राज्य नियो- जित विकास के लिए सहयोग करते हों वहाँ सहायता-अनुदानों को इसी उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। स्वयं योजना की प्राथमिकताओं और व्यवस्थाओं से योजना की अविध के लिए विकास की आवश्यकताएँ निर्धारित होनी चाहिएँ"।
- (२) "किसी राज्य के सामान्य राजस्व श्रीर उसके सामान्य श्रानिवार्य व्यय में बीच के श्रान्तर का, जहाँ तक सम्मव हो, करों के हिस्से से दूर किया जाना चाहिए। सहायता-श्रानुदान श्राधिकांशतः सामान्य तथा विना शर्त श्रानुदान के रूप में प्रदत्त शेप सहायता की शक्ति में होना चाहिए?
- (३) "मोटे-मोटे कामों के लिए मी अनुदान दिये जा सकते हैं। वे राजस्व के सहायता-अनुदान होने चाहिएँ लेकिन राज्यों का यह कर्तेज्य रहना चाहिए कि वे उल्लिखित मोटे कामों को पूरा करने में पूरी रकम खर्च करें। जहाँ ये काम विस्तृत योजना के अन्तर्गत आ गये हों वहाँ ऐसे अनुदानों की आवश्यकता नहीं"।

जैसा कि पहले श्रायोग ने किया या द्वितीय श्रायोग ने प्रायमरी शिद्धा के विकास, भवन निर्माण श्रादि ऐसे मोटे-मोटे कामों के लिए किसी श्रनुदान की सिफारिश नहीं की लेकिन इसने १४ राज्यों में से ११ के लिए पर्याप्त सहायता-श्रनुदान की सिफारिश की है। वस्त्रई, मद्रास श्रीर उत्तर प्रदेश के लिए किसी सहायता-श्रनुदान की सिफारिश नहीं की गयी क्योंकि श्रायोग की राय में वितरण की प्रस्तीवित योजना से उनको श्रयन चालू तथा योजना व्यय के लिए पर्याप्त साधन मिल जायेंगे।

सहायता-अनुदान की धन-राशि—"श्रायोग ने राज्यों को करों में हिस्सा देकर उनकी श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने की कोशिश की है लेकिन इस वितरण से श्रिधकारा राज्यों का काम नहीं चलेगा श्रीर इस कभी को सहायता-श्रनुदानों से पूरा किया गया है"। ये श्रनुदान जिनकी सिफारिश की गयो है, पूर्व काल के श्रनुदानों से कहीं ज्यादा वहें हैं क्योंकि पहले राज्यों की विकास श्रावश्यकताश्रों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। इस श्रनुमान पर कि देश मार्च, १६६२ के श्रन्त तक पाँच वर्षों की श्रविध में राज्यों के विकास में राजस्व-ज्यय उसी स्तर पर पहुँच जाय ग जैस कि दितीय योजना में है श्रीर प्रत्येक राज्य की विशेष स्थितयों पर विचार करके श्रायोग ने निम्मलिखित ढंग से विना शर्त श्रनुदान देने की सिफारिश की है:—

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	१६५७- ५८	१६५८- ५६	१६५ ६ - ६०	१ ६ ६०- ६१	१६६१- ६२	योग
न्नान्ध्र प्रदेश	8,00	8,00	X.00	A.00	X'00	₹0.00
ग्राधाम	३ ७५	ই∙৬५	३'७५	४.५०	४.त०	२०'२५
बिहार	३१५०	३.त०	३५५०	४ॱ२५	४'२५	00.38
वे. रल	१.७४	₹.64	३ .७४	१.७४	१॰७५	504
मध्य प्रदेश	₹'00	₹.00	₹*00	३'००	\$.00	१५,००
मैसूर	Ę *00	Ę.00	Ę.00	£'00	£.00	\$0.00
उद्गीवा	३॰२५	३०२५	३•२५	३•५०	३.त०	१६•७५
पंजाय	ર•રમ્	ર રપ્	२•२५	२•२५	२.५५	११•२५
राजस्थान	२.४०	र.तं	२.५०	रापु०	२.४०	१२५५०
पश्चिम बंगाल	३ २५	રૂ· ર પ્ર	३•२५	४.७४	४७४	१६.५४
जम्मू तथा कश्मीर	₹'००	3.00	३.००	3.00	\$.00	१५.००
	३६.५४	३६.५४	३६•२५	रह ५०	₹€.40	१८७'७५

ऋषा-- "श्रायोग ने श्रपने सामने प्रस्तुत की गई भूगा की व्यवस्थाश्रों श्रीर शतों पर विवार करने के बाद सिकारिश की कि जो भूग बगैर व्याज के दिये गये हैं उनमें कोई संशोधन करने की श्रावश्यकता नहीं। उद्वासित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दिये गये शृश्यों के बारे में उसने सिकारिश की कि १ श्रप्रैल,

१६५७ से राज्य सरकारें केन्द्र को केवल वही रकमें अदा करें जिन्हें वे उद्वासित ज्यक्तियों से मूलधन ज्याज और बकाया के सिलसिलों में वस्ल कर पायें। उसने सुक्ताव दिया कि ३ प्रतिशत या इससे अधिक ज्याज दर वाले ऋगों की बकाया रकमों को दो ऋगों का रूप दे दिया जाय और दोनों पर ज्याज की दर ३ प्रतिशत रहे। एक के अन्तर्गत उन ऋगों की वकाया रकमें रखी जायें जिनकी अदायगी २० या इससे कम वर्षों में होनी चाहिये थी और १५ वर्ष के अन्त में अदा कर दिया जाय। दूसरे के अन्तर्गत शेष ऋग्य रखे जायें जिनकी अदायगी २० साल के अन्त में की जाय। उसने ३ प्रतिशत से कम ज्याज दर वाले ऋगों को भी दो ऋगों में परिवर्तित करने का सुक्ताव दिया जिन पर २३ प्रतिशत की ज्याज दर रहे। आयोग ने ऋगों के एकीकरण की जो योजना प्रस्तुत की है उस से राज्यों को कुल मिला कर ५ करोड़ रुपये की वार्षिक वचत होगी?'।

राज्यों पर केन्द्र के जो ऋगा हैं उनके बारे में श्रायोग की सिफारिश श्रभी तक सरकार के विचाराधीन है। बाकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार करके लागू कर दिया है।

दिलीय श्रायोग ने राज्य सरकारों की श्रावश्यकताश्रों के साथ उदारता दिलाई है श्रीर वितरित किये जाने वाले करों में उनके हिस्से को काफी बढ़ा दिया है। उसने यह ठीक ही किया है क्योंकि श्राधकांश विकास-कार्यक्रमों की जिम्मेदारी राज्यों पर ही है। यद्यपि कुछ राज्यों की श्रव भी यह भावना है कि उन्हें श्रीर श्रिषक राशि मिलनी चाहिए थी लेकिन श्रायोग ने जो वितरण किया है वह मोटे तौर से उचित श्रीर न्यायपूर्ण है। दूसरे श्रायोग ने बगैर किसी खास उद्देश्य की शर्त जगाये सहायता श्रनुदान देकर श्रीर केन्द्र के दिये गये ब्याज को घटा कर केन्द्र श्रीर राज्यों की निरतंर कलह की सम्भावना को श्रगर पूरी तरह से नहीं दूर किया तो कम से कम घटा तो दिया ही है। श्रन्त में, दितीय श्रायोग ने प्रथम श्रायोग की श्रपेद्धा कर-वितरण का श्राधक श्रासान श्राधार श्रपनाया है श्रीर जन-संख्या इसकी सिफारिशों का मुख्य श्राधार रहा है यद्यि कुछ मामलों में कर-संग्रह के स्त्रोत तथा उपयोग के स्तर पर भी विचार किया गया है।

अध्याय ५५

कर जाँच आयोग की रिपोर्ट

(Taxation Enquiry Commissiaon's Report)

हाक्टर नान मथाई की अध्यक्षता में अभैन १६५१ में निम्नलिश्वित वार्तों की जींच के लिए एक कर जींन आयोग नियुक्त किया गया:—(१) भारत में जनता पर कर-भार, (२) देश के विकास कार्य कमी, इसके लिए आवश्यक साधनी और आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर मणानी की उपयुक्तता, (३) पूँजी निर्माण तथा उत्पादन उद्योग की रज्ञा और विकास पर आय-कर का प्रमान, और (४) मुद्रास्कीति तथा मुद्रासंकुचन की रिथितियों का मुकानला करने के लिए करों का आर्थिक उपकरण के रूप में प्रयोग । सरकार ने २० करवरी, १६५५ को आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की। यह तीन भागों में हैं। पहली में पूरी कर प्रणाली पर विचार किया गया है, दूसरी में केन्द्रीय करों पर श्रीर तीसरी में गज्य तथा स्थानीय करों पर विचार किया गया है।

सामान्य—श्रायोग ने देला कि यदापि युद पूर्व काल से सरकार का राज-स्य यहां है लेकिन इडका कारण श्राधिक श्रायों की ज्यापक (मुद्रास्कीत जन्य) वृद्धि रही है श्रीर करों से प्राप्त होने वाली कुल राजस्व राष्ट्रीय श्राय के लगभग ७ प्रतिशत के स्तर पर एक सी बनी रही है श्रीर "युदपूर्व काल के मुकाबले यह श्रनु-पात घटा ही दिलाई देगा यद्यपि तुलना के लिए युद्ध-पूर्व की राष्ट्रीय श्राय श्रीर कर राजस्व के सदी-सही श्रांकड़े नहीं दिये जा सकते"। यद्यपि श्रायोग ने यह श्रनु-मान नहीं लगाया कि कुल कर राजस्व श्रीर राष्ट्रीय श्राय में क्या श्रनुपात होना चाहिए परन्तु इवने कई देशों का उदाहरण दिया है जहाँ कुल कर-राजस्व राष्ट्रीय श्राय का बहुत बढ़ा श्रंश है श्रीर यह जान पढ़ता है कि श्रायोग को इस पर कोई श्रायित न होगी श्रमर कुल कर-राजस्व निकट मिवष्य में राष्ट्रीय श्राय का है है

यद्यपि भारत में कुल कर-राजस्व से प्रत्यक्त करों का प्रतिशत १६३८-३९ में १२ प्रतिशत से बहुकर १६४४-४५ में ४५ प्रतिशत हो गया लेकिन १६५३-५४ में यह घट कर २४ ही रह गया। इस वर्ष बस्तु-कर तथा झन्य कर को मुख्यतः देश के आन्तरिक उपभोग पर लगते हैं, कुल राजस्व के ४५ प्रतिशत वे। राज्य सरकारों द्वारा विक्री कर लगाये जाने से और केन्द्रीय उत्पादन करों में

श्रन्य वस्तुश्रों को शामिल करने तथा इसमें श्राय बढ़ने से श्रप्रारयज्ञ करी का भारतीय कर-प्रणाली में एक बहत्वपूर्ण स्थान हो गया है।

पूर्वकाल में भारतीय कर प्रणाली का एक गम्भीर दीप यह था कि राज्यों के राजस्व में लचीलापन श्रीर पर्याप्तता का श्रभाव था। श्रायोग ने देखा कि चूँकि केन्द्रीय राजस्व गायनों में से राज्य गरकारों के हिस्से में वृद्धि हो गयी है श्रीर केन्द्र से पर्याप्त श्रनुदान मिलते हैं इग्रलिए श्रव पहले की श्रपेचा केन्द्रीय राजस्व में राज्य गरकारों की वित्तीय दिलचस्पी कहीं ज्यादा त्रद्ध गयी है श्रीर इग्रीलए "गरकारी वित्तीय स्थित पर गंयुक्त रूप से विचार" जरूरी है। लेकिन इतनी ही महत्वपूर्ण दूशरी बात यह है कि इन परिवर्तनों के कारण राज्यों का राजस्व पहले की श्रपेचा काफी ज्यादा लोचदार तथा पर्याप्त हो गया है। लेकिन यह बात स्थानीय निगमों की वित्तीय स्थित के बारे में नहीं कही जा एकती। श्रायोग के मतानुसार स्थानीय निगमों के वित्तीय स्थानों के वारे में महीं कही जा एकती। श्रायोग के मतानुसार स्थानीय निगमों के वित्तीय साधनों के वारे में महीं कही जा एकती। श्रायोग के मतानुसार स्थानीय निगमों के वित्तीय साधनों के वारे में महीं कही जा एकती। श्रायोग के मतानुसार स्थानीय निगमों के वित्तीय साधनों के वारे में महीं कही जा एकती। श्रायोग के मतानुसार स्थानीय निगमों के वित्तीय साधनों श्रीर नगर-पालकाश्रों की श्राय के मुख्य श्रीत हैं श्रीर स्थानीय कोष श्रुल्क (Local fund cess) जिला वोडों की श्राय का मुख्य गायन है। इन गव के कारण स्थानीय निगमों की श्राय श्रपर्याप्त है श्रीर उसमें लचीलापन नहीं है जैसा कि पहले राज्य की वित्तीय स्थिति में था।

श्रार्थिक नियोजन के दृष्टिकीण से भारत में सरकारी न्यय को श्रमुत्पादक से उत्पादक बनाया गया है। श्रायोग के मतानुसार १६३८-३६ श्रीर १६५३-५४ के बीच केन्द्रीय प्रतिरहा न्यय कुल केन्द्रीय न्यय के श्रमुपात में ५४ प्रतिशत से घटकर ४८ प्रतिशत हो गया श्रीर प्रशासन पर न्यय १३ प्रतिशत से घट कर ६ प्रतिशत हो गया। यह सही है कि श्रम भी १६५३-५४ की भाँति गैर-विकास कार्यों में न्यादा न्यय होता है। भारत की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कुल राजस्व से श्राधार पर एक रुपये में करीब ६ श्राना ६ पाई गैर विकास कार्यों पर, ३ श्राना २ पाई सामाजिक सेवाश्रों पर श्रीर ३ श्राना ४ पाई श्रार्थिक विकास पर खर्च किया जाता है। लेकिन यह उत्साहवर्धक है कि विकास कार्यों पर होने वाले न्यय का श्रमुपात बढ़ता जा रहा है श्रीर श्रार इस कंन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पूँजीगत बजटों पर भी विचार करें तो हियित श्रन्धी तथा राज्य सरकारों के पूँजीगत बजटों पर भी विचार करें तो हियित श्रन्धी नजर श्रायेगी। श्रायोग के श्रमुसार मारत में श्राय की श्रसमनताश्रों को कम करने में सरकारी न्यय का बहुत कम श्रसर पड़ा है क्योंकि राष्ट्रीय श्राय के श्रमुपात में यह रकमबहुत कम है (१६५३-५४ में समस्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों श्रीर स्थानीय निगामों का कुल न्यय ११७० करीड़ हाया था जो राष्ट्रीय श्राय का

केवल ११ प्रतिशत था) और सामाजिक कल्याण पर, श्रथवा श्रल्प श्राय वाले वर्गों को श्रार्थिक सहायता देने के ब्यय पर बहुत कम महत्व दिया गया है।

कर भार के सम्बन्ध में आयोग की राय है कि यह नहीं कहा जा सकता कि दितीय महायुद्ध के आरम्भ के बाद देश में नगर होतों की अपेद्धा प्राम्य होतों के अपेद्धा नगर होतों के आप में कोई विशेष वृद्धि हुई है, यद्यपि विभिन्न होतों के अन्तगर्त विभिन्न नगों की आप में परिवर्तन हुआ है। अपोग ने यह भी पाया कि (१) यय प्राप्य होत्र की अपेद्धा नगर का कर-स्तर आय की सभी अवस्थाओं में कुल मिला कर ऊँचा है, परन्यु बीच की और नीचे की आयों में असमानता अधिक नहीं है; (२) नगर का अपद्धा माम्य होत्र की अपेद्धा माम्य होत्र में अब्द्धी आयों पर कर लगाने का अधिक अवसर है; (४) जमीन के लगान का भार अब अधिक नहीं है; और (५) ग्राम्य अर्थ व्यवस्था का गैर मुद्धा वाला विस्तृत होत्र एक साथ कर की सीमाओं और इस होत्र में कर लगाने की समावनाओं की और संकेत करता है यदि इसको बांछनीय समका जाय।

कस्पिनयों के बारे में श्रायेग इस परिणाम पर पहुँचा कि कर लगाने के पहले मुनाफे में करीन ४३ प्रतिशत पर कर लगता है जब कि मुनाफे का वितरित श्रंश ३४ प्रतिशत श्रोर संरक्तित मुनाफा, घिसानट श्रीर ट्रूट फूट छोड़ कर २२ प्रतिशत रहता है। नितरित मुनाफे श्रीर संरक्तित मुनाफे के तुलनात्मक श्रांकड़ों से जाहिर है कि नितरित मुनाफे का स्तर बनाये रखने अथवा उसको बढ़ाने की मानना काम कर रही है, जिससे व्यापार की प्रतिकृत स्थिति का संरक्तित मुनाफे पर अनुपात से श्रिक भार पड़ता है। सुलम श्रांकड़ों से जाहिर है कि संरक्तित मुनाफे की रकम श्रीर कुल मुनाफे से इसका श्रनुपात कर की माना श्रीर दर के मुकानते मुनाफे की माना श्रीर दर से मुकानते होते हैं।

भावी कर नीति—श्रायोग ने इस बात पर जोर दिया कि श्रावश्यकता इस बात की है कि कर प्रणाली का लोगों की श्राय श्रीर सम्पत्ति की श्रसमानताओं की दूर करने में प्रयोग किया जाय। इसके लिए उसने सिफारिश का है कि प्रत्यक्त कर में धीरे-धीरे वृद्धि की जाय श्रीर कर वस्त करने के लिए प्रभावशाली दंग श्रपनाये जाँय। श्रायोग ने सिर्फ प्रत्यक्त कर पर ही ध्यान नहीं दिया—उसने सम्पूर्ण कर प्रणाली को 'विस्तृत तथा गहरी' करने की सिफारिश की है श्रीर इसके लिए उसने सुमाव दिया है कि न्यापक रूप ने बिलास (Juxury) तथा श्राधिकास की वस्तुश्रों पर काफी कँची दर से श्रीर सार्वजनिक उपभोग की वस्तुश्रों पर श्रपेकाकृत नीची दरों से कर लगाये जायाँ। श्रायोग एक श्रत्यिक श्राश्चर्य-

जनक परिस्माम पर पहुँचा कि इस प्रश्न पर न्यापक रूप से विचार करने के बाद यह श्रावश्यक है कि करों के द्वारा भारत में सभी वर्मों के उपभोग को स्मित किया जाय। श्रायोग ने कहा— विकास कार्य-कम श्रीर इसके लिए श्रावश्यक साधनों को विचाराधीन रख कर कुल मिलाकर भारत की श्र्यं न्यवस्था के लिए वह कर प्रशाली सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है जो सार्वजनिक चेत्र में पूँजी लगाने के लिए साधन बढ़ाये श्रीर जिससे निजी चेत्र में लगाने के लिए यथा-सम्भव छोटी से छोटी व्यावहारिक पूँजी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इस कर-प्रशाली के श्रन्तर्गत सभी वर्गों के उपभोग पर यथासम्भव श्रधिक से श्रियक प्रतिबन्ध लगे। लेकिन श्रन्तर श्राय वाले वर्गों की श्रपेका लम्बी श्राय वाले वर्गों के उपभोग पर श्रियक प्रतिबन्ध लगे।

श्रायोग ने यह मत प्रकट किया कि (क) उपमोग के स्तरी की वर्तमान विपमता का श्रीमकों की मारी छंख्या पर दुरा श्रवर पढ़ता है, श्रीर (ख) श्रिषक कर भार के फलस्वरूप लम्बी श्राय वाले वर्गों के काम करने के उत्लाह में इतना प्रश्विल प्रभाव नहीं पढ़ेगा जितना प्रायः छमका जाता है। इसिल्प श्रायोग ने सुकाब दिया कि व्यक्तिगत वास्तिविक श्रायों की सीमा बाँघ दो जाय जो कर देने के बाद देश के प्रति परिवार की वर्तमान श्रीयत श्राय में लगभग ३० सुने से श्रिषक न हों। यह एक निश्चित काल में धारे-धारे किया जाय। फेवल करों में परिवर्तन करने से यह सम्भव नहीं हो सकता, इसके लिये श्रीक वातो को स्थान में रख कर छंयुक्त रूप से कार्रवाई करनी पढ़ेगी।

श्रीतिश्त राजस्व की प्राप्त निम्नलिखित उपायों से हो सकती है—:
(१) श्रांशिक रूप से निगम कर (Corporation tax) की घटा कर
श्रीर यचत करने तथा पूँजी लगाने के लिए प्रोत्सहन देने के लिए कुछ श्रीर
खूट देते हुए श्राय-कर बढ़ाया जाय, (२) केन्द्रीय उत्पादन कर में काफी वृद्ध की
लाय; (३) उचित मूल्य-नीतियों के द्वारा गैर-कर वाले राजस्व को बढ़ाया लाय
(व्यापारिक सेवार्थों से प्राप्त गैर-कर वाले राजस्व में वृद्धि कर के); (४) कृषि-ग्राय-कर की दरों को बढ़ाया जाय तथा इसका चेत्र विस्तृत किया जाय; (५) भूमि के
लगान पर पोड़ा श्रीर कर लगाया जाय; (६) सम्पत्ति कर का श्रीर श्रिष्ठिक विस्तृत
उपयोग किया जाय; (७) स्थानीय निगमों द्वारा सम्पत्ति इस्तान्तरण किये जाने पर
कर लगाया जाय; श्रीर (८) विकी कर की दरें बढ़ावी जायें तथा उनके श्रन्तर्गत
श्रम्य वस्तुएँ भी सम्मिलित की जायें।

वस्तु कर के बढ़ते हुए चेत्र को देखकर और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वीच सहयोग तथा सामझस्य की आवश्यकता का अनुमव करके आयोग ने सिफा-

रिश की कि राज्यों में श्रापस में श्रीर केन्द्र तथा राज्यों के बीच कर-नीति, कानून निर्माण तथा प्रशासन में सामझस्य लाने के लिए संविधान के श्रनुच्छेद २६३ के श्रनुसार एक श्रालित भारतीय कर-परिषद (All India Taxation Council) का निर्माण किया जाय।

फेन्द्रीय कर-जहाँ तक श्रायकर का संबंध है, कर दाताश्रो की संख्या श्राय कर श्रीर सुनरटैवस के निम्न स्तर पर ही कन्द्रित है। इसीलिए श्रायोग ने यह सुमाव दिया कि कर भार में श्रीर श्रविक समान श्रन्तर रखने के लिए श्रायकर श्रीर सुपरटैक्स दोनो की दरी में श्रीर श्रीषक संख्या में सोहियाँ बनाई जायँ। चॅकि श्रायोग ने श्रमत्यत् करों को बढ़ाने का सुमाव रखा था इस लिए उसने श्रल्पतम श्राय वाले वर्गी पर प्रत्यज्ञ कर का भार ज्यादा बढ़ाने का समर्थन नहीं किया, केवल उसने खूट की सीमा घटा कर ३,००० दवये कर दं।। श्रायोग ने मध्यम तथा ऊँची श्राय वाले वर्गों पर कर की दर बढ़ाने की विकारिश की वसते १ई लाख क्पये से अधिक आप पर कर का अधिकतम दर १३६ श्राने प्रति क्षये को दर से श्रधिक नहीं रहे श्रर्थात् १६ लाख वपये का आय के ऊपर 🖘 प्रतिशत तक की कर-दर रहे । आयोग ने यह भा । सकारिश की कि तीन साल के श्रन्दर परिवार छट देने की एक उचित प्रणाली लागू की जाय जिससे छूट की बतमान सीमा विवाहित व्यक्तियों के लिए १,५०० रपये से २,००० स्थये श्रीर श्रविवादित न्यक्तियों के लिए १,००० स्पये कर दो जाय। परिवार-छूट लागू करने के बाद पति तथा पत्नी अथवा छारे परि-बार की आय की मिलाकर आय कर लगाया जाय। अर्जित आय छूट बनाये रखी जाय लेकिन यह एक निश्चित सीमा के (उदाहरण स्वरूप २४,००० रुपये) नीचे दी जाय। बीमा प्रोमियम की श्रदायगों के लिए कटौती करने तथा प्रावि-डेन्ट फन्ड के लिए श्रंश दान देने की वर्तमान प्रणाली सफल सिद हुई है श्रीर बास्तव में यह व्यक्तिगत बचत की प्रीत्माहन देने के लिए श्रात्यनत उपयुक्त तरीकों में से है। इसको कुल श्राय के 🖟 हिस्से से बढ़ा कर 🐍 हिस्सा कर देना चाहिए लेकिन श्रविभक्त हिन्दू परिवारों के लिए उच्चतम सीमा १६,००० क्वये श्रीर दूसरों के लिए ८,००० कार्ये रखी जानी चाहिए। श्रायीम ने एक श्रानीखा सुमात दिया है कि लम्बी श्राय वाले वर्गों में २५,००० रुपये सं ऊपर व्यय की जाने वाली (disposable) आय को कम करने के लिए आर्त-रिक्त ग्रुल्क (surcharge) तथा श्रनिवार्य रूप से जमा करने की योजना लागू की जाय। इस योजना में उल्लेखनीय बात यह है कि २५,००० रुपये से उत्पर की सभी श्रायों पर क्रमिक दरों से श्रतिरिक्त शलक लगाया जाय श्रीर इसके बदले

कर-दाता सरकार से उतनी ही रकम का एक दीर्घकालीन ऋगा (मान लीजिये ४५ वर्ष के लिए) नाम मात्र की ज्याज दर पर ले सकता है।

श्रायोग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि वोनस शैयर को श्राय का ही श्रंश समका जाय श्रीर इस पर कर लगाया जाय श्रीर श्रयर इस पर कर न लगाया जाय श्रीर श्रयर की हानि होगी | श्रायोग के मतानुसार "श्रायकर के सिलसिले में बोनस शेयर का श्रय कदापि श्राय नहीं हो सकता" | लेकिन श्रायोग ने वोनस हुंहियों (debentures) को श्राय की परिभापा के श्रय्तर्गत रखा है श्रीर उनको कर लगाने के योग्य माना है । श्रायोग ने देखा कि निगम कर (Corporation tax) के मामले में छोटी भारतीय कम्पनियों को जिन्हें वर्तमान कर-छूट मिली हुई है वह उचित है श्रीर उसको खंड-श्राधार पर सभी कम्पनियों के लिए लागू किया जाना चाहिए । श्राय के प्रथम खंड पर (मान लीजिए कुल श्राय के पहले २५००० रूपयों पर) श्रल्य दर पर कर लगाया जाय श्रीर यह श्रव्य दर गैर भारतीय पन्लिक कम्पनियों पर भी लागू की जाय ।

श्रायोग ने श्राय छिपाकर कर टालने की महत्वपूर्ण समस्या पर भी विचार किया। उसने सुमान दिया कि (क) इस न्यापक चोरी के विचद्व जनमत उमाना जाय श्रीर यह सममाया जाय कि कर टालने से ईमानदार करदाता पर बोम बढ़ता है, (ख) 'निरोप चेन्न' (special circle) का श्रीर विस्तार किया जाय जिससे श्रायकर श्रायुक्तों (Income tax commissioners) के सामने पस्तुत श्रिषक किन मामलों को निशिष्ट श्रमसर सफलता पूर्वक निपटा सकें, (ग) जुर्माने की रकम बढ़ाकर टाले गये कर की रकम की तिग्रुनी कर दी जाय; (घ) मत्येक करदाता के लिए यह श्रमिनार्थ कर दिया जाय कि वह इर तीसरे वर्ष श्रपनी 'वास्तविक श्राय' (net worth) श्रयांत् श्रपने देने-पानने का खाता पेश करें, श्रीर (च) श्रायकर खोज श्रायोग (Income-tax Investigation Commission) जैसा विभागेतर संगठन, जिसको मामलों की जाँच करने तथा तय करने के विशेष श्रिषकार प्राप्त हों श्रीर जिसका श्रध्यन्न उच्च न्यायालय (High Court) का न्यायाघीरा हो, कर टालने के बड़े मामलों पर विचार करने के लिए नियुक्त किया जाय।

सम्पदा कर (Estate duty) के सिलिंग में श्रायोग ने सिकारिश की कि यदापि श्रमी उपहार-कर (gift tax) लगाना ठीक नहीं, लेकिन मृत्यु से पूर्व की श्रविम, जिसमें उपहार पर सम्पत्ति-कर लग जाता है दो वर्ष से बहाकर पाँच वर्ष कर दी जानी चाहिए, और सरकार को छूट की वर्तमान सीमा को घटाने का स्थान रखना चाहिए।

श्रायोग ने यह स्वीकार किया कि श्रायात-करों को घटाना श्रानिवार्य है श्रीर उसने सुकाव दिया कि जैसे की निर्यात का चेत्र विस्तृत होगा श्रीर श्राधिक निर्यात कर लगाने का श्रवसर मिलेगा यह कर दिया जायगा। उसने यह भी सिफारिश की कि निर्यातकर श्रीर निर्यात निर्यंत्रण का मिलाकर श्राय श्रीर श्रावश्यक वस्तुश्रों की कीमतों को स्थिर करने में उपयोग किया जाय श्रीर भारतीय उद्योग को संरक्षण दिया जाय।

श्रायोग ने श्रांतिरिक्त राजस्व के लिए खास तीर पर उत्पादन करों पर जोर दिया। उसने तम्बाक तथा तम्बाक से निर्मित बस्तुष्री, स्ती कपड़ा, चीनी, दियासलाई, मिट्टी का तेल, चाय, ऊनी कपड़ा, बिजली के लैंग्प, कागन, बिस्कट तथा 'एइ रेटेड बाटर' ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुत्रों की एक विशाल संख्या पर उत्पादन कर लगाने अथवा उन पर लगे वर्तमान कर को बढाने की चिफारिश की। उसने कहा कि (१) सभी प्रकार के कपड़ों पर लगे उत्पादन कर में इसकी बद्धि की जाय, (२) दियासलाई के उत्पादन कर की बढाया जाय लेकिन दियासलाई। के छोटे कारखानों पर कम दर लगायी जाय, श्रीर (३) १०-१५ रुपये प्रति हजार वाले चिंगरेटों पर लगे श्रातिरिक्त कर (Surcharge) को खत्म किया जाय और इससे होने वाले नुकसान को ४०-५० रुपये प्रति हजार वाले सिगरेटों के कर की दर बढ़ा कर पूरी की जाय। उसने यह भी सिफारिश की कि चीनी, मिट्टी के तेल, खुली तथा बन्द चाय के वर्तभान उत्पादन कर बढायें जायें श्रीर कनी कपड़े, बिजली के लैग्प, 'ड्राई' तथा 'स्टोरेज' बैटरी, कागज (हाथ से बने कागज को छोड़कर), िखलाई की मशीन, रंग तथा वार्निश, बिस्कुट, चीनी मिट्टी के वर्तनों, कांच तथा कांच की वस्तुश्रों, 'एरेटेड वाटर' श्रौर वनस्पति तैल (पानियों को छोड़ कर) .पर नये उत्पादन कर लगाये जायें। श्रतुमान है कि नये उत्पादन कर लगाने तथा वर्तमान कर बढ़ाने से केन्द्रीय उत्पादन करों से राजस्व में ४०-४५ मतिशत की वृद्धि हो जायगी।

श्रायोग ने सिफारिश की कि कुछ श्रायों पर, जैसे पहों के प्रीमियम, पेटेन्ट राइट तथा 'कोपी राइट' की बिकी से हुई श्रामदनी, मेंनेजिंग एजें शे खत्म करने से मिले मुश्राविजे श्रीर नौकरी जाने पर मिले मुश्राविजे पर कर लगना चाहिए। यद्यपि श्राकस्मिक तथा श्रनावर्तक श्रायों की वतंमान छूट में इस्तच्चेप करना टीक नहीं लेकिन कुछ प्रकार की श्राकस्मिक श्रायों जैसे, शब्द पहेली (Crossword puzzle) से हुई श्रामदनी पर श्रलग से कर लगना चाहिए। श्रगर मालिक किसी कर्मचारी को कोई सुविधाएँ देता है, श्रीर श्रंगर वह न देता तो उनके लिये खर्च कर्मचारी को करना पड़ता तो उन सुविधाओं के मूल्य पर कर्मचारी से कर वस्ता होना

चाहिए परन्तु अगरम्म में यह कर उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित रखा जाय जिनकी क्रल वार्षिक ग्राय २४,००० रुपये से ज्यादा है या जो कम्पनी के डायरेक्टर है। डायरेक्टरों के सम्बन्ध में वार्षिक श्राय की शर्त नहीं। कम्पनी के सिलिसिले में आयोग ने सिफारिश की कि नुकसान को सिर्फ ६ वर्ष की श्रविध के बनाय, जैसा कि इस समय है, अनिश्चित काल के लिए आगे लाने दिया जाय और ऐसे नुक-सान की पृतिं उसी कारोबार की आय से करने के बसाय, जैसा कि इस समय है, दृसरे कारोबार की ग्राय से भी करने की इवानत रहे। ऐसे नुकसान को पूर्ति एक साल के लिए गैर कारोबारी श्राय से भी करने दी जाय श्रीर करदाता की शक्ति के बाहर की परित्यितियों में कारोबार वन्द होने पर ही नुकसान की छूट दी जाय। श्रायांग ने दोनों सेद्वान्तिक तथा व्यावदारिक श्राधार पर ट्रट-फूट की छूट देने के लिए ग्रचल पूँजी के लगावार पुनः मूल्यांकन के सिद्दान्त को स्वीकार नहीं किया। भारत में मशीनों की कीमतें इतनी नहीं वहीं कि कारीवार की इकाइयों का मूल्योंकन टीक समक्ता बाय लेकिन पुरानी मशीनों के मुकाबलें उनकी जगह में नयी मशीनों को लगाने का खर्च काफी वहा है। इसको ध्यान में रख कर स्रायोग ने तिकारिश की कि उन उद्योगों के लिए जिनको विकास-छूट (Rebate) नहीं मिलती उनके लिए क्रमशः १६४६ श्रीर १६४६ में निश्चित प्रारम्भिक श्रीर श्रविरिक्त विधाई छूट पाँच छाल श्रीर रहने दी जाय। प्रारम्भिक विधाई छूट मशीनों के लिए मूल लागत के २० प्रतिशत से बढ़ाकर २५ प्रतिशत कर दिया जाय श्रीर मशीनों के मूल्य में कभी निश्चित करने में इसका ध्यान रखा जाय।

राज्य कर—राज्यों के करों के चेत्र में आयोग ने विक्री कर पर विशेष ध्यान दिया और कुछ महत्वपूर्ण िक्फारिशें कीं, जैसे (क) विक्री कर का तेवाओं ठक वित्तार करने से गम्मीर प्रशासन-किताइयाँ पैदा होगी और इस्तिए यह ठीक नहीं; (ख) वायदे के सीदों पर विक्री कर की अपेक्षा स्टाम्प शुल्क (Stamp duty) के निरंपे ज्यादा अच्छी तरह से कर लगाया जा सकता है; (ग) अखवारों पर विक्री कर लगाना वेकार है; (घ) प्रथम चरण एक-विन्दु विक्री कर (First stage single point sales tax) सामान्य रूप से विक्री कर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है यद्यपि इसका सीमित प्रयोग हो सकता है; (च) सभी राज्यों में छोटी दर के वहु-विन्दु कर (Multi-point sales tax) से 'हसाय-किताय में आसाना हो जायगी लेकिन छोटी दर से राज्यों को उतनी आय नहीं मिलेगी जितनी उन्हें इस समय मिलता है; (छ) विक्री कर के बजाय कय कर माटर कार तथा ऐसी ही कुछ अन्य चीजों पर जिनका पता फीरन लग सकता है लगाना ज्यावहारिक है परन्तु इसके सीमित प्रयोगसे बहुत ही कम आय होगो।

श्रायोग के श्रनुसार राजस्व के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विक्री कर को विशेषता इस तथ्य में है कि वस्तुओं और विकेताओं की एक मारी संख्या पर यह लाग है और इसीलिए छोटी दर पर भी काफी आय वसूल करना सम्भव है। ऐसी हिंपति में, जैसा कि कुछ का कहना है, इसकी जगह में उत्पादन कर, श्रायात कर (Customs) तथा चॅगी (Octroi) के समितित रूप को श्रासानी तथा सफलतापूर्वक नहीं लागू किया जा सकता । श्रायोग ने यह भी पसन्द नहीं किया कि विक्री कर केन्द्रीय राजस्व की मेढ बना दो जाय श्रयवा राज्यों के लिए इसकी वस्ती केन्द्रीय सरकार करे। बिक्री कर मुख्यतः राज्य-कर ही बना रहे। लेकिन आयोग ने सिफारिश की कि जब एक राज्य में बिक्री कर की विक्रेताओं पर लागू करने श्रीर उपमोक्ताश्रों से बस्ल करने का मार दूसरे राज्य पर पड़े तो वहाँ राज्य की जिम्मेदारी तथा श्रधिकार खत्म सममा जाय श्रीर केन्द्र की जिम्मे-दारी तथा ऋधिकार समका जाय | इस प्रकार ऋायोग इस परिसाम पर पहुँचा कि श्रन्तर-राज्य विक्री-कर की जिम्मेदारी केन्द्र पर रहे लेकिन केन्द्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखे कि वह अन्तर-राज्य ज्यापार श्रीर उसमें मुख्य रूप से चलने वाते निर्धारित कब्वे माल की बिकी पर विकी कर लगाने में इस तरह अपने अधिकार का प्रयोग करे कि दोहरा कर न लगने पाये और कर लगाने वाली दो सरकारों के बीच उचित सामझस्य रहे । श्रायोग ने सिफारिश की कि संविधान में संशाधन किया जाय श्रीर कोयला, लोहा, इस्पात, रूई, चमड़ा श्रीर खालें श्रन्तर-राज्य न्यापार में विशेष महत्व की वस्तुएँ निर्धारित की जायँ श्रीर इनके लिए किसी राज्य में एक-बिन्द्र बिक्री कर के अतिरिक्त दूसरी कोई प्रणाली न रहे।

राज्यों की मानी विक्री-कर प्रणाली के नारे में श्रायोग ने िक्फारिश की कि इस कर की एक उपयुक्त मात्रा की (श्रनुचित रूप से बोक्त के रूप में नहीं) श्रल्प श्राय नाले नगों तक पहुँचना चाहिए श्रीर इसके श्रन्तर्गत बहुत से लोगों को श्राना चाहिए। इसको संमन करने के लिए कर की दर नीची रखी जाय श्रीर बहु-बिन्द (multi-point) कर हो। मध्यम तथा लम्बी श्राय नाले नगों श्रीर लम्बी श्राय नाले विक्रेताश्रों के लिए एक-बिन्दु (Single-point) कर के साथ-साथ बहु बिन्दु (Multi-point) कर भी रहे। ५,००० रुपये सालाना से ज्यादा श्राय नाले सभी विक्रेताश्रों को श्रायोग द्वारा प्रस्तानित संयुक्त प्रणाली के श्रन्तर्गत बहु विन्दु कर देना पड़ेगा परन्तु कर की दर है प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। एक बिन्दु कर प्रणालों के श्रन्तर्गत श्राय सीमा श्रपेद्वाकृत ऊँची होगी जैसे ३०,००० रुपये प्रति वर्ष। एक विन्दु कर की ऊँची दर गरीज नगों के जीवन नहनं के लिए श्रावर्थक वर्ष्युशों को छोड़ कर नाकी सज पर लगेगी। यह जरूरी नहीं कि सभी तरह

की चीजों पर एक सी दर से कर लगाया नाय। विलास (luxurye) की कुछ चीजों पर ऊँची दर पर कर लगाना पड़ेगा। विकी कर के इस लचीलें ढांचे को अपनाने का अर्थ होगा कि हर राज्य को अधिक आय देने वाली और साथ ही साथ एक आसान और अधिक वैज्ञानिक प्रशाली मिल जायगी।

मोटर गाड़ियों श्रीर मोटर स्थिट पर कर लगाने के संबंध में श्रायोग ने कहा कि मोटर गड़ियों पर लगी चुँगी (octroi) श्रीर कर के बीच संबंध नहीं है क्यों कि पहली माल पर लगती है श्रीर दूसरी गाड़ियों पर । नगरपालिकाएँ जो गाड़ी-कर लगाती हैं वह राज्य सरकार द्वारा मोटर गाड़ियों पर लगाये गये कर में प्रत्युत वृद्धि है। ऐसी बात चुंगी श्रीर सीमा कर के साथ नहीं। ऐसी हालत में ठीक यह होगा कि नगर पालिकायें (नगर निगम नहीं) गाड़ी-कर को खत्म करके दोनों करों को एक कर दें श्रीर मोटर गाड़ी कर को बढ़ा दिया जाय श्रीर श्राय का एक श्रंश सम्बन्धित नगर-पालिकाश्रों को दे दिया जाय।

स्टाम्प शुल्क के बारे में श्रायोग ने राय दी कि श्रन्तर-राज्य सौदों से सम्बद्ध कागज-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की एक सी दरें रखना न तो श्रावश्यक ही है श्रीर न बान्छनीय। वैंकिंग के विकास के लिए जो मारत में श्रमी श्रपनी शैशवा-वस्था में है, श्रायोग ने सिफारिश की कि चेंकों पर स्टाम्प शुल्क न लगाया जाय। कोर्ट फीस (court fees) के सम्बन्ध में श्रायोग ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि प्रशासन के खचों को पूरा करने के श्राधार पर इसकी दरें निर्धारत की जायँ।

राज्य कर के रूप में तथा किसान पर बोक्त के रूप में भूमि-कर से प्राप्त श्राय (Land Revenue) के महत्व में परिवर्तन हुआ है। इस सिलिस्लि में आशोग नं सिकारिश की कि आयकर की तुलना में स्वामित्व की शतों, प्रारम्भिक राजस्व निर्धारण के तरीके, राजस्व के संशोधन के तरीके और भू-राजस्व के स्थान पर ऐसी अधिक बुनियादी वार्तों में अल्पतम एकरूपता लाने का लक्ष्य जरूरी और उपयुक्त है। आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि एक बार राजस्व-स्तर का मापद्र एस्थापित हो जाने पर मूल्य के स्तर के परिवर्तन को ध्यान में रख कर हर दस वर्ष के बाद भू-राजस्व में संशोधन होना चाहिए लेकिन मूल्य में २५ प्रतिशत की घटनढ़ पर राजस्व में संशोधन की जरूरत नहीं। लम्बी कृषि-आयों पर सभी राज्यों को कृषि आय कर लगाना चाहिए और ३००० रुपये सालाना से अधिक की सभी कृषि आयं पर कृषि आयकर लगना चाहिए। अन्तिम लक्ष्य कृषि आय को मिला कर पूरे पर आय कर लगाना होना चाहिए। मनोरंजन (entertainment) कर के विषय में आयोग ने सिकारिश की कि

वर्तमान खड-दरों के स्थान पर प्रतिशत दरें लागू की जायँ। पुरस्कार प्रतियोगिता तथा लाटरी पर कर लगाने का कार्य केन्द्रीय सरकार को लेना चाहिए। खिंचाई श्रीर विकास करों के सम्बन्ध में श्रायोग ने यह कहा कि श्रिष्टिकतम कर खिंचाई के फलस्वरूप भूमि की बढ़ी हुई कीमत के ५० प्रतिशत से स्थादा नहीं होना चाहिए श्रीर इसकी वस्ली एक उचित दीर्घकालीन श्रवधि में होनी चाहिए।

स्यानीय फर--श्रायांग ने देखा कि स्थानीय संस्थाश्रों की श्राय उनकी श्रावश्यकताश्रों के लिए बिल्कल श्रपयाम है। स्थानीय संस्थाश्रों की जिम्मेदारियाँ बढ़ने के साथ-साथ इनकी आय में वृद्धि नहीं हुई । स्थानीय संस्थाओं को आपनी जिम्मे-दारियों को संतोपननक रूप से निभाने में समर्थ बनाने के लिए जरूरी है कि उनकी श्राय के साधन बढाये जायें। लेकिन श्रायोग ने इस बात को पसन्द नहीं किया कि संविधान में संशोधन करके कुछ कर स्थानीय संस्थाओं के लिए सुरक्तित कर दिये जायँ। श्रब्छ। तो यह होगा कि ऐसी परम्परा वन जाय जिससे भूमि तथा इमारत पर कर, चुँगी, मशीन-चालित छोड़कर अन्य गाड़ियों का कर, पशु तथा नाव कर, पेशा, व्यापार तथा रोजगार कर तथा श्रखवारों में प्रकाशित विशापनों को छोड़कर श्रन्य विज्ञापनों का कर सिर्फ स्थानीय संस्थाश्रो के उपयोग के लिए रहें। इन के अलावा थियेटर कर, सम्पत्ति इन्तान्तरण कर श्रीर सहकों अथवा श्रान्तरिक जल-मार्गो पर चलने वाले माल तथा मुखाफिरों पर कर स्थानीय संस्थाश्रों के लिए निश्चित कर दिये जायँ। श्रायोग ने स्थानीय संस्थास्त्रों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए करों का भाग देने के बजाय अनुदान-महायता देने के तरीके की पछन्द किया है और इसके लिए कुछ िखानत सुकाए हैं। लेकिन उसने जिलारिश की है कि जहाँ तक मोटर गाड़ी कर तथा भू-राजस्य का संबंध है इनका बँटवारा गुज्य सरकारी श्रीर स्थानीय संस्थात्रों के बीच किया जाय !

व्यालोचना

स्रायोग की सिकारिशों में देश के स्रार्थिक विकास के लिए राजस्व बढ़ाने की स्रावश्यकता का प्रमान पड़ा है। भारत की विशाल स्त्रीद्योगिक तथा कृषि विकास सम्भावनास्त्रों के होते हुए भी यह स्त्रव मी स्त्रार्थिक हिंछ से एक पिछड़ा हुस्रा देश है। विकास कार्य में तेजी लाने श्रीर देश को समृद्ध बनाने के लिए भारी पैमाने पर पूँजी लगाने की जरूरत है श्रीर इसके एक स्रंश की पूर्ति स्त्रनिवार्य रूप से सरकारी स्त्राय से होनी चाहिए। स्त्रायोग ने सिकारिश की कि सभी दिशास्त्रों में कर वृद्धि की जाय जिससे केन्द्र तथा राज्य सरकारों को ज्यादा स्त्राय हो सके। स्त्राशा है कि यदि स्त्रायोग की बड़ी-बड़ी सिकारिशों को लागू कर दिया जाय तो भारत में विभिन्न सरकारों की कुल आय तुरन्त १ ग्रारव रुपये से लेकर १६ श्ररव हो नायगी श्रीर बाद में चल कर काफी बढ़ जायगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जितनी जल्द हो सके देश के आर्थिक साधनों का विकास होना चाहिए, लेकिन हमारी ऐसी पिछड़ी अर्थ व्यवस्था में एक बड़े अन्याय, असहनीय कठिनाइयों और व्यापक प्रतिकृत परिस्थितियाँ पैदा करने का खतरा उठाये बगैर विकास व्यय के लिए श्रविरिक्त कर लगा कर सामन एकत्र करने के लिए एक निश्चित सीमा को पार नहीं किया जा सकता। कर देने की ज्ञमता ऐसी ही एक चीज है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि अपनी सिकारिशें प्रस्तत करने में आयोग ने भारत की जनता की कर देने की ज्ञमता पर उचित ध्यान नहीं दिया। श्रायोग ने कर देने की समता की सही परिभाषा दी जब उसने यह कहा कि "कर देने की ज्ञमता न्याय 'equity) की तरह सापेज्ञिक सिद्धान्त है। श्रास्यन्त महत्वपूर्ण श्रार्थिक हिन्द से समाज के विभिन्न वर्गी का कर देने की ज्ञमता का संबंध कर की उस सीमा से है जिसके बाहर उत्पादक प्रयास श्रीर ज्मता दोनों को हानि होने लगती है।" लेकिन कर देने की ज्मता की चही परिभाषा देने के बाद शायोग विचलित हो गया श्रीर उसने कहा कि (क) दिक्तिग-पूर्व पशिया तथा श्रन्य विदेशों में मारत की श्रपेह्ना कर-श्राय का राष्ट्रीय अवय से अनुपात ज्यादा है, और (ख) इघर कुछ वधों से भारत में लोगों की कर देने की समता वड़ी है क्योंकि "यह कहना गलत न होगा कि कर देने की चमता श्रर्थ-जाभ-हीन तथा श्रलोक-प्रिय नीतियों श्रीर श्ररफल प्रसाशन से घटती है श्रौर कल्याग्यकारी तथा सुयोग्य प्रशासन से बढ़ती है। मारत में सरकारी व्यय करपा एकारी ज्यय की श्रोर तेजी से बढ़ रहा है लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह किफायतशारी और दत्तता की ख्रोर भी वढ़ रहा है। फिर मी मारत के सरकारी न्यय में सामाजिक तथा विकास सेवाओं को ज्यादा स्थान मिल रहा है जिससे कर देने की ज्ञमता की सीमा बढ़ रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार की जिम्मेदारी को श्रपनी जिम्मेदारी सममने की मावना का जन्म इसका दुसरा कारण है"।

दूसरे देशों का उदाहरण देना वेकार है। उन देशों में कुल सरकारी राजस्य राष्ट्रीय आय का एक बहुत वहा अंश होता है क्यों कि वहाँ कर देने की चमता ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आयोग का मत है, कर देने की चमता सोचने और इच्छा करने की चीज नहीं है। जहाँ तक कल्या- एकारी ज्यय का प्रश्न है, हमारे देश में सम्पत्ति के गलत वितरण के फल-स्वरूप, देश के जनता की कर देने की चमता नहीं बढ़ी। जहाँ तक जनता के

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सवाल है. उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं। श्रायोग ने इस परिणाम पर पहुँचने के लिए, कि कुछ, वधों में जनता की कर देने की ज्ञमता बढ़ी है, बहुत ही श्रानोखा तर्क दिया है। श्रायोग के ध्यान में मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ रही होंगी जब उसने जनता की कर देने के ज्ञमता की वृद्धि की बात कहीं क्योंकि जहाँ तक ठोस परिस्थितियों (physical conditions) का सवाल है भारत की जनता की कर देने की ज्ञमता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई।

''अधिक विकसित पश्चिमी देशों में प्रति व्यक्ति आय जनता की न्यन-तम आवश्यकताओं से ज्यादा है और बहुसंख्यक लोगों की आय श्रीसत प्रतिव्यक्ति श्राय से कहीं ज्यादा है। श्रीर इसी ग्राधार पर पूर्ण विकसित श्रर्थ ज्यवस्था में कर देने की अधिकतम ज्ञमता राष्ट्रीय आय की २५ प्रतिशत निकाली गयी है। इसी ब्राघार पर ब्रिधिक विकसित पश्चिमी देशो में मारत की उपेजा सरकारी राजस्व विना कोई प्रतिकृत श्रमर डाले राष्ट्रीय श्राय का एक बहुत बड़ा श्रंश है। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय के १६५०-५१ में १,११० करोड़ रुपये से १६५५-पूह में १०,८०० करोड़ रुपये हो जाने तथा १९६०-६१ (समी १९५२-५३ की कीमतों के श्राघार पर) में १३,४३० करोड़ रुपये हो जाने के श्रनुमान पर श्राधारित प्रति न्याक्त स्त्राय १६५०-५१ में २२५ काये से बढकर १६५५-५६ में २८० रुपये श्रीर १६६०-६१ में ३३० रुपये होगी। इसके श्रलावा भारत में श्रधिकांश लोगों की आय प्रति व्यक्ति ऋौसत आय से कम है और देवल थोड़े से ही लोगों की आय श्रीसत प्रति व्यक्ति श्राय से श्रिधिक है। इस प्रकार श्रिधिकांश लोगों में कर देने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। केवल दूसरे किस्म के लोगों में कर देने की समता है लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि श्रगर उनकी पूरी श्राय जन्त कर ली जाय तो भी राष्ट्रीय आय से सरकारी कर का अनुपात पश्चिमी देशों के स्तर तक नहीं पहुँचेगा"। इसीलिए इम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अगर अधिकांश कर जिनकी विफारिश कर जाँच श्रायोग ने की है लागू कर दिये जाते हैं तो भार भारतीय जनता की कर देने की ज्ञमता से कहीं ज्यादा बढ़ जायगा और उस को श्रमह्नीय श्रौर श्रन्यायपूर्णं कठिनाई फेलनी पड़ेगी।

श्रतिरिक्त पूँ जी संग्रह करने के लिए सभी वर्गों के उपभोग पर श्रविक से श्रिषक नियंत्रण लगाने की सिकारिश करने में आयोग प्राचीन (Classical) श्रार्थिक चिद्धान्त से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है जिसका परित्याग बहुत पहले

१. २५ फरवरी १६५६ के 'कामसं' (Commerce) के प्रष्ट १६७ पर लेखक का निवन्घ देखिये।

हो किया जा चुका है। मार्शन (Marshall) तथा पीगू (Pigou) आदि विचारकों ने बचत श्रीर पूँची लगाने की समस्याश्रों पर विचार करते हुए पूर्ण रोजगार की स्थित को श्राधार बनाया था। यह मान कर चलने से यह सीचना वरूरी हो गया कि धन बचाने के लिए लोग श्रपने उपभीग में कमी करें ख्रीर इस प्रकार पूँ जी लगाने के लिए साधन सुलम् करें। ऐसी स्थिति में जब सुलभ साधनों से जो पूर्ण रूप से सिक्षय हैं उपभोग श्रीर विनियोग (investment) के बीच चुनाव करना है, पूँजी बढ़ाने के लिए उपभोग में कमी करना जरूरी है। लेकिन जैसा कि केन्सियन (Keynesian) सिद्धान्त जोर देता है श्रमर पूरी सिक-यता नहीं है थ्रीर सामन निष्क्रिय तथा वेकार हैं तो श्रतिरिक्त उपभोग तथा त्रातिरिक्त विनियोग दोन। साथ-साथ चल सकते हैं। केन्सियन सिदान्त की यही सीख है। कर जाँच श्रायोग ने इस पर विचार नहीं किया श्रीर इस प्रकार उसने भारी भूल की। यह पूछा जा सकता है कि श्रागर लोग श्रापने उपभोग में कभी कर के घन नहीं बचाते तो श्रार्थिक विकास के लिए श्रावश्यक धन कहाँ से श्रायेगा। केन्सियन सिद्धान्त ने दिखाया है कि 'निर्मित' धन से किया गया कोई भी विनियोग (investment) गुणक के सिद्धान्त पर जल्द ही आय का भाग बन जाता है श्रीर इससे जनता को श्रपनी श्राय में से उपभोग-स्तर को कम किये वरीर अपने आप वचत में और वृद्धि होती है। यह तर्क देना गलत है कि फेन्सियन **चिद्धान्त भारत तथा दूसरी पिछ्न**ी श्रयं व्यवस्थाश्रों में लागू नहीं होता श्रीर इसलिए इमें अब भी शास्त्रीय आर्थिक सिद्धान्त के आधार पर सोचना पड़ेगा। इससे ज्यादा निरर्थक बात श्रीर कोई नहीं हो छकती। कुछ खास कारण से भारत में केन्छियन प्रणाली के कार्यान्वयन की गति मन्द हो सकती है लेकिन इसकी यहाँ उसी प्रकार लागू किया जा सकता है जिस प्रकार विश्व के दूसरे देशों में। एक श्रीर महत्वपूर्ण बात है जिसकी कर जाँच श्रायोग ने पूरी उपेचा कर दी है। पूँजी लगनं से उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए श्रीर इसकी बनाये रखने के लिए श्रीर उत्पादन की सम्भव करने के लिए यह जरूरी है कि जो उत्पादन हो वह विके भी। लेकिन श्रगर उपमोग कम करने के सम्बन्ध में श्रायोग की सिफारिश मान ली जाय तो यह असम्भव हो जायगा और उपभोग कम करके विकास में पूँजी लगान सं स्वय विकास को जाति पहुँचेगी।

यद्यिप श्रायोग ने कहा है कि करदाता के प्रयास और उद्यम को नष्ट होने से बचाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए लेकिन मालिक द्वारा कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधा के मूल्य को कर आय के अन्तर्गत शामिल करने, अथवा अनिवार्य रूप से जमा करने के लिए अतिरिक्त कर (surcharge) आदि के सुकार्यों का मुख्य रूप से यही श्रसर पड़ेगा। श्रार्थिक दृष्टि से श्रविकसित तथा विछड़े देश में विना हानिकारक हुए श्रौद्योगिकों (entrepreneurs) पर ऐसे बोक्त नहीं लादे जा सकते।

लेकिन श्रायोग की खिकारिशों में इन दोषों के होते हुए मां उसकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है श्रीर इसमें श्रनेक श्रव्छे सुक्ताव हैं। १६ लाख कपये से उत्तर की श्रायों पर श्रिधिकतम संपूर्ण श्राय कर दर को १३६ श्राना प्रति कपये से जगर की श्रायों पर श्रिधिकतम संपूर्ण श्राय कर दर को १३६ श्राना प्रति कपये से जगदा न करने, भीमा प्रीमियम की कटीती (abatement) श्रीर प्रोविडेन्ट फन्ड के श्रंश-दान की श्रिधिकतम रक्षम श्राय की है से से करने श्रीर कमशः १६९६ तथा १६४६ में निर्घारित प्रारम्भिक तथा श्रितिक विसाई छूट की प्रणाली जारी रखने की जो सिकारिशों श्रायोग ने की हैं उनसे देश में श्रीद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह सुकाव कि नव स्थापित उद्योगों को कुछ परिस्थितियों में 'कर से छुट्टी' दी जाय श्रीर नुकसान को श्रिनिश्चित श्रविध तक श्रागे ले जाने दिया जाय, इसका भी यही परिणाम होगा। कर टालने, विकी कर तथा स्थानीय विच से सम्बन्धित श्रायोग ने जो सिकारिशों की हैं वे रिपोर्ट के महत्वपूर्ण श्रंग हैं। श्रायोग की कुछ विकारिशों को भारत सरकार १६५५-५६ श्रीर १६५६-५७ की बजटों में लागू कर चुकी है।

छाध्याय ४६

कर प्रणाली सुधार पर कान्डॉर रिपोर्ट

प्रोफेसर निकोलस काल्डॉर ने मार्च १६५६ में 'भारतीय कर प्रगाली में सुघार' पर अपनी रिपोर्ट भारतीय सांख्यिकी विद्यापीठ (Indian Statistical Institute) के द्वारा भारत सरकार को दी। प्रोफेसर काल्डॉर को इस विद्यापीट 'ने निमंत्रित किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारतीय कर प्रगाली के सम्बन्ध में कान्तिकारी मुक्ताव दिये हैं। चूँकि भारत सरकार पूँजी लाभ कर (Capital Gains Tax), सम्पदा कर (Wealth Tax), उपहार कर (Gift tax) श्रीर ब्यय कर (Expenditure tax) पहले ही, यद्यपि कुछ ह्यान्तर कर के, लागू कर चुकी है इसलिए काल्डॉर रिपोर्ट को नया महत्व मिल गया है।

काल्डॉर रिपोर्ट में कहा गया है कि "भारत की वर्तमान प्रत्यक्त कर प्रणाली श्रायगंप्त (inefficient) श्रीर श्रायमान (inequitable) दोनों है। यह इसीलिए न्यायसंगत नहीं है क्योंकि कर के वर्तमान श्राधार (श्राय) की कानूनी परिभापा दोष पूर्ण है श्रीर कर लगाने की ज्ञमता का ज्ञेत्र पञ्चपातपूर्ण है श्रीर कर देनं वाले कुछ वर्ग श्रपनी वास्तविक श्राय को घटाकर दिखा सकते हैं। वह इसिलए श्रप्यांत्र है क्योंकि करदाता सीमित विवरण देते हैं श्रीर सम्पत्ति के सीदों तथा सम्पत्ति श्राय जानने के लिए कोई विस्तृत उपाय नहीं है। इसके फलस्वरूप मुनाफे श्रीर सम्पत्ति श्राय को छिपाकर श्रयवा इसका घटा कर दिखाकर इसकर की चोरी में श्रपेचाकृत श्रामानी रहती है"। इस बात को ध्यान में रखकर श्रीर हमारी कर प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए काल्डॉर रिपोर्ट में भारत में सम्पदा पर वार्षिक कर, पूँजी लाभ पर कर, उपहार कर श्रोर व्यक्तिगत व्यय कर लगाने की सिफारिश की गर्या है। श्रान्तिम कर को श्राय के वर्तमान सुपरटैक्स के स्थान में श्रांशिक रूप से लागू करने की सिफारिश की गर्द है।

व्यय कर — व्यय कर करदाता के उपभोग के व्यय पर लगने वाला व्यक्तिगत उपभोग पर कर है। इसमें मालिक की श्रोर से मिलने वाला खर्च भी शामिल है। काल्डॉर रिपोर्ट के श्रनुसार यह कर "प्रति वयस्क (बच्चों को श्राधा वयस्क सममा जाय) १०,०० रुपये वार्षिक से ज्यादा के निजी खर्चे पर प्रति व्यक्ति के श्राधार पर खंड-प्रणाली के श्रनुसार क्रिक रूप में लगाया जाय। १०,००० रुपये श्रीर १२,५०० के बीच २५ प्रतिशत श्रीर ५०,००० रुपये से ऊपर ३०० प्रतिशत वार्षिक प्रति वयस्क रहे।" उदाहरण स्वरूप माता, पिता श्रीर दो बच्चों का एक परिवार है जो सालाना ४०,००० रुपये खर्च करता है। चूँकि परिवार तीन वयस्क हकाइयों का है इसीलिए खर्च प्रति वयस्क १३,३३३ रुपया श्रीय श्रीर कुल कर प्रथम ३,३३३ रुपये कर का तिगुना होगा।

"कर निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत उपमोग का खर्च छाल के ग्रुरू में कर दाता के कुल दायित्व श्रीर छाल भर की छमी श्रायों के योग से वर्ष के श्रन्त के कुल दायित्व को घटाने से बची राशि के बरावर छमका जायगा। दूछरे शब्दों में नाघारण श्राय जैसे उपहार (gift) विकने योग्य छम्पत्ति श्रादि के श्रितिरक्त दूखरी श्रायों से होने वाले खर्चों पर भी कर लगेगा। किसी कार्य में जो पूँजी लगेगी (investment outlay) वह कर-मुक्त रहेगी। इसके श्रितिरक्त कारोवार का वास्तिवक खर्च, एक निश्चित रकम के ऊपर दूखरों को दिया गया उपहार जिसके श्रन्तर्गत दहेज श्रादि मी है, श्रीर उपमोग की कुछ बस्तुर्थ, जिन्हें श्रावश्यक कहा जा सकता है, कर-मुक्त रहेंगे। श्रावश्यक वस्तुश्रों के श्रन्तर्गत एक निश्चित रकम तक श्रन्त्येष्टिकिया तथा जन्म, दवा का खर्च, श्रिकांड, चोरी श्रादि के कारण होने वाला खर्च सम्मिलित है। कर्नीचर, मोटर कार श्रादि ज्यादा दिनों तक चलने वाली उपमोग की वस्तुश्रों का खर्च कर लगाने के लिए कई वर्षों में फैलाया जा सकता है??।

इस कर के समर्थन में कहा गया है कि (१) कर देने की ज्ञमता जानने के लिए आय सही कसीटी नहीं है क्योंकि यद्यपि किसी की आय कम हो सकती है लेकिन वह पुरानी बचत, पूँजी लाम, उत्तराधिकार, उपहार, पुरस्कार, विरासत, आदि के फलस्वरूप अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उपमोग कर सकता है। व्यय-कर व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर पर आधारित है और इस प्रकार उसकी कर देने की ज्ञमता जानने का अधिक उचित साधन है। (२) व्यय कर से बचत पर कर नहीं लगता और इस प्रकार यह वचत को प्रोत्साहन देता है। चूँकि भारत के आर्थिक विकास के लिए अधिक बचत की आवश्यकता है इसलिए यह दितीय योजना के हित में है; और (३) "आगे चल कर आय-कर की कँची दरों के कारणा लोग व्यापक रूप से कर को बचाने लगते हैं जिसका फल यह होता है कि इस कर से आय कम होती है। व्यय कर लगाने और आयकर की कपर की दरों को घटाने से सफलता मिलेगी क्योंकि इससे कर की चोरी हमेंगी और साथ ही चोरी करना अधिक कठिन कार्य सिद्ध होगा।"

सम्पदा कर (Wealth Tax)-"यह किसी व्यक्ति की सम्पदा पर कर:

है श्रीर हर वर्ष उसकी कुल श्रम्मली सम्मित्त के मूल्य पर निर्धारित किया जायगा । यह कर विस्तृत होगा श्रम्मत यह कृषि सम्मित्त, सभी प्रकार की श्रम्मली मिल्कियत, स्टाक तथा शेयर, वाजार में भिक्षी योग्य सभी वस्तुश्रों श्री। वैंक में जमा पूँजी, जनाहरात तथा कीमती वस्तुश्रों श्रादि सभी व्यक्तिगत सम्मित्तियों पर लागू होगा। वैंक में जमाधन तथा घरेलू फर्नीचर श्रीर कपड़े जैसी व्यक्तिगत वस्तुएँ एक सीमा तक कर मुक्त रखी जा सकती हैं।" १,००,००० रुपये से कम की सम्मित्त को कर मुक्त रखने के बाद प्रस्तावित कर की दर्रे निम्नलिखित होंगी।—

सम्पत्ति की कीमत	प्रतिशत द्र
१,००,००० रुपये से नीचे	0
१,००,००० र० श्रीर ४,००,०० र० के बीच	9
४,००,००० र० ग्रीर ७,००,००० र० के वीच	9 9
७,००,००० र० स्रीर १०,००,००० र० के बीच	
१०,००,००० रु० और १५,००,००० रु० के बीच	. 8
१५,००,००० ६पये से ऊपर	2.5

इस कर के पद्म में यह तर्क है कि (१) श्राय कर की श्रपेद्धा इस से किसी की कर देने की द्माता का ज्यादा श्रव्छा पता चलता है क्योंकि किसी व्यक्ति के पास िक श्राय के द्वारा ही नहीं बल्कि समादा के द्वारा भी वस्तुएँ श्रा सकती हैं; (२) "वर्तमान श्रायों की श्रपेद्धा पूँजी स्वामित्व (Capital Ownership) पर श्राधारित कर को प्रशासनात्मक दृष्टिकोण से निर्धारित करने में श्रीर श्राय के निम्नतर खंडों में वसूल करने में श्रीक श्रासानी होगी"; श्रीर (३) एक श्रिषक कीमक श्राय-कर से खतरनाक पूँजी विनियोग (investments) के विरुद्ध पद्ध-पात होता है। "चूँकि श्राय की वृद्धि के साथ श्राय कर की दरों में वृद्धि होती है इसीलिए खतरनाक पूँजी विनियोग के जिर्चे लम्बी श्राय करने की प्रवृत्ति घटती है। दूसरी श्रोर किमक वृद्धि होने के बावजूद सम्पत्ति पर लगा कर इस तरह का श्रसर नहीं डालता। यह सम्पत्ति की कीमत पर लगेगा श्रीर ऐसी सम्पत्ति से होने वाली श्राय से भिल नहीं होगा। इसका भार दोनों सन्देहजनक तथा सुरिद्धित सम्पत्ति पर समान रूप से पड़ेगा।

पूँजी लाभ कर (Capital Gains Tax)—काल्डॉर रिपोर्ट ने िकारिश की कि "सभी पास पूँजी-लामों पर जिन पर इस समय श्राय के श्रर्थ के श्रन्दर न श्राने के कारण श्राय-कर नहीं लगता श्राय-कर लगना चाहिए। इसका श्रर्थ यह हुश्रा कि संयुक्त श्राय (समस्त पूँजी-लामों के सहित) २५,००० स्पये से ज्यादा होने पर मोटी दर से ७ श्राने प्रति स्पया कर लगेगा"।

"कम्पनियों के पूँजी लाभ पर उसी प्रकार कर लगाना चाहिये जिस तरह व्यापारिक सुनाफे पर लगेगा। दूसरे शब्दों में संभी लामदायक श्रायों पर चाहे वे व्यापारिक लाभ, साधारण श्राय, कम्पनी श्राय श्रयना पूँजी-लाभ हों, २५००० रुपये के ऊपर ७ श्राना प्रति रुपये की एक सी दर से कर लगेगा"।

पूँजी लाभ कर के पत्त में यह तर्क उपस्थित किया गया है कि (१) पूँजी लाभ कर से व्यक्ति की कर देने की ज्ञमता बहती है इसलिए कर लगायां जाने वाली आय में इसको सम्मिलित रहना चाहिए; श्रौर (२) "किसी व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर सदा रहते हैं कि वह आपने हिसाब-किताब इस तरह से बनाये कि उसकी सम्पत्ति का लाभ कर लगने वाली आय की जगह पूँजी-वृद्धि (Capital appreciation) का रूप ले ले । उदाहरण स्वरूप सुपर टैक्स देने वाले के लिए कम हिविडेन्ड वाली लेकिन मारी मात्रा में अनुमानित पूँजी वृद्धि (Capital appreciation) वाली प्रतिभूतियों में पूँजी लगाने अथवा हिस्का उन्ट वाले बांडों को खरीदने में लाम है"। आय पर लगने वाले कर की दर से पूँजी लाम पर कर लगाने से इस प्रकार की कर चोरी सक जायगी।

उपहार कर (Gift Tax)—"वर्तमान सम्यक्तिकर (Estate Duty) के स्थान में यह कर लगाने की सिफारिश की गयी है। यह कर सभी उपहारों पर लगेगा। इसके अन्तर्गत जीवित व्यक्तियों को दिये गये उपहार तथा उत्तराधिकार में मिले उपहार भी शामिल हैं। सम्पत्ति-कर के लिए जो प्रणाली अपनायी गई है उसके प्रतिक्ल यह करदाता की सम्पत्ति पर नहीं बल्कि पाने वाले की सम्पत्ति पर निर्धारित किया जायगा। एक अकेले प्राप्त करने वाले के लिए १०,००० रुपये तक छूट देने का सुक्ताव दिया गया है। इसके ऊपर उपहार पर अगर पाने वाले की असली सम्पत्ति १,००,००० रुपये से नीचे की है तो १० प्रतिशत की दर से कर लगेगा। १,००,००० रुपये श्रीर १,५०,००० रुपये के बीच १५ प्रतिशत की दर से कर लगेगा। श्रीर यदि पाने वाले की कुल सम्पत्ति (उपहार समेत) २०,००,००० रुपये से ज्यादा बढ़ जाती है तो ८० प्रतिशत की दर से कर लगेगा। श्रीर यदि पाने वाले की कुल सम्पत्ति (उपहार समेत) २०,००,००० रुपये से ज्यादा बढ़ जाती है तो ८० प्रतिशत की दर से कर लगेगा। दूसरे शब्दों में १,००,००० रुपये से ऊपर के खंडों के लिए वर्तमान सम्पत्ति कर की दरों को दूनी दरें प्रस्तावित की गयी है,"।

"यह सुक्ताव दिया गया है कि एक बार वार्षिक सम्भदा कर लागू हो जाने और वार्षिक असली सम्पदा का पर्यात ब्यौरा मिल जाने पर वर्तमान सम्पत्ति कर की जगह उपहार कर पूरी तौर से लागू कर दिया जाय । उत्तराधिकार कर का असला भार उत्तराधिकार पाने वाले र पहता है, मृत व्यक्ति पर नहीं। दूसरे जीवित व्यक्तियों के बीच के उपहारों और वसीयत में मिलने वाली सम्पत्तियों के वीच श्रन्तर करने में कोई श्रीचित्य नहीं इसलिए सम्पत्ति कर के त्थान में एक क्रमिक उपहार कर लगाया जाय"।

"उपहार कर के ओचित्य के प्रति तर्क उसकी आवश्यकता तथा प्रशा-सनात्मक सरलता है। कहा जाता है कि उत्तराधिकार पर कर लगाने का वास्तविक श्रीचित्य यह है कि श्रपनी सम्पत्ति श्रपने उत्तराधिकारी को देने की व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार समाज को है। लेकिन अगर ऐसा है तो उपहारों द्वारा सम्पत्ति देने और वसीयत द्वारा सम्पत्ति पाने में श्रन्तर करने का कोई कारण नहीं।

इन नये करों का सुमाव देते हुए काल्डॉर रिपोर्ट में बहुत ही साफ तीर से विकारिश की गयी है कि (१) व्यक्तियों, कम्पनियों आदि पर आय कर तया सुपर टैक्स की जपर के खंड की दर मिला कर २५,००० रुपये से जपर की श्रायों पर ७ माना प्रांत रुपया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। २५,००० रुपये तक की श्रायों पर कर की क्रमिक ट्रें लगेंगी और इसके ऊपर ७ श्राना प्रति रुपये की मोटी दर लाग होगी। इस प्रकार यह सिफारिश की गयी कि आय कर और सुपर-टैक्स की संयुक्त दर तत्कालीन ६२ प्रतिशत की दर से घटा कर ४५ प्रतिशत कर दी जाय: श्रीर (२) नहाँ तक कम्पनियों का सवाल है वर्तमान जटिल कर प्रणाली की जगह वर्तमान टूट-फूट छूट तथा विकास छूट को मान कर कम्पनियों की पूरी श्राय पर ७ श्राना प्रति रुपये की दर का एक कर लगाया जाय।

काल्डॉर रिपोर्ट के अनुसार न्यक्तिगत करों के फलस्वरूप नये करों से कल श्रुसली श्राय निम्नालिखित होगां :---

न्यक्तिगत कर	अनुमानित वार्पिक आय
१. व्यय कर	१० करोड़ रुपये से १५ करोड़ रुपये तक
२. सम्पदा कर	१५ करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपये तक
३. पूँजी लाम कर	२५ करोड़ रुपये से ४० करोड़ रुपये तक
४. उपहार कर	२० करोड़ रुपया

पo करोड़ रुपये से ११० करोड़ रुपये तक योग

३ श्राना प्रति रुपये के ऊपर सपर-देवस सतम करने त होने वाली कमी

१८ करोड रुपया

६२ करोड़ राये से ६२ करोड़ रुपये तक

श्रसली श्राय

आलोचना-कर प्रणाली के सुधार के रूप में प्रोफेसर काल्डॉर का श्रत्यधिक चुनियादी सुक्ताव व्यय-कर के रूप में है। प्रोफेसर काल्डॉर का तर्क यह है कि जितनी सही परिभाषा न्यय की दी जा सकती है उतनी आय की नहीं और ध्यय-कर देने वाले श्रीर कर वसूल करने वाली सरकार दोनों के लिये न्याय-पूर्ण है। कॉल्डार रिपोर्ट के अनुसार असमानता की जाँच करने के लिये, जिसको दूर करना कर प्रणाली का उद्देश्य होता है, उपमोग की श्रममानता, श्राय श्रथवा सम्पदा की श्रसमानता की कसीटी से ज्यादा उपयुक्त है। जहाँ तक व्यय कर का प्रश्न है जितना कोई व्यक्ति राष्ट्र की वस्तुओं और सेवाओं की घारा से अपने लिए निकाल लेता है उसी के अनुसार उस पर कर लगता है और जहाँ तक श्राय-कर का प्रश्न है वह जो कुछ इस धारा में लगाता है उस पर कर लगता है। विभिन्न लोगों की समानता की जाँच उस आवार पर नहीं होनी चाहिए जितना वे लगाते हैं विलक उस आधार पर होनी चाहिए जितना वे लेते हैं। ज्यय कर के लिये कुछ सैदान्तिक श्रौचित्य है लेकिन यह कर बुरा इस अर्थ में है कि यह अजेय व्यवहारिक कठिनाइयाँ पैदा करता है ! पिछली शताब्दी के मध्य में इस कर को लगाने का सुमाव दिया गया या लेकिन कुछ ही देशों को छोड़ कर किसी देश ने इन्हों ज्यावहारिक कठिनाइयों के कारण लागू नहीं किया। कुछ विशेष कठिनाइयां के कारण जो इमारे सामने हैं भारत के लिये यह और अनुपयुक्त है। हमारे यहाँ अन भी संयुक्त परिवार की प्रणाली है श्रीर सीमित श्रायों वाले लम्बे परिवारों के लिए यह श्रवित होगा। प्रोफेसर काल्डॉर ने इस कठिनाई को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने सुमान दिया कि यह प्रति व्यक्ति श्राधार पर लगाया जाय श्रर्थात् कर निर्धारण में परिवार के लोगों की खंख्या का ध्यान रक्खा जाय। लेकिन भारत में काफी लोगों को ऐसे व्यक्तियों की मदद करनी पड़ती है जिन्हें किसी भी परिमाधा के अन्तर्गत उनके परिवारों के अन्तर्गत नहीं समका जा सकता। और उनके कुल खर्च में ऐसे बाहरी व्यक्तियों पर होने वाला भी खर्च शामिल रहता है। ऐसी स्थिति में व्यय-कर श्रनचित होगा तथा उक्त सहायता को रोकेगा और इस प्रकार यह समाज विरोधी होगा।

दूसरे, जब तक कीमतें स्थिर रहेंगी व्यय कर न्यायपूर्ण रहेगा लेकिन जब कीमतें बढ़ेगी श्रथवा घटेंगी यह न्याय पूर्ण नहीं रह जायगा। कीमतें बढ़ने पर, जैसे कि भारत में हुआ है और द्वितीय तथा बाद की योजनाओं को देखते हुए भविष्य में भी हो सकता है, उपभोक्ता को हानि होगी क्योंकि वस्तुओं श्रीर सेवाओं के उपयोग के लिए उसको ऊँची कीमतें चुकानी पहेंगी। इसके श्रतिरिक्त यदि वह उतनी ही वस्तुओं श्रीर सेवाओं का उपभोग करना

चाहता है जितनी का उपभोग वह पहले करता था तो उसको लम्बा व्यय-कर देना पढ़ेगा क्योंकि ऊँची कीमतों के कारण उसकी वचत घट जायगी। िषर्फ हसको छोड़ कर उसके व्यय का पता लगाने के लिए श्रीर कोई व्यावहारिक उपाय नहीं है कि पहले उसकी श्राय का श्रानुमान लगाया जाय श्रीर तब पता लगाया जाय कि इसमें से कितना बचा है।

श्रन्त में, भारत में सब से बड़ी कठिनाई कर चोरी की है। कर की चोरी उस सीमा तक श्रीर बढ़ जायगी जिस सीमा तक लोग पहले साल छिपा कर रखे गये नकद रुपये से श्रीर उन लोगों से उचार लिये गये रुपये से श्रपने वर्तमान उपमोग का काम चलायेंगे जिनकी श्राय पर प्रत्यक्त रूप से कर नहीं लगता तथा जिन्हें श्रायकर श्रधिकारियों के सामने श्रपनी श्राय का ब्योरा नहीं पेश करना पहता । इसके श्रातिरिक्त वीमारी, विवाह, ज्यादा दिनों तक चलने वाली उपभोगता वस्तुक्रों क्रादि पर हुये खर्च से अनेक कठिनाइयाँ पैदा होंगी। भारत में छोटे व्यापारी निजी हिराव तथा व्यापार का हिसाव साथ रखते हैं और ऐसी स्थिति में निजी व्यय को व्यापार के हिसाब में दिखा के कर की चोरी के मामलों को पकड़ना घरल न होगा। बड़े कारोबार में श्रधिकारियों को कारोबार से सम्बन्धित खर्च में जो छूट मिली है उससे भी कठिनाइयाँ पैदा होंगी। प्रोफेसर ए॰ ग्रारं पेस्ट (Prof. A. R. Prest) ने सही कहा है कि "प्रोफेसर काल्डॉर का मानिएक चित्र यह है कि लोगों का एक छोटा समुदाय विरासत में मिले धन को विलास की वस्तुत्रों में लुटा रहा है। दूसरा चित्र यह हो सकता है कि सभी श्राय वर्गों के भारी संख्या में नाम मात्र की अपनी श्राधिक श्रायों को विभिन्न स्तरों में, जिन्सों ग्रीर विभिन्न रूपों ग्रीर मात्राश्रों में खर्च मत्तों से पूरा करते हैं। इसके मामले में व्यय-कर जितनी समस्याएँ इल नहीं करता उतनी पैदा करता है। इसलिए इम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है।

पूँजी लाभ कर, उपहार कर श्रीर सम्पदा कर में यह गम्भीर दोप है कि वचत करने का उत्साह बुरी तरह घट जायगा श्रीर पूँजी निर्माण रुक जायगा जब कि ये भारत की श्रर्थ ज्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य श्रमेरिका जैसे उन्नत देश में ऐसे करों से श्रिधक हानि सम्भव नहीं क्योंकि वहाँ पहले से ही सम्पदा का 'श्रत्यधिक' संग्रह है लेकिन भारत ऐसे श्रार्थिक हिंछ से पिछड़े देश में पूंजी निर्माण श्रीर धन संग्रह को प्रोत्साहन देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके श्रांतिरक्त 'कर लगाने में मितन्ययिता' (economy in taxation) का शास्त्रीय सिद्धान्त जितना पहले महत्वपूर्णया

उतना ही आज भी है। अगले कुछ वर्षों में इन करों से जो छोटी आय होगी और सरकार को इनके वस्ल करने में जितना समय और घन खर्च करना पड़ेगा उससे इनका श्रीचित्य नहीं सिद्ध होता । काल्डॉर रिपोर्ट में श्रुतिशयोक्ति से काम लिया गया है कि सरकार को पूँजी लाम कर से २५ करोड़ रुपये से ४० करोड़ रुपये तक, उपहार कर से ३० करोड़ रुपये श्रीर वार्षिक सम्पदा कर से १५ करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपये तक की आयहोगी। पर्याप्त आंकड़ों के आभाव में इन करों की सम्मावित आय का अनुमान जगाने का कोई साधन नहीं लेकिन सम्मावना इस बात की है कि अगले कुछ वर्षों में इन करों की कुल आय छोटी सी होगी। हमारे पास पशिचित आय कर अधिकारी हो जाते हैं तो उन्हें पहले कर की चोरी रोकने में लगाना चाहिए जिससे सरकार के पास प्रोफेसर काल्डॉर द्वारा प्रस्तावित कल्यनाशील करो की अपेन्स ज्यादा राजस्व आये।

श्रपने सुकावों के श्रीचित्य के पत्त में प्रोफेशर काल्डॉर का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इनसे भारत में करों की चोरी रुकेगी क्योंकि "श्रगर इन करों का निर्धा-रण एक ही समय, एक ही श्रधिकारी द्वारा श्रीर कर-दाता द्वारा प्रस्तत हिसान-किताब एक हा पूर्ण न्योरे (साल की समस्त आयों, कर मुक्त सभी खर्च, श्रीर श्रपनी समस्त सम्पत्ति का नकशा) के श्राधार पर किया जाय तो कर की चोरी अधिक कठिन हो जायगी, केवल इसीलिए नहीं कि कर-दाता के लिए विशेष आयें अथवा सम्पत्ति के हिस्से लगातार छिपाने में कठिनाई होगी बल्कि इस वजह से कि एक कर-दाता (खुद श्रपनी देने की जिम्मे-दारी को कम करने के हित में) द्वारा प्रस्तुत विवरण दूसरों के द्वारा प्रस्तुत विवरण पर प्रत्यज्ञ रोक थाम का काम करता है"। काल्डॉर रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण वातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अनुभव से हम जानते हैं कि करों की चोरी करने वाले भारतीय कर-दाता श्राय-कर श्रिषकारियों की श्रिपेक्षा ज्यादा चालाक निकले हैं और फर्जी व्योरा देने के बावजूद उनके लिए अपने आय-कर विवरण में एकरूपता बनाये रखना कठिन न होगा। कर की चोरी पकड़ने के लिए हम उनके श्राय-कर विवरण की संभावित श्रंश गति पर निर्भर नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आय-करदाताओं के सभी सीदे सिर्फ दूसरे स्रायं कर दातास्त्रों के साथ नहीं होते इस लए एक द्वारा प्रस्तुत विवरण दूसरों पर रोक-थाम का काम करके करों की चोरी नहीं रोक सकता। यह बहुत सम्भव है कि एक आय-करदाता उस मद को फर्जी रूप में पेश करे जिस पर वह भ्राय-कर न देने वालों के साथ सौदा करने के सम्बन्ध में कर की चेरी

करता है। केवल इस सम्भावना पर कि शायद श्रागे चल कर कुछ रोक-धाम हो सम्बा खर्च श्रीर तकलीक उठाना ठीक नहीं।

भारत में करों की चोरी के बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल कर-दाता ही कर की चोरी नहीं करते विल्क काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी आय छूट की न्यूनतम सीमा को पार करती है लेकिन वे आय-कर अधिकारी की पकड़ में नहीं आते क्योंकि प्रशिक्षित आय-कर अधिकारियों की कमी है। यदि हमारे पास प्रशिच्चित अधिकारी अधिक हों तो वे उन लोगों को पकड़ सकते हैं जिनकी आय छूट की न्यूनतम सीमा से अधिक हैं लेकिन इस समय नहीं पकड़े जा रहे हैं क्योंकि उनको पकड़ने के लिए कोई खाली ही नहीं है। भारत में हमने अब तक करों की बड़ी चोगी करने वालों पर ही अपना ध्यान दिया है लेकिन छोटी आय वालों हारा भी करों की चोरी होने से सरकार को एक लम्बी रकम नहीं भिल पार्ता।

भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रमाव—भारत सरकार ने पूँजी लाभ कर, सम्पदा कर, व्यव कर तथा उपहार कर के संवंध में काल्डॉर रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें स्वांकार कर ली हैं। यद्यपि ये कर काल्डॉर रिपोर्ट में प्रस्तावित दरों से कम दरों पर लागू किये गये हैं लेकिन सरकार ने व्यक्तिगत आयों परआय-कर तथा सुपर-टैक्स की संयुक्त उच्चतम दर को ७ आना प्रति रुपया तक नहीं घटाया और कम्पनियों के मामले में करों की अनेकता को हटा कर ७ आना प्रति रुपया दर वाला एक कर नहीं लागू किया। इसका परिणाम यह हुआ है कि सभी वर्गों के लोगों पर कर-मार अधिक वह गया है आर कर-प्रणाली सुघार के प्रस्तावित उद्देश्य के अनुसार भारतीय कर-प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और वैज्ञानिक नहीं हो पायी।

स्पष्ट रूप ते द्वितीय योजना के लिए श्रिषक साधन जुटाने के लिए १६५६-५७ श्रीर १६५८-५६ के बीच तीन वर्षों में नये कर लगाये गये हैं श्रीर वर्तमान कर बढ़ाये गये। लेकिन जैसा कि योजना श्रायोग ने श्रपने "द्वितीय योजना का मूल्यांकन तथा सम्मावनाएँ" में स्वीकार किया है कि "इस कर-संग्रह ने योजना के लिए साधन नहीं जुटाये, इसका एक बड़ा हिस्सा दूसरी मांगों (प्रतिरज्ञा,गैर विकास न्यय तथा योजना से बाहर विकास न्यय) पर हुशा।" जैसी कि श्राशा थी, करों से श्राय बढ़ाने पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने श्रीर मी लापरवाही से श्रीर योजना की श्रावश्यकताश्रों पर ध्यान दिये विना चपया खर्च किया। इस प्रकार जनता ने वेकार इतनी बड़ी मुश्किलें मेली हैं।

श्रन्त में इतनी कँची दरों पर श्रांतिरिक्त कर लगाने से उद्योगों के उत्पादन

करोड़ रु०, श्रीर १५६ ६ करोड़ रु० का बाटा ही हुआ। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की वित्त व्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में लगभग ३६६ करोड़ रुपये का घाटा रहा। १६५२-५३ श्रीर १६५३-५४ में घाटे का प्रवन्ध मुख्यतः कोष में रोकड़ की मात्रा घटा कर किया गया परन्तु मार्च १६५४ के श्रन्त तक कीप में रोकड़ की मात्रा घटकर कंवल ३७ करोड़ रुपया रह गई श्रीर श्रगले वर्ष घट कर ३२ करोड़ रुपया हो गई। इस कारण १६५४-५५ से बराबर घाटे का श्रर्थ प्रवन्ध प्राय: पूर्णत्या ट्रेजरी श्रुण पत्रों के विस्तार हारा किया जा रहा है। इधर हाल में कन्द्रीय बजटों में श्रीर श्राधक घाटा रहा है श्रीर १६५६-५० में यह कमशः १८४ ७५ करोड़ रुपया, ४५८-५८ करोड़ रुपया (संशाधित), २५६-६६ करोड़ रुपया तथा २२१.४४ करोड़ रुपया (बजट) था।

घाटे का बजट बनाने के पक्त श्रीर विपक्त में काफी कहा गया है। इसके समर्थन में यह कहा गया है कि: (१) कोई भी सरकार श्रपनी वर्तमान आय की रकम में से पंचवर्षीय योजना जैसी बड़ी योजना में निहित विकास कायों की वित्तीय श्रावश्यकता पूरी नहीं कर सकती है। इसलिए घाटे के बजट की नीति श्रपनानी पड़ती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेगा और देश निर्धन ही बना रहेगा: (२) सरकार के आय-व्यय की श्रवधि को १२ महीनों तक ही सीमित रखना आवश्यक नहीं है और इस बात का भी कोई कारण नहीं कि बजट को प्रतिवर्ष सन्तुलित किया जाय। यह सम्भव है कि सरकार झगले ५ या १० वर्षों के लिए वजट-व्यवस्था करे जिनमें से कुछ वर्षों में घाटा हो ग्रीर श्रन्य में लाभ हो ग्रीर दीर्घकाल में छरकार की वित्त स्थिति सन्तुलित हो जाय; श्रीर (३) केन्स के सिद्धान्त के श्रनुसार ऐसी श्राधिक व्यवस्था में जिसमें कुल माँग श्रीर कुल पूर्ति में श्रन्तर (gap) होता है देश के साधनो का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। साधनों के पूर्ण उपयोग के लिये कुल माँग के स्तर को कुल पूर्ति के स्तर तक ऊँचा उठाने के लिए माँग श्रीर पूर्ति के वीच के ग्रन्तर को राज्य ऋगा इत्यादि (created money) के विनियोग द्वारा पूरा करता है। इससे राज्य के साधनों का पूर्ण उपयोग हो सकता है श्रीर राष्ट्रीय ब्राय में श्रिधिक से श्रिधिक वृद्धि होती है। इस विधि का स्वाभाविक परिणाम घाटे के बजट की व्यवस्था है। घाटे के वजट की व्यवस्था न होने पर राष्ट्रीय भ्राय को ययासंगत उच्च सार तक नहीं पहुँचाया जा सकता है।

इसमें कुछ संदेह नहीं है कि घाटे की बजट व्यवस्था से कुछ लाभ हैं। देश के श्राधिक कारोबार में सकियता लाने के लिये यह श्रचूक उपाय है श्रीर इससे राष्ट्रीय लाभांश में भी श्रधिक से श्रधिक चूढि हा सकती है। परन्तु जहाँ तक

भारत का सम्बन्ध है इस व्यवस्था का प्रभाव प्रतिकृल ही पड़ा है: (१) घाटे के वजट की न्यवस्या में यह मान लिया जाता है कि देश की आर्थिक न्यवस्या मुद्रास्कीति से प्रस्त नहीं है श्रीर देश में ऐसे साधन हैं जिनका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है परन्तु जिनका पूर्ण उपयोग इस व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। भारत में युद के कारण श्रत्यधिक मुद्रास्कीति फैल गई जो श्रव तक फैली है। यद्यपि भारत में कुछ ऐसे साधन हैं जिनका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे अक्रुशल मजदूर, परन्तु इसके साथ ही अन्य साधनों, जैसे मशीन, कच्चा माल, रासायनिकों इत्यादि का भी श्रभाव है जनकि ये साधन देश के श्रीयोगिक कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने के लिए अत्यन्त श्रावश्यक हैं। घाटे की वजट व्यवस्था ने उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति को बढ़ा दिया है जिससे देश की वर्तमान मुद्रास्फीति की स्पिति श्रीर भी बिगइ गई, वस्तुश्री के भावों में श्रीर वृद्धि हो गई श्रीर जनता की कठिनाइयाँ भी बढ़ गई; (२) चूँकि पंचवर्षीय योजना को अधिकांश योजनाएँ दीर्घकालिक हैं इसलिए घाटे की वजट व्यवस्था को शीध उत्पादन बढ़ाने में सफलता भी नहीं मिली है जिसका परिग्राम यह हुन्ना है कि अनेक वस्तुओं की पूर्ति आवश्यकता से बहुत कम है। इससे वस्तुओं के भाव बढ़ते जा रहे हैं। यदि पंचवर्षीय योजना में श्रत्यकालिक योजनास्त्रों पर जोर दिया जाता जिससे शीघ्र पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बढ़ता तो उपमोक्ता की क्रय शक्ति के बढ़ते हुए मी वस्तुत्रों की कीमर्ते गिर जातीं; (३) मजदूरी श्रांघक होने से, कच्चे माल की कीमत बढ़ने से श्रीर श्रिधिक कर लगने से भारतीय उद्योगों का उत्पादन व्यय बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप उत्पादित माल की कीमतें भी बढ़ गई'। इससे बहुत कुछ बाटे की वजट व्यवस्था का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया; श्रीर (४) मारतीय पूँ जी बाजार से आवश्यकता से बहुत कम रुपया प्राप्त होता है श्रीर घाटे की वजट व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आवश्यक विदेशी पूँजी भी बहुत कम उपलब्ध है। सरकार अपने धाटे की पूर्ति या तो देश के द्रव्य वाजार ते ऋण लेकर, या विदेशों से ऋण लेकर, या अपने नकद कांप में से, या कुछ सीमा तक पीरह पावने में से कुछ रकम लेकर करती है। सरकार द्रव्य वाजार से श्रावश्यक मात्रा में ऋग प्राप्त नहीं कर सकी है श्रीर उसका नकद कीव तो प्रायः खाली हो जुका है जिसके फलत्वरूप घाटे की बजट व्यवस्था से सरकारी विच व्यवस्था पर काफ़ी भार पड़ा है।

कर-ज्यवस्था-पुद के पहले भारतीय कर-ज्यवस्था प्रतिगामी (regressive) थी श्रीर दिद केन्द्रीय श्रीर राज्य वित्त ज्यवस्था पर एक साथ विचार किया जाय तो पता चलेगा कि भारत में श्रप्रत्यज्ञ करीं (indirect taxes) का प्रभुत्व रहा। राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये श्रिषकतर कर श्रप्रत्यन्न कर हैं। १६३८-३६ में केन्द्रीय सरकार की कुल श्राय ८४'४७ करोड़ रुपये थी जिसमें से ४०'५ करोड़ रुपया श्रायात-निर्यात कर से, ८'६६ करोड़ रुपया केन्द्रीय उत्पादन कर से श्रीर १७'२८ करोड़ रुपया श्रायकर से (जिसमें कार्पोरेशन-कर भी शामिल है) प्राप्त हुश्रा। इस प्रकार, जहाँ तक केन्द्रीय वित्त ज्यवस्था का सम्बन्ध है श्राय कर कुल करों की श्राय का केवल २२'६ प्रतिरात था। यदि इम कुल श्राय पर विचार कर तो पता चलेगा कि १६३८-३६ में श्रायकर श्रीर कार्पोरेशन-कर कुल के १८'६७ प्रतिशत थे, श्रायात-निर्यात कर श्रीर केन्द्रीय उत्पादन कर ५८'१७ प्रतिशत श्रीर रेल, डाक, करेन्सी इत्यादि (Commercial Services) से श्राय केवल २'५३ प्रतिशत थी।

युद्ध काल में कर की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया और १६४३-४४ में श्राय-कर (जिसमें कार्पोरेशन कर शामिल है) से श्राय कुल १२६ करोड़ रुपया थी, केन्द्रीय उत्पादन कर से २७.४२ करोड़ वपया श्रीर श्रायात-निर्यात कर से श्राय २६:२२ करोड़ रुपया थी जब कि कुल करों की श्राय १६३ करोड़ रुपया थां। १६४३-४४ में स्राय-कर करों की कुल स्राय का ६६ प प्रतिशत या स्रीर १६४४-४५ में ६००१ प्रतिशत था। यदि कुल स्राय पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि ग्रायकर श्रीर कार्पोरेशन कर कुल का ४१ ४ प्रतिशत थे, ग्रायात-निर्यात कर श्रीर केन्द्रीय उत्पादन कर ३२'३ प्रतिशत श्रीर रेल, डाक, करेन्छी इत्यादि (Commercial Services) से श्राय १६ ६६ प्रतिशत थी। इस प्रकार युद्ध काल में : (१) केन्द्रीय सरकार की श्राय में श्रायकर निसका श्रव तक द्वितीय स्थान या कमश: प्रथम स्थान लेने लगा; (२) केन्द्रीय उत्पादन कर से श्राय बढ़ी श्रीर श्रायात-निर्यात कर से श्राय घटी परन्तु दोनों की श्राय लगभग बराबर रही: न्नौर (३) रेल, डाक, करेन्धी इत्यादि (Commercial Services) से न्नाय १६३८-३६ में कुल आय की केवल २३ प्रतिशत थी परन्तु १६४५-४६ में यह बढ़ कर १६६ प्रतिशत हो गई। इस प्रकार सरकार की आय के साधनों में इनका महत्व बढ़ा।

युद्ध काल में प्रत्यज्ञ कर (Direct Taxes) की आय सर्वोच्च स्तर तक पर्हेंच गई थी परन्तु युद्धोत्तर काल में यह स्थिति बनी न रह सकी और प्रत्यज्ञ कर व्यवस्था का स्तर घटाना पड़ा और अप्रत्यज्ञ कर व्यवस्था का स्तर ऊँचा उठाना पड़ा। इस बीच केवल १६४७-४८ में, जब लियाकत अली खाँ वित्त मंत्री थे, प्रत्यज्ञ कर व्यवस्था का स्तर ऊँचा उठाया गया। १६४४-४५ में आय-कर करों की कुल आय का ६८१ प्रतिशत था परन्तु १६४५-४६ में गिरकर ५७ २ प्रतिशत,

१६४८-४६ में ५० र प्रतिशत, १६५० ५१ में ४२ द प्रतिशत, १६५५ ५६ में २७ ५ प्रतिशत तथा १६५८-५६ (नजट) में २४ ६ प्रतिशत हो गया वावजूद इसके कि पिछले दो नजटों में प्रत्यज्ञ करों में काफी वृद्धि की गई थी। १६५८-५६ में ६८५ ०२ करोड़ दाया को कुल आय में से करों से प्राप्त आय ५७२ ३४ करोड़ द्या की कुल कर-आय में से आय और व्यय पर लगे करों से प्राप्त आय १४३ ०३ करोड़ द्या की कुल कर-आय में से आय और व्यय पर लगे करों से प्राप्त आय १४३ ०३ करोड़ द्या हो। चस्तुओं तथा सेवाओं से प्राप्त आय ४१० १५ करोड़ द्या थी।

श्रप्रत्यक्त करों में वृद्धि होने तथा प्रत्यक्त करों के श्रानुपात में कमी होने से भारतीय कर-व्यवस्था युद्ध काल की श्रपेक्षा कम प्रगतिशील हो गई है। यह प्रतीत होगा कि ऐसी स्थित विकास की दृष्टि से उचित नहीं है परन्तु वास्तव में स्थित ऐसी नहीं है। प्रतिगामी कर-व्यवस्था को पसन्द किया जाता है परन्तु यह संभव है कि कर-व्यवस्था श्रात्यन्त प्रगतिशील हो सकती है, जैसे कि भारत में हुश्रा है, जिससे (१) सहसी उद्योगपित नथे उद्योगों में स्पया लगाने के लिए श्रापे नहीं श्रात हैं श्रीर (२) इससे बचत कम हो जाती है श्रीर पूँजी निर्माण का कार्य मन्द पड़ जाता है जो देश के श्राधिक विकास के लिए श्रत्यन्त धातक है। भारत जैसे निर्धन देश में जहाँ श्रधिकतर लोगों की श्राय बहुत कम है यह श्राव-रयक है कि प्रत्यक्ष करों से श्रप्रत्यक्त करों को श्रपेक्षा कम श्राय हो। जैसे-जैसे भारत का राष्ट्रीय लाभाश बढ़िगा श्रीर जनता घनवान बनती जायगी, जैसे ब्रिटेन, श्रमरीका तथा श्रन्य देशों में हुश्रा है, वैसे-वैसे बिना प्रतिकृल प्रभाव के प्रत्यक्त कर व्यवस्था को ऊचा उठाया जा सकता है।

१६५६-५७ से बजटों की विशेष महत्ता है क्योंकि इनसे सरकार की आय को यथासम्मव बढ़ाने का संकल्म लिज्ञत होता है। इसे पूर्णतया समस्तने के लिये हमें यह जान लेना आवश्यक है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय चेत्र में ही करों की वृद्धि की गई थी, विशेष कर १६५१-५२, १६५४-५५ और १६५५-५६ के वर्षों में जब कि उनसे आय क्रमशः ३२ करोड़ रुपया, ११ करोड़ रुपया और ७ करोड़ रुपया हुई थी। बाद में जो निर्यात कर में १६५५-५६ में परिवर्तन किया गया उससे ११ करोड़ रुपये का घाटा ही हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पांच वर्षों में लगभग १६० करोड़ रुपये की मात्रा का अविरिक्त कर आरोपित किया गया। १६५५-५६ में करों में वृद्धि कर जाँच आयोग की सिकारिशों के अनुसार ही की गई थी। यह कम तब से जारी है।

"द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से कर नीति का उद्देश्य कर व्यवस्था

को नियोजन के अनुकुल बनाना है। १९५६-५७ में केन्द्र ने कर जाँच श्रायोग द्वारा प्रस्तावित कर-सम्बन्धी श्रानेक परिवर्तन किये। करारोपण के श्रान्य उपायों की घोषणा ितम्बर व नवम्बर १९५६ में की गई । १९५६-५७ के वर्ष में करों से प्राप्त ग्राय ५५ करोड़ ६० के लगभग अनुमान की गई थी तथा उसकें श्रनन्तर पूर्ण वर्ष के लिये ८१ करोड़ र∙ की । १६५७-५८ के केन्द्रीय बजट में कर श्राचार को श्रीर प्रशस्त श्रीर गहरी करने का लक्ष्य सामने रखा गया था। उस वर्ष अतिरिक्त करारोपण से अनुमानित आय ६३ करोड़ ६० थी तथा पूर्ण वर्ष में इससे प्राप्त श्राय १०७ करोड़ रु० श्रनुमानित थी। बाद में दी हुई रियायती तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सम्पत्ति-कर तथा रेलवे यात्री कर से अनुमा-नित आय प्रारम्भ में अनुमानित राशि से कम हुई थी, अतिरिक्त करारोपण से प्राप्त श्राय लगमग ७३ करोड़ रु० थी तथा पूर्ण वर्ष की ग्राय 🛶 करोड़ रु० थी। १९५८-५६ के बजट में प्रस्ताबित कर सम्बन्धी परिवर्तनों से कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ। उपहार कर, मृत्य कर तथा सीमेन्ट पर बढ़े हुये उत्पादन कर श्रादि से हुई प्राप्ति सूती वस्त्रों के उत्पादन कर में की गई कमी से लुप्त हो गई। १६५६-६० की स्थित भी बहुत कुछ इसी समान है और कर-प्रस्तानों से केवल २६:०७ करोड़ रुपयों की प्राप्ति श्रांकी जाती है; राज्यों को उत्पादन करों में मिलने वाले हिस्से को छोड़कर केन्द्रीय बगट से २३.२५ करोड़ चाये प्राप्त होंगे ??

पाँच वर्षों के समय में केन्द्र द्वारा प्रस्तावित श्रितिरिक्त करारोपण से कुल श्राय का श्रमुमान लगभग ७२५ करोड़ कo है। योजना में प्रारम्भ में प्रस्तावित लक्ष्य (२२५ करोड़ कo) की तुलना में यह राशि ५०० करोड़ कo श्रिषक है। यह श्राय संगठित-कर-व्यवस्था (integrated tax structure) द्वारा प्राप्त की जायगी जिसके श्रम्तर्गत (1) श्रमेक नये कर (उदाहरणार्य सम्पत्ति कर तथा व्यय कर लगाये गये हैं), (11) वर्तमान करों की दरें बढ़ा दी गई हैं, (111) भृतकाल की श्रपेक्षा श्रप्रत्यक्त करों से, जो स्वभावतः ही प्रतिगामी होते हैं, श्रष्टिक श्राय प्राप्त की गई है। इस प्रकार योजना के श्रर्थ प्रबन्धन के लिये यथासम्भव श्राय प्राप्त करने के हेतु प्रगामी तथा प्रतिगामी दोनों ही प्रकार के कर लगाये गये हैं।

, नये-कर

पूँजी लाम कर (Capital Gains Tax)—३० नवम्बर, १६५६ के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने लोक-समा में पूँजी लाम कर को पुनः लागू करने की घोषणा की। यह कर उन लामों पर लगेगा नो पहली श्रमेल,

१६५६ को या उसके बाद प्राप्त हुये हों। छूट की सीमा ५००० रु० निर्घारित की गई है किन्तु यह भी न्यवस्था है कि "यदि कुल योग, पूँजी लाम को स्मिलित करते हुये, १०,००० रु० से अधिक न हो तो पूँजी-लाम कर नहीं लगेगा"। कर वस्त करने की दर इस प्रकार निकाली जाती है कि पूँजी-लाम-कर का एक-विहाई अन्य आय में जोड़ दिया जाता है तथा उस समय चालू आय-कर की दर वस्ती जाती है।

यह नया कर उस पूँजी लाभ कर से विल्कुल भिन्न है जो पहली श्रामैल, १६४६ से ३१ मार्च १६४६ तक लागू था। (i) पुराने कर में छूट की सीमा १५००० रु० थी जबिक नये कर में सिर्फ ५००० रु० है; (ii) पुराने कर में छुछ छूट की ज्यवस्था थी, लेकिन नये कर में इनको हटा कर चेत्र बढ़ा दिया गया है; (iii) पुराने कर में दर खण्ड प्रणाली पर थी श्रीर एक चपये में एक श्राना से पाँच श्राना तक थी जब कि नये कर में ऊँची दर लागू की गई है क्योंकि पूँजी लाम पर भी वही दर है जो कि करदाता की श्रान्य श्राय पर है।

इस कर के समर्थन में यह कहा जाता है कि (अ) सरकार को विकास कार्य और अन्य कार्यों के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता है और इसके लिए सब साधनों का प्रयोग करना चाहिये, तथा (व) जैसा कि काल्डॉर रिपोर्ट ने कहा है, आय का सही विचार वह है जो कि सभी प्राप्त लाभ को एक हिन्द से देखे। इसलिए आय में पूंजी लाभ को भी शामिल करना चाहिये।

लेकिन इसके विपन्न में यह कहा जाता है कि (१) यह कर विनियोग तथा कम्पनी के हिस्सों में तथा अन्य सम्पत्ति के स्वतन्त्र विक्रय में बाधा डालता है, जो कि प्लाबाद की सुवाद गति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार का कर प्ली-सम्पत्ति के न्यापार में ज्याकर्षण (distortion) लाता है क्योंकि प्ली लाम के समय में उन्हें वेचने में हिचक होगी और हानि होने पर इन्हें वेचने के लिये प्रेरणा मिलेगी। (२) कर-जींच आयोग ने ठीक ही बताया है कि इस कर के लागू करने से कर से बचने की प्रवृत्ति को वल मिलेगा तथा लोग अन्यथा कर देय आय को प्ली लाम के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। (३) इस कर से प्राप्त राजस्व इतना कम है कि यह कर उत्पन्न जिल्लताओं का समयेन नहीं करता।

सम्पदा-कर (Estate Duty)—यह छन् १६५३ में भारत में लागू किया गया था। सम्पदा कर उत्परिवर्तन (mutation) कर है जो कि सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार उस समय लगाया जाता है जब सम्पत्ति एक व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरे के हाथ में जाती है। इसमें इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि सम्पत्ति किस व्यक्ति के हाथ में जा रही है। १५ अवद्वर, १६५३ को सम्पदा कर

सम्पूर्ण सम्मिष्प, चाहे वह वास्तिविक हो या वैयक्तिक, न्यवस्थापित हो या श्रन्यवस्थापित, जो किसी न्यक्ति की मृत्यु पर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, लगाया जायेगा। श्रिधिनियम में सम्पत्ति की विस्तृत परिभाषा दी गई है श्रीर कुछ श्रपवाद स्वीकार किए गए हैं: (१) सार्वजिनिक धर्मार्थ उपहार जो कि मृत्यु से ६ महीने के श्रन्दर दिये गये हों श्रीर जब २५०० रुपये तक के हों। (२) या श्रन्य उपहार जो दो वर्ष के श्रन्दर दिया गया हो श्रीर १५०० रुपये तक का हो। (३) बीमा श्राय जो कि सम्पदा कर देने के लिए हो श्रीर सरकार के नाम कर दी गई हो, परन्तु यह ५०,००० रु० से श्रिधिक न होनी चाहिये। (४) मरने वाले न्यक्ति की वीमा से ५००० रु० तक की श्राय।

कुछ शर्तों के पूरे होने पर मृत्यु से ६ महीने के पहले किए गए सार्वजनिक धर्मार्थ उपहार श्रीर दो वर्ष से पहले दिये गये अन्य उपहार, कर से मुक्त हैं। यह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लाभ के लिए लगाया जाता है और उसको नास्तविक आय राज्यों में बाँट दी जाती है। कृषि सम्पत्ति पर यदि उचित श्रिधिनियम पास हो चुका हो तो राज्यों में यह कर लगाया जा सकता है। कर की दर ५ प्रतिशत से (५०,००० रुपये के प्रथम खरह पर जो कोई कर नहीं देता) ४० प्रतिशत तक है। यह दर संयुक्त हिन्दू परिवार के लिये है जो मिताचर, मर्रमकदृयम या अलीयासन्तना के नियम से संचालित हैं। अन्य परिवारों के लिये यह दर ७ई% प्रतिशत से (एक लाख के प्रथम खरह जिस पर १र कोई कर नहीं हैं) ४० प्रतिशत तक है। ४० प्रतिशत की ऋषिकतम दर दोनों ही स्थितियों में सम्पत्ति के ५०,००,००० व० से अधिक होने पर पहुँचती है । शीझ क्रम में मृत्यु होने पर अधिनियम छूट भी देता है। सम्पदा कर से कुल आय १६५४-५५ में दर लाख रुपये, १६५५-५६ में १ दर करोड़ रुपये, १६५६-५७ में २'११ करोड़ रुपये. १६५७.५८ में २'३१ करोड़ रुपये, १६५८-५६ (संशोधित) में २.५ करोड़ ६० श्रीर १९५६-६० (बजट) में २.५५ करोड़ रुपये बहुत ही कम है।

यह कर इन कारगों से लगाया गया था कि (श्र) कर देयता श्राय पर ही नहीं वरन व्यक्ति के घन श्रीर सम्पत्ति पर भी निर्भर है जो मृत्यु होने से श्रनायास प्राप्त होती है। श्रतएव उस पर कर लगाना चाहिये। (व) यह कर श्राय श्रीर सम्पत्ति की श्रसमानताश्रों को दूर करता है जो कल्याग्यकारी राज्य (welfare state) में श्रावश्यक है। (स) सरकार को विकास कार्यों के लिए श्रतिरिक्त राजस्व की श्रावश्यकता है।

सम्पदा कर के निम्न दोष हैं: (१) यह बचत श्रीर पूँजी संचय को कम

करता है। (२) जीवित व्यक्तियों से दिये गये उपहार द्वारा कर से वचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इन किमयों को पूरा करने के लिए श्रीर इससे प्राप्त श्राय को अधिक करने के लिए १६५८-५६ के वजट में सुमाव दिया गया था कि (श्र) कर मुक्त सीमा एक लाख रुपये से घटाकर ५० हजार रुपये कर देनी चाहिए, (३) श्राप्रेल, १६५८ के वाद में होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में समय (श्रविध) दो साल से पाँच साल कर देना चाहिए ताकि मृत्यु के पाँच वर्ष पूर्व तक जीवित व्यक्तियों को दिये गये उपहारों पर सम्पदा कर लगाया जा सके। यदि संसद ने इन सुमावों को मान लिया तो सम्पदा कर से श्राय वढ़ जायगी।

चपहार कर—यह कर मारत में पहली अप्रैल, १६५८ से लागू किया गया। सम्पत्ति का उपहारों द्वारा अपने निकट सम्बन्धों के लिए या परिचित के लिए हस्तान्तरण सम्पदा-कर, आय-कर, सम्पत्ति-कर और व्यय कर से बचने का अत्यिषिक सामान्य रूप है। इसे प्रभावपूर्ण ढंग से केवल उपहारों पर कर लगा कर ही रोका जा सकता है। इस कर को लगाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय कर-प्रणाली के छिद्रों को वन्द करना है। उपहार कर ढा० कॉल्डार के प्रस्ताव से कुछ मिन्न रूप में लागू किया गया है।

उपहार कर व्यक्तियों से, संयुक्त हिन्दू परिवारों से, कम्पनियों, फर्म या व्यक्तियों के संगठन से पिछले वर्ष में कर-देय उपहारों पर लगाया जाता है। अधिनियम के श्रंतर्गत प्रथम कर निर्धारण में श्रर्थात १६५८-५६ के लिए उपहार कर उन उपहारों पर लागू होगा जो पहली श्रुपेल, १६५७ या उसके बाद दिये गए हैं। कर-देय उपहार का मूल्य पता लगाने के लिये पिछले वर्ष में दिये गए कुल उपहारों के मूल्य से कर मुक्त उपहारों के मूल्य को, जिनकी सूची सेक्शन ५ (१) में दी गई है, घटा दिया जाता है। यदि पिछले वर्ष में घटाने पर शेष दस हजार से श्रियक हो, तो इस श्रियक राशि पर उपहार देने वाले को कर देना पढ़ेगा। कर की दर ५०,००० रु० के प्रथम खरह पर ४ प्रतिशत है तथा पचास लाख रुपये से श्रियक के उपहारों पर ४० प्रतिशत है। उपहार कर की श्राय १६५८-५६ में (संशोधित) में १ २० करोड़ रुपया श्रीर १६५६-६० (बजट) में भी उतनी ही होने की श्राशा है।

सम्पत्ति कर (Wealth Tax)—सम्पत्ति कर व्यक्तियों पर, श्रविमाजित हिन्दू परिवार श्रीर कम्पनियों पर उनकी 'वास्तविक' सम्पत्ति पर एक श्रप्रंत, १६५७ से लागू किया गया। श्रिधिनियम की परिभाषा के श्रनुसार वास्तविक सम्पत्ति मूल्यन तिथि पर श्रुण मार के श्रविरिक्त शेष सम्पत्ति का मूल्य है। निम्न वस्तुर्ये कर-मुक्त हैं: (श्र) करदाता का निजी मकान; (ब) लकड़ी का सामान, घरेलू वर्तन, पहनने वाले कपड़े श्रीर श्रन्य निजी सामान; (स) करदाता के २५ इजार द० तक के जेवरात । वैंकिंग, वीमा, विनियोग तथा कुछ कम्पनियाँ इस कर से मुक्त हैं ।

सम्पत्ति कर की दर (१) ज्यक्तियों के लिये दस लाख रु० के द्वितीय खरड पर दे प्रतिशत से लेकर (जबिक प्रथम २ लाख रुपये के खरड पर छूट है) २२ लाख रुपये की वास्तिवक सम्पत्ति पर १५ प्रतिशत है; (२) हिन्दू अविभाजित परिवार के लिये यह दर वास्तिविक सम्पत्ति के ह लाख के दूसरे खरड पर ५ प्रतिशत (पहले ४ लाख के खरड पर कोई कर नहीं है) तथा वास्तिविक सम्पत्ति के २३ लाख से अधिक होने पर १५ प्रतिशत है; (३) कम्पनियों पर १ प्रतिशत जब वास्तिविक सम्पत्ति ५ लाख के प्रथम लाख से अधिक हो (५ लाख के प्रथम खरड पर कोई कर नहीं है)। इस कर से १९५७-५८ में ७ ०४ करोड़ रुपये की आय थी, १९५८-५९ (वंशोधित) में दस करोड़ रुप की आय होने की आशा है, और १९५८-६० (वजट) में १३ करोड़ रुप की।

सम्पत्ति कर के पन्न में तर्क है कि (श्र) सम्पत्ति व्यक्ति की करदेयता की बढ़ाती है श्रीर यह उचित ही है कि सम्पत्ति पर कर लगाया जाये, (ब) कल्याया-कार्य राज्य में सम्पत्ति सम्बन्धी श्रसमानताश्रों को दूर करने का उद्देश्य होना चाहिए श्रीर यह कर इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त है, (स) सरकार की दिवीय योजना के लिये धन की श्रावश्यकता है श्रीर इसके लिए प्रत्येक साधन का उपयोग करना चाहिये।

सम्पत्ति कर के विपन्न में यह कहा जाता है कि (क) यह बचत श्रीर पूँजी संचय को कम करता है जो कि देश के श्रीचोगीकरण में बाबा डालता है श्रीर यह श्रायिक दृष्टि से भारत जैसे श्रविकसित देश के लिये बहुत बुरा है। (ख) यह करदाता श्रीर श्राय-कर श्रिषकारियों में इन्टरप्रेटेशन की किटनाई श्रीर बहुत से श्रन्तर उत्पन्न कर इतना श्रिक श्रयन्तीय श्रीर उत्पीदन बढ़ाता है श्रीर इससे इतना कम राजस्व भिलता है कि इसकी छोड़ देना ही उचित है। (ग) कम्पनियों से श्राधा (है) प्रतिशत कर की दर होते हुए श्रीर नई कम्पनियों को पाँच साल तक छूट देने पर भी सम्पत्ति-कर सफल सम्पत्ति (assets) के भी उचित नियोजन तथा संयुक्त पूँजी कम्पनियों द्वारा नई कम्पनियों के बनाने में बाधक है। यह भारत को श्रीचोगिक उन्नति से रोकता है श्रीर इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य का इनन करता है।

व्यय-कर—व्यय कर श्रिधिनियम १९५६, जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर सारे भारत में पहली श्रप्रैल, १९५८ से लागू हुशा। इसलिये कर वस्त करने का पहला वर्ष १९५८-५९ था। व्यय-कर केवल व्यक्तियों श्रीर हिन्दू श्रिविभाजित परिवारों पर लगेगा। श्रन्य, जैसे कम्पनियाँ, कर्म या व्यक्तियों के संव श्रादि जो कि श्राय कर देते हैं उन पर यह कर नहीं लगेगा। न्यक्तिया हिन्दू श्रविभाजित परिवारीं को भी श्राय-कर देने के पश्चात किसी वर्ष में न्यय-योग्य श्राय के ३६००० ६० से श्रिधक होने पर ही कर देना पहेगा।

कर योग्य व्यय में कुछ श्रपबाद भी हैं जो कि व्यय-कर श्रिषिनियम के वर्ग प्र में वर्णित हैं जिसमें व्यापारिक खर्च, सम्पत्ति पर खर्च, विनियोग के मुगतान, उपहार, वीमा प्रव्याजि श्रादि श्रादि सम्मिलित हैं। छूट रहित व्यय में से भी कुछ रकम घटाई जायेगी जो कि वर्ग ह में वर्णित है जिसमें सबसे मुख्य ३०,००० ६० का श्राधारभूत श्राधदेय तथा श्रविमाजित हिन्दू परिवार में (परिवार के कर्ता को छोड़ कर) प्रत्येक सामेदार के लिये ३००० ६० की श्राविरक्त श्राधिदेय है। श्रम्य घटाई जाने वाली रक्तमों में निम्न श्राती हैं: दिये हुये कर, प्रत्येक श्राधित के विवाह में श्राधिक से श्रिषक ५००० ६० का व्यय, माता-पिता के लिये ४००० ६० का मरण्पोपण श्राधदेय, ५००० ६० तक का डाक्टर खर्चे का श्रिषकतम श्राधिदेय, विदेशी शिक्ता पर श्रिषक से श्रिषक ८००० ६० का श्राधिदेय, श्रादि श्रादि । व्यय-कर श्रिषिनियम के श्रन्तर्गत वर्ग ५ में दी गई छूटों को न गिन कर श्रीर वर्ग ६ में घटाई जाने वाली रक्तमों को घटा कर ही करदेय व्यय का पता लगाया जा सकता है। इस करदेय पर ही व्यय-कर लगाया जायेगा। श्रिष्टिनियम के श्रनुसार कर की दर प्रथम १०,००० ६० करदेय व्यय पर १० प्रतिशत से लेकर ५०,००० ६पये से श्रिषक करदेय व्यय पर शत प्रतिशत है।

इस कर के पत्त में निम्न तर्क हैं: (१) जैसा कि प्रोफेसर कॉल्डार ने बताया है, कर में समता निर्धारण करने के लिये आय या सम्पत्ति की अस-मानता की द्वलना में, जिस पर आय-कर तथा सुपर-टैक्स आधारित हैं, व्यय-कर अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह उपभोग की असमानताओं को हथ्यि में रखता है। (२) यह बचत को बढ़ाता है क्योंकि जो व्यय किया जाता है उसी पर कर देना पड़ता है, इस्विये यह कर भारत के औद्योगिक विकास में सहायता पहुँचायेगा। (३) यह कर अपवंचन या घोले से कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकेगा क्योंकि कर-प्रणाली अधिक संगठित हो जायगी और कर अधिकारियों का अधिक विस्तृत चेत्र पर जाल सा फैल जायेगा।

विस रूप में न्यय-कर भारत में लगाया गया है, उसके रूप में उसके विपज्ञ में निम्न बातें हैं: (i) श्राय-कर देने वाली जनसंख्या में से थोड़े से ही लोगों द्वारा न्यय-कर दिया जायेगा । सरकार ने श्राय-कर तथा सुपर-टैक्स की श्राधिकतम दर को सात श्राना प्रति रुपया नहीं किया श्रायांत ४५% से कम नहीं किया जैसा कि डॉक्टर कॉल्डार ने सुकाव दिया था। श्रनजित श्राय पर श्रिधिकतम दर ५४% तथा श्राजित श्राय पर ७७% है। श्राप्तयक्ष करों (जैसे कि उत्पादन-कर, श्रायात कर, विकी कर श्रादि) को भी कम नहीं किया है। ऐसी दशा में व्यय-कर देने वाले सीमित वर्ग पर बहुत श्रिषक भार हो जायेगा। इसिलये यह कर श्रविचत है। (ii) यदि यह मान लिया जाय कि व्यय-कर बचत को बढ़ावा देता है, तो यह बढ़ावा घनी वर्ग के ही लिये होगा, निर्धनों के लिये नहीं श्रीर जैसा कि प्रोफेसर कॉल्डार ने बताया है, यह बढ़े लोगों की धन-राशि के संचय में ही वृद्धि करता है। यह कल्यायाकारी राज्य के उद्देश्यों के श्रनुकूल नहीं है। (iii) यह कर उन लोगों को, जिनकों कि कर-श्रिषकारियों को सन्तुष्ट रखने के लिए सही हिसाब रखना पढ़ेगा, वड़ी किठनाइयाँ उत्पन्न करेगा तथा इससे शासन सम्बन्धी बहुत सी समस्यायँ उत्पन्न होंगी। यह कर श्रिषक श्रसन्तोप उत्पन्न करेगा। इससे उपलब्ध श्रितिक राजस्व—१९५६-५९ (संशोधित) में एक करोड़ हपए श्रीर १९५६-६० (बजट) में भी बही रकम—इस कष्ट को न्याय-संगत सिद्ध नहीं करता।

स्राय (Revenues)

केन्द्रीय सरकार की आय के प्रमुख साधन आय-कर, आयात-निर्यात कर, केन्द्रीय उत्पादन कर तथा ज्यापारिक सेवायें हैं। इनमें से कुछ केन्द्रीय सरकार हारा वस्रुले जाते हैं तथा संघ और राज्यों के बीच में बाँट दिये जाते हैं। भ्राकाल में आय-कर तथा जूट-निर्यात-कर संघ और राज्यों के बीच बाँटे जाते थे किन्तु अब आय-कर तथा कुछ केन्द्रीय उत्पादन-कर बाँटे जाते हैं। ज्यापारिक सेवाओं से केन्द्रीय सरकार को रेलवे, डाक-तार विभाग तथा रिजर्व वैंक के लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है।

श्राय-कर—श्राय-कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया श्रीर वस्ता जाता है तथा भारतीय कर-व्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये श्रन्य कर श्रिषकांशतः श्रम्रत्य हैं तथा गरीनों पर श्रिषक पढ़ते हैं किन्द्र श्राय-कर का भार धनी वर्ग पर श्रिषक पढ़ता है। यह कर-देय च्रमता के श्राधार पर लगाया जाता है। इसका श्र्य यह है कि यह कर भार-वहन करने योग्य कन्धों पर पड़ता है। श्रायात-निर्यात तथा केन्द्रीय उत्पादन-कर जैसे श्रमत्यच्च कर उपभोग के श्रनुसार देने पड़ते हैं श्रतप्त इसका भार धनी वर्ग पर दालना उतना सरल नहीं है। इसके विपरीत श्राय-कर प्रगामी बनाया जा सकता है। श्राय की एक निम्नतम सीमा को कर से छूट दी जा सकती है तथा श्राय श्राय पर कर प्रगामी दर से लगाया जा सकता है। तथा एक सीमा के बाद श्रीकर (supertax) लगाया जा सकता है।

इस प्रकार सर्वाधिक आय वाले व्यक्तियों की आय का अधिकांश केन्द्रीय सरकार स्वयं लेलेती है और अर्जन करने वाले के पास उपभोग के लिए अपेनाकृत कम अंश वचा रहता है। आय कर राजस्व का लचीला साधन है क्यों कि जनता की आय में वृद्धि होने के साथ ही सरकार की आय में भी वृद्धि होती है और जनता की आय में कमी होने के साथ ही सरकार की आय में भी कमी हो जाती है। आर्थिक समृद्धि के समय सरकार की आय-कर से आमदनी बढ़ती है और मंदी के समय यह आमदनी स्वयं गिर जाती है। जैसा कि अपर कहा जा चुका है, आय-कर की आमदनी वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में बाँटी जाती है और इसका उपयोग सन्तुलन स्थापित करने वाले साधन के रूप में किया जाता है।

श्रावश्यकतानुसार श्राय-कर को कम या श्रिधिक प्रगतिशील बनाने के लिये श्राय-कर श्रीर सुपर-टेक्स की दर में परिवर्तन किया जा सकता है, श्रीर श्राय-खरहों का भी पुनस्संगटन किया जा सकता है। एक निश्चित न्यूनतम श्राय पर कर नहीं लगाया जाता। यह न्यूनतम सीमा समय-समय पर बदली गई है श्रीर साथ ही व्यक्तियों तथा कम्पनियों पर लागू श्राय-कर श्रीर सुपर टैक्स की संयुक्त दर में भी परिवर्तन किये गये हैं।

विवादित व्यक्ति दिसकी कुल श्राय २०,००० रु० से श्रधिक न हो

	कि व्यक्ति पर	जब कि व्यक्ति पर	जब कि व्यक्ति पर	()
पूर्णतः या श्रंशतः निर्भर		पूर्णतः या श्रंशतः	पूर्णेवः मा श्रंशतः	कर की
कोई वच्चा न हो		निर्भर एक वच्चा हो	एक से र्श्राधक	दर
			बच्चा निर्भर हो	
	50	₹०	₹•	
पहले	3,000	३,३००	३,६००	
दूसरे	2,000	2,600	१,४००	₹%
तीसरे	२,५००	२,५००	२,५००	٤%
चौये	२,५००	२,५००	२,५००	٤%
पाँचवें	२,५००	२,५००	२,५००	₹१%
छुटे	२,५००	२,५००	२,५००	28%
सातवें	4,000	५,०००	५,०००	१⊏%

श्रायकर पर श्रिधिमार—यदि कुल श्राय ७५०० रु० से श्रिधिक न हो तो कोई श्रिधिमार नहीं लगता। जब श्राय ७,५०० रु० से श्रिधिक हो, तो ऊपर बताई हुई दरों के श्रनुसार जितना भी श्राय-कर हो, उस पर ५% के हिसान से श्रिधिमार लगेगा। यह श्रविभार फेन्द्र के लिये होगा। कुल श्राय ७५०० र० से जितनी श्रविक होगी, श्रविभार उसके श्रावे से श्रविक नहीं होगा।

श्रधि-कर (Super Tax)—२०,००० रु० से श्रधिक की श्राय पर ही श्रधि-कर लगता है।

श्रविवाहित व्यक्ति जिसकी श्राय २०,००० रु० से श्रधिक न हो

	व्यापनाहित ज्या	क कि कि कि	एक स आवना न हा
	पदले	₹0 ₹,600	
•	दूसरे तीसरे	40 x,000	₹%
		च० २,५००	६%
	चौथे	६० २,५००	٤%
	पीचर्वे	६० २,५००	28%
	छठें	इ० २,५००	የሄ%
	सातर्वे	₹0 ¥,000	₹5%

३००० र० से आय जितनी श्रिषक होगी, कर उसके आषे से श्रिषक नहीं होगा।

श्रायकर पर श्रिधभार—याद श्राय ७५०० रु० से श्रिधक न हो तां कोई श्रिधभार नहीं लगता। जब श्राय ७५०० रु० से श्रिधक हो तो ऊपर बताई हुई दरों के श्रनुसार, जितना भी श्रायकर हो, उस पर ५% के हिसाब से श्रिधभार लगेगा। यह श्रिधभार केन्द्र के लिये होगा। कुल श्राय ७५०० रु० से जितनी श्रिधक होगी, श्रिधभार उसके श्राध से श्रिधक नहीं होगा।

ग्रधिकर---२०,००० ६० से ग्रधिक की ग्राय पर कोई ग्रधिकर नहीं लगेगा। वे व्यक्ति जिनकी भ्राय २०,००० ६० से श्रधिक है (चाहे विवाहित हों या श्रविवाहित, चाहे सन्तान वाले हों या नि:सन्तान) श्रायकर की दर

पहले		2,000	रु० पर		_	
दूसरे		8,000	र० पर		₹%	
तीसरे		२,५००	६० पर		६ %	
चीये		२,५००	रु० पर		٤%	
पाँचवें		२,५००	रु० पर		११%	
छटें		₹,५.0	रु० पर	•	88%	
सातवें		4,000	रु पर		85%	
 २०,०००	र० से	ग्रधिक	श्रंश पर		२५%	

श्राय कर पर श्रिधमार—संघ के लिये श्राय-कर की राशि पर ५% की दर से श्रिधमार लगेगा। १ लाख से श्रिधक श्राय होने पर केन्द्र के लिये एक श्रीर श्रिधमार लगेगा जो कुल श्राय पर लगे श्राय-कर तथा १ लाख ६० पर लगे श्राय-कर के श्रन्तर के ५% के बराबर होगा।

श्रधि-कर की दरें

	पदले	२०,००० रु० पर	
	दूसरे	प्र,००० च० पर	4%
	तीसरे	५,००० ६० पर	१ 4%
	चीये	१०,००० च० पर	२०%
	पौचवें	१०,००० च् पर	₹0%
	छुठें	१०,००० ६० पर	14%
	सातर्वे	१०,००० च <i>०</i> पर	¥0%
	90,000	र० से ऋषिक ऋाय पर	४ ५%
-			

अधिकर पर अधिमार—अधिमार निम्न के कुल ओड़ के बराबर लगाया जायेगा:

(१) अधि-कर का ५ प्रतिशत।

(२) कुल श्राय के श्रिषकर तथा १ लाख २० की श्राय के श्रिषकर के श्रन्तर का ५%। यह श्रिषमार संघ के लिये होगा।

उपर्युक्त दशाश्रों में, बीमें की किस्त पर दी गई छूट, कर्मचारी द्वारा प्रावि-डेन्ट-फन्ड के लिए दिये गये श्रंश-दान पर श्राय कर के लिये श्रीसत दर से कर लगेगा। यह कर वेतन के चीयाई माग श्रथवा ८,००० ६० पर में जो भी कम हो, लगेगा। विवाहित व्यक्तियों तथा श्राधितों के लिये दी गई छूट पूरे वर्ष के लिये दी जा सकती है वशर्ते कि यह दशा वर्ष के श्रन्तिम दिन लागू हो।

कम्पनियों के लिये १९५७-५८ के वजट में श्राय-कर की दर कुल श्राय के लिये २५% से वड़कर ३०% कर दी गई तथा निगम कर (श्रिधिकर) की दर १७ से २० प्रतिशत कर दी गई।

१६५७-५८ के बनट में श्राय-कर की सूठ की सीमा न्यक्तियों के लिये ४२०० का प्रति वर्ष से घटा कर २००० का तथा श्रविमाजित हिन्दू परिवारों के लिये ८४०० क्पया प्रति वर्ष से घटा कर ६००० क्पया कर दी गई। श्रव वन्चों के लिये रियायत की जाती है, श्रतएव उस विवाहित न्यक्ति के लिये जिसके एक सन्तान हो श्राय कर से मुक्त श्राय की सीमा ३३०० रुपया प्रति वर्ष, तथा एक से श्रिषक सन्तान वाले व्यक्ति के लिये ३६०० रु० प्रति वर्ष है।

३००० ६० के प्रथम खराड पर कर की निम्नतम दर ३% है तथा अर्जित तथा अन्जित आय पर आयकर व अधिकर (१ लाख ६० से अधिक आय पर अधिकर मी सम्मिलत है) की सम्मिलत अधिकतम दर क्रमशः ७७% व ८४% है। १६५६-५७ तक अर्जित आय पर छूट दी जाती थी जो वेतन का २०% या अधिक से अधिक ४००० ६० होती थी। यह छूट अब नहीं दी जाती है और अर्जित तथा अन्जित आय पर कर की एक हो दर लागू है। किन्तु अन्जित आय पर अब भी अधिक दर से कर लगता है क्योंकि उस पर १५% का विशेष अधिभार देना पड़ता है।

पिछले कुछ वर्षों में मारतीय आयकर न्यवस्था में श्रनेक परिवर्तन हुए हैं परन्तु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन १ अप्रैल, १६३६ में हुआ जनकि आयकर निर्धा-रित करने के लिये श्राय को निश्चित खरहों में विभाजित कर दिया गया श्रीर प्रत्येक खरड के लिये श्रायकर की दर निर्घारित कर दी गई। पहली प्रणाली (step system) के श्रनुसार एक निश्चित न्यूनतम रकम को श्रायकर से छूट दी गई थी परन्तु इस सीमा से अधिक आय होने पर पूरी आय पर आयकर की ऊँची दर लागू कर दी जाती थी। इस प्रणाली के अनुसार उदाहरण के रूप में ५,००० रुपये की श्राय पर श्रायकर की तब की दर के श्रनुसार ३ ४ प्रतिशत कर देना पड़ता था परन्तु ५,३३३ रुपया श्राय पर पूरी श्राय का ५ र प्रितिशत श्रायकर देना पहता था। इसी प्रकार १०,००० रुपया आय पर भ्रं प्रतिशत की दर से श्रायकर दिया जाता या परन्तु १०,६०० रुपया श्राय पर कुल श्राय का ६ द प्रति-शत श्रायकर चुकाना पड़ता था। इससे स्पष्ट है कि श्रायकर की दर में वृद्धि क्रमशः न होकर एकदम हो जाती थी। यदि किसी व्यक्ति की श्राय पहली श्रेणी की श्राय से कुछ मी श्रिधिक बढ़ी तो श्रपनी कुल श्राय पर दूसरो श्रेणी की कर की श्रिधिकतम दर के हिसाब से उसे कर देना पहता था। यह बहुत अनुचित व्यवहार था। इसके साथ ही इस प्रणाली से कुछ भ्रष्टाचार भी फैला। करदाता निम्न श्राय की श्रेणी के श्रन्तर्गत रहने के लिये प्राय: श्रधिक हानि तथा वसूल न होनेवाले ऋण (bad debt) बताया करते ये श्रीर श्रायकर श्रिषकारी उन्हें निम्न श्राय की श्रेशी से दूसरी श्रेगी में लाने के लिए प्रयत्न करते थे। इस प्रगाली से उन लोगों को भारी क्षति उठानी पहतीथी जिनकी श्राय दो श्रेशियों के लगभग मध्य में होती थी। नई खरङ प्रगाली (Slab System) के अन्तर्गत यह दोष दूर कर दिये गये और ५,००० ६१ये श्राय पर कर की तब की दर के अनुसार ३ ३ प्रतिशत श्रायकर

होता है जबिक भ, २२२ रुपया श्राय पर २ ६ प्रतिशत श्राय कर होता है। इसी प्रकार १०,००० रुपये की श्राय पर भ ६ प्रतिशत श्रायकर होता है जबिक १०,६०० रुपये की श्राय पर श्राय की दर ६ प्रतिशत होगी। इससे श्रायकर प्रणाली श्रिधक न्यायसँगत हो गर्या है श्रीर श्रायकर की दर में श्रकरमात परिवर्तन होने का दोप समाप्त हो गया है।

युद्ध काल में आयकर में वृद्धि की गई। नवम्बर, १९४० से सभी आयकरी पर जिनमें कार्पीरेशन कर भी शामिल है २५ प्रतिशत सरचार्ज लागू किया गया। यह सरचार्ज कमशः ६६३ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया । इसके श्रतिरिक्त १६४० मं श्रितिरिक्त लाम कर (Excess Profits Tax) लागू किया गया। यह कर पहली नवस्वर, १६३६ के बाद ३६,००० रुपये से अधिक अतिरिक्त लाम पर ५० मतिशत की दर से लगाया गया। यह दर कमश: ६६३ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। इसके परिणामस्वरूप आयकर श्रीर कार्णोरेशन कर की श्राय १६४४-५५ में १६१ है करोड़ तक बढ़ गई जबकि १६३८-३६ में यह केवल १७ है करोड़ थी। कर की दर में वृद्धि होने से कुल श्राय में विशेष वृद्धि नहीं हुई। इस वृद्धि का वास्त-विक कारण श्रविरिक्त लामकर की श्राय थी। कुल १६१३ करोड़ रुपये की श्राय में ६२ करोड़ रुपया श्रतिरिक्त लाभ कर की आय का था। इतना श्रधिक कर श्रीर विशेषकर अतिरिक्त लाभ कर उद्योगों की कर मार वहन करने की ज्ञमता से श्रधिक या। इसके बाद के वर्षों में सरकार का सदा यह प्रयत्न रहा है कि प्रत्यक्त-कर उस सीमा तक कम किया जाय जो उद्योगों को भार वहन करने की जमता से श्रिधिक न हो। इसके परिणाम स्वरूप १६४४-४५ में श्रायकर करों की कुल ग्राय का ६८ १ प्रतिगत या जो १६४८-४६ में गिरकर ५१ ५ प्रतिशत ग्रीर १६५३-५४ में ३६ र प्रतिशत हो गया।

१६४६-४७ में ३६ लाख रुपये से श्रीधक की अनिर्जत श्राय (unearned income) पर श्रीर ५ लाख से श्रीधक श्रींजत श्राय (earned income) पर कर तथा सुपर टैक्स की संयुक्त दर १५६ श्राना प्रति रुपया थी। १६४७-४८ के लियाकत श्रली खीं वजट में श्राय के उन खरडों का पुनःसंगठन किया गया जिन पर सुपर टैक्स लगाने का विचार था निससे सुपर टैक्स श्रीधक प्रगतिशील हो जाय। १६४६-४७ की १५६ श्राना प्रति रुपया संयुक्त दर ३६ लाख रुपया श्रानित श्राय श्रीर ५ लाख रुपया श्रानित श्राय पर वस्त् की जाती थी जो १६४७-४८ के वजट में कमश: १ र लाख रुपये श्रीर १ ५ लाख रुपये की श्राय पर वस्त् की गई। श्रतिरिक्त लाम कर पहली श्रमें ल, १६४७ से रद्द कर दिया गया। लियाकव श्रली खीं के वजट में इसके स्थान पर व्यापार-लाम कर (Business Profits

Tax) लागू किया गया। यह व्यवस्था की गई कि एक लाख से अधिक व्यापार लाभ पर या कुल लगी पूँजी के ६ प्रतिशत के बरावर या इन दोनों में जो अधिक रकम हो उस पर न्यापार-लाभ कर १६३ प्रतिशत की दर से लगाया जाय । इसके श्रांतिरिक्त इमारतों तथा शेयरी इत्यादि की कीमतों में १५,००० से श्रिधिक वृद्धि (capital gains) होने पर भी कर (Capital Gains Tax) लागू किया गया। पिछले वर्षी में भारत सरकार ने प्रयज्ञ करों को कमशः कम करने की नीति श्रपना रखी थी परन्तु प्रत्यम्ब करों का स्तर बढ़ा देने से सारी व्यवस्था उलट गई। इससे उद्योगों को भारी चति पहुँची ऋीर बचत तथा विनियोग भी कम हो गया। परन्तु सीभाग्य से यह स्थिति अल्पकालिक रही ग्रीर १६४८-४६ के बजट में सुपर टैस्स लागू करने के लिये श्राय-खरहों को पुनःसंगठित किया गया जिससे 👯 लाख क्यें की अर्जित और अनिजेत आय पर आय कर की अधिकतम संयुक्त दर १५ई त्राना प्रति रुपया कर दी गयी। न्यापार लाम कर १६ड्डे प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत कर दिया गया और एक लाख काये की आय की अपेना अब २ लाख हपये की आय तक ब्यापार लाभ कर से छूट दे दी गई। उद्योगों की अनेक रियायतें भी दी गई ख्रीर पयल्ब करों को कम करने की नीति फिर से लागू की गई | ज्यापार लाभ कर को १६४६-५० में रह कर दिया गया । ग्राय-कर श्रीर सुपर-टैक्स के लिए भ्राय के खरडों का पुनरसंगठन किया गया भ्रौर सुपर-टैक्स लागू करने के लिए श्रर्जित श्रीर श्रनर्जित श्राय का श्रन्तर समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष डेढ़ लाख रुपये से श्रधिक आय पर अधिकतम संयुक्त कर की दर १२ई आना प्रति रुपये तक घटा दी गई। इसके पश्चात् स्थिति में निशेष परिवर्तन नहीं किया गया, केवल १६५१-५२ के बजट में आयकर तथा सुपर टैक्स पर ५ प्रतिशत अधिमार लागू किया गया। इसमें कार्पीरेशन कर शामिल नहीं था। जैसा ऊपर बताया जा सुका है, १९५६-५७ तथा बाद के बनटों में आय-कर के सम्बन्ध में विशेष परिवर्तन हुये ।

कर से बचने की प्रवृति—भारत में आय छिपाने की समस्या बहुत गंभीर है। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि करदाता पूरा आयकर चुकता कर दे तो उससे सरकार को कुल जितनी आमदनी हो सकती है इस समय उसका केवल ५० प्रतिशत माग ही वस्तुल किया जाता है नयों कि करदाता अपनी असली आय नहीं बताते हैं। इससे सरकार की आय को भारी श्वति पहुँचती है। कर से बचने के कारण यह है कि (१) अधिकतर मनुष्यों की यह तीन इच्छा होती है कि सरकार को कर न दिया जाय और अपनी वास्तिक आय न वतायी जाय, (२) जनता कर न देने वालों का विरोध नहीं करती है क्योंकि वह इस प्रश्न के प्रति सजग नहीं है। श्राय छिपाना कोई मारी श्रपराध नहीं समका जाता है। प्रायः कर्मचारियों को घोखा देने में सफलता की प्रशंसा की जाती है, श्रीर (३) श्रायकर विभाग में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं श्रीर वह उचित रीति से इस समस्या को इल नहीं कर सकते हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से विभाग का खर्च भी श्रवश्य बढ़ेगा परन्तु कर की वार्षिक श्राय में इस खर्च की श्रपेक्षा कहीं श्रिषक वृद्धि होगी। यदि श्रायकर विभाग का प्रसार किया जाय, कर छिपाने वालों के विरुद्ध जनमत संगठित किया जाय श्रीर कर छिपाने वाले श्रपराधियों को उचित दरह दिया जाय, तो यह बुराई क्रमशः दर की जा सकती है।

भारत सरकार ने १६४७ में आयकर जाँच समिति नियुक्त की जिसने १९५३ के अंत तक आय छिपाने वालों के १०३१ मामलों पर विचार किया और श्रपनी नाँच में लगभग ४६ करोड़ रुपयों से श्रधिक छिपी श्राय का पता लगाया । इस छिपीश्राय पर कर लगाया गया है श्रीर इस प्रकार त्राय छिपाने वालों को दिख्डत करके अच्छा उदाहरण दिया गया है। आयोग के काम पर बहुत अधिक व्यय नहीं करना पड़ा है क्योंकि इस जाँच में जितनी कर की रकम बस्ल हुई ब्यय उधसे कम हुआ है। १६४६ में यह न्यय आयोग द्वारा वस्ता किये गये आयकर का केवल र'न प्रतिशत या परन्तु १६५० में घटकर १'७ श्रीर १६५१ में ७'६ हो गया। श्रायकर जाँच श्रायोग के श्रालोचकों का कहना है कि इससे उन व्यापारियों को वहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है जिनके मामलों पर श्रायोग ५ वर्ष से श्रिधिक समय से विचार कर रहा है। व्यापारियों को सभी काग-जात श्रीर हिसाव-किताव सुरज्ञित रखने पड़ते हैं। परन्तु वास्तविक श्राय छिपाने वाले न्यापारियों के लिए यह उचित ही है श्रीर उनको कठिनाइयों के प्रति कुछ सहातुभूति प्रकट नहीं की जा सकती है। कुछ आलोचकों का मत है कि आयोग के कार्य से उद्योग चेत्र में दुविषा फैली है जो देश के उचित श्रौद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। परन्तु फिर भी श्रालोचकों का यह मत उचित नहीं है क्यांकि इस दुविधा श्रीर मय का कारण जाँच श्रायोग नहीं विकक स्वयं व्यापारी लोग है। श्रालोचकों का यह तर्क युक्तिसंगत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई न्यायालय नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चोर की मय और दुविधा बनी रहती है। श्रारम्म में श्रायोग ने बड़े-बड़े मामलों पर विचार किया श्रीर इनकी समाप्ति के बाद छोटे मामलों पर विचार किया जायगा। जींच ख्रायोग का कार्य-काल ख्रीर त्राने वढ़ा दिया गया है।

आयात-निर्यात कर और उत्पादन कर—केन्द्रीय सरकार के बजट में आयात-निर्यात कर श्रीर केन्द्रीय उत्पादन कर दो प्रमुख अप्रत्यज्ञ कर हैं। युद्ध पूर्व

काल में श्रायात-निर्यात कर की प्रधानता रही है परन्तु युद्ध काल में श्रायात-निर्यात पर श्रनेक प्रतिवन्ध लगने के कारण श्रायात-निर्यात कर का महत्व घट गया श्रीर केन्द्रीय उत्पादन कर का महत्व वहा । १६४३-४४ में श्रायात-निर्यात कर से श्रीर केन्द्रीय उत्पादन कर से कमशः २६.२ श्रीर २७.४२ करोड़ रुपये की श्राय हुई श्रीर १६४४-४५ में क्रमशः ३६:७६ श्रीर ३८:१४ करोड़ रुपये की श्रामदर्ना हुई जबिक १६३८-३६ में केवल ४०.५१ करोड़ श्रीर ८'६६ करोड़ रुपये की श्रामदनी हुई। थी। इस प्रकार युद्ध काल में श्रायात-निर्यात कर श्रीर उत्पादन कर का महत्व बरावर हो गया । इसका कारण यह है कि उत्पादन कर की दर में वृद्धि कर दी गई थी श्रीर श्रनेक श्रतिरिक्त उत्पादन कर लागू किये गये थे। १६४५-४६ में श्रीर इसके बाद श्रायात-निर्यात कर ने फिर से प्रयम स्थान ले लिया। इसका कारण यह है कि इस बीच विदेशी-व्यापार को पुनःसंगठित किया गया है श्रीर श्रायात-निर्यात कर की दर भी बढ़ा दी गई है। श्रायात-निर्यात कर १६५१-५२ तक निरन्तर बहुता गया। १६५१-५२ में इससे २३१ ६६ करोड़ रुपये की श्रामदनी हुई, परन्तु बाद के दो वर्षों से श्रायात-निर्यात कर से श्रादमनी गिरी है। १६५१-५२ में उत्पादन कर से ८५'७८ करोड़ रुपये की आमदनी हुई जो १९५३-५४ में बढकर १३.५५ करोड़ रुपया हो गई।

१६५१-५२ में स्रायात-निर्यात कर से २३२ करोड़ रुपये की स्राय हुई जब कि १६५०-५१ में केवल १५७ कराइ रुपये की श्राय हुई थी। इस वृद्धिका कारण यह है कि आयात किये गये माल की कीमत में वृद्धि हुई और साथ ही निर्यात करों से मी अधिक आगदनी हुई है। १६५३-५४ में आयात-निर्यात कर से केवल १५८ है करोड़ रुपये प्राप्त हुये क्योंकि निर्यात करों में श्रीर विशेषकर जुट के माल पर निर्यात कर में कमी कर दी गई थी। १९५२-५३ में श्रायात-निर्यात कर से केवल १७३ है करोड़ रुपये की ग्रामदनी हुई क्यों कि मँगफली के तेल, कार्डीसीड, निगार सीड ग्रीर ऊन पर से नियात कर हटा दिया गया श्रीर इसके साथ ही कपास श्रीर जूट के माल पर निर्यात कर मं कमी कर दी गई और श्रायात करों में भी कमी कर दी गई थी। इधर हाल के वर्षों में आयात-निर्यात कर से आय बढकर १९५६-५७ में १७३% करोड़ रु०, १९५७-५८ (वंशोधित) में १८३ करोड़ रु०, १९५८-५६ (वजट) में १७० करोइ ६० हो गई । श्रंशतः इसका कारण कुछ करों में दूदि, कुछ नये करों का लगना तथा व्यापार के आकार में वृद्धि है। विविध मदी पर से निर्यात कर हटा लेने या कम करने श्रीर विदेशी विनिमय संकट के फलस्वरूप श्रायात पर पतिवन्य लगने के कारण १९५९-६० में आयात-निर्यात राजस्व कम होकर १३२'७७ करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है।

उत्पादन कर से आय बढ़ी है। इसका कारण यह है कि श्रीवांगिक उत्पादन में श्रीर साथ ही कर की दर में भी वृद्धि हुई है। १६५२-५३ की अपेन्त १६५३-५४ में केन्द्रीय उत्पादन कर में १० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि स्ती कपड़े पर अधिक उत्पादन कर लगाया गया। उत्पादन करों में इसर हाल के सभी बलटों में वृद्धि की गई है। वस्तुत: अप्रत्यन्त-करों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति का मुख्य सहारा उत्पादन-कर ही रहे हैं। इनने प्राप्त श्राय में लगातार वृद्धि हुई है जो इस प्रकार है: १६५३-५४ में ६५ करोड़ रु०, १६५६-५७ में १६०ई करोड़ रु०, १६५६-५७ (बजट) में ३०४ड़ करोड़ रु० श्रीर १६५६-६० (बजट) में ३२७ई करोड़ रुपये से अधिक। केन्द्रीय सरकार की राजस्व व्यवस्था में केन्द्रीय उत्पादन कर का महत्व आशातीत बढ़ गया है। हाल ही में वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय उत्पादन कर की कुल आय में से राज्य सरकार में भाग पाती हैं।

जैसा कि ऊपर कहा जा जुका है कि युद्ध काल में प्रत्यज्ञ कर बहुत श्रिधिक बढ़ गये थे श्रीर युद्धोत्तर काल में इस कर का स्तर कम करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किया गया। इससे यह श्रावश्यक हो गया कि श्रप्रत्यज्ञ करों को बढ़ाया जाय जिससे भारत सरकार श्रावश्यक राजस्व प्राप्त कर सके। भारत सरकार को केवल चालू खर्च चलाने के लिए ही नहीं बल्कि विकास योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के लिये भी राजस्व की श्रावश्यकता होती है श्रीर इस श्रावश्यकता की पूर्ति के लिये श्रप्रत्यज्ञ करों द्वारा श्राविरिक्त राजस्व संग्रहीत किया गया है। इसके साथ ही सुद्रास्कीति रोकने के लिए श्रायात-निर्यात कर श्रीर केन्द्रीय उत्पादन करों से भी श्राविरिक्त राजस्व करों हो यहात करों से भी श्राविरिक्त राजस्व वस्त्व किया जाता है। इन करों से यद्यपि जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई है परन्तु इससे उद्योगों का उत्पादन व्यय भी बढ़ा है। श्रीर फलस्तरूप वस्तुशों की कीमतें भी बढ़ी हैं।

वाणिज्यिक सेवार्ये (Commercial Services)—रेलवे, हाक श्रीर तार, मुद्रा, टक्साल श्रीर रिलर्व वैंक सरकार की श्राय के महत्वपूर्ण साधन हैं। १६३८-३६ में इन साधनों से केन्द्रीय सरकार को २ करोड़ रुपयों की श्रामदनी हुई श्रीर १६४५-४६ में ६० करोड़ रुपयों की श्रामदनी हुई। इस वृद्धि का कारण यह था कि (१) युद्ध काल में रेलवे यातायात बढ़ा था श्रीर (२) रेल तथा डाकन्तार का भाड़ा भी बढ़ गया था। परन्तु इधर कुछ वर्षों से इन कार्यों से होने वाली श्राय कम हो गई है श्रीर प्राय: २० करोड़ रुपयों के लगमग ही सीमित रह गई है क्योंकि मलदूरी वढ़ जाने से श्रीर कच्चे माल का भाव श्रिषक होने से उत्पादन ज्यय बढ़ गया है। यद्यपि कर की दरें बढ़ा दी गई हैं परन्तु वह इतनी नहीं हैं

जिनसे उत्पादन न्ययं की वृद्धि का घाटा पूरा किया जा सके। १९५४-५५ की २७ करोड़ द० की श्राय की तुलना में १९५५-५६ में इन साधनों से श्राय बढ़कर २९ करोड़ रुपये हो गई। इसका कारण टकसाल से प्राप्त श्राय में वृद्धि तथा डाक महस्रल तथा रेलवे की दरों श्रीर किराये का बढ़ना था। १९५६-५७, १९५७-५८ (संशोधित), १९५८-५९ (बजट) तथा १९५६-६० (बजट) में बाणिन्यक सेवाश्रों से प्राप्त श्राय ३९० करोड़ द०, ३७६ करोड़ द०, ३३० करोड़ द० तथा ५४० करोड़ द० ते कुछ श्रिष्ठ थी। यह कहना श्रानुवित न होगा कि मविष्य में इन साथनों से होने वाली वास्तविक श्राय में वृद्धि होगी।

व्यय (Expenditure)

मारत खरकार का न्यय तीन भागों में विभक्त है—प्रतिरज्ञा, नागरिक प्रशासन छीर पूँजी-न्यय (Capital expenditure)। नागरिक प्रशासन के अन्तर्गत अधीनक प्रशासन, ऋण के साधन, यरणाधियों का पुनर्वास, खाद्यानन स्थयस्था इत्यादि शामिल हैं। प्रतिरज्ञा के अन्तर्गत स्थल तेना, जल सेना, वायु तेना, पूर्वि श्रीर स्टोर इत्यादि भी शामिल हैं। इस वर्ग में प्रतिरज्ञा विभाग हारा ही जाने वाली पेन्यानें इत्यादि भी शाती हैं। तीसरे प्रकार के न्यय का उद्देश्य उद्योगों का विकास, रेलवे, विमान, डाक-तार श्रीर योजना इत्यादि को कार्यान्वित करना है। १६३८-३६ में केशल ८५.११ करोड़ क्या न्यय किया गया या जबिक १६५६-६० (वजट) में ७४६ ०६ करोड़ क्या हो गया। इस अविष में प्रतिरज्ञा की जलना में नागरिक प्रशासन पर बहुत श्रिषक न्यय हुशा है। पूँजी न्यय, जिसका वजट (Capital budget) प्रयक रूप से तैयार किया जाता है, १६५०-५१ में ७१.०३ करोड़ रुपये से बहकर १६५६-६० (वजट) में ४७७ ५३ करोड़ रुपये से बहकर १६५६-६० (वजट) में ४७७ ५३ करोड़ रुपये से बहकर १६५६-६० (वजट) में ४७७ ५३

प्रतिरत्ता न्यय—१६५६-६० के वजट में प्रतिरत्ता न्यय २७५ ४२ करोड़ क्ष्या (२४२ ६८ करोड़ राजस्व के मद तथा ३२ करोड़ क्ष्यए पूँजी के मद में) है जो भारत सरकार के कुल न्यय का २५% प्रतिरात है। १६३८-३६ में यह न्यय ५४% प्रतिरात था। इससे प्रस्ट होता है कि प्रतिरत्ता में न्यय कम कर दिया गया है परन्तु किर भी यह बहुत श्रधिक है श्रीर निरंतर यह माँग की जा रही है कि प्रतिरत्ता पर न्यय कम किया जाय। भारत जैसा निर्धन देश प्रतिरत्ता पर इतना श्रधिक न्यय नहीं कर सकता है। परन्तु यह न्यय करना श्रनिवार्य है क्योंकि किसी संभावित श्राक्षमण से देश की रत्ता करने श्रीर देश के श्रन्दर गांति तथा न्यवस्था वनाय रखने के लिये सरकार का उत्तरदायित्व बहुत गम्भीर है। प्रतिरत्ता न्यय में

कुछ कमी हो सकना संमव भी था। परन्तु कोरियाई युढ, काश्मीर की समस्या और पड़ोस के देशों में, विशेष कर पाकिस्तान में, श्रानिश्चित राजनीतिक हिथति होने के कारण भारत सरकार के लिये प्रतिरक्षा व्यय घटाना श्रसम्भव हो गया है।

प्रतिरक्षा व्यय का लगभग तीन चीयाड सना पर ही होता है और जल सेना तथा वायु सेना पर इसके अनुपात में कम क्योंकि ये विभाग अभी अपनी शैशवावस्था में ही हैं। मिविष्य में इन पर व्यय कम होने के स्थान पर बढ़ाया ही लायगा। 'अपितवर्तनशील' व्यय प्राय: पेन्शन आदि देने के सम्बन्ध में किए जाते हैं जो कि सरकार का निश्चित उत्तरदायित्व है। व्यय घटाने की थोड़ी बहुत संमानवना केवल सेना में है। यह कमी (१) सेना की शक्त घटाकर, (२) सारा प्रशासन कार्य आमूल पुनःसंगठित करके और वरवादी तथा अकुशलता दूर करके, और (३) स्टोरों की खरीद में बचत कर के की जा सकती है। इमें भारत की स्वतंत्रता और सुन्जा को संकट में डालकर प्रांतरज्ञा व्यय में कमी नहीं करनी चाहिए। परन्तु यदि स्थित में कोई विशेष परिवर्तन न हो और कमशः प्रतिरक्षा व्यय में कमी की जा सके तो इससे समाज सेवा कार्यों और विकास योजनाओं को शीध कार्यान्वित किय जा सकेगा।

नागरिक प्रशासन व्यय—नागरिक प्रशासन व्यय के अन्गतत (१) नागरिक प्रशासन, अगृण के साधन, राजस्व वस्ली में खर्च, विस्पापितों का पुनर्वास, (२) खाडान्न को खरीदे हुये माव से कम भाव पर वेचकर उपमीक्ता को सहायता (Food subsidies), राज्य सरकारों को अधिक अन्न उपजाओ अनुदान, और (३) विकास योजनाओं पर व्यय इत्यादि शामिल हैं। इनमें से कुछ मदों को कम नहीं किया जा सकता है न्योंकि पञ्च-वर्षीय योजना की वित्तीय आवश्यकता की पृति के लिये और अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये जरूरी हैं। यदि आयिक बचत की श्रीर अधिक ध्यान दिया जाय तो अवश्य ही इन मदों में भी बचत की जा सकती है।

नागरिक प्रशासन में न्यय बढ़ने का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों का प्रसार किया गया है, वेतन समिति की रिपोर्ट के अनुसार वेतन तथा महंगाई भन्ते में वृद्धि हुई है और यात्रा के मन्ते के रूप में तथा अन्य प्रकार के कार्यों में अतिरक्त न्यय भी बढ़ा है। विभिन्न मंत्रालयों ने विना इस बात का विचार किये हुए कि भारत सरकार की विन्त स्थिति पर क्या प्रमान पड़ेगा अपने न्यय को बढ़ा दिया है। भारत सरकार की आर्थिक बचत समिति (Economy Committee) ने सिफारिश की कि कार्यालयों के न्यय में ३५ करोड़ रुपये की वास्तविक बचत की जाय और अन्य मदों पर २ ५ करोड़ रुपये की बचत की नाय

परन्तु विभिन्न मैत्रालयों द्वारा विरोध करने के कारण ये सिफारिशें लागू नहीं की जा सकीं। इसका एक कारण यह भी है कि मैत्रालय व्यय कम करने का महत्व नहीं समसे।

पूँजी-ज्यय (Capital expenditure)—मारत खरकार का कुल पूँजी-विनियोग १६५०-५१ में ७१ ०३ करोइ घपये से बढ़कर १६५६-६० (बजट) में ४७७ ५३ करोइ उपया हो गया। दीर्धकालिक ज्यय की इन मदों का सरकार के चालू बजट पर विशेष भार नहीं पहता है। इन मदों पर किया जाने वाला ज्यय म्रुण तथा मारत सरकार के अन्य कीषों से पूरा किया जाता है। चूँकि देश के आर्थिक साधनों का विकास करने के हित में विभिन्न योजनाओं पर ज्यय करना पड़ता है इसिलये यह अच्छा है कि ज्यय चालू बजट की अपेचा पूँजी बजट से किया जाय। परन्तु १६४६-४६ से भारत सरकार ने मुद्रास्कीति निरोधक उपाय के रूप में पूंजी ज्यय की पूर्ति चालू बजट से करने की नीति अपना रखी है। इससे करदाताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा है जिससे बचत और पूँजी निर्माण में बहुत स्कावट पैदा हो गई है। यदि वित्त मंत्री ने ऐसा न किया होता और पूँजी ज्यय केवल पूँजी बजट के अन्तर्गत ही सीमित रखा जाता तो इसका परिणाम देश के लिए इतना गम्भीर न होता।

केन्द्रीय सरकार के पूंजी बजट में केवल पूंजी ब्यय की मर्दे ही शामिल नहीं हैं बरन् उसमें वे सब ब्यय जो इस प्रकृति के हैं सिम्मलित हैं। सारी स्थित पर विचार करने के पश्चात यह प्रकट होता है कि पूँजी बजट में १६५१५२ में १२४ इह करोड़ क्यये का बाटा हुआ जो १६५३-५४ में बट कर ८६,५० करोड़ क्यये हो गया। १६५७-५८ में यह बहकर ५४५.४५ करोड़ क० हो गया पर यह १६५६-६० (वजट) में कम होकर १६४'०१ करोड़ क० हो गया।

अध्याय ४८

राज्यों की वित्त व्यवस्था

अवीत में राज्यों के वजट की मुख्य विशेषता यह थी कि वह अपे चाकत अपरिवर्तनशील होते थे, उनके आय के साधन पर्याप्त नहीं थे और समाज कल्याण कार्य में प्रति व्यक्ति बहुत कम व्यय किया जाता था। राज्य के बजटों में बचत दिखाई जाती थी परन्तु इसका तारार्य केवल यह या कि आवश्यक कार्यों पर पर्याप्त व्यय नहीं किया गया और सरकारों ने अपनी सीमत आय नागरिक प्रशासन, काचून और व्यवस्था और कुछ सामाजिक कार्य जैसे शिज्ञा, जन-स्वास्थ्य इत्यादि में व्यय किया। पिछले कुछ वर्षों से स्थित बदल गई है। बिकी इत्यादि कर लगा देने से राज्य की आय अधिक परिवर्तनशील हो गई है। इसका एक कारण यह भी है कि राज्यों को केन्द्रीय सरकार से अपूजा तथा सहायता अनुदानों के अतिरिक्त केन्द्रीय आय में भी पहले की अपेजा अधिक माग मिलने लगा है। राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए राज्य ही वास्तविक केन्द्र होते हैं परन्तु उनकी आय के सावन आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है। यदि राज्यों की आय अधिक होती, तो वह अपने राष्ट्र-निर्माण के कार्य की अच्छी तरह संगठित कर सकते थे।

सभी राज्यों के राजस्य व बजटों को मिलाकर देखने से पता लगता है कि १२.७ करोड़ रुपये, ३.१ करोड़ रुपये तथा ५.५ करोड़ रुपये की वचत क्रमशः १९५१-५२, १९५२-५३ श्रीर १९५३-५४ में हुई। इसके बाद से घाटा रहा है। १९५६-५७ में ७७.४ करोड़ रुपये का श्राधिकतम घाटा रहा। इसके बाद से स्थिति सुवरी श्रीर १९५८-५६ (वजट) में केवल ३.७ करोड़ रुपये का घाटा रहा। १९५८-५६ (संशोधित) में १८ करोड़ रुपये की वचत हुई श्रीर १९५९-६० (वजट) में ४ करोड़ रुपये की वचत हुई श्रीर १९५९-६० (वजट) में ४ करोड़ रुपये की वचत हुई। श्रागर राजस्व तथा पूंजी वजट समेत पूरी स्थिति

१. १ नवस्वर, १६५६ के राज्य पुनगँठन के पहले देश में 'क' 'ख' छोर 'ग' श्रेणी के राज्य थे। अब कुल १४ राज्य हैं। दिल्ली छोर हिमाचल प्रदेश श्रव केन्द्रीय केन्न प्रदेश हैं। इनको सर्वोच्चिय में नहीं शामिल किया गया। कच्छ बम्बई का भाग हो गया है। जम्म तथा करमीर की रक्नें योग में शामिल नहीं। उनको अलग दिखाया गया है क्योंकि "बिल्कुल हाल तक वहाँ के वजट पेश होने का तरीका दूसरे नाज्यों से बहुत मिन्न था।"

पर विचार किया जाय तो १९५५-५६ में ५७ करोड़ रुपये, १९५६-५७ में १०४.७ करोड़ रुपये, १९५८-५६ (संशोधित) में ७.२ करोड़ रुपये तथा १९५६-६० (बजर) में ५०,६ करीड़ रुपये का घाटा रहा । १६५७-५८ के संशोधित गजर श्रनुमान में यह घटा कर ४३.७ करोड़ रुपया कर दिया गया नविक बनट में १११-२ करोड़ सबये का घाटे था। इसका कारण यह था कि दितीय वित्त श्रायोग की सिफारिश के श्रवसार राज्य सरकारों की श्रतिरिक्त धनराशि इस्तान्त-रित कर दी गयी थी। फहास्यरूप १६५८-५६ (धंशोधित) में कुल राज्यों के संयुक्त राजस्य दजटनेंगे १८ करोड़ रुपये की बचत हुई श्रीर राजस्य तथा पुँनी बजट दोनों को मिलाकर देखने पर कुल मिला कर ७.२ करोड़ चाये का घाटा निकला। इस संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच काफी श्रन्तर है। जैसा कि तालिका १ के न्यीरे से शत होगा, जहाँ तक राजस्य यगर का प्रश्न है, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बन्बई, राजस्थान, फेरल श्रीर श्रांश्र प्रदेश में घाटा श्राया । दुसरे राज्यों में बचत निकली। लेकिन जहाँ तक राजस्य तथा पँजी बजटों को एक साय लेकर पूरी स्थिति का प्रश्न है आरागम, मद्रास, पंताब तथा पश्चिम र्गगाल में बचत निकली जब कि दूसरे राज्यों में घाटा। इन घाटों का कारण श्रंयतः योजना में श्रातिरिक्त न्यय है श्रीर श्रंशत: कुछ राज्यों में श्रकाल श्रीर खाद्यात्रामाय पर व्यय। उन्छ राज्यों में कुल मिलाकर घाटे छोटे निकले हैं वयों कि उन पर विकास, व्यव योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कम पड़ा है श्रीर श्रंशतः इस कारण से कि केन्द्रीय श्राधिक सहायता से उनको काफी इद तक लाम दुशा है। चैंकि राज्य धरकारों केपास नकद रुपया नहीं रह गया श्रीर मुरहित कोप खत्म हो चुका है इसित्ये इनको मविष्य में श्रपना राजस्व या ऋरा श्रिषक बढाना पहेगा या फिर श्रपना ब्यय घटाना पहेगा।

श्राय

राज्य सरकारों की श्राय के मुख्य साधन (१) कुछ केन्द्रीय करों की श्राय से प्राप्त श्रंश, फेन्द्रीय सहायता श्रन्तवान, (२) उत्पादन कर, िक्की कर इत्यादि, तथा (३) श्रन्य उपायों (non-tax revenues) से प्राप्त की गई श्राय है। श्रम मृत्यु कर (Estate Duty) भी लगाया गया है। यह कर राज्यों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्ल किया नायगा। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न करों का महत्त्व भी भिन्न है परन्तु किर भी सारी स्थित पर विचार करने से एक निश्चित प्रत्वि दिखाई देती है। १६३ द्व-३६ में खरह 'क' राज्यों की श्राय के प्रमुख साथन कमशाः मालगुजारी, उत्पादन कर श्रीर स्टाम्प

तालिका १ १९५९-६० (धजट) में राज्य सरकारों का कुल राजस्व तथा व्यय (करोड़ रुपयों में)

राज्य	कुल राजस्व	कुल राजस्व क्यय	वचत या घाटा	राजस्व तथा पूँजी वजट मिलाने परवचत या घाटा
ग्रान्ध्र प्रदेश	६६'६०	७०.५७	0°₹७	6.80
श्रासाम	३३'०६	२६ ६८	+3.80	40.08
विद्वार	40°08	६५:२१	+ ५′५३	—o'३२
बम्बई	१३४'५३	१३५'५१	<u>۰٬٤</u> ۶	२७° २ ६
केरल	३७•२९	३८०७	0'65	१ ∙०₹
मध्य प्रदेश	५६'४६	યુપૃત્યુદ્	+•'€₹	—१.€•
मद्रास	७२"४६	66.00	+१•३६	+ 2.54
मैसूर	प्र३१३६	प्रश्हर	+0.82	-E.RO
उद्गीसा	२६'द१	२६ ७५	+ 0.08	+0.80
पंजाब	५०'५१	५०'द३	0'37	—्प्र.७६
राजस्यान	३८.८५	३दः२६		•'4'
उत्तर प्रदेश	१०६'२८	१११'१४	१'द६	३'दर्ह
पश्चिम बंगाल	03'00	८१ ६०	—₹÷₹₹	40,82
ं कुल जोइ	- 	प्रश्निह	33.8+	—५० १६५
जम्मू तथा कश्मी	र १२ २५	१० ०६	+7.48	—० २६
				~ ~

कर थे। केन्द्रीय श्रायकर ग्रीर श्रायात-निर्यात कर की श्राय में से राल्यों को बहुत कम श्रंश मिलता था श्रीर विकी कर लागू नहीं था। तब से स्पिति तिल्कुल बदल गई। जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है १६५६-६० में ५३१ करोड़ रुपये के कुल कर राजस्व में से १०० ८० करोड़ रुपया, १०० ५ करोड़ रुपया, ७७ ३३ करोड़ रुपया, श्रीर ७२ ७५ करोड़ रुपया कमशः श्राम विकी कर, भूमि के लगान, श्राय कर के हिस्से, श्रीर केन्द्रीय उत्पादन कर के हिस्से से श्रायेगा। उम्मीद है कि सम्पत्ति कर श्रीर रेल माड़ा कर से, जो पहले नहीं थे, १६५६-६० में कमशः २.५२ करोड़ रुपये श्रीर १० ८७ करोड़ रुपये की श्राय होगी। गैर कर वाला राजस्व (Non-tax Revenue) जैसे राजकीय यातायात, विजली की योजनात्रों, सिंचाई, वन, उद्योग, केन्द्रीय सहायता श्रनुदान श्रीर राजस्व कोप से हस्तान्तरित रकमों से १६५६-६० में ३०२ ८६ करोड़ रुपये की श्राय होगी। इस

प्रकार १९५६-६० में कर राजस्व कुल राजस्व का ६४ प्रतिशत से कुछ कम या जन कि १९५१-५२ में ६९ प्रतिशत था।

मालगुजारी—भारत के राज्य प्रचीन समय से मालगुजारी वस्त करते त्राये हैं। यह कर कृषि के वास्तविक उत्पादन पर लगाया जाता है। १८५५ के सहारनपुर कानून के अनुसार कुल उत्पादन के ५० प्रतिसत से अधिक मालगुजारी नहीं वस्त की जा सकती थी। पिरचम वंगाल, मदास, विहार, उद्दीसा, उत्तर प्रदेश, आसाम और अजगेर के उन चेजों में जहाँ इस्तमरारी बन्दोवस्त लागू है मालगुजारी की दरें निश्चत हमेशा के लिये कर दी गयी थीं। देश के अन्य चेजों में जहाँ इस्तमरारी बन्दोवस्त लागू नहीं है वहाँ पूरी जाँच-पदताल के परचात मालगुजारी निर्धारित की जाती है। यह पैमायश तथा निर्धारण ३० से ४० वर्ष के बीच कराई जाती है। इस अवाली के परिस्थाम-स्वरूप कीमत बढ़ने पर मालगुजारी का मार कम हो जाता है और कीमतें गिरने पर यह भार बढ़ जाता है।

चूँकि मालगुजारी वास्तिविक उत्पादन पर वस्त की जाती है इसिलए यह एक प्रकार से भूमि-कर है। इसका भार भूमि के मालिक पर पढ़ता है। यदि इस का उन्मूलन कर दिया जाय तो इससे लगभग सभी भूमि के मालिकों को लाभ पहुँचेगा। वर्तमान रूप में यह कर वैपम्पपूर्ण है क्योंकि यह कर वास्तिविक उत्पादन पर लगाया जाता है इसिलये भूमि की उत्पादन शक्ति के साथ-साय इस कर की दर में भी परिवर्तन होना श्रमिवार्य है। इस नियम में इस तथ्य की श्रोर प्यान नहीं दिया गया है कि भूमि पर विभिन्न फरलें पैदा की जा सकती हैं जिनकी उत्पादन मात्रा भी भिन्न हो सकती है। इसके साथ ही यह कर सभी पर समान रूप से लागू होता है, बड़े जमींदार श्रीर छोटे किसान में मेद नहीं किया जाता है श्रीर दोनों को समान सोटी दर से कर चुकाना पढ़ता है। इसिलए कर की विपमता को समान्त करने के लिये मालगुजारी व्यवस्था में सुधार करना श्रावश्यक है।

मालगुजारी श्रव राज्य सरकार वसल करती हैं। श्रतीत में यह श्राय का महत्वपूर्ण साधन रहा है। १६ वी शताब्दी के पूर्वार्द में कुल सरकारी श्राय का ७० प्रनिशत मालगुजारी से वसल होता था। इसके पश्चात से इसका महत्व घटा। परन्तु पंचवर्षीय योजनाएँ चालू होते के साध-साथ श्रीधक श्राय की श्रावश्यकता हुई श्रीर भारतीय किसान की स्थिति में कुछ सुनार हुआ। इसने मालगुजारी से श्राय बढ़ी। यह १६५६-६० में १००,४५ करोड़ रुपये होगी जब कि १६५८-५६ में १५,०६ करोड़ रुपये, १:५५५५२ में ४७,६६ करोड़ रुपये थी।

	तालिका २ राज्यों का राजस्व तथा राजस्व व्यय	तार्षिका २ ाजस्व तथा राजस्व ⁵	यय	(H)	A FEET A
	१९५१-५२ (नास्तविक)	१९५५-५६ (संशोषित)	१९५६-५७ (बजट)	१९५८-५६ (बजट)	*を4を-年。 (年925)
राजस्व के साधन :					
[आय पर कर]	30.93 3	m •• ••	\$\$ \$ \$	પ્ર પ્રં	กู้ เก
(१) ज्याय कर का भाग	ກ ິ່ງ ເປັນ	ध्रम्भ	43.4%	3 5. 59	ଅଟି ବ୍ୟ
(२) कृषि आय कर	æ. •••	አ ຄ. ሕ	e 9. h	น้	ั้ง
(३) पेशा कर	90.0	**	go.0	• • •	P
[सम्पत्ति तथा पँजी के सौदों पर कर]	୦ <i>ମ</i> . ୪୭	११२:३९	(१२६ चन	9३११६	938.80
(१) मृत्यु कर	•	% ₩.~	જે	4%	फ़ फ़
(२) मालगुजारी	चेद्रः ९%	E	क के के दे व	इ०.५व	\$ 00 ° 84.
(३) स्टाम्म और रजिस्ट्रेयान	રમ્પ્રફ	२ १८ १८	. ० स. स. स. स.	54.3 6	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
(४) यहरी अचल सम्पत्ति कर	ሉ ። }	≈ •• ••	*3.*	e c. c.	54.5

[मस्तुत्रों तथा सेवात्रों पर कर]	₹8 ₽.€0	१०६,०५	१८०११	ગ્રફ્ધ દૂધ	304.38	
(१) केन्द्रीय उत्पादन कर का भाग	09.0	\$ \$. \$ \$	>.০.১	66.X°	२ ७.५०	
(२) राज्य उत्यादन कर	¥6.%	3 ኢ. ት አ	39.6%	৳৸.১৯	४३.प२	
(३) सामान्य विक्षी कर	0 0 0 2 2 2 3	ह त .श्र	\$ g. • 9	ध सं. संश	\$. .	
(४) मोटर-सिगट तथा विक्री कर		Ŋ ŵ	ភ្ជុំ	0°	१४,४४	
(५) मनोश्जन कर	w m	න ආ් ආ	بر بر دو	ប បំ	ന ന ന	
(६) विजली कर	w m	4 8 8	ŭ. *	# h. n	<i>ଇ</i> ଅ	
(७) मोटर गाड़ी कर	2000	\$4.56	\$ \$ \$ \$	\$ 5.3	ችች ₁ Å &	
(८) रेल भाड़ा कर	0 0 0 0	•	9 9 9	w w	१ ° मि	
(६) अन्य कर तथा ग्रुल्क	इहे चे	\$ 11 11	& o . x	8E'58	२०,६व	
कुल कर राजस्य	अ०.४ घट	389.43	366.03	८७६ .६५	देवनिवर्	
कुल राजस्य	88. 308 8	४६०.४३	४७६०५	४०.२८७	त्य भूभ त	

राज्य उत्पादन कर-संविधान के अनुसार (१) अल्कोहल की शरावी ग्रौर (२) श्रक्तीम, भौंग तथा श्रन्य नशीली वस्तुत्री पर उत्पादनकर लगाने श्रीर वस्ल करने का श्रधिकार राज्यों को दिया गया है। इनके श्रन्य वस्तुश्रों पर उत्या-दन कर लगाने श्रीर वयुल करने का श्रधिकार केन्द्रीय सरकार को है परन्तु यदि संसदीय कानून में व्यास्था की जाय तो इस कर की ग्राय में से केन्द्रीय सरकार राज्यों को भी कुछ भाग दे सकती है। राज्य सरकारों का उत्पादन कर लगाने का उदेश्य श्रांशिक रूप से इन वस्तुश्रों के उत्पादन पर नियंत्रण रखना श्रीर श्रांशिक रूप से न्नाय संग्रहीत करना रहा है। महात्मा गाँघों के नेतृत्व में काँग्रेस ने मदानिपेध नीति स्वीकार की। गाँधी जी का मत था कि राज्य की श्राय के लिए किसी बुरी चीज से लाम नहीं उठाना चाहिये। फलस्यरूप जब प्रान्तीय स्वायत्तता श्रारम्भ होने पर काँग्रेस ने १६३७ में प्रान्तों में श्रानी सरकारें बनाई, तो उन्होंने मदानिषेत्र की योजना लागू की। परन्तु काँग्रेधी मन्त्रिमएडल द्वारा इस्तीफा दे देने पर मद्यनिषेध श्रान्दोलन वन्द कर दिया गया श्रीर छलाहकार-शासन ने इसे प्रायः समान्त हो कर ः दिया । काँग्रेस ने १६४६ में जब पुनः शासन-सत्ता ग्रह्ण की तब सभी राज्यों में मद्यनिषेध की नीति को लागू किया गया । संविधान के एक निर्देशक सिद्धान्त के श्रन्तर्गत मद्यनिपेध की नीति लागू करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर ही है। वित्तीय श्रमाव के कारण केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को १६४८ में सलाह दी कि मद्यनिषेध की नीति लागू करने में कुछ धीमी गति से बहना चाहिये। सरकार की मुद्रास्कीति निरोधक नीति में इससे सहायता मिल सकती थी। कुछ राज्यों, जैसे उदीसा, उत्तर प्रदेश श्रीर विहार, ने केन्द्रीय सरकार की सलाह मान ली परन्त श्रन्य राज्यों, जैसे मद्रास श्रीर वम्बई, ने श्रयनी पूर्ण मश्रनिपेघ नीति को तेजी से न्नागे बढ़ाया । यह योजना इन दो राज्यों में क्रमशः १६४८ स्त्रीर १६५० में लागू की गई थी। मद्यनिषेध की नीति अपने उद्देश्य की पूर्ति में अधकल रही है। इससे राज्य की श्राय कम हो गई श्रीर विना किसी लाभ से इस नीति को लागू करने में व्यय की मात्रा बढ़ी है। शराब पीने की श्रादत छुड़ाई नहीं जा चकती है। इसके विपरीत गैर कानूनी तौर पर शराव वनने लगी है श्रीर श्रन्य स्थानों से निपेध-चेत्रों में चोरी से शराव पहुँचने लगी है। मद्यनिषेध को मंग करने के श्रपराधों की संख्या बढ़ी है। काँग्रेस सरकार ने कानून बनाकर समाज सुधार लागू करने के लिए अपनी श्राय का बलिदान किया है। इस बलिदान के कारण राज्य सरकारी को विवश होकर श्रपनी विकास योजनाश्रों पर ब्यय घटाना पड़ा है जो राष्ट्रीय हित में नहीं कहा जा सकता।

१६५१-५२ ग्रीर १६५५-५६ के बीच राज्य उत्पादन करों से होने

वाली श्राय ४५ करोड़ रुपये के श्रास-पास रही है। लेकिन बाद में यह घटी श्रीर १६५६-५७ (बजट) में यह ४२.७६ करोड़ रुपये, १६५७-५८ (बजट) में ४१.७८ करोड़ रुपये हो गयी श्रीर १६५८-६० के बजट में इसमें ४३.८२ करोड़ रुपये हो जाने का श्रनुमान है। वित्त श्रयोग की सिफारिशों के श्रनुसार श्रव राज्यों को कुछ केन्द्रीय उत्पादन करों से हिस्सा मिल रहा है श्रीर जो १४ दिसम्बर १६५७ में चीनो, तम्बाक् श्रीर स्ती कपड़ों पर बिकी कर हटा देने से श्रीर बढ़ गया है। राज्य सरकारों को १६५६-६० में केन्द्रीय उत्पादन करों के हिस्से के रूप में ७२.७२ करोड़ रुपया (दिखये वालिका २) मिलेगा जबकि १६५८-५६ में ६७.४० करोड़ रुपया, १६५७-५८ (संशोधित) में ३७-४२ करोड़ रुपया, १६५७-५८ में ०,७० करोड़ रुपया श्रीर १६५१-५२ में ०,७० करोड़ रुपया श्रीर १६५१-५२ में ०,७० करोड़ रुपया था।

विक्री कर—िकसी वस्तु के विक्रय श्रीर क्रय पर राज्य सरकार कर लगा सकती हैं। मद्यिनिपेद नीति लागू करने से श्राय में जो कभी हो गई उसकी पूर्ति करने के लिये श्रीर साथ ही विकास योजनाश्रों की विचीय श्रावश्यकता की पूर्ति के लिये बिक्री कर लगाया गया। मद्रास ने सबसे पहले १६३६ में विक्री कर लगाया। वर्तभान समय में वाकी सभी राज्यों में यह कर लागू है। विक्री कर राज्यों की श्राय का मुख्य साधन हो गया है।

विक्षी कर दो प्रकार से लागू होता है। प्रथम प्रणाली 'एक बिन्दु' (Single Point) के श्रन्तर्गत उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुँचने की सारी प्रक्रिया में केवल एक बार विक्षी कर लगाया जाता है। इस प्रणाली के श्रन्तर्गत कर या तो श्रारम्भ में उत्पादक से उत्पादित माल बेचते ही वस्त्त कर लिया जाता है या श्रन्त में फुटकर विक्रेता से उपभोक्ता को माल बेचते समय वस्त्त किया जाता है। दूसरी प्रणाली 'बहुबिन्दु' (Multiple Point) के श्रन्तर्गत विक्री कर विक्री की हर श्रेणी पर लागू होता है। इस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचने की सारी प्रक्रिया में माल पर श्रनेक बार कर वस्त्त किया जाता है। दूसरी प्रणाली के श्रन्तर्गत कर को दर प्रथम प्रणाली की दर से कम रहती है। दूसरी प्रणाली के श्रन्तर्गत कर कम जुराया जा सकता है क्योंकि उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुँचने की प्रक्रिया में कर का जुराया जा सकता है उनकी विक्री का हिसाब प्रथक-प्रथक रखा जाता है श्रीर जिन वस्तुश्रों पर कर नहीं लगाया जाता है उनके विक्रेता तथा उत्पादकों की रजिस्ट्री कर ली जाती है। भारत में दोनों प्रणालियों के श्रनुसार कार्य होता है। दूसरी प्रणाली महास, बम्बई (इसमें प्रणाली महास, बम्बई (इसमें

पहले प्रथम प्रणाली लागू थी), हैदराबाद श्रीर मैस्र में श्रीर प्रथम प्रणाली पिर-चमी बंगाल, पंजाब, मध्य भारत श्रीर दिल्ली में लागू है। उत्तर प्रदेश में कुछ बस्तुश्रों पर प्रथम प्रणाली के श्रमुसार श्रीर श्रन्य पर दूसरी प्रणाली के श्रमुसार कर लगाया जाता है।

मारतीय संविधान में अनुच्छेद २८६ के अन्तर्गत राज्यों के विक्री कर लगाने के भ्रधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। राज्य माल के श्रायात होने की प्रक्रिया में विक्री कर नहीं लगा सकते हैं और न ही भारत से बाहर के देशों की निर्यात करने की प्रक्रिया में ऐसा कर सकते हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय न्यापार में पूर्ण केन्द्रीय नियंत्रण रहता है। राज्यों में परस्यर स्वतंत्र ज्यापार के हित में राज्य अन्य राज्यों में विकने वाली वस्तुऋां पर भी कर नहीं लगा सकते हैं या श्रन्तर-राज्य-व्यापार की प्रक्रिया में भी कर नहीं लगा सकते हैं। संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार जिन वस्तुत्रों को त्रावश्यक घोषित किया गया है राज्य उन वस्तुत्रों पर भी कर नहीं लगा सकते हैं। मारत सरकार ने १९५२ में आवश्यक वस्तु कानून (क्रय-विकय पर कर लगाना और नियंत्रण) बनाया निसमें संविधान के अनुच्छेह १८६ के अन्तर्गत अनेक वस्तुओं को आवश्यक घोषित कर दिया गया। चूँ कि केन्द्रीय सरकार का कानून पिछली अवधि से लागू न होकर घोषणा के समय से ही लागू होता है इसलिये अधिकांश राज्य इन आवश्यक वस्तुओं में से अनेक पर कर वस्तु करते रहे हैं। १४ दिसम्बर, १९५७ से तम्बाकू, चीनी ख्रीर स्ती कपड़ों से बिक्री कर इटा कर त्रतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन कर लगाया गया। फलस्वरूप सामान्य विक्री कर की ग्राय १६५७-५८ (एकाउन्ट्स) में १०७.३७ करोड़ ६पये से घट कर १९५८-५९ के वजट अनुमान में ७५.४६ करोड़ रुपये रह गयी परन्तु १६५६-६० में इसकी १००.८४ करोड़ रुपये तक बहुने की श्राशा है। राज्यों के राजस्व में बिकी कर का एक ऊँचा स्थान है।

कृषि श्राय कर — भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त किये जाने वाले श्राय कर कृषि-श्राय पर लागू नहीं होते हैं। मारत सरकार के १६३५ के कानून के श्रनुसार राज्य सरकारों को कृषि श्राय पर कर लगाने का श्रधिकार मिला। इस प्रकार का कर सबसे पहले विहार ने १६३८ में लागू किया। वर्तमान समय में वम्बई श्रौर पंजाव को छोड़ कर सभी राज्यों में यह कर लागू है। सामान्यतः श्राय की एक न्यूनतम रकम निर्धारित की गई है जिस पर कर नहीं लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह न्यूनतम रकत ३,००० रुपया है श्रौर राजस्थान में ६,००० रुपया है। विहार श्रौर राजस्थान को छोड़कर श्रन्य चेत्रों में कृषि श्राय कर श्राय खएडों पर (Slab System) लागू होता है। इस कर से श्राय १६५१-५२ में

४.३३ करोड़ रुपये से बढ़ कर १६५५-५६ में ५.७४ करोड़ रुपये ख्रीर १६५६-६० के बजट खनुसान में ⊏ ११ करोड़ रुपये हो गयी।

कृषि आय पर केन्द्रीय सरकार के आयकर लागू नहीं होते हैं। यह एक एतिहासिक विपमता है जो भारत सरकार के १९३५ के कानून से स्थाई रूप धारण कर चुकी है। भारतीय संविधान में भी इसको सम्मिलित कर लिया गया है। ध इसका उद्देश्य शायद यह है कि राज्यों को भूमि पर कर लगाने और भूमि से होने वाली आय पर कर लगाने का एक मात्र अधिकार मिल जाय। भारतीय संविधान में इस त्रुटि को दूर कर देना चाहिये था। भूमि अथवा कृषि आय तथा अन्य साधनों से प्राप्त आय में किसी प्रकार का आधारभूत अंतर नहीं है।

मृत्यु कर (Death Duties)—उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर प्रायः सभी देशों में लागू है। भारत में यह कर १५ अवट्टबर १६५३ से लागू किया गया है। संविधान के अनुसार उत्तराधिकार कर कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जायगा और वस्त्ला जायगा और उससे प्राप्त आय राज्यों में वाँट दी जायगी। कृषि भूमि पर भी उत्तराधिकार कर राज्यों द्वारा लागू किया जा सकता है परन्तु राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को इस कर के लागू करने का अधिकार दे दिया है जिसकी आय राज्यों में बाँट ली जायगी।

उत्तराधिकार कानून के श्रनुसार मरे हुये व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर कर लागू किया ला सकता है। यह कर सम्पत्ति की मात्रा के खरडों पर लागू किया जाता है। व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रथम ५० इनार रुपया की सम्पत्ति श्रीर संयुक्त हिन्दू परिवार में हिस्से के सम्बन्ध में ५०,००० रुपया की सम्पत्ति को बिल्कुल छूट दी गई है। कर की दर ५% से धीरे-धीरे बढ़ कर ५० लाख रुपयें की सम्पत्ति पर ४० प्रतिश्चत हो जाती है। इस कानून में श्रनेक छूट दी गई है। यदि मृत्यु के दो वर्ष पहिले दान दे दी जाय (जनता के हित के लिये केवल ६ महीने पहिले ही यदि दान में दी जाय) तो उस सम्पत्ति पर कर नहीं लगाता। श्रन्य छूटें निम्नलिखित हैं—(१) एहस्पी के सामान २,५०० रुपये तक के मृत्य वाले; (२) ऐसी पुस्तकों जो विक्री के लिये नहीं संग्रहीत की गई हैं; (३) गीमा की रकम श्रयवा उत्तरा-धिकार कर देने के लिये सरकार में जमा ५०,००० रुपया तक की रकम; (४) जीवन बीमा की ५,००० रुपया तक की रकम; (५) मृत्यु संस्कार के लिये जमा की हुई १,००० रुपया तक की रकम, श्रीर (६) लड़कियों के विवाह के लिये प्रति

१ इस विपमता को दूर करने को सरकार कमेटी ने सिफारिश की थी। १६५५ में कर जांच श्रायोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।

कन्या ४,००० रुपया की निश्चित की हुई रकम, इत्यादि । जल्दी-जल्दी उत्तरा-चिकार वदलने के सम्बन्ध में भी ५०, ४०, ३०, २० और १० प्रतिशत क्रमशः उत्तराधिकार कर का छोड़ा जा सकता है यदि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु प्रथम व्यक्ति की मृत्यु के एक, दो, तीन, चार और पाँच वर्ष के मीतर हो।

उत्तराधिकार कर से राज्यों की आय १६५४-५५ में ० ५२ करोड़ रुपये से बहु कर १६५६-६० के वजट अनुमान में २ ५५२ करोड़ रुपया हो गई। इस कर से कुल आय केन्द्रीय वित्त मन्त्री की आशा से बहुत कम हुई है।

मनोरंजन कर — सभी राज्यों में मनोरंजन कर वस्त किजा जाता है। साधार एतः कम कीमत के टिकट पर कर की दर कम रहती और टिकट की कीमत में वृद्धि होने के साथ ही कर की दर भी बढ़ती है। मनोरंजन कर से आय १६५१-५२ में ६ १२६ करोड़ रुपये से वढ़ कर १६५५-५६ में ६ १५० करोड़ रुपये और १६५६-६० (बजट अनुमान) में ६.६६ करोड़ रुपये हो गयी। लेकिन देखा गया है कि कर की कँची दरें न केवल सिनेमा उद्योग की प्रगति को रोक रही हैं बल्कि आय वृद्धि भी रोक रही हैं। उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ राज्य दरों को घटाने के प्रशन पर विचार कर रहे हैं। स्थानीय विच्न जाँच समिति (१६४६-५०) ने सिफारिश की कि मनोरंजन कर आय स्थानीय निगमों को दी जानी चाहिये जिससे उन्हें अपना कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकने में किसी प्रकार की किटनाई न उठानी पड़ें। अधिकांश राज्य सरकारों ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। मद्रास में कर वस्ती का व्यय काटकर शेप आय उन स्थानीय निगमों में जिनके चेत्र से कर वस्त किया जाता है बाँट दी जाती है। मैसूर में कुल आय का दर्ध मैं प्रति स्थानीय निगमों में बाँट दिया जाता है। मैसूर में कुल आय का दर्ध मैं प्रतिशत स्थानीय निगमों में बाँट दिया जाता है।

केन्द्र से सहायता—राज्य सरकारों को आयकर के हिस्से के रूप में, जलादन करों से प्राप्त आय के हिस्से के रूप में, अरुण तथा अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार से बहुत सहायता मिलती है। वित्त आयोग की लिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को वास्तविक आयकर का एक वड़ा हिस्सा मिलता है। आरे १६५२-५३ से कुछ केन्द्रीय उत्पादन करों में से भी हिस्सा मिलने लगा है। राज्यों का राजस्त्र और पूँजी ज्यय विशेष रूप से १६५४-५५ से बढ़ गया है और तभी से केन्द्र द्वारा ज्यय में सहायता की मात्रा भी बढ़ गई है। १६५४-५५ के पहिले केन्द्रीय सहायता ३०% और ४०% के बीच रहा करती थी परन्तु इस वर्ष के वाद से ४०% और ५०% के वीच हो गई। करों के हिस्से, अनुदान तथा अरुणों के रूप में राज्यों को केन्द्र से जो धन मिलता है वह १६५१-५२ में १६० करोड़ व्यये से बढ़कर १६५६-६० (वलट) में ६५५५६ करोड़ रूपया हो गया

	सावन
	官
	किये
ام ج	सुलम
त्रात्वक	बिस
,	Æ
•	राज्यां
	ष्ट्र
1	y F

भूर भूभू भूभू १६ (संशोधि १६ (संशोधि १६ (संशोधि संस्थाएँ के		ं गांच ज्यवस्या
करों का हिस्सा अनुदान सुस् योग राजस्व खाता पूँजी कातार योग पर् पर् पर्ट हेह । ७३.३ १६०.१ हेहर १५४.३ १५४.७ १५१.३ १४४.० १५१.६ ४६५.० १५१.३ १५४.० १६१.६ ४६५.० १५१.६ ४६५.० १६६.० १६२.० १८७.७ १६२.० १८७.७ १६२.० १८७.७ १६२.० १८७.७ १८०.७ १८०.७ १८०.७ १८०.७ १८०.० १८०.० १६२.० १८०.० १८०.० १८०.० १६२.० १८०.० १८०.० १८०.० १६२.० १८०.० १८०.० १८०.० १६२.० १८०.० १८०.० १६२.० १८०.० १८०.० १८०.० १८०.० १८०.० १६४.० १८०.० १८०.० १८०.० १६४.० १८०.०	क्षेत्र के एस एस इस्त्री का	स्ता के स्टब्स्ट के स्टब्स के स
करों का दिस्सा अनुदान सुयु योग राजस्व खाता भर् भर् भर्ट हे हे हि॰ ११६० स्१० १६७० भर्ट ७२°६ स्१० ११६० ११६० १६८० भर्ट ७२°६ १५४० २०२°६ ४१७० १६ (संशोधित) ७३°६ १८०°७ २६६०७ १६६०७ १८६०७ ६ (संशोधित) ७३°६ १८२० १८६०७ १८६०७ ६ (संशोधित) १६२० १८०० १८३० १८६०७ ६ (संशोधित) १६२० १८०० १८३० १८६०७ ६ (संशोधित) १६२० १८०० १८३० १८६००० १८६००० १८६०० १८६०० १८६०० १८६०० १८६०० १८६०० १८६०० १८६००० १८६०० १८६०० १८६०० १८६०० १८६००० १८६००० १८६००० १८६०० १८६०० १८६००० १८६००० १८६००० १८६००० १८६००० १८६००० १८६००० १८६००० १८६०००० १८६०००० १८६००००००००००	युन वित्र	2888.0 2888.0 208.2 988.2 1080.0 1080.0 1088.6
केन्द्र दारा सुलम किये गये गावन । पर् पर् पर्ट वर्ग्ड वर्ग्ड पर्ट वर्ग्ड वहुल योग पर्ट पर्ट वर्ग्ड वर्ग्ड पर्ट रहुल वर्ग्ड वर्ग वर्ग्ड वर्ग वर्ग्ड वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग	खावा	
केन्द्र द्वारा सुलम किये गये वाक्ष भरे भरे हेन्द्र हेन्द्र हेन्द्र हेन्द्र भरे ७२°६ हेन्द्र हेन्द्र हेन्द्र भरे ७२°६ भरे हेन्द्र हेन्द्र १६ (संशोधित) ७३°६ भरे हेन्द्र हेन्द्र १७ (बजट) १६२°६ ११०°२ हेन्द्र हेन्द्र १६ (संशोधित) १६२°६ ११०°२ हेन्द्र		1
केन्द्र द्वारा मुलम भर् सर्वेश्व केन्द्रीय वजहों के अनुसार है। करों का दिस्सा अनुस् भर् धरुः हु। प्रभः वर्षः सुरुः दिस्योधित । ७३.६ हु। प्रभः वर्षः वर्षः हु। प्रभः वर्षः वरषः वरषः वरषः वरषः वरषः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वरषः वरषः वरषः वरषः वरषः वरषः वरषः वर		,
करों का हिस्सा भरे भरे भरे धरे धरे हि (संशोधित) ७३.६ १७ (बंबट) १६०.१ ६ (संशोधित) १६२.१ १० (बंबाणित) १६२.१	सुलम किये गये अनुदान ः	at • mr > -
भूर भूर भूर भूर १६ (संशोधित) १७ (बजट) ६ (संशोधित) १९ (संशोधित) १९ (संशोधित)	G : 6	8
Profession and a second	# # #	मित्र) गट्छ) मित्र) मित्र)
***	à 16-3 16-3 16-3 16-3 16-3 16-3 16-3 16-3	१९५२-५३ १९५४-५५ १९५४-५६ १९५८-५८ १९५६-६० १९५६-६०

२. अकिस्मिक निधि तथा अन्य कोष, राज्य ग्यापार के सीचे, राज्यों के ऋषा तथा पेशारी के श्रवाचा समस्त ऋष तथा जमा

राज्यों के कुल ज्यय के अनुपात में यह १६५१-५२ में २६ मितशत से बढ़कर १६५६-६० में लगमग ५१ है प्रतिशत हो गया। रेल माझा कर शुरू होने, चीनी, तम्बाक् सूती कपड़े पर राज्यों से विक्री कर के स्थान में श्रितिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन कर लगने (बस्ली राज्यों को दे दी गयी है), श्रीर द्वितीय दित्त आयोग की सिकारिश के अनुसार साधनों के श्रातिरिक्त इस्तान्तरण से हाल में इसमें वृद्धि हुई है। संचुप में कमीशन की सिकारिश में प्रति वर्ष १४० करोड़ द्वपये के (१५ करोड़ द्वपये के रेल माझा कर को छोड़कर) वितरण की ज्यवस्था है जब कि प्रथम वित्त श्रायोग की रिपोर्ट में श्रीसतन ६३ करोड़ द्वपये की ज्यवस्था थी। श्रानुदानों के श्रन्तर्गत इच्छा पर निर्मर (discretionary) अनुदान श्रव अनुज्छेद २७३ के कानूनी श्रनुदानों से कही ज्यादा महत्वपूर्ण है और श्रनुज्छेद २७५ (१) के श्रन्तर्गत श्रनुदान की रकम केवल ३६.४ करोड़ स्थये होती जब कि कुल श्रनुदान १४६.१ करोड़ स्थये हैं।

इससे यह पता लगता है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं तथा उनके व्यय के बीच पहिले से अब अधिक उचित सामंजस्य है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की आय राज्यों की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से एक हो जाती है और आय की लोच का प्रभाव राज्यों की आय पर भी पर्याप्त मात्रा में पहता है। इसका कुछ प्रभाव केन्द्रीय वित्त-व्यवस्था की योजना पर होगा विशेष कर जबिक केन्द्रीय सरकार के कुल अनुदानों में अपनी इन्छा से दिये हुये अनुदानों और व्यय में हाथ बटाने के रूप में सहायता का अंश अधिक है।

व्यय

राज्य सरकारें श्रापनी श्राय नागरिक प्रशासन में व्यय करती हैं। नागरिक प्रशासन के श्रन्तर्गत सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस इत्यादि, सार्वजनिक निर्माण कार्य श्रीर विकास योजनाएँ सम्मिलित हैं। विकास योजनाश्रों पर राजस्व तथा पूँजी खातों से व्यय किया जाता है। इधर कुछ वर्षों से राज्यों का व्यय बढ़ा है परन्द्र श्रिषकांश व्यय सार्वजनिक निर्माण कार्यों श्रीर विकास योजनाश्रों पर हुआ है।

राजस्व ज्यय (Revenue Expenditure)—समस्त राज्यों को मिलाकर राजस्व खाते का ज्यय १६५१-५२ में ३६२.६८ करोड़ काये से बढ़कर १६५६-६० में ८२९.८९ करोड़ काया हो गया (तालिका ४)। लेकिन विकास ज्यय (१६६.४७ करोड़ काये से बढ़कर ४८०.६६ करोड़ काये) में गैर विकास ज्यय (१६६.४७ करोड़ काये से बढ़कर ३४८.६३ करोड़ काये) की अपेसा ज्यादा वृद्धि हुई है।

राज्य सरकारों के राजस्व खाते का विकास व्यय तालिका ४

								(
8 (S* e) E	\$ m	35.86	8. E.	88.00	:	:	:	E. अन्य विकास मद्
ች의. ১১	55.80	೨೪, 3%	ବାଞ୍-୦%		:	:	:	द, उद्याग तथा प्रतः
かんぱん	40'4'	7 J. J. J.	9 g. 0 9	\$0. \$0. \$0.	:	*	:	क. मारारक जिमाह कार र
9	אל מל מל	カイドの	7	e l	:	4124114	2	
,						3		The same and the s
% %	ر ا ا	B*8%	0 % . 5)	~ w	•	:	:	बिजली योजनाए
₹. \$.	२३.५४	からなる	र्य. ० र	\$ @. @ \$	*	:	•	मिचाई
8 ಕ್ಕಿದ್ಗಳ	48.38	\$ 000 000 000 000	~ e e e e e e e e e	24.E.o	:	:	कारता	क्रांष, पशुपालन तथा चह्नारता
្រាញ	\$0.00 00.00	গ্ৰহ, ২%	४प्पर्	78.22	:	:	[स्थ्य	चिकित्मा तथा जन-स्वास्थ्य
* 4C-33	******	48883	20.40}	m, o	:	:	:	, যিহা
१९५६-६० (मजट)	१९५द-५६ (वजट)	१९५६-५७ (मजट)	१९५५-५६ (संशोधित)	१९५१-५२ (बास्तविक)				ध्यय की मद

१. इसमें मुतकरिक तथा वैज्ञानिक विभागों, उद्धयन, बन्द्रगाह और पायबट की फीस का क्यय शामिल है

लेकिन (क) गैर विकास व्यय की इस वृद्धि ने भी एक इद तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्ट गीत व्यय के लक्ष्यों की पूर्ति करने में राज्यों की ज्ञमता घटा दी है श्रीर इस प्रकार जनता को मिलने वाले लाम को घटा दिया है, (ख) विकास कर्च में जितनी किशायतशारी सम्भव यी उतनी राज्य सरकारों ने नहीं की, श्रीर (ग) नागरिक प्रशासन सेवाश्रों तथा ऐसी हो मदों में गैर विकास खर्च श्रकाल में होने वाले व्यय से कहीं च्यादा बढ़ गया है। १६५१-५२ श्रीर १६५६-६० के बीच जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है सब से व्यादा शिक्ता में बढ़ा। इसके बाद प्रामीण तथा चामुदायिक विकास योजनाएँ, चिकित्सा तथा जन-स्वा-श्य, क्रांप, पश्चपालन तथा सहकारिता श्राते हैं। उद्योग तथा पूर्ति, सिंचाई तथा विकास में कम विकास व्यय हुशा। इस परिणाम पर पहुँचना ठीक होगा कि राज्यों में जनता के लिए खीवघाएँ बढ़ी हैं श्रीर राज्यों के विकास व्यय के फलस्व-रूप देश का काफी श्रायिक विकास हुशा है।

पूँजी ट्यय (Capital Expenditure)—राज्य सरकारों का विकास तथा गिर विकास मदों का कुल पूँजी ज्यय १६५१-५२ में १२७ ५७ करोड़ रुपये से बहुकर १६५५-५६ में २३१ ५६ करोड़ रुपये छीर १६५६-६० में २७६ ७६ करोड़ रुपया हो गया। जिन मदों में पूँजी ज्यय हुआ है वे बहु-धन्धी नदी घाटी योजनाएँ, सड़क यातायात, श्रौद्योगिक योजनाएँ और राज्य ज्यापार हैं। अगर हम पूँजी ज्यय की पूरी स्थित सामने रखें, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अग्रुण और पेशिंगियाँ, स्थायी अग्रुण की अदायगी, केन्द्रीय अग्रुण की अदायगी आदि है, तो पता चलेगा कि कुल पूँजी ज्यय १६५१-५२ में १८५०-६० (वजट अनुमान) में ४६५-६० करोड़ रुपये हो गया।

राज्यों की वित्त व्यवस्था तथा योजना—इसके बावजूद कि राज्य सरकारों ने नये कर लगाये हैं श्रीर वर्तमान करों की दरें बढ़ा दी हैं, वे द्वितीय योजना के लिए १७३ करोड़ रुपये से ज्यादा संग्रह नहीं कर सकते जब कि योजना के लिए २२५ करोड़ रुपये का लक्ष्य है।

जहाँ तक विजली कर तथा शुल्क, मोटरगाड़ी कर श्रीर राज्य उत्पादन करों का प्रश्न हैं राज्य सरकारों ने श्राशा से श्रिषक श्राय की है। कमी माल-गुजारी तथा क्षिचाई कर, विकास कर, सामान्य विक्री कर श्रीर मोटर स्पिट तथा डीजल श्रायल कर में रही है। "राज्यों में श्रित्रिक्त कर लगाने तथा वर्तमान करों में वृद्धि करने के फ्लस्बरूप पाँच वर्षों में १७३ करोड़ रुपये की श्राय का श्रनुमान है। इस प्रकार उनकी योजना के मूल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ५२ करोड़ रुपया श्रीर जुटाना है। महत्व की वात यह नहीं है कि करों द्वारा वे कितना संग्रह करते हैं बल्कि यह है कि उन्हें भोजना के लिए पूंजी जुटाने में राजस्व से कितना मिलता है। राज्यों से श्राशा की गयी थी कि वे इस खोत से कुल ३७० करोड़ रुपया इकहा करेंगे। पहले तोन वर्षों में उनका श्रंश दान करीब १३५ करोड़ रुपया होगा श्रीर पाँच वर्षों की श्रवधि में वर्तमान कर-दर के श्राधार पर यह करीब २६५ करोड़ रुपया होगा। दूसरे शब्दों में, श्रतिरिक्त करों की पाँच वर्षों की श्रवधि की १७३ करोड़ रुपये की सम्मावित श्राय से, जो राज्यों के श्रंश-दान के रूप में है, मूल लक्ष्य की मान्ति होने की सम्मावना नहीं है। यह कमी है बावजूद इसके कि वित्त श्रायोग के निर्णुण के फलस्वरूप १६० करोड़ रुपये का लाम हुशा है और कुछ केन्द्रीय करों के दिस्से के रूप में श्राय में वृद्धि हुई है"।

सितम्बर, १६५८ में योजना में न्यय के पुनः मूल्यांकन के अनुसार, जिससे योजना के मुख्य कार्यक्रमों (खंड क) का न्यय ४,५०० करोड़ रुपये से बह कर ४,६५० करोड़ रुपये हो गया है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि ने दितीय योजना के शेप दो वर्षों में १४० करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त साधन जुटायें यानी ६० करोड़ रुपये अतिरिक्त करों से, ५० करोड़ रुपये ऋगों तथा अल्प बंचतों से, श्रीर ३० करोड़ रुपया गैर-योजना खर्च में किफायत करके संग्रह करें। इसकी आशा करना वैकार है कि राज्य अतिरिक्त करों से ६० करोड़ चपया यहाँ तक कि इसका आधा ही इकटा कर पायेंगे क्योंकि (१) विक्री कर तथा आय कर के हिस्से से कुछ करों को छोड़ कर जिनसे श्रतिरिक्त श्राय पहले ही श्रा चुकी है ऐसे कर नहीं हैं जिन्हें लगा कर राज्य सरकार अधिक अतिरिक्त आय कर एकें, (२) 'संयुक्त कर प्रखाली' लागू करने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये कर पहले ही बहुत बढ चुके हैं और चँकि केन्द्रीय तथा राज्य करों का भार उन्हीं लोगों पर पहला है जो राज्य सरकार की श्रातिरिक्त कर देने में समर्थ हो सकते थे, राज्य सरकारों के कर राजस्य को बढ़ाने की अधिक संभावना नहीं है। कर देने की समता जैसी भी कोई चीज है और यह दिखता है कि विछले कुछ वर्षों में केन्द्र द्वारा कर बढ़ाये जाने के फलस्वरूप वह खत्म ही गयी है, श्रीर (३) विकास कर श्रीर सिंचाई श्रादि के प्रश्न पर राजनीतिक कठिनाई है नयोंकि इनका भार उन्हीं लोगों पर पड़ेगा निनके समर्थन पर सचारूढ पार्टी निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में यह ब्राशा करना तर्कसंगत नहीं कि राज्य सरकारें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए धन जुटाने के लिए अधिक अतिरिक्त राजस्व संग्रह कर सर्केंगी।

स्थानीय वित्त व्यवस्था

भारत में महत्वशाली स्थानीय निकायों, नगरपालिकार्ये श्रीर जिला बोर्ड

है। नगरपालिकार्ये नगरों में श्रीर जिला बोर्ड ग्रामीया देशों में होते हैं। स्पानीय विच जाँच समिति (१६४६-५०) ने श्रनुमान लगाया था कि १६४६-४७ में भारत में कुल नगरपालिकार्ये जिनमें तीन नगर निगम भी सम्मिलित हैं लगभग २'७ करोड़ जनसंख्या की सेवा कर रही थीं। उनकी कुल खोंतों से श्राय २७५ करोड़ रुपया थी निसमें १६ २ करोड़ क्पया अथवा लगमग ७०% करों से प्राप्त आय थी। जिला बोडों की संख्या १७६ थी जो २०५५ करोड़ जन-संख्या की सेवा करते थे। उनकी कुल खोतों से आय १५ ६ करोइ स्पया यी निसमें से ५.२ करोड़ स्पया अथवा ३४% कर से प्राप्त श्राय थी। यह बढ़े खेद की बात है कि बाद के स्थानीय संस्थाश्रों की श्राय श्रीर व्यय के सम्मिलित आंकड़े प्राप्त नहीं हैं और प्रत्येक स्थानीय संस्थाओं के बनटों से आंकड़े इकटे करना बहुत ही दुस्मद कार्य है। जो आंकड़े प्राप्त हैं उनसे दी यह बात स्पष्ट हो नाती है कि स्थानीय निकायों के श्राय के खोत बहुत जीए हैं। यदि उन्हें श्रपना कर्चन्य संतोषपद दंग से करना है तो उन्हें श्रधिक धन की प्राप्ति होती श्रत्यन्त श्रावश्यक है। श्रधिक ज्यय शीर्यों को स्थानीय निकायों से लेकर राज्य सरकारों पर स्थानान्तरित करना एक विपरीत रीति होगी। ये स्थानीय निकाय प्रजातंत्र शासन प्रणाली के सिदान्तों की शिचा देने के लिये वहत ही उपयुक्त देत्र हैं श्रीर स्थानीय कार्यों, जैसे सफाई, पानी की सुविधा इत्यादि के करने के लिये बहुत ही उपयुक्त श्रिषिकारी भी हैं।

स्यानीय निकायों के पास अपर्याप्त आय स्रोतों के न होने का कारण संत्रीय अर्थ प्रवन्यन के अन्तर्गत स्वामाविक केन्द्रीय और राज्य सरकारों की पारस्परिक स्रोतों को अपने अधिकारों में कर लेने की प्रतिद्वन्द्विता है जिसके कारण लोचवाले आय के कोई मी स्रोत स्थानीय निकायों के कार्य में लाने के लिये नहीं वचे हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय निर्वाचित निकाय को कुछ भी थोड़े आय के स्रोत उनके अधिकार में हैं, उनका पूर्ण प्रयोग करने में संकोच करती हैं क्योंकि ये निकाय स्थानीय जनता के मतदान अधिकार पर आधारित हैं इसलिए अधिकांश निकायों ने उन करों का पूर्ण प्रयोग आय बढ़ाने के लिए नहीं किया जिनके आरोप का अधिकार उन्हें प्राप्त है। बहुधा आय की एक बड़ी मात्रा तिना वस्ली पड़ी रह जाती है। किसी सीमा तक कर वस्ल करने वाले कर्मचारियों की अज्ञमता और किसी सीमा तक सम्बन्धित लोगों के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण ऐसा होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस ओर सुधार होना चाहिए। यदि आवश्यक समक्ता जाय तो राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में देख-रेख की ला सकती है।

"भारत में स्थानीय रांजस्व की श्रलग करने का सिद्धान्त सर्व प्रथम

१६१६ के भारत सरकार कानून में शामिल किया गया था श्रीर श्रनुस्चित-कर-नियम के श्रन्तर्गत कुछ कर सिर्फ स्थानीय निकायों के लिये श्रलग से सुरिक्त कर दिये गये थे। भारत के नये संविधान में स्थानीय करों की कोई सूची श्रालग से नहीं रखी गयी । इसलिए इस बात की बार-बार माँग हुई है कि संविधान में संशोधन किया जाय जिससे संविधान की सातवीं अनुसूची में कानूनी अधिकारों की एक पृथक स्थानीय सूची शामिल कर ली जाय श्रीर स्थानीय राजस्य की प्रयक व्यवस्था की जाय: लेकिन १९४६ में नियुक्त स्थानीय वित्त जाँच समिति ने इस माँग को नहीं स्वीकार किया। इसने सिफारिश की कि कर राजस्व के निश्चित स्रोत श्रलग कर लिए जायें, श्रीर यह सुकाय दिया कि यह काम एक समक्रीते द्वारा हो। उसने सिफारिश की कि एक कर (माल श्रीर मुसाफिरों पर सीमा कर) केन्द्रीय सूची से ब्रीर बारह कर राज्य सूची में से निकाल कर सुरक्तित कर दिये जायेँ। कर जाँच श्रायोग (१९५३-५४) ने भी संविधान में संशोधन करने की माँग स्वीकार न की लेकिन उसने इस बात की जोरदार सिकारिश की कि कुछ विशेष कर स्थानीय निकाय ही लगायें या उनके लिए लगाये जाँय श्रीर श्रगर इस समय राज्य सरकारें श्रपने लिए इनमें से किसी कर को वस्ल कर रही. हां. तो वे धोरे-घोरे उसे छोड़ दें श्रीर इस बीच उसकी श्राय सम्बद स्थानीय निकायों के नाम कर दें? ।

स्थानीय वित्त जाँच समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्थानीय निकार्यों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सम्पत्ति पर भी कर लगाने का श्रिधिकार होना चाहिए या उसके बदले उनको अंशदान मिलना चहिए।

श्रार्थिक कठिनाइयों तथा विकास योजनाश्रों के विस्तार के कारण राज्य सरकारों ने स्थानीय वित्त जाँच सिमित की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

⁽१) रेल,बायु अथवा समुद्ध द्वारा लाये व्यक्तियों और वस्तुओं पर सीमा कर (Terminal tax); (२) भूमि और भवनों पर कर; (३) कान खोदने के अधि-कार पर कर; (४) वस्तुओं के स्थानीय चेत्र में प्रवेश करते ही कर चाहे वे उपयोग के लिये हों अथवा किसी और काम के लिए या वेचने के लिए हों; (५) विजली की विक्री पर कर; (६) विज्ञापन पर कर; (७) वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के सदकों अथवा निवयों द्वारा लाये जाने पर कर; (८) उन यानों पर कर जो यंत्रों से नहीं चलाये जाते; (६) जानवरों और नावों पर कर; (१०) प्रवेश कर (Toll tax); (११) व्यवसायों, व्यापारों, तथा कारोबारों पर कर; (१२) प्रति व्यक्ति पर कर (Capitation tax), और (१३) मनोरक्षन कर।

केवल मदास में मनोरखन कर से प्राप्त आय स्थानीय निकायों को बाँट दी जाती है।

जिला बोटों के श्राय का मुख्य खोत मालगुजारी पर लागू उपकर है जो कि राज्य सरकार मालगुजारी के साथ उनके लिए वसूल करती हैं। इस उपकर की दर ६३% से १२६% तक बदलती रहती है श्रीर यही इस उपकर की कानून द्वारा निर्वारित न्यूनतम श्रीर श्रधिकतम सीमा भी है।

नगरपालिकायें निम्न कर लागू करती हैं; (१) चुझी अथवा सीमा कर; (२) सम्पत्ति कर; (३) पेशा कर; (४) यात्रियों, घरेलू नौकरों, कुत्तों, साइकिलों आदि पर कर; और (५) लाइसेन्स कर । कुछ नगरपालिकाओं को जलवायु, विजली अथवा गीस की सक्षाई, नगर वस अथवा रेल सर्विस से आय प्राप्त होती है। इस प्रकार की जनता के हित की सेवाओं से दुहरा लाभ हो सकता है। उनसे जनता को मी लाम होता है और स्थानंथ निकायों को वित्तीय सहायता मी पहुँचती है।

स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों से सहायता श्रनुदान भी प्राप्त होते हैं। ये श्रनुदान बहुधा किसी विशेष कार्य के लिए या विशेष शतों पर दिये जाते हैं।

श्वध्याय ४६ प्रथम पंचवर्षीय योजना

नियोजन का तात्वर्य यह है कि देश के उपलब्ध साधनों का नियमबद रूप से उपयोग फिया जाय श्रीर इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोग्। श्रपनाया जाय जिससे उत्पादन बढ़े, राष्ट्रीय लामीश बढ़े, रोजगार श्रीर सामाजिक कल्यास में वृदि हो। इसके लिये यह श्रावश्यक है कि उपलब्ध साधनों की सावधानों से र्जीच परल को जाय श्रीर राष्ट्रीय उत्पादन श्रीर श्राय में निर्वारित वृद्धि करने के लिये इन साधनों के उपयोग की गति को भी नियोजित किया जाय। भारत की प्रयम पंचवर्षीय योजना १६५१-५२ में लागू हुई श्रीर १६५५-५६ तक पूरी हो गई। इस योजना पर ५ वर्ष में २,०६९ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। व्यय की मात्रा निर्धारित करने में योजना आयोग ने इन वातों पर विचार किया कि (१) विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का समारंग किया जाय जिसके श्राधार पर भविष्य में श्रीर बड़ी योजनाश्रों को कर्यान्त्रित किया जा सके: (२) विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए देश को कुल कितने साधन उप-लन्य हो सकते हैं; (३) विकास की गति श्रीर निजी तथा सरकारी चेत्र के श्रन्तर्गत साधनों की श्रावश्यकता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो, (४) योजना लागू होने के पूर्व केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई विकास योजनाओं को पूरा किया जाय श्रीर (५) युद तथा देश विभाजन से देश की श्रव्यवस्थित श्चार्यिक न्यवस्था को सुनियोजित श्राघार प्रदान किया जाय।

भारत की द्यापिक स्थित में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या में प्रतिवर्ण १ प्रे प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस तथ्य पर ख्रीर देश के सभी उपलब्ध साधनों पर विचार करने के पश्चात् योजना श्रायोग ने यह व्यवस्था की है कि १९७७ तक वर्षों में प्रति व्यक्ति की श्राय दूनी हो जाय। भारत की श्रपेक्षा श्राधिक विकसित देश में प्रति व्यक्ति की श्राय दूनी करने में कम समय लगेगा परन्तु भारत जैसे निखड़े देश में इसमें श्रानिवार्यतः श्रिषक समय लगेगा क्योंकि देश में साधनों की कमी है, टेकनिकल कुशलता का श्रभाव है श्रीर संगठन की स्थिति कमजोर है। मारत में प्रति व्यक्ति श्राय दूनी करने के लिए अनेक पंचवर्षीय योजनाशों की श्रावश्यकता पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारत सरकार ने इस दिशा में कार्य श्रारम्म कर दिया है। समय के साथ कार्य की गति भी जीर पकड़ती जायगी।

पूजी निर्माण की गृति—योजना श्रायोग ने यह माना है कि श्रापारभूत वर्ष १६५०-५१ में भारत की राष्ट्रीय श्राय ६,००० करोड़ रुपया थी श्रांर छल राष्ट्रीय श्राय का श्रीवतन ५ प्रतिशत बचत की जाती थां। इसका ताल्प्य यह है कि १६५०-५१ में सारी जनता की छल बचत ४५० करोड़ रुपया थी। यह १६५१-५२ श्रीर १६५५-५६ के दीच प्रांत वर्ण २० प्रतिशत श्राविरक्त श्राय पूँजी निर्माण में लगा दी जाय, श्रयांत मशीन इत्यादि श्रीर काफी समय तक चलने वाले सामानो पर रुपया लगाया जाय तो पंचवर्णीय योजना के श्रेत तक भारत की राष्ट्रीय श्राय १०,००० करोड़ रुपये तक बढ़ नायमी श्रीर बचत की दर भी ६३ प्रतिशत वाणिक हो जायगी। १६५५-५६ में इस प्रकार छल ६ ५५ करोड़ रुपया राष्ट्रीय बचत होगी। योजना श्रायोग ने दताया है कि इसके पाद १६६७-६८ में समाप्त होने वाले १२ वर्षों में केवल २० प्रतिशत नहीं बल्जि ५० प्रतिशत श्राविरक्त राष्ट्रीय श्राय प्रतिवर्ष वर्षों निर्माण में लगाई जानी चाहिये। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो १६७७ तक प्रति व्यक्ति की श्राय (Per capita income) दो गुनी हो नायगी।

प्राथमिकता का कम-राष्ट्रीय श्राय में उत्त-लिशित वृद्धि करने के लिए प्रतिन्यक्ति की श्राय दोशुनी करने के लिए संशांधित योगना में २,३५६ करोड़ रुपया विकास योजनाश्री में व्यय करने का निश्चय किया गया। योजना में भारतीय श्रार्थिक व्यवस्था को सरकारी तथा निजी उचीग होत्र में विभाजित किया गया है। सरकारी चेत्र में वह उद्योग समिलित है जिनका गालिक स्वयं सरकार हैं, जिन पर फेन्द्रीय या राज्य सरकार श्रयवा इन सरकारों के श्राधीन श्रधिकारियों का नियंत्रण है। निजी उद्योग चेत्र में वह उद्योग, वाणिव्य छौर व्यापार शामिल हैं जिनके मालिक उद्योगपित हैं, जिन पर उनका नियंत्रण है ग्रीर जिनका संवा-लन स्वयं इन्हीं उद्योगपांतयीं द्वारा होता है। इन दोनी उद्योग होती की समस्याएँ प्रायः समान हें श्रीर दोनों को श्रेणियों में स्पष्ट विशेषताश्री के श्राधार पर विभक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु सुविधा की दृष्टि से पंचवर्षीय योजना में इन दोनों उद्योग चेत्रों पर प्रथक रूप से विचार किया गया है। सरकारी उद्योग चेत्र के लिए कुल लागत की भात्रा निर्घारित कर ली गई है और इस चेत्र की वित्तीय श्रावश्यकता सरकार पूरी करती है परन्तु निजी उद्योग स्नेत्र के निर्घारित लक्ष्य के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ, न कह कर केवल सामान्य लक्ष्य बता दिया गया श्रीर इस लद्य की पूर्ति तथा श्रावश्यक वित्त जुटाने के लिए भी उद्योग क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। सरकारी उद्योग होत्र में लक्ष्य की पूर्ति सरकार का प्रत्यच उत्तरदायित्व है परन्तु यही बात निजी उद्योग चेत्र में लागू नहीं होती

है क्योंकि निजी उद्योग होत्र में सरकार अमत्यज्ञ रूप से सहायता प्रदान करती और कारोबार के परिणामों का निरीज्ञण करती रहती है। इसके मूल में यह विचार निहित है कि यदि निजी उद्योग होत्र निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है और उसकी प्रगति अपेज्ञित गति नहीं हो पाती है तो सरकारी उद्योग का कार्य होत्र बढ़ जायगा और सरकार इन निजी उद्योग होत्र की विभिन्न इकाइयों का कार्य भार धीरे-धीरे स्वयं प्रहण कर लेगी। कुछ समय तक सरकारी और निजी होत्र दोनों ही रहेंगे।

पंचवर्षीय योजना के प्राच्य में जो जुलाई १६५१ में प्रकाशित किया गया था श्रीर स्वयं पंचवर्षीय योजना में जो दिसम्बर १६५३ में संसद के सामने प्रस्तुत की गई यी क्रवि विकास को प्राथमिकता दी गई है और इसके बाद यातायात तथा संचार, समाज सेवा कार्य श्रीर उद्योग को रखा गया है। पंचवर्षीय योजना की यदि योजना के प्रारुप से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि योजना के श्रंतिम रूप में उद्योग के महत्व को कुछ श्रधिक बढा दिया गया है पर इससे योजना का प्राथमिकता क्रम नहीं बदलता है। योजना के अंतिम रूप में क्रांप, सिचाई श्रीर विजली की लागत कुल लागत का ४३'२ प्रतिशत रखी गई, याता-यात तथा संचार की लागत २३.६ प्रतिशत, समाज सेवा कार्यों पर व्यय की लागत २२.६ प्रतिशत श्रीर उद्योग की लागत केवल ७ ६ प्रतिशत रखी गई थी। योजना आयोग ने कृषि को आधिक महत्व प्रदान करने के कारणों पर प्रकाश ढाला है | स्रायोग का मत है कि खाद्यान श्रीर कच्चे माल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने से उद्योगों के तीन विकास की संभावना नहीं है। सबसे पहले यह श्रावश्यक है कि श्राधिक स्पिति के मूल को हह किया जाय, कृषि चेत्र में पर्याप्त श्रितिरिक्त खाद्यान्न तथा कच्चा माल पैदा किया जाय श्रीर अन्य चेत्रों का कार्य श्रागे बढ़ाने में उसका उपयोग किया जाय। इसी उद्देश्य के कारण कृषि को प्रायमिकता प्रदान की गई है। संशोधित योजना में यद्यपि कुल व्यय बढाकर २३५६ करोड़ रुपया कर दिया गया फिर मी प्राथमिकता के कम में कोई विशेष परिवर्तित नहीं किया गया है।

जहाँ तक श्रौद्योगिक चित्र का सम्बन्ध है प्राथमिकता निर्धारित करते समय इन वार्तो पर विचार किया गया है कि (१) जूट और प्लाईवृढ जैसे उद्योगों (Producer goods industries) की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय और उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले उद्योगों, जैसे सूती कपड़ा, चीनी, साबुन और वनस्पति उद्योगों की भी वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (२) लोहा और इस्पात, एल्यूमोनियम,

विमेंट रसायनिक खाद, भारी रसायनिक, मशीनों के श्रीजारों इत्यादि उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जाय, (३) उन श्रीद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाय जिन पर काफी पूँजी लगाई जा चुकी है श्रीर (४) जिप्सम से गन्धक, विशेष प्रकार के रेशम का उत्पादन करने के लिए श्रावश्यक सामग्री, श्रीर श्रलीह धातुत्रों के टुकड़ों का उत्पादन करने के लिये नये कारखाने स्थापित किये जायँ जिससे नहे श्रीर श्रात्यन्त महत्व के उद्योगों के लिए श्रावश्यक कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। प्राथमिकता का यह क्रम यह प्रकट करता है। कि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जायगा श्रीर किसी भी उद्योग के प्रति उदाधीनता नहीं श्रपनायी जायगी। राज्य श्रनेक कारखाने स्थापित कर सकते हैं परन्त कृषि के विपरीत उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी उद्योग चेत्र के हाथों में छोड़ दिया गया है। कृषि तो सरकारी उद्यंग त्रेत्र के श्रन्तर्गत श्राता है। पंच-वर्षीय योजना में ४२ उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित किये गये ये श्रीर यह अनुमान लगाया गया था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाँच वर्ष में कुल २३३ करोड़ रुपया व्यय करना पड़ेगा। इसके साथ ही कारखानों के श्राद्यनिकीकरण में श्रीर मशीनों को बदलने में १५० करोड़ रुपया श्रीर व्यय होगा। यदि इसमें चालू पँजी की रकम भी जोड़ दी जाय तो पता चजेगा कि पाँच वर्ष में केवल उद्योग ही की वित्तीय त्रावश्वकता ७०७ करोड़ रुपये के वरावर होगी। इस वित्तीय स्रावश्यकता की पर्ति सरकार नहीं करेगी। इसके लिए निजी उद्योगों को स्वयं प्रयत्न करना पहेगा ।

वित्त-योजना को उफल बनाने के लिए उनसे महत्वपूर्ण वात यह है कि वित्तीय आवश्यकता पूरी करने में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। कृषि तथा औदी-गिक साधनों का विकास करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी लगाने की आवश्यकता है। यदि यह पूँजी देश के अन्दर ही प्राप्त नहीं होती तो इसके लिए हमें विदेशी लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। मारत की पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वर्तमान आय में से बचत, भारतीय रेलवे की आय में से बचत, भारतीय रेलवे की आय में से बचत, भ्रमण तथा जनता की बचत और विदेशी पूँजी पर निर्मर करती है। योजना के ज्यय की पूर्ति करने के लिए मारत के पीएड पावने, विदेशी सहायता और भ्रमण पर भी पूरा विचार कर लिया गया है। इन सारे साधनों का उपयोग कर लेने के चाद भी कुछ कभी रह जाती है लिसकी पूर्ति के लिए यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त कर लगाकर या स्वदेशी बाजार से अधिक मात्रा में भ्रमण लेकर इस कभी को पूरा किया जायगा परन्तु यदि ऐसा संभव न हो सका तो पंचवर्षीय योजना की लागत में इतनो रकम की कमी कर दी जायगी।

योजना की कुल लागत २,०६६ करोड़ रुपया थी; सरकारी तथा निजी बचत से पाँच वर्ष में १,२५८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबकि इन्हीं छोतों से योजना के मूल वर्ष १६५०-५१ में २२२ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। १,२५८ करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि में से ७४० करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों श्रीर रेलवे बजट की श्रितिरिक्त श्राय से प्राप्त होंगे श्रीर ५१८ करोड़ रुपया निजी बचत से। संशोधित योजना में बजट से प्राप्त श्रीय में श्रीर व्यक्तिगत बचत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि श्राशा की जाती है कि ७४३ श्रीर ५१८ करोड़ रुपये क्रमशः होगी। बढ़ी हुई लागत श्रिधिकांश घाटे के श्रर्थ प्रवन्धन द्वारा पूरी की जायगी जैसा कि कभी की मात्रा में ६८८५ करोड़ रुपया बढ़कर हो जाने से प्रतीत होता है। यह श्राशा की जाती हैं कि पौरड पावने से प्राप्ति को विचाराधीन रखते हुये यह कभी ७०१ करोड़ रुपये की रह जायगी।

योजना को अंतिम रूप देने के पहले मारत को विदेशों से सहायता श्रीर श्रूण के १५६ करोड़ रुपया मिला था। योजना श्रायोग ने इसे भी सम्मिलित कर लिया। योजना में यह व्यवस्था भी की गई थी कि घाटे का बजट बढ़ाकर २६० करोड़ रुपयों की श्रीर पूर्ति की जाय। इसके बाद भी ३६५ करोड़ रुपयों की पूर्ति शेष रह जाती है। यह बहुत संभव है कि यह कभी श्रीर श्रिषक हो यदि राज्य तथा निजी बचत की स्थिति श्राशा के श्राकुल न रही।

यदि सारी स्थिति पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि सरकारी चेंत्र
में जो कुल २,०६६ करोड़ रुपये की लागत रखी गई है उसमें से दीर्घकालिक व्यय
(Capital expenditure) केवल १,६०० से १,७०० करोड़ रुपये के बीच में
होगा। यदि इसमें निजी उद्योग चेत्र में लगायी गयी पूँची को भी मिला लिया
जाय (जिसमें उद्योग, वािश्वय क्रीर व्यापार में लगी पूँची भी सम्मिलत है) तो
पाँच वर्ष में स्वदेशी छोतों से ही दीर्घकालिक व्यय की २,७०० से २,८०० करोड़
हत्ये की राशि पूरी करनी पड़ेगी। यदि इसमें इसी अविष में पौरड पावने की मद
में से मिलने वाले २६० करोड़ रुपये (जो मारत में घाटे की बजट व्यवस्था का
ब्राधार हैं) श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अमेरिका, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
हत्यादि से मास १५६ करोड़ रुपया जोड़ा जाय तो कुछ साधन ३,१५० से ३,२५
करोड़ रुपयों के बीच हो जाते हैं। संशोधित रूप में यह धनराशि ३३६०-३४३०

; आलोचना—पंचवर्षीय योजना में भारत के कृषि तथा श्रौद्योगिक विकास के सम्बन्ध में बड़ा श्राशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। श्राँकड़ों के श्रमाव श्रौर साधन ंकी कमी के कारण इससे श्रम्छी योजना तैयार करना संमव नहीं था। योजना पूर्ण होने पर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगी, आय बढ़ेगा और जनता अधिक धनवान श्रीर प्रथम हो सकेगी, भारत के श्रार्थिक विकास में जो किमयाँ हैं उन्हें दूर किया जा सकेगा, खाद्यान में देश निरन्तर स्वावलम्बी बनता जायगा श्रीर कुछ कब्चे मालों का जिनके लिये देश आयात पर निर्भर है, उत्पादन बढ़ेगा। योजना में वैज्ञानिक प्रगति श्रीर टेकनिकल शिच्यण की श्रावश्यकता को भी महत्व दिया गया है। इन पर उद्योग श्रीर कृषि की सफलता निर्भर करती है। वैज्ञानिक लाँच-परख, टेकनिकल शिच्यण इत्यादि के लिये भी योजना में विशेष व्यवस्था की गई है। कुछ समय बाद इसका प्रभाव प्रकट होगा।

यह ब्रालोचना की गई है कि पाँच वपों में योजना को कार्यान्त्रित करने के लिए आवश्यक वित्त के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना ने बहुत आशावादी दृष्टि-कोण श्रपनाया है श्रीर जनता से बहुत श्राशा की है। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि (क) योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि ५ वपों में केन्द्रीय सरकार के बजट, राज्य सरकारों के बजट और रेलवे से क्रमश: १६० करोड़ रुपया, ४०८ करोड़ रुपया श्रीर १७० करोड़ रुपया श्रतिरिक्त प्राप्त होगा परन्तु इस मात्रा में अतिरिक्त आय होना समन नहीं है। जनता में अन और अधिक कर देने की चमता नहीं है श्रीर रेलवे तथा करकारों की श्राय भी अतनी श्रीधक होना संमव नहीं है जितनी की योजना में अपेजा की गई है। इसका तालर्य यह है कि पंचवर्षीय योजना श्रपने मूलरूप में कार्यान्वित नहीं हो पायेगी श्रीर उसमें काट र्छाट करनी पड़ेगी। (ख) योजना में यह माना है कि १६५१ ग्रीर १६५६ के बीच पति वर्ष अतिरिक्त आयं का २० प्रतिशत पूँची निर्माण में लगाया जायगा और १६५६ से १६६८ तक अविरिक्त आय का ५० प्रतिशत इसमें लगाया जायगा। मारत जैसे निर्घन देश में जहाँ की अधिकतर जनता की श्राय श्रपने जीवन निर्वाह के लिए ही प्रयन्ति नहीं है अतिरिक्त आय का इतना अधिक अंश पूँजी निर्माण में लंगा सकने की आशा करना वास्तविक स्थिति के अनुकुल नहीं है। यदि जनता की आय बढ़ती है तो वह उसको विनियोग में लगाने की अपेद्धा उपयोग में व्यय करना श्रमिक पसन्द करेगी। यदि ऐसा होता है तो योजना श्रायोग की यह आशा कि १६५६ तक कुल राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये तक वढ़ जायगी श्रीर १६७७ तक प्रति व्यक्ति की आय दूनी हो बायगी, पूरी नहीं हो सकती है।

इन श्रालोचनाश्रों में कुछ सत्य श्रवश्य है परन्तु यह योजना का श्राधार भूत दोप नहीं हैं। किसी भी योजना की श्रालोचना में यह तर्क दिये जा सकते हैं। नियोजन के लिए यह श्रावश्यकीय है कि जनता त्याग करे। भारत की प्रयम पंचवर्णिय योजना में संवभतः श्रन्य योजनाश्रों की श्रपेत्ता कुछ श्रिष्क त्याग करने की माँग की गई है। परन्तु इस विषय में विभिन्न यत हो सकते हैं कि भारतीय जनता से किस सीमा तक त्याग करने की श्रपेत्ता की जाय श्रीर वह कितना त्याग कर सकने में समर्थ है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि १९५१-५६ के बीच प्रति वर्ष श्राविरिक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाया जाय जनकि १९५०-५१ में, जो योजना का प्रथम वर्ष था, केवल ५ प्रतिशत के विनियोग की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद की योजनाश्रों में प्रतिशत के विनियोग की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद की योजनाश्रों में प्रतिशत के विनियोग की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद की योजनाश्रों में प्रतिशत कि कायगी। जहाँ तक इस पत्त का सम्बन्ध है योजना श्रमी पहला प्रयोग मात्र है। यदि जनता योजना में निर्धारित श्रनुपात में रुपया नहीं लगा सकी तो कम मात्रा में लगायेगी परिणाम स्वरूप प्रगति की गति भी घीमी हो जायगी। यही बात श्रतिरिक्त श्राय के सम्बन्ध में भी लागू होती है। बिना सही सूचना के इस द्वेत्र में उपयुक्त श्रनुपात निर्धारित करना संभव नहीं है। जैसे-जैसे योजना लागू की जायगी श्रीर नए श्रनुसव प्राप्त होंगे उसी के साथ साथ योजना में श्रावश्यक परिवर्तन किए जायेंगे।

पंचवर्षीय योजना के ऋालोचकों ने कुछ गंभीर तर्क भी दिये हैं। उनका कहना है कि: (१) योजना में उद्योग की अपेत्ता कृषि को अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि जो योजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं उन्हें पूरा किया जाय और भविष्य में देश के श्रीद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ श्राधार स्थापित किया जाय । इस तर्क का मूल विचार यह है कि भारत का वर्तमान श्रीद्योगिक विकास कृषि विकास के अनुरूप हुआ है। परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। भारतीय स्थिति का शान रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि भारत में कब्चे माल श्रीर विजली इत्यादि का वर्तमान में जितना उत्पादन होता है उससे देश का बहुत अधिक औद्योगिक विकास किया जा सकता है। योजना आयोग ने एक श्रीर बात की श्रोर ध्यान दिया। यह बहुत संभय है कि जब तक इम भारत के भावी ख्रीद्योगिक विकास के लिए सुदृढ श्राधार स्थापित करेंगे तब तक विश्व स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिससे भारत का श्रीदोशिक विकास श्राज की अपेद्धा अधिक कठिन हो जायगा। ऐसी स्थिति में कृषि के विकास का क्या उपयोग किया जा सकेगा ! श्रंत में इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना का उद्देश्य भारत की आर्थिक व्यवस्था की प्रदियों को दूर करके देश का श्राधिक छन्तुलित विकास करना है। इस दिशा में सबसे बड़ी कमी यह है कि भारत में मशीनों के निर्माण करने वाले

उद्योग नहीं हैं, विद्युत, इंजीनियरिंग, केमिकल इत्यादि के उद्योग का अच्छी तरह विकास नहीं हो सका है इसलिए आधिक सन्तुलित व्यवस्या बनाने के लिए योजना को इस दिशा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए था और इन उद्योगों का विकास करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

(२) योजना के अनुसार देश का ऋौद्योगिक विकास निजी उद्योगपितयों के हायों में सींपा गया है। इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है क्योंकि अतीत में निनी उद्योगपितयों ने भारतीय उद्योगी का कुशलता पूर्वक विकास किया । परन्त योजना के आलोचकों का मत है कि औद्योगिक विकास अधिकांश रूप से निजी उद्योगपतियों के हायों में सींपने और उत्पादन के लक्ष्य निर्घारित करने के साय निजी उद्योग के पूर्ण उपयोग के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है। मारतीय उद्योगपतियों का मत है कि योजना में २३३ करोड़ रुपये की पूँजी का विनियोग करने की श्रीर १५० करोड़ रुपये की पूँजी टूट-फूट इत्यादि के लिए रखने की व्यवस्था की गई है। परन्तु यह पूँजी उत्पादन के निर्घारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए विल्कुल श्रपर्याप्त है। इसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि उद्योग केवल वित्त की ही आवश्यकता नहीं होती है विलक इसके अतिरिक्त श्रनेक सुविधात्रों की भी श्रावश्यकता होती है, जैसे कर सम्बन्धी, छूट टूट-फूट इत्यादि के लिए अधिक पूँजी और कुछ परिस्थितियों में नकद आर्थिक सहायता। यह खेद की बात है कि पंचवपीय योजना में इसके लिए कुछ न्यवस्था नहीं की गई है। इसके अभाव में निजी उद्योग देश के श्रीद्योगिक विकास के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है।

(३) प्रयम योजना का एक और गंभीर दोष यह है कि इसमें दोर्घकालीन योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि सुनियो- जित आधिक व्यवस्था में दोर्घकालिक योजनाओं पर विशेष जोर देना चाहिये। कुछ विदेशी राष्ट्रों में, जिसका सबसे उत्तम उदाहरण सोवियत रूस है, दोर्घकालिक योजनाओं को ही नियोजन का आधार बनाया गया। परन्तु भारत की स्थिति उससे भिन्न है। मारत में दीर्घकालिक योजनाएँ अधिक होनी चाहिये परन्तु साथ ही श्रत्यकालिक योजनाओं पर विशेष जोर देना चाहिये था। इससे प्रति एक इत्यादन में शीप्र वृद्धि की जा सकती। थी और खाद्याज के सम्बन्ध में देश शीप्र स्वावलम्बी बनाया जा सकता था। इससे बहुत सीमा तक मारत की बेरोजगारी की समस्या मी हल की जा सकती थी।

दीर्घकालिक योजनायों पर श्रिषक जोर देने में एक श्रीर हानि यह है कि वस्तुयों के उत्पादन में दीर्घकाल के वाद वृद्धि होगी जविक जनता की क्रय शक्ति शीम ही बढ़ेगी। इससे मुद्रास्फीति का जोर और वढ़ जायगा। मुनियोजित व्यवस्था में कुछ श्रंश तक मुद्रास्फीति और परिणाम स्वरूप श्रिषक कीमतें होना श्रानिवार्य है परन्तु यदि नियोजन के द्वारा वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है तो उससे मुद्रास्फीति का प्रभाव कम हो जाता है यदि पंचवर्षीय थोजना में श्रल्पकालिक योजनाश्रो पर श्रिषक जोर दिया जाता तो ऐसा होना संभव था। इसके श्रभाव में योजना के लागू होने से मुद्रास्फीति का जोर बढ़ा है जिससे उपभोक्ताश्रों को हानि हुई है।

(४) योजना की सफलता विशेष कर उस संगठन की कार्यज्ञमता पर निर्भर करती है जिस पर उसके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है। मारतीय प्रयम पंचवर्षीय योजना की यह सबसे वड़ी कमी थी कि इसमें योजना को लागू करने के लिए किसी विशेष संगठन की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ श्रीद्योगिक श्रीर नदी घाटी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने का कार्य स्वतन्त्र कार्पीरेशनों को सीपा गया है। इन कार्पीरेशनी पर सरकार अपना नियंत्रण रख सकने में विशेष समर्थ छिद्र नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जनता का बहुत सा रुपया नष्ट हो गया है. योजनाओं में प्राय: वंशोधन किया गया है और श्राशानुकृत उत्पादन भी नहीं बढ़ा है। अन्य बहुत सी योजनाएँ राज्य सरकारों के अधिकार चेत्रों में रखी गई हैं छीर राज्य सरकारें इनकी लागू करने का कार्य जिला म्रिविकारियों की सींप देती हैं। यह प्रबन्ध सन्तोपजनक सिद्ध नहीं हो सका है। जिला अधिकारी श्रन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विकास योजनात्रों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियोजन श्राधिकारियों का कार्य विशेष सन्तों-षजनक नहीं रहा है। इसका परिगाम यह हुआ है कि योजना को उचित रीति से लागू नहीं किया गवा है और उससे जितनी आशा की जाती थी उतना लाभ नहीं हो सका। इसके विपरीत जो कुछ प्रगति हुई है वह केवल कागजों तक ही सीमित है। यदि भारत सरकार आई। ए० एस० की तरह 'भारतीय आर्थिक प्रशासन' (Indian Economic Service) के श्रन्तर्गत उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करती श्रीर इस प्रकार योजना को कार्यान्वित करने के लिये विशेष संगठन को जन्म दिया जाता तो इस दिशा में श्रीधक प्रगति की जा सकती थी। इससे कार्यालयों इत्यादि पर सरकारी व्यय में श्रवश्य वृद्धि होती परन्तु वह व्यय व्यर्थ नहीं जाता उससे पंचवर्षीय योजना की उपयोगिता बढ सकती थी।

इन दोषों के होते हुये भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में एक प्रसंसनीय प्रयत्न था। आरम्भ में तो अवस्य ही योजना की सफलता कम होती। परन्तु यह देश के कृषि उद्योग, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि करने के प्रयत्न का आरम्म ही था।

सफलता की प्रगति

योजना आयोग द्वारा मई १९५७ में प्रकाशित प्रथम पंचवर्षीय योजना के पुनर्वीचर के अनुसार सम्पूर्ण पाँच वर्षों में किया नया व्यय २०१२४ करोड़ ६० हुआ (जबिक संशोधित लक्ष्य २३७७.७ करोड़ ६० था)। इसमें से १२७७.३ करोड़ ६० वजट से प्राप्त आय थी तथा २०३.२ करोड़ ६० विदेशी सहायता से प्राप्त हुये। इस प्रकार लगभग ३६६ करोड़ ६० कम व्यय हुये। पहले पाँच वर्षों में राज्य सरकारों ने ६६७५ करोड़ ६० तथा केन्द्रीय सरकार ने १११४६ करोड़ ६० का व्यय किया।

चूँ कि १६५५-५६ की वास्तविक संख्यारें पता नहीं है श्रवएव यह सम्मव है कि योजना का कुल न्यय २०१३ करोड़ रु के वजाय १६६० करोड़ रु हो जाय। प्रारम्भ में २६० करोड़ रु के छोटे के श्रर्थ प्रवन्धन की न्यवस्था थी। -वास्तव में यह १२० करोड़ रु हुश्रा। इसके फलस्वरूप मारतीय श्रर्थ न्यवस्था पर काफी मार पड़ा।

योजना में राष्ट्रीय श्राय के ५% के विनियोग को बहा कर ७% तक करने का उद्देश्य था तथा पाँच वर्षों में ३५००-३६०० करोड़ र० के विनियोग का लक्ष्य था। सरकारी चित्र में लगमग १५०१ करोड़ र० का विनियोग हुन्ना जब - कि निजी चित्र में १६०० करोड़ र० का विनियोग हुन्ना। इस प्रकार पाँच वर्ष की श्रविष में ३,०० करोड़ र० विनियोग हुन्ना। १९५०-५१ की तुलना में योजना के श्रन्त तक विनियोग का स्तर लगभग दूना हो चुका था।

कुछ कार्यों में प्रथम योजना की प्रगति और सफलता निस्सन्देइ आश्चर्य-जनक रही है। खाद्यान इंजन और सती कपड़ों के सम्बन्ध में १६५५-५६ में उत्पादन सोचे हुये १६५५-५६ के स्थेय से कहीं आगे वह गया। अमोनियम सल्फेट, तटीय जलयात्रा और सीमेयट के सम्बन्ध में यद्यपि उत्पादन १६५५-५६ के अनुमानित स्थेय से कम ही रहा फिर भी काफी वृद्धि हुई है। कुछ ही कार्य ऐसे रहे हैं जिनमें आशा के निपरीत बहुत कम वृद्धि हुई है और उनमें १६५५-५६ तक मी सोचे हुये स्थेय तक वृद्धि न हो। इसलिये इस निर्णय पर पहुँचना कि पंचवर्षीय योजना ने अर्थ व्यवस्था पर अनावश्यक भार डाले बिना संतोषप्रद प्रगति की है, युक्ति संगत होगा।

अध्याय ६०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अविध १९५६-५७ से १९६०-६१ तक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेनाकृत इसकी घारणा (Conception) अधिक न्यापक श्रीर सुद्द है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता श्रीर विकास की गति से प्रोत्साहित होकर योजना आयोग ने दितीय पंचवर्षीय योजना को अधिक ऊँचे लक्ष्यों के साथ सामने रखा। द्वितीय योजना के प्रमुख उद्देश्य यह है कि (ग्र) राष्ट्रीय श्राय में बृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप देशवासियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा किया जा सके; (ब) अत्यन्त शीवता से श्रीद्योगीकरण हो, जिसके अन्त-र्गत आधारभूत उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाय; (स) रोजगारी में वृद्धि हो: श्रीर (द) सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाय। यह उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुकृत ही हैं, अन्तर केवल इतना है कि दितीय योजना में श्रीद्योगिक विकास को पहली योजना की श्रपेद्धा श्रविक महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्तर श्रीर मी है। मारत-सरकार ने 'समाजवादी ढाँचे पर श्राधारित समाज' (socialistic pattern of society) का श्रादर्श स्वीकार कर लिया है श्रीर इसी के फलस्वरूप दितीय पंचवर्षीय योजना में समा-जिक न्याय पर इतना जोर दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नियोजन के द्वारा कृषि व श्रीद्योगिक उत्पादन श्रीर कुल राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि करने की उस समय तक कोई सार्थकता नहीं जब तक कि उस वृद्धि के साथ-साथ वितरण में सचार न हो क्योंकि इसी वितरण के द्वारा निर्धन व्यक्तियों का जीवन पहले की श्रपेताकृत श्रधिक उत्तमं हो जाता है।

पूँजी निर्माश की गति—प्रथम योजना ने आगामी २७ वर्षों के लिए प्रगति का एक आदर्श सामने रखा। उस आदर्श या लक्ष्य के अनुसार यह अनुमान है कि २२ वर्षों में राष्ट्रीय आय और २७ वर्षों में प्रति न्यक्ति आय दोगुनी हो जायगी। इसके अतिरिक्त २५ वर्ष से कुछ अधिक समय में (१६५०-५१ और १६७७ के बीच) प्रति न्यक्ति उपमोग की मात्रा में लगभग ७०% वृद्धि हो जायगी। दितीय पंचवर्षीय योजना इस आदर्श के अनुरूप ही है।

सबसे कठिन समस्या जो योजना बनाने वालों के सम्मुख उपस्थित है वह विनियोग की उस दर का श्रनुभान है जिसको बिना किसी श्रारांका के कार्यान्वित किया जा सकता है श्रीर राष्ट्रीय श्रायं की वृद्धि पर उसका प्रभाव है। योजना वनाने वालों को श्रव प्रथम योजना का श्रनुमव मी प्राप्त है जिसके सहारे वे श्रपने कार्य में श्रागे वद सकते हैं। १६५०-५१ में विनियोग राष्ट्रीय श्राय का ४१६% था परन्तु १६५१-५२ में बद्दकर ७% हो गया। इस वृद्धि का कुछ श्रंश तो माल का विना विके जमा रहने के कारण या जिसके परिणाम स्वरूप श्रायात में वाहुल्य हो गया। श्रगले दो वधों में विनियोग की दर घट कर राष्ट्रीय श्राय की ५% हो गई, १६५४-५५ में पुनः बद्दकर ६% या ६ ५५% हुई श्रीर बद्दे बद्दे योजना काल के श्रन्तम वर्ष में ७ ३% हो गई। यदि योजना काल की पूरी श्रविध में विनियोग की दर का राष्ट्रीय श्राय के सम्बन्ध में प्रतिशत श्रीसत लगाया जाय तो लगमग ६% होता है जो कोई विशेष श्राकर्षक नहीं है। इस विनियोग के परिणाम स्वरूप भारत की राष्ट्रीय श्राय लगमग १८% बद्दी श्रयोत् ६,११० करोड़ रुपयों से जितनी कि १६५०-५१ में यी बद्दकर १६५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपये हो गई।

वालिका १ श्राय श्रौर विनियोग में विद्धि जिसकी आशा की जाती थी १६४०-४१ से १६७१-७६ तक

(१६५२-५३ के मूल्य स्तर के आधार पर)

	प्रथम	द्वितीय	वृत्तीय	चतुर्य	पचम
^	योजना	योजना	योजना	योजना	योजना
	१९५१-५६	१६५६-६१	१९६१-६६	१९६६-७१	१६७१-७६
श्रवधि के श्रन्त में राष्ट्रीय					
श्राय (करोड़ रुपयों में)	१०८००	१३४८०	१७२६०	र१६८०	२७२७०
कुल वास्तविक विनियोग					
(करोड़ रुपयों में)	2200	६२००	0033	१४८००	20000
अवधि के श्रन्त में विनि-					,
योग का कुल राष्ट्रीय श्राय	}				
से प्रतिशत अनुपात	ტ. გ	ર્• 'હ	१३'७	१६ • ०	१७.०
श्रविष के श्रन्त में जन	}			{	
'संख्या (१० लाख)	३८४	४०८	४३४	४६५	५०
वृद्धिकी मात्रा का पूँजी					1
श्रीर उत्पादन श्रनुपात	१'ददः१	२"३०:१	र•६२:१	३॰३६ः१	३:७०:१
प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय			}		'
श्रवधि के श्रन्त में				1	
		1 :	1	}	
(रुपयों में)	२८१	'३३१] ३६६	। ४६६	4,86

दितीय पंचवर्षीय योजना में यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय बचत तथा विनियोग में वृद्धि के कारण १९५५-५६ की राष्ट्रीय आय के ७'३% से १६६०-६१ में १०'७% वढ़ जाने से, राष्ट्रीय आय में लगमग २५% की वृद्धि हो जायगी आर्यात् १९५५-५६ के १०,८०० करोड़ रुपयों से १६६०-६१ में वढ़कर १३,४८० करोड़ रुपया हो जायगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि क्या भारत इतने अधिक विनियोग का भार वहन कर सकता है ! योजना आयोग के अनुसार वहन कर सकता है । बीजना आयोग के अनुसार वहन कर सकता है । बीजना आयोग देशों का अनुभव वतलाता है :

"प्रयम योजना रिपोर्ट में १९५६-५७ से ५०% बचत करने की छीमान्त दर मान ली गई थी श्रीर इसके श्रावार पर यह अनुमान लगाया गया था कि १९६८-६९ तक देश की आर्थिक व्यवस्था में राष्ट्रीय आय का २०% विनियोग किया जायगा श्रीर श्रागे चलकर इसी स्तर पर स्थायी हो जायगा। श्रव ऐसा ग्रामास होता है कि यह अनुमान श्रत्यिक है। जिन प्रच्यों (projections) का अनुगणन किया गया है उनके आधार पर विनियोग का गुणक (Coefficient) ७% से जो कि १६५५-५६ में था बढकर १६६०-६१ में ११% हो जायगा: १९६५-६६ तक गुराक के १४% श्रीर १९७०-७१ तक १६% तक बढ जाने का श्रनुमान है। उसके पश्चात् गुणक स्थिर रहेगा श्रीर १६७५-७६ तक १७% तक वह जायगा (तालिका नं० १ के श्रनुसार) । १६% या १७% राष्ट्रीय श्राय का विनि-योग निस्संदेह ऊँची दर है पर पहुँच के वाहर नहीं है। पाश्चात्य देशों में जिन्होंने श्रपना श्रीदोगिक विकास पहिले श्रारम्भ किया था पँजी निर्माण की दर १० श्रीर १५ प्रतिशत के बीच रही है। जापान में विनियोग की दर का १९१३-१९३९ के बीच श्रीसत १६ श्रीर २० के बीच या। रूस में १५ श्रीर २० प्रतिशत की दर निरन्तर स्थिर रही है। उन देशों के आंकड़ों से जोई० सी० ए० एफ० ई० (ecafe) नेत्र के अन्तर्गत आते हैं यह पता लगता है कि १६५० से कुल पूँजी का निर्माण बर्मा में १० से २० मतिशत के बीच, जापान में २४ से ३० मतिशत के बीच, लंका में १० से १३ प्रतिशत के बीच श्रीर फिलीपाइन्स में ७ से ८५ प्रतिशत के बीच रहा है। भारत के सम्बन्ध में बुलनात्मक आँकड़े १० से ११ प्रतिशत हैं। कुछ लैटिन श्रमरीकी देशों में इस सम्बन्ध के श्रांकड़े १५ श्रीर २६ प्रतिशत के बीच प्राय: रहे हैं। कभी कभी स्तर कुछ कैंचा भी हुआ है। पूर्वी योरप के कुछ देशों में जैसे नैकोस्लोवेकिया श्रौर पोलैंग्ड में पँजी निर्माण की दर २० श्रीर २५ प्रतिशत के बीच रही है। नये विकासोन्मुख देशों में विनियोग की दर वर्तमान स्तर से निश्चय ही बढ़ाई जा सकती है-याद उपयुक्त विनियोग नीति का अनुसरण किया जाय

श्रीर यदि राज्य द्वारा विकास कार्यक्रम श्रारम्भ किये जायँ। इसिलिये मारत के सम्बन्ध में यह धारणा बनाना कि प्रयत्न करने से विनिगयो की दर ऊपर बताये गये स्तर तक बढ़ाई जा सकती है श्रसंगत नहीं हो सकता"।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य या कि देश में जीवन की आधारभूत वस्तुश्रों के उपमोग को पुन: उस स्तर पर ले श्राया जाय जिस पर वह महायुद्ध के पूर्व था। दितीय पंचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में एक पग आगे है और उसका लक्य यह है कि योचना काल के श्रन्तर्गत कुल उपभोग की मात्रा में लगभग २०% श्रौर व्यक्ति उपमोग की मात्रा में १२ से १३ प्रविशत की वृद्धि हो। कुछ विशेष वस्तुश्रों के प्रति व्यक्ति उपभोग के श्राकड़ों से इस बात का श्रामास मिलता है कि कितनी अधिक प्रगति का अनुमान लगाया गया है। पौष्टिक उलाहकार समिति (Nutrition Advisory Committee) ने यह श्रनुमान लगाया या कि एक वयस्क के प्रतिदिन के चन्तुलित आहार में कम से कम १४ औं अन होना चाहिये। १९५०-५१ में प्रत्येक वयस्क प्रतिदिन १३ श्रींस श्रम का श्रीसत उपमोग करता था। किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप १९५३-५४ में प्रतिव्यस्क प्रतिदिन श्रम के उपभोग की मात्रा वढ़कर १५ श्रोंस हो गई। परन्तु चने श्रीर दालों का उपमोग श्रमी भी निम्नतम श्रावश्यकतात्रों से कम है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यस्क को प्रतिदिन २६ से ३ श्रोंस तक चने और दालों का उपमोग करना चाहिये। किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या श्रीर प्रति व्यक्ति की श्राय में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप श्रज के उपमोग में वृद्धि होगी श्रतएव द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के मीतर खाद्यान का उत्पादन वहाने के लिए प्रयत्न किया नाना चाहिये। "दूघ, घी, मास, मछली, ग्रंडे, चर्बी, फल, तरकारियाँ ग्रौर चीनी के उपमोग का वर्तमान स्तर निम्नतम श्रावश्यकताश्रों से बहुत कम है। द्वितीय योजना में रहन-सहन के अधिक ऊँचे स्तर की व्यवस्था करने के लिये पशु-पालन, मञ्चली-उद्योग, मुर्गी पालन, तरकारियों की खेती श्रीर श्रन्य प्रकार की खाद्य सामग्री के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए"। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत में प्रति व्यस्क प्रति वर्ष के हिसाब से १५ गज सूती कपड़े का उपमोग करता या श्रीर प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर कपड़े के श्रीसत उपमोग का वही स्तर पुनः प्राप्त कर लिया गया है। सूती कंपड़े की जाँच समिति की सिफारिश को मानकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६६० तक प्रति व्यक्ति स्ती कपड़े के श्रीसत उपमोग को १८ गन करने का लक्ष्य निर्घारित किया गया है।

प्राथमिकता का क्रम-प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, विचाई

श्रीर बिजली की शांकि के विकास को प्रमुख महत्व दिया गया था श्रीर इन महीं पर योजना को कुल लागत की ४३.२% रकम व्यय करने का श्रनुमान था। इसके विपरीत द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों को प्राथमिकता दी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत उद्योगों पर कुल लागत की ७.६% रकम व्यय के लिये निर्धारित थी जबिक इस दूसरी योजना में (जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है) कुल लागत का १८.५% व्यय होने का श्रनुमान लगाया गया है। प्राथमिकता के कम में परिवर्तन करने के दो कारण हैं: (श्र) कृषि, विचाई श्रीर शक्ति (विद्युत) के निकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले ही से पर्याप्त ध्यान दिया गया है, श्रीर विकास की वर्तमान गित के द्वारा भी उन्हें पूर्ण रूप में विकसित किया जाना संभव है, श्रवण्य उन पर कोई विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता नहीं है, श्रीर (ब) श्रव यह श्रनुमान किया जाने लगा है कि देश के श्राधार भूत उद्योगों को वगैर विकसित किए हुए यह संमव नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय श्राय में एक केंचे स्तर तक वृद्धि की जा सके श्रयवा बेरोजगारी की समस्या का ही कोई इल खोला जा सके।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है कि देश की राष्ट्रीय आय में प्रति तालिका २

सरकारी क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कुल लागत के तुलनात्मक आंकड़े

1	प्रथम ये	ोजना ।	द्वितीय योजना	
	कुल लागत (करोड़ रुपयों में)	कुल का मविशत	कुल लागव (करोइ चपयों में)	कुल का प्रतिशत
१. कृषि श्रीर धामुदायिक विकास २. विवाद श्रीर शक्ति	३५७	१५`१	प्रद	११ंद
(बिजली)	६६१	रद १	६१३	0.38
३ परिवहन ग्रीर संचार	प्पूष	१२३ ६	१३⊏५	२८°६ १८°५
४. उद्योग श्रीर खनिन ५. निर्माण कार्य श्रीर	१७६	७°६	5E0	१८५
सामाजिक सेवार्ये	प्रकृ	२२ ६	EXX	98'9
६ विविध	इह	3.0	338	र १
कुल	२३५६	१००%	84.00	१००%

वर्ष लगभग ५% की वृद्धि हो श्रीर इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये पाँच वर्ष की श्रविष में कुल ६२०० करोड़ रुपये का वास्तिविक विनियोग (Net Investment) करने की श्रावश्यकता होगी, जबिक प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत मूल रूप में वास्तिविक विनियोग की रक्षम ३१०० करोड़ रुपये थी। श्रनुमान है कि इसमें से ३८०० करोड़ रुपये की रक्षम का विनियोग सरकारी चेत्र पर होगा, जिसकी ज्यवत्था सरकार श्रपने वित्तीय साधनों से करेगी श्रीर शेप २,४०० करोड़ रुपये निजी चेत्र पर व्यय होगे, जो निजी विनियोग हारा उपलब्ध होंगे। विकास सम्बन्धी व्यय में ४८०० करोड़ रुपयों की कमी जो कि प्रस्तावित वास्तिविक विनियोग के कारण सरकारी चेत्र में श्रावश्यक होगा तालिका नं २ में दिया हुआ है।

द्वितीय पंचवर्णीय योजना की 'श्राघारभूत नीति' यह है कि (श्र) इस्पात, यनत्र-निर्माण, खनिज-पदार्थ श्रादि के प्रमुख श्रीर श्राघारभूत उद्योगों पर यथासंमव श्रिषक से श्रिष्ठक घन विनियोग किया जाय श्रीर इसके विपरीत सामान्य उपभोग में प्रमुक्त होने वाली वस्तुश्रों के उद्योगों पर यथासंभव कम से कम घन व्यय किया जाय; श्रीर (ब) छोटे पैमाने के व घरेलू उद्योग-धंघों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाय, चाहे इस प्रयास में बड़े पैमाने के उद्योगों की हानि ही क्यों न हो।

उद्योगों श्रीर खिनज पर प्रस्तावित ८० करोड़ रुपयों के न्यय में से ६१७ करोड़ रुपयों के लगभग बड़े श्रीर मध्य वर्ग के उद्योगों पर, ७३ करोड़ रुपये खिनज के विकास पर श्रीर २०० करोड़ रुपये ग्राम्य तथा छोटे उद्योगों पर न्यय किया जायगा। उद्योगों में से लोहे श्रीर इस्पात उद्योग को सबसे श्रिषक भाग मिलेगा। प्रमुख विशेषता दितीय योजना की छोटे श्रीर कुटीर उद्योगों को प्रायमिकता देने की है, जिस पर २०० करोड़ रुपया न्यय करने के लिए नियत किया गया है।

यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों श्रीर खनिन पदायों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी गई है, किन्तु कृषि, परिवहन श्रीर सामाजिक सेवाश्रों की उपेद्या नहीं की गई है। श्रनुमान है कि १६५५-५६ से १६६०-६१ तक दितीय योजना के श्रन्तर्गत खाद्यान्न का उत्पादन ६५० लाख से ७५० लाख टन, रुई का ४२ लाख से ५५ लाख गाँठ, गन्ने का ५० लाख टन से ७० श लाख टन, तिलहन का ५५ लाख से ७० लाख टन, चाय का ६४ करोड़ से ७० करोड़ पींड हो जायगा। विचाई की जाने वाली भूमि का दोत्रफल ६ ७ करोड़ एकड़ हो जायगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों श्रीर सामुदायिक योजनाश्रों के मण्डलों की संख्या ५०० से ३८०० श्रीर ६२२ से ११२० कमशः हो जायगी। दित्तीय योजना की विशेषता यह है कि इसमें श्रनेकों कृषि उत्पत्ति की वस्तुयें जैसे

नारियल, सुपाड़ी, लाख, कालीमिर्च श्रौर वृक्कफल श्रादि, जिनकी श्रोर प्रथम योजना में ध्यान नहीं दिया गया था, इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं श्रौर उनके विकास का ध्येय निश्चित कर दिया गया है। द्वितीय योजना में कृषि का विकास श्रिषक विस्तृत ढंग पर होगा।

जहाँ तक परिवहन से सम्बन्ध है भारतीय रेलों की यात्रियों तथा माल ले जाने की शक्ति बढ़ा दी जायगी। रेलपथ १० करोड़ ८० लाख मील से बढ़ाकर १२ करोड़ ४० लाख मील और माल की ढुलाई १२ करोड़ से १६ करोड़ २० लाख हो जायगी। इसी काल में राष्ट्रीय सड़कें १२,६०० मील से १३,८०० मील और कच्ची सड़कें १०७,००० मील से १२५,००० मील बढ़कर हो जायगी। तटीय व्यापार में जलयानों द्वारा टनेज ३ २ लाख जी० श्चार० टी० से बढ़कर ४ ७ लाख जी० श्चार० टी० हो जायगा। भारतीय बन्दरगाहों की माल चढ़ाने श्चीर उतारने की शक्ति २ करोड़ ५० लाख टन से बढ़कर ३ करोड़ २५ लाख टन हो जायगी।

वालिका २ से प्रकट होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (अ) हाथ के करघे और शक्तिचालित करघे से तैयार किये गए कपड़े, रामायनिक खादों, लोहे व हस्पात, एल्यूमीनियम और कोयले के उत्पादन में मन से अधिक वृद्धि होगी; (व) मारी रमायनों, घातु के मामान, अभ्रक, मैंगनीज, साहिकलों, सोने की मशीनों और विजलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कमवृद्धि की जायगी; और (स) मिल में तैयार होने वाले स्ती कपड़ों, ऊनी सामान, चीनी, साबुन, जूलों और वनस्पति तेलों के उत्पादन में और भी कम वृद्धि होगी। इस प्रयास में यह ध्यान रखा गया है कि आघारमूत और प्रमुख उद्योगों का यथासम्मव अधिक से अधिक विकास किया जाय और जहाँ तक अन्य उद्योगों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन के द्वारा आत्मिनभैरता के अधिक से अधिक निकट पहुँचा जाय।

रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता (Employment potential)
—िद्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि रोजगारी के पर्याप्त अवसर उत्पन्न किए जायें। भारतीय अर्थं-व्यवस्था की इसी आवश्यकता के फलस्वरूप कृषि की अपेजाकृत उद्योगों पर अधिक बल दिया गया है। इस योजना को इतना अधिक विस्तृत बनाने का आंशिक कार्ण यह है कि वेकारी की समस्या को इल करने का प्रयक्ष किया जाय। द्वितीय योजना काल में नये काम करने वालों की संख्या जो वर्तमान संख्या में जुड़ जायगी लगभग १ करोड़ के अनुमान की गई है। यदि उसमें से ३८ लाख व्यक्तियों को, जो नगर की मजदूर संख्या में वृद्धि अनुमानित है, पृथक कर लें तो जितने मजदूर देहातों के चेत्र में वर्देंगे उनकी

संख्या ६२ लाख के लगमग श्राती है। यदि एक करोड़ नये अमिकों की संख्या में ५३ लाख पहले के वेकारों की संख्या (२५ लाख नगरों की श्रीर २८ लाख प्राप्य चेत्र में) जोड़ दी जाय तो छुल वेकारों की संख्या १९५६-६१ में लगमग १ ५३ करोड़ हो लायगी । इतने नये व्यक्तियों को काम फरने का श्रवसर प्राप्त करवाना सम्भव नहीं है। कदाचित ८० लाख व्यक्तियों के लिये दितीय योजना में काम के नये श्रवसर दिये जा सकते हैं। किंद्र रोजगारी के श्रतिरिक्त श्रयसरी की केवल योजना-मात्र गढ़ लेने से तो समस्या इल नहीं की जा एकती। व्यापार श्रीर उद्योगी का प्रसार मात्र करके यह आशा करना कि उनके द्वारा अब अधिक व्यक्तियों की खपत अपने आप होने लगेगी न्यर्थ है। इस समय ऐसे अनेक न्यवसाय है जिनमें आव-श्यकता से श्राधिक लोगों को खपा लिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि जैसे-जैसे उन व्यवसायों में काम की वृदि होगी, वैसे-वैसे पहले से ही श्रिधिक संख्या में काम करने वाले व्यक्तियों पर काम का बोक्त श्रिथक होता जायगा श्रीर इस प्रकार उन व्यवसायों में रोजगार के श्रवसरों में वृद्धि नहीं हो सकेगी। कुछ उद्योगों श्रीर न्यापारिक संस्पात्रों में श्रमिनवीकरण की योजनाएँ लागू किये जाने की भी सम्भावना है, जिसका फल यह होगा कि प्रसार किये गरे उन उद्योगों में रोजगार के लिये और मी अधिक कम संख्या में लोगों की खपत की जा सकेगी। योजना आयोग इन कठिनाइयों से मली भाँति परिचित है। "रोजगारी में अनु-मानित वृद्धि लाने के लिए विच श्रीर टपयुक्त नीति का श्रवसरण करने की श्राव-श्यकता तो होगी ही, उसके साय-साय सुगठित सङ्गठन की भी व्यवस्था करनी पढ़ेगी। वेकारी दर करने के लिये छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को विकसित करने पर श्रिधिक बल दिया गया है, किन्तु यह स्वष्ट है कि सुव्यवस्थित प्रयत्नों के श्रिमाय में इनका उस सीमा तक विकास और प्रसार नहीं हो सकता। काम करने के अवसर मदान करने का श्रर्थ केवल नौकरियों की जगहें बढा देना मात्र नहीं है। यह जगहों के बढ़ा देने के प्रति जनता की प्रतिकिया पर निर्भर करता है। रोजगारी की व्यवस्था करने का यह भी श्रर्थ है कि मिन्न-मिन्न कर्मचारियों के लिए जितने प्रशिद्धण की श्रावश्यकता है उसे प्रदान करने की सुविषाश्रो का प्रवन्ध किया जाय। यह श्रमुमान लगाया गया है कि श्रनेक चेत्रों में उत्पादन वृदि होने के फलस्वरूप उसी श्रनुपात में थोड़ी या बहुत मात्रा में रोजगारी में भी वृद्धि होगी। श्रतएव इस बात की श्रावश्यकता है कि अत्यधिक अभिनवीकरण पर नियंत्रण किया लाय। साथ ही वह भी देखने की श्रावश्यकता है कि कहीं पहले से रोबगार प्राप्त लोगों की मजदूरी वढ़ जाने से उस वस्तु की मौंग में कमी न आ जाय और इस प्रकार वेकार लोगों की स्थिति श्रीर भी न विगढ़ जाय।"

वित्त ज्यवस्था — योजना की सफलता वित्त की प्राप्ति पर निर्भर है।
भारत में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय बचत का स्तर राष्ट्रीय ग्राय के
भारत में बहुत कम है। इसिलेये विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना
ग्रावश्यक हो जाता है। द्वितीय योजना के ग्रानुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़
ग्रावश्यक हो जाता है। द्वितीय योजना के ग्रानुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़
ग्रावश्यक हो जाता है। द्वितीय योजना के ग्रानुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़
रयों के ज्यय का प्रवन्य ताजिका नं० ३ में जैसा दिखाया गया है किया जायगा।
उसमें से ८०० करोड़ रुपया केन्द्रीय ग्रीर राज्य सरकारों की ग्रातिरक्त ग्राय से,
उसमें से ८०० करोड़ रुपया केन्द्रीय ग्रीर राज्य सरकारों की ग्रातिरक्त ग्राय से,
१२०० करोड़ रुपया सरकारी म्ह्या से, ४०० करोड़ रुपया श्रीर १२०० करोड़ रुपया
ग्राय स्त्रोतों से, ८०० करोड़ रुपया विदेशी सहायता से ग्रीर १२०० करोड़ रुपयों की कमी पड़ेगी
घाटे के बजट से प्राप्त किया जायगा। इससे ४०० करोड़ रुपयों की कमी पड़ेगी
जिसका प्रवन्य या तो नये करों से प्राप्त श्राय द्वारा श्रमवा श्रीवक घाटे के ग्रर्थ
प्रवन्य द्वारा या श्रविक विदेशी सहायता द्वारा या द्वितीय योजना के विस्तार की
प्रवन्य द्वारा या श्रविक विदेशी सहायता द्वारा या द्वितीय योजना के विस्तार की

सरकारी चित्र में विकास योजनायों का श्रार्घ प्रतन्य एक दूसरे हिंहकोस से भी देखा जा सकता है। पाँच वर्षों की ग्रविंघ में ४८०० करोड़ इपयों के न्यय में से लगमग १००० करोड़ रुपयों का न्यय तो शिचा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक जन्वेपण स्त्रीर राष्ट्रीय विकास आदि पर चालू व्यय के रूप में होगा । इस प्रकार के व्यय से पूँजी का प्रत्यज्ञ रूप से निर्माण नहीं होता ग्रीर इसलिये विनियोजित व्यय नहीं माना जाता। ऐसे चेत्रों पर व्यय चालू श्राय स्रोतों से पूरा किया जाता है। इसिलिये वास्तविक विनियोग ३८०० करोड़ रुपयों का है और इसका प्रवन्य ऋग द्वारा किया जा सकता है। विकासोनमुख अर्थ व्यवस्था में जहाँ पर पूँजी निर्माण सम्बन्धी व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, वहाँ यह वांछनीय होगा कि उसके एक अंग्र का प्रबन्ध कर से प्राप्त श्राविरिक्त श्राय में से किया जाय। इस सिद्धान्त पर प्रथम योजना की रिपोर्ट में जोर दिया गया था श्रीर इस पर फिर जोर देना चाहिये। योजना के ग्रर्थ प्रवन्य की न्यवस्था में चालू ग्राय में से केवल ८०० करोड़ रुपयों के प्रवन्ध की ज्यवस्था की गई है जब कि चालू ज्यय के श्रनुसार १००० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। रेलवे से प्राप्त १५० करोड़ रुपयों की आय को चालू ग्राय का भाग सममला चाहिये। इसका अर्थ यह है कि कुल चालू ग्राय से योजना के लिये पाप्त वित्त ६५० करोड़ रुपयों का हुआ जब कि चालू व्यय की मात्रा १००० करोड़ रुपया अनुमान की गई है | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकारी श्राय में कुछ भी बचत नहीं है जिसका प्रयोग ३८०० करोड़ रुपये के विनियोग के लिए किया जाय, वास्तव में ५० करोड़ रुपयों का घाटा है। दूसरे शब्दों में कुल ३८०० करोइ पूका जी निर्माण का अर्थ-प्रवन्ध व्यक्तिगत वचत द्वारा ही करना सम्भव होगा। यदि ८०० करोड़ रुपयों की विदेशी विचीय सहायता को अलग कर दिया जाय क्योंकि यह विदेशों की बचत पर निर्भर है श्रीर २०० करोड़ रुपयों की सहायता पीएड पावने की बची हुई रूप से प्राप्त की जाय, तो देश की श्राप्ति व्यवस्था के श्रन्तर्गत चालू बचत की मात्रा जो कि सरकारी योजनाश्रों में विनियोजित की जायगी, २८५० करोड़ रुपयों के वराबर टहरती है। यदि यह मान लिया जाय कि ४०० करोड़ रुपयों की कमी सरकारी वचत द्वारा पूरी करली जायगी तो व्यक्तिगत बचत की मात्रा जो सरकारी चेत्र में स्थानान्तरित की जायगी वह २४५० करोड़ रुपयों की होगी।

तालिका नं० ३ सरकारी क्षेत्र के लिये वित्त के स्रोत (करोड़ रुपयों में) १. चालू आय के अतिरिक्त से 500 (i) १९५५-५६ में प्रचलित कर की दर से 340 (ii) श्रतिरिक्त कर से 84. २. जनता से प्राप्त ऋण से 2200 (i) वाजार भ्राण (Market loans) 1900 (ii) छोटी वचत 400 ३. वजट के श्रन्य श्राय स्रोतों से 800 (i) रेल का विकास कार्यक्रम में योगदान १५० (ii) पाविहेन्ट फरह तथा श्रान्य शीपों के श्रन्तर्गत जमा धन से 740 ४. विदेशों के स्रोतों से 500 ५. घाटे के श्रयं प्रवन्ध से १२०० ६. कमी-देशीय श्रतिरिक्ति स्रोतों से पूरी की जायगी YOU 8200

"क्या यह मान लेना युक्तिसंगत न होगा कि २४५० करोड़ रुपयों तक की व्यक्तिगत बचत की रकम सरकार को विनियोग के लिये प्राप्त हो जायगी? इस संबंध में बाजार में ऋणा लेने, छोटी मात्रा की बचत और घाटे के अर्थ प्रवन्ध में अन्तर बहुत साधारण महत्व की बात है। ये सब व्यक्तिगत बचत को अपनी और से अथवा मृत्य की वृद्धि द्वारा वरवश राजकीय कोप में पहुँचाने के ढक्क हैं। व्यक्तिगत बचत की मात्रा राजकीय कोप में कितनी और किस ढक्क से पहुँचती है जनता की अपनी सम्पत्ति को रोकड़, सरकारी अपनी सम्पत्ति को रोकड़, सरकारी अपनी सम्पत्ति को रोकड़, सरकारी अपनी तमा छोटी मात्रा वाले सेविंग

सर्टीफिकेट के रूप में या जमा घन के रूप में रखने की इच्छा पर निर्मर रहता है। जब तक कुल बचत जो सरकारी कोष में पहुँचती है पर्याप्त मात्रा में रहती है तब तक हस बात से लोग उदासीन रहते हैं कि बचत की रकम ऋण पत्र, छोटी मात्रा के सेविंग सर्टीफिकेट अथवा सरकारी नोट के रूप में है। ऐसी स्थित में सबसे अमुख महत्ता की बात यह जानने में है कि क्या जनता की व्यक्तिगत बचत की मात्रा को हम व्यक्तिगत चित्र की आवश्यकता से उतनी अधिक होने की आशा कर सकते हैं जितनी कि सरकारी चेत्र की आवश्यकता है। व्यक्तिगत बचत इस हिक्कोण से पर्याप्त तभी हो सकती है जब कि उपभोग पर आवश्यक नियंत्रण लगाया जाया। दूसरे शंब्दों में इसका अर्थ है कि प्रस्यच्च रूप से जितने ही कम अनुपात में जनता की बचत सरकार को अतिरिक्त करों की आय के रूप में अथवा सरकारी अनुक्रमों के लामांश के रूप में होगी उतनी ही अधिक आवश्यकता ऐसे उपभोग में लाने की बढ़ती जायगी जिनसे उपमोग आवश्यक सीमा से आगेन बढ़े"।

"केन्द्र श्रीर राज्यों के बजट होतों से जो श्राय करों, श्रुण, तथा श्रन्य उपायों से प्राप्त की जा सकती है वह लगमग २४०० करोड़ रुपये की है। घाटे के श्रर्य प्रवन्य हारा लगभग १२०० करोड़ रुपयों की श्रीर श्राय बढ़ाई जा सकती है। इस मान्ना में यदि ८०० करोड़ रुपयों की विदेशी विचीय सहायता श्रीर जोड़ दी जाय तो कुल श्राय जो सरकारी चेन में योजना के कार्यक्रम को कार्योत्वित करने के लिये प्राप्त होगी वह ४४०० करोड़ रुपया होती है। इससे ४०० करोड़ रुपयों की कमी रह जाती है जिसके प्राप्त करने के विस्तृत उपायों को बाद में ढूँढ़ा जायगा। यह तो मान लिया गया है कि यह कमी देश के स्रोतों में वृद्धि हारा ही पूरी की जायगी। घाटे के श्रर्थ प्रवन्ध की सीमा को विचाराधीन रखते हुये जिसके बारे में ऊपर संकेत किया जा जुका है तथा इस बात को भी विचाराधीन रखते हुए कि जिस श्रर्थ प्रवन्ध की योजना की रूपरेखा यहाँ बताई गई है उसमें श्र्यण पर श्रावश्यकता से श्रधक मरोसा किया गया है, इस कमी को पूरा करने का एक ही उपाय जिस पर निर्मर रहा जा सकता है वह करों का श्रारोग्य, तथा सम्मावित सीमा तक सरकारी उपक्रमों का लामांश है।"

द्वितीय योजना को इस वात का पूरा ज्ञान है कि १२०० करोड़ क्यों के घाटे के अर्थ प्रवन्य किये जाने से मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जायगी। योजना बनाने वालों ने ऐसी स्थिति से बचाव के लिये अनेक प्रतिवन्धों का निर्देश दिया है। उनके विचारानुसार:—

"सबसे प्रमुख संरत्त्रण का उपाय बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान एकत्रित करके

रख लेना होगा जिससे जब जब मुद्रास्फीति का प्रभाव जीर पकड़े तो उसका निरा-करण किया जा सके। जहाँ की ऋार्थिक व्यवस्था में तीवगति से विकास का प्रयक्ष किया जा रहा है वहाँ चाहे कितनी ही सममदारी से श्रर्थ प्रवन्ध क्यों न किया जाय मुद्रास्पीति का भय पूर्णतया मिटाया नहीं जा सकता। मुद्रास्पीति से सबसे उत्तम बचाव का ढंग मुद्रास्कीति न होने देना है परन्तु ऐसी नीति जिसमें मुद्रास्फीति तो हो पर उसके दुष्प्रभावों से वच निकलें कभी सफल नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में कुछ जोखिम तो उठानी ही पड़ेगी। इस जोखिम से वचने का सबसे अधिक सफल उपाय खाद्यान्नों के ग्रीर ग्रन्य श्रावश्यक वस्तुग्रों के भगडार पर श्रधिकार रखना है ताकि जब इनकी कभी पड़े तो बाजार में इनकी पूर्ति वढ़ा दी जाय । मारतीय आर्थिक व्यवस्था में अन्न और वस्त्र के मूल्यों का विशेष महत्व है श्रीर इनमें श्रधिक वृद्धि हर प्रकार से रोकना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। जब तक इन वस्तुश्रों के मूल्य को युक्ति-संगत स्तर पर रक्खा जा सकेगा तब तक देश की अधिकांश जनसंख्या के जीवनस्तर की लागत नियंत्रण में रहेगी। श्रन्य वस्तुश्रों के मूल्यों में वृद्धि श्रपेज्ञाञ्चत कम महत्ता की वात होगी यद्यपि व्यवस्था में किसी भी वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने से द्रव्य के अपेचाकृत कम आवश्यक उपयोग की वस्तुश्रों पर न्यय किये जाने का भग है। यदि ऐसा हो जाय तब उसे ठीक करने का प्रयत्न करना त्रावश्यक होगा। मुद्रास्फीति के प्रभावों से बचने का दूषरा उपाय विवेचनात्मक (discriminating) परन्तु तुरन्त ही करारोप के उपाय का श्रमुसरण कुछ वस्तुत्रों का स्रावश्यकता से श्रधिक उपयोग होने से बचाने के लिये ग्रौर ग्रत्यधिक लामांश तथा ग्रनायास प्राप्त हुये लामांश की रोक देने के लिये (जिनका कि घाटे के ऋर्य प्रबन्ध में उत्पन्त हो जाना स्वाभा-विक ही है) श्रत्यन्त श्रावश्यक होगा। श्रन्त में, कन्ट्रोल के उपाय का जिसमें राशनिंग तथा मात्रा नियत करना स्नादि सम्मिलित होंगे उपभोग के उचित सीमा से आगे जाने से रोकने के लिये तथा दुर्लम वस्तुश्री और कब्चे माल आदि के प्रयोग में मितव्यता लाने के लिये प्रयोग करना श्रावश्यक होगा। परन्तु श्रातीत का श्रनुभव बताता है कि श्रावश्यक प्रयोग की वस्तुत्रों पर कन्ट्रोल लम्बी समया-विध के लिये विश्वस्त उपाय सिद्ध नहीं होंगे। इस कारण यह श्रिनवार्य हो नाता है कि इसके अतिरिक्त अन्य बचाब के उपायों का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाय क्योंकि योजना के कार्य-क्रम में कमी करने की सम्भावना तो अत्यन्त कठिनाई में पद्दने पर ही करना उचित होगा।"

श्रालोचना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की धारणा प्रथम योजना की श्रपेत्ता श्रिषिक व्यापक और सुदृढ़ है। जब यह योजना समाप्त होगी तो प्रति व्यक्ति की बास्तविक छाय में अपेजाकृत छावक वृद्धि दोगी छौर लोगों की छार्थिक स्थिति में निश्चित रूप से मुधार दोगा। द्वितीय योजना की निम्नलिखित प्रमुख विशेषवाएँ है:

(१) इयके श्रन्तर्गत मीविक (physical) नियोजन पर वल दिया गया धे, न कि वित्तीय (financial) नियोजन पर । इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य मीतिक उत्पादन के रूप में निर्धारित किये गये हैं जैसे इतने लाख टन इस्पात. कोयला, सीमेन्ट श्रादि श्रीर फिर इन भिन्न-भिन्न वस्तुश्रों के लक्ष्यों के लिये वित्त को निर्धारण किया गया है। प्रथम पंचनपीय योजना के श्रन्तर्गत पर्याप्त दर से व्यय नहीं किया जा सका श्रीर वास्तविक रूप में विकास का कम भी नहीं जारी रह सका, यथंकि वह वितीय नियोजन पर श्राधारित यो। भौतिक नियोजन में इस बात पर बल नहीं दिया जाता है कि श्रमुक योजना पर कितनी मात्रा में धन व्यय किया गया है, वरन् उसमें महत्वपूर्ण वात यह रहती है कि उस उस्तु के उत्पादन में फितनी एफलता प्राप्त हुई है। इसका परिणाम यह होता है कि नियोजन में श्रीधक पास्तविकता थ्रा जावी है। किन्तु भीतिक श्रीर वित्तीय लक्ष्यों में समन्वय स्यापित करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्न विषयों पर विस्तुत और यथार्थ सचना प्राप्त की लाय : (श्र) भिन्न भिन्न यस्तुश्रों की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने में कितनी मात्रा में कन्ने माल, शक्ति, अम ग्रादि की ग्रावरयकता होती है. श्रीर (ब) भविष्य में इन विभिन्न कच्चे मालों व अस श्रादि का क्या-वया मत्य होगा। श्रमाय्यया भारत में इनसे सम्बन्धित सही-सही श्रीर विश्वसनीय सूचनाएँ उपलब्ध नहीं है श्रीर हसीलिए यह श्राशंका उत्पन्न होती है कि मीतिक नियोजन से समस्या इल होने के स्थान पर कहीं श्रीर जटिल न हो जाय। "लोकतान्त्रिक नियोजन के शन्तर्गत श्रार्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये एक ऐसे देश में जहाँ का शासन-यंत्र श्राधिक नियोजन की श्रायश्यकवाश्री की पूर्ति नहीं कर सकता श्रीर नहीं का प्रत्येक विभाग श्रीर प्रत्येक सन्त्रालय श्रपनी चलाई हुई वोजनाश्री पर ययारांभव श्रधिकतम धन व्यय करने का प्रयत्न करता है, वित्तीय नियोजन के स्थान पर भीतिक नियोजन पर बल देने का श्रानिवार्य परिशाम यह होगा कि (क) श्रद्याचिक धन का श्रपञ्यय होगा श्रीर (ख) श्रिधिक मात्रा में सरकारी ज्यय के कारण मुद्रास्कीति की प्रवृतियों के उत्पन्न होने की संभावना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत वित्त मन्त्रालय ने यह छिढ़ांत सामने रखा कि विशेष परिस्थि-तियों को छोड़ कर अन्य स्थितियों में किसी को भी निर्धारित रकम से अधिक रुपय करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये श्रीर इस प्रकार सरकारी व्यय पर कटा नियंत्रण स्थापित किया गया । फिन्त जहाँ तक भौतिक नियोजन का सम्बन्ध है, यह तर्क विल्कुल निर्धक है। चूंकि द्वितीय पंचवर्णीय योजना का मूलभूत उद्देश्य है कि निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्यों (physical targets) की पूर्ति की जाय, अतएव मिन्न-भिन्न विभागों और मन्त्रालयों को अपने निर्धारित वित्त से कुछ अधिक व्यय कर सकने की छूट प्राप्त होगी। सरकारी व्यय में कभी करना अयवा योजना-काल के अन्तर्गत अनुमानित रकम का विनियोग न कर सकना योजना का एक दोध है। किन्तु उससे भी बड़ा दोध यह है कि धन का अपव्यय किया जाय और उसके फलस्वरूप सरकारी धन की हानि तो हो ही साथ ही साथ अनियन्त्रित मुद्रास्कीति के दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़े ।" इससे यह प्रकट होता है कि वित्तीय नियोजन से सम्बद्ध खतरों और भूलों से बचने के लिये अत्यिक सावानी की आवश्यकता है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वित्तीय नियोजन के स्थान पर मौतिक नियोजन पर बल दिये जाने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक वास्तविकता आ गई है।

- (२) द्वितीय योजना ने प्रमुख रूप से श्रीद्योगिक विकास पर बल दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत कृषि श्रीर शक्ति (बिजली) के विकास की प्राथमिकता दी गई थी। इस प्रकार द्वितीय योजना से देश का श्रार्थिक विकास श्रिषक स्मृत्तित्व हो जायगा। श्रीद्योगीकरण पर इसलिए जोर दिया गया है कि (श्र) प्रथम योजना के श्रन्तर्गत कृषि श्रीर सिंचाई में पहले ही से काफी प्रगति हो सुकी है श्रीर इसीलिए उद्योगों पर श्रिषक ध्यान देना श्रावश्यक हो गया है, क्योंकि प्रथम योजना के श्रन्तर्गत उद्योगों की उपेज्ञा की गई थी; (३) यदि हम प्रमुख रूप से केवल कृषि पर ही श्रपना घ्याम केन्द्रित करते हैं तो यह संमव नहीं है कि तेजी से बद्दी हुई जनसंख्या के साथ-साथ बेरोजगारी श्रीर श्रांशिक रोजगारीकी समस्या को हल किया जा सके। श्रीद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य है कि वेरोजगारी श्रीर श्रांशिक रोजगारी की समस्या को हल करने में सहायता मिजे; श्रीर (स) पहले की श्रपेज्ञाकृत यह श्रिषक स्पष्ट रूप से श्रनुमव किया जाने लगा है कि देश की श्रार्थिक सम्पन्नता श्रन्ततः श्रीद्योगीकरण से सम्बन्ध रखती है।
- (३) प्रथम पंचवर्षीय योजना की श्रपेचाकृत दितीय योजना के श्रन्तर्गत 'सामाजिक न्याय' पर श्रिषक क्यान दिया गया है। प्रथम योजना का उद्देश्य यह या कि देश में महायुद्ध के पूर्व दैनिक उपयोग की वस्तुश्रों की जिस मात्रा में खपत

^{1.} Vide the Author's article on "Some Basic Considerations about the Second Five-year Plan" in the Commerce, dated July 2, 1955, page 15.

होती थी, उसी स्तर को फिर से ले आया जाय। द्वितीय योजना एक पग और श्रागे वह गई और उसका लक्ष्य यह है कि उसके समाप्त होने पर देश के कुल उपभोग में लगमग २०% और प्रति न्यक्ति के उपभोग में १२-१३ प्रतिशत की वृद्धि हो। यह संभव होगा या नहीं, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक राष्ट्रीय श्राय की १०% राशि करों के रूप में ली जायगी, जबिक श्रमी तक करों के रूप में ली जाने वाली राशि इसकी ७% है और यह निर्माण, सामाजिक कल्याण श्रादि पर श्रिषक रकम न्यय करने की न्यवस्था की गई है क्योंकि इनके द्वारा धनिकों की श्रमेचा निर्धनों को श्रिषक लाम होता है। इसी कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रगतिशील कहा जा सकता है।

नि:संदेह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे अनेक दोव हैं जो इसे एकाङ्गी श्रीर श्रात-श्राकांची (over-ambitious) नना देते हैं। सबसे पहले तो यही तर्क रखा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में द्वितीय योजना के लिए यह संमव नहीं है कि वह पाँच वर्ष की अवधि में कुल ६,२०० करोड़ रुपए के वास्तविक विनि-योग (net investment) का प्रबन्ध कर सके, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि १९५५-५६ में राष्ट्रीय अाय की जों ७'३% राष्ट्रीय बचत होगी, उसे १६६०-६१ तक राष्ट्रीय श्राय की १० ७% कर देना संमव नहीं होगा। इस घारणा का समर्थन कुछ ऐसे विदेशी राष्ट्रों के अनुभवों के दृष्टान्त देकर किया गया है जहाँ पर लोकतान्त्रिक श्राघार पर नियोजन हुआ है या हो रहा है। प्रो० बी० श्रार० शिनोय की यह धारण है कि "अपने पिछले वर्षों के और दूसरे जनतान्त्रिक देशों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी ऊछ समय तक यह आशा करना न्यर्थ है कि विकास कार्य-क्रम के लिए इतने अधिक विचीय साधन उपलब्ध होंगे, जिनसे राष्ट्रीय श्राय में होने वाली वृद्धि की दर दुगुनी हो जायगी। इस समय हमारे देश में राष्ट्रीय बचत की दर राष्ट्रीय आय की ७% या इससे भी कुछ कम है। पिछले पाँच वर्षों के अन्तर्गत इसमें लगभग १% वृद्धि हुई है। यह अनुमान करना कि भावी पाँच वर्षों में वृद्धि की दर बहुत अधिक तेज हो जायगी, केवल दराशा-मात्र है। सरकार ने यह नीति घोषित की है कि आय वितरण की अस-मानतात्रों को यथासंभव कम किया जायगा, जिसका परिणास यह होगा कि सम्पूर्ण वचत की रकम में घटती हो जायगी। च्ँकि हमारे देश के अधिकांश लोग जिस मात्रा में खाद्यान का उपयोग करते हैं, वह राष्ट्रीय श्रीसत श्रीर पौष्टिक भोजन के निम्नतर स्तर से कम है, इसलिए यह अनुमान है कि दैनिक उपयोग के व्यय में जो वृद्धि होगी उसका ५०% तो खाद्यान्न पर ही व्यय कर दिया जायगा। परम्परा के श्राघार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इधर कई वर्षों में पैदावार

श्रन्छी श्रवश्य हुई है, किन्तु फिर भी संभावना है कि श्रागामी वर्षों में फसलें बिल्कुल ही खराव होंगी या उनसे कम पैदावार होगी। इन परिस्थितियों में यह श्रानुमान करना कि मावी पाँच वर्षों में बचत की दर म प्रतिश्रत से श्रिष्ठिक होगी उचित नहीं है। किन्तु इसके साथ ही बचत की दर में श्रानुमान से श्रिष्ठिक दृद्धि होना भी बिल्कुल श्रसंभव नहीं है। श्रतएव इस बात की श्रावश्यकता है कि बचत की उक्त दर से जिस मात्रा में वित्तीय साधन वास्तव में उपलब्ध होंगे, उन्हों के श्रानुरूप योजना के श्राकार को बनाने के लिए उसमें संशोधन किए जायं श्रीर राष्ट्रीय श्राय की श्रानुमानित वृद्धि के श्रानुस्तर ही विनियोग की रकम निर्धारित की जाय"।

यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी भी योजना के अन्तर्गत अनुमानित व्यय की रकम स्वभावतः ही प्रयोगिक (Tentative) रूप में निर्धारित की जाती है ग्रीर यदि ग्रनुमानित साधन उपलब्ध न हों तो योजना की लागत को उसी के अप्रनुसार घटाया जा सकता है। किन्तु इस तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है कि (भ्र) ''इस प्रकार संशोधन करने से नियोजन में गुड़बड़ी श्रा जाती है। चनसे नदा दोष तो यह है कि अनुमानित विनियोग और उत्पादन के स्तर में बहुत अधिक कमी कर देने से सामान्य जनता में योजना के प्रति निराशा उत्परन हो जाने की संभावना रहती है। यदि सरकार कृत्रिम रूप से विनियोग की दर की लादने का प्रयास करती है, तो उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से भीषण मुद्रास्फीति का उदय होगा । श्रार्थिक नियम ग्रत्यन्त कठोर होते हैं श्रीर उनके लागू होने में साँ (Statisticians), अर्थ-शास्त्रियों या राजनीतिशों की सुविधा-असुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यदि कोई भूल की जाती है, तो उसके दुष्परि-याम हमें निश्चित रूप से मुगवने पहुँगे। इससे यह निष्कर्ष निकलवा है कि अधिक से अधिक यथार्थनादी होकर अधिकतम सावचानी वरतने की आवश्यकता है", श्रीर (व) "वास्तव में जितने साधन उपलब्ध हैं, उनकी ज्ञामता से श्रीधक विकास कार्य-क्रम को वलपूर्वक गतिशील बनाने का अनिवार्य रूप से यह परिणाम होगा कि श्रनियंत्रित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी । एक ऐसे जनतान्त्रिक देश में, जहाँ की श्रिषिकांश जनता के पास जीविका-निर्वोह के केवल निम्नतम साधन हैं, वहाँ मुद्रास्फीति के परिशाम श्रात्यन्त मयंकर होंगे श्रीर संमव है कि उनसे समाज का वर्तमान ढाँचा भी जर्जर हो जाये। यदि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साम्यवादी

^{1.} Prof. B. R. Shenoy, "A Note of Dissent on the Memorandum of the Economists' Panel", p.4. Also see for a summary of this note Commerce, dated May 28, 1955, p. 15.

श्चर्य-व्यवस्था के समान भीतिक साधनों का सहारा लिया गया तो योजना की श्चावश्यकताश्चों को पूरा करने के लिए शासन-सम्बन्धी या श्चन्य वैधानिक उपायों के द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्चौर जनतांत्रिक संस्थाश्चों का (धीरे धीरे या तेजी से) लोप हो जायगा। श्चतएव श्चतिश्चाकां ही योजना के भयंकर दुष्परिसामों के प्रति हमें सचेत रहने की श्चावश्यकता हैं । ।

द्वितीय पंचवर्णीय योजना की श्रालोचना का दूसरा श्राधार यह है कि उसके अन्तर्गत उपभोक्ता की क्य शक्ति पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। जब किसी विकास कार्य-कम पर धन ज्यय किया जाता है तो वह अमिकों, कज्बे माल की पूर्ति करने वालों ग्रीर ग्रन्थ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो स्वयं उस धन को उत्पादित वस्तुश्रों पर व्यय करते हैं। वस्तुत: श्रार्थिक विकास की यही प्रक्रिया है। यदि सभी दृष्टिकोणों से विचार करें तो ज्ञात होगा कि धन-उपार्जन करने वालों के द्वारा उसका व्यय किया जाना ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुत्रों को वेचने का श्रवसर प्राप्त होता है जिसका परिणाम यह होता है कि उन विकी हुई वस्तुत्रों के फलस्वरूप फिर नई वस्तुत्रों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया को बराबर जारी रखने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति (purchasing power) में वृद्धि हो। जब तक कि सभी साधनों का पूर्ण उपभोग नहीं हो जाता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। यदि किन्हीं कारणों से लोग उत्पादित वस्तुश्रों का उपभोग नहीं कर पाते तो श्रार्थिक विकास की प्रक्रिया का चेत्र संक्रुचित हो जाता है। द्वितीय योजना में यह निर्देश किया गया है कि योजना की वित्तीय श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए देश में राष्ट्रीय आय पर कर की ७ प्रतिशत दर को ब्रहाकर १६६०-६१ तक ६ या १० प्रतिशत किया जायगा। यही नहीं, कर की दर में १२ प्रतिशत तक वृद्धि करने की ब्रावश्यकता पड़ सकती है। भारत में कर की दर पहले ही से ऊँची है थ्रार इसीलिए योजना ग्रायोग की यह घारणा है कि "करों के वर्तमान स्तर-राष्ट्रीय ग्राय का ७%-को मी बनाए रखने के लिये उसमें कुछ न कुछ संशोधन ग्रवश्य करने होंगे"। यदि करों में श्रव तनिक भी वृद्धि हुई, तो उससे लोगों को श्रत्यधिक कथ्टों का सामना करना पढ़ेगा और न्यापार व उद्योगों के सामने भी श्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायेंगी। यदि करों की किसी भी विधि से लोगों की क्यशक्ति चीए होगी अथवा वस्तुओं में वृद्धि होगी, तो यह निश्चित है कि हितीय योजना के कार्य-कम में बाधा पहुँचायेगी। जैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि

Wide the Author's article, loc cit., p.15.

होगी श्रीर श्रोद्योगिक व व्यवसायिक कार्यों का चेत्र विस्तृत होता जायगा, वैसे-वैसे करों से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व में निश्चित रूप से वृद्धि होती जायगी। किन्तु यदि उपभोक्ताश्रों की क्रय-शक्ति को श्वीण बनाते हुए करों में वृद्धि करने का प्रवास किया जायगा तो यह निश्चय है कि योजना के कार्यान्वित होने में वाधा पड़ेगी श्रोर राज्द्रीय श्राय में श्रनुमानित वृद्धि भी नहीं श्रा सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि वाजार में तथा कारस्तानों के गोदामों में वगैर विकी हुई वस्तुश्रों का . देर लग जायगा श्रोर इस प्रकार उसका उत्पादन या तो घट जायगा या विल्कुल ही बन्द हो जायगा। इस श्रव्यवस्था के फलस्वरूप योजना की प्रगति को गहरा घक्का लगेगा।

यदि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपना उपमोग कम ग्रौर बचत ग्रधिक करें, तो ठीक वंसे ही दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे। कुछ समय पूर्व यह धारणा प्रचलित यी कि अधिक बन्तों से उसी अनुपात में श्रार्थिक विकास भी अधिक होता है। किन्तु अर्थशास्त्र के श्राष्ट्रनिक सिद्धान्त इस धारणा के बिल्कुल विरोधी निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। उनके अनुसार जितना ही अधिक उपमोग किया जायगा उतना ही श्रिधिक श्रार्थिक विकास होगा । यदि क्रित्रम राशि का विनियोग करने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो श्रीर उसकी खपत हो जाने पर पहले की श्रपेचाक्रत अधिक उत्पादन हो श्रीर यह सम्पूर्ण श्रार्थिक प्रक्रिया निर्वित्र रूप से चलती रहे, तो बचतों के सम्बन्ध में कठिनाई उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय आप में वृद्धि होने के फलस्वरूप वचत की कुल रकम में भी वृद्धि होती है ग्रीर ग्रन्त में वचतों के द्वारा विनियोग छन्तुलित हो जाता है। किन्तु यदि बहुत शीघता से यचत की रकम में वृद्धि करने का प्रयास किया जाय तो आर्थिक विकास का चेत्र संकुचित हो जायगा। यदि सरकार की कर नीति श्रथवा श्रन्य नीतियों से वस्तुश्रों के मूल्य में दृद्धि हो श्रीर उपभोक्ताश्रों की कय-शक्ति घट जाय, तो इसका परिखाम यह होगा कि कपड़े, चीनी, खाद्यान श्रीर श्रन्य वस्तुश्रों की प्रति-व्यक्ति खपत (Per ca pila consumption) में अनुमानित वृद्धि नहीं होगी श्रीर न रहन-सहन का स्तर ही ऊँचा उठेगा, चाहे किसी प्रकार उन वस्तुश्रों का उत्पादन बढ़ा ही क्यों न लिया जाय।

तीसरी बात यह है कि योजना के अन्तर्गत अनुमानित घाटे के वजट की १,२०० करोड़ रुपये की रकम (जो देश की वर्तमान द्रव्य-पूर्ति का ५०-६०% है) से अत्यधिक मुद्रास्पीति उत्पन्न हो जाने की संमानना है। किसी भी ऐसे देश में, जहाँ व्यवस्थित रूप से आर्थिक विकास किया जा रहा है, मुद्रास्पीति का उदय

होना अवश्यम्भावी है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रास्फीति पर कहा नियंत्रण रखा जाय जिससे कि अधिक हानि न होने पाये। प्रोफेसर शिनोय की यह धारणा ठीक ही है कि "यदि यह मान भी लिया जाय कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर दुगुनी हो जायगी, तो भी अतिरिक्त रोकड़ वाकी (cashbalances) के लिए इतनी अधिक माँग नहीं हो सकती कि कुल द्रव्य-पूर्ति (money supply) की ५०-६०% रकम की व्यवस्था घाटे के बजट के रूप में करने की आवश्यकता पड़े। यदि केन्द्रीय वैंक (Central bank) का एक-तिहाई अनुमानित द्रव्य घाटे के बजट के द्वारा चलन में आकर व्यवसायिक वैंकों (Commercial banks) के सुरिक्त कोपों में वृद्धि करता है और उसके आधार पर वे व्यवसायिक वैंक ६-७ गुनी साल का निर्माण कर लेते हैं, तो योजना-काल के उपरान्त कुल द्रव्य की पूर्ति योजना प्रारंग करने के समय की द्रव्य-पूर्ति से दुगुनी या उससे भी अधिक हो सकती है। इसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति को निश्चित रूप से जन्म मिलेगा"।

१ पर्याप्त स्चनायं न होने के कारण यह बताना कि किस सीमा तक घाटे का शर्थ प्रवन्ध भारतीय शर्थ व्यवस्था विना हानि पहुँचाये सहन कर सकती है ग्रसमाव है। प्रो० शिनोय ने अनुमान लगाने का साहस किया है। "इस शीर्यक के श्रन्तर्गत बाटे के अर्थ प्रवन्ध की मात्रा में पीएड पावने की मात्रा जो सरकारी चेन्न की आर्थिक आवश्यकता के लिये काम में लाई गई है जोड़ देने पर जो मात्रा आवे -इसे ही घाटे के ग्रर्थ प्रबन्ध करने की वह सीमा समसा जा सकता है जिस तक किसी हानि की भारांका नहीं की जा सकती। पाँच वर्षों के भीतर पोंड पावने की माला ९०० से लगाकर १५० करोड़ रुपये तक योजना के अन्तर्गत मानी गई है। इसके एक श्रंश को व्यक्तिगत चेत्र के लिये नियत करना पहेगा श्रीर उसकी भात्रा के वरावर वैकों द्वारा साख उत्पन्न करनी पहेगी। यदि हम रोकड़ बचत तथा पोंड पावने की रकमों को सरकारी श्रीर ब्यक्तिगत चेश्रों में २:१ के अनुपात में क्रमशः वाँटें तो कुल धारे का भर्य प्रवन्ध १८० से लगाकर २२० करोड़ रुपये तक पाँच वर्यों की अविध में उहरेगा, शर्यात ३५ से ४४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर के हिसाय से होगा।" इस मात्रा को घाटे के अर्थ प्रवन्ध की उचित सीमा चाहे हम माने या न माने पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि २०० करोड़ रुपयों का घाटे का प्रति वर्ष श्रीसत ग्रर्थ प्रवन्ध जो कि द्वितीय योजना में किया जाने वाला है बहुत श्रधिक है। इससे ऐसी सुदारफीति शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती है कि योजना ही नष्ट-श्रष्ट हो जाय।

श्रंतिम बात यह है कि यद्यपि द्वितीय योजना द्वारा प्रथम योजना की एक भूल का सुधार किया गया है श्रौर श्रौद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, किन्तु फिर भी संमव है कि एक दोषपूर्ण श्रौद्योगिक ढाँचे का ही निर्माण हो, नयोंकि उसमें दैनिक उपयोग में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले कारखानों के उद्योगों की उपेज्ञा की गई है। "यदि योजना त्रायोग की बढ़े पैमाने वाले उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के श्रीर घरेलू उद्योग-धंधों को विकित करने की योजना सफल हो जाती है, तो इसका परिणाम यह होगा कि वड़े-बड़े उद्योगों का हास होने लगेगा श्रीर उनके द्वारा प्रत्यज्ञ या श्रप्रत्यज्ञ रूप में प्रयुक्त होने वाली मशीनें, इस्पात और अन्य आघारभूत खामग्री की मांग बढ़ने के स्थान पर श्रीर भी घट जायगी"। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "यदि संरत्त्रण, संगठन श्रीर श्रार्थिक सहायता के द्वारा जितना ही श्रधिक घरेलू उद्योग-धंषों का विकास होगा और कारखानों के क्षेत्र में आधिनकीकरण व प्रसार करने का कार्य जितने ही श्रिधिक समय के लिए स्थिगित किया जायगा, तो उक्त समस्यात्रीं को हल करने की कठिनाई भी बढ़ती ही जायगी । यदि ऐसा विकास कार्य कम श्रपनाया गया, निसमें छोटे-छोटे उद्योगों का प्रसार करके श्रीद्योगिक नीति विल्कुल परिवर्तन कर दी जायगी और मशीनों व बिजली की शक्ति की पूर्ति भी इन्हीं घरेलू उद्योग-धंघों के लिए की जायगी, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य श्रार्थिक इप्टि से नितान्त अनुचित होगा"।

१ इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना उचित होगा कि "छोटे और प्राम्य उद्योगों को संगटित करने के लिये बहुत श्रधिक प्रयत्न करना श्रावश्यक होगा। ऐति- हासिक दृष्टि से तो प्रवृत्ति सुसंगटित फेक्ट्रियों की स्थापना के साथ प्राग्य उद्योगों के विहिष्कार करने की रही है। यह विहष्कार जहाँ कहीं भी हुआ है प्रशासन की श्राचानुसार नहीं हुआ है। यह तो श्रधिक कुशल उत्पादन की प्रणाली के प्रति पद्मपति जो कि श्राधिक विकास का तर्कयुक्त परिणाम है उसके कारण हुआ। इसिलिये स्वभावतः नष्ट्राय प्राग्य उद्योगों का पुनरुद्धार करने के लिये हमें विकास-क्रम के ऐतिहासिक प्रवाह के विरुद्ध चलना पढ़ेगा श्रीर उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फेक्ट्री की व्यवस्था वाले उद्योगों के विस्तार के विरुद्ध कृत्रिम याधार्ये उपस्थित करनी पढ़ेंगी, श्रीर इस सम्बन्ध में मुद्दास्फीति की ऐसी स्थित उत्पन्न करनी पढ़ेंगी कि जो श्रागे चलकर सम्भवत: हमारे नियंत्रण के वाहर हो जाँच श्रथवा हमारी श्राधिक व्यवस्था को सदा के लिये स्थिर कर दें। यदि परम्परागत ढक्न के छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों को विकसित किया जाय तो खर्चाली व्यवस्था का प्रवन्ध करना

इस सम्बन्ध में एक दूसरा दिण्टकोगा यह है कि मावी श्रीद्योगीकरण सरकार श्रीर निजी उद्योगों के सम्मिलित प्रयास पर श्राधारित होगा। यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निजी चेत्र के अन्तर्गग २४०० करोड़ इपए के ज्यय की रकम निर्धारित की गई है किन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी अधिक राशि किन साधनों से उपलब्ध होगी। योजना के अनुसार, "निजी उद्योगों के निर्माण-कार्य के लिए बचत की रकम प्राप्त करने के क्या साधन होंगे, यह निर्देश करना कठिन है। इसके अतिरिक्त यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि निर्माण-कार्य में भ्रतुमानित वृद्धि की पूर्ति होगी ही। कुल बचत के श्रपयीप्त होने पर कमी कहाँ से पूरी की जायगी, इसका पता नहींग। चँकि सरकारी चैत्र को सभी साधन उपलब्ध होने की कदाचित ग्राधिक संभावना है, इसीलिये बहुत इछ संमव है कि निजी चेत्र को अनुमानित साधन न प्राप्त हो सकें। इस परिश्यित का फल यह होगा कि इधर सरकारी चेत्र के श्रंतर्गत श्रीशोगिक विकास होगा श्रीर उधर निजी चेत्र में श्रीद्योगिक प्रगति न होने के कारण सम्पूर्ण श्रीद्योगिक विकास की स्थिति बहुत कुछ सीमा तक वैसी ही रह जायगी। अतएव दितीय योजना के अन्तर्गत जितना औद्योगिक विकास होने का अनुमान किया गया है वह नहीं हो सकेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने वेरोजगारी की समस्या को हल करने पर वहुत जोर दिया है। वास्तव में छोटे पेमाने के श्रीर घरेलू उद्योग-धन्धों के विकास को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण भी यही है। किन्तु यन्त्र तैयार करने वाले उद्योगों का नियोजन इंगलैंड, श्रमरीका श्रीर रूस के श्राधार पर किया जा रहा है। योजना श्रायोग को चाहिये था कि हमारी विशिष्ट श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के नये यन्त्र तैयार करने की व्यवस्था करता, जो इतने कार्यचम होते कि उनके द्वारा प्रति इकाई के उत्पादन की उतनी ही लागत पड़ती जितनी कि विश्व के श्रन्य श्रीद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में तैयार की गई 'श्रम की वचत करने वाली' (Labour-saving) श्रीर श्रपने श्राप चलने वाली मशीनों के द्वारा पड़ती है, किन्तु उनके (भारत की विशेष श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर वनने वाली मशीनों) द्वारा पूँजी-विनियोग की प्रति इकाई में श्रिधिक श्रमिकों की खपत होती। यदि उचित ध्यान दिया जाय तो इस प्रकार

भावश्यक होगा । ऐसा करने पर सफलता तो सीमित मात्रा में ही प्राप्त होगी पर यदि श्रसफल हुये तो परिणाम भयावह होगा।" (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry's "Second Five-Year Plan, A Comparative Study of the Objectives and Techniques of the Tentative Plan-frame", pp. 78)

के यन्त्रों का निर्माण होना पूर्णरूप से सम्भव है। केवल पूँजी की बचत करने वाले (Capital-saving) ऐसे यन्त्रों का निर्माण करने का महत्व इसलिए भी बहुत श्रधिक है कि केवल इन्हीं के द्वारा भारत की वेरोजगारी श्रीर श्रांशिक रोजगारी की समस्या स्थायी रूप से इल की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था की कमी दित्तीय पंचवर्षीय योजना का एक बहुत गम्भीर दोप है।

योजना का पुनर्मूल्यन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रारम्म से ही ग्रसाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। (अ) आयात की हुई मशीनों, कच्चे माल तथा अन्य माल का मूल्य स्वेज़-संकट के कारण बढ़ गया। विदेशों में भी मूल्य बढ़ गये। देश में विनियोग की श्रत्यधिक देर के कारण मुद्रास्कीति की दशा उत्पन्न हो गई जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई। परिणाम यह हुआ कि योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनात्रों की लागत बढ़ गयी तथा प्रारम्भ में निर्धारित वित्त से मीतिक लक्ष्यों (physical targets) की प्राप्ति अवस्मव हो गई । (व) योजना के लिये श्रत्यधिक कर लगाने तथा अन्य उपाय करने पर भी साधनों की कमी पड़ गयी और विदेशी विनिमय का संकट उपस्थित हो गया। (स) द्वितीय योजना का भार जनता की वहन शक्ति के लिये श्रिधिक सावित हस्रा। योजना में सदैव ही कुछ त्याग करना होता है किन्तु द्वितीय योजना में श्रपेश्चित त्याग बहुत अधिक हो गया । अतएव योजना आयोग तथा भारत सरकार को यह समाव दिया गया कि योजना में कटौती की जाय तथा विनियोग की दर कम की जाय। योजना श्रायोग, राष्ट्रीय विकास परिपद तथा भारत सरकार ने विचार-विमर्श के वाद योजना में कटौती करने के बजाय उसे दो भागों में बाँट दिया। (१) भाग श्र जिसके श्रन्वर्गत कृषि उत्पत्ति की वृद्धि से प्रत्यज्ञ रूप से सम्बन्धित योजनार्ये, मुख्य (core) योजनार्ये (रेलवे, वड़े बन्दरगाह, स्टील, कोयला तथा श्चन्य शक्ति योजनायें) जो काफी श्चागे बढ़ गयी हैं तथा श्चन्य योजनायें जिन पर कुल ४५०० करोड़ रु के न्यय का अनुमान है, तथा (२) भाग व निसमें ३०० करोड़ रुपये की शेष योजनायें सम्मिलत हैं।

जैसा कि 'द्वितीय पंचवर्षीय योजना: पुनर्मूल्यन व सम्भावनायें' (मई 'रे६५८) से प्रकट है योजना श्रायोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि योजना पर प्रारम्भिक श्रानुमान की तुलना में ५४० करोड़ रु० कम श्रर्थात् ४२६० करोड़ रु० व्यय होगा।

मई १६५८ में योजना श्रायोग ने घोषणा की कि यथार्थ उपलब्ध साधन ४२६० करोड़ रु० ही है, फिर भी भाग श्रु के श्रर्थ प्रवन्धन का पूरा प्रयन्न किया

द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में विभिन्न मदों के बीच वित्त का निर्धारण (करोड़ र० में)

	योजना के मूल लक्ष्य	श्रधिक लागत के कारण पुनर्निश्चित लक्ष्य (४८०० करोड़ क० के भीतर)	श्रव प्रस्तावित व्यय (योजना का भाग श्र)
कृषि श्रीर सामुदायिक	५६=	५६ ८	५१०
विकास	 - -		
सिंचाई श्रीर शक्ति	६१३	८६०	८२ ०
मामीण तथा छोटे उद्योग	२००	२००	१६०
उद्योग तथा खनिज	६६०	250	030
परिवह्न श्रीर संचार	१,३⊏५	१,३४५	१,३४०
सामाजिक सेवाये	884	द६३	⊏ १०
∙वििव्घ	33	₹ 8	90
कुल योग	¥500	8500	४५००

सेवाश्रों' के अन्तर्गत हुई है ताकि कुल व्यय ४५०० करोड़ ६० हो सकें। विभिन्न योजनाश्रों के लिये निर्घारित वित्त में परिवर्तन युक्तिपूर्वक नहीं किये गये हैं अतएव ये गलत भी हो सकते हैं।

"योजना में ७६ लाख व्यक्ति कृषि के बाहर तथा १६ लाख कृषि में काम पार्येंगे, ऐसी आशा की जाती है। विभिन्न योजनाओं की लागत वढ़ जाने के कारण ऐसा अनुमान किया गया है कि कृषि के बाहर ७० लाख व्यक्तियों को काम मिलेगा। यह अनुमान ४८०० करोड़ र० के व्यय तथा निजी चेत्र के व्यय में कोई परिवर्तन न मानने पर आधारित है। ४५०० करोड़ र० के व्यय के अनुमान पर ६५ लाख व्यक्तियों को काम मिलने की आशा है"।

श्रध्याय ६१ तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

भारत की तृतीय योजना की तैय्यारी की जा रही है और सबसे श्रधिक गंभीर प्रश्न जो योजना आयोग तथा धरकार के समज्ञ है वह योजना के रूप श्रीर श्राकार के सम्बन्ध में है। तृतीय योजना के श्रारम्भ न करने का तो कोई भरन ही नहीं है। यद्यपि द्वितीय योजना के कुछ ध्येयो की पूर्ति होना सम्भव नहीं है श्रोर देश का छार्थिक विकास हमारी श्राशा से कहीं कम हुआ है, फिर भी प्रथम श्रीर द्वितीय योजनाश्रों ने राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा श्राय, कार्य के श्रवसरों तथा जनता के रहन-सहन के स्वर को प्रभावशाली ढंग से बढाया है। यह सिल-िषता चलता रहना चाहिये श्रीर इसके लिये श्रिधिक विस्तृत श्रीर महत्वाकांची तुतीय योजना की श्रावश्यकता है। इसके भी ध्येयों को लगभग प्रथम श्रीर द्वितीय योजना के समान ही होना चाहिये, अर्थात् देश में प्राप्त वस्तुओं के साधनो का सर्वोक्तष्ट ढंग से उपयोग, श्रोद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी उत्पत्ति को श्राधिक से श्रिधिक बढाना ताकि काम करने के श्रवसरों की वृद्धि तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को वास्तविक रूप से ऊँचा उठाया जा सके, होना चाहिये। सारांश यह कि मारत में वास्तव रूप से कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके। यह तो प्रत्यच्च है कि इन आदशों को पूरा कर लेने के लिये लोगों को कुछ वस्तुऋं के अपने वर्तमान उपमोग को श्रधिक कर (tax) देकर त्यागना पड़ेगा श्रोर श्रपनी वचत की मात्रा को पूँजी की वृद्धि करने के लिये बढाना पड़ेगा।

श्रभी तक तृतीय योजना के सम्बन्ध में मतमेद उसके श्राकार पर ही केन्द्रित रहा है। सरकारी मतानुसार तृतीय योजना का ध्येय १०,००० करोड़ रुपयों के विनियोग का ५ वर्ष की श्रवधि में होना चाहिये जबिक द्वितीय योजना में प्रस्ता-वित मात्रा केवल ६२०० करोड़ रुपया ही थी। इस नीति के विरोधकों का कहना है कि इतनी मात्रा का विनियोग श्रत्यधिक होगा श्रीर उन्होंने यह सुमाव उप-रिथत किया है कि तृतीय योजना में विनियोग का स्तर लगभग वही होना चाहिये जितना कि द्वितीय योजना में था। परन्तु तृतीय योजना के श्राकार के सम्बन्ध में मतमेद विना उसके रूप के समके श्रसंगत श्रीर निरर्थक है।

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक गम्मीर बात विनिमय की मात्रा में सरकारी अभीर व्यक्तिगत चेत्रों के भाग की है। प्रथम योजना में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में व्यक्तिगत चेत्र का भाग कुल विनियोग में आधा था परन्तु द्वितीय योजना में वह घटाकर एक-तिहाई कर दिया गया था। ऐसा स्पष्ट रूप से लिक्त हो रहा है कि तृतीय योजना में व्यक्तिगत चेत्र का भाग श्रीर भी श्रधिक घटा दिया जायगा । इसका अर्थ यह है कि द्वितीय योजना में केन्द्रीय श्रीर राज्य सर-कारों द्वारा विकास सम्बन्धी विनियोग जो कि ४८०० करोड़ रुपया था (ग्रीर जो बाद में बटाकर ४५०० करोड़ रूपया कर दिया गया था) उसे ७५०० करोड़ रूपया करना पड़ेगा यदि योजना का कुल व्यय १०००० करोड़ रुपया रक्ता गया। यदि ऐसा हुआ तो १०००० करोड़ रुपयों के आकार की योजना देश की शक्ति के बाहर होगी श्रीर यदि लादी गई तो देश में वड़ी कठिनाई तथा श्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ४५०० करोड़ रुपयों की विकास योजना की वित्त व्यवस्था करने में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बहुत से नये करों का आरोप किया है और पहिले से आरोपित करों में नृद्धि की है जिनते ५ वर्षों में ६०० करोड़ रुपयों की कुल श्रविरिक्त श्राय की श्राशा की जाती है। इन करों के श्रविरिक्त सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में घाटे की ऋर्य-व्यवस्था भी की है जो कि द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षी में ६५० करोड़ रुपये की मात्रा के लगभग होगी यद्यपि संघ के वित्त मंत्री ने १९५६-६० तक उसका २२२ करोड़ चन्ये ही अनुमान लगाया है। चुँकि यह सर्व विदित है कि दितीय योजना की ५ वर्ष की पूरी अविध में १५०० करोड़ रुपयों से श्रिधिक का घाटे का शर्थ प्रवन्धन होगा इसलिये हम यह परिएाम निकाल सकते हैं कि वित्तमंत्री द्वारा अनुमानित मात्रा कम है। यदि सरकार अपनी विकास योजनाश्ची पर कर-श्राय श्रथवा जनता से लिये गये ऋणु का व्यय करती है तो मुद्रास्फीति उसका परिणाम नहीं होना चाहिये ग्रीर उसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि भी न होनी चाहिये। ऐसा इसलिये होगा कि जनता की द्राव्यिक श्राय, लिसमें से वह कर देती है श्रथवा सरकारी ऋगों में लिसका विनियोग करती है समान मात्रा की सेवाओं तथा वस्तुओं द्वारा संदुलित हो जाती है। यदि जनता श्रपनी श्राम का व्यय करती है तो वह इन सेवाश्रों श्रीर वस्तुश्रों का उपभोग स्वयं कर लेती है श्रीर यदि वह कर (tax) देती है श्रयवा सरकारी ऋग में विनियोग करती है तो दूसरे शब्दों में वह इस प्रकार सरकार को उसी मात्रा की सेवाश्रों और वस्तुश्रों के उपमोग का श्रधिकार प्रदान कर देती है। यदि सरकारी विकास योजनाश्रों की वित्त व्यवस्था कर-स्राय तथा ऋगा द्वारा प्राप्त घन से की जाती है तो देश में ऐसी वस्तुयें श्रीर सेवायें प्राप्त होंगी जिन पर यह द्रव्य व्यय किया जा सकता है श्रीर कुछ ही समय में ऐसी समायोजना स्वयं हो जायगी कि ऐसे व्यय के कारण मूल्य स्तर में वृद्धिन हो। लगभग ऐसी ही स्थिति उस समय भी होती है जब कि विकास योजनात्रों की वित्त व्यवस्था विदेशी ऋतुदानों ऋथवा

देश के विदेशी विनिमय निधियों से की जाती है क्योंकि यह धन भारत के वस्तुओं के आयात से ही प्राप्त होता है और इस प्रकार जो कुछ भी ज्यय सरकार योजना पर करती है उससे संतुलित हो जाता है। यथार्थ में ये आयात की हुई वस्तुयें यही नहीं कि मूल्य स्तर की वृद्धि में ही रोकथाम करें वरन् ये वास्तव में मूल्य स्तर को नीचे गिराने में सहायक होती हैं और इसलिये इन्हें इम मुद्रा संकुचन उत्पन्न करने का कारण कह सकते हैं। परन्तु ऐसा घाटे का अर्थ प्रवन्धन जिसका अर्थ ऐसी स्थित है जिसमें सरकार अपनी चालू कर-आय, ऋण से प्राप्त धन, जमा धन और निधियाँ इत्यादि से जो कि उसके पास हैं अधिक ज्यय करती है, मुद्रास्कीति उत्पन्न करने का कारण है और यदि इसकी कुल मात्रा अधिक हुई तो यह मुद्रास्कीति का बहुत अधिक प्रभावशाली कारण वन सकती है, क्योंकि इन्य के न्यय का वस्तु की पूर्त द्वारा इस स्थिति में संतुलन नहीं होता।

तालपर्य यह है कि अपने देश में करारोप अपनी अधिकतम सीमा पर पहुँच चुका है और जनता बिना असह कब्ट उठाये अब और अधिक कर देने में अध-मर्थ है; और घाटे का अर्थ प्रबन्ध मयावह सीमा तक पहुँच चुका है और उसका परिणाम सुद्रास्फीति जन्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो चुकी है। इसलिये सरकार के लिये अब और अधिक घाटे के अर्थ प्रबन्धन का विचार करना अनुचित होगा। परन्तु यदि हमारी तृतीय योजना अधिक विस्तृत और महत्वाकां ही और सरकारी चेत्र अधिक विस्तृत है तो करों तथा घाटे के अर्थ प्रबन्धन के स्तर को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सरकार के लिये महत्वाकां ही योजना को पूरा करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कुल व्यय में सरकारी चेत्र का भाग और अधिक बढ़ाना है और सरकार को उसकी व्यवस्था करने के लिये धन कहीं से ढूँढ़ निकालना है तो हमें समक्तना चाहिये कि अधिक विस्तृत योजना को पूरा करना हमारी सामर्थ के बाहर है चाहे हमारी कितनी ही अधिक अवश्यकता क्यों न हो।

परन्तु यदि तृतीय योजना के अन्तर्गत कुल व्यय में व्यक्तिगत चेत्र का भाग वढ़ा दिया जाता है और यदि सरकार की आर्थिक, श्रीद्योगिक तथा अन्य नीतियों को आत्रश्यकतानुसार परिवर्तित करके उचित वातावरण का सजन किया जा सकता है तो यह सम्भव हो सकता है कि हम अपनी तृतीय योजना को विना कठिनाहयों तथा मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न किये हुये ही अधिक विस्तृत तथा महत्वाकां ही बनाएँ। यह इसिलये सम्भव है कि व्यक्तिगत चेत्र में विनियोग का प्रवन्ध प्रायः वचत की मात्रा और कुछ योहा सा विदेशी पूँजी से किया जाता है और यह व्यय वस्तुओं की पूर्ति द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था में संतुत्तित हो

जाता है। जहाँ तक बैंक द्वारा लिये हुये ऋण से इसकी न्यवस्था होती है उस सीमा तक वस्त की पूर्ति द्वारा संतुलन नहीं होता श्रीर मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। परन्त भारत में व्यक्तिगत चेत्र के कुल विनियोग के बहुत थोड़े से श्रंश की व्यवस्था इस ढंग से होती है इसलिये व्यक्तिगत चेत्र द्वारा विकास-योजना में विनियोग से मुद्रास्फीति के प्रोत्साहित होने की सम्मावना नहीं है। यही कारण है कि नृतीय योजना की रूपरेखा उसके श्राकार को प्रभावित करती है।

इसमें संदेह नहीं कि द्वितीय योजना में श्रारम्म किये हुये विकास कार्यों को उनकी शाखा-प्रशाखाश्रों सहत तृतीय योजना में पूर्ण करना है इसिलये विनियोग की मात्रा द्वितीय योजना से श्राधक श्रवश्य होगी। यद भी सत्य ही है कि यदि जनसंख्या के श्राधक श्रंश को काम देना है तो यह श्राव्यन्त श्रावश्यक है कि भारतवर्ष में जनता को काम करने के श्राधक श्रवसर प्रदान किये जाने साहिये। भारत की जनसंख्या में २% की प्रतिवर्ष वृद्धि को विचाराधीन रखते हुये लोगों को वृद्धिमान रहन-सहन का स्तर प्रदान करने के लिये श्राधक तीत्र गति से श्राधिक विकास की श्रावश्यकता है।

परन्तु यदि सरकारी चेत्र के विस्तार को बहा दिया नाय तो यह सब सम्भव न हो चत्रेगा। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय लगभग २% प्रतिवर्ष की श्रीसत दर से वही है श्रीर लगभग २७ लाख ५० हजार व्यक्तियों की काम करने के अतिरिक्त अवसर प्रदान किये गये हैं जब कि द्वितीय योजना का ध्येय ५% प्रतिवर्ष की वृद्धि राष्ट्रीय त्राय में ग्रीर ८० लाख व्यक्तियों को ग्रातिरिक्त काम देना निश्चित किया गया था। वृद्धि की इस दर ने जनता पर ऊँचे करों, जीवन-यापन के ऊँचे मूल्शों, ग्रीर नीचे गिरे हुये रहन-सहन के दर्जे के रूप में बहुत कठिनाइयाँ लादी हैं। ताकि इन कठिनाइयों को बिना अधिक मात्रा में बढ़ाये तृतीय योजना का विस्तार बढ़ाया जा सके इसिलये योजना आयोग स्रीर सरकार को यह निश्चय करना पड़ेगा कि किसी विचारादर्श के प्रति श्रपनी श्रास्था प्रदर्शित करने के लिये उसी पर श्रहे रहना, अधवा अधिक तीव गति से देश का आर्थिक विकास करना देश के लिये कहाँ तक हितकर होगा। चूँ कि पूँजीवादी व्यवस्था का स्थान समाजवादी व्यवस्था द्वारा धीरे-धीरे लिये जाने का कार्य आरम्भ हो चुका है इसलिये वह तो श्रपना पूरा समय लेगा, परन्तु यदि उसके स्वामाविक विकास को जल्दी लाने का पयल किया गया तो इसका श्रर्य आर्थिक उन्नति श्रीर देश की सम्पन्नता की प्रगति में बाधा हालना होगा।

तृतीय योजना की रूपरेखा का नानना उसके आकार को निश्चित

हरने के लिये ही श्रावश्यक नहीं है वरन् देश को विकास योजनाओं से श्रिविकतम जाभ माप्त करने के लिये भी आवश्यक है। व्यक्तिगत चेत्र को उसका उचित श्रंश ेदेने के बाद दूसरा आवश्यक प्रश्न योजना के अन्तर्गत आये हुये विकास कार्यों का कम है। क्या तृतीय योजना के विकास कार्यक्रम में कृषि को वही स्थान दिया जाना चांहिये जो कि उद्योग को दिया जाय ? द्वितीय योजना के अनुभव के 'स्राधार पर जिसमें कृषि को श्रीद्योगिक विकास की तुलना में कम महत्व का स्पान दिया गया था इम कह सकते है कि कृषि का स्थान अधिक महत्व का होना चाहिये । द्वितीय योजना में सर्वप्रथम १०० लाख टन खाद्यान के उत्पादन क़ा लक्ष्य बनाया गया था जो कि बाद में बढ़ाकर १ ७५ लाख टन कर दिया गया। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस लक्ष्य का आधे से अधिक पूरा न किया जा सकेगा। कृषि के प्रति उदासीनता के परिणाम स्वरूप खाद्यान में कमी तथा उनके निरन्तर बढ़ते जाने वाले मूल्य देश के समज्ज श्राये। ऐसी श्रर्थ व्यवस्था में जहाँ खाद्यान के मूल्य का सबसे श्रिषिक महत्वशाली स्थान है वहाँ श्रन के मूल्य के बढ़ने के साथ ही साथ ग्रन्य वस्तुत्रों के मूल्य भी बढ़ने लगते हैं। श्रीर इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब वातों को उत्पन्न न होने देने के लिये तृतीय योजना में कृषि उत्पत्ति के श्रिधिक बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें सैदेह नहीं कि देश की कुल आय तथा उत्पत्ति श्रीद्योगिक विकास के फलस्वरूप कृषि के विकास की तुलना में श्रविक . तीव गति से बढ़ जायगी। यही बात काम के ऋवसरों, निर्यात तथा जनता के रहन-सहन के दर्जे के बढ़ाने के सम्बन्ध में भी सत्य है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि ऐसी अर्थिक उन्नति का क्या प्रयोजन जब जनता को भर पेट भोजन मिलना ही दुष्कर हो जाय। कृषि के विकास के प्रति विशेष ध्यान देने का श्रर्थ चाहे आर्थिक विकास में कमी करना ही क्यों न हो यह जोखिम उठाने योग्य है क्योंकि इससे म्रज की उपज तथा म्रन्य कृषि उत्पत्ति के बढ़ जाने के कारण भ्रौद्योगिक विकास के लिये हु श्राधार प्राप्त हो जाता है।

श्रीद्योगिक विकास में वास्तिविक किताई विभिन्न हितों के समायोजित करने की है जैसे: (१) छोटे स्तर के बरेलू उद्योग-धन्ये श्रीर ज्वाइंट स्टाक कम्पनी ज्यवस्था वाले बड़े स्तर के उद्योग, श्रीर (२) बड़ी मशीनों के निर्माण करने वाले उद्योग तथा उपमोक्ता की वस्तुश्रों तथा श्रन्य छोटी-छोटी वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योग । भारतीय श्रार्थिक तथा उद्योग ज्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योग । भारतीय श्रार्थिक तथा उद्योग ज्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग-धन्यों का एक विशेष स्थान है श्रीर इसलिये उन्हें पूर्ण रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि बड़े स्तर

पर उत्पादन करने वाले उद्योगी का ब्रव्हित करके ऐसा किया नाय। द्वित य योजना में एक महान भूल बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की चिन्ता न कर में छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा घरेलू उद्योग घन्घों को वदाने की की गई थी। इसके मूल में योजना के श्रन्तर्गत काम करने के श्रवसरों की बढ़ाने की भावना थी। इसका उदाहरण स्ती कपड़ा उत्पादन करने वाले उद्योग थे। यह नीति काम के श्रवसरों के बढ़ाने में सफल नहीं हुई वरन् उसने बड़ी मात्रा में उत्पा-दन करने वाले उद्योगों को घाटा पहुँचाया। यह भूल तृतीय योजना में वचाई जानी चाहिये और केवल उन्हीं वरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिनका विकास बिना बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों को हानि पहुँ-चाये किया जा सकता है ब्रीर केवल ऐसे ही ढंगीं का प्रयोग किया जाना चाहिये जिनसे घरेलू उद्योगों की तो सहायता प्रभावशाली ढंग से हो पर बड़े उद्योगों की किसी प्रकार की हानि न पहुँचे । जैसे-जैसे बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों का विकास होता चलेगा श्रिविकाधिक काम करने के अवसर जनसंख्या की मिलते जायंगे श्रीर इस बीच में इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि अम-बचाव के ढंग का प्रयोग न हो वरन् नये कारखानों में तथा उन पुराने कारखानों में जहाँ मशीनें बदली जाने वाली हैं अधिक कुशलता से काम लेने वाली मशीनों का प्रयोग हो।

तृतीय योजना में अधिक व्यय होने के कारण व्यो-च्यों लोगों की आय बढ़ेनी त्यों-च्यों उन्हें अधिक उपभोग की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। मृत काल में ऐसी वस्तुयें अंगुटः विदेशों में अपने विदेशी विनिमय निधियों के और अंग्रतः सुगतान संतुत्वन के आतिरेक के आधार पर आयात की जा सकती यीं। अब उपभोक्ता की सूर्विक्रों की पूर्ति देश में दिन बढ़ानी है। परन्तु यदि इन्हीं उद्योगों पर आधिक विनिमय केरे दिया गया तो मशीनों के निर्माण, मारी रासाः निक प्रव, इन्जीनियरिंग तथा अन्य इस प्रकार के उद्योगों पर जो कि अभी भारत हैं पूर्ण क्य से विकसित नहीं हुये हैं, और जिनके विकास को औद्योगिक आधार प्राप्त करने के लिये आवश्यकता है, व्यय करने के लिये पर्याप्त मात्रा से धन न करने के लिये आवश्यकता है, व्यय करने के लिये पर्याप्त मात्रा से धन न करने विज्ञतिय में ये उद्योग लोगों को इतने काम के अवसर न प्रदान कर स्वती जितने कि उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन वाले उद्योगों के विकसित करने ने मिलते। इसके अतिरिक्त उनका उत्पादन वालार में विक्री के लिये अधिक दिनों के प्रश्चित अधिक अधिक विनियोग होने के कारण वाजार में माल पहुँचने के पहिले पहुँच जायगी जिससे सुद्रास्क्रीति की स्थित उत्पन्न हो जायगी।

पर खु इन सब किटनाइयों के होते हुये भी भारत की तृतीय योजना के अन्तर्गत भूद काल की अपेक्षा अधिक मात्रा में व्यय बड़ी मशीनों के निर्माण करने वाले कारखानों के लिये नियत करना आवश्यक होगा।

चूँ कि अपने देश में साधन का श्रमाव है इसिलये महत्व में प्रथम वस्तु को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि तृतीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये विकास से असम्बन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना के बाहर विकास सम्बन्धी व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिये और भारत के सरकारी व्यय में जितनी भी मितव्ययता सम्मव हो, की जानी चाहिये। इस बात पर बारम्बार योजना आयोग ने तथा सरकार ने जोर दिया है परन्तु अभी तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे कोई प्रयोगारमक रूप नहीं दिया गया है। प्राप्त साधनों का सर्वोचम प्रयोग करने के लिये भी यह आवश्यक है कि तृतीय योजना के बाहर के व्यय को न्यूनतम करने के लिये कोई प्रयोगात्मक उपाय दूँ विकाला जाय।